

भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा

द्वितीय भाग



लेखक

शंकर सहाय सक्सेना एम० ए०, एम० कॉम०

प्रिन्सिपल, महाराणा भूपाल कालेज, उदयपुर
डीन, कामर्स फैकल्टी, राजपूताना विश्वविद्यालय, जयपुर
तथा

प्रेमनारायण माथुर एम० ए०, बी० कॉम०

भूतपूर्व गृह तथा शिक्षा मंत्री, राजस्थान
एवं आचार्य, वनस्पती विद्यापीठ

मूल्य १०)

निवेदन

भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा के द्वितीय भाग को लेकर उपस्थित होते हुए लेखकों को अत्यन्त हर्ष है। पाठकों ने पुस्तक के प्रथम भाग का जैसा अभूतपूर्व स्वागत किया—कुछ महीनों में ही उसका प्रथम संस्करण समाप्त हो गया—यह इतनी बात का द्योतक है कि भारतीय अर्थशास्त्र के अध्यापकों तथा छात्रों की पुस्तक उपयोगी प्रतीत हुई।

द्वितीय भाग में उद्योग-धंधों, भारतीय श्रम की समस्याओं, वातायात के साधनों, व्यापार, मुद्रा साख और बैंकिंग, राजस्व और आर्थिक योजना का विशद विवेचन किया गया है। पुस्तक लिखने में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि भारतीय अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को भारत की आर्थिक समस्याओं के संबंध में केवल आधुनिकतम तथ्य ही अवगत न हों किन्तु वे आर्थिक समस्याओं पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विचार कर सकने की योग्यता प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य से उन सभी आर्थिक समस्याओं जिन पर आज देश में गहरा मतभेद है और जिनके सम्बन्ध में ठीक दृष्टिकोण अपनाने से ही देश के आर्थिक निर्माण को जीव रक्षी जा सकती है उन सभी समस्याओं पर भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करके लेखकों ने अपने-अपने मत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रतिपादन किया है।

आज भारत के आर्थिक निर्माण के प्रश्न को लेकर प्रत्येक देशभक्त भारतीय चिन्तित है, सरकार की अर्थ-नीति बहुत स्पष्ट नहीं है और सम्भवतः इसी कारण अधिक प्रभावशाली और दृढ़ भी नहीं है। आज देश में इस बात पर दो मत हैं कि देश बड़ी मात्रा की यांत्रिक खेती को स्वीकार करे अथवा छोटी मात्रा की अत्यन्त गहरी खेती को प्रोत्साहन दिया जावे, ग्राम्य और ग्रह-उद्योगों का देश के भावी आर्थिक संवर्धन में क्या स्थान हो, बड़ी मात्रा के उत्पादन में व्यक्तिगत साहस को रहने दिया जावे अथवा उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया जावे, सरकार की औद्योगिक नीति क्या हो, रुपये के अवमूल्यन की आवश्यकता थी अथवा नहीं और क्या रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन करने का समय उपस्थित हो गया है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन तथा रिजर्व बैंक की सार्व सम्बन्धी नीति क्या होनी चाहिए, आर्थिक नीति और ग्राम्य जीवन से सम्पर्क क्या तथा सरकार की अर्थ-नीति, न्यूनतम अथवा अधिकतम अर्थ-नीति सरकार का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, सरकारी अर्थ-नीति—मजदूरों की अर्थ-नीति क्या होनी चाहिए, अर्थ-नीति क्या दोषपूर्ण है, उसमें क्या सुधार

प्रत्येक विषयों का विशद एवं गम्भीर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। पञ्चवर्षीय योजना, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और मारन, सरकार की औद्योगिक नीति, रुपय का अवमूल्यन इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर वृथक परिच्छेद लिखे गए हैं।

लेखकों ने पुस्तक लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रक्खा है कि पुस्तक को अनावश्यक लम्बा (आकड़ा की) तालिकाओं से बोझिल न किया जावे। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रक्खा गया है कि आधुनिकतम तथ्य और निर्णयात्मक आकड़े दिए जावें जिससे आर्थिक समस्याओं का ठीक-ठोस अध्ययन करने में सहायता मिले।

भारत एक स्वतंत्र हो जाने पर देश आज एक मजबूत आर्थिक संकट में घेर निकल रहा है। आज देश एक कगार पर खड़ा हुआ है, अर्थ-नानि को निर्धारित करने में तनिक भी भूल हान पर देश पर गम्भीर संकट उपस्थित हो सकता है। ऐसी दशा में प्रत्येक भारतीय, राजनैतिक व्यक्ति और दशभक्त का यह कर्तव्य है कि वह देश की आर्थिक समस्याओं का गम्भीरता वृथक अध्ययन करे। देश के असह्य निरासी अंग्रेजी न जानने के कारण भारत की आर्थिक समस्याओं पर अर्थशास्त्रियों के विचार जानन में बाधित रह जाते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए लेखकों ने इस पुस्तक को लिखने का प्रयास किया है।

जो भी राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरान्त देश की आत्मा जब विदेशी भाषा को दासता को गिलागलि देने के लिए छुटपन रही है। वयति अधिकांश विश्वविद्यालयों में वा ए तथा वा काम परीक्षाओं में हिंदी भाषा स्वाकृति कर लिया गया है किन्तु हिंदी में भारतीय अर्थशास्त्र पर कोई प्रमाणिक ग्रन्थ न होने के कारण विद्यार्थी इस सुविधा से लाभ उठाने से बाधित रहते हैं। लेखक लिखने बाध क्यों से हिंदी द्वारा उच्च शिक्षा दिए जान के समर्थक और प्रचारक रह हैं। इस लक्ष्य का लेकर उन्होंने अर्थशास्त्र तथा साहित्य का दिव्य में निभाया किया है और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर वे इस पुस्तक को दिव्य अंग्रेज के सामने लेकर उपस्थित हुए हैं।

विषय-सूची

परिच्छेद १

पृष्ठ

उद्योग-धन्धे : साधारण विवेचन

१—२७

आधुनिक उद्योगों का प्रारम्भ—औद्योगिक अवनति की ओर देश का
 भ्रान्त—प्रथम महायुद्ध काल में औद्योगिक उन्नति—युद्धोत्तर तेजी और मंदी—
 मन्दी के उपरान्त स्थिति में, सुधार तथा विगाड़—दूसरा महायुद्ध और हमारी
 औद्योगिक उन्नति—औद्योगिक उत्पादन—दूसरे महायुद्ध के उपरान्त हमारी
 औद्योगिक उन्नति—भारत के विभाजन का प्रभाव—भारत सरकार की औद्योगिक
 नीति—औद्योगीकरण से लाभ ।

परिच्छेद २

उद्योग-धन्धे : प्रस्तुत प्रश्न

२८—६९

योजना की आवश्यकता—राज्य और उद्योग-धन्धे—भारत की
 राजकोपीय नीति—भारत की संरक्षण-नीति की आवश्यकता—राजकीय सहायता
 के अन्य प्रकार—उपसंहार—राजकोपीय आयोय की सिफारिशें ।

परिच्छेद ३

उद्योग-धन्धे : प्रस्तुत प्रश्न

६३—१३१

संगठन की समस्या—मैनेजिंग एजेंसी—१९३६ का कम्पनी एक्ट—
 औद्योगिक अर्थ प्रवन्ध—विदेशी पूँजी—कम्पनी कानून में सुधार—भारत सरकार
 के प्रस्ताव—मैनेजिंग एजेंसी में सुधार सम्बन्धी-प्रस्ताव—कम्पनी कानून में दूसरे
 प्रस्तावित संशोधन ।

परिच्छेद ४

उद्योग-धन्धे : श्रम

१४४—१९८

भारत में श्रमिक वर्ग का उदय—कृषि और ग्राम्य जीवन से सम्पर्क—
 स्थान परिवर्तन के कारण—गाँव से सम्पर्क के लाभ—हानि—मजदूरों की शर्तों—
 श्रम से

चाय के भेद (प्लान्टेशन्) — उद्यानों पर काम करनेवाले — रान मजदूर —
 मार्मंत्रिक निर्माण — एम्प्लायमेट एक्टवैव — मजदूरों का शिक्षण — मजदूरों का
 स्थायित्व — काम न पड़े — आराम और श्रमकाश — कारमानों आदि में
 काम करने की परिस्थितियाँ — कारमानों में उपलब्ध श्रमिकों की सुविधाएँ — सफाई
 — रक्षा — मजदूर हितकर काम — मजदूरों के भ्रष्टाना का समस्या — सामाजिक
 सुरक्षा — श्राव और रहन-सहन का दवा — श्रम — भारतीय मजदूर की
 काम-सुचन ।

परिच्छेद ४

मजदूर-कानून

१४० — १६६

✓ कैबटरी एक्ट १८८८ — मध्यप्रदेश और मद्रास के श्रमिकान्वित कैबटरी
 कानून — भारतीय सार कानून — चाय बागों में काम करने वाले मजदूरों संबंधी
 कानून — भारतीय रेलवे एक्ट १८८० — नौनिवेद्य (सेंसिंग) में काम करने वालों
 संबंधी एक्ट १८४८ — दुकानों में काम करने वालों से संबंधित कानून — साप्ताहिक
 श्रमकाश (डोलाई) कानून १८४४ — भारतीय श्रमिक मजदूर कानून १८९४ —
 कोयले की शानों संबंधी सुरक्षा (स्ट्रेचिंग) एक्ट — कोयले और श्रमिकों की
 शानों के मजदूरों के हित संबंधी कानून — सेन्ट ऑफ सेन्ट्रल एक्ट १८९६ — मूलभूत
 मजदूरों कानून १८४८ — मजदूर-सुविधा कानून १८२३ — एम्प्लोयर्स एंड इम्प्लोई
 रेल्वे एक्ट १८४८ — कोल भारतीय प्राविडेंट वर और बोयल स्कीम एक्ट १८४८ —
 भारतीय नाम कानून — मानक धन कानून — बालकों की नौकर रखने का कानून
 १८३८ — औद्योगिक अकैडमी कानून १८४४ — श्रम संबंधी कानून ।

परिच्छेद ५

औद्योगिक सम्बन्ध

१६७ — १८३

मजदूर समारोह और औद्योगिक संबंध — भारत में मजदूर सम्मेलन — ईस्ट
 यूनियन एक्ट १८३६ — औद्योगिक संपर्क — औद्योगिक शानि के प्रवाल — केन्द्रीय
 औद्योगिक संपर्क कानून — इन्स्ट्रुक्शन लिस्सूट्स (एपिलेट दिव्यूनल) एक्ट
 १८४० — इन्स्ट्रुक्शन एम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर) एक्ट १८४२ — राज्यों के
 औद्योगिक संपर्क मजदूरों कानून — ईस्ट यूनियन और मजदूर सम्बंधों सम्बन्धी
 सम्बंधित कानून — अन्तर्राष्ट्रीय तथा दूसरी समितियों और सम्मेलनों में भारतीय
 प्रतिनिधित्व — भारतीय मजदूर सम्मेलन ।

परिच्छेद ७

संगठित उद्योग-धन्धे

१९४—२७७

सूती-वस्त्र-मिल उद्योग : प्रारम्भिक इतिहास, प्रथम महायुद्ध, युद्धोत्तर प्रभिष्टुद्धि, संकट काल १९२३, संरक्षण-प्रारम्भ, विश्व-संकट, १९३५-३७, प्रगति की ओर, द्वितीय महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्, अधिष्य-पटसन (जूट) मिल—ऊनी मिल—रेशम—रेयोन—शकर—लोहा और इस्पात—कोयला—इस्त्रीनिवरिंग—औद्योगिक प्लांट—ऐजिन—मोटर—हवाई जहाज—मशीन टूल्स—सिलाई की मशीनें—बाइसिकिल—हरीकेन टेनेटर्न—विजली का सामान—डीजिल ऐजिन—पावर प्लान्ट्स—रेडिओ रिसेवर्स—टेलीफोन इन्विपमेंट—रासायनिक पदार्थ—चमड़ा—तेल का मिल—वनस्पति ची—कागज—दियासलाई—कॉच—सीमेंट—अलुमिना (नॉन-फेरस) बादुर्ण—एल्यूमीनियम—जहाज निर्माण ।

परिच्छेद ८

व्यापार

२७८—३०७

भारत का विदेशी व्यापार : स्वेज नहर का निर्माण, भारतीय बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा, प्रथम महायुद्ध के पश्चात्, द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात्, आज की स्थिति—आयात और निर्यात के मुख्य पदार्थ—विदेशी व्यापार और सरकार का नियंत्रण—विदेशी व्यापार के प्रचार और प्रसार के साधन—विदेशी व्यापार की भावी दिशा—स्वतः द्वारा विदेशी व्यापार—भारत का 'एन्ट्रीपो' व्यापार—भारत का आन्तरिक व्यापार ।

परिच्छेद ९

यातायात

३०८—३४८

यातायात का महत्त्व—यातायात के प्रमुख साधन—रेल-वातायान : प्रारम्भ, पुरानी मारटो व्यवस्था, ब्रांच लाइन कम्पनीज, तत्कालीन देशी राज्यों में रेल निर्माण, प्रथम महायुद्ध के पूर्व, प्रथम महायुद्ध का समय, एकद्वय, कमेटी, प्रथम महायुद्ध के बाद आज तक, रेलवे के स्वामित्व और प्रबन्ध का प्रश्न, रेलों का शासन प्रबन्ध, रेलवे वित्त व्यवस्था, रेलवे की आर्थिक स्थिति, रेलवे जॉच कमेटीयों, रेल-भाड़ा नीति, रेलवे द्वारा आगमन की स्थिति, रेलवे की फिर से

समूहोत्थरण, रेलों का आर्थिक प्रभाव—मछली पालना—शुद्धी का वर्गीकरण—
 शुद्धी का विकास, पौर मण्डल योजना—मोटर वातायन का राष्ट्रीयकरण—
 नदी यातायात—समुद्रमार्ग यातायात—मार्केटगार्स मरीन कोटी, समुद्रमार्ग
 यातायात का राष्ट्रीयकरण का प्रश्न, दिनांक महापुरुष और उनके परचाय, दीव
 योजना योजना—हवाई यातायात—बन्धन स्थिति, मार्फी विकास, ईश्वरीय
 योजना—यातायात व भाषनों का समन्वय।

प्राथमिक १८

बैंकिंग व्यवस्था

१४६—१४७

देशी बैंकर उन्नत कार्य, देशी बैंकों का अधर्नाम व कारण, देशी बैंकों
 तथा उन्नत प्राइवेटों का संबंध, देशी बैंकों का व्यापारिक बैंक से संबंध, देशी
 बैंकों व एकात्म व दाय और गुण, देशी बैंकर और रिजर्व बैंक का संबंध—
 मिथिन पूंजी वाले बैंक का व्यापारिक बैंक प्रसाधन बैंक, मिथिन पूंजी वाले
 बैंक, मिथिन पूंजी वाले बैंकों का कार्य—देशी का वर्गीकरण—विनिमय बैंक या
 एक्सचेंज बैंक—देशी भारतवासि द्रव्य बाजार में प्रभाव, उन्नत कार्य—देशीय
 बैंकिंग कमीटी का मन—भारतीय एक्सचेंज बैंक—इंग्लिश बैंक और इंडिया
 प्रबन्ध, १९१४ के पूर्व, कार्य, वर्तमान स्थिति, इंग्लिश बैंक को रिजर्व बैंक से
 क्यों न परिणित कर दिया जाय, इंग्लिश बैंक का मविष्य में भारत—रिजर्व
 बैंक और इंडिया बैंक हिस्सेदारों का हो अथवा राज्य का, रिजर्व बैंक का
 विधान, प्रबंध, स्थानीय बोर्ड और उन्नत कार्य, रिजर्व बैंक के कार्य, रिजर्व बैंक
 का अन्य विशेषताएँ, रिजर्व बैंक का नाम और रजिस्टर कोष, रिजर्व बैंक
 एक्ट १९११, रिजर्व बैंक और द्रव्य बाजार, रिजर्व बैंक और धातु का नियंत्रण,
 रिजर्व बैंक और इंग्लिश बैंक, रिजर्व बैंक और बाजार मार्केट, धातु व निधि
 पूंजी के उपाय, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, देश की बैंकिंग व्यवस्था का रिजर्व
 बैंक से सहामता—भारतीय समाशोधन शुद्ध अथवा क्लीयरिंग हाउस—
 उप मदक, प्रबंध, निरीक्षक बैंक—भारतीय द्रव्य बाजार द्रव्य बाजार में शुद्ध
 की दर, बैंक डिपॉजिटों पर शुद्ध का दर शुद्धी जमा पर शुद्ध की दर, विनिमय
 दर मिलने वाले शुद्ध की दरें, शुद्ध वजार का दरें, भारतीय द्रव्य बाजार में अस्थिर
 रता तथा अधिक उन्नत-वृद्धि का होना, व्यापारिक मिलों का प्रभाव—भारत में
 बैंकिंग संबंधी कानून रिजर्व बैंक एक्ट बनाने का प्रस्ताव, बैंकिंग विन १८४२—
 द्वितीय महापुरुष का भारतीय बैंकिंग पर प्रभाव—देश के स्वतंत्र होने तथा विमोक्त

ग प्रभाव—अन—द्रव्य कोष—अन्तर्राष्ट्रीय बैंक : पूँजी, प्रबन्ध, कार्य—
भारत और अ १ मुद्रा कोष तथा बैंक—भारत के बाँवों में बैंकिंग का
विस्तार ।

परिच्छेद ११

मुद्रा और विनिमय

४७५—५०८

रुपया पूर्ण कानूनी सिक्का—स्वर्णमान की माँग—रुपया पूर्ण कानूनी मुद्रा
नहीं रहा—फाउलर कमेटी की सिफारिशें—सरकार की कार्रवाई—स्वर्णमान से
स्वर्ण विनिमय मान की ओर—स्वर्ण मुद्रा के चलन का प्रयत्न—स्वर्णमान कोष—
कौंसिल ड्राफ्ट—स्वर्ण विनिमय मान पद्धति के प्रमुख लक्षण—चेम्बरलेन कमी-
शन—प्रथम महायुद्ध—वेबिंगटन स्मिथ कमेटी, श्री दलाल का मतभेद, सरकार
का निर्णय—२ शि० सोने की विनिमय दर की असफलता, उसके कारण—विनि-
मय दर का १ शि० ६ पै० तक पहुँचना—हिल्टन यंग कमीशन, स्वर्ण विनिमय
मान के दोष, गेल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, विनिमय दर की समस्या, कमीशन की रिपोर्ट
पर सरकार की कार्रवाई—विनिमय दर १९२७-३१—१९३१ का संकट—रुपया-
स्टरलिंग सम्बन्ध—सोने के निर्यात की समस्या—विनिमय दर में परिवर्तन की
माँग जारी—भारतीय कागजी मुद्रा : प्रारम्भिक इतिहास, १९१४ के पूर्व की
स्थिति, १९१४-१८ की स्थिति, प्रथम महायुद्ध के बाद ।

परिच्छेद १२

द्वितीय महायुद्ध और मुद्रा

५०९—५३३

मुद्रा का विस्तार—स्टरलिंग सिक्यूरिटीज़ का जमा होना—रुपया
सिक्यूरिटीज़—रुपया और रजगारी की माँग में वृद्धि—विदेशी विनिमय
की स्थिति और उसका नियंत्रण—आयात-निर्यात नियंत्रण—एम्पायर
बालर पूल ।

द्वितीय महायुद्ध के बाद भारतीय मुद्रा का विस्तार—स्टरलिंग सिक्यु-
रिटीज़—रुपया सिक्यूरिटीज़—विदेशी विनिमय का नियंत्रण—स्टरलिंग पावने
की समस्या—रुपये का अवमूल्यन—क्या रुपये का पुनः मूल्यन किया जाय—अव-
मूल्यन नहीं करने का पाकिस्तान का निर्णय—विदेशी विनिमय संबंधी नीति क्या
हो—विनिमय दर में कब परिवर्तन करना चाहिए ।

सार्वजनिक विधा

~~व्यापक~~ विधा

५३४—५६५

सार्वजनिक वित्त का महत्त्व—भारत व सार्वजनिक वित्त की विशेषताएँ—
केन्द्र और राज्य का वित्त संबंध—पैसे का गिरावला व वित्त का एकत्रीकरण—
केन्द्र और राज्यों में आय व व्ययों का विभाजन—अर्थ व सम्बन्ध में अधि-
कार—संविन निधियों और लाक लेखे तथा आकस्मिकता निधि—केन्द्र और
राज्यों के वित्त व्यवस्था का इतिहास १९१६ व मुघल के पहल तक का इतिहास,
१९१६ व मुघल और वित्त सम्बन्ध, १९३५ का विधान और वित्त सम्बन्ध,
निमित्त रिपोर्ट, निमित्त निष्पत्ति व परिणाम, देशमुख निर्णय—भारत सरकार
और राज्यों व बजट ।

केंद्रीय विधा भारत सरकार को आय सीमा शुल्क, आयकर, निम्न-
कर, अतिरिक्त लाभ-कर, व्यापार लाभ-कर, पूँजीगत लाभ-कर, मधीय उत्पादन
शुल्क, नमक शुल्क, व्यापारिक विभागों में आय, आय व अन्य साधन—भारत
सरकार का व्यय रक्षा व्यय, राजस्व समूह पर होने वाला व्यय, सामरिक
व्यय, पूँजीगत व्यय—भारत सरकार का सार्वजनिक अर्थ अर्थ का बुझावा,
स्ट्रालिंग अर्थ का 'रिपेडियेशन', देश का विभाजन और सार्वजनिक अर्थ, मुद्रा-
बाजार में अर्थ मिलने में कठिनाई ।

राजकीय वित्त राज्यों की आय भूमि राजस्व, आबकारी शुल्क,
चिन्ता, जमाना, रजिस्ट्रेशन, स्टेम्प, विक्रय-कर, इति आयकर, मगारजन-कर,
पण लगाने (बेटिंग) पर कर, मोटर गाड़ियाँ पर कर, आयकर, केन्द्र से सहा-
यता—राज्यों का व्यय राज्य पर प्रत्यक्ष मार्ग चिन्ता, साति-व्यय, सामाजिक
सेवाकार्य, अर्थ संग्रहण, पूँजीगत सर्वे, 'जी' राज्यों का रख—राज्यों का सार्व-
जनिक अर्थ—केन्द्र और राज्य की वित्त व्यवस्था की वर्तमान स्थिति ।

स्थानीय वित्त नगरपालिका वित्त प्रत्यक्ष कर, अत्यन्त कर, व्यापारिक
कार्यों से आय—निला बोर्डों की वित्त व्यवस्था भूमि उपकर, स्थिति और
स्थिति पर कर, टोल, दुर्गम किराया और फीस, अनुदान—स्थानीय वित्त में
मुघल की आवश्यकता ।

राजस्व और व्यय के बजट भारत सरकार का बजट—देश
प्रदेश का बजट—मध्य प्रदेश का बजट—बम्बई का बजट—देवर
का बजट ।

परिच्छेद १४

मूल आर्थिक समस्या—मँहगाई और उत्पादन वृद्धि

५६६—६०३

द्वितीय महायुद्ध और मँहगाई—युद्ध के बाद मँहगाई की स्थिति—मँहगाई को रोकने के सरकार के प्रयत्न—उत्पादन वृद्धि और नई मुद्रा जारी नहीं करना मुख्य उपाय ।

परिच्छेद १५

आर्थिक योजना

६०४—६५५

हमारा जीवन-दर्शन क्या हो—हमारा सामाजिक लक्ष्य : सुरक्षा, स्वतन्त्रता और अवकाश—सही अर्थ-रचना का स्वरूप—गांधीजी के अर्थ-व्यवस्था संबंधी विचार—माथी अर्थ-रचना गांधीवाद और समाजवाद का समन्वय—भारत में आर्थिक योजना के प्रयत्न—कोलम्बो योजना ।

पंचवर्षीय योजना : योजना का आधार जनतंत्र—जनता का सहयोग आवश्यक—सहयोग और उत्साह का आधार क्या—कृषि व्यवस्था का महत्व—देश की कृषि व्यवस्था के आधारभूत दोष—प्लानिंग कमीशन के सुझाव—भूमि सुधार का अन्तिम ध्येय—औद्योगिक उन्नति की आवश्यकता—आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय का महत्व—आर्थिक संगठन का रूप कैसा हो—प्लानिंग कमीशन मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था के पक्ष में—मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था की सफलता का आधार—सरकार का नियंत्रण आवश्यक—मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था ठीक नहीं—क्या व्यक्तिगत व्यवस्था का नियंत्रण सम्भव है—परस्पर विरोधी दलील—प्लानिंग कमीशन के तर्क सही नहीं—आज के उदाहरण सही नहीं—मिली-जुली व्यवस्था में समाज-हित सम्भव नहीं—कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्व—योजना का आधार प्रगतिशील अर्थ-रचना नहीं—योजना क्या है : कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, बातायात और संघादन, आर्थिक साधनों की व्यवस्था—योजना कैसी है ?

उद्योग-धंधे : साधारण विवेचन

प्राज के कल और कारखाने के युग में भी औद्योगिक दृष्टि से भारत एक पिछड़ा हुआ देश है और उसके आर्थिक जीवन में खेती की प्रधानता है। देश के आर्थिक जीवन के इस वर्तमान खेती-प्रधान स्वरूप को देख कर यह कल्पना नहीं होती कि कभी इस देश के उद्योग-धंधे में उन्नत अवस्था में ये और हमारे आर्थिक जीवन में उनका महत्त्व था। पर औद्योगिक कमीशन की रिपोर्ट से लिया गया निम्नलिखित अंश इस संबंध में वस्तु-स्थिति पर समुचित प्रकाश डालता है। औद्योगिक कमीशन का कहना है:—“उस समय, जबकि पश्चिमी यूरोप में जो कि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का जन्मस्थान है, असंख्य लोग निवास करते थे, भारत अपने राजा-नवाबों की सम्पत्ति और अपने करीगरों के कौशल के लिए विख्यात था। और इसके बहुत समय बाद भी, जबकि पश्चिम के व्यापारी पहले-पहल यहाँ आए, यह देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से पश्चिम के जो अधिक उन्नत राष्ट्र हैं उनसे यदि आगे बढ़ा हुआ नहीं तो किसी प्रकार कम तो नहीं था।”

अत्यन्त प्राचीन काल से भारतवासी अपने विभिन्न प्रकार के कला-कौशल, जैसे सुन्दर ऊनी वस्त्रों के उत्पादन, अलग-अलग रंगों के समन्वय, धातु और जवाहरात के काम तथा इत्र आदि श्रद्धों के उत्पादन के लिए संसार-प्रसिद्ध रहे हैं। इस बात का प्रमाण मिलता है कि सन् ई० पू० ३०० में भारत और बेबीलोन में व्यापारिक सम्बन्ध थे। सन् ई० १-२००० तक की पुरानी मिख की क़त्तों में जो ‘ममीज़’ (शब) हैं, वे भारत की बहुत बढ़िया मलमल में लिपटे हुए पाए गए हैं। लोहे का उद्योग भी प्राचीन भारत में बहुत उन्नत अवस्था में था। उसके द्वारा बेबल देश की आवश्यकता ही पूरी नहीं होती थी, बल्कि उसमें उत्पन्न भाल विदेशों को भी भेजा जाता था। लगभग दो हजार वर्ष पुराना दिल्ली के पास जो मशहूर लोहे का स्तम्भ है, उससे मालूम पड़ता है कि उस समय की कारीगरी कितनी उच्च थी जिसे देखकर आज का इंजीनियर भी आश्चर्य में पड़ जाता है। भारत का इस्पात फार्स, अरब और इंग्लैंड तक को भेजा जाता था। सारांश यह है कि बहुत प्राचीन काल में ही भारत का लोहे और इस्पात का उद्योग अत्यन्त उन्नत अवस्था को प्राप्त कर चुका था। वास्तव में यह भारतीय उद्योगों का ही प्रताप था कि उस समय भारत से व्यापार करना बहुत लाभप्रद माना जाता था और यूरोपीय देशों में

भारतीय उद्योगों के जिस महत्त्व का ऊपर उल्लेख किया गया है वह बहुत समय तक क्रायम नहीं रह सका। यद्यपि आरम्भ में 'ईस्ट इंडिया कंपनी' ने भारतीय उद्योग-धर्मों का प्रोत्साहन दिया क्योंकि उसका निर्यात व्यापार इसी बात पर निर्भर था, पर योड़े समय के पश्चात् ही ब्रिटिश पूंजीपतियों के विरोध के कारण कंपनी को अपनी यह नीति छोड़नी पड़ी। ब्रिटिश पूंजीपति यह चाहते थे कि कंपनी ब्रिटिश कारखानों के लिए आवश्यक कच्चे माल को भारत से निर्यात करने पर जोर दे। अस्तु; बाद में भारतीय उद्योग-धर्मों का क्या भविष्य हुआ यह सर्वविदित है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब राजनैतिक सत्ता प्राप्त हुई तो उसका उपयोग भारतीय उद्योगों को नष्ट करने में किया गया। हमारे उद्योगों के ह्रास के अन्य कारण भी थे। सन् १८५८ में भारत का शासन जब सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया तब भी भारतीय उद्योगों के प्रति जो कंपनी की जान-भूझ कर उदासीनता दिखाने और उनको नष्ट करने की नीति थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही नीति चलती रही, यद्यपि अब उसने अहस्तक्षेप सिद्धान्त का आवरण पहन लिया। यह वह समय था जबकि इंग्लैंड में आर्थिक जीवन में राश्ट्र द्वारा कम से कम हस्तक्षेप करने का सिद्धान्त सर्वमान्य था। इंग्लैंड अपने आर्थिक विकास की जिस अवस्था में था उसमें अहस्तक्षेप का यह सिद्धान्त उसके लिए उपयुक्त था। ये वे दिन थे जबकि पूंजीवादी विस्तार के लिए इंग्लैंड के सामने पूरा मौका था, उसके तैयार माल के लिए समार के बाजार का द्वार खुला पड़ा था, और देश अथवा विदेश कहीं के बाजारों में उसका कोई प्रतिद्वन्दी नहीं था। इसलिए अहस्तक्षेप-सिद्धान्त से इंग्लैंड को लाभ ही-लाभ था। किन्तु भारत की स्थिति सर्वथा भिन्न थी। इस पर भी वही अहस्तक्षेप का सिद्धान्त उस पर भी लादा गया। यह राजनैतिक पराधीनता की कीमत था जो इस देश ने उस समय चुकाई और बाद में भी बहुत वर्षों तक बराबर चुकाता रहा। भारत जब तक इंग्लैंड के अधीन रहा आर्थिक मामलों में वह कभी भी अपनी स्वतंत्र नीति नहीं अपना सका। उसका भाग्य अपने विदेशी शासकों के साथ बंधा रहा और उनका एकमात्र लक्ष्य अपनी मातृभूमि इंग्लैंड के स्वार्थों की रक्षा करना रहा। परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन सरकार ने भारत के नष्ट होते हुए उद्योग-धर्मों की ओर तनक भी ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत सरकार ने इस विचार का लगातार प्रचार किया कि भारत की उपजाऊ भूमि और वहां की जलवायु ही ऐसी है कि वहां कच्चे माल का उत्पादन हो और उसके बदले में बाहर से तैयार माल मंगाया जाए। यह कहा जाता था कि भारतीय मजदूर बहुत ही अयोग्य हैं, वहां की गर्म जलवायु

मान्य की शिक्षित बनाता है, और लोगों में साहस की कमा दे, इसलिए इस दश में आधुनिक उद्योगों का विकास गढ़ा हो सकता। अनन्त यह विस्मय पैदा किया गया कि भारत औद्योगिकरण का दृष्टि से अनुपपन्न है। ब्रिटिश सरकार के हाथ में शासन आने के बहुत पहले ही हा, *स्ट्र इंडिया कंपनी भी इसी नीति पर चल रहा थी। उदाहरण के लिए काना न भारत में कपास की खेती के विस्तार और उन्नति में बड़ा दिलचस्पी ला। उन्नामरी शताब्दी के प्रारम्भ में कम्पनी ने भारतीय जाल उद्योग का पुनर्जाति कराने का निश्चय किया और पश्चिमी शीर मनुष्य से इन कार्य के लिए कुशल स्थितियों को लाया गया। चाय के बागों का उद्योग, जो भारत का इस प्रकार का प्रमुख उद्योग रहा, सरकार द्वारा ही प्रारम्भ किया गया था। कपड़ा के बाग भी कपड़ों के कहने से ही कायम किया गए। सांग्रस यह है कि आधुनिक उन्नति के प्रति सरकार की उदासीनता हानि से गया कुछ श्रम महापक्ष कारणों के उपस्थित होने रहने से, उन्नामरी शताब्दी के प्रारम्भ में ही भारत का आधुनिक महत्त्व समाप्त होने लगा और वह बचक एक कृषि प्रधान देश बना दिया गया। इस प्रकार भारत का आर्थिक पतन अपना उरम माना पर पूर्ववर्त हुआ था।

आधुनिक उद्योग का प्रारम्भ — अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक ब्रिटेन में आधुनिक फैक्टरी उद्योगों का पूरा गौर पर स्थापना हो चुका था। उन्नामरी शताब्दी के मध्य तक दार्जिलिंग स्थापना का कारणाना बन चुका था। इस समय तक प्राचीन भारतीय उद्योगों का भाग्य ही हुआ था और धार धारे एक दो आधुनिक उद्योगों का प्रारम्भ हो होने लगा था। जहाजों में भार का उपराग करने वाले उद्योग हा सबसे अधिक सकल नए भारतीय उद्योग मान्य पड़ते थे। भारत में एक कोयले की खान में, नौशाद्व (नॉर्स) में, एक कागज का मिल में, दूध की टरुमाल में, आटा पीसने में, रेशम की राल तैयार करने में और लोदी कपड़े के छापने और उनमें से तथा लुफा करने में भा भाग के रत्नों का प्रयोग होने लगा था। व तमाम आधुनिक उद्योग उलझने के प्रारम्भ में स्थित थे, क्योंकि यूरोपीय व्यवसायी इसी प्रदेश में सबसे अधिक थे। कन्दलाप नाम के 'स्ट्र इंडिया कंपनी' के एक कमवाले ने मद्रास में आरकट नाम के स्थान पर सबसे पहला लोह का कारखाना स्थापित किया। आधुनिक युग के ये उद्योग प्रतिक्रिया दिनों जाति नहीं रहे सके, क्योंकि इनको मराने, मशीनों के विभिन्न भाग और दूसरी आवश्यक सामग्री जहाजों में वेप के रास्ते से मंगाना पड़ती थीं। इ लौहियर, फोरमन और जमी कमा तो मजदूर तक दार्जिलिंग से बुलाने पड़ते थे। भारत में कोयला निकालने का उद्योग सन् १८१४ तक निरमित

रूप से आरंभ नहीं हुआ था। सन् १८५३ तक रेलवे नहीं खुली थी। इसी साल एक छोटी-सी लाइन बंबई से आरंभ की गई और दूसरे वर्ष सन् १८५४ में एक और लाइन हावड़ा से गनीमंज के कोयले की खानों तक शुरू हुई। इसके बाद रेलवे लाइनें जल्दी-जल्दी खोली जाने लगीं और इसके परिणामस्वरूप कोयले के उद्योग का प्रसार भी हुआ। सन् १८६० तक भारत में कोयले का कुल उत्पादन १० लाख टन से भी अधिक हो गया।

कोयले के उद्योग के विकास और रेलवे के विस्तार होने से भारतीय कैक्टरी-उद्योग के मार्ग को कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां समाप्त हुईं। कलकत्ते के पास जो 'बाओरेह मिल' १६ वीं शताब्दी के आरंभ में स्थापित हुई वह तो सफल नहीं हुई, पर सन् १८५१ में सी० एन० डावर नाम के एक पारसी सज्जन ने सबसे पहली सफल सूती कपड़े की मिल की स्थापना की। शुरू-शुरू में मिलों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ी। सन् १८६० में कपास के व्यापार में आरंभ होने वाली तेजी जब समाप्त होगई तो कपड़े के मिलों की संख्या काफी बढ़ पाई। पटसन कान्ने की सबसे पहली मिल एक अंग्रेज ने सन् १८५५ में सिरामपुर (कलकत्ता) के निकट रिशरा नामक स्थान में स्थापित की। इसके ठीक चार वर्ष बाद कलकत्ते के पास ही शक्ति से चलने वाली पहली जुनाई की कैक्टरी भी कायम हुई। इस प्रकार १६ वीं शताब्दी के मध्य तक विदेशियों के प्रयत्न से भारत में एक-दो आधुनिक उद्योगों का आरंभ हुआ किन्तु प्रगति बहुत धीमी और असंतोषजनक थी।

औद्योगिक अवनति की आंश देश का ध्यान:--१६ वीं शताब्दी की पिछली दो दशकियों में राजनैतिक चेतना के साथ-साथ देश के नेताओं और अर्थशास्त्रियों का ध्यान हमारी औद्योगिक अवनति की ओर भी गया। दादा भाई नारोमी और रानाड ने तो यहाँ तक कहा कि यह हमारी औद्योगिक अवनति का ही कारण है कि देश को प्रायः अकालों का सामना करना पड़ता है और आम जनता निर्धनता की चक्की में पिसी जा रही है। सन् १८८० के अकाल कमीशन ने भी यही राय दी कि भारत में बार-बार अकाल पड़ने का एक मुख्य कारण यह है कि उसका आर्थिक जीवन एक मात्र खेती पर आश्रित है। सन् १९०१ के अकाल कमीशन ने भी इसी विचार पर जोर दिया और देश के औद्योगीकरण पर आग्रह किया। भारतीय अर्थशास्त्रियों ने इस विचार की कि प्रकृति ने भारत को एक कृषि-प्रधान राष्ट्र ही बनाया है अस्तित्व प्रकट करना आरंभ की। थोड़े से समय में जापान में जिस तीव्र गति से औद्योगिक विकास हुआ उसने भी हमारे आर्थिक जीवन की कमजोरी को स्पष्ट कर दिया।

भारतीय अर्थशास्त्र का रूपरेखा

जनता के आर्थिक जीवन के लिए जा हित का प्यास रखने वाली सरकार क्या कर सकती है, इसका जागन ने एक अच्छा उदाहरण उपस्थित किया और भारत का सरकार ने भारतीय उद्योगों को प्रति जा अर्थव्यवस्था उदात्तीनता दिखाई यह जापान से मजबूत प्रतिकूल और दुःखद उदाहरण था। रानाडे ने भारतीय पूँजीपतियों से अनुरोध किया कि वे अपनी अवैधताओं को जा उद्योग में लगाएँ और शिक्षित नवयुवकों से कहा कि हाथों का काम के प्रति अस्वभाविक परम्परागत अवधि का त्याग कर और उद्योगधर्मों में काम करने योग्य अपने आप को बनाएँ।

देश में राजनैतिक असमन्वय के साथ साथ यह आर्थिक असमन्वय भी पर करता जा रहा था। आगे जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) के सहयोग में सन् १९०५ में भारतीय आचार्यिक सम्मेलन का स्थापना से विविध होता है, असमन्वय का इन दोनों धाराओं का धारणात्मक मजकूर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बंगाल के विभाजन की यह करारों के लिए जो देश स्थायी आंदोलन हुआ उसने भी इन आपसी संघर्षों को पुष्टि हा किया। १९०५ का स्वदेशी आंदोलन इसी का परिणाम था, और ब्रिटिश माल के बहिष्कार का आंदोलन भी इसी का नकारात्मक स्वरूप था। देश में एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई थी। भारतवासियों ने अनेकों नई वैयक्तिक स्थितियों में जिन में कपड़े, माका, दियामलाइ, पल्लि, काच और छुगाचाइ (कल्लरी) की वैयक्तिकीयें मुख्य थीं। कई स्वदेशी भंडार भी कायम हुए जहाँ इन वैयक्तिकीयों का माल बचा जाता था। पर इन तथे उद्योगों में मजदूरी का अधिक दिन नहीं चल सका। व्यावहारिक शिक्षा और व्यापारिक अनुभव का अभाव तथा राज्य की उदात्तीनता में लापरवाही इस असफलता के मुख्य कारण थे। बहुत समय तक राज्य ने निम्न अर्थव्यवस्था टक्कीकृत और औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करने, कुछ व्यापार और उद्योग सम्बन्धी जानकारी एकत्रित और प्रचारित करने, कुछ औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन करने और भारतीय उद्योगियों के विषय में कुछ साहित्य प्रकाशित करने के और कुछ नहीं किया। सन् १९०५ में लार्ड कर्जन के मुकाबल पर पन्ध्र में व्यापार उद्योग का एक प्रथम सरकारी विभाग कायम किया गया पर यह सब कुछ नहीं के बराबर था। यदि कभी शिक्षा प्राप्ति में जैसा महासभा अथवा मधुतपान्त के उदाहरण सामने आए भी औद्योगिक उन्नति के क्षेत्र में कोई विशेष क्रियात्मक रुचि दिग्गद, तो उन्ने सन्नायारियों ने उनके उत्साह को मजकूर दिया। माराय यह है कि देश में स्वदेशी आंदोलन के कारण औद्योगिक उन्नति के लिए जो अनकूल वातावरण बना गया था, सरकार

ने उसका कोई लाभ नहीं उठाया। यहां तक कि विभिन्न रेलवे कंपनियों के माल को लाने-लेजाने के जो अलग-अलग दर थे उनमें भी सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया; बल्कि ये दर उद्योग-धन्यों की प्रगति में बाधक थे। सरकार ने विदेशी माल की प्रतिद्वन्द्विता रोकने के लिए न तो रक्षात्मक कर लगाए और न और कुछ ही किया। इस सबसे भारतीय जनता का यह विश्वास और भी बढ़ होगया कि राज्य की क्रियात्मक सहायता और संरक्षण के बिना, खासतौर से प्रारंभिक अवस्था में, देश के उद्योग-धन्यों की उन्नति संभव नहीं है।

उपर्युक्त विवरण का चार यह है कि सन् १९१४ के पहले तक भारत औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। हमारी इस धीमी औद्योगिक प्रगति का एक कारण आरंभ में लोगों का अज्ञान और उनमें व्यावसायिक साहस का अभाव, तथा अब तक भी उनमें दूरदर्शिता और प्रतिभा की कमी बताया जाता है। इन बारे में यह अवश्य ध्यान रखने की बात है कि यदि किसी हद तक भारतवासियों में उक्त गुणों का अभाव रहा है या आज भी पाया जाता है तो उसका प्रमुख कारण देश की पराधीनता और उससे उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों को ही मानना होगा। देश की स्वतंत्रता के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी भारतीय प्रतिभा व्यक्त होगी, इस में कोई संदेह नहीं। प्रथम युद्ध से पहले तक भारत में मुख्यस्थित और बड़े पैमाने पर चलने वाले केवल निम्न-लिखित उद्योग थे:—बंबई का सूती कपड़े का उद्योग, बंगाल का पटसन का उद्योग, बिहार, उड़ीसा और बंगाल का कोयले का उद्योग, बर्मा में तेल का उद्योग और आसाम में चाय का उद्योग। सूती कपड़े के उद्योग को छोड़कर बाकी सब उद्योग विदेशियों के हाथ में थे। प्रथम महायुद्ध के पहले लोहे-इस्पात और सीमेण्ट के उद्योगों की शुरुआत हो चुकी थी। सन् १९०७ में जमशेदपुर में स्थापित 'टाटा आइरन एंड स्टील कंपनी' भारतीय औद्योगिक उन्नति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और बड़े पैमाने पर इस्पात उत्पन्न करने वाला देश का यह प्रथम कारखाना था। यह पूर्वतया भारतीय उद्योग था। इसी काल में एक और उद्योग की प्रगति के चिह्न दिखाई पड़ने लगे थे—यह था शक्ति और रोशनी के लिए बिजली पैदा करने का उद्योग। इस उद्योग की प्रगति टाटा के ही प्रयत्नों से बाद में हुई। उपर्युक्त उद्योगों के अनिश्चित छोटे-मोटे और उद्योगों का आरंभ भी देश में हुआ, जैसे पटसन और कपास के धेनु, कागज की मिलें, चायल और शकर के उद्योग, चमड़े के उद्योग, इंजीनियरिंग के कारखाने आदि। पर इन उद्योगों की संख्या कम थी और इनका कोई विशेष महत्व नहीं था।

प्रथम महायुद्ध-काल में औद्योगिक उन्नति—प्रथम महायुद्ध के समय भारतीय उद्योग धंधों की अपनी उन्नति करने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर मिला। शत्रु राष्ट्रों में और विशेषतया जर्मनी में माल का आना बिल्कुल बंद हो गया। मित्र राष्ट्रों में भारत को माल बनाने में अमूल्य था, क्योंकि एक तो वे युद्ध सामग्री उत्पन्न करने में लग हुए थे, और दूसरे शत्रु राष्ट्रों के आक्रमण तथा युद्ध के कारण बड़ी हुई मात्रा में पल्लव रूप में माल का लाने का जाना वाले जहाजों की भी कटिनाई थी। इसके अनिश्चित युद्ध के लिए आवश्यक चीजों की विशेष मात्रा में हम समय पैदा हो गए थे। साधारण यह है कि भारत के सामान अपना उत्पादन बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर आया। परंतु भारत इस अवसर का लाभ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। भारत में न मशीन उत्पादन करने वाले कोई उद्योग थे नहीं और विदेशों से मशीन अधिकांश माल मगाना पड़ता था। और भी कई प्रकार की कटिनाइयाँ हमारे मार्ग में थीं, जैसे टेक्निकल विशेषज्ञों की बड़ी कमी थी, तथा रेल के डिब्बों में मजदूरों जहाज, कोयला शुद्ध करने की मशीन (कोकिंग प्लांट) और इस्पात मजदूरों की भी कमी थी। सदा की भाँति सरकार का अक्षमता का कारण भी हो। इन सभी कारणों से युद्ध के समय भारत औद्योगिक उन्नति का विषय प्रगति नहीं कर सका और हमारे देश में उभरने वाला तथा अमेरिका आदि विदेशों लोगों ने भारत के साथ अपना औद्योगिक सम्बन्ध बना लिया, तथा हमारे बान्धवों पर अपना औद्योगिक कायम कर लिया।

इतना सब होने पर भी युद्ध ने सरकार और जनता को मान्यता अवश्य कर दिया। जनता ने पहली बार यह अनुभव किया कि जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के मामले में विदेशों पर निर्भर रहने का अर्थ क्या है। अग्रणी सरकार ने भी देखा कि यदि भारत एक औद्योगिक राष्ट्र होना तो पूर्वीय युद्ध-काल में उल्लेख अधिक सहायता मिल सकती थी। अतः, सरकार का भी देश का औद्योगिक उन्नति के लिए कुछ न कुछ करना अनिवार्य जान पड़ा। सन् १९१६ में सरकार ने औद्योगिक कमिशन की नियुक्ति की। कमिशन ने भारत की औद्योगिक उन्नति के व्यापक प्रश्न पर, और सरकार किस प्रकार इसमें सहायक हो सकती है इस विषय पर पूरी तौर से विचार किया। कमिशन की रिपोर्ट १९१८ में प्रकाशित हुई। उसमें कमिशन ने नव बात पर विशेषतया जोर दिया कि देश के औद्योगीकरण में सरकार को अधिक श्रियामय सहयोग देना चाहिए ताकि देश अनेक स्वावलंबी बन सके। कमिशन ने यह भी राय दी कि इन प्रश्नों पर सरकार का ध्यान देने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति होना चाहिए।

कमीशन का यह भी सुझाव था कि प्रान्तीय मंडलों (बोर्डों) की स्थापना की जावे । इसी बीच में १९१७ में सरकार इण्डियन म्यूनिशन्स बोर्ड की स्थापना कर चुकी थी । उसका उद्देश्य युद्ध की दृष्टि से भारतीय साधनों का पूरा-पूरा उपयोग करना था । इस बोर्ड ने स्वयं भारत में आवश्यक माल खरीद कर, इंग्लैंड तथा दूसरी जगहों से खरीदा जाने वाला माल भी प्राथमिकता और निर्वन्धन के आधार पर भारत से खरीदवा कर, और नए उद्योग आरंभ करने वालों को आवश्यक सलाह और जानकारी देकर, भारतीय उद्योग-धन्वों की उन्नति में सहायता पहुँचाई । इस प्रकार कई उद्योगों को यथेष्ट प्रोत्साहन मिला । उनमें से खास-खास नाम ये हैं:— सूती कपड़े, पटसन, लोहे-इस्पात, चमड़े, और इन्जीनीयरिंग के उद्योग, तथा कागज, काच, सीमेंट, छुरी-चाकू, खाद, रंग, वार्निश, डाक्टरों औजार, रासायनिक पदार्थ (केमिकल्स) और मिनरल एसिड्स तैयार करने वाले उद्योग । औद्योगिक कमीशन की सिफारिश के अनुसार केन्द्र तथा प्रान्तों में सरकारी औद्योगिक विभागों की स्थापना भी हुई । युद्ध कालीन सरकारी व्यय की पुर्ति करने के लिए आयात-करों में भी वृद्धि की गई । पर इन छोटी-मोटी बातों से कोई बड़ा परिणाम आने वाला नहीं था, और युद्ध के कारण जो अचसर आया था भारत उसका लाभ न उठा सका तथा औद्योगिक दृष्टि से वह एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र ही बना रहा ।

युद्धोत्तर तेजी और मंदी:—युद्ध के समाप्त होते ही थोड़े समय के लिए व्यापार-व्यवसाय में तेजी आई । इस आशा से कि युद्ध कालीन मुनाफे कायम रहेंगे और युद्ध के समय जो मांग बढ़ी उसे पूरी करने का अब समय आया है, कई नए-नए उद्योग-धन्वे आरंभ किए गए । सन् १९१६ से १९२१ तक यह प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखाई पड़ी । परन्तु थोड़े समय के पश्चात् ही व्यापारिक मंदी के लक्षण दिखाई पड़ने लगे । मंदी के इस युग का आरंभ होते ही बहुत सी कम्पनियाँ और फर्म अपना काम बन्द करती दिखाई पड़ने लगी । इस मंदी के कई कारण थे । ऊँची कीमतों और बढ़ती हुई मांग संबंधी आशाएँ पूरी नहीं हुईं । कारण यह था कि लड़ाई से जो विनाश हुआ था उसके फल स्वरूप संसार के राष्ट्रों का कमर टूट गई थी, उनमें माल खरीदने की शक्ति बची ही नहीं थी । इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों ने अपनी-अपनी मुद्राओं को युद्ध के पूर्व की स्थिति में पहुँचाने की दृष्टि से जो मुद्रा संकुचन नीति अपनाई, उसका भी जनता की कय शक्ति को कम करने का प्रभाव हुआ । साथ ही साथ १९२०-२१ में भारत के रुपये का विनिमय-दर बहुत गिर गया जिससे उन आयात के व्यापारियों के सामने, जिन्होंने ऊँचे विनिमय-दर की आशा लगा रखी थी, एक संकट उपस्थित

तब तक निर्यात व व्यापारियों का सम्बन्ध था पहले के ऊँचे विनिमय दर का दुरा प्रभाव उनको भा अब मालूम पड़ा। बाद में सन् १९२४ में जब दर का विनिमय दर फिर बढ़ गया तो उसका असर भी मदी को बढ़ा के हा हुआ, क्योंकि दर व विनिमय दर व बढ़ जाने से भारत के वात्रारों में विदेशी माल की प्रतिद्वन्द्विता बढ़ गई। जब सन १९२६ में विश्व-व्यापी आर्थिक मदी की शुरुआत हुई तो भारतीय आर्थिक जीवन पर भारत के कृषि प्रधान देश होने के कारण अप्रत्याशित अधिक दुरा असर पड़ा। कृषि-उद्योगों का कामें निर जाने का प्रभाव भारतीय उद्योगों पर सा अस्वाभाविक नहीं हुआ। विदेशी राष्टों की अपनी अपनी मुद्राओं व मूल्य घटाने का और दूसरे दरों में बढ़िम सस्ते मालों पर माल बेचने की नीति व कारण भी भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतिद्वन्द्विता और बटिन समर्थ का सामना करना पड़ा। अस्तु, तुल्य मिनाकर यह कहना गलत न होगा कि प्रथम महायुद्ध के पश्चात् भारतीय उद्योग के क्षेत्र में जो मदी आरम्भ १९१४-१५ १९२६ के समारंभगी मदी तक बराबर चलती रही। इसका यह अर्थ लगाना ना ठीक नही होगा कि इस मारे माल में आर्थिक जीवन व विभिन्न अंगों की स्थिति में मध्यम समानता था। विभिन्न उद्योगों की विभिन्न समय विभिन्न परिस्थितियाँ रही हैं। पर सामान्यतया यह कहना ठीक है कि युद्ध व बाद से भारतीय उद्योग की स्थिति बिगड़ी हा रही और इसी बीच में १९२२ की मदी का आरम्भ हो गया।

इस प्रथम महायुद्ध के बाद व समय में हमारे देश के औद्योगिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना भारत का तत्कालीन सरकार द्वारा, अक्टूबर १९२१ में स्थापित अर्थ आयोग (विमल कमिशन) की गिफारिश पर, मकुचिन औद्योगिक मन्त्रालय (इंस्टीट्यूट ऑफ़ प्रोडक्शन) की नीति का अपनाता था। युद्ध के पूरा की सरकार का अस्तित्व का नीति में इस प्रकार का परिवर्तन देश की औद्योगिक प्रगति की दृष्टि में वहाँ तक पर्याप्त हा यह एक अलग प्रश्न है, जिस पर आगे चल कर विचार किया जाएगा। यहाँ से इतना सा स्पष्ट कर देना अपेष्ट होगा कि सरकार की इस नीति व फलस्वरूप कुछ उद्योगों को सरकार मिला और उससे उनकी सुदोस्तर मदी का सामना करने में सहायता मिली। इस प्रकार के उद्योगों में लोहे और इस्पात का उद्योग, सूत कपड़े का उद्योग, शर्करा का उद्योग, कागज का उद्योग और दियामलाई का उद्योग विगत रूप से उल्लेखनीय हैं।

मन्त्री के उद्घाटन स्थिति में सुधार तथा विगाड़—१९२६ में आरंभ होने वाला आर्थिक मदी ने समस्त समार और उसके साथ साथ भारत

उद्योग-धन्ये : साधारण विवेचन

आर्थिक जीवन को पूरी तौर से अस्तव्यस्त कर दिया। सन् १९३२ में और उसके बाद इस मंदी के समाप्त होने के चिह्न दिखाई पड़ने लगे। भारत इस दृष्टि से कोई अपवाद नहीं था। लोहे और इस्पात, मृती कपड़े, सीमेंट, शकर, पटसन और कागज के उद्योग-धंधों का उत्पादन बहुत कुछ बढ़ा। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, इस प्रगति में संरक्षण का बड़ा हाथ था। सन् १९३१ से भारत का बहुत-सा छोटा विदेशों को जाने लगा और उसके बदले में जो स्वधा प्राप्त हुआ वह उद्योग-धंधों में लगाया जाने लगा। इसके अलावा देश में स्वदेशी की जो भावना जामत हो चुकी थी उससे भी इनारी औद्योगिक उन्नति को बहुत सहायता मिली। कृषि-पदार्थों के मूल्य बढ़ने से देश की ग्रामीण जनता की क्रय-शक्ति में वृद्धि हुई और इस कारण से उनमें औद्योगिक पदार्थों की मांग भी बढ़ी। इन सब बातों का अंतर औद्योगिक दृष्टि से अच्छा हुआ और देश के स्थल बाजार (स्टोक एक्सचेंजों) के लेन-देन में इस औद्योगिक उन्नति के चिह्न स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे। इतना ही नहीं, सारी स्थिति अति की ओर जाने-लगी और अत्यधिक आशावाद के कारण सट्टे तथा बिना सोचे-समझे व्यापार करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलने लगा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होने वाला था कि देश के आर्थिक जीवन को फिर चक्का लगे। सन् १९३७-३८ में जब सारे संसार को इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा तो भारत भी उससे न बच सका। जब सन् १९३९ में दूसरा विश्व-युद्ध आरंभ हुआ तो स्थिति ने पलटा खाया। भारत इस स्थिति का वास्तव में कितना लाभ उठा सका इस विषय में अब विचार किया जाएगा।

दूसरा महायुद्ध और हमारी औद्योगिक उन्नति—जैसा कि स्वाभाविक था, दूसरे महायुद्ध के कारण भारतीय उद्योग-धन्यों के विकसित होने का एक अच्छा अवसर फिर इस देश को प्राप्त हुआ। इस बार की स्थिति प्रथम महायुद्ध की अपेक्षा भी कुछ अंशों में अधिक अच्छी थी। जापान के युद्ध में शामिल होने से और बर्मा तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया तक उसके बढ़ जाने से पूर्वी युद्ध-क्षेत्र को अपने आप में स्वावलंबी होना आवश्यक था, और पूर्वी युद्ध-क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण स्थान था। इस सबका परिणाम यह होना चाहिये था कि भारत के उद्योग-धंधों में जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक प्रगति की जाती; पर वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। भारत की विदेशी सरकार का अब भी वही पुराना संकुचन दृष्टिकोण था। भारत में १९४० में 'इंस्ट्रुमेंट्स कांफेंस' का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया था कि पूर्व के देशों को बधा-संभव युद्ध-सागरी के मामले में स्वावलंबी बनाया जा सके। इसी प्रकार डा० जेडी के नेतृत्व में अमरीकन

टेकनिकल मिशन मात्र १९४० में भारत में आया और गया भारत में नए नए धर्मों की स्थापना के बारे में एक विस्तृत मिशन पत्र था। पर बावजूद इन सबके युद्ध के प्रारंभ में भारत सरकार ने मिशन को आग्रह मित्र प्रगति के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। भारत सरकार का इस तथे के कह प्रमाण दिए जा सकता है। भारत सरकार का उस में यह करने में ही तत्काल था कि भारत में कबल उन चीजों का उपयोग बढ़ाया जाय या ना। निश्चय रूप से जाना है और जो दूसरे देशों में प्रयत्न नहीं की जा सकता है। उन उल्लंघनों का स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया जो भारी आधुनिक उद्योगों की दृष्टि से महत्व के थे। बाद में तत्काल भाड़ा मुक्ताने का है। भारत में (तत्कालीन) के प्रिन्सिपल पार्लियामेंट में नवम्बर १९४० में एक गैर निर्यात निम्न शुल्क इस दृष्टि से उल्लंघनीय है। भारत के लिए आर्थिक वस्तुओं के निर्यात ६०८, भाग के लिए भारत स्थापित की जायगा। इसी तथे का यह परिणाम था कि युद्ध के प्रथम दो वर्षों में भारत सरकार मिशन का उपयोग नैपार मान और कया मान भजता रही। इसके लिए भारत द्वारा उनकी लाहौर और इनके बाहर जहाँ भी आवश्यकता होगी थी भय जान में और उनके भारत में उपयोग का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता था। इसके मुकाबले में आधुनिक और कनाडा ने जो युद्ध के शुरू होने के दो वर्षों के अन्तर्गत प्रगति करली थी वह उल्लंघनीय था। आधुनिक ने जो वष के अन्तर्गत जहाज वायुसेना आदि वस्तुओं का निर्यात प्रयत्न से उत्पादन आरम्भ कर दिया था। कनाडा को सरकार ने भी मान सरकारों, गारपोरेशन स्थापित किए इनमें से चार हजार जहाज साल राक्षस और औजार बनाने के लिए थे। तत्कालीन आवश्यक युद्ध सामग्री और मशीन इन्स परीदने के लिए थे। तत्कालीन भारत सरकार ने इस अनुसार तथे का एक और उदाहरण यह था कि उसने आन्ध्रप्रदेश और गोवर्धन (लाहौर में एक विभागत कम्पनी का मिन्कारिष भीगू भी और यात्राओं की स्वरूपा भी तैयार हायर थी पर आग्रह वत इस आवाज पर कि बाहर से ही पंजिन प्रदाना पादा अच्छा है वह योजना रह करती गई। मोटर आदि के उद्योग के बारे में १९३६ में ही भारत सरकार के सामने यात्रा उपस्थित करवाया था पर भारत सरकार ने पांच वर्ष के परवान् निसम्बर १९४० में जब यह योजना के मचानकों-न वत कुञ्ज तैयारी भी करली था उस प्रस्ताव को नामूर कर दिया। कारण यह था कि युद्ध के कारण कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी हैं। यह निष्पत्ति भारत सरकार ने उस समय किया जब कि वह विन्शा से बड़ी सन्धा में

मोटरें आदि मंगा रही थीं। सारांश यह है कि युद्ध के आरंभ में भारत की विदेशी सरकार की नीति देश में बड़े-बड़े उद्योगों को, जो भारतीयों द्वारा संचालित और व्यवस्थित हों, प्रोत्साहित और विकसित करने की नहीं थी। १९४१ के अन्त तक रासायनिक और धातु संबंधी तथा दूसरे भारी उद्योगों का बहुत ही छोटे पैमाने पर आरंभ मात्र हो सका था। औद्योगिक विकास में उपयुक्त मशीनों और टेक्निकल लोगों की कमी के कारण धरावर कठिनाई होती रही और उनको हल करने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। यातायात को कठिनाई भी रही।

द्वितीय महायुद्ध के समय भारत के औद्योगिक विकास के मार्ग में जो कुछ प्रमुख कठनाइयाँ उपस्थित हुईं उनका हमने ऊपर उल्लेख किया है। इस कारण से जितनी औद्योगिक उन्नति इस देश में हो सकती थी उतनी अवश्य नहीं हो सकी। पर फिर भी किसी दृष्टि तक युद्ध ने औद्योगिक उन्नति में सहायता पहुँचाई, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कई उद्योग-धन्वों में—जो पहले से ही मौजूद थे—अधिक से अधिक संभव उत्पादन होने लगा और प्रायः एक से अधिक पाली में काम होने लगा। जिन पुराने उद्योगों को प्रोत्साहन मिला उनमें से खास-खास के नाम ये हैं—बस्त्र-उद्योग, लूटठ-द्योग, कागज का उद्योग, चाय का उद्योग, शकर का उद्योग, लोहे और इस्पात का उद्योग, कोयले का उद्योग, सीमेंट का उद्योग। इनमें से कुछ उद्योगों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही जितनी दूसरे उद्योगों की। उदाहरण के लिए कोयले तथा शकर के उद्योगों को कई कठिनाइयों रहीं। कई उद्योगों में नई मशीनें लगाई गईं और कुछ आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई। छोटे पैमाने पर चलने वाले उद्योगों का भी काफी प्रसार हुआ और अनेकों प्रकार का सामान तैयार होने लगा। कई नए उद्योगों का भी, या ऐसे उद्योगों का जो सर्वथा प्रारंभिक अवस्था में थे, युद्ध-काल में विकास हुआ। जैसे—हवाई जहाज तैयार करने वाली हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी की १९४० में स्थापना हुई। इसी प्रकार एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत भी इसी समय हुई। म्यूनिशन्स (युद्ध-ग्रामजी) और शस्त्रों के उद्योग की युद्ध के समय काफी प्रोत्साहन मिलना विल्कुल स्वाभाविक था। रॉजर मिशन ने, जो १९४० में भारत में आया, युद्ध-ग्रामजी संबंधी उद्योग-धन्वों के विकास की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप कई करोड़ रुपये खर्च करके मौजूदा कारखानों का विस्तार किया गया और कई नए कारखाने बन्दूकों, गोलों, कारखानों, घम गोलों और अन्य चीजों का उत्पादन करने के लिये स्थापित किये गए। रासायनिक पदार्थ, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, बेलोराईन, बोरिक एसिड और

अल्पमात्रा पर्याप्त पैसा माँगा जाता है व सार्वजनिक की भी कुछ व समय में इजाजत मिलती है। कई प्रकार की दवाइयाँ व साधन भी यही कहा जा सकता है। कुछ है पहले भारत में बहुत पैसा था पर व्यवस्थित रूप से मर्यादित या मर्यादित और दूसरे का उत्पादन नहीं होता था, यद्यपि कहीं-कहीं मर्यादित के भाग अथवा इन्फ्लेशन की वृद्धि और सरकार का उत्पादन का उत्पादन अवश्य होता था। कुछ कारखानों में आने ही काम के लिए मर्यादित और दूसरे भाग तैयार होने से और बाजार में बिजली के लिए माद सराफ सध नया प्रिन्सिपल, शक्ति और प्रमाणिकता भी तैयार होती थी। कुछ व कारण मर्यादित और दूसरे व कारखानों की प्रमाणिकता मिलान पर पैसा मर्यादित का उत्पादन कि भाग अथवा नहीं हुआ। बाइकिटिव व उत्पादन भाग हम देश के लिए गए व और उनका भाग हमी कुछ हाल में अथवा हुआ। लोह के रॉड, वायर और वायरलेस का उत्पादन भाग बढ़ा और इस प्रकार का उत्पादन करने वाले नए कारखाने भाग गले। कई प्रकार की नई चीजें भी इन कारखानों में पैदा की जाने लगी।

उपरोक्त विवरण से यह अवश्य स्पष्ट होता है कि सरकार की प्रीमिरी नीति नया दूसरा कठिनाइयों के हल रूप में महायुद्ध के कारण भारतीय उत्पादन का विस्तार हुआ। निम्नलिखित तालिका में हम विस्तार का सामान्य अनुमान लगाया जा सकेगा।

औद्योगिक उत्पादन

१९३०=१००

वर्ष	सामूहिक सूचीकृत पूरा	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन
	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन
१९३०	१०५.८	१०६.०	१०६.१	१०६.०	१०६.०	१०६.०	१०६.०	१०६.०	१०६.०
१९३१	१०२.७	१०६.१	१०६.१	१०६.०	१०६.०	१०६.०	१०६.०	१०६.०	१०६.०
१९३२	१०६.६	१०६.६	१०६.६	१०६.६	१०६.६	१०६.६	१०६.६	१०६.६	१०६.६
१९३३	११७.८	११७.८	११७.८	११७.८	११७.८	११७.८	११७.८	११७.८	११७.८
१९३४	१११.२	१०२.०	१०२.०	१०२.०	१०२.०	१०२.०	१०२.०	१०२.०	१०२.०
१९३५	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०
१९३६	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०
१९३७	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०
१९३८	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०
१९३९	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०	११७.०

भारत सरकार के आर्थिक सहायकार का कार्यालय

उपरोक्त वर्षों के विकास सम्बंधी उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता

कि द्वितीय महायुद्ध का औद्योगिक उन्नति की दृष्टि से बहुत लाभ सका। और इस असंनोपजनक स्थिति का मूल कारण एक ही था हमारी पराधीनता।

दूसरे महायुद्ध के उपरान्त हमारी औद्योगिक उन्नति—गत महायुद्ध ने किस हद तक देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता दी, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। युद्ध के पश्चात् देश की आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाय और प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास की योजनाएँ लागू की जाएँ, इस बात की आवश्यकता अनुभव होने लगी थी। युद्धांतर पुनर्निर्माण की केन्द्रीय और तत्कालीन प्रान्तीय सरकारों ने योजनाएँ तैयार की। औद्योगिक उन्नति से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ औरसरकारी योजनाएँ भी प्रकाशित हुईं—जैसे बिकला-योजना जिसे बोम्बे योजना भी कहा जाता है, गांधीवादी योजना, जनता-योजना आदि। यह सब होते हुए भी अभी तक आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से हमारा देश किसी निश्चित मार्ग पर चल पड़ा हो यह नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक औद्योगिक उन्नति का सम्बन्ध है वह भी गत महायुद्ध के बाद एक प्रकार से अशुद्ध हो रही है।

भारत के विभाजन का प्रभाव—गत महायुद्ध के पश्चात् इस देश के जीवन में दो ऐसी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी हैं जिनका असर हमारे आर्थिक और औद्योगिक जीवन पर बहुत गहरा पड़ा है और आगे पड़ेगा भी। एक घटना है देश के स्वतन्त्र होने की और दूसरी घटना है देश के विभाजन की। जहाँ देश की स्वतन्त्रता के कारण हमारे भाग्य के हम स्वयं निर्माण बन गए हैं और अपनी इच्छानुसार राष्ट्र की प्रगति कर सकते हैं, वहाँ देश के विभाजन के कारण हमारे राष्ट्रीय जीवन की बड़ी हानि हुई है और उसकी प्रकृति-दत्त संपूर्णता को भारी धक्का लगा है। देश के विभाजन से भारत के आर्थिक जीवन पर क्या क्या असर पड़ा है इसके बारे में हम विस्तार से तो अलग लिखेंगे; यहाँ तो केवल कुछ मोटी-मोटी बातों का संकेत मात्र करेंगे। विभाजन के कारण लाखों आदमी एक देश से दूसरे देश को अत्यन्त अशांति और विचलता की हालत में आये। इसका असर दोनों ही देशों की जनसंख्या के पेशेवार बटवारे पर पड़ा और लाखों मनुष्यों को आर्थिक वर्चस्वी का सामना करना पड़ा। स्पष्ट है, इसका असर आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से बहुत बुरा पड़ा। देश के बटवारे का दूसरा बुरा असर यह पड़ा कि कपास तथा जूट जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिये भारत पाकिस्तान पर बहुत कुछ निर्भर हो गया। जूट की सब मिलें हिन्दुस्तान में आगे पर जूट पैदा करने वाली अविभाजित भारत की केवल एक चौथाई भूमि हिन्दु-

को मिला। इसी प्रकार अधिप्राजित भारत की ६६% शुची वस्त्र को मिये मो हिंदुस्तान में है पर १० लाख बल लम्ब नया बाय व रेडा के कगम व निर भारत पाकिस्तान पर निर्भर है। परिचया पंजाब और गिर व पाकिस्तान में होने से मिन्दाई का कड बढा बढा नहरे भारत म आज उही रहा और मिथ और पश्चिमी पंजाब नेम् लायात्र उ उत्र करनवाय प्रदशों र भारत मे अन्नग होजाओ का अत्तर हमारी ग्यायस्थिति पर बुरा पडा। न्तिज पदायों व उत्पादन का जहाँ तक सम्भव है ६७%, भारत और परल , पाकिस्तान म होजा है। पाकि स्तान में कोपले और लाई का बडा अभाव है। सामान यह है कि देश व बैटवार मे भारत व औद्योगिक विद्याम व मिण कं प्ररा उपस्थित हो गए है यद्यपि कुल उपयोग परा ५ ६०%, कारव्या भारत म और जवन ६७% पाकिस्तान मे है।

दश व इस बैटवार की पृष्ठभूमि में यदि हम युद्धांतर भारत की औद्योगिक प्रगति का विचार करें तो हम दवेंगे कि युद्ध व समय जो उल्लेख वर्षों को प्राप्तारन मिला यह बाद म स्थाया नहो रह गया। बई एमे कारण रकवे होगए जैव सामायाय का कठिना, उत्पाग पनिया और मजदूरों के आपत्ता सम्बन्धों म बिचार और निगाह, कच्चे माल की कमी और उतर प्रम करन और बाँटा व नरकों म पाए जाने वाल दा र मशीन आदि पूँजी वस्तुओं को प्राप्त करन और हमारन व सामान भिन्न की कठिना, तथा तकनिकल लोगों की कमी, जिनका परिणाम यह हुआ कि देश में धीरे धीरे एक औद्योगिक सफट पैदा होने लगा। इसी बीच म १५ अगस्त १९४७ का हम स्वतन्त्र हुए, और राष्ट्राय सरकार का निर्माण हुआ। उम समय दश हा औद्योगिक स्थिति 'अच्छी' नहो था और डिसेम्बर १९४७ म वा उपयोग परा का सम्मेलन हुआ उसने यह अनुभव किया कि दश म चारों ओर उत्पादन किया म शिथिलता औरहा है। इस सम्मेलन ने इस प्रश्न पर विचार किया और राष्ट्रीय सरकार के सामने कुछ सुझान भी प्रस्तुत किये। राष्ट्र के नेताओं और भनिया ने जो वक्तव्य समय समय पर दिये और राष्ट्रायकरण का जो वातावरण पैदा किया जाने लगा उमस भी देश ने आर्थिक जीवन में एक प्रकार की अस्थिरता आ गयी। विनियोग बाजार में मदी का साम्राय वा और आर्थिक तरा औद्योगिक प्रगति का माग रुक सा गया था। उद्योग वर्षों सम्बन्धों सम्मेलन मे देखिए यह निष्कारिष की कि सरकार को अपना औद्योगिक नीति का स्पष्ट धारणा करनी चाहिये और राजस्व तथा व्यक्तिगत उत्पादन व ननों को सुनिश्चित

कर देना चाहिये। इसी उद्देश्य को लेकर ६ अप्रैल, १९४८ को भारत-सरकार ने अपना औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रकाशित किया।

भारत सरकार की औद्योगिक नीति:—देश की भावी औद्योगिक उन्नति की दृष्टि से इस प्रस्ताव के महत्त्व को देखते हुए इसके सम्बन्ध में थोड़ा विस्तार से लिखना आवश्यक है। इस प्रस्ताव में सरकार ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के आदर्श की स्वीकार किया है जिसमें सब व्यक्तियों को समान रूप से न्याय और विकास का अवसर मिल सके। पर तत्काल उनका उद्देश्य लोगों के रहन-सहन के दर्जे को ऊँचा उठाना और इस दृष्टि से देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग करना, उत्पादन बढ़ाना और सब को राष्ट्र की सेवा में काम देना है। सरकार ने इसके लिए आर्थिक योजना के महत्त्व को स्वीकार किया और एक प्लानिंग कमीशन नियुक्त करने के अपने विचार का प्रकाशन किया। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की मौजूदा अवस्था में उत्पादन बढ़ाने का और खास तौर से उद्योग वस्तुओं और निर्यात की वस्तुओं की उत्पादन-वृद्धि का बड़ा महत्त्व है। साथ ही साथ न्यायपूर्ण वटवारे की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया। सरकार ने वह भी माना कि भविष्य में औद्योगिक उन्नति के सम्बन्ध में उसको अधिकाधिक क्रियात्मक भाग लेना पड़ेगा; पर राज्य के पास जो धन और जन सम्बन्धी साधन हैं उनका इस मामले पर बराबर ध्यान रखना होगा। जहाँ तक राज्यकीय और व्यक्तिगत उत्पादन दोनों के वटवारे का प्रश्न है, उद्योग-धंधों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है। पहली श्रेणी में वे उद्योग आते हैं जो केवल राज्य द्वारा ही संचालित किये जाएँगे—जैसे शस्त्र और सैनिक सामग्री [एम्प्लिशन] संबंधी उद्योग, एटोमिक शक्ति का उत्पादन और नियंत्रण, तथा रेलवे-मातायात। संकट-काल में राज्य को हमेशा बड़ा अधिकार होगा कि राष्ट्रीय रक्षा के लिए महत्वपूर्ण किसी भी उद्योग को वह अपने अधिकार में करले। दूसरी श्रेणी में उन उद्योगों की गिनती होती है जो जहाँ तक उनके क्षेत्र में गए कारखाने खोलने का प्रश्न है राज्य के लिए ही सुरक्षित हैं, यद्यपि राज्य को, यदि राष्ट्र के हित में आवश्यक मालूम पड़े तो, आवश्यक नियंत्रण के साथ व्यक्तिगत उत्पादन का सहयोग लेने का भी अधिकार होगा। कोयला, लोहा, इस्पात, हवाई जहाज-निर्माण, जहाज-निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ और वायरलेस एपरेटम का उत्पादन [रेडियो रिसेविंग सेट के अलावा], और जमीन में से निकलने वाले तेल सम्बन्धी उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। इन उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाले जो मौजूदा कारखाने आदि हैं उनका दस वर्ष तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा

और उनको भले प्रकार चलने और उचित विस्तार के लिए सब प्रकार की सुविधाएँ दी जायेंगी। दस वर्ष के बाद इस बारे में विचार किया जाएगा और यदि सरकार किसी कारखाने का राष्ट्रीयकरण करेगी तो उचित मुआवजा दिया जाएगा। राज्यकीय उद्योगों के प्रबंध के लिए राज्य के कानूनी नियंत्रण में पब्लिक कारपोरेशन स्थापित किये जाएंगे जिन पर सरकार का आवश्यक नियंत्रण होगा। बिजली की शक्ति का उत्पादन और वितरण इस सम्बन्ध में बने कानून के अनुसार होगा। इस कानून के अन्तर्गत मन्दूल इलेक्ट्रिसिटी को मोशन पावर दिया जा चुका है। तीसरी श्रेणी में भारी व गुरु उद्योग शामिल हैं और ध्वनिगत उत्पादन के लिए ठाम पुरो स्वतंत्रता है, पर राज्य भी इस क्षेत्र में अद्विधाधिक भाग लेगा और यदि उद्योग धर्मों की मावी उन्नति के लिए आवश्यक मालूम पड़ेगा तो राज्य को हस्तक्षेप करने में भी मनाब नही होगा। इस सम्बन्ध में दामादर पाटी-योजना, हीराकुड बाँध आदि का उल्लेख किया गया था।

उपयुक्त तीनों श्रेणियों के अलावा कई ऐसे आधारभूत धर्म हैं जिनका आयोजन और नियंत्रण राष्ट्रीय हित में कन्द्रीय सरकार द्वारा होना आवश्यक समझा गया। इन धर्मों में पूँजा बहुत चाहिये, ऊँचे दम का टेक्निकल कौशल चाहिये और उनकी स्थिति का देशव्यापी महत्त्व के आर्थिक कार्यों को ध्यान में रखकर निश्चय करना चाहिये। जमक, मोटर ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक एंजीनियरिंग, मशीन टूल, भारी रासायनिक पदार्थ, रास, ऊना-मृत्ती वस्त्र उद्योग, चाँदी, शकर, कागज, खनिज पदार्थ, रक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले उद्योग, हवाई और समुद्री वातायान, अणु-धनु आदि उद्योगों का समावेश इस श्रेणी में होता है। इन उद्योगों के सम्बन्ध में भारत सरकार राज्य का सरकारों, तथा उद्योग-पतियों और मजदूरों के प्रतिनिधियों से भा सलाह करेगी यह भी शष्ट किया गया था। औद्योगिक नीति सम्बन्धी इस प्रस्ताव में यह और छोटे पैमाने के उद्योग धर्मों के महत्त्व को स्वीकार किया गया और केन्द्र में यह उद्योग मंडल स्थापित करने का विचार किया गया। देश भर में सहकारी आधार पर छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने पर जोर दिया गया। मजदूर और मालिक के सम्बन्ध को ठीक करने पर भी जोर दिया गया और इस दृष्टि से मजदूरों को उचित माला गया। एक कन्द्रीय सलाहकार समिति स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया और उसी प्रकार राज्यों में समितियों बनाने की बात सोची गई। कन्द्रीय और राज्य को सलाहकार समितियों के नीचे देश भर या राज्य भर के लिए

खास-खास उद्योगों के लिए कमेटी बनाने का निश्चय हुआ। प्रान्तीय समितियों के नीचे हर बड़े कारखाने के साथ एक मजदूर-समिति और एक उत्पादन-समिति कायम करने का प्रस्ताव किया गया। केन्द्रीय और राज्य की समितियों में सरकारी, उद्योग और मजदूर तीनों के प्रतिनिधि और बाकी की दो समितियों में [मजदूर-समिति और उत्पादन समिति] मिल मालिकों और मजदूरों के बराबर प्रतिनिधि रहेंगे, ऐसा निश्चय किया गया। मिल मालिकों और मजदूरों के सम्बन्ध इस तरह से अच्छे रह सकेंगे, यह आशा की गई। स्थायी इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाने की कार्यवाही भी की गई। औद्योगिक मकान-व्यवस्था में सुधार करने पर भी जोर दिया गया। विदेशी पूँजी की देश को आवश्यकता है, यह स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध में एक कानून बनाने का प्रस्ताव किया गया जिसमें इस बात का अवश्य समावेश हो कि विदेशी पूँजी लगे उद्योगों का वास्तविक नियंत्रण और स्वामित्व भारतीय हाथों में रहे। अन्तिम बात इस प्रस्ताव में डेरिफ' नीति के बारे में कही गई कि अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा से भारतीय उद्योगों को संरक्षण दिया जाएगा और उपभोक्ताओं पर बिना अनुचित भार डाले भारत के साधनों का उपयोग किया जाएगा।

औद्योगिक नीति सम्बन्धी इस प्रस्ताव को ध्यान से देखने पर मालूम होगा कि सरकार के सामने एक ओर तो यह उद्देश्य है कि देश का उत्पादन बढ़े और दूसरी ओर पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करके एक मिली-जुली अर्थव्यवस्था कायम करने की इच्छा है। मिली-जुली अर्थव्यवस्था का विचार तो कोई नया नहीं है, बल्कि जो व्यवस्था आज चल रही है वह भा मिली जुली व्यवस्था ही है। पर इस प्रस्ताव की विशेषता इस बात में है कि यह पहले से ही निश्चित कर दिया गया है कि अमुक-अमुक धंधे तो राज्य द्वारा ही संचालित होंगे। इस बटवारे के पीछे सरकार का दृष्टिकोण तो यह था कि व्यक्तिगत उत्पादन के लिए एक प्रकार की जो अनिश्चितता अब तक रही है वह दूर हो जाय। पर वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। यद्यपि कुछ उद्योगों के बारे में यह स्पष्ट हो गया कि उनका संचालन सरकार द्वारा ही होगा, पर दूसरे उद्योगों के बारे में यह स्पष्ट नहीं कहा गया कि उनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। पूँजी-पतियों के लिये अनिश्चितता का यह एक बड़ा आधार हो गया।

भारत सरकार की उपर्युक्त औद्योगिक नीति को घोषित हुए आज तीन साल हुए। पर इन तीन वर्षों में देश में औद्योगिक उन्नति के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं हुए। यह ठीक है कि जो उद्योग-धन्वे स्थापित हैं वे चल रहे हैं और कुछ उद्योगों को—जैसे सूती कपड़े का उद्योग, ऊनी कपड़े का उद्योग, मशीन-द्वारा

उद्योग, जूट उद्योग आदि को छोड़कर बाकी के लगभग सभी उद्योगों का उत्पादन विद्यमान १० सालों में थोड़ा बहुत बढ़ा है। कोयला सीमेंट, इस्पात, एल्यूमिनियम, रसायन-यथाय, विज्ञानों का सामान, शर्करा, कागज के उद्योग इग भेजो में आते हैं। चीने की मशीन और बाइमिकल्स के उत्पादन में तो काफी वृद्धि हुई है। पर चालू उद्योगों के उत्पादन में थोड़ी बहुत वृद्धि होना एक बात है और औद्योगिक प्रगति दूसरी। नए-नए उद्योगों के विकास और मौजूदा उद्योगों में नए कारखानों की स्थापना के लिए आज कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है और विनियोग बाजार में स्थिरता छाई हुई है। औद्योगिक विकास का दृष्टि में हम असन्तोषजनक स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, यह एक विचारणीय प्रश्न है।

हम सम्बंध में एक बात यह कही जाती है कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति व्यवहार में सुनिश्चित नहीं रही है और उद्योग और राज्य की सरकारों की नीति में सामन्त्र्य का अभाव रहा है। कभी कभी भारत सरकार के ही विभिन्न विभागों में सामन्त्र्य का अभाव दलने की मिला है। इन बातों के उदाहरण स्वरूप जैसे यह कहा जाता है कि यद्यपि भारत सरकार कहने को यह कहती रही है कि सरकार के पास राष्ट्रीयकरण के लिये आज आवश्यक साधन नहीं हैं, पर व्यवहार में कुछ राज्यों की सरकारों ने विप्लव उत्पादन करने वाला कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में कदम उठाया है। इस प्रकार उदक वाला यात के राष्ट्रीयकरण की बात है। भारत सरकार का योजना में उदक-यातायात के राष्ट्रीयकरण को स्थान नहीं हाते हुए भी राज्यों की सरकारों ने उदक यातायात के राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया है। भारत सरकार द्वारा यातायात-कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर भी विचार कर रही है। इसने अलावा भारत सरकार और राज्य की सरकारों ने सरकारी तौर पर उद्योग धंधे भी स्थापित किये हैं और करने की योजना भी है। जैसे भारत सरकार दो स्लोट और इस्पात के कारखाने और मशीन टूल उद्योग का एक कारखाना स्थापित करने की सोच रही है। मिदकी राइड फैक्टरी की स्थापना भी भारत सरकार ने की है। सारांश यह है कि केन्द्रीय और राज्य की सरकारों की इस नीति के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत उत्पादन के क्षेत्र में एक प्रकार का अनिश्चितता रही है और उसका असर देश की भावी औद्योगिक उन्नति पर बुरा पड़ रहा है। भारत सरकार ने उद्योग धंधों के नियंत्रण के सत्र में जो बिल पारितामट में पेश किया है उसे भी व्यवसायों के ने बहुत आपत्तिजनक बताया है। उनका विरोध के कारण उसमें कुछ संशोधन भी किये गए हैं पर पूर्णोपति वह अभी संतुष्ट नहीं है। साथ ही से उद्योग धंधों की स्थिति के नियंत्रण के बारे में भी उनका विरोध

है। प्रन्तु हमारा ऐसा विचार है कि सरकारों के ऊपर इस तरह से दोष डालकर पूँजीपति वर्ग-अपने दायित्व और दोषों से-बचने का प्रयत्न करता है। वास्तविक स्थिति यह है कि इस देश के व्यवसायी वर्ग ने देश के प्रति अपने दायित्व को बिल्कुल नहीं निभाया है। कभी राज्य की नीति की आड़ में और कभी मजदूरों की अनुचित माँगों और उनके कारण बढ़ने वाली उत्पादन-लागत की आड़ में उसने अपने कर्तव्य की बराबर अवहेलना की है। उन्होंने अपने कल-कारखानों में नवीनतम मशीनों लगाने और योग्य टेक्निकल लोगों की सेवाएँ लेने में बराबर ढिलाई की है। आज भी इस देश का पूँजीपति वैज्ञानिक खोज पर रुपया खर्च करना अप्रव्यय समझता है। प्रबंध, हिसाब और बिक्री के क्षेत्र में जो नई-नई पद्धतियाँ निकल रही हैं उनका वह उपयोग करने को चिन्ता नहीं करता। माहस-पूर्वक नए-नए जैशों में उत्पादन करने का वह कोई प्रयत्न नहीं करता और अपनी पूँजी और लाभ का उपयोग परिकल्पनात्मक कामों में करता है। व्यावसायिक नैतिकता का उनका स्तर बहुत ही नीचा है। मजदूरों के साथ आज भी वह उदारता और न्याय का व्यवहार नहीं करना चाहते। इन सब बातों का अर्थ यह है कि भारत का व्यवसायी राष्ट्र निर्माण के काम में अपना उचित योग देने को आज तैयार नहीं है। और जनतंत्रीय शासन में सरकार पर जन-कल्याण की दृष्टि से जो बड़ी हुई जिम्मेदारियाँ आती हैं और जिनके कारण देश के आर्थिक जीवन में उसे अधिकाधिक क्रियाशील होना पड़ता है, उस परिस्थिति से अभी वह अपना मेल नहीं बिठा सका है। आज तो ऐसा लगता है कि भारत का व्यवसायी वर्ग अपने लाभ को सुरक्षित रखने के लिए सरकार से एक छिपा हुआ संघर्ष कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि वह अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को समझे और जन-कल्याण और देश के आर्थिक नवनिर्माण में उचित योग दे। इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार की नीति में कोई दोष ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विभिन्न सरकारें देश के आर्थिक जीवन का जहाँ तक सम्बन्ध है एक ही नीति चरते और उनका आपस में पूरा-पूरा सहयोग हो। इसके अलावा विभिन्न कामों के बीच में आज हमें प्राथमिकता निश्चित करने की बड़ी आवश्यकता है। हमारे सामने काम बहुत हैं और हमारे साधन सीमित हैं। ऐसी दशा में हमें किस काम को पहले करना है और किस को बाद में यह सोच-विचार कर निश्चय करना चाहिये। इस बात की भी आवश्यकता है कि सरकार के आर्थिक निर्णय स्थिर हों। इस बात की अभी तक बड़ी कमी रही है। देश की नियंत्रण-व्यवस्था अथवा जो बड़ी-बड़ी बड़ उद्देश्यीय योजनाएँ (दामोदर घाटी योजना, हीराकुड बांध आदि) आज चल रही हैं, उनके संबंध

में सरकार की नीति में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। इसका असर आर्थिक जीवन पर घातक पड़ता है। इस बात की भी आवश्यकता है कि सरकारी उद्योगों के संचालन का काम खासतौर पर कमचारी वर्ग के लोगों को, जो स्वभाव और शिक्षा तथा अनुभव से केवल व्यवस्थापक काम करने के अर्हस्त हैं, न सौंपे, बल्कि हम क्षेत्र व मानव संसाधनों के ह्रास में यह काम दे। इसके लिए देश में एक नए कमचारी वर्ग (इकोनॉमिक सर्विस) का निर्माण करना होगा। देश में टेक्निकल आदमियों की भी बढ़ाव करना है। इस कमी को भी पूरा करना होगा और यह ध्यान देना होगा कि जो टेक्निकल आदमी तैयार होते हैं वे देश की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किए जाते हैं।

उपयुक्त विवरण का सार यह है कि देश की औद्योगिक उन्नति के लिए एक सुव्यवस्थित और सुनिश्चित योजना की आवश्यकता है और उस योजना को कार्यान्वित करने में राज्य, उद्योगपति और मजदूरों का आपस में पूरा-पूरा सहयोग जरूरी है। देश को एक ओर तो इस बात का अकसर है कि उसके निवासियों को खाने, कपड़े और मकान आदि की प्रारंभिक आवश्यकताओं की तत्काल पूर्ति हो, दूसरी ओर ऐसे आधारभूत उद्योगों के विकास का प्रश्न है जो आधुनिक उद्योग की औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक है। और यह सब आज की आर्थिक स्थिति की दृष्टि में हमें करना है जब कि चीजों के दाम बराबर बढ़ते जा रहे हैं, विनियोग पूंजी का देश में अकाल मा है, टेक्निकल और मशीनों आदि पूंजी वस्तुओं के लिए हम विदेशों पर बहुत निर्भर रहना पड़ता है, जन संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और खाने-कपड़े का प्रश्न तत्काल हल करने की आवश्यकता है। इन तमाम परिस्थितियों में हमें निश्चित रूप से तत्काल आर्थिक और औद्योगिक नीति का निर्माण करना हमारी सबसे बड़ा आर्थिक आवश्यकता है। मार्च १९५० में इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने योजना आयोग (प्लानिंग कमिशन) का गठन किया है। इसका काम होगा देश के समस्त जन और जन संख्या साधनों का अभिनिर्धारण (एसेसमेंट) करना और अपेक्षित साधनों में अतिरिक्त की संभावनाओं का जांच करना तथा उनके साधनों का संश्लेषण और संतुलित उपयोग करने की दृष्टि से एक योजना तैयार करना। वह यह भी निश्चय करेगा कि इस योजना के विभिन्न अंगों में प्राथमिकता का क्रम क्या होगा और उस आधार पर साधनों का बंटवारा कैसे करना होगा। देश की आर्थिक उन्नति में जो बाधाएं आ रही हैं उनका निराकरण का माग भी इस दृष्टि से होगा ताकि उस योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो सके। योजना को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था पर भी यह आयोग विचार करेगा।

अन्त में इस योजना-आयोग का काम योजना टीक-ठीक कार्यान्वित होरही है, इसकी देख रेख करना भी होगा और इस चारे में वह सरकार को बराबर आवश्यक सुझाव भी देता रहेगा ।

योजना-आयोग की रिपोर्ट शीघ्र ही (मई १९५१) प्रकाशित होने की आशा है । अपने काम को करने के लिए उसने राज्यों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की है और उनकी योजनाओं को देश व्यापी आधार से जांचा और उनका समन्वय किया है । हम आशा करते हैं कि इसके प्रयत्नों के फलस्वरूप देश का आर्थिक भविष्य उज्ज्वल होगा । देश को औद्योगीकरण से क्या-क्या लाभ होंगे अब हम इस विषय में थोड़ा विस्तार से विचार करेंगे और इस सम्बन्ध में जो विचार प्रचलित हैं उनका मूल्यांकन भी करेंगे ।

औद्योगीकरण से लाभ:—प्रायः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या भारत के लिए औद्योगीकरण लाभप्रद होगा । यहाँ यह सन्देह कर देना आवश्यक है कि औद्योगीकरण से तात्पर्य बड़े बड़े उद्योग-धंधों की स्थापना से है । अस्तु, हमें आधुनिक उद्योग-धंधों और भारत की दृष्टि से उनका क्या उपयोग है, इस विषय पर थोड़ा विचार करना चाहिये ।

कई बार आधुनिक उद्योग-धंधों की बिना सोचे-समझे विभिन्न कारणों को लेकर बहुत आलोचना होती हुई देखी गई है । इस प्रकार की आलोचनाओं का यदि ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए जो मालूम होगा कि विचारों की अस्पष्टता उनका एक बड़ा आधार है । एक उदाहरण लीजिए । जो लोग आधुनिक उद्योगों के पक्ष में नहीं हैं उनकी ओर से एक बात यह कही जाती है कि भारत में पूँजी का अभाव और श्रम का बाहुल्य होने से बड़े पैमाने के उद्योग उसके लिए उपयुक्त नहीं हैं । यहाँ ध्यान देने की बात है कि श्रम और पूँजी सम्बन्धी कारणों को इस प्रकार जोड़ना उचित नहीं है । यह एक अलग बात है कि चूँकि भारत में श्रम की अधिकता है इसलिए हम ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन न दें जिनमें अधिकश्रम काम मशीनों द्वारा ही हो जाता हो और जिनमें मजदूरों के लिए अपेक्षाकृत कम जगह हो । पर भारत जैसे प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न देश के लिए केवल द्रव्य पूँजी (मशीन के पिटल) की कमी के कारण यह राय बनाना कि आधुनिक उद्योगों की दृष्टि से उनके पास साधन नहीं हैं, विचार-भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता । द्रव्य पूँजी को उपलब्ध मात्रा का असर हमारे देश के औद्योगिक उन्नति की गति पर तो पड़ सकता है पर उसको देश के लिए आधुनिक उद्योगों की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का आधार बनाना सर्वथा गलत है । चालू पूँजी की स्थिति को

मुद्रारत्ने का जहाँ तक सम्बन्ध है वह उदात्त भोज्य है। देश की वैशिष्ट्य और सामान्यवस्था और उस सम्बन्धी नीति में आवश्यक सुधार करने से, उचित शर्तों पर विदेशों से पूँजी उधार ले कर, तथा अनुकूल मुद्रा नालि अरना कर देय की चानू पूँजी की समस्या का हल निकाला जा सकता है। औद्योगिक उन्नति स्वयं ही आगे के लिए अधिक पूँजी प्राप्त करने का एक साधन है। माराश यह है कि अम और पूँजी सम्बन्धी तर्कों को एक साथ मिला देना उही नहीं है।

भारत के लिए औद्योगिक प्रसार की आवश्यकता पर विचार करते समय हमारे सामने कई आने सृष्ट हानी चाहियें। सबसे मूल बात यह है कि किछा भी देश की आर्थिक व्यवस्था का अन्तिम सत्य वेधन आर्थिक हित की प्रति करना नहीं है बल्कि सम्पूर्ण मानव हित की, आर्थिक हित जिनका एक अन्न भाग है, प्रति करना है। हमें आने समस्त साधनों का इसी दृष्टि से उपयोग करना है। इसी दृष्टि से हमें ये प्रश्न हल करने हैं कि किछा देश में कृषि, यह उद्योग और बड़े उद्योगों को किनना कितना स्थान मिलना चाहिये। जिसे हम मनुष्य मानव हित कहते हैं उसमें एक तरफ तो इस बात का समान्य हो जाता है कि जनता के जीवन यापन का एक स्वस्थ मापदण्ड हो, और दूसरी ओर उसमें यह बात भी आती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का सर्वोन्मुखी विकास करने का समान और सम्यक् अवसर हो। यह नयी ममव हो सकता है जबकि देश में एक ऐसी न्याययुक्त समाज-व्यवस्था हो जिसमें अधिकतम उपदान, न्याययुक्त वितरण और मनुष्यत्व के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण—इन तीनों में समुचित संतुलन समझ हो सके। इसीलिए कृषि अथवा उद्योग किसी एक के प्रति पक्ष विपक्ष का भाव लेकर चलना उचित नहीं कहा जा सकता।

दूसरे हमें औद्योगिकवाद और पूँजीवाद के भेद का भी स्पष्ट समझना चाहिये। एक के लोगों को दूसरे के लोगों के साथ न मिलाया जाए। पहले बड़े पैमाने पर चलने वाले उद्योग यहाँ में क्या-क्या दोष हैं इस पर विचार किया जाए। बड़े उद्योगों के विरुद्ध एक आम शिक्षाएत यह है कि मिल में काम करने शक्ति का विकास नहीं हो सकता और इसीलिए उनका काम उदात्त व्यक्तित्व के विकास में सहायता नहीं पहुँचाना। पर इस सम्बन्ध में कई बातें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। पहला बात तो यह है कि यह दोष केवल बड़े बड़े मरान-उद्योगों में ही नहीं है। दसकरी के एक बहुत काम हैं जिनके द्वारा काम

करनेवाले की रचनात्मक शक्ति का विकास नहीं होता और जो नीरस होते हैं। इसके अलावा मशीन पर काम करने वालों में मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाने वाले कुछ गुणों का, जैसे बुद्धि, जिम्मेदारी और सावधानी का, अपेक्षाकृत अधिक विकास होता है। उनको इस बात का भी अवसर रहता है कि वर्तमान मशीनों में क्या-क्या सुधार हो सकता है इस विषय में विचार करें। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि आधुनिक मशीन का कई पुरानी हाथ की दक्षताओं और कारीगरियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। परं साथ ही साथ उसने कई ऐसी नई कुशलताओं के लिए रास्ता भी खोल दिया है जिनकी आवश्यकता टेक्निकल योग्यता, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में काम कर सकने की उपयुक्तता, नए सुधार सोचने की शक्ति, और निरर्थक-बुद्धि के लिए होती है। यह भी सही है कि मशीन के काम में एक हद तक नीरसता है, लेकिन इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि मशीन ने बहुत से थका देने वाले और मारी कामों को अपने ऊपर ले लिया है और एक ही प्रकार की क्रिया को बार-बार सुहराने से जो नीरसता पैदा होती है उसका अन्त कर दिया है। क्योंकि ऐसे कामों को ही मशीन आसानी से कर सकती है। यही कारण है कि इस तरह के नीरस कामों से छुटकारा पाने के लिए मशीन के उपयोग के क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है न कि उसे घटाने की। मशीन से होने वाले कुछ और भी लाभ हैं जैसे काम का जल्दी हो जाना, मनुष्य में कई प्रकार के नए काम करने की शक्ति उत्पन्न होना, भ्रम को स्थानान्तर करने की सुविधा बढ़ जाना आदि, जिनको हमें भूलना नहीं चाहिये।

आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों के बिगड़ सामाजिक हित की दृष्टि से एक आपत्ति यह भी उठाई जाती है कि उनके द्वारा आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण होता है। इस आपत्ति में बहुत कुछ तथ्य है और यह भी किसी हद तक ठीक है कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण मात्र से यह आपत्ति नहीं मिट जाती। इसका कारण यह है कि जिन व्यक्तियों के हाथ में आर्थिक सत्ता होगी वे उसका अच्छे अथवा बुरे के लिए अथवा ही उपयोग कर सकेंगे, फिर चाहे वह व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसायी, श्रम या समाजवादी सरकार के कर्मचारी। यह भी ठीक ही है कि जब तक मनुष्य-स्वभाव में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो जाता और मनुष्य राष्ट्र के प्रति अपने नैतिक कर्तव्य की भावना में पूर्णतया ओछप्रोत नहीं हो जाता तब तक उसके द्वारा उसके हाथ में केन्द्रित सत्ता के उपयोग की अपेक्षा दुरुपयोग की संभावना अधिक रहेगी। यह ठीक है कि समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत, जबकि मुनाफा-वृत्ति की जगह समाज-सेवा की भावना ले-लेगी, समस्त समाज:

य वातावरण में एक अवश्य गंभीरी परिवर्तन होगा जिसका कि प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व पर अवश्य ही अन्धका होगा। इसके साथ साथ यदि जनतन्त्रीय समाज का समुचित नियन्त्रण भी रहे तो समाजवादी व्यवस्था व अदर वेन्द्रित आर्थिक मता से उत्पन्न होने वाले स्वतरे अवश्य ही बहुत कुछ कम हो सकते हैं।

मशीन उद्योगों में कुछ और दोष भी हैं। आन के युग में पाए जाने वाले आर्थिक शोषण, बेकार और विभिन्न राष्ट्रीय के आपसी साम्राज्यवादी भगनों का कारण भी आधुनिक उद्योगवाद ही बताया जाता है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। यह ठीक है कि आरम्भ में मशीन उद्योगों की स्थापना के साथ साथ मजदूर तथा आम जनता के हितों की रक्षा का ध्यान नहीं रखा जा सका। आर्थिक जीवन का आधार किसी प्रकार की योजना नहीं रही। पर जैसे-जैसे समाज और मजदूर हित के कानून बनने लगे हैं और राज्य ने एक न एक सीमा तक आर्थिक जीवन को आयोजित करने का प्रयत्न करना शुरू किया है, मशीन उद्योगों के साथ साथ उत्पन्न आर्थिक शोषण और बेकारी जैसे दोषों को कम किया जा सका है। यह अवश्य है कि उद्योगों की पूर्णवादा व्यवस्था जिन हद तक समाज में निर्बाध रूप से रहेगा उस हद तक उपर्युक्त दोष भी मशीन उद्योग के साथ बने रहेंगे।

मशीन उद्योगों के बारे में जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है उससे इसका विचार का पुष्टि होती है कि यह कहना कि मशीन उद्योग सर्वथा बुरे हैं अथवा सर्वथा अच्छा ठाक गहा है। अन्धका अथवा उगार इस बात पर बहुत निर्भर है कि किस परिस्थितियों और किस वातावरण में कौन से उद्योगों की स्थापना होता है। जहां तक भारत का मदन है उसका बारे में भी हम यह नहीं कह सकते कि उस मशीन उद्योगों का सर्वथा बहिष्कार ही करदना चाहिए। इसके कई कारण हैं। भारत अपने आप की मसार से सर्वथा अलग नहीं बन सकता और यह निश्चित है कि दुनिया आधुनिक मशीन-उद्योगों का बहिष्कार नहीं करने वाला है। दूसरे आधुनिक जीवन की आवश्यकताएँ, जिनमें दूर की रक्षा का प्रश्न भी आजाता है, ऐसा है कि उनका पूर्ति के लिए भी बड़े पैमाने पर मशीन उद्योगों की स्थापना पड़ेगी। तब, हमारे सामने अपनी बढ़ती हुई जन मख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रश्न भी है। मशीन द्वारा उत्पादन थोड़े समय में और अधिक मात्रा में होता है और इसलिये बड़ी हुई मात्रा को पूरा करने में उसकी आवश्यकता स्पष्ट है। भारतीय आर्थिक व्यवस्था में बड़े पैमाने के मशीन उद्योगों की स्थापना होगी, यह एक विवक्षित में समझ में आ जाता है।

इतना अवश्य है कि समाज के हित में इन उद्योगों का यथेष्ट नियंत्रण होना चाहिये।

जब हम देश के औद्योगीकरण की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य केवल बड़े-बड़े उद्योगों से ही नहीं होता। छोटे और बीच के दर्जे के उद्योगों का भी देश के औद्योगीकरण में स्थान है। बड़े-बड़े उद्योगों से मिलने वाले लाभ के अतिरिक्त, देश के आर्थिक जीवन को औद्योगिक विकास से, जिसमें सब प्रकार के उद्योगों का विकास आ जाता है, और भी कुछ लाभ हैं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है।

सबसे बड़ी बात तो यही है कि खेती की भूमि पर अत्यधिक जन संख्या के भार को कम करने के लिए देश में नए धंधों के खोलने की आवश्यकता है। देश का औद्योगीकरण इस दिशा में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त, देश के आर्थिक जीवन की खेती पर जो अत्यधिक निर्भरता आज पाई जाती है उसको कम करने का उपाय भी देश का औद्योगीकरण ही है। औद्योगिक विकास से हमारी राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। इसका असर लोगों के जीवन-यापन के माप-दण्ड को ऊँचा उठाना और उनकी कर देने की क्षमता को बढ़ाना होगा। इससे राज्य की आय भी बढ़ सकेगी ताकि राष्ट्र-निर्माण के कामों में वह अधिक व्यय कर सके। उद्योग-धंधों के विस्तार से मध्यम श्रेणी के लोगों में भी बेकारी कम हो सकेगी।

देश के औद्योगिक उन्नति से उपर्युक्त आर्थिक लाभ तो होंगे ही पर उसका राष्ट्र के चरित्र पर भी श्रद्धा असर पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की योग्यता और बल के लिए अवसर मिलने के साथ-साथ, देश की जनता में औद्योगिक उन्नति के फलस्वरूप और भी कई गुण पैदा हो सकेंगे। उदाहरण के लिए बौद्धिक जागरूकता, कार्य और विचार की निश्चितता, और रुढ़िवादिता का अभाव कुछ ऐसे गुण हैं जो कि औद्योगिक देशों के रहने वालों में साधारणतया पाये जाते हैं और जो प्रत्येक राष्ट्र के लिए वांछनीय हैं।

देश के औद्योगीकरण के संवध में हमारा अंतिम निष्कर्ष यही है कि भारत को एक निश्चित योजना के अनुसार अपने उद्योग-धंधों की उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिए। यह उन्नति न केवल बड़े उद्योगों के क्षेत्र में बल्कि बीच के और छोटे उद्योगों के क्षेत्र में भी होना आवश्यक है। अब तक राष्ट्र की पराधीनता इस दिशा में एक बहुत बड़ी बाधा थी। इस बाधा के हट जाने के पश्चात् और भारत एक जनतन्त्रीय गणराज्य घोषित हो जाने के बाद अब यह आशा रखी जा सकती है कि हमारा देश जीवन के अन्य क्षेत्रों की भाँति औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रगति करेगा।

उद्योग-धंधे—प्रस्तुत प्रश्न

योजना की आवश्यकता—विद्युत् परिच्छेद से यह स्पष्ट है कि हमारे देश की उद्योग धंधों संबंधी वर्तमान स्थिति सतोग जनक नहीं है और देश में औद्योगिक विकास का अत्यन्त आवश्यकता है। बिना देश के औद्योगीकरण के यह समझ नहीं मालूम पड़ता कि आम जनता की जो दयनीय स्थिति आज है उसमें यथेष्ट सुधार हो सकेगा।

देश का औद्योगिक विकास सदा और व्यवस्थित ढंग से हो इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारा पास विकास की कोई निश्चित योजना हो। देश में अब तक जो भी उद्योग धंधे स्थापित हुए उनको एक बड़े कम। यह रहा है कि व किन्हीं निश्चित योजना के अनुसार स्थापित नहीं हुए। कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो सकता है, जैसे एक ओर तो हमारे देश में एला कपड़े, शर्करा आदि के उद्योगों का आवश्यकता से अधिक विस्तार हुआ और दूसरी ओर कई उपयोगी धंधों, जैसे—मशीन और रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करने वाले उद्योगों की ओर गत महायुद्ध तक देश का कोई ध्यान ही नहीं गया। आवश्यकता से अधिक विस्तार होने का इतना ही अर्थ है कि भाग की दृष्टि से अत्यन्त उद्योग शक्ति की आवश्यकता की पूर्णतया व्यवस्था करीब करीब पूर्णतया संतुष्ट कर सकता है। “यदि कोई उद्योग ऐसा है जिससे कि अच्छा मुनाफा कमाला प्रभव है, तो उसमें उस समय तक पूँजी बराबर लगती ही आती है जब तक कि उसमें पूँजी की मात्रा आवश्यकता से अधिक नहीं हो जाती और उस उद्योग से मुनाफा की कोई आशा नहीं रहती।” हमारे देश में अब तक उद्योग धंधों का जिस प्रकार विकास हुआ है उससे यह भां स्पष्ट है कि कच्चा माल उत्पन्न करने वाले प्रमुख और औद्योगिक केन्द्र में कितनी दूरी है जबकि औद्योगिक केन्द्र और बाजार, जहाँ माल बिकने जाता है, उनमें कितनी दूरी है, इसका या विशेष ध्यान नहीं रखा गया। और स्थानों का मिलान की व्यवस्था नहीं की गयी कपड़े की मिलों की कठिनार्थ का यही कारण है कि बिना बाजार की सुविधा की दले एक ही जगह कई मिलों का कच्ची करण होता गया। इसी प्रकार की कठिनार्थ में देश का सीमेन्ट की मिलें बँस गई थीं। हमारे व्यवस्थित औद्योगिक विकास का एक प्रमाण यह भी है कि बड़े बड़े उद्योगों का विकास करते समय यह बात विस्तृत ध्यान में नहीं रखी गई कि उनका संवर्धित यह उद्योगों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे यह उद्योगों का क्या हानि हो सकती है और उसको किस प्रकार कम किया

जा सकता है इसका हमारे उद्योगपतियों अथवा तत्कालीन सरकार ने कभी विचार ही नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में जो योद्धावहुत औद्योगीकरण हुआ उसका भी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बुरा प्रभुत्व पड़ा। यदि हमारा औद्योगीकरण किसी योजना के आधार पर होता तो बहुत से उद्योगों को नष्ट होने से बचाया जा सकता था और नए बड़े पैमाने पर चलने वाले उद्योगों का भी एकांगी विकास नहीं होता। अस्तु, भविष्य में सही और व्यवस्थित औद्योगिक प्रगति के लिए किसी निश्चित योजना का होना अत्यन्त आवश्यक है। उद्योग-धंधों सम्बन्धी योजना समस्त राष्ट्रीय योजना का एक अभिन्न अंग होना चाहिये, यह तो स्पष्ट ही है। इसका कारण यह है कि देश के उद्योग-धंधों में और कृषि तथा राष्ट्रीय जीवन के दूसरे आर्थिक और अन्य पहलुओं में एक न एक प्रकार का संतुलन होना तो आवश्यक है ही। राष्ट्रीय जीवन के किसी एक अङ्ग से सम्बन्ध रखने वाली योजना राष्ट्र भर के लिए जो संपूर्ण योजना हो उससे मेल खाती हुई तो होनी ही चाहिये।

राज्य और उद्योग-धंधे—निर्वाध व्यापार चनाम संरक्षण नीति—देश को औद्योगिक उन्नति से सम्बन्ध रखनेवाला एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि राज्य की इस बारे में क्या नीति हो। यह नीति दो प्रकार की हो सकती है। एक तो यह कि राज्य देश के उद्योगों को किन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर संरक्षण दे। दूसरी यह कि इस विषय में राज्य कुछ न करे और विभिन्न देशों से जो व्यापार होता है उसे निर्वाध रूप से होने दे। इसी को निर्वाध व्यापार की नीति कहते हैं। देखना यह है कि निर्वाध व्यापार और संरक्षण इन दोनों में से कौन सी नीति सही है। *Free trade*

निर्वाध व्यापार के पक्ष में सब से बड़ा तर्क यह है कि इस नीति के अपनाने से प्रत्येक देश के लिए यह संभव हो सकता है कि वह अपने साधनों का उपयोग उन चीजों के उत्पादन में ही करे जिनका उत्पादन वह और चीजों की अपेक्षा दूसरे देशों से अधिक सस्ता कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक देश वही माल पैदा करेगा जिसके लिए वह सबसे अधिक आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त है और दूसरे देशों से अपनी आवश्यकता की दूसरी चीजें मंगाएगा और दूसरे देशों को अपने यहाँ का तैयार माल भेजेगा। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर एक ऐसा श्रम का विभाजन स्थापित किया जा सकता है जिससे प्रत्येक देश को लाभ होगा और हानि किसी को नहीं होगी। व्यवहार में इसका परिणाम यह होगा कि जो देश भौगोलिक तथा अन्य कारणों से खेती के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है वे अपने उत्पादन-साधनों का उपयोग खेती के लिए ही करेंगे और

अन्यो वेदाचार के बदले में और दलों से या औद्योगिक वर्गों के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त हैं औद्योगिक माल प्राप्त करेंगे। ऊपर ऊपर से देखने में निर्बाध व्यापार के पक्ष में उपर्युक्त सब सही मान्य पड़ता है। पर यदि इस तर्क का हम गहराई से अध्ययन करें तो हमें उसमें कई अप्रमृताएँ मालूम पड़ेंगी। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि किंसा भी देश का नेता अपना उद्योग धर्मों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्तता का नियम हम किस आधार पर करें। क्या यह नियम कबल उपयुक्त जनशक्त, कच्चे माल और शक्ति की सुविधा आदि जैसे प्राकृतिक कारणां पर आधार पर ही किया जाना चाहिये? या हमें और बातों का भी विचार करना चाहिये, जैसे भूमि और आवायन माध्यमों की सुविधा, सरकार का मुद्रा-नीति, और इसी प्रकार की सब बातें। जीवन के अनेक क्षेत्रों की भौतिक आर्थिक क्षेत्रों में भी हम वर्तमान को अतीत से अलग नहीं कर सकते, और जब हम किसी प्रश्न पर विचार करना आरम्भ करने हैं तो वर्तमान स्थिति को आधार मान कर ही चलने हैं। और यही एक विचारणात्मक प्रश्न है। क्योंकि किसी भी प्रश्न पर सम्भव है जो स्थिति एक समय होना है वह सदा ही नहीं बनी रहती। समय के साथ स्थिति में भी परिवर्तन आता है। जो स्थिति आज एक देश के अनुकूल मालूम पड़ती है वही कल दूसरे देश के अनुकूल बनाई जा सकती है। ऐसा देश में यह कैसे सम्भव हो सकता है कि यदि कोई व्यवस्था आज किसी देश के प्रतिफल है तो वह सदा के लिए उस व्यवस्था को स्वीकार करल और उसे अपने अनुकूल बनाने का कोई प्रयत्न नहीं करे। एक उदाहरण से यह बात अधिक स्पष्ट की जा सकती है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक विदेशी शासन ने हमारे देश के उद्योगों का सवनाश कर दिया था और एक हद तक इसी सवनाश के आधार पर उन्नीसवें में अपने उद्योग धर्मों का विकास किया और औद्योगिक मगार के सम्राट का स्थान प्राप्त किया। और इस प्रकार ज्ञान बूझ कर जो स्थिति उत्पन्न की गई थी उसी को आधार बना कर निर्बाध व्यापार के समर्थकों ने इस नीति का प्रतिपादन करना आरम्भ किया कि भारत को वृत्ति पदार्थों के उत्पादन में अपने साधनों का उपयोग करना चाहिये क्योंकि प्रकृति ने भारत को वृत्ति प्रधान देश ही बनाया है और इंग्लैंड को उद्योग धर्मों पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिये, क्योंकि वह औद्योगिक विकास की दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट है। यदि भारत अमेरिका के अशोक करता। अब शासन ने विचार्यो इस बात से प्रती प्रकार परित्यक्त है कि किस प्रकार अमेरिका और जर्मनी ने निर्बाध व्यापार के सिद्धान्त को अस्वीकार करके

अपने उद्योग-धन्यों को विकसित किया और औद्योगिक क्षेत्र में इंग्लैंड के प्रति-
द्वन्द्वी राष्ट्रों के रूप में आ उपस्थित हुए। और आज औद्योगिक संसार का नेतृत्व
अमेरिका के पास है न कि इंग्लैंड के पास। निर्वोध व्यापार के तर्क की असत्यता
का इससे अधिक ज्वलंत उदाहरण और क्या हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक
बात और है। अन्तर्राष्ट्रियता की कितनी भी बात हम क्यों न करें राष्ट्रों के
स्वतंत्र अस्तित्व को भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक राष्ट्र आज अपने राष्ट्रीय हित
को सामने रख कर चलता है। यहां तक कि स्टेलिन के नेतृत्व में रूस भी अपनी
अन्तर्राष्ट्रियता का परित्याग कर चुका है। यह ठीक है कि रूस को यह
अन्तर्राष्ट्रियता एक सुदूर आदर्श के अतिरिक्त और कुछ कभी भी नहीं रही।
अस्तु, यद्यपि कोई भी राष्ट्र राष्ट्रीय स्वावलंबन के आदर्श का पूर्णतया पालन
करना न व्यावहारिक और न उचित ही समझता है, पर फिर भी जहाँ तक सम्भव
हो सकता है प्रत्येक राष्ट्र का वह प्रयत्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जीवन की
प्रारम्भिक और आधारभूत आवश्यकताओं और राष्ट्र के प्राकृतिक तथा जन
साधन का यथोचित उपयोग करने की दृष्टि से वह अधिक से अधिक स्वावलम्बी
बने। इन सब प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार-समष्टता की बड़ी आवश्यकता है। प्रत्येक
राष्ट्र को हर कीमत पर अपनी सुगुत्ता का प्रबन्ध तो करना ही होगा। आर्थिक
हित का कोई भी सिद्धान्त इस में बाधक हो, यह कदापि स्वीकार नहीं किया जा
सकता। सारांश यह है कि सुरक्षा से सम्बन्ध रखने वाले जितने उद्योग हैं उनके
मामले में कोई राष्ट्र दूसरों पर निर्भर रहना पसन्द नहीं कर सकता। इस बारे में
सापेक्षिक लागत का सिद्धान्त निर्णायक कदापि नहीं हो सकता। जहाँ तक जीवने
के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं का सम्बन्ध है उनके बारे में भी यही तर्क लागू
होता है। इसी के साथ-साथ राष्ट्रीय साधनों के पूरे-पूरे उपयोग का प्रश्न भी
है। निर्वाध व्यापार-सिद्धान्त का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसके अनुसार सस्ते
से सस्ते मूल्य पर उपयोग की वस्तुएं मिल सकना ही आर्थिक हित की कसौटी है।
पर सोचने का यह ठग सही नहीं है। अधिकतम आर्थिक हित की स्थिति उसी
समय मानी जाना चाहिये जब समाज में सब काम कर सकने वालों के लिए काम
की व्यवस्था हो। निर्वाध व्यापार-सिद्धान्त इस प्रकार की व्यवस्था मौजूद है, वह
मान कर ही चलता है। अस्तु, यदि हम यह भी स्वीकार कर लें कि उस स्थिति
में जब सब काम कर सकने वालों के पास काम है, हमारे साधनों का सबसे अच्छा
उपयोग निर्वाध व्यापार-सिद्धान्त के आधार पर ही हो सकता है, तब भी यह
प्रश्न तो रह ही जाता है कि यदि उपर्युक्त स्थिति नहीं है तब इस सिद्धान्त को
कैसे स्वीकार किया जा सकता है। और इस में तो कोई सन्देह नहीं कि निर्वाध

व्यापार के रहते हुए और उसका परिणामस्वरूप भी भारत भीने विकसित हुए और आर्थिक दृष्टि में अविभक्त देश में बहुत कुछ बढ़ावा दे सकती है। भारत यह है कि केवल आर्थिक हित की दृष्टि से विचार करने पर भी निर्वाह व्यापार का सिद्धान्त सब परिस्थितियों में यही तरीका मान्य पड़ता।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि निवारण व्यापार के समर्थकों का वैज्ञानिक आधार भी जगह ठोस नहीं है जितना साधारणतया माना जाता है। यही कारण था कि भारत जैसे इस सिद्धान्त के समर्थकों की भी कुछ अववाद स्वीकार करने पड़े—उदाहरण के लिए फ्रेडरिक मिश्ट के “यह उत्तर करने का नाममात्र” और “भण्ड उद्योग” सम्बन्धी तर्क का भारत ने स्वीकार किया। “यह उत्तर करने की समझ” सम्बन्धी तर्क, ऐसा कि प्रो० पीगू ने भी माना है, उन दृष्टि में देशों के बारे में ज्ञान की रीति में लागू होता है जो औद्योगिक प्रगति करना चाहते हैं क्योंकि राष्ट्रीय सम्पत्ति को बढ़ाने में ऐसे देशों में औद्योगिकरण का प्रभाव औद्योगिक देशों की अपेक्षा कहीं अधिक होता है।

यह स्पष्ट है कि सब देशों के लिए सब समय के समान निर्वाह व्यापार का सिद्धान्त उपयुक्त नहीं मान्य पड़ता। पर इतना यह स्पष्ट भी नहीं है कि यह सिद्धान्त कितना भी देश के लिए किसी समय उपयुक्त नहीं माना जा सकता। उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का ठोस प्रश्न देश की विशेष परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। आर्थिक सिद्धान्तों का इस सापेक्षता के कारण ही, हम देखते हैं कि, हरमैड एक समय ‘मॅकडिल्लियम’ की नीति का अपनाता है ता दूसरे समय अहस्तक्षेप की नीति का पालन करता है, और फिर आर्थिक मरन्य-नीति को स्वीकार करता है। इसा मापेक्षितता का यह प्रभाव था कि लिस्ट और बरे ने भारत से हा जमनी तथा श्रमरिखा के लिए संरक्षण नीति का प्रतिपादन किया। ‘ये दोनों ही व्यक्ति दो ऐसे देशों के निवासी थे जिनमें औद्योगिक विकास के लिए बहुत क्षेत्र था पर विश्वास होता बारी था।’ अपने देश के शिष्ट निष्ठ आर्थिक नीति को स्वीकार करना चाहिये इसका निष्पत्ति हम भी अपनी परिस्थितियों का ध्यान में रख कर ही करता होगा। यह ठीक है कि जब तक भारत में विदेशी शासन रहा हमारा देश की आर्थिक नीति का निष्पत्ति देश का आवश्यकता को सामने रखकर नहीं किया जा सके।

अब तब हमने निर्वाह व्यापार सिद्धान्त का विवेचना की। पर संरक्षण के सिद्धान्त के विषय में भी एक और विचार से बहुत कुछ कहा जा सकता है। भारत के सम्बन्ध में विचार करते समय हम हमारा तब विचार का ध्यान रखेंगे।

भारत की राजनीतिक नीति—यह हम लिख चुके हैं कि पराधीनता के युग में

में भारत की विदेशी सरकार ने देश की औद्योगिक उन्नति के प्रति न केवल उदासीनता का भाव रखा बल्कि किसी हद तक विरोध का भाव प्रदर्शित किया। जून १९२१ में प्राप्त तथाकथित राजकोपीय (फिक्कल) स्वतंत्रता के पहले भारत में सरकार की नीति विशुद्ध निर्वाध व्यापार की रही। पर इस अर्थ नीति सम्बन्धी तथाकथित स्वतंत्रता के मिलते ही भारत सरकार ने अक्टूबर १९२१ में देश के लिए उपयुक्त राजकोपीय (फिक्कल) नीति के विषय में सरकार को सिफारिश करने की दृष्टि से एक शाही कमीशन की नियुक्ति की। जैसा कि सर्वविदित है पूरी जांच पड़ताल के पश्चात् इस कमीशन ने सरकार से विवेकशील (डिस्की-मिनेटिंग) संरक्षण नीति का अनुसरण करने की सिफारिश की। कमीशन ने निम्नलिखित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया :—

(i) ✓ संरक्षण चाहने वाला उद्योग ऐसा होना चाहिये जिसे प्राकृतिक सुविधाएं प्राप्त हों—उदाहरण के तौर पर कच्चे माल, सस्ती चालक शक्ति, यथेष्ट श्रम-शक्ति और विस्तृत घरेलू बाजार की सुविधाएं इस श्रेणी में आती हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि किसी ऐसे उद्योग को संरक्षण न दिया जाए जो एक निश्चिन्त समय के पश्चात् बिना संरक्षण के जीवित न रह सके और वरावरी के आधार पर दुनिया के बाजार में सफलतापूर्वक मुकाबला न कर सके।

(ii) ✓ संरक्षण पाने वाला उद्योग ऐसा भी होना चाहिए जो बिना संरक्षण के या तो विल्कुल ही विकसित नहीं हो सकता है या फिर देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस गति से होना चाहिये उससे नहीं हो सकता है।

(iii) तीसरी शर्त यह है कि संरक्षण प्राप्त करने वाले उद्योग को आखिरकार बिना संरक्षण के दुनिया के बाजार में खड़ा हो सकना चाहिये। उपर्युक्त शर्तों के अलावा, कमीशन की यह भी सम्मति थी कि जिस उद्योग में कमगान वृद्धि नियम लागू होता हो, या जिसके सम्बन्ध में यह संभावना हो कि निकट भविष्य में ही वह देश की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा उसका संरक्षण की दृष्टि से विशेष अधिकार माना जाना चाहिये। कमीशन ने यह सिफारिश भी की कि आधारभूत और रक्षा सम्बन्धी उद्योगों को तो बिना किसी शर्त के संरक्षण मिलना चाहिये।

कमीशन ने उन देशी उद्योगों के संरक्षण के विषय में जिनको विदेशी माल की अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा हो, अलग से सुझाव दिये। विदेशों द्वारा माल पाटने की नीति अथवा सरकारी सहायता प्राप्त विदेशी माल की प्रतिस्पर्धा उपर्युक्त अनुचित प्रतिस्पर्धा की मर्यादा में आती

है। किंगडल कमीशन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि संरक्षण उन उद्योगों का ही मिलता चाहिये जो गहरे आधार पर स्थापित हो हों हुए हैं यद्यपि यह है, कि उन उद्योगों का जो मर्यादितता में हैं और जो अपने मातृ उद्योगों का स्वयं निराधार आधारों पर खड़े हैं। कमीशन ने यह भी निर्धारित की कि उद्योगों की शक्तों का ध्यान रखते हुए आधारभूत उद्योगों का संरक्षण को प्रत्यक्ष आधारित गहनता कर संरक्षण करना चाहिये और जो दूसरे उद्योग हैं उनका आधारभूत लगाकर संरक्षण किया जाता चाहिये। कमीशन ने एक स्थायी टैरिफ़ बोर्ड का नियुक्ति का सिफारिश भी की ताकि सरकार संरक्षण की उपायों का भले प्रकार प्रालोचन कर सके और हों विभिन्न उद्योगों का और ने जाने वाला मार्गों की बराबर जान करना रहे और निम्न उद्योगों को संरक्षण मिल चुका है उनका स्थिति का प्रभाव अनुमान करना रहे।

किंगडल कमीशन द्वारा प्रतिपादित विवेकपूर्ण (डिस्टिन्क्शनिंग) संरक्षण का सिद्धान्त तथा उद्योगों द्वारा जो यह अन्य विधिवारियों को सरकार ने स्वीकार कर लिया। फरवरी १९२३ में कलकत्ता केंद्रीय बोर्ड गंगा में इन मामलों का एक प्रस्ताव मां पास किया गया। जुलाई १९२३ में टैरिफ़ बोर्ड का स्थापना हुई। इस प्रकार भारत में संरक्षण का उस नीति को स्वीकार किया जिसका बराबर बहुत कुछ आलोचना की जाती रही है।

कमीशन ने उक्त सिफारिशें बहुत ही विचारपूर्वक थीं। कमीशन के कुछ सदस्य विमल कमीशन के अध्यक्ष सर इब्राहीम अब्दुल्ला और डा. व. अल्लिप्प शप भारतीय सदस्य शामिल थे, इन सिफारिशों से सहमत नहीं थे। नदी शप में इसका कोई आशय नहीं था कि भारत में संरक्षण विधान का इस मर्यादित रूप में स्वीकार किया जाय। इसका यह अर्थ कहना नहीं कि अलग-अलग विवेक कि ये लोग इन पक्ष में नहीं थे कि संरक्षण विधान का प्रयोग विवेकपूर्ण रूप में किया जाय। पर व संरक्षण सम्बन्धी अधिक उदार नीति के पक्ष में अर्थव्यय से और उनका यह मानना था कि कमीशन (बहुमत) ने विवेकपूर्ण विवेकपूर्ण चाहते वाले उद्योगों पर लागू करने का सिफारिश की है वे देश के आर्थिकोन्नति में बाधा हान। किंगडल कमीशन के बहुमत और अल्पमत के विचारों पर अब हम सिद्धान्त तथा वास्तविक अनुभव का ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष लेंगे।

कमीशन के बहुमत ॥ संरक्षण सम्बन्धी सिफारिशें कीं। उनका मूल तार्किक आधार यही था कि देश में पन उद्वेल करने की क्षमता बढ़ाने के लिए और नए उद्योगों को गहनता देने के लिए संरक्षण की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में वे

नए उद्योग जो पुराने और सुसंगठित करने हो प्रकार के दूसरे उद्योगों का आज केवल नए होनेसे मुकाबिला नहीं कर सकते, यद्यपि कुछ समय पश्चात् वे उनके समान ही आखड़े होंगे, संरक्षण के अधिकारी हैं। इससे स्पष्ट है कि कमोशन ग्राम तौर पर संरक्षण को अग्राने के पक्ष में नहीं था। उसको राय वो यह थी कि प्रत्येक उद्योग के विषय में उसकी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना चाहिये। लिस्ट के 'नए उद्योग' सम्बन्धी तर्क को ठीक-ठीक नहीं समझने के कारण ही कमोशन ने इस प्रकार की सिफारिश की। लिस्ट का तर्क किसी एक उद्योग पर लागू नहीं होता था। वह तो उन्म चार राष्ट्र पर लागू होता था जो उद्योगीकरण के मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है। इस सम्बन्ध में लिस्ट की दृष्टि में ऐसे राष्ट्र थे जिनमें औद्योगीकरण के लिए सब प्रकार के साधन मौजूद हैं पर जो दूसरे देशों के मुकाबिले में पीछे रह गए हैं। लिस्ट का कहना था कि इस प्रकार पिछड़े हुए राष्ट्रों का संरक्षण की नीति अपनाकर ही अन्य औद्योगिक राष्ट्रों के बराबर लाया जा सकता है। लिस्ट के सामने विशेषतया जर्मनी का उदाहरण था जो औद्योगिक प्रगति में इंग्लैंड से बहुत पीछे रह गया था। सारांश यह है कि किसकल कमोशन के बहुमत ने संरक्षण की जिस संकुचित नीति की सिफारिश की, उसका आधार ही गलत था। ग्राम संरक्षण के विरुद्ध कमोशन ने कई तर्क उपस्थित किए जैसे-राजनैतिक भ्रष्टाचार की संभावना, औद्योगिक एकाधिकार की प्रोत्साहन, अयोग्य उत्पादन की प्रोत्साहन और उपभोक्ताओं को हानि, तथा ग्राम मूल्य वृद्धि की संभावना। पर कमोशन के ये तर्क या तो असत्य थे या असंगत। उदाहरण के लिए संरक्षण से अयोग्य उत्पादकों को प्रोत्साहन तभी मिल सकता है जब कि संरक्षण का दर अत्यधिक हो। और इस बात का कि संरक्षण नीति संकुचित है अथवा नहीं, इससे कोई सम्बन्ध नहीं आता। इसलिए ग्राम संरक्षण नीति के विरुद्ध अपने आप से यह कोई तर्क नहीं हो सकता। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो यह प्रश्न तो संरक्षण से सम्बन्ध नहीं रखता। इसका सम्बन्ध तो संरक्षण किस मात्रा में दिया जाता है, इस बात से है। उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ डालने का प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। इसका सम्बन्ध भी संरक्षण के दर और समय से है। इसी प्रकार यह बात भी समझ में नहीं आती कि संकुचित संरक्षण नीति को अग्राने मात्र से राजनैतिक भ्रष्टाचार अथवा औद्योगिक एकाधिकार की संभावना क्यों कर नहीं रहती। कमोशन का यह मय कि ग्राम संरक्षण नीति को स्वीकार करने से मूल्य-वृद्धि होगी और उसका कुपरिणाम हमारे निर्यात पर पड़ेगा जिससे विदेशी-व्यापार का संतुलन हमारे विरुद्ध हो जायगा—निराधार ही गानना

चाहिये। इसके साथ ही साथ यदि रखने की बात यह भी है कि यदि राष्ट्र की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ समय तक विदेशी व्यापार का संकुचन हमारे विरुद्ध भा जाता हो तो उसका चिन्ता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि निम्नलिखित कमीशन के अनुमति से संकुचित सरक्षण के पक्ष में चिन्ते भी एक उपायमय किए उनमें कोई तथ्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इसी बात को लेकर अल्पमत का मतभेद था जो आम जनता का अधिक उदार नीति के पक्ष में। इसका यह अर्थ लगाना भूल होगी कि अल्पमत अत्यधिक अथवा अमर्यादित और विपक्षीय सरक्षण के पक्ष में था। अतः, हमारी राय में अल्पमत का दृष्टिकोण अधिक गहरा था और संकुचित सरक्षण नीति का अमर्यादितता या एक जीवन प्रमाण्य यह भी है कि इस नीति के कार्य काल में देश के उद्योग धर्मों का विकास अल्पमत में गति में हुआ।

संकुचित सरक्षण नीति का एक माय दोष नहीं था कि वह प्रत्यक्ष उद्योग पर अल्पमत अल्पमत प्रचार करने के पक्ष में थी। उक्त नीति के अनुसार तो देखिए यदि उन उद्योगों के प्रिय में भी विचार नहीं कर सकते या जिनके मार्ग विनाश की समाप्ति मानी जा सकती हो। निम्नलिखित कमीशन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह मत व्यक्त कर दिया था कि जो उद्योग अब स्थापित ही नहीं हुए हैं उनको किसी प्रकार की सहायता देने का प्रयत्न नहीं करना। यह नीति यह उपनामा उद्योगों को विकसित होने में रोकने में सफल हुई। इससे अनिष्टित क्रमागत ने उद्योगों को सरक्षण देने के सम्बन्ध में किम्विधा प्रतिपक्ष की विचारिता का है यह भी दोषपूर्ण और असंगत है। पहला बात यह है कि ज. शर्मे उसमें नहीं गई है वे बहुत कठिन हैं। किसी भी उद्योग का सरक्षण देने का मुख्य आधार उत्पादन लागत होना चाहिये। अगर यह माना जा सकता है कि कोई उद्योग एक उचित समय में अपने उत्पादन-लागत को हम मर्यादा में ला सकता है वह उद्योग अपने पाव पर खड़ा हो जाए तो उस सरक्षण निम्नता चाहिये। यह सबसे शालत है कि सरक्षण पाने के लिए किसी भी प्रकार के प्राकृतिक मानकों—जैसे कच्चा माल, आंतरिक बाजार आदि से हाना अनिवार्य माना जाए, जैसी कि निम्नलिखित कमीशन ने विचारित की। इसका यह अर्थ कदापि न लगाया जाय कि इन तमाम सुविधाओं का सरक्षण पाने न पाने में कोई सम्बन्ध नहीं आता है। तथ्य की बात यह है कि इन बातों का महत्त्व वहीं तक है जहां तक वे उत्पादन-लागत पर अगर डालते हैं। पर किसी भी उद्योग को सरक्षण देने अथवा नहीं देने का निर्णय अन्तर्गत या उत्पादन-लागत के आधार पर जाना चाहिये। अगर हम दूसरे देश के उद्योगों पर दृष्टिपात करें

तो हम देखेंगे कि बिना कच्चे माल अथवा आन्तरिक बाज़ार की सुविधा हुए भी वे खूब उन्नत हैं। इंग्लैंड कपास उत्पन्न नहीं करता और फिर भी सूती कपड़े का उद्योग वहां का एक प्रमुख उद्योग है। पश्चिमी देशों के उद्योगों का तैयार माल हजारों मील दूर बाज़ारों में विकता है यह भी हम जानते हैं। यह भी बात सही है कि जैसे-जैसे औद्योगीकरण की किसी देश में प्रगति होती है उसी के साथ-साथ उस देश की कय-शक्ति भी बढ़ती है और देश के अन्दर बाज़ार का निर्माण होता है। इसलिए औद्योगीकरण के लिए बाज़ार (आन्तरिक) की शर्त लगाना अपने-आप से भी कुछ उल्टी-सी बात है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि इस सारे मामले में किसकल कमीशन का दृष्टिकोण बहुत ही अवैज्ञानिक और कड़ा रहा। इसका परिणाम भारत की औद्योगिक उन्नति के लिए हानिकारक हुआ। किसकल कमीशन ने संरक्षण देने के बारे में जो तीन पूर्व शर्तें लगाई थीं उनमें पारस्परिक विरोध भी है। उदाहरण के लिए एक शर्त यह थी कि संरक्षण उसी देश में किसी उद्योग को मिलना चाहिये जब कि वह बिना संरक्षण के या तो विलकुल ही थिकसित न हो सके या जिस गति से विकास होना चाहिये यह संभव न हो। पर विचारने की बात यह है कि यदि किसी उद्योग को वे सब प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त हैं जो कि कमीशन की राय में संरक्षण प्राप्त करने के लिए होनी चाहिये, तो उस उद्योग को फिर संरक्षण की आवश्यकता ही क्यों होगी? इसका मीमांसा अर्थ यह है कि कमीशन की प्राकृतिक सुविधाओं वाली शर्त को कुछ ढीला करना होगा। कमीशन की सिफारिशों की परस्पर की असंगति इससे स्पष्ट है।

कमीशन ने जिस संरक्षण-नीति की सिफारिश की उसकी कमियों का विवेचन ऊपर किया जा चुका है। अब हम इस विषय में विचार करेंगे कि उक्त नीति को व्यवहार में लाने के लिए कमीशन ने जो सिफारिश की वह कहाँ तक ठीक थी। इस बारे में कमीशन की जो सिफारिश थी उसी के अनुसार १९२३ ई० में टेरेफ बोर्ड की स्थापना की गई। पहली बात जो इन सम्बन्ध में ध्यान में आती है वह यह है कि जैसा कि अन्य देशों में है, हमारे टेरेफ बोर्ड के विधान, कार्य और कार्यविधि के बारे में सिवा सरकार के व्यापारिक विभाग के एक प्रस्ताव के और कोई कानून नहीं बनाया गया। जहां तक बोर्ड के कामों का सम्बन्ध है सरकार का उपर्युक्त प्रस्ताव बहुत संकीर्ण है। इस प्रस्ताव के अनुसार बोर्ड का एक मात्र काम संकीर्ण संरक्षण नीति को व्यावहारिक रूप देना था। टेरेफ बोर्ड के मार्ग में यह एक बहुत बड़ी कठिनाई रही। किसकल कमीशन की सिफारिशों के यह सर्वथा विपरीत था। किसकल कमीशन की दृष्टि में टेरेफ बोर्ड का क्षेत्र कहीं अधिक विस्तृत होना चाहिए था। व्यवहार

म टेरेरि बॉट न "रग" क प्रस्ताव र बाहर भा काम दिया। जैस टेरिज रमा नता और चिन्शी माल स अनन्ति न्य ॥ बाहर पाने क दर्शना पर भी टेरेरि बोट न विचार किया। निम्नवत् रमाशन न टेरिज बोट र कामा की ना शिस्त न कल्पना की थी रमम नून मा बाता का समावेश होता था, जैस श्राव की दृष्टि से लगाए गर श्रावण करा क सरक्षण का दृष्टि स हात वाल प्रभाव पर विचार करना साम्राज्य-तमन मुविषा (इम्पारियलप्रिपरेस) श्रीर द्विदशाय सम्मेलन (राइलंदरत एवाम-रुस) क अन्तर पर विचार करना, मन्द ग्याहार और ग्याहन सम्प्रदा दर्शना पर मरुतिन उद्यागा क रिप म विचार करना, भारतीय उद्यागा पर उद्याहन-कर और श्रावत-निर्वात-कर के प्रभाव का अध्ययन करना और उपमानाश्रा क दिन दृष्टि से एकविंशत सम्प्रदा शिक्कापता पर विचार करना। इनक श्रावणा टेरिज बोट का काय पद्धति भा बाधपूर्ण रही। आरम्भ से लहर अन तक टेरिज बोट का सरकार क मन्वावधान में काम करना पड़ता था और काम करने का यह मारा पद्धति एसा था जिसमें समय बहुत लगता था और अनुविषा मा बहुत होता थी। इसका अन्तर सरक्षण चाहने वाले उद्यागा पर बहुत घाव पड़ा था। बोट क काम क शार म अन्वयान्त प्रचार होने से पात्र क विषय का और नमन बहुत कम आकर्षित हो पाता था और प्रतिद्वन्दा ब्रिटिश उद्यागा का, ताम मात्र का भारतीय उद्यागा को दो गद समाप्त मुविषा क नाम पर यह माका दना, कि ॥ सरक्षण सम्प्रदा होने वाली जात्र न सम्भव म सरक्षण चाहने वाले उद्याग से प्रश्नोत्तर कर करते हैं और अपनी गमाहा भी न सकते हैं और भी अनुचित था। बोट का म्य का स्थायित्व नहीं होने से और उसके सदस्या न स्थायित्व मरिष्य हान म तथा तन्वालीन सरकार का इच्छा पर बोट का अस्तित्व निभर होने ॥ भा बोट का बहुत कुछ उपयोगिता कम हो गई। सारांश यह है कि उग मामलों म सुधार का दुरा श्राव स्वकता थी। बोट क काय न न की विस्तृत होना था, उम्हरो एक स्थाया माटन का स्वरूप मिलना चाहिय था, उसके सदस्या को स्थायित्व सम्प्रदाी आराधन जोगा चाहिये था और बोट पर सरकारी अन्तर कम होना आवश्यक था।

अब तह क विवेचा से अनुचित सरक्षण-नीति का अनुपयोगिता मर्या स्तह हो जानी है। इसक अनिरिक्त एर बात यह मा है कि कुछ अन्वदा को छोड़ कर सरक्षण की दृष्टि से जा श्राव कर रूपाए गए क उद्योग-प्रदा न समुचित विज्ञान की दृष्टि से अन्वदा क। प्रथम महायुद्ध क पश्चात् समस्त दुनिया और उसके साथ मारन मा, आर्थिक दृष्टि से एक असाधारण परिस्थिति म ॥ होकर गुजर रहा था। कभी आर्थिक मर्दी का सामना करना पड़ता था तो कभी विदेशों

में सस्ते भावों पर बाजार-घाटने की दृष्टि से भेजे गये माल का । अनुचित प्रतिस्पर्धा और विनिमय-दर के अचमूल्यान के कारण भी कटिनाई आजाती थी । अस्तु, संरक्षण की दृष्टि से जो भी आव-कर लगता था उनका प्रभाव तो उक्त कारणों से उत्पन्न स्थिति का सामना करने में ही समाप्त हो जाता था और उद्योग-धन्यों के विकास के लिए जो विशेष प्रोत्साहन चाहिये था वह नहीं मिल सकता था । “यदि उपर्युक्त असाधारण स्थिति न होनी नो या तो हमारे उद्योगों को संरक्षण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती या बहुत कम संरक्षण से उनका विकास सम्भव हो जाना ।” अस्तु, संकीर्ण संरक्षण-नीति से भी देश के उद्योग-धन्यों को जो लाभ पहुँचना वह भी विशेष आर्थिक परिस्थिति के कारण नहीं पहुँच सका ।

संकीर्ण संरक्षण नीति के व्यवहार के सम्बन्ध में भी कई खोप पाए गए । डेरिक बोर्ड ने जो-जो जांच की और सरकार ने उन पर जो कार्रवाई की उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने सिद्धान्ततः जिन संरक्षण-नीति को स्वीकार कर लिया था उसको व्यवहार में लाने का उसे उतना उत्साह नहीं था । नारी कार्रवाई में जितना समय लग जाता था और बोर्ड की सिफारिशों को सरकार जितना महत्त्व देती थी वह यह बतलाता था कि वास्तव में सरकार देश के औद्योगीकरण और संरक्षण नीति के पक्ष में नहीं थी । और भारत और इंग्लैंड के हितों में विरोध पड़ने का प्रश्न तो अन्ततोगत्वा उपस्थित होता ही । यह तो नाक ही था कि भारत का औद्योगीकरण इंग्लैंड के उद्योगों के लिए हानिकर साबित होता । फिसकल नीति के सम्बन्ध में भारत को स्वतंत्रता मिलने का यदि कोई अर्थ था तो सबसे पहले यह था कि सर्व प्रथम भारत-सरकार भारतीय दृष्टि से विचार करने के लिए तैयार और स्वतंत्र है और अन्य देशीय दृष्टि, जिनमें इंग्लैंड भी आजाता है, इसके बाद आती है । भारत के स्वतंत्र हुए बिना यह सब कुछ असम्भव था । अस्तु, फिसकल नीति सम्बन्धी भारत को दी गई स्वतंत्रता नाममात्र की ही थी । भारत और ब्रिटेन में जो हितां का संघर्ष रहा उसके सम्बन्ध में श्री अष्टाकर ने अपनी ‘इंडियन फिसकल पोलिसी’ नामक पुस्तक में लिखा है “(१) जहाँ संरक्षण से सुख्यन, अथवा केवल ब्रिटेन के अलावा दूसरे हितां को हानि पहुँचने का संभावना रही वहाँ सरकार ने बहुत करके संरक्षण स्वीकार किया । (२) जहाँ संरक्षण के कारण मुख्यतः ब्रिटिश हितां को हानि पहुँचने का संभावना होती वहाँ संरक्षण के प्रति उपेक्षानीति बरती गई । (३) जहाँ दोनों बातें सम्भव हो सकती थी, अर्थात् ब्रिटेन के हितां का रक्षा करते हुए दूसरे राष्ट्रों से आने वाले माल को संरक्षण दिया जा सकता था, वहाँ दस प्रकार की समझौता-नीति का पालन किया गया और संरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया । (४) बहुत

थोड़े उद्योगों के मामले में जैसे कामच, टीन की चादर जहाज निर्माण आदि के उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार ने सराफा मालिगाना स्थापित की, क्योंकि भारत में सराफा का काम उठाने के लिए ब्रिटिश कारखानों मात्र से यह और विशुद्ध उद्योगों के विरोध का उत्पन्न द्वारा निराकरण हो सकता था।" मंदी से सराफा मालिगाना एक बान और रह जाती है जिससे उल्लेख कर जना में आवश्यक है। इस एक बात का सम्बन्ध सामान्य जन सुविधा (पब्लिक प्रिविलेज) से है जहाँ परिस्थितियों के बावजूद साराफा मालिगाना में १९१२ में स्थापित की गई। इस समय हम सामान्य जन सुविधा मालिगाना के विवेचन नहीं करेंगे। बल्कि यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हम जानते हैं कि कारण मंदी से जन सुविधा का ठीक ठीक व्यवहार मालिगाना में भी अक्षम उपस्थित है। इस कारण में भारत में जिन मालिगानों की स्थापना उसी उपयोगिता के होगी।

द्वितीय महायुद्ध और राजकीय नीति—द्वितीय महायुद्ध के आरंभ होने पर देश के सामने औद्योगिक प्रसार का एक अत्यन्त अचानक उपस्थित हुआ। यद्यपि हम उस अचानक से पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सके, पर फिर भी युद्ध की हम से तत्कालीन सरकार की इस ओर थोड़ा-बहुत ध्यान तो देना ही पड़ा। जून १९४० के एक सूचनापत्र द्वारा भारत सरकार ने यह घोषणा की कि जो उद्योग युद्ध के लिए आवश्यक हान से स्थापित होंगे उनका युद्ध के बाद में यदि जरूरत होगी तो बाहरा प्रविवेध से सराफा मालिगाना दिया जायेगा। नवम्बर १९४५ में एक अन्तरिम गैलरी टारिफ बोर्ड का भी नियुक्ति का यह तारीख तय करने वाला उद्योगों के बारे में विचार दिया जा सके। विमानन के परवाने नवम्बर १९४७ में बोर्ड का द्वारा विमानन दिया गया। उसके कार्यक्षेत्र का भी पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत दिया गया। विदेशी माल के मुकाबले में भारतीय माल का उत्पादन-लागत के अधिक होने के तथा कारण है और माल से माल लागत पर देश में उत्पादन-वृद्धि करने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिये—य प्रश्न भी अब टारिफ बोर्ड के विचार-निर्णय के अन्तर्गत आया। टारिफ बोर्ड में उद्योगवाद दो सदस्य और वन गैर हैं और अगस्त, १९८८ के भारत सरकार के एक प्रस्ताव के अनुसार उनमें राजस्व मंत्री और अधिक वृद्धि कर दे गये हैं। टारिफ बोर्ड के नाम से हैं—विमानन का उत्पादन-लागत मान्य करना और उसका थोक, पुष्टकर तथा दूसरे मूल्यों का निमात्र करना। विदेशी माल के राशिपातन [डंपिंग] से भारतीय उद्योगों का संरक्षण करने के उपाय उपलब्ध, दूसरे देशों के माल पर प्रत्युत्क (टारिफ) सम्बन्ध रियायत और

आयात-कारों के असर का अध्ययन करना; संरक्षित उद्योगों में एकाधिकार के बारे में और उनके उत्पादन के ह्रास और कीमतों के कायम करने और बढ़ाने के सम्बन्ध में होने वाले असर के बारे में रिपोर्ट करना और निराकरण के आवश्यक उपाय सुझाना, एवं संरक्षित उद्योगों की प्रगति का ध्यान रखना तथा संरक्षण की शर्तें पाली जा रही हैं और कार्य-कुशलता बनी हुई है इन और भी ध्यान देना। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात् भारत सरकार ने अपना औद्योगिक नीति की घोषणा में यह स्पष्ट कर दिया था कि उत्कर्ष प्रशुल्क (टेरिफ) नीति का लक्ष्य अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा से भारतीय उद्योगों का संरक्षण करना और उपभोक्ताओं पर अनुचित भार डाले बिना भारतीय साधनों का श्रद्धा से श्रद्धा उपयोग करना होगा। अप्रैल १९४६ में फिसकल कमीशन की नियुक्ति की गई और १९५० के मध्य में कमीशन की रिपोर्ट भी प्रकाशित होगई। इस कमीशन का भी यही निर्णय है कि द्वितीय महायुद्ध के पहले की प्रशुल्क नीति अपने सर्वाधिक क्षेत्र में तो काफ़ी हद तक सफल हुई, पर देश की अर्थ व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में अमी विकास की बड़ी कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिये बड़े प्रयत्न की आवश्यकता होगी। औद्योगिक उन्नति की दृष्टि से प्रशुल्क नीति के संबंध में इस कमीशन का भी यही मानना है कि उद्योग-धन्वों का संरक्षण देश के संपूर्ण आर्थिक विकास से सम्बद्ध होना चाहिये नहीं तो संरक्षण का भार असमान और उद्योग-धन्वों की प्रगति असमन्वित हो सकती है। (फिसकल कमीशन की सिफारिशें परिच्छेद के अन्त में परिशिष्ट के रूप में दी गई हैं)।

हमने जो कुछ अब तक लिखा उसका सार यही है कि भारत की औद्योगिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि हमारा देश संरक्षण नीति को स्वीकार करे। लिस्ट का 'घन उत्पन्न करने की क्षमता' और 'औद्योगिक विकास की दृष्टि से सर्वथा नया देश' सम्बन्धी तर्क भारत के सम्बन्ध में इसी नीति को अपनाने के पक्ष का समर्थन करते हैं। मार्शल और पीगू जैसे निर्बाध व्यापार के समर्थकों ने भी इस तर्क को स्वीकार किया है। अस्तु, संरक्षण के विरुद्ध जो तर्क उपस्थित किए जाते हैं और भारत के सम्बन्ध में वे कहाँ तक लागू होते हैं इस पर अब हम विचार करेंगे।

भारत की संरक्षण-नीति की आवश्यकता—संरक्षण-सिद्धान्त के विरुद्ध जो तर्क उपस्थित किये जाते हैं उन पर विचार करने के पहले दो बातों की ओर संकेत करना आवश्यक है। एक तो यह कि हमें इस समस्या पर दीर्घ कालिक दृष्टि से विचार करना है। दूसरे यह कि देश के साधनों का पूर्णतया उपयोग हो, इसके साथ-साथ यह भी देखना होगा कि हमारा राष्ट्र आज के हिंस और

प्रतिस्पर्द्धा के युग में दूसरे राष्ट्राँ के मुकाबले में अपनी अतिवृत्ति कायम रख गये। इस दृष्टि से जना और जातों का अविवाय व्यापार भव आनन्दप्रकाशों के मामलों में हम स्वायत्तकी बना रहा अन्य अनेक मामलों के अन्तर्गत रहना होगा। केवल आर्थिकवाद के नाम पर हम उरु शक्ति की भाव का अदहेषना नहीं कर सकते।

मरुतुण के विपक्ष में एक बड़ा तर्क यह है कि यह सम्भावना है। हानि पड़ती है और भी उत्पादनकर्ता का लाभ पड़ता है। इस अर्थ में यह तर्क गलत है कि मरुतुण नाति के कारण विपक्ष में आता बाल आयात पर कर लगने से उनका मुख्य में जो हानि होता है उसका अन्तर्गत विपक्षी उत्पादन कर्ता वयागमय उपभोक्ता पर डालने का प्रयत्न करना है। इस हानि के मुकाबले में मरुतुण से मिलने वाले लाभ का हम विचार करना चाहिये। यहाँ तक विदेशी माल की मुख्य हानि का सवाल है, यह मुख्य हानि प्रत्यक्षान्वित का मत है। मरुतुण के कारण जो राष्ट्रीय उद्योग भला प्रकार विकसित हो पाएँगे तो यह समझना है कि वे मरुतुण के पहले विंग भाव पर विदेशी माल विदेशी या उमा या उमम भी मरने मात्र पर उस माल का बच सकें। यह टाँक है कि विदेशी के मुकाबले में अपने देश में उत्पादन लागत मरुतुण का स्थिति द्वारा उस पर यह निर्भर होगा। दूसरे मरुतुण के कारण न केवल मरुतुण किन्तु आम तौर से या उपयोग पक्षों की प्रगति द्वारा उसमें देश का आर्थिक बढ़ेगी और उपभोक्ताओं का बढ़े हुए मुख्य से जो भी हानि सम्भव है उसका मुकाबले में यह लाभ उठाने होगा। मरुतुण से मिलने वाला सबका बड़ा लाभ यह है कि देश के समस्त स्थानीय उद्योगों का उपयोग का मरुतुण और यदि इस कारण से थोड़ा बहुत मुख्य-हानि हो तो उसका बारे में कोई आपत्ति का बात नहीं हो सकता। मरुतुण के कारण बढ़े हुए मुख्य के रूप में सम्भावनाओं का अनुचित हानि नहीं उठाना पड़े इस दृष्टि में यह दृष्टव्यता होगी कि मरुतुणमय मरुतुण व्यवस्था का आधार एक सुगम-हित और सम्भवित तथा समस्त राष्ट्र का सामने रखकर बनाई गई औद्योगिक विकास का यत्न है। इस स्थिति में यदि राष्ट्र के किसी एक अर्थ का आशा त्याग मा करता पड़े तो यह करना चाहिये।

मरुतुण के विपक्ष दूसरा आपत्ति यह है कि उसका देश का कर-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। करा का बोझ घनवानों की अपेक्षा विधियों पर अधिक बढ़ जाता है। कारण यह है कि उपयोग का वस्तुओं पर कर लगने पर परिवार अपेक्षा करा में हानि करना होता है और अपेक्षा कर उपयोग का वस्तुओं पर होने से उनका बोझ-आम लोगों पर अधिकपड़ता है। यह तर्क वास्तव में विंग समझ सिद्धता लागू

होगा इसका अनुमान तो इसी से लगाया जा सकता है कि जिन वस्तुओं को संरक्षण दिया जाने वाला है वे आम उपभोग की हैं अथवा नहीं। यदि वे किसी वर्ग-विशेष के उपभोग में ही आने वाली हैं तो उनका असर भी आम जनता पर न पड़े उस वर्ग विशेष तक ही सीमित रहेगा। पर वास्तव में विचारणीय प्रश्न तो यह है कि इस तरह का बोझ पड़ने देना उचित है अथवा नहीं। कर-व्यवस्था को प्रगतिशील बनाने का जहाँ तक सम्बन्ध है वह नए प्रत्यक्ष कर लगाकर भी बनाई जा सकती है। और उपभोक्ताओं के बोझ को भी वास्तव में हल्का किया जा सकता है यदि करों में होने वाली आय समाज की मलाई के कामों में व्यय की जा सके।

संरक्षण के विपक्ष में एक इलील यह भी है कि सरकार की आय पर उसका अगर अच्छा नहीं पड़ता। यदि वर्तमान आय-कर विदेशी माल को आने से रोकने की दृष्टि से बढ़ाया जाता है तो थोड़े समय के लिए सरकारी आय पर थोड़ा असर अवश्य पड़ेगा। किन्तु अन्ततोगत्वा संरक्षण राष्ट्र के औद्योगीकरण में सहायक होगा और इस प्रकार उसके द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, तो सरकारी आय के भी कई नए स्रोत निकल आवेंगे। अल्प काल में भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि संरक्षण का परिणाम राज्य की आय कम करना ही होगा।

संरक्षण के विरुद्ध जितने भी तर्क उपास्थित किए गए हैं उनमें सब में ही अलग-अलग से विचार करने पर कुछ न कुछ सत्यता का अंश अवश्य है। पर उनके बारे में इस प्रकार से विचार करना सही नहीं है। हमें राष्ट्र के सम्पूर्ण हित की दृष्टि से, न कि केवल आर्थिक दृष्टि से ही इन बातों पर विचार करना चाहिये। यदि राष्ट्र के सम्पूर्ण हित की दृष्टि से संरक्षण नीति को अपनाना आवश्यक है तो उसे अपनाना चाहिये, फिर चाहे किन्हीं एक दृष्टि अथवा दूसरी दृष्टि से ऐसा करना उचित न मालूम पड़ता हो। संरक्षण के विरुद्ध एक बहुत बड़ी आपत्ति यह भी उठाई जाती है कि उसके कारण आर्थिक स्थिर हित और राजनैतिक भ्रष्टाचार उत्पन्न होते हैं। हमें वहाँ यह बात नहीं भूलना चाहिये कि आर्थिक स्थिर स्वार्थ पूँजीवादों व्यवस्था के अवश्यम्भावी परिणाम हैं। संरक्षण इन स्थिर स्वार्थों का कारण इस वजह से समझा जाता है कि वह औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देता है। यह दोष तो है पर उसका इलाज यह नहीं है कि औद्योगीकरण ही न किया जाए। इस दोष को क्या शक्ति कम से कम करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। इसका एक उपाय यह है कि जनता के हितों की रक्षा करने के लक्ष्य से सरकार संरक्षित उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखे। इतना ही

देश की औद्योगिक उन्नति के लिए संरक्षण-पद्धति के स्थान पर दूसरे सरल सीधे और अधिक फलदायी उपायों को काम में लिया जाय। ये दूसरे उपाय आयात की मात्रा निश्चित करना, विनिमय नियंत्रण और द्विराष्ट्रीय समझौते हैं। ये उपाय वास्तव में कितने सरल हैं यह भी एक विवाद का प्रश्न है। पर जो कुछ भी हो, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए संरक्षण-पद्धति का सर्वथा परित्याग नहीं किया जा सकता।

राजकीय सहायता के अन्य प्रकार—औद्योगिक उन्नति को प्रोत्साहन देने के लिए जिन उपायों का ऊपर विवेचन किया गया है उनके अतिरिक्त कुछ दूसरे उपाय भी हैं। उनका संक्षेप में हम यहां उल्लेख करेंगे।

कच्चे माल को बाहर जाने से रोकने के लिए, ताकि देश के उद्योगों को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके, निर्यात-कर लगाना भी उद्योग-धन्वों को प्रोत्साहन देने का एक उपाय है। इसके बारे में विचारणीय प्रश्न एक ही है और वह यह कि उत्पादन-कर्ता अर्थात् व्यवसायी को थोड़ा-सा लाभ पहुँचाने के लिए कच्चे माल को पैदा करने वालों को बहुत हानि तो नहीं उठानी पड़ती है। औद्योगीकरण में सहायता पहुँचाने का दूसरा उपाय यह है कि उद्योग-धन्वों के काम में आने वाला जो कच्चा माल अथवा मशीन आदि बाहर से आती हैं, उन पर आयात-कर न लगाया जाए।

औद्योगिक उन्नति में राज्य देश को वैकिंग व्यवस्था को सही आधार पर विकसित होने में मदद पहुँचा कर, रेल और जहाजों के किरायों के सम्बन्ध में उदार नीति बरत कर और विक्री के लिये अच्छी व्यवस्था खड़ी करके भी सहायता पहुँचा सकता है। व्यापारिक और औद्योगिक सूचना प्राप्त करने को सुव्यवस्था करने का भी बड़ा महत्त्व है। पराधीन भारत में इन नव मानकों में असन्तोषजनक स्थिति रही। आज भी स्थिति पूर्णतया संतोषप्रद नहीं मानो जा सकती। उदाहरण के लिए भारतीय रेलों के किराये सम्बन्धी नीति के बारे में क्रिसकल कमीशन का यह कहना है कि अक्टूबर १९४६ से किराये की जो मंशोधित दरें लागू की गई हैं उनके परिणामस्वरूप रेलवे की किराये की दरों का वैज्ञानिक तो दुष्टा है और फ्रांस के बढ़ने के साथ-साथ किराये में कमी भी की गई है, पर कुछ दूसरी समस्याएँ खड़ी हो गई हैं। कमीशन ने इस प्रश्न पर रेलवे बोर्ड द्वारा दुबारा विचार करने की सिफारिश की है ताकि उद्योगों के विकेन्द्रीकरण और खाद्य या खनिज पदार्थ को अपने ही स्थान तथा प्रदेश में तैयार माल में बदलने में अधिक सहायता मिल सके। इसी प्रकार देश की वैकिंग व्यवस्था में भी कई प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, जैसे व्यापारिक बैंक औद्यो-

शिक्षक पूजा के बारे में अधिक उदात्त भावना को व्यक्त कर और विगत प्रकार के एक स्थापित सिद्धे जाय। व्यावहारिक और औद्योगिक शिक्षा के लिए केन्द्रों पर कार्य के व्यावहारिक सूचना और उद्देश्य विभाग के अन्तर्गत राज्य की मांगों के औद्योगिक विभागों में भी सूचना सम्बन्ध में आवश्यकताओं को पूरा करना है। परन्तु यह व्यवस्था मनोरन्जन नहीं है। गणकारी तथा सूचनाएँ पुरानी शैली हैं और अपूर्ण भी होना हैं।

— औद्योगिकीकरण के लिए अनुसूचित योजनाएँ बनाने की आवश्यकता का भाव बढ़ा महत्व है। अमेरिका में यह मामला शिक्षा पद्धति का प्रभावित किया उसका फल स्वरूप हाथ के काम से देश के नवपुरजों में अग्रणी पत्र दूरी। पुनर्जीव शिक्षा पर जोर होने से विद्यार्थी का दृष्टिकोण भी नया मान्य करने पर। इस स्थिति में सामान्य परिवर्तन की आवश्यकता बन समय में अनुभव में आ रहा है। तत्कालीन भारत सरकार के नियंत्रण पर नवम्बर १९०६ में भारत में शिक्षा विभाग का एक और एक एक बुद्धि आया था। जन १९१३ में उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश की। उसमें भी हमें जान पर जोर दिया गया कि भारतभर में शिक्षा प्रदान करने में पुनर्जागरण है। अनुचित है। विपरीत समाधान में भी यह विचारों का था कि सरकार का दक्षिण शिक्षा की और ध्यान देना चाहिये। अब कर्मचारियों और कमरेदारों में भी इस बात की कल्पना है। उदाहरण के लिए औद्योगिक कर्मचारियों (१९१६-१८) रेलवे विभाग में विभाग में कर्मचारियों (१९१७-१९, जाकिर हुसैन कमेटा (१९३३) टेक्निकल और औद्योगिक शिक्षा सम्बन्धी समिति (१९३३) और भारत सरकार द्वारा टेक्निकल शिक्षा पर विचारों का मुद्रास्थान आवश्यकता पूरा करने का दृष्टि से विचार करने के लिए नियुक्त सार्वजनिक समिति (१९६०) इन सब ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा पुनर्जीव होकर अब व्यावहारिक होनी चाहिये। दो बातों पर विशेषतया ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली में बच्चे की शिक्षा का और विशेष मुकाबला होना चाहिये। वर्षों शिक्षा प्रणाली इस दृष्टि से एक प्रयत्नाय प्रयत्न है। इस पद्धति में देश में अधिकाधिक प्रचार होना चाहिये। दूसरा बात यह है कि हमारा आवश्यकतानुसार टेक्निकल शिक्षा देने के बाला मर्यादा का देश में स्थापना होना चाहिये। उसी सम्भावनाओं का आज भाग्य है। ऊँच दर्जा के काम करने वाला—जैसे फोरमन, मनेजर आदि के लिए आवश्यक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। भारत सरकार और राज्य के सरकारों को भिन्नतुल्य कर इस दिग्दर्शक में एक व्यवस्थित योजना के अनुसार काम करना होगा। देश में टेक्निकल शिक्षा सम्भावनाओं को स्थापित करने

के अलावा, छात्रवृत्ति देकर भारतीय छात्रों को शिक्षा के लिए विदेशों में भेजना होगा। विदेशी कमनियों से भी माल खरीदने की एक शर्त यह लगाई जा सकती है कि वे भारतीय विद्यार्थियों को आवश्यक टेकनिकल शिक्षा दें। हमारी केंद्रीय और राज्य की सरकारों का इस ओर ध्यान है और इस दिशा में वे प्रयत्नशील होने की चेष्टा भी कर रही हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के अनुसार १९४५ में भारत सरकार ने अन्विल भारतीय टेकनिकल शिक्षा कॉमिल की स्थापना की जिसका काम-उच्च टेकनिकल शिक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार की सलाह देना है। सुदोत्तर-शिक्षा-योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में टेकनिकल स्कूलों और पॉलीटेकनिक तथा औद्योगिक स्कूलों की स्थापना हुई है। भारत सरकार ने भी टेकनिकल शिक्षा के प्रचार की ओर ध्यान दिया है। दिल्ली के पोलिटेकनीक का विस्तार किया गया। हाल ही में बिजला (५० बंगाल) में इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर टेकनालाजी की भारत सरकार ने स्थापना की है। दूसरे स्थानों पर भी ऐसी इन्स्टीट्यूट स्थापित करने का विचार है। बंगाल के इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स के विकास में भारत सरकार योग दे रही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार विदेश में शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ भी देती है। यहां एक बात का उल्लेख कर देना और आवश्यक है कि टेकनिकल शिक्षा से पूरा लाभ उसी दशा में संभव होगा जबकि उद्योग-धन्य और शिक्षा-संस्थाओं में निकट का सम्पर्क रहे।

औद्योगिक अन्वेषण का प्रश्न भी बड़ा महत्व का है। देश की औद्योगिक व्यवस्था का अन्य उन्नत राष्ट्रों की औद्योगिक व्यवस्था के बराबर रखने की दृष्टि से तथा उन विषय में बराबर उन्नति का द्वार खुला रखने की दृष्टि से भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र में औद्योगिक अन्वेषण की समुचित व्यवस्था हो। बड़े-बड़े व्यवसायों और राज्य दोनों का ही इस सम्बन्ध में बहुत बड़ा कर्तव्य है। सरकार का कर्तव्य है कि गैर सरकारी प्रयत्नों को आर्थिक सहायता तथा आवश्यक मार्ग दर्शन और समन्वय द्वारा प्रोत्साहन दे। इस क्षेत्र में विश्व विद्यालय भी औद्योगिक अन्वेषण के स्वतन्त्र विभाग स्थापित करके बहुत कुछ काम कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों को उद्योग-धन्य का पूरा सहयोग मिलना चाहिये। सरकार को भी इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएँ स्थापित करना चाहिये। नाथ ही इस प्रकार के सरकारी तथा गैर सरकारी सब प्रयत्नों में समन्वय की भी बहुत आवश्यकता है। एक या दो अपवादों को छोड़कर भारतवर्ष में औद्योगिक अन्वेषण का अभी तक अभाव ही रहा है। भारत के अधिकांश उद्योग-धन्य छोटे अथवा बीच के दर्जे के हैं और अल्पे औद्योगिक खोज के क्षेत्र स्थापित

करना उनकी शक्ति न बाहर की बात है। इस देश में संगठित औद्योगिक खोज का प्रारम्भ हुए बहुत समय नहीं हुआ है। विभिन्न पदार्थों संबंधी समितियों, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि मिति, भारतीय कपड़ा मिति और भारतीय राष्ट्रीय लाल उपकरण (सेम) मिति आदि में नव स्थापना हुई तो इन में से प्रत्येक के साथ एक कनालानिजल इन्स्टीट्यूट भी स्थापन किया गया। इस देश में संगठित औद्योगिक खोज का यही प्रारम्भ था। परन्तु कि उपर्युक्त समितियाँ कृषि-क्षेत्र से सम्बन्ध रखती थीं, इस लिए इनसे सम्बन्ध रखने वाली तकनीकी कानिजल इन्स्टीट्यूट्स में औद्योगिक खोज में न केवल काम किया। देश के विभिन्न भागों में कुछ स्वतन्त्र रिसर्च इन्स्टीट्यूट्स भी कार्यरत हुए हैं, परन्तु इन्होंने आधारभूत वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल प्रयोगों पर अधिक ध्यान दिया है तथा उद्योग पक्षों से सम्बन्ध रखने वाला समस्या विरोध की ओर उनका ध्यान कम रहा है। इस कारण से उनसे भी देश के उद्योग पक्षों को विशेष लाभ नहीं हुआ है। ध्यान की ओर से इसका कारण यह भी रहा है कि उनका उद्योग-पक्षों से सम्बन्ध भी बहुत कम रहा है। सरकार ने भी इस दिशा में पिछले वर्षों में कुछ प्रयास किए हैं और अब तो इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पाचवें औद्योगिक सम्मेलन (१९६४) की सिफारिश के परिणामस्वरूप 'इण्डस्ट्रियल रिसर्च ब्यूरो' का प्रारंभ १९६५ में स्थापना की गई जिसका महायन्त्रा और सलाह के लिए 'इण्डस्ट्रियल रिसर्च कॉमिटी' भी स्थापित का गये। यह रिसर्च ब्यूरो इन्विजन स्टॉक डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है। इसका काम औद्योगिक जानकारी एकत्रित करना प्रारंभिक, औद्योगिक खोज में उद्योग पक्षों का साथ देना और औद्योगिक प्रदर्शनों के संगठन में महायन्त्रा पदवर्ती आदि है। सन् १९४० में एक नई संस्था 'बोर्ड ऑफ साइंटिफिक एंड इण्डस्ट्रियल रिसर्च' नाम की स्थापित हुई है। इससे तत्कालीन में देश के विभिन्न भागों में कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। औद्योगिक खोज का क्षेत्र तो बहुत प्रसृत है। पर आवश्यकता इस बात की है कि जाने वाले कुछ वर्षों में निम्नलिखित समस्याओं पर ही विशेष ध्यान दिया जाए—उत्पादन क्रिया, पेटेंटियों में काम करने की परिस्थितियों और उनका काम करने वालों के स्वास्थ्य और कुशलता पर प्रभाव, यान्त्रिक सम्बन्धी खोज, और प्रचलित संबंधी खोज। इस प्रकार के खोज कार्य के मुख्य उद्देश्य होने कच्चे माल में सुधार करना, नैयार माल में सुधार करना, कच्चे माल से तैयार माल का मात्रा में वृद्धि करना, और उत्पादन क्रिया में सुधार करना ताकि प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ा सके। औद्योगिक खोज के सम्बन्ध में दूसरी महत्व की बात यह है कि इस कार्य में सरकार और उद्योग पक्षों को

सम्मिलित प्रवृत्ति करने चाहिये। अन्तर्गतवाट टेक्स्टाइल इन्स्टीट्यूट रिमर्च ऐसोसिएशन द्वारा स्थापित रिसर्च इन्स्टीट्यूट इन सम्मिलित प्रवृत्ति का एक अच्छा उदाहरण है और सरकार के जो उन्में मददगारी की है वह प्रशंसनीय है। एक और ध्यान देने की बात यह है कि राजस्व संबंधी विभिन्न संस्थाओं के कार्य को व का उचित व्यवस्था होना चाहिये और उद्योग-धर्मों और सरकार द्वारा जो चलन-चलन, प्रवृत्ति हैं उनमें इन्विन सम्मिलन होना चाहिये। जैसे इन समय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ, टेक्नोलॉजिकल रिमर्च इन्स्टीट्यूट्स जो विभिन्न पदार्थ सम्मिलितों में सम्मिलित हैं, इन्विन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स (बंगलौर) जैसे विज्ञान संस्थानों, और विश्व-विद्यालयों द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट्स जो देश में चल रहे हैं उनमें जैवों का समुचित व्यवस्था होना चाहिये। इनके प्रकाशित प्रोजेक्ट्स और उद्योग-धर्मों के पारस्परिक स्थायी सहयोग की पूर्ण आवश्यकता है। इनमें उद्देश्य में एक बात तो यह भी है कि राष्ट्रीय भौतिक ज्ञान प्रयोगशाला और रसायन-विभाग प्रयोगशाला (नेशनल किजिकल लैबोरेटरी ऑफ ने० टेक्निकल लैबोरेटरी) के द्वारा प्रत्येक प्रयोगशालाओं की सरकारी विभाग के तौर पर न चला कर स्वतंत्र प्रोजेक्ट-संस्थाओं के रूप में चलाना चाहिये और उद्योग-धर्मों पर उनके सम्मिलन में बड़े योगदान होना चाहिये।

उद्योग-धर्मों को प्रोत्साहन देने का सरकार के पास एक उपाय यह भी है कि वह अपनी आवश्यकताएँ राष्ट्रीय मातृ द्वारा भी पूर्ण करे। इन दिनों में भी पराश्रित भारत में सरकार की नीति बराबर आलोचना का विषय रही। यहाँ तक कि सरकार द्वारा नियुक्त औद्योगिक कमीशन ने भी इन दिनों में सरकार की नीति की आलोचनाएँ की हैं। सरकार ने भी स्वीकार किया कि उपयुक्त व्यवस्था न होने से यह कमी रही कि जो मातृ भारत में खरीदा जा सकता था वह भी इंग्लैंड से आया गया। तत्कालीन भारत-सरकार की स्वीकृत नीति के भी यह विरोध था। औद्योगिक कमीशन की निवारण के अनुसार इस प्रश्न पर विचार करने के लिए १९२१ में 'स्टोर्ग परचेज कमेटी' की नियुक्ति की गई। उस कमेटी ने भी कमीशन की इस राय का समर्थन किया कि सरकार द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं के निरीक्षण के लिए एक केन्द्रीय विशेषज्ञ विभाग की स्थापना होनी चाहिये। अस्तु, इन्विन स्टोर्ग विभाग की स्थापना हुई। इसकी सेवाओं का लाभ केन्द्रीय सरकार के अलावा राज्य की सरकारों तथा स्वतंत्र शासन संस्था आदि को भी मिलता है। यह विभाग एक मलाहकार के रूप में काम करता है। और खरीदने, और खरीदे जाने वाले माल को जांच करने तथा मूल्य आदि

व्यवस्था करने के वास्ते राज्य का क्या कर्तव्य है यह हम आगे के परिच्छेद में लियेंगे। यहाँ हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि इन कार्य में भी राज्य का पूरा सहयोग चाहिये। सारांश यह है कि बिना राज्य के क्रियात्मक सहयोग के देश की औद्योगिक उन्नति संभव नहीं है। प्रथम महायुद्ध ने नव्कार्लिन भारत सरकार के इण्डिकोण में थोड़ा परिवर्तन किया था। द्वितीय महायुद्ध ने इस इण्डिकोण को और प्रोत्साहन दिया। विभिन्न राज्यों के औद्योगिक विभागों ने भी टेक्निकल और इन्वेंस्ट्रियल शिक्षा, औद्योगिक सूचना, उद्योग वन्धों को आर्थिक सहायता (छोटे और कुट्टिर उद्योगों को) और क्रय-विक्रय स्टोर्स और प्रदर्शनिशों की व्यवस्था करके औद्योगिक प्रगति में सहायता देने का बराबर पिछले कई वर्षों से प्रयत्न किया है। जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से केंद्रीय और राज्य की सरकारों ने इस ओर विशेष ध्यान देना आरंभ किया है। इस सम्बन्ध में अन्वय हम विस्तार में लिख चुके हैं। यहाँ तो इतना बूझना ही काफी है कि राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद देश की प्रमुख समस्या आर्थिक ही है और यह वर्षों शानिपूर्वक हल हो सकेगी जब सरकारें, जनता, उद्योगपति और मजदूरगर्ग सभी राष्ट्र के व्यापक कल्याण को साधने रखकर पूरी शक्ति और लगन के साथ एक निश्चित योजना के अनुसार काम करना अपना एक मात्र लक्ष्य बनाएंगे।

राजकोपीय आयोग की सिफारिशें

भारत सरकार ने अप्रैल १९४८ में वित्त आयोगिक नीति की घोषणा की थी, उसमें प्रमुख (टेरिक) नीति के बारे में स्पष्ट कर दिया था कि अनुचित प्रतिद्वन्द्विता को रोकने और भारत के प्राकृतिक साधनों के सदुपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उस नीति का निर्माण किया जायगा और यह भी ध्यान रखा जायगा कि उपभोक्ता को अनुचित भार उस नीति के परिणाम स्वरूप न उठाना पड़े। इसी घोषणा के अनुसार २० अप्रैल १९४९ को भारत सरकार ने राजकोपीय आयोग की नियुक्ति की। राजकोपीय आयोग का कार्य अन्य बातों के साथ-साथ उद्योगों के संरक्षण और सहायता सम्बन्धी किस नीति को सरकार अपनाये और संरक्षित उद्योगों के क्या कर्तव्य-दायित्व माने जायें, तथा इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक है—इस संबंध में भी भारत-सरकार के सामने श्रमना अभिमत प्रस्तुत करना था।

संरक्षण-नीति का निर्णय किस आधारभूत दृष्टि से होना चाहिये इस सम्बन्ध में विवक्षित करते हुए राजकोपीय आयोग ने लिखा है कि 'संरक्षण नीति का उद्देश्य केवल अनुक प्रकार के उत्पादन को प्रोत्साहन देना न होकर जनसंख्या

तथा ग्राम व्यवस्था मजदूरी हानि में इस प्रकार का परिवर्तन लाता है जिससे कि जंग का मजदूरी आर्थिक चालाकरण का बदल जाय और मजदूरी राष्ट्रीय उत्पादन का स्तर ऊँचा हो जाय। इस दृष्टि से सरलण एक लक्ष्य का गान मात्र हो जाता है—यदि यह लक्ष्य ६ मासों में हो। 'गोपाल' का यह दृष्टि कोण सचचा वैधानिक और प्रगतिशील है जब कि १९११ के भारतीय रक्षा आयोग का दृष्टिकोण अत्यन्त मनुष्यिक और एकाग्र था। राजकीय आयोग १९५० ने भी इस सम्बन्ध में यही राय दी थी कि 'यदि हम 'यदि' की दृष्टि से राजकीय आयोग के सरलण सम्बन्ध में दृष्टि काय में एक मौलिक दोष था। सरलण का सामान्य आर्थिक प्रगति का मापन के रूप में इस प्रकार उद्योग विभाग को विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में सहायता देने के लिये रक्षा के रूप में लेना गया। इसका परिणाम यह हुआ कि आर्थिक विभाग मनुष्यिक रूप में ही रखा। यह दृष्टि कोण सरलण आयोग के उद्योग का विकास करना सम्भव नहीं था। यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्यिक और राजकीय उद्योगों का स्थापित करने का कोई प्रयत्न किए बिना उद्योग विभाग का सरलण न केवल सामान्य जनता पर पड़ने वाले भार में भी वृद्धि हुई।' पण्डित मन्मथलाल के परम्परा १९५५ में भारत सरकार ने एक अन्तःसालीन प्रयुक्त मन्त्रालय की स्थापना करने समय सरलण प्राप्त करने के लिये निम्न शर्तों का अन्तर्गत किया, उक्त से यह अर्थ निकलता है कि बाद में इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने दृष्टि कोण में पुनरावृत्ति। सरकार ने प्रयुक्त मन्त्रालय की उद्योगों का सरलण का विकास करने के लिये कहा निम्नका विकास १९११ से १९५१ तक। इस प्रयुक्त मन्त्रालय का कार्य क्षेत्र भी व्यापक किया गया, यद्यपि सरकार ने अपने उद्योगों के अन्तर्गत पूरी नीति से कार्य नहीं किया है।

सरलण का निम्न मनुष्यिक नानि का पराधात भाग में व्यवहार हुआ उत्तर द्वारा देश को क्या आर्थिक लाभ हुआ इस सम्बन्ध में राजकीय आयोग का कहना है कि सरलण का उक्त नानि में गति मुख्य लाभ हुआ है—(१) आर्थिक मन्त्रालय प्रमाण में सरलण उद्योग अपमानित मुरतिन रहे। जब अन्य उद्योग मन्त्रालय का सामना कर रहे थे, जो सरलण उद्योग के उनका आर्थिक मन्त्रालय में भी विस्तार हो रहा था। (२) सरलण उद्योगों का भी विस्तार हुआ। १९२१ से १९३१ तक १७ वर्षों में इसका विकास (स्टील इन्डस्ट्री) का उत्पादन आठ गुना, सूती वस्त्रों का दस गुना, दियायना और कागज का ३०% और ५०% तथा शर्करा का उत्पादन १९२० में ४५०० टन से १९३० में १,००,००० टन बढ़ गया। इसी के साथ सरलण का एक अप्रत्याशित लाभ यह

भी हुआ कि लोहा-इस्पात, कागज, और सूती वस्त्र के संगठित उद्योगों पर जो आधारित उद्योग थे उनको भी स्थापना हुई। जैसे रासायनिक पदार्थ, स्टार्च आदि के उद्योग। (३) औद्योगिक जनसंख्या की वृद्धि। यद्यपि इस सम्बन्ध में बहुत विश्वासनीय और-संपूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी यह कहा जा सकता है कि गत दो दशान्दियों में जनसंख्या के भविष्य वटवारे में गौण और अप्रत्यक्ष सेवा सम्बन्धी धंधों (टेरटियरी) के पक्ष में थोड़ा सुधार हुआ है। इस विषय में सारस्व में राजकोपीय आयोग में लिखा है कि “संगठित उद्योगों की प्रगति के इस विवरण से यदि हम निष्कर्ष निकालें तो यह कहा जा सकता है कि विवेचन संरक्षण की नीति ने अपने मर्यादित क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है और जनता को मिलने वाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ का यदि ध्यान रखें तो उनमें उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले भार की पूर्ति हो जाती है।” गत महायुद्ध के बाद की राजकोपीय नीति के परिणामों का पूर्ण-पूरा अनुमान अभी लगाना कठिन है। यह सब होते हुए भी विवेचन संरक्षण की जो संकुचित नीति अपनाई गई उसके स्थान पर यदि अधिक उदारनीति का पालन किया जाता तो भारत के औद्योगिक नकशे में जो आज अपूर्यताएँ और रिक्तबिन्दु दिखाई देते हैं वे इतनी मात्रा में न दिखाई देते।

राजकोपीय आयोग के इस अभिमत का हम उल्लेख कर चुके हैं कि देश की औद्योगिक रक्षण नीति का निश्चय राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था की भावी रूपरेखा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये। इसी बात को दूसरे शब्दों में आयोग ने भी कहा है कि राष्ट्रीय हित लक्ष्य है और औद्योगिक रक्षण नीति उसका एक साधन मात्र। अतः, राजकोपीय आयोग ने देश की भावी आर्थिक व्यवस्था की रूपरेखा का एक चित्र प्रस्तुत किया है जिसकी पृष्ठ भूमि में ही उसने देश की भावी राजकोपीय नीति संबंधी सिफारिशें भी की हैं।

राजकोपीय आयोग ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था में खेती का बड़ा महत्त्व रहने वाला है और उसकी प्रगति पर राष्ट्र को एकप्रतिष्ठ होकर ध्यान देना चाहिये। हमारे कृषि-उद्योग के विकास से सम्बन्ध रखने वाली विभिन्न समस्याओं में सबसे विषम समस्या खेतों में लगे हुए लोगों की जो आज अत्यधिकता है उसे कम करने की है। इन समस्या की विषमता का अन्दाज राजकोपीय आयोग ने जो आंकड़े अनुमान के तौर पर दिये हैं उनसे लगाया जा सकता है। यदि हम कृषि में जो अधिक जनसंख्या है उसे आगामी २० वर्षों में दूसरे धंधों में लगाने की योजना बनाएँ तो हमें वर्तमान कृषि-जनसंख्या में से १५ लाख जनसंख्या प्रतिवर्ष दूसरे धंधों में लगाने की व्यवस्था

समन्वय पर बहुत गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के आधार पर देश के बड़े उद्योग-वर्गों के स्वरूप का जो चित्र आयोग ने प्रस्तुत किया है उसके प्रधान अंग इस प्रकार हैं:—

(क) रक्षा उद्योग—जिनमें अस्त्र-शस्त्र तथा युद्ध-सामग्री से संबंध रखने वाले उद्योगों के अलावा दूसरे बहुत उच्च दक्षता चाहने वाले ऐसे उद्योग—जैसे हवाई जहाज-निर्माण तथा वेतार के तार आदि के उद्योग भी शामिल हैं। (ख) भारी आभारोद्योग—जैसे नाताचात्र के सामग्री संबंधी उद्योग, जहाज-निर्माण का उद्योग आदि। (ग) भारी प्रमुखोद्योग (बेसिक इन्डस्ट्रीज)—जिनके महारे दूसरे कई पूँजी पदार्थों और उपभोग-पदार्थों के उद्योगों की स्थापना की जा सकती है, जैसे लोहे और इस्पात का उद्योग, यंत्रोपकरण- (मशीन टूल) उद्योग, मोटर-उद्योग आदि। (घ) हल्के प्रमुखोद्योग—जैसे कार्टिक मोटर, अलुमिना धातु, कृत्रिम रेशम आदि। (ङ) आवश्यक उपभोगपदार्थ-उद्योग—जैसे दूदायक वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सीमेंट, शक्कर, कागज, आदि। आयोग ने यह भी स्वीकार किया है कि देश के औद्योगिक विकास का उद्युक्त चित्र संपूर्ण होने में समय लगेगा और उसका मानना है कि इस आदर्श की ओर हम धीरे-धीरे अग्रसर होना चाहिये। इस दृष्टि से उन्होंने राजकीय और व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता की एक शृंखला विशेष का सुझाव भी दिया है। देश के इन भागी औद्योगिक चित्र की उपस्थिति करने हुए सार लक्ष्य में राजकोपीय आयोग का कहना है कि “बड़े उद्योगों के जिस स्वरूप की हम कल्पना करते हैं वह एक प्रकार से अमेरिका और इंग्लैंड के जैसे बहुत ही पूँजी प्रधान उद्योगों और भारत की प्राथम्य प्रधान अर्थ व्यवस्था के बीच की सी दिव्यति की कल्पना है।” राजकोपीय आयोग ने देश के विदेशी व्यापार के बारे में भी थोड़ा विस्तार से विचार किया है और देश के औद्योगीकरण के भारी स्वरूप की दृष्टिभूमि में विदेशी व्यापार सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति का विश्लेषण किया है। राज्य को देश के इस भागी आर्थिक ढाँचे के निर्माण और विकास में किस प्रकार और कितना सहयोग देना चाहिये, इस विषय में भी राजकोपीय आयोग ने अपने विचार प्रकट किये हैं। सारांश यह है कि देश के जित आर्थिक संरचना को सामने रखकर राजकोपीय आयोग ने भारत-सरकार के विचारार्थ राजकोपीय नीति सम्बन्धी सिफारिशों की हैं उसकी एक मोटी रूपरेखा आयोग ने उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। इसी रूपरेखा का उल्लेख हमने यहाँ करना आवश्यक समझा। अब देखना यह है कि इस आर्थिक स्वरूप को लक्ष्य में रखकर राजकोपीय आयोग ने किस प्रकार की राजकोपीय नीति का प्रतिपादन किया है।

राजकीयों का आचार्य न राजा का उक्त वाक्य न हृदय अन्तर-भूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। वेम तो वाक्य का यन्त्र रचना है कि उद्योगों का रक्षण आचार्य विचार ही सम्पूर्ण यन्त्र का ध्यान में रख कर हा किया जाना चाहिये, अतः राजा की प्रत्येक प्रतिक्रिया और उद्योग-कार्य पर अस्मिता बाध पड़ने का सम्भावना ही संभव है। परन्तु वह हिंस्र अन्तर की कीद सम्पूर्ण वाक्यता में बाध न हो, अतः धर्म की निरालिप्त आचार्य-भूत सिद्धान्तों के अनुसार रक्षण मिलना चाहिये।

(३) उद्योग-प्रकार के अनुसार उद्योगों का रक्षण—

(१) रक्षा और दूसरे सामाजिक महत्त्व के उद्योग (२) प्रमुख और आपातकालीन, (३) अन्य उद्योग। १. २. ३. चर्चा का स्थापना कर रक्षा में हीनी ही चाहिये और जो अन्य और सरावत आचार्यक ह वह विचार विमो लागत के विचार के बाध हित में हो जाना चाहिये। २. ३. उद्योग का भी रक्षण मिलना चाहिये पर अन्य का स्वरूप और उसका प्रभाव (उद्योग) का निरूप प्रमुख अधिकारों पर छाड़ा जाना चाहिये न ३. चर्चा ही रक्षण नहीं मिलना चाहिये जब कि उनके जो आचार्य रक्षा प्राप्त है या प्राप्त हो सकते हैं और उनकी जो वास्तविक अवस्था सम्भावित उद्योग-लागत हो सकती है उनको रक्षण हृदय यह सम्भव मान्य हो सकता है कि एक प्रत्येक समय में ३. रक्षा रक्षण अवस्था महायत्ना पर काम करना सर्वेभ। ३. यह उद्योग उद्योग हानि चाहिये कि राहु के हित में रक्षणता प्रभाव रक्षा रक्षा आवश्यक है और प्रत्येक तथा अत्यधिक लाभों का ध्यान करते हुए इस प्रकार का रक्षणता या रक्षण का सम्भावित लागत राशु के लिए अत्यधिक नहीं है।

(४) जो उद्योग प्रारम्भ स्थापित योजनाओं के अन्तर्गत २. आने हैं उनके रक्षण के प्रश्न पर प्रमुख अधिकारों को उपर्युक्त आधार पर विचार कर अपनी गितारिष्ठ सरकार के आसन उद्योगिक रक्षा चाहिये।

(५) जहाँ की रक्षित वाक्यता महा है—(१) रक्षा और दूसरे सामाजिक महत्त्व के चर्चा की राष्ट्रीय हित में बिना लागत का विचार रक्षण मिलना चाहिये। (२) दूसरे उद्योगों के बाधे में ऊपर (३. ५) जो आचार्य बताया गया है उसी के अनुसार निरूप हानि चाहिये।

रक्षण सम्बन्धी उपर्युक्त मूल भूत सिद्धान्तों के अन्तर्गत रक्षा-धर्म आयोग ने रक्षण नीति से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ विचार प्रश्नों के विषय में भी अपनी राय दी है। प्रत्येक माल के बारे में उसका करना है कि यदि किन्हीं उद्योगों को दूसरे

आर्थिक सुविचारों प्राप्त हैं तो कच्चे माल की सुविधा रक्षण देने की आवश्यक बात नहीं मानी जानी चाहिये। इसी प्रकार रक्षण देते समय भावी निर्यात-वाजार की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिये। देश की सम्पूर्ण मांग को पूरी कर सकना भी रक्षण-प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं होना चाहिये, यद्यपि प्रशुल्क अधिकारी की दृष्टि में यह बात तो होनी ही चाहिये कि इतने सम्पूर्ण मांग के वषष्ट अंश की पूर्ति रक्षण चाहनेवाले उद्योग के द्वारा अवश्य हो ही सकेगी। इसी प्रकार जो रक्षित उद्योग किसी दूसरे रक्षित उद्योग द्वारा तैयार माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है उसे अतिरिक्त रक्षण देना आवश्यक हो सकता है। राजकोपीय आयोग ने यह भी स्वीकार किया है कि कई उद्योगों को उनकी स्थापना के पूर्व ही रक्षण का आश्वासन देना आवश्यक हो सकता है। जो उद्योग कारी पूर्वी-व्यय चाहते हैं, या जिनको काफी ऊँचे दर्जे के विशेषज्ञ चाहियें और साथ ही जिनको विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े, उनको इस प्रकार के रक्षण की आवश्यकता हो सकती है। प्रशुल्क अधिकारी को सारी स्थिति की जाँच करके सरकार को सिकारिश करना चाहिये। इसी प्रकार राजकोपीय आयोग की यह भी सिकारिश है कि शगर राष्ट्र के हित में आवश्यकता है तो कृषि-पदार्थों को भी रक्षण दिया जा सकता है। पर यथासम्भव कम से कम पदार्थों को रक्षण दिया जाना चाहिये और यह रक्षण अल्प काल के लिये, (एक समय में पाँच वर्ष से अधिक के लिए किसी भी दशा में नहीं) मिलना चाहिये। रक्षित उद्योग के पदार्थों पर उत्पाद-कर लगाने के विरुद्ध भी राजकोपीय आयोग ने अपनी राय दी है।

रक्षण-नीति से सम्बन्ध रखनेवाला एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न रक्षण के स्वरूप का है। राजकोपीय आयोग ने निम्नलिखित स्वरूपों के बारे में अपनी रिपोर्ट में विचार किया है—(१) प्रशुल्क—दोनों प्रकार के अर्थात् यथामूल्य-कर (एक्वेलरम ड्यूटी) और परिमाण-कर (स्पेसिफिक ड्यूटी)। (२) मासिक प्रति बन्ध—अर्थात् सरकार यह निर्दिष्ट करदे कि अमुक समय में अमुक मात्रा में ही आयात हो सकेगा। इस के बारे में आयोग का यह मत है कि साधारण स्थिति में रक्षण की इस पद्धति का बहुत कम उपयोग करना चाहिये क्योंकि इस पद्धति में कई प्रकार की कठिनाई पैदा होती है। (३) अर्थ-साहाय्य (सब्सिडी)—इस पद्धति के अनुसार सरकार रक्षित उद्योग को सीधी आर्थिक सहायता देती है। (४) एकत्रीकरण (प्लीग)—अर्थात् सरकार यह व्यवस्था करे कि देश में जो माल-उत्पादन हो और विदेश से जो आयात किया जाए वह एकत्रित कर दिया जायगा और सारा ही माल एक ऐसे निर्दिष्ट मूल्यपर बेचा जायगा जोकि देश के

विशेष की स्थिति और प्रतिस्पर्धा की स्थिति दोनों का ही ध्यान रखकर होना होगा। यह ठीक है कि विकास की दृष्टि से रक्षण अधिक समय के लिए आवश्यक होगा, परन्तु किसी तात्कालिक कठिनाई का सामना करने के लिए यदि रक्षण आवश्यक है तो वह अपेक्षाकृत कम समय के लिए होगा। पर राजकोषीय आयोग का यह निश्चित मत है कि रक्षण के समय के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्त यही होना चाहिये कि उद्योग-बन्धों को पर्याप्त लम्बे समय के लिए रक्षण दिया जावे ताकि बन्धों में पूंजी भी आकर्षित हो सके और उनके विकास के लिए उचित योजना नैवार की जाकर उसको कार्यान्वित भी दिया जा सके। पर्याप्त समय के लिए रक्षण नहीं मिलने से उनका सारा उपयोग ही नष्ट हो जाता है।

जिन उद्योग-बन्धों को समाज की ओर से सहायता और रक्षण प्राप्त हो उन पर इस बात का प्रतिबन्ध भी होना चाहिये कि इस मुविधर के बदले में वे किन्हीं कर्तव्यों का पालन भी करें। राजकोषीय आयोग का यह मत है कि रक्षित उद्योग पर इस बात का दायित्व होना चाहिये कि वह अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता बढ़ावे। किस उद्योग पर क्या दायित्व डालना चाहिये इसका निर्णय तो उपयुक्त अधिकारी द्वारा सब सम्बन्धित बातों पर सोच-विचार कर ही किया जाना चाहिये। परन्तु फिर भी उचित मूल्य, उत्पादन मात्रा में वृद्धि उत्पादित वस्तु के गुण, उत्पादन और वितरण की अधिक से अधिक वैज्ञानिक प्रणाली के उपयोग, अनुसंधान, उच्च श्रेणी के मजदूरों और उम्मीदवार कारीगरों (एप्रेंटिसेज) के शिक्षण, समाज विरोधी कार्य और देश में उत्पन्न कच्चे माल के उपयोग सम्बन्धी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके विषय में रक्षित उद्योगों पर समाज के हित की दृष्टि से आवश्यक जिम्मेदारी डाली जाना चाहिये। इन विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का पालन कराने का सबसे अच्छा उपाय राजकोषीय आयोग की दृष्टि में यह नहीं है कि रक्षण सम्बन्धी जो भी कानून बने उसमें इनका समावेश कर लिया जाए। इससे तो एक अनावश्यक कड़ाई आजाने का भय है। आयोग का यह मानना है कि प्रशुल्क अधिकारी की स्थापना सम्बन्धी जो कानून बने उसमें मार्गदर्शक सिद्धान्तों की तरह, जिनका कानून द्वारा पालन नहीं कराया जा सकता, इस प्रकार के दायित्वों का उल्लेख होना चाहिये। फिर यह उस अधिकारी पर छोड़ दिया जावे कि वह किस उद्योग पर कौन सी बातों का और किन शर्तों पर दायित्व डालता है। साथ ही इस अधिकारी का यह भी काम होना चाहिये कि कौनसा उद्योग अपने दायित्व को कहाँ तक वास्तव में पूरा कर रहा है या नहीं, इसकी वह निगरानी रखे और इस सम्बन्ध में वह सरकार को

भी समय समय पर विचार पथ करता रहे। यदि सरकार यह अनुमति कर कि किसी स्थिति में कानून द्वारा ही इन दायियों में पालन कराया जा सकता है तो वह हमें कानून में धाम कर सकता है। इन दायियों का महत्त्व रक्षित उद्योगों पर विचार प्रसार का बंधन लगाना नहीं है बल्कि देखें कि औद्योगिक विकास में गति का नेतृत्व करने में हमें क्या है इन दायियों की आवश्यकता समझा गई है।

राजकायस्थ आयोग ने प्रस्तावित योजना में धन के दूसरे उपायों पर भी विचार किया है। पूँजी का स्वयं विदेशों में जाना का भय, औद्योगिक प्रबंध, औद्योगिक अनुसंधान प्रसारोत्तरण (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) और गुण नियंत्रण, भवन दत्तता मजदूर शिफ्ट आगाराएँ और मान और सुविधा, तथा अतिरिक्त व्यवस्था सम्बंधी प्रश्नों पर भी औद्योगिक विकास की दृष्टि से विचार किया गया है। हमने इन विषयों पर अत्यंत ध्यान उपलब्ध होना पर विचार किया है।

राजकायस्थ आयोग ने देश की रक्षण क्षमता प्रवृत्त का अन्ताराष्ट्रीय आगार मंत्र (आइ० टी० आ०) की पृष्ठभूमि में भी विचार किया है। उनका यह मत है कि राजकायस्थ आगार मंत्र में शामिल होने हुए भी हम देश में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक रक्षण क्षमता को अपना सकते हैं। अतः हमने निम्नलिखित बातें कि भारत की अन्ताराष्ट्रीय व्यापार का सम्बन्ध स्वीकार कर लेना चाहिये यदि प्रत्यक्ष आर्थिक दृष्टि में महत्त्वपूर्ण देखें—जिनमें 'डब्ल्यू' और अमरास भी शामिल हैं—सदस्य होना स्वीकार करें तथा देश की उस समय की आर्थिक स्थिति में ऐसा करना उचित समझा जाए।

राजकायस्थ आयोग ने देश में आर्थिक योजनाओं और रक्षण क्षमता के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में भी अत्यंत ध्यान प्रकट करते हुए कहा है कि रक्षण योजना का एक माध्यम मात्र है और उमर द्वारा देश की सेवा उसी दशा में हो सकती है जबकि देश के आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक आर्थिक योजना तैयार की जाए और उसको कार्यान्वित करने के अर्थ साधनों को उपलब्ध किया जाए। आर्थिक क्षमता में समर्थन दे सकने वाले केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के समन्वयकारी निकायों पर जोर देते हुए, आयोग ने डब्ल्यू के उदाहरण पर व्यापार उद्योग मंडल की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार करने में सुझाव भी उपस्थित किया है।

रक्षण क्षमता के सम्बन्ध में स्थापित अन्तिम प्रश्न यह है कि इस नीति

को कार्यान्वित करने का जिम्मा किसका सम्पत्ता जाए। राजकोषीय आयोग ने इस काम के लिए 'प्रशुल्क आयोग' की स्थापना की सिफारिश की है। यह आयोग एक स्थायी संस्था होना चाहिये जैसी कि भारतीय राजकोषीय आयोग (१९२२) ने भी सिफारिश की थी, यद्यपि तत्कालीन भारत-सरकार ने उन सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। रक्ष-नीति में स्वायत्त और समानता के लिए इस प्रकार के स्थायी आयोग की बड़ी आवश्यकता है। इस आयोग की स्थापना संसद के कानून द्वारा की जानी चाहिये ताकि उसके कार्य के अनुसूच उसको प्रतिष्ठा मिल सके। इसमें पाँच सदस्य हों जिनमें से एक अध्यक्ष हों। यह संख्या ७ तक बढ़ाई जाके इसका कानून में गुंजाइश होनी चाहिये। विशेष काम के लिए सलाहकारों को नियुक्त करने का भी आयोग को अधिकार होना चाहिये। सदस्यों की नियुक्ति का एक मात्र आधार योग्यता होना चाहिये और किसी भी प्रदेश अथवा हित विरोध के प्रतिनिधित्व का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहिये। सदस्यों पर कुछ विशेष प्रतिबन्ध भी होने चाहिये जैसे सदस्य होने के समय प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत कम्पनियाँ में अग्रधारी (शेयर होल्डर) की हैमियत से या अन्य किसी प्रकार के धरने हितों की चोखा करनी चाहिये और सदस्यता समाप्त होने के बाद तीन साल तक बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के किसी व्यक्तिगत उद्योग-धन्ये में कोई जिम्मेदारी का पद न ग्रहण कर सके, यह प्रतिबंध होना चाहिये।

प्रशुल्क आयोग के निम्नलिखित कार्य होने चाहिये:—

(१) रक्षण और आम सम्बन्धी प्रशुल्क की जाँच करना। इस संबंध में रक्षण के लिए धाए हुए आवेदनपत्रों और व्यापारिक समझौतों के अनुसार आवश्यक प्रशुल्क में रियायतों विषयक जाँच तो आयोग को सरकार के कहने पर ही करनी चाहिये। परन्तु वस्तु-राशिपातन (डपिंग) की शिकायत और रक्षण करों में परिवर्तन सम्बन्धी जाँच प्रशुल्क आयोग अपनी इच्छा से अथवा सरकार के कहने से भी कर सकता है।

(२) मूल्यों और देश की अर्थ व्यवस्था पर रक्षण के समान्य प्रभाव सम्बन्धी जाँच करना। ये जाँच सरकार के कहने पर ही आयोग को करनी होगी और इसमें वस्तु विशेष के मूल्यों, प्रशुल्क का मूल्यों के समान स्तर पर प्रभाव, रहन-सहन के खर्च पर प्रशुल्क का प्रभाव और देश की अर्थ व्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रशुल्क के प्रभाव सम्बन्धी जाँच का समावेश होगा।

(३) रक्षण-करों का सिद्धांतलोकन करना। इस अर्थ में प्रशुल्क के कार्यान्वित होने सम्बन्धी पद्धति, रक्षण-करों का उत्पादन-लागत, उत्पादन-

उद्योग-धन्ये—प्रस्तुत प्रश्न

संगठन की समस्या—औद्योगिक विकास से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों में एक प्रश्न उद्योग-धन्यों के संगठन के प्रकार का है। यह खेद का विषय है कि हमारी औद्योगिक समस्या के इन पक्षों की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया जा सका। आधुनिक औद्योगिक संसार में व्यापारिक संगठन के क्षेत्र में मिश्रित पूँजी वाली कंपनियों की प्रधानता है। व्यापारिक संगठन के दूसरे प्रकार जैसे सामेदारो अथवा व्यक्तिगत स्वामित्व का महत्त्व अपेक्षाकृत बहुत कम है। १९वीं शताब्दी के मध्य में (१८५७) भारत सरकार के एक कानून द्वारा मिश्रित पूँजी वाली कंपनियों को भारत में भी कानूनी स्वरूप मिला। तब से इनारे देश में भी नये उद्योग-पाद के विकास के चिह्नस्वरूप मिश्रित पूँजीवाली कंपनियों का महत्त्व बराबर बढ़ा है यह संतोष की बात है, फिर भी मिश्रित पूँजी वाली कंपनियों के मंत्र में कुछ ऐसी कमियाँ रही हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान जाना आवश्यक है।

पहला प्रश्न कम्पनी की स्थापना से सम्बन्ध रखता है। यह काम सरल नहीं है और इसकी समुचित व्यवस्था के लिए तीन प्रकार के विशेषज्ञों के सहयोग की आवश्यकता होती है। तीन प्रकार के विशेषज्ञों में पहला श्रेणी आर्थिक विशेषज्ञों की है जिनका काम कच्चे माल सम्बन्धी दृष्टि, बाजार और मजदूरों सम्बन्धी स्थिति तथा प्रस्तावित व्यवसाय की आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त आकार (साइज) के विषय में सलाह देना है। दूसरी श्रेणी में एंजीनियर आते हैं जिनका काम उद्योग सम्बन्धी आवश्यक सामग्रियों के लागत का अनुमान लगाना, और उपयुक्त मशीनों के बारे में तथा उनको लगाने के बारे में आवश्यक सलाह देना है। अन्तिम श्रेणी में वे आर्थिक विशेषज्ञ आते हैं जिनका काम अर्थ-प्रबन्ध के विषय में सलाह देना है। कम्पनियों की स्थापना करने वाले उपर्युक्त विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करते हैं जिसके लिए वे उनको उचित पुरस्कार देते हैं। चूंकि कम्पनी की स्थापना में प्रथम व्यय होता है और उसमें अनिश्चितता भी रहती है इसलिए कम्पनी स्थापित करने का काम कोई व्यक्ति अपेक्षा अपने पर नहीं लेता। प्रायः कुछ पूँजी-पतियों और अधिकारियों (Bankers) का एक छोटा-सा संगठन इस काम को करता है। जब कम्पनी का ठीक प्रकार से संगठन हो जाता है तो संगठन करने वालों का काम समाप्त हो जाता है और आवश्यक पुरस्कार पाने के बाद वे क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। संरांश यह है कि कम्पनियों की स्थापित करने का काम

हिस्सेदारों को हानि उठानी पड़ती है और भविष्य में वे शंकाशील बन जाते हैं। (यह आवश्यक है कि मावी हिस्सेदारों के सामने किसी कम्पनी के बारे में जो भी अनुमान प्रस्तुत किए जाएँ वे किसी मान्य संस्था द्वारा प्रमाणित होने चाहिये। क्रिसकल कमीशन ने इस बारे में यह सिफारिश की है कि भारत सरकार को उपयुक्त मंत्रालय में एक 'यूरो ऑफ कनसलटेन्स' की स्थापना करनी चाहिये जिन की सेवाओं का उपयोग उद्योगपति कर सके।)

अब तक हमने स्थापना के सम्बन्ध में विचार किया। दूसरा प्रश्न कम्पनियों के सुप्रबन्ध का है। मिश्रित पूँजीवाली कम्पनियों के वास्तविक स्वामी हिस्सेदार होते हैं। पर संख्या के अधिक होने से, एक वित्तुत प्रदेश में धिखरे होने से तथा आवश्यक टेक्निकल जानकारी की कमी से, किसी कम्पनी की वास्तविक प्रबन्ध की जिम्मेदारी उठाना उसके लिए समभव नहीं है। साधारण जनतंत्रीय प्रथा के अनुसार हिस्सेदार एक संचालक मंडल का चुनाव करते हैं। कम्पनी की रीति-नीति का निर्णय यह मंडल करता है पर वास्तविक प्रबन्ध का काम वैतनिक व्यवस्थापक करते हैं। किन्तु ध्यान से देखने पर मालूम होगा कि इन व्यवस्था में व्यवहार में कई प्रकार के दोष हैं। पहली बात तो यह है कि संचालक मंडल सही अर्थ में हिस्सेदारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वस्तु स्थिति यह है कि वे वैतनिक व्यवस्थापकों पर बहुत कुछ निर्भर रहते हैं। भारत में, जहाँ कि व्यवस्था का काम मैनेजिंग एजेन्सी प्रथा पर होता है, यह बात और अधिक लागू होती है। इसके अलावा संचालकों को कोई टेक्निकल जानकारी नहीं होती और इस कारण से भी वे कुछ अधिक नहीं कर पाते। हिस्सेदारों का यह हाल भारत में नहीं दूसरे देशों में भी है। इस स्थिति का निराकरण तो यही हो सकता है कि संचालकों पर हिस्सेदारों का अधिक नियन्त्रण हो। सन् १९१६ में जो कम्पनी एक्ट पास हुआ उसमें इस बात का ध्यान रखा गया। दत्त स्थिति में सुधार करने का एक उपाय मत देने की पद्धति में कुछ परिवर्तन करना भी है। वर्तमान पद्धति के अनुसार प्रत्येक हिस्से के पीछे एक मत होता है। अमेरिका में जो पद्धति प्रचलित है उसका यहाँ उल्लेख कर देना उचित होगा। अमेरिकन पद्धति के अनुसार एक निश्चित संख्या तक प्रत्येक हिस्से के पीछे एक मत होता है, उसके पश्चात् कई हिस्सों के पीछे एक मत होता है और इसी के साथ किसी भी एक हिस्सेदार को अधिक से अधिक विवने मत मिल सकते हैं, इसकी संख्या भी निश्चित रहती है। संचालकों की कम्पनी के काम में अधिक रुचि पैदा करने का एक उपाय यह भी है कि उनको उचित पुरस्कार मिले। संचालकों की संख्या चाहे कम करदी जाए पर उनको पारिश्रमिक पूरा मिलना

संचालकों और व्यवस्थापकों को मत देने का अधिकार ही नहीं रहे। यदि ऐसा प्रतिबन्ध बहुत कड़ा मालूम पड़े, तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिये कि जो मतदाता अनुपस्थित रहनेवाले हों उनके मतों को प्रदान करने का अधिकार संचालकों तथा व्यवस्थापकों को न रहे। वास्तव में तो सभी चुनावों में यह द्वारा मत देने की पद्धति को हटा ही देना चाहिये।

मैनेजिंग एजेन्सी:—कम्पनियों की व्यवस्था में सुधार करने के प्रश्न का मैनेजिंग एजेन्सी के प्रश्न से घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारत में कम्पनियों की व्यवस्था सम्बन्धी एक विशेष पद्धति मैनेजिंग एजेन्सी की है। इस विषय पर कुछ विस्तार से लिखना आवश्यक है।

भारत में ब्रिटिश व्यवसाय जिन विशेष परिस्थितियों में पनपा मैनेजिंग एजेन्सी पद्धति उसी का परिणाम है। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज पूँजीपतियों को भारत में पूँजी लगाना लाभदायक मालूम पड़ने लगा। इस काम के लिए इंग्लैंड में कम्पनियों की स्थापना होने लगी। भारत में औद्योगिक कम्पनियों की व्यवस्था कर सकने वाले कुशल व्यवस्थापकों का अभाव-सा था। इस समय भारत में कुछ विदेशी फर्म जिनको 'एजेन्सी हाउसेज़' कहते थे, काम करती थीं। इन 'एजेन्सी हाउसेज़' का एक काम तो यह था कि विदेशी फर्मों के प्रतिनिधि के रूप में वे ब्रिटिश माल का भारत में आयात करती थीं और भारतीय माल विदेशों को निर्यात करती थीं। इसके अतिरिक्त वह रुपये के लेन-देन का काम भी करती थीं। विदेशी पूँजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योगों की व्यवस्था का काम भी इन्होंने करने ऊपर लेना आरम्भ किया। इन उद्योगों के लिए आवश्यक अर्ध-व्यवस्था भी वे एजेन्सी हाउस करने लगे, क्योंकि रुपये के लेन-देन का काम तो वे करते ही थे। उद्योगों की व्यवस्था सम्बन्धी इस नए काम को आरम्भ करने से इन एजेन्सी हाउसेज़ को 'मैनेजिंग एजेन्सी फर्म' के नाम से पुकारा जाने लगा। बाद में इन्होंने भारतीय उद्योगों की स्थापना और व्यवस्था का काम भी आरम्भ कर दिया। इन विदेशी एजेन्सी हाउसेज़ का अनुकरण भारतीय व्यापारी वर्ग ने भी करना शुरू किया। इस प्रकार भारतीय मैनेजिंग एजेन्सी फर्मों की भी स्थापना हुई और मैनेजिंग एजेन्सी की यह प्रथा आज तक चली आ रही है। मैनेजिंग एजेन्सी को यह काम विशेष रूप से लाभ प्रद साबित हुआ है और वे इसे कदापि छोड़ना नहीं चाहते। मैनेजिंग एजेन्सी-पद्धति का प्रमुख लक्षण यह शर्तनामा है जो मैनेजिंग एजेन्सी और सम्बन्धित फर्म के बीच में उसकी स्थापना के समय ही किया जाता है। १९३६ के कम्पनी एक्ट के पास होने के पहले इन शर्तनामों की अवधि २०-४० साल से लेकर अनिश्चित समय तक के लिए

हुआ करता था। व्यवहार में मन्ने ने म तो यह आता था कि यदि शर्त-नामे में कोई समय निश्चित भा हुआ तो उसका वास्तव में कोई मूल्य नहीं हुआ करता था। मैनेजिंग एजेंट्स का जितना प्रभाव हुआ है उसका कारण शतनामे का समय पूरा हो जाने पर उस द्वारा जारी किया जाना एक आगमन सा बात था। इसीलिए एकबार यदि कोई फर्म मैनेजिंग एजेंट के हाथ में आ गई तो फिर उसका उनके हाथ में निहलता अलम्भव सा बात था। मैनेजिंग एजेंट्स पारिश्रमिक रूप में उगादन, बिना या मुताफ पर रमाशन लेते हैं। इसके अलावा वे और भी कई प्रकार के कमाशन अनेकों नाम से यकूल करते हैं। १९२६ के अगली एकट नम स्थिति में कुछ सुधार अवश्य किया है। मशान तथा कच्चा माल खरीदने और बिक्री तथा चाल और अचल पूँजा की व्यवस्था करने के नाम पर इस प्रकार के कमीशन लिए जाते हैं। मैनेजिंग एजेंट्स की आय के कुछ छोटे मोटे भाग और भी हैं। मैनेजिंग एजेंट का बराबर यह प्रयत्न रहता है कि जिन फर्मों में उनका सम्बन्ध है वे अथ न मामलों में उन्हीं पर नियंत्रण रहे। इसके कारण स्पष्ट है। क्योंकि इस प्रकार उन फर्मों पर मैनेजिंग एजेंट्स का पूरा नियन्त्रण रह सकता है। मैनेजिंग एजेंसी-प्रवृत्ति का परिणाम कम्पनी व्यवस्था के क्षेत्र में—जैसा कि अथ व्यवस्था, जैसा दूसरे क्षेत्रों में भी हुआ, हाविकर हुआ है। जिन फर्मों का प्रबन्ध मैनेजिंग एजेंट्स के हाथ में होता है उनके वे बाल्य में सँतसा बन आते हैं। उनके सामान्य हिस्सेदारा, सचालकों तथा आडिटर्सों किमा का भी कुछ नहीं चलता। मैनेजिंग एजेंटों की हटाने सम्बन्धी बारा की व्यवहार में लाना अवम्भव सा होता है। ऐसा करने में कई प्रकार का अवधानों का सामना करना होता है। उदाहरण के लिए मैनेजिंग एजेंट की हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव लाने के लिए बहुत सच्चा नोटिस—जैसे एक वर्ष का—देना होता है। दूसरे छद्म प्रस्ताव बहुत भारी बहुमूल्य से हा पाम करना होता है। यह भी होता है कि कुल मतों का एक न्यूनतम भाग, जो प्राय तीन चौपाद होता है, ऐसे प्रस्तावों पर अवश्य हो आना चाहिये। और अंतिम शर्त यह होनी है कि एक बार प्रस्ताव पास हो जाने के पश्चात् कुछ महीनों बाद उसकी पुनरा पुष्टि होने पर ही वह अमल में आ सकता है। लग्न नोटिस और दो बार प्रस्ताव पास करने का ऐसी शर्त है जिनका कारण सम्बन्धित मैनेजिंग एजेंट की अपना पक्ष टोक करने के लिए सयेंत समय और अवसर मिल जाता है। और कोई चारा न होने पर वे हिस्से खराद कर अपने मतों का सख्या बटा लेते हैं। अगर इतना सब करने पर भी मैनेजिंग एजेंट की हटाना ही पड़े तो उनकी काफी भारी मुआवजा देना होता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मैनेजिंग एजेंट्स के काम ने कुछ पैतृक काम का रूप ले लिया है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि चर्या प्रारंभ में मैनेजिंग एजेन्सी-पद्धति ने एक आवश्यकता की पूर्ति की परन्तु अब उसका कोई उपयोग नहीं बचा है। बल्कि मुख्यतया और अर्थ-प्रवन्ध दोनों ही के मार्ग में वह एक बड़ी बाधा होगई। अस्तु, इस पद्धति का इसी स्वरूप में बना रहना किसी दृष्टि से भी आवश्यक नहीं रहा।

१९३६ का कम्पनी एक्टः—कम्पनी-व्यवस्थासम्बन्धी जो दोष थे वे धीरे-धीरे सामने आने लगे। विशेषतया मैनेजिंग एजेन्सी-पद्धति की बुराईयाँ, और कम्पनी एक्ट में इसके सम्बन्ध में कुछ भी न होना बहुत ही खटकने लगा। अस्तु, कम्पनी एक्ट में आवश्यक सुधार करने की माँग बग़ावर उठने लगी। और १९३६ में एक नया कम्पनी एक्ट पास किया गया।

१९३६ के एक्ट में कई प्रकार के सुधार किए गए हैं। न केवल हिस्सेदारों का नियन्त्रण अधिक दृढ़ किया है बल्कि मैनेजिंग एजेन्सी-पद्धति के दोषों को भी कम करने का प्रयत्न किया गया है।

१९३६ के कम्पनी एक्ट में जहाँ तक हिस्सेदारों का सम्बन्ध है, कई धाराएँ ऐसी हैं जिनके अनुसार उनको कम्पनी और उसके कारोबार के विषय में पूरी-पूरी जानकारी मिलना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर एक्ट के अनुसार यह अनिवार्य है कि विवरणपत्रिका (प्रोस्पेक्टस) में वे सब सूचनाएँ होनी चाहियें जो कि किसी भी हिस्सा खरीदनेवाले व्यक्ति को हिस्सा खरीदने या न खरीदने के विषय में अपना निर्णय करने के लिए जानना जरूरी है। इसीलिए जिन कम्पनियों में मैनेजिंग एजेन्ट हैं उनमें मैनेजिंग एजेन्टों के नाम और पते के अलावा 'आर्टिफ़िशल ऑफ़ प्रसीसिवेशन' या उनके अहंदासे में उनकी नियुक्ति और मुआवजे सम्बन्धी जो धाराएँ हैं वे सभी प्रकट करना होती हैं। कम्पनी के कारोबार सम्बन्धी पूरी-पूरी जानकारी हिस्सेदारों को मिल सके इस उद्देश्य से और भी कई धाराएँ कम्पनी-एक्ट में रखी गई हैं। जो हिसाब हिस्सेदारों को पेश किए जाते हैं वे तत्काल में होते हैं और लाभ-हानि का हिसाब, डाइरेक्टर की रिपोर्ट तथा आखिटर की रिपोर्ट पेश करना भी अनिवार्य है। पहली बार हिस्सेदारों को यह कानूनी अधिकार मिला है कि विशेष प्रस्ताव पास करके वे डाइरेक्टरों को हटा सकते हैं। मैनेजिंग एजेन्टों की नियुक्ति-उनका वेतन आदि और एक्ट पास होने के पश्चात् उनके साथ किए गए इकरार में किया जाने वाला कोई भी परिवर्तन हिस्सेदारों की आम सभा में स्वीकृत होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मुआवजे सम्बन्धी कोई भी शर्त, जो कानून द्वारा निर्रक्त नहीं है, कम्पनी की स्वीकृति से ही की जा सकती है।

नहीं माना जा सकता। मैनेजिंग एजेंट पर यह प्रतिबन्ध भी है कि वह स्वयं कोई ऐसा व्यवसाय न करे जो कि उस कम्पनी के व्यवसाय से प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्दी में आता हो जिसका कि वह मैनेजिंग एजेंट है। इसी प्रकार कोई कम्पनी किसी ऐसी दूसरी कम्पनी के हिस्से अथवा डिवेंचर (अथ पत्र) नहीं खरीदेगी जो कि पहले वाली कम्पनी के संचालकों द्वारा ही संचालित है। ऐसा खरीद तभी हो सकती है जबकि संचालन-समिति (बोर्ड) ने इसके लिए पहले से ही रवाकृति दे दी हो।

उपर्युक्त विवरण से इतना तो स्पष्ट हो है कि नए कम्पनी कानून के अन्तर्गत यद्यपि मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली तो आज भी जारी है पर उस पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गए हैं। इन प्रतिबन्धों के बावजूद भी मैनेजिंग-एजेंसी प्रथा के बारे में शिकायतों की कमी नहीं हुई है। आज भी वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते पाये जाते हैं। भारत सरकार के सामने यह प्रश्न फिर विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में आलोचना के लिए उन्होंने कुछ प्रस्ताव भी प्रकाशित किए हैं (जैसे इस परिच्छेद के अन्त में परिशिष्ट)। भारत सरकार के सामने प्रश्न केवल इतना ही नहीं है। वह तो सम्पूर्ण कम्पनी एक्ट में संशोधन करने का विचार कर रही है। इन सम्बन्ध में सरकार के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए विवेकशो की एक समिति भी काम कर रही है। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने की है कि पिछले वर्षों में ऐसी नई फर्मों की नक़्का बढ़ी है जो कि किसी मैनेजिंग एजेंसी के तत्वावधान में स्थापित नहीं हुईं। यह इस बात का संकेत है कि देश में व्यावसायिक नेतृत्व का विकास हो रहा है। यह शुभ चिह्न है। क्योंकि व्यवस्था में ईमानदारी और कार्यक्षमता केवल कानून के पल पर नहीं लाई जा सकती। कानून से कुछ सहायता मिल सकती है, पर, अधिक जापत जन मन, व्यवसायी वर्ग में अपेक्षाकृत अधिक कर्तव्य-बुद्धि, और श्रमभवा, विशेषज्ञ, ईमानदार, और साहसी व्यवसायी-नेतृत्व की भी बड़ी आवश्यकता है। बिना इनकी मदद के व्यवस्था और अर्थ दोनों ही समस्याओं के हल नहीं निकल सकते।

औद्योगिक अर्थ प्रवन्धः—यह बात सर्व विदित है कि आधुनिक उद्योगों के लिए बहुत बड़ी पूँजी चाहिए। अतः, औद्योगिक अर्थ प्रवन्ध के बारे में विशेष जानकारी करना आवश्यक है।

उद्योग-धन्यों को दो प्रकार की पूँजी चाहिये। स्थायी (फिक्स्ड) पूँजी और चालू (वर्किंग) पूँजी। स्थायी पूँजी की भूमि, इमारत, मशीनरी और दूसरे स्थायी उपकरणों के लिए आवश्यकता होती है। मैजूदा उद्योगों में नए

जानना आवश्यक है कि भारतवर्ष में स्थायी (ब्लाक) और चालू (वर्किंग) दोनों ही प्रकार की औद्योगिक पूंजी की पूर्ति आज किस तरह से होती है।

देश के प्रमुख उद्योग धन्वे स्थायी पूंजी की व्यवस्था निम्न लिखित उपायों में से किसी एक या अधिक उपायों द्वारा करते हैं:—(अ) हिस्सों और ऋण पत्रकों (डिवेंचर्स) को सार्वजनिक रूप से अथवा सीमित मात्रा में बेच कर, (आ) नकद रुपया हवालगी जमा (डिपोजिट) के रूप में प्राप्त कर, और (इ) किसी व्यक्ति अथवा साझेदारों (पार्टनरशिप) विशेष से रुपया उधार लेकर। वैसे तो उपर्युक्त उपायों में से अलग-अलग उद्योग-धन्वों के लिए अलग-अलग उपायों का विशेष महत्त्व माना जा सकता है, पर फिर भी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि धातु-कल हिस्सों और ऋण पत्रकों (डिवेंचर्स) को बेचकर स्थायी पूंजी प्राप्त करने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। साधारण हिस्सों के अलावा विशिष्ट हिस्सों (प्रिफरेंस शेयर) तथा ऋण-पत्रकों (डिवेंचर्स) का भी पूंजी प्राप्त करने के लिए उपयोग हुआ है, खास तौर से जूट के उद्योग में। इस सम्बन्ध में एक शुभ परिवर्तन यह भी हुआ है—कि प्रत्येक हिस्सा कम कीमत का रखा जाता है ताकि सामान्य स्थिति का व्यक्ति भी आसानी से खरीद सके। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां स्थायी पूंजी का प्रमुख आधार नकद रुपया जमा के रूप में प्राप्त करना ही है। अहमदाबाद की सूती कपड़ा-व्यवस्था इन प्रकार का एक बड़ा उदाहरण है। मिश्रित पूंजी वाली कम्पनियों का जब तक प्रचार नहीं हुआ था व्यक्ति अथवा साझेदारी (पार्टनरशिप) विशेष से पूंजी उधार लेने के भी कई उदाहरण मिल जाते थे। नए उद्योगों में—जैसे शकर के, खान के, कागज के और दिवानलाई आदि के उद्योगों में आज भी ऐसा देखा जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि यह उद्योग अपने अपने क्षेत्र में अगुआ रहे हैं।

चालू पूंजी (वर्किंग कैपिटल) के सम्बन्ध में भी यह बात देखने को मन ती है कि पूंजी प्राप्त करने के लिए कई उपाय काम में लिए जाते हैं। मुख्यतः ये उपाय निम्नलिखित हैं—(अ) जमा के रूप में सर्व साधारण से रुपया प्राप्त करना, (आ) व्यवसायियों, उनके मित्रों अथवा मैनेजिंग एजेंटों से जमा के रूप में रुपया प्राप्त करना, (इ) इन्डजिनिस् बैंक्स से हवालगी के रूप में रुपया प्राप्त करना, और (ई) मिश्रित-पूंजी वाले बैंकों से ऋण लेना। सूती कपड़े के बम्बई और विशेषतः अहमदाबाद स्थिति कारखानों में सर्व साधारण से जमा के रूप में रुपया प्राप्त करने का उपाय ही प्रधानतः काम में आता है। ये जमा थोड़े समय के लिए, प्रायः एक वर्ष से लेकर छह महीने तक के लिए, प्राप्त

होती है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि हिमा कनिहा के समय जब स्पष्ट ही सन्ने अधिक आवश्यकता हो सन्ता है तबानक सन्ना बारम बीच लिखा जाण। निछले क्या म अहमदाबाद म यह भा दया गया कि इस तरह का जमा पान म मान नपना न निष्ट हो सन्ता है। इसम अचानक सन्ना लिख पाण का खतरा ना बन्त सम हो जाता है परन्तु इस प्रणाली का एक बड़ा हानि यह है कि सिस्वमनाय ग्रीगमिज हिस्मा, अन्तु परकों तथा दूसर प्रति भूता (रिक्वारिटाव) का सन्ना म क्या ज्ञान न विनियोग (इन्वन्टमन्) क बाजार न विज्ञान म बाया जाता है।

बाच न पन न आर अरनाउन तण उगाता न गुना प्राप्त करण का एक मात्र उपधन अन्तु न दूसर पम्बर की प्रणाली है। इस पणाली क अनेक लाभ भी हैं। १ लाभ ना सन्ना उदार दस है उस अन्तानविरण म अपना ज्ञानम भी मानत है और समलिण अचार सन्ना लिख जान का नर इसम नहा रहता। समर अलाना दश म एस आगों क लिण समुचित वकिग व्यवस्था न हान न उनर लिए पृ त्त प्राप्त करण का अ य का उपाय है भा नहा। इस प्रकार न जिना जमा का एक लाभ दन् मा है कि सन्ना न समय नर बैक तक सुरलि सन्ना न सम लों म भा थका सन्ता का नीति उरतने लगते हैं इस प्रकार का पृ त्त म नको महामता मिलता है। पन्तु उपरुच लाभों क राध-राध इस प्रणाली न कुछ दाप मा हैं। २ वार इस प्रणाली क कारण जिना एक ही मैनिग एन्टी का पम पर उम हातन म अन्तिम बार आ पकता है नर कि जना एक पम का क सन्ना का आदिग व्यवस्था करण पकता है। समर अलाना विनियोग (इन्वन्टमन्) न बाजार क विज्ञान म इस प्रणाली न भा ककावट सन्त हाता है।

५ जी प्राप्त करन का तामरा प्रणाली जिमरा ऊपर उल्लेख किया गया है इस नकम (इन्वन्टमन् मैडम) म कवावगी सन का है। इस प्रणाली का सहाय एस पृ त्त का अभाव अनुभव करन वाल था छूट आग, मा कामन शकर, दियागभाद न नैस अषदाहत नए ननों म काम करने हैं लेव है। एम उगागों क पास दूसरा का विज्ञान मा नहा हाता। इस प्रणाली का महत्त कम होता नारहा है, हालाकि कुछ उगागा क लिण और काद चाग नरों है। उका यह विवशता हमारा मिबित पृ त्ताना बैचम व्यवस्था और पञा क बाजार का अन्तमता का एक प्रमाण है।

हमारे उगागा क अन्तु शूका-सन्त नरत नर अन्तिम पान मिनिन शूकी जाने बैच है जिनें इन्वन्टमन् बैक आव इष्टिया को भा शामिल कर लेना

चाहिये। इन बैंकों के बारे में आम तौर से देश में यह धारणा है कि औद्योगिक पूँजी की व्यवस्था में इनकी नीति अनावश्यक रूप से कड़ी और अनुदार रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तक इम्पोरियल बैंक एक इव तक केन्द्रीय बैंक का काम भी करता था और इस कारण से उसे कई प्रकार की भयांकाओं में काम करना पड़ता था। आज भी इम्पोरियल बैंक पर पहले की कुछ बर्बादाएँ तो हैं जैसे छद्म महीने से अधिक समय के लिए ऋण अथवा इजालगी नहीं दे सकना, और अपने ही हिसाबों अथवा अखल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकना। परन्तु अन्य सब मामलों में अब वह दूसरे व्यापारिक बैंकों की तरह स्वतन्त्र है। स्वभावतः इस बैंक के पास जैसे साधन और योग्य कर्मचारि हैं उनको देखते हुए इससे औद्योगिक पूँजी के मामलों में अधिक सहानुभूति पूर्ण नीति चलाने की आशा की गई। इससे यह अपेक्षित था कि विभिन्न उद्योगों की पूँजी सम्बन्धी आवश्यकता की जाँच कराई जायगी और जर्मन बैंकों के उदाहरण पर व्यापारिक और औद्योगिक मिला-जुला बैंकिंग का काम शुरू होगा। पर वह आशाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। जो छोटे बैंक हैं, जिनके साधन सीमित हैं और जिनके पास जैसी योग्यता के कर्मचारी नहीं हैं उनसे अधिक आशा जैसे भी नहीं की जा सकती। साधन मग्न और योग्य कर्मचारी वर्ग की जिनकी सेवाएं प्राप्त हैं उन मिश्रित पूँजीवाले बैंकों को इस दिशा में पथ-प्रदर्शन करना चाहिये। फ्रिसकल कमोशन ने भी यह सिफारिश की है कि भारत सरकार को रिजर्व बैंक की सलाह का इस प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में जर्मन बैंकों की कार्यप्रणाली की जानकारी उपयोगी होगी। जर्मनी में उद्योग-धन्ये और साधारण व्यापारिक बैंकों में निकट का सम्बन्ध रहा है। १६ वीं शताब्दी के मध्य में जब जर्मनी में औद्योगीकरण आरम्भ हुआ तो इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई। पैसेवाले लोग न स्वयं उद्योग में लगना चाहते थे और न दूसरों को इस काम के लिए पैसा देने को विचार थे। पूँजी के इस अभाव की पूर्ति बैंकों ने की। जिन के पास पैसा था उनको बैंकों में विश्वास था और इसलिए बैंकों में वे अपना रुपया जमा करते थे और बैंक उस रुपये का उपयोग उद्योग धंधों के लिए करते थे। इस प्रकार बैंकों और उद्योग-धंधों का आपसी सहयोग आरम्भ हुआ।

बैंकों और उद्योगों का यह सम्बन्ध तीन प्रकार का है। पहला प्रकार चालू खाते का है और साधारणतया जर्मन फर्म न केवल चालू पूँजी, पर स्थायी पूँजी के लिए भी, जब तक कि स्थायी प्रबन्ध नहीं होता, इस आधार पर बहुत निर्भर रहती है। दूसरा प्रकार यह है कि बैंक स्वयं औद्योगिक कम्पनियों चालू

करते हैं और उनको पूँजा देने है तथा बाद में सा गाधारण को कमनीय हिस्से बँच कर अनायास राश्व वसूल करलेते हैं। इस उद्देश्य से कूट बैंक मिलकर ना एक सा बताते हैं उच्छा मिड्रास्ट या 'वनमोंगट्रियन' का नाम दिया जाता है। यह सब आरम्भ में 'मम नम' कमाना के ना करने द्वारा जानू का गम है हिस्से खरीद लेना है जो बाद में नमालपर निगाा गया है, अतः को वच श्रिय जान है। यथा यह अर्थ मा है कि निमी मा 'पूँ' का किसी उद्योग से काई स्थाया मकान आयम नहा होना। उद्योगों में मन्व्यर रगन का मोसरा प्रकार आर्थगिक कम्पनियां व गुच्छालर मन्व्यर म नम का प्रतिनिधित्व रखता है, ताकि एक अना दिता ना रना कर उन्हें आर कम्पना की नानि का हम दृष्टि में प्रभाविन भा कर उन्हें। जनन बैंकों की इस नानि को मप नना का एक कारण यह है कि व अने हर प्रकार व लोन देन का निवास अपन आर में बराबर रखत हैं। उदाहरण व तीर पर थोड़े समय व लिए आया हुआ मपया कमी लम्ब समय व लिए किसी काम में नहीं लगाया जायता। उस लिए बैंक को पूँ' का आर समय रनिन काय का उपयोग रिग नायता। यदि कहीं पूँ' की रक मा जाता है तो वह जालम क' रना म क' रना है और हमने अलापा इस दृष्टि में गुन रनिन कोय भा रहत है। इस रमा प्रणाली का एक लाभ तो यह है कि औद्योगिक कम्पनियों को डिगनर्मा स आर्थिक राय मिल जाती है, और दूसर यह कि पूँ' लागाना चाहने वाल व्यक्तियों को बैंक के बीच में पड़ाने से विश्वास अधिक हा जाता है। इस प्रणाली का कुछ हानिर्वा भा है। ना छोटा छोटा पूँ' लागाना चाहने वाल 'यनि हैं उनका महत्व घट जाता है और साधारण वन की जो औद्योगिक कम्पनियों हैं उनकी रचनयता भी किसी हद तक कम हा जाती है। बैंकों न औद्योगिक एकीकरण का भा प्रोत्साहन दिया है। अल्पकालिक साम् व्यवस्था आर व्यापार की आवश्यकता प्रति पर भी इस नीति का असर वादनीय 'ही हुआ है क्योंकि राष्ट्र व सुरन् वाम में आ सकन वाल मारतो का उद्योग में उपयोग हान से जहाँ उनका वामनव में उपयोग हाना चाहिये वहाँ रमा आता है। प्रथम महायुद्ध न पश्चान और द्वितीर शासन के पहले बैंकों का इस प्रगति में कुछ अन्तर अवश्य आया। उद्योग धर्मा की रचनयता, प्रथम महायुद्ध के बाद व मुद्रा प्रसार के कारण उत्पन्न वकों का कमनोर स्थिति, और दुसरे वधिग से होनवाला हानियों का ध्यान, इस परिवर्तन के कारण है। फिर मा जमन वनों की इस नीति से औद्योगिक उन्नति में महायता मिली है और भारत की मा इस दिशा में आगे आना चाहिये।

भारतीय विभिन्न पूँ' वाल बैंकों के बार में एक शिकायत उनके अर्थ

देने की प्रणाली के बारे में भी रही है। शिकायत यह रही है कि बैंक व्यक्तिगत जमानत मात्र पर उधार नहीं देते जैसा कि दूसरे देशों में होता है। इसके लिए बैंकों के साथ-साथ उधार लेने वालों को भी अपने तरीकों में सुधार करना होगा।

उधार लेने वालों को उनके बारे में जाही जाने वाली सारी जानकारी कराना चाहिये। प्रेसीडेन्सी बैंकों और इम्पोरियल बैंक की परम्परा, बैंकों की असफलताओं का ध्यान और मैनेजिंग एजेंटों द्वारा भारती देने की हर समय की तैयारी ने भी इस नानि को प्रोत्साहित किया। विलों के बाजार के विकास और गोदामों द्वारा दीर्घ उनके पास जमा किये गए माल की गोदाम-रसीद का उधार रुपया लेने के लिए उपयोग होने से देश की औद्योगिक पूँजी की समस्या का इस निकलने में सहायता मिलेगी।

औद्योगिक पूँजी की वर्तमान स्थिति का पूरा हाल जानने के लिए इस विषय में मैनेजिंग एजेंटों का जो योग रहा है उसे भी जानना आवश्यक है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से आर्थिक सहायता देते हैं। सीधा उधार देने के अलावा कम्पनियों के हिस्से और ऋण पत्रक भी इनके द्वारा खरीदे जाते हैं। अप्रत्यक्ष सहायता कम्पनी के उधार लेते समय बैंक को गारन्टी देने और जिस कम्पनी का उनसे सम्बन्ध है उसके हिस्से आदि बिकने अथवा सर्व साधारण से खींचे जमा प्राप्त करने में उनके नाम से सहायता मिलने से होती है। मैनेजिंग एजेंसी का काम करने वाली फर्मों पर इस प्रकार की निर्भरता धाँकनीय नहीं है पर दूसरे साधनों के अभाव से यह निर्भरता तो रहनेवाली ही है।

अभी तक हमने औद्योगिक पूँजी की व्यवस्था करनेवाली मौजूदा बैंकिंग संस्थाओं के विषय में विचार किया है। अब हमें दूसरे देशों के उदाहरण को सामने रखकर नई संस्थाएँ स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में एक सुभाव पूँजी लगानेवालों के मनो-विज्ञान का अध्ययन और उनका पथ प्रदर्शन करनेवाली संस्थाओं को स्थापित करने का है। इंग्लैंड और अमेरिका के 'ग्रन्डर-राइटर्स' और जर्मनी के 'सिन्डीकेट' इसी प्रकार की संस्थाएँ हैं और उनकी विशेष जानकारी तथा दृढ़ आर्थिक स्थिति से पूँजी लगाने वालों में एक विश्वास पैदा होता है और उसका परिणाम कम्पनी के सफल संस्थापन में आता है। भारत में इस काम के लिए कोई पृथक् संस्थाएँ तो नहीं बनी हैं, हालाँकि मैनेजिंग एजेंट किसी हद तक इस अभाव की पूर्ति करते हैं।

सहायक हो सकती है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नमूने की कुछ संस्थाएँ हमारे देश में काम भी हुई हैं। जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लि., जे०के० इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लि. आदि। बम्बई और कलकत्ते में कुछ, दसू एट प्राइन्स हाउसेज नाम की संस्थाएँ भी स्थापित हुई हैं जिनका काम निर्यातियों के बिज़ी का डिम्मा लेना अर्थात् अभिगोपन (अन्डर राइट करना) है।

औद्योगिक पूँजी की समस्या को सुलझाने के लिए समय-समय पर वह सुझाव भी रखा गया कि हम काम के लिए अलग-अलग बैंक कायम किए जाने चाहिये। औद्योगिक कर्मीशन और केंद्रीय बैंकिंग जॉब कमेटी भी इसी राय की थी। केंद्रीय बैंकिंग जॉब कमेटी का यह निष्कर्ष था कि, प्रत्येक प्रान्त में एक प्रान्तीय औद्योगिक कॉर्पोरेशन की स्थापना होनी चाहिये और उसकी पूँजी की व्यवस्था प्रारंभ में या फिर स्थायी तौर से हो प्रान्तीय सरकारों द्वारा भी जानी चाहिये। प्रान्तीय सरकारों को इनके द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रक (डिबेंचर्स) भी खरीदना चाहिये या उन पर मिलने वाले व्याज की गारन्टी देना चाहिये। ये कॉर्पोरेशन दीर्घकालीन जमा-जिनका समय दो वर्ष से कम का न हो—स्वीकार करें। जब तक इनके सम्बन्ध में सरकार का स्पष्ट या किसी दूसरे प्रकार का डिम्मा रहे उनके संचालक मण्डलों पर सरकार का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। इनका काम उद्योग-धन्यों को लम्बे समय के लिए पूँजी उधार देना होना चाहिये। किस प्रकार के उद्योगों को ये कॉर्पोरेशन सहायता दें इसका निर्णय बैंकिंग कमेटी की राय में सम्बन्धित प्रान्तीय सरकार पर ही छोड़ना ठीक होगा। केवल इतना ध्यान अवश्य रहना चाहिये कि सहायता पानेवाले उद्योग ऐसे हों जिनसे “जनता का हित होने वाला हो, प्रान्त की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो और लोगों को काम मिले।” प्रान्तीय कॉर्पोरेशनों के कामों में सम्भव करने की दृष्टि से एक अखिल भारतीय औद्योगिक कॉर्पोरेशन की स्थापना भी आवश्यक मानी गई। इन प्रकार के अखिल भारतीय कॉर्पोरेशन की आवश्यकता इसलिए भी मानी गई कि जिन उद्योग-धन्यों का मद्दब सारे राष्ट्र की दृष्टि से है उनके विकास में सहायता देना इस कॉर्पोरेशन का काम होगा। इसके अलावा और भी कई ऐसे काम हैं जैसे उद्योग-धन्यों के लिए सामान खाने-लेजाने के रेल-किरायों में रियायत करवाना, केंद्रीय सरकार की सामान खरीदने की नीति, आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी नीति तथा दूसरी उद्योग-धन्यों से सम्बन्ध रखनेवाली नीतियों का औद्योगिक उद्योग को ध्यान में रखते हुए निर्णय कराना, जिनको अखिल भारतीय कॉर्पोरेशन व्यापक अन्धी तरह कर सकता है।

पिछले वर्षों में इस प्रकार की कुछ संस्थाएँ देश में कायम हुई हैं।

‘इन्डस्ट्रियल कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ यूनाइटेड प्राविप’ नाम की संस्था उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए सभी समय हमारा । परन्तु हमारा उद्देश्य छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायता करना है । अन्य प्रांतों (अन्य राज्यों) में भी हम प्रसारण प्रयत्नों का बड़ा आवश्यकता है ।

हम दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयत्न कर्नाटक सरकार द्वारा ‘इन्डस्ट्रियल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन’ की स्थापना करने दिया गया है । जनवरी १९४८ में मलाला पार्लियामेंट ने इस विषय में आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया । कॉरपोरेशन का उद्देश्य बांध में समय के लिए और हाथकालीन औद्योगिक पूँजी का व्यवस्थापन करना है । कॉरपोरेशन का पुनः दिशा पूँजी १० करोड़ रुपये तक होगी है । हमारे स ४ करोड़ का पूँजी ५ हिस्से निम्नलिखित जारी किए गए हैं । बांध के बाद में आवश्यकतानुसार कर्नाटक सरकार को स्थापित करने और अन्य भाग सकते हैं । ५ भाग वापिस करने और हिस्सेदारों का मूलतः लाभ मिलने में । गारंटी कर्नाटक सरकार ने दी है । कॉरपोरेशन में ६० प्रतिशत हिस्सा पूँजी भारत सरकार और शेष ४० का बांध । १० प्रतिशत सहायता बैंक का हिस्सा होगा । उद्योग अनाया इम्पारियल बैंक, स्टार्ट अप बैंक (स्टार्ट अप बैंक) और इन्वेंट्स कम्पनियों को है । कॉरपोरेशन के हिस्से सहायता का अधिकार है । का” व्यक्ति विभिन्न कॉरपोरेशन में हिस्से नहीं करीब सकता । मानि सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार का यह अधिकार है कि वह बैंक को आवश्यक हिस्सेत द मर । इन सब प्रतिस्था का लक्ष्य यहाँ है कि कॉरपोरेशन राष्ट्र के हित की दृष्टि में औद्योगिक उन्नति के लिए काम कर सकें ।

बक न कार्य संचालन का अधिकार १२ व्यक्तियों के एक माल को है जिसमें छह भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त होंगे । शेष छह अन्य हिस्सेदार चुनेंगे । इन बारह में एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा । कॉरपोरेशन अपनी सहायता के लिए सलाहकार समितियों स्थापित कर सकता है जो उसे यह सलाह दें कि अधिक व्यवसाय को अक्षय देना टाक होगा या नहीं । अक्षय स्थल सहयोगी समितियों और मिश्रित पूँजी वाला कम्पनियों का है दिया जा सकता है और कोई एक अक्षय ५० लाख रुपये से अधिक का नहीं हो सकता । अक्षय रूपों में प्रयत्न विदेशी मुद्रा में जहाँ भी आवश्यकता समझी जाए दिया जा सकता है । औद्योगिक उन्नति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अमेरिका के ‘एकमोट एन्ड ट्रम्पोर्ट कॉरपोरेशन’ से अक्षय प्राप्त करने के लिए या हमारा यह कॉरपोरेशन अक्षय में काम कर सकता है । कॉरपोरेशन का सारा कार्य संचालन व्यापारिक

सिद्धान्तों के अन्वय पर होगा। जैसा पहले कहा चुका है इस बात की आवश्यकता है कि राज्यों में भी इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की जाए।

उद्योग-धंधों की आर्थिक सहायता पहुँचाने का एक और उपाय जो काम में लाया गया है वह है उद्योग-धंधों को राज्य द्वारा सहायता देने सम्बन्धी कानून पास करके उनके अन्तर्गत आवश्यक आर्थिक सहायता करना। सबसे पहले मद्रास ने १९२२ में इस मामले में पहल की और उसके पश्चात् कई प्रान्तों ने उसका अनुकरण किया, जैसे तत्कालीन बिहार-उड़ीसा (१९२३), बंगाल (तत्कालीन) (१९३१); मध्य प्रान्त १९३४ और तत्कालीन पंजाब १९३५। उद्योग धंधों को इन कानूनों के अन्तर्गत कई प्रकार की सहायता दी गई, जैसे—ऋण देना, बैंक से प्राप्त केस फ्रेडिट, बैंक ड्राफ्ट और फिक्सड एडवांस की गारंटी देना, हिस्से अथवा ऋणपत्रक (डिवेन्स) खरीदना, पूँजी के किसी अंश पर न्यूनतम मुनाफा की गारंटी देना, 'हायर-यरचेज' व्यवस्था के अन्वय पर मशीनें उपलब्ध करना, और रियायती दामों पर जर्मन, कच्चा माल, ईंधन पानी, तथा विशेषज्ञों और राज्य कर्मचारियों की सेवाओं की व्यवस्था करना, और अनुसंधान तथा मशीनें खरीदने के लिए आर्थिक सहायता करना। यह स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार जो भी सहायता उद्योग-धंधों को दी गई उसका अनुभव कुछ संतोषजनक नहीं रहा। सहायता के बावजूद भी कई उद्योग सफलतापूर्वक नहीं चल सके और कईयों ने उधार लिया रुपया नहीं लौटाया। इस असफलता के कारण भी अनेक रहे हैं, जैसे—यिना किसी निश्चित योजना के रुपया लगाना, शलत उद्योगों की सहायता कर देना, जोखिम का विभिन्न प्रकार के उद्योगों में समुचित बटवारा न करना, समय पर कर्ज नहीं मिलना, और पूरी जाँच के बाद सहायता दी जा सके इसकी समुचित व्यवस्था न होना। इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान रखने की अत्यन्त आवश्यक है कि आर्थिक सहायता के ये प्रयोग आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त संकटपूर्ण समय में आरंभ किए गए थे। अस्तु, केवल उपर्युक्त अनुभव के अन्वय पर किसी निर्णय पर पहुँचना उचित भी नहीं हो सकता।

अब तक औद्योगिक पूँजी के प्रश्न पर हमने केवल इस दृष्टि से विचार किया है कि देश में जो पूँजी के साधन उपलब्ध हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग कैसे किया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वसाधारण में विनियोग की वृत्ति का और विनियोग की वर्तमान सुविधाओं का पूरा-पूरा विकास कैसे संभव हो सकता है, इस विषय में हम ऊपर-विचार कर चुके हैं। पर इस प्रश्न का एक और पक्ष भी है—जो अधिक आधारभूत महत्त्व का है। इस पक्ष का

सम्बन्ध लोगों का आय में है। अन्ततः गत्वा यह बात गढ़ा है कि जितना अधिक हमारा आय होगा उन्ही दिशाओं में यदि हम चारों तरफ से अपना बना सकेंगे और औद्योगिक पूँजी में अपना लगाया जा हमारी सम्पत्ति भी हम पर आश्रित होगी। इसका अर्थ यह है कि हम अपने उन साधनों में जो अभिवृद्धि करने चाहिये वे हमारा आर्थिक पुँजी का स्रोत हैं। उदाहरण का प्रायः बढाने का प्रश्न आश्रित होता है। परन्तु यह कि जब बार में उत्पादन का दृष्टि का नहीं करना। दूसरी बात विचारों का यह है कि हम में अपने देश का उद्योग की अपेक्षा पूँजी के रूप में लगान का उचित षट्। इसमें एक प्रकार की जित फटिनाइयाँ का उल्लेख किया जाता है जो है—राज्यीकरण का अर्थ, अर्थिक आदक, मैनेजिंग प्रवर्तकों का बना कायदागिरी, स्टॉक बाजार में गद्दा और उभार परिणाम स्वरूप सिधोरिटाउन के मूल्य में अस्थिरता, राष्ट्रीय आय में अन्तर्गत में प्रविष्टि पर विवतन और पूँजी जारी करने के बारे में सरकार का पूँज्य स्थापित। इस बात का पूरी आवश्यकता बनाई जाता है कि उदाहरण का यह है कि कठिनाइयों को दूर किया जाए। पर यह बात समझने का बात है कि हमें से कई कठिनाइयों का कारण में कोई बड़ा अर्थ नहीं है।

अपनी राष्ट्रीय आय बढाने और उनका एक अन्तर्गत अर्थ पूँजी का तीर पर लगान में लिए जो कुछ किया जा सकता है वह अर्थ है किया जाना चाहिये। पर जो औद्योगिक पूँजी का बढाने का एक उपाय और है और वह है विदेशी पूँजी की व्यवस्था। अब हम विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में मोड़ा विचार करेंगे।

विदेशी पूँजी—देश में आर्थिक उन्नति में सब-सब में विचार करते समय विदेशी पूँजी का प्रश्न भी बराबर सामने रहा है। विदेशी पूँजी की हमारे देश में जो प्रगति रही है, और जो इस समय भी गमात नहीं हो गई है, उसे देखते हुए उसका व्यावहारिक महत्त्व और भी बढ जाता है। १९ वीं शताब्दी के मध्य में ही विदेशी पूँजी का आना आरम्भ हुआ और आज हमारे कई प्रमुख उद्योग वहाँ में, जैसे—चूँच, उदाहरण गतागत का कम्पनिया, रेल्व, बीमा कम्पनिया, चाय और काफी के वन, अन्न उद्योग, चमड़ा कमाने के उद्योग, और पाट बनाने के उद्योगों में विदेशी पूँजी ही लगा हुआ है और विदेशी पूँजीगिरियों द्वारा ही वे उद्योग गतिमान और नियंत्रित भाँ होने हैं। हमारे सामने विचारणीय प्रश्न एक ही है कि विदेशी पूँजी को सहायता से अन्तर्गत आर्थिक विकास करना उचित है या नहीं और इस सम्बन्ध में मारत का स्थिति क्या है।

। किसी भाँ देश को आर्थिक उन्नति के लिए विदेशी पूँजी की सहायता

तभी चाहिये जब उस देश के पास अपनी पूँजी अपत्यांत माना में हो। यदि विदेशी पूँजी पर जो व्याज देना पड़े उससे अधिक उसके द्वारा आय हो, और आन्तरिक पूँजी की अपेक्षा सस्ते आघार पर वह पूँजी मिल सके, तो विदेशी पूँजी लेने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इस पूँजी का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि देश आर्थिक उन्नति अधिक तीव्र गति से कर सकता है। और आर्थिक दृष्टि से जैसे-जैसे कोई देश प्रगति करता जाता है, विदेशी पूँजी की उसकी जरूरत भी कम होती जाती है। इस प्रकार एक निश्चित समय में विदेशी पूँजी की आवश्यकता अपने आप कम हो जाती है।

विदेशी पूँजी से कुछ नुकसान भी हैं। एक सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि देश में निहित स्वायों की एक ऐसी भेगी बन जाती है जो आगे चलकर राष्ट्रीय हित के विपरीत हो। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। सारांश यह है कि किसी भी देश में विदेशी पूँजी का अबाध प्रवाह उस देश के हित में कभी नहीं हो सकता। सरकार को विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में ऐसी शर्तें लगाना चाहिये जिससे एक ओर तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो सके और विदेशी पूँजी को देश के आर्थिक जीवन में कोई प्रभुत्व प्राप्त न हो। दूसरी ओर विदेशी पूँजी से मिलने वाले समस्त सम्भावित लाभ भी उस देश को मिल सकें। उदाहरण के तौर पर जो भी विदेशी कम्पनियाँ भारत में स्थापित हों वे भारत में ही रजिस्टार की जाती चाहिये और उनकी पूँजी भारतीय मुद्रा—रुपये में होनी चाहिये। हिस्सा पूँजी का एक निश्चित अंश भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित होना चाहिये। संचालक-मंडल में भी भारतीयों के लिए अनुकूल संख्या में स्थान निश्चित होने चाहियें। और अन्तिम बात यह है कि ऐसी कम्पनियों को भारतीयों को शिक्षा देने की व्यवस्था भी करनी चाहिये। उपर्युक्त प्रतिबन्धों का वास्तव में क्या परिणाम आने वाला है, इस बारे में पहले से ही कुछ निश्चयात्मक रूप से कह सकना कठिन है, पर फिर भी अनुभव से लाभ उठाते हुए इस दिशा में आगे तो बढ़ना ही चाहिये।

भारत को अपने औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूँजी चाहिये इसमें कोई सन्देह नहीं। विदेशी पूँजी की आवश्यकता का केवल यही एक कारण नहीं है कि जितनी पूँजी हमें चाहिये उसकी अपेक्षा जो पूँजी हमें अपने देश में ही उपलब्ध हो सकती है वह कम है। इसका एक दूसरा कारण भी है। देश की औद्योगिक उन्नति के लिए हमें मशीनों आदि जैसा कई प्रकार का सामान आन चाहिये और उसमें से अधिकांश हमें विदेशों से मँगाना होगा जिसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। देश के आयात-निर्वात की जो आल स्थिति है, उसमें

आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का हमारे पास या तो यह साधन है कि जो हमारा स्वरचित जमा है उसका हम उपयोग करें, या फिर विदेश में पूँजी उधार लें। श्री चू कि गो स्टर्बलिंग हम उपार्ज होगा यह सारा का साग ही स्थावर म परिणत न । मिया जा सकता इसलिए सिया विदेश प्रदानत अनेरिछा जैम न्मम मुद्रा वाते देशों र पूँजी उधार लने क और कोई उधार हमारे पास है नहीं । 'गो उर भा निष्ठा ना चुका है, विदेश पूँजा से और भा लाभ है । टेकनिकल ज्ञान' और आधुनिक अनुसंधान का लाभ मिल सकता है । साथ ही 'नैतिकता' और 'प्रवृत्तियों' की प्राप्ति के उम पर ट्रेनिंग की सुविधा भी मिल सकती है ।

विदेशी पूँजा र सम्बन्ध में दूसरा महत्त्व का प्रश्न यह है कि हम पूँजा का उपयोग किस किस कामों के लिए किया जाय । इन बारे में प्रात सर्व सम्मति म यह माना जाता है कि विदेशी पूँजा का उपयोग या तो राज्य द्वारा मन्त्रालय उन पात्रनाम्ना के लिए किया जाए जो विदेशी मरानों आदि पर निर्भर हैं, जैसे—पानी से बिजला उत्पादन की योजनाएँ या उन नए प्रकार क उपयोगों क वास्तु मिनक । विदेशी टेकनिकल सहायता क बिना स्थापना नहीं हो सकता । व्यक्तिगत उत्पादन के क्षेत्र में भी विदेशी पूँजा का उपयोग फल उसे नए उम र उत्पादन कार्यों में किया जाना चाहिये मिनक लिए देश में पूँजी और प्रवृत्त उपलब्ध न हो । किसकल कमीशन (१९५०) इस राय से साधारण तथा सहमत है । उसका एक सहीपा उनका है कि जहाँ किसी भी चीज़ का देश में उत्पादन उसका साग की अवेना कम है और उसमें तत्काल वयेष्ट मात्रा में वृद्धि होने का भी कोई संभावना नहीं है, तो सरकार की उस काम के लिए विदेशी पूँजी की, जो वह उचित समझे, उन शर्तों पर व्यवस्था करने का पूरी आज़ादी होनी चाहिये ।

विदेशी पूँजी से सम्बन्ध रखनेवाला तीसरा प्रश्न यह है कि किस रूप में यह पूँजी आनी चाहिये । मोटे रूप में दो प्रकार से यह पूँजी आ सकता है—एक तो सीधे तौर से विनियोग द्वारा और दूसरे अप्रत्यक्ष विनियोग (इन्वेंस्टमेंट) द्वारा । सीधे विनियोग का अर्थ यह कि विदेशी पूँजी हिरमे आदि का शकल में उपयोग घरों में लगाई जाए । इसके कद लाभ हैं । जहाँ पूँजी के साथ साथ 'टेकनिकल ज्ञान' (टेकनिकल नो हाऊ) और अनुभव की आवश्यकता है, जैसे मण ढग के उद्योगों में, जिनसे भारतीय व्यवसायी वर्ग अपरिचित है, या उन रास्तीय योजनाओं में जहाँ ऐसे ज्ञान और प्रवृत्त की जो देश में उपलब्ध नहीं है, आवश्यकता है, वहाँ सीधे विनियोग द्वारा विदेशी

पूँजी प्राप्त करना अधिक उपयोगी होगा। देश के लोगों के लिए आवश्यक ट्रेनिंग की व्यवस्था भी इस प्रकार अच्छी और जल्दी हो सकती है। विदेशियों से ऋण सम्बन्धी जो मुद्दाइये किए जाएँ उनमें भी किसी हद तक परिवर्तन की गुंजाइश इस प्रकार के विनियोग में संभव है। इसके अतिरिक्त एक लाभ यह भी है कि इस प्रकार से देश के विदेशी मुद्रा के जो साधन हैं उन पर कुछ बोझ कम हो सकता है, क्योंकि सीधे विनियोग द्वारा जो विदेशी पूँजी प्राप्त की जायगी और जिसमें विनियोग के एजेंट में मिलने वाले मुआवजे का व्यवसाय-विशेष का आय से सम्बन्ध होगा, उसके बारे में विदेशी उधार देने वालों को उनके ऋण के लिए जो कुछ देना पड़ेगा, वह देश की मुद्रा में ही दे दिया जा सकता है, और परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा पर से उतना बोझ कम हो जाता है। अब तक हमने सीधे विनियोग से प्राप्त होने वाली विदेशी पूँजी का ही विचार किया है। अप्रत्यक्ष विनियोग का जहाँ तक प्रश्न है वह उन मामलों में उल्लेख हो सकता है जहाँ विदेशी पूँजी की आवश्यकता केवल इसलिए होती है कि विदेशी मशीनों तथा अन्य आवश्यक साधनों और साधरण से साधारण सलाह, जो ऐसे साधनों के उत्पादक देते हैं, का चुकारा करना है। विदेशी मुद्रा की कठिनाई होने से ही इस प्रकार विदेशी पूँजी की आवश्यकता होती है। सरकारी तौर पर या ऐसी अर्द्ध सरकारी संस्थाओं, जैसे—अन्तर्राष्ट्रीय बैंक या अमेरिका का आयात-निर्यात बैंक से ही इस प्रकार की विदेशी पूँजी प्राप्त हो सकती है।

विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में जो कुछ हम ऊपर लिख चुके हैं उसका सार यह है कि अपने औद्योगिक विकास के लिए यद्यपि हमें विदेशी पूँजी की महापटा लेनी होगी पर उस सहायता के सम्बन्ध में आवश्यक सावधानी और मर्यादाओं का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना होगा। इसकी आवश्यकता का महत्त्व समझने के लिए पिछले वर्षों में हमारे देश में भारतीय नामों की छत्रछाया में कई विदेशी कंपनियों ने भारत-सरकार की भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की नीति से लाभ उठाने के वास्ते जो अपना विस्तार फैलाना चाहा है, उसे हमें याद रखना चाहिये। इस प्रकार की कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम ये हैं—लीवर ब्रदर्स इंडिया लिमिटेड, इनलेप रबर कंपनी इंडिया लि०, बारा शू. मेन्यूफैक्चरिंग इंडिया लि०, गुडरिच टायर्स एन्ड रबर कंपनी इंडिया लि०। इन सब कंपनियों ने अपने नाम के आगे भारतीय दिखाने के लिए 'इंडिया लिमिटेड' शब्दों का प्रयोग किया है और वे अपने संचालक-मंडल में एक-दो भारतीय को भी स्थान देने की होशियारी बरतती हैं। देशी व्यवसाय की रक्षा के लिए इस प्रकार के प्रयत्नों को किसी न किसी प्रकार रोकने की आवश्यकता तो है।

कम्पनी-कानून में सुधार

भारत सरकार के प्रस्ताव

सन् १९२६ में वर्तमान कम्पनी एक्ट पाग हुआ था। उससे परचाए गए महायुद्ध के समय श्री बादल मिश्रित गुंजावाना कम्पनियाँ की माल्या में काफी वृद्धि हुई। यह अनुभव किया जाना लगा कि वर्तमान कम्पनी कानून में सुधार की आवश्यकता है। विशेष तौर पर मैनजिंग एजेंट्स प्रथा के सम्बन्ध में सुधार की आवश्यकता और भी अधिक सागन आरहा थी। अक्टू १९४६ के मन्त्रालय महानिर्देश में भारत सरकार ने कम्पनी-कानून में सुधार करने सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव आगे रखा है जिसे प्रस्तावित किया। संतोष में हम इन प्रस्तावों का पढ़ा उल्लेख करेंगे। पहले मैनेजिंग एजेंट्स प्रथा से सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्तावों के बारे में लिखा उचित होगा।

मैनजिंग एजेंट्स में सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव—इन प्रस्तावों में सबसे पहले यह कहा गया है कि यद्यपि वर्तमान कम्पनी एक्ट में मैनेजिंग एजेंट्स सम्बन्धी यह धारा है कि निम्न द्वारा हम प्रणाली को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया गया है पर वह प्रयत्न सफल नहीं हो सका है और इस प्रणाली में आज भी कई दोष हैं जो न्याय में हैं। निम्न मुख्य मुख्य दोषों का इन प्रस्तावों में उल्लेख किया है वे इस प्रकार हैं—हालांकि समझा यह जाता है कि मैनेजिंग एजेंट्स कम्पनी के संचालकों के नियंत्रण में काम करते हैं, पर वास्तविकता इससे सर्वथा विपरीत है। संचालकों पर मैनेजिंग एजेंट्स का प्रभाव होता है और वे जैसा चाहें वैसा संचालकों से करवाते हैं। दूसरा शिकायत यह है कि मैनेजिंग एजेंट्स अपने स्वार्थ के सामने रखते हैं—कि हिस्सेदारों के हित का ध्यान रखते हैं—कम्पनी के काम का संचालन करते हैं। दूसरी शिकायत यह है कि कम्पनी की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैनेजिंग एजेंट्स स्वयं ले लेते हैं और हिस्सेदारों के लिए बहुत कम छोड़ते हैं। भारत सरकार उपर्युक्त शिकायतों को दूर करने की दृष्टि से मैनेजिंग एजेंट्स प्रणाली पर जो प्रतिबंध आन है ठीकी और अधिक बड़ा करने की आवश्यकता समझती है। इस उद्देश्य से सरकार ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं वे निम्नलिखित हैं—

(१) पत्यक्ष अथवा परान रूप से मैनेजिंग एजेंट्स कोई ऐसा व्यापार नहीं करेंगे जो उस कम्पनी के, जिसने वे मैनेजिंग एजेंट्स हैं, व्यापार के समान है।

(२) मैनेजिंग एजेंट्स किसी गा ऐसी दो या दो से अधिक कम्पनियों के मैनेजिंग एजेंट्स नहीं होंगे जो एक ही प्रकार का व्यापार करती हैं।

(३) प्राइवेट कम्पनियों में मैनेजिंग एजेन्ट्स नहीं रह सकेंगे।

(४) कम्पनियों में मैनेजिंग एजेन्ट्स का कार्य नहीं कर सकेंगी।

(५) मैनेजिंग एजेन्ट्स को शुद्ध लाभ का जो अधिकतम प्रतिशत दिया जा सकता है वह निश्चित होना चाहिये और पर्याप्त लाभ न होने की हालत में जो न्यूनतम मुआवज़ा उनको दिया जाये वह वसूल-भूँजी (पेट अप केपिटल) के प्रतिशत के रूप में एक निश्चित शृंखला के अनुसार होना चाहिये।

(६) मैनेजिंग एजेन्ट्स को जो मुआवज़ा दिया जाए उसमें कार्बाल-सर्व के लिए कोई अलाउन्स नहीं होना चाहिये।

(७) मैनेजिंग एजेन्ट्स के नियुक्त होने के बाद हिस्सेदारों की पृथक् साधारण सभा में जो मुआवज़ा उनको दिया जाए वह स्वीकृत होना चाहिये।

(८) नं. ५ में दिये गए मुआवज़े के अलावा और कोई मुआवज़ा देने की यदि शर्त होगी तो वह कम्पनी पर लागू नहीं होगी। मैनेजिंग एजेन्ट्स या अन्य कोई, जिनमें मैनेजिंग एजेन्ट्स का आर्थिक हित है कय, विक्रय अथवा टर्नओवर पर कोई कमीशन नहीं ले सकेंगे।

(९) यदि कुप्रबन्ध के कारण अथवा उन हिस्सों के मत से जो मैनेजिंग एजेन्ट्स के पास अथवा प्रभाव में है, मैनेजिंग एजेन्ट्स की सेवाएँ समाप्त की जायँगी तो उनको कोई हज़ाना नहीं मिलेगा।

(१०) प्रथम कार्य-काल के पहले या ठीक उसके समाप्त होने पर दुबारा नियुक्ति प्रधान कम्पनी के विशेष प्रस्ताव से हो सकती चाहिये। प्रथम पुनः नियुक्त का कार्य काल १० वर्ष का और उसके बाद ५ वर्ष का ही होना। यदि मैनेजिंग एजेन्ट्स किसी कार्य-काल के प्रत्येक वर्ष में एक निश्चित औचित 'डेविडेंट' देते हैं तो उनका कार्य-काल साधारण प्रस्ताव से ही ५ साल के लिये बढ़ाया जा सकेगा और हर कार्य-काल के बारे में यही बात लागू होगी। पर बीस वर्ष तक ही ऐसा हो सकता है।

(११) मैनेजिंग एजेन्ट्स की परिभाषा को भी इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिये—“मैनेजिंग एजेन्ट्स से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म से है जो कम्पनियों से हुए किसी शर्तनामे के अनुसार और संचालकों के नियंत्रण और मार्ग दर्शन में कम्पनी के कारोबार का प्रबन्ध करने का अधिकारी है—कोई भी व्यक्ति या फर्म जो इस प्रकार के पद पर काम करता है, फिर किसी भी नाम से सही, वह इस परिभाषा के अन्तर्गत माने जायँगे।

(१२) मैनेजिंग एजेन्टों संबंधी प्रत्येक सहमति पत्र (एग्रीमेंट) रजिस्ट्रार के पास पेश होगा।

चलू करना चाहिये और इसके अलावा कानून के अनुसार जो कुछ किया जा सकता है वह तो किया ही जा सकता है।

(२३) लाभ-हानि के हिसाब के साथ मैनेजिंग एजेन्ट को मिलने वाले मुआवजे के हिसाब का एक व्यौरा भी होना चाहिये। कंपनी के आडिटर द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिये कि मुआवजे का जिस तरह से हिसाब लगाया गया है वह कानून और मैनेजिंग एजेन्ट के मुआवजे सम्बन्धी जो शर्तें हैं उनके अनुसार है।

(२४) केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किन्ती भी समय यह घोषणा करदे कि अमुक धनों और कंपनियों का जहां तक सम्बन्ध है मैनेजिंग एजेन्सी प्रथा लागू नहीं होगी।

भारत सरकार के उपसुक्त प्रस्तावों की देश के व्यवसायी वर्ग ने कड़ी आलोचना की है और उसका आचार यह है कि उक्त प्रस्तावों को स्वीकार करने का तो एक ही परिणाम आ सकता है कि मैनेजिंग एजेन्सी-प्रणाली का अन्त हो जाए। देश की औद्योगिक उन्नति के लिए यह अत्यन्त घातक निर्णय होगा। भारत वर्ष को आज इनका (मैनेजिंग एजेन्ट) सेवाओं की आवश्यकता है। यह हो सकता है कि कुछ मैनेजिंग एजेन्ट अपने स्वयं और पद का दुरुपयोग करते हों और जिनके बारे में कई प्रकार की शिकायतें सही हों, पर सबके बारे में यह स्थिति ठीक नहीं हो सकती। ऐसी दशा में सबके साथ एकसा न्यवहार करना न्याय संगत नहीं होगा। ज्ञान तीर से जो आपत्ति उठाई गई है वह एक तो इस मुद्दा के बारे में है कि एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाली दो या दो से अधिक कंपनियों का एक ही मैनेजिंग एजेन्ट नहीं हो सकता। यह कहा जाता है कि इससे कई प्रकार की हानियाँ होंगी। एक ही मैनेजिंग एजेन्ट जब कई कंपनियों का प्रबन्ध करते हैं तो वे सबके लिए मिला जुला बहुत अच्छा टेक्निकल और दूसरा स्टाफ रखते हैं और इससे उनका खर्च भी कम आता है। इसी प्रकार यह प्रस्ताव भी, कि कोई कंपनी मैनेजिंग एजेन्ट नहीं हो सकती, आपत्तिजनक है। कंपनियों इस अर्थ में व्यक्तिगत आधार पर नहीं चलतीं कि पिता के पश्चात् पुत्र ही अधिकारी होगा, चाहे वह योग्य हो वा नहीं। ऐसी हालत में कंपनी का प्रबन्ध बराबर अच्छा रह सकता है। उसको मैनेजिंग एजेन्ट बनाने का भी वह लाभ है कि जिस कंपनी की वह मैनेजिंग एजेन्ट है उसकी व्यवस्था भी अच्छे हाथों में बराबर रह सकती है। मैनेजिंग एजेन्ट्स की दुवारा भ्रष्टाचार के संबंध में समय को मर्यादित करने का जो प्रस्ताव है उसमें दो आपत्तियाँ उठाई गई हैं, एक तो यह कि २० वर्ष के बाद की स्थिति अनिश्चित रूप में छोड़ दी गई है, और दूसरे

यह कि पुनर्निर्गुण का समय उल्टा होना है। इसका अन्तर बड़े बड़े धर्मों को प्रारम्भ करने में बाधा पड़ने का कारण होगा क्योंकि बड़े-बड़े धर्मों का परिणाम तो लम्बे समय में बाध ही आता है। इतिहास चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्पादक ने प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपने विचार इस शब्दों में व्यक्त किये हैं—“य प्रस्ताव असाधारण तथा विविध और अनियोजित उद्देश्यों के लिए आने का हमारा प्रमुख आवश्यकता है, का इतिहास आपत्तुल है।” जो आपत्तियाँ हैं प्रस्तावों के बारे में ऊपर उठायी गई हैं उनका यह अर्थ नहीं है कि इन प्रस्तावों में कोई अक्षय्य बाधा है ही नहीं। मैनेजिंग एजेंटों के सम्बन्ध में (पुस्तक), मालिकों के दायित्व के बारे में जो सम्बन्ध स्थापित हैं वे उचित हैं। इस प्रकार उद्देश्य लेने और विविधता के बारे में भी प्रस्ताव स्थापित करने में भी बाधा है। शुद्ध लाभ ही जो परिणाम सुभाषित है वह भी अति वैज्ञानिक और न्यायमान है।

इन सबका निराकरण यह है कि उपर्युक्त प्रस्तावों में जो बाधें व्यवसायों के लिए हैं आपत्तिजनक मानी गई हैं वे बाधें हैं निम्नलिखित सम्बन्ध मैनेजिंग एजेंटों के कार्यान्वयन और कार्यान्वयन का सामना करने में हैं। इस बारे में हिंसा निश्चित मत पर पहुँचने में पण्डितों के सम्बन्ध में हम आचारभूत प्रश्न का उत्तर देना चाहिये कि शिक्षित हम सम्बन्ध में प्रणाली को देश की आर्थिक व्यवस्था में बाधा पड़ना चाहता है अथवा नहीं। यदि हम यह चाहते हैं कि यह प्रणाली पथान्त्र प्रचलित रहे और देश में आर्थिक विकास में इसका प्रमुख सहयोग हो न कि बाधा आपत्तियाँ ऊपर उठायी गई हैं वे अवश्य ही विचारणीय हैं। परन्तु यदि हमारा मत था यह है कि मनजिग एजेंटों की प्रणाली का देश के आर्थिक जीवन सम्मान्य हो जाता है प्रदर्शित है तो उपर्युक्त आपत्तियों का उत्तर आश्वस्य नहीं रहता। यह ठीक है कि जब तक देश में मैनेजिंग एजेंटों का स्थापन न हो तब तक दूसरी आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न नहीं होती तब तक हम उनका आवश्यकता होगी और हमारे लिए हम एक साथ उनका बहिष्कार नहीं कर सकते। परन्तु हमारा प्रयत्न यहाँ हो सकता है कि हम एक ओर तो न केवल मैनेजिंग एजेंटों के कार्यों पर उचित नियन्त्रण स्थापित करें और दूसरी ओर उनके कार्य क्षेत्रों को सामान्य करते हुए उनकी सहायता के बिना आर्थिक प्रगति के कार्य में किसी प्रकार की बाधा न हो इसका पूरा पूरा ध्यान रखें। यह एक स्पष्ट है कि देश में अब बिना मनजिग एजेंटों का सहायता के भी नये धर्मों की स्थापना होने लगी है। राज्य का कर्तव्य है कि इस प्रवृत्ति को अनिकाधिक प्रोत्साहन दे। क्योंकि हमारा यह निश्चित मत है कि अन्तर्निर्गुण हमारा अर्थ देश के आर्थिक जीवन में मैनेजिंग एजेंटों की प्रणाली का अर्थ करना होना चाहिये।

कम्पनी कानून में दूसरे प्रस्तावित संशोधन—भारत सरकार के व्यापार-मंत्रालय ने कम्पनी कानून में सुधार करने सम्बन्धी जो दूसरे (मैनेजिंग एजेंसी सम्बन्धी प्रस्तावों के अलावा) प्रस्ताव उपस्थित किये हैं, उनका गम्भीर विवरण इस प्रकार है। प्राइवेट कम्पनियों को अभी तक अपने काम और स्थिति के बारे में सरकार को और जनता को बहुत कम जानकारी देना होता है। अब वह प्रस्ताव है कि वेल्लेसशीट और लाभ-हानि के हिसाब को ऑडिट कराने, कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास सालाना स्टेटमेंट्स और अकाउन्ट्स पेश करने और सब हिस्सेदारों के पास उनको भेजने के बारे में प्राइवेट कम्पनियों पर पब्लिक कम्पनियों के जेसा ही नियंत्रण कर दिया जाए। प्राइवेट कम्पनी अपने रूप को मन चाहे ढंग से उधार न दे सके इस पर भी नियंत्रण करने का सुझाव है। कानून को लागू करने के बारे में भी कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं ताकि कानून अधिक कारगर रूप में लागू किया जा सके और कानूनी कार्यवाही में शीघ्रता हो सके। उदाहरण के तौर पर यह सुझाव है कि कम्पनी कानून का पालन करती है या नहीं इसकी जिम्मेदारी कम्पनी के किसी एक पदाधिकारी पर, चाहे फिर वह कोई एक संचालक हो, या मैनेजर हो, या मैनेजिंग एजेंट हो, या गैरी हो, डाली जानी चाहिये। और किसी तरह की इस विषय में यदि कमी रहे तो वह उक्त पदाधिकारी को कमी मानी जाएगी। पर दूसरे संचालकों और पदाधिकारियों की जो आज जिम्मेदारी है वह व्यों की त्यो रहेगी। कम्पनियों के कारोबार के जांच करने के सम्बन्ध में आज सरकार के अधिकार बहुत सीमित हैं। इसलिये यह सुझाव है कि जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार की आज से बैंकिंग कम्पनी-एक्ट के अनुसार रिज़र्व बैंक किसी बैंकिंग कम्पनी का निरीक्षण कर सकता है, उसी तरह केन्द्रीय सरकार के आदेश से रजिस्ट्रार को या अन्य किसी योग्य इन्स्पेक्टर को साधारण कम्पनियों का निरीक्षण करने का अधिकार हो। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को और कई आवश्यक अधिकार देने का प्रस्ताव भी है। पूंजी सम्बन्धी ढाँचे में भी कुछ सुधार आवश्यक समझे गए हैं। आज तो स्थिति यह है कि अधिकृत पूंजी (ओथराइज्ड केपिटल) और प्राप्त पूंजी (पेड अप केपिटल) में बहुत अन्तर रहता है और कुछ श्रेणी के हिस्सेदारों को मताधिकार भी अनुचित अनुपात में प्राप्त है। अतः, इस स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से भी कई संशोधन करने का प्रस्ताव है। जैसे, किसी भी कम्पनी की वितरित (सम्सक्राइड) पूंजी अधिकृत पूंजी से आधी से कम और प्राप्त (पेड अप) पूंजी वितरित पूंजी से आधी से कम नहीं होनी चाहिये। हिस्सेदारों ने वितरित पूंजी का जितना रुपया चुका दिया है, उसी आधार पर उनको मता-

धिकार प्राप्त होता चाहिये और हिस्से के प्रकार के मारण इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिये, यह भी एक सुझाव है। साधारण हिस्सेदारों को जिस दर से लाभ बांटा जाय उसमें दुगुना से अधिक दर में लाभ डेफ़ड हिस्सेदारों को नहीं मिलना चाहिये और डिफ़ेरेन्स हिस्सेदारों को एक निश्चित दर से ही लाभ मिलना चाहिये। संचालक के दायित्व के बारे में संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं ताकि संचालक मैनेजिंग एजेंटों के कटपुनर्ता बनकर ही न रहें और अपने दायित्व को भली प्रकार समझें। इसा दृष्टि से यह प्रस्ताव किया है कि मैनेजिंग एजेंट के होते हुए भी जानूँ की यदि कोई अग्रहेयता होनी है तो उसके लिए संचालकों का ही निम्नकार माना जाना चाहिये। इसी प्रकार किसी भी सुप्रबंध और अनुचित कार्य के लिए संचालकों की जिम्मेदारी समझा जाती चाहिये। संचालकों के सम्बंध में कई स्वस्थ प्रतिबंध लगाने का भी सुझाव है, जैसे—

डायरेक्टर को मिलने वाला पुरस्कार आय पर से मुक्त नहीं होना चाहिये, ७० वर्ष से अधिक आय का संचालक नहीं होना चाहिये, संचालक के पास जितने हिस्से हैं और जितने अणु पत्र (डिविडेंड) इसका पूरा पूरी सूचना रहनी चाहिये, तथा सदस्य साधारण के, अथवा किसी कम्पनी के निर्माण प्रपत्र व्यवस्था आदि के सम्बंध में सलाह मिल चुका है या व्यक्ति का एक निश्चित समय तक जो पाय वर्ष में अधिक नहीं होना चाहिये संचालक नहीं बनाना चाहिये। आडिटर के बार में जो सुझाव प्रस्तुत किए गये हैं उनका उद्देश्य आडिटर को अधिक स्वतंत्रता और सरलता देना है ताकि वे कम्पनी के बेजा बचाव से बच सकें। जैसे एक सुझाव यह है कि आडिटर का नियुक्ति सम्बंधी प्रस्ताव पर संचालक और मैनेजिंग एजेंट मत नहीं दें। इसा प्रकार दूसरा सुझाव यह है कि जब तक कि कोई आडिटर दुबारा नियुक्ति के अयोग्य ही नहीं हो, या वह दूसरा नियुक्त नहीं होना चाहता उसकी उसने निश्चित सूचना कम्पनी को न देदी हो, या उसका स्थान पर और किसी की नियुक्ति न हासिल हो, उसकी पुनः नियुक्ति करने काय हुं सम्भव माना चाहिये। बेल्लैस शीट और लाभ हानि के विवरण के लिए काम के बार में भी सुझाव है ताकि आज से कहीं अधिक गहरा कम्पनी के कार्य में उपलब्ध हो सकें। अन्तर्गत में यह हिस्सेदार हैं उनका हितों की रक्षा करने का दृष्टि से भी कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं ताकि ज. बटुमंत में हैं वे प्रत्यक्ष जाला के हिता को आघात न पहुँचा सकें। जैसे इस सम्बंध में एक सुझाव यह है कि अन्तर्गत वालों को या संचालकों का समुक्त सम्पत्ति में नियुक्ति करने का अधिकार होना चाहिये। यदि कम्पनी का एक भाग मध्य कम्पनी के कारणों से सम्बंधी कोई सिफाएत करता है तो उस पर आव

रक ध्यान दिया जाने को समुचित व्यवस्था हो इस बारे में भी कुछ सुझाव उपस्थित किये गये हैं। विदेशी कम्पनि सम्बन्धी भी कुछ प्रस्ताव किये गये हैं। इस समय तो उन पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। केवल इतना ही है कि प्रत्येक ऐसी कम्पनी को, जो विदेश में रजिस्टर हुई है और भारतवर्ष में कोई काम करती है, उस प्रान्त (राज्य) के रजिस्ट्रार के पास जहां वह काम करती है, विधान-संचालकों और कम्पनी के पदाधिकारियों के बारे में कुछ जानकारी भेजनी पड़ती है। रजिस्ट्रार के पास विदेशी कम्पनी के हिसाब भी भेजने पड़ते हैं। यदि विदेशी कम्पनी भारत में अपने हितों के बचाव के लिए, तो जिस प्रान्त में हितों के बचाने हैं वहां के रजिस्ट्रार के पास कम्पनी का प्रोस्पेक्टस भी फाइल करना होता है। विदेशी कम्पनी का भारतीय कारोबार भी भारतीय कानून के अनुसार ही चलाया जा सकता है। अब यह सुझाव है कि विदेशी कम्पनियों सम्बन्धी सब कागज दिल्ली में ही रहें और विदेशी कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल हों और उनकी नकल उन प्रान्तीय रजिस्ट्रारों के पास, जहां कम्पनी का काम है, भेज दी जाय। इसी प्रकार विदेशी कम्पनी के भारतीय शाखाओं के काम को समाप्त करने सम्बन्धी कार्रवाई भी दिल्ली में ही केन्द्रित करने का सुझाव है। न्यूनतम पूँजी वितरण के बारे में अधिक ब्यौरा प्राप्त करने सम्बन्धी सुझाव भी उपस्थित किया गया है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि आवश्यकता से कम तो न्यूनतम वितरित पूँजी नहीं रखी गई है। अन्तिम बात इस सम्बन्ध में यह है कि कम्पनी कानून के संचालन सम्बन्धी सुझावों का भी भारत-सरकार के इन प्रस्तावों में समावेश किया गया है। इस समय यह काम पश्चिमी बंगाल और बम्बई के अलावा अन्य प्रान्तीय सरकारों के द्वारा कराया जाता है। वास्तव में केन्द्रीय सरकार की इस एक्ट को लागू करने के लिए कोई पृथक् व्यवस्था है ही नहीं। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। भारत-सरकार के इन प्रस्तावों में रजिस्ट्रार-जनरल ऑफ कम्पनीज़ नाम के एक पदाधिकारी के तत्वा-वधान से ऐसी पृथक् मशीनरी स्थापित करने का सुझाव भी किया गया है। इसके अलावा एक सलाहकार बोर्ड, जिस पर उद्योगपति, मजदूर, स्कॉप त्रिनिटीज आचार (स्टाक एक्सचेंज), निनियोग करने वाली जनता आदि के प्रतिनिधि होंगे, की स्थापना का भी सुझाव है।

भारत-सरकार के उक्त प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं। कम्पनी एक्ट में आवश्यक संशोधनों पर विचार करने के लिए भारत-सरकार ने एक समिति भी नियुक्त की है। उस समिति ने अपना कार्य अभी (मार्च १९५१) समाप्त नहीं किया है। वर्तमान कम्पनी-कानून में सुधार की आवश्यकता है यह तो स्पष्ट ही है।

परिच्छेद १
उद्योग धर्म—श्रम

भारत में आर्य समाज का उद्भव—भारत में पहले आधुनिक अर्थ में भूमि-
व्यवस्था के प्रथम चरण नहीं था। तब प्रथा जो भारत की विरासत रही है,
एक सामाजिक आर्थिक संगठन है और विभिन्न उद्योग-धंधों में काम करनेवाले
स्वामी का वर्गीकरण भी हमारे देश में तब तक आमतौर पर होना रहा है।
जब हम देश में आधुनिक व्यवस्था का जन्म हुआ तो उसके परिणामस्वरूप
आज के आर्य समाज का भी उद्भव हुआ।

हमारे यह उद्योगों व व्यवसायों और गंगा व क्षात्र क्षात्र दुर्गों में गहन
जान का प्रशिक्षण का यह अंश हमें कि शरीर में लग लगी वी गंगा का आय बहुत
कम हाथों था फिर व वंश वंश वंश । ऐसा दशा ॥ इन लोगों ने उज्जर पर काम
करना आरम्भ कर दिया और एक वृक्ष भूमि होन आधिक वंश पैदा हो गया ।

अप्रज्ञा के भारत में गान व माष हाँ माष धमिक जग की माग भी उठान हुए। नील राम शोभ बापों उ भर्ना व लिए मझा मंज्या म मझूरा की आवश्यकता अनुभव होने लगी। मित्रित उपनिषदों में १८६४ में दान प्रथा के समाप्त होने से या इन उपनिषदों में माग्या मझूरा की माग पैदा हु। रेल, कायले का लान और छली कपड़े आर पन्ना उ कारखानों जै आधुनिक उद्योगों का भी स्थापना होने लगी। आरम्भ में इन उद्योगों का मझूर मिलने में कठिनाई हु। पर जन मंज्या में जैम पैस बुद्धि हुइ यह कठिनाई भी कम जाने लगी। शुरू शुरू में कारखानों व लिए मझूरा की भरती करने व पारन काइलाओं के प्रतिनिधिया की गाथा में जाना पड़ता था और तब भी मझूरा की सरया में बराबर कमा नही रहता था। आज तो यह परिस्थिति गवया बदल गई है। पर आसाम के बाप उ नवों के लिए भी मझूर चाहिये, उई तो अब भी जगह जगह जाऊर मज्गी करना पड़ता है। बाका तो आज मझूरी करनेवाले रमय ही मझूरी का ललाय म कारखाना तक पहुँच पात है।

एसा अनुभव किया जाता है कि कुल मजदूरों को संज्या भारत और पाकि-
स्तान में मिलाकर खाली लाल के लगभग है। इनमें पैक्टरियों, चाय आदि
के स्वतंत्र, खाना, रेल के कारखानों, डॉक, तथा पानी और बिजली का कम्पनियों
आदि सब में काम करनेवालों की संख्या शामिल है। इस मजदूर जन सख्या का
लगभग आधा हिस्सा वा बम्बई और कलकत्ते में ही है और बाकी का काफ़ी
बड़ा हिस्सा अहमदाबाद, शोलापुर, कानपुर, जमशेदपुर, मदुरा, कोयंबटूर,

मदरास, नागपुर, और दिल्ली तथा लाहौर (पाकिस्तान) जैसे औद्योगिक केन्द्रों में नियोजन करता है। खान के मजदूरों के केन्द्र बंगाल और बिहार की खानों और आसाम तथा भारत के दक्षिण के प्लान्टेशन इन क्षेत्रों में काम करने-वालों के केन्द्र हैं।

कृषि और ग्राम्य जीवन से सम्पर्क—भारत में मजदूर-वर्ग प्रधानतः गांवों से आता है। पश्चिम के मजदूर-वर्ग से भारतीय मजदूर-वर्ग इस अर्थ में भिन्न है। पश्चिम का मजदूर नगरों का रहने वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत का मजदूर स्वभाव से तो किसान है पर मजदूरी में कारखानों में काम करना है। प्रायः अधिकांश भारतीय मजदूरों का निवास-स्थान शहरों से दूर गांवों में होता है जहाँ से मजदूरी करने के लिए वे शहरों में आते हैं। उनका यह स्थान परिवर्तन स्थानी नहीं होता। इसका यह अर्थ नहीं कि भारतीय मजदूर इस अर्थ में पूर्णतया अस्थायी और स्थान बदलने वाला है (नाइटेरी) कि वह किसी एक स्थान अथवा कारखाने में जम कर काम ही नहीं करता। (लेबर इन्वेस्टीगेशन कमेटी प्रधान रिपोर्ट)। इसका तो केवल इतना ही अर्थ है कि मजदूर अपना घर अपने गांव को ही मानता है। उसकी आकांक्षा यहाँ रहती है कि वह अपने गांव को बापिस लौट जाए। जब तक वह शहर में मजदूरी करता है तब तक भी उसका गांव में आना-जाना बराबर बना रहता है। अधिकतर मजदूरों का तो अपने गांव से खचमुख सम्बन्ध होता है। बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका वास्तव में सम्बन्ध नहीं होता पर फिर भी भावना से वे अपना सम्बन्ध मानते रहते हैं।

इसका यह अर्थ भी कदापि नहीं है कि भारतीय मजदूर मूलतः एक किसान है जैसा कि कई लेखक और मिल-मालिक मानते मालूम पड़ते हैं। बात केवल यह है कि उसका पालन-पोषण गांव में हुआ, उसकी परम्पराएं गांव की हैं, और गांव से उसका सम्पर्क बना रहता है। ऐसे मजदूर बहुत कम हैं जिनका स्वयं खेती के काम से कोई सम्बन्ध होता हो। वह टीक है कि ऐसे मजदूर बहुत होते हैं जो अपना घर गांव से उठाते नहीं, जिनका परिवार गांव में रहता है, जो अपनी आय का एक अंश अपने गांव को भेजते हैं और समय-समय पर वहाँ जाते रहते हैं। पर, जो कारखाने साल भर न चल कर वर्ष के कुछ महीनों ही चलते हैं उनके मजदूर खेती के काम से सम्बन्ध रखते हैं। कोचले की खानों में काम करनेवालों में खेती के काम से सम्बन्ध रखने वालों की संख्या बंधेष्ट होती है। पर बराबर चलनेवाले कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों का प्रायः खेती से सम्बन्ध नहीं होता। वे गांव से सम्बन्ध अवश्य रखते हैं और उस दिन की प्रतीक्षा

में रहते हैं जश्न अपने गांव को लौट जायेंगे। ऐसे मजदूरों की मज्जा बहुत कम, जो न्यायी रूप से औद्योगिक शहरों के निवासी बन गए हैं। इसका कारण यह है कि वहां उनका लिए कोई आश्रय नहीं है। अहमदाबाद, नागपुर, मद्रास, और पम्पदपुर कुछ ऐसे उद्योग केन्द्र हैं जहां स्थायी मजदूरों की अकम्पनी मज्जा है।

ग्राम परिवर्तन का कारण—गांवों से शहरों में जाने की प्रवृत्ति के कई कारण हैं। मजदूर बड़े बाग़ सा यह है कि जब सप्ताह में बराबर कृषि होने से और प्रमाद्यों में नष्ट होने से गांवों में रहना करने वालों का मज्जा बढ़ती जाती है। इन दोनों कारणों में अमिहान में निहारे मजदूरों का संस्था भी काफी है। वेनी से बचपन आया न हवा से बलाग़ शहरों में बालकों में मजदूरों करने जाना पसंद कर लेते हैं। ग्राम ज्ञान का माध्याम ग्राम उपनग्न है ही। सुयुक्त परिवार-प्रणाली में इसमें सहायक होता है, क्योंकि बिना गांव परिवार का पर लुझाए और थोड़ी बहुत यदि रहना है तो उसे बिना छोड़े ही पर न कुछ लोग शहरों में जाकर कारखानों में काम कर सकते हैं। न बाग़ गांव के महात्मनों से छुटकारा पाने के लिए भी शहर में लोग चले जाते हैं। हरिजा आदि जाति के लोग जो गांव में कई प्रकार की सामाजिक अमानताओं का शिकार होते हैं, अपनी स्थिति सुधारने का आशा में गांव से शहर में जाकर काम करना पसंद करते हैं। गांवों से शहरों की ओर जो यह प्रवाह है उसकी एक विशेषता यह है कि शहरों में कोई आश्रय लोगों को नहीं है। य तो गांवों से परगना होने के कारण शहर में जाना पसंद करते हैं, और इसलिए जब काम करने के वे आशय हो जाते हैं तो वापिस गांव की ही लौट आते हैं।

गांव से सम्पर्क के लाभ—मजदूर का अपने गांव से जो सम्पर्क बना रहता है उसका उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अकम्पनी असर पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से भी यह लाभप्रद है क्योंकि मजदूर बकारी, बीमारी अथवा इत्यादि जैसे किछा भी स्थिति में गांव की लौट सकता है और वहां कुछ न कुछ काम भी उसे मिल सकता है। गांव की दुनिया का व्यापक जीवा से सम्पर्क में आने का अथवर मिलता है और वहां के लोगों में व्याप्त अविश्वास और कृषि प्रियता को मिटाने में इससे सहायता मिलती है। उपर्युक्त लाभों का मुफ़ावले में उद्योग पधों की दृष्टि से कई हानिया भी हैं। मजदूर की अपने काम में स्वाई दिलचस्पी पैदा नहीं हो पाती। इसका उसका कार्य प्रश्रयता पर बुरा असर पड़ता है और मजदूर समुदाय की दृष्टि से भी यह बाछनीय नहीं है। इससे अलावा मजदूर की स्वयं की दृष्टि से भी कई कठिनाइयों उपस्थित होती हैं। शहरी जीवन का

उत्तरे स्वास्थ और चरित्र पर बुरा असर पड़ता है। जुआ और शराब को बुरी आदतें उत्तम आ जाती हैं। कारखाने में जो लगातार कड़े अनुशासन में काम करना पड़ता है वह भी उसके अनुकूल नहीं पड़ता क्योंकि गांवों में वह इस प्रकार के काम करने का अभ्यस्त नहीं होता। ये सब होते हुए भी 'विटले कमीशन' का यह स्पष्ट मत था कि गांवों के इस सम्पर्क से कुल मिलाकर लाभ है और वह भविष्य में बना रहे ऐसा प्रयत्न होना चाहिये। पर इस सम्बन्ध में 'लेबर इन्वेंस्टी-गेशन कमेटी' की राय भिन्न है। उनका मत है कि जहां तक आराम के लिए गांवों से सम्पर्क रखने का सवाल है, मजदूर को भविष्य में भी इस सम्पर्क को बनाए रखने के लिए पूरा प्रोत्साहन और सुविधाएं मिलनी चाहियें। पर जहां तक उसकी आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न है उसे गांव पर निर्भर बनाए रखना वांछनीय नहीं है; और न गांव की आज ऐसी स्थिति है कि वह मजदूर की इस अर्थ में कोई विशेष सहायता कर सकता है (प्रधान रिपोर्ट)। इसका अर्थ यह है कि औद्योगिक केन्द्रों में मजदूरों के काम और रहने की परिस्थितियों में सुधार होना चाहिये ताकि नजदूर इन औद्योगिक केन्द्रों के स्थायी निवासी बन जाएं।

हां, यदि बड़े पैमाने के उद्योग गांवों में विकेंद्रित कर दिए जाते हैं तो कई दूसरे आर्थिक लाभों के साथ-साथ एक यह लाभ भी होगा कि नजदूर के अस्थायी होने की हानियां जाती रहेंगी और गांव के सम्पर्क से होने वाले लाभ और बढ़ जाएंगे। मकान, औद्योगिक बेकारी और ऐसी ही दूसरी समस्याओं का हल भी उस हालत में आसानी से निकल आवेगा।

मजदूरों की भर्ती—मजदूरों की भर्ती के सम्बन्ध में, जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, अब स्थिति बदल गई है और मजदूरों को आह्वान वाले लोग स्वयं ही कारखानों तक काम की तलाश में पहुंच जाते हैं। पर मजदूरों का प्रधान स्रोत आज भी गांव ही है; यद्यपि पिछले वर्षों में मजदूरों का एक ऐसा वर्ग अवश्य पैदा हो रहा है जो उद्योग पर ही अपने निर्वाह के लिए निर्भर रहने को तैयार है और बाहर में स्थायी रूप से बस जाना चाहता है।

मजदूरों की भर्ती के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि मिल के मालिक स्वयं मजदूरों की सीधी भर्ती नहीं करते। इस काम के लिए उनके और मजदूरों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति रहता है जो 'जोबर', 'ड्रफ्ट्समैन', 'सरदार', 'टिडल', 'चौबरी', 'कांगानी' या मिस्त्री के नाम से जाना जाता है। प्रधानतः यह 'चार्जमेन' होता है जो अपने विभाग के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है और अपने नीचे काम करने वाले मजदूरों की देख-रेख करता है। भर्ती, वस्त्रास्तगी, छुट्टी, तरफकी या किसी अच्छी जगह पर तबादला, ये सब वास्तव में उसके हाथ

में रहते हैं। इस अतिरिक्त वह मजदूर का स्वयं भी उधार देता है, उनका रहन-रहान उसका हाथ है, और वह उनका पारिवारिक भयभीत आदि की जिम्मेदारी में भी भाग लेता है। पर उसका सबसे प्रधान काम तो मजदूरों की भर्ती करना होता है। अपना इस काम के लिए वह मजदूरों से रिश्ता बनाता है। यहाँ तक कि अस्थायी नाकरा तक के लिए उसे रिश्ता बना होता है। जोर के अलावा और पावू लगाने की (बलक) भी मजदूर का रिश्ता बना पड़ता है। रिश्तादारों के भारनाय कारखाना और रेल के कारखानों में काफी प्रचलित है। जोर एक तरफ तो मजदूरों से रिश्ता बनाता है और दूसरी ओर मिल-मालिक भी उसे भर्ती के काम के लिए मुआवजा देते हैं। कहीं-कहीं तो 'जागर' मजदूरों का मासिक आय में से एक अंश छुट्टी लेना है।

मजदूरों सम्बंधी इंडियन कमिशन ने और बाग्स टक्स्टाईल लेबर एनक्वायरी कमिटी ने भी इस प्रश्न पर काफी विचार किया और उन्होंने अपनी राय मजदूरों की भर्ती सम्बंधी इस पद्धति के विरुद्ध दी। उनका निष्कर्ष यह था कि मिल-मालिकों को स्वयं इस काम की सीधे तौर पर अपने हाथ में लेना चाहिए और इस लिए 'लेबर आफिसर' नियुक्त किए जाने चाहियें। ये लेबर ऑफिसर जनरल मैनेजर का सीधा मानहता में काम करेंगे। किसी को भी नियुक्ति अथवा परखाएली सीधे निमागव अथवा द्वारा नहीं होकर लेबर आफिसर तक के मामले जाने चाहियें। इस सम्बंध में 'कापुर लेबर इनक्वायरी कमिटी' ने 'जीवनी' द्वारा मजदूरों की भर्ती की प्रचलित प्रथा के विरुद्ध अपनी राय देते हुए यह सिफारिश की थी कि सरकार के नियंत्रण में एक 'लेबर एक्सचेंज' स्थापित करना चाहिए जो मिलों के माग करने पर उनके पास नौकरी के लिए जिन लोगों के आवेदन पत्र आए हुए हैं उनमें से भरती करे।

यद्यपि भरती की यही पुरानी पद्धति आज भी अधिकतर प्रचलित है, पर पिछले वर्षों में लेबर आफिसरों द्वारा सीधी भरती करने की व्यवस्था भी कई उद्योगों में आरम्भ की है। इसके अलावा बम्बई मिल-मालिक मंच ने 'बदली नियंत्रण प्रणाली' भी जारी की है। इस प्रणाली के अनुसार बदली पर काम करने वाले मजदूरों को (खसटोव्स्) अर्थात् उन मजदूरों को जो अस्थायी तौर पर साला स्थानों पर काम करते हैं, काट दिये जाते हैं, और जिनके पास ये काट होते हैं वे व्यक्ति हर रोज काम की तलाश में मिलों के पाटक पर उपस्थित होते हैं। ज्येष्ठता के आधार पर उनमें से साला स्थानों पर अस्थायी नियुक्तियाँ की जाती हैं और उाके रहते हुए नए मजदूरों की भरती नहीं होती। पर इस प्रणाली से भी यद्यपि जोर के अधिकारों में कुछ कमी अवश्य हुई है, पर उससे

सवथा मुक्ति नहीं मिल सकती है। वम्बई के मिल-मालिकों के संघ ने इस दिशा में अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने लेबर आफिसरों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की है और उन लेबर आफिसरों के काम की वे देखरेख भी करते हैं जिनको नियुक्ति उनके द्वारा की जाती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय और 'इंस्टिटयन अट मिल एसोसियेशन' के सम्मिलित प्रयत्न से भी 'लेबर वेल्फेयर आफिसर' की शिक्षा की व्यवस्था चालू की गई है। कानपुर की 'नॉरदर्न इन्डिया एम्प्लोयर्स एसोसियेशन' ने भी एक 'एम्प्लोयमेंट एक्सचेंज' की स्थापना की है। सारांश यह है कि मजदूरों की भरती सम्बन्धी इस नई पद्धति को अपनाते का देश में प्रयत्न अवश्य आरम्भ हुआ है और यह आशा रखना अनुचित न होगा कि पुरानी पद्धति का स्थान यह नई पद्धति अन्ततोगत्वा ले लेगी।

अब तक हमने मजदूरों की भरती सम्बन्धी प्रश्न का आम तौर पर विचार किया है। अब हम कुछ विशेष उद्योगों—जैसे प्लान्टेशन और खानों तथा सार्वजनिक निर्माण को लेकर इस चारे में जानकारी करेगे।

चाय के खेत (प्लान्टेशन)।—चाय की खेती भारत में सबसे अधिक आसाम में होती है। वहां खेतों में काम करनेवाले मजदूर दूर-दूर के प्रान्तों से जाते हैं। आज कल इन मजदूरों की भरती १९३२ में पास किये 'टी डिस्ट्रिक्ट एमिग्रेंट लेबर एक्ट' से नियंत्रित होती है। इस कानून के पास होने से पहले इन खेतों में काम करनेवाले मजदूर इकरार (कान्ट्रैक्ट) के आधार पर नौकर रखे जाते थे। अब इस व्यवस्था का अन्त हो गया है।

१९३२ के कानून के बाद किसी भी व्यक्ति को आसाम में जाकर मजदूरी करने का अधिकार है। पर अपने आप से जानेवाले लोगों की संख्या नगण्य ही मानना चाहिये। इसलिए आज भी इस बात की आवश्यकता है कि आसाम के चाय के खेतों में मजदूरी करने के लिए लोगों को भेजा जाए। इस प्रकार भेजे जानेवाले मजदूरों को सहायता प्राप्त 'एमिग्रेंट' कहते हैं। इन लोगों की भरती करने का जो लोग काम करते हैं उन्हें 'सरदार' कहते हैं। बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो बिना 'सरदार' की मध्यस्थता के अपने आप को भरती कराने को तैयार हो जाएं। जो लोग भरती होना चाहते हैं, चाहे स्वयं और चाहे 'सरदार' की मध्यस्थता से, वे भरती के दिनों पर पेश होते हैं। वहां से लाइसेंस प्राप्त फारवर्डिंग एजेंट उन्हें निश्चित मार्ग से, जहां उनके खाने-पीने, ठहरने और दवा-दोरु का प्रबन्ध होता है, आसाम भेजते हैं। १६ वर्ष से कम के बालक अपने माता-पिता के साथ और विवाहित स्त्री अपने पति की स्वीकृति से ही आसाम भेजी जा सकती है। तीन वर्ष पूरे होते ही और विशेष परिस्थिति में उससे पहले

भी इस प्रकार सहायता देकर भेजे गए मजदूरों को वापस उतारने पर भेजने का विमर्श उनके रेल व मालिकों का है। प्रायः जिन प्रदेशों से मजदूर जाते हैं, उन्हें राय का सरकार का पन्द्रोस सरकार व निवन्धन में, १९३२ के कानून के अनुसार, नियमित भरती व प्रदेश (कन्ट्रोल्ड एमिग्रेशन एरिया) धार्मिक करने का अधिकार है—जैसे मगान बिहार उड़ीसा, मध्यप्रदेश, मद्रास और उत्तर प्रदेश। इन्हीं में से किता प्रन्श अथवा उसके किता भाग का मयादिन भरती व प्रदेश (रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रिक्ट एरिया) धार्मिक करने का अधिकार भा राज्य की सरकार को है। इन मयादिन प्रन्श में साइमन प्राण फार्माटिव एजन्ट या भरती करनेवाला या प्रमाण पर प्राण सरदार' को आशाम व सेवा के लिए मजदूरों का भेजने में सहायता कर सकता है। १९३२ के कानून व अनुसार 'कन्ट्रोल एरिया एमिग्रेशन एरिया' नाम का एक अधिकारी भा नियुक्त है जिसका काम यह देखना है कि उक्त एरिया का टार टीक पालन किया जा रहा है।

'सरदार' का मध्यस्थता में मजदूरों का भरती व काम में शिप में बहुत शिकायत रही है। पीछे से भरती करना, शरण अथवा अथ किसी नशीली चात का मजदूरों का मनन करना आदि रूढ़ शिकायतें हम बारे में पाई गई हैं। १९३२ के कानून व प्रमेल में आन व कानून मुबार अरथ हुआ है। पर वास्तविक मुबार भी नभी होगा जब 'सरदारी पद्धति' ही समाप्त होनाए और स्वतन्त्र रूप से काम करने व लिए आशाम जानेवालों की मख्या इतना हो जाए कि इनमें मजदूरों का माय पूरा हो सके।

दक्षिण भारत में चाय व तैली के लिए मजदूर आग-आग के प्रदेश से जा आते हैं। भरती करीशाल मध्यस्था का व (Kanganyas) कहते हैं। मजदूरों को लाने के लिए इनकी सेवा दिया जाता है। कई बार ये लोग पूरा रूपका मजदूरों को नहीं देते। और भा शिकायत इनके बारे में है। जैसे मजदूरों को शरा देना, बाद में हिसाब साफ करते समय उनकी धोखा देना, मजदूरों को उनसे द्वारा लूट का व मजदूरों में से अग्न लिए कुछ चला लेना और मजदूरों से उनकी मजदूरी पर १० से १५ प्रतिशत तक कमाशन लेना आदि। इस पद्धति व दोनों के कारण यह प्रश्न भा विचारणीय है कि कानून से इसका अन्त हो क्यों न कर दिया जाए।

नहाजी पर काम करनेवाले—अभी तक बहाजी यातायात पर विदेशियों का हा प्रभुत्व रहा है। व मजदूरों की भरती गवर्नमेंट लाइसेंस प्राप्त 'शिपिंग एजेंटों' द्वारा करता है। इस पद्धति में कई दोष हैं। रिस्वत का गूब प्रचार है। इन मजदूरों की समीचीनी समस्या बेकारी की है। यह अनुमान लगाया गया है

कि कुल समुद्री मजदूरों की संख्या—जो काम चाहते हैं—३ लाख है, और लगभग ५० हजार को काम मिलता है।

भारत सरकार ने १९२१ में समुद्री मजदूरों की भरती सम्बन्धी जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी। इस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि 'एम्प्लोयमेंट व्यूरो' की स्थापना की जाए जो मजदूरों की रिश्तत और नौकरी में अस्थायित्व से रक्षा कर सके। जहाजों के मालिकों के विरोध के कारण १९२६ में जाकर सरकार इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने आदेश जारी कर सकी। लाइसेंस प्राप्त ब्रोकरों और दूसरे मजबूतों की सर्वथा मनाही तो नहीं की गई, पर उनके अधिकारों में अन्वय कमी की गई। पर इससे समुद्री मजदूरों को कोई राहत नहीं मिल सकी।

१९४७ में भारत सरकार ने एक विधायी समुद्री मजदूर सलाहकार समिति (मेरीटाइम लेबर एडवाइजरी कमेटी) की स्थापना की है जो सरकार को इन मजदूरों की समस्याओं पर सलाह देने का काम करेगी। बेकारी के प्रश्न को हलकाने के लिए इस कमेटी की सलाह से समुद्री मजदूरों के द्वारा रजिस्ट्रेशन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। भरती के सम्बन्ध में सुधार करने की दृष्टि से कलकत्ते और कर्माई में 'मेरीटाइम बोर्डों' की स्थापना की गई है। इन बोर्डों में मजदूरों के, जहाज के मालिकों के और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं।

खास मजदूर—यहाँ हम बंगाल और बिहार की कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों की भरती के बारे में ही विचार करेंगे। कुछ खानों को छोड़कर, जो अपने मजदूरों की भरती की व्यवस्था स्वयं ही अपने वेतन भोगी जमादार, चपरासी और मजदूर-सरदारों द्वारा करती हैं, अधिकांश खानों में आज भी मजदूरों की भरती मध्यस्थ के द्वारा होती है। ये मध्यस्थ (ठेकेदार) दो प्रकार के हैं—एक वे जो केवल मजदूरों को लाने का प्रबन्ध करते हैं और बाद में खान के मालिक उनको काम पर लगाते हैं और उनको मजदूरी चुकाते हैं; दूसरे वे जो केवल भरती ही नहीं करते पर उनको खान में से कोयला निकालने और उसे डिब्बों में भरने के काम पर रखते हैं और उनको स्वयं ही मजदूरी चुकाते हैं। इन दूसरी प्रकार के ठेकेदारों को ही 'रेजिंग कन्ट्रैक्टर' कहते हैं। एक तीसरी प्रकार के ठेकेदार और होते हैं जिन्हें प्रबन्ध-ठेकेदार (मैनेजिंग कन्ट्रैक्टर) कहते हैं जो मजदूरों की भरती और कोयला निकालने के अलावा खानों के विकास और कुछ न कुछ प्रबन्ध के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। पर इन सब में रेजिंग कन्ट्रैक्टर का तरीका ही सबसे अधिक प्रचलित है (लेबर इन्वेस्टीगेशन कमीशन—प्रधान रिपोर्ट)। इन ठेकेदारों और मजदूरों के बीच में

‘मरदार’ नाम का एक मध्यम और होता है जो गाँव-गाँव में जाकर मजदूरों को लाता है, उसका हाजिरी खर्चा देना है, उस पर गिरानी रखना है और उनको काम करना की सुविधाएँ मिलनी हैं इस का ध्यान रखना है। मजदूरों को जो आहार आदि बातें करने के लिए दिये जाते हैं वे भी इसी की जिम्मेदारी पर दिये जाते हैं। इसी के माँफ उनको उता चुक्या जाना है। उसे अगले इस काम के लिए साप्ताहिक अथवा मासिक वता मिलना है या फिर एक आना प्रति हफ्ता या दो आने प्रति हफ्ता प्रति मजदूर कीदला गिराने के हिसाब से कमीशन मिलना है। ‘मरदार’ के चयन का ठेकेदार मजदूरों को हथामगा करवा देते हैं।

उत्पत्ती का पद्धति में मजदूरों का भरती करने के बन् दोष है। रेलवे का कोयले का खानों में इस पद्धति का समाप्त करने का प्रयत्न हाल में किया है, जैसा कि ‘कोयले का खान में निवास करने वाला प्रोवाइन्स समिति’ (इन्डस्ट्रियल कमिटी ऑफ कोल माइनिंग) ने विचारिश की थी (जनवरी १९४८)। कोयले की दूसरी खानों में सम्भव में इसी कम्पनी ने गितम्बर १९४८ की बैठक में विचार किया था और निश्चय किया था कि कुछ समय तक वर्तमान पद्धति ही चलने का जाए और इस समस्या को आगे जान का जाए। खानों में काम करने और रहने महा की स्थिति में निम्ना सुधार होगा उनका ही काम करनेवाले मजदूरों में स्थायित्व आणना और ठेकेदारी प्रथा का अन्त हो नकेगा। जहाँ और जब तक ठेकेदारी प्रथा रहे वहाँ उनका उचित निर्धारण होना अत्यन्त आवश्यक है ताकि उनसे होने वाला हानिया कम से कम का जा सकें।

भारतीय निर्माण—मरदारों साधनिक विभाग, और म्युनिमिपल कमिटिया तथा जिन्ना बान् भी निमाण काय के लिए ठेकेदारी-पद्धति से काफी मदद में मजदूरों का भरती करते हैं। ठेकेदारी प्रथा के सब दोष यहाँ भी पाए जाते हैं और मजदूरों का शोषण होता है। इटले कमीशन ने भी इस बात का समर्थन किया था और इस पद्धति में सुधार और आवश्यक नियन्त्रण पर पूरा जोर दिया था।

एम्पलायमेंट एक्सचेंज—भारतीय उद्योग धंधों में मजदूरों को भरती की जिम्मेदारी प्रणाली की आज प्रधानता है उससे तथा उससे उत्पन्न दोषों के विषय में हम ऊपर लिख चुके हैं। हमने यह भी देखा कि अत्यन्त भारती के प्रयत्न भी—जैसे लेबर ऑफिसरों द्वारा या फिर बदली नियन्त्रण प्रणाली द्वारा हुए हैं, पर इन प्रयत्नों का अन्त नका महत्व नहीं है। लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी (१९४६) ने तो कहा तक लिखा है कि लेबर ऑफिसरों द्वारा होने वाली इस अत्यन्त भारती के बाधों में अत्यन्त भारती काम करती है, क्योंकि लेबर ऑफिसर

बिना मध्यस्थों की मदद के अपरिचित होने की वजह से गांवों में जाकर भरती के काम में बहुत सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है, कि इस कमेटी ने यह राय व्यक्त की है कि अप्रत्यक्ष भरती की तमाम ज़रूरतों के बावजूद भी यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय मजदूर ऐसी स्थिति में पहुँच गया है जहाँ मध्यस्थ द्वारा भरती की प्रणाली का आसानी से त्याग किया जा सकता है। इनका यह तात्पर्य हरमिन नहीं है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली को व्यवस्थित और नियंत्रित ही न किया जाए।

इतना होते हुए भी इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें भरती की अप्रत्यक्ष प्रणाली के स्थान पर प्रत्यक्ष प्रणाली स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिये। 'एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज' की स्थापना इसी प्रकार का एक प्रयत्न है।

ब्रिटिश कमीशन एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के पक्ष में नहीं था। पर बावजूद कमीशन की इस राय के इनके पक्ष में राय बढ़ी है और मजदूर तथा मालिक दोनों ही इनकी स्थापना के पक्षपाती हैं। यह ठीक है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज किसी देश के बेकारी के आधारभूत प्रश्न का हल नहीं निकाल सकते, यद्यपि भांग और पूर्ति में सामञ्जस्य स्थापित कर सकने के कारण इस अन्तर्मनस्य से उत्पन्न बेकारी को वे अवश्य कम कर सकते हैं। पर मजदूरों की भरती से सम्बन्ध रखनेवाली भारत में प्रचलित अप्रत्यक्ष प्रणाली के दोषों को वे अवश्य दूर कर सकते हैं और मिल-मालिकों को भरती के काम में बहुत सहायता दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में यूरोप, अमेरिका और जापान का अनुभव भी एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के पक्ष में ही है। भारत में सबसे पहला एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज १९१८ में फानपुर में उत्तरी भारत एम्प्लोयर्स एसोशियन के द्वारा कायम किया गया था।

सेबर इन्वेस्टीगेशन कमेटी ने एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के मुख्य काम वे बताए हैं—(१) काम चाहने वालों और काम के बारे में जानकारी देना। (२) खाली स्थानों के लिए मजदूरों की भरती करना। (३) मजदूरों की टेक्निकल ट्रेनिंग की क्या आवश्यकताएँ हैं और क्या प्रकृति है उसकी जानकारी करना। (४) विभिन्न धन्वों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन कराना। (५) काम के बारे में ऐसी सामान्य जानकारी जो मिल-मालिकों, सरकार और जनता के लिए उपयोगी सिद्ध हो। (६) विभिन्न वर्गों में, जिनमें मिल-मालिक और मजदूर भी शामिल हैं, सम्बन्ध स्थापित करना और दूसरी सरकारी संस्थाओं से सहयोग करना।

द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने से कुछ पूर्व (अक्टूबर, १९४५) भारत-

सरकार ने फौज से लौटे हुए लोगों और अन्य युद्ध कर्मियों में काम करवाने के लिए मजदूरों का काम पर लगाने का प्रथम एम्प्लायमेंट एक्ट १९१९ का एक अध्याय संशोधन अधिनियम किया। पर बाद में इन काम में वे अधिक व्यापक बना दिया गया और वे विस्थापित लोगों तथा औद्योगिक मजदूरों को काम पर लगाने का कार्य भी करने लगे। इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियमों को 'एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट और एम्प्लायमेंट' कहते हैं। इसका तीन विभाग है और प्रत्येक विभाग एक डायरेक्टर के अधीन है। (१) एम्प्लायमेंट एक्जामिनेशन विभाग (२) ट्रेनिंग विभाग (३) प्रशासन विभाग। भारत के छह प्रदेशों में विभाजित है वे हैं 'राजस्थान डायरेक्टर' के अधीन काम करते हैं। दस मद्रास कुल १४ एम्प्लायमेंट एक्जामिनेशन, २३ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लायमेंट एक्जामिनेशन और ११९ एम्प्लायमेंट ऑफिस हैं। यह एक्जामिनेशन के माध्यम से नौकरों को नियुक्त करते हैं।

मजदूरों का शिक्षण—हमारे सामने आने में आने वाले बाले मजदूरों का अधिकांश और तकनीकी शिक्षा से रहित होते हैं। यह एक बड़ा कमी है। अन्तर्गत में हम दिशा में काम करके प्रयत्न हुआ ही नहीं है। अधिकांश लोग यह है कि मजदूरों को नौकरों के रूप में काम आरम्भ करते हैं और अनुभव के आधार पर उन अपने अपने कामों तक पहुँचते हैं जहाँ कि काम करने में काम कुशलता से आवश्यकता होती है। कुछ प्रमुख उद्योग धर्मों में मजदूरों को शिक्षा देने की कोशिशें की जा रही हैं, यद्यपि आवश्यक है, यद्यपि तोर से उन लोगों की ट्रेनिंग का व्यवस्था है जिनको निम्नलिखित (मुख्य उद्योग) का काम करना पड़ता है। इलाहाबाद तथा रेल के कामगारों में एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग की मनुष्य योजनाएँ आवश्यक बालू हैं। यह तरह के कुछ प्रमुख उद्योगों के लिये पर जमशेदपुर के दादा शहाबुल्लाह स्टाव वल, जमशेदपुर के रेलवे तकनीकी स्कूल, और देहरादून के रेलवे स्टाफ कॉलेज के नाम बताए जा सकते हैं।

युद्ध के समय सन् १९४० में भारत सरकार ने तकनीकी ट्रेनिंग की एक योजना बनाई थी, जिसके अन्तर्गत मद्रास में सरकारों और गैर सरकारी कारखानों में तकनीकी लोगों का ट्रेनिंग दादा थी और बिना स्कूल के अन्तर्गत कुछ भारतीय मजदूरों की ट्रेनिंग प्रिन्सिपल में भी हुई थी।

ट्रेनिंग की जो योजनाएँ इस समय काफी बड़े और मजदूरों के काम पर चल रही हैं वे डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट और एम्प्लायमेंट (अन्तर्गत भारत सरकार) के अन्तर्गत में जारी की गई हैं। इस प्रकार की तीन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है—(१) औद्योगिक, व्यावसायिक और एम्प्लॉयमेंट शिक्षा योजना जो फौज से लौटे हुए व्यक्तियों के लिए है, (२) ऐसी

ही दूसरी योजना जो विस्थापितों के लिए है, और (३) इन्सट्रक्टर्स के शिक्षण की योजना। पहली योजना सन् १९४६ में और दूसरी दो सन् १९४८ में आरम्भ हुई थी। पहली दो योजनाओं में अब साधारण लोगों का प्रवेश भी होने लगा है और उनके द्वारा इंजीनीयरिंग और हमारत आदि के धन्यों तथा कुटीर उद्योगों की शिक्षा दी जाती है। जनवरी १९५० के अन्त तक २५००० से ऊपर व्यक्तियों ने इन केन्द्रों से शिक्षण प्राप्त किया। ३० सितम्बर १९४६ की ७४ टेक्निकल, ७९ बोकेशनल और ३१८ एपरेन्टिसशिप केन्द्र इन योजनाओं के अन्तर्गत काम कर रहे थे। अम मंत्रालय के अलावा और मंत्रालय भी, जैसे रेलवे बोर्ड, सार्वजनिक निर्माण और शिक्षा मंत्रालय भी, राब्यों के सहयोग से व्यावहारिक शिक्षा का प्रबन्ध कर रहे हैं। देश में टेक्निकल शिक्षण की जो योजनाएँ चल रही हैं उनमें सबसे बड़ी कमी यह है कि फोरमेन वर्ग के लोगों के शिक्षण का बड़ा अभाव है। इस अभाव की पूर्ति आवश्यक है।

विभिन्न उद्योगों में एपरेन्टिसशिप की जो योजनाएँ चल रही हैं उनमें भी कई प्रकार के दोष हैं। नित शर्तों पर ट्रेनिंग दी जाती है वे सुनिश्चित नहीं होतीं और ट्रेनिंग के पश्चात् काम मिलने की कोई गारन्टी नहीं होती। कई बार मिल-मालिक एपरेन्टिस को या तो मजदूरी देना ही नहीं, या बहुत कम मजदूरी देता है। यह आवश्यक है कि भविष्य में इन दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया जाए।

मजदूरों का स्थायित्व:—हमारे देश में मजदूरों का एक दोष यह है कि उनमें स्थायित्व की बड़ी कमी है, अर्थात् यदि किसी कारखाने के मजदूरों की कुल संख्या में से उन मजदूरों की संख्या देखी जाए जो अनुकूल समय में अले गए और उनके स्थान पर दूसरी भरती होगई तो यह संख्या काफी बड़ी होगी। इसी को अंग्रेजी में 'लेबर टर्न ओवर' कहते हैं। यद्यपि इस सम्बन्ध में जो आंकड़े हमारे देश में उपलब्ध हैं वे बहुत विश्वसनीय नहीं हैं, फिर भी उनसे इतना संकेत तो मिलता ही है कि कुल मिलाकर मजदूरों में स्थायित्व की काफी कमी है। यह कमी अलग-अलग उद्योगों और अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग है।

भारतीय मजदूरों में स्थायित्व की इस कमी के मुख्य कारण दो हैं—अस्तीक्षा और बरखास्तगी। इसका अन्तर मजदूरों की उत्पादन शक्ति पर अब्दा नहीं पड़ता और इसलिए इसमें कमी लाने का प्रयत्न करना चाहिये। भरती की जो अप्रत्यक्ष प्रणाली इस देश में प्रचलित है उससे भी इसमें प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि भरती करने वाले जोवर को तो इसमें लाभ ही है कि पुराने मजदूरों को निकाल कर नई भरती की जाए ताकि भारती के समय विश्व आदि से होने वाली उसकी आय अधिकधिक हो सके। मजदूरों की आर्थिक स्थिति और सुरक्षा

म निता सुधार दामा और विम गानावरण में उसे काम करना पड़ता है यह निता आरथर १ या उपा ह्म तह मम रथावित्र का माया भी बढगी। भरता या प्रणाली म सुधार हन का भी ह्म सम्बन्ध म अन्ध्रा अमर दामा।

मजदूरा म अनुपस्थिति—भारतीय मजदूरों का एक दाव यह भी है कि उनका अनुपस्थिति का अनुपात काफी अधिक है। अनुपस्थिति सम्बन्धी आर्यों का पूरा परस्वा अधा मारे म नही है और जहा ये आर्यो इकट्ठे निर मा गद है वहाँ क प्रकार का काम म आता है। सम्बन्ध सरकार एली कप म मिला और मालिकों क कारखाना के बार म अनुपस्थिति क आर्यो तदर मन्त्र ३५ म ह्म महान प्रकाशित करनी है। हनी प्रकार मैमूर सरकार भा अपने शाय क सध उपाय उधा क बारे म अनुपस्थिति क आर्यो अपने लबर गण्ट १ प्रकाशित करता है। पिछले महायुद्ध म भारत सरकार ने मिल मालिकों और मजदूरों क प्रतिनिधियों का मिलाह सक मारमाना क अनुपस्थिति क आर्यो इकट्ठ करवाने का निश्चय लिया था। ह्मन् एमिकासत्वरूप लबर ब्यूरो (भारत सरकार) के डायरेक्टर क कार्यालय म इन्ड ग्राफ़ आते है और इन आधार पर मन्त्रिम लेबर मन्त्र म अनुपस्थिति सम्बन्धी आर्यो प्रकाशित भी होते है। ह्मा प्रसार म्ता भारत क मिल मालिकों का मर भी कारपुर की एता कपकों कना कपका आर चमड़े क सामान का मिला म अनुपस्थिति क आर्यो प्रकाशित करता है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार क लेबर बुनेटिन म छपन है। लबर इन्स्टीगेशन कमिटी ने भी हम बार म जॉब का जैम बाय कॉफी और रबर के गेत्तों तथा अबरक (माका) को खानों क बारे म। उपरुक्त आधार पर जो जानकारी म बार म मामल आर है उसका मार यह है कि पेस्टरी उपायों म अनुपस्थिति की मात्रा १० से १५ प्रतिशत प्लांटशनों तथा फोरेले की खानों म २५ प्रतिशत तक और अबरक की खानों म ४० प्रतिशत तक मा चली जाती है। एसा भी मान्य पड़ता है कि अनुपस्थिति म्तर भारत क अपना दमिण भारत म कम है।

इन आर्यों क सम्बन्ध म एव कमी तो यह है कि अनुपस्थिति के यह आर्यो किसी एक परिभाषा क आधार पर एकत्रित नहीं किए गए हैं। ऐसा करना बहुत आवश्यक है। अनुपस्थिति की एक सय मान्य परिभाषा सर्वसा सुमान भारत सरकार क अम विभाग क अपने एक परिपत्र में दिया था। इस सुभाव के अनुसार जो व्यक्ति पृथ निश्चित अवकाश पर होना है उसे अनुपस्थित नहीं माना जाना चाहिय। पर जो व्यक्ति बिना सूचना क चला जाता है उसे अनुपस्थित मानना चाहिय। पर हड़ताल क कारण अनुपस्थित रहने वालों को

इस अर्थ में अनुपस्थित नहीं मानना चाहिये। पूर्व निश्चित अवकाश के समय के अलावा जो व्यक्ति छुट्टी चाहता है उसे भी अनुपस्थित मानना चाहिये। दूसरी कमी इन अनुपस्थिति के आंकड़ों के बारे में यह है कि उनको इकट्ठा करने का सब जगह एक ही तरीका काम में नहीं आता। इन कमियों को जब तक दूर नहीं कर दिया, जाता अलग-अलग धंधों के आंकड़ों को आपस में सही तुलना नहीं की जा सकती।

अनुपस्थिति के कारणों का यदि हम अध्ययन करें तो ये कारण ख़ास तौर से मिलेंगे—१. बीमारी, २. औद्योगिक दुर्घटना, ३. सामाजिक और धार्मिक कारण, ४. गांवों को जाना। रात की पाली में अनुपस्थिति अधिक मिलेगी। कई बार नये श्रमिक मनोरंजन के कारण भी अनुपस्थित होती हैं।

अनुपस्थिति की मात्रा कम करने का यह उपाय है कि काम करने के वातावरण में सुधार हो, मजदूरी ब्येष्ट मिले, औद्योगिक दुर्घटनाओं और बीमारी से रक्षा का अच्छा उपाय हो, और आराम तथा मनोरंजन के लिए निश्चित अवकाश की व्यवस्था हो। मजदूरों के रहने के मकानों का सुप्रबन्ध होने से भी अनुपस्थिति की मात्रा में कमी होगी।

काम के घंटे—औद्योगिक मजदूर से संबंध रखने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न उसके काम करने के घंटों का रहा है। किसी भी देश के औद्योगिक विकास का इतिहास देख लिया जाए; मिल-मालकों में यह प्रवृत्ति मिलेगी कि वे स्वार्थवश मजदूरों से बहुत लम्बे समय तक काम ले। चौबीस घंटों में से १८ घंटे तक काम कराने के उपादरण मिलते हैं। भारत की स्थिति और देशों से इस अर्थ में किसी प्रकार भिन्न नहीं रही है। मजदूरों से लम्बे समय तक काम कराने की प्रवृत्ति यहाँ भी देखी गई है। यही कारण है कि आज मजदूर कितने घंटे काम करे इसका कानून से नियंत्रण होता है।

भारत में कानूनद्वारा मजदूरों के काम करने के घंटों का नियंत्रण सबसे पहले १९११ के फेक्टरी कानून द्वारा, उन मजदूरों के लिए, जो इस कानून के अन्तर्गत आने वाले कारखानों (फेक्टरीज) में काम करते थे, किया गया। इस कानून के अनुसार पुरुषों के लिए दिन भर में काम करने के १२ घंटे निश्चित किए गए थे। इससे अधिक कोई मिल-मालिक कानूनन काम नहीं ले सकता था। इसी प्रकार खानों में काम करने वाले मजदूरों के काम करने के घंटों का सबसे पहले १९२३ के खानों सम्बन्धी कानून से नियंत्रण हुआ। रेलों सम्बन्धी मजदूरों में से जो फेक्टरी कानून में नहीं आते, उनके काम के घंटों का नियंत्रण रेलवे एक्ट के अन्तर्गत होता है। यह नियंत्रण सबसे पहले १८८० के रेलवे एक्ट

द्वारा किया गया था। चाय, कॉफी और खर के पाग में काम करने वाले मजदूरों के काम के घंटों का आग्रह भी कोड कानून द्वारा नियन्त्रण नहीं होता है। हा, चाय और खर के कारखानों पर कारखानों सम्पत्ति कानून अन्वेष्य लागू होता है। उपर्युक्त सब कानूनों में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है और यह परिवर्तन काम करने के घंटे में सम्बन्ध में माहुरा है। इस सम्बन्ध में मौजूदा स्थिति इस प्रकार है।

कारखानों (फैक्टरीज) में काम करने वाले मजदूरों के काम करने के घंटे १६४८ के फैक्टरी एक्ट द्वारा नियन्त्रित होने हैं। इस कानून के अनुसार कारखानों के मजदूरों में सप्ताह में अधिक से अधिक ४८ घंटे और प्रतिदिन अधिक से अधिक ६ घंटे काम लिया जा सकता है। कारखानों चलने का (स्पेड ऑवर) श्रमिक से श्रमिक १०॥ घंटे का समय निर्दिष्ट किया गया है। शालाभर चलने वाले और मौसमी (सीजनल) कारखानों में हमने पहले १६१४ के एक्ट में जो अंतर था वह अब हटा दिया गया है। स्त्री मजदूर सुबह ६ से शाम के ७ बजे तक काम कर सकती हैं। १४ वर्ष का पूरा आयु न हो जान तक कोई बालक कारखानों में काम नहीं कर सकता। "सब" बाद कोई भी बालक दिन में ४॥ घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता और उसके काम का समय सुबह ६ बजे से शाम के ७ बजे तक होना चाहिए। काम के घंटों में समय में बहुत स्थिति भी कहा है कि वह कारखानों में ८ घंटे प्रतिदिन से अधिक काम नहीं लिया जाता। जो छोटे-छोटे कारखानों कानून के नियन्त्रण में नहीं आते उनमें काम के घंटे अवश्य अधिक हैं। जैसे रंगे कपड़ों के अनुसार लागू आदि के कारखानों में १२ घंटे प्रतिदिन के हिसाब से भी काम कराया जाता है। नौकाधरों, वह बड़े बड़े इन्धोनिशरिंग के कारखानों, और करीब करीब सभी रेलवे कारखानों में सप्ताह में ४८ घंटे काम कराया जाता है, पर प्रतिदिन के काम के घंटों में थोड़ा अंतर है, जो सप्ताह के दिन कितने घंटे कहा काम कराया जाता है उससे निर्दिष्ट होता है। स्त्री कपड़ों की मिलों में लगभग सभी जगह ८ घंटे प्रतिदिन के हिस्से में काम लिया जाता है।

खानों में काम करने वाले मजदूरों का यहाँ तक सम्बन्ध है, जो मजदूर जमीन के नीचे काम करता है उसका काम के अधिक से अधिक ६ घंटे प्रतिदिन और ५४ घंटे प्रति सप्ताह भाइस एक्ट द्वारा निर्दिष्ट हैं। खानों में काम करने का अधिक से अधिक समय (स्पेड ऑवर) भी ६ घंटे का है। जमीन के ऊपर काम करने वाले मजदूरों के लिए प्रतिदिन अधिक से अधिक १० घंटे और प्रति सप्ताह यहाँ ५४ घंटे निर्दिष्ट हैं। स्पेड ऑवर १२ घंटे का निर्दिष्ट है। रंगे

कमेटी के अनुसार मामूली तौर से खानों में जमीन के नीचे काम करने वाले मजदूर प्रतिदिन ६ से १० घंटे काम करते हैं। स्प्रेड ऑवर जमीन के नीचे काम करने वालों का तो ६ घंटे और ऊपर काम करने वालों का ६ से ११ घंटे तक का होता है।

रेल्वे में काम करने वाले उन लोगों के जो फेक्टरी एक्ट या माइन्स एक्ट के अन्तर्गत नहीं आते, काम के घंटों का निर्वण १८६० में पास तथा १९३० में संशोधित रेल्वे एक्ट के अनुसार होता है। इस कानून में आने वाले लोगों को दो श्रेणियों में बांटा गया है—लगातार काम करने वाले लोग और लगातार काम नहीं करने वाले लोग। पहली श्रेणी वालों के लिए ६० घंटे प्रति सप्ताह और दूसरी श्रेणी वालों के लिए ८४ घंटे प्रति सप्ताह का महीने भर का औसत अधिक से अधिक काम का समय निश्चित है। विशेष स्थिति में रेल्वे अधिकारी द्वारा थोड़े समय के लिए इस मर्यादा का उल्लंघन भी किया जा सकता है। इस एक्ट के अन्तर्गत सरकार को नियम बनाने का भी अधिकार है। इन नियमों को 'रेल्वे सर्वेयट्स अवर्स ऑफ एम्प्लायमेंट रूल्स' कहा जाता है पर एक्ट और रूल्स दोनों को प्रायः 'अवर्स ऑफ एम्प्लायमेंट रेगुलेशन्स' भी कहा जाता है। लैबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी (रीनो कमेटी) का कहना है कि थोड़े समय के लिए काम के घंटों की मर्यादा उल्लंघन करने, और काम करने वालों को लगातार काम करने वालों और नहीं करने वालों को दो श्रेणियों में बांटने के संबंध में शिकायत रही है। अखिल भारतीय रेल्वेमेन्स फेडरेशन के मांग करने पर भारत-सरकार ने अप्रैल १९४६ में बी जस्टिस जी० एल० राज्याध्यक्ष को कुछ मामलों का निर्णय करने के लिए निर्णायक नियुक्त किया। इन मामलों में काम के घंटे, आराम के समय, छुट्टी और अवकाश के प्रश्न शामिल थे। श्री राज्याध्यक्ष ने सिफारिश की कि बहुत से रेल्वे-कर्मचारी जो अबतक अवर्स ऑफ एम्प्लायमेंट रेगुलेशन्स के अन्तर्गत नहीं आते हैं उनको इसके अन्तर्गत लेना चाहिए और समस्त कर्मचारियों का निम्नलिखित चार श्रेणियों में दुबारा वर्गीकरण करना चाहिये—(१) 'इन्टेन्सिव'—वे लोग जिनका काम अत्यधिक परिश्रम चाहता है, (२) 'इंटेन्सिवली-इन्टरमिटेंट'—जिनके काम का स्वभाव ही ऐसा है कि उनको बीच-बीच में आराम मिल जाता है, (३) 'एक्सबलूडेड'—इसमें कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, जैसे हल्का काम करने वाले चपरासी आदि श्रेणी के लोग, विद्युत् काम करने वाले लोग, सुपरवाइजरों स्टाफ और डॉक्टर आदि। (४) 'कन्टीनुअस'—उपयुक्त तीनों श्रेणियों के अलावा जो लोग रह जाते हैं। श्री राज्याध्यक्ष ने सिफारिश की कि नं० (१) को ४५ घंटे, नं० (४) को ५४

घंटे और न० २ को ७५ घंटे गनाई म काम करना चाहिये। न० (१) के लिए जो मर्यादा निश्चित नहीं की। रॉयग स्टॉक न बार में उनकी सिफारिश बढ़ाये, कि उस लगातार १० घंटे से ज्यादा काम नहीं होना चाहिये। भारत सरकार ने राम न घंटों गवारा इन सिफारिशों का अपने १५ जून १९४८ के आदेशानुसार भी धन के लिए स्वाभार कर लिया। यह आदेश उही रेलवे पर लागू किया गया जो अन्य भगद से संबंधित थे। आराम और हुटो के दिन गवारा जा सिफारिशों का गठ था व भी भारत सरकार में मंजूर करना।

राय आदि न धारा में राम करने वाले मजदूरों के काम करने के घंटों का कानून में कोई नियम नहीं है, यह उपर लिख चुके हैं। धनु स्थिति यह है कि पुण्य, आर वालक मर्यादावर समय काम करने हैं। यह अवश्य है कि बालक का अप्रत्याशित हल्का काम दिया जाता है। आराम और बगाल के काम न बाग में आम तौर पर 'हजार' (Hazaar) के आधार पर काम होता है। राय ५ या ६ घंटे में मजदूर करना हतारा खनम कर लेता है और उसका बाद वह उसकी इच्छा पर निर्भर रहता है कि वह अतिरिक्त काम करे या न कर। पतिया चुनने के भाग्य में मजदूर १० ११ घंटे तक भी काम करते हैं।

काम न घंटों के सवा में आ विवरण ऊपर दिया गया है उससे यह अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि अनियमित कारखानों के अलावा और जगह स्थिति कुछ मिलाकर सतोपजनक है।

आराम और अवकाश—काम न घंटों से मिला उना दूसरा महत्व का प्रश्न यह है कि मजदूरों को काम के घंटों के बीच में आराम करने का समय कितना मिलता है और सप्ताह में अवकाश मिलता है या नहीं। १९४८ के फाटरी कानून के अनुसार कोई प्रीट मजदूर ५ घंटे से अधिक लगातार काम नहीं कर सकता और ५ घंटे न बाद उसे कम से कम आधा घंटे का विश्राम मिलना चाहिये। इसी प्रकार उसे सप्ताह में वृद्ध एक दिन का अवकाश मिलना भी अनिवार्य है। माइंस एक्ट में भी यह निषेधित है कि कोई भी व्यक्ति सप्ताह में छह दिन से अधिक खान में काम नहीं कर सकता। विश्राम के बारे में कानून द्वारा कितना प्रकार की अनिवार्यता तो नहीं है, पर फिर भी व्यवहार में विश्राम का समय दिया जाता है, यद्यपि कहीं कहीं नहीं भी दिया जाता। जो भान मजदूर टंक पर काम करते हैं उनका कानून द्वारा तो कोई नियम है नहीं और उन्हें कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता। चाय आदि के बागों में काम करने वाले मजदूरों को दो पहर में एक घंटे का विश्राम देने की व्यवस्था तो है,

पर रीगे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मजदूरों को यह आम शिकायत थी कि वास्तव में उन्हें विभ्राम मिलता नहीं। काम के स्थान पर ही जल्दी-जल्दी में भोजन करने के लिए ५-१० मिनट का समय अवश्य मिल जाता है। चाय और कॉफी के वागों में सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलता है, मिला उन दिनों के जब काम की अधिकता होती है। स्वर के वागों में अवकाश नहीं मिलता। रेलवे-कर्मचारियों को कानून के अनुसार सप्ताह में एक बार इतवार से कम से कम २४ घंटे का लगातार अवकाश मिलना अनिवार्य है। जॉ 'इंसेंशियली इन्टरमिटेन्ट' श्रेणी में आने वाले कर्मचारी हैं, या जिनके लिए सरकार ने काम, समय का अवकाश निश्चित कर दिया है उनके बारे में २४ घण्टे के लगातार अवकाश का नियम लागू नहीं होता है। विशेष स्थिति में अवकाश संबंधी नियमों में रेलवे अधिकारी द्वारा छूट दी जा सकती है। श्री राज्याध्यक्ष ने साप्ताहिक अथवा पाल्किक अवकाश के बारे में जो शिफारिशें की थीं वह भी सरकार ने तीन वर्ष के लिए (जून १९५१) स्वीकार करली थीं। इसके अनुसार 'इन्टेन्सिव' और 'कन्टीनुअस' श्रेणी के लोगों को सप्ताह में लगातार ३० घण्टे और 'इंसेंशियली इन्टरमिटेन्ट' श्रेणी के लिए लगातार २४ घण्टे (एक पूरी राशि सहित) और 'एम्प्लूडेड' श्रेणी के लिए पंद्रह दिन में लगातार २४ घण्टे अथवा महीने में लगातार ४८ घण्टे का अवकाश मिलता है।

कारखानों आदि में काम करने की परिस्थितियाँ—कारखानों आदि में काम करनेवाले मजदूरों के सम्बन्ध में एक बात जानने की यह है कि जिन परिस्थितियों में वे काम करते हैं वे कैसी हैं। रीगे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि काम करने की परिस्थितियों के बारे में अधिकांश मिल-मालिक केवल उतना ही ध्यान देते हैं जितना ध्यान देना कानून की निगाह से अनिवार्य है। बल्कि कई लोग तो इतना भी करने से बचना चाहते हैं। काम की परिस्थितियों के बारे में मुख्यतः तीन दृष्टियों से विचार करना चाहिये—(१) हवा (२) ताप और (३) प्रकाश

जहाँ मजदूर काम करते हों वहाँ शुद्ध हवा आने-जाने का प्रवन्ध होना आवश्यक है, खास तौर से सूती कपड़ों आदि के कारखानों में जहाँ काम धूल और नम हवा में होता है। हवा के आने-जाने का प्रवन्ध या तो खिड़कियों अथवा केन्टीलेटरो द्वारा होता है या फिर कृत्रिम रूप से पंखों से या दूसरे साधनों से हवा बाहर निकालने और अन्दर लाने का प्रवन्ध किया जाता है। इसी प्रकार इस बात की आवश्यकता होती है कि काम करने के कमरों में ताप न बहुत अधिक हो न बहुत कम। उचित प्रकाश की व्यवस्था भी अत्यन्त

आवश्यक है नात्रि मज्जरो को आगो पर दुरा अस्तर न पड़े। रोशनी के निर-
विडम्बिता आदि का प्रवच होना चाहिये और आवश्यकता होने पर दिन म मी
नया रान म बिजला आगि का राशनी नी अग्ना द्यवस्था होती चाहिये।
रोशनी न प्रदत्त म द्यु जाल का भा ध्यान रखा जाता आवश्यक है वि आगो
पर साधा राशनी न पड़े।

रोग नमन का कहना है कि वयं बड़े भारगानों म तो काम करने की
परिस्थितिया कुल भिन्नाकर अनोपजनक हैं। गर वा छात्र और अनियमित
कारग्या है शिष्य करर वा पुगनी दमारना म चलन है उनम स्थिति संतोष
चलन तहा है और बहुत रुध मुधार की आवश्यकता है। कई सूती कपड़ों की
मिली म पैम कर, अहमदाबाद म हवा का तापमान ठीक रखा के लिए एयर
कन्डिशनर का प्रयोग है। इसा प्रकार कहीं-कहीं कपास मे उत्तम धूल
का यन तारा हटाते वा भा व्यवस्था है। पर जूट की मिलों म अप्रत्याहत स्थिति
रुम मन्तरपनक है। अनियमित क गारग्याना म भा हवा और प्रकाश की
व्यवस्था ठीक ठीक ही है। छात्रग्याना का स्थिति मामूला तीर पर सतोपजनक
नहा पाइ जाता है। गासे का पत्र म चला जाना बड़ा भवानक है पर छापेवाने
के काम करन जाला की इसम बजान का कोड स्वात प्रयत्न नही जाना है। वास्तव
म ता इस सम्बन्ध में प्रस मालिका और प्रेस में काम करने वालो का जामभारा
ही बहुत कम है। ग्याना क बार म भा यह बात देखने को मिलता है कि कई जगह
काम करन का स्थिति अनोपजनक नहीं है, जैसे अवरक की स्थानी और मंगनीज
की ग्याना म हवा और रोशनी का प्रवच स्वात तीर मे जमीन क नाचे, ठीक नहीं
है। १९४८ के फरवरी एक्ट म हवा, ताप मान और प्रकाश की समुचित व्यवस्था के
नजर में आवश्यक धाराग्या का समानश कर लिया गया है। इसी प्रकार से धूल
नया अप्र वफार पदार्था (वेस्ट) आदि से मजदूरों का रक्षा करने सबसे धारा भी
१९४८ क एक्ट म मौजूद है। प्रत्येक मजदूर के लिए कम से कम नितना स्थान
होना चाहिय इसका निश्चय भी इस एक्ट में कर दिया गया है। धाराश यह
है कि १९४८ क एक्ट म कारखानो में काम करने का परिस्थिति में मुधार करने
की और यथ स्थान दिया गया है।

कारग्याना में उपलब्ध अनियाय सुविधाएँ—कारखानों आदि में काम
करने का जिन परिस्थितियों का ऊपर उल्लेख किया है उनसे अलावा कुछ और
सुविधाएँ भा मजदूरों की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक हैं, ताकि काम करते समय उसके
व्याप्य का रक्षा हो सके और उसकी काय शक्ति पर दुरा अस्तर न पड़े। इन
आवश्यक सुविधाओं में पाने के पाना, पेयान-धर तथा शौच गृह और निवास-गृह

की सुविधाएं प्रमुख हैं।

पीने के पानी की कोई न कोई व्यवस्था तो अधिकांश कारखानों में होती है पर उसमें कई प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। जैसे नर्मियों में मज़दूरों को पीने के लिए ठन्डा पानी प्रायः नहीं मिलता। गिन बर्तनों में पानी रखा जाता है वे भी स्वच्छ नहीं होते। पानी पिलाने का ठीक से कोई प्रबन्ध नहीं होता। कई जगह तो पीने के लिए खारा पानी ही उपलब्ध होता है। कहीं-कहीं तो मज़दूरों को नल पर ही पानी पीना होता है। कई कपास धुनने के और बीड़ी के कारखानों में तो स्थिति यहां तक खराब है कि पीने के लिए पानी ही उपलब्ध नहीं होता। अनियंत्रित खानों और कारखानों में पीने के पानी की विशेष कठिनाई पाई जाती है।

मज़दूरों के स्वास्थ्य और सुविधा की दृष्टि से शौच-गृह और पेशाब-घरों की समुचित व्यवस्था भी अत्यन्त आवश्यक है। पर इस सम्बन्ध में भी हमारे कारखानों और खानों आदि की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जहां शौच-गृह आदि हैं वहां उनकी सफाई का ठीक प्रबन्ध नहीं होता और इस कारण से मज़दूर उनका उपयोग करने में हिचकते हैं। शौच-गृह के आन्त-मान पदों का प्रबन्ध भी नहीं होता। आवश्यकता इस बात की है कि मज़दूरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यथेष्ट संख्या में शौच-गृह और पेशाब-घरों की अलग-अलग व्यवस्था हो और उनको साफ़ कराने का अच्छा प्रबन्ध हो। साथ ही पदों का भी प्रबन्ध होना आवश्यक है। आज तो कई जगह—जैसे अनियंत्रित कारखानों में या अवरक की खानों में ज़मीन के नीचे तो शौच-गृह आदि की कोई व्यवस्था ही नहीं पाई जाती।

मज़दूरों को विश्राम करने के लिए और दोपहर की छुट्टी में बैठकर भोजन करने के लिए हर फेक्टरी अथवा खान पर विश्राम-गृह की व्यवस्था होना आवश्यक है। ये विश्राम-गृह पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग-अलग हों यह भी जरूरी है। बैठने के लिए बैठ अथवा चबूतरों आदि का प्रबन्ध भी होना चाहिये और उनकी सफाई की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। आज तो हमारे देश में विश्राम-गृह सम्बन्धी स्थिति भी असंतोषजनक है। सूती कपड़ों की अधिकांश मिलों में इनकी व्यवस्था है, यद्यपि बूट की मिलों में उनका अभाव है। दूसरे बड़े-बड़े उद्योगों में भी विश्राम-गृहों की व्यवस्था है। पर छोटे कारखानों में प्रायः इनका अभाव होता है। मज़दूरों की संख्या की दृष्टि से इन विश्राम-गृहों में स्थान की कमी भी रहती है। सफाई का प्रबन्ध नहीं होता और न बैठने का कोई प्रबन्ध होता है। खानों में आम तौर से विश्राम-गृहों का अभाव है।

१६X८ म फरारी जातून म पान व जल आग शोध गह तथा पेशावपरो

१६५८ में फरवरी में जल का जल आग शोध गृह तथा पेशाबघरो के बारे में समुचित व्यवस्था करो ता भारत मिल् मालिका पर डाला गया है। राज्य की सरकारों को इस सम्बन्ध में आवश्यक नियम बनाने का अधिकार भी दिया गया है। २५० से अधिक मजदूर जहाँ काम करने हों उस कारखाने में गर्मा में टाउ पानी की व्यवस्था मा फर्स्टरी एक्ट के अनुसार करना अनिवार्य है। इस प्रकार फर्स्टरी एक्ट के अनुसार शा. गृह और पेशाबघरों की आवश्यक सफाई और नाला प्रणाली के लिए अलग अलग बजट शोध-गृह तथा पेशाबघरों के अन्तर्गत भी बनाया गया और राशना का टाउ प्रबंध किया और २५० से अधिक मजदूर जहाँ काम करते हैं उन कारखानों में एक निश्चित प्रकार का शौच घर तथा पेशाबघर बनाना अनिवार्य है।

संज्ञा—फकटरी म काम करनेवाले मजदूरों व श्रावण की दृष्टि से फकटरी का साम मुधग रहता भी अत्यन्त आवश्यक है। १९४८ ने फकटरी-एक व अतुल्य यह आवश्यक है कि काम करने के कमरों आदि में गद और गद्दी लगी जमा होने दी जाने, पशु को बरानर धोकर नफाई की जाए और फकटरी की पुताई इत्यादि में बरानर समय समय पर डांती रहे।

रक्षा—आधुनिक ढंग के कल-कारखानों में एक समस्या मजदूरों की सुरक्षा की है। जहां शक्ति से चलने वाली मशीना स काम होता है वहां इस बात का जखर नखावर रहता है कि उन मशीनों पर काम करने वाले मजदूर मशीन स कट न जावें अथवा उनक हाथ पाव स चोट न आनावे। मशीनों के अतिरिक्त मजदूरों को दूसरी प्रकार के खतरे भा रहने हैं। उदाहरण के लिए कारखानों में बहुत सी दुपटनाएँ मोटिया अथवा विइन्ड्रियों आदि से गिरने से होती हैं। यदि कारखाने की दमागत टांक तरह से बनी हुई नहीं है तो इस कारण से भी कई दुपटनाए हो आता हैं। आग लगाने का डर भी कारखानों में रहता है। कई बार गुरत आग पकड़ लेने वाला धूल, गैस अथवा भाप जो उत्पादन क्रिया स अनिवार्यत उत्पन्न होता है अथवा काम स आता है, असस भी दुपटनाए होतो दम्भा गर्द हैं। जैसे कोयले की धूल जल्दी से आग पकड़ लेती है और कोयले की आनों स इससे बहुत सी दुपटनाए होती दम्बो गर्द हैं। कई बार आटा, शकर आदि पैसा रोज काम स आने वाली चीजों की धुंध भी आग पकड़ती हुई पाव गर्द है। इसी प्रकार कई ऐसे खतरनाक (फ्यूम्स) होते हैं जो यदि किसी बमरे आदि स अधिक मात्रा में हों और उसमे कोई आदमी चला जाए तो उसका दम घुट सकता है। कुछ ऐसी (फ्यूम्स) होती हैं जो आग भी पकड़ लेती हैं। अत्यधिक बोक उठाने से भी मजदूर को मुकसान पहुँचता है।

कई औज़ार ठीक नहीं होते और उनका प्रयोग करने से आंखों को नुकसान पहुँचता है, क्योंकि उन औज़ारों से जो धातु के कण अथवा टुकड़े निकलते हैं वे आंखों में जाते हैं और उससे आंखों को नुकसान होता है। सारांश यह है कि आधुनिक कारखानों में अनेक प्रकार से मजदूरों को जोखिम पहुँचने की संभावना होती है और उससे उनकी रक्षा करना आवश्यक है।

१९४८ के फेक्टरी-एक्ट में उपर्युक्त सब जोखिमों से मजदूरों की रक्षा करने के सम्बन्ध में मिल-मालिकों पर जिम्मेदारी डाली गई है। इस अर्थ में यह एक्ट १९३४ के फेक्टरी-एक्ट की अपेक्षा कहीं अधिक आगे बढ़ा हुआ है क्योंकि १९३४ के एक्ट में फेक्टरी इन्स्पेक्टर पर यह जिम्मा था कि वह आगे बढ़कर यह बतावे कि मिल-मालिक को मजदूरों की रक्षा के लिए क्या-क्या करना चाहिये। अब तो मिल-मालिक को एक्ट में दी गई बातों का अपनी जिम्मेदारी से पालन करना आवश्यक है। इस एक्ट में रक्षा सम्बन्धी कई नई जिम्मेदारियाँ भी मिल-मालिक पर डाली गई हैं। जैसे खतरनाक मशीनरी पर बालकों को काम करने से रोका गया है और अत्यधिक बोझ उठाने से होने वाले नुकसान से, खतरनाक (पयुन्स) से तथा बहती आग पकड़ने वाली धूल से मजदूरों की रक्षा करने की व्यवस्था भी की गई है। कई बातें जो पुराने एक्ट के अनुसार नियमों में शामिल की गई थीं, अब एक्ट में ही शामिल कर ली गई हैं। रक्षा-सम्बन्धी जो दूसरी मुख्य-मुख्य बातें इस नए एक्ट में दी गई हैं उनमें मशीनरी की घेरेबंदी (फेन्सिंग) करने, नई मशीनरी को सुरक्षित रखने (एन केस करना) और होइस्ट्स, और लिफ्ट्स, जेन्स तथा प्रेशर प्लांट्स सम्बन्धी नियमों को खास स्थान दिया गया है। इन्डियन माइन्स एक्ट और उसके अन्तर्गत प्रकाशित रेगुलेशन्स और रूल्स में भी रक्षा सम्बन्धी आवश्यक धाराएँ हैं। इसके अलावा चीफ इन्स्पेक्टर अथवा इन्सपेक्टर को भी यह अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक हिदायतें खान के मालिक अथवा मैनेजर को दे सकता है।

रक्षा के महत्त्व को समझने के लिए और उसके लिए आवश्यक उपाय काम में लाने के लिए मजदूरों में प्रचार करने की बड़ी आवश्यकता है। इस विषय में पोस्टरों तथा छोटी-छोटी सचित्र पुस्तिकाओं के द्वारा भी बहुत कुछ प्रचार किया जा सकता है, जैसाकि सब रेल्वे कम्पनियाँ करती हैं। बम्बई के मिल-मालिक-संघ ने भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। भारत की सेफ्टी फर्स्ट एसोसिएशन की सहायता से मिल-मालिक-संघ ने एक सेफ्टी कीड प्रकाशित किया है। कई मिलों में सेफ्टी-फर्स्ट कमेटियाँ भी स्थापित हुई हैं। भारत

सरकार ने भा विछले दिना इस नियम म अधिन ध्यात दिया है और चौक एवाङ्कार केवटरी के कार्यालय मे रत्ता के सम्पत्ति म समय समय पर माहित भा प्रकाशित होना रहता है। मजदूर तथा ना भा यह जर्नल दे कि वे इस काम में मिले माहित और सरकार की सहायता करें।

मजदूर हितकर कार्य—पूजोवादी अथर्ववस्था ना यह लागू है कि उद्योगपति और मिल-मालिक मजदूरों का हर प्रकार से शोषण करना चाहते हैं। यहा कारण है कि राज्य की मानन बात कर मजदूर के हित की रक्षा करना होता है। बिना परिस्थितिया म मजदूर कारखानों में काम करना है, जो दूसरी अत्यन्त आवश्यक सुविधा उते मिलनी चाहिये, और उसकी रक्षा की जो व्यवस्था आवश्यक है, हा सब बात का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। हमारी यह भी दम्ता कि राज्य न मानन जाता इन सब मामलों म मजदूरों व हितों की रक्षा करने का प्रयत्न किया है। और यदि हम व्यापक दृष्टि से देखें तो इन सब बातों का समावेश मजदूर हितकर कार्यों में हो जाना है। पर मजदूर हितकर कामों म उपयुक्त बात का समावेश न करके मजदूरों व हित में किए जाने वाले दूसरे कार्यों की गिनता हा की जाती है। उदाहरण के तौर पर मजदूरों के लिए नल पान गृह (रङ्गीन) और बच्चा व लिए शिशुगृह (नेबेन) की व्यवस्था, मजदूरों व स्नान आदि की सुविधा, उनके मोटरजन, शिक्षा और चिकित्सा ना व्यवस्था, मकान व व्यवस्था, अण्ड स्वच्छ भोजन का प्रवच, स्वैतन अवकाश और सामाजिक सुरक्षा व अनान आने वाली सुविधाओं—जैस बीमारों और प्रवृत्ति व समय वा जाने वाला सहायता, प्रोविडेंट फण्ड, प्रोस्पटी और पशन व व्यवस्था इन उन कामों ना गिनता मजदूर हित व कार्यों में वा जाना है। इन कामों की अब तक एक विशेषता यह भा रही है कि मजदूर-कानून में इन बातों का समावेश नहीं था। इसालिए मजदूर हितकर कार्यों म प्राय उन कामों का गिनती होती रहा है जो कानून से बाध्य न होने पर भी मजदूरों का भला के लिए किये जायें। पर और यह मर्यादा उपयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि उपयुक्त कामों में से बढ के लिए कानून में भी व्यवस्था की जा चुकी है। १९४८ के फक्टरी एक्ट को यदि हम लें तो देखेंगे कि मजदूर हित के कार्यों पर एक अलग परिच्छेद है जिसम जलपान-गृह, शिशुगृह, विधाम गृह और नहान पावे व सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, तथा काम करते-करते मौका मिलने पर मजदूर बैठ सक इस बात की सुविधा व विषय में आवश्यक धाराओं का समावेश किया गया है। इसा प्रकार कुछ और कानून भी बने हैं जिनका सम्बन्ध मजदूर हितकर कार्यों म है। जैन मारुस मेटरनिटी

बेनिफिट एक्ट (१९४१), माइका माइन्स लेबर वेलफेयर फन्ड एक्ट (१९४६), कोल माइन्स लेबर वेलफेयर फन्ड एक्ट, (१९४७) कोल माइन्स प्रोविडेंट फन्ड एन्ड वोनर्स स्टॉम्स एक्ट (१९४८), और एम्प्लोईज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट (१९४८) इसी प्रकार के कानून हैं।

मज़दूरों के स्वास्थ्य और कार्यकुशलता की दृष्टि से मज़दूर-हितकर कार्यों का बड़ा महत्त्व है। उनमें अपने कार्य के प्रति तत्परता और लगन पैदा करने, उनके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने और उनमें संतोष उत्पन्न करने की दृष्टि से भी इन कार्यों की बड़ी आवश्यकता है। जलपान-गृह को ही लीजिए। मज़दूर सुबह मिल में काम करने जाता है। प्रायः वह अपने साथ रात का चासी लाता ले जाता है जो दोपहर की छुट्टी में वह खालेता है। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर अच्छा नहीं पड़ता। यदि कारखानों आदि में अच्छे जलपान-गृह की व्यवस्था हो, जहाँ मज़दूर को सस्ता और स्वस्थ भोजन मिल सके तो उसके स्वास्थ्य और कार्यशक्ति पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अन्ततोगत्वा उसका लाभ मिल-मालिकों को भी मिलेगा। इसी तरह शिशुगृह की आवश्यकता भी स्वयं सिद्ध है। मज़दूर स्त्रियाँ जब मिलों में काम पर आती हैं तो शिशुगृह के अभाव में वे अपने बच्चों को या तो अपने साथ ले आती हैं और मशीनों के पास ही वे उनको रखती हैं, या फिर वे घर पर अफोम खिलाकर उनको छोड़ आती हैं। दोनों ही स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर घातक असर पड़ता है। यदि कारखानों आदि में अच्छे शिशुगृहों की व्यवस्था हो, जहाँ बच्चों की देख-भाल के लिए किराी नर्स आदिकी व्यवस्था हो, और उनके खेलने आदि का प्रबन्ध हो तो मौजूदा स्थिति में बहुत सुधार हो सकता है। जो बात जलपान-गृह और शिशुगृह के बारे में कही जा सकती है वही मनोरंजन के बारे में भी। कारखानों के थका देने वाले काम के बाद मज़दूर को स्वस्थ मनोरंजन की आवश्यकता होती है। उसकी जब व्यवस्था नहीं होती तो वह कई प्रकार की बुराइयों में फँस जाता है। मज्जपान करने लगता है। आवश्यकता इस बात की है कि अपने काम से लौटने के पश्चात् उसको खेलने आदि का समय और साधन प्राप्त हों, रात्रि में अच्छी फिल्मों उसे देखने को मिलें, भजन आदि अच्छे गायन का उसके लिए प्रबन्ध हो तथा दूसरे मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हों। चिकित्सा और शिक्षा की उचित व्यवस्था के अभाव में भी मज़दूरों की कार्यशक्ति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। चिकित्सा की दृष्टि से तात्कालिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) का बड़ा महत्त्व है। प्रत्येक कारखाने में तात्कालिक चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिये और इस काम को कर सकने वाले व्यक्ति होने चाहियें। भारत की

मिला में मजदूर प्रायः अशिक्षित आता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाए ताकि अशिक्षित होने से जो अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं उससे बचा जा सके। प्रौढ़ों के अभाव में मजदूरों के बच्चों का शिक्षा का भी प्रबंध होना आवश्यक है। मजदूरों के स्वास्थ्य की दृष्टि से इस बात का बड़ा आवश्यकता है कि कारखानों तथा काम करने के अन्य स्थानों पर उद्योगों की पूरी सुरक्षा हो ताकि दुर्घटना के समय मजदूर नष्ट हो जायें और जरूरत पड़ने पर काम करना बंद करके होना पड़े। प्रायः मजदूरों में इतना समय नहीं रहता कि वह काम पर जाने से पहले श्रमका वाद मस्तिष्क करे। इसलिए काम करने के स्थान पर वह सुविधा आवश्यक है। पानी के साथ साथ चयन नालियाँ आदि का प्रबंध भी होना चाहिए। मजदूरों के हित में सामाजिक सुरक्षा की सुविधा व्यवस्था का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बीमारी के दिनों में उचित चिकित्सा का प्रबंध होना चाहिए। यद्यपि नहीं है, पर यह भी जरूरी है कि उस समय का सुआवका भी मजदूरों को मिले। इसी तरह से जब मजदूर बकारी की अवस्था में हो उस कुछ सुआवका मिलना चाहिए, ताकि उसका जीवन निर्वाह होता रहे और बकारी की अवस्था में उसकी कार्य क्षमता क्षीण न हो। प्रकृति के समय मजदूरों को शारीरिक महावकाश मिलना उसी तरह आवश्यक है जैसे बीमारी के समय। बृद्ध अवस्था में और परिवार में बसने वाले की मृत्यु का ज्ञान पर भी मजदूरों को सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। प्रोविडेंट फंड, पेन्शन, और रेशन मिलने का व्यवस्था इस दृष्टि से आवश्यक है। कारण यह है कि मजदूरों के हितों का अनेक प्रकार से हो सकते हैं और मजदूरों का जीवन की सुखी और अनुष्ठानता के लिए तथा उनके कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए इन कार्यों का बहुत महत्त्व है।

मजदूरों के हितों का हमारे देश में जो आज स्थिति है उस पर यदि हम विचार करें तो मालूम पड़ेगा कि स्थिति सतत-अच्छा बिल्कुल नहीं है। इस सम्बन्ध में थोड़ा विस्तार से लिखना अनुचित न होगा। सबसे पहले हम जलपान यह के बारे में ही विचार करें। अधिकांश मिलों और फैक्ट्रियों में तो इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है, और वहाँ है भी तो उनकी दशा और व्यवस्था अच्छी नहीं है। न वहाँ शराब की कोई खास व्यवस्था होती है और न इस बात का प्रबंध है कि जो पाने आदि का सामान बेचा जावे वह अच्छा और उचित दामों पर बिके। मौजूदा फैक्ट्रियों एकटके अनुमान राज्य की सरकार को यह अधिकार है कि ₹२० से अधिक व्यक्ति जिस कारखाने में काम करते हैं, उस के मालिक को जलपान-यह का व्यवस्था करने के लिए बाध्य किया जाए। इसी

प्रकार जिस कारखाने में १५० व्यक्ति काम करते हों उसमें फेक्टरी एक्ट के अनुसार आराम करने और भोजन करने के उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है। पिछले वर्षों में, खास तौर से द्वितीय महायुद्ध के समय से इस दिशा में कुछ प्रयत्न अवश्य हुआ है और भारत-सरकार तथा राज्य की सरकारों ने भी ध्यान दिया है। उद्योगपतियों में कर्मई की ई. डी. सेलून कम्पनी, जमशेदपुर की टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी, और इंडियन टी मारकेट एक्सचेंज बोर्ड ने भी अच्छा काम किया है।

शिशुपाकन-गृह के बारे में भी हमारे देश की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। जिन उद्योगपतियों पर कानूनी बंधन नहीं है वे तो इस बारे में कोई ध्यान देते ही नहीं, पर जिनको कानून की दृष्टि से शिशुगृह की व्यवस्था करनी चाहिये वे भी अपनी ज़िम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं। जहाँ शिशुगृह हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। न बालकों को देखने-भालने की उचित व्यवस्था होती है, न उनको रखने का स्थान स्वच्छ और हवादार होता है और न बालकों के खेलने आदि की कोई व्यवस्था होती है। पर कुछ उदार उद्योगपतियों ने इस ओर भी अपना कर्तव्य किसी हद तक पूरा करने की चेष्टा की है। इनमें टाटा, बकिंगहम और कर्नाटक मिल्स, मद्रास और मदुरा मिल्स के नाम खास तौर से गिनाए जा सकते हैं। १९४८ के फेक्टरी एक्ट के अनुसार प्रत्येक ऐसे कारखाने में जहाँ ५० से अधिक स्त्रियाँ काम करती हैं शिशुगृह की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है और इस सम्बन्ध में कुछ विशेष सुविधाओं की व्यवस्था कराने का अधिकार राज्य की सरकारों को दे दिया गया है।

मनोरंजन, शिक्षा व चिकित्सा आदि संबंधी अन्य हितकारी कार्यों का जहाँ तक सवाल है उनमें भी बहुत कुछ करने की बाकी है। यह ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत-सरकार, और राज्य की सरकारों ने भी इस ओर ध्यान दिया है। कुछ मिल-मालिकों और उद्योगपतियों ने भी अपने मजदूरों के लिए चिकित्सा, शिक्षा और मनोरंजन की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है। जहाँ तक मिल मालिकों द्वारा चिकित्सा की व्यवस्था का प्रश्न है यह व्यवस्था तात्कालिक चिकित्सा और छोटी-छोटी डिस्पेंसरी से लेकर अच्छे और बड़े-बड़े अस्पतालों तक की है। उदाहरण के तौर पर टाटा कम्पनी, दिल्ली जल मिल्स, बकिंगहम और कर्नाटक मिल्स मद्रास, तथा आसाम ऑयल कम्पनी डिगबोई ने काफी अच्छे और सुसंचालित अस्पतालों की व्यवस्था कर रखी है। जितनी भी प्रयम-श्रेणी की रेलवे हैं उन सबने अपने कर्मचारियों की चिकित्सा का अच्छा प्रबन्ध कर रखा है। टाटा कम्पनी ने कई स्कूलों की व्यवस्था भी कर रखी है और

त्रिमनात्रियम तथा क्ववा का, विनम क प्रसार के मनोरञ्जन के माधन उपनयन है, प्रथम भी है। दित्ता ज्ञापि मित्त, वर्त्तिगम और काटक मित्त मद्रास, त्रिगिण्ड इडिया कारपारेखा नानपुर, दग सदर नैट मू और मित्त कापुर, ज व इडस्ट्राज नानपुर, धम्पेन मित्त गगपुर, मदरा मित्त, कोलार गोल्ड फोल्ड का रम्पनिना, तालगिया रामट कम्पनी, डालमिया नगर, तथा टाटा ओइल पम्पनी तानापुरम (एरनेकुलम के पास ट्रान्स्फोर रोबो में) — ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने मजदूरों के लिए त्रिमित प्रसार के हितकारी कामों का प्रस्थापना है। इन कामों में शिक्षा, चिकित्सा, मनोरञ्जन और कहीं कहीं आभाराधना, पञ्चन भूटो प्रोविन्ट फन्, शिशुग्रह, अजपान ग्रह, अज्ञान की दूकान, मदरास समिति, मानुग्रह शिशुहितकारों केन्द्र और विधवाग्रह आदि कई प्रकार की प्रवृत्ति का समावेश होता है। प्रथम श्रेणी की रत्नों और चाय आदि व बागों में काम करनेवाले लोगों को भी इस तरह की कोशिशें कई मुकामों पर की ओर ध्यान दिया गया है। मजदूर हितकारी कार्यों में नहान धोने का मुकाम का भी महत्त्व काफी है। १९४८ के फेब्रुअरी कानून के अनुसार प्रथम पर्यटन में इस प्रकार की मुकामों को मान्यता दी गई। पर वास्तव में एसी मुकाम बहुत कम हैं क्योंकि अधिकांश कारखानों में हाथ पाव धोने के बर्तनों का प्रयोग तो फिर भी होता है, पर मावन, तालिया आदि की व्यवस्था नहीं होता। नहाने का मुकाम तो बहुत कम होता है।

मजदूर हितकारी कार्यों के बारे में राज्य तथा मजदूर नभाओं द्वारा जो प्रयत्न अब तक हुए हैं, उनका भी संक्षेप में उल्लेख कर देना आवश्यक है। चौदह मई १९४७ तक तो भारत सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयत्न किया नहीं था, पर पिछले कुछ वर्षों से उसने इस ओर ध्यान दिया है। न केवल स्वयं ने इस सम्बन्ध में कार्य किया बल्कि राज्य की सरकारों और उद्योगपतियों को भी कई प्रकार से इस दिशा में काम करने के लिये प्रोत्साहन और सुविधाएँ प्रदान कीं। भारत सरकार के कारखानों आदि में मजदूर हितकारी कार्यों की स्थापना की गई है ताकि मजदूरों के खेल और मनोरञ्जन तथा वाचनालय आदि की व्यवस्था हो सके। कोयले, अन्न के गाना में काम करने वाले मजदूरों के लिए भारत सरकार ने कोल माइंस वेल्फेयर फंड और माइन्स माइन्स वेल्फेयर फंड की स्थापना की है। कोल माइन्स वेल्फेयर फंड का उपयोग मजदूरों, तपार्थ और स्वास्थ्य का दृष्टि से अस्पताल बनवाने और मलेरिया तथा तपार्थ निराधक काय करने, पानी की व्यवस्था करने, शिशुग्रह, चलने फिरते जलपान ग्रह और दुकानों की व्यवस्था करने में किया जाता है। स्त्रियाँ और बच्चों के लिए

अलग से हितकारी केन्द्रों की स्थापना भी की गई है जहां शिक्षा, मनोरंजन तथा खेल आदि का प्रबन्ध किया जाता है। इसी प्रकार माइका मारुन्स फण्ड के द्वारा माइका की स्त्रियों को मजदूरों की चिकित्सा के लिए अलग डिस्पेंसरी बनाने और पानी के लिए कुएँ खुदवावे का प्रबन्ध किया जा रहा है। राज्य की सरकारों का जहां तक ताल्लुक है १९३७-३८ में जब पहली बार कजिस्ती सरकारों की स्थापना हुई तो इस ओर विशेष ध्यान दिया गया। बम्बई, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयत्न किए हैं। विभिन्न राज्य की सरकारों द्वारा मजदूर-हितकारी केन्द्रों की स्थापना की गई है, जहां मजदूरों के मनोरंजन, खेल, स्नान तथा शिक्षा आदि के लिए सुविधा करने का प्रयत्न किया जाता है।

मजदूर-सभाओं में अहमदाबाद टेक्स्टाइल मजदूर संघ, रेलवेमेन्स यूनियन और मजदूरसभा कानपुर ने इस दिशा में थोड़ा ध्यान दिया है। पर कपड़े की कमी की वजह से मामूली तौर पर मजदूर-सभाएं मजदूर-हितकारी कार्यों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाती।

मजदूरों के मकानों की समस्या:—आज के औद्योगिक पुंजीवाद की एक प्रमुख समस्या मजदूरों के लिए स्वस्थ और सुविधाजनक मकानों की व्यवस्था करने की है। मजदूर जैसे मकान में रहता है उसका अक्षर उसके रहन-सहन के ढंग और उसकी कार्य-शक्ति पर पड़ता है। भारतीय मजदूर की भी एक बहुत बड़ी समस्या रहने के मकानों की है। इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति अत्यन्त अस्-तोषजनक है, चाहे फिर हम कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दृष्टि से विचार करें या स्त्रियों और बाल आदि के वर्गों में काम करने वाले मजदूरों की दृष्टि से। जो मकान उद्योगपतियों ने बनाए हैं वे भी सब एक ढंग के नहीं हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ अच्छे नहीं हैं। पर जो अल्प व्यक्तियों द्वारा बने हुए मकान हैं, जिनमें कि अधिकांश मजदूर बर्ग रहता है, उनकी हालत तो एक दम दयनीय है। न मकानों में हवा आने की सुविधा है और न धूप की। शौच आदि की व्यवस्था का पहले तो प्रश्न ही क्या, और यदि कहीं है भी तो वह ऐसी कि वह न होने के बराबर है। पानी आदि की व्यवस्था का भी यही हाल है। मकानों में भीड़ का तो कहना ही क्या। एक ही कमरे में एक से अधिक परिवार के लोग, जिनमें पुरुष-स्त्री-बच्चे सभी होते हैं, रहते हुए मिलेंगे। अधिकांश मकान एक ही कमरे के मिलेंगे। इस एक कमरे में अलग-अलग परिवारों के अलग-अलग चूल्हे मिल जाएंगे, और यदि कोई स्त्री गर्भवती है तो उसकी प्रसूति का प्रबन्ध भी वहीं होता हुआ मिल जाएगा। एकान्त की तो इन एक कमरे के

मकानों में रहता है क्या हो सकती है। और यदि धूल और धूप से बचने का प्रबंध करता है तो वह प्रबंध फर्श बोरियों के निचकों अथवा कनस्टर के टुकड़ों से ही किया जाना है। कुछ उदाहरण यह कहते ही सकते कि गांव में जिन मकानों में मनदूर रहना है, वह भी कोई अच्छा नहीं होते, किन्तु वह ऐसा कहते समय यह भूल जाते हैं कि यद्यपि गांव में मकानों में हवा का पूरा प्रवाह नहीं होता और रात की शिला इत्यादि गंदी रहनी है, फिर भी उनमें जो आगन होता है, उसमें धूप रोशनी और हवा यथेष्ट मात्रा में रहनी है। फिर किसान लेना न स्वास्थ्य युक्त वातावरण में काम करना है, जबकि मजदूर को नगर और कारखाना में दूषित और अस्वास्थ्य वातावरण में रहना पड़ता है।

मजदूरों के रहने में मकानों की जिस शोचनीय स्थिति का वर्णन ऊपर दिया गया है उसमें अनेक प्रकार की सुगंधा पैदा होती है। उनके स्वास्थ्य और चरित्र पर इसका अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। मनदूर नगरों की, जहाँ वे काम करते हैं, अपना स्थायी घर नहीं मानते, और इससे उरा अछर उनके स्थायित्व और स्थिति पर भी बिना पड़े रहा रहता। अब हम कुछ प्रमुख औद्योगिक नगरों की मजदूरों के मकानों सम्बन्धी समस्या पर संक्षेप में विचार करेंगे।

बम्बई — भारत का एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। वहाँ के मनदूर जिन मकानों में रहते हैं उनको "बालें" कहते हैं। 'बाल' एक लम्बी कोठरियों की पत्तियों को कहते हैं, जिसमें सामने पतला बरामदा होता है। यह दो तीन मंजिल की होती है, और एक-दूसरे से लट्टी लट्टी बनी होती है। मकानों की दो पत्तियों के बीच में एक कमरे से अधिक जगह नहीं होती। इससे कमरे में हवा और रोशनी का प्रभाव पड़ता है। अरिक्काश बालों में शौच यह नहीं होते। दो बालों के बीच में जो पतली मा गची होता है उसमें ही टटिया होती है। इन टटियाँ में सफाई का प्रबंध ठीक न होने से बड़ी गन्दगी रहती है, जिसका अछर आसपास भी पड़ता है। कुछ समय पहले बम्बई सरकार ने एक छोटी बान्स्टर की मनदूर दिवों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जांच करने के लिए नियुक्त किया था। उसी एक मकान के सम्बन्ध में लिखा है "ये बाल की दूसरी मंजिल में एक कमरे में कम, जिसकी लम्बाई १५ फीट और चौड़ाई १९ फीट थी। उस कमरे में ६ परिवार रह रहे थे। उसका भोजन पकाने के लिए उस कमरे में ६ छूट थे। उस परिवारों में स्त्री पुरुष बच्चे सभी मिलाकर ३० प्राणी थे और ये सब उन्हीं एक कमरे में रहते थे। छत से बोरियाँ बांधकर, उनमें बांस बांधकर, उन पर टाट और कम्पल डाल दिये गये थे, जिससे कि प्रत्येक

परिवार पृथक रह सके। उनमें से तीन स्त्रियाँ गर्भवती थीं और उनके शीघ्र ही वच्चा होने वाला था। मेरे पूछने पर मुझे एक कोने में चार फीट लम्बी और तीन फीट चौड़ी जगह दिखाई गई जिस पर पर्दा कर दिया गया था। इसी जगह में वच्चा उत्पन्न होने की व्यवस्था थी। वह इस तरह का अकेला कमरा नहीं था। ऐसे बहुत-से कमरे मेरे देखने में आए।” उपर्युक्त वर्णन से बम्बई की चालों के नारकाय जीवन का अन्दाज़ लगाया जा सकता है। अधिकांश चालों की इमारतें जर्जर अवस्था में हैं। नीचे के मंजिल में वेहद सीलन होती है। कहीं-कहीं तो चाल की इमारत सड़क के बराबर से ही खड़ी कर दी गई है, उसकी कुर्सी होती ही नहीं। नतीजा यह होता है कि वर्षा की ऋतु में सड़क का पानी कमरों में आ जाता है। सीलन का तो कहना ही क्या। इन चालों के अहातों में कुड़ा-कचरा और यहां तक कि मल के ढेर लगे रहते हैं, जो कि वर्षा के दिनों में बड़ी सड़न और दुर्गन्ध पैदा करते हैं। प्रत्येक चाल में एक स्थान पर पानी के नल की थोड़ी सी टॉटिया होती है। चाल के सभी लोग उन्हीं नलों पर नहाते-बोते भी हैं। ये चालें व्यक्तिविशेष की उम्पत्ति होती हैं और उनका ध्येय अधिक से अधिक किराया वसूल करना होता है। कहीं-कहीं जाबर भी चाल को पट्टे पर ले लेता है और अपने अधीन मजदूरों को उसमें रखकर मनमाना लाभ उठाता है।

मजदूरों के रहने के मकानों की उपर्युक्त अवस्था में सुधार करने का बम्बई-सरकार, बम्बई सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट और कुछ मिलों ने प्रयत्न किया है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् बम्बई-सरकार ने एक विशेष डेवलपमेंट विभाग स्थापित किया था और उस विभाग ने २०७ कंक्रीट की चालें बनाईं। प्रत्येक चाल में ८० कमरे (एक ६४ कमरे की को छोड़कर) हैं। इन चालों में कुल १६२२४ रहने के कमरे और १०० सुकाने हैं। १९३७-३८ में जब कांग्रेस-सरकार शासन में आई तो उसने भी इस बारे में काफी ध्यान दिया। इन चालों में कमरे बड़े हैं, रोशनी और हवा की सुविधा है। साथ ही फ्लश, बिजली की रोशनी, पानी की सुविधा है। इन चालों में स्कूल अस्पताल तथा दूसरे मजदूर-हितकारी कामों का भी म्यूनिसिपैल्टी और दूसरी परोपकारी संस्थाओं द्वारा प्रवन्ध किया गया है। बम्बई-सरकार ने हाल में एक ‘हाउसिंग बोर्ड’ की स्थापना की है जिसका मुख्य काम मजदूर आदि कम वेतन पाने वाले लोगों के रहने के मकानों की सुविधा करना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रान्त भर के औद्योगिक नगरों में १२५००० मकान बनाने का कार्यक्रम है। मकान सरकार स्वयं तो बनाएगी ही, पर व्यक्तिविशेष भी बनाएंगे और स्वायत्त शासन की संस्थाओं

को सरकार से सहायता भी मकान बनाने में मिलेगा। मिल मालिकों अपना सहकार समिति का कृत्तव्य किया जाएगा। १९४७ के नवम्बर में बम्बई सरकार ने यह योजना स्वीकार की थी। पोर्ट ट्रस्ट ने भी अपने मजदूरों के लिये मकान बनवाये हैं। हर कमरे में हवा और राखनी का अच्छा प्रबंध है। स्नानागार, और शौचगृह का व्यवस्था बंद मकानों में भी की गई है। मजदूरों की भलाई की दृष्टि से न सिर्फ एक कमरे का मुक्ति-केंद्र है। बल्कि इन्फ्रामेंट ट्रस्ट और बम्बई म्युनिसिपैलिटी ने भी कुछ चाल हैं। इससे अन्धारा लगभग ३० मिमी १ भी और मजदूरों के लिए एक कमरे की चालें बचाई हैं। इसमें संदेह नहीं कि यह चालें उन चालों में से हैं जो कि गिराव में सम्मिलित होना, अच्छी हैं, फिर भी काम स्थान का काम है।

कलकत्ते — यहाँ भी मजदूरों के रहने के मकानों की समस्या बड़ी निकट है। अधिकांश मजदूर बस्तियों में रहते हैं। यद्यपि अधिकतर सरकार का अर्थ-योजना में होता है। सरकार भूमि को पट्टे पर ले लेता है और जो मजदूर रहने के लिये मकान चाहते हैं, उनका तथा कुछ इत्यादि देकर स्थान बनाना देता है और मजदूर उमा स्थान पर एक कमरा मरिदा गढ़ा कर लेता है। कलकत्ता का यह बस्तिया इतना गढ़ा और गहरा होता है कि उनकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। हवा, रोखना और स्वच्छ पाना का अभाव होता है। बस्तियों में जाने के मार्ग दलदल और गढ़ा में भरे रहते हैं। हाउस की बस्तियों का गिराव भी भयंकर है। कुछ मिनी ने अपने मजदूरों के लिए कुछ कुला-लाइन बनवाई हैं। इन कुला-लाइनों में एक एक कमरे के लगभग ४०००० फीट हैं। कमरों में सामान बरामदा होता है। ये लाइनें पक्की हैं और पानी की सुविधा होती है। रोखना हवा का प्रबंध ठीक होता है पर बहुत अनोपयुक्त नहीं है। कुली-लाइन क्वार्टरों का एक लाइन होता है। शौच-गृह और पछान घर का भी व्यवस्था नहीं है पर वह भी काफी नहीं है। उन बस्तियों से यह लाइन अत्यंत अच्छी है पर इनको भी पूरी तौर से अनोपयुक्त नहीं माना जा सकता। पिछले वर्षों में बहुत मिनी में काम करने वालों के लिये कुछ अच्छे मकान बने हैं। बिड़ला नूट मिल्स कॉलोनी बहुत अच्छी शौचाली में से है। और मिल मालिकों ने भी अपने मजदूरों के लिए मकानों की व्यवस्था की है। पोर्ट भी मकान बनाये हैं। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने भी प्रांतीय हाउसिंग बोर्ड की स्थापना की है।

मद्रास — यहाँ भी मकानों की समस्या इतनी ही गंभीर है। मकानों की इतनी भयंकर कमी है कि ऐसी-सी मजदूरों को मकान तक नहीं मिलते। वे सड़कों

के किनारे अपना सामान रखकर पड़े रहते हैं वा बंदरगाह के किनारे जो वड़े-वड़े भालगोदाम बने हुए हैं, उनके बरामदों में रहते हैं। मद्रास में तो स्थिति और भी भयानक है। वही हाल कोचम्बटूर तथा तूतीकोरन का है। मद्रास में अधिकांश मजदूर एक कमरे के मकानों में रहते हैं जिनमें हवा और रोशनी का समुचित प्रबंध नहीं होता। प्रायः कमरों में खिड़की वा रोशनदान भी नहीं होता। एक मकान में कई कमरे होते हैं। शीचग्रह मकान के सब कमरों के बीच में एक-एक होते हैं। ये मकान व्यक्तिविशेष की उत्पत्ति होते हैं। कई जगह मकानों की कुर्ची सामने की गली से नीचे होती है और इस कारण वर्षा का पानी कमरों में चला जाता है। मकानों की कमी के कारण मद्रास शहर में मजदूर खाली स्थानों पर अस्थायी भाँपड़े या फची-पफी कोठरियाँ खड़ी कर लेते हैं और जब उन जमीनों के मालिक ज़मीन का किराया बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं तो वे उठकर दूसरी जमीनों पर चले जाते हैं। इन अस्थायी वस्तुओं को ही चैरी कहते हैं। सफाई आदि की इनमें कोई व्यवस्था नहीं होती। हवा और रोशनी के प्रवेश के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। पानी और शीचग्रह की कोई व्यवस्था नहीं होती। इन चैरियों की कोठरियाँ ८ फीट लम्बी और ८ फीट चौड़ी होती हैं। जो चैरियों सरकार वा म्यूनिसिपैल्टी की ज़मीन पर हैं उनमें पानी के नल, ग्राम शीचग्रह, और सड़कों को सुविधा अवश्य है। अन्य चैरियों में इनका अभाव है।

मद्रास सरकार के मजदूर विभाग तथा एच-दो सहकारी ग्रह समितियों ने कुछ मकान मजदूरों के लिए बनाए हैं। बरिधम, वनाटक मिलने लगभग १०% अपने मजदूरों के लिए मकानों का अर्द्धा प्रबंध किया है। इस कम्पनी ने चार आदर्श मजदूर-ग्राम बसाये हैं। प्रत्येक मकान में एक कमरा, सामने बरामदा एक रसोई घर, एक स्नानागार और आंगन होता है। पक्की सड़कें बनाई गई हैं जिन पर बिजली की रोशनी का प्रबंध है। पानी के लिए नल का प्रबंध है। सड़कों की रोशनी, पानी और सफाई का खर्च कंमनी उठाती है। पश्चिमी बंगाल की मॉलि मद्रास-सरकार ने भी एक 'प्रोविडिडल हाउसिंग बोर्ड' की स्थापना की है।

कानपुर—के तीन चौथाई मजदूर वस्तियों का अहातों में रहते हैं। यह अहाते व्यक्तियों की सम्पत्ति हैं। लगभग २०० अहातों में यहाँ की अधिकांश मजदूर-जनसंख्या निवास करती है। इन अहातों में एक कोठरी और कहीं-कहीं सामने बरामदे वाले बहुत से मकान होते हैं। कोठरियाँ १० फीट लम्बी और ८ फीट चौड़ी होती हैं। हवा और रोशनी तथा सफाई का प्रबंध अल्प

असतोपनन होता है। पाना और शीत व लिए आम पानी के नलों और शीतपत्रों की व्यवस्था होना है जो अत्यंत नाकामी और स्वास्थ्य तथा मर्यादा की दृष्टि से असतोपननक होती है।

कानपुर में मजदूरों के लिए अच्छे मकानों का मुनिवा का प्रबंध सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया वाररेशन ने किया। इस कंपनी ने एलनगज और मैर्रावर्टगज में दो बड़े मजदूर उपनिवेश बनाए हैं। इन उपनिवेशों में १६६० क्वार्टर हैं। मकानों में दो कमरों उपनिवेशों में अच्छा है। मकानों की हालत अच्छी है, आराम मर्यादा है और चिकित्सा और शिक्षा का भी प्रबंध है। पाना और शीतपत्र का भी व्यवस्था है। गन्ध के लिए मीदान भी है। इसके अतिरिक्त कानपुर इन्टरमिडियेट ट्रस्ट ने भी मजदूरों के लिए कुछ क्वार्टर बनवाए हैं। कुछ अन्य मिल मालिकों ने भी इस प्रकार प्रदान करना चाहा है पर जमीन का कमा में उनका प्रयत्न बहुत सफल नहीं गया है। संयुक्त प्रांत की सरकार ने भी इस प्रकार ध्यान दिया है।

अहमदाबाद—की भी ठीक ऐसा ही दयनाय दया है। अफिराश मजदूर एक कमरे के मकानों में रहते हैं। इवा, पाना का अभाव, गंदगी, पानी और शीतपत्र की व्यवस्था, न ही मकानों का विशयता है। मिल मालिकों ने 'अहमदाबाद मिल्स हाउसिंग कंपनी लिमिटेड' के द्वारा मजदूरों के मकानों की व्यवस्था की है। मकान में एक कमरा, एक खोदपर और एक बगमदा है। इन मकानों में साना, पाना, सब्जी व्यवस्था और मरम्मत के बारे में काफी शिकायत है। कुछ मिल मालिकों ने अपनी मिला के निकट ही 'चार्ज' बनाई हैं, पर एक दो को छोड़कर उनकी व्यवस्था भी ठीक नहीं है। अहमदाबाद की शेवर एमोसियेशन ने भी एक मजदूर उपनिवेश का निर्माण किया है। इस मकान में दो कमरे, एक बगमदा और एक आगन है। इस योजना के अनुसार अन्ततोगत्वा २० वर्ष में मजदूर मकान का स्वयं मालिक हो सकेगा और हर महीने एक निश्चित रकम देनी होता है।

नागपुर—में भी मकानों की व्यवस्था उतना ही बुरी है जितनी दूसरी जगह। परन्तु एम्प्रेस मिल्स नागपुर ने मजदूर उपनिवेश बनाने की जो योजना हाथ में लाई है वह उल्लेखनीय है। मिल ने सरकार से इंदोरा के समीप २०० एकड़ भूमि लगभग पट्टे पर ली है और उस जगह कंपनी २५ लाख रुपये व्यय करके १५०० मकान बनवा रही है। मकान कंपनी बनवाती है पर मजदूर मासिक किर्सें देता है और अन्ततोगत्वा मकान उसका हो जाता है। प्रत्येक घर में शीतपत्र और पाना व नल की व्यवस्था होना है। मजदूर कच्चे मकान भी बनाए

सकता है, पर मकान का नकशा कंपनी देती है। कंपनी मजदूर को मकान बनाने के लिए पेशगी रुपया देदेती है और मजदूर मासिक किश्तों में रुपया चुका देता है। इस उपनिवेश में सार्वजनिक उद्यान, बाजार, अस्पताल, स्कूल, मजदूरों की इन्स्टीट्यूट तथा दूसरी संस्थाओं के लिए ज़मीन निश्चित करदी गई है।

चाय के बागों—में (आसाम-बंगाल) भी मकानों की समस्या संतोषजनक नहीं है। अधिकांश मकानों में एक ही कमरा होता है। मकानों की कुर्सी नीची होने से सीलन रहती है, हवा और धूप की कमी मकानों में रहती है। सबसे बड़ी कठिनाई इन मकानों के बारे में यह है कि जहाँ यह बने हैं वह ज़मीन चूँकि बागों के मालिकों की है इसलिये वहाँ किसी बाहर के आदमी को इस भय से नहीं जाने दिया जाता कि वह मजदूरों को भड़कावेगा। वहाँ के मजदूर कैदियों की-सी अवस्था में रहते आ रहे हैं।

खानों—में काम करने वाले मजदूरों के रहने के मकानों की समस्या भी उतनी ही जटिल है जितनी कारखानों के मजदूरों की। बंगाल की कोयले की खानों में मजदूरों के रहने के मकानों को 'धौरा' कहते हैं। इन 'धौरों' में एक १०' X १०' का कमरा होता है और एक कमरे में दो-दो तीन-तीन परिवार रहते हैं। हवा, पानी, सफाई, शौचगृह, नहाने-धोने का स्थान सभी की व्यवस्था संतोष जनक नहीं है।

जमशेदपुर—में मजदूरों के मकानों की समस्या को हल करने का अच्छा प्रयत्न किया गया है। जिस भूमि पर जमशेदपुर नगर बसा हुआ है वह टाटा कंपनी की सम्पत्ति है। नगर का प्रबन्ध कंपनी के देख-रेख में ही होता है। रोयनी, नालियों और सड़कों की सफाई, शिक्षा, चिकित्सा तथा जल की व्यवस्था का व्यवसाय कंपनी ही करती है। मजदूरों के रहने के लिए भी कंपनी ने मकान बनवाये हैं। मकान के चारों ओर छोटा-सा बगीचा होता है और साफ शौचगृहों की भी व्यवस्था की गई है। मजदूरों को भी कंपनी रुपया कर्ज़ देकर मकान बनाने के लिए उत्साहित करती है।

कोयले की खानों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए भारत-सरकार ने लो कोल माइन्स वेल्फेयर फण्ड स्थापित किया है उसका एक उद्देश्य मजदूरों के लिए मकानों की व्यवस्था करना भी है। ये मकान बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश और बरार की खानों के मजदूरों के लिए बनेंगे। कुल ५०००० मकान बनाने की योजना है। ये मकान उपनिवेशों को शकल में बनेंगे। खानों के मालिकों को भी अपनी जमीन पर मकान बनाने की स्वीकृति है। मकान बनाने का खर्च फण्ड देगा और जमीन मिल-मालिक।

मनूष्यों के रहने के मर्यादा की समस्या निम्नी विकट है, यह उपर्युक्त वचन में स्पष्ट हो गया होगा। यह बटवारा ने हम प्रश्न का और भर्दकर रूप दिया है। इस समस्या का हल यह का अधिष्ठान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। हम मनूष्य में मान का बर्णन का भी एक प्रश्न है, यद्यपि संचार उचित मुद्राधना और मनूष्यों के रहने के मर्यादा वचन के लिए मान में (मनूष्य-मान-मान) मान प्राप्त कर सकता है। यदि मर्यादा मिली सूर बनाए जा सताया जा अधिष्ठान प्रचलन यह अधिष्ठान आवश्यक है ताकि मनूष्य को मर्यादा मान मान मान में बर्णनाई न हो। उन अधिष्ठानिक वचन में जा पहुँचे में ही धने आबाद हो गए कारणान्तर तथा तत्काल भव हो नहीं गालन स्थि जाए। पर इस सम्बन्ध में मर्यादा महत्व की बात यह है कि हम सगत्या जा हो एक अधिष्ठान तात्त्विक आधार पर हाँ हाँ करता है। भारत सरकार और राज्य की सरकारों तथा अधिष्ठानों और मर्यादा सभी के मनोयोग की समान आवश्यकता होगी यह अधिष्ठान की जाती है कि प्लासिंग कमोशन जो तोड़ना यह के लिए न कर रहा है उगम मर्यादा की समस्या को हल करने के प्राथमिकता में जायगी।

सामानिक मुद्रा — मर्यादा धर्म के लिए सामानिक मुद्रा का प्रश्न भी बहुत में प्रश्न है। हम अधिष्ठान है कि मनूष्य को धनेका प्रकार की अधिष्ठान तात्त्विक और मनूष्य का सामना करना पड़ता है जिन प्रकार की बीमारी वृद्धावस्था, मृत्यु दुष्टता जिस कारण अधिष्ठान अधिष्ठान स्थान और मर्यादा काम करने के अधिष्ठान का नाम है और अधिष्ठान होना [स्त्रियों के लिए]। प्रत्यक्ष अधिष्ठानिक धर्म से उत्पन्न राष्ट्र में इस प्रकार की अधिष्ठान से व्यवस्था है कि जब भी मनूष्य का उपर्युक्त खनरों में सकिनी एक या अधिष्ठान का सामना करने का अधिष्ठान जा तो उनकी अधिष्ठान तथा दूसरे प्रकार से सहायता का जा सके। उपर्युक्त खनरों में सकिनी एक के लिए, नैसर्गिक बीमारी, अधिष्ठान, अलग से व्यवस्था हो सकता है और यह भी होगा है कि कई मिले जुले खनरों की एक साथ व्यवस्था हो, नैसर्गिक बीमारी, वृद्धावस्था होना और जाट लग जाता। इस में निम्न सा और डाक्टरों सहायता की आवश्यकता होती है और सभी एक योजना के अधिष्ठान का व्यवस्था की जा सकती है। वास्तव में दखा जाय तो सामानिक मुद्रा का मोटा मोटा अर्थ यह है कि आज के अधिष्ठानिक समाज में उद्योग खनरों का समय समय पर प्रत्यक्ष व्यक्ति को सामना करना पड़ता है जिनके लिए व्यक्ति यह निम्नकार नहीं है और इसलिए समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति विशेष को इन खनरों से मुद्रा करे। यहाँ यह बात अवश्य ध्यान में

रखने की है कि सामाजिक सुरक्षा का यह ध्येय कदापि नहीं है कि समाज में उत्पादक श्रम और काम का महत्त्व कम हो जाए और व्यक्तिः लोग यह सोचने लगें कि जब बीमारी, बेकारी, अथवा दुर्घटन में सहायता मिल ही जायगी तो श्रम काम करने की और उत्पादन की चिन्ता क्यों की जाए। समाज के व्यक्तियों की सुरक्षा का भार लेने का यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जा सकता है। वास्तव में बात तो इससे सर्वथा विपरीत है। जिस राष्ट्र में उत्पादन और राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी उतना ही सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न आसानी से हल हो सकेगा। क्योंकि सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर जो व्यय होगा उसकी क्षमता उन्नत और साधन-सम्पन्न राष्ट्र में ही हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में दूसरी विचारणीय बात यह है कि यद्यपि प्रारम्भ सामाजिक सुरक्षा के अलग-अलग खतरों के लिए अलग-अलग योजना बनाकर किया जा सकता है, पर अन्तिम ध्येय यह होना चाहिये कि राष्ट्रव्यापी सामाजिक सुरक्षा की एक सम्पूर्ण योजना हो जो राष्ट्र के सब लोगों पर लागू हो और जिसका एक आधारभूत सिद्धान्त यह हो कि जब एक व्यक्ति काम करने के योग्य किसी कारण से नहीं रहता है तो उसकी आय का ऐसा निश्चित साधन उसे प्राप्त होना चाहिये कि वह अपना शेष जीवन आराम से व्यतीत कर सके। चर्चिल के शब्दों में—‘अनिवार्य बीमा सब लोगों के लिए और सब कामों के लिए—जन्म से मृत्यु तक’। ब्रिटेन की वेवरिज सुरक्षा योजना का भी यही आधारभूत सिद्धान्त है कि कार्य न कर सकने की हालत में व्यक्ति को एक निश्चित आय मिल सके जिससे साधारणतया वह अपना निर्वाह करले। सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू उसपर होने वाले खर्च की व्यवस्था करना है। इस सम्बन्ध में मूलतः दो आधार प्रचलित हैं—एक सामाजिक बीमा का जिसके अनुसार जिन व्यक्तियों को लाभ मिलता है वही प्रधानतः खर्च के लिए जिम्मेदार होते हैं, दूसरा सामाजिक सहायता का जिसके अनुसार खर्च का जिम्मा समाज अर्थात् राज्य पर होता है। आज तो सामाजिक सुरक्षा की देशव्यापी योजनाओं में इन दोनों आधारों का समुचित समन्वय होना आवश्यक है। न्यूज़ीलैण्ड, डेनमार्क, स्वीडन तथा दूसरे कुछ देशों में ऐसा है भी।

भारत में सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में अभी कोई विशेष प्रयत्न नहीं हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि भारत में अभी उद्योग-धन्ये का बहुत विकास नहीं हुआ है। रोयल कमीशन [लेनर] ने बेकारी सम्बन्धी बीमा तो भारत के लिए व्यावहारिक नहीं समझा और बीमारी के बारे में उसने यह निष्कारिण की कि इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये और इस दृष्टि से एक

वाजता भी प्रस्तावित की। इस प्रश्न पर बोम्बे टंकमन्दाय लेखक इत्याचार्यी
 कमेटा १ भा रिपार किया। और अग मसियों २ प्रथम भा सम्मेलनों में भी इस
 भाग में विचार हुआ। आतिरकार भारत सरकार १ मार्च १९४३ में प्रो० बा०
 पा० अन्तरकर को आशयित मन्त्रियों के लिए स्वास्थ्य-बामा का एक योजना
 तैयार करने के लिए नियुक्त किया। १९४४ में प्रो० अन्तरकर का रिपोर्ट प्रका
 शित हुआ। भारत सरकार के निम्नलिखित पर अतःशुल्क मन्त्रदूर मन्त्र ने मन्त्र भा
 स्थापित और मन्त्र भाग २ दा निशाना का इस्तान्ति नियुक्त किया कि न मा प्रो०
 अन्तरकर का रिपोर्ट पर विचार करने अर्थात् राय भारत सरकार का है।
 उद्देश्य आन्तरिक मन्त्र १९४४ और निम्नलिखित के बाद अन्तरकर रिपोर्ट
 पर कुछ तुलना दिन जो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया। इसी आशय
 पर फिर भारत सरकार १९४४ में १९४४ में एक दिन 'स्थिति' किया और १९
 अर्थात् १९४४ में यह कानून बन गया। इसी का नाम 'एम्प्लॉयमेंट रेट्स इन्फो
 र्म एक्ट' है। यह एक्ट उन सब कारखानों पर जो मॉनोपली कारखाने नहीं हैं,
 लागू होता है और ६००)०० मासिक तक पाये जाने लोग इससे लोभ में आते
 हैं। 'एम्प्लॉयमेंट रेट्स इन्फोर्मेशन कारपोरेशन' नाम का एक स्वतन्त्र संस्था को इस
 एक्ट के अनुसार कार्य-मन्त्रालय का भार दिया गया है। एक्ट के अन्तर्गत 'मन्त्रों
 को जो लाभ, मिल सकते हैं वे हैं—बामारी लाभ, पशुति लाभ, काय शक्तिहास-लाभ,
 आभिन लाभ और निमित्त लाभ। मिलशाल कुछ चुने हुए टखोनों में
 ही इस एक्ट को लागू करने का निश्चय किया गया है क्योंकि अधिक व्यापक
 आधारपर लागू करने के लिए पूर्ण व्यवस्था अभी तक हो नहीं सकी है। भारत में
 सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उठाया गया यह पहला महत्वपूर्ण कदम है। इस
 अन्तर्गत 'मन्त्र मन्त्र कमेडिशन एक्ट, मेटरनिटी बनिनिटि एक्ट, और कौल
 माइस प्रोविडेंट फंड एंड बानस स्कीम एक्ट के अन्तर्गत भी सामाजिक सुरक्षा
 का कुछ व्यवस्था की गई है। व्यक्तिगत उपयोगियों और मिलों में भी कहा-
 कही आन मन्त्रों के लिए रिटायरमेंट बनिनिटि स्कीम [मन्त्र लीवर वर्कर्स],
 प्रच्युटी स्कीम [टाटा आइरन एंड स्टील कम्पनी] और प्रोविडेंट फंडों का
 व्यवस्था का है। रेलवे कम्पनियों में भी अपने कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट
 फंड आदि का व्यवस्था कर रही है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा
 के क्षेत्र में अभी प्रारम्भ मात्र हुआ है और करने को बहुत कुछ बाकी है। देश
 की निर्धनता, मन्त्रों का आर्थिक दृष्टि में असामर्थ्य और तथ्यो तथा आर्थिक
 की कमी कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न

हमारे देश में और भी अधिक जटिल बना हुआ है। पर हमें इन सब कठिनाइयों को जीतना होगा और भारतीय मजदूर के लिए सामाजिक सुरक्षा की अन्ततोगत्या समुचित व्यवस्था करनी होगी।

आय और रहन-सहन का दर्जा:—मजदूरों सम्बन्धी अन्तिम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उनकी आय का है जिस पर उनके रहन-सहन का दर्जा भी बहुत कुछ निर्भर है। इस सम्बन्ध में भारतीय मजदूर की क्या स्थिति है इस पर अब हम संक्षेप में विचार करेंगे।

मजदूरी के कई आधार होते हैं। दो आधार जो सबसे अधिक प्रचलित हैं वे ये हैं—समय का आधार और काम का आधार। अमुक समय तक काम करने पर अमुक मजदूरी मिलेगी; यह समय का आधार है। और अमुक काम की अमुक मजदूरी मिलेगी, यह काम का आधार है। भारत में अधिकांश धंधों में समय के अनुसार मजदूरी दी जाती है। परन्तु कुछ धंधे ऐसे भी हैं जिनमें काम के अनुसार मजदूरी देने की प्रथा बहुत प्रचलित है, जैसे—वस्त्र-व्यवसाय, इंजीनीयरी सम्बन्धी उद्योग तथा कपड़ा सीने के कारखानों में। कहीं-कहीं उपर्युक्त दोनों पद्धतियों का सम्मिश्रण भी कर दिया जाता है। भारत में ऐसा बहुत कम है। वास्तव में तो होता यह है कि न केवल भिन्न-भिन्न उद्योगों में परन्तु एक ही प्रकार के उद्योग में एक ही स्थान अथवा अलग-अलग स्थान में भिन्न-भिन्न मजदूरी की पद्धति देखने को मिल जाती है।

मजदूरी के सम्बन्ध में दूसरा तवाल मजदूरी के दरों का है। इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे महायुद्ध के कारण भारत के औद्योगिक मजदूरी के ढांचे में बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया है। मुद्रकाल में केन्द्रीय तथा राज्य की सरकारों का बराबर यह प्रयत्न रहा कि उत्पादन अधिक से अधिक हो और इस दृष्टि से मजदूरों को उनकी आय को बढ़ाकर, बराबर संतुष्ट रखने का प्रयत्न किया। मजदूरों के वेतन सम्बन्धी भत्तों को सुलभाने के लिए औद्योगिक पंचायतें और कचहरियें नियुक्त की गईं और उन्होंने जो फैसले दिये उनसे मजदूरों को अवश्य लाभ भी हुआ। औद्योगिक पंचायतों के निर्णय के लागू करने के पहले बहुत-से उद्योगों में आधार भूत मजदूरी बहुत कम थी। और कई स्थानों पर मंहगाई-भत्ता मूल वेतन से चार से पांच गुना तक था। पर भारत-सरकार द्वारा केन्द्रीय वेतन कमिशन की सिफारिशें मान लेने से और औद्योगिक पंचायतों के निर्णयों को लागू करने से, देश के औद्योगिक मजदूरों का एक अच्छा अंश आज से कुछ वर्ष पहले जो मूल वेतन पाता या उससे कहीं अधिक मूल वेतन पा रहा है। इसी प्रकार सन् १९४७ में जब बोर्ड ऑफ

कृषीनिवेश की निगमिष्टों सरकार ने स्वाकार करलीं तो कोयले के खानों के मजदूरों का मजदूरा में भी यथष्ट वृद्धि हुई। रीगे कमेटी ने अपना रिपोर्ट में लिखा कि अधिकारा समुचित उद्योगों में मजदूरों के मूल वेतन में बहुत घाटा परिवर्तन हुआ पर जो उद्योग समुचित नहीं हैं अथवा जो मुद्रक समय में काफी बढ़ हैं वे—कान् अथवा इनामिचरी व कारखाने, उनमें मजदूरों के मूल वेतन में काफी वृद्धि हुई है। वहीं वहीं १००% में भी अधिक। मुद्रक समय का महंगा हुआ उद्योग पूर्ण करने के लिए भारत में मजदूरों के मूल वेतन में वृद्धि के कारण उनमें महंगाई होने का भाग में अधिक मजदूरा दी गई। इससे अलावा मजदूरों को सस्ते दामों पर लाभांश वेचन की व्यवस्था भी की गई। महंगाई भत्ता का बोझ सब माध्य आधार अर्थात् तक निश्चित नहीं हुआ है। अलग अलग स्थानों और अलग अलग उद्योगों में ही नहीं बल्कि एक ही स्थान के एक ही उद्योग के विभिन्न कारखानों में महंगाई होने का अलग अलग आधार पाया जाता है। भारतीय मजदूरों के मूल वेतन संबंधी मुख्य मुख्य उद्योगों के आंकड़ों को देखकर मान्य प्रकृति कि आज भी न्यूनतम मूल वेतन ३० द० मासिक से और न्यूनतम महंगाई भत्ता ७० द० मासिक से अधिक नहीं है। तथा यह है कि कुल मासिक आय १०० द० मासिक से अधिक नहीं है। उदाहरण के लिए मरमे अधिक आय करने उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की है। बम्बई में न्यूनतम मूल वेतन ३० द० और महंगाई भत्ता ५२ द० और अहमदाबाद में न्यूनतम मूल वेतन २८ द० और महंगाई भत्ता ७० द० १९४६ में था। तब के मजदूरों की आय सबसे कम है और उनमें भी अवरक के खान के मजदूरों की। एरिचमी बंगाल में कोयले के खान के मजदूरों का १९४६ में न्यूनतम मूल वेतन १३ द० और महंगाई २० द० कुल ३३ द० मासिक आय थी और बिहार के अवरक के खान मजदूरों का कुल न्यूनतम मासिक आय २८ द० (११ द० वेतन और १७ द० महंगाई) थी। भारत में मजदूरों के दर आज भी बहुत कम हैं इसका रूप में अनुमान लग सकता है। इसी के साथ दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए मजदूरों की आर्थिक स्थिति में कोई वास्तविक सुधार हुआ है या नहीं। इस संबंध में कोई एक उत्तर नहीं दिया जा सकता। मजदूरों के लिए काम का क्षेत्र पहले से काफी बढ़ा है और इसलिए मजदूरों का पहले से अधिक काम मिलने लगा है। पर जहाँ तक प्रति मजदूर हानि वाला आय का संबंध है, जो उद्योगों में महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ता या वेतन रहा है नीचे का अंशों ने मजदूरों की वास्तविक आय को है। पर ऐसा बहुत कम जगह हुआ है। रीगे कमेटी का कहना है, सारे देश

को सामने रख कर यदि राय बनाई जाए तो यह कहना होगा कि सबसे कम मजदूरी पाने वाले जो 'अन स्किल्ड लेबरर' हैं, उनको मंहगाई के कारण बहुत नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। कुछ संगठित उद्योगों में—जैसे जूट, बाग, खान, मजदूर की वस्तुविक्रय आय निश्चित रूप से कम हुई है। जो अच्छी श्रेणी के मजदूर हैं उनके बारे में कुछ अपवादों को छोड़कर जहां मंहगाई के अनुपात में मंहगाई-भत्ता मिलता है, साधारणतया यह कहा जा सकता है उनकी वास्तविक आय में कमी हुई है। मजदूरों की आय का मूल घंठन और मंहगाई के अलावा एक साधन और है। वह है 'बोनस' मिलने का। बोनस मुनाफे के आधार पर भी दिया जाता है, उपस्थिति के आधार पर भी दिया जाता है, और काम के आधार पर भी दिया जाता है। बोनस का हिसाब मासिक वेतन के आधार पर लगाया जाता है, अर्थात् ४ महीने के वेतन जितना रुपया साल भर में बोनस के रूप में मिलेगा। कई भारतीय उद्योग-धंधों-द्वारा अपने मजदूरों को 'बोनस' भी दिया जाता है। मजदूरों की आय का एक और साधन लाभ में हिस्सा मिलना है। भारत-सरकार ने इस विषय पर विचार करने के लिए एक कमेटी भी नियुक्त की थी जिससे कुछ सिफारिशें भी कीं। परन्तु अभी सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया। फिर भी टाटा कंपनी जैसे प्रगतिशील उद्योग-पतियों ने अपने मजदूरों के लिए लाभ-विभाजन की योजना जारी की है जिसके अनुसार कंपनी के सालाना शुद्ध लाभ का २७% प्रतिशत मजदूरों को उनके द्वारा कमाई गई मजदूरी के अनुपात में बांटा जाता है।

मजदूरों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी मिले इसकी कानून द्वारा भी व्यवस्था की जा सकती है। औद्योगिक दृष्टि से उन्नत कई राष्ट्रों में जैसे इंग्लैंड अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि में ऐसे कानून हैं। भारत में भी १९४८ में न्यूनतम मजदूरी एक्ट पास किया गया जिसके अनुसार सेटी तथा कुछ ऐसे दूसरे उद्योगों में जहां मजदूरों का अत्यधिक शोषण होता है, सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जा सकती है। पर इस एक्ट के अनुसार अभी कोई कार्य नहीं किया गया है।

मजदूरी के सम्बन्ध में विचार करते समय एक और प्रश्न प्रस्तुत होता है और वह यह है कि मजदूरी समय पर चुकाई जाती है या नहीं और उसमें से बुर्माना आदि के रूप में कोई अनुचित कटौतरी करली जाती है या नहीं। भारतीय मजदूरों को इन बातों के बारे में काफ़ी शिक्षा मिली। पर १९१६ में जब मजदूरी चुकारा कानून पास कर दिया गया तो इस बारे में सुधार हो गया है। अब मजदूरों को वेतन समय पर मिल जाता है। मजदूरी चुकारा कानून

(पोस्ट ऑर वॉच एण्ड)। य वह भी प्रभाव लगाया गया है कि बचल उड़ी अरराय ५ लिए उभाय रिश का सक्ता है निनव भार म पूर्ण घोषणा को जा चुना है। उमाना मरय म दौ ७ पैम से अधिक् तहां रिश जा सक्ता और १५ वय म रम आनु ५ यानर पर उमाना १। रिश जा सक्ता।

यब नरु हनने भारतीय मरुदूर को आर व सम्बन्ध म विचार रिग है। पर नु बचल दूनन परसे हा उमर रहन महन ५ दन का अनुमान नहीं लगाया जा सक्ता। उतर लिण और भी उड पार्ना का विचार करा आवश्यक है। सवम पहला बात जा रहन सहा ५५ ५ बार म है। दूसरे शब्दों म, अगर गैहगाइ है ना उभा आय म रहा मरन का म्ना नाग हागा निरम कि सम्मान अगर हागा ना रहन गहन का दना उँता हो मक्ता गा। दूसरा बात रिमका रहन महन ५ दन म सम्बन्ध आगा है वर यह है कि परिवार में किनो लोग हैं और उनम कमाने वाला का मर्या का है। तीसरी बात रिशका रहन महन ५ दर्जे पर अगर पड़ना है वह यह है कि आय ५ अन्य कोई महापक् मदन है या तहां और गा काम बन्ति करता है उमम उनम ५ अनाम और किरी प्रकार की सुरिग जैसे—भक्षण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की बात है या नहीं। और प्रन्तिम बात जो भवने अधिक महत्वपूर्ण मा है वह है सब सम्बन्धी आदता की, कि भगदूर अपनी आय किन वालों म खच करना है और वह मरम मानकर खच करना है या नहीं। क्योंकि कबल इसी बात में किनो व्यक्ति ५ रम मरन ५ दन का पना नहीं लग सक्ता कि वह खर्च किना करता है, पर साथ में यह भी दग्गता हागा कि गुर्त किनी चीजों पर रिमा जाता है। उपर्युक्त नमाम दृष्टियों म यदि हम भारतीय मरुदूर का स्थिति पर विचार करें तो हम इस नतीजा पर आगा पड़ेगा कि उरर रहन महन का दना सन्तोषपतक नहीं है। उनकी आय और उतर मुताबले में रहन महन के खर्च का विचार करने पर हमन दग्ग कि कुल मिलाकर उल्ल गाने की बेसी ५ मरुदूर को छोड़कर दूसरा ना जहाँ तक सम्बन्ध है, आय का प्रवृत्त त्यक् अधिक् बड़ा है। दूसर महापुद ५ बाद से रहन मरन का खच तीन गुने से लेकर कहां कहीं छठ गुने तक बड़ा है। आदिन है इस अनुपात म आय नहा बढ़ी है और इसका असर रहन महन ५ दर्जे पर बुरा पड़ा है। तहां तक परिवार ५ लोगों को सत्वा और उनम कमाने वालों का मर्या का प्रश्न है, उरलब्ध आदता से पना चलता है कि परिवार का सत्वा ५ से ७ व्यक्तियों तक माना जाना चाहिय और उनम कमाने वालों का सत्वा प्राय ११ से २ आदमी ५ बराबर की मानना चाहिये। इन परिवारों ५ मासिक आय सम्बन्धी आकड़ा से पता चलता है कि

यह आय प्रायः ६० और ७० ८० मासिक के आस-पास है। यद्यपि बम्बई और जमशेदपुर जैसे स्थानों में १०० ८० मासिक के आस-पास और अहमदाबाद जैसे स्थान में १२४ ८० मासिक तक भी यह आय पाई जाती है। अहमदाबाद में चूँकि परिवार के लोगों की संख्या भी ५ से कुछ कम है और उनमें कमाने वालों की संख्या भी १३ से कुछ अधिक ही है और रहन-सहन का खर्च भी लगभग ३३ गुना बढ़ा है [युद्ध के पूर्व समय से], इसलिये यह कहा जा सकता है कि अहमदाबाद में मजदूरों की स्थिति सब जगह से अच्छी है। जहाँ तक विभिन्न चीजों पर होने वाले खर्च का सम्बन्ध है, यह पता चलता है कि परिवार को आय का ५० प्रतिशत से अधिक और प्रायः ६० प्रतिशत और कहीं-कहीं तो ७० प्रतिशत और ८० प्रतिशत के आस-पास तक भोजन पर खर्च हो जाता है। ईंधन पर प्रायः ७-८ प्रतिशत और कहीं कहीं १०-१२ प्रतिशत तक व्यय होता है। हाँ, किराया के आन-मजदूरों का खर्च ३ प्रतिशत से भी कम आता है। मकान पर व्यय ३ प्रतिशत के लगभग से ७ प्रतिशत तक जाता है। प्रायः ३ प्रतिशत से ५ प्रतिशत खर्च माना जा सकता है। कपड़ों पर अधिकतर खर्च १० प्रतिशत से १२ प्रतिशत के आस-पास है। प्रायः १५ प्रतिशत से २० प्रतिशत खर्च दूसरी बातों पर माना जाना चाहिये। मजदूर-परिवारों के खर्चों के उपर्युक्त चित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज भारतीय मजदूर अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं पर ही अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग व्यय करता है। इससे उसके रहन-सहन के दर्जे पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका रहन-सहन का दर्जा संतोषजनक नहीं है। यह अक्षर्य है कि मजदूरों बढ़ने के कारण कहीं-कहीं मजदूरों ने पहले की अपेक्षा कुछ कँचे दर्जे का अनाज और कपड़ा आदि काम में लाना आरम्भ कर दिया है, पर इससे उसके रहन-सहन के स्तर में कोई मौलिक अन्तर आया हो ऐसा नहीं माना जा सकता। उमकी मकान थिच्चा, स्वास्थ्य, और मनोरंजन सम्बन्धी स्थिति का हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि कुल मिलाकर वह बड़ी असंतोषजनक है। जिस प्रकार का भोजन करने को उसे मिलता है वह भी स्वास्थ्यप्रद नहीं है। प्रायः एक बार तो वह बासी भोजन ही करता है। दूध और साग-सब्जी जैसे पोषिक पदार्थों का उसके भोजन में अभाव-सा है। भोजन बनाने का ढंग अच्छा नहीं है। इसके अलावा दिन भर को अपनी मकान उतारने के साधन स्वल्प मनोरंजन के स्थान पर शराब पीना या अश्लील सिनेमा देखना मात्र है। मजदूर के जीवन की इन तमाम बातों की जब हम एक साथ कल्पना करें तो समझ सकते हैं कि वास्तव में उसके रहन-सहन का दर्जा कैसा है और

उत्तम स्थिति सुधार की आवश्यकता है। आज तो भारतीय मजदूर का रहन सहन का स्तर अत्यन्त गम्भीरस्वभाव और गंभीर है, इसमें कोई संदेह नहीं।

श्रृंग — भारतीय मजदूर व आर्थिक जीवन के बिना को पूरा करने के लिए उम्मीद श्रम सम्बंधी विधि का भी थोड़ा सा होना आवश्यक है। भारतीय मजदूर और किसानता जो कारणाना काग करते हैं प्रायः कलदार होते हैं। आज की अर्थशास्त्रज्ञता का इसका एक मात्र कारण नहीं, है क्योंकि जिसकी आय अर्थशास्त्र अर्थ है, वे अधिक अर्थमूल भी हैं। उदाहरण के तौर पर अहमदाबाद जैसे शहर में जहाँ आय अर्थ है, अर्थ में काँट उमी नहीं है। मजदूरों के अर्थ सम्बंधी जो आर्थिक उपलब्ध हैं उनसे पता लगता है कि बम्बई में ६४१ प्रतिशत जलगाव में ६०७, प्रतिशत शोलापुर में ८५७, प्रतिशत कलकत्ते में ४१५, जमशेदपुर में ६४२, प्रतिशत और भरिया में २४३, परिवार कर्तदार हैं और औद्योगिक प्रति परिवार बम्बई में लगभग २२५ रु०, जलगाव में २९७ रु०, कलकत्ते में २१७ रु०, जमशेदपुर में २३५ रु० और भरिया में २८ रु० पाया गया। रींग कमटी का इस सम्बन्ध में यह कहना है कि मजदूर का बुरी और पतन एवं कल की आदत भी उत्तम कलदार होने का एक कारण है, पर मूल कारण उसकी अर्थशास्त्र आय ही है। जहाँ तक कि प्रयागव गवों का प्रश्न है, रींग कमटी का कहना है कि मजदूर को वे लक्ष्य करने ही पड़ेंगे और इसलिए अर्थ यह है कि उनकी सामने रखकर ही उसकी आय व बारे में निर्णय करना चाहिये। 'जीवर' पर मजदूर का निर्भरता का उगम अर्थ की समस्या को थोड़ा पचीदा बनाती है। रींग कमटी न तो यह भी लिखा है कि यदि मजदूर को अर्थ मुक्त करने के प्रयत्न किये जायें तो वे उसमें सहयोग देते हैं, यदि उनकी इसकी आवश्यकता अर्थ से समझने का प्रयत्न किया जाये। सरकारों राष्ट्र-समितियों व प्रचार, उचित शिक्षण और उचित कानूनी संरक्षण से इस समस्या का हल हो सकता यदि इस व साथ साथ मजदूरों की आय में आवश्यक वृद्धि करत व प्रयत्न भी किये जायें।

✓ भारतीय मजदूर की कार्य कुशलता — भारतीय औद्योगिक मजदूर व विषय में प्रायः यह कहा जाता रहा है कि दूसरे देशों के मजदूरों की अपेक्षा उसमें कार्य-कुशलता कम है। अन्तिम भारतीय उद्योगपति तो उसे कम वेतन देने का यही औचित्य उपस्थित करते हैं। भारतीय मजदूर की कार्य-कुशलता की कमी के बारे में अब तक जो कुछ कहा और लिखा जाता रहा है उससे भारतीय मजदूर के प्रति बहुत बड़ा अन्वेषण हुआ है। यदि हम मजदूर की कार्य कुशलता का अनुमान प्रति मजदूर होने वाले उत्पादन से लगाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें

यह ध्यान रखना चाहिये कि उत्पादन का परिणाम किन-किन बातों पर निर्भर रहता है। उसके लिये केवल मजदूर ही जिम्मेदार नहीं होता। जिन परिस्थितियों में मजदूर काम करता है, जिस तरह का सामान काम करने के लिये उसे मिलता है, जैसी मशीनों पर उसे काम करना पड़ता है, कारखाने में जैसी व्यवस्था है और जितना वेतन उसे मिलता है—इन सभी बातों का उत्पादन पर असर पड़ता है। फिर मजदूर का भी जहाँ तक सम्बन्ध आता है उसमें उसकी शिक्षा कैसी हुई है, उसको कैसा भोजन मिलता है, उसके रहने का कैसा मकान है, उसके मनोरंजन की क्या व्यवस्था है, बीमार पड़ने पर उसकी भिक्षिता की कैसी व्यवस्था है और उसके आस-पास का जीवन कैसा है—इन सब बातों का असर पड़ता है। अस्तु, अगर किसी की यह मान्यता हो कि उपर्युक्त सब बातों में भारतीय मजदूर और दूसरे देश के मजदूर की परिस्थिति में जो अन्तर है उसके लिए गुंजाइश होवने के बाद भी, भारतीय मजदूर में कुछ ऐसी प्रकृतिदत्त कमी है कि वह दूसरे देश के मजदूरों की अपेक्षा कम कार्य-कुशल है तो यह सर्वथा निराधार और अमोत्यावक बात है। सच पूछा जाए तो भारतीय मजदूर की कार्य-क्षमता के बारे में परीक्षण तो नहीं के बराबर ही हुए हैं और उसकी कार्य-कुशलता की कमी के बारे में जो उदाहरण अवतक दिये जाते रहे हैं, वे बिना उसकी परिस्थिति का ध्यान रखे केवल ऊपर ही ऊपर की बातों के आधार पर दिये जाते रहे हैं। कई उदाहरण तो मजदूरों के शोषण करने के लिए औचित्य स्थापित करने की दृष्टि से ही उद्योग-पतियों द्वारा दिये जाते हैं, जैसे-यह उदाहरण कि लंकाशायर की एक श्रमिक लड़की बस्त्र बुनने का छह भारतीय मजदूरों के बराबर काम कर सकती है। औद्योगिक कमीशन के सामने सर एलेक्जेंडर मैकरोवर्ट ने कहा था कि अंग्रेज मजदूर भारतीय मजदूर से चौगुना कार्य-कुशल है। सर विलमेट सिम्पसन का अनुमान था कि लंकाशायर मिल का एक मजदूर भारतीय मजदूर से २.६७ गुना कार्य-कुशल है। पर डा० मिलवर्ट स्लेटर का यह कहना है कि इस ठुलाना में भारतीय मजदूर की अक्षमता अतिरिक्त रूप में दिखाई गई है। एक कक्ष पर भारत और इंग्लैंड में कितने मजदूर काम करते हैं, केवल इसी पर से दोनों देशों के मजदूरों की कार्य-कुशलता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भारत में मजदूरी कम होने से अधिक मजदूर लाने में लाभ होता है जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। भारतीय मजदूर के बारे में सर टामस हाल्लैंड लिखते हैं “भारतीय मजदूर से किसी भी उद्योग में, जो इस देश में चल सकता है, काम लिया जा सकता है। मैंने जमशेदपुर में उन मजदूरों को देखा है जो कुछ वर्ष पहले जंगलों में रहते थे। अब वे लोहे और इस्पात के कारखानों में उत्ती योग्यता

परिच्छेद ५

मजदूर-कानून

ग्राज के औद्योगिक राणा के आर्थिक जीवन का यदि हम अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि उनमें अनका प्रकार के मजदूर-कानून मौजूद हैं। मजदूरों सम्बन्धी कानून का आवश्यकता इसलिए होती है कि देश का पूँजीपति-वर्ग अपने मात्कालिक स्वार्थों को बर्खास्त होकर मजदूर वर्ग का शोषण न कर सके, और मजदूरों का आर्थिक हित सुरक्षित रखा जा सके। जैम जैम मजदूर संगठन शक्ति शाली होता है, इस प्रकार के कानून आगामी म पाम होते जाते हैं, क्योंकि मजदूरों की संगठित शक्ति के सामने मजदूरों के हितों का अवलम्बना करना किसी भी सरकार के लिए समभव नहीं हो सकता। जो जनता के दश हैं वहाँ की सरकारों पर तो वैसे ही मजदूर वर्ग का, जो पर्याप्त संख्या में होता है प्रभाव होता है। जबकि अन्तराष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना हुई है, मजदूरों सम्बन्धी कानूनों की और भी अधिक प्रेरणादायी मिला है। भारत में भी प्रथम महासुद्ध के पश्चात् मजदूर कानून की ओर विशेष ध्यान गया है। अन्तराष्ट्रीय मजदूर संघ का भारत भी सदस्य है, अतः इसका भी असर मजदूर कानूनों की प्रस्तावना देना हुआ है। भारतीय मजदूरों में अपने अधिकारों के प्रति जो चेतना उत्पन्न हुई और मजदूर संगठन जैसे-जैसे शक्ति शाली बना, मजदूर कानूनों की माग देश में बढ़न लगी। १९३७ में जब प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारें स्थापित हुईं तो मजदूर-कानूनों के सम्बन्ध में विशेष प्रगति हुई। कई प्रान्त, जैसे बम्बई, संयुक्तप्रान्त (उत्तर प्रदेश) बिहार, मध्य प्रान्त में मजदूर कमेटीयों की नियुक्ति हुई। इन्होंने मजदूरों सम्बन्धी स्थिति की जानकारी की और उसमें सुधार के अनेक उपाय सुझाये। भारत सरकार ने भी मजदूर जाव कमेटी (रिगे कमेटी) की नियुक्ति की जिसने देश के मजदूरों के सम्बन्ध में गहरा अध्ययन किया और अनेकों रिपोर्टों में अपने इस अध्ययन का परिणाम प्रकाशित किया। इन सब बातों का असर मजदूर कानूनों पर भी पड़ा और पिछले वर्षों में इस दिशा में भारत में काफी प्रगति हुई है। देश की स्वाधीनता ने इस प्रगति के मार्ग को और भी अधिक प्रेरित कर दिया है। अब हम मुख्य मुख्य मजदूर-कानूनों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत करेंगे।

फेक्टरी एक्ट १९४८—भारत में प्रथम फेक्टरी एक्ट १८८१ में पास हुआ था। उसके बाद से फेक्टरी-कानून में कई बार परिवर्तन हो चुके हैं और

प्रत्येक नए कानून में पहले की अपेक्षा बहुत कुछ सुधार होता रहा है। इस समय जो कानून देश में लागू है वह १९४८ में पास हुआ था। इस १९४८ के फैक्टरी एक्ट की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं:—

क्षेत्र—यह एक्ट उन तमाम औद्योगिक कारखानों पर लागू होता है जहां यदि शक्ति का प्रयोग होता है तो दस या दस से अधिक और अन्यथा बीस या बीस से अधिक मजदूर काम करते हैं। राज्य की सरकारों को यह अधिकार है कि काम करने वालों की संख्या का अथवा शक्ति के उपयोग का ध्यान रखे बिना ही वे किसी भी कारखाने पर इस एक्ट को लागू कर सकते हैं। इस संबंध में एक अपवाद अवश्य है कि यदि किसी कारखाने में परिवार के सदस्यों के द्वारा ही काम होता है तो उस पर यह एक्ट लागू नहीं किया जा सकता। मौसमी और सातभर चलने वाले कारखानों में जो अब तक भेद था वह इस एक्ट में नहीं रहा है।

स्वास्थ्य, रक्षा और भलाई—इस एक्ट में मजदूरों के स्वास्थ्य-सम्बन्धी कई धाराएं हैं जिनका उद्देश्य है कारखाने में सफाई-उत्पादन-क्रिया के समय उत्पन्न होने वाली गंदगी को हटाना, शुद्ध हवा और उचित ताप मान का प्रवन्ध करना, गर्मियों में पीने के लिए ठंडे जल की व्यवस्था करना, कृत्रिम उपायों द्वारा पैदा की गई नमी की मात्रा को अत्यधिक न होने देना, प्रकाश, शौचगृह और पेशाब-घरों की व्यवस्था करना, भीड़ को रोकने का प्रवन्ध करना तथा धूमने के लिए जगह-जगह स्पिटून्स की व्यवस्था करना। भीड़ को रोकने के लिए एक्ट में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि एक्ट के लागू होने के पश्चात् जो फैक्टरी बनी हो उसमें प्रति मजदूर ५०० क्यूबिक फिट और दूसरी फैक्टरियों में ३५० क्यूबिक फिट कमसे कम स्थान होना चाहिये।

मजदूरों की रक्षा सम्बन्धी भी एक्ट में कई धाराएं हैं। जैसे मशीन के चारों ओर घेरा करना, जब मशीन चल रही हो और उसके चारों ओर घेरा न हो तो उस पर काम करने अथवा उसके निकट जाने पर रोक लगाना, स्तरताक मशीनों पर बालकों के काम करने पर प्रतिबन्ध लगाना, स्वचालित मशीनों के आस-पास पर्याप्त स्थान छोड़ना ताकि जब वे काम कर रही हों तो जगह की कमी के कारण कोई दुर्घटना न हो सके; नई मशीन को सुरक्षित रखने का दायित्व मिल-मालिक के साथ-साथ मशीन बेचने वाले पर भी डालना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका मजदूरों की रक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है और जो फैक्टरी एक्ट में समाविष्ट की गई हैं। इनके अलावा रक्षा संबंधी और भी धाराएं हैं। उत्पादन करते समय कई प्रकार की धूल पैदा होती है या ऐसी गैस आदि काम में आती

और हम मध्यम म ममाम आवश्यक पृष्ठताछ करने और रजिस्टर प्रादि रखन का भी उनका अधिकार है। भारत सरकार का फैक्टरी एक्ट को पालन करान का कोट कसब नहीं है, पर फिर भी उन्होंने मलाह प्राप्त करने का दृष्टि में जीप एक्साइजर फैक्टरीज का एक टफ़र स्थापित कर रखा है।

१९४८ का फैक्टरी एक्ट का एक विशेषता यह है कि जहाँ १९१४ के एक्ट में बहुत सी बातें राज्य की सरकारों पर, जिन्हें एक्ट का अंतिम नियम बनाने का अधिकार था लाइ दिया गया था। इस एक्ट में मजदूरों की स्वास्थ्य रक्षा और मलाह मध्यम कम से कम आवश्यकताओं का एक्ट में ही समावेश कर दिया गया है।

मध्यम और ममाम का अनिवार्य फैक्टरी कानून — १९१४ का फैक्टरी कानून उसी कारणों से लागू होना था जहाँ २० या उससे अधिक आदमा काम करने हैं और यांत्रिक शक्ति का (विजला, भाप, गैस) उपयोग होता हो। प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार अर्पण था कि वे ऐसे स्थानों पर भी यह एक्ट लागू कर दें जहाँ २० या उससे अधिक आदमा काम करते हैं फिर वहाँ यांत्रिक शक्ति का उपयोग होता हो या न होता हो। कई प्रान्तीय सरकारों ने अपने इस अधिकार का उपयोग भी किया। शाही मजदूर कमीशन (१९२६) ने यह सिफारिश की थी कि जिन कारखानों में यांत्रिक शक्ति का उपयोग नहीं होता है उन पर नियन्त्रण के लिए एक पृथक कानून ही बन जाना चाहिये। यद्यपि भारत सरकार ने इस मध्यम में कोई देशव्यापी कानून नहीं बनाया, पर मध्य प्रांत की सरकार ने १९३७ में और मद्रास सरकार ने १९४७ में इस प्रकार के कानून अवश्य बनाए। इन कानूनों का उद्देश्य उन फैक्टरीयों में जिनमें १९१४ का फैक्टरी एक्ट लागू नहीं होता था काम करनेवाले मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का नियन्त्रण करना था। मध्य प्रांत का कानून १९३४ के फैक्टरी एक्ट से बाहर के उन कारखानों में लागू होता है जिनमें ५० या उससे अधिक व्यक्ति काम करने हैं, और जहाँ बड़ी घनाता, लाल नैयार करना और चमड़ा कमाने का धंधा होता हो। सरकार को यह भी अधिकार है कि वह यह कानून दूसरे धंधों में भी लागू कर दे। मद्रास का कानून मध्य प्रांत के कानून की अपेक्षा अधिक विस्तृत और व्यापक है। यह कुछ ऐसे निश्चित धंधों और दस्तकारियों पर लागू होता है जहाँ १ या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं और जो १९१४ के फैक्टरी एक्ट के क्षेत्र के बाहर हैं। सरकार को यह अधिकार है कि वह इस कानून का क्षेत्र व्यापक कर दे। मध्य प्रांत के कानून में अधिक से अधिक एक दिन में काम के घण्टे प्रोदों के लिए १८, स्त्रियों के लिए ६ और

बालकों के लिए ७ निश्चित किये गये हैं और पांच घण्टे के लगातार काम के पश्चात् कम से कम आधे घण्टे का विश्राम आवश्यक है। १० वर्ष से कम आयु के बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता और १४ वर्ष की आयु तक वह बालक को श्रेणी में ही गिना जाता है। स्त्रियों और बालकों को किस समय काम पर लगाया जा सकता है इसका भी नियंत्रण किया गया है। साप्ताहिक अवकाश (होली डे) की भी एक्ट में व्यवस्था है। मद्रास एक्ट में काम के घण्टे दिन में अधिक से अधिक ६ और सप्ताह में ४८ तथा दिन भर में काम के कुल समय का विस्तार १० घण्टे निश्चित किया गया है। साप्ताहिक अवकाश की भी एक्ट में व्यवस्था है। बारह महीने की लगातार सेवा के पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति १२ दिन की छुट्टी ले सकता है। १२ दिन की बीमारी की और १२ दिन की आकस्मिक छुट्टी भी साल भर में हर एक व्यक्ति को मिल सकती है। स्वास्थ्य और रक्षा संबंधी धाराएँ भी एक्ट में दी गई हैं।

चूँकि १९४८ के फेवटरी एक्ट के अन्तर्गत उन कारखानों का समावेश भी हो गया है जहाँ यांत्रिक शक्ति का प्रयोग नहीं होता है और २० या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं, इसलिए अलग-अलग राज्यों में इस प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता अब नहीं रही है।

भारतीय खान कानून—भारतीय खान कानून सबसे पहले १९०१ में पास किया गया था। उसके पश्चात् १९२२ में एक नया कानून पास हुआ। इस कानून में भी कई बार संशोधन हो चुके हैं। शाही मजदूर कमीशन द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए १९३५ में इस कानून में काफी महत्वपूर्ण संशोधन किये गये। उसके पश्चात् भी कई बार इस कानून में संशोधन हो चुके हैं। इस समय जो कानून है उसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

(क) यह कानून सब खानों पर लागू होता है। 'खान' की कानून की परिभाषा भी दे दी गई है उसके अनुसार कोई भी खुदाई जो खनिज पदार्थ ढूँढने और प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाए खान की परिभाषा में आ जाती है।

(ख) जो व्यक्ति भूमि पर काम करते हैं वे दिन में अधिक से अधिक १० घण्टे और सप्ताह में अधिक से अधिक ५४ घण्टे काम कर सकते हैं। काम करने के कुल समय का विस्तार अधिक से अधिक १२ घण्टे निश्चित किया गया है जिसमें ६ घण्टे काम करने के पश्चात् एक घण्टा विश्राम का भी शामिल है। जो खान के अन्दर काम करते हैं उनके लिए साप्ताहिक काम के घण्टे तो इतने ही हैं जितने खान के ऊपर काम करनेवालों के लिए, पर दिन भर में काम के घण्टे और कुल

काम के समय वे विस्तार में अन्तर किया गया है और इन दोनों हाथों अधिकतम समय ६ घण्टे निश्चित किया गया है। को० भी व्यक्ति स्थान में स्नान मर में ६ घण्टे से अधिक काम नहीं कर सकता। जो व्यक्ति दुस्र भात और प्रबन्ध आदि का काम करते हैं उन पर उपर्युक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होते।

(ग) १५ वर्ष से कम आयु के बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता और १७ वर्ष से कम आयु वाला का भूमि के नाश तथा दशा में काम करने की इजाजत है और कि वे उसी लिए डाक्टरों आदि से योग्य टहाराये जायें।

(घ) स्त्रियों को गानों के अन्दर काम करने का मनाही ७ मार्च, १९१६ को दत्त नियम के अनुसार का गइ थी, और १ जुलाई १९३६ तक सब स्त्रियाँ खान के अन्दर काम करना बन्द कर दें यह आवश्यक था। परन्तु युद्ध के समय कायने का काम के कारण भारत सरकार ने अस्थायी रूप से स्त्रियों को खानों के अन्दर काम करने की फिर आशा दे दी। १ फरवरी १९४६ से यह आशा रद्द हो गई है और अब स्त्रियाँ को खानों के अन्दर काम करने की आज्ञा नहीं है।

(ङ) खान कागज में पाने के लिए यथयुक्त जल, चिम्टिया के साधन और उपयुक्त सफाई सम्बन्धी व्यवस्था करने के लिए आवश्यक धाराओं का समावेश किया गया है। खान के लिए पुराने और स्त्रियाँ के लिए अलग अलग प्रबंध करना अनिवार्य है। कागज के अनुसार सिगुण्ड के लिए भी व्यवस्था करना आवश्यक है।

(च) खान मजदूरों की सुरक्षा की दृष्टि से एस्ट के तत्वावधान में बहुत से नियम बनाए गए हैं।

(छ) इस एकट की पाबान कराने का निम्मा केन्द्रीय सरकार का है जो खानों का चीज इन्स्पेक्टर नियुक्त करती है और उसके अधीन और बहुत से निरीक्षक होते हैं। केन्द्रीय सरकार को नियमादि बनाने का भी अधिकार है। प्रमुख खान प्रदर्शों में खान मजदूर (महनिंग बोर्ड) स्थापित किये जा सकते हैं। इन मजदूरों में मजदूर, खान मालिक और सरकार तीनों के प्रतिनिधि होते हैं। इनका काम खानों सम्बन्धी नियम आदि बनाना तथा दूसरे मामलों में सरकार के आह्वान पर उनकी सहायता करना है।

खान सम्बन्धी कानून में और संशोधन करने की बात सरकार के विचार में थी। इस प्रश्न पर कोयले की खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति (इन्डस्ट्रियल कमिटी ऑन कोल माइनिंग) ने भी विचार किया था और कुछ सिफारिशों की थीं जो सरकार के विचाराय प्रस्तुत की गई थीं। उनके आधार पर कुछ संशोधनों

के साथ दिसम्बर १९४६ में खान-मज़दूरों सम्बन्धी बिल संसद में पेश किया जा चुका है।

बागों में काम करने वाले मज़दूरों सम्बन्धी कानून:—आसाम के चाय के बागों में प्रारम्भ से ही मज़दूरों के अभाव की समस्या रही। कानून की सहायता से इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया। सन् १८६३ से १९०१ तक इस सम्बन्ध में जो कानून पास हुए वे मज़दूरों की अपेक्षा बागों के मालिकों के स्वार्थों की अधिक रक्षा करने वाले थे। उन्होंने अनुवद (इंजेंचर्ड) मज़दूरों की एक ऐसी दूषित प्रथा को जन्म दिया जिसके अनुसार प्रसंविदा भंग (ब्रीच ऑफ कन्ट्रैक्ट) के अपराध में मज़दूरों को सज़ा दी जा सकती थी और बाग के मालिकों को उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार था। आखिरकार १९०१ में आसाम-मज़दूर और प्रवासी कानून पास किया गया। इसका उद्देश्य आसाम के बागों के लिए अनुवद मज़दूर की भर्ती का नियंत्रण करना था। १९०८ और १९१५ में इस कानून में संशोधन किये गये। इन कानूनों का एक लक्ष्य अनुवद मज़दूर-प्रणाली का अन्त करना था। पर वास्तव में इस प्रणाली का अन्त १९२६ में हुआ जबकि मज़दूर प्रसंविदा भंग कानून (वर्कमेन्स ब्रीच ऑफ कन्ट्रैक्ट एक्ट) रद्द कर दिया गया। शाही मज़दूर कमीशन ने भी आसाम के बागों के लिए मज़दूरों को भरती के प्रश्न पर विचार किया था और कई सुझाव भी प्रस्तुत किये। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही १९३२ में 'टीडिस्ट्रिक्टस एमोप्रेशन लेबर एक्ट' पास किया गया और १ अक्टूबर १९३३ से यह एक्ट लागू किया गया। यह एक्ट आसाम के बागों में काम करने वाले मज़दूरों की भरती और उन्हें आसाम भेजने के सम्बन्ध में है। चाय के बागों में मज़दूरों के काम करने की परिस्थिति का यह एक्ट नियंत्रण नहीं करता है। इस कानून की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं—

(क) राज्य की सरकारें केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में किसी भी क्षेत्र को नियंत्रित प्रवास-क्षेत्र (कन्ट्रोल्ड एमोप्रेशन एरिया) घोषित कर सकती हैं। इन क्षेत्रों से सहायता प्राप्त प्रवासी (एसिस्टेड एमोप्रेंट्स) लायसंस प्राप्त एजेन्टों के द्वारा ही, जो बाग के किसी मालिक की ओर से काम करता है, आसाम भेजे जा सकते हैं। वे उन्हीं निश्चित मार्गों से बिना पर एजेन्ट ने भोजन और ठहरने आदि की व्यवस्था कर रखी है आसाम भेजे जा सकते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार की अनुमति से राज्य की सरकारें किसी भी नियंत्रित प्रवास-क्षेत्र का या उसके किसी भाग को सीमित भर्ती क्षेत्र (रेस्ट्रिक्टेड रिक्रूटिंग एरिया) भी घोषित कर सकती हैं। इस क्षेत्र में लायसंस-प्राप्त

फोरवर्डिङ्ग एन्ड, या लायभेस प्राप्त भर्ती करने वाला, या बाग का सरदा ही, निम्ने पास नाच के बाग के मानिक का प्रमाणपत्र हो, किसी व्यक्ति के सहायता प्राप्त प्रणाम के तौर पर आसाम जाने के लिए सहायता दे सकता है।

(ग) १६ वर्ष से कम आयु के बालकों को आसाम जाने के लिए उर्भ दया से सहायता दी जा सकता है जबकि उनके साथ उनके माता पिता या अन्य भवधा तिन पर वे निर्भर हैं, हाँ। विवाहित स्त्रियों को, जो अपने पति के साथ रहते हैं, पति का अनुमति के बिना आसाम जाने की सहायता नहीं दी जा सकती।

(घ) प्रत्येक प्रवासियों मजदूर और उसका परिवार इसका अधिकारी है कि आसाम में तीन वर्ष काम कर लेने के पश्चात् धाय के बाग के रख पर बाग अपने घर भेज दिया जाय। विगत परिस्थिति में उसे जल्दी जाने का अधिकारी भी है। बाग ने मानिक को रेल आदि के किराये के अलावा बाग के दिनांक निवास-व्यय में दत्ता होता है।

(ङ) एकट से निश्चित कर्मियों को पोषण कराने का काम भारत-सरकार द्वारा नियुक्त 'कंट्रोलर ऑफ एम्प्लोयमेंट सर्वर' नाम के अधिकारी का है जिसका एक या अधिक सहायक का सहायता भी मिल सकती है। कंट्रोलर अपने दूध कामों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों का भर्ती और डाकी आपसी (रिपट्रिडिंग) पर भी निगरानी रखता है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, यह एकट बागों के मजदूरों के काम परिस्थितियों का नियंत्रण नहीं करता। इस प्रकार के एक कानून बनाने पर प्रश्न बाग सम्बन्धी औद्योगिक कमिटी न (जो जनवरी १९४७ में स्थापित) गई थी और जिसका काम बाग के मजदूरों सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करना और भारत सरकार का सलाह देना है) सामने है। बागों सम्बन्धी कानून एक ममविदा भी तैयार किया गया है और बागों सम्बन्धी औद्योगिक कमिटी अपने तीसरे अधिवेशन में (४५ नवम्बर १९४०) इस पर विचार किया। बागों सम्बन्धी समाम आवश्यक बागों का इस कानून में समावेश होगा, मजदूरों के काम के घटे, उनकी मलाह के काम जिनमें उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, मानव साम, नलपान गृह, शिशुगृह, पीने का पानी, मनोरंजन साधन आदि सभी बाग का समावेश हो जाता है, तथा उनके मरान की व्यवस्था। जहाँ तक मजदूरों का प्रश्न है वह इस कानून में नहीं आवेगा क्योंकि उसने लिए न्यूनतम मजदूरी एकट (१९४८) पहले से ही पास हो चुका है। फेक्टरीज—जो फेक्टरी कानून के अंतर्गत आती हैं—इस प्रस्तावित कानून क्षेत्र से बाहर रहेंगे।

भारतीय रेलवे एक्ट १८६०—रेलवे में काम करने वाले उन व्यक्तियों के अलावा जिन पर फेक्टरी एक्ट या सानो सम्बन्धी कानून लागू होता है, बाकी के लगभग सब लोगों पर भारतीय रेलवे एक्ट लागू होता है। यह एक्ट १८६० में संशोधित हुआ था। जिन लोगों पर यह एक्ट लागू होता है उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है—एक श्रेणी उन लोगों की है जिनका काम निरंतर चलता रहता है और बीच-बीच में रुकता नहीं है। दूसरी श्रेणी में वे लोग हैं जिनका काम रोक-टोक जाता है। इस एक्ट के अनुसार पहले श्रेणी के लोगों के काम के घंटे महीने के औसत के हिसाब से सप्ताह में ६० और दूसरी श्रेणी के लिए सप्ताह में ५५ निश्चित किये गए हैं। सब रेलवे कर्मचारियों को हर सप्ताह में इतवार के दिन से आरंभ करके कम से कम २४ घंटे का लगातार विश्राम मिलना आवश्यक है। विश्राम संबंधी यह नियम उपर्युक्त दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों और उन दूसरे लोगों पर, जिनके लिए सरकार ने विश्राम का कम समय निश्चित कर रखा है, लागू नहीं होता। विशेष परिस्थिति में सरकार को काम के घंटे और विश्राम सम्बन्धी नियमों से मुक्ति देने का भी अधिकार है। निर्धारित समय से अधिक काम करने पर सवाई मज़दूरी देना आवश्यक है। सरकार को इस एक्ट के अन्तर्गत नियम बनाने का भी अधिकार है और इन नियमों को 'रेलवे कर्मचारी काम के घंटों सम्बन्धी नियम' का नाम दिया गया है। एक्ट और नियम दोनों का सम्मिलित नाम 'अवर्स ऑव एम्प्लायमेंट रेगुलेशन' है।

सन् १८४६ से एक्ट के पालन कराने का काम प्रधान लेबर कमिश्नर (केन्द्रीय) और तीनों प्रदेशों के, जिनमें सारा देश बंटा हुआ है, प्रादेशिक लेबर कमिश्नरों को सौंपा हुआ है। इन पदाधिकारियों को रेलवे मज़दूर उपरवाइजर्स का नाम दिया गया है और लेबर इन्स्पेक्टर इनकी सहायता करते हैं।

अप्रैल १८४६ में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ की मांग पर भारत सरकार ने जस्टिस जी. एस. राज्याध्यक्ष को रेलवे कर्मचारियों को कुछ मांगों पर विचार करने के लिए निष्पक्ष नियुक्त किया। दैनिक वेतन पाने वाले और छोटे कर्मचारियों के काम के घंटे, विश्राम, अवकाश और उससे सम्बन्धी नियमों के बारे में कुछ मांगें थीं जिन पर विचार किया जाना था। श्री राज्याध्यक्ष ने अपना निर्णय मई १८४७ में दिया। भारत-सरकार ने उनकी काम के घंटों, विश्राम और अवकाश संबंधी [लीव रिज़र्व] संबंधी सिफारिशें १८ जून १८४८ से तीन महीने के लिए उन रेलवे कम्पनियों के संबंध में जो शिकायत में शामिल थीं, रीकार करवा लीं।

भारतीय ब्रिटिश पोत एक्ट [मर्चेण्ट शिपिंग एक्ट] १८२३—जहाजों पर काम करने वालों (भारतीयों) के काम की परिस्थितियों का निरूपण इस एक्ट के अनुसार होता है। इस एक्ट के मुख्य-मुख्य प्रावधान यहाँ दिये जाते हैं —

(क) इस एक्ट के अनुसार अंग्रेजी या विदेशी जहाज पर काम करने वाले लोगों का भर्ती जहाज के मालिक के द्वारा नौ अधिकारी [शिपिंग मास्टर] की उपस्थिति में एक्ट में वर्णित पद्धति के अनुसार की जाती है। भरती के समय प्रत्येक अंग्रेजी जहाज के मालिक और जहाज पर काम करना चाहने वाले में एक सविदा होता है। सविदा में यात्रा के विवरण, काम की शर्तें और मृति [वेज] आदि के बारे में धाराएँ होती हैं। पर ३०० टन से कम के घरेलू व्यापार के ब्रिटिश जहाजों पर काम करने वाला के साथ इस प्रकार का सविदा नहीं करना पड़ता है। विदेशी जहाज के मालिक को अगर किसी भारतीय बन्दरगाह पर विदेशी यात्रा के लिए कोई व्यक्ति भर्ती करना होता है तो उसके लिए भी इस प्रकार सविदा करना अनिवार्य है।

यह भी आवश्यक है कि विदेश जाने वाले ब्रिटिश जहाजों पर काम करने वालों को नौ अधिकारी के सामने हो कायमुक्त दिया जाय और कायमुक्ति का प्रमाणपत्र दिया जाय। प्रत्येक जहाज के मालिक को जहाज पर काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रमाणपत्र भी देना होता है जिसमें उसका नाम, रखा और सविदा की शर्तों का उल्लेख किया या नहीं इसका उल्लेख रहना है।

(ख) कुछ अपवादों को छोड़ कर बालकों को काम पर लगाने का एक्ट में मनाही है। १८ वर्ष से कम आयु के लड़कों को भारत में रजिस्टर्ड किताब में जहाज में कुछ निश्चित शर्तों का अभाव को छोड़ कर द्विगर्ग या स्टोकन काम नहीं दिया जा सकता।

(ग) एक्ट में जहाज पर काम करने वाले लोगों को समय पर भत्ता चुकाने, भत्ता चुकाने में निर्धारित समय से अधिक देर हो जाने पर उनके प्रति-पूर्ति करने, भत्ता चुकाने में से कटौती करने और समय से पहले सविदा समझ किये जाने पर भत्ता चुकाने सम्बन्धी बातों का भी उल्लेख रहना है।

(घ) जल तथा दूसरी आवश्यक वस्तुएँ मिलाने के समुचित प्रबंध, बीमार अथवा दुर्घटना के समय दवा और चिकित्सा की व्यवस्था और रहने के स्थान के विषय में भी एक्ट में आवश्यक प्रावधान (प्रोविजन) हैं।

(ङ) एक्ट में और प्रावधान भी हैं जिनका जहाज पर काम करने वालों को अनुशासन, डाँकी मृत्यु के पश्चात् उनकी संपत्ति के बारे में निर्णय, और आपत्ति

अस्त जहाज़ पर काम करने वालों की सहायता से सम्बन्ध रखते हैं।

(च) एक्ट के पालन करने का काम नौ-अधिकारियों (शिपिंग मास्टर्स) और उप-नौ-अधिकारियों का है। जहाँ नौ-कार्यालय (शिपिंग आफिस) नहीं होता वहाँ कस्टम्स कार्यालय को यह काम सौंपा जाता है। नौ-अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि जहाज़ पर काम करने वालों को नियुक्ति और वसंस्तगी के विषय में एक्ट के अनुसार कार्य होता है और समय पर वे जहाज़ पर उपस्थित हो जाते हैं, आदि मामलों की देख-रेख रखें।

(छ) इस एक्ट का १९४६ में जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार को भारत में बन्दरगाहों पर जहाज़ों पर काम करने वालों के एम्प्लायमेंट ऑफिसेशन स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। इनका काम मजदूरों की पूर्ति का उचित नियंत्रण करना होगा ताकि ऐसे मजदूरों की आवश्यकता से अधिक संख्या होने से सबको ही नम्बरवार काम मिलने की व्यवस्था की जा सके।

नौ निवेश (डाक्स) में काम करने वालों (सेवायुक्ति नियंत्रण) संबंधी एक्ट (१९४८)—नौनिवेश में काम करने वाले मजदूरों की एक प्रमुख समस्या यह रही है कि उनके काम में निश्चितता और नियमितता का अभाव है। इस समस्या का निराकरण करने की दृष्टि से ही उक्त कानून १९४८ में पास किया गया। इस एक्ट के अन्तर्गत बड़े-बड़े बन्दरगाहों के लिये भारत-सरकार को और दूसरे बन्दरगाहों के लिये राज्य की सरकारों को डाक-मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की योजना बनाने का अधिकार दिया गया है ताकि उनके काम में अधिक नियमितता लाई जा सके और उन्हें यह भी अधिकार दिया गया है कि वे सब डॉक मजदूरों के (रजिस्टर्ड हों या न हों) काम को और काम की शर्तों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने की योजना बना सकें। इस प्रकार जो भी योजना बनाई जाए उसमें मजदूरों की भर्ती के नियंत्रण सम्बन्धी और रजिस्ट्रेशन संबंधी व्यवस्था को अवश्य स्थान होना चाहिये। मजदूरों की दर, काम के घंटे, सवेतन अवकाश, दिन डॉक-मजदूरों पर योजना लागू नहीं होती उनको काम में लगाने सम्बन्धी रोक, मजदूरी अथवा नियन्त्रण, डॉक मजदूरों की शिक्षा और भलाई, उनके स्वास्थ्य और रक्षा की व्यवस्था, और योजना के अन्तर्गत आने वाले डॉक-मजदूरों को उस समय की जब उन्हें काम अथवा पूरा काम न मिले न्यूनतम मजदूरी देने संबंधी बातों का भी योजना में समावेश किया जाता है। एक्ट के अनुसार एक ऐसी सलाहकार समिति का निर्माण भी आवश्यक है जो डॉक-मजदूरों की समस्याओं के बारे में सरकार को सलाह दे सके। एक्ट का पालन कराने को दृष्टि से निरीक्षकों की नियुक्ति करना होता है।

* दुकानों में काम करनेवालों में सम्बन्धित कानून—इस विषय में सबसे पहले १९४० में बम्बई सरकार ने कानून बनाया। उसके बाद कई राज्यों में यह कानून पारित हुआ है जैसे पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मध्य प्रदेश आदि। बम्बई में १९४६ में एक नया कानून पारित किया है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने इसी कानून को अपना लिया है। भारत सरकार ने भी १९४२ में सामाजिक प्रवर्धन कानून पारित किया। यह उन्हीं राज्यों में लागू हो सकता है जहाँ की सरकारें उसे लागू करना की घोषणा करें। इन कानूनों का उद्देश्य दुकानों में काम करनेवाले लोगों के काम करने की परिस्थितियों का नियंत्रण करना है। इनकी मुख्य मुख्य बातें हैं —

(क) कुछ अवधारणों की छोड़कर यह कानून कुछ चुने हुए जगहों दुकानों, व्यापारिक स्थानों, जल पानगृहों और मनोरंजन के स्थानों पर लागू होता है। सरकार चाहे तो इनका और स्थानों पर भी लागू कर सकती है। जिस लोगों का काम खानपान बनाना है या जो ऐसा है कि उसे लगावार नहीं करना पड़ता, उन पर यह कानून लागू नहीं होता।

(ख) काम के घण्टे, विधान का समय, काम शुरू करने और बंद करने का समय और निर्धारित समय में अधिक कितने समय तक काम किया जा सकता है—इन सब बातों का भी इन कानूनों में उल्लेख है। दिन भर में काम के घण्टे ८ (उ.प्र. और मद्रास), ६ (बम्बई, मध्य प्रदेश, आसाम), या १० (पंजाब, प. बंगाल) निर्दिष्ट किए गए हैं। विधान का समय १ घण्टा (पू. बंगाल, उ.प्र., पंजाब) या १ घण्टा (आसाम, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश) निर्दिष्ट है। कहीं कहीं व्यापारिक स्थानों, जल-पानगृहों, और मनोरंजन के स्थानों में काम करने वालों के काम के घण्टों में अंतर भी है।

(ग) सामाजिक छुट्टी (होली व) करने का भी इन कानूनों में उल्लेख है, हालांकि कहीं कहीं, जैसे बम्बई या आसाम में, होटलों, थियेटर आदि को इस धारा से मुक्त रखा गया है। रियायती छुट्टी (लीव) की भी इन कानूनों में व्यवस्था की गई है। कहीं-कहीं आकस्मिक और वामापी की छुट्टी की व्यवस्था भी है।

(घ) बालकों की काम करने का न्यूनतम आयु १२ (आसाम, मध्य प्रदेश) और १४ (मद्रास, उत्तर प्रदेश) निर्दिष्ट की गई है और उनके काम के घण्टे ६ (बम्बई, उ.प्र.) या ७ (पंजाब, मद्रास, उत्तर प्रदेश) प्रतिदिन तय किये गए हैं। उत्तर प्रदेश में शाम को ७ बजे पश्चात् और मद्रास, बम्बई, और पंजाब में रात को ६ बजे पश्चात् बालकों के काम करने की मनाही है।

(ङ) बम्बई के कानून में सरकार को यह अधिकार है कि भारत सरकार

के न्यूनतम मज़दूरी क़ानून को दुकानों आदि पर लागू करदे। मज़दूरी जुकाने का समय कहीं-कहीं अधिक से अधिक १ महीना (मद्रास, उ. प्र.) और कहीं-कहीं अधिक से अधिक १५ दिन (पंजाब) निश्चित है। समय पूरा होने के बाद एक निश्चित समय के अन्दर-अन्दर, जो कहीं ५ (मद्रास), कहीं ७ (उ. प्र.) और कहीं १० दिन (आसाम) तक का है, मज़दूरी चुका देना आवश्यक है। निर्धारित समय से अधिक समय काम करने पर मज़दूरी की दर सवाई (बंगाल), बम्बई (बम्बई, म. प्र.), और दुगनी (मद्रास, उ. प्र., पंजाब) तक देनी होती है। मद्रास और उत्तर-प्रदेश के क़ानूनों में अर्ध दंड और मज़दूरी में से कटौती के बारे में भी प्रावधान हैं। काम से मुक्त करने के बारे में भी एक महीने (उ. प्र., पंजाब, मद्रास, म. प्र.) पूर्व सूचना या उसका बेटन देना आवश्यक है। बम्बई के क़ानून में १४ दिन का नोटिस या उतने समय का बेटन देना निश्चित है। मद्रास, और बम्बई के क़ानूनों में सफ़ाई, हवा, रोशनी और आग लगने पर उससे बचने के उपायों के सम्बन्ध में भी व्यवस्था है।

साप्ताहिक अवकाश (होली डे) क़ानून (१९४२)—यह क़ानून भारत-सरकार ने पास किया था और उन्हीं राज्यों में, जहाँ की सरकारों ने ऐसी घोषणा की हो, यह क़ानून लागू होता है। बिहार, अजमेर, कुर्ग, उड़ीसा में यह क़ानून लागू किया भी जा चुका है। जिन राज्यों में दुकानों आदि में काम करनेवाले लोगों के बारे में कोई अपना क़ानून नहीं है उन्हीं के लिए यह क़ानून है। इसके अनुसार सप्ताह में एक दिन दुकानें बन्द रखना आवश्यक है। राज्य की सरकारें यदि चाहें तो आधे दिन की छुट्टी और कर सकती हैं।

भारतीय नौनिवेश-मज़दूर क़ानून (१९३४)—यह क़ानून १९३४ में पास हुआ पर १० फरवरी १९४८ को लागू हुआ। इसका उद्देश्य नौनिवेशों में माल उतारने और चढ़ाने का काम करनेवाले मज़दूरों की दुर्घटनाओं से रक्षा करना है। इस क़ानून के अन्तर्गत जो रेगुलेशन बने हैं उनमें और बातों के साथ-साथ इन बातों की भी व्यवस्था की गई है:—काम करने के स्थानों और उन तक जाने वाले रास्तों की सुरक्षा; उनकी रोशनी और घेरे बन्दी; जहाजों तक आने-जाने के साधन; जल-मार्ग से मज़दूरों को जहाज तक सुरक्षित ढंग से आने जाने की व्यवस्था; मशीनों के सुरक्षित ढंग से काम करने की व्यवस्था; मशीनों को घेरा बन्दी; और दत्काल चिकित्सा के लिए आवश्यक साधनों, एम्बुलेंस और हवते हुए लोगों को बचाने के साधनों का प्रवन्व। एक्ट का पालन कराने के लिए राज्य की सरकारों द्वारा निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के लिए नौनिवेश-सुरक्षा-निरीक्षकों की नियुक्ति भी की गई है।

कायने की खान। सम्बन्धी मुरत्ता (स्टोयिंग) एक्ट—इस कानून का उद्देश्य एक एम्प कोयल का निर्माण करना है जिसमें से कोयले की खानों में से कोयला निकलवाना आसानी से हो सके। यह जो गड्डा रह जावे है उसको भरने में (स्टोयिंग) होने वाले खानों में सहायता का काम करता है। एक्ट में खानों के प्रवाह निराकरणानिरीक्षणों को यह अधिकार दिया गया है कि वे खानों में मालिक को खान के अन्दर स्टोयिंग या दूसरे स्थापना के नामक उपाय काम में लाने चाहिये इस विषय में उचित आदेश देंगे। इस एक्ट के अनुसार 'स्टोयिंग गेज' नाम का एक कर भी इस एक्ट के अनुसार लगाया जाना है जिसका आय एक कोयल में जाता है। इस कोयल की व्यवस्था का भार कोयल माइन स्टोयिंग बोर्ड पर है जिसका स्थापना इस एक्ट के अनुसार हुई है और नियम छह मदत है।

जायले और अवरक की खानों के महदूरों के हित सम्बन्धी कानून — 'कोयल माइन लेबर वेल्फेयर एक्ट' मई १८४७ में पास हुआ। इसके पहले ३१ जनवरी १८४४ को भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था और जब यह एक्ट पास हो गया तो उसने उस अध्यादेश का स्थान ले लिया। इस एक्ट का उद्देश्य कोयल की खानों में काम करने वाले मजदूरों की भलाई के कामों के लिए अधि प्रबंध करना है। एक्ट के अनुसार 'कोयल माइन लेबर हाउसिंग और जनरल वेल्फेयर एक्ट' की स्थापना की गई है। इस एक्ट के दो स्वतंत्र विभाग हैं—एक का नाम 'हाउसिंग अकाउन्ट' और दूसरे का 'जनरल वेल्फेयर अकाउन्ट' है। खानों में भेजे जाने वाले कोयले या कोयल के आधार पर एक्ट में एक उपकर (गस) लगाने की व्यवस्था की गई है और छह आने प्रति टन कोयला या कोयल के हिस्से से यह उपकर हम समय लगाया जाता है। इस एक्ट के द्वारा मजदूरों का भलाई के जो-जो काम किए जा रहे हैं उसका विवरण पहले दिया जा चुका है। एक्ट का संचालन भारत सरकार द्वारा होता है और एक सलाहकार समिति—जिसमें सरकार, खान-मालिक और खान मजदूरों के वरान-वरान प्रतिनिधि हैं—सरकार की सलाह देती है। एक 'कोयल माइन लेबर हाउसिंग बोर्ड' स्थापित करने की भी एक्ट में व्यवस्था है। इस बोर्ड का काम भारत सरकार की स्वीकृति से मजदूरों के लिए फंड से मकान बनाने की योजनाएँ तैयार करना और उनसे कार्यान्वित करना है। १८४८ में किए गये एक अधोपन के अनुसार हाउसिंग बोर्ड के नियंत्रण में वे दूसरे इमारतों के काम भी आगए हैं जो जनरल एक्ट में मजदूरों का भलाई के कामों के बारे में कराए जाते हैं, जैसे अस्पताल या मातृगृह बनाना आदि। भारत सरकार का एक कोयल माइन लेबर वेल्फेयर कमिशनर तथा अन्य आवश्यक

अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी अधिकार है।

अवरक की खान-मजदूरों के लिए भी 'माइका माइन्स लेबर वेल्फेयर फंड एक्ट' १९४७ के अन्तर्गत एक फंड स्थापित किया गया है। भारत से निर्यात होने वाले अवरक पर उसके मूल्य के आधार पर निराक्रम्य (कस्टम) कर लगाने का भारत-सरकार को इस एक्ट से अनुसार अधिकार है। कर की अधिक से अधिक दर ६.५ प्रतिशत निश्चित की गई है और इसी कर की आय से फंड का निर्माण किया गया है। दो सलाहकार समितियों की नियुक्ति भी एक्ट के अनुसार की जा सकती है। एक समिति विहार के और दूसरी मद्रास के लिए है। फंड के काम के विषय में पहले लिखा जा चुका है।

पेमेन्ट आवेजेज एक्ट १९३६—इस कानून का उद्देश्य यह है कि मजदूरों को सनय पर वेतन मिल सके और उसमें से मन-माने तौर पर कटौती न की जा सके। यह कानून आरंभ में फ़ैक्टरियों और रेलों में ही लागू किया गया, पर राज्य की सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे इसे दूसरे धंधों और उद्योगों में भी लागू कर सकते हैं। कोयले की खानों के अलावा दूसरी खानों में भी यह कानून लागू कर दिया गया है। भारत-सरकार की राज्य-पत्र में प्रकाशित एक सूचना के द्वारा यह कानून कोयले की खानों में लागू कर दिया गया है। मद्रास, पंजाब, उत्तरी प्रदेश, विहार, उड़ीसा, दिल्ली, कुर्ग और पश्चिमी बंगाल में यह कानून दूसरे उद्योगों—जैसे बागों, मोटर-सर्विस आदि में भी लागू किया गया है। इस कानून के अन्तर्गत वही लोग आते हैं जो २००) मासिक से कम पाते हैं।

कानून में 'वेलेज' शब्द की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार बोनस भी इसके अन्तर्गत आ जाता है परन्तु यात्रा-भत्ता, प्रोविडेन्ट फंड में दी जाने वाली सहायता आदि की गिनती 'वेलेज' में नहीं की जाती।

वेतन का समय एक महीने से अधिक नहीं हो सकता, और वेतन नकद रुपयों या नोट में ही (धस्तुओं में नहीं) चुकाया जाना चाहिये। जहाँ एक हजार व्यक्तियों से कम काम करते हैं वहाँ वेतन का समय होने के ७ दिन के अन्दर-अन्दर और जहाँ एक हजार से अधिक व्यक्ति काम करते हों वहाँ १० दिन के अन्दर-अन्दर सबको वेतन मिल जाना चाहिये। जो व्यक्ति नौकरी से अलग कर दिया गया हो उसको निकाले जाने के दूसरे दिन तक उसका वेतन अवश्य मिल जाना चाहिये। वेतन छुट्टी के दिन नहीं वांटा जा सकता।

कानून द्वारा जो कटौती स्वीकृत है (जैसे बुर्माना, गैरहाजरी के कारण कटौतरी, मकान का किराया, आय-कर, प्रोविडेन्ट फंड की किरत,

अदालतों तथा जो दाना हो, मालिकों ने जो रुपया पेशगी दे दिया हो, सरकारी समिति का कर्न और अन्य कोई सुविधा के कारण कटौतरी जो कि मालिक द्वारा मजदूर को पहुँचावे) उसका अतिरिक्त वेतन में से और अधिक कटौती नहीं हो सकती । नहा तक तुर्माने का मकसद है, कानून द्वारा उसका इस प्रकार नियंत्रण किया गया है—मालिकों पर तुर्माना नहा हो सकता, तुर्माने की रकम कितनी हो या तुर्माना करने के ६० पिन ताद वसूला नहीं की जा सकती, किसी भी महीने में मजदूरों ने जो वेतन प्राप्त किया है उसपर आधार आना प्रति रुपया से अधिक तुर्माना नही किया जा सकता, तुर्माने में जो रुपया इकट्ठा हो वह मजदूरों के हित के किसी काम पर हो व्यवस्था किया जा सकता है जिसकी स्वीकृति मालिकों को सरकार में लेना आवश्यक है, जिस दोर में कीमा तुर्माना हुआ है उसकी सूचा मालिक का नोटिस बोर्ड पर लगाना चाहिये, मजदूर को तुर्माने के बारे में सफाई देने का अधिकार होना चाहिये और तुर्माना एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिये । कानून का अमल करना करने पर दण्ड का विधान किया गया है ।

फेक्टोरिया ग फेक्टरी निरन्तरिक कानून का पालन कराते हैं । रेलवे तथा दूसरे पथों के लिए अलग में इन्सपेक्टर नियुक्त किए जा सकते हैं । इस समय भारत सरकार का प्रधान लेबर कमिशनर पर रेलवे और खानों में इस कानून के पालन कराने का दायित्व है । दूसरे शब्दों में भी इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था है ।

न्यूनतम मजदूरी कानून १९४८—इस एक्ट का उद्देश्य जिन धंधों पर यह लागू किया जाए उनमें मजदूर को कम से कम अनुकूल मजदूरी तो अवश्य ही मिले, इसका निश्चय करना है । एक्ट में केन्द्रीय अथवा राज्य की सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुकूल समय तक एक्ट के परिशिष्ट में जिन उद्योगों का नाम है उनमें (पहलमय सेती के लिए तीन वर्ष (मार्च १९५१) का और अन्य उद्योगों के लिए दो वर्ष (मार्च १९५०) का था । पर बाद में उद्योगों के लिए एक वर्ष का समय (१९५१ मार्च) इसलिये बढ़ाना कहा कि अधिकांश राज्यों में एक्ट के अनुसार कार्य नहीं हो सका था । अब फिर यह समय मार्च १९५२ तक बढ़ा दिया गया है ।) काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित करदे । पर यदि राज्य भर में किसी धंधे में १००० से कम काम करने वाले हैं तो उसमें न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना आवश्यक नहीं है । परिशिष्ट में जिन धंधों का नाम दिया गया है वे ये हैं—ऊनी मालीचा तैयार करने का धंधा, शाल बुनने का धंधा, चावल, आटा या दाल का चक्की, तम्बाकू बनाने और बीड़ी का धंधा, बाग, तेल की

मिलें, किसी स्थायक शासन संस्था द्वारा चलाये जाने वाला काम, सड़क या इमारत का काम, पत्थर तोड़ने का काम, लाख का धंधा, अवरक का धंधा, सार्वजनिक मोटर-वातावात, चमड़े कमाने का तथा चमड़े का धंधा, और खेती। सरकार को यह अधिकार है कि यदि वह किसी और भी धंधे में यह कानून लागू करना आवश्यक समझे तो कर सकती है।

कानून में निम्न प्रकार की मज़दूरी तय करने की व्यवस्था की गई है— न्यूनतम समय-दर, न्यूनतम कार्य-दर, प्रत्याभूत (गारण्टीड) समय-दर, और अतिरिक्त समय-दर। इस कानून में यह भी कहा गया है कि मज़दूरी नकद में हो चुकानी होगी, यद्यपि सरकार को इसमें अपवाद करने का अधिकार है।

एक्ट के अन्तर्गत सरकार को समितियाँ और उपसमितियाँ नियुक्त करने का अधिकार भी है जिनका काम सरकार को न्यूनतम मज़दूरी निश्चित करने के संबंध में आवश्यक जांच के बाद सलाह देना है। इस प्रकार निश्चित मज़दूरी में परिवर्तन करने के लिए सलाह देने के वास्ते सरकार को सलाहकार समितियाँ अथवा उपसमितियाँ नियुक्त करने का और इन समस्त समितियों, उपसमितियों, सलाहकार समितियों और उपसमितियों के कार्य में समन्वय करने की और साधारण रूप से सलाह देने की दृष्टि से एक सलाहकार-मंडल (बोर्ड) नियुक्त करने का भी अधिकार है। केन्द्रीय और राज्य की सरकारों को सलाह देने और प्रांतीय सलाहकार-मंडलों में समन्वय करने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार मंडल की नियुक्ति करने का भी भारत-सरकार को अधिकार है। उल्लिखित तमाम समितियों और मंडलों में सरकार, मालिक और मज़दूरों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि होना आवश्यक है। जिन धंधों में यह एक्ट लागू किया जाए उनमें दिन भर में काम के घंटे, सप्ताह में एक छुट्टी और अतिरिक्त समय के काम के लिए मज़दूरी आदि का निश्चय करने का भी सरकार को अधिकार है।

निश्चित पद्धति के अनुसार रजिस्टर आदि रखने, और इन्स्पेक्टर आदि की नियुक्ति करने का भी कानून में उल्लेख किया गया है।

राज्य की सरकारों के मार्ग दर्शन के लिए केन्द्रीय सरकार ने नियम बना लिए हैं। केन्द्रीय सलाहकार-बोर्ड की कार्यपद्धति और निर्माणसम्बन्धी नियम भी बन चुके हैं। इन नियमों के अनुसार केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना भी हो चुकी है। भारत-सरकार और कई राज्य की सरकारों ने कानून के अनुसार एक्ट के अन्तर्गत आनेवाले उद्योगों में काम करनेवाले लोगों के रहन-सहन के खर्च सम्बन्धी जानकारी इकट्ठी करने के लिए कमेटियाँ आदि बनवाई हैं। पर फिर भी सभी राज्यों में अभी तक मज़दूरी निश्चित करने सम्बन्धी आवश्यक

प्रवस्था नहीं हो सकी है। यही कारण है कि पैसा ऊपर लिखा जा चुका है मजदूरी निश्चित करने का समय ठा आगमि मजदूरी के लिए जो एक्ट के अन्तर्गत आते हैं, मात्र १८५० तक बढ़ा दिया गया है। अभी तक कुछ राज्यों में ही न्यूनतम मजदूरी निश्चित हुई है। तब तक गतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है एक्ट के अन्तर्गत उनका न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने का समय भी बढ़ा दिया गया है और राधा का इस बार में आवश्यक स्वतन्त्रता देना आवश्यक समझा जा रहा है। अतः, इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन किया जायगा। अब तक केवल कच्छ में गतिहर मजदूरों का मजदूरी निश्चित की गई है। और कई राज्यों ने एसा करने का इच्छा प्रकट की है।

मजदूर संहिता पूर्ण कानून, १९०३—यह कानून १ जुलाई, १९२४ को लागू हुआ था। उसका इत्तम ४ बार संशोधन हो चुके हैं। शाही मजदूर कमीशन का सिफारिशों का आधानित करने के लिए १९३३ में एक संशोधन कानून पास किया गया था। उन परन्तु भी इस कानून में कई बार संशोधन हो चुके हैं। इस कानून के मुख्य-मुख्य प्रावधान नीचे दिये गये हैं—

(क) यह कानून उन तमाम लोगों पर, जो दफ्तर में या प्रत्यक्ष सम्बन्धी काम करते हैं या मिलकी (रेलवे कमचारियों के अलावा निम्न पर मासिक आय की मर्यादा लागू नहीं होती) मासिक आय ४०० रु० से अधिक है, लागू नहीं होता। माटे तौर पर वधों का दृष्टि से इस कानून के अन्तर्गत रेलवे, बैंकटारिया, आने, नौमिषेय (डॉक्टर) कुछ खास इमारती काम, सफाई, पुन, बाध आदि का काम, वार और प्लानिंग लाइन सम्बन्धी काम, वाता (चाय आदि के), विज्ञानी अथवा गैस पैदा करनेवाले स्टेशन, खुदाई का काम, आग बुझाने का काम, जहाज पर होनेवाला काम जैसे—जहाज में मांस लादने, जहाज से मांस उतारने, जहाज की मरम्मत करने, साफ करने या रंग करने आदि कामों का समावेष होता है। राज्य का सरकारों को यह अधिकार है कि वे इस कानून को उन लोगों पर भी, जो आज तक उसके बाहर हैं, लागू कर दें यदि उनका काम जोखिम भरा समझा जा सके। बैंकटारिया के बाहर में स्थान देने की बात यह भी है कि यह कानून या तो बड़ा लागू होता है जहां १० आदमी से अधिक काम करते हों और यात्रिक शक्ति का उपयोग होता हो, या यदि यात्रिक शक्ति का उपयोग नहीं होना है तो जहां ५० से अधिक आदमी काम करते हों। जो व्यक्ति 'एम्प्लोईज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, १९४८' के अन्तर्गत आता है और उसके अनुसार लाभ पाने का अधिकारी है वह इस कानून के अन्तर्गत लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।

(ख) सति पूर्ति का किसी व्यक्ति को जो इस कानून के अन्तर्गत आता है

उसी समय अधिकार है जबकि उसके चोट काम करते समय अथवा उसके फल स्वरूप लगे। परन्तु यदि चोट इस तरह की है कि जिसकी वजह से ७ दिन से अधिक समय के लिये कोई असमर्थ नहीं होता या फिर ऐसी चोट है, जिसका परिणाम मृत्यु नहीं होता, और जिसके लगने में मज़दूर का स्वयं का दोष है तो मज़दूर को क्षति-पूर्ति का कोई अधिकार नहीं रहता। शारीरिक चोट के अतिरिक्त कुछ धन्वे से उत्पन्न बीमारियों के होने पर भी क्षति-पूर्ति मिलती है। ये बीमारियाँ एक परिशिष्ट में दे दी गई हैं। राज्य की सरकारों को यह अधिकार है कि वह बीमारियों की इस सूची में कोई नई बीमारी और जोड़ें। क्षति-पूर्ति करने का दायित्व कानून के अनुसार मालिक का है।

(ग) क्षति-पूर्ति की मात्रा का निर्णय दुर्घटना कैसी है और मज़दूर की मालिक आय क्या है—इन दो बातों से निर्णित होती है। क्षति-पूर्ति मृत्यु, स्थायी पूर्ण असमर्थता, स्थायी अपूर्ण असमर्थता, और अस्थायी असमर्थता होने पर मिलती है। किसी मज़दूर की मृत्यु होने पर क्षति-पूर्ति का रकम उसकी स्त्री, नाबालिग पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा माता या कुछ ऐसे दूसरे व्यक्तियों को जो उस पर आश्रित थे, मिलेगा। दुर्घटना से मृत्यु हो जाने की हालत में वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन के कमिश्नर के पास सूचना अवश्य भेजी जानी चाहिये। यदि मालिक अपना जिम्मा स्वीकार कर लेता है तब तो क्षति-पूर्ति का रकम कमिश्नर के पास जमा हो जाना चाहिये। यदि मालिक अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता तो कमिश्नर का यह काम है कि आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद आश्रितों को वह यह सूचना दे दे कि वे चाहें तो क्षतिपूर्ति की मांग रख सकते हैं। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि मालिक और मज़दूर दुर्घटना होने पर दी जाने वाली रकम के सम्बन्ध में आपस में कोई ऐसा समझौता कर लें जिससे कि मज़दूर अपने क्षति-पूर्ति का अधिकार छोड़ दें। किसी भी दुर्घटना के होते ही मालिक के पास तुरन्त ही रिपोर्ट पहुँचाना चाहिये। ऐसा नहीं होने की हालत में कमिश्नर क्षति-पूर्ति सम्बन्धी मांग को सुनेगा नहीं।

(घ) एकट के पालन करके का जिम्मा राज्यों पर ही है और इस काम के लिए राज्य की सरकारों को कमिश्नर नियुक्त करने का अधिकार है। कमिश्नरों का काम विवादग्रस्त दावों का फैसला करना, और मृत्यु हो जाने पर क्षति-पूर्ति का रकम बांटना है। कई राज्यों में—जैसे बंबई, मद्रास और पश्चिमी बंगाल में—कमिश्नरों की नियुक्ति हो चुकी है। दूसरी जगह किन्हीं दूसरे अधिकारियों को यह काम सौंपा गया है।

एम्प्लोइय स्टेट इन्श्योरेंस एक्ट १९४८—यह एक्ट अप्रैल १९४८ में

पास हुआ था। उसकी मुख्य मुख्य बातें ये हैं—

(क) यह कानून सब फक्टरियों पर, निम्न सरकार की फक्टरिया भी शामिल हैं लागू होता है। मौसमी फक्टरिया एक्ट के अर्तगत नहीं आती। य तमाम कमचारी जो एक फक्टरिया में काम करते हैं (उनको छोड़ कर जितना ४०० से अधिक मालिकों की वेतन अथवा मजदूरी से आवे है) फिर चाहे उनकी नियुक्ति मौसमीर में मजदूराने के प्रथम विभाग द्वारा हुई हो या किसी के द्वारा उस एक्ट के अन्तगत आते हैं। कलर लाग भी एक्ट के अन्तर्गत बाहर नहीं हैं। चित्त लोगो पर यह एक्ट लागू होता है उनका सबका काम कराने का व्यवस्था है। एक एम्प्लोइंग एन्ड इन्सुरेंस बिल के निर्माण का व्यवस्था भी की गई है। उस बिल का निर्माण मिल मालिक, मजदूर और सरकार से प्राप्त होना चाहते रूप से किया जायगा। उस अलावा सरकारों और व्यक्तियों से चला आगे भी आ सकता है। केन्द्रिय सरकार पहले पान बरों में कॉरपोरेशन का नियन्त्रण व्यवस्था सबका रखे हागा उनका दो निश्चय वार्षिक सहायता के नीचे पर देती रहेगी। मिल मालिक और कमचारी दोनों के ही हिस्से का अपना चुकाने का निम्मा मिल मालिक का हा है। यदि किसी कमचारी ने पूरे सप्ताह भर काम न किया हो और जिसकी मजदूरी नहीं मिलने वाली हो तो उस सप्ताह का कटौती पूषन का कपवा कपल नहीं हागा।

जाने निम्न लाभ इस एक्ट के अन्तगत कमचारियों को मिल सकते हैं— बीमारी लाभ मातृत्व लाभ असमयता लाभ, आधितों का लाभ, और चिकित्सा लाभ। कमचारियों अथवा उनके आधितों का पैसा भी हो, उपर्युक्त लाभ किसी शर्तों के साथ मिलाने की व्यवस्था है। यदि कोई कमचारी जितना एक के अन्तर्गत बीमा हुआ है बीमार पड़ जाय तो उसे दैनिक मजदूरी के आध के हिसाब से बीमारी के दिना में आर्थिक सहायता मिल सकेगी। साल भर में अधिक से अधिक ५६ दिन के लिए यह लाभ मिल सकता है और बीमार होने के पहले दो दिन का लाभ नहीं मिल सकता जब तक कि १५ दिन में ही दूसरी बार कमचारी बीमार न पड़ जाय। इस प्रकार बारह आने प्रतिदिन के हिसाब से १२ सप्ताह का मातृत्व लाभ भी मिल सकता है जिसमें ६ सप्ताह से अधिक समय बचा होने से पहले का नहीं हाना चाहिये। इसी तरह असमयता यदि अस्थायी है तो दैनिक मजदूरी के आधे के हिसाब से यदि असमयता आधिक और स्थायी है तो दैनिक मजदूरी के आध के एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से, (जो मजदूर क्षतिपूर्ति कानून के अनुसार होगा) और यदि असमयता पूर्ण और स्थायी है तो दैनिक मजदूरी का आधा जावन भर मिलेगा। कमचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके

आश्रितों को एक निश्चित आधार पर रुपया मिलेगा। कर्मचारियों को मुक्त चिकित्सा का लाभ मिलने की व्यवस्था भी की गई है। यह लाभ कर्मचारियों के परिवार वालों को भी कोरपोरेशन चाहे तो दे सकता है। जिस व्यक्ति को इस कानून के अन्तर्गत लाभ मिलेगा उसे वही लाभ और किसी कानून के अन्तर्गत नहीं मिल सकेगा। योजना के संचालन करने के लिए एक्ट के अनुसार 'एम्प्लोइज स्टेट इन्श्योरेंस कोरपोरेशन' उसकी स्थायी समिति और कोरपोरेशन को सलाह देने के लिए मेडिकल बेनिफिट कौंसिल की स्थापना हो चुकी है। इन तीनों संगठनों में मिल-मालिक, कर्मचारी, डाक्टर, सरकार और संसद के प्रतिनिधि हैं।

उपयुक्त कानून १९४८ में पास हुआ था परन्तु वह आज तक भी लागू नहीं हो सका है। कुछ समय तो कानून लागू करने के पहले की आवश्यक तैयारी में लगा। जुलाई १९५० से दिल्ली और कानपुर में प्रयोग के तौर पर इस कानून को लागू करने का निश्चय किया गया था। पर इन स्थानों के मिल-मालिकों ने इस आधार पर विरोध किया कि इस कानून के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा की योजना केवल इन दो स्थानों पर लागू करने से जो जहाँ के मिल-मालिकों पर इसके फट्ट में रुपया (लेवी) देने से आर्थिक भार पड़ेगा उसके कारण बाजार में उनका माल औरों की अपेक्षा महंगा होगा और दूसरों की प्रतिस्पर्धा में उनको हानि होगी। अतः, भारत-सरकार इस कानून में अब (मार्च १९५१) इस आशय का संशोधन करना चाहती है कि जिससे कोरपोरेशन द्वारा दिल्ली और कानपुर के अलावा जहाँ कि प्रयोग के तौर पर यह योजना लागू की जायगी देश के दूसरे सब सेवा-योजकों (एम्प्लॉयर) से भी कम दर पर लेवी ली जा सकेगी। कानपुर और दिल्ली के सेवायोजकों से उनके द्वारा जुलाई जाने वाली कुल मजदूरी का १.३% और दूसरे स्थानों के सेवायोजकों से ३% लेवी के रूप लेने का विचार है। इन दूसरे स्थानों के मजदूरों से उनके हिस्से का रुपया तभी लिया जायगा जब उन स्थानों में योजना लागू होगी। पर दिल्ली और कानपुर के मजदूरों को तो अपना हिस्से का रुपया देना ही होगा। उक्त संशोधन हो जाने के बाद ही स्वास्थ्य बीमा की योजना दिल्ली और कानपुर में लागू की जायगी। कोरपोरेशन और मद्रास सरकार में भी योजना लागू करने के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है।

फॉल माइंस प्रोविडेंट फण्ड और चोनस स्कीम्स एक्ट, १९४८—इस एक्ट में केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि कोयले की खानों में काम करनेवाले मजदूरों के लिए वह चोनस और प्रोविडेंट फण्ड की योजना तैयार करे। ये दोनों ही योजनाएँ लागू होगई हैं। इनमें तमाम आवश्यक बातों

का समावेश किया गया है—किन्तु धर्मचारियों पर ये योजनाएँ लागू होती हैं, प्रोविडेंट फंड में मालिकों की ओर का कर्तव्यपूर्ण कर्मा होना, वह किस तरह दिया जायगा, किस दर से दिया जायगा, किस समय दिया जायगा आदि। इस प्रकार बोनस किन शर्तों पर मिलेगा किम दर से मिलेगा, बोनस का हिस्सा कैसा लगाया जायगा, किस समय और किस प्रकार बोनस मिलेगा, और किन परिस्थितियों में बोनस देना रोखा जा सकता है—य सब बातें भी योजना के अन्तर्गत हैं।

मानव्य लाभ कानून—मानव्य लाभ सन् ३१ जून तकसे पहले वर्ष, सरकार ने १९२० में पास किया था। उससे बाद १९३१ में मध्य प्रदेश ने यह कानून पास किया। शाही मजदूर कमीशन की जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो इस सम्बन्ध में कमीशन ने जो राय दी थी वह भी सामने आई। इस सम्बन्ध में शाही कमीशन ने जो सिफारिशों का उनके परिणामस्वरूप का रायों में मानव्य लाभ कानून पास किया गया। मद्रास, आसाम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आगरा, दिल्ली और पश्चिमी बंगाल में अपने-अपने मानव्य लाभ कानून इस समय लागू हैं। मुख्य सिद्धान्त इन सब कानूनों में समान हैं। आसाम का कानून फैक्टरियों और बागों दोनों में और बंगाल का कानून चाय के बागों में लागू होता है। बाकियों के सब कानून फैक्टरियों में ही लागू हैं। भारत सरकार ने भी एक माइंस मटराइट्री बेनिफिट एक्ट १९४१ में पास किया। बाद में इसमें थोड़ा बहुत संशोधन भी हुआ है। इन विभिन्न कानूनों में आधारभूत सिद्धान्त तो एक से हैं। कैमिया होना के पहले और बाद में एक निश्चित समय के लिए, या छह सप्ताह या छह सप्ताह के आस पास होता है, नकद सहायता दी जाती है। सहायता की यह दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है—आसाम के बागों में बच्चा हान के पहले १ रु० प्रति सप्ताह और बाद में १ रु० ४ आ० प्रति सप्ताह, तथा दूसरे उद्योगों में औसत मासाहिक आय या कम से कम ० रु० सप्ताह, बंगाल में औसत दैनिक आय या आठ आन प्रतिदिन जो भी अधिक हो, पर चाय के बागों और फैक्टरियों में ५ रु० ४ आ० प्रति सप्ताह, पंजाब में औसत दैनिक आय या १२ आ० प्रतिदिन जो भी अधिक हो, उत्तर प्रदेश और बिहार में आठ आन प्रतिदिन या औसत दैनिक आय जो भी अधिक हो, मद्रास राज्य तथा अहमदाबाद और बम्बई शहर में आठ आना प्रतिदिन और अन्य राज्यों में आठ आना या औसत दैनिक आय प्रतिदिन जो भी अधिक हो तथा कन्द्रीय एक्ट में १२ आ० प्रतिदिन के हिसाब से सहायता दी जाती है वहीं-वहीं अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था भी है जो कि बोनस का शकल में

जा सकती है यदि स्त्री किसी प्रमाणित नर्म आदि की सेवाओं का उपयोग करती है। यह बोमस ३ रु० से (माइन्स मेटरनिटी बनिफिट एक्ट) ५ रु० (उत्तर प्रदेश और बिहार) तक है। आसाम और पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक स्त्री गर्भावस्था, वच्चा पैदा होने के समय और बाद में चिकित्सा और डाक्टरी देख-भाल की अधिकारी है। वच्चा होने के बाद और यदि दुधना दी जाय तो वच्चा होने के पहिले विश्राम का अवकाश भी दिया जाता है। सब कानूनों में मातृत्व लाभ मिलने के लिए यह आवश्यक है कि लाभ पाने वाली स्त्री एक निश्चित समय तक उस कारखाने में काम कर चुकी हो जहां से उसे सहायता मिलेगी। यह काम का समय केन्द्रीय और उत्तर प्रदेश के कानून में छह महीने और अजमेर-मेरवाड़ा में एक वर्ष और दूसरे कां कानूनों में ६ महीने का निश्चित है। यदि कोई मिल-मालिक अपने हउ जिम्मे से बचने के लिए किसी स्त्री मजदूर को बर्खास्त करना चाहे तो कानून में स्त्री की इससे रक्षा करने की व्यवस्था है। मातृत्व अवकाश के समय किसी स्त्री को काम से अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री को किसी मिल-मालिक से मातृत्व लाभ मिल रहा है तो यह किसी दूसरी जगह काम नहीं कर सकती। ऐसा यदि करती है तो वह वयस की भागी होगी। फेक्टरी-निरीक्षक ही सब राज्यों में इन कानून का पालन कराने के लिए जिम्मेदार हैं। केन्द्रीय माइन्स मेटरनिटी बनिफिट एक्ट के पालन कराने का खागों के प्रधान इन्स्पेक्टर पर जिम्मा है।

बालक संरक्षक कानून [चिल्डरन (प्लेजिंग आब लेबर) एक्ट १९३३]—यह एक्ट एक विशेष कुरीति को रोकने के लिए पास किया गया है। शाही मजदूर कमीशन की जांच के समय यह ज्ञात हुआ कि बहुत से माता-पिता अपने बालकों के भ्रम को मालिकों के पास बंदक रख देते हैं। इस कानून के अनुसार इस प्रकार का कोई भी सौदा—चाहे वह लिखित हो या ज़बानी—गैर कानूनी होगा। परन्तु यदि उचित मजदूरी पर बिना बालक को हानि पहुंचाये किसी बालक की सेवायें लेने सम्बन्धी कोई प्रसविदा किया जाता है और अधिक से अधिक सप्ताह भर की मूचना देने पर यदि वह समाप्त किया जा सकता है तो वह प्रसविदा गैर कानूनी नहीं होगा। १५ वर्ष से कम आयु के बालक इस एक्ट में बालक माने गये हैं। कानून को भंग करने पर २०० रु० का जुर्माना हो सकता है। लेबर इन्वेंस्टीगेशन कमेटी की जांच से मालूम पड़ा कि यह कुरीति दक्षिण भारत के बीड़ी के धंवे और मैसूर राज्य के अलावा अब और कहीं नहीं पाई जाती है। यहाँ पर भी सरकार इस कुरीति का अन्त करने के लिये प्रयत्नशील है।

बालक की नींर रखने का कानून, १९३८ — इस कानून का उद्देश्य अमुक आयु से कम आयु के बालकों को नींर करने में रोकना है। अर्थात्, १५ वर्ष से कम आयु के बालक किमा भी काम में, निम्नता मजदूरी से मान, डाक और यात्रियों को लाना लेना है या जो किमा भारतीय पोस्ट एक्ट [१९०८] द्वारा नियमित बन्दरगाहों की सामान में माल को इधर उधर करने में सम्मिलित रहता है, नहीं लगाया जा सकता। १९३६ में इस कानून में मशौदा किया गया जिसके अनुसार १० वर्ष से कम आयु के बालकों को निम्नलिखित उद्योगों में काम पर लगाना न मनाई की गई। राज्य की सरकार को कानून के अन्तर्गत की बदलने और बनाने का अधिकार दिया गया है। एक्ट में जिन धर्मों को शामिल किया गया है उनमें दाई बनाव, गलाचा बनाने, सामेंट तैयार करना, कपड़ा छांटने, रंगने, और बुनने, दियामला, आनिशवाची और रिक्कोटन पन्थ तैयार करने, अवरर काटो और अलहदा करने, लागू तैयार करने, सामान बनाने और बनाने बनाने तथा उन भाग बनाने के पथे हैं। मद्रास सरकार ने मोटर वातावात कम्पनियों के वर्कशोप को और उत्तरप्रदेश में पील्स के सामान के रथ और बॉल की बुझियों के पथे को भी इस कानून के अन्तर्गत कर दिया है। १९४८ के पैकरी एक्ट में अनुच्छेद १६ वर्ष से कम आयु के बालकों को नींर रखने की मनाही है, इसलिए इस एक्ट में भी १० वर्ष के स्थान पर १४ वर्ष की कम से कम आयु मानने का मशौदा कर दिया गया है। राज्य में एक्ट का शान्त प्रभाव निरीक्षक, फेक्टरिया द्वारा कराया जाता है। केन्द्रिय कारखानों में इस एक्ट को लागू करना शामिल था। एक्टर कमिशनर का है। सपाय रेलवे का पहा तक सम्बन्ध है लोक लेबर कमिशनर, प्रादेशिक लेबर कमिशनर और केन्द्रीय लेबर इन्स्पेक्टर को इस कानून के लागू कराने का जिम्मा दिया गया है। बन्दरगाहों के बारे में भारत सरकार द्वारा लेबर इन्स्पेक्टर की नियुक्ति की गई है।

औद्योगिक ऑर्डर, कानून, १९४७ — इस कानून के पास होने के पहले तक मजदूरी, काम करने का परिस्थिति और उद्योगों सम्बन्धी दूसरे मामलों की जानकारी का आधार उद्योग पथों का सम्पादन और उनकी स्वेच्छा ने किया गया प्रयत्न मात्र था। यह स्थिति अनोपयुक्त नहीं होने से १९४२ में उपर्युक्त कानून भारत सरकार द्वारा पास किया गया। इस एक्ट के अनुसार निम्नलिखित बातों के विषय में सार्वजनिक करने का इजाजत है — औद्योगिक मूल्य, मात्रा, रक्षण महान की परिस्थिति निम्न महान, जल और माफद सम्बन्धी यन्त्रा भी शामिल है, अथ, शिफा, मजदूरी और आय, प्राविष्ट और दूसरे पन्ध जो मजदूरों के

लिए कायम किये जायें; मजदूरों को मिलने वाली सुविधायें और लाभ, काम के घण्टे, रोजगार और बेकारी, और औद्योगिक तथा मजदूर संबंधी संघर्ष। यदि कोई व्यक्ति जानकारी देने से इनकार करे तो उसे दण्ड दिया जा सकता है। 'स्टेटिस्टिक्स अधिकारी' (आथेरेट्री) नाम का एक आफिसर राज्य की सरकारों को नियुक्त करने का अधिकार है। एकट में फैक्टरियों संबंधी आंकड़े—जैसे उत्पादन आदि के और मजदूरों की मलाई के मामलों संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने का भी अधिकार है। कई राज्यों ने फैक्टरियों सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे करना आरंभ कर दिया है और औद्योगिक आंकड़ों के संचालक ने उत्पादन के संबंध में आंकड़े इकट्ठे करना शुरू कर दिया है। मजदूरों के आंकड़ों सम्बन्धी कानून की धाराओं को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

अणु सम्बन्धी कानून—मिल-मजदूरों की एक समस्या उनके अणुग्रस्त होने की है। इस संबंध में उनको आवश्यक संरक्षण देने के लिये समय-समय पर कई कानून बनाए जा चुके हैं। १९३७ में भारत-सरकारद्वारा एक एकट पास करके यह व्यवस्था कर दी गई कि उन मजदूरों की जो १०० रु० मासिक से कम वेतन पाते हैं तनखा कुर्क नहीं हो सकती। सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह विधान है कि जो १०० रु० मासिक से अधिक भी पाते हैं उनके पहले १०० रु० तथा शेष वेतन का आधा कुर्की में मुक्त कर दिया गया है। कानून में इस बात का भी विधान है कि मजदूर के वेतन की कुर्की कुल भिलाकर २४ महीने तक यदि होगई है तो आगे के १२ महीने तक उसकी कुर्की नहीं हो सकती।

भारत-सरकार ने शार्दा मजदूर कमीशन की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए १९३६ में सिविल प्रोसेज्जोर कोड में एक संशोधन किया जिसके परिणाम स्वरूप कर्जदार मजदूर को कैद की सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि वह न माफूम पड़े कि कर्जदार ने अपनी संपत्ति बेईमानी से हस्तान्तरित कर दी है या विधियों के दायरी में कबहूरी के अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर बाधा पहुँचाना चाइता है। पंजाब-सरकार ने भी १९३५ में एक कानून (पंजाब रिलीफ ऑन इंडेब्टेनेस एक्ट) लागू करके अणुग्रस्त मजदूर को कैद करने पर प्रतिबंध लगा दिया है जब तक कि विधियों का रूपवा अधिनो शक्ति के अनुसार उस संपत्ति में से जो कुर्क हो सकती है देने से ही वह इनकार न करदे।

१९३६ के मध्य प्रदेश के 'एडजस्टमेंट एन्ड लिक्विडेशन ऑफ इन्डस्ट्रियल वर्कस डेट एक्ट' के अनुसार जो मजदूर ५० रु० मासिक तक कमाते हैं उनको किन्हीं परिस्थितियों में (यदि उसकी संपत्ति और तीन महीने के वेतन से अणु अधिक हो) अपने कर्ज का फैसला कर देने की दरखास्त देने का अधिकार है,

और आवश्यक जाच के बाद कचहरी उसका फैसला कर देती है और यह निश्चय कर देती है कि कजदार को उसकी मजदूरी और उसके व्ययों की गणना को दमते हुए कितना रकबा कितने समय में चुका देना चाहिये।

बंगाल सरकार ने १९३४ में बंगाल वस्त्रमन्त्र प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था। इस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति क्रिमिनालस्थाने, स्नान, रेलवे स्टेशन आदि के आदर या पाम में हम इरादों से जिस कारखाने के किसी मजदूर से यह कल बसूल करता चाहता है, घूमना फिरता पाया जायगा तो उसे जुर्माना या कैद या दोनों सजा दी मर्गा। १९४० में एन सशोपन द्वारा मजदूर को परना और भा कड़ा से वर्जित कर दिया गया है तथा एक्ट का कार्यक्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है ताकि उसमें लोकल आडिरिटीय, और सार्वजनिक उपयोग के धारा में लग मजदूरों और गहान पर काम करने वाले मजदूरों को भी शामिल किया जा सके। १९३७ में मध्य प्रदेश ने भी एक ऐसा ही कानून पास किया। मद्रास सरकार ने १९४१ में इस सम्बन्ध में कानून पास किया है।

बिहार वकमेस प्रोटेक्शन एक्ट १९४८ कुछ भेदा के मजदूरों से जहा व काम करते हैं या मजदूरी पाते हैं वहा घरा डाल कर कर्ज बसूल करने पर रोक लगाता है। कजदार मजदूरों को उनके महानन डरा घमका न सकें इसमें भी उनका इस कानून में रक्षा की गई है। इन स्थानों पर घरा डालने के आरम्भ में जुर्माना या छह महीने तक की सजा या दोनों ही दण्ड दिये जा सकते हैं।

मजदूर जाच कमेटी का यह कहना है कि श्रेष्ठ सबंधी इन कानूनों का बहुत अछर नहीं पड़ा है। पर फिर भी उसने जहा ऐसे कानून नहीं हैं वहा उनका पास करने व पन म राय दी है।

परिच्छेद ६

औद्योगिक सम्बन्ध

पिछले परिच्छेद में हम मजदूर सम्बन्धी कानूनों का विवरण दे चुके हैं। केवल उन कानूनों का हमने वहाँ विवरण नहीं दिया जिनका सम्बन्ध मजदूर-मालिक के आपसी सम्बन्धों (औद्योगिक सम्बन्धों) से आता है। इस परिच्छेद में हम मजदूर-मालिक-सम्बन्ध की इस समस्या पर विचार करेंगे और इस सम्बन्धी जो कानून हैं उनका भी यहाँ विवरण देंगे।

औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण यह है कि समाज के आर्थिक जीवन में मजदूरों और पूंजीपतियों के दो परस्पर विरोधी वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं और उनमें निरन्तर संघर्ष की पृष्ठभूमि बनी रहती है जो कभी-कभी मथानक संघर्ष के रूप में फूट पड़ती है। ये संघर्ष देश के आर्थिक जीवन को अस्तव्यस्त कर देते हैं और समाज में अशांति और अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न करते हैं। देश के आर्थिक जीवन का सुचारु रूप से संचालन हो सके उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि मजदूर और पूंजीपति में न केवल प्रत्यक्ष संघर्ष और उसकी पृष्ठभूमि ही न हो, बल्कि पारस्परिक सहयोग हो। बिना इस आपसी सहयोग के राष्ट्र की उत्पादन शक्ति का अष्टम उपयोग नहीं हो सकता जिसका अर्थ है आर्थिक जीवन की समृद्धि और प्रगति के मार्ग का अविरोध होना। इसी लिए मजदूर-पूंजीपति-सम्बन्धों या औद्योगिक संबंधों की समस्या का इतना महत्व समझा जाता है। हम अब इसी समस्या पर विचार करेंगे।

मजदूर संगठन और औद्योगिक संबंध—औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या का एक पक्ष मजदूरों के संगठन से संबंध रखता है। जब आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ तो शुरू-शुरू में मजदूरों की स्थिति कमज़ोर थी और वे असंगठित थे। इसलिए मिल-मालिक उनका शोषण आसानी से कर सकते थे। परन्तु जैसे जैसे समय बीतता गया मजदूरों की स्थिति में भी परिवर्तन आया। एक साथ हजारों आदमी जब काम करते हैं तो उनका आपस में सम्पर्क होना भी स्वाभाविक है। जब वे एक दूसरे के दुःख-दर्द को बात सुनते हैं तो उनमें आपस में सहानुभूति का भाव उत्पन्न होता है। धीरे-धीरे उनके यह समझ में आने लगता है कि यदि वे आपस में एक दूसरे की सहायता करने को तैयार हो जाते हैं और अपना संगठन बना लेंगे हैं तो फिर मिल-मालिकों के लिए मन चाहे ढंग से उनका शोषण करना आसान नहीं होगा। इसी विचार में से दुनिया के मजदूर-संगठन

का उदय हुआ है और आज तो दुनिया के सभी औद्योगिक देशों में मजदूर-संगठन का बड़ी शक्ति माना जाता है। मजदूरों के राजनैतिक दल भी हैं और कई देशों में जैसे इंग्लैंड में राज्य का शासन तंत्र भी उनके हाथ में है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज मजदूर संगठन का बड़ा महत्व है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् अन्तराष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना होने लगी थी दुनिया के मजदूर संगठनों की बहुत शक्ति मिली है और अब वे एक मूल में बंध गए हैं।

मजदूर संगठन का प्रभाव मालिक मजदूर के सम्बन्धों पर भी पड़ा है। जब तक मजदूर यथा असंगठित होता है वह अपने हितों की रक्षा के लिए पूजा-पति वगैरे में समय माल नहीं ले सकता और उनकी कृपा पर ही अपने आप को जीवन समझता है। जब मजदूरों में चेनसा और संगठन शक्ति का उदय होने लगता है तो उनकी दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आता है। वे मालिक को अपना माना-पना नहीं समझते और अपने हितों की रक्षा के लिए उसे गंभीर करने को वे तैयार हो जाते हैं। इकतार्वी को मजदूर अपना एक प्रबल अस्त्र मानने लगते हैं। औद्योगिक तथ्यों जो अन्दर ही अन्दर दबा रहना था, वह अब बाहर फूट पड़ता है और मिलमालिक मजदूर के परस्पर सम्बन्ध का एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस दृष्टि से मजदूर संगठन ही इस समस्या का कारण माना जा सकता है। यही कारण है कि आरम्भ में पूजा-पति वगैरे ने मजदूर संगठन का हमेशा हाथ धिरोप किया है और उम्मेद यह था कि मजदूर संगठन को कानूनी सहायता न मिले। पर यह तो असम्भव था। मजदूरों की सामाजिक शक्ति अब बनने लगी तो उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। मजदूर संगठनों को कानूनी मान्यता मिलना आरम्भ हुआ। आज सब देशों में मजदूरसंगठनों को यह मान्यता प्राप्त है। इधर पूजा-पति वगैरे दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आने लगा। आज का पूजा-पति संगठित मजदूर वर्ग को अधिक पसन्द करता है न कि असंगठित मजदूर को। वह समझता है कि संगठित मजदूर वर्ग अधिक अनुशासन में रखा जा सकता है, उससे विचार विनिमय करना आसान है, वह अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करता है, और उससे यह आशा की जा सकती है कि वह किसी भी प्रश्न पर सकीर्ण दृष्टि से न सोचकर अधिक व्यापक और समान की दृष्टि से सोच। इसलिये मजदूर संगठन औद्योगिक शक्ति में बहुत कुछ सहायक हो सकता है और यह विचार सही नहीं है कि उसका परिणाम मिल मालिक मजदूर सम्बन्धों में संघर्ष और कटुता उत्पन्न करने का होता है। यह अक्षर्य है कि संगठित होने से मजदूरों की शक्ति बनती है और मिल मालिक यदि उनके हितों का अवहेलना करते हैं तो वे संगठित रूप से उसका प्रतिकार करने को तैयार हो

जाते हैं। दास्तव में देखा जाए तो मजदूरों में कोई संगठन न हो यह तो असम्भव है। जब वे एक साथ, एकसी परिस्थितियों में, एक ही स्थान पर काम करते हैं और एकसी समस्याओं उनके सामने उपस्थित होती हैं तो उनका संगठित रूप से सोचना और व्यवहार करना तो अवश्यम्भावी है। इसलिए संगठित और असंगठित मजदूर वर्ग में चुनाव करने का प्रश्न तो है ही नहीं। प्रश्न यह हो सकता है तो वह यही हो सकता है कि समाज और राज्य मजदूरों के संगठन को मान्यता दे या न दे। ऐसी स्थिति में इस बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि मजदूर-संगठन को मान्यता देना और उनके अस्तित्व की स्वीकार करके चलना कहीं अधिक अच्छा है। हम यहां तक भी कह सकते हैं कि श्रीयोगिक शांति के लिए स्वस्थ मजदूर-संगठन का होना अत्यन्त आवश्यक है। अब हम भारतवर्ष के मजदूर-संगठन के बारे में कुछ विचार करेंगे।

भारत में मजदूर-संगठन—भारत में मजदूर आन्दोलन का प्रारम्भ उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण (१८७५ के आस-पास) में होता है। इस आन्दोलन के प्रवर्तकों में श्री सौरावजी सापुरजी बगाली प्रमुख थे। १८८० में श्रीसुत नारायण मेघजी लोखंडे ने, जो भारतीय मजदूर-संगठन के जनक और उसकी आत्मा थे, पहला मजदूर-संगठन बम्बई में स्थापित किया। इसका नाम था 'बम्बई मिल-मजदूर संघ' (बोम्बे मिल-वेल्फेयर एसोसियेशन)। पर वास्तविक अर्थ में यह संघ मजदूर-संघ न था। इसका काम तो बम्बई के मिल-मजदूरों की शिकायतों के समाशोधन यह (क्लियरिंग हाउस) का था। इसके बाद आने वाले १५ वर्षों में कई मजदूरसभाएँ स्थापित हुईं—जैसे एंगेलमेमेट्रेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इन्डिया एन्ड बर्मा (१८८७), प्रिंटर्स यूनियन कलकत्ता (१८७५), बोम्बे पोस्टल यूनियन (१८७७), और कामगार हितवर्क सभा बम्बई (१८७६)। जब भारत में आधुनिक ढंग के कारखाने खुलने लगे और उनमें काम करने वाले मजदूरों का—फिर वे स्त्रियाँ हों या बालक—शोषण होने लगा तो उनके संरक्षण के प्रश्न की लेकर ही इस मजदूर-आन्दोलन का आरम्भ हुआ था। मैनेज्मन्ट के वस्त्र-व्यवसायियों ने भी भारत के मजदूर-आन्दोलन की बड़ी सहायता और प्रोत्साहन दिया। बात यह थी कि भारत की मिलों में मजदूरों को कम वेतन देकर और अधिक घंटों उनसे काम कराकर जो कपड़ा तैयार होता था वह मैनेज्मन्ट के वपदे से सस्ता पड़ता था और उससे मैनेज्मन्ट के वस्त्र-व्यवसायियों की हानि होने का डर था। इसलिए वे चाहते थे कि भारतीय मजदूरों के काम करने की परिस्थितियों पर कानून द्वारा नियंत्रण किया जाये—जैसे उनको ठीक वेतन मिले, काम के घंटे अधिक न हों आदि। इसी दृष्टि से वे यह चाहते थे कि भारत में

या रजिस्ट्री करने के बाद उसे रद्द कर दें। उसके आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट तक अपील की जा सकती है। कानून में ट्रेड यूनियन की परिभाषा इस ढंग से दी गई है कि उसके अंतर्गत मजदूरों व श्रमावा मिल-मालिकों का संग्रह आ सकता है, पर जिन संग्रह में मजदूर और मिल मालिक दोनों हों वह उसका अंतर्गत नहीं आ सकता। यह संग्रह कम आयु का व्यक्ति रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं हो सकता।

(क) रजिस्टर्ड यूनियन का कुछ अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। एक तो यह कि उसमें पदाधिकारियों या सदस्यों पर यूनियन की उद्देश्य की पूर्ति के लिए का गई ज़िम्मेदारी या गारंटी पर, जैसे इकतान के कारण पीनकारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार से वे दीयानो कार्रवाई में भी सुरक्षित हैं।

(ग) रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पर कई प्रकार का जिम्मेदारिया भी हैं। उसे हर साल रजिस्ट्रार के पास खालाना या सहे आदि भेजने होते हैं और खर्च गमा गमा का आविष्ट किया हुआ खीरा भी देना होता है। कोई भी यूनियन का पदाधिकारी या सदस्य यूनियन के हिस्से की जाबबदारी करता है। यूनियन के नाम, विधान और नियम में अगर कोई परिवर्तन हो तो उसका सूचना रजिस्ट्रार को मिलना चाहिये। यूनियन का आम कोष किन किन चीजों पर खर्च हो सकता है वह कानून में नया है। इन तयशुदा चीजों में औद्योगिक भवन, जिनमें यूनियन का पकना पड़े, शामिल हैं। अस्त, इस तरह का खर्चा इन प्रकार के भवन पर भी व्यय हो सकता है। सदस्यों के कल्याण के लिए कोई स्थापन किया जा सकता है। इसमें चन्दा देना न करना शामिल है। इन जिम्मेदारियों को नही निभाने में उल्लंघन हो सकता है चाहे वह गुप्तता का खर्च हो या यूनियन को रजिस्ट्रेशन नो रद्द करने की शक्ति में।

(घ) यह इन नियमों के कि १६४७ में ट्रेड यूनियन एक्ट में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इससे अनुसार यदि कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अपने मिल मालिक को मान्यता के लिए आवेदन पत्र दे और फिर भी उसे मान्यता न लेबर कोर्ट (नो इस कानून के अनुसार नियुक्त की जा सकती है और जिनमें एक पट्टे कि ट्रेड यूनियन उन मामलों की पूर्ण करती है या मान्यता प्राप्त करने

के लिए आवश्यक है, और जिनमें से एक यह है कि वह यूनियन उस मिल-मालिक के यहाँ काम करने वाले सब मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती हो, तो उसे- (लेबर कोर्ट को) मिल-मालिक को उस यूनियन को मान्यता देने के लिए आज्ञा देने का अधिकार है। जो मान्य ट्रेड यूनियन होती हैं उन्हें नियुक्ति, काम की परिस्थिति और शर्तों आदि मजदूरों सम्बन्धी सब मामलों में मिल-मालिकों से पूछताछ और क्लैसला करने का अधिकार होता है। उन्हें मिल के अन्दर अपने मोटिस आदि लगाने का अधिकार भी होता है।

(इ) दूसरी महत्वपूर्ण बात जो १९४७ के संशोधन के अनुसार हुई है यह है कि मान्य ट्रेड यूनियनों और मिल-मालिकों के लिए कुछ बातों को अनुचित घोषित कर दिया गया है। यूनियन (मान्य) के लिए जो बातें अनुचित घोषित की गई हैं वे इस प्रकार हैं:—(१) यूनियन के सदस्यों के बहुमत का अनियमित हड़ताल में भाग लेना, (२) यूनियन की कार्य-कारिणी का अनियमित हड़ताल में सहयोग, सलाह या प्रोत्साहन देना, (३) यूनियन के पदाधिकारी द्वारा गलत जानकारी देना। मिल-मालिकों के लिए जो बातें अनुचित मानी गई हैं वे ये हैं:—(१) मजदूरों द्वारा ट्रेड यूनियन आदि संगठन बनाने के मार्ग में, उसके काम में तथा उसे आर्थिक सहायता देने में रुकावट पैदा करना, (२) किसी व्यक्ति को जो मान्य ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी है, या जिसने मान्य ट्रेड यूनियन के अधिकारों के सम्बन्ध में कोई गवाही आदि दी है बर्खास्त करना या उसके विरुद्ध पक्षपात करना, और (३) मान्य ट्रेड यूनियन के पत्रों आदि का उत्तर न देना या उसे मुलाकात न देना। यदि कोई यूनियन अनुचित बात करती है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है और मिल-मालिक पर एक हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

(ज) एक्ट के पालन कराने का जिम्मा राज्यों पर है और वे इस काम के लिए रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को नियुक्ति करते हैं। पर रजिस्ट्रार को ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार आदि जांचने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार कानून में संशोधन करके रजिस्ट्रार को दिया जाना चाहिये।

औद्योगिक संघर्ष—मजदूर-संगठन के सम्बन्ध में लिखते हुए हमने यह लिखा है कि प्रथम महायुद्ध के पश्चात् ही भारतीय मजदूर ने अपने आप को संगठित करने का विशेष प्रयत्न आरम्भ किया। औद्योगिक संघर्षों का इतिहास भी हमें यही बतलाता है कि भारतवर्ष में प्रथम महायुद्ध के बाद ही मजदूरों और मिल-मालिकों के संघर्ष का युग आरम्भ होता है। १९२४ में और १९२५ में और बाद में १९२८ और १९२९ में बम्बई में बहुत बड़ी-बड़ी आग हड़तालें हुईं जिनमें

प्रभाव हुआ, यह भी उपयुक्त विचारण से स्पष्ट है। यदि हम मजदूर समानों संवरी आँकड़े देखें तो हमें और स्पष्ट रूप से यह मालूम होगा कि मजदूर संगठन का प्रगति हमारे देश में किम गति में हुई है। जो आँकड़े हमें उपलब्ध हैं वे केवल उन्हीं समानों के हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रखा है और जो अपने बारे में आवश्यक जानकारी प्रविष्ट करवा करके पेश करते हैं। जो मजदूर समानें रजिस्टर्ड नहीं हैं उनसे आँकड़े हमारे पास नहीं हैं। ऐसी मजदूर समानों की संख्या भी यथार्थ है। रजिस्टर्ड मजदूर समानों सम्बन्धी आँकड़ों को देखने में प्रकट होता है कि १९०७-०८ में मारनबर्ग ११ २६ मजदूर समानों था, १९१२-१३ में उनकी संख्या बढ़कर १७० हो गई और १९१८-१९ में यह संख्या ५६२ थी। १९४५-४६ में १००० मजदूर-समान (रजिस्टर्ड) अविभाजित भारत में (पन्नाब क आँकड़े शामिल नहीं हैं) था। इससे स्पष्ट है कि युद्ध के समय में मजदूर समानों की संख्या लगभग दुगुना होगी। १९४६-४७ में यह संख्या बढ़ कर १०२५ होगी। स्थान रमन का मान यह है कि यह आँकड़ अविभाजित भारत के हैं और पूर्वी पन्नाब क आँकड़ इसमें शामिल नहीं हैं। १९४७-४८ में यह संख्या २६६६ होगी। इन २६६६ में केवल २६०८ में अपने आँकड़ पेश किये तिनके अनुसार इन १५०८ मजदूर समानों के सदस्यों का कुल संख्या १६ लाख ॥ ऊपर था। १९२७-२८ में कुल सदस्य संख्या २६ रजिस्टर्ड यूनियनों में २०८ का १ लाख ४० हजार थी। १९२२-२३ में १७- में से १४७ की सदस्य संख्या २ लाख २० हजार से कुछ अधिक थी और १९०८-१९ में ५६० में से ३६४ का ४ लाख से कुछ कम था। १९४५-४६ में १८८०० में से ५८४ की ८ लाख ६४ हजार से कुछ अधिक थी और १९४६-४७ में १७०५५ में से ६६८८ की ११ लाख ३० हजार से कुछ अधिक था। इन मजदूर समानों ॥ अविभाजित औद्योगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रियल यूनियन) हैं जो कि किसी भी एक उद्योग में काम करने वाले सब मजदूरों का संगठन करते हैं। इसमें अलावा कुछ शिल्प मंत्र (क्रेफ्ट यूनियन) हैं और तीसरी श्रेणी में कुछ सामान्य मजदूर संघ हैं, जिनमें विभिन्न उद्योगों और शिल्पों के मजदूर एक ही संघ में संघटित हो जाते हैं जैसे मजदूर समाजानुसार या गिरनी कामगार यूनियन, वगैरह। घबो की दृष्टि से यातायात और वस्त्रोद्योग में मजदूर संगठन न अच्छी प्रगति की है।

विद्यमान वगैरे मजदूर समानों की संख्याओं में यद्यपि वृद्धि हुई है, पर फिर भी यह सत्य है कि हमारे देश का मजदूर संगठन अभी उतना शक्तिशाली नहीं बन पाया है जितना पश्चिम के कई देशों का है। मजदूर समानों का नेतृत्व अधिकांश स्वयं मजदूरों के हाथ में न होकर राजनैतिक कार्यकर्ताओं के हाथ में है। यह

स्थिति बहुत स्वास्थ्यकर नहीं कही जा सकती। उनके पास धन की कमी है और हड़ताल के समय वह अपने सदस्यों को सहायता नहीं दे सकते। बहुत कम मजदूर-समाजें ऐसी हैं जो मजदूरों की भलाई के कामों की ओर ध्यान देती हैं और ध्यान देने की शक्ति भी रखती हैं।

भारत में मजदूर-संगठन के मार्ग में कई कठिनाइयाँ रही हैं और आज भी हैं। भारतीय मजदूर अशिक्षित है, वह अपने आपको स्थायी रूप से मजदूर नहीं समझता और एक स्थान से दूसरे स्थान को वह आता-जाता रहता है, वह निर्बल है और अपने संगठन के लिये अधिक पैसा नहीं दे सकता, मजदूर-संगठन का नेतृत्व योग्य हाथों में नहीं है और विभिन्न राजनैतिक दल मजदूरों के संगठन का उपयोग अपने राजनैतिक हेतुओं को निरूप करने के लिए करना चाहते हैं, और अन्तिम बात यह है कि मिल-मालिक सफल और शक्तिशाली मजदूर-संगठन का हर प्रकार से विरोध करते हैं और यह प्रयत्न करते हैं कि मजदूरों में फूट डाली जाये और उनका संगठन कमजोर बना रहे। अतः, भारत में सशक्त मजदूर संगठन बनाने के लिये उपयुक्त कमियों को मिटाने की बड़ी आवश्यकता है। अब हम ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में विशेष जानकारी करेंगे।

ट्रेड यूनियन एक्ट १९२६—यह कानून किन परिस्थितियों में सात हुआ इसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। १ जुलाई १९२७ को यह एक्ट लागू किया गया। सन् १९४७ तक इस कानून में कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं हुआ। पर इसी वर्ष कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य प्रतिनिधि मजदूर-समाजों की मिल-मालिकों द्वारा अनिवार्यतः मान्यता दिलाना, और मिल-मालिकों तथा मजदूर-समाजों को क्या-क्या अनुचित कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहियें इसकी कानून में व्यवस्था करना था। इस कानून के मुख्य-मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं—

(क) किये भी ट्रेड यूनियन के सात या सात से अधिक सदस्य यूनियन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। कानून के पालन कराने का जिम्मा राज्य की सरकारों का होने से हर राज्य में राज्य की सरकार द्वारा ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है जिसका काम ट्रेड यूनियनों को रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर होने की कुछ शर्तें हैं जिनकी पूरी किये बिना कोई यूनियन रजिस्टर नहीं की जा सकती। उनमें से एक शर्त यह है कि यूनियन की कार्यकारिणी में कम से कम ५०% व्यक्ति जिस उद्योग या धंधे की यूनियन है उस उद्योग या धंधे में काम करने वाले होने चाहिये। रजिस्ट्रार को वह अधिकार है कि वह किन्हीं कारणों के उपस्थित होने पर किसी यूनियन को रजिस्टर करने से इन्कार कर दे

पूट पड़ जाने पर उमने अपने आपको अलग कर लिया और १९३५ तक उससे बाहर ही रहा। अ. भा. ट्रेड यू. कांफ्रेंस में १९३१ में फिर पूट पड़ी और एम. रा. दश पांड और बा. टी. रानाविव के नेतृत्व में एक 'अ. भा. ट्रेड ट्रेड यूनियन कांफ्रेंस' की स्थापना की गई। इस प्रकार दश के मजदूर संगठन में पूट पड़ जाने से मजदूर आंदोलन को बड़ा धक्का लगा। यद्यपि एकता के प्रयत्न १९३१ में ही शुरू हो गए, परन्तु वास्तव में १९३८ में अ. भा. ट्रेड यू. कांफ्रेंस और राष्ट्रीय [नेशनल] ट्रेड फेडरेशन नाम के एक दूसरे अखिल भारतीय संगठन का नागपुर में एक सम्मिलित विजय अभियान हुआ और उद्यम यह निश्चय हुआ कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांफ्रेंस और नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन मिलकर एक पन्थाप संगठन का निर्माण करें। १९४० में अ. भा. ट्रेड यू. कांफ्रेंस के बम्बई अभियान में इस निष्पत्ति का पता कर दिया गया। इस राष्ट्रीय [नेशनल] ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना १९४३ में मजदूर संगठन में एकता स्थापित करने के फलस्वरूप हुआ थी जिसमें कम्युनिस्ट प्रभाव के अखिल भारतीय मजदूर संगठन, अ. भा. ट्रेड यूनियन कांफ्रेंस, र. अलावा जो देश में अनेकों अखिल-भारतीय मजदूर संगठन उस समय थे, उनमें शामिल किया गया था। इन ही संगठनों में एक तो १९१९ में स्थापित अ. भा. ट्रेड यूनियन फेडरेशन था जो ट्रेड यूनियन कांफ्रेंस में पूट पड़ जाने पर सुवारवादी पक्ष के लोगों ने बनाया था, और दूसरा नेशनल फेडरेशन था जो देश की उन मजदूर समानों के अखिल भारतीय संगठन के रूप में १९३३ में ही स्थापित किया गया था जिनका कम्युनिस्टों और सुवारवादियों द्वारा सही सम्बन्ध नहीं था। इससे तो देश के मजदूर संगठन में एकता लाने का प्रयत्न सफल हुआ, पर उसी समय दूसरी ओर १९४० में इसी वर्ष अभियान में दिनांक महायुद्ध के प्रश्न को लेकर फिर पूट पड़ गया। ट्रेड यू. कांफ्रेंस ने द्वितीय महायुद्ध के वारे में तटस्थता की नीति रखने का प्रस्ताव पास किया। इस नीति से उन लोगों को जो युद्ध का समर्थन करना चाहते थे अखिल भारतीय हुआ और उनमें से था आपत्ताव अली ने तो अपनी जहाजों पर काम करने वालों की यूनियन (नोमैन यूनियन) को अलग कर लिया और श्री एम. एन. राय ने और श्री जमनादास महाता ने 'इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर' नाम का एक प्रयत्न अखिल भारतीय संगठन का कार्य कर लिया। इस संगठन का मजदूरों में कोई खास प्रभाव नहीं है। १९४८ के अखिल भारतीय महीनों और १९४९ के प्रारम्भ के महीनों में फिर देश के मजदूर-आंदोलन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ घटीं। कम्युनिस्टों और उदार विचारों के लोगों में फिर संघर्ष हो गया और अ. भा. ट्रेड यूनियन कांफ्रेंस से बहुत सी यूनियनों ने अपने अपने अलग कर

लिया। ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर कम्प्यूनिस्टों का प्रभाव रहा पर उसका मजदूरवर्ग में पहला जैसा असर अब नहीं है। १९४० में एक और महत्वपूर्ण अखिल भारतीय मजदूर-संघटन कांग्रेस नेताओं के मार्ग दर्शन में कायम हुआ है। इसका नाम इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस रखा गया। महात्मा गांधी की विचारधारा के अनुसार मजदूरों में काम करने वाली 'हिन्दुस्तान मजदूर सेवक संघ' नाम की संस्था के प्रभाव में जो मजदूर-सभायें थीं वे इस भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इ. ने. ट्रे. यू. कांग्रेस) से संबंधित हो गईं। अहमदाबाद टेक्स्टाइल लेबर एसोसिएशन भी इससे सम्बद्ध हो गई। इसी प्रकार जो समाजवादी विचार के मजदूर कार्यकर्ता थे उन्होंने भी अपना 'हिन्द मजदूर पंचायत' नाम का एक अलग संगठन बना लिया। दिसम्बर १९४८ में इण्डियन लेबर फेडरेशन और हिन्द मजदूर पंचायत ने मिल कर हिन्द मजदूर सभा नाम का एक अलग अखिल-भारतीय संगठन स्थापित कर लिया है। मई १९४९ में कुछ मजदूर सभाओं ने जो कुछ समय पहले अ. भा. ट्रे. यू. कांग्रेस से अलग हो चुकी थीं एक और अखिल भारतीय संगठन 'यूनाइटेड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस' के नाम से स्थापित किया है। अखिल भारतीय मजदूर संगठनों का जो विवरण हमने ऊपर दिया है उससे यह मालूम पड़ता है कि मोटे रूप से तीन बड़े और प्रमुख अखिल भारतीय संगठन इस समय देश में काम कर रहे हैं। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार), हिन्द मजदूर सभा (समाजवादियों की विचारधारा के अनुसार) और अखिल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (कम्प्यूनिस्ट विचारधारा के अनुसार)।

भारतीय मजदूर संगठन के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या कानूनी मान्यता प्राप्त करने की भी थी। क्योंकि मजदूर संघों को यदि कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है तो मजदूर-नेताओं के विरुद्ध हड़ताल कराने के अपराध में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जैसा कि १९२१ में बकिंघम मिल के मजदूरों और मालिकों में झगड़ा होने पर हुआ भी। वहाँ के निल-मालिकों ने श्री. जी. पी. चाडिया तथा दूसरे मजदूर-नेताओं के विरुद्ध हाईकोर्ट में हर्जाने का दावा कर दिया और उनके विरुद्ध ७००० पाँच और मुकदमे के खर्च की डिगरी कराली। कोर्ट के इस आदेश का मजदूर-नेताओं ने बड़ा विरोध किया और पांच वर्ष के लगातार प्रयत्नों के बाद १९२६ में भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ। इसके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे लिखेंगे।

प्रथम महायुद्ध के बाद से भारतीय मजदूर आन्दोलन ने किम प्रकार प्रगति की उसका व्यौरा हम ऊपर दे आये हैं। द्वितीय महायुद्ध का भी वही

मजदूरों का आंदोलन हो और उसकी शक्ति मिले ताकि उसने दबाव से भारत में भी मजदूर-कानून बनें।

प्रथम महायुद्ध तक भारतीय मजदूर संगठन ने बहुत कम प्रगति की थी। परन्तु प्रथम महायुद्ध के पश्चात् कई कारण ऐसे उपस्थित हो गए जिनसे मजदूर संगठन को विशेष बल मिला। एक ओर तो देश में जो राजनैतिक चेतना फैली उसका प्रभाव मजदूर आंदोलन पर भी पड़ा, और दूसरी ओर युद्ध के कारण उत्पन्न महंगाई का असर मजदूरों के रहन सहन के खर्च को बढ़ाने का जो दुआ पर उनका मजदूरों में उस अनुपात में शक्ति नहीं हुई। मिल मालिकों ने इस विपरीत काफ़ी मुनारता किया। इस गांग स्थिति से मजदूरों के मन में गहवा असंतोष हुआ और इसमें मजदूर संगठन को अधिक मुश्किल बनने में सहायता मिली। नतीजा यह हुआ कि लोग लोड कर आदि के परिचय के विचार और वाना परण का अर्थन साथ लाए और जब उनका यहां के मजदूर से संपर्क हुआ तो उसकी अंतर भी उनका उग्र बनाने में ही हुआ। इस की बोझविक्रान्ति, काभ्रस द्वारा मन्नामा गाथा के मन्त्र में चलाया गया अग्रहयोग आंदोलन, और ब्रिटिश सरकार की दमन नीति—इन सबका परिणाम भी यही हुआ कि राष्ट्रीय जागृति और संगठन का यह भर में एक लहर भी दौड़ गई और उससे देश का मजदूरवर्ग भी अचूकता में रह सका। अस्तु १९१८ के उपरान्त देश में मजदूर समाजों का तर्जो से संगठन होने लगा। सबसे पहला औद्योगिक दूध यूनिशन (मजदूर मंडल) १९१८ में मद्रास शहर के मूनी रूपड़े के कारखानों के मजदूरों की आवाजों का वाक्या न स्थापित का। यह मजदूर समाज बहुत सकल हुए और इसमें मजदूरों में बहुत उत्साह उत्पन्न हुआ। १९१९ में मद्रास प्रांत में चार मजदूर संघ काम कर रहे थे और उनके सदस्यों का संख्या २० हजार था। मद्रास से मजदूर संगठन का लहर और प्रांतों में भी फैली और देखते देखते बम्बई, कलकत्ता अहमदाबाद तथा अन्य औद्योगिक केंद्रों में मजदूर समाजों के तर्जो से स्थापित होने लगा। यहाँ हम महानाम गाथा के मन्त्र में १९२० में अहमदाबाद का मूनी कपड़े का मिलों के मजदूरों का जो संगठन किया गया उसका विशय रूप से उल्लेख करना चाहेंगे। इस मजदूर संगठन का नाम 'टंकुछटाइल लेबर एसोसियशन' अहमदाबाद है। यह हमारे देश का एक बहुत ही सबब और सकल मजदूर संघ है। यह कुछ घण्टावार मजदूर संघों (मजदूर यूनिऑन) का एक संघ है। जो मजदूर संघ इसमें शामिल हैं उनके नाम ये हैं—(१) बुनकर संघ (२) धोसल संघ (३) काट मम, ब्लोम और पैम डिपार्टमेंट यूनिशन (४) बाइ यूनिशन (५) ट्राइंग, आइलमस, और फायरमस यूनिशन (६) जालम और मुकदम

यूनियन। इस संघ की सफलता का एक बड़ा कारण यह है कि मजदूरों की भलाई के लिए, जैसे उनकी शिक्षा, चिकित्सा, दुर्घटना के समय आर्थिक सहायता आदि के सम्बन्ध में, इसने बराबर प्रयत्न किया है और इस आधार पर मजदूरों में एकता और संगठन कायम रखा जा सका है। इस मजदूर-संगठन की दूसरी विशेषता यह रही है कि इसने अहमदाबाद मिलमालिक-संघ से मिलकर आपस के मगड़े मुलफाने की नीति को बराबर अपनाया है और उसका परिणाम यह हुआ है कि अहमदाबाद में अपेक्षाकृत मिल-मालिकों और मजदूरों में कम संघर्ष हुये हैं। भारतीय मजदूर आन्दोलन में कम्युनिस्टों का प्रभाव भी रहा है। यह ठीक है कि यह प्रभाव किन्हीं औद्योगिक केन्द्रों, जैसे बम्बई, कानपुर में विशेष रहा है तो किन्हीं में कम। यह भी ठीक है कि उनके इस प्रभाव में उत्तार-चढ़ाव भी आते रहे हैं। १९२४ के उपरान्त भारत के मजदूर आन्दोलन में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ने लगा। इसी समय सरकार ने जब कम्युनिस्टों के दमन की नीति अपनाई तो उसका परिणाम भी यही हुआ कि उनका प्रभाव मजदूरों में बढ़ा। बम्बई में १९२७ में कम्युनिस्टों ने "गिरनी कामगार यूनियन" की स्थापना की। अगले इस बढ़ते हुए प्रभाव का लाभ उठाने की दृष्टि से ही उन्होंने हिन्दुस्तान भर का जो मजदूर संगठन "ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस" था, उस पर नागपुर के १९२६ के अधिवेशन में आधिपत्य जमा लिया। उसी के फलस्वरूप इस अखिल भारतीय संगठन में फूट पड़ गई और जो सुधारवादी पक्ष था वह अलग हो गया और आ० इ० ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर कम्युनिस्टों का प्रभुत्व कायम हो गया।

भारतीय मजदूर-संगठन में विभिन्न मजदूर-समाजों के केन्द्रीय संगठन स्थापित करने का प्रयत्न भी प्रथम महासुद के तुरन्त बाद ही आरम्भ हुआ। विभिन्न स्थानों में केन्द्रीय संगठन स्थापित हुए और प्रांतीय संगठनों की स्थापना भी की गई। १९२० में मजदूर-समाजों का एक अखिल भारतीय संगठन भी कायम हुआ—इसी का नाम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस रखा गया। बम्बई में २६० लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि १९२६ में इस संगठन में फूट पड़ गई और उसके परिणामस्वरूप सुधारवादी पक्ष ने श्री एन० एम० जोशी के नेतृत्व में एक दूसरे अखिल भारतीय संगठन, 'ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन', की स्थापना की। रेलवे यूनियनों ने मिलकर अपना एक अखिल भारतीय संगठन "अखिल भारतीय रेलवेमैन्स फेडरेशन" के नाम से १९२५ में स्थापित किया था। रेलवे मजदूरों का यह एक प्रबल संगठन है और रेलवे बोर्ड ने इसे स्वीकृत कर लिया है। यह फेडरेशन भी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में सम्मिलित था, पर १९२६ में

या रजिस्ट्रार करने के बाद उस रहस्य रहता है। उसका आदेश के खिलाफ हारकी तरह अपील की जा सकती है। कानून में टूट यूनियन का परिभाषा इस ढंग में है कि उसमें अलग-अलग मजदूरों के अलावा मिल मालिकों का गण भी आ सकता है पर जिस मध्यम मजदूर और मिल मालिक दोनों यह उसके अंतर्गत नहीं आ सकते। ५ वर्ष से कम आयु का व्यक्ति रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं हो सकता।

(ख) रजिस्ट्रार यूनियन को कुछ अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। एक तो यह कि उसमें पदाधिकारियों या संस्था पर यूनियन की उद्देश्य की प्रति प्रतिष्ठा की गई रिमा या सारनाइ पर, जैसा हफ्ता के कागज फीजरी सुदृष्टता नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार से वे शासकीय कार्रवाई में भाग ले सकते हैं।

(ग) रजिस्ट्रार यूनियन पर एक प्रकार की जिम्मेदारियाँ भी हैं। उस हर साल रजिस्ट्रार के पास सारनाइ आदि भेजने होते हैं और सूचनानामा का आर्गेंट किया हुआ पत्र भी देना होता है। कोई भी यूनियन का पदाधिकारी या सदस्य यूनियन के हितों की जाँचकर सकता है। यूनियन के नाम विधान और नियमों में अगर कोई परिवर्तन हो तो उसका गूना रजिस्ट्रार को भिजना चाहिये। यूनियन का नाम कोश किन किन बातों पर गवच हो सकता है यह कानून में तय है। इस संबंध में आचार्यजी ने एक नियम यूनियन का पढ़ना पड़े, शामिल है। अस्तु इन सब का अपना इस प्रकार के संपर्क पर भाव्य हो सकता है। सदस्यों के राजनैतिक उद्देश्य प्रति - जिस यह काय नाम नहीं आ सकता, पर हम काम के लिए अलग कायस्थापन किया जा सकता है। इसमें बाद देना न करना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर है। इन जिम्मेदारियों को नहीं निभाने से सजा नहीं जा सकती है चाहे वह अमान की शक्ति में हो या यूनियन के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की शक्ति में।

(घ) यह हम लिख चुके हैं कि १९४७ में टूट यूनियन एक्ट में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था। इसका अनुसार यदि कोई रजिस्ट्रार टूट यूनियन अपने मिल मालिकों को मान्यता के लिए आवेदन पर दे और फिर भी उस मान्यता न मिले तो उस दशा में उस यूनियन का यह अधिकार है कि वह इस विषय में लैबर कोर्ट (जो इस कानून के अनुसार नियुक्त की जा सकती है और जिनमें एक या अधिक नजद होते हैं) को लिखे लैबर कोर्ट यदि पांच के बाद इस निष्पत्ति पर पहुँचे कि टूट यूनियन उन समान बातों को पूरा करनी है जो मान्यता प्राप्त करने

के लिए आवश्यक है, और जिनमें से एक यह है कि वह यूनियन उस मिल-मालिक के यहां काम करने वाले सब मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती हो, तो उसे (लेबर कोर्ट को) मिल-मालिक को उस यूनियन को मान्यता देने के लिए आज्ञा देने का अधिकार है। जो मान्य ट्रेड यूनियन होती है उन्हें नियुक्ति, काम की परिस्थिति और शर्तों आदि मजदूरों सम्बन्धी सब मामलों में मिल-मालिकों से पूछताछ और फैसला करने का अधिकार होता है। उन्हें मिल के अन्दर अपने नोटिस आदि लगाने का अधिकार भी होता है।

(छ) दूसरी महत्वपूर्ण बात जो १९४७ के संशोधन के अनुसार हुई है वह यह है कि मान्य ट्रेड यूनियनों और मिल-मालिकों के लिए कुछ बातों को अनुचित घोषित कर दिया गया है। यूनियन (मान्य) के लिए जो बातें अनुचित घोषित की गईं हैं वे इस प्रकार हैं:—(१) यूनियन के सदस्यों के बहुमत का अनिवारित हड़ताल में भाग लेना, (२) यूनियन की कार्य-कारिणी का अनिवारित हड़ताल में सहयोग, सलाह या प्रोत्साहन देना, (३) यूनियन के पदाधिकारी द्वारा शान्त जानकारी देना। मिल-मालिकों के लिए जो बातें अनुचित माना गईं हैं वे ये हैं:—(१) मजदूरों द्वारा ट्रेड यूनियन आदि संगठन बनाने के मार्ग में, उसके काम में तथा उसे आर्थिक सहायता देने में रुकावट पैदा करना, (२) किसी व्यक्ति को जो मान्य ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी है, या जिसने मान्य ट्रेड यूनियन के अधिकारों के सम्बन्ध में कोई गवाही आदि दी है बरखास्त करना या उसके विरुद्ध पक्षपात करना, और (३) मान्य ट्रेड यूनियन के पत्रों आदि का उत्तर न देना या उसे मुलाकात न देना। यदि कोई यूनियन अनुचित बात करती है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है और मिल-मालिक पर एक इज्जत खपा तक जुर्माना हो सकता है।

(घ) एक्ट के पालन कराने का जिम्मा राज्यों पर है और वे इस काम के लिए रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन की नियुक्ति करते हैं। पर रजिस्ट्रार को ट्रेड यूनियन के रजिस्टर आदि आँखने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार फ़ानुल में संशोधन करके रजिस्ट्रार को दिया जाना चाहिये।

औद्योगिक संघर्ष—मजदूर-संगठन के सम्बन्ध में लिखते हुए हमने यह लिखा है कि प्रथम महायुद्ध के पश्चात् ही भारतीय मजदूर ने अपने आप को संगठित करने का विशेष प्रयत्न आरम्भ किया। औद्योगिक संघर्षों का इतिहास भी हमें यही बतलाता है कि भारतवर्ष में प्रथम महायुद्ध के बाद ही मजदूरों और मिल-मालिकों के संघर्ष का युग आरम्भ होता है। १९२४ में और १९२५ में और बाद में १९२८ और १९२९ में बम्बई में बहुत बड़ी-बड़ी आम हड़तालें हुईं जिनमें

लाभ मजदूरों ने भाग लिया। १९२६ का हड़ताल में पहली बार कम्युनिस्टों का प्रभाव प्रकट हुआ था। इन हड़तालों का एक परिणाम यह हुआ कि १९२६ में ट्रेड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट पास किया गया। इस नया इस जैसे दूसरे राज्यों का विलुप्त वणन हम आगे करेंगे। १९२७ में उन राज्यों में लोक प्रिय कांग्रेसी मंत्रिमन्त्रि स्थापित हुए तो फिर हड़तालों का बाढ़ सा आगई। तत्कालीन कांग्रेसी सरकारों ने मजदूरों की स्थिति की जांच करने के लिए जांच कमेटियाँ नियुक्त की (उ.प्र., बा.प्र., बिहार), लेकिन औपनिवेशिक नियुक्त किये गए और मजदूरों की स्थिति में सुधार करने की योजनाएँ भी बनाई गई। परन्तु मजदूरों की गरीबी न हुआ क्योंकि उनकी आसपास बहुत बड़ी हुई थी, और वास्तव में मजदूरों के लिए बहुत ही भी नहीं सका था। इससे अलावा मजदूर यह जानते थे कि कांग्रेसी शासन में उन पर दमन नहीं हो सकता। कांग्रेस के विरोधी राजनैतिक दल भी इस स्थिति का लाभ उठा कर मजदूरों को उकसाने में लगे रहते थे। कानपुर की १९३८ की आम हड़ताल, और बंगाल में अट की मिलों की आम हड़ताल (१९३८) इस समय की खास हड़तालों थी। गण महायुद्ध के शारम्भ होते ही कांग्रेसी मंत्रिमन्त्रियों ने स्वीकार दिया और मजदूर दिनकर कायों की उनकी योजनाएँ आगे नहीं बढ़ सकी। महायुद्ध के समय में (१९३९-१९४५) हड़तालों आदि की दृष्टि से देश में अपनाकृत शांति रही। इसका एक कारण यह था कि भारत का नियम के अंतर्गत मजदूरों पर कई प्रतिबंध थे, दूसरे कम्युनिस्ट और गणवादी मजदूर कार्यकर्त्ताओं ने युद्ध के समय का मजदूरों में बहुत प्रचार किया। यद्यपि १९४१ से हड़तालों की संख्या तो १५६ ने बढ़कर १९४२ में ६६४, १९४३ में ७५६, १९४४ में ६५८ और १९४५ में ८२० होगई, पर काम के दिनों में हानि की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। १९४१ में जहाँ ३३ लाख काम के दिनों की हानि हुई थी १९४५ में यह हानि ४० लाख दिन के लगभग थी। परन्तु युद्ध समाप्त हो जाने के उपरान्त जब नए चुनावों के अनुसार अधिकांश राज्यों में कांग्रेसी सरकारें स्थापित होगई तो फिर हड़तालों की संख्या बढ़ने लगी। नतीजा यह हुआ कि युद्ध के समय की अपना १९४६ और १९४७ में हड़तालों का संख्या और नाम के दिनों का हानि दोनों ही दृष्टियों से स्थिति बहुत बिगड़ गई। हड़तालों की संख्या १९४६ में, १९२६ और १९४७ में १८१२ होगई, और काम के दिनों के हानि का संख्या क्रमशः १ करोड़ २७ लाख और १ करोड़ ६३ लाख होगई। १९४७ के अप्रैल में हड़तालों की लहर अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी। उससे बाद उसमें उतार आया जो इस समय तक जारी है। हड़तालों के सम्बन्ध में दो एक बात और उल्लेखनीय है जिनका संकेत कर देना उचित है।

यदि हम प्रथम महाबुद्ध के बाद से अब तक के इन तीस वर्षों का हड़तालों सम्बन्धी अध्ययन करें तो हमें एक बात तो यह मालूम होगी कि कुल मिलाकर हड़तालें करने की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी है। हड़ताल में शामिल होनेवाले मज़दूरों की संख्या में भी यह वृद्धि देखी जाती है। हॉ पिछले दो या तीन वर्षों में इन दोनों बातों में सुधार देखने को मिलता है; पर इसका कोई स्थायी महत्व मानना ठीक नहीं हो सकता। एक बात और है कि हड़ताल करने की प्रवृत्ति में उसमें शामिल होनेवाले मज़दूरों की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह है कि अब हड़तालें ऐसे छोटे-छोटे उद्योगों और कार्यों में भी होने लगी हैं जिनमें पहले नहीं होती थी। हड़तालों के समय के बारे में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि अब हड़ताले उतनी लम्बी नहीं होती जितनी पहले होती थीं। मज़दूर-संगठन के विकास के बावजूद भी मज़दूरों की चौंका करने की शक्ति किसी हद तक कम होती गई है, क्योंकि मज़दूरों की संख्या बड़ी है, मिल-मालिकों का विरोध कम नहीं हुआ है और राष्ट्र की सहानुभूति में भी कमी आई है। फिर भी सरकार के हस्तक्षेप से मज़दूरों को बल मिला है। इसका असर हड़तालों के कारण मज़दूर को होनेवाली हानि में कमी होने का भी हुस्वा है।

हड़तालों के कारणों का यदि हम विरलेपक्ष करें तो हमें निम्नलिखित कारण मिलेंगे—वैतन-वृद्धि अथवा, वोनस या मेंहगाई-भत्ते सम्बन्धी मांग, व्यक्तिगत शिकायतें—जैसे मज़दूरों के साथ मिल-मालिकों का दुर्व्यवहार सम्बन्धी, या बरखास्तगी तथा छुटनी आदि सम्बन्धी, अन्य कोई विशेष आर्थिक परिस्थिति जैसे आर्थिक मंदी, वस्तुओं की मेंहगाई, रोज़गार की स्थिति आदि। पर अधिकतर हड़तालों का कारण मज़दूरों की वैतन वृद्धि सम्बन्धी मांग ही होती है। कभी-कभी राजनैतिक कारणों को लेकर भी हड़ताले हुई हैं, पर ऐसा बहुत कम हुआ है। उद्योग-धन्धों की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो मालूम पड़ेगा कि सूती, कनी और रेशमी कपड़े के उद्योग में सबसे अधिक हड़ताले हुई हैं। राज्यों की दृष्टि से बम्बई, मद्रास और बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में हड़तालों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रही है।

औद्योगिक शांति के प्रयत्न—हम यह लिख चुके हैं कि १९४७ में औद्योगिक अशांति बहुत बढ़ गई। उसका परिणाम यह हुआ कि देश में उत्पादन का मात्रा में भी बड़ी कमी आ गई। इस स्थिति की ओर भारत-सरकार का ध्यान गया और दिसम्बर १९४७ में उसने एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया जिसमें सरकार (केन्द्रीय और राज्यों की), मज़दूर और मिल-मालिक तीनों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस सम्मेलन में सर्व सम्मति से औद्योगिक शांति संबंधी एक प्रस्ताव पास किया

गया। इस प्रस्ताव में मजदूरों और पृथ्वीनिवासियों के आराम के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया और यह कहा गया कि मजदूरों को उचित मजदूरी और काम की परिस्थितियों प्राप्त हानी चाहिए और पृथ्वीनिवासियों को उचित भुनाका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य का पूर्ति के लिए सम्मेलन ने निम्न उपायों के बारे में सिफारिश की—(१) यदि मजदूरों और मिल मालिकों में कोई मतभेद उत्पन्न हो तो उनकी मिल चुप कर शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिये और हमक लिफ्ट ग्राहकों और दूसरों जो मा व्यवस्था हो उसका उपयोग करना चाहिये। नहीं ऐसी व्यवस्था न हो वहाँ सुरक्षा एनी व्यवस्था लकी बननी चाहिये। नहीं एक समय हो दस मर में एक मी व्यवस्था होना चाहिये। (२) उचित मजदूरी और काम की परिस्थितियों और पृथ्वी निवासियों के लिए उचित पुरस्कार सम्मेलन और निश्चय करने के लिए कन्ट्राय, प्रांशियर और एक्सेक्यूटिव व्यवस्था बननी चाहिए और उत्पादन सम्बंधी मजदूरी का सहयोग प्राप्त करने के लिए कन्ट्राय प्रांशियर और कारखाना धार उत्पादन समितियों स्थापित होनी चाहिए। (३) हर एक कारखाना में रोजमर्रा के मजदूरों की सुलझाने के लिए मजदूर और मिल मालिक के प्रतिनिधियों की 'वर्कर्स कमेटियों' कायम की जानी चाहिए। (४) मजदूरों के मकानों का समस्या हल करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और नहीं तब तक का सम्बन्ध है उसका मजदूर, मिल मालिक और सरकार में बनना होना चाहिए। मजदूर का हितवा उचित निरासे के रूप में वगल किया जाना चाहिए। अन्त में सम्मेलन ने मजदूरों और पृथ्वीनिवासियों से आर्थिक शान्ति कायम रखने की अपील की।

भारत सरकार ने तमाम शान्ति के सरकारी की उक्त प्रस्ताव के अनुसार कारवाई करने के बारे में लिखा। अप्रैल १९४८ में सरकार ने जो औद्योगिक नीति सम्बंधी प्रस्ताव स्वीकार किया उसमें भी औद्योगिक शान्ति सम्बंधी इस प्रस्ताव की स्वीकार किया गया। इस सम्बंध में सरकार ने जो व्यवस्था विभिन्न स्तर पर स्थापित करने का निश्चय किया वह इस प्रकार थी—पारे देश के लिए एक 'कन्ट्राय सलाहकार-समिति' हो और उसके नीचे प्रत्येक प्रमुख उद्योग क्षेत्रों के लिए एक कमिटी हो। इन कमिटियों की कई उप-कमिटियाँ हो सकती हैं जो सम्बंधित उद्योग क्षेत्र की अलग अलग समस्याओं के बारे में बनाई जाएँ—जैसे उत्पादन, औद्योगिक सम्बंध, मजदूरी सम्बंधी नियम, और काम का बंटवारा आदि। इसी प्रकार शान्ति में प्रांतीय सलाहकार मण्डल हो जो प्रांत मर के उद्योग का अपना क्षेत्र माने। उनके नीचे हर प्रमुख उद्योग के लिए प्रांतीय कमिटियाँ हों और इन प्रांतीय कमिटियों का और उप-कमिटियाँ

भी हो सकती है। प्रान्तीय कमेटियों के बाद प्रत्येक बड़े कारखाने में उत्पादन कमेटी और वर्क्स कमेटी भी स्थापित की जानी चाहिये। १९४८ में इंडियन लेबर कांग्रेस ने औद्योगिक शांति सम्बन्धी प्रस्ताव को पक्की तौर से स्वीकार कर लिया।

प्रश्न यह है कि उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या-क्या प्रयत्न अब तक हुए हैं। भारत सरकार ने इसी दृष्टि से एक विशेष पदाधिकारी सितम्बर-१९४८ में नियुक्त किया। बम्बई सरकार ने एक ट्रिब्यूनल इसीलिए बनाई कि वह यह देखे कि इस प्रस्ताव का उल्लंघन कहीं-कहीं होता है। पश्चिमी बंगाल और मद्रास ने भी औद्योगिक ट्रिब्यूनल की नियुक्ति की है। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय मजदूर-सलाहकार-परिषद् (सेन्ट्रल लेबर एडवाइजरी काउंसिल) की स्थापना कर दी है। इसमें सरकार, मजदूर, और मालिक नीनों के प्रतिनिधि हैं। एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद् (उद्योग धन्वे) की स्थापना भी की जा चुकी है। इसमें केन्द्रीय और राज्य की सरकारों, पार्लियामेंट, मिल-मालिकों के संगठनों, मजदूर-संगठनों और देश के प्रमुख उद्योग धन्वों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका काम औद्योगिक उत्पादन और उद्योग-धन्वों सम्बन्धी दूसरे मामलों में सरकार की सहायता करना है। कुछ प्रान्तों ने भी प्रान्तीय मजदूर-सलाहकार मण्डलों (प्रोविंशियल लेबर एडवाइजरी बोर्ड) की स्थापना की है। केन्द्रीय सरकार के कारखानों के मजदूरों को उचित मजदूरी और काम की परिस्थितियों प्राप्त हो सकें इस दृष्टि से भारत-सरकार ने एक विशेष ट्रिब्यूनल (केन्द्रीय कार्यालय कलकत्ता) स्थापित की है। राज्य की सरकारें भी मजदूर-नृजीपतियों के भगड़े अस्थायी संस्थाओं, एडजुटीकेटर या ट्रिब्यूनल्स के पास भेजती हैं ताकि मजदूरों को उचित मजदूरी और काम की परिस्थितियों मिल सकें। न्यूनतम मजदूरी कानून पास हो चुका है। फोवले की खानों में काम करने वालों के लिए प्रोविडेंट फंड की योजना का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। कई बड़े-बड़े उद्योगों के लिए तीनों पक्षों (सरकार, मालिक और मजदूर) के प्रतिनिधियों की औद्योगिक समितियाँ स्थापित हो चुकी हैं—जैसे सूती कपड़े की मिलें, वास, कोबला निकालने का उद्योग और सीमेंट-उद्योग। केन्द्रीय सरकार ने वर्म कमेटियाँ और उत्पादन कमेटियाँ स्थापित करने के लिए बड़े-बड़े बन्दरगाहों, खानों, तेल निकालने के स्थानों और केन्द्रीय सरकार के कारखानों आदि (रेलवे के अलावा) के मालिकों को आदेश दिये हैं। उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश की सरकारों ने भी इसी प्रकार के आदेश उन-तमाम कारखानों को, जो १९४७ के औद्योगिक संघर्ष कानून के अन्तर्गत आते हैं, भेजे हैं। केन्द्रीय मजदूर

सलाहकार परिषद् को उचित मजदूरी, पूँजी पर उचित मुद्रावृद्धि और अतिरिक्त लाभ में मजदूरों के हिस्से सम्बन्धी मामलों का निर्णय करने में सहायता देने के लिए भारत सरकार ने विभागों से पूँजी पर उचित पुरस्कार, मजदूर का अनिश्चित लाभ में हिस्सा, और वाणिज्य रक्षित क्षेत्र पर प्रारम्भिक अध्ययन कराना उचित समझा। अतः इन बातों पर विचार करो के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की (बमेटा ऑन प्रोफिट गवर्निंग) जिसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित हो चुकी है। केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के मामले जब यह रिपोर्ट पेश हुई (जुलाई १९४६) तो यह हम बात में कोई नियम नहीं दे सकी। हाँ उचित मजदूरी के बारे में जो कमेटी नियुक्त हुई उसकी रिपोर्ट परिषद् ने स्वीकार कर ली। इस समय (मार्च १९४७) उचित मजदूरी सम्बन्धी बिना संसद के सामने पेश है। इस बारे में अन्तिम प्रश्न यह है कि औद्योगिक शान्ति के प्रस्ताव का वास्तव में क्या परिणाम आया। १९४८ के औद्योगिक हड़तालों सम्बन्धी घाँवके देखने से पता लगता है कि इस रिषति में विशेष अन्तर हुआ है। १९४८ में कुल १२५६ हड़तालें हुई और ७८ लाख के लगभग काम के दिनों की हानि हुई जब कि १९४७ में हड़तालों की संख्या यद्यपि १८११ थी पर काम के दिनों का मुकामान एव करोड़ पैसठ लाख का हुआ जो १९४८ की अपेक्षा बहुत अधिक है। १९४८ के बारे में यह प्रवृत्ति जारी रही है। औद्योगिक शान्ति के प्रस्ताव के अन्तर्गत हड़तालों सम्बन्धी स्थिति में निम्नलिखित बातों में जो गुंथार हुआ है उसके कुछ कारण और भी हैं, जैसा—मजदूर संगठन पर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रभाव, रोजगार की असमोन्वयन स्थिति, कम्युनिस्टों का मजदूरों पर गिरता हुआ प्रभाव और अनिवार्य पैन निर्णय की पद्धति का बढ़ता हुआ उपयोग। अब हम औद्योगिक शान्ति के लिए जो-जो कानून पास हो चुके हैं उन पर थोड़ा विचार करेंगे।

केन्द्रीय औद्योगिक संघर्ष कानून—मजदूर और मालिकों के आपसी संघर्ष को सुलझाने के लिए भारत में सबसे पुराना कानून १८६० का एम्प्लोयर्स और वर्कमेन (डिस्प्यूट्स) एक्ट था। इस कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट को रेलवे, नहर और दूसरे सार्वजनिक कामों में लगे हुए मजदूरों के मजदूरी संबंधी झगड़ों को सुलझाने का अधिकार था, और प्रसविदा भग को फौजदारी संपराध माना गया था। यद्यपि हम कानून का उपयोग तो पहले ही बढ़ ही गया था, पर यह रद्द १९३२ में हुआ। सन् १९३६ में पाँच वर्ष के लिए औद्योगिक संघर्षों के सम्बन्ध में पड़ला कानून भारत सरकार ने 'ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट' के नाम से पारित किया। १९३४ में यह एक्ट रद्द कर दिया गया। सादी मजदूर कमीशन

ने जो इस सम्बन्ध में सुझाव दिये वे उनमें से भी कुछ इस समय इस कानून में शामिल कर-लिये गये थे। इस एक्ट में औद्योगिक संघर्ष को सुलझाने के लिए जॉच कचहरियों (कोर्ट ऑफ इन्कावरी) और समझौता मंडल (कन्सोलिडेशन बोर्ड्स) स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। सार्वजनिक सेवा से सम्बन्ध रखने वाले कारखानों में अचानक हड़ताल या द्वारावरोध न हो सके, इस उद्देश्य से हड़ताल या द्वारावरोध के लिए इन उद्योग-धन्यों में १४ दिन का नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया था। औद्योगिक संघर्ष के अलावा और किसी उद्देश्य से की जाने वाली हड़ताल या द्वारावरोध गैर कानूनी करार दिया गया था। १९३८ में इस कानून में संशोधन किया गया। इस संशोधित कानून के अन्तर्गत समझौता अफसर (कन्सोलिडेटिंग ऑफिसर्स) नियुक्त करने की व्यवस्था की गई जिनका काम मजदूर-मालिक के संघर्ष में बीच बचाव करना और उनके निपटारे में सहायता देना था। कानून का क्षेत्र भी पहले की अपेक्षा थोड़ा विस्तृत कर दिया गया। गैर कानूनी हड़तालों और द्वारावरोध के बारे में व्यवस्था थोड़ी ढीली कर दी गई।

गत महायुद्ध के समय इस कानून के कुछ दोष खास तौर से सामने आए। इस कानून में औद्योगिक कगड़ों को सुलझाने के लिए केवल अस्थायी व्यवस्था की गई थी। दूसरे जॉच कचहरी या समझौता मंडल के निर्णय अन्तिम और अनिवार्यतः लागू होने वाले नहीं थे। गत महायुद्ध के समय भारत रत्ना नियम के नियम ८१ ए के अनुसार जो दिसम्बर १९४२ में लागू किया गया था, सरकार को यह अधिकार था कि वह किसी भी कगड़े को निर्णय के लिए पेश करदे और जो भी निर्णय हो उसे कार्यान्वित करे। यह नियम अस्थायी था और भारत-सरकार इसे स्थायी बनाना चाहती थी। अस्तु, १९४७ में इंडस्ट्रियल डिस्पूट्स एक्ट पास किया गया। इसके मुख्य-मुख्य प्रावधान नीचे दिये गये हैं—

(क) भारत सरकार (संघीय रेलवे, केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित ध्वे, बड़े-बड़े बन्दरगाह, खान, तेल निकालने के स्थान) और राज्य की सरकारों को अपने-अपने क्षेत्र में यह अधिकार है कि वह किसी भी कगड़े को जॉच कचहरी के पास जॉच के लिए, समझौता मंडल के पास समझौते के लिए, और औद्योगिक ट्रिब्यूनल के पास निर्णय के लिये भेज दें। यदि किसी कगड़े का संबंध सार्वजनिक सेवा से संबंध रखने वाले ध्वे से है और उसका नोटिस दे दिया गया है तो उस कगड़े को ट्रिब्यूनल के पास भेजना अनिवार्य है; जब तक कि सरकार यही न समझे कि ऐसा करना अनुचित होगा या जो नोटिस दिया गया है वह निरर्थक है। यदि किसी कगड़े से संबंधित दोनों पक्ष यह माँग करें कि उनका कगड़ा कोर्ट

बोर्ड या ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाना चाहिये तो सरकार को उसे भेजना होगा। जब मामला ट्रिब्यूनल या बोर्ड के पास है तो सरकार इजलास या दारारतों के रास्ते की मनाही कर सकती है।

(ख) सम्बन्धित सरकारों को यह भी अधिकार है कि वे किसी भी वयस, उर्ध्व १०० या अधिक व्यक्ति काम करते हैं वयस कमिटी बनाने का आदेश दे दें। इन कमिटीयों में मजदूरों और मालिकों के बराबर प्रतिनिधि होने चाहिये और इनका काम मजदूर और मालिकों में अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने का प्रयत्न करना और किसी भी मामले में इस दृष्टि से आपसी मत भेद को दूर करना है।

(ग) संबन्धित सरकार को किसी भी स्थान या उद्योग के लिए स्थायी और पर या अस्थायी निश्चित समय के लिए समझौता आदेश निरुक्त करने का भी अधिकार है। इनका काम कगड़ों को मिलाने कर मुलभूतों का प्रयत्न करना है। समझौता अक्षम के लिए यह प्रतिपादित है कि सावधानिक सेवा से सम्बन्ध रखने वाले पक्षों में होने वाले कगड़ों को यदि आपस में नोटिस दे दिया गया है तो सुलझाया जा प्रयत्न करें। समझौता आदेश का कर्तव्य है कि समझौते के समय में जो भी कारवाई की गई है उसका सरकार को कारवाई आरम्भ होने से उपादा से ज्यादा १५ दिन में रिपोर्ट करे। अगर समझौते की कारवाई असफल रहे तो सरकार उन मामले को चाहे तो बोर्ड या ट्रिब्यूनल के पास भेज सकती है। यदि सरकार ऐसा न करे तो सम्बन्धित पक्षों को ऐसा नहीं करने का कारण बतलाया जाना चाहिये।

(घ) संबन्धित सरकार की आवश्यकता होने पर समझौता बोर्ड निरुक्त करने का अधिकार है। समझौता बोर्ड में एक स्वतंत्र अध्यक्ष और मजदूर और मालिकों के बराबर बराबर प्रतिनिधि, जिसकी मिलाकर सख्या दो या चार हो, होना आवश्यक है। सदस्य संबन्धित पक्षों की सिफारिश पर नियुक्त किये जाते हैं। उनका काम वही है जो समझौता अक्षमों का। परन्तु समझौते की कारवाई के असफल होने पर बोर्ड को रिपोर्ट में समझौते संबंधी अपनी सिफारिशों भी देनी होती है। यदि सरकार सावधानिक सेवा में सम्बन्ध रखने वाले पक्षों के कगड़ों को समझौते की कारवाई के असफल होने पर भी ट्रिब्यूनल के पास नहीं भेजती है तो संबंधित पक्षों को इसका कारण बताना होगा। समझौते बोर्ड की साधारणतया दो महीने में अपनी रिपोर्ट दे देनी चाहिये।

(ङ) संबन्धित सरकार को आवश्यकता होने पर किसी कगड़े की जाँच करने के लिए कोर्ट निरुक्त करने का अधिकार है। कोर्ट में एक या एक से अधिक स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं और एक से अधिक व्यक्ति होने पर उनमें से एक अध्यक्ष

होता है। कोर्ट का काम जो मामला उसके सामने आवे उसके बारे में जांच करके छह महीने में सरकार को रिपोर्ट दे देना है।

(च) संबंधित सरकार को औद्योगिक मजदूरों-संबंधी निर्णय देने के लिए ट्रिब्यूनल नियुक्त करने का अधिकार है। ट्रिब्यूनल में एक या एक से अधिक स्वतंत्र व्यक्ति, जो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं या रह चुके हैं, सदस्य होते हैं। हाई कोर्ट की स्वीकृति से वे व्यक्ति भी ट्रिब्यूनल में नियुक्त किये जा सकते हैं जो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हैं। ट्रिब्यूनल का निर्णय दोनों पक्षों के लिए मानना आवश्यक है। यदि सरकार स्वयं किसी झगड़े में एक पक्ष के तौर पर है तो ट्रिब्यूनल का निर्णय धारा सभा के सामने जायगा यदि सरकार उसे लागू करना ठीक नहीं समझती है और धारा सभा का जो भी निर्णय होगा—रद्द करने का, संशोधन करने का या स्वीकार करने का—वह सरकार को मानना होगा।

(छ) कानून में गैर कानूनी हड़ताल और द्वाराबरोध की भी व्याख्या की गई है। उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक सेवा के धंधों में नियमित नोटिस न देने पर और नोटिस देने के १४ दिन के अन्दर-अन्दर या समझौता कार्रवाई जब समझौता अफसर के सामने चल रही है उस समय में और उस कार्रवाई के समाप्त होने के बाद सात दिन पहले, हड़ताल या द्वाराबरोध करना गैर कानूनी है। इसी प्रकार से सब धंधों के बारे में ग्राम प्रतिबंध है कि यदि बोर्ड के सामने समझौते की कार्रवाई चल रही है तो उस बीच में अथवा समझौता की कार्रवाई समाप्त होने के बाद सात दिन से पहले, ट्रिब्यूनल के सामने मामला पेश हो तब और कार्रवाई समाप्त होने के बाद दो महीने पहले, या उस समय में जब कोई निर्णय लागू है, हड़ताल या द्वाराबरोध होगा तो वह गैर कानूनी होगा। गैर कानूनी हड़ताल या द्वाराबरोध को आर्थिक सहायता देने की भी मनाही है।

कानून में गैर कानूनी हड़ताल या द्वाराबरोध करने और उनको प्रोत्साहन देने और निर्णय को भंग करने आदि के अपराधों के लिए दण्ड का विधान भी किया गया है। जब बोर्ड, ट्रिब्यूनल, या समझौता अफसर के सामने कोई कार्रवाई चल रही हो तो कोई मालिक किसी मजदूर को बिना बोर्ड, ट्रिब्यूनल या समझौता अफसर की लिखित स्वीकृति के न बरखास्त कर सकता और न सजा दे सकता है, जब तक कि उसके अनुचित व्यवहार का संबंध झगड़े के अलावा किसी दूसरी बात से न हो।

इस कानून को कार्यान्वित करने के लिए सम्बन्धित सरकारों ने नियम भी बनाये हैं।

इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स (एपिलेट ट्रिब्यूनल) एक्ट १९४०—इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट १९४७ में एक यह दोष था कि विभिन्न ट्रिब्यूनलों में समन्वय करने वाली देश भर के लिए कोई एक संस्था न थी। जिन उद्योगों का कारबार एक से अधिक राज्यों में फैला था उनको अलग अलग ट्रिब्यूनलों के परस्पर विरोधा और एक दूसरे से भिन्न निष्कर्षों से विशेष कठिनाई होती थी। अस्तु, इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह कानून पास किया गया है। यह देश भर के लिए एक एपिलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना करता है।

इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टैंडिंग आर्डर्स) एक्ट १९४६—यह कानून गहरे धरा में लागू होता है और १०० या अधिक व्यक्ति जहाँ काम करते हैं वे स्थान हमेशा आगतगत आते हैं। जिन उद्योगों पर बम्बई इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट का पाँचवा परिच्छेद लागू होता है उन पर यह एक्ट नहीं लागू होगा। कन्द्रीय और राज्य की सरकारों को इसमें हस्तक्षेप को बढ़ाने का और किसी चीजों को उत्तम मुक्त करने का अधिकार है। इस कानून का उद्देश्य ऐसे स्थायी नियमों का निर्माण करना है जो सरकार द्वारा स्वीकृत किये जायें और जो मजदूरों और मालिकों के परस्पर सम्बन्धों और काम की परिस्थितियों का नियंत्रण करते हैं।

राज्य के औद्योगिक संघर्ष सम्बन्धी कानून—कई राज्यों ने भी औद्योगिक संघर्ष सम्बन्धी कानून अपनी विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पास किये हैं। बम्बई सरकार ने इस मामले में पहले का भी और १९३४ में एक कानून पास किया था। १९१८ में उसने स्थान पर दूसरा कानून पास किया गया। फिर १९४७ में बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध कानून पास हुआ जो इस समय भी लागू है। १९४८ में इस कानून में कुछ संशोधन किये गए थे। इस एक्ट का उद्देश्य औद्योगिक शांति स्थापित करना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक्ट में मालिक और मजदूर की सम्मिलित समितियाँ (ज्वाइंट कमिटी) स्थापित करने की, कगका होने की हालत में अनिवार्य विचार विनिमय और बात चीत द्वारा (निश्चय के लिए सात दिन का समय निश्चित किया गया है) कगका सुलभाने के प्रयत्न करने की और यदि यह प्रयत्न सफल न हो तो समझौता के लिए समझौता-अपसर और समझौता ब्रेक स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। इसने अलावा एक्ट में अन्तिम प्रयत्न के रूप में पंच निष्पत्ति (आरबीट्रेशन) के लिए भी व्यवस्था है। यह पंच निर्णय दोनों पक्षों के चाहने पर तो अनिवार्य निष्पत्ति के लिए लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल कोर्ट के पास भेजदे। अस्तु, अनिवार्य पंच निष्पत्ति (आरबीट्रेशन) का सिद्धान्त इस एक्ट में भी स्वीकार कर लिया गया

है। इन्डस्ट्रियल कोर्ट (कोर्ट फॉर इन्डस्ट्रियल आरबीट्रेशन) मामूली तौर से अपील कोर्ट का काम करती है और रजिस्ट्रार, लेबर कमिश्नर और लेबर कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती है। यदि कोई समझौता-अफसर (कन्सोलिडेटर) या समझौता-मंडल इसके पास कोई मामला भेजे तो उसका निर्णय करना भी कोर्ट का काम है। एक्ट में लेबर ऑफिसर और कोर्ट ऑफ इन्कायरी की नियुक्ति संवली धाराएँ भी हैं। १९४८ में जो संशोधन किया गया था उसके अनुसार मजदूर-मंडलों (वेज बोर्ड्स) की स्थापना भी की जा सकती है। इनका काम समस्त उद्योग से सम्बन्ध रखनेवाली ऐसी आम समस्याओं पर विचार करना है जैसे मजदूरी का प्रमापी करण (स्टेन्डर्डिजेशन), वैशानिकन (रेशनलाईजेशन), कार्य की दक्षता आदि। प्रत्येक उद्योग के लिए राज्य भर में एक वेज बोर्ड स्थापित किया जा सकता है और इसमें मजदूरों और मालिकों के बराबर की संख्या में प्रतिनिधि तथा कुछ स्वतन्त्र व्यक्ति सदस्य होते हैं। इन्डस्ट्रियल कोर्ट को अधिकार है कि वेज बोर्ड पर सामान्य नियंत्रण रखे। वेज बोर्ड के निर्णयों की अपील इन्डस्ट्रियल कोर्ट के सामने की जा सकती है। एक राज्य भर के लिए वेज बोर्ड नियुक्त करने की भी एक्ट में व्यवस्था की गई है। इसका काम सब उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर विचार करना है। हड़ताल द्वारा विरोध आदि अन्य बातों के बारे में भी इस एक्ट में प्रावधान है।

मध्य-प्रान्त और उत्तर-प्रदेश में भी इन्डस्ट्रियल डिस्पूट्स एक्ट लागू है जो १९४७ में पास किये गये थे। मध्य प्रान्त के कानून में भी अन्य बातों के अलावा वर्क्स कमेटी, लेबर कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविन्शियल इन्डस्ट्रियल कोर्ट, समझौता और पंच निर्णय [आरबीट्रेशन] संवली धाराएँ हैं।

उत्तर प्रदेश के एक्ट में सरकार को हड़तालों और द्वारावरोध रोकने के लिए आम अधिकार दिया गया है और इन्डस्ट्रियल कोर्ट आदि स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह (१) हड़ताल या द्वारावरोध पर आम प्रतिबन्ध लगाने या किसी अगड़े विशेष के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाने, (२) मजदूरी और मिल-मालिकों को काम की अधिक शर्तों और परिस्थितियों को स्वीकार करने, (३) इन्डस्ट्रियल कोर्ट्स नियुक्त करने (४) किसी अगड़े को समझौता या निर्णय के लिए पेश करने (५) सार्वजनिक सेवा के धंधे को काम करते रहने और बन्द न होने देने और उन पर नियंत्रण स्थापित करने (६) तथा दूसरे संबंधित मामलों के बारे में आदेश जारी कर सकें।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि श्रीयोगिक शांति कायम करने के

त्रिपक्षीय और राज्य की सरकारों ने क्या-क्या कानून पास किये हैं। अधिकांश राज्यों में केन्द्रीय और राज्य के कानून के अनुसार जो संगठन स्थापित होना चाहिये वह स्थापित किया जा चुका है। चण्ड, आत्म विभिन्न स्थानों में औद्योगिक मादक को रोकने और मुक्तकाने के लिए वर्कर्स कोमेटीय, ज्वाइंट कोमेटीय [वर्कर्स] लेबर आडिशन, कमीजियशन आनिगम, तथा पंच नियम के लिए लेबर कोर्ट्स और इन्डस्ट्रियल कोर्ट्स नाम कर रहा है। बम्बई में नेम बोर्ड नामक किय गये हैं। केन्द्रीय और राज्य की सरकारों द्वारा व्यवसायी इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की स्थापना भी की जाती है। स्थायी इन्डस्ट्रियल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल का भी कई जगह स्थापना की गई है। केन्द्रिय सरकार ने दो स्टैंडिंग ट्रिब्यूनल घोषणा और कलकत्ते में स्थापित किये हैं।

आधुनिक धर्म की दृष्टि से पिछले वर्षों में जो कानून पास किये गए हैं उनमें सम्बन्ध में मजदूर नताओं का पूरा खोज नहीं रहा है। औद्योगिक धर्म का प्रथम मुक्तकाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि कारखानों के अन्दर पत्नी व्यवस्था हो लोकि गुणवत्ति और मजदूर के सम्बन्धों में बहुत न आने दे। यदि कोई मजदूर मर जाय तो उसे मुक्तकाने का शौचालय भीम प्रदान किया जाए। वर्कर्स कोमेटी की स्थापना इस दृष्टि से एक बड़ी दिशा का और उदाहरण दिया जाय है। परन्तु अभी तक इनकी भी आस्थातीन सफलता नहीं मिली है। प्रायः मजदूर-संग इनकी अपना प्रतिद्वन्दी समझते हैं और इनकी सहयोग नहीं देते हैं। परन्तु जो कानून पास किये गए हैं उनका एक परिणाम यह भी हुआ है कि मजदूरों का हकनाल करने का अधिकार किसी भी मजदूर को नहीं दिया गया है। क्योंकि जब तक मतभौते की बात चले रही हो और इस प्रकार के साधनों का पूरा-पूरा उपयोग न कर लिया जाए, हकनाल करना और कानूनी हो जाना है। इसका अलावा इन कानूनों में अतिबाध एवं नियम का भी व्यवस्था की गई है। मजदूर-वर्ग इन बातों का विरोध करता है और इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था को मजदूर हित के विरुद्ध मानता है। मजदूरों का यह दृष्टिकोण सचवा सत्यमान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हकनाल को बहुत कुछ सफलता इस बात पर निर्भर रहनी है कि वह एक मनोवैज्ञानिक योके पर धारण करदी जाए। यदि हकनाल बहुत समय तक समझौता आदि के चक्कर में टल जाए तो फिर उसका सफलता की आशा कम हो जाना है। पर इसी के साथ यदि हम व्यापक दृष्टि से विचार करें तो हमें मालूम होगा कि हकनाल का प्रभाव समाज के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। इसलिये इस अर्थ का आसानी से उपयोग करना भी उचित नहीं हो सकता। इस सब विवाद का कारण यह है कि जो

हड़ताल-कानून पिछले वर्षों में हमारे देश में बने हैं वे इस व्यापक दृष्टि से तो उतने आपत्तिजनक नहीं कहे जा सकते जितना कि मज़दूर-नेता उनके बारे में कई बार प्रचार करते-माहूम पड़ते हैं। पर यदि हम मज़दूरों का दृष्टि से विचार करें तो उनको असंतोष जनक मानना कोई बहुत अनुचित नहीं है।

ट्रेड यूनियन और मज़दूर सम्बन्धों संबंधी प्रस्तावित कानून—मज़दूरों से सम्बन्ध रखने वाले दो अत्यन्त महत्वपूर्ण कानून इस समय भारतीय संसद के विचाराधीन हैं। इनमें से एक है 'लेबर रिलेशन्स बिल' और दूसरा है 'ट्रेड यूनियन एक्ट (एमेंडमेंट) बिल'। ये दोनों प्रस्तावित कानून १९५० के बजट सेशन में पेश किये गये थे और इस समय इनके सम्बन्ध में सेलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट संसद के सामने है।

इन दोनों प्रस्तावित कानूनों को लेकर देश में बहुत अधिक विवाद चला है और सरकार की कड़ी आलोचना की जा रही है। विशेषता यह है कि यह आलोचना मज़दूर और पूँजीपति दोनों ही पक्षों की ओर से की जा रही है। जबकि मज़दूर-पक्ष इन प्रस्तावित कानूनों को मज़दूर-हितों और मज़दूर-संगठन के लिए घातक मानता है, सरकार का यह कहना है कि इनका उद्देश्य मज़दूर-हितों की रक्षा करना, उनमें स्वस्थ संगठन की प्रोत्साहित करना, और पूँजीपतियों और उनमें न्याय संबंध स्थापित करना है।

पहले हम लेबर रिलेशन्स बिल के बारे में विचार करेंगे। इसका उद्देश्य मज़दूर-पूँजीपति-सम्बन्धों में समस्त देश में समानता लाने का प्रयत्न करना है। इस समय केन्द्रीय तथा अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग कानूनों के होने से कई प्रकार की उलझनें और विरोधाभास उत्पन्न हो जाते हैं। अतः, इस कानून का एक उद्देश्य देश भर में समान आधार पर मज़दूर-सम्बन्धों की स्थापना करना है। और दूसरा उद्देश्य मौजूदा कानूनों में जो भी कमियाँ हैं उनको दूर करना है। इस प्रस्तावित कानून का खेव बहुत ही व्यापक रखा गया है। न केवल औद्योगिक और व्यापारिक बल्कि सब प्रकार की संस्थाओं (इन्स्टिट्यूट) पर जिसमें दस वा अधिक व्यक्ति काम करते हैं, और सब प्रकार के कर्मचारियों पर (राज-कर्मचारी, फ़ील्ड में काम करने वाले और घरेलू काम करने वाले लोगों को छोड़कर) यह बिल लागू होता है।

इस बिल की जिन मुख्य-मुख्य धाराओं पर विवाद है वे इस प्रकार हैं। इस बिल में मज़दूरों के हड़ताल करने संबंधी अधिकार पर कुछ मर्यादाएँ लगाई गई हैं। जैसे मज़दूरों और मालिकों दोनों के लिए हड़ताल या द्वारावरोध के पहले नोटिस देना आवश्यक है, और नोटिस आने के बाद सात दिन के अन्दर

जिनको नोटिस मिलता है उस समकालीन की बात बात शुरू कर देनी चाहिये। एक निश्चित समय में वह बात चीत बनाता कर देना आवश्यक है और ऐसा नतीजा दानों पक्ष में समझना ही का यदि न था व ना हकना व शराबाय दिया जर सकता है। सर्वजनिक सेवा से सम्बन्ध रखने वाले धर्मों में हकना व शराबाय के लिए १५ दिन का नान्मि गता अनिवार्य है। यदि कोई मानने किसी लेजर कोट या ट्रिप्लन व पाग भय दिया जाय तो हकना व शराबाय है। इस तरह से यदि सिमा पक्ष गिण्य व लागू होने व समय हकना की बार तो वह भी और बातों हागी। दूसरी विवादमस्त द्वारा अनिवार्य पंच नियम व सिद्धान्त से संबंध रखती है। जिन में अनिवार्य पंच गिण्य व सिद्धान्त का स्वीकार किया गया है जैसा कि हम संबंधी मौजूदा कानून में भी है। तीसरी धारा जिन पर आसति की जानी है वह यह है कि मिल मालिक को यह अधिकार दिया गया है कि 'वाम काम' की नीति की वह वाकायना एक भगवा घोषित करावे। पर वह अधिकार मजदूरों को मिल-मालिकों व विपक्ष भी दिया गया है। जिन में सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह किसी भी ट्रिप्लन व गिण्य को बदलने या रद्द करे। इसका भी बहुत विरोध किया जा रहा है कि यह ला-माय में सरकार का हस्तक्षेप करना जैसा होता है। यदि किसी उचित कारण से किसी मजदूर का मिल मालिक अलग कर दे या धानर्यकता से अधिक मजदूरों को छुटना करवा जाए, तो हम जिन में ये दानों बाते भगवा के अन्तर्गत नहीं माना गई हैं। यद्यपि मिल मालिक इसमें मजदूर हैं पर मजदूरों को इससे विरोध है क्योंकि उनका यह कहना है कि इसका अर्थ तो यह है कि मजदूरों की छुट्टी को लेकर तो हकना का ही नहीं आ सकता। उपर्युक्त कारणों को लेकर मजदूरों की ओर से इस विषय का बड़ा विरोध किया जा रहा है। पर कुछ बाबाएँ ऐसी भी हैं जिनका पूज्यरति खास तौर से विरोध करते हैं। जैसा व इस बात का विरोध करते हैं कि इस कानून का औद्योगिक और व्यापारिक कारवायों के अन्तर्गत दूसरे सरनाओं पर भी लागू किया जाय और मजदूरों व अन्तर्गत दूसरे उच्च वर्ग के कमचारी, जैसे-मैनेजर आदि भी इस कानून के अन्तर्गत आवें। पूजायनियों को हम मान ले भी बहुत आपत्ति है कि ट्रिप्लन का किसी भी बरखास्त किए गए कमचारी का दुबारा काम पर लगान का अधिकार हो। हम जिन में यदि कोई हकना और कानूनी नहा है तो हकना व समय का मजदूरों का उनकी मजदूरी का ३ भाग तक अलाउंस व रूप में दिलाव जाने की व्यवस्था है। पूजायनियों इसका भी विरोध में है। जिन में सरकार को कि-ही विजय परिस्थितियों में यह अधिकार भी दिया गया

है कि वह किसी उद्योग विशेष पर निर्णय को लागू करने की दृष्टि से ही उस उद्योग को अपने निर्वन्धन में लेले। ऐसा तभी हो सकता है जब समाज के जीवन के लिये किन्हीं धर्मों का चलना आवश्यक समझा जाय। उपर्युक्त विवेचन 'लेबर-रिलेशनस बिल' से संबंध रखता है।

जहाँ तक ट्रेड यूनियन सम्बन्धी बिल का सम्बन्ध है, कुछ बातों को लेकर विशेष रूप से विरोध किया जा रहा है। एक तो यूनियन की कार्य-कारिणी में बाहर के (गैर मजदूर) लोगों की संख्या के बारे में विवाद है। मजदूर-नेता यह संख्या ५० प्रतिशत तक चाहते हैं जबकि बिल में २५ प्रतिशत या चार-आँ भी कम हो सकती, व्यवस्था है। मजदूर-पक्ष यह भी नहीं चाहता कि यूनियन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार रहे। राज-कर्मचारियों को हड़ताल करने के अधिकार से वंचित रखने का जो प्रस्ताव बिल में किया गया है उसका भी विरोध किया जा रहा है। मिल-मालिकों का यह भी कहना है कि मजदूरों को शलत जानकारी देने के अपराध में जेल की सजा होनी चाहिए।

इन दोनों महत्वपूर्ण बिलों का कितना विरोध किया जा रहा है उनको देखते हुए यह कहना कठिन है कि उपर्युक्त धाराओं में से किल-फिल में कितना संशोधन होगा। सेलेक्ट कमेटी ने इस विवाद का कितना असर लिया है यह अभी मालूम नहीं है। यदि कुछ सिद्धान्तों को बातों को स्वीकार कर लिया जाता तो फिर विभिन्न पक्षों में समझौता होना इतना कठिन नहीं है। इन सिद्धान्तों की बातों में हड़ताल सम्बन्धी अधिकार पर मर्यादा, अनिवार्य पंच-निर्णय का सिद्धान्त प्रमुख है। अभी जो कानून लागू हैं उनमें भी इन सिद्धान्तों को स्वीकार किया जा चुका है। यदि हम देश के आर्थिक संगठन का एक वर्ग विरोध की दृष्टि से निर्माण नहीं करना चाहते और सरकार पर प्रगतिशील तत्वों का पूरा प्रभाव रहता है, और प्रत्येक वर्ग अपने संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठने के लिये तैयार है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इन प्रस्तावित कानूनों में जो मूल भूत सिद्धान्त हैं वे आपत्तिजनक नहीं कहे जा सकते।

अन्तर्राष्ट्रीय तथा दूसरी समितियों और सम्मेलनों में भारतीय मजदूर का प्रतिनिधित्व—इस बारे में हमने पहले लिखा है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संगठन का आरम्भ से ही सदस्य है। इस संगठन की स्थापना प्रथम महाभुज के पश्चात् वासॉई की सन्धि के अनुसार की गई थी। इस संगठन के तीन मुख्य अङ्ग हैं—अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-कार्यालय, संचालक मण्डल ('गवर्निंग बोर्ड'), और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन। संचालक मण्डल में ३२ सदस्य हैं—१६ सरकारी प्रतिनिधियों में से चुने जाते हैं और ८ मिल-मालिकों की ओर से और बाकी ८

मजदूरों को श्रम से। १६ सरकारी स्थानों में से ८ स्थान सबसे प्रमुख ८ औद्योगिक राष्ट्रीय के लिए स्थायी और से सुरक्षित हैं। इनमें से एक स्थान भारत का भी है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में सदस्य राज्यों के सरकार, मिल-मालिक और मजदूर तीनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर मंच के ६८ कन्वेंशन (प्रस्ताव) में से भारत ने अभी तक १७ कन्वेंशन्स स्वीकार किये हैं। पिछले दशकों में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन में प्रादेशिक मजदूर सम्मेलन करने का नए नीति का विकास हुआ है। १९४७ में भारत सरकार के निमन्त्रण पर दो प्रादेशिक एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन (ट्रिपार्टीटरी एशियन रीजनल कांफ्रेंस) दिल्ली में हुआ था, वह एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन का तैयारी के लिये ही हुआ था। एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन जनवरी १९५० में लका में हुआ था। अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर मंच के काम को ठमके द्वारा स्थापित औद्योगिक समितियाँ न भी सहायता मिलता है। इनमें से कई समितियों का भारत भी सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर मंच समय समय पर अस्थायी सम्मेलन और समितियाँ भी बुलाता रहता है। इनमें भी भारत हिस्सा लेता है। सामुद्रिक समस्याओं पर विचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर मंच के विभिन्न अधिवेशन होते हैं और सामुद्रिक प्रश्नों पर मरालक मंडल की सलाह देने के लिए एक सम्मिलित सामुद्रिक कमिशन है जिस पर नौकराने के मालिक और जहाज पर कानून करने वाले मजदूर दोनों के प्रतिनिधि होते हैं।

भारतीय मजदूर सम्मेलन—अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन का तरह भारत में भी एक भारतीय मजदूर सम्मेलन हर वर्ष होता है जिसमें सरकार, मजदूर और मिल मालिक तानों ही पक्षा के प्रतिनिधि होते हैं। मजदूरों सम्बन्धी सब समस्याओं पर इस सम्मेलन में विचार होता है। इसका अलावा एक स्थायी मजदूर समिति भी है जो वर्ष में भारत सरकार के निमन्त्रण पर एक से अधिक बार मिलती है। इस त्रिपक्षीय संगठन (ट्रिपार्टीटरी मशीनरी) का आरम्भ १९४९ में ही हो गया था। अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर मंच की तरह भारत सरकार ने भी अलग-अलग उद्योग वर्गों के लिए औद्योगिक समितियाँ नियुक्त करने की नीति स्वीकार कर ली है। अस्तु, सबसे पहली कमटी बातों के धारे में स्थापित हुई थी और उसकी पहली बैठक जनवरी १९४७ में हुई थी। अब तो और उद्योगों के लिए भी इस कमेटियों का स्थापना का जा चुकी है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि किस प्रकार भारत सरकार मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है और राज्य की सरकारों का भी इस ओर ध्यान रहा है। राज्य की सरकारों, मजदूरों और मिल मालिकों में विचार विनिमय करने और ठमके सहयोग से भारत

सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए एक पंच वर्षीय योजना सन् १९४६ में बनाई थी। आज उसी योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है, और काफी हद तक वह कार्यान्वित भी की जा चुकी है।

परिच्छेद ७ संगठित उद्योग-धन्ये

सूती वस्त्र मिल उद्योग—भारत के आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग धन्यो, में सूती वस्त्र-मिल उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग है। देश के फैक्टरी उद्योग में कुल ३० लाख के लगभग लोग काम करते हैं। इनमें से लगभग ८ लाख आदमी सूती वस्त्र की मिला में काम करते हैं। इन मिलों की कुल संख्या १६६ है जिनमें ८८ सिर्फ सूत का उत्पादन करती हैं और शेष २७८ सूत और कपड़ा दोनों का उत्पादन करती हैं। १०० करोड़ रुपये की स्थायी पूंजी (ब्लॉक कैपिटल) इस उद्योग में लगी हुई है। और लगभग २५० करोड़ रुपये का सालाना उत्पादन है। देश की कपड़े की कुल मांग का दो तिहाई से अधिक भाग इन मिलों द्वारा ही पूरा होता है। इनकी औसत सालाना पैदावार लगभग ४५० करोड़ गज कपड़ा और १४० करोड़ पाउंड सूत है और अधिकतम उत्पादन शक्ति ५०० करोड़ गज कपड़े और १५०-१६० करोड़ पाउंड सूत का माना जा सकती है। १ करोड़ से अधिक तनुए (स्पिन्नेस) और २ लाख से लगभग करीब इन मिलों में चलते हैं। कपाम की साल भर में ५० लाख गांटों का खपत होती है। दुनिया के सूती वस्त्र मिल उद्योग में तनुए और कपड़ों की दृष्टि से भारत का स्थान पाचवाँ और कपास की खपत की दृष्टि से चौथा है। साथ उद्योग के बाद राष्ट्रीय महत्त्व की दृष्टि से दूसरा स्थान इस उद्योग का है। सारांश यह है कि सूती वस्त्र मिल उद्योग इस देश का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धंधा है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह पूंजी और प्रबंध दोनों की दृष्टि से ही आरम्भ से भारतीय हाथों में रहा है। अब हम इसी के विषय में आगे की पंक्तियों में लिखेंगे।

प्रारम्भिक इतिहास—इस धंधे का इतिहास सो वर्ष पुराना है। इसका आरम्भ १८५१ में हुआ जब बम्बई में श्री कोंबासजी नाना भाई डावर नाम के एक पारसा सज्जन के एक सूत की मिल की योजना बनाई और १८५४ में इस मिल ने काम करना भी आरम्भ कर दिया। इसके कुछ वर्षों पश्चात् अमरीका का गृह-युद्ध आरम्भ होगया और इंग्लैंड में भारत के कपास की मांग बढ़ गई तथा कपास का मूल्य भी बढ़ गया। इसलिए कुछ वर्षों तक इस उद्योग की प्रगति धीमी रही। परन्तु अमरीका के गृह युद्धों के समाप्त हो जाने के बाद कपास के निर्यात से जो रुपया कमाया गया था वह देश के उद्योग-धन्यो में लगाने लगा और सूती कपड़ों की मिलों की संख्या भी बढ़ने लगी। १८७६ में सूती कपड़ों के मिलों

की संख्या ४७ तक पहुँच गई थी। इस समय के सूती उद्योग के प्रमुख लक्षण ये थे:—कपड़े की अपेक्षा सूत के उत्पादन की प्रधानता; बम्बई शहर और द्वीप में उद्योग का स्थानीयकरण; चीन को निर्यात होनेवाले सूत पर उद्योग की निर्भरता और आन्तरिक बाज़ार की अवहेलना। पूँजी की सुविधा, सस्ते और तेज यातायात के साधन और चीन के बाज़ार को निकटता के कारण इस उद्योग का बम्बई में स्थानीयकरण हुआ।

१८५५-१८६०—उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश के पहले १५ वर्षों में (१८५५-१८६०) इस उद्योग के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं आई और उसका अच्छा विस्तार हुआ। पर बाद के दस वर्षों में कई प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं। इंग्लैंड के वस्त्र-उद्योग के (लकाशायर और मैनचेस्टर के) व्यवसायी भारत में इस उद्योग की उन्नति माला कैसे देख सकते थे। उन्होंने इसका विरोध किया। उस समय की विदेशी सरकार पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। विदेशी सूती माल पर से आयात कर धीरे-धीरे हटा लिया गया। बाद में जब सरकार को अपनी आय-वृद्धि के लिए फिर आयात कर लगाना पड़ा तो उसने भारतीय उत्पादन पर उत्पादन कर (एक्साइज ड्यूटी) उसी हिसाब से लगा दिया ताकि भारत की मिल्लों में तैयार माल की प्रतिस्पर्धा में विलापती माल महंगा न पड़े। १८६४ में यह दानों कर (देशी सूती और विदेशी कपड़ा और सूत दोनों पर) ५ प्रतिशत के हिसाब से लगाये गये थे पर १८६६ में घटाकर ३½ प्रतिशत कर दिये गये। आयात कर में तो समय-समय पर वृद्धि होती गई, पर उत्पादन कर (जो २० नम्बर से ऊपर के सूत पर था) इसी हिसाब से लगा रहा। बहुत कुछ प्रयत्न और आन्दोलन के पश्चात् १८२६ में यह कर हटाया गया। सूती वस्त्र-मिल-उद्योग के मार्ग में एक और कठिनाई उपस्थित होगई। १८६३ में रुपये का टंकन (सिन्ड्रेज) बन्द हो गया और उसका परिणाम यह हुआ कि चीन की मुद्रा में, जो चांदी के आधार पर थी, रुपये का मूल्य बढ़ गया और भारत तथा चीन के बीच का विनिमय-दर भारतीय निर्यात की दृष्टि से प्रतिकूल होगया। इसका प्रभाव भारतीय सूत-उद्योग पर, जो चीन पर इतना निर्भर था, बुरा पड़ा। इसके अलावा चीन और जापान में भी वस्त्रोद्योग का विकास होने लग गया था। अकाल और प्लेग का भी इसी समय इन देशों को सामना करना पड़ा जिससे लोगों की कार्यशक्ति में और मजदूरों की पुर्ति में कमी आई। इन समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी सूती वस्त्र-मिल-उद्योग की प्रगति जारी रही। १८०० में मिल्लों की संख्या बढ़ कर २६३, तकुओं की ४६ लाख के लगभग, और करघों की ४० हजार के लगभग होगई। इस काल में एक नया

परिवर्तन यह भी हुआ कि जो नद मिलें सुन्नी वे बम्बई शहर के अलावा बम्बई प्रांत और प्रांत के बाहर के बूखरे स्थानों में भी स्थापित हुए, जैसे अहमदाबाद, सोलापुर, सूरत, बदीदा, नागपुर तथा कानपुर। कच्चे माल की निर्यात, अन्न और बाजार की सुविधा और रेल के वातायात की सुविधा के कारण ही इन स्थानों में कपास के मिलों की स्थापना हुई। अमी तर सूत उत्पादन और चीन को सूत के निर्यात की प्रधानता पहले वैसी ही बनी रही।

१६००-१८१८—बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से लगा कर प्रथम महायुद्ध के शुरू होने तक सूती धातु मिल उद्योग की प्रगति चल्ती रही। १६०५ के स्वदेशी आंदोलन से इसके प्रोत्साहन मिला। हालांकि चीन जापान से सूत का व्यापार घटता गया और दुनिया के कच्चे माल के बाजार में भी १६०७ में मंदी आई, पर भारत के कपास उद्योग की प्रगति जारी रही। सन् १६१३ में मिलों की संख्या २७१, तथा तंतुओं की ६८ लाख और करघों की १ लाख के लगभग थी। रेल की अपेक्षा अन्न बुनाई की प्रधानता होगई क्योंकि चीन और जापान ने अब हमारे सूत की मांग नहीं रखी। अन्धे दर्जे का कपड़ा भी अब तैयार होने लगा और बम्बई से बाहर उद्योग का विस्तार और भी तेजी से होने लगा।

प्रथम महायुद्ध—जब १६१४ में प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ तो बाहर से माल का आना कम हो गया और देश के अंदर का खपत बढ़ गई। इसका असर उद्योग के विकास के लिए सहायक हुआ। मिलों के लाभ में सूत वृद्धि हुई और उनके हिस्सों का मूल्य भी बाजार में काफी ऊंचा हो गया। पर मशीनरी और दूसरे आवश्यक सामान जो करघों की मिलों को चाहिए और जो बाहर से आता था उसका आने में सुद के कारण कठिनाई होगई। इस कारण इस उद्योग का जितना विस्तार हो सकता था वह नहीं हो सका। मिला और सिंडिकेट की संख्या तो लगभग वही रही पर करघों की संख्या में अथवा २५ प्रतिशत वृद्धि हुई। कपड़े के उत्पादन की मात्रा बढ़ी, बुनाई की प्रधानता बनी रही और सूत के निर्यात में कमी होगई। बाहर से आनेवाले कपड़े और सूत की पुनर् मांग अथवा कमी हुई पर जापान से आनेवाले माल की मात्रा बढ़ गई।

युद्धोत्तर अभिवृद्धि—युद्ध के अंत बाद ही युद्धोत्तर अभिवृद्धि (रूम) का आरम्भ हुआ। बम्बई में तो इसकी शुरुआत १६१७ से ही हो गई। वैसे अभिवृद्धि का समय आध्यात्मिकता १६१६ से १६२८ तक युद्ध के अंत बाद तीन साल का माना जाता है। हालांकि १६२१ के बाद भी यह अभिवृद्धि १६२२ में जारी रही। इस समय में देश में मिलों की संख्या बढ़ा यद्यपि बम्बई में तंतु (स्पिन्डल) और करघों की संख्या को बढ़ाकर ही उद्योग का विस्तार किया गया। कपड़े

और सूत के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई, मिलों ने अपनी शक्ति-भर काम किया, और कपड़े और सूत का आयात काफी गिर गया। परन्तु जापान का आयात बढ़ता ही गया।

संकट काल—१९२३ में भारतीय सूती वस्त्र-मिल उद्योग के लिए संकट का समय आरंभ होता है, और एक तरह से १९३७ तक उसकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं होता। इस संकट की स्थिति का सामना बम्बई की मिलों को अपेक्षाकृत अधिक करना पड़ा। इस संकट के कई कारण थे। कुछ कारण तो विश्व-व्यापी थे। युद्धोत्तर अभिवृद्धि के बाद सारे संसार में स्वाभाविक चक्रवर्ति के नियम के अनुसार मंदी का युग आया जो १९२२ से १९२४-२५ तक रहा। १९२० के पश्चात् जब मूल्यों का हास होने लगा तो कच्चे माल और खाद्य पदार्थों के मूल्यों में तैयार माल के मूल्यों की अपेक्षा अधिक हास हुआ। भारतीय किसान की ऋण शक्ति इससे गिर गई और उसकी मांग भी कम होगई। इसका भी देश के वस्त्रोद्योग पर बुरा असर पड़ा। इसके अलावा एक बात यह भी हुई कि कपड़े के मूल्य में तो कमी हुई पर कपास की कीमत बढ़ती गई और इससे मिलों को नुकसान हुआ। उपर्युक्त विश्व-व्यापी कारणों के अलावा कुछ कारण ऐसे थे जिनका केवल भारत से सम्बन्ध था। भारतीय मिलों में तैयार कपड़े से विदेशी कपड़े ने फिर प्रतिस्पर्धा करना आरंभ कर दी। यह प्रतिस्पर्धा इंग्लैंड और खास कर जापान से अधिक थी। जापान के वस्त्रोद्योग को वहाँ की सरकार से आर्थिक सहायता मिलती थी, वहाँ का मज़दूर बहुत कम मज़दूरी पर काम करता था, उद्योग का संगठन अच्छा था, अच्छे यंत्रों का उपयोग होता था और वहाँ की विनिमय-नीति निर्यात के अनुकूल थी क्योंकि वहाँ की मुद्रा का मूल्य कम था। इस बाहरी प्रतिस्पर्धा के अलावा भी कुछ और कारण थे जिनका देश के वस्त्रोद्योग पर हानिकर असर पड़ा। भारत-सरकार की विनिमय-दर सम्बन्धी नीति देश के हित में नहीं थी। १९२२ से ही विनिमय-दर को बढ़ाने दिया गया और आखिर में जाकर १ रु०=१ शि० ६ पैसों की दर निश्चित कर दी गई। यह दर देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऊँची थी। बाहर से आनेवाला कपड़ा भारतीय बाज़ार में सस्ता पड़ने लगा और हमारे निर्यात की आमदनी कम हो जाने से भारतीय किसान की ऋण-शक्ति को भी हानि पहुँची। हमारे वस्त्रोद्योग का आन्तरिक संगठन दोषपूर्ण था। उसमें अधिपूँजीयन (ओवर कैपैटिलाइजेशन) था। युद्धोत्तर अभिवृद्धि के समय मिलों ने ऊँचे-ऊँचे मुनाफे बाँटे पर रक्षित कोष का निर्माण बिल्कुल मात्रा में नहीं किया ताकि नई मशीनरी आदि की व्यवस्था उसमें से की जा सकती। मेनेजिंग एजेन्सी-प्रणाली के

दोनों का भी उपयोग पर पुरा अधर पड़ रहा था। इन सब बातों के साथ साथ पूँजी मिलने में भी अड़थक होती थी। नतीजा यह हुआ कि देश के वस्त्र-व्यवसाय को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। जैसा हम पहले लिख चुके हैं, बम्बई को इस समय सब से अधिक कठिनाई भेलनी पड़ी। इसके कुछ कारण थे। चीन के सातार में सूत की माग अब जाती रही थी। देश के अन्य भागों में जो मिलें स्थापित हो गई थीं उनकी प्रतिद्वन्द्विता भी थी। और वे उन कई दोषों से मुक्त थीं जो बम्बई की मिलों में आ गए थे। बम्बई में मजदूरी भी अधिक थी। बम्बई में श्मानीय कर तथा पानी का खर्चा अधिक था और इसी प्रकार बिजली आदि का खर्चा भी बड़ा हुआ था। इन तमाम कारणों का यह परिणाम आया कि जब दुनिया के दूसरे देशों में आर्थिक मंदी का अठ होने लगा और स्थिति सुधार का ओष जाने लगी तब भी भारतीय वस्त्रोद्योग में मन्दी चलती रही। और इसी चीन में फिर दुबारा विश्व-व्यापक मंदी का चक्र १९२९ में आरम्भ हो गया। सन् १९२८ और १९२९ में बम्बई की मिलों में लम्बी हड़तालें भी हुईं क्योंकि प्रशुल्क मंडल कि सिफारिशों [जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे] के अनुसार मिलों ने काय की दखला बढ़ाने की आर प्रमाणाकरण की कुछ योजनाएँ लागू की थीं जिन ने मजदूरों की छुटनी होने का भय मजदूरों में उत्पन्न होगया था। साधारण यह है कि वस्त्रोद्योग में यह मंदी की अवस्था अभी बनी रही।

सरक्षण प्रारंभ — इस मकट कि स्थिति का सामना करने के लिये व्यवसायी वर्ग ने सरक्षण की माग की। अभी तक इस राष्ट्रीय व्यवसाय को सरकार ने कोई सरक्षण नहीं दिया था। १९२७ में प्रशुल्क मंडल ने इस व्यवसाय की स्थिति की जांच की। मंडल ने उद्योग में कई मुद्दों सम्बंधी सिफारिशें कीं। कच्चे माल की व्यवस्थित रूप से खरीद, मजदूरों की कार्यदक्षता में उन्नति, अच्छे और जोमती कपड़े का अधिक उत्पादन, देश के अंदर और बाहर बिना में बड़ोतरी आदि बातों की ओर प्रशुल्क मंडल ने ध्यान खींचा। सरक्षण के बारे में प्रशुल्क मंडल के बहुमत और अल्पमत ने अलग अलग सिफारिशें कीं। बहुमत ने सारे विदेशी माल से सरक्षण देने का प्रस्ताव किया पर अल्पमत ने आपानी माल से सरक्षण देने की ही सिफारिश की। पहले तो तत्कालीन भारत सरकार ने कुछ भी करने से इन्कार कर दिया पर बाद में जब बहुत विरोध हुआ तो बाहर से आने वाले सूत पर थोड़ा सा आयात कर लगाने का निश्चय किया और २१ मार्च १९३० तक की उसकी अवधि निश्चित की गई। बाद में यह अवधि १९३३ तक बढ़ा दी गई। कारण यह था कि १९२७ में जो अपवात सरक्षण दिया गया था उस से वस्त्रोद्योग

की समस्या हल नहीं हुई थी। इस लिए भारत-सरकार श्री जी. एस. हार्डी (जो कलकत्ते के कस्टम्स-कलेक्टर थे) द्वारा फिर संरक्षण सम्बन्धी जांच कराई। इन्होंने संरक्षण की आवश्यकता बताई और उसके लिए सिफारिश की। इसी के परिणामस्वरूप १९३० में कॉटन टेक्सटाइल इन्डस्ट्री प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। इसके द्वारा १९२७ में विदेशी सूत पर जो संरक्षण-कर लगाया गया था वह १९३३ तक जारी रखा गया और विदेशी कपड़ों पर अब तक जो १९ प्रतिशत आयात-कर था उसको बढ़ा कर १५ प्रतिशत कर दिया गया और इसके अतिरिक्त ५ प्रतिशत संरक्षण-कर और लगाया गया। यह संरक्षण-कर ब्रिटिश माल पर नहीं लगाया गया। केवल कुछ ब्रिटिश माल पर (प्लेन ट्रे गुड्स) जो भारतीय माल से प्रतिस्पर्द्धा में आता था, अन्य विदेशी माल के समान ३३ आने प्रति पाँड के बिसाब से न्यूनतम संरक्षण-कर लगाया गया। इस प्रकार ब्रिटिश माल के पक्ष में पक्षपात किया गया। यह संरक्षण का समय मार्च १९३३ तक का निश्चित किया गया।

विश्व-संकट—यह हम पहले लिख चुके हैं कि १९२६ में विश्वव्यापी मंदी आरम्भ होगई थी। इसका असर अन्य उद्योगों के साथ वस्त्रोद्योग पर भी पड़ा। पर १९३० में स्वर्गीय महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आरम्भ हुआ और स्वदेशी के पक्ष में देश में जो प्रचार और वातावरण बना उससे वस्त्रोद्योग को अवश्य प्रोत्साहन मिला। आर्थिक मंदी के कारण भारत-सरकार के बजट में भी घाटा हुआ। उसकी पूर्ति करने के लिए भारत-सरकार ने करों में भी वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप विदेशी सूती कपड़ों पर भी आयात-कर बढ़ा और विदेशी सूत पर लगनेवाले आयात-कर में भी वृद्धि हुई। इधर आर्थिक मंदी से रक्षा करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा स्वर्णमान का परित्याग किया जाने लगा। इंग्लैंड ने २१ सितम्बर, १९३१ को स्वर्ण मान का परित्याग किया और कई देशों ने उसका अनुसरण किया। भारत की मुद्रा का इंग्लैंड की मुद्रा से सम्बन्ध था, इसलिए स्टर्लिंग के साथ-साथ रुपये का भी सोने से सम्बन्ध-विच्छेद होगया। जापान इस समय स्वर्ण-मान पर था इसलिए विदेशी बाजारों में, जहाँ स्वर्ण मान का त्याग कर दिया गया था, उसका माल महंगा पड़ने लगा। भारत में जापानी कपड़ा बयोट मात्रा में आता था। उसे भी कठिनाई होने लगी। अतः दिसम्बर, १९३१ में जापान भी स्वर्ण-मान से अलग होगया और वहाँ की मुद्रा (येन) का मूल्य तेजी से घटने लगा। जापानी कपड़ा फिर भारतीय बाजार में बहुत सस्ता होगया। १९३० में जो संरक्षण कानून पास हुआ वह ३१ मार्च १९३३ को समाप्त होनेवाला था। उसके पहले भारत-सरकार सारी स्थिति की

जाँच करा वे आगे के लिए नियम करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से वने अप्रैल, १९३२ में फिर प्रशुल्क मंडल की नियुक्ति करदी थी। जब जापानी मात्र भारतीय बाजार में अत्यधिक माना में आने लगा, और भारतीय माल का उसके सामने टिकना कठिन होगया, तो इस प्रशुल्क मंडल ने भारत-भारत के बहने पर जापानी कपड़े की प्रतिद्वन्द्विता के प्रेश पर भी विचार किया और उसकी सिफारिश पर ब्रिटिश माल व अलावा दूसरे विदेशी माल पर आयात कर ५० प्रतिशत कर दिया गया। समी प्लेन में शुद्ध (ब्रिटिश तथा दूसरे) पर अनिवार्य कर ५३ आना प्रति पींड कर दिया गया। जून १९३२ में कर की वे दरें और बढानी पड़ी जो ५० प्रतिशत की जगह ७५ प्रतिशत और प्लेन में शुद्ध पर अनिवार्य कर ५३ आ को मन्नाय ६३ आ प्रति पींड कर दिया गया। जून १९३० के सरलण कानून की अवधि दो बार करके ३० अप्रैल, १९३४ तक के लिये बढ़ा दा गई। क्योंकि १९३२ की टेरिफ बोर्ड की रिपोर्ट पर अभी तक सरकार का कोई निष्पत्ती नहीं हो पाया था। भारत और जापान के बीच में जून १९०४ में हुआ एक व्यापारिक समझौता था जिसके अनुसार भारत सरकार केवल जापानी माल व विरुद्ध सरलण नहीं द सकती थी। १९३३ की अप्रैल में इस समझौते का भी अन्त कर दिया गया। जापान और भारत के बीच में एक व्यापारिक सम्बंध बिगड़ने लगे तो फिर समझौते की बात-चीत शुरू हुई और ७ जनवरी, १९३४ को दोनों देशों में फिर व्यापारिक समझौता होगया और २३ जनवरी, १९३४ से ही यह लागू भी होगया। इस समझौते की अवधि ३१ मार्च, १९३७ तक थी। इस समझौते के अनुसार भारत में जापानी कपड़े के आयात की मात्रा और जापान की निर्यात होनेवाला भारतीय कपास की मात्रा में निश्चित कर दी गई। जापानी माल पर आयात कर ५० प्रतिशत और प्लेन में शुद्ध पर अनिवार्य कर ५३ आ प्रति पींड कर दिया गया। इसी समय भारत और इंग्लैंड व बीच में लीड मोदी समझौता भी किया गया। इस समझौते की अवधि ३१ दिसम्बर, १९३५ तक था। यह समझौता भारतीय हितों के विरुद्ध और ब्रिटिश स्वार्थों की रक्षा करनेवाला था। इन दोनों समझौतों और १९३० में नियुक्त प्रशुल्क मंडल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मार्च १९३४ में इम्पियल टेरिफ (टेक्सटाइल प्रोटेक्शन) एक्ट पास किया गया। यद्यपि सरलण का अवधि ३१ मार्च, १९३६ तक की स्वीकार की गई थी पर सरलण-जनों की दरों के बारे में यह निश्चित किया गया कि १९३५ के दिसम्बर में लीड मोदी समझौता, और मार्च १९३७ में जापान-भारत समझौता की अवधि समाप्त होने पर उन पर फिर विचार किया जाये। इस एक्ट में ब्रिटिश कपड़ों

पर २५ प्रतिशत और दूसरे विदेशी कपड़ों पर ५० प्रतिशत आयात-कर लगाया गया था और प्लेन व्रे गुड्स पर कमश ४½ आ. और २½ आ. प्रति पाँड कर स्वीकार किया गया। विदेशी सूत पर भी आयात-कर लगाया गया। ब्रिटिश सूत पर ५ प्रतिशत और दूसरे विदेशी सूत पर ६½ प्रतिशत या कमश १½ आ. और १½ प्रति पाँड अनिवार्यकर (५० और उससे कम नम्बर के सूतपर) की दरें निश्चित की गईं।

१८३५—३७—उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश के इस महत्वपूर्ण उद्योग को संकट के समय किस हद तक सरकार ने संरक्षण दिया। १८३५ से १८३७ तक सूती वस्त्रोद्योग की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। इसी बीच में इंग्लैंड के माल पर जो आयात-कर लगा हुआ था उस पर लीज-मोदी समझौते के अनुसार फिर प्रशुल्क मण्डल ने, जो सितम्बर १८३५ में नियुक्त किया गया था, विचार किया। उसकी सिकारिश के आधार पर आयात-कर की दर २५ जून, १८३६ से प्रिन्ट्स को छोड़ कर बाक़ी सब माल पर २० प्रतिशत कर दी गई और प्लेन व्रे गुड्स पर भी ३½ आ. प्रति पाँड अनिवार्य कर की दर कर दी गई। भारत-जापान समझौता भी तीन वर्ष के लिए (मार्च १८४० तक) और आगे बढ़ा दिया गया और करों को वरें पूर्ववत् ही रहीं।

प्रगति की ओर—सन् १८३७ से १८३८ तक वस्त्रोद्योग की अच्छी प्रगति हुई। इसके कई कारण थे। विश्व-व्यापी मन्दी के पश्चात् सुधार होने लग गया था। जापान और इंग्लैंड की प्रतिस्पर्धा पर रोक लग गई थी। संरक्षण से भी प्रगति में सहायता मिली। चीन-जापान का युद्ध छिड़ जाने से भी जापान की प्रतिस्पर्धा में कमी आ गई। सन् १८३८ के अन्त में अग्रगण्य प्रगति रुकने के फिर कुछ लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे। मजदूरी में वृद्धि, कपास पर आयात कर में दो पैसे से एक आना प्रति पाँड की वृद्धि (१८३६ में), और बम्बई और अहमदाबाद में संपत्ति-कर का लगाना—ये कुछ ऐसी बातें उत्पन्न हो रही थीं जो कपास के उद्योग के प्रतिकूल जाने वाली थीं। इसके अलावा मार्च १८३६ में औटावा समझौते (१८३२) के स्थान पर भारत-इंग्लैंड का एक नया समझौता हुआ जिसके आधार पर अप्रैल १८३६ में इंडियन टेरिफ़ (थर्ड एमेन्डमेंट) एक्ट पास किया गया। इसकी अवधि १८४२ के मार्च तक थी। इसमें ब्रिटिश माल पर आयात-कर २०% से १५% कर दिया गया। पिटेड माल पर दर १७½ और प्लेन व्रे गुड्स पर अनिवार्य कर २ आ. ७½ पाई कर दिया गया। ये आधारभूत दरें थीं जिनमें आयात में कमी अथवा आधिन्य के अनुसार कमी या वृद्धि हो सकती थी। १ अप्रैल १८३६ से ये नई दरें लागू हो गई थीं। इस प्रकार ब्रिटिश माल

से जो सरक्षण पहले मिला था उसमें फिर कमी आने लग गई थी। जापान ने भी फिर भारतीय बाजार की ओर ध्यान देना चाहा। १९३८ में समार की आर्थिक स्थिति में जो फिर क्षिप्रता के निद दिवाई पड़ने लगे थे उसका आर्थिक मास पर बुरा असर पड़ा। भारतीय कपास उद्योग का भविष्य उस सब कार्यों से फिर एक चिन्ता का विषय बनता हुआ मान्य पड़ने लग गया था। पर एगो बीच में सितम्बर, १९३९ में दूसरे महायुद्ध का आरम्भ हो गया और उसके परिणामस्वरूप सारा स्थिति ही एक दिन बदल गई।

द्वितीय महायुद्ध—महायुद्ध ने कारण इस उद्योग की भी प्रोत्साहन मिला। जापान और इंग्लैंड में मात आना बंद हो गया। भारत के कपड़े की विदेशों में माग बढ़ने लगी क्योंकि जो देश इंग्लैंड, अमरीका और जापान से मात मगाते थे अब वे भी भारत से कपड़ा मगाने लगे। भारत के कपड़े का निर्यात एशिया और अफ्रीका के देशों और आस्ट्रेलिया के अलावा इटली और अमेरिका तक को होने लगा। इस बाहरी माग के अलावा अन्दर भी माग भी बढ़ी। एक तो बाहर से कपड़ा आना बंद हो गया। दूसरे सैनिक आवश्यकता के लिए सरकार बहुत धा करवा खरादने लगा। इस बढ़ी हुई माग को पूरा करने के लिए भारतीय मिलों ने शक्ति भर उत्पादन करना आरम्भ किया। मिलों में तान वान पाला काम होने लगा। नए मिलों की स्थापना करना तो कठिन था क्योंकि मुद्रकाय में मशानरी मिलना आसानी से सम्भव नहीं था। इसलिये मिलों ने अपनी मौजूदा उत्पादन शक्ति का ही पूरा पूरा उपयोग किया। मिलों की मस्या में थोड़ी त्रुटि अवश्य हुई। सन् १९३९ में कुल ३८८ मिलें भारत में थीं और १९४५ में यह संख्या बढ़ कर ४१७ हो गई। तदुद्योगों की मर्यादा १ करोड़ के आस-पास से बढ़ कर २ करोड़ २ लाख के आस पास हो गई और करधा की संख्या लगभग वही दो लाख के आस पास रही। कपड़े की उत्पादन शक्ति में वास्तविक त्रुटि का अनुमान तो करघों से ही लगाया जादिय। इस दृष्टि से यह सबका स्पष्ट हो जाना है कि दूसरे महायुद्ध के समय में उत्पादन शक्ति में थोड़ा वास्तविक त्रुटि नहीं हो सकी और अधिक उत्पादन मौजूदा शक्ति के अचिन्तम उपयोग से ही किया जा सका। यह उत्पादन त्रुटि युद्ध के इन छह वर्षों में कितनी हुई इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जहां १९३९ में भारतीय मिलों में कुल कपड़ा ४११ करोड़ गज से कुछ अधिक तैयार हुआ वहां १९४५ में ४७३ करोड़ गज से कुछ अधिक कपड़ा तैयार किया गया था। १९४४ में तो उत्पादन अरनी चरम सीमा पर (४८० करोड़ गज) पहुँच गया था। कपास की कल की दृष्टि से परिदृश्य देखें तो जहां १९३९ में

कुल ३८ लाख गांठों की खपत हुई थी वहां १९४५ में ४९ लाख गांठों की खपत हुई। काम करने वालों की संख्या भी ४ लाख ४२ हजार (१९३९) से बढ़कर ५ लाख से कुछ अधिक (१९४५) हो गई। सूत की दृष्टि से उत्पादन १३० करोड़ पाँड के लगभग (१९३८-३९) से बढ़ कर १६५ करोड़ पाँड (१९३८-४५) के हो गया था। कई प्रकार का नया माल जैसे मच्छरदानी, वाटर-प्रूफ खाकी, आदि भी भारतीय मिलों में युद्ध के समय तैयार होने लगा। ऊँचे दर्जे का कीमती कपड़ा तैयार करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी। उत्पादन बढ़ने का स्वाभाविक परिणाम मुनाफ़ा बढ़ने का भी हुआ। १९४० में वास्तविक मुनाफ़ा १३ करोड़ था वह १९४३ में २१ करोड़ तक हो गया था। डिबिडेण्ड की दर १९३९ में १०% प्रतिशत थी वह १९४२ में २७ प्रतिशत तक हो गई थी। युद्ध के समय में कपास-उद्योग के उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ मांग में भी बहुत वृद्धि हुई और इसलिए कपड़े का मूल्य भी बढ़ने लगा। महायुद्ध के आरम्भ होते ही कीमतों का बढ़ना शुरू हो गया था। पर १९४१ के मध्य तक स्थिति विशेष रूप से चिन्ताजनक नहीं हुई थी। जब अगस्त १९४१ में जापान के परिसंयत् (एसेट्स) को जफ़ीकृत (क्रिप्ड) कर दिया गया तो वहां से आने वाला कपड़ा सर्वथा बन्द हो गया। इससे कपड़े की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं और १९४२ के अन्त में तो अगस्त १९३९ की चाँगुनी-पच्चुनी कीमत हो गई। १९४३ के मध्य तक सरकार कीमतों को बढ़ने से रोकने में सफल नहीं हो सकी और अन्तोगत्या कपड़े का मूल्य नियंत्रण कर दिया गया। इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार से तो हम आगे लियेंगे। यहाँ तो हम इतना ही लिख देना चाहते हैं कि युद्धकाल में भारतीय मिलों का उत्पादन तो एक सीमा से अधिक सम्भव नहीं हो सका और बाहर से भी कपड़े का आना बिल्कुल बन्द हो गया, पर मांग बहुत बढ़ गई—हमारे देश में और देश के बाहर भी। नतीजा यह हुआ कि युद्धकाल में कपड़े की तंगी और महंगाई की समस्या बराबर बनी रही। इसके पहले कि हम युद्ध-काल में किये गए सरकार के उक्त समस्या को सुलझाने के प्रयत्नों का उल्लेख करें एक बात की और जानकारी करना आवश्यक है। वह है कपास-उद्योग सम्बन्धी युद्धकालीन संरक्षण-नीति की।

यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि १९३९ में जो प्रशुल्क कानून लागू किया गया था उसमें इस बात की सुझाव थी कि विलायती माल की आयात-वृद्धि अथवा कमी के अनुसार इंग्लैंड से आनेवाले माल पर लगने वाले कर में कमी अथवा वृद्धि की जा सके। चूँकि द्वितीय महायुद्ध के कारण इंग्लैंड से आने वाले कपड़े की मात्रा में कमी हो गई, इसलिये १७ अप्रैल, १९४० से सब प्रकार के ब्रिटिश

कपड़े पर २३ प्रतिशत कर कम कर दिया गया। सन् १९४२ तक सरदर का जो प्रवधि १९३६ में बढ़ा दी गई थी वह बाद में फिर समय-समय पर १९४७ तक के लिए बढ़ा दी गई। १९४६ में सरदर सम्पदा सारे प्रशासक प्रमुख मण्डल ने विचार किया और यह सिफारिश की कि ३१ मार्च १९४७ से सरदर समाप्त कर दिया जाये। जो मालिक आवात-कर हैं वे आगम कर (रेवेन्यू क्यूं) के रूप में बने रहें। और जब कभी लगातार तीन महीने तक थोमत २३ करोड़ गज मासिक कपड़ा बाहर से आये तो प्रमुख मण्डल सरदर के प्रश्न पर विचार करे। अतः, भारत सरकार ने १ अप्रैल, १९४७ में सूची कपड़े और सूत पर जो सरदर कर था उनका आगम कर में बदल दिया। प्रायः इस देश का यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योग इस अर्थ में अपने पाँव पर खड़ा है।

यह हम पहले लिख चुके हैं कि द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होते ही अन्य वस्तुओं के साथ साथ कपड़े का कीमत बढ़ता भा शुद्ध हुआ और १९४३ के मध्य में तो स्थिति बहुत ही विनाशक हो गई। स्थिति पर शाब्द पाने के लिये जून, १९४३ में भारत सरकार ने कपड़े और सूत पर नियंत्रण लागू कर दिया और 'टेक्सटाइल कमिश्नर' नामक एक आसन्न का नियुक्ति करके नियंत्रण सम्बन्धी व्यवस्था का भार उसे सौंप दिया। पञ्चीत समस्याओं का टेक्सटाइल कंट्रोल बोर्ड नाम की एक कमेटी भी नियुक्त की गई जिसका काम नियंत्रण सम्बन्धी मामलों में सरकार को सहाय देना था। नियंत्रण की इन व्यवस्थाओं के अनुसार कपड़े और सूत का मूल्य नियंत्रण कर दिया गया, अनावश्यक माल मिल-मालिक या व्यापारी के पास बचना न हो इसका प्रबंध कर दिया गया, कपड़े के लाने लेजाने पर नियंत्रण कर दिया गया, और कपास तथा दूसरी आवश्यक सामग्री के मूल्यों का नियंत्रण भी कर दिया। इन नियंत्रणों का परिणाम मूल्यों में कमी होने का हुआ, और जून १९४३ में वहाँ तली बरत के मूल्य का देशांतर [इन्डेक्स नम्बर] १९३६ को आधार [१००] मानकर ५३३ हो गया था वहाँ दिसम्बर १९४४ में २६५ हो गया। पर इससे जनता की समस्या का पूरा हल नहीं हुआ। कपड़े की तंगी बराबर बनी रही और काला बाजार गूढ़ बना। अतः, जनता को नियंत्रित मूल्य पर कपड़ा नहीं मिलने से काले बाजार के बढ़े हुए मूल्यों पर अपनी रुबड़े को मॉल पूरी करनी पड़ती थी। मुद्रास्फी में कपड़े का उत्पादन बढ़ने पर भी कपड़े की कमी बनी रही जनता की स्वतंत्र के लिये जो कपड़ा उपलब्ध था उसमें मुद्रा के समय में कितनी कमी आ गई इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि मुद्रा के पूष के दो वर्षों में हाथ के करवों पर पैयार कपड़े को शामिल करके जनता की स्वतंत्र के लिये ६४० करोड़

गल कपड़ा उपलब्ध था वह १९४२-४३ में उसी आधार पर केवल २६० करोड़ गज या ४० प्रतिशत ही रह गया था। मूल्य नियंत्रण होने पर भी बढ़े हुए मूल्यों पर कपड़ा विक्रता रहा—यह सारी स्थिति का निचोड़ मानना चाहिये।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्:—७ मई १९४५ को जर्मनी के साथ, और १४ अगस्त, १९४५ को जापान के साथ, द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ। आशा यह थी कि युद्ध के पश्चात् कपड़े की तंगी कम हो जायगी और कीमतेँ भी नीचे उतरेंगी। पर यह आशा पूरी नहीं हुई। मई १९४५ में सरकार ने कपड़े तथा सूत के उत्पादन पर नियंत्रण किया और जुलाई १९४५ में वितरण सम्बन्धी नई योजना जारी की। सूत व कपड़े सम्बन्धी उत्पादन के नियंत्रण की जो योजना लागू की गई थी उसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना था और इस दृष्टि से मिलों को कौन-सा कपड़ा और सूत कितना उत्पन्न करना चाहिये इस सम्बन्ध में कुछ नियंत्रण किया गया था। इसी के अनुसार 'यूटीलिटी क्लाय' की योजना भी बनी थी। वितरण सम्बन्धी योजना में राज्य और प्रान्त की सरकारों को बहुत अधिकार दिये गये थे। प्रान्तों का कोटा निश्चित कर दिया गया था। उस कोटा के ठीक-ठीक वितरण का प्रयत्न करना उनका काम था। देश में कपड़े के आने-जाने पर और कच्चे माल तथा दूसरी आवश्यक सामग्री की उचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में भी नियंत्रण किया गया। परन्तु सरकार के इन तमाम प्रयत्नों का कोई परिणाम नहीं आया। यूटीलिटी क्लाय की योजना १९४५ के अन्त में समाप्त कर दी गई। १९४६ में उत्पादन बहुत गिर गया। जहाँ १९४५ में ४७१ करोड़ गज कपड़े का उत्पादन हुआ था वहाँ १९४६ में ४०२ करोड़ गज का उत्पादन ही हुआ। उत्पादन-लागत में वृद्धि होती रहने पर भी कपड़े के मूल्य नहीं बढ़ाये गये। मज़दूरों के काम के घटे ५४ से ४८ प्रति सताइ कर दिये गये थे। हड़तालों आदि के कारण भी उत्पादन बंद रहा। सांप्रदायिक भागड़े भी देश में हुए। सरकार की नियंत्रण-नीति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। कीमती कपड़े के उत्पादन को बढ़ाने और मोटे कपड़े के उत्पादन को घटाने की दृष्टि से मूल्यों में मई, १९४५ के पश्चात् नवम्बर, १९४५ में कुछ परिवर्तन किये गये थे पर उनके बारे में यह शिकायत तो बनी ही रही कि बढ़ी हुई उत्पादन-लागत को देखते हुए सरकार ने कपड़े के निर्यात में पहले तो कमी की पर फिर कुछ समय के लिये बन्द ही कर दिया। और फिर जब निर्यात जारी हुआ तो उस की मात्रा में कमी कर दी। १९४७ में उत्पादन की स्थिति और भी बिगड़ गई और कुल कपड़े का उत्पादन ३८० करोड़ गज ही हुआ। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से स्टैंडरडाइजेशन (प्रमापीकरण) की योजना बनाई जो

१ दिसम्बर, १९४७ को लागू की गई। पर कपड़ों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई। प्रमाणीकरण की उच्च योजना के अनुसार मोटे सूत और कपड़े के उत्पादन पर अधिक ध्यान देने, कपड़े के प्रकारों में कमी करने और अभूक्त नम्बर तक के ही सूत काटने का निश्चय किया गया। मिल मालिकों और मज़दूरों की सम्मिलित कमेडिया प्रवेसों में और अल्प-अल्प मिलों में उत्पादन बढ़ाने की गति से हथियार की गई। पर इन सब प्रयत्नों का भी कोई अच्छा परिणाम नहीं था। बाज़ार में कपड़े की तंगी बनी रही और चोर बाज़ारी बढ़नी गई। महात्मा गांधी निश्चय के विद्वद् थे और उनके नेतृत्व में देश में नियंत्रण हटा लेने के पक्ष में पातावरण बन रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि जनवरी, १९४८ में सरकार ने सूत तथा कपड़े पर से नियंत्रण हटा लिया यद्यपि पूरा नियंत्रण अभी नहीं हटा था। प्रमाणीकरण की योजना अब समाप्त होगई। कपड़े और सूत पर सरकारों नियंत्रण समाप्त हो गया यद्यपि मिलों ने इस मूल्यों का नियंत्रण करना स्वीकार किया। कपड़े के विनरण और सूत तथा कपड़ों के एक निश्चित दर में (ज़ोन) आने जाने पर से भी नियंत्रण हट गया। इसी प्रकार सूत और कपड़ों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। कपास पर से भी मूल्य नियंत्रण हट गया। जबल सूत के विनरण और कपास के निर्यात पर अन्तर्गत नियंत्रण रहा। नियंत्रण व्यवस्था के समाप्त होने का मूल्य तंत्री से बढ़ने लगा। मिला द्वारा मूल्य-नियंत्रण सफल नहीं हो सका। आन्विकार अपेक्ष, १९४८ में सरकार ने रहा सहा नियंत्रण भी उठा लिया। अब कपड़ों और सूत पर मूल्य लिखने की आवश्यकता नहीं रही। सूत के विनरण से नियंत्रण हटा लिया गया। टेकमटाइल कट्टील बाइ भी समाप्त कर दिया गया। पर कपड़े और सूत के लाने से जाने, उन पर उत्पादन के तिथि लिखने और कपड़े और सूत का आयाज (डिफ़) करने मन्त्राली नियंत्रण जारी रखा गया। पर नियंत्रण के पूरा नीर से हटते ही मूल्यों में और भी वृद्धि आर और मन्त्र में तो कामत बहुत हो बढ़ गई। इस विधि से ध्वराकर जुलाई, १९४८ में भारत सरकार ने फिर नियंत्रण लागू करने का निश्चय किया। इसके अनुसार भारत सरकार को कपड़े और सूत के मूल्य निश्चित करने और उनको छापने (स्टैम्प करने) का अधिकार प्राप्त हो गया। विनरण की व्यवस्था का भार राज्यों पर छोड़ दिया गया। कपास के मूल्यों का भी नियंत्रण किया गया। इसके कुछ समय बाद (दिसम्बर १९४८) से उत्पादन पर भी सरकार ने नियंत्रण लागू कर दिया। उत्पादन पर नियंत्रण करने का लक्ष्य उत्पादन में वृद्धि करना और अधिक टिकाऊ कपड़ा तैयार करना था। पहली बार काम में आने वाले कपड़े १६ और ओ पहनने के काम नहीं आते थे

१२ प्रकार के तय कर दिये गये। मोटे कपड़े के उत्पादन पर अधिक ज़ोर दिया गया। नियंत्रण-व्यवस्था ठीक-ठीक लागू होती है या नहीं इसकी निगरानी रखने के लिये एक एन्फोरसमेंट विभाग खोला गया। १९४८ में उत्पादन में वृद्धि हुई। इस वर्ष ३३३ करोड़ गज़ कपड़ा उत्पन्न हुआ, परन्तु चोर-वालाचारी जारी रही। कपास की कमी की समस्या भी देश के विभाजन के कारण उत्पन्न हो गई। मूल्यों के दर कम हैं, यह शिकायत मिल-मालिकों को बराबर बनी रही। कपड़ों के निर्यात के विषय में सरकार ने उदार नीति अपनाना आरम्भ किया और निर्यात-कर में २५ प्रतिशत से नवम्बर १९४८ में १० प्रतिशत तक की कमी कर दी गई। इससे निर्यात को और इस कारण से उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने की आशा थी। १९४९ का वर्ष फिर वस्त्रोद्योग का दृष्टि से कठिनाई का बीता। उत्पादन १९४८ की अपेक्षा फिर गिर गया। उस महीनों के वास्तविक उत्पादन के आधार पर कुल ३८४ करोड़ गज़ कपड़ा १९४९ में उत्पन्न हुआ। सरकार ने उत्पादन सम्बन्धी नियन्त्रण की व्यवस्था को टेक्सटाइल प्रोडक्शन कंट्रोल कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कुछ बदला। कमीती कपड़े के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया और उत्पादन नियंत्रण योजना में आवश्यकतानुसार परिवर्तन की गुंजाइश रखी। पर बाद में स्थिति और भी अधिक बिगड़ने लगी तो सितम्बर १९४९ में नियन्त्रण सम्बन्धी नई नीति की सरकार ने घोषणा की। उसके अनुसार उत्पादन से नियन्त्रण हटा लिया गया, केवल उतने से नियन्त्रण के अलावा जो मूल्य नियन्त्रण के लिए आवश्यक था। वितरण की योजना में भी सुधार किया गया। एक बार तो केवल इतना ही परिवर्तन किया कि मिलों को, यदि राज्य अपने हिस्से का कपड़ा समय पर न ले सके तो, उस कपड़े को बेचने की इजाज़त दे दी। पर इसके बाद सितम्बर में सरकार ने वितरण की योजना और भी उदार कर दी। मिलों को ३ माल सीधा बेचने का अधिकार मिल गया और बाकी का राज्यों को महीने की १५ तारीख तक खरीदना आवश्यक था। यदि राज्य की सरकारें अपने हिस्से का माल समय पर न खरीद लें तो मिलों को बेचने की इजाज़त मिल गई। इन सब प्रयत्नों से स्थिति सुधरी। मूल्य नियंत्रित किस आकार पर किया जाए यह प्रश्न १९४८ में सरकार ने टेरेफ्रॉ बोर्ड के सुपुर्द कर दिया था। टेरेफ्रॉ बोर्ड की सिफारिश के अनुसार हर तीसरे महीने मूल्यों की जाँच करके आवश्यक हेर-फेर करने की नीति सरकार ने जनवरी १९४९ को स्वीकार कर ली और आज भी उसी के अनुसार हर तीसरे महीने मूल्यों में सरकार आवश्यक हेर-फेर करती है। सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने की नीति भी अपनाई। अप्रैल १९४९ में बाहर-जाने

वाले सर कपड़े का मूल्य नियंत्रण किया गया और २० प्रतिशत निर्यात परमा १ नून १९४६ को हटा लिया गया। हालांकि हाल ही में [अप्रैल १९५१] सरकार ने कपड़े के निर्यातों में मुख्य बड़ जाने से १० प्रतिशत कर फिर लागू दिया है। मिला की उचित मूल्य पर (जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट है) कपास का मिलन से आ कटिनाइ उत्पाद हो रही थी उसको हल करने के लिए मार्च १९४६ में कपास का निर्यात दुर्लभ मुद्रा के देशों को छोड़कर बाकी के देशों का बना कर दिया गया ताकि कपास का स्थिति ठीक हो जाये। सरकार के इन उपाय प्रयत्नों के बाद भी वस्त्रोद्योग की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं रही। कपास के कमी रही, निश्चित मूल्य पर उसका मिलन कठिन रहा। आरम्भ में नियंत्रण सम्बंधी व्यवस्था में बड़े दाप रह जिन में बाद में सुधार किया गया। पर कपड़े का मूल्य नियंत्रण की समस्या तो फिर भी हल नहीं हुई और मिल-मालिकों का घरोघर असंतोष रहा। मार्च १९४६ को उत्पादन कर (एक्साइज ड्यूटी) लागू किया गया यह भी मिल-मालिकों के असंतोष का कारण रहा। १९५० में भी इस उद्योग की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। गिनम्बर १९४८ में ही नियंत्रण सम्बंधी कड़ाई में तो आवश्यक कमी आगई थी, पर और कटिनाइयां बनीं रहीं। कपास का कमी और उसके मूल्य की अधिकांशता, नून नया कपड़ों की कीमत में नवम्बर १९४६ में की गई ४ प्रतिशत की कमी, जो मिल-मालिकों ने हरेच्छा से सरकार की अवगमन के बाद मूल्य घटाने में सहयोग देने की दृष्टि में शीकार की था, उत्पादन-लागत का दमते हुए कपड़े का प्रच-मूल्य, ये कुछ ऐसी कटिनाइयां थीं जिन्का सारा वस्त्रोद्योग को १९५० में सामना करना पड़ा। इसी कारण से १९५० से बवल १६५ करोड़ गज (१० महोने के ग्राहकों के आभार पर) कपड़ा उत्पादन होने का अनुमान लगाया जाता है। कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने की नाति छान भर जारी रही और १०० करोड़ गज से अधिक कपड़ा १९५० में निर्यात किया गया। इसी प्रकार कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये भी राज्य ने प्रयत्न आरम्भ किया, और थाया की जाती है कि उसका यह प्रयत्न सफल होगा। भारत सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि इस वर्ष (१९५१-५२) ४३० करोड़ गज कपड़ा उत्पाद किया जा सके। इसी दृष्टि से भारत सरकार ने पाहन, सुपर पाहन और रगान और छोटे मोटे और मध्यम अंशों के कपड़े को छोड़ कर शेष कपड़े पर से और सत पर से ४ प्रतिशत की मूल्य की कमी वापस उठा ली है। कपड़ों की कीमतों में भी उन्होंने क्रमबद्ध और अप्रैल १९५१ में श्रद्धा की है। मिल-मालिकों का कहना है कि कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार को कपड़े का कीमत और बढ़ाना चाहिए और देखि बोर्ड

को दुबारा इस प्रश्न पर विचार करने को कहना चाहिये। जिस कपड़े पर से ४ प्रतिशत की मूल्य की कमी अभी नहीं हटाई है वह हटा लेना चाहिये। सुपर फाइन क्लाय पर जो २० प्रतिशत उत्पादन-कर है उसे हटा लेना चाहिये। जो मिलें आर्थिक दृष्टि से ठीक ढंग पर नहीं चल रही हैं, उनको उनकी भर्तानरी आदि ठीक करके अच्छे स्तर पर लाना चाहिये। हाथ करचों को सहायता पहुँचाने की दृष्टि से जो मिलों पर अनुकूल प्रकार का कपड़ा नहीं तैयार करने का प्रतिवन्ध है वह हटा लेना चाहिये। युद्धोत्तर-काल सम्बन्धी जो सूती वस्त्रोद्योग का विवरण हमने ऊपर दिया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी स्थिति पिछले ५ वर्षों में संतोषप्रद नहीं रही है। देश के इस प्रमुख उद्योग के मार्ग में दूर दृष्टि से क्या क्या बाधाएँ हैं जिनको हल किये बिना उसकी भावी प्रगति अवसृद्ध रहेगी, अब इस बारे में संक्षेप से विचार करेंगे।

भविष्य—मिल वस्त्रोद्योग के भविष्य के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उसके क्षेत्र का है। मिल के कपड़े के अलावा, हमारे देश में हाथ के सूत से हाथ करचे पर बनी खादी और मिल के सूत से हाथ करचे पर तैयार किया गया कपड़ा भी उत्पन्न होता है। हाथ करचे के उद्योग की स्थिति आज संतोषप्रद नहीं है। अब तक खादी के उद्योग का आचार एक आदर्शवाद और भावना रही है। पर केवल भावना के आचार पर कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं चल सकता। इसी के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी हम खादी और हाथ करचे पर बने कपड़े के उद्योगों को नष्ट नहीं होने दे सकते। हाथ करचे के उद्योग को सहायता पहुँचाने की सरकार कई प्रकार से कोशिश कर भी रही है। पर आवश्यकता इस बात की है कि इन तीनों प्रकार के वस्त्रोद्योगों में समन्वय किया जाए और उनके क्षेत्रों का बटवारा किया जाये। वह प्रश्न राष्ट्रीय सरकार के निश्चय करने का है और उसका किया हुआ निश्चय सबकी गान्य होना चाहिये। खादी और हाथ करचे के उद्योग में वैज्ञानिक उत्पादन विधियों को चालू करना भी अत्यन्त आवश्यक है। इन उद्योगों का सामाजिक और आर्थिक मूल्य उनके विवेकित होने में है न कि वैज्ञानिक उत्पादन के तरीकों और यांत्रिक शक्ति का बहिष्कार करने में।

दूसरी बात यह है कि हमारे वस्त्रोद्योग का लक्ष्य यह भी होना चाहिये कि हम उचित उपायों से यथासम्भव बाहर के देशों में अपने माल के लिए बाजार का निर्माण करें।

इन मूल मूल्य समस्याओं का उल्लेख करने के बाद अब हम मिल के कपड़े के उद्योग तक ही सीमित कुछ समस्याओं का चिह्न करेंगे। पहली समस्या कपास और उसके उचित मूल्य की है। आज हमारे देश में लगभग ३० लाख

गाँठ बपास देना होता है। खरब हमारी ५० लाख गाँठों के लगभग है। लगभग १० लाख गाँठ बपास हम पाकिस्तान और दूसरे देशों से आन मिल सकते हैं। सारांश यह है कि बाग्री के इस लाख गाँठों का उत्पादन हम देश में करना चाहिये। ये आँकड़े केवल मोटे अनुमान के आधार पर दिये गये हैं। देश के विभाजन के पश्चात् बपास सम्बन्धी समस्या बढि हो गई है। इसे हल करने का प्रयत्न देश में चल रहा है। इस प्रयत्न में सफलता भी मिल रही है। १९५०-५१ में लगभग ३३ लाख गाँठ बपास आर्थिक उत्पन्न हुआ और १९५१-५२ के लिए ४० गाँठ बपास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमें लम्बे रेशे के बपास उत्पन्न करने का और भी ध्यान देना है।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न पुरानी के रपाय पर नई मशीनरी और नवीनतम मशीनरी लगाने का है। इस सम्बन्ध में यह याद रखने की बात है कि गठ महा युद्ध के समय से मिलों ने बहुत काम किया है इसलिए मशीनों को बदलने की बड़ी आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में दूसरी आवश्यक बात यह भी है कि यह मशीनरी हमारे देश में ही उत्पन्न की जाए। इस दिशा में कुछ प्रयत्न हुआ भी है। हाल में हम उद्योग को सरकार से सहायता भी मिला है। मशीनरी के साथ ही दूसरी आवश्यक सामग्री का भी खयाल है। उसकी व्यवस्था भी देश में होना आवश्यक है।

सातवीं समस्या इस उद्योग के विविधीकरण की है। छोटे छोटे नगरों और गाँवों में बिजली की शक्ति के प्रसार के साथ इस उद्योग का प्रसार होना चाहिये। यह सामाजिक और आर्थिक दार्ता दृष्टियों से वांछनीय होगा।

चौथी समस्या उत्पादन-लागत को कम करने की है। इसका उपाय मई दूर कम करना नहीं हो सकता। इसका तो एक ही उपाय है कि मजदूरों का उत्पादन का क्षमता बढे। जो मिलें इस समय इतना छोटी हैं कि उनको आर्थिक दृष्टि से नहीं चलाया जा सकता, उनका विस्तार किया जाना चाहिये। इसी दृष्टि से मजदूरों की कार्य-क्षमता बढाने की आवश्यकता है। पिछले वर्षों में इस विषय में मिल-मालिकों को बराबर शिक्षा मिल रही है। इसके लिए कार्य करने में ईमानदारी के अभाव आवश्यक शिक्षा की भी बड़ी आवश्यकता है। इसकी देश में कमी है। इसी के साथ साथ वैज्ञानिक (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली को यदि तत्काल समाप्त नहीं किया जा सकता तो भी उस पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता तो स्पष्ट है। ये सब बातें होने पर ही उत्पादन लागत में कमी आ सकती है। इस दृष्टि से औद्योगिक स्टाफ का महत्व भी बहुत है। इस ओर भी बराबर ध्यान देते रहने की आवश्यकता है।

यदि देश के उद्योगों को हमें ठीक और व्यवस्थित स्थिति में लाना है तो उपर्युक्त समस्याओं को हल करना आवश्यक होगा। सन् १९४५ में युद्धोत्तर योजना-समिति ने इस उद्योग के विकास की पंचवर्षीय योजना बनाई थी। उस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है यद्यपि कपास और पूंजी की कमी और मशीनरी के ऊँचे मूल्यों के कारण जिस गति से विकास हो रहा है वह बीबी है। पिछले साल सरकार ने टेक्सटाइल वर्किंग पार्टी की नियुक्ति की थी। यह एक छह वर्षीय योजना टेक्सटाइल उद्योग के विकास के बारे में तैयार कर रही है। योजना आयोग भी इस प्रश्न पर विचार कर रहा है। इन सब प्रयत्नों में समन्वय की जरूरत है। टेक्सटाइल सेक्टरल प्लैटफॉर्म कमिटी इस उद्योग के विकास सम्बन्धी प्रश्नों पर सरकार और व्यवसायी वर्ग का मार्गप्रदर्शन करती है।

पटसन [जूट] मिल उद्योग :- कपास के बाद इस देश का दूसरा महत्त्वपूर्ण उद्योग पटसन का ही है। इस उद्योग में ३ लाख से अधिक आदमी काम करते हैं। यह उद्योग अधिकतर पश्चिमी बंगाल में कलकत्ते शहर, हुगली, हावड़ा और २४ परगना के जिलों में केन्द्रित है। बिहार, मद्रास, उत्तर प्रदेश में भी कुछ मिलें हैं। इसका प्रबन्ध आज भी विदेशी हाथों में है और पूंजी में भी उनका बड़े भाग है। कुल ५० करोड़ की पूंजी [२० करोड़ स्थायी पूंजी और ३० करोड़ चालू पूंजी] इस उद्योग में लगी है। इसने १९४७ में १२७ करोड़ ६० का माल पैदा किया। इसके उत्पादन की मात्रा १० लाख टन के लग-भग है। सब मिलों में [कुल ११३] लग-भग ७० हजार करघे हैं। ६० लाख गांठों की [कच्चा पटसन] साल में कुल खपत है। दुनिया के (५७ प्रतिशत) करघे भारत में ही हैं। जूट का उद्योग भारत के लिये एक अन्य दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। देश के निर्यात में जूट के माल का बहुत बड़ा स्थान है और इस लिये विदेशी विनिमय प्राप्त करने का यह एक अच्छा साधन है। द्वितीय महायुद्ध के पहले देश के सालाना निर्यात के कुल मूल्य का १६ प्रतिशत, युद्ध के बाद [१९४६-४८] का औसत २८ प्रतिशत और देश के विभाजन के बाद १९४८-४९ में ३५ प्रतिशत तक पटसन के उद्योग का हिस्सा रहा है। १९४८-५० में यह भाग फिर २८ प्रतिशत हो गया। विदेशी विनिमय की मात्रा का यदि हम विचार करें तो १९४६-४७ में ७० करोड़ १९४७-४८ में १२७ करोड़-१९४८-४९ में १४६ करोड़ और १९४९-५० में १२७ करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय हमें पटसन के माल निर्यात से प्राप्त हुआ। अधिकांश माल अमेरिका जाता है; इस लिये ६० प्रतिशत दुर्लभ मुद्रा हमें इसी से मिलती है। भारत की पटसन के माल के उत्पादन का लगभग एकाधिकार प्राप्त है। अब हम इस महत्त्वपूर्ण उद्योग के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे।

(आरंभ) प्राचीन भारत में वस्त्र की तरह पटसन के उपयोग का भी विकास हुआ था या नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, पर १६वीं शताब्दी के आरम्भ में जूट के मान का स्पष्ट प्रचार या हमम कोइ मंदर नहीं है। १८२३ से अब टंडी [स्कोटलैंड] में जूट का उपयोग विकसित हुआ तो उसका प्रभाव भारतीय उपयोग पर बुरा पड़ा। भारत कच्चे जूट का उत्पादन और निर्यात करने वाला देश था गया। परन्तु १६वीं शताब्दी के मध्य में फिर भारत में जूट का आधुनिक उद्योग का आरम्भ हुआ। बंगाल में बिरागपुर व निकट स्थित नामक स्थान पर १८२५ में पहली जूट की बस्ताई करने वाला मिल की स्थापना हुई। १८५६ में पहला यांत्रिक शक्ति में संचालित करवा लगाया गया। हाथ करपे का जो अर्थोपेक्षक हुआ था, मिल उद्योग का स्थापना में उसका भी विनाश हो गया। पहले-पहले उद्योग की प्रगति धीमी रही, क्योंकि नया व्यवसाय था और अनुभवही और जानकार मजदूरों का अभाव था। पर १८५७ तक उद्योग की अच्छी प्रगति हो गई। इस समय मशीनरी का उत्पादन में प्रधानता थी।

प्रथम महायुद्ध तक—१६वीं शताब्दी के अन्तिम दस वर्षों में कच्चे पटसन का मुख्य भवृद्धि होजाने, अकाल पड़ने, महार मारियाँ फैलने और भय की कमा होने से इस उद्योग का एकदम का सामना करना पड़ा। एकदम का आरम्भ तो और भी धीका पहले, भाँग के अनुपात से अधिक उत्पादन होने के कारण हो गया था। पर धीरे-धीरे सफ़ट-वाल लफ़ात हो गया और प्रथम महायुद्ध तक उद्योग की स्थिति सतोष जनक रही। अब 'धनी देश' के स्थान पर 'हिसिंगल स्थान' का अधिक उत्पादन होने लगा।

प्रथम महायुद्ध और उसके बाद—प्रथम महायुद्ध जैसे ही आरम्भ हुआ पटसन के माल की डैनिक तथा दूसरे कार्यों में बहुत आवश्यकता होने लगी। यद्यपि शत्रु राष्ट्रों से होनेवाला व्यापार बंद हो गया, माल लाने-लेजाने की कठिनाई होगई, कच्चे और तैयार माल पर मात्र १६१६ से निषाद-कर लग गया, पर फिर भी युद्ध-जनित बड़ी दूर भाँग व कारण पटसन के उपयोग का अच्छा विकास और विस्तार हुआ। युद्ध के पश्चात् मान के गिर जाने से और कच्चे माल की कीमत तथा मजदूरी के बढ़ने के परिणाम-स्वरूप उत्पादन-लागत में वृद्धि हो जाने से सुदोतर मदी का इस उपयोग को भी सामना करना पड़ा। पर थोड़े समय बाद वापस स्थिति में सुधार आ गया।

विश्व-संकट—१९२९ के विश्व आर्थिक संकट का असर दूसरे उद्योगों की भांति इस उद्योग पर भी पड़ा। परन्तु यह उद्योग अधिक संगठित था। और इस-लिये इसने और उद्योगों की, जैसे कपास-उद्योग की, अपेक्षा संकट का सामना अधिक सफलता के साथ किया। जब मूल्य गिरने लगे, गोदाम में माल जमा होने लगा और मांग कम होगई तो इस उद्योग ने उत्पादन कम करने की व्यवस्थित रूप से योजना बनाली। ३१ मार्च, १९३६ तक के दस वर्षों में जूट मिल एसोसियेशन (स्थापित १९३६) ने काम के घंटे ४० प्रति-सप्ताह के हिसाब से मर्यादित कर दिये थे। पर १ अप्रैल, १९३६ से काम के घंटे ४० प्रति सप्ताह से बढ़ा कर ५४ प्रति सप्ताह कर दिये गये और १ मार्च, १९३७ से कोई प्रतिवन्ध ही नहीं रहा। बात यह थी कि जूट-मिल एसोसियेशन की जो मिलें सदस्य नहीं थी उनके साथ कोई समझौता नहीं हो सका। काम के घंटे अधिक होजाने से १९३७ और १९३८ में उद्योग की स्थिति बहुत ही विन्ताजनक होगई। आखिर बंगाल-सरकार ने एक आर्डिनेन्स के द्वारा सितम्बर, १९३८ में काम के घंटे फिर घटाकर ४५ प्रति सप्ताह कर दिये। जूट मिल एसोसियेशन और एसोसियेशन के बाहर की मिलों में कुछ समय बाद समझौता होगया और १५ मार्च, १९३९ से यह आपस में तय होगया कि काम के अधिक से अधिक प्रति सप्ताह ५४ और कम से कम ४० घंटे रहेंगे। ३१ जुलाई, १९३९ से काम के घंटे ४५ प्रति सप्ताह कर दिये गये और यह भी तय हो गया कि २० प्रति शत हेसियन तैयार करने वाले और ७३ प्रतिशत घारे तैयार करने वाले करके काम में नहीं लाये जायेंगे।

द्वितीय महायुद्ध और उसके बाद—जैसे ही द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ जूट के माल की देश और विदेश से मांग बढ़ गई। भारत-सरकार ने सैनिक दृष्टि से बहुत माल खरीदना आरम्भ कर दिया। अब काम के घंटों पर प्रतिवन्ध लगाना आवश्यक नहीं रहा। विशेष आशा से मिलों ने ६० घंटे प्रति सप्ताह काम करना आरम्भ कर दिया। उद्योग की स्थिति ने पलटा था। और १९४० के आरम्भ से १९४१ के आरम्भ तक उद्योग की स्थिति कुछ दबो हुई ही रही। और उसके बाद फिर स्थिति में सुधार आया। सच्ची बात यह है कि लम्बी दृष्टि से देखें तो यह कहना होगा कि अपने जन्म से लेकर आज तक इस उद्योग ने बराबर प्रगति की है। यदि बीच-बीच में कभी कठिनाई की स्थिति आई तो उसने उसका संगठित रूप से सामना किया। द्वितीय महायुद्ध के समय और उसके बाद भी यही क्रम चला। नीचे के आंकड़ों से इस उद्योग की पिछले कुछ वर्षों की प्रगति का हाल स्पष्ट होजाता है:—

वर्ष	उत्पादन		कुल उत्पादन		निम्नतम	
	इसिया	सेरिंग	अग्र	अग्र	अग्र	अग्र
[जुलाई-अक्टूबर]						
१९३६ ३७ से						
१९३८ ३९ का औसत	५.०१	६.२८	०.३६	११.६५	१०.०४	१४.३
१९३९ ४०	५.७६	६.४६	०.४२	१२.६४	११.४३	१४.६
१९४० ४१	४.४९	४.९९	०.३६	९.८४	८.२१	१४.५
१९४१ ४२	५.६१	५.८८	०.४६	११.९५	८.२५	१५.१
१९४२ ४३	४.८४	६.६०	०.६९	११.०५	६.८९	१०.५
१९४३ ४४	३.६३	५.४१	०.४०	९.४४	६.३५	१६.५
१९४४ ४५	४.१५	५.४५	०.४०	१०.००	६.७३	१७.७
१९४५ ४६	४.६३	५.८९	०.४१	१०.८५	८.०९	१८.८
१९४६ ४७	४.९८	५.१०	०.३४	९.६२	८.००	१७.६
१९४७ ४८	४.८३	५.२०	०.३२	१०.३५	९.५४	१२.०
१९४८ ४९				१०.१८	९.२६	

[भारत पाकिस्तान इयरबुक १९५०]

उपयुक्त तालिका से कई बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि द्वितीय महायुद्ध के ६ वर्षों में (१९३९ ४० से १९४४ ४५) कुल मिना कर जूट उद्योग की स्थिति ठीक रही। १९४० ४१ और १९४३ ४४ में उत्पादन काफी कम हो गया जबकि १९३९ ४०, १९४१ ४२ और १९४२ ४३ में उत्पादन की मात्रा काफी अधिक रही। युद्ध का अन्तिम वर्ष बाघ का सा रहा। इन वर्षों में उत्पादन ६३ लाख टन से लगाकर १२३ लाख टन के बीच में कम-ब्यादा होता रहा जबकि युद्ध के पूर्व चार वर्षों का औसत उत्पादन ११३ लाख टन से कुछ ऊपर था। महायुद्ध के समाप्त होने के पश्चात् तबसे १९४६ ४७ को छोड़कर बाकी के वर्षों में उत्पादन १० लाख टन से अधिक ही रहा है। यह ध्यान रखने की बात है कि अगस्त १९४७ में भारत का विभाजन हुआ था। और उससे पहले और बाद में देश की राजनैतिक और साम्प्रदायिक स्थिति में बहुत उथल-पुथल हुई थी। देश में साम्प्रदायिक दंगे हुए। इसका प्रभाव उद्योग घरों पर पड़ा। १९४८ के फेब्रुवारी एकट के लागू होने से काम के घंटे ४८ प्रति सप्ताह हो गये। कीयलो की भी कमी रही। १९४७ का वर्ष देश में औद्योगिक संकट का वर्ष था। गृह-उद्योग से भी इस बात का समर्थन मिलता है। इसके बाद दो वर्ष तक स्थिति ठीक सी रही पर १९४९ ५० में फिर उत्पादन में बहुत कमी आई। कुल उत्पादन ८२४ लाख टन

से अधिक नहीं हुआ। (कॉमर्स १२ अगस्त १९५० पृष्ठ २६४) जूट की खपत भी ११३ जूट मिलों की ६२ लाख गांठों से घटकर ५० लाख से भी कम गांठे होगई। १९४६-५० में उद्योग की इस संकटमयी स्थिति का मुख्य कारण तो पटसन की कमी ही था। भारतीय पटसन की मिलों के लिये यह समस्या देश के विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न हो गई थी। जब सितम्बर १९४६ में भारत ने इंग्लैंड के साथ साथ रुपये का अवमूल्यन किया और पाकिस्तान ने अवमूल्यन करने से इन्कार कर दिया तो भारतीय मिलों के लिये एक और समस्या उत्पन्न हो गई। जूट का मुख्य पहले से ही अधिक था और पाकिस्तान से आने वाले जूट में पानी का अंश बहुत होता था जिससे उसकी लागत और बढ़ी हुई हो जाती थी। अवमूल्यन के बाद जब पाकिस्तान ने अपने १००=१४४ [भारत] की दर निश्चित कर दी तो कच्चे पटसन का मूल्य ४४ प्रतिशत और बढ़ गया। भारतवर्ष में और पाकिस्तान में पटसन का मूल्य नियंत्रण कर दिया गया पर भारत ने जो मूल्य निश्चित किया वह पाकिस्तान द्वारा निश्चित मूल्य से कम था। इसलिए भारतीय मिलें पाकिस्तान का पटसन खरीदने को तैयार नहीं थी। कच्चे जूट की इस कमी का सामना संगठित रूप से मिलों के आपसी समझौते के आधार पर उत्पादन में कमी करके किया गया। इस समझौते के अनुसार [जो अप्रैल १९४६ में किया गया था] १२५ प्रतिशत कच्चे धन्द करने और सेकिंग का उत्पादन बढ़ाने का निश्चय किया गया। सेकिंग में साधारण दर्जे के पटसन की आवश्यकता होती है। इसलिये उसका उत्पादन बढ़ाने से पाकिस्तान के अच्छे प्रकार के पटसन की आवश्यकता कम की जा सकती है। यह समझौता जुलाई १९४६ में फिर बदल गया और यह निश्चय किया गया कि जुलाई १९४६ से दिसम्बर १९४६ तक महीने में एक सप्ताह मिलें धन्द रद्द करेंगी। इसी बीच में रुपये के अवमूल्यन से जो स्थिति उत्पन्न हुई उसका हम उल्लेख कर चुके हैं। इसका सामना करने के लिए पटसन के माल में भावी पणन, पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने रोक लगा दी। और जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है पश्चिम बंगाल की सरकार की सहमति से इन्डियन जूट मिल एसोसियेशन ने कच्चे जूट और जूट के माल की कीमत निश्चित कर दी। इस नीयत के अनुसार पाकिस्तान से जूट का आयात करने के लिये इन्डियन जूट मिल एसोसियेशन को लाइसेंसिंग अधिकारी नियुक्त किया गया। उसके अलावा पाकिस्तान से दूसरा कोई जूट का आयात नहीं कर सकता था। इसके अनुसार पश्चिम बंगाल की सरकार ने ३० अक्टूबर को जूट [कन्ट्रोल आब प्राइसेज] आर्डिनंस जारी किया। भारत-सरकार ने जूट के माल के निर्यात के सम्बन्ध में जूट गृह [एक्सपोर्ट कन्ट्रोल] आर्डर, १९४६ के

अनुसार मूल्य का निवारण कर दिया। इतिथि पर निदात कर ८० ६० से ३५० ६० टा कर दिया गया। राज्य का सरकारों ने भी जम्बर के दूसरे मन्त्रालय में नूट के माल के उत्पादन, पूर्ण और वितरण सम्बन्धी आकांक्षें जारी कीं। पाकिस्तान में भी कच्चे जूट पर सरकार द्वारा नियंत्रण प्रारम्भ किया गया। मूल्य निश्चित कर दिये गये। जूट-बोट की स्थापना की गई और बिना इस बोट की स्वीकृति के पाकिस्तान से जूट का निर्यात बन्द कर दिया गया। पर शीघ्र ही पाकिस्तान और भारत में भारी स्थिति पर विचार हुआ और अप्रैल १९५० में भारत-पाकिस्तान-जूट समझौता किया गया, जिस अनुसार ११ जुलाई, १९५० तक पाकिस्तान से भारत को ४० लाख मन जूट भेजने का निर्णय किया गया। पर जिस क्रम से जूट आना चाहिए था, वह मई और जून में कम बदलने के बाद भी, आया नहीं। भारतीय मिलों को जूट सम्बन्धी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि यह की-पड़ला अवसर नहीं था जब पाकिस्तान ने अपने वचन के अनुसार कच्चा जूट भेजा नहीं। मई, १९४८ में जो इंटर-डोमिनियन समझौता [जुलाई १९४८ से जून १९४८] भारत-पाकिस्तान में हुआ था [विभाजन के बाद यह पहला समझौता था] उसको पाकिस्तान ने भंग किया। सुबारा जब भारत-पाकिस्तान कमोडिटी एग्रीमेंट जुलाई १९४८ से जून १९४८ तक का हुआ उसका भावही हाल हुआ। और फिर अवमूल्यन के बाद से तो जूट का पाकिस्तान से भारत में आना ही बन्द हो गया था। उनके बाद ही फिर अप्रैल १९५० में यह समझौता हुआ। उपर्युक्त विवरण से यह सार निकलता है कि १९४९-५० में भारतीय जूट उद्योग की कच्चे माल की बराबर कठिनाई रही और इसी से उसका उत्पादन कम हुआ। अप्रैल १९५० के समझौते के परवाज़ जूट मिलों की कच्चे माल की स्थिति में थोड़ा सुधार अवश्य होने लगा था। अप्रैल १९५० [४० हजार टन] और मई १९५० [७४ हजार टन] की अपेक्षा जूट का उत्पादन बढ़ कर ७० हजार टन से कुछ ही कम था। अप्रैल १९५० के भारत-पाकिस्तान समझौते के अनुसार सितम्बर १९५० के पहले-पहले तक जिनका जूट भारत को मिलने वाला था वह सब मिल गया। उसके बाद भारत-पाकिस्तान का नूट का व्यापार बन्द हो गया। भारत-पाकिस्तान के मिदेली विनमय के प्रश्न का स्थायी हल निकले बिना भारत-पाकिस्तान से और अधिक जूट खरीदने के लिये तैयार नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि १९५०-५१ [जुलाई-जून] के आरम्भ में जूट सम्बन्धी स्थिति अस्पष्ट था। यह नहीं मालूम था कि पाकिस्तान और भारत का सम्बन्ध कैसा रहेगा, पाकिस्तान से भारत को जूट मिलेगा या नहीं, या भारत

को अपने ही पॉव पर इस मामले में खड़ा होता पड़ेगा। यद्यपि कच्चे पटसन और पटसन के माल के मूल्यों का सरकार द्वारा नियंत्रण जारी था पर इन मूल्यों पर माल मिलता नहीं था और काला बाजार पनप रहा था। दिसम्बर १९५० के मध्य में सेन्ट्रल जूट बोर्ड की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मिलों को को जाने वाली कच्चे पटसन की बिक्री का नियंत्रण करना था। मिलों को जूट बोर्ड के द्वारा ही कच्चा पटसन खरीदना अनिवार्य था, वे सोचा वेचने वाले से नहीं खरीद सकती थी। फरवरी १९५१ के अन्त में भारत-पाकिस्तान व्यापारिक समझौता हुआ। इस समझौते की अवधि १६ महीने की है। जहाँ तक जूट का सम्बन्ध है इस समझौते के अनुसार पाकिस्तान भारत को ६० जून, १९५१ तक १० लाख गॉट्स जूट भेजेगा। १३ लाख गॉट्स जूट तो पाकिस्तान-सरकार भारत-सरकार को एक निश्चित मूल्य पर देगी और बाकी की ६३ लाख गॉट्स खुले बाजार में से खरीदना होगा। जुलाई-जून १९५१-५२ में पाकिस्तान भारत को २५ लाख गॉट्स पटसन भेजेगा। इस समझौते से जूट की कमी की जब आशंका न रही तो जूट पर से ६ मार्च १९५१ से मूल्य-नियंत्रण भी हटा लिया गया है। मूल्य नियंत्रण कच्चे पटसन और पटसन के तैयार माल दोनों पर से ही हटा लिया गया है। जूट बोर्ड बना रहेगा और अब उसका काम मिलों में जूट का उचित और न्यायपूर्ण बटवारा होकर इसकी व्यवस्था करना होगा। १९५०-५१ में जूट के उत्पादन में भी वृद्धि होगी ऐसी आशा है, क्योंकि जैसा कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है अब मिलों को कच्चे माल की फटिनाई नहीं होगी। जुलाई १९५० से जनवरी १९५१ तक के जो ऑफसेट प्रकाशित हुए हैं [कामर्स ३ मार्च, १९५१ पृष्ठ ३८०] उनसे भी इस बात का समर्थन होता है। इन सात महीनों में [जुलाई १९५० से जनवरी १९५१] कुल उत्पादन ५,११,२०० टन हुआ जब कि १९४६ में इसी समय का उत्पादन ४,६८,१०० टन था।

अब तक हमने इस बात का उल्लेख किया है कि पटसन उद्योग में उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय महायुद्ध के समय से आज तक क्या-क्या उतार-चढ़ाव आए। देश के विभाजन और रुपये के अवमूल्यन से कच्चे पटसन और उसके मूल्य की जो समस्याएँ पैदा हुईं उनका कैसे सामना किया गया। पर पटसन के उद्योग के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका बहुत कुछ आपार निर्यात पर है। जो तालिका ऊपर दी गई है उसे ध्यान से देखने से मालूम होगा कि कुल उत्पादन का बहुत बड़ा भाग निर्यात ही होता है। यह भाग लगभग ५५ प्रतिशत (१९४९-४३) से लगा कर ६० प्रतिशत तक रहा है। १९४६-५० में उत्पादन

म कमी होने से निर्यात घर भी असर होगा स्वामाविद्ध था। अथमूल्यन क नार
जुट के माल की निर्यात संबंधी मूल्यों का नियन्त्रण भी हो ही गया था। इसके
पहले भी किन्ना माल कहां-कहां भेजा जासकता है इस पर सरकार का नियन्त्रण
था ही। द्वितीय महायुद्ध के बाद जब १९४६ के अन्त में जुट के मूल्यों (प्राथमिक
और निर्गत सम्बन्धी) पर से नियन्त्रण हटा लिया गया, तब सरकार ने जुट क
निर्यात पर नया नियन्त्रण लागू कर दिया था कि किस मात्रा में और किन देशों
को जुट का निर्यात होसकता है। अर्थात् परवर्ती १९५१ के अन्त में मूल्य नियन्त्रण
हटजाने के बाद भी भारत सरकार की यह अधिकार तो है ही। यह हम पहले
निलखुने हैं कि अथमूल्यन के बाद जुट के माल पर (हेसियन) निर्यात-कर ८० व०
मे ३५० व० टन कर दिया था। कोरिया युद्ध के आरम्भ हो जाने के बाद जब
अमरीका म जुट के माल का मूल्य बहुत बढ़ने लगा तो निर्यात कर में भी परत
३५० व० टन से ७०० व० टन और बाद में १५०० व० टन (नवम्बर १९५०) तक
वृद्धि कर दी गई। ऐसा कहा जाता है कि इसने अधिक निर्यात कर लगा देने से
अमरीका ने हमारा माल खरीदना कम कर दिया है। निर्यात सम्बन्धी जो सर
कार का नियन्त्रण है उसका कारण इस कमी की पूर्ति दूसरे देशों को माल भेज
कर भी नहीं हो सकता।

भारत - जुट उद्योग की प्रगति का विवरण हम ऊपर के चुक है। अब
परन यह है कि उसने भविष्य के बारे में नया अनुमान लगाया जा सकता है।
देश के विमानन से जुट उद्योग के लिए कच्चे माल की बड़ी समस्या पैदा हो गई
है। जुट के माल के उत्पादन-लागत का ७० प्रतिशत भाग कच्चे जुट का होता
है। इससे इसका महत्त्व स्पष्ट है। भारत की जुट की मिलों को ६० लाख गांठ
पटसन प्रति वर्ष चाहिये। इसके अलावा लगभग ६ लाख गांठ निर्यात के लिए
और १३ लाख गांठ घरेलू खपत के लिए चाहिये। इस प्रकार कुल ७३ लाख
गांठ हमें चाहिये। विमानन के पहले के आर्यों को अपार मान कर यदि हम
विचार करें तो १९४५-४६ में भारत में १५.५६ लाख गांठ जुट उत्पन्न हुआ था
जब कि पाकिस्तान में ६२.३५ लाख गांठ उत्पन्न हुआ था। युद्ध के पूर्व के चार
वर्षों का (१९३६-३७ से १९८८-८९) औसत देखने से मान्य होता है कि भारत
में २०.०२ लाख गांठ और पाकिस्तान में ६३.६० लाख गांठ जुट पैदा हुआ था।
१९४०-४१ में भारत में २७.५६ लाख गांठ और पाकिस्तान में १०.४१ लाख
गांठ जुट उत्पन्न हुआ। विमानन के बाद से भारत वर्ष में कपास के साथ साथ
जुट में भी स्वावलम्बी होने का प्रयत्न करना आरम्भ किया। इस प्रयत्न में भारत
को सरलता मिली है। द्रावगंडोर, मद्रास और बम्बई में जुट पैदा करने के लिये

जो प्रयोग किये गये वे सफल हुए हैं। पर इन प्रयोगों का देश को पूरा लाभ नहीं मिल सका है। १९४७-४८ में १६.६६ लाख गांठ, १९४८-४९ में २०.२७ लाख गांठ और १९४९-५० में ३१.१७ लाख गांठ पटसन पैदा किया गया। ऐसी आशा की जाती थी कि १९५०-५१ में १२ लाख गांठ जूट का उत्पादन और बढ़ जायेगा। पर यह आशा सफल नहीं हुई। १९५०-५१ में ३२.७ लाख गांठ जूट ही पैदा हुआ। (कोमर्स १४ अप्रैल १९५१) जूट की समस्या केवल उत्पादन-वृद्धि की ही नहीं है, जूट के प्रकार का भी सवाल है। ऊंची प्रकार का जूट भारत में कम होता है और वह हमें पाकिस्तान से मँगाना पड़ता है। लगभग ७० प्रतिशत जूट हमारी मिलों को पाकिस्तान में पैदा होने वाला जूट चाहिये। यदि हम जूट में स्वात्मन चाहते हैं तो हमें अच्छे प्रकार का जूट पैदा करना होगा या फिर नीचे दर्जे का माल अधिक मात्रा में तैयार करना होगा। इसी विषयता से पिछले वर्षों में हमारी मिलों में हेसियन का उत्पादन कम और सेकिंग का अधिक हुआ है। जहाँ १९४६-४७ में कुल उत्पादन में हेसियन ४९ प्रतिशत और सेकिंग का ५२ प्रतिशत था वहाँ १९४८-४९ में हेसियन का भाग ३७ प्रतिशत और सेकिंग का ५४ प्रतिशत हो गया।

दूसरा प्रश्न: जिसका भारत के जूट-उद्योग पर असर पड़ सकता है वह है स्वयं पाकिस्तान में जूट उद्योग के विकास का। इस समय पाकिस्तान में एक भी जूट की मिल नहीं है। पर पाकिस्तान का ध्यान इस ओर है और यह स्वाभाविक भी है। ऐसी स्थिति में भारत को जूट-उद्योग का जो प्रायः आज एकाधिकार, सा प्राप्त है वह सुदूर भविष्य में भी बना रहेगा यह आशा नहीं की जा सकती। यह ठीक है कि निकट भविष्य में कोई बड़ा खतरा इस ओर से नहीं माना जा सकता। पर कुछ लोगों का यह विचार है कि अगर भारत का जूट का माल खस्ता नहीं हुआ तो स्पेन, फ्रांस, इटली आदि के जूट की मिलों का माल भारत के माल को अपेक्षा अधिक बिखेगा। आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी आस्ट्रेलिया में जूट के उत्पादन का प्रयत्न कर रहे हैं।

तीसरा प्रश्न है जूट के माल के स्थान पर दूसरे माल के उपयोग का। पिछले वर्षों में यह प्रवृत्ति बढ़ी है। कपास और कागज के थैलों का अमेरिका आदि में जूट के थैलों के स्थान पर उपयोग किया जाता है। रेयोन स्टेपल के थैले भी जूट के थैलों की जगह काम आते हैं। अमेरिका भी इस दिशा में प्रयत्नशील बताया जाता है कि जूट के माल के सम्बन्ध में उसकी भारत और पाकिस्तान पर निर्भरता कम हो जाये। जूट के माल का मूल्य जब बढ़ता है तो यह खतरा अधिक होता है। फिर भी भारी काम के लिये जूट के बोरे ही उपयोगी होते हैं।

निकट भविष्य में उन श्रौर से कोई बचा कर नहीं है, यह जानते हुए भी हमें मतकं तो रहना ही है। इंडियन जूट मिल एसोसियेशन का इस श्रौर ध्यान है भी।

जूट उद्योग के भविष्य के बारे में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे जैसे दुनिया का व्यापार बढेगा और उत्पादन और आर्थिक स्तर बढ़ेगा जैसे-जैसे जूट के माल की माग भी बढेगी। भारतीय जूट उद्योग के भविष्य के बारे में विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उद्योग के बारे में हमें अपने निश्चित तो नहीं रह सकते जितने आज तक रहे हैं। औद्योगिक लोग पर हमें विशेष शोर देना होगा ताकि हमारे देश में उत्पन्न होने वाले जूट के मितों में अच्छा से अच्छा उपयोग हो, क्या जूट ज्यादा अच्छा हमारे देश में पैदा किया जाये, उत्पादन बिधि में सुधार हो ताकि उत्पादन-लागत कम हो और दूसरे प्रकार के माल से जिस प्रतिस्पर्धा को आसना आता हो रहा है वह कम से कम हो। निकट भविष्य में तो चाहे नहीं पर मुझे भविष्य में दुनिया के बाजार में भारत को पाकिस्तान के जूट के माल की प्रतिस्पर्धा तो करनी होगी। आज का उत्पाद एकधिशार अन्ततोगत्वा समाप्त होगा। पर यदि दूसरी आवश्यक बातों की और जितना ऊपर उल्लेख किया गया है उस पर ध्यान रखा तो भारतीय जूट-उद्योग के भविष्य के बारे में चिन्ता का कोई कारण नहीं है।

ऊनी मित उद्योग — कपास और जूट के उद्योगों के मुकाबले में ऊनी उद्योग का देश के आर्थिक जीवन में बहुत कम महत्व है। यह उद्योग भारत में ही केन्द्रित है और पाकिस्तान में मुसवाटित मिल तो एक भी नहीं है। ऊनी उद्योग तीन प्रकार का है — (१) ऊनी मिल उद्योग (२) ऊनी एह उद्योग (३) शालीचे का उद्योग। शालीचे का उद्योग, एह उद्योग और पेंकटरी उद्योग दोनों ही प्रकार का है। उना मिला में भी तीन प्रकार हैं। पहली प्रकार का वे मिलें हैं जिनमें 'पूलन' [मीचे दर्जे का] और बोस्टेंड [बढ़िया] दोनों ही प्रकार के कपड़ा तैयार होते हैं। दूसरी प्रकार की वे मिलें हैं जिनमें केवल एक प्रकार का कपड़ा तैयार होता है। तीसरी श्रेणी में अमृतसर की मिलें हैं जो तैयार धन खरीदती हैं और फिर उसका बुनाई और रंगाई आदि करता है। पहली श्रेणी में कानपुर और धारोवाल की ऊनी मिलें आती हैं। ऊनी मिल उद्योग में २५ हजार आदमी काम करते हैं। एह उद्योग में लगभग १ लाख और शालीचे का उद्योग में लगभग ४० हजार आदमी काम करते हैं। मिल उद्योग में बोस्टेंड उद्योगों का संख्या १७,५००, पूलन उद्योगों की ५०,००० और पॉवरलूम की २,२०० है। मिलों की उत्पादन शक्ति ३ करोड़ पाँच प्रति वर्ष मानी जा सकती

है। भारत के विभाजन के समय १७ बड़ी और २२ छोटी मिलें थीं। ऊनी मिल-उद्योग में लगभग ४-५ करोड़ रुपये की पूँजी लगी होगी।

प्रारम्भ :—भारत की पहली ऊन की मिल १८७६ में कानपुर में स्थापित की गई। यहाँ कच्चे माल और बाजार दोनों की ही सुविधा थी। दूसरी मिल धारीवाल [पंजाब] में १८८२ में स्थापित हुई। बम्बई में १८८८ में और बेंगलोर में १८८६ में और मिलें स्थापित हुईं। प्रथम महायुद्ध के समय तक भारत में ५-६ मिलें थीं।

प्रथम महायुद्ध और उसके पश्चात्—प्रथम महायुद्ध में ऊनी मिल-उद्योग को प्रोत्साहन मिला। बम्बई में खास तौर से कुछ नई मिलें स्थापित हुईं। युद्ध के बाद १९१६-२० में नई मिलें स्थापित हुई थीं। युद्धजनित यह सफलता स्थायी नहीं साबित हुई। इटली और जापान के माल की भारतीय मांग से प्रतिस्पर्धा होने लगी। इटली के कम्बल, और ट्वीड और जापान का बढिया [बोस्टेड] कपड़ा भारत के बाजार में खूब विकने लगा। १९३१-३२ में ३७ लाख गज माल बाहर से आयात हुआ था। १९३४-३५ में १ करोड़ ६७ लाख गज माल बाहर से आया। केवल जापान के माल का हिस्सा १९ लाख गज से बढ़कर ७९ लाख गज हो गया था। इस पर से ऊनी मिल उद्योग ने संरक्षण की माँग की। प्रशुल्क मंडल ने १९३५ में इस सम्वन्ध में जांच की और संरक्षण की सिफारिश की। पर भारत की विदेशी सरकार ने संरक्षण देने से इसलिये इन्कार कर दिया कि कानपुर और धारीवाल की मिलों ने संरक्षण की माँग नहीं की थी। कानपुर की मिलें अंग्रेजों के हाथों में थी, यह ध्यान रखने की बात है। विश्व संकट और जापानी मुद्रा के विनिमय दर में गिरावट आने से और भारत का विनिमय दर ऊँचा होने से इस उद्योग को विदेशी माल से और खास करके जापान से जो प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी वह और भी अधिक होगई।

द्वितीय महायुद्ध और उसके बाद :—द्वितीय महायुद्ध के कारण ऊनी माल की भी माँग बढ़ी और इससे इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला। सरकार ने ऊनी माल अधिक मात्रा में खरीदना आरम्भ कर दिया। इसका परिणाम ऊनी मिलों का उत्पादन बढ़ने का हुआ। पर जहाँ बढ़ी हुई माँग के कारण द्वितीय महायुद्ध ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया वहाँ बाहर से ऊनी यार्न न आने से मिलों को कठिनाई भी हुई। अमृतसर और लुधियाना की मिलों को जहाँ यांत्रिक शक्ति द्वारा संचालित करणों पर बनाई का काम होता था बहुत धक्का पहुँचा। परन्तु बाद में भारत-सरकार ने इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया से यार्न

मैदान की समस्या पर दो ची और इससे मिला की बटिनहि मुल कम हो गी। मुद्र क पहले चार वर्षों का (१९३६-१९३६) औद्योग उत्पादन १ करोड़ ११ लाख पौंड था। मुद्र क बाद सन १९४६ में उत्पादन की मात्रा २ करोड़ ७० लाख पौंड थी। मा १९४७ म उत्पादन मोहा कम हो गया। इस वर्ष २ करोड़ ४० लाख पाउ मान पैदा हुआ। १९४६ में हीमन की दृष्टि स ६६ करोड़ रुपा का उत्पादन हुआ पर १९४७ म ८० करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ। उत्पादन की मात्रा म कमो हो। पर भी मूल्य का बढ़ा घ्या देने योग्य है।

१९४० में जब दश का विमात्रा हुआ ना उगका अक्षर इस उद्योग पर भा एक हद ना पडा। अविमानि भारत म कच्चे ऊा की बुन पैदावार ८६ करोड़ पौंड थी। भारत क विमात्रा मे ६ करोड़ पौंड भारत मे और १६ करोड़ पौंड पाकिस्तान म पैदा होने का अनुमान लगाया जा सकता है। विमात्रन का कच्चे माल की दृष्टि मे ऊन उद्योगपर उत्रा पातक अक्षर ना पडा जितना कराग अक्षरा पटमन क उद्योग पर पडा। ऊनी माल के उत्पादन का अहां तर समाल है विमात्रा से उसमें भी कमी तो आइ है। और इसका सबसे उरा अक्षर नुर्खे पत्राव पर पडा है। वहां का ऊनी मिल उद्योग सबसे अधिक सगटित था और विमात्रन क कारण सबसे अधिक अक्षयवस्था भी पडा हुई। इन मिलें जो मुगलमानों क हाथों मे थी वे मुगलमानों के पाकिस्तान चले जान म दूसरी क हाथों म आ गई। धारीवाल, प्रमृतनगर और पानापन का ऊनी मिला म अविचार काम करने वाले मुगलमान थे। उनक पाकिस्तान चले जाने स भा इस उद्योग की बन्त बन्ता लगा है क्योंकि ऊन के उद्योग में कुशल मजदूर का विशेष महत्व है। अख्ये प्रकार का ऊन जो पाकिस्तान से आता था उस पर भी विमात्रन का अक्षर पडा है। पाकिस्तान का बाह्यर भा अब भारत के हाथ से निहल गया है। ऐसा अनुमान है कि कुल उत्पादन के लगभग १० प्रतिशत भाग की पाकिस्तान और विशपनया पश्चिमी पत्राव में खपन होती थी।

संशय—अब प्रश्न यह है कि ऊनी मिल उद्योग का भविष्य हमारे देश में क्या है। ऊनी माल का आत्र भी देश में उत्पादन की अपेक्षा अधिक मात्रा है, खास तौर से बढ़िया माल का। उदाहरण क लिये रमें और बढ़िया कामलों की मात्रा देश में काफी है। १९४५ में भारत सरकार ने ऊनी उद्योग के लिए जो पैनल नियुक्त किया था उसने यह अनुमान लगाया था कि भारत म (अविमात्रित) ३ करोड़ पौंड की मात्रा थी अब कि उत्पादन १ करोड़ १८ लाख पौंड और विदेशी माल का आवात ८० लाख पौंड क लगभग था। अर्थात् १ करोड़ पौंड

की मांग अधिक थी। और यदि विदेशी माल को निकाल दें तो उत्पादन से मांग की अधिकता लगभग १६० लाख गौड के हो जाती है। विभाजन के बाद इस स्थिति में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया है। आज पाकिस्तान में ऊनी उद्योग नहीं है। हां, भविष्य में उसका विकास हो सकता है। पर उसमें समय लगेगा। इस बीच में मध्यपूर्व और निकट पूर्व के देशों में भारतीय माल के लिये बाजार पैदा किया जा सकता है। देश के अन्दरूनी बाजार का भी, जैसे-जैसे हमारा आर्थिक स्तर ऊपर उठेगा, विस्तार होगा। इसलिये ऊनी उद्योग की बाजार की कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। कच्चे माल के बारे में यह स्थिति है कि बढ़िया ऊन की देश में कमी है। आज भी इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया तथा न्यूजी-लैंड से बढ़िया ऊन हमारे देश में आती है। देश के विभाजन से भी बढ़िया ऊन पैदा करने वाला प्रदेश (पश्चिमी पंजाब) भारत से अलग हो गया है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि बढ़िया ऊन पैदा करने की ओर हमारे देश में अधिक ध्यान दिया जाये। ऊनी माल की उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ बढ़िया माल का उत्पादन आवश्यक है। यह भी बढ़िया ऊन पैदा करने से ही सम्भव हो सकता है। ऊन के मिल उद्योग की भावी प्रगति के लिये मशीनों और कुशल काम करने वालों की भी बड़ी आवश्यकता है। द्वितीय महायुद्ध के समय पुरानी मशीनरी बदलने की सुविधा न होने से आज मशीनरी बदलने की बहुत आवश्यकता है। सरकार इस ओर आवश्यक सुविधा देने के लिये प्रयत्नशील भी है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि भारत में ही मशीनरी का उत्पादन किया जाये। ऊनी उद्योग सम्बन्धी पेनल ने भी इसकी आवश्यकता पर जोर दिया था। कपास के उद्योग सम्बन्धी मशीनरी का उत्पादन इस दिशा में सहायक होगा क्योंकि दोनों उद्योगों में कई बातें समान हैं। ऊन के उद्योग में काम करने वालों की आवश्यक ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। यदि उपर्युक्त सब बातों की ओर हमने ध्यान दिया तो इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। भारत में शालीन बनाने के लिए बहुत अच्छा ऊन पैदा होता है। फिर भी इस उद्योग का समुचित विकास नहीं हुआ है इसकी सबसे बड़ी कठिनाई आधुनिक मशीनरी का अभाव है।

रेशम का उद्योग—भारत के आधुनिक उद्योगों में रेशम का उद्योग भी है। ऊनी मिल-उद्योग की भांति भारत के आर्थिक जीवन में इस उद्योग का महत्त्व भी थोड़ा है, यद्यपि यह भारत का अत्यन्त प्राचीन धन्धा रहा है, जैसा कि कपास के उद्योग के बारे में भी कहा जा सकता है। ऊनी उद्योग की भांति रेशम के उद्योग में भी हाथ-करघे का विशेष महत्त्व है और मिल-उद्योग का कम। हम यहां मिल-

उद्योग का ही विचार करेंगे। इस उद्योग में लगभग ५० हजार आदमी काम करते हैं। विभाजन के पहले रेशम और नकली रेशम के वारिक गति द्वारा संचालित करघों की कुल संख्या १२ हजार थी। इसमें पाकिस्तान का हिस्सा तो नगण्य था—१८० करघों में भी कम। इसका अर्थ यह है रेशम का मिल उद्योग भारत में ही केन्द्रित है। यहाँ बात हाथ के करघों के बारे में भी है। यह ग्नेय शहरी उद्योग है और उत्तर प्रदेश, काश्मीर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, और म्यांमर के राज्यों में प्रधानतया पाया जाता है। मिल उद्योग का वारिक उत्पादन १५ करोड़ गज रेशम और नकली रेशम का माना जा सकता है। भारत के विभाजन के समय मिलों की कुल संख्या २८ थी, उसमें से २०४ भारत में और ६ पाकिस्तान में थी। ३० जनवरी, १९४६ को रेशम के मिल उद्योग में लगभग १८ हजार करघे लगे हुए थे। इनके अलावा लगभग ८ हजार हाथ के करघे भी इस उद्योग में लगे हुए हैं।

सारम्भ—रेशम व मिल उद्योग का भारत में इसी शताब्दी में आरम्भ हुआ। कई कारणों से इसकी प्रगति धीमी हुई है। इसके उत्पादन में कलात्मक दृष्टि का अति महत्त्व है जो आधुनिक ढंग के प्रमापी करण प्रधान कारणों में सम्मिल नहीं हो सकती। उशल मजदूर और उपयुक्त मशीनरी का भारत में अभाव रहा है। अलग अलग प्रान्तों (राज्यों) में भाग भी एक ही नहीं है, क्योंकि जगह जगह की पोशाक और रवि में भी बहुत अन्तर है। पिछले वर्षों में इस उद्योग के मार्ग में कठिनदया आई हैं। सवार व्यापी आर्थिक मंदी, स्वतंत्रता के परिवर्तन के बाद मुद्रा के मूल्यों में हास और नील, जापान तथा युरोपीय माल की प्रतिस्पर्धा जो विविध दर में मिराबट आने से और भी अधिक घातक हो गई, तथा विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा अपने अपने देश के रेशम के उद्योग को मिलने वाली सहायता के कारण भारत के रेशम के उद्योग को बधेष्ट हानि हुई है। १९३४ में जब इंडियन टेक्सटाइल (टेक्स्टाइल प्रोटेक्शन) एक्ट पास हुआ था तो कपास व उद्योग के साथ साथ उसके द्वारा रेशम के उद्योग को भी सरक्षण दिया गया था। कच्चा रेशम, रेशम का तार (थान) रेशमीन कपड़ा, रेशम का मिलावटी कपड़ा, और नकली रेशम का कपड़ा तथा मिलावटी कपड़ा सभी पर आयात-कर लगाये गये थे। नकली रेशम के तार पर भी आयात-कर बढ़ाया गया था। पर एक तो यह आयात कर कम थे और दूसरे विदेशी माल की प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही थी, इस लिए इस उद्योग की स्थिति सुधर नहीं सकी। १९३८ में सरक्षण जारी रखने का प्रश्न फिर टेक्सटाइल बोर्ड के सामने प्रस्तुत हुआ और उसने सरक्षण-कर की दरों में वृद्धि करने का सिफारिश भी की। परन्तु सरकार ने

निर्णय करने से इन्कार कर दिया। उसका कहना यह था कि युद्ध जनित अनिश्चित अवस्था में कोई निर्णय करना उचित नहीं है। पर सरकार को यह नीति दोष-पूर्ण थी।

द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात्:—द्वितीय महायुद्ध के कारण इस उद्योग को भी अन्य उद्योगों की तरह प्रोत्साहन मिला। बाहर के माल की प्रतिस्पर्धा कम हो गई। जापान और इटली से तो माल आना बिल्कुल बन्द हो गया। पर ज्ञानान से कच्चा रेशम आना बन्द होने का असर रेशम के उद्योग पर अच्छा नहीं पड़ा। फिर भी कुल मिलाकर युद्ध से प्रोत्साहन ही मिला। युद्ध के समाप्त होने ही फिर उद्योग की स्थिति बिगड़ने लगी। १९१४ में जो संरक्षण रेशम के उद्योग को दिया गया था वही १९४२ तक जारी रहा क्योंकि १९३८ की टेरिफ बोर्ड की सिफारिशों पर उस समय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। १९४२ में इन सिफारिशों के अनुसार सब आयात-करों में वृद्धि की गई। यह संरक्षण १९४६ तक जारी रहा। इस वर्ष फिर टेरिफ बोर्ड में इस उद्योग के संरक्षण के प्रश्न पर विचार किया और संरक्षण-कर बढ़ाने की सिफारिश की। सरकार ने इन सिफारिशों के आधार पर नए संरक्षण-करों की घोषणा कर दी इसके अनुसार कच्चा रेशम और रेशम को कोकून पर और रेशम के तार [थाने] पर २५ प्रतिशत मूल्य के अनुसार + १४ आ. प्रति पींड + $\frac{1}{4}$ कुल कर का जो अब तक आयात कर था उसे बढ़ा कर अब ३० प्रतिशत + २५ व. १२ आ प्रति पींड या कुछ प्रकार के तार पर ३० प्रतिशत + ४३ व प्रति पींड या केवल ३० प्रतिशत कर दिया गया। इसी प्रकार रेशमीन कपड़े पर अभी तक जो आयात-कर था [५० प्रतिशत + १ व० प्रति पींड + $\frac{1}{4}$ कुल कर का, या ५० प्रतिशत + १३ प्रति पींड + $\frac{1}{4}$ कुल कर का, या ५० प्रतिशत + २ व. प्रति पींड + $\frac{1}{4}$ कुल कर का] उसे बढ़ाकर ७५ प्रतिशत + ५ व. ८ आ. प्रति पींड या ७५ प्रतिशत + ४ व० प्रति पींड कर दिया गया। यह संरक्षण की दरें ३१ मार्च १९५१ तक के लिए तो जारी कर दी गई थी और बाद में ३१ मार्च १९५२ तक उनकी अवधि बढ़ाई जाने का निश्चय था। यह संरक्षण की मात्राएँ पर्याप्त मानी जानी चाहियें। रेशम के तार व कच्चे रेशम पर सरकार की स्पेसिफिक ड्यूटी में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार भी है। पर जैसा हम आगे चलकर लिखेंगे केवल संरक्षण के आधार पर ही किसी उद्योग का और इसलिये रेशम के उद्योग का भी विकास नहीं हो सकता। इसके पहले कि रेशम के उद्योग के भविष्य के बारे में हम विचार करें यह जान लेना आवश्यक है कि देश के विमानन का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि अविमानित भारत की २८० मिलों में से २७४ जिनमें सभी

[६८] खास खान मिलों का शामिल है हिंदुस्तान में है। कच्चे रेशम का वहाँ तक सम्बन्ध है विभाजन का उस पर भी कोई असर नहीं पड़ा है। अधिकार वहाँ रेशम मैगूर, मद्रास, पश्चिमी बंगाल और काश्मीर में पैदा होता है। रेशम का उत्पादन पूर्वी पंजाब में काम करने वाले मुसलमान थे। उनके पाकिस्तान में चले जाने से उद्योग पर कुछ बुरा असर अवश्य पड़ा है। पाकिस्तान का बाजार भी अब विदेशों का भार हो गया है। और उस पर उस तरह से अब हम भिन्न नहीं रह सकते। अस्तु, विभाजन के कारण ये दोनों हानियाँ अवश्य हुई हैं।

भविष्य — अब प्रश्न यह है कि रेशम का उद्योग का इस देश में भविष्य क्या है? इस सम्बन्ध में पहले एक बात समझ लेनी चाहिए कि रेशम का उद्योग दूसरे धरम उद्योगों से अधिक पेशीदा है। रेशम का तार [यान] कपड़े बुनने की अवस्था में आये उससे पहले आवश्यक बातों में सुधार करना आवश्यक है। पचा शहतूत की खेती की उन्नति, क्योंकि रेशम का कीड़ा उसी पर पनपा है, बढिया बीज की, जो रोग मुक्त हो, पर्याप्त मात्रा, रेशम के कीड़ों का घामारियों का नियंत्रण, रेशम के कीड़े पालने, बीज तैयार करने, संगठन और बिक्री का प्रबंध, रेशम कातने के उद्योग का विनाश और सहायक पदार्थों [बाई प्रोडक्ट] का पूरा पूरा उपयोग, और उपर्युक्त सब मामलों में विभिन्न राज्यों में सहयोग। हाँ सब विद्याओं में आवश्यक सुधार करने का दृष्टि से भारत सरकार ने एक मन्त्रीय रेशम मण्डल [सिंदूर मिश्र बोर्ड] का हाल में स्थापना की है। इसका कार्यालय बेंगलूर में है। इसका काम कच्चे रेशम के उद्योग का उन्नति के बारे में भारत सरकार को सलाह देना है और इसे इस उद्योग पर उपकरण [सिच] लगाने का अधिकार भी है। १९४६ में जब टेक्स्टाइल बोर्ड ने रेशम के उद्योग के सार्वजनिक प्रश्न पर विचार किया तो उसने भी इस सम्बन्ध में कई प्रकार के सुधारों का आवश्यकता पर जोर दिया। रेशम सम्बन्धी खोज के लिये पर्याप्त सुविधा और साधन का व्यवस्था, विदेशी रेशम के कीड़ों के लिए एक केन्द्रीय बीज के स्टेशन का स्थापना, रेशम के कीड़ों के रोगों का कानून द्वारा नियंत्रण, रोग मुक्त बीजों का धीरे धीरे अनिवार्य उपयोग चर्खा द्वारा रेशम की रील तैयार करने के काम में सुधार, विदेशों में विगेषकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था, और रेशम के उद्योग के लिए आवश्यक मशीनरी तथा दूसरा सामान प्राप्त करने में सरकार द्वारा सहायता—ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका टेक्स्टाइल बोर्ड ने स्पष्ट तौर से उल्लेख किया है। मैदूर की सरकार तथा दूसरे राज्यों की सरकारों का इन बातों का और ध्यान भी गया है। केन्द्रीय रेशम मण्डल, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है, इस दिशा में बहुत काम कर सकता है। यहाँ यह बात याद रखनी की है कि

रेशम-मिल-उद्योग की सफलता के लिये आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारे देश में कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़े, उसका प्रकार बढ़िया हो, और उसके मूल्य में कमी हो। हमारे देश में २४ लाख पौंड कच्चा रेशम उत्पन्न होता है। उससे हमारी ६० प्रतिशत माँग पूरी होती है। बाक़ी का रेशम बाहर से, जैसे जापान, इटली आदि स्थानों से आता है। हमारे देश में रेशम पर बहुत ऊँचा आयात-कर होने पर भी बाहर का रेशम सस्ता पड़ता है, और वह बढ़िया भी होता है, इसलिये हमें इन दोनों बातों की और भी (अधिक उत्पादन के साथ-साथ) ध्यान देना चाहिये। केन्द्रीय रेशम मण्डल के तत्वावधान में एक टेक्निकल विक्राम समिति की स्थापना रेशम का उत्पादन दुगुना करने और मूल्य को कम करने-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिये की जा चुकी है। रेशम की रील बनाने का काम आज भी हाथ के चक्के पर अधिकतर होता है। इसमें सुधार करना चाहिये, पर इसके सुधार की आखिर मर्यादा है। इसलिये 'फिलेचर' पर रील करने के काम को राज्य की सरकारों को प्रोत्साहित करना चाहिये। ऐसा कई राज्य कर भी रहे हैं। सहकारिता के आधार पर भी इस काम को करना चाहिये। सहकारिता का आधार रेशम पालने और बुनने में भी किया जाना चाहिये। उपर्युक्त विवरण का सार यह है कि भारत में रेशम के उद्योग के लिये यथेष्ट गुंजाइश है परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि उससे सम्बन्ध रखने वालों समस्याओं को राज्य की और केन्द्र की सरकारें तत्परता से हल करने का प्रयत्न करें। भारत-सरकार और राज्य की सरकारों का इन ओर प्रयत्न चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं।

रेयोन उद्योग—रेयोन [Rayon] एक प्रकार के तकली रेशम है, इस तरह की शलत धारणा कई लोगों को आज भी है। वास्तव में रेयोन सेलूलोज या सेलूलोज बेस से रासायनिक ढंग से तैयार किया गया ऐसा रेशा या तार है जो बुना जा सकता है। इसकी तैयार करने की चार मुख्य विधियाँ हैं। इनके नाम इन प्रकार हैं:—नाइट्रो-सिल्क, कुपरामोनियम सिल्क, विसकोज़ सिल्क, और एसीटेड सिल्क। इनमें विसकोज़ सिल्क-पदार्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेयोन तैयार करने के लिये प्रमुख कच्चा माल सेलूलोज है। ये तमाम पदार्थ जिनसे सेलूलोज मिल सकता है रेयोन बनाने के काम में आ सकते हैं, जैसे कपास, बांस, लकड़ी, पटसन आदि। पर लकड़ी की छुन्दी इस काम के लिये अत्यन्त उपयुक्त है और उसमें भी स्प्रूस की लकड़ी खास तौर से। विसकोज़ पदार्थ में तो स्प्रूस की लकड़ी की छुन्दी ही काम में लेते हैं। रेयोन उत्पादन के लिये दूसरी आवश्यकता रसायन-पदार्थों की है जैसे—कॉस्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाई-

सलफाइट, सोडियम मनरेट, सोडियम सलफाइड। इस वास्ते रेयोन उद्योग की सफलता के लिये यह भी आवश्यक है कि रसायन-व्ययों का उपयोग पूर्णतः विकसित हो। जीवला, पानी और यांत्रिक शक्ति भी वषेष्ट मात्रा में चाहिए। आरम्भ में तो रेयोन का उपयोग असली रेशम की बजाय ही किया जाता था। परन्तु अब तो यह कई कामों में आता है और इसका अपना वस्तुयोग में एक स्वतन्त्र भूमा है। रेयोन के बारे में एक बड़ा भ्रम यह है कि यह टिकाऊ नहीं होता। पर यह धारणा सही नहीं है। द्वितीय महायुद्ध में इसकी टायोसिल बहुत मजबूत हो चुका है। और आज तो रेयोन का दुनिया के घुने जा सकने वाले पदार्थ [टेक्सटाइल फाइबर्स] में दूसरा स्थान है। रेयोन का उपयोग असली रेशम, कपास, ऊन आदि के साथ मिलावट करने के लिये भी किया जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक रेशा [नेचुरल फाइबर्स] के साथ रेयोन के रेशों की मिलावट करने के लिये यह आवश्यक है कि रेयोन के रेशों की लम्बाई भी उन प्राकृतिक रेशों की लम्बाई के समान हो। नकली रेशम के एक निश्चित लम्बाई के छोटे छोटे टुकड़े प्राकृतिक रेशों के साथ मिलाकर बानने की दृष्टि से काट लिये जाते हैं। इनको ही 'स्टैपल फाइबर' कहते हैं और इसकी आज बहुत मांग है। सन् १९४६ में रेयोन का कपड़ा तैयार करने वाली मिलों की संख्या हमारे देश में १८ थी और लगभग २५००० यांत्रिक शक्ति से काम करने वाले और ७५००० हाथ-करघे इस उद्योग में लगे हुए थे। यह ठीक ठीक नहीं मानूँ कि इस उद्योग में कितनी पूँजी लगी है। पर कुछ लोगों का अनुमान है कि लगभग १५ करोड़ रुपये और ३ लाख मजदूर इसमें लगे हैं। [फरवरी २८ ४५०] बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, अमृतसर और शरत में मुख्यतः रेयोन के कारखाने का उद्योग वृद्धि है। रेयोन के तार का उत्पादन हमारे देश में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् आरम्भ हुआ है और इस समय जबतक सोन मिलें [झाबनकोट, हैदराबाद, बम्बई] स्थापित की जा रही हैं। इनमें से दो मिलों ने काम करना भी आरम्भ कर दिया है और तीसरी मिला १९५२ में काम शुरू करने वाली है। इन तीनों मिलों का उत्पादन १७ टन प्रतिदिन का होने का अनुमान है। इस समय हमारी आवश्यकता लगभग १०० टन प्रतिदिन की है। 'बिड़ला ब्रदर्स' द्वारा स्थापित होने वाला मवानियर रेयोन मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी 'स्टैपल फाइबर' का उत्पादन भी शीघ्र ही आरम्भ कर देगी, ऐसा आशा है।

विकास—रेयोन के वस्त्र उद्योग की हमारे देश में स्थापना हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ है। यह उद्योग समष्टि आधार पर १९३६ में आरम्भ हुआ था। कारण यह था कि सूती वस्त्रोद्योग की संरक्षण देने के लिये अब

भारत-सरकार ने रेयोन के वस्त्र पर आयात-कर बढ़ा दिया तो भारत के रेयोन-उद्योग को उससे प्रोत्साहन मिला। उसके पहले रेयोन का तार वा तो हाथ करवे से बुनकर कान में लाते थे या मिलों में साड़ी का किनारा बनाने के काम में आता था। रेयोन के कपड़े का उत्पादन नाम मात्र को था। १९३६ के बाद रेयोन के वस्त्र-उद्योग ने जो प्रगति की है वह उल्लेखनीय है। आज टेक्सटाइल उद्योग में कपास के उद्योग के बाद इसी उद्योग का नम्बर आता है। द्वितीय महायुद्ध में रेयोन के तार का आयात बहुत कुछ बन्द हो जाने पर भी यह उद्योग जीवित रह सका। १९४७ में जब सूती वस्त्र मिल-उद्योग का संरक्षण समाप्त कर दिया गया था, तब भी सरकार ने इस उद्योग का संरक्षण जारी रखा। अग्नी अग्रेल १९५१ से दो वर्ष के लिये प्रशुल्क मंडल की शिफारिश के अनुसार सरकार ने इस उद्योग का संरक्षण-काल और बढ़ा दिया है।

भविष्य—रेयोन-उद्योग का भविष्य इस देश में उज्ज्वल है। इस समय इसकी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि अधिकतर रेयोन का तार हमारी मिलों को बाहर से [जापान, इंग्लैंड, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इटली] मँगाना होता है। यह कमी आसानी से पूरी हो सकती है। हमारे देश में स्पूस तथा बूसरे प्रकार की काफ़ी लकड़ी ऐसी होती है जिसकी छुन्दी से रेयोन का तार उत्पन्न किया जा सके। जो रासायनिक पदार्थ चादियें वे भी देश में पैदा किये जा सकते हैं। जहाँ तक कि रेयोन के तार के उत्पादन के लिये मशीनरी आदि का प्रश्न है, वह अभी तो अधिकांश में विदेशों से मँगानी पड़ेगी। पर मशीनरी के ऐसे कुछ भाग अवश्य हैं जो देश में तैयार किये जा सकते हैं और इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। रेयोन के तार के उद्योग की एक समस्या टेक्नीशियनों के अभाव से सम्बन्ध रखती है। योग्य नवयुवकों को इस काम की शिक्षा की देश और विदेश में व्यवस्था करना आवश्यक है। रेयोन के वस्त्र की माँग का क्षेत्र काफी व्यापक है। पाकिस्तान को काफ़ी माल जाता है और निकट भविष्य में पाकिस्तान का बाजार कहीं बाने वाला नहीं है। इसके अलावा मध्यपूर्व के देशों में भी इसके लिये अप्रत्याक्ष क्षेत्र है। हमारे देश में भी रेयोन के कपड़े की काफ़ी माँग बढ़ सकती है। कई लोगों का यह कहना है कि भारत में लम्बे देश के कपास की बड़ी कमी है। जब देश में अन्न-उत्पादन की इतनी आवश्यकता है तो यह अधिक सापेक्ष और हितकर होगा कि कपास के स्थान पर हम अपनी आवश्यकता रेयोन से पूरी करें। इस समय हम विदेश से जितना रेयोन और कपास आयात करते हैं उसकी पूर्ति के लिये सारा रेयोन हम अपने देश में पैदा करें तो हमें १०० टन रेयोन के तार और ४०० टन स्पेशल फ़ाइबर

५. तिदिन के उत्पादों की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ यह है कि ग्रिन्ड के रेयोन् उद्योग से भी बड़ा रेयोन् उद्योग हमारे देश में आया चारिये। दोनों वर्ग के अन्दर अन्दर देश में इस उद्योग का इतना विकास हो सकता है। सारांश यह है कि हमारे देश में रेयोन् के कपड़े और तार तथा स्टीम फायर सम्बंधी उद्योगों का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। आवश्यकता यह है कि इस और आवश्यक प्यान् और इस उद्योग की आवश्यक प्रोत्साहन दिया जावे। जैसे सरकार को इस उद्योग के लिये कच्चा माल और आवश्यक मशीनों मँगाने और बर्तों, लकड़ों, इंडोशिया, मध्यपूर्व, सुदूरपूर्व और पूर्वी अफ्रीका आदि देशों में भारतीय माल व विय बाजार पैदा करने में सहायता करनी चाहिये। इस उद्योग के लिये आवश्यक कच्चा माल—जैसे पल्प और रासायनिक पदार्थ आदि—देश में उत्पन्न करने के बाले यह आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर रेयोन् के तार का उत्पादन करने वाली ऐसी मिल स्थापित की जाय जो अपना कच्चा माल भी स्वयं पैदा कर ले। रेयोन् के तार उत्पादन की मौर्या मिलें इस दृष्टि से छोटी हैं। रेयोन् व तार पैदा करने बाले उद्योग से फइ लाभ हो सकते हैं। देश में विज्ञानी उत्पादन की जो नई योजना चल रहा है उनमें जून विज्ञानी पैदा होने लगेगी तो उसका इस उद्योग में प्रयुक्त उपयोग हो सकेगा। इससे लिये एल्यूमीनियम एसिड का नव उत्पादन होगा तो दूसरे उद्योगों के लिये यह आवश्यक पदार्थ उपलब्ध हो जायगा। एल्यूमीनियम एसिड से सीमेंट का उत्पादन भी बढ़ेगा क्योंकि सीमेंट इसका उप-उत्पाद है। इसी प्रकार पल्प और कागज के उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सारांश यह है कि रेयोन् के उद्योग विकास से हमारे कपड़े का आवश्यकता हो पूरी नहीं होगी और लाभ भी होंगे।

शर्करा की उद्योग—देश के उद्योग वर्गों में शर्करा के मिल उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। चालू शर्करा की इंक्टोरिया की १९५०-५१ में (नवम्बर से अक्टूबर) कुल उत्पाद हमारे देश में १४ था। लगभग ४५ करोड़ रुपये की पूंजा इस उद्योग में लगी हुई है। लगभग लाख नवा लाख आदमी शर्करा की मिलों में काम करते हैं और लगभग २ करोड़ किसान जो मन्ने की खेती करते हैं इस उद्योग पर अपना दारोमदार रखते हैं। इस समय हमारे देश में शर्करा की कुल खपत १३ लाख टन प्रतिवर्ष मानी जाती है और हमारी शर्करा की मिलों की उत्पादन-क्षमता (इन्स्टाल्ड कैपसिटी फिसल कमीशन १९५०) ११ लाख टन और वास्तविक उत्पादन १० लाख टन के आस पास है। यहाँ प्यान् रखने की यह बात भी है कि हमारे देश में कुछ शर्करा मिलों के अलावा या तो सीधी गुड़ से या खट्टासे से भी उत्पन्न होती है। पर कुल मिला कर यह उत्पादन की मात्रा

मिल की शकर से बहुत कम है। गुड़ से शकर बनाने का धन्धा तो बराबर गिरता जा रहा है। जहां १९३३-३४ में गुड़ से लगभग ६५ हजार टन शकर तैयार होती थी वहां अब केवल ४००० टन शकर इस तरह से तैयार होती है। खंडसारी शकर का उत्पादन भी कम हुआ है। १९३३-३४ में २ लाख टन शकर खंडसारी से उत्पन्न होती थी। आज इसका उत्पादन १ लाख टन से भी कुछ कम है। सारांश यह है कि यदि शकर का देश में कुल उत्पादन ११½ लाख टन के आस पास माना जाए तो उसमें से १० लाख टन उत्पादन मिलों का १ लाख टन से भी कुछ कम खंडसारी का और ½ लाख टन से थोड़ा अधिक गुड़ से सीधे तैयार की जाने वाली शकर का मानना चाहिये। आज मिल की शकर साल भर में लगभग १०० करोड़ रुपये की हमारे देश में उत्पन्न होती है। लगभग ३४ लाख एकड़ भूमि पर आज हमारे देश में गन्ने की खेती होती है। यह देश की कुल खेती की भूमि का केवल २० प्रतिशत भाग है और सारे संसार में जितनी भूमि पर गन्ने की खेती होती है उसका ३५ प्रतिशत है। इससे दुनिया के शकर-उद्योग में भारत का कितना बड़ा स्थान है यह भी स्पष्ट हो जाता है। शकर के उत्पादन की दृष्टि से भी १९४८ के आंकड़ों के अनुसार कुबा (६० लाख मेट्रिक टन) और मार्जाल (१७ लाख मेट्रिक टन) के बाद तीसरा स्थान भारत का (१२ लाख मेट्रिक टन) हो जाता है। उपर्युक्त विवरण से भारत के शकर-उद्योग का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। यह उद्योग मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में है। परन्तु अब इसका विस्तार दूसरे राज्यों में भी होता जा रहा है।

विकास—भारत में शकर के उद्योग का विकास पिछले १८ वर्षों में खास तौर से हुआ है। १९३२ में इस उद्योग को सरकार ने संरक्षण दिया और तभी से इसकी प्रगति तेजी से होने लगी। जैसे आधुनिक ढंग की शकर की मिलें भारत में १९०३ के आस-पास स्थापित हुईं थी। प्रथम महायुद्ध के समय जब शकर पर आयात-कर बढ़ गया और बाहर से शकर आना कम हो गया तो हमारे शकर के उद्योग को प्रोत्साहन मिला। परन्तु उद्योग-धन्धे की जो भी प्रगति हुई वह बहुत मन्तोपजनक नहीं थी। १९२६ में इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग््रीकल्चरल रिसर्च की शकर समिति ने यह मध्य प्रकट किया कि यदि शकर की मिलों की संख्या नहीं बढ़ती है और शकर का अधिक उत्पादन नहीं बढ़ता है तो बाज़ार में गन्ने की बहुतायात हो जायगी। गन्ना पैदा करने वाले किसानों को इस संकट से बचाने के लिए ही सरकार ने १९३२ में टे्रिक बोर्ड की सिफारिश पर शकर-उद्योग को संरक्षण दिया। यह संरक्षण १९३५ वर्ष के लिये स्वीकार किया गया था। १९३७ में टे्रिक बोर्ड ने दुबारा चॉच की और संरक्षण जारी रखने की सिफारिश की। सर-

कार ने सरकार के बाद उत्पादन बढ़ जाने से १९३४ में जो उत्पादन-कर (पिस्टो में घनी शकर पर) लगा लिया था उसने बार में बोर्ड ने यह राय दी कि शकर के उद्योग और गन्ने की खेती करने वालों दोनों ही पर इस उत्पादन-कर का असर अच्छा नहीं पड़ा। सरकार द्वितीय महायुद्ध के समय तक चलता रहा। फिर १९४७ में टेरिफ बोर्ड ने दो वर्ष के लिए सरकार बढ़ाने की सिफारिश की और १९४८ में फिर दो गान के लिये सिफारिश की। दूसरी बार सरकार ने केवल एक वर्ष के लिये संरक्षण बढ़ाया। और टेरिफ बोर्ड से फिर से विचार करने के लिये कहा। टेरिफ बोर्ड ने इन बार १९५० से सरकार समाप्त करने की सिफारिश की और सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली। टेरिफ बोर्ड का सरकार समाप्त करने की सिफारिश का मुख्य कारण यह नहीं था कि बार प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक सामना करने की इस उद्योग की शक्ति हो गई है, परन्तु यह था कि सरकार ने उद्योग निश्चान और सरकार तीनों में ही एक बूट आत्मसन्तोष का भाव उत्पादन हो गया और उद्योग की कार्यक्षमता बढ़ाने की और इस कारण से आवश्यक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चूंकि इस समय विदेशी विनिमय की कठिनाई के कारण भारत सरकार विदेशी से अमर्यादित माना में शकर का आयात नहीं होने लगे, इसलिये विदेशी शकर की प्रतिस्पर्धा का कोई खतरा नहीं है और इसी कारण से टेरिफ बोर्ड ने सरकार समाप्त करने का यह उपयुक्त समय समझा।

सरकार के कारण शकर के उद्योग ने कितनी प्रगति की इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि १९३१-३२ में भारतवर्ष में केवल ३१ लाख की मिलों और १,५८,००० टन शकर का उत्पादन था और सरकार के बाद बार वर्ष के अंदर अंदर मिलों की संख्या ११५ और शकर का उत्पादन ६,१६,००० टन होगया। आरम्भ में (१९३५-३६ तक) जैसे-जैसे भारतीय मिलों का उत्पादन बढ़ा विदेशी शकर का आयात कम होता गया, पर १९३५-३६ में यद्यपि शकर का उत्पादन लगभग ३३ लाख टन से बढ़ गया, पर आयात में उस अह्रास से कमी नहीं हुई। १९३६-३७ में भी गन्ना बहुत पैदा होने से उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार ने मिलों को उत्पादन कम नहीं करने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में शकर का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होगया। माल बहुत उगा होगया, मूल्य गिरने लगा। उस समय 'शुगर सिंडीकेट' की स्थापना की गई ताकि शकर की बिक्री का सिन्डीकेट द्वारा ऐसा नियंत्रण किया जाये कि शकर का मूल्य गिरने से रोका जाय। सिन्डीकेट अपने इस प्रयत्न में सफल हुआ। शकर का उत्पादन कम किया गया और

१९३८-३९ में केवल ६,५१,००० टन शर्कर का उत्पादन हुआ।

द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात—द्वितीय महा युद्ध के समय शर्कर के उद्योग की स्थिति बहुत सन्तोष जनक नहीं रही। जहाँ तक उत्पादन का सवाल है उसमें भी उतार-चढ़ाव आता रहा। जहाँ १९३८-३९ में फेक्टरी में तैयार शर्कर का उत्पादन केवल ६३ लाख टन के लगभग था वहाँ १९३९-४० में उत्पादन बढ़ कर १२३ लाख टन हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि फिर बाजार में शर्कर की अधिकता हो गई और उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने उत्पादन में कमी करने की व्यवस्था की। इन दोनों राज्यों में 'शुगर फैक्टरी बन्दोल एक्ट्स' पहले से ही मौजूद थे जिनके अनुसार शर्कर की मिल चलाने के लिये सरकार से लाइसेन्स लेना आवश्यक है। उत्पादन में दो साल तक कमी हुई और १९४१-४२ में उत्पादन की मात्रा केवल ७.७८ लाख टन थी। शर्कर की असुरक्षा आयात की मात्रा भी १९३९-४० से १९४१-४२ तक ३४ हजार टन से कम होकर २४ हजार टन के लगभग रह गई थी। १९४२-४३ में स्थिति में सुधार हुआ और उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव हुई, खास तौर से फौजी आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से। १९४३-४४ में उत्पादन फिर १२ लाख टन से ऊपर पहुँच गया। पर उसके बाद फिर उत्पादन गिरने लगा और १९४६-४७ में कुल उत्पादन ९ लाख टन ही रह गया। १९४७-४८ से स्थिति में थोड़ा-सा सुधार हुआ और कुल उत्पादन ११ लाख टन के आस पास पहुँचा गया। पिछले तीन वर्षों में उत्पादन १० लाख टन से १०.३ लाख टन तक रहा है। आयात इन वर्षों में क्रमवन्तः बढ़ रहा है। देश के विभाजन का इस उद्योग पर कोई खास असर नहीं पड़ा। गन्ने की खेती का लगभग अधिभागित भारत का १७ प्रतिशत भाग और शर्कर की मिलों का ६ प्रतिशत भाग पाकिस्तान को मिला है।

अन्य उद्योगों की भांति शर्कर के उद्योग पर भी राज्य द्वारा १९४२ में नियंत्रण किया गया और १९४७ के दिसम्बर तक यह नियंत्रण कायम रहा। शर्कर और गुड़ दोनों के उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण था। नियंत्रण मूल्य-वृद्धि को रोकने में तो किसी सीमा तक सफल हुआ पर उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी यद्यपि नियंत्रण का सरकार की दृष्टि में वह भी प्रधान उद्देश्य था। उत्पादन-वृद्धि नहीं होने के कई कारण थे—जैसे मिलों को गन्ने की कमी क्योंकि बहुत-सा गन्ना गुड़ बनाने के काम में ले लिया जाता है, मिलों का इस कारण से थोड़े समय तक चलना, गन्ने से मिलाने वाले रस की अपेक्षाकृत कम मात्रा, मौजूदा मशीनरी आदि से अत्यधिक काम लेना, और मजदूर-खर्च तथा माल लाने ले

धान का कठिनाई। दिसम्बर १९४७ में शकर पर नै नियमन हटा लिया गया। नियमन हटाने का असर शकर के उत्पादन पर अच्छा हुआ। यद्यपि सरकार को जानून व अनागत मूल्य निवारण का अधिकार नहीं था पर अब मूल्य नियमन प हटते ही शकर का क्रोमन २१ ६० मन से ५० २० मन तक पहुँच गई तो गुजर सिडीकट ने, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की मिलों का संगठन था [१९४४ से बिहार की मिलों और उत्तर प्रदेश की मिलों में भगदा होने से बिहार की कई मिलों में सिडीकट में स्थान प्राप्त हो दिया और बिहार की सरकार ने भी बिहार का मिलों पर स सिडीकट का सदस्यता सर्वोच्च प्रतिवार्धना हटा ला, तथा १९५० में टरिफ बाड का मिश्रित व अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी सिडीकट में मायता वापस ले ली। इस प्रकार सिडीकट अब समाप्त हो गया है] शकर का मूल्य ३५ ६० ७ आ० मन निश्चित कर दिया और गन्ने का कीमत भा १ ६० ४ आ० मन से बढ़ाकर २ ६० ४ मन कर दी। अब मिलों की गन्ने की कमा नहीं रहा और शकर का उत्पादन बढ़ गया। १९४८-४९ में शकर और गन्ने दोनों का क्रान्ति में कमी कर दी गई। शकर का मूल्य २५ ६० ७ आ० मन से घटाकर २८ ६० ८ आ० मन और गन्ने का मूल्य २ ६० ४ मन से घटाकर १ ६० १० आ० [उ प्र] और १ ६, १३ आ [बिहार] कर दिया गया। इसलिये इस वर्ष शकर का उत्पादन कुछ कम हुआ। चूँकि विछले वर्ष का मिलों व पास काफ़ी स्टॉक था इस वजह से भी मिलों ने उत्पादन की ओर कम ध्यान दिया। पर फिर शकर की अधिक हुई। दश ॥ एक साथ शकर की बड़ी कमी अनुभव होने लगी और वातावरण में पबराहट पैदा होगी। शकर का मूल्य आकाश छूँ लगा। इस सारा स्थिति में पबरा कर सरकार को फिर शकर पर नियमन करने का निणय करना पड़ा और दिसम्बर १९४९ में भारत सरकार ने शकर पर नियमन लागू करने का घोषणा कर दा। शकर के मूल्यों का सरकार ने नियमन कर दिया। शकर के वितरण पर भी सरकार का नियमन स्थापित हो गया। शकर के उत्पादन को बढ़ाने के लिये १९४९-५० के आरम्भ में सरकार ने मिलों को कुछ रियायतें देने की भी घोषणा की। जैसे—विछले वर्ष से जितना अधिक उत्पादन होगा उस पर उत्पादन-कर माफ कर दिया जायगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने पर जो उपकर (मिसे) लगता है उसे कम कर दिया गया। पर फिर भी शकर के में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इसका एक कारण तो यह था कि अक्टूबर १९५० तक शकर पर सरकार का नियमन अपूर्ण था, क्योंकि गुड़ और खडसारी शकर पर सरकार का नियमन नहीं था। खडसारी व गुड़ की

क्रीमों बहुत कैंची थी और इसी कारण से गन्ना मिलों में बड़े मात्रा में न पहुँच कर गुड़ व खंडसारी पैदा करने के काम में आता रहा। निबंधन की इस अपूर्णता को पूरी करने के लिये ७ अक्टूबर १९५० को भारत-सरकार ने अपने शर्करा तथा गुड़ कंट्रोल आर्डर के अनुसार गुड़ पर भी निबंधन कर दिया। गुड़ का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया और गुड़ के उत्पादन पर भी निबंधन करने का सरकार ने अधिकार ले लिया। शर्करा के निबंधन सम्बन्धी पूर्व कानून के अनुसार राज्य का सरकारों को जो अधिकार मिले हुए थे वे, जिन हद तक इस नये कानून के प्रतिकूल थे, वापस ले लिये गये। गुड़ के निबंधन सम्बन्धी भारत-सरकार की नीति का बड़ा विरोध हुआ। नतीजा यह हुआ कि गुड़ के उत्पादन पर कोल्हू का लाइसेंस कराने का आदेश निकाल कर जो निबंधन करने का सरकार का निश्चय था वह उसे छोड़ना पड़ा। शर्करा के उत्पादन-कर संबंधी जो रियायत देने का निश्चय किया गया था उसके स्थान पर सीधा मूल्य द्वारा प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया। दिसम्बर १९५० में सरकार ने अपनी शर्करा और गुड़ के निबंधन सम्बन्धी नीति में फिर परिवर्तन किया है। इस नीति के अनुसार शर्करा, गुड़ और गन्ने के मूल्यों में वृद्धि की गई है और शर्करा पर निबंधन थोड़ा ढीला कर दिया है। अधिक मूल्य सम्बन्धी अधिक उत्पादन के लिये जो रियायत थी वह वापस ले ली गई है। १९५०-५१ में केवल १० लाख टन शर्करा पर ही निबंधन रहेगा और यदि इससे अधिक उत्पादन होगा तो उस पर निबंधन नहीं होगा। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सरकार का नीति में स्थिरता का अभ्यास रहा है। शर्करा का उद्योग आज भी गिरी हुई अवस्था में है और शर्करा का उत्पादन बढ़ाना शर्करा के मिल-उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है। अब हम शर्करा के उद्योग के भविष्य के बारे में विचार करेंगे।

भविष्य—उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय शर्करा के मिल-उद्योग की स्थिति संतोषजनक नहीं है। मौजूदा मिलें जितना उत्पादन कर सकती हैं उतना उत्पादन भी आज हो नहीं रहा है। इस दिशा में सरकार ने पिछले वर्षों में जो प्रयत्न किया है उसका भी कोई बहुत संतोषजनक परिणाम नहीं आया है। यह ठीक है कि पिछले वर्ष [१९४६-५०] से उत्पादन की स्थिति में फिर सुधार होना शुरू हुआ है और इस वर्ष भी यह आशा है कि १० लाख ४० हजार टन शर्करा का उत्पादन हो जायगा। भारत-सरकार ने शर्करा के उद्योग के विकास की जो योजना बनाई थी उसके अनुसार १९५० में शर्करा का उत्पादन वर्ष भर में १८३ लाख टन तक पहुँचाने का

लक्ष्य था। देश के विमानन के बाद १९४८ में यह मात्रा घटाकर १६ लाख टन प्रति वर्ष कर दी गई थी। इस १६ लाख टन के मुकाबले में जब हम यह देखते हैं कि गरी कोशिश के बाद भी इस वर्ष १०३ लाख टन शर्करा भी तैयार नहीं होगी, यद्यपि इस समय हमारी उत्पादन शक्ति लगभग १२ लाख टन प्रतिवर्ष है, तो शर्करा के मिल उद्योग की स्थिति का साधा बिन्दु हमारे सामने आ जाता है। वहाँ तक कि शर्करा की माँग का प्रश्न है, १६५० के टेरेफ बोर्ड ने आन्तरिक माँग १३ लाख टन प्रति वर्ष की आँकी है। यदि इसने नियाम के लिए भी थोड़ी शर्करा और शामिल कर लें तो सरकार की माँग १६ लाख टन मान लेना अनुचित नहीं है। यह ध्यान रखने की बात है कि जन गत्या की वृद्धि ने अभाव उपमाग सम्बन्धी हमारी आदतों का भी असर शर्करा की खपत बढ़ने का हाँ आता जा रहा है। इस समय हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष शर्करा की औसत खपत ७ पौंड है और हमने २४ पौंड गुड़ की खपत और जोड़ दें तब भी कुल खपत ३०-३१ पौंड प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आती है। इंग्लैंड में दिताय महापुद्ग व पहले शर्करा की खपत १०६ पौंड प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। दूसरे देशों में भी खपत हमारे देश से कहीं बराबर है, जैसे फ्रांस, ५२ पौंड, अमरीका ६७ पौंड, जर्मनी ५८ पौंड, आस्ट्रेलिया ११६ पौंड, जापान ३३ पौंड। इन सब का सार यह है कि यह तो ठीक है ही कि जेने-जैम दरा का आर्थिक स्तर ऊँचा उठेगा शर्करा के उद्योग का खन भी बढ़ेगा, पर ध्यान की माँग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और हमारी मौजूदा मिश्रों की उत्पादन क्षमता को देखते हुए भी शर्करा के उत्पादन बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। उत्पादन वृद्धि व मार्ग में क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है, अब हम बारे में हम विचार करेंगे।

सबसे पहला कठिनाई तो यह है कि शर्करा की मिश्रों को बराबर यह शिकायत रहती है कि उनको पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिलता और जो गन्ना मिलता है वह बकिया प्रसार का नहीं होता तथा उसमें से जो रस की मात्रा प्राप्त होती है वह कम होती है। शर्करा की मिश्रों का पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिलने का एक कारण यह है कि बहुत सा गन्ना गुड़ पैदा करने में उपयोग में आ जाता है। भारत में गुड़ का उत्पादन शर्करा से तीन गुना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से गुड़ आदमी काम करते हैं। इसलिए गुड़ ने कुटार उद्योग को हानि पहुँचा कर शर्करा के मिल उद्योग को प्रोत्साहन देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। पर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गुड़-यह उद्योग के साथ अनुचित रियायत

को जाय। उदाहरण के तौर पर शकर और गुड़ की कीमतों का अनुपात उचित होना चाहिये ताकि इस कारण से शकर की मिलों में गन्ने की कमी न रहे और किसान यह न अनुभव करे कि शकर की मिल को गन्ना बेचना लाभदायक नहीं है। इसके अलावा गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। इस समय हमारे देश की प्रति एकड़ उपज कम है। कुवा को तुलना में $\frac{3}{4}$, जावा की तुलना में $\frac{1}{2}$ और हवाई की तुलना में $\frac{1}{4}$ हमारे देश में गन्ने की प्रति एकड़ उपज है। इसके लिए खेती के तरीकों में तो उन्नति करना आवश्यक है ही, पर यह भी आवश्यक है कि गन्ने की खेती का दक्षिण में अधिक प्रचार हो, क्योंकि दक्षिण भारत की जलवायु गन्ने की खेती के लिये अधिक उपयुक्त है। जब कि उत्तर प्रदेश में एक एकड़ में ११-१२ टन गन्ना पैदा होता है, बम्बई में ३०-३२ टन, और मैसूर में १८-१९ टन तक पैदा होता है। गन्ने की उपज बढ़ाने के साथ उससे प्रकार में उन्नति करना भी अत्यन्त आवश्यक है। हमारे यहाँ एक एकड़ गन्ने के खेत से १५ टन शकर मिलती है जबकि हवाई और जावा में ६४ टन शकर प्राप्त होती है। इण्डियन शुगर केन कमेटी ने इस ओर काफ़ी काम किया है। प्रान्तीय [अब राज्य की] सरकारों ने [उत्तर-प्रदेश, बिहार और बम्बई] शकर पर जो उप कर लगा रखा है उससे मिलने वाले रुपये का उपयोग गन्ने सम्बन्धी खोज में ही होना चाहिये; पर इस बात की शिकायत है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने, जिन्होंने सन् १९४७ से यह उपकर लगा रखा है, इस खोज के काम में बहुत कम रुपया व्यय किया है। यह कमी भविष्य में पूरी होनी चाहिये। बढ़िया गन्ने से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में शकर मिलती है। एक कमी यह भी है कि शकर की मिलों की दृष्टि से गन्ने की खेती का बटवारा ठीक नहीं है। किन्हीं मिलों के आस-पास आयुष्कता से अधिक गन्ना होता है, तो किन्हीं के पास कम। खेतों से मिलों तक गन्ना ले जाने के लिये वातायात के साधनों की भी कठिनाई रहती है। इसके अलावा पश्चिम के देशों की तरह से हमारे यहाँ बहुत थोड़ी मिलें स्वयं गन्ना उत्पन्न करती हैं। अतः इन बातों की ओर ध्यान देने से भी गन्ने की समस्या हल होने में सहायता पहुँचेगी।

गन्ने सम्बन्धी कठिनाई के अलावा दूसरी कठिनाई मिलों की कार्यक्षमता (एफ़ीशियन्सी) से सम्बन्ध रखती है। हमारे मिलों की कार्यक्षमता काफी नीची है। इसके कई कारण हैं। मिलों में मशीनरी आदि पुरानी है। मिलों की बनावट, उनकी सादृष्ट आदि में भी कई प्रकार की कमियाँ हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए विज्ञानिक (रेशनलाईजेशन) की आवश्यकता है। कई मिलों की

रियनि हा कच्चे माल और बाजार का दृष्टि से ठीक मिला मालूम पड़ती। शर्करा में शर्करा की गणना सबसे अधिक है जब कि उत्पादन सबसे कम है। हमारे विदेशी विहार १ उत्पादन बहुत अधिक है और गणना बहुत कम है। इस समय तो उत्तर प्रदेश और विहार में ही शर्करा का मिल उत्पादित है। देश की ७५ प्रतिशत मिलें और ८० प्रतिशत का मजदूर उद्योग इन दो राज्यों में चला जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि शर्करा का मिल उद्योग का हमारे राज्यों में प्रसार हो और गांवों में उसका विकास होना चाहिए। एक और बड़ा बिजली का प्रायः किताब बाजार है वह उद्योग-कार और उद्योग (सह) की है जो जनता भारत सरकार या उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्य की सरकारों ने शर्करा पर लगा रगे हैं। इसमें भारत का मिलों में बना शर्करा की लागत और भी बड़ा जाता है। शर्करा का उद्योग का परित्यागस्वरूप जो 'मोलासेज' उत्पन्न होते हैं उनके मधुनिता उपयोग की भी काई व्यवस्था अभी हमारे देश में नहीं है। 'मोलासेज' से पॉवर एलकोहल उत्पन्न किया जा सकता है। पावर एलकोहल पेट्रोल में मिलान के काम में आ सकता है। भारत में माला भर में तुल ४ ५ लाख टन मोलासेज उत्पन्न हो जाता है। इसमें सड़हारा शर्करा में मिलान वाला मोलासेज भी शामिल है। ३ लाख टन का लगभग मोलासेज तो शर्करा का मिलों से ही मिलता है। अगर सब मोलासेज का पॉवर एलकोहल तैयार किया जाय तो लगभग १ करोड़ गैलन पॉवर एलकोहल तैयार किया जा सकता है। परन्तु इस समय केवल १० लाख गैलन पॉवर एलकोहल ही तैयार होता है। इस विषय में भविष्य में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार बेगासा एक और पदार्थ है जो शर्करा उत्पन्न करते समय हमें मिलता है। आज इसका उपयोग केवल ईंधन के तौर पर शर्करा की मिलों में होता है। पर इसका भी अच्छा उपयोग किया जा सकता है—जैसे बागान बनाने में, तथा प्लास्टिक, ग्रेज बोर्ड, और रूबोर्ड आदि बनाने में। इन पदार्थों का अच्छा उपयोग होने में शर्करा का उत्पादन-भाग में कमी आ सकती है। उत्पादन-लागत में कमी करने का एक और उपाय यह है कि गन्ना पैलने का समय आन धिनना है उसमें अधिक हो ताकि शर्करा की मिलें अधिक समय तक काम कर सकें। इसके लिए हमें दोनों तरह का गन्ना पैदा करने की और ध्यान देना चाहिये—जो जल्दी पक जाय और जो देर से पक।

ऊपर हमने कुछ उन बातों का उल्लेख किया है जो शर्करा के उत्पादन के में बाधक हैं। जैसे शर्करा का मिल उद्योग का भविष्य हमारे देश में उत्थान है। हमारे पास क्या माल है और तैयार माल के लिए अगला बराबर बड़ने वाला बाजार है। आवश्यकता कबल यह है कि आयोजित दृष्टि से इस उद्योग के

विकास का प्रयत्न किया जाये। इस दृष्टि से अखिल भारतीय शक्कर-उद्योग का कोई संगठन यदि स्थापित किया जा सके तो अच्छा हो। शुगर सिंडीकेट के समाप्त हो जाने से इसकी आवश्यकता और अधिक हो गई है। इस संगठन का काम शक्कर-उद्योग की उन्नति से सम्बन्ध रखने वाली सब बातों की—जैसे योजना, खोज आदि—समुचित व्यवस्था करना होगा। इसके स्वर्ग को अपना राज्य की सरकारों के पास गन्ने पर लगे उपकर में जो बचाया जाता है उसमें से ही मिलना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को भी इसमें योग देना चाहिये। और मिलों का भी इस विषय में काफ़ी बड़ा कर्तव्य है। यदि हमारी सरकारें और व्यवसायी वर्ग अपना-अपना कर्तव्य करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में शक्कर के मिल-उद्योग की अच्छी उन्नति हो सकती है।

लोहा और इस्पात का उद्योग —भारत के आधुनिक उद्योग धंधों में लोहा और इस्पात के उद्योग का स्थान बहुत महत्व का है। फिर भी इस उद्योग का अभी तक बहुत विकास नहीं हुआ है। देश में लोहा और इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना जमशेदपुर स्थित टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी है। दक्षिण में मेसूर सरकार का मेसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स है, परन्तु जमशेदपुर के कारखाने के सामने यह बहुत छोटा है। इन दोनों कारखानों में लोहा और इस्पात दोनों ही तैयार किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त एक कारखाना (इखिडयन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी कुल्टी और हींगपुर, पश्चिमी बंगाल) केवल लोहा, और इसी से सम्बन्धित दूसरा कारखाना स्टील कोरपोरेशन ऑफ बंगाल, केवल इस्पात तैयार करता है। इन कारखानों के अलावा कुछ छोटे-छोटे कारखाने तथा लगभग ५० री-रोलिंग मिलें और हैं। देश में कई लोहे की फाउण्डरीज और रोलिंग मिलें भी हैं जो लोहे और इस्पात का मास तैयार करती हैं। देश में १९४६ में लोहे का (पिग आइरन) कुल उत्पादन १५ लाख टन और इस्पात (इंगोत्स और फॉस्टिंग) का १३३ लाख टन और फिनिश स्टील का १० लाख टन के लगभग था। देश के इस्पात उद्योग की अधिकतम उत्पादन-शक्ति १९ लाख टन फिनिश स्टील है। टाटा के कारखाने को महत्व इसी से स्पष्ट हो जाता है कि १० लाख टन के मुकाबले में ७ लाख टन से अधिक इस्पात तो केवल इसी एक कारखाने में तैयार होता है। जहाँ तक पूंजी का सवाल है टाटा के कारखाने में लगभग ४० करोड़, इखिडयन आइरन और स्टील कम्पनी में ११ करोड़, स्टील कोरपोरेशन बंगाल में ८ करोड़ रुपये प्लांट केपिटल के तौर पर लगे हुए हैं। जहाँ तक काम करने वालों की संख्या का सवाल है लोहे और इस्पात के उद्योग में लगभग ७० हजार आदिमी काम करते हैं। इनमें से ४२

हज़ार आदमी तो टाटा के कारखाने में ही काम करते हैं। हमारे देश के लोहे और इस्पात व उद्योग की तुलना दूसरे देशों के लोहे और इस्पात के उद्योगों से करने पर मालूम होता है कि १९३६ के आँकड़ों के आधार पर जहाँ लोहा और इस्पात कास्टिंग का भारत में ७३ लाख टन का उत्पादन था वहाँ जापान का ७० लाख टन, ब्रिटेन का १५९ लाख टन, रूस का २०७ लाख टन और अमेरिका का ५२७ लाख टन का लगभग था।

प्रारम्भ और प्रगति—इस देश में लोहे को पिघलाने और ढालने का और इस्पात तैयार करने का धन्धा अत्यन्त प्राचीन काल से (कम से कम दो हजार वर्ष पहले से) चला आ रहा है। भारत में केवल अपनी आवश्यकता पूरी करता था बल्कि विदेश को भी लोहा और इस्पात भेजता था। और भारत के मान का विदेशों में बड़ी प्रशंसा थी। दिल्ली का विख्यात लोहे का स्तम्भ भारत के इस प्राचीन उद्योग का एक ज्वलन्त उदाहरण है। उससे बिज्जात डेगस्कन के तलवार और कटार की फालें (ब्लेड्स) भारत के इस्पात की ही बनी होती थी। आधुनिक ढंग के लोहे और इस्पात के उद्योग के जन्म और विकास के रूप भारत के दूसरे प्राचीन उद्योगों की तरह यह उद्योग भी नष्ट होगया और भारत विदेशों में लोहा और इस्पात का आयात करने वाला देश बन गया।

१९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इस उद्योग को आधुनिक ढंग से विकसित करने के प्रयत्न भारत में प्रारम्भ हुए। ये प्रयत्न १८३० में और उसने आस-पास यूरोपियन लोगों ने किये थे। मद्रास के सालेम, आरकट और मालाबार के त्रिंल्लोम, बंगाल में बारभूम में, और पनाब में कुमाग्राम ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सहायता से ये प्रयत्न किये गये थे। पर वे सब असफल रहे। आखिरकार १८७४ में बाबर आयरन वर्क्स की स्थापना हुई। करिया के कोयले की खान के पास (बंगाल में) यह लोहे का कारखाना स्थापित हुआ। १८८६ में कलकत्ते की मार्टिन एण्ड कम्पनी ने इस कारखाने की ले लिया। बाद में इसी का नाम बंगाल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी होगया जो हाल में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में मिला लिया गया है।

पर इस देश में लोहे और इस्पात के उद्योग का वास्तविक इतिहास तो टाटा के कारखाने की स्थापना के साथ ही प्रारम्भ होता है और आज भी हमारे इस उद्योग का वास्तविक केन्द्र वही कारखाना है। भारतीय साहब और पूँजी का यह एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। इस कारखाने के प्रवक्त स्वर्गीय जमशेदजी जाना थे। पर कारखाने की स्थापना के पहले ही जमशेदजी की मृत्यु होगी। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की स्थापना साकची (सिगभूम) में

हुई। पिग आइरन १९११ में और इस्पात १९१२ में इस कारखाने में सबसे पहली बार तैयार किया गया। इस कारखाने के साकची (अमरोदपुर या ताता नगर) में स्थापित होने के कई कारण थे, जैसे लोहे और कोयले तथा चूना, पत्थर का पास में मिलना तथा पानी और रेल की सुविधा और कलकत्ते के बन्दरगाह का पास में होना। इस कारखाने की विशेषता केवल इतनी ही नहीं है कि यह इस देश का लोहे और इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना है। वह इस बात में भी निहित है कि यह कारखाना लोहे और इस्पात से सम्बन्धित कुछ दूसरे कार्यों की भी व्यवस्था करता है। जैसे लोहे और इस्पात के कारखाने के अलावा इस कम्पनी की लोहे कोयले, चूने पत्थर और मैंगनीज को भी अपनी जगहें हैं। टाटा कम्पनी के अलावा जो दूसरे प्रमुख उत्पादक हैं उनमें इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी की स्थापना १९१८ में, मैसूर के कारखाने की १९२३ में और बंगाल स्टील कारपोरेशन की १९३६ में हुई।

इस उद्योग का विकास खास तौर से १९२३ से जब इसे सरकार से संरक्षण मिला, होने लगा। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् और उसके बाद के आर्थिक संकट में इस उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रथम महायुद्ध के समय संसार के इस्पात उद्योग का बहुत विकास हुआ था। युद्ध समाप्त होते ही भारत के नवजात उद्योग को इस विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। मॉग में कमी आ रही थी, विदेशी विनिमय हास के कारण विदेशी प्रतिस्पर्धा और भी विकट होगई थी तथा बाहर से माल भारतीय बाजारों में पाटा जा रहा था। आतिरकार टेरिफ बोर्ड के सामने संरक्षण की मॉग पेश हुई और उसने तीन वर्ष के लिये संरक्षण देने की सिफारिश की। टेरिफ बोर्ड की सिफारिश सरकार ने स्वीकार करली और १९२४ में संरक्षण सम्बन्धी कानून पास किया गया। उसके बाद १९२६ और १९३३ में दो बार तो टेरिफ बोर्ड ने इस उद्योग के बारे में स्टेटूटरी (कानूनन) जॉच की और संरक्षण जारी रखने की सिफारिश की जो सरकार ने स्वीकार की। इन मुख्य जॉचों के अलावा १९२४, १९२५, और १९३० में तीन बार और टेरिफ बोर्ड ने सहायक जॉचें कीं। सतिर्पूति संरक्षण (कम्पेनसेटरी प्रोटेक्शन) के मामले में टेरिफ बोर्ड के सामने आए और जहाँ आवश्यक मालूम पड़ा वहाँ संरक्षण दिया गया। १९२४ में जो संरक्षण दिया गया था वह दोनों ही प्रकार का था—कुल सामान पर आयात-कर के रूप में और कुछ पर नकद सहायता (वाउन्टी) के रूप में संरक्षण दिया था। १९२६ की स्टेटूटरी जॉच के पश्चात् जो संरक्षण कानून पास किया गया (१९२७ में) उसकी अवधि ३ वर्ष के लिये थी। इस कानून के अनुसार नकद

आर्थिक महायुद्ध देना बंद कर दिया गया। इस सरक्ष्य कानून की दूसरी विशेषता यह थी कि ब्रिटिश माल पर दूसरे देशों की अथेना बग कर लगाया गया था। इसका देश में विरोध किया गया। १९२३ की वार्च के बाद फिर १९२१ में नया सरक्ष्य कानून पार हुआ और उसमें अथेना भी ७ वर्ष की निश्चिन्ता की गई। इस वार्च में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो गया। सरक्ष्य का समय १९२१ से बरकर रखा गया। १९४७ में जब अन्तिम नॉच हुद तो उद्योग ने सरक्ष्य पर जोर नहीं दिया और टेरिफ बोर्ड के कहने पर २७ वर्ष के पश्चात् इसका उद्घोष में छान्द हटा लिया गया, और सरक्ष्य कर आगमन-कर (रेवेन्यू इयूटॉज़) में बदल दिया गया। सरक्ष्य-करी में अभी तो १९३८ के कानून से ही हो गई थी। सरकार द्वारा समय समय पर रबीकार किये गए इस सरक्ष्य से इस उद्योग को विशेष सहायता मिली और इसकी अत्यन्त प्रगति हुई। यह प्रगति उत्पादन में हुई वृद्धि, मनुष्यों की कार्यक्षमता में हुई उत्थिति तथा उद्योग में लगे विदेशी लोगों की सहायता और उत्पादन-लागत में हुई कमी से स्पष्ट है।

द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात्—द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होते ही इस उद्योग के विकास का एक नया परिच्छेद आरम्भ हुआ। सरकार और रेलन कम्पनियों की इत्याद की माग बढ़ने में उनके उत्पादन में वृद्धि हुई। इस युद्ध के पहले हमारे देश में साधारण इत्याद का ही अन्विकाश उत्पादन होता था। पर द्वितीय महायुद्ध के कारण अब गृह से इत्याद का आयात बहुत कम हो गया और भारत का सामरिक महत्त्व बढ़ गया तो भारत ने कई नए प्रकार के बकिया इत्याद का उत्पादन करना शुरू कर दिया। टाटा कम्पनी में खाद्य तेल से विकास हुआ, और युद्ध की दृष्टि से उपयोगी कई प्रकार का नया और बकिया इत्याद तैयार किया जाने लगा। १९३७ में जमशेदपुर में लोह के लिए एक भयोगशाला की स्थापना की गई थी। द्वितीय महायुद्ध के समय जो लोह की गी उद्योग के परिणामस्वरूप खाद्य तेल का 'एलोये स्टील' का सामान टाटा कम्पनी तैयार कर सका, जैसे आरमर प्लेट जिस पर गोली का जखर न हो सके, प्रशो द्रुम के लिए हाई स्पीड स्टील, सर्जिकल औजारों के लिए स्टेनलेस स्टील, हाँ काबन स्टील मिट डाइन के लिये और फिनल स्टील प्लेट्स आदि। टाटा कम्पनी में द्वितीय महायुद्ध के समय दो दिशाओं में जो विस्तार हुआ वह निम्न रूप में उल्लेखनीय है। १९४१ में जमशेदपुर एक डील टायर और एक्सेल प्ला लगीया गया। इसके दो साल के अन्दर ही अन्दर जमशेदपुर एजीनियरिंग ए मशीन मेयूफकचरिंग कम्पनी ने काम करना आरम्भ कर दिया। इसी प्रकार टाटा लोहो मोटिव एंड एजीनियरिंग कम्पनी में १९४३ से मोटर्स और एंजिन

तैयार करना आरम्भ किया। व्यक्तिगत साहस का इस दिशा में यह पहला प्रयत्न था। द्वितीय महायुद्ध के समय इस उद्योग का उत्पादन कितना बढ़ा इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जहां १९३६ में पिग आयरन का उत्पादन १७½ लाख टन, स्टील इन्गोत्स और कास्टिंग का १०½ लाख टन और फिनिश इस्पात का ८½ लाख टन था, वहां १९४१ में पिग आयरन का उत्पादन २० लाख टन, स्टील इन्गोत्स और कास्टिंग का १४ लाख टन और फिनिश स्टील का ११½ लाख टन से कुछ कम उत्पादन हुआ। १९४१ के पश्चात् उत्पादन में कमी आना शुरू हुई। पिग आयरन का उत्पादन १९४७ में १३ लाख टन के आस-पास पहुँच गया हालां कि बाद के दो वर्षों में फिर उत्पादन की मात्रा बढ़ी और १९४६ में १५ लाख टन पिग आयरन तैयार हुआ। इसी प्रकार स्टील इन्गोत्स और कास्टिंग का उत्पादन घटते-घटते १९४८ में १२½ लाख टन तक पहुँच गया यद्यपि १९४६ में उत्पादन १३½ लाख टन हुआ। फिनिश स्टील का उत्पादन १९४५ तक तो ११½ लाख और १०½ लाख टन के बीच में घटता-बढ़ता रहा पर उसके पश्चात् तो और अधिक कमी होने लगी और १९४८ में ६½ लाख टन तक उत्पादन गिर गया। १९४६ में अवश्य फिर उत्पादन १० लाख टन से कुछ अधिक हुआ। १९५० में उत्पादन की मात्रा और बढ़े ऐसी आशा है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् लोहे और इस्पात का उत्पादन गिरने लगा। युद्ध में अत्यधिक काम करने के कारण मशीनरी और प्लांट बहुत काफी घिस गये हैं, और उन को बदलने की बड़ी आवश्यकता है। उत्पादन के मार्ग में पूँजी की कमी की भी एक बड़ी बाधा रही है पर इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिनसे देश के लोहे और इस्पात के उद्योग के विकास में बाधा आती है। यद्यपि भारत-सरकार ने कम से कम १० वर्ष तक मौजूदा लोहे और इस्पात के उद्योगों का राष्ट्रीय करण नहीं करने की घोषणा कर दी है, पर यह दस वर्ष का समय पूँजीपतियों की दृष्टि में भारी विकास के लिये बहुत कम है। इससे इस उद्योग का विकास रुका हुआ है। इसी प्रकार मजदूरों के उत्पादन में जहां कमी आई है वहां मजदूरों पर होने वाला खर्च बढ़ा है। एक टन फिनिश स्टील पर मजदूरों की लागत १९३६-४० में ३१.३६ रु थी वह १९४८-४९ में ६२ रु हो गई और प्रति मजदूर उत्पादन २४.३६ टन से गिर कर १६.३० टन हो गया। इसके साथ ही साथ मजदूरों की संरक्ष भी आवश्यकता से अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि हमने ही उत्पादन के लिए विदेशों में जितने मजदूर काम करते हैं, उनसे चार गुने मजदूर यहां काम करते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस उद्योग में विज्ञानिकता की बड़ी आवश्यकता है।

जहाँ तक मूल्य नियंत्रण का संबंध है १९३६ में ही भारत-भारत और टाटा कंपनी में एक समझौता हो गया था। यह मूल्य नियंत्रण एक नए रूप में आज तक चला रहा है। १ अक्टूबर १९३६ से ३० जून १९४४ तक कच्चा तेल मान का मूल्य नियंत्रण था जो सरकार युद्ध के लिये खरीदनी थी। व्यापारिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं था। १ जुलाई १९४४ से ३१ मार्च १९४६ तक व्यापारिक मूल्यों का भी नियंत्रण कर दिया गया पर युद्ध के लिये आवश्यक मान और व्यापारिक आवश्यकता के लिये बचे जाने वाले मान भी जीमने अलग-अलग निश्चित होती थी। १९६ के बाद युद्ध के लिये छा ३५६ मान का मूल्य नियंत्रण हटा लिया गया है और गिक व्यापारिक मूल्यों पर इस समय नियंत्रण है। इन मूल्यों के बारे में यह शिकायत रही है कि वे उचित मूल्य नहीं हैं।

मधिर- लोहे और इस्पात के उद्योग का जो विवरण हम ऊपर मिल चुके हैं उससे यह स्पष्ट है कि इस उद्योग के भाग में कुछ कठिनाइयाँ हैं। परन्तु यह है कि इन उद्योग का हमारे देश में क्या भविष्य है? इस सम्बन्ध में राजी विचारणाएँ बाएँ नहीं माल की है। कच्चे लोहे को इस देश में कमी नहीं है। ऊँचे दर्जे का हमटाइट कम, लोहा रिहार और उड़ीसा में ही ८०० करोड़ टन होने का अनुमान है। हमने अभिरिक्त मध्यप्रदेश, मद्रास और बर्मा में भी हेमटाइट और मग्नेटिक कच्चा लोहा १०० करोड़ टन के लगभग है। भारतीय कच्चे माल में शुद्ध लोहे का अंग बहुत कम है। कच्चे लोहे को शुद्ध करने के लिये चूना पत्थर आदि का उपयोग होगा है, यह भी हमारे देश में मिलता है। मगनाइट और सिलिकोन का भी आवश्यकता होती है और ये भाउ भी हमारे देश उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय कोयला का। अण्डे कोयले के बारे में हमारा स्थिति यद्यपि बहुत सन्तोषजनक नहीं है, पर यदि हम सावधानी से खोलें तो हमारा काम काफ़ी समय तक (१०० वर्ष के लगभग) चल सकता है। कारण यह है कि कच्चे माल को हमारे पास कमी नहीं है। तथा तक इस्पात की माग का संबंध है वह भी यथेष्ट मात्रा में है और यह उत्तरोत्तर बढ़ने वाली है। इस्पात की मीनूडा उत्पादन प्रति १० लाख टन के लगभग है और हमारी माग २५ लाख टन के लगभग है। फिर जैसे-जैसे हमारे आर्थिक विकास की योजनाएँ कार्यान्वित होंगी हमारी इस्पात की माग बढ़ेगी। देश की मकानों की समस्या को हल करने के लिये, तथा सिंचाई, बिजली आदि की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये काफी इस्पात की आवश्यकता होगी। इसी के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया का बाजार भी है जहाँ का इस्पात की माग हम पूरा कर सकते हैं। कारण यह है कि इस उद्योग का भविष्य हमारे देश में उज्ज्वल हो सकता है। १९४५ में तो

और इस्पात के पेनल ने १-१ लाख टन की उत्पादन शक्ति के दो बड़े कारखाने स्थापित करने की सफाई की थी। भारत-सरकार दो सरकारी कारखानों की योजना भी तैयार करवा चुकी है पर अभी अर्थोभाव के कारण वे कार्यान्वित नहीं हो सकी हैं। भारत सरकार ने स्टील कारपोरेशन बंगाल और इंडियन आइरन एंड स्टील कंपनी को अपनी दो लाख टन से उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए कर्ज अवश्य दिया है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ने कई फ़ाउण्डरी को भी उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋण दिया है। टाटा और मैसूर के कारखानों को ऋण देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन चल रहा है। अस्तु, मौजूदा कारखाने अपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह तो स्पष्ट ही है। इस समय हमारे देश में इस्पात और पिग आइरन (खासकर बढ़िया पिग आइरन) की बड़ी कमी है। यह कमी हो सके वहाँ तक पूरी की जानी आवश्यक है।

सहायक उद्योग—टाटा के इस्पात के उद्योग के आस-पास कुछ दूसरे सहायक उद्योग भी खड़े हो गये हैं। इनमें से मुख्य-मुख्य उद्योगों के नाम ये हैं— जैसे टिन प्लेट, वायर, वायर नेल उद्योग, जमशेदपुर एंजीनियरिंग एंड मशीन मेन्फैक्चर, टाटा नगर फ़ाउण्डरी, टाटा लोको मोटिव एंड एंजीनियरिंग कंपनी और खेती के औजार तैयार करने वाली एग्रीको फ़ैक्टरी। देश का एंजीनियरिंग उद्योग का विकास भी बहुत कुछ इस्पात-उद्योग के कारण ही हुआ है। यही कारण है कि टाटा नगर आधुनिक उद्योगों का एक बहुमुखी केन्द्र बनता जा रहा है।

कोयले का उद्योग—भारत का कोयले का उद्योग प्रधानतः बंगाल और बिहार में केन्द्रित है। रानी गज, मरिया, गिरडीह कोयले के उत्पादन के कुछ प्रमुख केन्द्र हैं। पश्चिमी बंगाल और बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में, जैसे आसाम, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, उड़ीसा और राजपूताना में भी कोयला मिलता है। १९४६ में भारत में कोयले का कुल उत्पादन ३३ करोड़ टन के आस-पास था। इसके मुकाबले में अमेरिका में १६ करोड़ टन, इंग्लैंड में २१ करोड़ टन जर्मनी में ६ करोड़ टन, जापान में ३३ करोड़ टन, आस्ट्रेलिया में १३ करोड़ टन, पाकिस्तान में २३ लाख टन, दक्षिणी अफ्रिका में २३ करोड़ टन और कनाडा में १३ करोड़ टन का १९४८ का उत्पादन था। देश की कोयले की वर्तमान आवश्यकता भी ३ करोड़ टन के आस-पास है, यद्यपि भविष्य में देश की आवश्यकता बढ़ना निश्चित है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि १९५६ तक हमारी मांग ४ करोड़ टन से भी ऊपर निकल जायेगी। इस उद्योग में

२½ लाख से भी अधिक आदमी काम करते हैं। देश के सब सान-उद्योगों ने लाख ने ऊपर आदमी काम करते हैं। इसका अर्थ यह है कि लॉन बौगाह अधिक मनदूर केवल कोयले के उद्योग में लगे हुए हैं।

प्रारम्भ और विकास—इस उद्योग का प्रारम्भ १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ। १८६० में कुल कोयले का उत्पादन ३ लाख टन था। दो-तीन दशक बाद उद्योग का विभाग होने लगा। सन् १८०० में कुल उत्पादन ६० लाख टन तक पहुँच गया और उसमें ३० लाख टन केवल रानीगंज में उत्पन्न था। दोरे-तीरे रानीगंज की अथवा भरिया के कोयले की ज्वालनों का महत्व होने लगा और रानीगंज में भी वहाँ का उत्पादन बढ गया। गिरडीह में भी कायन का उत्पादन होने लगा। देश के दूसरे भागों में भी थोड़ा बहुत उत्पादन हुआ। १८७७ में कुल उत्पादन १ करोड़ ६० लाख टन का था उसमें से ६० लाख टन से अधिक भरिया और ५० लाख टन रानीगंज में उत्पन्न होता था। गन्दी, स-सन और फाम के उद्योग तथा लोहे और इस्पात के उद्योगों में अधिक कोयले की जरूरत थी। प्रथम महायुद्ध और उसके पश्चात् के कुछ समय में इस उद्योग की अच्छी प्रगति हुई। युद्ध के कारण विभिन्न उद्योग घरों के उत्पादन करने के कारण कोयले की माँग भी बनी और बढ़ी हुई माँग की पूर्ति करने के लिए उत्पादन बढाया गया। परन्तु उत्पादन माँग के बराबर न बढ सका। १८९४ में कोयले का कुल उत्पादन जहाँ १ करोड़ ६० लाख टन के लगभग था वहाँ १८९० में उत्पादन की मात्रा २ करोड़ टन में ऊपर हो गई। बीजराघी खान का विकास इसी समय हुआ। इसी समय में कोयले की ज्वालनों में बिजली लगाने की विधा में भी वषेष्ट प्रगति हुई। युद्ध के समय की इस प्रगति में इस कारण से कुछ बाधा अवश्य उत्पन्न हुई कि विदेश से मशीनरी आदि का आना कठिन था। और जब यह कठिनाई दूर हुई तो कोयले का माँग में कमी आने लग गई। कोयले की माँग में यह कमी १८२० से प्रारम्भ हुई और इस कारण से उत्पादन में भी कमी आने लगा। १८२० में कोयले का उत्पादन ६० लाख टन से कुछ कम होगा। १८२० से १८२६ का समय हम उद्योग के निम्ने अत्यन्त कठिन समय था। इसके कई कारण थे। युद्ध के समय की माँग में युद्ध समाप्त होने के पश्चात् कमी आना स्वाभाविक था। कोयले की माँग में कमी आने का एक कारण यह भी था कि बम्बई में पॉलिश सॉल व तैल पर बिजली और तेल का उपयोग होने लग गया। हमारा निर्यात व्यापार भी गिरता जा रहा था। युद्ध के समय में जहाँ की कमी निर्यात व्यापार की कमी का प्रमुख कारण था। हमारा निर्यात व्यापार यहाँ तक गिर गया था कि १८१८ में केवल ४४ हजार टन कोयला बाहर भ-

गया जब कि युद्ध के पूर्व लगभग ७ लाख टन कोयला निर्यात होता था। युद्ध समाप्त होने के बाद एक बार वो निर्यात व्यापार वास्तव बढ़ा। १९२० में लगभग १२ लाख टन कोयला निर्यात हुआ। पर भारत सरकार ने यह सोच कर कि देश के अन्दर की मांग पूरी नहीं होगी कोयले के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जो जनवरी १९२३ तक रहा। हमारा कोयला घटिया होने से भी विदेशों में उसकी मांग कम हुई। इसके अलावा विदेशी कोयले जैसे अफ्रिका के कोयले की प्रतिस्पर्धा भी हमारे बाजारों में बढ़ने लगी। बम्बई और कराची में यह प्रतिस्पर्धा विशेष तौर पर थी। हमारे कोयले का घटिया होते हुए भी मूल्य अधिक था। इसका असर भी विदेशों की मांग पर और विदेशी माल की प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ। इसी समय में कोयले के उद्योग को मजदूर संघर्ष का भी सामना करना पड़ा। सारांश यह है कि उपर्युक्त अलग-अलग कारणों से १९२०-१९२६ तक का समय कोयले के उद्योग के लिये अच्छा प्रमाणित नहीं हुआ। १९२३ तक कोयले के मूल्यों में वृद्धि होती रही पर १९२३ से १९२६ तक मूल्यों में गिरावट आती रही। एक कारण तो इसका यह था कि उत्पादन की मात्रा में वापस सुधार हो रहा था और दूसरा कारण मुद्रोत्तर मंदी का था।

निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए कोयले के प्रकार का भी एक सवाल था। इस का ठीक-ठीक वर्गीकरण करने के लिये भारत-सरकारने [१९२५ में] कोल रेजिग बोर्ड की स्थापना की। कोयले की कीमत कम करने की दृष्टि से भी कुछ प्रयत्न किये गए। इन प्रयत्नों के फल स्वरूप विदेशों में भारत के कोयले का खोवा हुआ स्थान फिर प्राप्त होगया। उद्योग की आन्तरिक स्थिति को ठीक करने का सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया। संभवतः इसका एक कारण यह था कि उद्योग का संकट काल समाप्त हो चुका है ऐसा भारत-सरकार का विचार रहा हो। क्योंकि १९२७ से १९३० तक का समय कोयले के उद्योग की दृष्टि से संतोषप्रद रहा। १९३० में उत्पादन २ करोड़ ४० लाख टन हो गया था। निर्यात व्यापार की बहुत कुछ खोई हुई स्थिति फिर सुधर गई थी।

सन् १९३० से फिर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर कोयले के उद्योग पर भी पड़ने लगा। कोयले की सपत जैसे-जैसे कम होने लगी वैसे-वैसे मूल्य गिरने लगे। इसका परिणाम उत्पादन की कमी का होना स्वाभाविक था। सीमान्त खानों ने अपना उत्पादन बंद कर दिया और दूसरी खानों ने अपना लाभत खर्च कम करने की दृष्टि से उत्पादन को हर तरह से बढ़ाने का प्रयत्न किया। चूंकि कोयले की मांग के मुकाबले में उत्पादन अधिक था इसलिये मूल्य गिरने ही गये। यद्यपि उत्पादन की मात्रा २ करोड़ ४० लाख टन से कम होकर १९३३ में

२ कराड़ टन के नीचे पहुँच गया था, पर फिर भी खसत की अपेक्षा यह कम थोड़ी ही रही। कायले के उद्योग की यह स्थिति १९३६ तक चलती रही। १९३६ से लगा कर दिनाय महायुद्ध आरम्भ तक स्थिति में उच्चोत्तर सुधार होता गया। कोयले की आन्तरिक मांग बढ़ने लगी। निर्यात भी बढ़ा। लकड़ा को कोयला जने लगा और चीन जापान की लड़ाई के कारण सुदूर पूर्व के बाजार में भारतीय कोयले के लिए खुल गये।

द्वितीय महायुद्ध और वमरु परधात—द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ के समय में भी कोयले के उपयोग की स्थिति में सुधार आता गया। पर १९४२ से यह दिखने लगा कि कोयले के उत्पादन में फिर कमी आरम्भ हो गई और देश में कोयले का अकाल सा अनुभव किया जा रहा है। मांग बढ़ने से मूल्य बढ़ने लगे पर विशेष दृष्टि १९४२ के बाद से हो गई। यातायात का कठिनाई और समुद्रमार्ग जहाजों की कमी तथा मसदूरों की कमी का भी असर उत्पादन पर पड़ा। सरकार और स्वामियों ने उत्पादन बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयत्न किया, जैसे शान्ति में काम करने के लिए बाहर से मसदूरों की मर्तों की गई और उत्पादन में दृष्टि करने के लिए वह आर्थिक प्रलाम्भ जैसे उत्पादन बोनस, अतिरिक्त लाभ कर में छूट आदि दिये गये। बहुत सा मशीनरी भी बाहर से मंगाई गई। इन तमाम प्रयत्नों का असर हुआ और उत्पादन में जो कमी आ गई थी वह ज़रा-ज़रा पूरी हो गई। कोयले का कुल उत्पादन १९४२ में २ करोड़ ६४ लाख टन के लगभग था वह १९४३ में २३ करोड़ टन हो रहा गया। १९४४ में बहुत थोड़ी दृष्टि हुई पर १९४५ में उत्पादन २ करोड़ ६० लाख टन के लगभग पहुँच गया। मूल्यों का ज़रा तक समान है जब उनमें बराबर तेजी आती गई तो १९४४ में सरकार ने मूल्य नियन्त्रण लागू कर दिया। कोयले के वितरण पर भी आवश्यक नियन्त्रण किया गया। यह नियन्त्रण आज तक लागू है। कोयले के उद्योग का उत्पादन द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् भी बराबर बढ़ता रहा है। वर्तमान उत्पादन ३ करोड़ २० लाख टन के लगभग मानना चाहिये। पाकिस्तान में ३० लाख टन के आसपास की जा खान होती थी उसमें देश के विमानों के कारण असर आना सर्वथा स्वाभाविक है। अस्तु आज कोयले के उद्योग के सामने फिर वही समस्या है कि उत्पादन मांग से अधिक न हो सके।

भविष्य—कोयले के उद्योग का किसी भी आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र के लिये बहुत बड़ा महत्त्व है। इसकी सफलता के मार्ग में भारत में जो-जो कठिनाइयाँ हैं उन पर अब हम विचार करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अच्छे कोयले की मात्रा हमारे देश में बहुत नहीं है। अच्छे कोयले की मात्रा का

एक अनुमान यह है कि खपत के वर्तमान आधार पर लगभग ७० वर्ष में सब कोयला [७५ करोड़ टन] खर्च हो जायगा । परन्तु सन् १९४७ में श्री ई. आर. गी ने यह अनुमान लगाया कि बढ़िया कोयले की मात्रा २२६ करोड़ टन है । और यदि कोयले को संचय करने की समुचित व्यवस्था की जाय तो २०० वर्ष से अधिक हमारा कोयला चल सकता है । कोयले के रिजर्व की मात्रा का जो कुछ भी हमारा अनुमान हो, इतना तो साफ़ ही है कि बढ़िया कोयला जो लोहे और इस्पात के उद्योग में काम आता है अधिक से अधिक समय तक संचित रहे [कतर्ज हो] इसका पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये । १९४६ का कोयला समिति [कोल कमेटी] ने भी राष्ट्रीय हित में इस बात पर बहुत जोर दिया था कि बढ़िया कोयले के संचय [कन्सर्वेशन] की पूरी-पूरी व्यवस्था होनी चाहिये । जहाँ-जहाँ घटिया कोयले से काम चलतकता हो, जैसे रेलवे में, तथा फ़ास उद्योग में, वहाँ बढ़िया कोयले का खर्च बन्द कर देना चाहिये । १९४६ में इस समस्या पर विचार करने के लिए भारत-सरकार ने एक समित भी [मेटलर्जिकल कोल कन्सर्वेशन कमेटी] नियुक्त की है । इसकी रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है । कई प्रकार के कोयलों को कारबनाइजेशन के लिये मिलाने से भी बढ़िया कोयला उत्पन्न हो सकता है । कोक बनाने के लिये भी घटिया कोयला काम में आसकता है, ऐसी खोज हाल में कॉंसिल ऑफ साइन्टिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने टाटा स्टील कंपनी की सहायता से की है । इससे भी बढ़िया कोयले में बचत हो सकी है । कोयले के उद्योग से सम्बन्ध रखने वालों दूसरी समस्या यह है कि कोयला खोदने की वर्तमान पद्धति को अधिक वैज्ञानिक बनाया जाये । कोयला खोदने की जो पद्धति [पिलर एंड स्टाल] आज हमारे देश की खानों में अधिकतर प्रचलित है और जिस के कारण कोयला खराब होना है और जो पद्धति सुरक्षित भी कम है, उसके स्थान पर अधिक वैज्ञानिक [लॉंग वॉल] पद्धति काम में लानी चाहिये । बड़ी खानों में इस पद्धति का युद्ध के समय से उपयोग भी किया जाने लगा है । कोयले के उद्योग की तीसरी समस्या यह है कि चूंकि इस समय खान में काम करने वाले मजदूरों की संख्या उत्पादन के मुकाबले में कहीं अधिक है, इसलिये अब उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिये । कोयले को लाने-लेखाने की कठिनाई भी कई बार उपस्थित हो जाती है । अतः यातायात सम्बन्धी कठिनाई को हल करने का भी बराबर ध्यान रखना आवश्यक है । अन्तिम बात कोयले के निर्यात के बारे में है । यद्यपि आज भारत का कोयला हाँगकॉंग, न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया आदि देशों को भी जाता है, पर लंका, सिंगापुर, मलाया प्रायद्वीप, और बर्मा तो भारतीय कोयले के स्थायी

चानार माने जायकृत हैं। फल आवश्यकता है इस बात की कि बढ़िया कौनसा वाणिज्य दाम पर नियात किया जाए। यदि उपर्युक्त बातों का हम गूरा-गूरा ध्यान रख सकें तो कायले व उद्योग का भविष्य उज्ज्वल माना जायकता है। भारत सरकार ने १९४६ में कायले व उद्योग का समस्याओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी। इसने कई सिफारिशों की जिन में से एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि एक राष्ट्रीय कायला आयोग नियुक्त किया जाए जो कमेटी सम्बन्धी समस्त प्रश्नों का मचालन करे और विभिन्न मन्त्रालयों की बशाय एक ही मन्त्रालय में सब समस्याओं का सम्बन्ध रहे। इन सिफारिशों पर विचार न करके भारत सरकार ने एक रजि ग पार्टी 'फॉर द कोल इंडस्ट्री', हाल में मित्र का है जो इस उद्योग सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर अपनी राय दगी। इन समस्याओं में कायले का उत्पादन-वृद्धि, उत्पादन-लागत में कमी, महदूरों, व्यवस्था और संगठन का कार्य-कुशलता में वृद्धि, वैज्ञानिक, नव विचार और कायले व प्रकार में सुधार की समस्या व प्रमुख हैं।

एञ्जीनियरिंग उद्योग — एञ्जीनियरिंग उद्योग किसी एक उद्योग का नाम नहीं है पर कुछ उद्योगों का सामूहिक नाम है। एञ्जीनियरिंग उद्योगों में निम्न उद्योगों का समावेश किया जाता है—इंजनचरल एञ्जीनियरिंग जिसके अन्तर्गत पुल बनाना, तथा ईगर्भ ट्रान्शन टावर, लेम के कुए, आदि हमारे इस्तेमाल के कामों का निर्माण करना आता है औद्योगिक प्लांट और मशीनरी के निर्माण का उद्योग, एजिन बनाने का उद्योग, मोटर (प्रोटोमोबाइल) आदि बनाने का उद्योग, हवाई जहाज बनाने का उद्योग, मशीन-टूल का उद्योग जिसके अन्तर्गत व समान वाणिज्य उपकरण (मरनिङ्गल कट्टाविसेज) आ जाते हैं जो लकड़ा या घात के काटने, पोलिश करके, या उन पर काम करने के लिये आवश्यक होते हैं। सिलाई का मशीनों, बाइसिकिल और हरोकेन या लान्डेन के उद्योग आ इत्यादि एञ्जीनियरिंग के नाम से जाने जाते हैं, बिजली के सामान आदि सम्बन्धी उद्योग जिसमें पम्प, लेम्प, मोटर, तार और पेबन्स, एक्मूलेटर्स और ट्रांसफार्मर, बिजली का सामान जैसे स्विच, प्लग, मोरेट आदि, ट्रांसफार्मर्स, डीजल एजिन सम्बन्धी उद्योग, पावर प्लांट्स रेडियो रिमावर्स का उद्योग और टेलीफोन व सामान का उद्योग। एञ्जीनियरिंग उद्योग में स्टील फोर्जिंग का काम जिसके द्वारा कच्चे इस्पात से फ़िनिश इस्पात बनाया जाता है और स्टील फेबरीकेशन को समान विधायें जैसे पेंट करना, मशीनिंग, ड्रिलिंग (छेद करना), रिब्रिटिंग आदि जिनके द्वारा 'रोल्ड स्टील' को निच काम में वह आने वाला हो उसने योग्य बनाया जाता है, भी आ जाते हैं। एञ्जीनियरिंग

उद्योगों की गिनती आधार भूत उद्योगों में होती है और इनकी प्रगति लोहे और इस्पात के उद्योग पर बहुत कुछ निर्भर होती है, क्योंकि लोहा और इस्पात ही इन उद्योगों का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। भारत में एंजीनियरिंग उद्योगों का अभी वषष्ट विकास नहीं हुआ है यद्यपि पिछले वर्षों में इस दिशा में प्रगति अवश्य हुई है। जब १९२४ में इस्पात की संरक्षण मिला तो उसका असर एंजीनियरिंग उद्योग को प्रोत्साहन देने का भी हुआ। परन्तु विश्वव्यापी मंदी के कारण इन उद्योगों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। द्वितीय महायुद्ध के समय से फिर इन उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। जैसे-जैसे देश का आर्थिक और औद्योगिक विकास होगा वैसे-वैसे इन उद्योगों का विकास होना भी अवश्यम्भावी है। वास्तव में बात तो यह है कि इन उद्योगों की उन्नति पर ही बहुत कुछ हमारे देश का औद्योगिक विकास आधारित है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् देश में जो औद्योगिक मंदी आई और देश के विभाजन से जो हमारे माल के लिये बाजार की हानि हुई उसका असर भी एंजीनियरिंग उद्योगों पर पड़ा। इन उद्योगों की प्रगति के लिये निम्नलिखित सुविधाओं की आवश्यकता है—मजदूरों की ट्रेनिंग खास तौर से ट्रेन्ड मिस्त्री की व्यवस्था, वातायात की सुविधा, रेलवे-किराये में सहानुभूतिपूर्ण नीति, ठेकार कर-नीति, अच्छे कोयले की व्यवस्था सस्ते दामों पर, मजदूरी का उत्पादन के साथ संबंध। कुछ खान-खास एंजीनियरिंग उद्योगों के सम्बन्ध में देश की वर्तमान स्थिति क्या है, इसका हम अब अत्यन्त संक्षिप्त विवरण यहां देंगे।

रुद्धकचरल एंजीनियरिंग उद्योग:—इस उद्योग से सम्बन्ध रखने वाली क्रमों में से खास-खास फर्म कलकत्ते [१६], बम्बई [६] और मद्रास [१] में है। इनके काम की मांग प्रधानतः सरकारों की ओर से ही होती है। देश में विकास सम्बन्धी योजनाओं को जैसे-जैसे कार्यान्वित किया जायगा वैसे-वैसे इन उद्योगों की मांग भी बढ़ेगी।

औद्योगिक प्लान्ट सम्बन्धी उद्योग:—मशीन-उत्पादन का उद्योग भी देश के औद्योगिक विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है। अब तक हम मशीनें विदेशों से मंगाते रहे हैं। लगभग १०० करोड़ रु० की मशीनें हमारे देश में हर साल आती हैं। इस उद्योग के लिये सब कच्चा माल [लोहा-इस्पात, पोटल, कांसा, एलुमिनियम एलुमि, रिनेट्स, पाइप्स, ट्यूब्स, फोर्ज्ड स्टील के पदार्थ] हमारे देश में उपलब्ध हैं और जैसे-जैसे टेक्नोलॉजिकल स्कूल आदि की संख्या देश में बढ़ेगी, टेक्निकल स्किल की कमी का प्रश्न भी हल हो सकेगा। इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख फर्म टेक्स्टाइल मशीनरी कोरपोरेशन लि० है, जो कर्यों

और नक़्शों का उत्पादन करता है। टेक्साइल मशीनरी का उत्पादन करने वाला कुछ और फर्मों भी हमारे देश में हैं।

एजिन उद्योग — रत्न यातायात व विस्तार और विकास के मार्ग में एक बड़ा कठिनाई पैदा मालूम में एजिन नहीं मिलने की रही है। हमारे देश में दा रत्न वस्तुओं में (अत्रमर और जमालपुर) एजिन तैयार करने का काम हुआ है। पर जमालपुर में एजिन बनाने का काम १९२६ में बंद हो गया। टाटा लोकोमोटिव एंड एलोनियरिंग कंपनी वैयक्तिक आधार पर आरम्भ किया गया एजिन तैयार करने का प्रथम व्यवसाय था। १९५६ में भारत सरकार ने यह निश्चय लिया कि एजिन तैयार करने का एक कारखाना स्थापित किया जाय। इस निश्चय व अनुसार पश्चिम बंगाल में चित्तरजन [मिर्जा नाम] नाम के स्थान पर इंडियन रेलवे में लूकचरिंग वर्क्स नाम के कारखाने की स्थापना का काम जारी है और नवम्बर १९५० में उत्तर द्वारा पहला एजिन तैयार भी किया जा चुका है। अभी तो बाहर से एजिन के भागों का आयात करके एजिन तैयार किये जाते हैं, पर धीरे धीरे इस मार्गों का निर्माण भी इस कारखाने में शुरू किया जा रहा है और ऐसा आशा है कि १९५४ तक सब भाग यहीं बना लगने और इस प्रकार पूरा चित्तरजन में बना एजिन १९५४ में तैयार होने का उमावना मानी जा सकता है। यह भी आशा है कि १९५४ तक १२० एजिन और ५० अतिरिक्त मोटरसे, जो इस कारखाने का अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य है, बन सकेंगे।

मोटर उद्योग — मोटर उद्योग भी एक आधारभूत उद्योग है जिसका शांति और युद्ध दोनों ही समय में बहुत महत्व है। आरम्भ में कुछ विदेशी फर्मों की शाखाएँ यहाँ स्थापित हुई जैसे बम्बई में 'जनरल मोटर्स एसम्बलिंग प्लांट' जिन्होंने विदेश से आया हुए विभिन्न हिस्सों को मिलाकर मोटर तैयार करने का काम शुरू किया। १९४६ में प्रीमियर ओटोमोबाइल्स लि० नाम के एक भारतीय फर्म की वक् में स्थापना हुई। इसी प्रकार पुराने बकौदा राज्य में हिन्दुस्तान मोटर्स की स्थापना की गई। १९४८ में कुल ३६८५४ मोटर गाड़िया अलग अलग हिस्से मिला कर तैयार (एसम्बलिंग) की गई। हाल में विदेशी फर्मों के सहयोग में कुछ नई फर्मों भी स्थापित हुई हैं। मोटर एक्सेसरीज की सरकार से भी मिला है। इस उद्योग व विकास के लिये इस बात की चर्चा बड़ी

है कि मोटर के विभिन्न हिस्सों का उत्पादन भी हमारे देश में ही वैज्ञानिक हो। इस विषय में प्रयत्न अग्रसर हो रहा है पर इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका एक उपाय यह है कि कोई भी मोटर

तैयार करने वाली कर्म अधिक से अधिक अमुक्त मूल्य तक के हिस्से ही बाहर से मंगा सकती है, यह निश्चित कर दिया जाए, और यह मर्यादा धीरे-धीरे कम की जाए। इसका असर मूल्य में कमी होने का भी होगा। दूसरी बाधा इस उद्योग के मार्ग में यह बताई जाती है कि विभिन्न रूपों में इस पर कुल मिलाकर करों का भार अत्यधिक हो जाता है—जैसे आयात कर, बिक्री कर, रजिस्ट्रेशन फीस, पेट्रोल पर लगाने वाला कर तथा टायर आदि दूसरे सामान पर लगाने वाला कर। ये सब ही मिलकर मोटर पर होने वाले खर्च को बहुत बढ़ा देते हैं। मोटरों आदि पर लगने वाले करों से सरकार को २८ करोड़ रुपये की आय होती है जबकि सबकों को पूंजीगत (कैपिटल) कीमत २०० करोड़ रुपये के लगभग है। इसका अर्थ है पूंजी पर १४ प्रतिशत आय। जब रेलवे में लगी पूंजी पर सरकार ४ प्रतिशत से संतोष मानती है तो मोटर पर १४ प्रतिशत आवश्यक ही बहुत है। इसमें कमी करना आवश्यक मालूम पड़ता है। मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण वा परिणाम भी मोटर-उद्योग के प्रतिकूल हुआ है क्योंकि मोटरों की मांग पर इसका बुरा असर पड़ा है। पर राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर इस प्रकार तात्कालिक और संकीर्ण दृष्टि से विचार करना गलत है और उसके मार्ग में जो बाधाएं मालूम पड़ें उनको हल करने की ओर ध्यान देना चाहिये न कि राष्ट्रीयकरण के विचार का ही परित्याग कर दिया जाये।

हवाई जहाज उद्योग—अभी इस उद्योग का हमारे देश में अभाव ही है। हिन्दुस्तान एयर कोर्प लि० नाम की एक फैक्टरी १९४० में स्थापित की गई थी जहां बाहर से आये सामान से हवाई जहाज तैयार किये जाते हैं। युद्ध के समय इस फैक्टरी का महत्व बढ़ गया और इसने प्रधानतया एक सरकारी फैक्टरी का रूप ले लिया। भारत में एलुमिनियम और उसकी निश्चित मात्रा होती है जो हवाई जहाज के उद्योग के लिये आवश्यक है। अतः इस उद्योग का हमारे देश में विकास हो सकता है। हिन्दुस्तान एयर कोर्प फैक्टरी की अच्छी प्रगति हो रही है।

मशीन टूल्स—द्वितीय महायुद्ध के पहले अधिकांश मशीन टूल्स विदेश से आते थे। पर फ्रान्स के पतन और जापान के युद्ध में शामिल होने के बाद जब बाहर से माल का आना बन्द-सा हो गया तो हमारे देश के उद्योग को प्रोत्साहन मिला। हमारा वार्षिक उत्पादन ११ हजार मशीन टूल्स तक पहुँच गया। कलकत्ता, बम्बई, सतारा, हरीहर, बटाला, और लुधियाना इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं। १९४६ में कुल उत्पादन ६१ करोड़ रुपये तक पहुँच गया था। पर युद्ध के बाद से इस उद्योग की स्थिति मांस कम हो जाने के कारण संतोष-

जनक नहीं रही है। १९४६ में कुल उत्पादन ४८ लाख रुपये का ही रह गया था। मांग की कमी के कई कारण हैं, जैसे विकास की योजनाओं व कार्यान्वित नहो होने से मांग की कमी होना, विदेशी मशीनों की कम कीमत पर विदेशों और युद्ध कालीन सामान की सरकार द्वारा सस्ते दामों पर बिक्री। इसके अतिरिक्त वर्तमान फेक्टरियों की यह हालत हो रही थी, उधर भारत सरकार ने एक पंचवर्षी काफी बड़े पैमाने पर स्थापित करने का निश्चय कर लिया था। जब सरकार ने इस निश्चय का विरोध किया गया और उसका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि हम गमय मांग में गिरावट आती जा रही है तो भारत सरकार ने अपने निश्चय में आवश्यक परिवर्तन कर दिया। अब भारत सरकार १८ करोड़ रुपये की बजाय ६६ करोड़ का पूँजी लगानगी और उत्पादन ८ करोड़ की बजाय ४ करोड़ रुपये का ही किया जायगा। इसके अलावा सरकारी फेक्टरी में व मगानें तैयार होंगी जो अब तक वैयक्तिक फेक्टरियाँ में तैयार नहीं होनी हैं, ताकि आपस में प्रतिस्पर्धा न हो। यह आशा है कि पाँच वर्ष में यह फेक्टरी की योजना कार्यान्वित हो सकेगी। सरकारी फेक्टरी में हाइड्रोजन सेल्स, हाइड्रोजन शक्ति मशीनें, और क्यूरी जिलिंग मशीनें लाखों लीटर में तैयार की जायगी। देश के आर्थिक विकास में इस उद्योग का बड़ा महत्त्व है। पेट्रोल, रोलिंग स्टील के पदार्थ और अलुमिना धातु तथा कोयला, कोक, चूना पत्थर और लकड़ी का इस उद्योग में अच्छे माल के रूप में आवश्यकता होती है। ये सब चीजें हमारे देश में उपलब्ध हैं।

सिलिकॉन की मशीनें—भारत में लगभग १ लाख सिलिकॉन की मशीनों का प्रापिक व्यय है। १९४६ में भारत में १५००० मशीनें तैयार की गई। अधिकतम उत्पादन शक्ति साल में १७००० मशीनों के लगभग है। पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पन्जाब और पपुन इन मशीनों के बनाने के कारखाने हैं। १९४७ में ४६ लाख की पूँजी इनमें लगी हुई थी।

नाइसिकिल—इस उद्योग का प्रारम्भ कलकत्ते में १९३८ में हुआ और कुछ भागों के उत्पादन के साथ इनके कार्य आरम्भ किया। युद्ध में इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला। भारत में सांख्यिकी की वार्षिक मांग ३ लाख है और हमारी उत्पादन शक्ति ६० हजार के लगभग है। १९४७ में १२ फेक्टरियाँ इस उद्योग में थी जिनमें १६०० आदमी काम करते थे और ७ लाख के लगभग पूँजी लगी थी।

हरीकेन लेटर्न—इस उद्योग में ६ सगठित फेक्टरियाँ हैं। देश की कुल मांग ५० लाख सालाने प्रतिवर्ष है। १९४६ में १७ लाख सालाने हमारे देश में

तैयार हुईं। इनारी उत्पादन क्षमता ३३ लाख लालटेन हैं।

विजली का सामान—हमारे देश में २८ विजली के पंखे, ६ विजली के लेम्प, और ६ एक्सेसरीज जैसे स्विच प्लग आदि और ५ फ्लेश लाइट्स की फेक्टरियां हैं। इनके अलावा वायर और केबल्स, मोटर्स और एकुमूलेटर्स और ड्राई सेल्स तथा ट्रान्सफोर्मर्स भी हमारे देश में थोड़े बहुत तैयार होने लगे हैं।

डीजिल एंजिन—अपनी सादा बनावट, और संचालन और सत्तेपन के कारण डीजिल एंजिन का बड़ा प्रचार हो रहा है। पानी निकालने, और खेती के काम में तथा रेल और सड़क के यातायात में इनका उपयोग हो सकता है। सतारा, दहली और कोल्हापुर इनके मुख्य उत्पादन-केन्द्र हैं। भारत में लगभग ५००० डीजिल एंजिन हर साल बाहिरें। हमारे कारखानों की उत्पादन-शक्ति १९४६ में ५२०० एंजिन थी पर वास्तव में केवल २१०० एंजिन तैयार किये गये। बाहर से बहुत से एंजिन अभी आयात होते हैं। भारत-सरकार एक फ्रेक्टरी स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

पावर प्लान्ट्स—विजली उत्पादन के काम में ये पावर प्लान्ट आते हैं। हमारे देश में अभी यह विल्फुल तैयार नहीं होते हैं। भारत-सरकार ने इस संवत् में एक योजना बनाई थी पर वह आर्थिक कठिनाई के कारण स्थगित कर दी गई।

रेडियो रिसेवर्स—पिछले वर्षों में रेडियो रिसेवर्स के उद्योग में बड़े-बड़े प्रगति हुई है। १९४७ में भारत की उत्पादन क्षमता ८००० सेट्स की थी। १९४६ में रेडियो रिसेवर्स की उत्पादन शक्ति ६० हजार सेट्स प्रति वर्ष थी और १६ हजार सेट्स का वास्तविक उत्पादन था जबकि १९४७ में उत्पादन १००० हजार सेट था।

टेलीफोन इक्विपमेंट—यम्बाई, कलकत्ता और देहरादून में टेलीफोन के सामान तैयार करने की एक-एक फ्रेक्टरी है। जुलाई १९४८ में बंगलोर में इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज नाम का एक कारखाना भारत-सरकार ने स्थापित किया था। बाद में इसमें मैसूर सरकार और इंग्लैंड की ओटोमेटिक टेलीफोन एण्ड इलेक्ट्रिक कंपनी की साझेदारी भी स्वीकार कर ली गई। १९४६ के आरंभ में इस फ्रेक्टरी ने काम करना आरंभ कर दिया। इसकी उत्पादन-शक्ति ५० हजार टेलीफोन और ३६ हजार एक्सचेंज लाइन्स प्रतिवर्ष है।

रासायनिक उद्योग—कई उद्योगों का सामूहिक नाम रासायनिक उद्योग है। ये उद्योग दो प्रकार के होते हैं—(१) भारी रासायनिक पदार्थ, जैसे—

सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, विभिन्न प्रकार के सनफेट, एलमेनीज़ जैसे कार्बेटिक सोडा, सोडा एश, एमोनिया और एल्वेसार्न पदार्थ जैसे स्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, पोटेशियम क्लोरेट, और रासायनिक खाद जैसे एमोनियम सनफेट, सुपरफोस्फेट पोटेशियम नाइट्रेट आदि। (२) कीमती रासायनिक पदार्थ (फाहा केमिकल्स) में फोटोग्राफी के काम में आने वाले रासायनिक पदार्थ, ड्रग्स और फार्मेस्यूटिकल पदार्थ, पट्टण, वार्निश और रंग के पदार्थ गिने जाते हैं। भारतीय रासायनिक पदार्थ कृषि और उद्योग दोनों में काम में आते हैं और इसलिये उनकी गिनती आधारभूत उद्योग में होती है। ये पदार्थ बड़ी मात्रा में और सस्ते दामों पर तैयार किये जाते हैं। कीमती रासायनिक पदार्थ कम मात्रा में उत्पन्न किये जाते हैं और उनके उत्पादन में कौशल की अधिक आवश्यकता होती है। अब हम भारी रासायनिक पदार्थों के उद्योग के बारे में सन प में कुछ लिखेंगे।

प्रथम महायुद्ध के पहले तक रासायनिक उद्योगों का हमारे देश में बहुत विकास नहीं हुआ था यद्यपि बहुत सा अच्छा माल हमारे यहाँ उपलब्ध था। प्रथम महायुद्ध के समय विदेश से आने वाले रासायनिक पदार्थों का आयात कम होगया और देश में भाँग बढ़ गई। इससे इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला। पर युद्ध समाप्त होजाने के बाद विदेशी प्रतिस्पर्धा फिर बढ़ गई। अतः सरकार द्वारा संरक्षण देने का प्रश्न उपस्थित हुआ। टेरेफ बोर्ड ने १९२०-२१ में जाव करके संरक्षण के पक्ष में राय दी और भारी रासायनिक उद्योग संरक्षण कानून १९३१ में पास किया गया। मगनशियम क्लोराइड के अलावा जितनी अवधि मार्च १९३६ तक थी और जो बाद में १९४६ तक के लिये बढ़ा दी गई थी, बाकी के पदार्थों को संरक्षण मार्च १९३३ तक ही दिया गया। संरक्षण के बाद ही एलमेनीज़ का उत्पादन हम देश में वास्तव में प्रारम्भ हुआ। इंग्लिश केमिकल्स लि० और टाटा केमिकल्स लि० नाम की दो बड़ी कम्पनियों सोडा एश तथा कार्बेटिक सोडा के उत्पादन के लिए स्थापित भी की गई। द्वितीय महायुद्ध के समय से इन उद्योगों को काफी रुचि दिखलाई क्योंकि युद्ध की दृष्टि से सरकार ने भी इनके विकास में काफी रुचि दिखलाई क्योंकि युद्ध की दृष्टि से इन उद्योगों का बहुत महत्व था। काथिल ऑयल साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च बोर्ड ने भी इस उद्योग का प्रगति में अच्छा योग दिया। कई रासायनिक पदार्थ जो पहले बाहर से आते थे अब हमारे यहाँ तैयार किये जाने लगे—जैसे कोपर सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, ग्लाइस पाउडर क्लोरीन आदि। कई का उत्पादन पहले से बहुत बढ़ गया जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन पिछले दस वर्षों

तीन गुना बढ़ गया। इसी प्रकार हाईड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का उत्पादन युद्ध के पहले ३५० टन और ५०० टन अब क्रमशः था, २५०० टन हाईड्रोक्लोरिक एसिड का और २७५० टन नाइट्रिक एसिड का उत्पादन होगया। वही बात कास्टिक सोडा और क्लोर्सिंग पाउडर के बारे में है, यद्यपि आजकल इन उद्योगों की स्थिति फिर कठिन होगई है। सोडा एण्ड वाइंगोनेट्स, मैग्नेशियम और मैग्नेशियम सल्फेट आदि का उत्पादन भी बड़ा है। रासायनिक खाद और सुपर फोस्फेट के उद्योगों की भी प्रगति तो हुई है पर अपेक्षाकृत कम। लारांश यह है कि अधिकांश रासायनिक पदार्थों के उद्योगों को द्वितीय महायुद्ध के समय प्रोत्साहन मिला और तब से उनका विकास हुआ है। देश के विभाजन का असर इन उद्योगों के लिए इस अर्थ में हानिकर हुआ कि पाकिस्तान के बाजार के बारे में अनिश्चयता आगई। युद्ध समाप्त होने के बाद कई रासायनिक उद्योगों ने संरक्षण की मांग की और उनको संरक्षण मिला भी। कास्टिक सोडा और क्लोर्सिंग पाउडर के उद्योगों ने भी संरक्षण की मांग की थी पर उनकी मांग ना-जूर कर दी गई है। द्वितीय महायुद्ध के समय इन उद्योगों का जो विस्तार हुआ उसमें एक बड़ा दोष यह था कि वह विस्तार किसी योजना के आधार पर नहीं हो सका।

अवतक हमने भारी रासायनिक पदार्थों, सम्बन्धी उद्योगों के बारे में ही विचार किया है। कीमती रासायनिक पदार्थ, ड्रग्स, और फार्मास्योटीकल्स के बारे में इतना ही कह देना सयष्ट होगा कि यद्यपि इन उद्योगों को भी गत महायुद्ध के समय प्रोत्साहन मिला परन्तु अभी वे अपने विकास की प्रारम्भिक अवस्था में ही हैं। इन उद्योगों पर भी विभाजन का असर इसी रूप में पड़ा है कि पाकिस्तान का बाजार अब अपना बाजार नहीं रहा है।

जहाँ तक भारी प्रगति का सवाल है दूसरे देशों के मुकाबले में हमारे रासायनिक उद्योगों का (भारी और कीमती दोनों) विकास बहुत कम हुआ है। पर भविष्य में विकास के लिये काफी गुंजाइश है। भारी रासायनिक पदार्थों सम्बन्धी उद्योग का विकास बहुत कुछ उन दूसरे उद्योगों के विकास के साथ बंधा हुआ है जिन में इन पदार्थों का उपयोग होता है। कीमती रासायनिक उद्योगों में भारी रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है। इसलिये एक हद तक इनका भी पारस्परिक सम्बन्ध है। फाइन केमिकल्स के लिए जहाँ तक इन थ्रोनेमिक हेवी केमिकल्स का प्रश्न है वे हमारे देश में आज भी मिलते हैं, पर थ्रोनेमिक हेवी केमिकल्स अभी हम बाहर से मंगाते हैं। अतः इस कमी को पूरा करने की ओर हमें ध्यान देना होगा। इसी प्रकार सिंथेटिक ड्रग्स के लिये

आवश्यक पाइन केमीकल्स अभी बाहर से आते हैं। यह कभी भी पूरी होनी चाहिये। सिंथेटिक डाइस्टिफर अभी हमारे देश में पैदा नहीं होने, पर इनका उत्पादन हो सकता है। इसके लिए कोलतार के उद्योग का विकास करना जरूरी है। कोलतार से ही सिंथेटिक ड्यूक और बड़े प्रिस्मेटिक पदार्थ पैदा होते हैं। सभी प्रकार का प्रोसेसिंग केमीकल्स (सल्फ्यूरिक एसिड आदि) का अपना आवश्यकता पूर्ण भी इस उद्योग को अलग से करना पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा उत्पादन मौजूदा उपयोग में समाप्त होता है। उपर्युक्त बातों के अलावा कुछ बातें दोती ही प्रकार के रासायनिक उद्योगों की प्रगति के लिए आवश्यक हैं। सबसे बड़ी बात तो विदेश से आवश्यक मशीनरी आदि के मँगाने की है। बाहर के टेक्नीशियनों की भी हमें कुछ समय के लिये सहायता लेनी होगी और यह प्रबंध भी बिठाना होगा कि हम अपने लोगों को आवश्यक ट्रेनिंग दे सकें। आवश्यक इन्फ्रामेंट और प्रिस्मेशन इन्स्ट्रुमेंट्स का भी हमारे देश में उत्पादन करने का प्रयत्न करना चाहिये। इसी के साथ हमें मशीनों की भी आवश्यक ट्रेनिंग देनी होगी। हमें अपने रासायनिक उद्योग के लिए ऐसे मैनेजर चाहिए जो जैने देंगे वे टेक्नोलॉजिकल इस्टीमेट में तैयार किये जायें, और सुपरवाइजर और स्विच मैन्यूर भी चाहियें। इन सब बातों के अलावा घर, रेल ठेकिया और आयात कर सम्बन्धी सरकार की नीति भी अधिक सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिये। सस्ती और पर्याप्त बिजली की शक्ति की भी इन उद्योगों के लिये बड़ा आवश्यकता है। उपर्युक्त सब बातों की ओर यदि हम पूरा ध्यान दें तो हमारे देश में रासायनिक उद्योगों का अच्छा विकास हो सकता है। इन समय का स्थिति का अनुमान तो इससे लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में कुल ४७० उत्पादन केन्द्र हैं जिनमें केवल १५ बड़े पैमाने पर काम करते हैं। इस उद्योग में कुल पूँजी ५ करोड़ ८० के लगभग लगी हुई है जो समस्त उद्योगों में लगी पूँजी का केवल ०.५ प्रतिशत होती है।

अब हम कुछ प्रमुख रासायनिक पदार्थों के उद्योगों के विषय में संक्षिप्त जानकारी करेंगे।

सल्फ्यूरिक एसिड — भारी रासायनिक पदार्थों में सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत महत्व है क्योंकि न केवल यह दूसरे उद्योगों [पाद, कपास उद्योग, चमड़ा और इजानियरिंग] में काम आता है पर दूसरे रासायनिक पदार्थों में भी इसका उपयोग होता है। हमारे देश में इस समय लगभग ४३ फ़ैमें सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करती हैं और उनकी उत्पादन शक्ति १३ लाख टन है, और वार्षिक वार्षिक उत्पादन १९५० में १ लाख टन के आस-पास हुआ था।

हमारी वर्तमान मांग १ लाख टन प्रति वर्ष है। इस उद्योग के मार्ग में एक बड़ी कठिनाई यह है कि गंधक [सल्फर] हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश में मिलने वाले गंधक वाले दूसरे पदार्थों का इस उद्योग में उपयोग किया जाये जैसा कि कई पश्चिम के देशों में होता है। राल-स्थान में कैल्शियम सल्फेट बथेष्ट मात्रा में होता है। उससे सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। जर्मनी में भी गंधक होता है। इसके अलावा यह भी प्रयत्न किया जाना चाहिये कि कई उद्योगों में सल्फ्यूरिक एसिड के उपयोग के बिना ही काम चल जाय। जैसे खाद पदार्थों में एमोनियम सल्फेट और सुपर फ़ोस् फेट और हाईड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड बिना सल्फ्यूरिक एसिड के भी तैयार किये जा सकते हैं। पर भारत में अभी ऐसा होना जल्दी संभव नहीं हो सकता। खाद-उद्योग के विकास के साथ-साथ सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन भी बढ़ेगा।

एलकलीजः—एलकलीज में कास्टिक सोडा एक प्रमुख पदार्थ है। यह साबुन, टेक्सटाइल्स, कागज तथा लगभग सब बड़े उद्योगों में काम आता है। इसकी उत्पादन क्षमता इस समय १८००० टन वार्षिक है। कुल छह कारखाने इस उद्योग के हैं। वास्तविक उत्पादन १९५० में ११ हजार टन के लगभग हुआ था और हमारी वार्षिक मांग ६५००० टन है। इस उद्योग के संरक्षण की मांगको सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। यह आशा है कि नए प्लान्ट की स्थापना और मौजूदा के विस्तार से शीघ्र ही इस पदार्थ में हम स्वावलंबी हो सकेंगे। कास्टिक सोडा तैयार करने का एक तरीका तो लाइम-सोडा से है और दूसरा तरीका इलेक्ट्रोलिटिक पद्धति का है जिससे सहायक-पदार्थ के तौर पर क्लोरीन भी पैदा होता है। हमारे देश में आज भी क्लोरीन जितनी मात्रा में पैदा होता है उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं होता है। क्लोरीन की वर्तमान उत्पादन शक्ति ६५०० टन है। १९५० में ४ हजार टन क्लोरीन पैदा किया गया। क्लोरीन क्लोचिंग पाउडर, हाइड्रो क्लोरिक एसिड और डी. डी. टी. तैयार करने में काम आता है। इसके उपयोग के और नये मार्ग ढूँढ निकालने की आवश्यकता है। क्लोचिंग पाउडर तैयार करने के देश में तीन कारखाने हैं जिनमें १९५० में ३ हजार टन के लगभग क्लोचिंग पाउडर तैयार किया गया। हमारी क्षमता ५ हजार टन तैयार करने की है। साल में १२ हजार टन के आस पास देश में मांग है जिसका अधिकांश भाग बाहर से आता है। इसकी संरक्षण की मांग भी सरकार ने अस्वीकार कर दी है।

सोडा एश भी एक दूसरा एलकली है जो शीशे, टेक्सटाइल्स, कागज

आदि व उद्योग व काम में जाता है। हमारी वार्षिक मांग १,३०,००० टन के लगभग है और वर्तमान उत्पादन लगभग देश के दानों और शर्करा स्थित प्लांटों से ५४,००० टन है। उच्च दाम पर औद्योगिक गन्धक की वृद्धि इस उद्योग व मांग में प्रमुख बाधा है। यही कारण है कि पुरा उत्पादन शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता। १९५० में कुल उत्पादन लगभग ४५ हजार टन के था। शेष मांग आयात से पूरा होता है।

रासायनिक खाद—हमारे देश में अन्न उत्पादन का कितना महत्व है यह सब जानते हैं। इसी से रासायनिक खाद का महत्व भी स्पष्ट हो जाता है। रासायनिक खादों में एमोनिया फॉस्फेट, एमोनियम सल्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपरफॉस्फेट आदि आते हैं। खादों में बहुत बंधन भारत में रासायनिक पदार्थों का उत्पादन नहीं कर सकते थे और खाद भी हमारी अधिकांश मांग बाहर से हो पुरा होता है। इस क्षेत्र में बड़ी प्रगत नौर सरकार ने बेलगूला नामक स्थान में फैक्टरी (उत्पादन शक्ति ७५०० टन) स्थापित करवा दिया था। दूसरी फैक्टरी १९५८ में ट्रावकोर में अन्नदा स्थान में स्थापित हुई थी इसका उत्पादन शक्ति ४८५०० टन वार्षिक था। अबने बड़ी योजना बिन्दरी (विहार) में ३३ लाख टन उत्पादन शक्ति का बड़ी स्थापित करने की है। यह फैक्टरी भारत सरकार द्वारा स्थापित का जा रही है। व दोनों ही फैक्टरी एमोनियम सल्फेट का उत्पादन करेंगीं। हमारे देश में एमोनियम सल्फेट का वर्तमान उत्पादन बहुत कम है। निम्नलिखित वर्षों में प्रगति अवश्य हुई है। देश की ६ फैक्टरी में निम्नलिखित उत्पादन लगभग ७८ हजार टन प्रति वर्ष है। १९५० में ४८ हजार टन एमोनियम सल्फेट तैयार किया गया था। एमोनियम सल्फेट न अलग हमारे देश में कुछ फैक्टरी सुपरफॉस्फेट की भी हैं। सुपरफॉस्फेट का १९५० में ५२ हजार टन का उत्पादन हुआ था। इस समय देश में सुपरफॉस्फेट तैयार करने के १४ कारखाने हैं निम्नलिखित कुल उत्पादन लगभग १,१०,००० टन है। यह रोक फॉस्फेट से तैयार होता है। रोक फॉस्फेट हमें बाहर से म्यास तीर से मोरको से मँगाना पड़ता है। एमोनिया खाद की हमारे देश में वार्षिक मांग ८० लाख टन के है, पर उसके मुकाबले में हमारा वर्तमान उत्पादन लगभग १ लाख टन ही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रासायनिक खादों के उत्पादन में वृद्धि करने की हमारे देश में किन्हीं आवश्यकता है। यह अभी संभव हो सकता है किन्तु भारतीय निम्नलिखित इन उपयोग से परिचित हो, इनका मुख्य उपयोग पशुओं के अन्न हो और आसानी से खाद उस तक पहुँच सकें।

हमारे रासायनिक उद्योगों के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्बिक सोडा, सोडा एश और ग्लोबिंग पाउडर में भारत स्वावलम्बी नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड, लिक्विड क्लोरोज, वाइक्रोमेट्स, कैल्शियम क्लोराइड, मैगनीज क्लोराइड और फोटोग्राफी में काम आने वाले तीनों रासायनिक पदार्थों में भारत स्वावलम्बी है। सल्फ्यूरिक एसिड और फोटोग्राफी में काम आने वाले रासायनिक पदार्थों को छोड़कर, बाकी के सब रासायनिक पदार्थ हमारे देश में उपलब्ध करने माल से ही तैयार होते हैं।

चमड़े का उद्योग—गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुओं के शरीर से, उसकी मृत्यु के बाद, जब खाल हटाई जाती है तो उसे कच्चा चमड़ा कहते हैं। गाय-भैंस के चमड़े के लिये अंग्रेजी में 'हाइड' शब्द और भेड़ बकरी के चमड़े के लिये 'स्किन' शब्द का प्रयोग होता है। चमड़े के लिये ही जानवरों को मार कर जो खाल उतारी जाती है वह बढ़िया होती है और मरे हुए जानवरों के शरीर से जो खाल उतरती है वह बर्तिया होती है। वार्षिक भावना के कारण भारत में गाय-भैंसों को चमड़े के लिये प्रायः मारा नहीं जाता। इसलिये इस प्रकार का चमड़ा बहुत कम होता है। भेड़-बकरी के चमड़े के बारे में यह बात लागू नहीं होती। यह चमड़ा अधिकांश में उन जानवरों का ही होता है जो मांस के लिये मारे जाते हैं। भारत में गाय का चमड़ा १ करोड़ ६५ लाख टुकड़े, भैंस का चमड़ा ५० लाख टुकड़े, बकरी का चमड़ा ३ करोड़ टुकड़े और भेड़ का चमड़ा १ करोड़ १८ लाख टुकड़े पैदा होता है। देश के विभाजन से बढ़िया चमड़े की देश में कमी आ गई है। भैंस के बढ़िया चमड़े की मात्रा में वह कमी खास तौर से आई है।

जानवरों के शरीर से जो तनका मिलता है वह या तो कच्चे चमड़े के रूप में विदेशों को भेज-दिया जाता है या फिर वह देश में कमाया जाता है। चमड़ा कमाने के काम को ही 'टेनिंग' कहते हैं। कमाये हुए चमड़े से ही फिर चमड़े का सामान तैयार होता है। इसको 'लेवर इन्डस्ट्री' कहते हैं। द्वितीय महायुद्ध के ठीक पहले भैंस के चमड़े का लगभग १० प्रतिशत, गाय के चमड़े का लगभग २२.५ प्रतिशत, भेड़ के चमड़े का लगभग ६.५ प्रतिशत और बकरी के चमड़े का लगभग ८० प्रतिशत विदेशों को कच्चे चमड़े के रूप में भेज दिया जाता था, और बाकी का भारत ही में कमाया जाता था। चिन्तले वनों में निर्यात की मात्रा में और भी कमी आई है क्योंकि भारत में टेनिंग-उद्योग का विस्तार हुआ है। भारत से कमाया हुआ चमड़ा भी निदेशों को भेजा जाता है।

टेनिंग या चमड़ा कमाने का उद्योग—भारत में चमड़ा कमाने के उद्योग

को चार भेदियों में बाँटा जा सकता है—(१) गात्र का पुराने ढंग से पम्पा कमाने का उद्योग—इस धंधे में लग हुए लोगों की संख्या का कोई अनुमान नहीं है। पर भारत के प्रत्येक गाँव में चमारों के घर होते हैं जो इस धंधे को कुटीर उद्योग के आधार पर करते हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग ८० से ९० लाख टुकड़े गाँव में के चमड़े के और ४० लाख टुकड़े मेढ़कबंदी के चमड़े के गाँवों में फैले हुए चमारों द्वारा प्रतिवर्ष कमाये जाते हैं। (२) चीनी काम चमड़ा पदा करने वाला—दश में लगभग २५० ऐसी मोम चमड़ा तैयार करने वाली टेनरीज हैं। ये चांगी लोगों के हाथ में हैं और प्रचलित वे ही इस काम में करते हैं। जूते के ऊपर के भाग में लगाने वाला मोम चमड़ा इन टेनरीज में तैयार किया जाता है और लगभग २५ लाख चमड़े के टुकड़े के कमाने का इनका शक्ति है। इन में १००० के लगभग व्यक्ति काम करते हैं। कलकत्ता इनका प्रधान केंद्र है। (३) ईस्ट इंडिया टेड लेदर—यह चमड़ा मद्रास और बंबई स्थित कुछ कुटीर उद्योग के आधार पर चलने वाली टेनरीज में तैयार किया जाता है। 'ईस्ट इंडिया टेड लेदर' के नाम से यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मशहूर है। यह प्रायः विदेशों को भेजा जाता है। विदेशों में यह फिर से कमाया जाता है और सब चमड़े का सामान आदि बनाने के काम में लिया जाता है। इन कुटीर उद्योगों की संख्या लगभग ५०० के हैं और लगभग १ करोड़ टेड 'हाइड' और १ करोड़ ९० लाख टेड 'स्किन' इनमें तैयार होते हैं। (४) चमड़ा चालिन टेनरीज—इनकी संख्या लगभग २४ के हैं जिनमें से २६ बड़ी टेनरीज हैं। इनमें 'विजिटेशन टेड कपेली लेदर' और 'मोम टेड अपर लेदर' तैयार होता है। एक पाली काम करने की हालत में इनकी उत्पादन शक्ति लगभग २२ लाख 'विजिटेशन टेड' चमड़े और लगभग २० लाख 'मोम टेड' चमड़े की है। लगभग ८००० हज़ार व्यक्ति इन टेनरीज में काम करते हैं। कानपुर, कलकत्ता, और मद्रास इनके प्रधान केन्द्र हैं। १९४९ में ६ लाख के लगभग मोम टेड चमड़ा और १८ लाख के लगभग विजिटेशन टेड चमड़ा इन टेनरीज में तैयार हुआ था।

चमड़े का सामान तैयार करने का उद्योग—इस उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण धंधा जूते बनाने का है। ये हाथ से कुटीर उद्योग और फैक्टरी उद्योग दोनों के आधार पर तैयार किये जाते हैं। हाथ से फैक्टरी के आधार पर जूते बनाने का सबसे बड़ा केन्द्र आगरा है जहाँ लगभग १५० जूते तैयार करने की फैक्ट्रियाँ हैं। आगरे के बाद नम्बर और कलकत्ते का नम्बर आता है। कुटीर उद्योग के आधार पर जूते बनाने का काम सारे देश में फैला हुआ है। आगरा,

कलकत्ता और बम्बई कुटीर उद्योग के भी प्रधान केन्द्र हैं। राजस्थान में जयपुर और जोधपुर की जूतियाँ मशहूर हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग ७ करोड़ जोड़ी जूते और १ करोड़ ३० लाख जोड़ी घूट जूते इन कुटीर और छोटे पैमाने के कारखानों में हाथ से तैयार होते हैं। हमारे देश में खंभ से चलने वाली जूते बनाने की केवल ६ फैक्टरियाँ हैं—कलकत्ता, वाटानगर, मद्रास, बम्बई, और बंगलोर में एक-एक और आगरा और कानपुर में दो-दो। इनमें ४७ लाख जोड़े जूते तैयार किये जा सकते हैं। जूतों के अलावा चमड़े का और सामान भी हमारे देश में बनने लगा है—जैसे चमड़े के बेल्ट, पिकर्स, रोलर स्किन्स आदि तथा व्यक्तिगत सामान और यात्रा का सामान। चमड़े के काम के दो बड़े केन्द्र बम्बई और कलकत्ते हैं। इनके अलावा और कई जगह भी यह उद्योग चलता है।

टेनिंग और चमड़े के उद्योग की प्रगति—टेनिंग और चमड़े के उद्योग की प्रगति पहले महायुद्ध के समय से विशेष रूप से हुई। द्वितीय महायुद्ध के समय इन उद्योगों को और प्रोत्साहन मिला। भारत के टेनिंग उद्योग की प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई टेनिंग पदार्थों की खास तौर से बाटल की छाल की कमी की है। देश के विभाजन से कच्चे चमड़े को खास तौर से पाकिस्तान के बड़िया चमड़े की भी कठिनाई होने लगी है। 'बाटल वुल्' की पैदावार हमारे देश में बढ़ाने की आवश्यकता है। जो कच्चा माल बाहर से ही मंगाना आवश्यक है, उसके आयात की सुविधा होनी चाहिये और जो देश में पैदा किया जा सकता है उसे यहाँ पैदा करने का प्रयत्न होना चाहिये। चमड़े को बड़िया बनाने के लिये भी कई सुधार आवश्यक हैं। टेनिंग के काम में आने वाली कई मशीनें हमारे देश में बनती हैं। पर जो ज्यादा पेचीदा मशीनें हैं उन्हें बाहर से मंगाना होता है। जूते बनाने की मशीनें भी बाहर से ही आती हैं। टेक्निकल कामों के लिये लोगों को शिक्षा देने की कई राज्यों की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में सुविधा है। एक केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था भी स्थापित होने वाली है।

पिछले वर्षों में गत महायुद्ध के समय से चमड़े के उद्योग का उत्पादन कम हुआ है। कच्चे चमड़े, टेनिंग में काम में आने वाले पदार्थ और रासायनिक पदार्थ की, और देश के विभाजन से होने वाली माँग की कमी इस कम उत्पादन के खास-खास कारखाने हैं। उद्योग की भावी प्रगति की दृष्टि से यह आवश्यक है कि टेनेरीज गाँवों में जहाँ कच्चा माल पैदा होता है, स्थापित की जायें। गाँवों में रहने वाले चमारों को नए ढंग के काम की शिक्षा दी जानी चाहिये। योजना आयोग इस उद्योग के विकास की योजना पर विचार कर रहा है। देश में इस

उद्योग की मात्रा प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि कच्चे चमड़े, रासायनिक पदार्थ, रंग और मशीनों के मामले में हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो। यूरोप और अमेरिका के मुझाबले से हमारा यह उद्योग अभी कम उन्नत है।

तेल का मूल उद्योग—भारत में तिलहन का अच्छी पैदावार होती है, यद्यपि पिछले १० वर्षों में उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। भारत और पाकिस्तान दोनों का तिलहन का सम्मिलित उत्पादन ७०-८० लाख टन का माना जाता था। भारत में तिलहन का कुल उत्पादन कितना होता है, हम तबच में बहुत पक्का आँकड़ा तो उपलब्ध नहीं है पर अनुमान यह है कि लगभग ५० लाख टन तिलहन इस समय हमारे देश में उत्पन्न होता है। खास-ग्यास तिलहन जो भारत में पैदा होते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—अजमा (लिंगसीड), मूँगफली (मोड्ड नट), तिल (सिलेमम सीड), विनोबा (कोटा मोड), लखौ (मस्टर्ड), मारियल (कोररा), अडा (कैन्टर सीड) और महुआ। देश के विभाजन से तिलहन के उत्पादन पर कोई ग्रास असर नहीं हुआ है।

शिक्षण महायुद्ध के समय तक भारत से कारी तिलहन विदेशों को निर्यात होता था। इससे देश को आर्थिक हानि होती थी। द्वितीय महायुद्ध के समय से तिलहन के निर्यात में काफी कमी आई है। सन् १९३८-३९ में १६ करोड़ बरत के तिलहन हमारे देश से बाहर निर्यात हुए थे। इससे मुझाबले में १९४८-४९ में मुख्य में तीन गुनी वृद्धि हो जाने के बाद भी कुल ११ करोड़ रुपये के तिलहन का ही निर्यात हुआ था।

हमारे देश में तिलहन से तेल कई प्रकार से तैयार किया जाता है, जैसे घानियों द्वारा जो बैला से चलती हैं हाथ से चलाये जाने वाले स्क्व प्रेसेज द्वारा, रोटरी मिल द्वारा जो शक्ति से चलती हैं, एक्सपेक्स द्वारा, और हार डोलिंग प्रमेन द्वारा। उपर्युक्त तरीकों में से घानी का देश में सर्वोत्तम प्रकार है। महायुद्ध ने इस उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन मिला। हमारे विद्युत् युद्ध वर्षों में तेल उद्योग की प्रगति की और कुछ ध्यान दिया है। घानी से तेल तैयार करने के तरीकों में काफी सुधार की गुआइस है। महामा गांग के नेतृत्व में स्थापित प्रामोद्योग संघ इस में सुधार करने का बराबर प्रयत्न करता आ रहा है। इंडिया ओइल सीड्स कम्पनी ने भी कच्चा घानी को लोकप्रिय बनाने का कुछ प्रयत्न किया है पर इस प्रयत्न की बराबर आगे बढ़ाते रहने की आवश्यकता है।

देश में तिलहन का उपयोग तेल-उत्पादन में अधिक से अधिक होना

चाहिये इस में कोई संदेह नहीं । तेल उद्योग की उन्नति से हमें कई लाभ हैं । देश में काम की सुविधा बढ़ती है । खली और तेल दोनों का लाभ हमें मिलता है । खली जानवरों के लिये बहुत उपयोगी भोजन है । तेल भी अनेकों कामों में आता है—जैसे भोजन में, साबुन, पेंट, वार्निश आदि तैयार करने में और मशीनों आदि के लगाने में ।

तेल उद्योग की उन्नति के मार्ग में अवसक्त जो अनेकों कठिनाइयों अनुभव की गई हैं वे ये हैं—तिलहन के आयात पर विदेशों में कोई कर नहीं लगता, तेल और खल के मुकाबले में तिलहन पर लाने-लेजाने का किराया कम लगता है, मशीन में तैयार खल के उपयोग करने में भारतीय किसान को क्लिप्त रहती है, न वह जानवरों को खिलाता पसंद करता है और न खाद के रूप में उपयोग करना । पर जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, गत महायुद्ध के समय हमारे तेल-उद्योग ने प्रगति की है । भविष्य में इसे अधिक उन्नत बनाने की आवश्यकता है ।

तेल-उद्योग के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हाथ की बानों के उद्योग को प्रोत्साहन देने से सम्बन्ध रखता है । लाखों परिवार आज इस उद्योग पर निर्भर हैं । उनकी भी स्थिति दूसरे कुटीर उद्योगों में लगे लोगों की तरह अच्छी नहीं है । उनकी स्थिति को सुधारने और शुद्ध तेल की उत्पत्ति को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि इस उद्योग को जीवित रखा जाये और मिल-उद्योग की प्रतिस्पर्धा से इसकी रक्षा की जाये । भारत सरकार और राज्य की सरकारों को इस ओर अधिक व्यवस्थित प्रयत्न करना चाहिये ।

वनस्पती घी का उद्योग—पिछले १५-२० वर्षों में वनस्पती घी का इस देश में बहुत प्रचार हुआ है और वह बड़ा वाद-विवाद का विषय बना हुआ है कि वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिये हानिकर है या नहीं । विशेषज्ञों में मतभेद है और इस उद्योग से लाभ उठाने वाले पूँजीपति इसके पक्ष में खूब प्रचार कर रहे हैं, और वैज्ञानिकों की इसमें सहायता ले रहे हैं । इतना तो वनस्पती के पक्ष के लोग भी स्वीकार करते हैं कि बितना रुपया इसमें आदमी खर्च करता है उसके अनुपात में उसे बहुत कम उपयोग मिलता है । एक बड़ी अजीब दलील यह दी जाती है कि शुद्ध घी तो मिलता नहीं है, इसलिये इस वनस्पती घी का ही उपयोग करना अच्छा है । वास्तव में वनस्पती घी स्वास्थ्य के लिये हानिकर हो या न हो, पर उसमें वे तत्व नहीं मिलते जो घी में मिलते हैं । इसका उत्पादन देश में कानून से बन्द होना चाहिये । शुद्ध घी के लिये वनस्पती घी एक बड़ा खर्चरा साबित हुआ है । वनस्पती घी की अपेक्षा शुद्ध तेल का उपयोग करना

कहीं अल्प है। हमारे देश का मूँट होता हुआ उद्योग जीवित रह सकेगा और यह स्वास्थ्य व लिय लाभदायक होगा।

हमारे देश में इस उद्योग का आरम्भ १९३० में हुआ था। १९४६ में ३८ फ़ैक्टरियाँ बनस्पती घी का उत्पादन करने वाली थीं और लगभग १३ लाख टन बनस्पती घी इस देश में बिक्रा था। भारत सरकार का नीति इस उद्योग के बारे में स्पष्ट नहीं है। यह नीति स्पष्ट होनी चाहिये और इस उद्योग का प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये।

कागज का उद्योग—भारत में कागज दो तरह से बनता है—हाथ से और मिल से। यहाँ हम मिल में बने कागज के उद्योग के सम्बन्ध में विचार करेंगे। हमारे देश में १५ मिलें कागज (लुन्दी से) तैयार करती हैं। इनमें से तान मिला में लुन्दी में मरुत कागज (पल्प बोर्ड) भी तैयार किया जाता है। इनका अन्तर्गत १७ मिलें स्ट्रॉ बोर्ड (स्ट्रॉ से तैयार किया जाने वाला साज कागज) तैयार करती हैं। मोटे रूप से तान प्रकार का कागज होता है—लुन्दी से बना साधारण कागज और मरुत कागज, स्ट्रॉ से बना मरुत कागज, और अखबार का कागज। हमारे कागज व मिल उद्योग की सब प्रकार के कागज की वर्तमान उत्पादन क्षमता १,१५,००० (एक लाख पन्द्रह हजार) टन है। १९४६ में कुल उत्पादन १ लाख १ हजार टन के आस पास था और १९५० का उत्पादन इसमें भी अधिक हुआ है। हमारा आवश्यकता से कुछ कम लुन्दी हमारे देश में पैदा होता है। इसलिये कुछ लुन्दी ग्रास कर रासायनिक लुन्दी, बाहर से मँगाना पड़ती है। पिछले तीन साल के आँकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में प्रति वर्ष १ लाख ७५ हजार टन कागज की ख़ाज है। भारत बाहर से सब तरह का कागज मँगाता है। अखबार का कागज तो सब का गद्य ही विदेश से आता है। १९४६-५० में कुल ६३ हजार टन का लगभग कागज, जिनकी कीमत ५ करोड़ ३६ लाख रुपये थी, बाहर से भारत में आया। बाहर से आयात की गई कागज बनाने के काम में आने वाली चीज़ों की मात्रा १४ हजार टन का लगभग थी और उनकी कीमत ६४ लाख रुपये के आस पास थी। इसी वर्ष में भारत में ५० लाख रुपये में ऊपर का नौ हजार टन कागज, पार वॉन, और कागज व काम में आने वाली चीज़ों का निर्यात भी हुआ। कागज का अधिकांश मिलें पश्चिमी बंगाल में हैं जहाँ कुल उत्पादन का लगभग ५० प्रतिशत कागज तैयार होता है। देश के विमानन का हम उद्योग पर कच्चे मान की दृष्टि से थोड़ा असर पड़ा है। जहाँ तक कागज की मिलों का प्रश्न है सभी मिलें भारत में ही रही हैं। सरस ऑयल मैन्युफ़ैक्चरर्स (१९४६) के हिसाब से २२

हजार आदमी इस उद्योग में काम करते थे और ७ करोड़ रुपये की पूँजी इस उद्योग में लगी हुई थी।

भारत में कागज का मिल उद्योग १८६७ में आरम्भ हुआ। इसी साल हुगली नदी के किनारे वाली मिल स्थापित हुई पर वह मिल असफल रही। बाद में १८८२ में कागज की मशहूर टीटागढ़ मिल स्थापित हुई। इसी समय के आस पास लखनऊ, पटना, रानीगंज, बम्बई आदि स्थानों में भी कुछ मिलें स्थापित हुईं। प्रथम महायुद्ध के समय तक इस उद्योग को विरोध सफलता नहीं मिली थी। विदेशी माल की प्रतिस्पर्धा इसके मार्ग में सब से बड़ी कठिनाई थी। जब प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ तो बाहर से कागज का आना कम हो गया और देश के उद्योग को इससे प्रोत्साहन मिला। १९२५ में जब वेम्बू पेपर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ तो इस उद्योग को विरोध प्रोत्साहन मिला। वॉस की छुन्दी का कागज बनाने के काम में खास तौर से उपयोग होने लगा और बाहर से कागज बनाने के लिये लकड़ी की छुन्दी का आयात बहुत कम हो गया। द्वितीय महायुद्ध के शुरू होते ही बाहर से आने वाला कागज करीब करीब बन्द हो गया। हमारी मिलों ने अपने उत्पादन को बढ़ाया, और अपने देश की आवश्यकता को पूरी करने का उन्होंने प्रयत्न किया। कई प्रकार का नया कागज भी तैयार होने लगा। आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार का कागज तैयार होता है, जिसमें टिश्यू, एपर, मेल, बैक, बोट, लेजर, कार्ट्रिजेज, फ़ैब्रिक और बोर्ड का कागज भी शामिल है। १९४७ के अग्रेज से कागज उद्योग से संरक्षण हटा दिया गया है।

कागज के मिल-उद्योग के भविष्य के बारे कई बातें विचारणीय हैं। सब से पहली बात कच्चे माल की है। इस समय लकड़ी की छुन्दी, घास, बॉस, चिपके, रद्दी कागज, रद्दी बूट, बेगोसी और फूस कागज बनाने के काम में हमारी मिलों में आता है। कुछ समय भारत में पाया जाने वाला 'सबाई घास' कागज बनाने के लिये सब से अधिक काम में आता था। पर अब बॉस ने उसका स्थान ले लिया है। बॉस का बना कागज घास के बने कागज से अच्छा और टिकाऊ होता है। लकड़ी की छुन्दी अभी बाहर से ही आती है। पर भारत में पाइन, स्पूस, और फर की ऐसी लकड़ी है जो इस काम में आ सकती है। रद्दी कागज और बेगोसी का भी अधिकाधिक उपयोग करने का प्रयत्न किया जाना आवश्यक है। कागज की मिलों को पर्याप्त मात्रा में सन्धक और कार्टिक सोदा भी प्राप्त नहीं होता है। इस कठिनाई को दूर करने की भी आवश्यकता है। हमारे कागज उद्योग के सामने एक समस्या अखबार के कागज तैयार करने की है। हमारे देश में

इस समय लगभग ३०-४० हजार टन न्यूज़ प्रिंट प्रति वर्ष खर्च होता है और वह सब का सब बाहर से आता है। न्यूज़ प्रिंट तैयार करने की ओर अब हमारे नज़र में आ ध्यान गया है। मध्य प्रदेश में इस सम्बन्ध में एक योजना तैयार की गई है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। न्यूज़ प्रिंट के ज़िये मित्वर पर और हल्का कच्चे गान्ध का रूप में काम आ सकता है और इतनी दूर में पर्याप्त मात्रा है। परन्तु मनमोहन से भी न्यूज़ प्रिंट तैयार किया जा सकता है, यह फ़ारल रिसर्च इन्स्टीट्यूट दरभंगा में किया गये प्रयोगों से प्रमाणित हो चुका है। हैदराबाद का धिरपुर परन्तु मिला में भी न्यूज़ प्रिंट तैयार करने का निरन्तर लगाया जा रहा है जो १६ हजार टन न्यूज़ प्रिंट प्रति वर्ष तैयार कर सकेगा।

भारत में कागज़ का माँग भविष्य में बढ़ने वाला है। ऐसा अनुमान है कि १९५६ तक २ लाख टन कागज़ का प्रति वर्ष हमें आवश्यकता होने लगेगी। मान्यता मिली है तो यह में उत्पादन शक्ति बढ़ाने का योजना है। इसमें प्रस्तावित है कि १९५२ के अन्त तक भारत में १ लाख ८० हजार टन कागज़ प्रति वर्ष तैयार किया जा सकेगा। कागज़ और न्यूज़ प्रिंट तैयार करने का निरन्तर नद मिला की स्थापना करने का योजना है। दान से एक ने तो काम करना प्रारम्भ कर दिया है, एक इस वर्ष और एक अगले वर्ष में काम शुरू कर सकेगी, और चौथा मिला न्यूज़ प्रिंट ही तैयार करेगी। इस दश में कागज़ का उपयोग की उन्नति के लिये कितना गुज़ारना है, इसका अनुमान हमी से लगाया जा सकता है कि जहाँ भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष १ पाँच कागज़ खर्च होता है, वहाँ अमेरिका में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ३०० पाँच, कनाडा में १८५ पाँच और यूनाइटेड किंगडम में १५० पाँच का खर्च है। जैसे-जैसे देश में शिक्षा का प्रचार होगा कागज़ की माँग भी बढ़ेगी। इसका परिणाम कागज़ का उपयोग के लिये अन्धा आयागा। हमारे देश में कागज़ के उपयोग का भविष्य उज्ज्वल है।

दियासलाह का उद्योग—दियासलाह का उद्योग कुटीर उद्योग और फेक्टरी उद्योग—दोनों ही आधार पर चलता है। कुटीर उद्योग का हिस्सा भी कामना बना है। वहाँ तक दियासलाह का फेक्टरियों का ख़ान है भारत में कुल ३६ फेक्टरियाँ हैं। इन में सब से प्रमुख फेक्टरी 'विमको' है। वह स्वेडिश फर्म के अनुसार जिसमें केवल ६५% उद्योग के आँकड़ों का समावेश है, इस उद्योग में लगभग १२ हजार आदमी काम करते हैं, और २ करोड़ ११ लाख की पूँजी लगाई गई है। इस उद्योग का वर्तमान उत्पादन-क्षमता ७ लाख केस [६० सीटों] का ५० मोस वज़न एक केस में होते हैं। प्रति वर्ष है। पर यह आँकड़े बहुत

विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। इस-देश में 'दियासलाई' तैयार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी 'बिमको' [वेस्टर्न इंडिया मेच कंपनी], जिसकी ५ फेक्टरियाँ हैं, कुल उत्पादन शक्ति के ३ भाग के लिये जिम्मेदार है। यह कंपनी दियासलाई तैयार करने के काम में आने वाली कुछ चीजें, जैसे थोडेशियम क्लोरेट और रूबू का भी उत्पादन करती है। थोडेशियम क्लोरेट का कुछ भाग दियासलाई तैयार करने वाली दूसरी फेक्टरियों को भी इस कंपनी से मिलता है। प्रति वर्ष दियासलाई का उत्पादन ५३ लाख केसेज के घास पास है और देश की आवश्यकता भी ५ लाख केसेज की है। इसका अर्थ यह है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार दियासलाईयां हमारे देश में ही तैयार करली जाती हैं।

हमारे देश में दियासलाई का उद्योग खास तौर से प्रथम महायुद्ध के बाद १९२९ से आरंभ होता है। इस वर्ष दियासलाई पर जो आयात-कर लगता था उसे दुगुना कर दिया गया था और इसी कारण इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला था। यह आयात-कर प्रति ओंस वक्स १ रु० ८ आ० कर दिया गया था। इसके पहले अहमदाबाद की गुजरात इस्लाम मेच फेक्टरी ही देश की एक मात्र सफल दियासलाई तैयार करने वाली फेक्टरी थी। १९३२ में जब दियासलाई पर आयात-कर बढ़ गया तो उससे लाभ उठाने के लिये स्वेडिश फर्मों इस देश में स्थापित की गईं और दियासलाई के उद्योग में आज भी उनकी प्रधानता है। इसके अलावा बाहर से आने वाली स्वेडिश मेचेज की प्रतिस्पर्धा भी हमारे उद्योग के लिये एक बड़ी समस्या के रूप में पैदा हो गई। भारतीय दियासलाई-उद्योग ने संरक्षण की मांग की और १९२८ में संरक्षण स्वीकार किया गया। पर यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि संरक्षण की मांग दियासलाई के उद्योग के उस भाग ने की थी जो भारतीयों के हाथ में था और वह संरक्षण न केवल बाहर से आने वाली दियासलाईयों के खिलाफ चाहते थे बल्कि भारत में ही जो स्वेडिश फेक्टरियां काम कर रही थी उनके विरुद्ध भी संरक्षण चाहा गया था। पर टेरिक बोर्ड के सामने तत्कालीन सरकार ने समस्या के इस पक्ष को उपस्थित नहीं किया था और इसलिये जो संरक्षण मिला उसका लाभ उमान रूप से भारत स्थित सर्व फेक्टरियों को मिला फिर चाहे वे भारतीयों के हाथ में हों अथवा विदेशियों के हाथ में। इसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश कंपनियों की प्रधानता इस उद्योग में बराबर बढ़ती गई। आज स्थिति यह है, जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, कि १९४८ में 'बिमको' की पाँचों फेक्टरियों का उत्पादन १ करोड़ ८० लाख ओंस मेचेज था जब कि बाकी के २०० दियासलाईयों के उत्पादन करने वालों का कुल उत्पादन केवल ८० लाख

प्रोस मनेज़न व लगभग था। इसका मीमांसा का अर्थ यह है कि इस तरह के दिवास्तीखाने-उद्योग पर विदेशियों का प्रभुत्व था।

दियागमना उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। एमी आया है कि आगामी पाँच वर्षों में इस देश का स्वतंत्र मूल्य प्रतिशत वृद्धि (२५००० फीस) हो सकती है। इस उद्योग को भी दूसरे उद्योगों का तरह सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इसका मूल्य बहुत कम है। दियागमना के एक लकड़ी और सामायिक पदार्थों का तोर में वास्तविक और मध्यम की होती कठिनाई अनुभव हो रही है। इसका मूल्य और मजदूरों का वेतन बढ़ना जा रहा है और इस कारण से उत्पादन लागत भी बढ़ना जा रही है। दियागमना की जर्मन सरकार निश्चित करती है और यह शिकायत है कि इस काम में मुनाफ़ का गुंजाइश बहुत कम है। इस उद्योग की दृष्टि से प्याग लकड़ी निर्यात रह इसका समुचित व्यवस्था करना भी जरूरी है। हमारे देश में दियागमना प्रदूषण न जाने-वाहक व जंगलों और बम्बई तथा मद्रास राज्यों के जंगलों का इस उद्योग के लिए उपयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त बातों की ओर आवश्यक ध्यान देने पर हमारे देश का दियागमनाई का उद्योग और भी उन्नत हो सकता है। भारतीय और स्थानीय कंपनियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है उसी को जगती बनाई जा रही है।

काँच का उद्योग—हमारे देश में काँच के सामान बनाने के कारखाने का संख्या १०१ है। इसका अभाव ३३ कारखानों ने विधिले दो वर्षों में उठाकर बढ़ाकर दिया है। पहले १०१ कारखानों का उत्पादन लगभग १ लाख ८१ हजार टन का आस पास है और बाजार ३२ कारखानों की उत्पादन क्षमता १८ हजार टन है—इस प्रकार कुल उत्पादन क्षमता २ लाख ११ हजार टन के लगभग है। इन कारखानों में कई तरह का काँच का सामान तैयार होता है, जैसे—बोतल, गार, लेम्प का सामान, बल्ब, टम्बलर, लेनोरेटर का सामान, आदि। एक अलावा २ कारखाने काँच की चट्टानें (शाट ग्लास) तैयार करते हैं और उनका उत्पादन क्षमता २ करोड़ ३४ लाख वगैरह है। लगभग १०० कारखाने चूड़िया बनाने के हैं जिनमें से अधिकांश कुटीर उद्योग के रूप में काम करते हैं। चूड़ा व कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में फोटोग्राफ है। काँच के फंक्चरी उद्योग व प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और नैनीताल, बर्ही, जबलपुर, अम्बाला आदि हैं। जहाँ तक वास्तविक उत्पादन का सवाल है काँच का विभिन्न प्रकार के सामान का १९५० का उत्पादन ८१ हजार टन था। काँच के चदर का १९५० का उत्पादन लगभग ६५ लाख

वर्ग फीट था। १९४४-४५ में कॉच के चहरों का उत्पादन १ करोड़ ३० लाख वर्ग फीट तक पहुँच गया था। कॉच और कॉच के सामान की देश में कुल खपत १० करोड़ रुपये से ऊपर की होती है जिसमें से ८ करोड़ रुपये का माल हमारे देश में पैदा होता है।

भारत में कॉच का उद्योग बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। आधुनिक ढंग के उद्योग का गत शताब्दी के अन्तिम दस वर्षों में आरम्भ करने के कई प्रयत्न हुए पर उनको सफलता नहीं मिली। स्वदेशी आंदोलन के समय भी कई कॉच के कारखाने स्थापित हुए, पर उनमें से कुछ ही जीवित रह सके। प्रथम महायुद्ध के समय इस उद्योग को वास्तविक प्रोत्साहन मिला। इस उद्योग ने संरक्षण की १९३२ में माँग की थी। पर उसकी यह माँग अस्वीकार कर दी गई। हाँ, सोडा एश पर लगने वाले आयात-कर में अवश्य यह रियायत की गई कि जो सोडा एश कॉच के उद्योग के काम में आएगा उस पर लगा आयात कर वापस कर दिया जायगा। यह रियायत गत वर्ष बढ़ कर दी गई। गत महायुद्ध के समय इस उद्योग को फिर प्रोत्साहन मिला क्योंकि विदेशों से माल आना बन्द या बहुत कम हो गया। गत वर्ष कॉच के चहर के उद्योग को संरक्षण भी दिया गया है।

कॉच के उद्योग के लिये आवश्यक कच्चे माल में कोयला, रेत और चूना पत्थर तो भारत में मिलता है। रिफ़ैक्टरीज भी हमारे देश में तैयार तो होता है पर कॉच के उद्योग की दृष्टि से वह हल्के दवों का होता है। भारी सोडा एश भी बाहर से ही मँगाना पड़ता है और कॉच-उद्योग की भारी सोडा एश पर लगने वाले आयात-कर में चापिप्त रियायत मिलने की माँग है। इस बारे में यह भी विचारणीय है कि कॉच के कारखाने अपने प्लान्ट में ऐसा परिवर्तन कर लें कि जिससे देश में तैयार होने वाला हल्का सोडा एश उनके काम में आ सके। कुछ और रासायनिक पदार्थ भी कॉच उद्योग को विदेशों से मँगाने पड़ते हैं, जैसे बोरेक्स, आरसनिक थ्रोसाइड, सोडियम नाइट्रेट आदि। हमारे देश में तैयार होने वाला कॉच का सामान बढ़िया दवों का हो इसके लिये सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि रेत को ठीक प्रकार से तैयार किया जाये और उसे साफ़ किया जाये। सेन्ड-वाशिंग प्लान्ट्स की हमारे बड़े-बड़े कारखानों में स्थापना होनी चाहिये। जो छोटे कारखाने हैं उनको मिलकर यह व्यवस्था करनी चाहिये। द्राचमकोर में जो रेत होती है वह बढ़िया होती है और उसे साफ़ करने की आवश्यकता नहीं है। सेन्ड्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता में खोज के जो साधन उपलब्ध हैं उनका कच्चे और तैयार माल को वहाँ भेज कर पूरा पूरा लाभ

उत्पाना चाहिये। हमारे कौंच उद्योग के सामने एक सवाल ओटोमेटिक मशीनरी को लगाने का है। इस समय कच्चे ताल कारखानों में ओटोमेटिक मशीनरी है। आत्मोमेटिक मशीनरी का ज्यादा समझ सोच कर लगाने की जरूरत है क्योंकि ऐसा मशीनरी में बहुत पैमाने पर तैयार मान का बाजार हमारे देश में सामिल है। इस मशीनरी में कुछ लाभ भी है जैसे कच्चे ताल में निर्यात होता है।

दश के विभाजन से हमारे कौंच उद्योग की कोई खास हालत नहीं पटुनी। कुछ तो कच्चे ताल पर अंतर पड़ा, जैसे रोवड़ा से बम्बई के कौंच के कारखाने गांधी एश मैगान के और पश्चिमी पंजाब से पोटेसियम नाइट्रेट में हमारे ताल के कारखानों के लिए आता था। पर यह कमो अथ पुरो कर भी गया है। पाकिस्तान में कौंच के सामान के लिये बाजार भी है। इस बाजार पर हम आज किना गिभर रह सकते हैं यह कहना कठिन है। इससे अलावा अब पाकिस्तान अपना कौंच उद्योग निर्यात कर लेगा तब तो हमारा यह बाजार गमात ही हो जायगा। पाकिस्तान में कौंच बनाने का रेल और चीन एश जैसे कच्चे ताल के होने से कौंच के उद्योग का निर्यात होता स्वाभाविक है।

हमारे देश में कौंच का सामान बाहर से भी काफी आता है। लकड़ और मजूर के दश को हमारे देश में कौंच का सामान निर्यात भी होता है। इस समय हमारा निर्यात व्यापार बहुत धाका है। इंग्लैंड जैसे देश की दश इसका एक कारण है।

मीम ट का उद्योग—हमारे देश में सामान तैयार करने के २१ कारखाने हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। एसोसियेटेड मीम ट कम्पनी और इण्डिया सीम ट, सामे ट तैयार करने वाले प्रमुख उत्पादक हैं। मीम ट के उपर्युक्त २१ कारखानों का उत्पादन जमाता २६ लाख टन के आस पास कूनी जाता है और १९६६ में वास्तविक उत्पादन २१ लाख टन हुआ था।

हमारे देश में मीम ट का पहला कारखाना १९०४ में मद्रास में स्थापित हुआ था पर प्रथम महायुद्ध के समय तक इस उद्योग का हमारे देश में विकास नहीं हो सका था। प्रथम महायुद्ध और उसके बाद की तैयारी के कारण इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला। १९२४ के आस पास सामे ट के कारखानों में आपसी प्रतिस्पर्धा आरम्भ हुई। बाहर से आने वाले मीम ट की प्रतिस्पर्धा भी पाई। इस का मुकाबला करने के लिए सरकार से सहाय्य की मांग की गई पर यह नामुमकिन हो गया। आपसी प्रतिस्पर्धा के राकने की दृष्टि से विभिन्न कारखानों ने मिलकर काम करने का प्रयत्न किया और-होल्डिंग के कारखानों

के 'एसोसियेशन' स्थापित किये गये। इन्हीं प्रयत्नों का अन्तिम परिणाम १९३५ में 'एसोसियेटेड सीमेंट कंपनीज़ लिमिटेड' की स्थापना के रूप में आया। उस समय की सीमेंट की सब कंपनियाँ इस एसोसियेशन में मिल गईं। इस से देश का सीमेंट उद्योग सुसंगठित हो गया। बाहर के माल की प्रतिस्पर्धा कम हो गई, सस्ते दाम पर सीमेंट तैयार होने लगा और बिक्री भी बढ़ गई। १९३८ में इस उद्योग के सामने फिर कठिनाई उपस्थित हुई। जालमिया ग्रुप की सीमेंट की कंपनियाँ क्रायम हुई और उन्होंने 'एसोसियेटेड कंपनीज़' के साथ प्रतिस्पर्धा आरम्भ कर दी। १९४० में जालमिया ग्रुप और एसोसियेटेड कंपनीज़ दोनों का माल एक ही केन्द्रीय संगठन के द्वारा बेचने का व्यवस्था हो गया और 'सीमेंट मार्केटिंग कंपनी प्राय लि०' की स्थापना हुई। इसी बीच में दूसरा महाबुद्ध आरम्भ हो चुका था। कच्चे माल की कीमत बढ़ने से सीमेंट की कीमत भी बढ़ी। निर्यात और देश के अन्दर की सीमेंट की मांग भी बढ़ी और बुद्ध के समय में मध्य और सुदूरपूर्व के लिये भारत से सीमेंट जाने लगा। बुद्ध समाप्त होने के बाद सरकार की मांग कम हो गई पर सरकार और जनता की सम्मिलित मांग में काफी वृद्धि हुई है। मार्च १९४८ से जालमिया ग्रुप और एसोसियेटेड कंपनीज़ फिर अलग हो गये हैं और अब वे अपना-अपना माल अलग से बेचते हैं। सीमेंट देश का एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण उद्योग है और उसका भावी विकास देश के लिये जरूरी है।

इस उद्योग के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ हैं। कोयले और जलाने के काम में (पहलू) आने वाले तेल तथा गनी वेग और बाहर से आने वाले कागज के वेग इन तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ी हुई हैं और उनके मिलने में भी कठिनाई होती है। रेल का किराया भी अधिक है और माल को लाने-सेजाने की सुविधा भी पूरी नहीं मिलती। जपान के बारे में भी सवाल तो है, पर वह अनुमान है कि इसकी सीमेंट उद्योग को कमी नहीं रहेगी। जहाँ तक सीमेंट की मांग का सवाल है उसका क्षेत्र काफी है। सार्वजनिक निर्माण के कामों में, नकानों में सीमेंट की मांग बराबर बढ़ने ही वाली है। दूसरे देशों में, खास तौर से एशिया के देशों में भी हमें अपने सीमेंट के लिये बाजार तैयार करना चाहिये। इस बात की भी आवश्यकता है कि सीमेंट के लिये आवश्यक मशीनरी और उसके विभिन्न भाग भी हमारे देश में ही तैयार किये जाय। एक सोज करने वाली संस्था की भी आवश्यकता है। इस बात की बड़ी जरूरत है कि डेरिफ बोर्ड जैसी कोई संस्था सीमेंट-उद्योग के हर पहलू की अच्छी तरह से जांच करे। इस जांच के आधार पर ही उपयुक्त कठिनाइयों का ठीक-ठीक हल निकालना संभव होगा।

सामान्य उद्योग व वित्तिय का जोषा है। यह है। नए का ज्ञान रीति लिए जा रहे हैं और युगनों में विचार का प्रयत्न चल रहा है। इन अनुमानों से कि १९५५ तक देश के सामान्य उद्योग का उत्पादन प्रति ४० लाख टन तक बढ़ाया जा सकेगा। यह ज्ञाता है कि हमारा सीमांत उत्पादन का मात्रा वृद्धि का आधार सराफा और उनिफिकेशन रहेगा और यह कि उद्योगों में नए मशीन-यंत्रों का प्रयोग होगा।

अन्तर्गत मान फरस। धारा १७१—उद्योग में निम्नलिखित धाराओं का समावेश होता है—एल्यूमिनियम, गंधा, एलीमाना, और जिस हमारे देश में नए फरस पाउ उद्योगों का विकास दिनांक महापुद्गल समारंभ का नाम लीजिए। उसमें पहले भारत में जल नवा पैदा किया जाता था। १९०८ में एडिन्बरो कारखाने का निर्माण निम्नलिखित काम शुरू किया था प्रतिवर्ष लगभग ५ हजार टन तारा युद्ध के पहले इस देश में ही होता था इससे अनायास पोतन का बढ़ते और विज्ञान के ताने का भार और बचन का उत्पादन भी होता था। दिनांक महापुद्गल के समय इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसका सही विवरण नीचे दिया जाता है।

गोमो लोभ उद्योग—उद्योग का नाम अर्थशास्त्र है। पहला अर्थशास्त्र में नवान्त स वेस्टाइट नाम का वस्तु (कोयला) पर उस शुद्ध एल्यूमिना में बदला जाता है और एल्यूमिना में एल्यूमिनियम के इन्फाट तैयार किए जाते हैं। दूसरी अवस्था में एल्यूमिनियम इन्फाट को रासायनिक में बदलें, रात आदि वस्तु तैयार का जाता है और फिर इन वस्तुओं से एल्यूमिनियम के घन प्रादि सामान तैयार किया जाता है। इस देश में इस उद्योग का विकास होता हुआ है। सबसे पहले १९१८ में सत्रास में एल्यूमिनियम का कारखाना आदि में एल्यूमिनियम के बच्चे बनाने का काम शुरू हुआ। १९४० के मान में पहली बार हमारे देश में भारत में प्रायः शुद्ध एल्यूमिना में एल्यूमिनियम इन्फाट तैयार किया गया और १९४५ में भारत में एल्यूमिनियम इन्फाट तैयार किया गया। इन वर्षों में भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाला दो कम्पनियाँ हैं—एल्यूमिनियम कम्पनी ऑफ इंडिया (एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और इन्फाट) इन दोनों का संयोजन उत्पादन २५०० टन है। यदि हमारे देश की एल्यूमिनियम का १०० (एल्यूमिनियम) टन है। मध्य प्रदेश में सरकार के प्रयत्न से एक और कम्पनी निर्मित की जा रहा है। एल्यूमिनियम के उद्योग के लिए हमारे देश में बहुत कारखाने हैं। इस देश में विज्ञान का विकास है। विद्युत् शक्ति भी देश में मौजूद है और विज्ञान के क्षेत्र में उसी मांग और बनने वाला है। इत्यादि

एल्यूमिनियम-उद्योग के विनास के लिए भारत में प्रायः सब सुविधाएँ हैं। आज के युग में एल्यूमिनियम का मुख्या तथा औद्योगिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्व है। इसी वजह से सरकार ने इस उद्योग को आगारभूत उद्योग घोषित किया है। भारत के एल्यूमिनियम-उद्योग की एक विशेषता यह है कि जब कि यूरोप और अमेरिका में केवल ५% एल्यूमिनियम वर्नन बनाने के काम में आता है और ६५% दूसरे औद्योगिक उपयोग में आता है, हमारे यहाँ केवल ५% दूसरे औद्योगिक उपयोग में आता है। भारत सरकार ने इस उद्योग को संरक्षित दिया है। पर इस सम्बन्ध में यह आपत्ति उठाई जाती है कि संरक्षण का ध्येय इन्गोट के उत्पादन को प्रोत्साहन देना नहीं है, बल्कि भारतीय-इन्गोट से नैगर माल की विदेशी माल की प्रतिस्पर्धा में रक्षा करना है। १९५० में फिर टेरिफ बोर्ड ने इस उद्योग के बारे में जांच आरम्भ की है। आशा है अब संरक्षण के हम पक्ष पर भी पूरा ध्यान दिया जायगा।

ग्रैन्य नॉन फेरस धातु उद्योग—भारत में ताँबे का वर्तमान उत्पादन ७ हजार टन के आस पास है। और देश की वर्तमान आवश्यकता ५१ हजार टन है। यदि कच्चे ताँबे का उपयोग करने पर ताँबे का उत्पादन बढ़ सकता है।

भारत में सीने का वर्तमान उत्पादन ६०० टन है जब कि हमारी वर्तमान वार्षिक आवश्यकता २५,३०० टन है। उदयपुर की जावर की खान में सीसा और जस्त दोनों ही पाये जाते हैं। सीसा पिघलाने का कारखाना बिहार में कटराम-गढ़ में है और उसकी उत्पादन क्षमता ७ हजार टन प्रतिवर्ष है। यद्यपि उसका वर्तमान उत्पादन जैसा कि ऊपर बताया गया है केवल ६०० टन है। इस उत्पादन में वृद्धि हो सकती है यदि आवश्यक पूँजी की व्यवस्था की जा सके।

भारत में अभी जस्त और टिन का उत्पादन नहीं होता है। हमारे देश में एंसेमोनी का उत्पादन द्वितीय महायुद्ध के समय आरम्भ हुआ। इस समय हमारा वार्षिक उत्पादन ३५० टन है जब कि हमारी वर्तमान माँग ६०० टन की है।

उपर्युक्त विवरण में यह स्पष्ट होता है कि नॉनफेरस धातु उद्योग का अभी हमारे देश में बहुत कम विकास हुआ है। एल्यूमिनियम के अलावा नॉन-फेरस धातु-उद्योग का जो विवरण ऊपर दिया गया है उसका सम्बन्ध शुद्ध धातु के उत्पादन से ही है। पर एल्यूमिनियम की तरह दूसरे धातुओं से भी अहरे आदि तैयार करने का काम हमारे देश में होता है। सन् १९३६ में उन विधा में ही सबसे अधिक प्रगति भी हुई है। बम्बई में ताँबे और पतली की कई तैयार करने वाले कई रॉलिंग प्लांट स्थापित किये गये हैं।

इसी प्रकार सीधे की चदरें भी कलकत्ते के आखपाय तैयार की जाती हैं। शींवे पीतल आदि के खूब, राउ और बार भी हमारे देश में तैयार होन लग हैं। संवे के पादप तथा चिनला के तार भी तैयार किये जाते हैं। विभिन्न प्रकार के अलौह धातुओं के एलरोन भी भारत में तैयार किये जाते लग हैं। जो रक्षा [स्टेप] धातु होता है उस दुबारा मुगारों का काम भी अब हमारे देश में होने लगा है। सरकार ने सन १९४८ में अलौह धातु में तैयार हान जाने उपर्युक्त वस्तुओं का संरक्षण देना स्वीकार कर लिया है।

नहान निर्माण उद्योग — जहाज बनाने का उद्योग देश में आधारभूत उद्योगों में है। देश में व्यापार और सुरक्षा दोनों ही की दृष्टि में इस उद्योग का बड़ा महत्व है। भारत में प्राचीनकाल में जहाज बनाने का उद्योग मौजूद था। पर इस्लाम के युग में आरम्भ के साथ इस उद्योग का पतन आरम्भ हुआ और आखिरकार इस उद्योग का अन्त हो गया।

आधुनिक ढंग में जहाज बनाने के नियम जहाज निर्माण रूढ़ की स्थापना मिथिया स्लाम नवागणन कम्पनी ने १९४१ में निगमापन में का। जहाज निर्माण रूढ़ के निर्माण का कार्य युद्ध के कारण कुछ सज्जी से नहीं चल सका। आखिरकार १९४७ में कम्पनी ने दो बथ ८००० से १०००० टन की निर्माणशक्ति की तैयार करली। इस याद में बना पहला जहाज जल ग्या था जिसका पं० नवाहरलाल नेहरू द्वारा मार्च १९४८ में पल प्रदग किया गया। अगला तब मिथिया कम्पनी के नियम ८००० टन के सामान ले जाने जाने वाला जहाज और एक घातिवा का ले जाने वाला छोटा जहाज निगमापन याद में तैयार किये जा चुके हैं। जहाजों की संख्या भी बढ़ गई है। यहाँ के पहले जहाज अग्रे स अग्रे चलेंगे और जहाजों में माने गये हैं। अब जहाज सरकार के लिए भी बनाया जा चुका है। निगमापन याद में आठ बथ का पुजाइय है क्योंकि इस समय तक केवल दो बथ तैयार की गई हैं। १५००० टन तक के जहाज यहाँ तैयार किये जा सकते हैं। इस उद्योग में अथनक लगभग ४ करोड़ रुपया मिथिया कम्पनी का लग जुका है। इस जहाज निर्माण रूढ़ के भावी विकास के लिए युवा की सबसे बड़ा आवश्यकता है। इस बात की भी ज़रूरत है कि जहाज बनाने का काम बराबर मिलता रहे। मिथिया कम्पनी अब अधिक रुपया लगाती है स्थिति में नहीं है। सरकार का विचार इस याद की सुरक्षा के साथ पर आर्थिक गठिनाई के कारण यह सम्भव नहीं हो सका है। इस याद में जहाजों के तैयार करने के लिए ८१० करोड़ रुपया की आवश्यकता और बनाई जाती है। जो जहाज इस याद में बनते हैं वे विदेशी जहाजों का

अनेक अधिक व्यर्थसे होते हैं। हमलिये सरकार से यह मांग की गई है कि वह हम उद्योग को आवश्यक सहायता दे ताकि जहाज के निर्माण में जो अधिक व्यय होने पर सरकार उठा ले। इस मांग के सामने मन्त्रालय यह समस्या है कि वह उद्योग किससे लिये बनाये। इन समय भारत-सरकार के लिये वह तीन जहाज बना रहा है। यह काम शीघ्र ही समाप्त होने का आशा है। उनके बाद उनके पास कोई काम नहीं है। आवश्यकता हम वान की है कि सरकार कुछ जहाज बनवाने का और आदेश दे और हम उद्योग को पूरी आर्थिक सहायता देकर हमकी रक्षा करें।

सागर की दक्षेष्ट प्रगति हुई। समुद्र तटीय व्यापार की भी इस समय अच्छी प्रगति हुई। भारत के पास अच्छा व्यापारिक समुद्रीय वेड़ा था जिसमें विदेशों से भी व्यापार होता था।

भारत का यह विदेशी व्यापार स्थल और जल-मार्ग से मध्य सागर के किनारे तक होता था और वहाँ से वेनिस और जेनेवा के व्यापारी भारतीय माल को यूरोप के बाजारों में बेचते थे। इस व्यापार के कारण वेनिस और जेनेवा के व्यापारी माला-माला हो गये थे। इससे हमारे देश के रहने वालों के मन में भी लालच पैदा हुआ और भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने की दृष्टि से नए मार्ग की खोज में वे लग गये। इनकी का नतीजा था कि पुर्तगाल के निवासियों ने केव आब होप गुड लेकर भारत पहुँचने का समुद्री मार्ग ढूँढ निकाला। इस मार्ग के मालूम होते ही विभिन्न यूरोप के देशों के रहने वाले भारत से व्यापार करने में एक दूसरे से होड़ करने लगे। पुर्तगाल, इंग्लैंड, होलेण्ड और फ्रान्स के निवासियों में जो प्रतिद्वन्द्विता हुई वह सुविख्यात है। इन संघर्ष में आखिरकार इंग्लैंड की विजय हुई। और भारत तथा पूर्व के दूसरे देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया। अब भारत से भारी माल में भी व्यापार होने लगा था।

ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति आरंभ में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिये भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नहीं। पर बाद में इंग्लैंड के औद्योगिक विकास के फल स्वरूप वहाँ के पूँजीपतियों के दबाव से भारत के उद्योग-पंथों को नष्ट किया गया, और भारत से यूरोप को कच्चा माल जाने लगा और पैयार माल वहाँ से आने लगा।

स्वेज नहर का निर्माण—१८६६ में स्वेज नहर का मार्ग खुल जाने से भारत के विदेशी व्यापार में एक नये युग का प्रारंभ हुआ। भारत और यूरोप के बीच का फासला अब लगभग ४५०० मील के कम हो गया और इस कारण से माल के लाने-लेवाने में कम समय लगने लगा। इसी समय कुछ और कारण भी ऐसे उपस्थित हो गये थे जिनसे हमारे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। जैसे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो जाने से राजनैतिक अशांति का अब अन्त हो गया, चातुर्व्याप्त के साधनों का विकास होने लगा, बम्बई और सुएज के बीच में समुद्री तार से संबंध स्थापित हो गया और जहाज़-निर्माण के उद्योग में बड़ी प्रगति होने से व्यापारिक जहाज़ी बेलों का भी इसी समय विकास हुआ। अब कम कीमत की भारी बोलें भारत से विदेश जाने लगी। भारत अन्न और कारखानों के लिये कच्चा माल निर्यात करने वाला और विदेशों से कारखानों

म तैयार माल—जैसे कपड़ा, मर्चीनरी, चाय, धुरी आदि, रेलवे का सामान आर कान का सामान भेजने वाला देश हो गया। भारत का विदेशी व्यापार इंग्लैंड और बाद में जर्मनी, अमेरिका और जापान से खास तौर से होने लगा। यद्यपि वहाँ के लिये भारत से व्यापार करने की सब देशों की स्वतंत्रता थी पर वास्तव में इंग्लैंड का भारत के विदेशी व्यापार पर प्रभुत्व था। १९ वीं शताब्दी के अन्त तक इंग्लैंड की यह प्रभुत्व बनी रही।

भारतीय व्यापार के लिये प्रतिस्पर्द्धा—उन्नीसवीं शताब्दी की अन्तिम दशक में इंग्लैंड का जर्मनी और फिर जापान की प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ा। इन देशों का सरकारों का अपने व्यापारियों को भारत से व्यापार बढ़ाने का काम में पूरा पूरा सहयोग और समर्थन था। इन देशों ने अपने अपने जहाजों का विमान विमान, भारत में इन्होंने अपने देशों का शास्त्राचार्य खोली, और भारत के प्रमुख नगरों में व्यापारिक गृहों की इन्होंने स्थापना की। अमेरिका से शुरू शुरू में भारत के साथ सीधा व्यापारिक संबंध स्थापन नहीं किया और लन्दन के द्वारा यह भारत से व्यापार करता रहा। पर प्रथम महायुद्ध के बाद अमेरिका ने भी भारत के साथ सीधा व्यापार करना शुरू किया।

प्रथम महायुद्ध आरम्भ होने के समय तक भारत के विदेशी व्यापार में काफी वृद्धि हो चुका था। १९१४ के पहले पांच वर्षों का औसत वार्षिक निर्यात २२४ २३ करोड़ रुपये का और आयात १५० ६७ रुपये का था। इसका तुलना में १८९६ में १६०६ तक का औसत निर्यात १२४ ६८ करोड़ रुपये का और आयात ८४ ६८ करोड़ रुपये का ही था। प्रथम महायुद्ध के समय में दुर्घटना के विदेशी व्यापार में कमी आना स्वाभाविक था। शत्रु राष्ट्रों के साथ व्यापार बंद हो गया। माल लाने-ले जाने के लिये जहाजों का कमी से मिन राष्ट्रों के साथ के व्यापार में भी कमी आ गई थी क्योंकि इन बात का सम्भावना रहता थी कि कहीं उनका द्वारा शत्रु राष्ट्रों के पास हमारा माल न पहुँच जाय। जहाजों के क्रियाय में वृद्धि होने में भी विदेशी व्यापार पर प्रतिफल अमर पड़ा। युद्ध के आखिर में आगे भी मित्र राष्ट्रों में युद्ध सामग्री के लिये भारत के माल की मांग बढ़ी और इससे भारत के निर्यात में वृद्धि हुई। भारत के आयात व्यापार में जापान और अमेरिका ने इन समय अगला अगला स्थान जमा लिया। जर्मनी में व्यापार बंद था। मित्र राष्ट्रों में युद्ध सामग्री तैयार करने में लगा हुआ था। भारत स्वयं भी कुछ वृद्धि में निर्यात हुआ राष्ट्र था। इसलिये जापान और अमेरिका के लिये यह एक अवसर भीका आ गया और उन्होंने इसका लाभ भा उठाया।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्—प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने के समय में दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होने तक भारत के विदेशी व्यापार में कई प्रकार के उतार-चढ़ाव आये। युद्ध के दुरन्त बाद भारत के निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई, क्योंकि युद्ध कालीन प्रतिवन्ध हट गये। किराया कम हो गया और युद्ध के समय में जिन राष्ट्रों से व्यापार बन्द हो गया था वह फिर से चालू हो गया। पर यह स्थिति शीघ्र ही समाप्त हो गई। देश का निर्यात व्यापार कई कारणों से घटने लगा। यूरोपीय देश क्षय शक्ति के अभाव में भारतीय माल विशेष गाना में नहीं खरीद सकते थे। ब्रिटेन, अमेरिका और जापान में भी पहले ही से इतना भारतीय माल खरीद लिया गया था कि अब उनके पास भी माल खरीदने की अधिक गुंजाइश नहीं थी। भारत में लगातार [१९१८-२१] वर्षों की कमी होने से अनाज की कमी हो गई थी और अनाज के भाव बढ़ गये थे। इसलिये अनाज का निर्यात रोकना पड़ा था। जापान भी आर्थिक संकट में पड़ जाने के कारण अधिक माल नहीं मंगा सकता था। भारतीय रुपये के विदेशी मूल्य को बढ़ा देने से भी निर्यात पर बुरा असर पड़ा था। इधर आयात में वृद्धि होने लगी। युद्ध के कारण जो आयात रुका हुआ था वह अब होने लगा। रुपये का विदेशी विनिमय बढ़ जाने से भी आयात को प्रोत्साहन मिला। नतीजा यह हुआ कि व्यापार संकुचन भारत के प्रतिकूल हो गया। १९२०-२१ में भारत का निर्यात से आयात ७९८ करोड़ रुपये का अधिक था। पर धीरे-धीरे यह स्थिति बदली और निर्यात-आयात अपनी सामान्य स्थिति में पहुँच गये। यूरोपीय मुद्राओं में अब स्थिरता आ गई थी और यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया था। १९२९ तक स्थिति संतोषजनक रही।

पर १९२९ में विश्व-व्यापी मंदी आरम्भ हो गई। विभिन्न देशों ने अपनी-अपनी आर्थिक सुरक्षा करने की दृष्टि से विदेशी व्यापार पर अनेकों प्रकार के प्रतिवन्ध लगाना शुरू कर दिये। दुनिया के विदेशी व्यापार की मात्रा घटने लगी। भारत कृषि प्रधान देश था और कृषि पदार्थों का मूल्य अधिक गिरा था, इसलिये भारत के विदेशी व्यापार को खास तौर से अधिक हानि हुई। निर्यात की मात्रा बहुत कम हो गई जहाँ तक कि १९३२-३३ में केवल १३६ करोड़ रुपये का माल भारत से निर्यात हुआ। आयात में भी कमी आई, पर निर्यात के मुकाबले में कम। विश्व-मंदी का असर १९३२ तक रहा। १९३३ से स्थिति में सुधार आने लगा और १९३६ तक स्थिति सामान्य अवस्था में पहुँच गई। पर आयात पर प्रतिवन्ध लगे रहे और इसलिये भारत के विदेशी व्यापार में

के देशों में सबसे अधिक माल हमारे देश से इंग्लैंड को जाता था। आयात की स्थिति इससे भिन्न रही। कामनवेल्थ के देशों का हिस्सा १९२०-२५ में ६५.४% था, वह १९३५-४० में ५३.८% रह गया और दूसरे देशों का हिस्सा इन वर्षों में ३४.६% से घटकर ४६.२% हो गया। १९३१-३२ में तो कामनवेल्थ के देशों का हिस्सा ही रह गया था। दूसरे देशों में जापान, जर्मनी और अमेरिका के हिस्सों में बराबर वृद्धि हुई। यद्यपि इम्पीरियल प्रीफरेंस के कारण कामनवेल्थ के देशों के आपसी व्यापार प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक था, पर हमारे आयात सम्बन्धी बढ़ती हुई आवश्यकताएँ ऐसी थीं जिनकी पूर्ति इंग्लैंड अपेक्षाकृत कम कर सकता था। अब हमारी कच्चे माल और उत्पादन वस्तुओं की माँग बढ़ती जा रही थी। इंग्लैंड भारत को पहले की अपेक्षा अब कम मात्रा में सूती भेजने लगा था और द्विपक्षीय व्यापार का प्रचार हो रहा था, इसका असर भी यही हुआ कि हमारे आयात व्यापार में कामनवेल्थ के देशों का भाग कम होने लगा।

भारत के विदेशी व्यापार का जो विवरण ऊपर दिया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ तक हमारे विदेशी व्यापार के चही लक्षण ये जो कृषि-प्रधान और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश के विदेशी व्यापार के होते हैं। हमारे निर्यात व्यापार में कुछ चीजों की प्रधानता थी जैसे कपास, जूट का तैयार माल, अनाज दाल और घाटा, कच्चा जूट, कच्चा चमड़ा और तैयार चमड़ा, चाय, बीज, धातु और कच्चा धातु और रूखी कपड़ा। आयात में मशीनरी और उपभोग में आने वाली चीजों की प्रधानता थी। हमारा निर्यात व्यापार मुख्यतः कुछ देशों तक ही सीमित था। व्यापार की शक्ति में हमें विदेशों को बहुत रुपया हर साल चुकाना पड़ता था। प्रति व्यक्ति विदेशी व्यापार की मात्रा बहुत थोड़ी थी और दुनिया के निर्यात व्यापार में जो हमारा हिस्सा १९२८ में ३.७% था वह १९३८ में २.६% ही रह गया था। साधारणतया व्यापार का संतुलन हमारे पक्ष में ही रहता था यद्यपि इसकी मात्रा बराबर कम होती जा रही थी। १९२०-२१ से १९२४-२५ में हमारा निर्यात ३०० करोड़ रुपये के और आयात २६१ करोड़ रुपये के लगभग था। पर १९३५-३६ से १९३९-४० में निर्यात केवल १८० करोड़ रुपये के और आयात १५० करोड़ रुपये के लगभग ही रह गया। विश्वव्यापी मंदी के कारण जब हमारे माल का निर्यात कम होने लगा तो उसकी पूर्ति हमने रोमा निर्यात करके की। सन् १९३१ से द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने तक हमारे यहाँ से सोना बाहर जाता रहा। इन वर्षों में भारत से ३६२ करोड़ रुपये का सोना बाहर गया।

द्वितीय महायुद्ध और उसके पचास — १९३६ में जब द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ तो उसका हाना फायदा विदेशी व्यापार पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध के कारण कामें बटने लगी और भारत के रूस, माल का विदेशों में माँग भी बढ़ने लगी, हालाँकि इसी व माय शत्रु राष्ट्रों के साथ हमारा व्यापार बन्द हो गया और निर्यात और आयात पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। १९३० के दशकों में जहाँ युद्ध होना रहने के कारण हमारे माल का विदेशों में माँग हो गया जैसे माल, हार्नेड, इनमाक, पेलिट्रियम, प्रॉम, और चर्मा, हिन्दुस्तान मचाया तथा सुदूर पूर्व के देशों पर मध्य पूर्व के देशों से हमारा व्यापार बढ़ मा गया और मित्र राष्ट्रों में भी हमारा माल की माँग बढ़ गई जैसा कि ऊपर उल्लेख किया है। माल लाने-लेजाने के नियम जहाजों की कटौती, बड़ा हुआ जहाजों का किराया और बड़े स्ट्रक्चर और मालवाहक जहाजों के कारण माँ विदेशी व्यापार के माँग में कठिनाई उत्पन्न हुई। लड़ाई के समय में इंग्लैंड और अमेरिका लड़ाई का सामान तैयार करने में लगे हुए थे। इसलिए भारत को इन देशों में तैयार माल माँगने में भी कठिनाई होने लगी। इन तमाम परिस्थितियों का नतीजा विदेशी व्यापार का माँग कम करने का हुआ। किन्तु जहाँ तक कि मूल्य का सवाल है, चार्ज का कामें बन्द जाने से आयात और निर्यात दोनों ही में युद्ध के पहले क्या का अपना युद्ध काल में वृद्धि हो गई। यह वृद्धि आयात में कम हुई थी और निर्यात में अधिक हुई थी। वेनल माल का ही हम विचार करें तो युद्ध के समय में हमारे निर्यात का अंक से अधिक मूल्य १९४५ में २६६ करोड़ रुपये तक पहुँच गया था और कम से कम १९४० में १९५ करोड़ रुपये तक रह गया था। आयात के अंक बतलाने हैं कि १९४० में ११६ करोड़ रुपये का माल हमारे देश में और १९४५ में अधिक से अधिक अर्थात् २६२ करोड़ रुपये का माल बाहर से आया। इससे युद्ध काल में विदेशी व्यापार के बारे में एक तो यह बात सिद्ध होती है कि आयात और निर्यात पर सरकारों नियंत्रण की कड़ाई अथवा हिलाई का माँग अक्षर पड़ता था। जब नियंत्रण कम होता था तो विदेशी व्यापार की माँग बढ़ जाता था, अगर नियंत्रण अधिक हो जाता था तो माँग कम हो जाती थी। दूसरी बात यह है कि विदेशी व्यापार का समुलन १९४३ तक बराबर हमारे पक्ष में बढ़ता गया। १९४० में आयात में निर्यात लगभग ५४ करोड़ रुपये का अधिक था। १९४० में १९४३ में व्यापारिक समुलन ८८ करोड़ रुपये तक हमारे पक्ष में पहुँच गया था। इसी वजह से स्ट्रालिंग पावना हमारे पास बहुत जमा हो गया। हमारे पास स्ट्रालिंग पावना जमा होने के दो कारण और भी थे। मित्र राष्ट्रों का फौजें भारत में जो माल सौदागरी थीं उसके बदले में हमें

स्टरलिंग पावना मिलता था। ईंग्लैंड की सरकार से भारत को युद्ध का जो खर्च वापस मिला वह भी स्टरलिंग पावने की शकल में ही मिला। इस स्टरलिंग पावने का उपयोग श्रेष्ठ में विदेशियों ने जो पूंजी लगा रखी थी उसे चुकाने में भी किया गया। इस प्रकार ३२ करोड़ पौंड की विदेशी पूंजी ४२५ करोड़ रुपये खर्च करके वापस की गई। युद्धकाल में जिन चीजों में विदेशी व्यापार होता था उनमें भी अन्तर आया। हमारे देश का तैयार कपड़ा काफी मात्रा में विदेशों को खास तौर से मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों को भेजा जाने लगा। युद्ध के पहले केवल ६ करोड़ रुपये का कपड़ा बाहर जाता था। १९४२-४३ में ४६ करोड़ रुपये का कपड़ा बाहर भेजा गया। चाय का निर्यात भी बढ़ा। इसके मुकाबले में मृगफली का निर्यात घटा क्योंकि अब हमारे देश में ही तेल उद्योग का विकास होने लगा था। सरांश यह है कि युद्धकाल में भारत ने तैयार माल बाहर अधिक जाने लगा और आयात में कच्चे माल का अनुपात बढ़ा और तैयार माल का अनुपात घटा। यह देश की औद्योगिक प्रगति का लक्षण था, हालांकि युद्ध-काल भारत ने औद्योगिक दृष्टि में उतनी प्रगति नहीं की थी जितनी कि करना चाहिये थी और दूसरे देशों ने की थी। १९३५-४० के निर्यात के पांच वर्षों औसत के आंकड़ों के अनुसार काय-बैप पदार्थ और तम्बाकू कुल निर्यात का २१.८%, कच्चा माल ४६.०% और तैयार माल ३०% था। वही आंकड़े १९४०-४५ में क्रमशः २३.८%, २५.४% और ४६.३% हो गये। अर्थात् तैयार माल का निर्यात बढ़ा और कच्चे माल का निर्यात घटा। कपास और पटखन का तैयार माल बाहर अधिक जाने लगा और तिलहन, कच्चा कपास और गूट का निर्यात कम हो गया। आयात के आंकड़ों से मालूम पड़ता है कि उस समय के ब्रिटिश भारत में समुद्री मार्ग द्वारा १९४०-४२ में ४२ करोड़ रुपये का कच्चा माल बाहर से आया।

जहाँ तक विदेशी व्यापार की दिशा का प्रश्न है युद्ध काल में ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के साथ इसका निर्यात व्यापार बढ़ा। आस्ट्रेलिया, कनाडा मिला, इराक और दूसरे मध्यपूर्व के देशों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध पहले से अधिक हो गया। १९३६-४० में समाप्त होने वाले पांच वर्षों में कामनवेल्थ के राज्यों और दूसरे देशों का हमारे निर्यात व्यापार में लगभग बराबर का हिस्सा था। पर १९४०-४५ के पांच वर्षों में कामनवेल्थ के देशों का हिस्सा ६४% से कुछ अधिक हो गया और दूसरे देशों का हिस्सा ३६% से भी कम रह गया। जहाँ तक आयात का मुद्दा है कामनवेल्थ के राज्यों का हिस्सा १९३५-४० में ५३.८% से १९४०-४५ में ५१.५% हो गया और दूसरे देशों का हिस्सा

प्रतिबन्ध लग गया। १९४६ के मई महीने तक हनारी स्थिति और भी बिगड़ गई। विदेशी व्यापार संबंधी इस बिगड़ती हुई स्थिति को और भारन सरकार का ध्यान गया। उसने १९४६ में आयात के बारे में जो जुलाई १९४८ में उद्घार नीति स्वीकार की थी उसे रद्द करके अब कड़ी नीति बनाने का निर्णय किया। मई १९४६ में ४०० चीनों के ओपन जनरल लाइसेंस की बजाय थोड़ी चीनों का ओपन जनरल लाइसेंस की श्रेणी में मंजूर किया गया। जन-६४६ में तुर्कम मुद्रा प्रदेश से आयात की स्वीकृति देना स्थगित कर दिया गया। जुलाई १९४६ में लन्दन में कामनवेल्थ के वित्तमन्त्रियों का सम्मेलन हुआ। उसमें तुर्कम मुद्रा प्रदेशों ने १९४८ के मुद्रावले में २५ प्रतिशत आयात में कमी करने का निश्चय किया गया और भारत ने भी इस निश्चय को मंजूर किया। भारत-इंग्लैंड के बीच के आर्थिक समझौते (फाइनेयियल एग्रीमेंट) पर जब अगस्त १९४६ में विचार किया गया तब फिर आयात पर और अधिक नियंत्रण लगाने का निश्चय किया गया। एक तरफ तो आयात को कम करने के ये प्रयत्न किये गये, दूसरी ओर निर्यात को बढ़ाने का भी सरकार ने प्रयत्न किया। १९४६ की जुलाई में 'एक्सपोर्ट प्रोमोशन कमेटी' की निजुफि की गई जिसने देश के निर्यात बढ़ाने संबंधी कई सिफारिशें कीं। जो कर निर्यात को रोकने वाले थे उनको हटाने, निर्यात के माल सम्बन्धी अत्यधिक स्ट्रे पर नियंत्रण करने, और निर्यात होने वाले माल का देश में उत्पादन बढ़ाने की इस कमेटी ने सिफारिश की। सरकार ने कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कार्य करने का प्रयत्न भी किया। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप आयात पर रोक लग गई और निर्यात में थोड़ा सुधार हुआ। जैसा कि हमें मालूम है मिनम्बर १९४६ में रुपये का अचानक गिरावट हो गया। उसके परिणामस्वरूप आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। पर इस सबके बावजूद भी १९४६ ने विदेशी व्यापार का मूलतः हमारे विपक्ष में ही रखा। पर इसके बावद स्थिति में सुधार आने लगा और १९४० में कई वर्षों के बाद पहली बार विदेशी व्यापार का मूलतः हमारे पक्ष में रहा। आज भी यह प्रवृत्ति जारी है। इस मुब्तगी हुई स्थिति के मुख्य कारण रुपये का अमूल्यन, निर्यात के प्रति प्रोत्साहन की नीति और निर्यात की वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमत, और कोरिया के युद्ध के कारण उत्पन्न हमारे माल की दुर्लभता की तैयारी की दृष्टि में बढ़ती हुई मांग है। युद्ध के बाद हमारे विदेशी व्यापार के मूलतः को जो स्थिति रही है उसका अनुमान भांग के 'ग्रेड्स' व्यापार सम्बन्धी नीति भी गारिहा ने अच्छी तरह लगाया जा सकता है :—

[करोड़ रुपये में]

वर्ष	आयात	निर्यात	कुल	व्यापार का संतुलन
१९४६	२२६ ३८	३०५ ७१	६३२ ०९	— १० ६३
१९४७	४१२ ३०	४२६ ७८	८३९ १०	— १५ ४४
१९४७-४८				
[अप्रैल मार्च]	४४५ ८१	१०८ २६	५५४ ०५	— ३३५ ८८
१९४८-४९	५४४ ९१	४२३ ३१	९६८ २३	— ११९ ५९
१९४९-५०	५८० ५१	४८५ १०	१०६५ ७१	— ७५ २१
१९५०-५१	५८५ ४६	५८६ ८८	११७२ ३४	+ ११ ४८

१९४६ और १९४७ के आंकड़े को ना फाइनेस का १९४७-४८ की रिपोर्ट के स्टेटमेंट नं० ३ में, १९४७-४८ के १९४८-४९ की रिपोर्ट के स्टेटमेंट नं० ३ में और नाप आंकड़ समाप्त है नून पृष्ठ १८८ पर से मिल गये हैं।

उक्त तालिका से यह भी साफ हो जाता है कि युद्ध के बाद हमारे विदेशी व्यापार का मूल्य बराबर बढ़ा है। १९४६ में कुल आयात और निर्यात ६३२ करोड़ रुपये का था यह १९५०-५१ में ११७२ करोड़ रुपये के पास पहुँच गया। इससे साफ यह भी है कि आयात का अक्षय निर्यात में वृद्धि ज्यादा हुई है।

विदेशी व्यापार के बारे में दूसरा जानने योग्य बात यह है कि हमारे निर्यात व्यापार में निरंतर मान का स्थान बढ़ता जा रहा है। और आयात व्यापार में अन्न और कच्चे माल का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। देखें कि निम्नलिखित में इस प्रवृत्ति का प्रोत्साहन मिला है। ध्यान भारत को कपास तथा जूट विदेशों से, खास कर पाकिस्तान से मँगाना पड़ता है। इसकी पुष्टि इस बात से होगी है कि आयात में कच्चा माल का हिस्सा १९४८-४९ में २३.६%, १९४९-५० में २५.७% और १९५०-५१ में २६.७% रहा है। अन्न निर्यात में १९४८-४९ में औसत मूल्य २.०६ करोड़ का था यह १९४९-५० में २४९.६ करोड़ और १९५०-५१ में ३०७.५५ करोड़ रुपये का हो गया। कुल असल निर्यात के अनुपात का अगर हम लें तो अनुपात १९४८-४९ में ५५%, १९४९-५० में ५७% और १९५०-५१ में ५६% आया है। (कॉमम ७ जुलाई १९५१ से)

हमारे विदेशी व्यापार में युद्ध के बाद वहाँ जहाँ तक आयात का सम्बन्ध है कामनवेल्थ राष्ट्रों का आर दगवैड का भी अनुपातिक भाग कम हुआ है। कामनवेल्थ के बाहर के देशों से व्यापार की दृष्टि से अमेरिका का महत्त्व बढ़ा है। इसी प्रकार निर्यात के सम्बन्ध में भी कामनवेल्थ का महत्त्व घट रहा है। परन्तु हम पाकिस्तान के साथ स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार का भी विचार करें

तो कामनवेल्थ की स्थिति में थोड़ा सुधार हो जाता है। १९३८ में ब्रिटिश कामनवेल्थ से हम अपने कुल आयात का ५७.३% और केवल इंग्लैंड से ३१.७% माल मँगाने थे। १९४५ में ब्रिटिश कामनवेल्थ का भाग ३७.९% और केवल इंग्लैंड का २१.२% था। १९४६ में ब्रिटिश कामनवेल्थ का भाग ५६.९% और इंग्लैंड का ३८.४% हो गया। उसके बाद १९४७ में ब्रिटिश कामनवेल्थ का भाग ४६.१% और केवल इंग्लैंड का ३०% रह गया। १९४८-४९ में यूनाइटेड किंगडम से १५२.९६ करोड़, १९४९-५० में १४९.४१ करोड़ और १९५०-५१ में १०५.७४ करोड़ रुपये का माल भारत में आया। दूसरे देशों में अमेरिका का हिस्सा १९३८ में ७.४% था वह १९४५ में बढ़कर २९.९%, १९४६ में १७.७% और १९४७ में २८.८% हो गया। १९४८-४९ में १०८.७१ करोड़, १९४९-५० में ८७.९१ करोड़ और १९५०-५१ में ११५.८१ करोड़ रुपये का माल अमेरिका से भारत में आया। इसी प्रकार निर्यात व्यापार में ब्रिटिश कामनवेल्थ का हिस्सा १९३८ में ५२.७%, १९४५ में ५९.७%, १९४६ में ५०.८% और १९४७ में ५१.३% था और इंग्लैंड का हिस्सा क्रमशः २४.१%, २२.३%, २५.२% और २७.५% था। देश के निर्यात व्यापार में अमेरिका का हिस्सा १९३८ में ८.३%, १९४५ में २३.२%, १९४६ में २५.२% और १९४७ में १९.२% था [करेंसी-फाइनैस रिपोर्ट १९४७-४८ टैबल १४]। यदि करेंसी प्रदेशों के आबाद पर सकलित आंकड़ों को लें तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अलावा स्टारलिंग प्रदेश का हिस्सा हमारे आयात में १९३८-३९ में ५८% था वह १९४७-४८ में ४२% और १९४८-४९ में ४४% था। इसी प्रकार निर्यात में १९३८-३९ में ५३%, १९४७-४८ में ४८% और १९४८-४९ में ४२% था [करेंसी और फाइनैस रिपोर्ट १९४८-४९ टैबल १८]। १९४९-५० के व्यापार के संतुलन संबंधी आँकड़ों को जिनमें पाकिस्तान के आंकड़े भी शामिल हैं, देखने से मालूम होता है कि स्टारलिंग प्रदेश का हमारे कुल आयात में ५३.९% भाग था। जहाँ तक निर्यात का सम्बन्ध है १९४९-५० में कुल निर्यात का ५०% भाग स्टारलिंग प्रदेश का था। [स्टैटमेंट ६४ करेंसी-फाइनैस रिपोर्ट १९४९-५० में दिये आँकड़ों पर से तैयार आंकड़े]

विदेशी व्यापार की आज की स्थिति:—भारत के विदेशी व्यापार का जो ऐतिहासिक विवेचन ऊपर किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि देश की आर्थिक स्थिति में जैते-जैते परिवर्तन आया उसका प्रभाव हमारे विदेशी व्यापार पर भी पड़ा। जब देश में औद्योगीकरण की ओर कदम बढ़ने लगा तो हमारे निर्यात

म नैवार माल का आर आयात में बन्दे माल का महत्व बढ़ गया। यह कठिन जा — कारण हम स्वयं पटना और अन्य के निर्यात करने वाले न रहकर प्राप्त करने वाले बन गए। दश के औद्योगिकरण और विनाय महापुद्गल के समस्त परिस्थितियों का यह ज्ञान आया कि हमारे देश के नैवार माल का महत्व अधिक बढ़ने लगा और अपने निर्यात के लिए, केवल कुछ देशों पर हम पहले की तरह में निर्भर रहे। कामनवेल्थ के अलावा दूसरे देशों में हमारा व्यापार बढ़ने लगा। आन कामनवेल्थ और दूसरे देशों का महत्व बराबर सा हो गया है जबकि पहले कामनवेल्थ के देशों की प्रधानता थी। हमारे विदेशी व्यापार के मूल्य में भी बराबर वृद्धि हुई है। हमारे विदेशी व्यापार का अनुपम दिनांक महापुद्गल के पश्चात् हमारे विरल में चला गया था। वह वर्ष फिर १९५० ई। में हमारे पक्ष में हुआ है। हमारे विदेशी व्यापार की स्थिति का यह कुछ विवरण है। हमारे देश से दूसरे देशों को जान वाले मुख्य पदार्थों का नाम इस प्रकार है — सूती वस्त्र, कपास वूट, वूट का नैवार माल, चाय, मूंगफली का तेल, कमाया हुआ चमड़ा, मसाला—मुगजन, कालामिन, कच्चा कपास, कच्चा ऊन, सूत, अवरक, नैवार कोयल लकड़, तथा मैंगनाज। इसी प्रकार दूसरे देशों से आने वाले मुख्य-मुख्य पदार्थों के नाम ये हैं — कच्चा कपास, गन्, चाय, नकली रेशम का धान, कागज, जपाने का तेल, चर सिंग, दवाइयों, रासायनिक पदार्थ, पत्राई, इलेक्ट्रिक मशीनरी और अन्य सहायक। दश का निर्यात हमारे मुख्य अमेरिका, युनाइटेड किंगडम, आस्ट्रेलिया, लंडा, इटली, चीन, ईरान, जपान, फ्रांस और कनाडा के साथ होता है। अमेरिका हमारे वूट कमाय का आस्ट्रेलिया, लंडा, युनाइटेड किंगडम, जपान, अरब, कानडा, जेब्रील, स्ट्रुस मैटलमैटल हमारे सूती कपड़े के अमेरिका, बल्जियम, जर्मनी कच्चे इस्ते, अमेरिका युनाइटेड किंगडम, आस्ट्रेलिया चीन, जेडरलंड, बल्जियम और जापान, हमारे कच्चे कपास के, अमेरिका और इंग्लैंड चमड़े के, अमेरिका अवरक और मैंगनाज के युनाइटेड किंगडम और अमेरिका हमारे चाय के प्रमुख गरीदार हैं। आयात में युनाइटेड किंगडम अमेरिका और जेफ्रेला वेकिया में हमें मशीनरी मिलती है। हमारे आयात और निर्यात में किन चीजों का जितना महत्व है इसका अनुमान आगे दी गई तालिका से लगाया जा सकता है —

आयात के मुख्य पदार्थ		कचे करोड़ में	
मान पदार्थ	अन० दिने०	१९४६ अप्रैल	१९४६ मार्च १९५०
प्रथम श्रेणी	फल और तरकारी	६५५	६६८
	छनाज, दाल और आटा	१०५४२	८८५५
	प्रेविजम और प्रोइलमैन स्टोर्म	८२८	७६८
	तम्बाकू	२१८	२०३
	कुल प्रथम श्रेणी	१०९००	१०८३६
द्वितीय श्रेणी	अधातु यान में निकलने वाले पदार्थ आदि	२८१	२७१
	तेल, सब प्रकार के—वनस्पति,		
	खनिज और पशु संबंधी	५८८६	५८१८
	कपास, ऊँचा और पारिज	६०६४	५६८४
	कच्चा ऊन	६८०	३०३
	अन्य	५६६	७०२
	कुल द्वितीय श्रेणी	१४२८८	१३७८८
तृतीय श्रेणी	रामायनिक पदार्थ, लकड़ और इमारत		
	इमारत	२१०५	१६१३
	पाक दूरी आदि	१८३८	१५६२
	रंग	१२४२	११११
	बिल्ली का तामास	१५०८	१३०२
	सब प्रकार की मशीनरी	१०७६३	१०५५२
	घातु, लोहा और इस्पात	१४०७	१०७०
	घातु—अन्य	२१४२	१८१६
	काराज, पेट्रोल बीई और स्टेशनरी	१४०२	८७१
	मोटर आदि	२८३२	२३४६
	कपासकानूत और तैयार मात	२५२१	१८४१
	ऊन का सूत और तैयार माल	७४३	५६८
	दूधरे टेक्सटाइल्स	२११८	१६०५
	अन्य	१८०३	१५५७
	कुल तृतीय श्रेणी	३३५४४	२८८५८
	कुल तीनों श्रेणी	६०७६३	५४७५७

(कॉमिश्नरियस रिपोर्ट १९४६-५० स्टेटमेंट ६७)

		विषयों के मुख्य वृद्धि		रकम दोनों में
नाम पन्नाय		जन	दिनांक ८/८ अप्रैल १९४६ मार्च १८२०	
प्रथम अंश	पुस्तक	१ ९०		१ ८१
	पत्र-पार साग	६ ८३		३ ५
	ग्रन्थान् दाल और आटा	० ०४		० ०४
	मसाला	१४ ५२		१८ ५७
	चाय	७३ ६५		७ १४
	त बाह	८ ६६		६ १
कुल		११ ९३		११९ ६०
द्वितीय अंश	अपानु ग्यान स निरुपन			
	बाल वृद्धि आदि	६ १		७ ११
	म द रजिस्टर, और लान	८ ०८		८ ६६
	रुपया चमड़ा	६ ४		६ ८९
	रुपय गाउ	४ २८		६ ६६
	तल रजिस्टर कनिज			
	मार गुरु	७ ६६		८ ८०
	ब न	८ ०५		१४ ७६
	रजिस्टर तथा और गारिज	१५ ८८		१६ ३४
	पत्रमन तथा और गारिज	११		१५ ७६
	ऊन तथा और गारिज	३५		३ ७१
	दूसरा टर्मिनाइल माल	२१		१ ६५
	अन	२ ६		१ ८६
कुल		६९ ६		१०३ ४६
तृतीय अंश	कपास का मूल और			
	नैयार माल	४६ ९३		३० ५६
	पत्रमन यान और			
	नैयार माल	५ ८४		६ ४ ३५
	ऊनी यान और नैयार			
	माल	२ ४९		२ ५४
कुल		६५५		६० ६०
कुल		०८ ४३		४० १६
कुल माना अंश		४०५ ६६		४५१ ५१

(करीमा पागलम रिपोर १९४६ ५० स्टैटमेंट ६८)

विदेशी व्यापार और सरकार का नियंत्रण—यह हम लिय चुके हैं कि गत महायुद्ध के समय से आरम्भक विदेशी व्यापार पर भारत सरकार का नियंत्रण चला आ रहा है। इस विषय में अब थोड़े विस्तार से विचार करेंगे। जब तक सड़ार्ड चलती रही विदेशी व्यापार पर सरकारी नियंत्रण का एक मात्र उद्देश्य यही रहा कि कुछ संभालन में सरकार को सहायता मिले। आयात और निर्यात दोनों पर कई प्रकार के प्रतिबंध और नियंत्रण लगाये गये। निर्यात पर जो नियंत्रण लगाये गये थे उनका उद्देश्य शत्रु राष्ट्रों को माल भेजने पर रोक लगाना, कुछ चीजों का जो शत्रु राष्ट्र नहीं थे उनको भेजने से भी मना करना, कुछ चीजों को शत्रु राष्ट्र नहीं थे उनको लाइसेंस द्वारा ही भेजने की स्वीकृति देना, और कुछ देशों को कुछ चीजें बिना लाइसेंस या 'ऑपन जनरल लाइसेंस' के मातहत भेजने की स्वीकृति देना था। मार्च १९४० से विदेशी विनिमय पर सरकार का नियंत्रण हो जाने से भी निर्यात पर नियंत्रण हो गया। जब तक निर्यात से मिलने वाले विदेशी विनिमय का सरकार के नियंत्रण नववी नियमों के अनुसार उपयोग करने का प्रमाणपत्र नहीं पेश किया जाता था निर्यात करने की स्वीकृति नहीं दी जाती थी। इस सब के पीछे प्रयोजन यह था कि निर्यात के कारण जो विदेशी मुद्रा प्राप्त हो उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण रह सके। आयात पर नियंत्रण कुछ आरम्भ होने के कुछ समय पश्चात् किया गया। शुरू-शुरू में शत्रु राष्ट्रों को छोड़ कर किसी भी देश से माल भेजने की पूरी आजादी थी। पर मई, १९४० में विदेशी विनिमय अंत खाल तौर से दुर्लभ मुद्रा का संचय करने की दृष्टि ने आयात का लाइसेंस देने की व्यवस्था चालू की गई। बिना आयात लाइसेंस प्राप्त किये विदेशों को माल का नुक़ारा करने पर रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध लगा दिया था। मई १९४० में ६८ चीजों के आयात पर नियंत्रण किया गया। बाद में यह संख्या बराबर बढ़ती गई। जनवरी १९४२ तक लगभग आयात की सब चीजों पर नियंत्रण कायम हो गया था। विदेशी विनिमय के नियंत्रण हो जाने से निर्यात की तरह आयात का भी नियंत्रण हो गया।

इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के काल में निर्यात और आयात पर नियंत्रण चलता रहा। युद्ध के समाप्त होने के बाद स्थिति में परिवर्तन आया। आयात के बारे में १९४६ और १९४७ के पहले सात महीनों में भारत-सरकार ने नरम नीति का पालन किया। दुर्लभ मुद्रा के बारे में भी सरकार की नरम नीति ही रही। पर अगस्त १९४७ के बाद सरकार की नीति कड़ाई की हो गई यहाँ तक कि भारत—यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुए समझौते (जनवरी-जून १९४८) के अनुसार हमारे जमा पौंड पावने के फंड में से जो पौंड पावने की रकम खर्च

करने के लिये हम मिली था वह भी हम पर नहीं कर सके। आम मुद्रा दर या बाहर से प्रथम आयात माल के बार में विनाशकारी नाति घटी गई। डालर क्षेत्र से कुछ मात्रा के आयात को तो शिज्जुल ही रोक दिया गया। उन पचास पदार्थों के आयात का भी स्वीकृति नहीं दी जाती थी जो यूनाइटेड किंगडम में उपलब्ध थे। पर वास्तव में यूनाइटेड किंगडम से मात्र आता नहीं था। सार इसका यह निकला कि देश में माल की कमी थी और आयात बन्द गिर गया। आयात बन्दगी इस कड़ी नाति का कारण डालर की मजबूती की हल करना था पर उसका असर मँहगाई बढ़ने का भी हुआ। यह वह समय था जब देश के विभाजन के कलरूप देश में बहुत अव्यवस्था फैली हुई थी आयात की कठिनाई के कारण परमाणु घट रहा था और निर्यात करने की नाति का योग दिया जा रहा था। इन सब कारणों का असर यह था कि देश में माल की हर तरह से कमी, हाँ 'ग' और 'होल' माल प्रदर्शन का इन्तजाम नम्बर को नम्बर ६७ में १०० था यह जुलाई ६४ तक १८६९ तक पहुँच गया। आयात में नरम नाति घटने का वास्तव में यह उपरान्त समय था। इस विपदात अनुभव के कारण जुलाई १९६८ में भारत सरकार ने आयात नीति में फिर नरमी आई। 'आपन जनरल लाइसेंस' के अन्तर्गत आयात वाली चीजों का माला में काफी वृद्धि का गई और ४०० के लगभग यह माला पहुँच गई। इन चीजों में आयात बिल्कुल बन्द था उनको उस श्रेणी से हटा लिया गया। इस नीति का असर यह हुआ कि हमारा आयात बन्द बन्द गिरा और व्यापार का माला हमारे बहुत विपन्न में जाने लगा। हालाँकि मँहगाई पर इस नाति का अन्धा असर हुआ। पर विदेशी निनिमय की इनार सामान कठिनाई का परिणाम हुआ। जो पांड पायना हम पहले देख नहीं कर पाय थे वह सब स्पष्ट हो गया और उसने अलावा निना हमने कमाया उससे कहीं अधिक स्टोरलिंग और डालर हमने खर्च कर दिया। नतीजा यह हुआ कि फरवरी १९४६ में भारत सरकार ने आयात निर्यात बन्दगी नाति में फिर कड़ाई आगई। डालर प्रदेश से आयात कम कराने का कांशिश की गई 'आपन जनरल लाइसेंस' के अन्तर्गत आयात वाली चीजों की माला बहुत कम कर दी गई। १ अगस्त, १९४६ से भारत यूनाइटेड किंगडम के बाहर के आयात में 'मॉड' में फिर आवश्यक सधोना हुआ और यूनाइटेड किंगडम ने भारत को जो डालर का पाटा हो रहा था उस पूरा करने का उत्तर दिया। इससे पहले में भारत 'एम्पायर जनरल' का पूरा माला बन गया। सरकार ने अपनी आयात नीति को और अधिक बन्द करने का निश्चय किया। आपन जनरल

लाइसेंस के अन्तर्गत चीजों की मर्यादा अब केवल २० रह गई। सितंबर १९४६ में जो आयात नीति सरकार ने घोषित की उसके अनुसार आयात को तीन श्रेणियों में बांटा गया—(१) वे चीजें जिनके लिये साधारणतया लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे। (२) वे चीजें जिनके लिये एक निश्चित परिमाण के आचार पर लाइसेंस दिये जायेंगे। (३) वे चीजें जिनका समय-समय पर लाइसेंस दिया जा सकेगा। बशर्ते कि उनके आयात का हर समय उचित कारण बताया जा सके। दुर्लभ मुद्रा प्रवेश से आयात करने की स्वीकृति उसी हालत में मिलने वाली थी जब कि स्ट्रालिंग प्रदेश में वह या उसकी जगह काम में आ सकने वाला दूसरा माल न मिलता हो। अगर किसी चीज के आयात की व्यवस्था कितां द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते में की जा चुकी है तो उनको दूसरी जगहों से आयात करने की स्वीकृति नहीं दी जाती थी। रिजर्व बैंक ने जनवरी १९४८ से अनधिकृत आयात का शुकरा करने के लिये विदेश रुपया भेजने की जो सुविधा दे रखी थी वह भी अब वापस लेली गई। इसके बाद भी जैसी-जैसी जरूरत आई अलग-अलग चीजों के आयात के बारे में कुछ फेर-फार होता रहा पर मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस बीच में रुपये का भी सितंबर १९४६ में अवमूल्यन हो चुका था और उसका हमारे विदेशी व्यापार के संतुलन पर अनुकूल असर भी पड़ रहा था। पर २५ फरवरी १९५० को जनवरी-जून १९५० के लिये जो आयात नीति घोषित की गई थी वह पहले की अपेक्षा थोड़ी सी उदार थी। कच्चा कपास, कच्चा रेशम और रेशम के तार, अलौह धातु, भारी रसायनिक पदार्थ, और बवाइचों आदि जैसे आवश्यक उपभोग के पदार्थों को मुख्य मुद्रा प्रदेशों से भेजने की स्वीकृति दी गई। कच्चे कपास का आयात दुर्लभ मुद्रा प्रदेशों से करने की भी इजाजत थी। जुलाई १९५० से दिसंबर १९५० के समय के लिये जो आयात नीति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। लगभग ३७ से ४० करोड़ रुपये प्रति मास के आयात की व्यवस्था की गई। लगभग इतनी व्यवस्था ही पिछले जनवरी-जून १९५० के समय के लिये की गई थी। जनवरी १९५१ में जून १९५१ के लिये घोषित आयात नीति के बारे में भी कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं थी। पर हाल में जुलाई-दिसंबर १९५१ के समय के लिये सरकार ने अपनी आयात नीति की घोषणा की है। इसके अनुसार आयात को प्रोत्साहन देने का खास तौर से प्रयत्न किया गया है। अब जुलाई-दिसंबर के बीच में जो लाइसेंस वियं जायेंगे वे सालभर के लिये होंगे। अभी तक लाइसेंस छह महीने के लिये होता था। बाहर से आने वाले माल के परिमाण और मूल्य दोनों में ही वृद्धि की गई है और नई चीजों को भी आयात की सूची में जोड़ा गया है। उपर्युक्त

विवरण का आग्रह यह है कि भारत सरकार की आयात नीति में यह समझ होने के बाद का भी हम विचार करें तो दमोग कि बराबर परिवर्तन हुआ रहा है। मुद्रा समझौता होने के बाद मुद्रा १९४७ तक आयात नीति नरम रहा। पर प्रथम १९४७ से जन १९४८ तक हमारा आयात नीति कड़ी हा गई। फिर जुलाई १९४८ में नरम नीति अपनाई गई। परन्तु १९४९ में फिर कड़ाई की नीति शुरू हुई। परन्तु १९५० में यह नीति नरम की और बढ़ना और और तक बढ़ा नीति चल रही है।

भारत सरकार का विधान सम्बन्धी नीति पहले तो प्रविष्टि-आमक थी। पर लक्ष हमारा विदेशी व्यापार का समुल्लेख विगड़ने लगा और विदेशी निम्न की तथा आगई खाद्यपदार्थों में १९४७ के अन्त में जो हमारा विदेशी आयात रिक समुल्लेख बहुत प्रतिफल हा गया तो भारत सरकार की नीति निम्न के प्रोत्साहन देने का हा गया। बड़ा १५ कीमती बड़ा १५ दश के आदर की मौज और दश के विभाजन के कारण पक्का प्रतिफल अन्तर हमारे नियामक व्यापार में मूल्य में आया है। पर भारत सरकार ने इस सब बाधाओं के बावजूद १९४८ से १९५० में विदेशी व्यापार का प्रोत्साहन नीति की नीति जारी रखा। कई चीजों का नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया और बहुतों का आगाना से लाइसेंस मिलने वाला शर्तों में ल लिया गया। इस समय के बावजूद भी १९४९ के पहले छद्म मूल्य में हमारे निर्यात व्यापार का स्थिति पहले से भी गिर गया। जून १९४९ में भारत सरकार ने एकछपाट प्रमाणन कमटी का नियुक्ति की। इस कमटी ने विधान का प्रोत्साहन नीति के लिए कई सिफारिशें की। उदाहरण के लिए निर्यात सम्बन्धी नियंत्रण को अन्तिम अधिकार मामित करने खास तौर से नैयार मान्य के विधान पर से प्रविष्टि होने का इस कमटी ने सिफारिश की। इस कमटी का सिफारिश का सरकार ने मंजूर किया। कई चीजों निर्यात मना था लाइसेंस के बावजूद निर्यात इन चीजों के मूल्यों में आया है। 'आयन जनरल लाई सेंस' के अंतर्गत जो बिना लाइसेंस के सब दशों को निर्यात की मुविधा हुआ है 'आयन' का समझ बन गया। लाइसेंस देने का पद्धति को पहले से भरल करने का प्रयत्न किया गया और व्यापार मन्त्रालय में ही निर्यात लाइसेंस मिलने का व्यवस्था की गई। पहले जो मात्र पदार्थ के लाइसेंस खास मन्त्रालय से मिलने थे अब व्यापार मन्त्रालय से मिलने लग। जो कर निर्यात में बाधक थे उन्हें कम किया गया या हटाया गया। जैसे भारतीय निर्यात कर में निर्यात पदार्थों का मुक्त कर दिया गया। स्पष्ट है अब मूल्यन का भी निर्यात पर अन्तर पड़ा। कोरिया को लकाई के कारण आगाना मुद्रा की नैयार का दृष्टि से दुनिया के देशों ने कचे

माल का संचय करना शुरू कर दिया उसका भी नियंत्रण पर अंतर पड़ा। इन सब कारणों का सम्मिलित असर यह हुआ कि हमारे निर्यात में वृद्धि हुई और १९५०-५१ में गत महायुद्ध के बाद पहली बार व्यापार का संतुलन हमारे पक्ष में हुआ।

भारत सरकार के आयात और निर्यात की नियन्त्रण नीति का उत्तर विवेचन किया गया है। भारत सरकार को इस काम में 'एक्सपोर्ट एडवाइजरी कौंसिल' और 'इम्पोर्ट एडवाइजरी कौंसिल' सलाह और सहायता देती हैं। भारत सरकार की आयात नियन्त्रण नीति की कई बातों को लेकर आलोचना की जाती थी। उदाहरण के लिये लाइसेंस मिलने में होनेवाली अनावश्यक देर, लाइसेंस पद्धति की पेचीदगी, तथा आयात नीति की स्थिरता आदि कुछ ऐसी बातें थीं जिसकी लेकर सरकार के प्रति असन्तोष था। सरकार ने १९५० में लागू आयात नीति पर विचार करने के लिए 'एक्सपोर्ट कंट्रोल एन्वायरिंग कमेटी' की नियुक्ति की। इस कमेटी ने ४ महीने में ही अपनी रिपोर्ट अक्टूबर १९५० में पेश कर दी। सरकार ने जनवरी १९५१ में इस कमेटी की सिफारिशों पर अपना निर्णय भी दे दिया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सब से बड़ा इसी बात पर जोर दिया था कि आयात सम्बन्धी नीति और संचालन में स्थिरता होनी चाहिये और स्वीकृत नीति का शीघ्र और समया के साथ पालन होना चाहिये। कमेटी ने यह सिफारिश की कि आगामी दो वर्षों में ४०० करोड़ रुपये वार्षिक का आयात भारत में होना चाहिये। आयात की चीजों की प्राथमिकता के बारे में भी इस कमेटी ने अपनी राय दी। आयात सम्बन्धी विद्वानों का विवेचन करते हुए कमेटी की यह राय कि हमें अपने आयात की मर्यादा विदेशी विनियम की स्थिति के अनुसार ही तय करनी चाहिये, और बाहर से आने वाली चीजों की प्राथमिकता इस दृष्टि से निश्चिन होनी चाहिये कि जिससे देश के कृषि-उद्योग के विकास और उपभोक्ताओं की आवश्यक वस्तुओं का मांग का लिहाज रखा जा सके। इसी के साथ-साथ किन्हीं वस्तुओं के मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को कम करने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिये, पर यह उसी हद तक जिन हद तक कि विदेशी विनियम मर्यादा और हमारे कृषि-उद्योग के विकास तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकता के साथ इसका मेल बैठ सके। उपर्युक्त सिफारिशों के अलावा कमेटी ने कुछ अन्य विषयों पर भी सिफारिशें की थी जेमे— लाइसेंस के समय को बढ़ाना, लाइसेंस-पद्धति का विकेंद्रीकरण करना, नए आयात के व्यापारिकों को सुविधा देना, मुलभ मुद्रा प्रवेश के किसी देश से माल मँगाने की अधिक आजादी, और किसी हद तक दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र से माल मँगाने

को अधिक से अधिक मात्रा में कम करने और उस व्यापार का विस्तार करने का रहा है।

भारत की उस नीति का एक प्रमाण तो भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समिती (इन्टर नेशनल ट्रेड ओरगेनाइजेशन) और बा. ए. टा. टा. (जनरल एसोसिएशन ऑफ ट्रेडिंग नेशन्स) के विषय में जो महायुक्त और समझौता का हस्ताक्षर किया है उसी से मिल जाता है। इस सम्झौते में उक्त विस्तार में निम्न की आवश्यकता है।

द्वितीय महायुद्ध के अन्त में उसी समय यह अनुभव किया जा रहा था कि विश्व शान्ति के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न देशों का राजनैतिक प्रभाव होना नहीं बल्कि आर्थिक प्रभाव पर भा. आधारित सहयोग हो। एक विश्व-शांति का यह मतवाला था कि जिस प्रकार राजनैतिक क्षेत्र में समुदाय राष्ट्र एक (यू. एन. ओ.) की स्थापना का यह उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी एक अन्तर्राष्ट्रीय समिती कायम करने का प्रयत्न किया गया। विश्व-शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए समुदाय आधारित अर्थ-प्रणाली का इसी आधार पर स्थापना की गई। इसी प्रकार एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थापित करने का विचार भी बना। राज्य-पक्षों के हवाला (हवा) में २० नवम्बर १९४७ और १९ मार्च १९४८ को दो सत्रों में २३ राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 'प्रिन्सिपल्स ऑफ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक समन्वित विचार' किया गया और उस पर विचार हुआ 'इस प्रिन्सिपल्स कमिटी' की स्थापना १९४६ में उस समय हुए था जो इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय के कुछ प्रस्ताव प्रकाशित किये थे और उनके बाद में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विचार करने के पहले एक छोटा-सा समिति द्वारा विचार करना उचित समझा गया था। इस कमिटी में १८ राष्ट्रों के अन्तर्गत भारत भी उनमें से एक था। इस समिति के अन्तर्गत सत्र हुआ था। हवाला सम्मेलन में ५४ राष्ट्रों ने भा. समन्वित विचार विनिमय के बाद तय किया था और उस पर हस्ताक्षर कर दिये गए हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी था। विभिन्न राष्ट्रों का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में मिलने पर ही यह अन्तर्राष्ट्रीय समिति में आने वाला था। हाल ही में (फरवरी १९४९) अमेरिका ने हवाला चार्टर को स्वीकार नहीं करने का अना-विचार प्रकट किया है और इस पर से ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समिति का कायम होने की आशा नहीं है।

इसका मतलब है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का उसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रभाव करना और निर्यात और आयात के अन्तर्गत देशों के आर्थिक विकास

में नहायक होना है। जो व्यापारिक नीति इस चार्टर में स्वीकार की गई है उसके अन्तर्गत इन बातों का समावेश किया गया है—(१) एक देश किसी दूसरे देश को आयात-निर्यात-कर अथवा विदेशी व्यापार संबंधी किसी प्रतिबंध के बारे में अगर कोई रियायत देगा तो वह बाकी के सब देशों को भी अपने आप मिलेगा। इन्हीं को 'मोस्ट फ़ेवर्ड नेशन' का व्यवहार कहते हैं। इसमें कुछ अपवाद किये गये हैं। एक अपवाद किसी देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से भी किया गया है, अर्थात् आर्थिक विकास के कारण इस सिद्धान्त के विपरीत व्यवहार करने की स्वीकृति मिल सकती है। पर वह अपवाद इन्हीं शर्तों के साथ किया गया है कि वास्तव में इस से होने वाला लाभ नदेहात्य है। (२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संधि के सदस्यों से यह अपेक्षा भी की गई है कि वे आपसी समझाने से आयात-निर्यात-कर और उस सम्बन्धी विशेष व्यवहार में कर्मा करे। इसमें भी कुछ अपवादों के लिये गुंजादश है और एक अपवाद यहां भी पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास में सम्मिलित रहता है। (३) आयात और निर्यात सम्बन्धी प्रतिबंध लगाते अथवा प्रवेश निषेध करने की मनाही की गई है। इसमें भी कुछ अपवाद हैं। (४) चार्टर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि त्रिन देशों में विदेशी-व्यापार राज्य द्वारा होता है उनके साथ न कोई विशेष रियायत होगी न कोई विपरीत व्यवहार होगा। आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण के बारे में चार्टर में एक अलग ही परिच्छेद है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संधि का यह कर्त्तव्य है कि इस कान में यह अपने सदस्यों को नहायता है और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मस्थाओं के साथ इस काम में सहयोग दे।

चार्टर के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की सलाहपर नक्सा 'कान्ट्रॉल' में निहित है जो एक व्यवस्था मंडल का चुनाव करेगी। साधारणतया कान्ट्रॉलम वर्ष में एक बार होगी, वह माना गया है। संयुक्त राष्ट्र संधि के साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का संबंध सहयोग का होगा और इस बात का ध्यान रखा जायगा कि संयुक्त राष्ट्र संधि की राजनीति में इनका हस्तक्षेप न हो। चार्टर की उक्त धाराओं की कई कारखों से छाकोचना भी हुई। छाकोचना का एक बड़ा आधार यह रहा है कि पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास का चार्टर में पूर्णतः ध्यान नहीं रखा गया है। विदेशी व्यापार को मात्रा बंदे, इन्हीं पर अधिक नजर दिया गया है। इस समय तो इन संगठन का मुख्य अन्वकार में मालूम पड़ता है।

अब इन 'जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेडिग्न और ट्रेड' के विषय में कुछ लिखेंगे। यह इन ऊपर लिख चुके हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के चार्टर

में एक धारा यह भी थी कि इस मस्यौदा के सदस्य आनखी समझौते के आधार पर आन्ताराष्ट्रीय व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को कम करें। इसी उद्देश्य के लक्ष्य में अनेक विभिन्न देशों में जोना सम्मेलन १९४७ में अक्टूबर ३० १९४७ तक सम्मिलित की चर्चा चर्चा और जो निश्चित उनका समावेश उत्त एप्रामेट में कर लिया गया। अस्थायी आधार पर यह एप्रामेट १ जनवरी १९४८ को अमल में आया। भारत भी इसमें शामिल था। इस एप्रामेट में प्रिपरटरा कमेटी के १८ सदस्यों में अफगानिस्तान, भारत, बर्मा, लद्दाख और दक्षिणी रोडेशिया भी शामिल थे। १९४८ विप्लव सम्मान इस देश का भी मध्य में था। इससे परचाल अक्टूबर १९४८ में अगस्त २० १९४८ को अन्तर्गत (प्राम) में फिर कांफेंस हुई जिसमें अफगानिस्तान, भारत, इराक, इटली, स्वाइज, डार्मिनिजन रिपब्लिक, लासवीग, निकारागा और उरुग्वे के दस नये देश और शामिल हुए। ३ नवंबर १९४८ तक ११ नए सदस्यों की उत्त एप्रामेट में शामिल करने के लिए एक 'प्रोत्साहन' पर इलाहूर किया गया और २० मई १९४९ से यह लागू किया गया। भारत में ११ नवंबर १९४९ में सम्मिलित में भाग लिया और विभिन्न देशों के साथ सम्मिलित किए। इन सम्मिलितों के अनुसार भारत ने रियायतें दीं और उन रियायतें मिलीं। इस बाद टोक्य (दार्जिलिंग) में तीसरा बार कांफेंस हुआ २१ अक्टूबर १९४९ को साथ में ११ नए सदस्यों के बाद समाप्त हुआ। इस कांफेंस में विभिन्न देशों में ४०० के लगभग सम्मिलित करने का प्रयत्न हो रहा था, परन्तु साथ में ८ देशों में उक्त १४७ सम्मिलित हो ही सके। भारत भी इसमें शामिल था। इस कांफेंस का सफलता मयादित हो रहा। कुछ नए देश इस एप्रामेट में इस सम्मेलन में शरीक किए गए। पुराने सम्मिलितों का (अन्तर्गत एप्रामेट) मिश्रित दिग्दर्श १९४९ तक करना गई। पुराने सम्मिलितों में कुछ देशों ने सहायक और परिवर्तन कराया और उनसे अनुशार दी गई कुछ रियायतें वापस ली गई। कुछ नए रियायतों के साथ में भी सम्मिलित हुए। जो ए प्रोत्साहन के अनुसार ३ नवंबर के बाद इस प्रकार का सहायक परिवर्तन हो सका है। इसी लिए १९४८ के बाद अब यह कांफेंस हुई थी। 'एप्राम' का कांफेंस इस प्रकार की नहीं था। जिन ३८ देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया वे दुनिया के लगभग विदेशों व्यापार के ८०% भाग में लिए सम्मिलित हैं।

भारत की व्यापारिक नीति का पिछले तान वर्षों में एक महत्वपूर्ण अंग हमारे विभिन्न विप्लव व्यापारिक सम्मिलितों से संबंध रखता है जो विभिन्न देशों के और भारत के बीच में हुए हैं। ये अल्प कालिक व्यापारिक सम्मिलित हैं।

इनका उद्देश्य दुर्लभ मुद्रा की स्थिति में सुधार करना, बुद्धिमान आर्थिक निर्माण में सहायता देना, अनाज की कमी की पूर्ति करना, दूसरी आवश्यक चीजों की जैसे मशीनरी, रासायनिक, पदार्थ, आदि की कमी की पूर्ति करना और निर्यात को प्रोत्साहन देना रहा है। जर्मनी और जापान के साथ इसलिये व्यापारिक समझौते करना आवश्यक थे कि इन देशों के विदेशी व्यापार पर राज्य का नियंत्रण है और जिन विदेशी राज्यों का इन पर आधिपत्य है उनके द्वारा निर्दिष्ट विदेशी व्यापार की योजना के साथ उसका मेल बैठना आवश्यक है। यही ध्यान रख और पूर्ण रूप से देशों—जैसे युगोस्लाविया, पोलैंड, चेकोस्लावकिया के बारे में लागू होता है, क्योंकि वे अपने विदेशी व्यापार का नियंत्रण सरकारों के बीच में ही करना पसंद करते हैं। इन व्यापारिक समझौतों का एक लाभ यह भी है कि भारत का इन देशों के साथ सीधा व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाता है और लंदन एमस्टर्डम आदि दूसरे देशों की मध्यस्थता समान हो जाती है। भारत ने इन पिछले वर्षों में कई देशों के व्यापारिक समझौते किये हैं। भारत का पाकिस्तान के साथ भी कई बार व्यापारिक समझौता हुआ है। इस समय भी एक व्यापारिक समझौता इन दोनों देशों के बीच में चालू है। यद्यपि इन व्यापारिक समझौतों के कारण हमारे विदेशी व्यापार को आशातीत सफलता नहीं मिली है और समझौते के अनुसार आयात और निर्यात नहीं हुआ है, परन्तु भी ये द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। इनका भविष्य में और अच्छा परिणाम आ सकता है।

विदेशी व्यापार की भविष्य दिशा—देश के विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में अन्तिम प्रश्न यह उठता है कि उसकी भावी दिशा क्या होने की संभावना है? किसी भी देश का विदेशी व्यापार उस देश के आर्थिक संगठन पर निर्भर होता है। हमारे देश में जिस प्रकार का आर्थिक संगठन हम स्थापित करेंगे उसी प्रकार का हमारा विदेशी व्यापार होगा। देश के भावी अर्थ-व्यवस्था के बारे में आज विभिन्न विचारधाराओं में संघर्ष चल रहा है। एक व्यवस्था गांधीजी के विकेंद्रित उत्पादन और स्वावलंबी गांवों पर आधारित हो सकती है। दूसरी व्यवस्था समाजवादी आधार पर स्थापित हो सकती है। तीसरी व्यवस्था उस मिले-जुले आर्थिक संगठन की है जो वर्तमान सरकारों की नीति है। जहां तक विदेशी व्यापार का संबंध है, चाहे समाजवादी व्यवस्था हो चाहे मिलजुली अर्थ-व्यवस्था हो, जब तक आधुनिक उद्योगवाद उसका आधार है, उसके स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आता। हां, गांधीजी की सुझाई अर्थ व्यवस्था की बात अलग है। यह अर्थ व्यवस्था विकेंद्रित और स्वावलंबन के आधार पर होगी, इसलिये

इसमें विदेशी व्यापार की मात्रा कम होगा। विदेश से जोड़ना सामान तो हमारे दैनिक जीवन के लिये अनिवार्य है और इसी प्रकार का सामान यहाँ से बाहर जा सकता है। देश के अन्दर जो उत्पाद का विकास रहे पैमाने पर होगा और ऐसी दशा में बाहर में मर्यादों आदि बहुत मँगाने का हमें आवश्यकता नहीं होगी। हाँ विजली, सिमेंट, त्रिभुजगणि आदि के उत्पादन के लिये जो मशीनरी आदि आवश्यक होगी उसे तो मँगाना ही होगा। पर उद्योगों के विकासों का अधिकतर उत्पाद एक उत्पाद — रुप में होगा। इसका अर्थ यह है कि गांधीजी द्वारा सुझाए हुए व्यवस्था यदि हम स्वीकृत करेंगे तो हमारे विदेशी व्यापार का सारा ढाँचा ही बदल जाता है। देश इस प्रकार का व्यवस्था स्थापित होगा हमें बची शक्ति है। इसका एक अर्थ नहीं कि हमारा एक उद्योगों का विकास नहीं होगा। पर वह पैमाने के अनुसार ही भी पूरा महत्त्व रहेगा ऐसा लगता है। ऐसा हालत में हमारा विदेशी व्यापार की भाँति दिशा के बारे में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों आधार पर मानना आवश्यक है। विद्यमान वहाँ में हमारा विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी समस्या विदेशी व्यापारिक अनुत्पन्नता रहा है और जिसका कारण है विदेशी विनिमय का सीमा है दुर्लभ मुद्रा की हम कमिना रहा है। हमारा अल्पकालिक दिग्दर्शी व्यापार सम्बन्धी उद्देश्य यह जाना चाहिये कि हम विदेशी विनिमय का अपना तात्कालिक आवश्यकता पूरा करने में कमिना न हो। यह तात्कालिक आवश्यकता मौजूदा उत्पादों का खानू रखन, उनमें मर्यादों आदि का आवश्यक परिवर्तन करने और आवश्यक उपकरणों का वस्तुओं का प्राप्त करने में सम्भव रहना है। इन बातों की कमी को पूरा करने के लिये हम अपने व्यापारिक अनुत्पन्नता का एक करना होगा। उसने लिये देश में माल का कीमती का कम करना मुद्रा का अनुत्पन्न करना, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन करना और विदेशी व्यापारिक सम्बन्धों को करना—यह उपाय है जो काम में लिये जाते हैं। भारत भी इस दिशा में प्रयत्नशील रहा है। इससे हमारा व्यापारिक अनुत्पन्नता मुद्रा भी है।

हमारा दीर्घकालिक विदेशी व्यापार की नीति ऐसा होना चाहिये जिससे हम अपने आर्थिक विकास में सहायता मिले। इस दृष्टि में आवश्यक माल हम विदेश से मंगा सकें जो माल हम बाहर बाजार में उस माल का बचन का व्यवस्था कर—यह हमारे विदेशी व्यापार का लक्ष्य होगा। इन दृष्टि में आर्थिक विकास का प्रथम अवस्था में पूर्णतया हम बाहर से मँगाना होगा और इस लिये हमारा व्यापार बचता और कच्चे माल का निर्यात होगा। दूसरी अवस्था में जब देश में व्यापार

भूत उद्योगों का उत्पादन बढ़ेगा और राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी तो पूँजी-माल का आयात कम होगा और उपभोग की वस्तुओं के आयात की प्रवृत्ति बढ़ेगी, अगर उसे रोकने का प्रयत्न न किया गया। अन्तिम अवस्था में उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ेगा। इससे इन चीजों का आयात कम होगा पर पर्याप्त उत्पादन होने पर निर्यात बढ़ सकता है। हाँ, विशेष प्रकार की और कीमती उपभोग की चीजें बाहर से मँगानी भी जा सकती हैं। वह तो हुआ व्यापार का स्वरूप। जहाँ तक इस व्यापार में विभिन्न देशों के स्थान का प्रश्न है उसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि हमें पूँजी-माल यूरोप-अमेरिका से और कच्चा माल पचीसी एशिया के राष्ट्रों से मँगाना होगा। हमारा निर्यात व्यापार भी इन देशों और एशिया तथा अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों के बीच में बँट जायगा।

विदेशी व्यापार का जो चित्र ऊपर उपस्थित किया गया है उससे केवल दिशा मात्र का अनुमान लगाना चाहिये।

हमारे भावी विदेशी व्यापार का एक प्रश्न यह भी है कि विदेशी व्यापार राज्य द्वारा संचालित होना चाहिये या व्यक्तियों के हाथ में ही रहना चाहिये। भारत सरकार ने १९५० में इस विषय में एक समिति नियुक्त की थी जिसने इस प्रश्न की पूरी जाँच-पड़ताल करके विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी थी। पर इसका कोई नतीजा नहीं आया। यह प्रश्न फिलहाल तो भारत सरकार का और से स्थगित ही कर दिया गया है।

स्थल द्वारा विदेशी व्यापार—देश के विभाजन से पहले भारत का स्थल मार्ग से अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया, नेपाल और तिब्बत से व्यापार होता था। देश के विभाजन के बाद पश्चिम के देशों से तो हमारा सीधा संपर्क हो गया है। अब तो पाकिस्तान के साथ हमारा पश्चिम और पूर्व दोनों ही ओर से स्थल मार्ग से सीधा सम्बन्ध है। भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी व्यापार स्थल मार्ग से ही होता है। १९४८-४९ में कुल ७० करोड़ का भारत से पाकिस्तान को माल निर्यात हुआ था। उसमें ४६.६१ करोड़ का माल समुद्र के मार्ग से और २०.३९ करोड़ का माल स्थल मार्ग से निर्यात हुआ था। १९४९-५० में कुल २९.६९ करोड़ के निर्यात व्यापार में से १३.८७ करोड़ का माल समुद्री मार्ग से और १५.८२ करोड़ का स्थल मार्ग से निर्यात हुआ था। आयात के आँकड़ों को देखने से मालूम होता है कि १९४८-४९ के १०९.२९ करोड़ में से २४.२९ करोड़ का माल समुद्री मार्ग से और ८५ करोड़ का स्थल मार्ग से तथा १९४९-५० में कुल ४३.९३ करोड़ में से ११.१६ करोड़ का समुद्री मार्ग से और ३२.७७ करोड़ का स्थल मार्ग से पाकिस्तान से भारत

को आया या। समुद्री व्यापार अधिकतर पश्चिमी पाकिस्तान से, और स्थल मार्ग से अधिकतर व्यापार पूर्वी पाकिस्तान में होता है।

भारत का 'ए' द्वीपी व्यापार—भारत के विन्श्या व्यापार का एक भाग ऐसा है कि दूसरे देशों में भारत में माल आता है और फिर वहां माल वापस निर्यात कर दिया जाता है। इसको 'ए' द्वीपी व्यापार कहते हैं। इसका कारण किताबों में दूध की दो दूधियाँ बाल में ऐसा भौगोलिक स्थिति होती है जिससे कि इन तरह का व्यापार आसानी से सम्भव हो सके। जबकि भूमण्डल के बाजार में स्थिति होना से पुष्प और पशुधन के बीच में एक बाल व्यापार के लिए भारत एक अच्छा विश्राम स्थल है। इसी कारण है कि प्राचीन काल से भारत इन तरह के व्यापार में भाग लेता आया है। प्राचीन समय में भारत के 'ए' द्वीपी व्यापार की मुख्य चीजें जिनमें रुपा, चीना का सामान, मसाला, जवाहरात, काजू का सामान (जिनमें का और रसायन था) सिम्पन, नेपाल, अफगानिस्तान आदि एक देश हैं जिनका अस्मा का समुदाय लग रहा है। उनका आयात नियम भी भारत के द्वारा ही होता है। बल्कि हम प्रकार के व्यापार का प्रमुख बन्दगाह है। इन और चमड़ा पश्चिम के देशों को जाता है और वहाँ से शहर चाय मसाला कपड़ा रासायनिक पदार्थ कच्चा धातु, आदि आता है। इस प्रकार के व्यापार का उच्च निदेशा व्यापार के मुकाबले में बहुत मजबूत रहा है। निदेशों में आयात रुपा माल ६५८-४ में ७ ६ करोड़ का १९५६-६० में ११ २६ करोड़ का और १९५०-५१ में १७ ८२ करोड़ का भारत में दुबारा निर्यात हुआ था। १९५६-५७ में दुबारा निर्यात १० करोड़ रुपये का हुआ था।

भारत का आंतरिक व्यापार—भारत के आंतरिक व्यापार के दो भाग हैं (i) समुद्र तटीय व्यापार और (ii) आन्तरिक व्यापार।

जब वसा भारत का अर्थ था तो भारत का वसा के साथ बन्दगाह समुद्र तटीय व्यापार होता था। वही बात कराची के बारे में भी है। आज कराची के साथ हमारा व्यापार निदेशी व्यापार का गिनता में आता है। समुद्र तटीय व्यापार का गिनता में नहीं। अब तो कलकत्ता मद्रास बंबई आदि बंदरगाहों के बीच का व्यापार ही समुद्र तटीय व्यापार का अर्थ में आता है। कलकत्ता (कच्छ) का नया बंदरगाह बनवाने पर इस व्यापार में वृद्धि होगी। छिंदी वर्षों में देश के समुद्र तटीय व्यापार में कमी आई है। १९५६ में कुल समुद्र तटीय व्यापार का अनुमान ७० लाख टन था। दस साल बाद यह घटकर ५० लाख टन हो रह गया और इस समय तो अक्सर समुद्र तटीय व्यापार

की (जिसमें विदेशी व्यापार शामिल नहीं है) मात्रा ३० लाख टन से भी कम है। यद्यपि यह व्यापार गिरा है पर इस पर भी भारतीय जहाज इस माल को लाने से जाने के लिये पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। समुद्र तटीय व्यापार की उन्नति के लिये भारतीय जहाजी बेड़े की प्रगति अत्यन्त आवश्यक है। रेलवे और जहाजी वातावात में समुचित मेल बैठाने और बन्दरगाहों के विकास का भी समुद्र तटीय व्यापार की दृष्टि से बड़ा महत्त्व है।

समुद्र तटीय व्यापार के अलावा जो हमारे देश का आन्तरिक व्यापार है उसका विदेशी व्यापार का अपेक्षा देश के आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। पर अभी तक आन्तरिक व्यापार के संपूर्ण और विरहसनीय आंकड़े हमारे देश में प्राप्त नहीं हैं। भारत सरकार का व्यापार-मंत्रालय जो आन्तरिक व्यापार सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित करता है वे भी प्रान्त का प्रान्त से और मुख्य बन्दरगाह के उस प्रान्त के जिसमें वह स्थित है या दूसरे प्रान्तों के साथ के व्यापार के आंकड़े होते हैं। इसका यह अर्थ है कि बहुत-सा व्यापार इस के बाहर रह जाना है। इस स्थिति को सुधारने की आवश्यकता तो है पर इतने बड़े देश में समस्त लेन-देन के आंकड़े एकत्रित करना असंभव-सा है। फिर भी इस विषय में जितना सुधार हो सके वह करना चाहिये। इस व्यापार की मात्रा देश के विदेशी व्यापार से आज भी कई गुनी (२-३ गुनी) है और देश के आर्थिक विकास के साथ यह मात्रा बढ़ने वाली है।

परिच्छेद ६

राजनीति, समाज, सामाजिक

१ यातायात का महत्त्व—मानव मनुष्य का विकास में यातायात का साधनों

का किनासा महत्त्व है, यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। यह महत्त्व समाज के आर्थिक जीवन तक ही सीमित नहीं है। मानव समाज का राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी इसका महत्त्व है। आज सारा विश्व यदि एक देश में बँट सका है, मानव सहानुभूति का ज्ञान यदि सारा धरा ही हो सका है, और सारा समाज एक परिवार के समान है, यह आदर्श यदि वास्तव में बरिष्ठा होना है—तो यातायात के उन्नत साधनों के आचार पर ही आज तक भी ऐसा हुआ है और आज भी हो सकता है। यातायात ने मनुष्य को याद दिलाने के लिए इतना लिखता ही परोक्ष है कि जो देश यातायात का दृष्टि में विच्छेद हुए हैं वे हर दृष्टि में—आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक—विच्छेद हुए मिलेंगे। समाज के विकास का एक बड़ा आधार मनुष्य का मनुष्य से संपर्क है और वह यातायात के बिना संभव नहीं। इसीलिए प्रचालन-संस्थाओं का जन्म स्थान समाजशास्त्र, नाल, वायुमय, जलमय और मृदाय का नदियाँ की स्वरूपा रहा है। आज भी विच्छेद हुए देशों का आर्थिक और दूसरे प्रकार का प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उनके यातायात के साधनों में समुचित उन्नति हो।

यातायात की सुविधा में हमारा कठिनाई और सब कुछ दृष्टि से बढ़े हुए भी मालूम पड़ सकते हैं। हमारे पास एक कोने का आवास और कठिनाई का अंतर सारे समाज में फैल जाता है। मानव का महार शक्ति को भी इसमें प्रोत्साहन मिला है और उसका जन्म व्यापक हुआ है। पर वह भी इसी बात है कि अर्थो में कठिनाई आज का भी उर हाथों में पड़ कर दुष्प्रयोग हो जाता है। यदि मानव समाज यदि तो उन्नत यातायात के साधनों में उत्पन्न हमारे तरफ से मानव कल्याण के लिए उपयोग हो सकता है—इसमें यातायात का वास्तविक महत्त्व है।

भारत और यातायात के प्रमुख साधन—भारत के यातायात के साधनों का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम रेल यातायात, सड़क यातायात, जल यातायात, वायु यातायात सभी का अलग अलग से अध्ययन करें।

रेल यातायात-भारत—उत्तीर्णता शताब्दी के पूर्वार्द्ध में (१८४१) जब सर नुकटानल स्टिफेन्सन ने दिमाग में भारत में चलने से उत्तर पश्चिम की

(५) कम्पनी के प्रबन्ध में राष्ट्र के हित की अपेक्षा तत्काल के लाभ का अधिक ध्यान रहा है।

(६) रेलों में लगी पूँजी का बहुत थोड़ा अंश कम्पनियों का है। उनका आर्थिक स्वार्थ कम होने से अच्छी व्यवस्था करने की उनको विशेष चिन्ता नहीं हो सकती। राज्य को चयेष्ट मात्रा में नियंत्रण रखना ही पड़ता है। ऐसी हालत में सारा प्रबन्ध राज्य के हाथ में आ जाने से कोई बड़ी कटिमाई नहीं होने वाली है।

एकदर्थ कमेटी ने इन सब बातों पर विचार करके राज्य द्वारा रेलों के प्रबन्ध किये जाने के पक्ष में अपनी राय दी। रेलवे फाइनेन्स कमेटी और इंडियन रिट्रूचमेंट कमेटी ने भी, जिन्होंने १९२१-२३ तक की रेलवे स्थिति पर विचार किया था, इसी पक्ष में राय दी थी। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया। परिणामस्वरूप १ जनवरी १९२५ को राज्य ने ३० आई० और १ जुलाई १९२५ को ३० आई० पी० रेलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद भारत सरकार ने बराबर इसी नीति का पालन किया और आज भारत की सब रेलवे राज्य के प्रबन्ध में हैं। १ अप्रैल १९५० से देशी राज्यों के भारतीय संघ में शामिल हो जाने के कारण उनकी रेलवे भी भारत सरकार के प्रबन्ध में आ गई। इस प्रकार लगभग ७५६० मील लम्बा रेल मार्ग भारत सरकार के पास और आ गया। अब भारत की तमाम रेलें भारत सरकार की रेलवे मिनिसू के नियंत्रण में हैं।

रेलों का शासन—प्रबन्ध—भारतीय रेलों पर हमेशा से ही भारत सरकार की देख-रेख और नियंत्रण रहा है। आरम्भ में भारत सरकार के सांख्यिक निर्माण विभाग के पास रेलों की देख-रेख का काम था। पर जब रेलों का काफी विस्तार हो गया तो यह व्यवस्था अपर्याप्त साबित हो गई। परिणाम स्वरूप १९०५ में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। बोर्ड में बोर्ड के अध्यक्ष के अतिरिक्त दो और सदस्य थे। बाद में भारत सरकार के व्यापार-उद्योग विभाग के अधीन था। बोर्ड के विषय में समय-समय पर साधारण परिवर्तन होते रहे हैं। १९०८ में भारत सरकार के व्यापार-उद्योग विभाग के हस्तक्षेप को अपेक्षाकृत कम करने की दृष्टि से बोर्ड के अध्यक्ष के अधिकारों में थोड़ी वृद्धि कर दी गई। अब उनको भारत सरकार के मंत्री का पद मिल गया और वाइसरॉय तक उनकी सीधी पहुँच हो गई। १९३७ में बोर्ड के त्रि सलाहकार का एक नया पद कायम किया गया। जब एक वर्ष कमेटी रेलवे सम्बन्धी जॉब करने के लिये नियुक्त हुई तो उसने भी इस प्रश्न पर विचार किया, और १९२४ में फिर रेलवे बोर्ड का

बोर्ड का अतिरिक्त मेम्बर बना रहेगा ।

रेलवे एकाउन्ट्स का काम भी १९२५ से रेलवे बोर्ड के पास आया है । पहले वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पास यह काम था । आडिट का काम एकाउन्ट्स ने अलग है और भारत के आडिटर जनरल के पास है ।

आपनी मामलों को मुलमाने के लिये १८७६ में ही रेलवे कानून को स्थापना की गई थी । १९०३ में इंडियन रेलवे कानून एग्रीमेंटेशन के नाम से इसे स्थायी बना दिया गया । यह एग्रीमेंटेशन रेलों के नीचे नियंत्रण में है और इसने काफी उपयोगी काम किया है ।

रेलवे वित्त व्यवस्था—रेलवे की वित्तव्यवस्था भारत सरकार की सामान्य वित्त व्यवस्था से अलग हो, यह प्रश्न एक छत से चल रहा था । जब एक वर्ष कमेटी के नामसे यह प्रश्न आया तो उसने पृथकीकरण के पक्ष में राय दी । रिटर्नमेंट कमेटी ने भी इस प्रश्न पर विचार किया और उसकी भी यही राय रही । २० सितंबर १९२४ को भारत सरकार व भारतीय धारा सभा ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पास किया । इस प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार की सामान्य वित्त व्यवस्था से रेलवे वित्त व्यवस्था को अलग करने का निश्चय किया गया । इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि प्रति वर्ष रेलवे बजट से भारत सरकार को एक निश्चित रकम मिलाने करेगी । यह निश्चित रकम कंपनियों अथवा देशी राज्यों द्वारा लगाई हुई पूंजी को छेड़ कर व्यापारिक रेलवे में लगी हुई बाकी सब पूंजी पर १% और इसके अलावा रेलवे से भारत सरकार को मिलने वाली उक्त निश्चित रकम काटने के बाद जो अरुल मुनाफा बचे उसका ३ भाग के बराबर होगी । भारत सरकार को रेलवे से मिलने वाली यह निश्चित रकम रेलवे की अरुल आय पर पहली बोन बारा मानी गई थी । यदि किसी वर्ष रेलवे आय उपर्युक्त १% चुकाने के लिये काफी न हो तो अगले वर्षों की आय में से यह रकम सबसे पहले चुकाई जाये और उसके बाद ही मुनाफा का बटवारा किया जाय—यह भी निश्चित किया गया था । सामरिक महत्त्व की रेलों में लगी हुई पूंजी पर व्याज और उनमें होने वाली हानि भारत सरकार को मिलने वाली निश्चित रकम में से कम करली जायगी और बाकी की रकम भारत सरकार को दी जायगी, यह भी साफ कर दिया गया था । यह भी तय था कि भारत सरकार को दी जाने वाली निश्चित रकम चुकाने के बाद जो बच जाये वह रेलवे रिजर्व में जमा हो । अगर वह रकम किसी साल ३ करोड़ रुपय से ज्यादा हो तो तीन करोड़ से ज्यादा रकम का २१३ रेलवे रिजर्व को और बाकी का ६१३ भारत सरकार को दिया जाय । रेलवे रिजर्व का नीचे लिखे अनुसार उपयोग होना

निश्चित हुआ था—भारत सरकार को दी जाने वाली वार्षिक रकम चुकाने के लिये, घिसावट की चढ़ी हुई रकम चुकाने के लिये वृद्धों को कम करने या वेवाक करने के लिये, और रेलवे का आर्थिक स्थिति को सुन्दर करने के लिये नाफि जतना को अधिक सुविधायें दी जा सकें और किंगड में कमी की जा सके। रेलवे को भारत सरकार द्वारा निश्चित शर्तों के अनुसार किसी स्वरूप के निरुत्त साल की आमदना में गुजादश न होने पर अस्थायी कूट लेने का अधिकार भी दिया गया। यह शर्तें वृद्धों का रिजर्व से लिया जा सकता है और आगामी लोगों की आय में से सुराया जा सकता है, यह भी इस प्रस्ताव में कहा गया था। इस प्रस्ताव में केंद्राय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की 'स्टैंडिंग फाइनेंस कमिटी फॉर रेलवेज' बनाने का निश्चय भी था।

रेलवे वित्त व्यवस्था के अलग हो जाने पर पश्चात् और भी कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये गये। घिसावट काय का निमाग हुआ जिसमें हर साल ग्लेवे आय में कुछ रकम जमा होती थी। रेलवे के लिये बिना वित्त विभाग के हस्तक्षेप के, कई वर्षों के आचार पर अपना धोरण बना सकता था अब सम्भव हो गया। आर्थिक रूप से समाप्त होने पर स्वयं लागू हो जाय का अब भय नहीं रहा।

मार्च, १९४३ में, रेलवे की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने से, उक्त प्रस्ताव के उस हिस्से में जिसका सम्बन्ध भारत सरकार की दी जाने वाली वार्षिक रकम और रेलवे के मुनाफ में उभर हिस्से से था यह संशोधन कर दिया गया कि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार होने तक हर साल का स्थिति दत्त कर इस रकम का निश्चय किया जायगा। यह संशोधन प्रस्ताव (कमेन्शन) दिसम्बर १९४६ में भारतीय संसद द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव का मुख्य-मुक्त्य माने इस प्रकार है—

(१) रेलवे वित्त व्यवस्था भारत सरकार का नामावित्त व्यवस्था से अलग बनी रहे। माधुर्य के लिये का भारतीय ग्लेवे का एक मात्र हिस्सेदार माना जाय और रेलवे में लगा वृद्धों पर ४०० दिविक्रम मिलने की उम्मीदारी हो जाय।

(२) डिपॉजिटेशन रिजर्व पंड में प्रति वर्ष कम से कम २५ करोड़ रुपये जमा किया जाय।

(३) रेलवे रिजर्व पंड का उपयोग नीचे लिखे अनुसार ही किया जाये—

(i) भारत सरकार का निश्चित दिविक्रम देने के लिये। और

(ii) बजट के घाटे को पूरा करने के लिये।

(४) नीचे लिखे उद्देश्यों से एक रेलवे डेवलपमेंट पंड खोला जाय—

(i) मुसाफिरों को सुविधायें देना ।

(ii) मजदूर-हितकारी कार्य करना ।

(iii) उन रेलों का निर्माण करना जो आवश्यक हों पर निर्माण के समय लाभप्रद न हों । जो 'वेटरमेंट फंड' है वह इस फंड में इस शर्त के साथ मिला दिया जाये कि आगामी पांच वर्षों तक तीन करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मुसाफिरों की सुख-सुविधा पर खर्च किये जायेंगे ।

(५) 'लोन अकाउन्ट' और 'ब्लॉक अकाउन्ट' को अलग-अलग कर दिया जाये । 'लोन अकाउन्ट' रेलवे में लगी पूँजी का रहे और 'ब्लॉक अकाउन्ट' जो 'एसेट्स' हैं उनका रहे, चाहे वे रेलों की आय में से खरीदे जायें और चाहे श्रव्य से ।

(६) कौनसा खर्च पूँजी से हुआ माना जाये और कौनसा चालू आय में से इसके नियमों में भी परिवर्तन किये गये हैं । जैसे रिट्रोसमेंट का सुधार सहित बड़ी हुई क्षीमता को मान कर पूरा खर्चा डिप्रीसियेशन फंड से होना चाहिये । साधारण सुधार और नये काम २५००० तक का खर्च मान्यता आय में से होना चाहिये । लाभ नहीं देने वाली लाइनों पर उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने सम्बंधी खर्च जो तीन लाख रुपये से अधिक न हो साधारण आय से और तीन लाख से जितना अधिक व्यय हो वह रेलवे डेवलपमेंट फंड से होना चाहिये । जो नई लाइनें बनाना आवश्यक हैं पर लाभदायक नहीं उनके निर्माण का खर्च हो सके वहाँ तक रेलवे डेवलपमेंट फंड से किया जाना चाहिये । जो स्ट्रैटेजिक रेलों पर जिनसे लाभ नहीं मिलता है खर्च हो वह पूँजी के नाम से होना चाहिये पर इस पूँजी पर कोई डिविडेंड नहीं दिया जायगा ।

रेलवे की आर्थिक स्थिति—उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक भारतीय रेलें हानि का सौदा ही रहीं । धीरे-धीरे माल और मुसाफिरों का आना-जाना बढ़ने लगा । पंजाब में नहरों के निर्माण से खेती की तरफ़की हुई और उनमें भी रेलवे की आय बढ़ी । सन् १९०० में पहली बार रेलवे ने राज्य को धोखा का लाभ हुआ । १९०८-१९०९ के साल को छोड़कर १९२०-२१ तक रेलों को बराबर मुनाफ़ा होता रहा । १९२१-२२ में फिर हानि का जानना करना पड़ा । जैसा पहले लिखा जा चुका है १९२४ में रेलवे की वित्त व्यवस्था भारत सरकार की सामान्य वित्त व्यवस्था से अलग कर दी गई थी । १९१९-२० से १९२९-३० तक का समय कुल मिलाकर भारतीय रेलों के लिये आर्थिक सफलता का समय रहा । कुल आय १९१९-२० में ८६.१५ करोड़ रुपये से १९२९-३० में ११६.०८ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी । इसी प्रकार चालू खर्च भी ५०.६४ करोड़ से

७५.४६ करोड़ का हो गया। असल बचन ३८.४६ करोड़ रुपया हो गई। डिप्रीसियेशन फंड ११.१० करोड़ वार्षिक व हिसाब स जमा हुआ। 'ओपरेटिंग रेसियो' ६०% के लगभग था। निमावट की निमान दन पर यह ५-१० हो आता था। लगा हुआ पृथी पर असल आय ५.३८ प्रतिशत हुई। १९२४ से १९३० व बीच में राय को आंखतन ५.६८ करोड़ रुपया साल मिला और रिजर्व फंड में २.७६ करोड़ रुपया साल जमा हुआ।

१९३०-३६ का समय 'वाणिज्यिक मंदी' का समय था १९३३-३४ तक चलती रही आर्थिक दृष्टि में मनोपयत्नक रहा रहा। इस समय में पहले ७ वर्षों में औसत आय घट कर ६५.०६ करोड़ वार्षिक हो गई। 'ओपरेटिंग रेसियो' (डिप्रीसियेशन सहित) ७०% हो गया और पृथी पर मिलने वाला असल आय ४.३८ रहा था। १९२६-३० से १९३६-४० व बीच में रिजर्व फंड में जो रुपया था वह ब्याज उठाने और १९.०० में भारत सरकार का वार्षिक रकम उठाने में लगाने हो गया और इससे अनायास डिप्रीसियेशन फंड से ३० करोड़ रुपया ब्याज उठाने के लिए उधार लिया गया तथा भारत सरकार को दा भाने वाला वार्षिक रकम का १६.०० में उठाना स्थगित कर लिया गया। यह बड़ा हुआ रकम ६३६.३७ तक ५०.७८ करोड़ रुपय का हो गया था। रेलवे का इस बिगड़ना हुआ आर्थिक स्थिति का मध्याह्न आवश्यक था। इन वर्षों में ताग कमटियों नियुक्त की गई रेलवे रिजर्वमें तन रकम (१९३३-३४ में १९४४-४५) और वजुद रकम (६३७)। इन कमटियों ने भारत के रकम रकम रकम का कई सिफारिश की और तहाँ तक समय हुआ ताकी स्वीकार भी किया गया। आगिरफार १९३६-३७ में आर्थिक स्थिति ने पलटा गया और १९३७ करोड़ का ब्याज उठाने के बाद रेलवे को लाभ हुआ। डिप्रीसियेशन फंड से लिया हुआ अर्थ का नियमानुसार रकम व लाभ में से सबसे पहले उठाना तागि या कुछ वर्षों तक (१९४३ तक) नहीं उठाने का प्रस्ताव पाल किया गया। रकम का ग्राम वनी धार धारे वक्त लगा। १९२६-४० में कुल आय २२२.५ करोड़ रुपया था यह जब कि १९२६-३० में १९६.०२ करोड़ रुपय था।

१९३६ में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो गया। रलों का आय और बढ़ने लगी। १९४४-४५ में कुल आय २.६२ करोड़ रुपय तक पहुँच गई। असल आय भी १९२६-४० में २२ करोड़ से १९४३-४४ में ७६ करोड़ हो गई। और इसी वष में ५०.८४ करोड़ रुपय का सरप्लस (बचत) रहा। १९४३ तक डिप्रीसियेशन फंड का अर्थ भारत सरकार का बनाया वार्षिक दनदारी का रुपया भी चुका दिया गया।

द्वितीय महायुद्ध के बाद रेलों की आर्थिक स्थिति फिर बिगड़ी। युद्ध का असर तो था ही पर देश के विभाजन से भी कई समस्याएँ लड़ी हो गई थीं। शांति-व्यवस्था के भंग होने से भी बहुत हानि हुई। इसका असर आर्थिक स्थिति पर पड़ना स्वाभाविक था। रेलवे की आय कम हो गई। खर्चा बढ़ गया। देश के विभाजन के बाद १५ अगस्त १९४७ से ३१ मार्च १९४८ के बीच में रेलवे बजट में २७४ करोड़ का घाटा हुआ जिसकी पूर्ति रिजर्व फण्ड से करनी पड़ी। इसके बाद १९४८-४९ में स्थिति थोड़ी सुधरी और रेलवे की कुल आय की दृष्टि से तब से स्थिति में बराबर सुधार आता जा रहा है। रेलवे का कुल आय १९४७-४८ में १०१ करोड़, १९४८-४९ में २१३.१० करोड़, १९४९-५० में २३६.३५ करोड़ थी। १९५०-५१ के संशोधित आंकड़े के हिसाब से कुल आय २६३.४० करोड़ थी और १९५१-५२ में २७९.५० करोड़ की कुल आय का अनुमान किया गया है। रेलवे की असल आय (नट रेवेन्यू) के आंकड़े (रुपये में) इस प्रकार हैं :—१९४७,४८ से १० ५३ करोड़, १९४८-४९ में ४२.३४ करोड़, १९४९-५० में ३७.७७ करोड़, १९५०-५१ में संशोधित अनुमान ४६.८१ करोड़ और १९५१-५२ के बजट के अनुसार ५५.२२ करोड़। पिछले तीन वर्षों के अन्तर्गत वचत के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं—१९४९-५० में १४.५९, १९५०-५१ (संशोधित अनुमान) १४.२४ और १९५१-५२ (बजट अनुमान) में २१.८५ करोड़ रुपये। डिप्रीसिएशन फंड, रिजर्व फंड और डेवलपमेंट फंड तीनों में १९४९ ५० के आखिर में कुल मिला कर १२९.६३ करोड़ रुपये थे वह १९५०-५१ के आखिर में संशोधित अनुमान ने १५०.९४ करोड़ और १९५१-५२ के आखिर में बजट अनुमान से १६०.८८ करोड़ रुपये हो गये। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पिछले वर्षों में रेलवे की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

रेलवे जाँच कमेटीयाँ—सन् १९२०-२१ में रेलवे संबंधी प्रश्नों की जाँच करने के लिये भारत सरकार ने एक वर्ष कमेटी की नियुक्ति की थी। उसके विषय में पहले झिंक आ चुका है। पिछले तीन वर्षों में तीन और कमेटीयाँ नियुक्त हुईं। संक्षेप में इनके बारे में हम यहां लिखेंगे।

पहली कमेटी १९३२ में पोप कमेटी के नाम से नियुक्त हुई थी। विश्व मंडी के समय जब रेलवे की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी तो इस कमेटी की नियुक्ति हुई। पोप एक अंग्रेज़ रेल विशेषज्ञ थे। उन्होंने यात्रियों की संख्या बढ़ाने और भात के आयातमन को बढ़ाने संबंधी कई सिफारिशें कीं। जहां मोटर की प्रतिस्पर्धिता कमी थी वैसे सिंगिल और बोक-एंड रिटर्न ट्रिजिट जारी किये गये, मातल का भाड़ा कम किया गया, पार्सल सेने देने के लिये शहरों में दफ्तर खोले

गये। तीर्थ दगनों के निचे स्वेचन ट्रेने चलाई गई। पांच कमटी का एक महत्वपूर्ण सिफारिश 'जोब एनेलिसिस' से सम्बन्ध रखती था। स्वस्थ-राम रेलवे में 'जोब एनेलिसिस' के निचे संगठन प्रथम क्रिय गये। इनका काम रेलवे के प्रत्येक काम का स्व निगाह से जांच करना था कि वह यह बना मँके का कामतमना में सुचारु करने के निचे और क्रियायत करते के निचे क्या करना चाहिये। यह काम के तराजों में सुधार हा गया तो यह संगठन समाप्त कर दिया गया। इस कमेटी ने एक्जिन, वैटने का गार्डिया, मरानगी और नाट का पूरा पूरा उपयोग करने, बसार् बगन को निवारण दे, विभिन्न रेलों के कार्यों का एकाग्रण करने, बिना डिस्ट्रिक्ट का यात्रा पर रोज लगाने और आन्दन बढ़ाने के बारे में भी सिफारिशों की थी।

दूसरा कमटी वेल्थुड कमेटी थी जो १९७५ में गठित हुई थी। इसी साल इस कमटी ने प्रस्ताव रिपोर्ट पेश की। इसका मुख्य मुख्य सिफारिशें ये थी --

भारत सरकार का रेलवे से जो सम्बन्ध रखना ही जाना है वह नहीं बना चाहिये। डिप्रोपियेशन और जनरल रिजर्व फंड में कटौत करनी चाहिये। स्टेशन में होने वाला प्रतिस्पर्धा का काम सर्वप्रथम पारस करार ट्रेनों की गति बढ़ा करके तथा अन्य उपयोगों से मुक्तकला करना चाहिये। एनक्विरींग स्टेशन में दुरोपयोग लीनों की सम्ख्या बढ़ाने चाहिये ताकि वे रोलिंग स्टॉक में अधिक काम ले सकें। समाचारपत्र, 'नगरियों' आदि से अधिक संपर्क रखना चाहिये। एक प्रशासन कार्यालय का स्थापना होना चाहिये। सुराविसा स्टेशन बढ़ाने और भारत सरकार का इस नाम वाला काम राकने सम्बन्धी सिफारिशों का देश में संपूर्ण विरोध हुआ। सरकार ने इन सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। पांच कमटी का क्रियायत सम्बन्धी सिफारिशों का भा इस कमटी ने समर्थन किया था। इस कमटी की स्थापना १९६५ के नियम लागू होने के पहले समय का स्थिति की जांच करने के लिए हुई थी।

(तीसरी कमटी वुल्थुड कमटी के नाम से विख्यात है जो १९६९ में गठित हुई थी। देश का विमानन होनाने में यह कमटी श्रद्धा बरह से अपना काम नहीं कर सका। इस कमटी ने रेलवे के रीग्रूटिंग की सम्स्या को विलम्बाल स्थगित कर देने और रेलवे बोर्ड की अगह यूनिटन रेलवे प्रोपेर्टी का स्थापना करने की सिफारिश की थी। मजदूरों की कायनमना में जमा आवाने का भा इस कमटी की रिपोर्ट था। इस की राय में मजदूरों को जिन्ना देने में ही यह कमी पूरी हो सकती है।

रेल माहा नीति — भारतीय रेल से सम्बन्ध रखनेवाला एक विधाया

स्पष्ट प्रश्न यह रहा है कि भारतीय रेलों की भांति नीति देश की आर्थिक उन्नति में सहायक नहीं रही है। इसके अलावा यूरोपियनों के साथ पक्षपात करने की भी शिकायत रही है। कच्चे माल और खाद्यान्न के निर्यात और तैयार माल के आयात को भारतीय रेलों ने बराबर प्रोत्साहन दिया है। औद्योगिक कमीशन (१९१६), क्लिकल कमीशन (१९२१) और एकवर्षीय कमेटी १९२०-२१ के सामने भी इस तरह की शिकायतें की गईं थीं। एंग्लो-कलचरल कमीशन (१९२७) ने भी इस प्रश्न पर विचार किया था। इन सबकी यह राय थी कि इस बारे में सुधार की आवश्यकता है। एकवर्षीय कमेटी इंग्लैंड के १९२१ के रेलवे एक्ट के तहत नैसी रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल है उसी तरह की ट्रिब्यूनल की भारत के लिये भी सिफारिश की। भारत सरकार ने इस तरह की स्वतन्त्र ट्रिब्यूनल तो नियुक्त नहीं की पर एक रेलवे एडवाइजरी कमेटी अवश्य १९२६ में बनाई। इसकी सिफारिशें सरकार के लिये मानना अनिवार्य नहीं थी। इसलिये इसमें कोई खास लाभ नहीं हुआ। पर भारत के स्वतन्त्र होने के बाद नई रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल १९४६-५० में नियुक्त हो चुकी है।

पुरी जंक्शन पड़ताल के बाद अक्टूबर १९४८ से भांडा सम्बन्धी नई व्यवस्था जारी की गई है। पहले की अपेक्षा यह व्यवस्था अधिक सरल है। अपवादों को हटा दिया गया है। पहले की प्रलेट क्लास रेट्स के बजाय अब 'टेलिकोपिक क्लास रेट्स' जारी की गई हैं जिसके अनुसार दूरों के वृत्तों के साथ-साथ भाड़े के दर में कमी आती है। कई प्रकार के कच्चे माल, जैसे कच्चे खनिज पदार्थ, जिपसम-चूना, चूना पत्थर, रेत, पिंग आइरन, रही (स्कोप) लोहा और इस्पात, कोयला, गन्ना, आदि पर भाड़ा कम कर दिया गया है। कुछ कच्चे माल के लिये, जैसे चमड़ा, तिलहन, नमक आदि, वेगन को दरें कम कर दी गई हैं। भारतीय कारखानों में तैयार माल—जैसे सीमेंट, रासायनिक खाद, राफ्ट, लोहा-इस्पात, कौस्टिक सोडा आदि पर भी भाड़ा कम किया गया है। रेलवे के जिम्मे पर जानेवाली चीजों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। भेजने वाले के जिम्मे पर जाने वाली और रेलवे के जिम्मे पर जानेवाली चीजों के भाड़े में पहले की अपेक्षा बड़ा वाजिब अन्तर कर दिया गया है। भाड़े की इस नयी व्यवस्था से निर्यात-आयात व्यापार को अनुचित प्रोत्साहन देने की और देश के औद्योगिक विकास में बाधक होने की शिकायत तो अब नहीं रही है। पर 'टेलिकोपिक प्रणाली' और संशोधित भाड़े को धरो का सम्मिलित अंतर यह हुआ है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के बन्दरगाहों में स्थित कारखानों को पहले की तरह अब भी अनुचित रियायत मिल जाती है। नई भाड़ा व्यवस्था का

परिव्याप्त थोड़े दूर की अपेक्षा अधिक दूर जानेवाले माल की प्रोत्साहन देने का भाग्य है। इसका अन्तर कच्चे माल की नहरों में ही उपयोग में लाने के प्रतिफल पड़ा है। थोड़ा दूर जाने जानेवाले माल के भाड़ा बढ़ने की भी शिकायत है। इसके जवाब में यह कहा जाता है कि चीजों का सामान जिस मात्रा में बढ़ा है उसके अनुपात में भाड़े में हुई वृद्धि नगण्य है। फिक्कल कमीशन (१९५०) ने अपनी रिपोर्ट में यह सिद्ध किया है कि औद्योगिक विप्लव-कारण का प्रोत्साहन देने के लिये रेलों के अधिकारियों को भाड़ा नीति में आवश्यक गतिमान करने के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं कि कच्चे माल की जहाँ वह पैदा होता है उससे पास ही तैयार माल की शुल्क में बढ़ाने में सुमीना हो। कच्चे माल और तैयार माल के लिए स्टेशन से स्टेशन के बीच में जो भाड़े की विभाग करें निश्चित करने का नीति अपनाई गई है उसका अधिक उदारता के साथ पालन करने का भाग फिक्कल कमीशन ने सिद्ध किया है।

रेलवे द्वारा आवागमन की स्थिति — पिछले वर्षों में रेल यात्रा करने का निम्नलिखित कारणों से बहुत बढ़ गया था। उनमें से एक यह है। यहाँ हम सक्षेप में इस सम्बन्ध में विचार करेंगे। कुछ वर्षों की अपेक्षा के रूप में यदि छोड़ दिया जाए तो दिल्ली की रक्षादिवा में रेलों अपने 'मॉडर्न' और 'रिट्चर्ड्स' (ट्रैट्ट सुधार और मरम्मत) पर पर्याप्त मात्रा में खर्च नहीं कर सके हैं। आज की स्थिति यह है कि १९५० में एक निहाई एंजिन और एक बोयार्ड माल के और मुलाफिरो के बिना अपना आगु पूरी कर चुके थे। विश्व मशीन के समय में आर्थिक समस्या मुख्य थी। रेलों की आवश्यकता कम हो गई थी। परिव्याप्तस्वरूप उनकी पूंजागत खर्च (कॉप्टल आउट ल) कम करना पड़ा। दूसरे गश्त उद्घ के समय और युद्ध के बाद रेलों की समस्या एक ता शक्ति का सक्षेप बढ़ाने की और दूसरा सामान आदि नहर मिलाने का रही है। जब जापान लड़ाई में शामिल हो गया तो समुद्रमार्ग आवागमन बहुत कम हो गया और वह सारा बोझ पास और से बोझ का लान लेनाने का रेलों पर आ पड़ा। इससे साधारण जनता के लिये उपलब्ध डिब्बों का कमी आ गई। रेलवे सरकारें युद्ध सामग्री धनाने के काम में लग गयी। इसका भाग अपर रेलों का कार्य-क्षमता कम करने का हुआ। रेल के यात्रियों की संख्या प्रायः युद्ध के पहले की अपेक्षा २५ गुनी होगई है। १९३८-३९ में जितनी रेलों में यात्रियों की स्थान मिलना था उसी की माप-वज्र मान लें तब भी मीनूदा डिब्बों का मख्या को दुगुनी कर देने से भी आज काम नहर चल सकता। सामान लाने ले जाने के बिना का भाग भारी कमी आ है। युद्ध के समय में जो लाहने नष्ट करदी गई थी उनकी दुवारा वनवाला

हैं। और भी कई प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता है। मुसाफिरों की, खास तौर से तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को, सहूलियतों को बढ़ाने का भी सवाल है। इधर रेल किराये में बराबर वृद्धि होती जा रही है। इन सब बातों का सार यह है कि मुद्र के वर्षों में रेल द्वारा आवागमन की स्थिति काफी बिगड़ गई थी। देश विभाजन से इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। मोर्थ वेस्टर्न रेलवे और आसाम-बंगाल रेलवे का अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया है। सांप्रदायिक भगड़ों के कारण भारत और पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन का बड़े पैमाने पर परिवर्तन होने से भी अव्यवस्था फैली। वृद्धत कुद्ध अंग्रेजी स्टेशन भी स्वतन्त्रता आजाने के साथ-साथ चला गया। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मुद्र के समय की स्थिति का तो फिर भी जैसे-तैसे नुकाबला कर लिया गया था, पर १९४७ और १९४८ में तो रेलों की व्यवस्था बिल्कुल ही बिखरने की सीमा तक पहुँच गई थी। पर यह संतोष की बात है कि पिछले दो-तीन वर्षों में स्थिति में लगातार सुधार होता जा रहा है। बाहर से नए इंजिन मँगाये गए हैं और आगे भी मँगाये जायेंगे। डिब्बों की कमी को पूरा करने का प्रयत्न भी जारी है। चितरंजन लोको मोटिव वर्कशॉप से २६ जनवरी, १९५० से काम करना शुरू कर दिया है और १९५१-५२ के आर्थिक साल में ३६ नए इंजिन यहाँ तैयार होने की आशा है। माल के डिब्बे और मुसाफिरो के डिब्बे तैयार करने के लिये और कारखाने शुरू करने की भी योजना है। मुद्र के समय में जो माल ले जाने-लाने के बारे में प्राथमिकता पद्धति (प्राथमिक सिस्टम) जारी की गई थी वह अब हटा ली गई है। केवल रेलवे बोर्ड को प्राथमिकता की स्वीकृति देने का अधिकार है पर यह अधिकार बहुत कम काम में लाया जाना है। रेलवे गाड़ियों की संख्या बढ़ा कर, और तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के लिये जनता एक्सप्रेस चालू करके भीड़ को कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हालांकि इस समय भी स्थिति में काफी सुधार की आवश्यकता है। मीटर गेज की रेलों पर अब तक बहुत कम ध्यान दिया जाता रहा है। अब इस दिशा में भी अधिक ध्यान देना शुरू हुआ है। रेलवे स्टोर्स के बारे में विचार करने के लिये एक कमेटी की दिसम्बर १९५० में नियुक्ति की गई थी जिसने सारी स्थिति पर विचार करने के लिये एक कमेटी अप्रैल १९५१ में पेश कर दी है। कमेटी ने यह सिफारिश की है कि स्टोर्स खरीदने की वर्तमान व्यवस्था जिसमें रेलवे के अलावा भारत सरकार के दूसरे मंत्रालय भी रेलवे स्टोर्स खरीदते हैं, असंतोषजनक है, और उसमें आमुल परिवर्तन करना आवश्यक है। 'रेलवे स्टोर्स' की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिये रेलवे बोर्ड के तहत में एक केन्द्रीय स्टोर्स संगठन कायम

करने, और सामान के स्टेशनडाईजेशन का और विविध ध्यान देने की कमेटी ने
मिफारिश का है। वैज्ञानिक खोज की प्रतिक्रिया अच्युती सुविधा पर भी कमेटी ने
ज़ोर दिया है। कमेटी की सिफारिशों का रेलवे मंत्रालय ने स्वीकार
कर लिया है और उक्त अनुसार कार्रवाई करने का प्रयत्न
आरम्भ हो गया है। मज़दूरों के दिनों का आर ध्यान किया जा रहा है
यद्यपि मज़दूरों का मांगे अनुसार नहीं हो सका है और मज़दूरों का मानव
जब तब उत्पन्न होता रहता है। रेल दुरुस्ती का काम करने का भी प्रयत्न
किया गया है। दो पैसे विज्ञापन का इस्तेमाल सुझाया गया था कि उस पर
एकतिन और रेल मार्ग पर बार में जान करन अपना रिपोर्ट दें। उनकी रिपोर्ट
भारत सरकार के विचारणीय है। मार्ग दूर के मुसाफिरों की अधिक सुविधा
की व्यवस्था करने का एक उपाय तो भाड़ का काम करने का है हा, जिसका ऊपर
उल्लेख किया जा चुका है। इसमें अलावा मानव दान के विचार और मुसाफिर-गानों
में विज्ञापन के पत्रों तथा स्टेशन पर जाने पाना को सुविधा करने की ओर भी
ध्यान दिया गया है। स्टेशनों पर बिजली का रोगना का प्रयत्न भी किया जा रहा
है, और प्लेटफार्मों पर छाया करा जा रही है। डिब्बों में बैठने का अच्युती
सुविधा, उनका का अच्युती पत्रों टिकट बांटने की अधिक सुविधा आदि बातों
की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। पर इस सम्बन्ध में रेलवे अधिकारियों
को अधिक समझ बूझ से काम लेने का आवश्यकता है। उदाहरण के लिए
तामरे दूने के मुसाफिरों का स्पीडब्रेकर के ठोड़ पाना का और मुसाफिर-घरों में
बिजली के पत्रों का इतना आवश्यकता नहीं है जितना बिजली की गुंजाइश बढ़ाने,
घैटन की दृष्टि से उनको अधिक सुविधाजनक बनाना, जिन्हा में आदर चलते फिरने
के लिये विशेष गुंजाइश करने और सामान रात की अधिक अच्युती व्यवस्था करने
का ज़रूरत है। इसमें अलावा तीसरे दान का का किराया बढ़ाया गया है वह
बहुत ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में दूसरे दर्जा से तुलना करना गर्वधा
होना चाहिए। अगर हम ग्लोब में तामरे दूने का किराया यहाँ से पांच गुना
और अमेरिका में चार गुना है तो यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि इंग्लैंड
का औसत आय यहाँ से २४ गुनी और अमेरिका का २४ गुनी है।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यद्यपि पिछले तीन वर्षों में रेल द्वारा
आवागमन की स्थिति सुधार की ओर जा रहा है पर अभी बहुत कुछ करना
पानी है। और तामरे दूने के मुसाफिरों के लिये अधिक प्रिक से काम लेने
का ज़रूरत है।

रेलवे का फिर से समुन्नीकरण—इस समय भारतीय रेलों की व्यवस्था

अलग-अलग कंपनियों के आधार पर होती है, हालांकि सब में प्रबंध का जिम्मा भारत सरकार का ही है। कुछ समय से इस व्यवस्था की वज्राय देश की समस्त रेलों को प्रदेश के आधार पर बांटने का प्रस्ताव चल रहा था। रेलवे बोर्ड की एक उपसमिति भी इस प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई थी। इन कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करने के पहले राज्य की सरकारों, व्यापारिक संस्थाओं, रेलवे मजदूरसंघों की राय भी जाननी गई। सबने कमेटी की सिफारिशों का सामान्यतया समर्थन किया है। प्रस्ताव यह है कि भारतीय रेलों को छह बड़े जोनों में तैयार किया जाये। जोंन बनाने समय एक नौ इस काम का ध्यान रखा जाये कि प्रत्येक जोन में आर्थिक एकलपता हो और दूसरा यह कि दृष्टिकोण की स्वाभाविक दशा क्या है? जिन छह जोनों में समस्त रेलों को बांटने का प्रस्ताव है वह इस प्रकार हैं—(१) मध्यवर्ती रेलवे (५३१५ मील) जिसमें बी० बी० एड० सी० आई० की बड़ी लाइन, जो० आई० पी० का अधिकांश भाग, और मिथिया और णालपुर राज्य रेलों का समावेश होगा (२) पश्चिमी रेलवे (५५२२ मील) जिसमें बी० पी० एड० सी० आई० की छोटी लाइन (कानपुर आगरा रूट के अलावा) और सीराष्ट्र राजस्थान और कच्छ की रेलों का समावेश होगा। (३) दक्षिणी रेलवे (५७२४ मील) जिसमें एम० आई० एम० एड० एम० एम० और मैदानी रेलों का समावेश होगा। (४) पूर्वी रेलवे (५०१६ मील) जिसमें मिजाम राज्य और जी० आई० पी०, एम० एड० एम० एम० और बी० एम० रेलों के भागों का समावेश होगा। (५) उत्तर-पूर्वी रेलवे (६११६ मील) जिसमें धो० एम०, ई० आई०, ओ० टी० रेलों के भाग, और आखाम तथा दार्जिलिंग-हिमालयन रेलों का समावेश होगा। (६) उत्तर-पश्चिमी रेलवे जिसमें कानपुर-लखनऊ के पश्चिम की रेलवे लाइन और बी० बी० एड० सी० आई०, ई० आई० और ओ० टी० के कुछ भाग तथा ई० पी० रेलवे का समावेश होगा।

उपयुक्त व्यवस्था से कई प्रकार के लाभ होने की आशा है। कार्य क्षमता में वृद्धि, खर्च में किञ्चायत और शासन प्रबंध में सुधार होने की पूरी आशा की जाती है। दो या अधिक रेलों के एक ही जोन में हो जाने से ऊँचे दर्जे का शासन प्रबंध का एकीकरण हो जायगा। इससे खर्च कम होगा। अलग-अलग रेलों के बीच में जो आज बहुत सा पत्र-व्यवहार होता है और आपन में लो कई तरह का मेल चिठाना होता है वह सब कम हो जायेगा। इससे काम भी जल्दी होगा, स्टाफ की कम आवश्यकता रहेगी और इससे खर्च में कमी आयेगी। व्यापारी-व्यवसायी वर्ग का भी अलग-अलग कंपनियों की वज्राय एक बड़े प्रदेश

में एक अधिकारी वर्ग में ही काम पड़ेगा। हमने उनको मुक्ति दी होगी। एनिन तथा डिन्ने आदि का बड़े प्रत्यक्ष म समुहोत्थान होने में अधिक अच्छा उपयोग हो सकता। रेलवे वक्साय का भी अधिक अच्छा उपयोग हो सकता। 'स्टोम' को बड़ा माया म एक बन्द्या व्यवस्था द्वारा गगदने आदि का प्रवर्धनीकरण से हो सकता। एक विचारधारा ऐसा भी है जो नए प्रकार के भूमि का बोध लाभ नहीं करता। इस विचारधारा में अगुमार करने में किनायत तो कुछ बातों में होगी पर वृद्धि अधिक बातों में हो जायेगा। नए इन्फ्रामाटम, वक्साय और स्टार फाउंडर बनाने में खर्च होगा। नए का दूर दूर तथादला होने लगेगा क्योंकि एक नौन में कई रेलें आयेगी। इसमें स्टार का अनुविधा बड़ेगा। इनका अंतर काम पर भी पड़ेगा। प्रवर्धन में मापन में स्थानीय स्वतंत्रता कम हो जाने से भी ज्ञानमता पर असर पड़ेगा। हमारे विचार से यह आशयिषा बहुत ठोस आशय पर उठा- हुआ नहीं है। इसके अन्तर्गत यह रत्न का मान यह है कि ज्ञान धन ममय ज्ञान आनन्दिक अवस्था का जो की वो रत्न का विचार है। इस समय अधिकांश रत्नों का व्यवस्था विभागाय आधार पर है न कि प्रादेशिक आधार पर। हम व्यवस्था से निरन्तर चिन्ता है वेही ही नवनी रहने का टाक होगा। इसमें स्टार का हार म उतर परिचयन भी अधिक नहीं होगा और न व्यवस्था का काम आसान से शुरू हो पायेगा।

उत्पुष्ट मय बातों पर विचार कर १९५१-५२ में दक्षिण ज्ञान का निमाण करने का भारत सरकार का विचार है। विभागाय आधार तो चारा रहगा, पर उद्घोकरण को कम करने में जिन मार ज्ञान का काम का दृष्टि से तीन सहायक प्रदिया में बांटने का हरादा है। इसके अर्थ यह है कि प्रत्येक विभाग में डिस्ट्रिक्ट (विभाग का आधार पर जो कम म कम क्षेत्र मय कर रखा है) अन्तर, सहायक प्रादेशिक अन्तर, विभागाय अन्तर और अनरल नौनर का मम रहेगा।

रत्ना का आर्थिक प्रभाव—हमारे मय में अधिकांश विकास का लिये रत्ना का महत्व है इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। यह ठाक है कि विदेशी शासन-काल में भारतीय रत्ना का विकास होने में उनका द्वारा कर प्रसार की राष्ट्र का हानि हुई है। हमारे औद्योगिक विकास में रत्ना का बाड़ा नानि बाधक हुई। हमारे यह उद्योगों का विनाश में वे सहायक हुई। हमारे रत्नों को उठाने करने इधन की आवश्यकता पूरी करने का लिये बड़ा किया। पर यह सब तो अब इतिहास की बातें हैं। आज तो भारत एक स्वतंत्र मय है और भारतीय रेलें राष्ट्रीय सरकार का उनके द्वारा मचालिन सबसे बड़ा उद्योग है। भारत के भारती

आर्थिक विकास के लिये रेलों का विस्तार आवश्यक है। देश के किसी प्रदेश में अकाल पड़ने पर रेलों से ही वहाँ अनाज पहुँचाया जा सकता है। रेलें ही कारखानों तक कच्चा माल और बाजार तक तैयार माल लातीं और ले जातीं हैं। लोगों को आने-जाने की सुविधा रेलों के कारण बहुत कुछ हुई है। रेलों से भारत सरकार को काफी आय होती है। इसी तरह के और लाभ भी गिनाये जा सकते हैं। रेलों का देश के आर्थिक जीवन में बड़ा महत्त्व है वह एक सर्वमान्य तथ्य है।

सड़क यातायात—हमारे देश में सड़कों की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। देश में चार तो बड़ी 'ट्रंक रोड' हैं। ये सड़कें बहुत पुरानी हैं। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण सड़क आंध्र ट्रंक रोड है जो कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली से खैबर तक जाती है। एक सड़क कलकत्ते से मद्रास, एक मद्रास से बंबई, और एक बंबई से दिल्ली को जाती है। इन सड़कों के अक्षाण फिर मध्यम सड़कें हैं जिनमें से कई इस ट्रंक रोडों से मिली हुई हैं। पर न तो ये सड़कें काफी हैं और न जो हैं उनकी हालत ही अच्छी है। इस असंतोषजनक स्थिति के कई कारण हो सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह रही है कि रेलों की अपेक्षा सड़कों पर ध्यान ही बहुत कम दिया गया। देश के विभाजन के बाद की भारत की सड़क-संबंधी स्थिति यह है कि १९४६ में कुल २३६,००१ मील पक्की (मेटल्ड) और कच्ची (ग्रान मेटल्ड) सड़कें हमारे देश में थीं। इनमें ८५,००० मील पक्की और १,५३,२६१ मील लंबी कच्ची सड़कें थीं। अगर मोटर चल सकने न चल सकने की दृष्टि से देखें तो १८१,४०६ मील लंबी मोटर चल सकने योग्य और ५७५,७५ मील लंबी मोटर नहीं चल सकने योग्य सड़कें थीं। सड़कों संबंधी हमारी इस स्थिति का दुनिया के कुछ दूसरे देशों से तुलना करने पर नीचे लिखी स्थिति सामने आती है :—

देश का नाम	वर्ष	जन सं०	सेक्टरल मोटर योग्य मोटर अथवा	कुल
			करोड़ ता०ब०मी०	सड़क मील सड़क मील मील
सं० रा० अमे०	(१९४०)	१६२२३०	२७ १,०००,०००	२,००६,००० ३,००६,०००
यूना० किंग०	(१९३६)	४६ ००८६	१६०,१२०	१६,१३० १,७६,२६०
फ्रान्स	(१९३६)	४२ २१३	—	— ४०५,०२८
भारत	(१९४६)	३१६ १२१७	१८१,४०६	५७,५७५ २३६,००१
पाकिस्तान	(१९४६)	७१ ३६५	५,५६६	४८,११६ ५५,६१३

उप्युक्त तालिका से यह मालूम पड़ता है कि भारत और पाकिस्तान में क्रमशः प्रतिवर्ग मील ०.१६ मील और ०.१५ मील लम्बी सड़क है, जब कि अमे-

रिका १ मील, ब्रिटन में ०.०२ मान, और फ्रांस में १.६ मील है। प्रति १००० व्यक्ति के पीछे भारत और पाकिस्तान में क्रमशः सड़क की लंबाई ०.७५ मील और ०.७६ मील है, जब कि अमेरिका में ०.०३ मील, युनाइटेड किंगडम में ०.०६ मील, और फ्रांस में ६ मील है। यदि हम सिंगा प्रदेशों का दृष्टि से विचार करें तो दक्षिण भारत में सड़कों की स्थिति सब से अच्छी और उद्योग, परिवहन, व्यापार, राजस्व आदि सभी पक्षों पर पुनः विचारों में स्थिति सब से अधिक गंभीर मिलेगी। हिमालय का निचला भाग हिमालयों की भाँति सड़क बनाने की स्थिति काफी असह्योग्य है।

सड़कों का वर्गीकरण—हमारे देश में सड़कों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है—(१) राष्ट्रीय सड़कें (नगनल हाइवेज) (२) प्रांतीय सड़कें, (३) जिला सड़कें, (४) गांव की सड़कें। राष्ट्रीय सड़कों द्वारा राज्य का राजधानियाँ, बड़े बड़े शहर और मुख्य मुख्य व्यापारिक स्थानों में एक दूसरे से जोड़ा गया है। भारत की बना, नेपाल और तिब्बत से भाग्य की सड़कें मिलती हैं। १ अप्रैल, १९४७ में इन सड़कों की बनाने और इनकी ठाक दिये गए रकमों का निम्नांकित सरकार ने ली लिया है। इस समय इन सड़कों की कुल लंबाई १३,००० मील है जिसमें से लगभग ११०० मील लम्बी सड़कें तो बनाई हुई हैं और लगभग १६०० मील लम्बे बाँट बाँट कर दुबड़े हुए हैं। प्रांतीय सड़कें प्रांत की प्रमुख सड़कें हैं और राष्ट्रीय सड़कों के साथ ये जोड़ी हुई हैं। जिले की सड़कें जिलों के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ती हैं और बड़ी सड़कों से तथा रेलों से भी उनका सम्पर्क है। गांवों को प्रांत में जोड़ने वाला गांव की सड़कें हैं। गांव से पक्का किया जाता है।

सड़कों का प्रबंध—भारत की दृष्टि में राष्ट्रीय सड़कें भारत सरकार का विषय हैं। इनके अन्तर्गत बाँट की सब सड़कें राज्य की सरकारों का विषय हैं। राज्य का सांख्यिक विभाग सड़कों के खाते में रहता है। इसका अपना जिला बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी की सड़कें भी हैं। म्युनिसिपैलिटी सड़कों को छाड़कर लगभग ८० प्रतिशत सड़कें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के हाथ में हैं। सड़कों का विकास सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिये प्रति वर्ष 'इंडियन रोड कांग्रेस' भी होता है।

सड़कों का विकास—हमारे देश में सड़कों के विकास की अत्यन्त आवश्यकता है, यह दुहराने की जरूरत नहीं। एक अर्थ में देश का भाग्य विकास ही इस पर निर्भर है। प्रधान महापुरुष के बाद जब मोटर द्वारा आवागमन की मात्रा बढ गई तो सड़कों का महत्व खान तौर से सामने आया। १९२७ में डा०

एम० आर० जयकर के समापतित्व में 'रोड डेवलपमेंट कमेटी' की नियुक्ति हुई। इस कमेटी को सिकारिश पर भारत सरकार ने मार्च, १९२६ को सेन्ट्रल रोड डेवलपमेंट फण्ड का निर्माण किया। मोटर ट्रिप्ट पर मार्च १९२६ में जो आयात और उत्पादन-कर बढ़ाया गया था उस बड़े हुए भाग की आय से यह फण्ड बना था। इस फण्ड में से राज्यों को सड़कों के निर्माण के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। इस फण्ड में ३१ मार्च, १९४७ तक २७.०९ करोड़ रुपया एकत्रित हो चुका था। इसमें से ५.०६ करोड़ रुपया तो रिजर्व में रखा गया था और २१.९४ करोड़ रुपया राज्यों में बाँटने के लिये उपलब्ध था। इसमें से १८.५ करोड़ रुपया ३१ मार्च १९४७ तक वास्तव में बाँटा जा चुका था। रोड फण्ड के निर्माण के बाद प्रान्तों और राज्यों की आर्थिक स्थिति बिलम्बने लगी। आज तक भी यही हालत चली आ रही है। इसलिये प्रान्त और राज्य की सरकारें अपनी आय में से जो राशि सड़कों पर खर्च करना चाहती थी और करती थी इसमें उन्हें कर्ता करनी पड़ी। पहले रोड फण्ड का रुपया अन्तर्राज्य और अन्तर-जिला के मजदूर भी सड़कों पर ही खर्च हो सकता था। पर बाद में भारत सरकार को यह मंजूर करना पड़ा कि रोड फण्ड से राज्य को मिलने वाले रुपये का २५ प्रतिशत मजदूर सड़कों पर खर्च किया जा सकता है। जो सड़के रेलों के मुकाबिले में आती हैं उन पर भी अपने हिस्से के २५ प्रतिशत से अधिक रुपया राज्य की सरकारें खर्च नहीं कर सकती। रुपये की कटिनाई के कारण सड़कों का विकास नहीं हो सका। हमारे देश में सड़कों का विकास किनने थामे हुआ है इसका अनुमान इसी से लग जाता है कि १९००-१९४५ तक ४५ वर्षों में हमने जितनी मील सड़कें बनाई उतनी भील सड़कें संयुक्त राज्य अमेरिका ने १३ वर्षों में ही बनाली थी। सन् १९०० में उस समय के अमेरिका भारत में १७६००० मील कुल सड़कों की लम्बाई थी। १९४५ में यह लम्बाई बढ़कर २,६५३५ मील लम्बी हो गई थी—यानी केवल ६०,५३५ मील लम्बी सड़क इन ४५ वर्षों में बनी। यदि हम केवल पक्की सड़कों की ही लें तो सन् १९०० में ४०००० मील सब सड़कों की लम्बाई थी वह १९४५ में ७२६६० मील हो गई—यानी ३२६६० मील लम्बी नई पक्की सड़कें ४५ साल में ब्रिटिश भारत में बन पाईं। सड़कों पर जो खर्च होता रहा है उससे भी इस धीमे विकास का पता चलता है। रोड फण्ड बनने के बाद सड़कों पर होने वाला कुल खर्च द्वितीय युद्ध के समय तक बढ़ने की अपेक्षा उल्टा कम हो हुआ, क्योंकि प्रान्तों और राज्यों ने अपनी आय में से सड़कों पर बहुत कम खर्च किया। हालांकि इन वर्षों में मोटर यातायात पर लगने वाले करों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। प्रान्त की सरकारों और केन्द्र की सरकार—उभों ने करों

में गृह की।

जब दिनाय महाबुद्ध आरम्भ हुआ तो महका का महत्त्व और अधिक सामने आया और हम ओर कुछ ध्यान दिया जाने लगा। दश व पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही तरह-दो तरह महकों का बंधन विस्तार और सुधार हुआ। यह विस्तार और सुधार बुद्धिमान आवश्यकता का फल है। रस्म-रिवाज ही किया गया था। १९६०-६१ में मधुबनी में तो महकों पर कुल रूप से ६ २६१ करोड़ रुपया हुआ था। १९४०-४१ में यह मात्र ३८८ करोड़ रुपया तक पहुँच गया था। और १९६५-६६ में १६२७ करोड़ रुपया तक पहुँच गया था। मौर्य यातायात में होने वाला आय हम खनन व मुद्राकरण १९४०-४१ में १९६७ करोड़ थी और १९४०-४१ में ३ करोड़ थी और १९४१-४२ में ४६ करोड़ थी। खनन उत्पादों का बंधन और अधिक है। यह इस आँकड़ा में स्पष्ट हो जाता है। १९६०-६१ में आय ८० करोड़ रुपया और १९४१-४२ में ३ करोड़ का हुआ।

नागपुर याचना—राष्ट्र का भाषा विकास व प्रश्न पर विचार करने के लिये नागपुर में १९४३ में चार योजनाओं का एक कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में आपाना बीस साल की आयु में नागरिकों का प्रान्त में रहकर रहना ही एक योजना स्वीकार की गई थी। योजना के अनुसार अर्धभारतीय भारत में ४ साल मातृ लम्बाई की ४४८ करोड़ रुपया की लागत पर रहने का प्रस्ताव था। भारत का विभाजन हो जाने पर भारत के हिस्से में ३७३ करोड़ रुपया की लागत पर ३, २१ ००० मातृ लम्बाई का सहन बनाना रहा। इनमें ६०,००० मातृ की राष्ट्रीय और राज्य का महक ६०० ० मातृ का तिल की बड़ा सहने, २,०० ००० मातृ की तिल की दूसरा सहने और २,५० ००० मातृ की मातृ की सहने सामिल है। इस योजना में यह लिखा गया था कि यह या कि कि राष्ट्रीय सहने का बनाने और एक डॉलर हालत में रहने का पूरा आर्थिक हिस्सा भारत सरकार का इलाका चाहिए। इससे अलावा भारत सरकार का काम दश के विभिन्न भागों में महक योजनाओं में सम्मिलित करना होना चाहिए और इस दृष्टि में मजदूरी व रिश्तेदारों के सहने में सहने स्वयंसेवक, और टेक्निकल सलाह का भारत सरकार का व्यवस्था करना चाहिए। योजना का मुख्य उद्देश्य दश में महकों का इस प्रकार निर्माण करना है कि एक विकसित इति प्रदेश का एक भी गाँव किसी न किसी मुख्य महक में ५ मातृ तक पहुँच सके। इस प्रकार जो इति प्रदेश नहीं [नीचे एकांकलन] है उसमें कोई गाँव किसी न किसी मुख्य सहने से २० मातृ तक न रहे। भारत सरकार और राज्य को सरकार ने इस योजना को सामान्य रूप से स्वीकार किया पर कितने समय

में यह योजना कर्तव्यत्व होनी चाहिये इस बारे में विचार मेद रहा। आखिर-
कार १० वर्ष के आचार पर ३०० करोड़ रुपये के खर्च की एक योजना बनी।
पर आर्थिक कठिनाई, ट्रेन्ड व्यक्तियों के अभाव और सामान की कमी के कारण
इस योजना के अनुसार प्रगति नहीं हो सकी। १९४७ की अप्रैल से १९५० की
मार्च तक के तीन सालों में 'ए' श्रेणी के राज्यों में २३ करोड़ 'बी' श्रेणी
के राज्यों में ३७०२ करोड़ और 'सी' श्रेणी के राज्यों में ०५७२ करोड़—कुल
२७११२ करोड़ रुपया सड़कों पर खर्च हुआ है। नागपुर योजना के अनुसार
इन वर्षों में राष्ट्रीय सड़कों के अलावा, जो भारत सरकार के जिम्मे हैं, ६११
करोड़ रुपया खर्च होना चाहिये था। इसके मुकामिले में केवल २७११ करोड़
रुपया खर्च हुआ। अर्थात् ५८% प्रगति हुई। यह स्पष्ट है कि नागपुर योजना के
अनुसार कार्य नहीं हो सकता है। सड़कों के भारी विकास के लिये वैज्ञानिक
सोज का बड़ा महत्व है। इसी उद्देश्य से सितम्बर १९५० में सड़को सम्बन्धी
एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान [सेंट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट] का शिलान्यास
किया गया है। इसका काम स्थानीय अनुसंधान संस्थानों का जैसे मद्रास, कल-
कत्ता, पटना, लखनऊ आदि में जो स्थित हैं उनके कामों का समीकरण करना
और उनका मार्ग दर्शन करना होगा।

पांच साला योजना:—भारत सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग ने
पहले पांच साल के लिए एक प्रस्तावित योजना प्रकाशित की है [जुलाई, १९५१]।
सड़कों के विकास के बारे में योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि
सड़को सम्बन्धी योजना आर्थिक जीवन के अन्य क्षेत्रों, जैसे कृषि, उद्योग आदि
सम्बन्धी योजनाओं की आवश्यकता की ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिये।
उत्पादन में जो सड़कें सहायक हों उनको आज प्राथमिकता देने की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश में इस बात का ध्यान रखा गया है। जो सड़कें रेलों के सहायक या
पूरक का काम करती हैं और किन्हीं स्थानों पर भौड़ को कम करती हैं उनको
पहले बनाना चाहिये।

इस योजना में राष्ट्रीय सड़कों के बारे में इस प्रकार से प्राथमिकता का
निर्याय किया गया है:—(१) सड़कों के बीच-बीच में जो टुकड़े छूटे हुए हैं उनको
बनाना। (२) सड़कों की ठप्पर को सतह में सुधार करना ताकि अधिक ट्रैफिक
वर्दाश्त कर सके। और (३) पुराने पुलों में सुधार करना ताकि भारी बोझ
ले जाने योग्य बन सकें। राज्य की अपनी सड़कों की योजना समझ-सोचकर
केन्द्रीय सड़क संगठन की सलाह ले बनानी चाहिये। गाँवों की सड़कें बनाने की
और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें गाँव वालों का सहयोग

ज्ञान दिया जाना चाहिये। इस उदाहरण मौन है कि मद्रास बनाने का उद्देश्य गाँव वालों ने दिया और कु सरकार ने। इस चौथी योजना में २३ कराड़ ग्यदा भारत सरकार, ५० १८५५ कराड़ 'ए' भौली के राज्य, ११ ७७८ कराड़ 'बी' भौली के राज्य और ५ २७१६ कराड़ 'सी' भौली के राज्य कुल ६६ ७६७ कराड़ ग्यदा मद्रास पर खर्च करने का प्रस्ताव है।

मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण — भारत के स्वतंत्र होना के बाद मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण का काम इस राज्य में अपनाया है। जिस बात को मैं इस दिशा में विभिन्न राज्यों में देखते प्रगति भी हुआ है। बम्बई में स्टेट रोड ट्रान्स्पोर्ट कारपोरेशन का गठन दिम्बर १९४६ में हुआ। इसमें ५ जी भारत सरकार और राज्य की सरकार ने १३ ४ अनुपात में लगाई है। इसका उद्देश्य छोटे छोटे राज्यों में मोटर यातायात को अपने हाथ में ले लना है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने १९४७ में ही दिसंबर बल ट्रान्स्पोर्ट का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय कर दिया था। सरकारों विभाग द्वारा हा माटर सर्विस का संचालन किया जाता है। पन्ना और मद्रास में भी सरकारी विभागों द्वारा हा माटर सर्विस का संचालन होता है। उदाहरण में राई ट्रान्स्पोर्ट कारपोरेशन की स्थापना का प्रस्ताव है जो राज्य द्वारा संचालित मोटर यातायात को अपने हाथ में ले लया। पश्चिमी बंगाल में किनारा बलरुस और बल बलकन की बल सर्विस तथा हा राष्ट्रीयकरण सम्मिलित रहने वाला है। मध्य प्रदेश में भी ही ट्रान्स्पोर्ट सर्विस लि० और प्राविशियल ट्रान्स्पोर्ट कम्पनी लि० द्वारा मोटर सर्विस चलायी जा रही है और इसा तरह की तीन और कम्पनियाँ बनाने का विचार है। 'बी' रेखा के राज्यों में ट्रान्स्पोर्ट कोचीन, मैसूर तीर्थपुरादि में भी मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण शुरू हो गया है। दिल्ली में ३ राज्य सरकार द्वारा मोटर यातायात का संचालन होता था। पर अब यह संचालन दिल्ली रोड ट्रान्स्पोर्ट ऑथोरिटी नामक स्वतंत्र संस्था के हाथ में चला गया है।

मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण का भी अन्य राष्ट्रीयकरण की योजनाओं का तरह ५ नीतिविरुद्ध बराबर विचार करता आया है, पर इस मामले में हमारी सरकारों ने दृष्टता में ज्ञान दिया है। दिम्बर १९५० में भारतीय संसद ने 'रोड ट्रान्स्पोर्ट कारपोरेशन बिज' पास कर दिया। इस विधेय के पास हो जाने से राज्य की सरकारों का मद्रास यातायात का राष्ट्रीयकरण का अधिकार मिल गया है। और राज्य की प्रशासन सचिवों का स्पष्टीकरण कारपोरेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष का अर्थिकार प्राप्त हो गया है। राष्ट्रीयकरण में मुम्बई के अधिकार

बड़ी है इसमें कोई संदेह नहीं। व्यक्तिगत हाथों में जब मोटर यातायात था उससे यदि आज किराया कुछ अधिक है और लाभ कम भी है तो इसे राष्ट्रीयकरण की असफलता मानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसका एक कारण यह भी है कि पहले की अपेक्षा यात्रियों और काम करने वाले दोनों ही को अब अधिक सुविधा दी जाती है। सरकार के हाथ में जो व्यवसाय है उसका एक मात्र दृष्टि-कोण शोषण द्वारा अनुचित लाभ कमाना नहीं हो सकना। फिर भी जहाँ कार्य-क्षमता की कमी हो और अपज्वब हो वहाँ बराबर सुधार करने का प्रयत्न करने चाहिये। राष्ट्रीयकरण की सफलता के लिये यह आवश्यक है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि राज्य की ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज जिन मोटर गाड़ियों को काम में लें उनका स्टैंडर्डइजेशन हो, और देश के मोटर उद्योग के विकास से पुरानी के स्थान पर नई गाड़ियाँ बचलने और उनकी संख्या बढ़ाने की योजना का मेल धिटाया जावे। मोटर गाड़ी सुधारने के कारखानों की स्थापना करने और 'टैकिनकल मेन' को शिक्षा देने की व्यवस्था करने की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिये।

पाँच वर्षीय योजना में राज्य द्वारा चलने वाली मोटर सर्विसेज के लिए 'अ' श्रेणी के राज्यों के लिए ५.६ करोड़ रुपया, 'ब' श्रेणी के राज्यों के लिये १.६ करोड़ रुपया और 'सी' श्रेणी के राज्यों के लिये २० लाख रुपया—इस प्रकार कुल ७.४ करोड़ रुपया अंश दिया है।

आन्तरिक जल यातायात—जल यातायात दो प्रकार के है—एक तो नदी यातायात और दूसरा समुद्र तटीय यातायात। पहले हम नदी यातायात के बारे में विचार करेंगे।

नदी यातायात—भारत में नदी यातायात अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है। लिखित इतिहास के पहले से नदी यातायात का इस देश में विकास हो चुका था। 'शुक्र कल्पतरु' नाम की एक प्राचीन संस्कृत की पुस्तक है, जिसकी प्राचीनता का ठीक-ठीक अनुमान लगाना भी कठिन है, उसमें समुद्र और नदी में चलने योग्य नावों की निर्मासकला का उल्लेख आता है। नावों के रूप में भी एक नाव का चित्र खुदा हुआ है। मेगस्थनीज़ ने भी नदी द्वारा यातायात का जिक्र किया है। १४ वीं शताब्दी में भी नदी यातायात उन्नत दशा में था। पर वह तो प्राचीन इतिहास की बात हुई। वर्तमान युग में भाप से चलने वाले इंटीमर का सबसे पहले १८२१ में उपयोग हुआ। १८४२ में कलकत्ता और आगरा के बीच में यमुना नदी में नियमित रूप से पात्रिक यात्रा का प्रवण्य था। पर स्टीमर का महत्त्व नदी यातायात में कभी बहुत अधिक नहीं

हुआ। देशी ताँबों द्वारा कहीं अधिक मात्रा में यातायात होता था।

देश में नदी यातायात का ह्रास रक्षा र विमान के साथ साथ १८५५ तक आरम्भ हुआ। निचाई के लिये जब बड़ा बड़ी नहरें बनने लगीं तो उनका अर्थ भी नदी यातायात पर घुस पड़ा क्योंकि नदियाँ में स्वाभिवार में उनका ऊपरी हिस्सा में नहरों में पानी चले जाना में पानी का काम खान गयी। वास्तव में नदी यातायात की मात्रा थोड़ी बनी है पर कि ३१ मील पर नदी यातायात देश के उत्तरी-पूर्वी भाग में-गंगा-ब्रह्मपुत्रा भाग पर-भी शामिल है। देश के विभाजन के कारण और भारत पाकिस्तान के मध्य अन्तर्गत नदी होने से भी नदी यातायात में अङ्कित उत्तर है और यह आवश्यक समझना चाहता है कि हमारे नदी यातायात की इस तरह पुनर्व्यवस्था हो चाहे कि पाकिस्तान में से होकर कम से कम आना-जाना पड़े।

भारत में साल भर जारी रह गये जाने वाले नदी मार्ग की लम्बाई ४१ ००० मील के लगभग है। इस पर स्थायी और स्थायी नदी बड़ा नदी चला सकती हैं। इसका अलावा एक जलमार्ग भी कई हैं जहाँ छोटी छोटी नहरें चल सकती हैं। वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में ६०० मील लम्बा नहरों पर यातायात होता था। १६५८ ई. में इन की ६ ०५ मील की लम्बाई हो गयी। कुल किस्मियों की संख्या १९ शताब्दी के आरम्भ में ०८००० थी। यह संख्या द्वितीय महायुद्ध के पहले २ ०६ ००० हो गई थी। इस वक्त में जल यातायात से आने वाले भारी मात्रा की मात्रा ९ लाख टन से १०० लाख टन (१६१८-१६) हो गई थी और यात्रियों की संख्या ६ लाख से १६ लाख हो गई थी। विभाजन के बाद जल यातायात के लिए उपलब्ध नहरों की लम्बाई ५७ ४ मील आने जाने वाले माल की मात्रा १६० लाख टन और यात्रियों की संख्या ३ ८० ००० है। (दिसंबर १९५० तक) गंगा-ब्रह्मपुत्रा जलमार्ग पर स्टामर से होने वाले ट्रैफिक की मात्रा साल भर में ६ १ करोड़ टन मील है। इहाँ नदियों में देशी नावों से इससे दुगुना ट्रैफिक होता है। कलकत्ता से आने जाने वाले कुल माल का मुद्रिकल से १/१२ वीं हिस्सा जल मार्ग से आता जाता है। दक्षिण में बंकिपूर नहर जो मगध और बंगाल को मिलाती है गोदावरी और कृष्णा नदी की नहरें और तुम्हगुन नहरें जल यातायात में प्रमुख साधन हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ उत्तर भारत की नदियों की अपेक्षा आवागमन के लिये कम उपयोगी हैं। इस प्रदेश का प्राकृतिक बनावट नदी द्वारा यातायात के मार्ग में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करती है।

भारत में नदी यातायात को विकसित करने की बड़ी आवश्यकता है।

पिछले महायुद्ध के समय इसका महत्व खासतौर से सामने आया था। जल-यातायात सबसे सस्ता साधन है। उसमें मार्ग बनाने का, और स्टेशन बनाने का और स्टेशनों आदि पर इतना प्रबन्ध रखने का प्रश्न ही नहीं उठता, और इस सम्बंध का सारा खर्च बच जाता है। जलयातायात अभी तक प्रांतीय सरकारों का विषय रहा है, इस कारण से भी इसके देशव्यापी विकास की कोई योजना नहीं बन सकी। अब स्वतन्त्र भारत का जो विषय बना है उसमें अन्तर्राज्य की नदियों और जल मार्गों का यातायात भारत सरकार का विषय कर दिया गया है। और 'सेन्सुस वाटर पावर इर्रिगेशन और नेवीगेशन कमीशन' के ज़िम्मे देश के नवी यातायात को एक योजना के आधार पर विकसित करने का काम दिया गया है।

इस प्रश्न पर यह कमीशन दो दृष्टियों से विचार कर रहा है। एक तो मौजूदा जल मार्गों का सुधार और नए जल मार्गों की स्थापना करना। दूसरे संगठन और व्यवस्था में सुधार करना। जलयातायात का प्रबन्ध राज्य की स्वयं ही करना चाहिये। मि० छोटे पोपर नाम के एक विशेषज्ञ की सेवाएँ भी 'इकोनॉमिक कमीशन एशिया फॉर ईस्ट' से इस विषय में जॉन्स पेटाल फरने और भारत सरकार को सलाह देने के लिये ली गई थीं। उनकी यह सलाह है कि देशी नावों की सहकारिता के आधार पर संगठित करना चाहिये और उनका पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। मि० पोप ने इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि गंगा के ऊपरी हिस्से में नावों के ठहरने के स्थान (रिवर पोर्ट) और सामान उतारने चढ़ाने के ढ़ेन आदि यांत्रिक साधनों की कमी है और उसकी पूर्ति करना आवश्यक है। क्रेन की यह कमी कलकत्ते तक में बताई गई है। नदी के किनारों को स्थान छोड़ने से रोकने के लिये किनारों पर काठियाँ लगाने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया है ताकि जमीन की विसावट से किनारों का स्थान न बढ़े और उससे होने वाली हानि न हो सके।

नदी यातायात के मार्ग में, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, एक कठिनाई यह है कि सिंचाई की नहरों के कारण पानी की कमी आ जाती है। इसका उपाय यह है कि जल संचय (रिवर कंजर्वेन्सी) की उचित व्यवस्था की जाये। यह व्यवस्था बड़ी सुचीली होती है और केवल जल यातायात के लिये इतना खर्च करना सम्भव नहीं हो सकता। इसलिये नदी के उपयोग की बहु-उद्देशीय (सिंचाई, विजली, बाढ़ नियंत्रण और यातायात) योजनाओं के बनने पर ही यह व्यवस्था सम्भव है। इसीलिये भारत-सरकार ने नदियों की बहु-उद्देशीय योजना की नीति को स्वीकार किया है। इससे जल यातायात की यह

कठिनाई दूर हो सकेगी।

इस समय जो नदी पाटी योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं उनमें से कई एक के पूरी होने पर देश के जल यातायात में मोड़ पड़ने होगा। उदाहरण के लिये उड़ीसा की हाराकुण्ड बाँध योजना पूरी होने पर महा नदी का १०० मील का टुकड़ा जल यातायात के योग्य हो जाएगा। इसी प्रकार दामोदर पाटी योजना के पल्लस्वर रानीगञ्ज की मिचली रियल की स्थानों की हुगली बंदी से एक जल यातायात की नहर के द्वारा भिजाया जा सकेगा। गंगा घरेलू प्रोपेक्ट व अन्तर्गत भी एक नहर बनाने का योजना है जो भागलपुर से काशीपुर के पास मिलेगा। गंगा और बागला नदी को भी यातायात के योग्य बनाने का विचार चल रहा है। 'मैट्रन वाटर पावर डेवेलपमेंट एंड नेविगेशन कमीशन' का श्रम तक का जीवन से यह मालूम होता है कि अभी प्रायः पश्चिमी घाट की भी जल यातायात से काफ़ी सम्भव है। पर यह योजना बहुत शाय हो सकती है। हमारे प्रकार आसाम और पश्चिम बंगाल के बीच में भी जल यातायात की स्थापना सम्भव है। माराश यह है कि भारत में जल यातायात के विहास के लिये बहुत कुछ चाहिये है। यह निराम आवश्यक है। इस प्रकार सरकारों का ध्यान भी है।

समुद्र स्त्रीय यातायात — प्राचीन काल में भारतीय जहाज़ों द्वारा समुद्री व्यापार होता था, यह बात अस्मिन् है। सिर्फ इस का कीर्ति उन लौटने लगीं तो २००० बहारा + येके पर उठाने अन्तर्गत समुद्री यातायात के लिये उत्तम किया था। अफ़सर के शासनकाल में ४०००० जहाज़ों को केवल सिन्धु नदी के व्यापार में लगा हुआ था। अब भारत की साम्राज्य शासक भारत में आया तो उसे यहाँ पेंने लाविय मिले ता जल यातायात के बारे में उसमें कहीं अधिक जानकारी रखने थे। उत्तमगी नदी पर भारतीय जहाज़ों द्वारा सिन्धु और समुद्रागम व्यापार में अच्छा प्रिय लगे रहे। पर बाद में अंग्रेज़ों ने जहाज़ों के प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी और अनुचित उपायों से भारतीय जहाज़ों यातायात को प्रायः नष्ट कर दिया। अंग्रेज़ों जहाज़ों व भारतीयों का ब्रिटिश सरकार पर भार प्रसार था। उन्होंने 'नेवीगेशन लाज़' पास करवाई। इन शक्तियों के बाद भारतीय जहाज़ों ब्रिटिश बंदरगाहों में जा नहीं सके थे। जहाज़ों के निर्माण में वैज्ञानिक तरीक़ों के उपयोग और लगे व जहाज़ बनाने से भी भारतीय जहाज़ी यातायात को बहुत पकड़ा पहुँचा। इसका नतीजा यह हुआ कि विदेशी व्यापार में भी भारतीय जहाज़ों का कोई स्थान बचा ही नहीं, पर समुद्र तटव्य व्यापार में भी ब्रिटिश जहाज़ों का प्रभुत्व कायम हो गया। ब्रिटिश नेविगेशन कमीशन ने 'क्वॉटिंग्स' के

रुम में श्राना एक संगठन बना लिया था। यह संगठन हर प्रकार से भारतीय जहाजों का विरोध करता था। भारतीय जहाजों का विरोध करने के दो उपाय खाल तौर से जान में लाये जाते थे। तरीका एक तो यह था कि पहले तो किराये को कम करके भारतीय जहाजों को इस क्षेत्र से हटा दिया जाये और फिर किराया बढ़ा दिया जाये। यहाँ किराये को लड़ाई का तरीका था। दूसरा तरीका यह था कि यदि माल भेजने वाले 'फार्मर्स' के जहाजों से ही अपना माल भेजते हैं तो उन्हें भारों का एक अंश, प्रायः १०%, एक निश्चित समय के बाद वापस मिल जाता था। अब तो इस 'फार्मर्स' में ही भारतीय जहाजों कंपनियाँ भी शामिल करली गई हैं। भारतीय जहाजों के मार्ग में और भी कई कठिनाइयाँ थीं। जैसे ब्रिटिश और यूरोपियन बीमा कम्पनियाँ उनके विवाद पक्षपात का व्यवहार करतीं, और समुद्रतटीय व्यापार और भुसाफिरों के आवागमन को ब्रिटिश जहाज प्रोत्साहन नहीं देते।

मरकेन्टाइल मेरीन कमेटी:—प्रथम महायुद्ध के बाद भारत में राष्ट्रीय जहाजों बेड़े के निर्माण की माँग की जाने लगी। देश की आर्थिक विकास की दृष्टि से तो यह आवश्यक था ही पर देश की सुरक्षा के लिये भी इसका महत्व था। भारत सरकार ने १९२३ में एक मरकेन्टाइल मेरीन कमेटी की नियुक्ति की। कमेटी ने भारतीय युवकों को जहाजी शिक्षा देने की व्यवस्था करने, भारतीयों को विदेशी जहाजों पर अनिवार्य रूप से काम देने, समुद्रतटीय बेड़े का भारतीयकरण करने, और जहाज निर्माण के उद्योग को सहायता देकर पुनर्जागरण करने की सिफारिशें कीं। तत्कालीन भारत सरकार ने इन सिफारिशों में से एक सिफारिश को स्वीकार किया। भारतीय युवकों को जहाजी शिक्षा के लिए 'इफरिन' जहाज की स्थापना की गई।

समुद्रतटीय व्यापार के भारतीयकरण के प्रयत्न:—समुद्रतटीय व्यापार भारतीय जहाजों के लिये सुचलित रखने की माँग भी देश में उठी। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में १९२८ में इस आशय के बिल भी पेश किये गये। पर तत्कालीन भारत सरकार के विरोध के कारण इन बिलों का कोई सतीजा नहीं आया।

द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात्:—जब गत महायुद्ध आरम्भ हुआ तो भारत सरकार को यह अनुभव हुआ कि भारतीय जहाजी बेड़े की कितनी आवश्यकता है। १९४५ में जहाजों सम्बन्धी 'रिकन्स्ट्रक्शन प्रोलिफ़ी सच कमेटी' की भारत सरकार ने नियुक्ति की। इस कमेटी ने जनवरी १९४७ में अपनी रिपोर्ट पेश की और सरकार द्वारा राष्ट्रीय जहाजी नीति अपनाने की सिफारिश की। आने

वाले पॉन्च से सात साल में २० लाख टन का जहाजी बेड़ा बढ़ा कर लेने का लक्ष्य इस कमेटी ने देश के सामने उपस्थित किया। समुद्रतटीय व्यापार पूर्णतया भारतीय हाथों में ले लेने की इस कमेटी ने सिफारिश की। इसी प्रकार दूसरे देशों के व्यापार के बारे में भी इसी कुछ अनुपात निश्चित किये। भारतीय शिपिंग बोर्ड की स्थापना करने की भी कमेटी की राय थी।

अगस्त १९४७ में भारत स्वतन्त्र हो गया। नयी नई भारत सरकार भारतीय जहाजी बेड़े के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दे रही है। जहाजी यातायात के एक नये सरकारी विभाग की स्थापना की जा चुकी है जो मैनेजर जनरल इंडियन शिपिंग के तहत में काम करता है। १९४७ व अगस्त में भारत सरकार ने तीन नए शिपिंग कॉरपोरेशन्स स्थापित करने की घोषणा की थी। इनमें से प्रत्येक की १० करोड़ की पूंजी मानी गई थी जिसका ५१% भाग भारत सरकार से मिलान की बात थी। प्रत्येक कॉरपोरेशन का अपना निश्चित मार्ग और निश्चित टनेज हो, यह भी तय किया गया था। इन कॉरपोरेशन्स का उद्देश्य था भारतीय टनेज की शोमानिष्ठता माफ़ा घटाना और जहाजी यातायात का विकास करना। पर भारत सरकार आर्थिक और अन्य कठिनाइयों के कारण अभी तक केवल एक कॉरपोरेशन की ही स्थापना कर सका है। इसका नाम आस्ट्रेलिया, छुट्टपूर्व और निकट पूर्व के साथ व्यापार करना है और इनका मैनेजिंग एक्सल डिप्टी स्टोम नौरीगेटन लिमिटेड के पास है।

जनवरी १९५० में जो शिपिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें समुद्र तटीय व्यापार की भारतीय मान्यताओं और अधिक बढ़ावे के प्रश्न पर विचार किया गया था। मौजूदा ब्रिटिश जहाजों में से कुछ को लाइसेंस रद्द करने और आगे नए लाइसेंस नहीं देने का कॉन्फ्रेंस में निर्णय किया गया। भारतीय कंपनियों को सरकार ने यह आश्वासन दिया कि जहाँ तक समय होगा सरकारी माल लाने से आने का काम वह जहाँ से होगी। विदेशी व्यापार के संबंध में भी यह निष्पत्ति किया गया कि आगे से विदेशी व्यापार संबंधी सरकारी समझौतों में यह धारा रखी जाय कि ५०% भाग भारतीय जहाजों में लाया-ले जाया जायगा। अगस्त १९५० में भारत सरकार ने समुद्रतटीय यातायात केवल भारतीय जहाजों के लिए ही सुरक्षित रखने का निर्णय कर लिया है। सरकार की इस नीति को कहीं तक सफलता मिली है इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि समुद्र तटीय व्यापार में जहाँ आज से दो साल पहले १,७८,००० विदेशी टनेज था वहाँ अब केवल ४८,००० टन हो है। विदेशी व्यापार का जहाँ तक संबंध है १९४६-४७ में इस क्षेत्र में एक मां भारतीय जहाज काम नहीं करता था, पर आज २५ जहाज काम कर रहे हैं।

इनमें से अधिकांश सामान ले जाने वाले हैं और कुछ मुसाफिर ले जाने वाले भी हैं। सन् १९४७-४८ में समुद्र तटीय व्यापार का ४३% और १९४८-४९ में ५३% भाग भारतीय जहाजों का था।

पाँच सालाना योजना:—इसने ऊपर वह लिखा है कि १९४७ में शिपिंग सब कमेटी ने भारतीय जहाजों के लिये आगामी ५-७ वर्षों में २० लाख टन का लक्ष्य उपस्थित किया था। इस लक्ष्य तक हम पहुँच नहीं सके हैं। युद्ध के पहले भारतीय टनेज २,४५,००० था और १९४६ में १,२७,००० ही रह गया था, वह १९५० के अन्त में ३,७७,५०० हो गया है। इस समय ७१ जहाज २,०५,७१७ टनेज के भारतीय समुद्र तट पर हैं और उनमें से आधे से ज्यादा २० वर्ष से अधिक आयु के हैं। भारतीय जहाजों की संख्या में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना न समुद्र तटीय व्यापार भारतीय जहाजों के हाथ में पूर्ण तौर से आसक्तता है और न पुराने जहाजों को बदला जा सकता, और न विदेशी व्यापार में ही हम अपना योग्य हिस्सा ले सकते हैं। इसीलिए पाँचवर्षीय योजना में इस काम के लिये १४.६ करोड़ रुपया खर्च करने का प्रस्ताव है। ८०००० टन तो समुद्रतटीय व्यापार के लिये और १,२५,००० टन विदेशी व्यापार के लिये और ६०००० टन इस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन के, जो भारत सरकार ने स्थापित किया है, लिये प्राप्त करने की योजना है। चूँकि टनेज बढ़ाने के लिये भारत सरकार कम्पनियों को आर्थिक सहायता देगी इसलिये वह कम्पनियों पर अपनी देख-रेख भी रखेगी ताकि उचित भाड़ा वसूल किया जाये, प्रबन्ध अच्छा हो और मुनाफा वापस इसी काम में लगे। मेरीन इंजीनियरिंग और मचेंट नेवो-रेटिंग की शिक्षा के लिए भी योजना में व्यवस्था की गई है।

हवाई यातायात:—भारत में हवाई उड़ान १९११ में आरंभ हुई। इस समय कुछ स्थानों में केवल प्रदर्शन की दृष्टि से हवाई उड़ान की व्यवस्था की गई थी। पहली बड़ी कठार्इ के बाद हवाई यातायात की हमारे देश में वास्तविक शुरुआत हुई। भारत सरकार ने कुछ लैंडिंग आउन्ड की व्यवस्था की। १९२७ में सीविल एवियेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। सीविल एरोड्रोम्ट बनवाए गए और हवाई जहाज चलाना सिखाने के लिये फ्लाइट क्लब्स कायम हुईं। १९२९ में भारत और लंदन के बीच में नियमित रूप से हवाई यातायात आरंभ हुआ। १९३२ में भारत में ही कुछ स्थानों के बीच में हवाई यातायात की सुविधा हो पाई। विदेशी कम्पनियों द्वारा भी भारत में होकर पश्चिम और पूर्व के बीच हवाई यातायात की शुरुआत की गई।

गत महायुद्ध के समय हवाई यातायात को अच्छा अतिवाहन मिला। और

इस समय तो हवाई यातायात का दश के यातायात में महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत व स्वतन्त्र होने के बाद हवाई यातायात ने अचूकी प्रगति की है। भारत सरकार ने बराबर प्रोत्साहन दिया। 'इंटरनेशनल सीविल एवियेशन ओरगेनाइजेशन' में भी भारत सरकार क्रियात्मक भाग लेती रही है।

वर्तमान स्थिति—१ जनवरी, १९५० का भारत में दस हवाई यातायात की कंपनियां थी—एयर इंडिया, बंबई इन्डियन नेशनल एयरवेज़, नई दिल्ली, एयर सर्विसेज़ आर इंडिया, बंबई चला एयर वेन, वेगम पट, इंडियन ओवर सीज़ एयर लाइंस, बंबई, एयर जेज़ (इंडिया), कलकत्ता भारत एयरवेज़, कलकत्ता, एयर इंडिया इंडर नेशनल, बंबई, हिमालया एवियेशन, कलकत्ता, कलिंगा एयर लाइंस, कलकत्ता। इनमें से एयर इंडिया इंटरनेशनल (१९४७ में स्थापित) बंबई, लद्दा तथा बरई अन्न, नरोबा व बाव में चलता है। इसमें भारत सरकार का भी हिस्सा है। भारत एयरवेज़ कलकत्ता बैंगलोक के बीच में भी चलता है। समार व हवाई यातायात का दृष्टि से भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ अच्छी है, क्योंकि पूरा और पश्चिम व बांन में यह स्थिति है। बी० ओ० ए० सा०, के० एल० एम०, टा० बल्फू० ए० तथा वे० एमरिक्न एयर वेन आदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हवाई यातायात का कंपनियों द्वारा हवाई यातायात का व्यवस्था भारत में होकर है।

१९४८ में हवाई जहाजों ने १९१९३ मील की यात्रा की और १,५७,४१५ यात्रियों ने इन यात्राओं से लाभ उठाया। १९४६ में हवाई जहाजों से १०,१२३ मील की यात्रा १,०५,०५१ यात्रियों ने की थी। हवाई जहाजों के अचूकनी और बाहरी दोनों मिलाकर ४६ मास इस समय काम करते हैं और २५००० मील इनकी कुल लाइ है। हवाई जहाजों से यात्रियां न अलावा सामान और डाक भी लाइ लाई जाती है। पर्याप्तियों को लाने-ले जाने में, आसाम में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने में और दूसरे ऐसे मौकों पर हवाई जहाजों से बहुत मदद मिली है।

राष्ट्रिय एवियेशन डिपार्टमेंट के नियंत्रण में दस समय ६६ एरोप्लेन हैं। इसमें से दिल्ली, बंबई और कलकत्ते व अंतर्राष्ट्रीय एरोप्लेन हैं। कुछ बड़े एरोप्लेन हैं, कुछ बाव के दर्जे के और कुछ छोटे हैं। कुछ एरोप्लेनों पर—लगभग २१ पर—रात की उड़ने की व्यवस्था भी है।

एरो नोटिकल कम्यूनिकेशन व इस समय ११ अचूक स्टेशन हैं। ट्रेनिंग को बेसा करने के लिये भी पिछले वर्षों में प्रबल हुए हैं। इलाहाबाद में सीविल एरोप्लेन ट्रेनिंग सेंटर हैं जिनमें चार विभागों की शिक्षा दी जाती है—उड़ना

एरोड्रोम, एंजीनियरिंग और कम्प्यूनिवेशन। सहारनपुर में भी सीविल एवियेशन ट्रेनिंग सेन्टर है जहाँ रेडियो टेक्नोशियन्स को तैयार किया जाता है।

पूना में इंडियन ग्लाइडिंग एसोसियेशन है। इसे भारत सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। इसका काम 'ग्लाइडिंग' को प्रोत्साहन देना है।

इंडियन एरो नोटिकल सोसाइटी की भी दिसम्बर १९४८ में स्थापना हो चुकी है। इसका उद्देश्य एरो नोटिकल साइन्स और एंजीनियरिंग की उन्नति में सहायक होना है।

अनुनवान और विकास के लिये भी सफरदरज एरोड्रोम, नई दिल्ली में कुछ व्यवस्था की गई है। बंगलौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स में एरो नोटिकल एंजीनियरिंग का पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा भी दी जाती है।

बंगलौर में एयर क्रैफ्ट फैक्टरी कई वर्गों से काम कर रही है। यह भारत सरकार के अधिकार में है। भारत सरकार का उद्देश्य इसे पूर्णतया हवाई जहाज बनाने के कारखाने का रूप देना है।

भावी विकास—भारतवर्ष में हवाई यातायात के विकास के लिये सघट गुंजाइश है। सुदोतर विकास योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार ने हवाई यातायात के विकास और नियंत्रण की भी एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार हवाई यातायात का क्षेत्र व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए खुला छोड़ने का निश्चय किया गया। एयर ट्रांसपोर्ट लाइसेंसिंग बोर्ड की स्थापना का फैसला किया गया और कोई भी हवाई यातायात की कंपनी बिना इससे लाइसेंस लिये कार्य नहीं कर सकती यह भी तय किया गया। हवाई यातायात की सब लाइसेंस केवल चार कंपनियों द्वारा चलाई जानी चाहिये, और सरकार हवाई यातायात की कंपनियों को आर्थिक सहायता दे सकती है—ये भी इस योजना के अन्तर्गत था। दूसरे महायुद्ध के बाद एयर ट्रांसपोर्ट लाइसेंसिंग बोर्ड के पास देश में हवाई यातायात की व्यवस्था करने के लिए कंपनियों खोलने के कई आवेदनपत्र आये और कई कंपनियों खुलीं भी। पर तुरन्त ही यह अनुभव किया जाने लगा कि इन कंपनियों की आर्थिक हालत संतोषजनक नहीं है। फरवरी १९५० में भारत सरकार ने एयर ट्रांसपोर्ट इनफ़ॉर्मरी कमेटी की, सारी स्थिति की जांच करने और हवाई यातायात की भावी उन्नति के लिये उपयुक्त सुझाव देने के लिये निधुक्ति की। कमेटी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि हवाई यातायात उद्योग की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है, और इसका मुख्य कारण यह है कि देश में हवाई यातायात की वर्तमान मांग की दृष्टि से हवाई यातायात की कंपनियों की संख्या कहीं अधिक है। इसका नतीजा यह है कि अनावश्यक और अधिक खर्च होता है, आपस में

अनुचित प्रतिस्पर्धा होती है, और कपनिर्वा की आय में कमी आती है। कपनियों के पास इनसे जहाज और उनके अतिरिक्त भाग भी आवश्यकता से कहीं अधिक हैं। लाइसेंसिंग बोर्ड ने आवश्यकता से अधिक लाइसेंस जारी करके भी किछी हद तक इस स्थिति को बिगाड़ने में सहायता प्रदान है।

हवाई यातायात के लिये कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उनमें से मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं—(१) मौजूदा स्थिति में प्रत्यक्ष चार हवाई यातायात की कपनिर्वा होनी चाहियें—बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और हैदराबाद में। इससे लिये मौजूदा कपनियों को मिला देना चाहिये। केंद्रन एयरवेज और एयर सर्विसेज को मिलाने की उद्देश्य सिफारिश भी है। (२) किराये के बारे में उन्होंने इस मत का मार्गदर्शन नहीं किया है कि जो किराया कपनिर्वा इन समय लेना है वह अनुचित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि स्थायी एसेट्स पर १०% की आय होना ही चाहिये और इस आधार पर किराया न्य होना चाहिये, हालांकि यह अत्यधिक नहीं हो जाय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है। (३) भारत सरकार हवाई यातायात कपनिर्वा का जो आर्थिक सहायता दे रही है वह कुछ समय तक (१९६० दिसम्बर) जारी रखने का भी कमेटी की सिफारिश है। यह सहायता पेट्रोल पर लगाने वाले आयान-कर पर रिबेट के रूप में दी जाती है। (४) मुनाफे पर सरकार द्वारा नियंत्रण रखने का भी कमेटी की सिफारिश है। (५) कमेटी ने यह भी कहा है कि आने वाले पांच साल तक तो कम से कम हम उद्योग में से व्यक्तिगत व्यवसाय को समाप्त नहीं करना चाहिये। पर अगर सरकार राष्ट्रीयकरण या निष्काय करे हा तो कमेटी की राय में स्टेटूटरी कारपोरेशन के द्वारा ही हवाई यातायात का संचालन होता चाहिये।

कमेटी की सिफारिशों सरकार के विनाराधीन हैं। हाल में ही संसद में भारत सरकार की ओर से यह बताया गया था कि सरकार अक्सर एयरवेज का राष्ट्रीयकरण करने का प्रायः निर्णय कर चुकी है और कमेटी की सिफारिश के अनुसार स्टेटूटरी कारपोरेशन द्वारा इसका संचालन किया जायेगा।

पाँच वर्षीय योजना प्रस्तावित पाँच वर्षीय योजना में हवाई यातायात पर पहले दो वर्ष में १००५ करोड़ प्रतिवर्ष के निष्काय के लक्ष्य करने का मुकाम है। बाकी के तीन सालों में कुल ६६७ करोड़ निष्काय निर्वहण करने की योजना है। पहले दो वर्षों में १३ करोड़ निष्काय पर और बाकी का 'एक्टिवमेंट' पर निर्वहण करने का सिफारिश है। इसी तरह सप्लाइने तानक्या में भी ७०% पर निर्वहण और ३०% एक्टिवमेंट पर निर्वहण करने की योजना है। इससे अलावा मौजूदा हवाई जहाजों के रखान पर अधिक आधुनिक ढंग के हवाई जहाज खरीदने की

आवश्यकता है। इसके लिये ५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कंपनियों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता हो सकती है। इस काम के लिये योजना में २५ करोड़ रुपये रखा गया है। भारत सरकार यह आर्थिक सहायता कर्ज के रूप में या पूंजी में भाग लेकर या और किसी प्रकार से दे सकती है।

यातायात के साधनों में समन्वय—यातायात के विभिन्न साधनों, रेल, सड़क, जलयातायात, समुद्र तटीय यातायात और हवाई यातायात पर ऊपर विचार किया जा चुका है। हम देख चुके हैं कि भारत में सभी प्रकार के यातायात के लिये घटेष्ट गुंजाइश है। पर वहाँ इस विषय में इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि यातायात के इन विभिन्न साधनों में समुचित समन्वय की आवश्यकता है। समन्वय के अभाव में अनुचित प्रतिस्पर्धा होने से सिवा सब पलों को हानि होने के और कोई नतीजा नहीं आ सकता। अब तक इस समन्वय नीति का हमारे देश में अभाव रहा है। यही कारण है कि रेल और मोटर की प्रतिस्पर्धा ने १९२६ के बाद एक समस्या का रूप ले लिया था और उस पर विचार करने के लिये रेल-रोड कम्पैटीशन कमेटी (मिसेलककनेस कमेटी) की १९६२ में भारत सरकार को स्थापना करनी पड़ी थी। इस कमेटी ने कई सिफारिशें की थीं। पर उसकी एक मुख्य सिफारिश यह थी कि एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ कम्प्यूनिवेशन्स की स्थापना होनी चाहिये जो सब प्रकार के यातायात के साधनों का समुचित समन्वय करे। कुंजल कमेटी ने भी इसी उद्देश्य से 'नेशनल ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी' स्थापित करने की सिफारिश की थी। मोटर यातायात को नियन्त्रित करने के लिये ही १९३६ में मोटर विहिकल्स एक्ट पास किया गया था। १९६५ में सेंट्रल ट्रान्सपोर्ट एडवायजरी कौंसिल की स्थापना की गई। भारत सरकार ने रेल-रोड समन्वय की एक योजना प्रकाशित की जो सब प्रान्तों के पास भेजी गई। कुछ प्रान्तों ने इसके अनुसार काम भी किया है। यातायात के विभिन्न साधनों के बीच में समन्वय नहीं होने का दूरवा उदाहरण रेलों और समुद्र तटीय जहाजी यातायात के बीच का है। समुद्र तटीय जहाजी यातायात और रेलों के बीच में भाड़ा नीति में पास्परिक सम्बन्ध, तथा सम्मिलित यातायात, और सम्मिलित भाड़ों की व्यवस्था होनी चाहिये। अब तक रेलवे की भाड़ा नीति से समुद्र तटीय यातायात को हानि पहुँची है। इसी प्रकार रेलवे और जल-यातायात तथा हवाई यातायात में भी समन्वय की आवश्यकता है। अब तक हमारे देश में रेलों की ओर ही विशेष ध्यान दिया गया है। इसका परिणाम जल यातायात और सड़क यातायात के लिये हानिकर हुआ है। अब इस कमी

को पूरा करना है। प्लानिंग मशीन ने अपनी प्रस्तावित रिपोर्ट में लिखा है—
 “यातायात व विकास की नमाम राष्ट्रीय योजनाएँ एक केन्द्रीय संस्था द्वारा
 जाँची जानी चाहिये ताकि उनमें समन्वय हो सके।”

यातायात व भावी विकास व सम्बन्ध में दूसरी ध्यान देने की बात यह
 है कि देश का औद्योगिक और कृषि विकास व गन्तव्य की आवश्यकताओं
 को ध्यान में रखकर ही यातायात का विकास दोषना जानना चाहिये। यातायात
 से उन साधनों का उठा स्थाना में पहले विकास होना चाहिये जो औद्योगिक
 और कृषि उद्योग में सहायक हो सकें। जग में उद्योगधर्मों के विकेंद्रीकरण व
 लिय यातायात का विकास आवश्यक है यह स्पष्ट है।

एक तात्पर्य बात और है कि एक यातायात से सम्बन्ध रखती है।
 आज भी हमारे देश में एक यातायात का वैलगादियों बहुत बड़ा साधन है।
 हमें वैलगादियों व साधन का विविध और उन्नत करना है न कि इनको नष्ट
 हो जाने देना है। भारतीय कृषि व दृष्टि में भी यह एक उपयोगी सहायक
 साधन है। वैलगादियों का महत्व हमारा स्पष्ट है कि लगभग १० करोड़ टन
 माल उनके द्वारा लाया-ले जाया जाता है—अर्थात् त्रिन्ता माल रेलों द्वारा
 ले जाया लाया जाता है उनका ही वैलगादियों द्वारा लेयायी है। वैलगादियों में
 देश की कुल २६१ करोड़ का पत्रा लगा हुआ है और लगभग ८५ लाख उनकी
 सवारी है। भारत व यातायात व विकास की कोश योजना यातायात के करने
 व्यापक और सुलभ साधन व और स उदात्तमान नहीं होसकता।

परिच्छेद १० बैंकिंग व्यवस्था

आधुनिक अर्थ व्यवस्था में बैंकिंग (अधिकोषण) व्यवस्था का बड़ा महत्त्व है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। आज की अर्थ व्यवस्था मुद्रा प्रधान अर्थ व्यवस्था है। मुद्रा के माध्यम से सारा आर्थिक जीवन संचालित होता है, फिर चाहे उत्पादन का प्रश्न हो या उपभोग का या वितरण का। मुद्रा व्यवस्था का यदि हम विचार करें तो देखेंगे कि उसमें साख (क्रेडिट) का बड़ा स्थान है। जब तक मुद्रा (मनी) और साख (क्रेडिट) व्यवस्था का किसी देश में समन्वय न हो तब तक वहाँ के आर्थिक जीवन का समुचित संचालन असंभव हो जाता है। ऐसी हालत में आज के आर्थिक जीवन में साख-व्यवस्था का बड़ा महत्त्व है। साख की व्यवस्था करने का काम बैंकों का है। तात्त्विक दृष्टि से यही देश की बैंकिंग व्यवस्था का महत्त्व है।

इस प्रश्न पर हम सरल और प्रत्यक्ष ढंग से भी विचार कर सकते हैं। कोई व्यापार और व्यवसाय बिना साख के या उधार के नहीं चल सकता। कारण यह है कि जब उत्पादन बेचने के लिये होता है तो उत्पादन में पूँजी तो आज लगानी पड़ती है और उसको विक्री से आय याद में होती है। इस बीच के समय के लिये मुद्रा का (मनी) उपयोग करने से कोई लाभ नहीं और यह व्यावहारिक भी नहीं, क्योंकि उस हालत में आज से कई गुना अधिक मुद्रा की आवश्यकता होगी। बैंक इस काम को बड़ी आसानी से साख की व्यवस्था करके कर देते हैं। इसलिये आज के आर्थिक जीवन में बैंकिंग व्यवस्था का ठीक-ठीक विकास होता अत्यन्त आवश्यक है। भारत की बैंकिंग व्यवस्था के विषय में अब इन विचार करेंगे।

देशी बैंकर (Indigenous Bankers)—भारत वर्ष में बैंकिंग व्यवसाय अत्यन्त प्राचीन काल से होता आया है। वैदिक युग के साहित्य (इंसा ने २००० वर्ष पूर्व से १४०० वर्ष पूर्व तक) में इसका उल्लेख मिलता है किन्तु बैंकिंग के सम्बन्ध में विस्तृत और क्रमबद्ध विवरण ईसा के ५०० वर्ष पूर्व के पहले नहीं मिलता। ईसा के ५०० वर्ष पूर्व में आने हमें भारतीय प्राचीन बैंकिंग व्यवसाय का पूरा विवरण प्राप्त है। उस समय भारत का बैंकिंग व्यवसाय उन्नत उपा में था। तत्कालीन साहित्य के पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि उस समय के देश के सभी व्यापारिक वृत्तों में 'अपेष्ठी' वा 'बैंकर' होते थे और उनकी व्यापारिक तथा औद्योगिक संघों और व्यापारी, सम्राट में बहुत प्रतिष्ठा और

का काम करना उसका मुख्य लक्ष्य है। अस्तु हुडी का कारबार समा देया बैकर का मुख्य लक्ष्य है।

साहूकारी और महाजनी का काम (अर्थात् लेन देन करना) तो सभी जाति के लोग करने हैं। किन्तु बैकिंग का काम कुछ विशेष जातियाँ ही करती हैं। उनमें मारवाड़ी वश्य, जैनी, चेन्नी, गवा और शिकारपुरी मुलतानी प्रमुख हैं। मारवाड़ी राजपूताना के मारवाड़ प्रदेश सम्मिल कर भारत के प्रत्येक प्रमुख आयागिक तथा व्यापारिक केन्द्र में फैल गए हैं। उनका कारबार कलकत्ता, बम्बई के अतिरिक्त सभी रज्जा में फैला हुआ है। चन्वियों का बैकिंग कारबार मुख्यतः मन्सूर तथा बम्बई में है। जैनी पन्थाव में अपना कारबार करते हैं और शिकारपुरी मुलतानी गिब और बम्बई प्रान्त में अपना कारबार करते हैं। योहर गुजरात और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमीय भाग में बैकिंग का कारबार करते हैं। दूरी बैकर कोटावाल, सराफ, गफ, तथा चेन्नी आदि नामों से पुकारे जाते हैं।

इनमें से बड़े बैकर अपने कायागत्य और एजेंसियों बम्बई, कलकत्ता, मन्सूर, दहला, रंगून, तथादि प्रमुख व्यापारिक नगरीयों में भी रखते हैं। इन शाखाओं का उनके मुनीम या गमस्तरे नजारे हैं। इन मुनीमों को बहुत अधिक अधिकार होते हैं और वे अत्यन्त दृढ, इमानदार और परिश्रमी होते हैं। वे लोग अपने प्रवासी कायागत्य का कारबार का रिकार्ड सज्जते रहते हैं और वहाँ से आशा लाने रहते हैं। समय समय पर बैकर स्वयं आकर हिसाब की जाँच करता है।

यद्यपि अधिकांश दूरी बैकर स्वतन्त्र रूप से काम करते हैं किन्तु उनमें से कुछ श्रम भाँतों (Guilds) के सदस्य हैं जिन्हें 'महाजना' कहते हैं और जो उत्तर और दक्षिण भारत में श्रम भाँत पाये जाते हैं। यद्यपि इन 'महाजना' अर्थात् सर्वा का मुख्य कार्य वाणिज्य तथा सामाजिक होता है किन्तु वे दो संस्थाओं के आपसी सम्बन्ध को निबटाने और दिवालिया अदालत का काम भी करते हैं। पिछले दिनों में दूरी बैकरों ने अपना दृष्ट परिपक्व (Associations) स्थापित का है। उदाहरण के लिए बम्बई, कलकत्ता और अहमदाबाद में भाफ एनामिश्यन और मारवाड़ी चैम्बर ऑफ वायन स्थापित हो गई हैं और बम्बई में मुलतानी और शिकारपुरी एनामिश्यन स्थापित है। रंगून में भी एक मारवाड़ी एनामिश्यन है और दहली में बैकर एनामिश्यन है। इन एनामिश्यनों द्वारा इन बैकरों के आपसी सम्बन्धों का ध्यान है तथा उनका संगठन बढा हो गया है। कभी कभी आपसी सम्बन्धों पर दूरी एनामिश्यनों की सम्मिलित सभा होती है,

क्योंकि एक एसोसियेशन का सदस्य दूसरे एसोसियेशन के सदस्य से कारबार करता है। इसके अतिरिक्त देशी बैंकों का ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसके द्वारा उन्हें ग्राहकों की साथ सम्बन्धी जानकारी का आदान-प्रदान हो और वे साथ-अग्रवा सूद के सम्बन्ध में एक-सी नीति निर्धारित कर सकें। भिन्न-भिन्न बैंकों में कोई सहयोग नहीं होता। हाँ भारवादी और चेष्टियर बैंकों में जातीय सहयोग अवश्य होता है और वे समय पड़ने पर एक-दूसरे की सहायता करते हैं।

इन बैंकों का कारबार पारिवारिक होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अतएव इनको बैंकिंग की व्यावहारिक शिक्षा अनायास ही अपनी कर्म का काम देखने से प्राप्त हो जाती है। हाँ उन्हें बैंकिंग की सिद्धान्तिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती। देशी बैंकर का कारबार नरल और भ्रमकों से मुक्त होता है, इस कारण देशी बैंकर से काम करने में देरी नहीं लगती और न कोई विशेष भ्रमक ही होता है। ग्राहक हर समय बैंकर के पास जा सकता है। उसके काम का समय कोई निश्चित नहीं होता, वह हर समय काम करता है। उसके काम करने का ढंग बहुत कम खर्चीला और उनके दफ्तर इत्यादि का खर्चा बहुत कम होता है। उसके कार्यालय में कोई विशेष परनिचर या बहुत ने क्लर्क नहीं होते। केवल मुनीम और एक-ग्राह सजोरी होती है। उनका हिसाब रखने का ढंग सरल और कम खर्चीला होता है, किन्तु हिसाब बहुत ठीक रहता है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। हिसाब की जाँच की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती, और न कभी लेनी-देनी का लेखा (Balance Sheet) ही तैयार किया जाता है। देशी बैंकर बैंकिंग के साथ और भी व्यापार करता है किन्तु दोनों के हिसाब पृथक् नहीं रहते और न दोनों का रुपया ही अलग रक्खा जाना है। इन बैंकों का कारबार भी अधिकतर पुस्तैनी पुराने ग्राहकों से ही होता है। ऐसे व्यापारी अधिक मिलने जिनकी कई पुस्तै एक ही बैंकर की कर्म से कारबार करती रही हैं।

ये बैंकर अपने पुराने ग्राहकों के परिवार से, उनकी आर्थिक स्थिति और उनके व्यापार की दशा से मली भाँति परिचित होता है। इस कारण उन्हें इस बात का निश्चय करने में देरी नहीं लगती कि किस ग्राहक को कितना ऋण देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए। ऋण देने के उपरान्त भी वह बैंकर अपने कर्मचारियों के कारबार को समीप से देखमाँल सकते हैं जैसा कि व्यापारिक बैंकों के लिए सम्भव नहीं है। यही कारण है कि उनका रुपया बहुत कम मारा जाता है। देशी बैंकों से जब भी जमा किया हुआ रुपया वापस माँगा जाता है, वे दुरन्त ही वापस

कर देते हैं। ऐसा बहुत कम होना है कि बाद बैंकर मामले पर जमा किया हुआ रुपया पुरत वापस न करे। यहाँ उही व अपना फर्म की सामान्य और प्रतिष्ठा का बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वे यथेष्ट नरुद कोष (Cash Reserves) रखते हैं। वे अपने ग्राहकों को उम्मीद भिमित हिसाब समय समय पर दत्त हैं। यह बैंकर अपने उत्तरदायित्व को निवाह और दमानदारों से शरवार करने के लिए प्रमिद होत हैं। यह कारण है कि ग्राही साम्य (Credit) बहुत जँचा होनी है और व्यापारी उन पर विश्वास रखते हैं।

यह बैंकर चालू जमा (Current Deposits) और मुदती जमा लेते हैं। मुद की दर मोहन, रकम और स्थिने समय के लिए जमा की जा रही है इस अनुसार भिन्न भिन्न होता है। परन्तु यहाँ यह न भूल जाना चाहिए कि आपुनिर दम के बैंक गितता जमा (डिपॉजिटों) पर निर्भर रहते हैं उतने दशी बैंकर निर्भर नहीं रहते। वे अपनी पूँजी पर ही अधिक निर्भर रहते हैं। मुदतानी और मादपाकी बैंकर तो साधारणतः जनता से डिपॉजिट स्वीकार ही नहीं करते। वे अपनी पूँजी (Capital) से ही कारबार करने हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपन जातिभार्यों में जो शिक्कापुर तथा रातपुतान में रहने हैं श्रण से लेते हैं। मुदतानी इम्पारियल बैंक से भा प्रधिकतर आनश्यकता पड़ने पर श्रण से लेते हैं। पिछले दिना में सहकारी बैंक (Co-operative Banks), भिन्न पूँजी वाले व्यापारिक बैंक (Joint Stock) तथा सरकार के प्रनियदा के कारण दशी बैंकों को कम डिपॉजिट भिमन लया है। पारट्याकित, कैश सर्टीफिकेट, सरकारी श्रण, नशवल सकिस्त सर्टीफिकेट, तथा सहकारी बैंकों तथा भिन्न पूँजी वाले व्यापारिक बैंकों की कान्यदति अधिक आकर्षण है। वे डिपॉजिट आकर्षित करने के लिए बिप्रा का सहारा लेते हैं। इस कारण जनता उनकी ओर अधिक आनयित होनी है और उँटे डिपॉजिट अधिक भिमन जाती है। यह दशा बकर भित लोगों की डिपॉजिट लेने हैं उँह माँगने पर नकदा म हा रुपया निकालने का सुभिया नहीं दते। कुछ देशी बैंकर अवश्य ही बक पूँजी और पाम धुक देते हैं कि उँ व्यापारिक बैंक तथा इम्पारियल बैंक उन चर्का का स्वीकार नहीं करत इस कारण उन पर कटे गए चर्कों का चलता मोमिति हो होता है। जब सीजन आन पर इँह आधन रुपय की आवश्यकता होता है ता वे एक दूसरे से उधार से लेत हैं और बड़े बड़े बैंकों और सहकारी बैंक तथा अन्य भिन्न पूँजी वाले व्यापारिक बैंकों में प्रामिसरा नाट पर श्रण लेलेते हैं या फिर इंडिया का बैंकों से मुना कर अविन कोष (Fund) प्राप्त करते हैं।

देशी बैंकर किसानों को सीधे ऋण नहीं देते परन्तु स्थानीय महाजन अथवा साहूकार को आवश्यकता पड़ने पर ऋण देते हैं। यह महाजन किसानों को ऋण देते हैं। यही नहीं, देशी बैंकर व्यापारियों और आइतियों को भी ऋण देते हैं जो खेती की पैदावार को खरीदते हैं। देशी बैंकर व्यापारियों और व्यवसायियों को साख देने का कार्य विशेष रूप से करते हैं। वे हुंडी भुनाते हैं, हुंडियों खरीदते हैं, पैदावार पर ऋण देते हैं और डिपॉजिट स्वीकार करते हैं। कुछ औद्योगिक केन्द्रों में देशी बैंकर मिलों में अपना धन जमा कर देते हैं। धन मुहूर्त जमा (Fixed Deposit) के रूप में जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त देशी बैंकर बड़े-बड़े कारखानों को और कोई आर्थिक सहायता नहीं देते। हां आफ कारखानों के डिबेंचर खरीद कर, तथा कम्पनियों के शेयरों को अपने पास रख कारखानों को अधिक समय के लिए ऋण देते हैं।

देशी बैंकर बहुधा प्रामिसरी नोट पर ऋण देने हैं। यदि रकम बहुत अधिक हुई तो प्रामिसरी नोट पर जमानती के हस्ताक्षर ले लेते हैं, नहीं तो बहुत अधिक सूद लेते हैं। एक दूसरा तरीका यह है कि ऋण लेने वाला प्रामिसरी नोट लिखने के स्थान पर ऋण को स्वीकार करते हुए एक रसीद लिख देता है जिसमें सूद की दर का भी उल्लेख रहता है। एक तीसरा तरीका स्टाम्प पर पुर्जा लिखाकर ऋण देने का है। इस बॉर्ड में ऋण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक सभी बातों का उल्लेख रहता है। एक चौथा तरीका ऋण देने का यह भी है कि ऋण लेने वाला बैंकर की बही में ही हस्ताक्षर करदे और उस पर स्टाम्प लगा दिए जाये। जब बैंकर बहुत बड़ी रकम ऋण देते हैं तो भूमि तथा इमारत इत्यादि को बंधक रख लेते हैं किन्तु उस दशा में सूद की दर कम कर दी जाती है।

ऋण देने के अतिरिक्त देशी बैंकर हुंडी का कारबार बहुत अधिक करते हैं। हुंडियाँ कई प्रकार की होती हैं। (१) दर्शनी हुंडी का भुगतान तुरन्त करना पड़ता है। मुहूर्त हुंडी की एक अवधि होती है (११, २२, ३३, ४४ दिन इत्यादि ३६१ दिन तक)। धनलोभ और शाहजोग हुंडियाँ भी होती हैं। उनका भुगतान करने से पूर्व बैंकर को यह निश्चय कर लेना पड़ता है कि वह जिस व्यक्ति को भुगतान कर रहा है वही उस हुंडी का न्यायोचित स्वामी है। यदि वह शलत व्यक्ति को भुगतान कर देता है तो वह वास्तविक स्वामी के लिये फिर भी देनदार रहेगा। किन्तु दर्शनी हुंडी और मुहूर्त हुंडी को जो भी व्यक्ति उपस्थित करे उसे भुगतान कर देने से बैंकर का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता। हुंडियों देखनहार (Bearer) और फरमान योग (Payable to Order) भी होती कभी-कभी यह लोग हुंडियों को अपने एजेंट तथा अन्य व्यापारियों

इसलिए निम्न दत्ते हैं जिससे उन्हें रुपये प्राप्त हो जाय। उदाहरण के लिए एक व्यापारी को दस हजार रुपये की आवश्यकता है। वह अपने एजेंट तथा किता अन्य व्यापारी पर, जिससे उसका सम्बन्ध है १५ हजार का हुंडी लिए जाता है और उसको किसी देशी बैंकर से भुना कर रुपये प्राप्त कर लेता है। निम्न दर को दर पर न्याय बैंकर हुंडी भुनाते हैं उसको बाजार दर कहते हैं। यह बाजार दर घटती बढ़ती रहता है और मित्र मित्र व्यापारिक कम्पनों की बाजार दर में बहुत मितता रहती है। हुंडियों के द्वारा न्याय बैंकर रुपये का एक स्थान से दूसरे स्थान का प्रवाह है।

बैंकिंग का काम करने पर अनिवार्य न्याय बैंकर अन्य व्यापार भी करते हैं। उनका जो पृथक् बैंकिंग के कारोबार में लगा हुंडी है उसमें तथा व्यापार में लगी हुंडी पृथक् में बाँध भेद नहीं किया जा सकता। जब भी आवश्यकता हुई हथर ही पृथक् उपर लगा दी जाता है। कल मन्त्रालय प्रांत १ नईकोटा चेन्न और सम्बन्ध प्राप्त के गुलतानी हा एत देशी बैंकर हैं जो बैंकिंग के साथ अन्य व्यापार नहीं करते हैं। नहीं तो अधिकांश न्याय बैंकर प्रवास, गृह तथा अर्थ तथा का पैदावारों रुपये और साना चीनी का व्यापार या मसू या फाटका करते हैं। इनके अनिवार्य १ जनरल मरचण्ट प्राइम ब्रॉकर जेल्मन (नवरका) का भी काम करने हैं। व्यापार १ माय माय के शक्कर, तेल, आठ के कारखानों तथा कपान गृह धान रहम तथा गीला १ कारखानों का भी चलाते हैं। सत्र १ म हम यह यह भक्त हैं कि न्याय बैंकर बैंकिंग के साथ और माँ व्यापार तथा व्यवसाय करते हैं और भन्ना उनका अपने व्यापारिक तथा व्यावसायिक कारोबार से बैंकिंग का अपना अधिक लाभ होता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि पिछले दिनों में देशी बैंकरों का बैंकिंग कारोबार कम होता जा रहा है इस कारण उन्होंने अपना ध्यान व्यापार तथा व्यवसाय में और अधिक लगाना आरम्भ कर दिया है।

देशी बैंकरों की अग्रगति के कारण—देशी बैंकरों का क्रमशः अग्रगति हो रहा है। उसका नीचे निम्न कारण मुख्य है —

(१) इम्प्लीमेंट बैंक मित्रि पूँजी के व्यावसायिक बैंक (Joint Stock Banks) तथा सहकारी बैंक (Co-operative Banks) की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा। इम्प्लीमेंट बैंक में रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए बहुत सुविधा है। इस कारण देशी बैंकर रुपये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में उससे हाथ नहीं कर सकते। सहकारी बैंकों का सरकार से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण वे सरलतापूर्वक डिपॉजिट आकर्षित कर लेते हैं और

मिश्रित पूँजी वाले बैंक प्रणाली देने में उनसे होख करते हैं। इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के होते हुए भी देशी बैंकों ने अपनी कार्यपद्धति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जिससे वे इस प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें।

(२) उनकी अवनति का दूसरा कारण यह है कि हुंडियों पर स्टाम्प-क्यूटी बहुत अधिक है इस कारण हुंडियों का चलन और कारबार कम होता है।

(३) बैंकर्स साक्षी एक्ट (Bankers Evidence Act.) में जो बैंकों को कानूनी सुविधायें प्राप्त हैं वे देशी बैंकों को प्राप्त नहीं हैं।

(४) वस्तुओं का निर्यात (Export) करने वाली फ़र्में अब प्रमुख मंडियों और व्यापारिक केन्द्रों में अपनी शाखायें स्थापित करने लगी हैं। वे अभी तक इनको ही अपना एजेंट बना देती थीं। इस परिवर्तन का फल यह हो रहा है कि देशी बैंकों का एजेंसी का कारबार भी कम होता जा रहा है।

(५) देश में व्यापार का विस्तार होने के कारण देशी बैंकों को व्यापार में अधिक लाभ दिखलाई देने लगा है अतएव वे सहज और व्यापार की ओर अधिक ध्यान देने लगे हैं।

पिछले कुछ वर्षों से कुछ उच्च दर्जे के देशी बैंक अपनी कार्यपद्धति को बदलने लगे हैं और आधुनिक बैंकिंग के ढंग को अपनाने लगे हैं। वे चेक और पास बुक का उपयोग करते हैं और सेविंग डिपॉजिट भी स्वीकार करते हैं।

देशी बैंकों तथा उनके ग्राहकों का सम्बन्ध—सभी बैंकिंग इनफ़ोर्मरों की कनेटियों ने देशी बैंकों की सम्झाई और ईमानदारी की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। ग्राहक उनका बहुत आदर करते हैं और उन्हें अपना हित और भित्त हैं। वे केवल अपने ग्राहकों से बैंकिंग का कारबार ही नहीं करते वरन् व्यापार सम्बन्धी सलाह और परामर्श भी देते हैं। वे अपने ग्राहकों के बार पर दृष्टि रखते हैं और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वे किस कारबार का कारबार करते हैं। अपने ग्राहकों से ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति का ठीक-ठीक पता रहता है जिसका वे अपने बैंकिंग कारबार में पूरा लाभ उठाते हैं।

देशी बैंकों का व्यापारिक बैंकों (Commercial Banks) से सम्बन्ध—यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि साधारणतः देशी बैंक अपनी पूँजी और डिपॉजिटों से ही काम चलाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे एक दूसरे से रुपया ले लेते हैं। किन्तु जब व्यापार की तेजी होती है और उनके ग्राहक ऋण की माँग करते हैं तो उनके यह साधन पर्याप्त नहीं होते। उन्हें इम्पोर्टिंग बैंक, विनिमय बैंक (Exchange Banks) तथा व्यापारिक बैंकों

के पास आर्थिक सहायता के लिए प्रिय होकर जाना पड़ता है। निम्न यह बैंक उन्हीं बैंकों को श्रेष्ठ देखते हैं जिसका नाम उनकी स्वीकृत सूची में है। इम्पीरियल बैंक तथा प्रत्येक व्यापारिक बैंक उन सूची बैंकों का एक स्वीकृत सूची रखता है जिनका वह श्रेष्ठ तथा उच्च मानता है। यही नहीं, उन सूची में यह भी निर्धारित रहता है कि जिस बैंक का अधिक न अधिक निम्न श्रेष्ठ दिया जा सकता है। अतः अन्तर यह बैंक सूची बनाने की शक्ति पुनः ही उन्हें श्रेष्ठ मन है।

राष्ट्रीय बैंक इनकायता कमटी तथा प्रांतीय बैंकिंग कमिटियों के सामने गाने दल हुए देश के बैंकों के प्रतिनिधियों ने बार बार यह शिक्षा देना कि इम्पीरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंक उनका साथ देना महाबल-मति का व्यवहार नहीं करते जैसा कि एक बार होने के लिये उचित मान्य होना चाहिए। जब न इम्पीरियल बैंक में श्रेष्ठ मन है तो इम्पीरियल बैंक उनके नारदार का जिस भरोसे हम न जान-बूझता करता है वह उनको बहुत खलना है। किन्तु भी इम्पीरियल बैंक उन्हें यह सुविधाएँ प्रदान नहीं करता जो व्यापारिक बैंकों का प्रदान करता है। यहाँ स्पष्टि बहुत व्यापारिक बैंकों को है। कभी-कभी बहुत ऊँचे दल के प्रतिष्ठित देशी बैंकों को भी श्रेष्ठ देना सरकारी कर दिया जाता है। इन कारणों से उत्तर में इम्पीरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों का कहना है कि देश के बैंक हमारे साथ काम देना नहीं रखते और वे बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य व्यापार तथा छोटे मनुष्यों अधिक देना रहते हैं कि उनका अधिक श्रेष्ठ देना जालिम का काम है। उनकी ठीक ठीक आर्थिक स्थिति को जान लेना कठिन होता है, क्योंकि वे कभी अपनी लेनो देना का लेखा (Balance Sheet) तैयार नहीं करते। इस कारण उनकी श्रेष्ठ देने में सावधानी बरतना आवश्यक है।

हम कहें यह नहीं कि ऊपर लिये आर्थियों में बहुत लय है। जब इम्पीरियल बैंक तथा व्यापारिक बैंक को किसी देशी बैंक की पक्की आर्थिक स्थिति न सम्पन्न न पिशपास और भरोसा हो जाता है तो वे उसको एक प्रकार आर्थिक सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए मदरास के चेदिया और बम्बई के मुलतानी बैंकों का इम्पीरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों से श्रेष्ठ प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं होती। बैंकिंग के विद्वान के भी यह सर्वथा विरुद्ध है कि जो देशी बैंक छोटे तथा अन्य व्यापार में अधिक पैसा हो उसको अधिक श्रेष्ठ दिया जावे।

देशी बैंकों के समूह के दोष और गुण—यदि हम आनपूर्वक देशी

बैंकों के कार्यों का अध्ययन करें तो हमें उनके संगठन में निम्नलिखित दोष दिखाई पड़ेंगे :—

(१) उनमें से अधिकांश दक्कियानूमी और रूढ़िवादी हैं और आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। उनमें समय के साथ अपनी कार्यपद्धति को बदलने की क्षमता नहीं है और न वे नई दिशाओं में अपने कारबार को बढ़ाने की ही क्षमता रखते हैं। वे अपनी कारबार पुराने ढंग में चलेते और बहुत ही गुप्त रूप से करने के अनुरक्त हैं। इस कारण सर्वसाधारण की दृष्टि को वे आकर्षित नहीं कर पाते और न उनका जनता पर अधिक प्रभाव ही पड़ता है। इसका सम्भवतः एक कारण यह है कि देशी बैंकिंग का कारबार केवल कुछ परिवारों में ही सीमित है इस कारण उसमें नया रुचिर नहीं आता। इस कारण उनमें नये विचारों का समावेश नहीं हो पाता। इनके दक्कियानूसी होने तथा पुराने ढंग से निपटें रहने का एक कारण यह भी है कि वे आधुनिक बैंकों के सम्पर्क में बहुत कम आते हैं।

(२) उनके संगठन का दूसरा दोष यह है कि वे बहुत कम जमा (डिपॉजिट) लेते हैं जो आधुनिक संगठित बैंकों का मुख्य कार्य है। इसका फल यह होता है कि देशवासियों की वसूली डिपॉजिट के रूप में आकर्षित नहीं होती और न उसका उपयोग अधिक उत्पादन के लिए हो पाता है। बहुत-सी पूँजी देश में बेकार पड़ी रहती है।

(३) वे व्यापार में दुष्टियों का उपयोग कम करते हैं। नक़द रुपये का उपयोग अधिक करते हैं।

(४) उनका व्यापारिक बैंकों से कोई सम्बन्ध नहीं होता इस कारण देश में दो द्रव्य-बाज़ार (Money Markets) साथ-साथ एक दूसरे से टूटकर रहकर काम करते हैं और दो तूट की दरें प्रचलित रहती हैं। यही नहीं, रिज़र्व बैंक का भी हम पर कोई निर्भरण नहीं है। इस कारण देशी बैंकिंग असंगठित रहता है।

यद्यपि देशी बैंकों के संगठन में ऊपर लिखे दोष हैं, परन्तु फिर भी उनकी देश को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देश में बड़े-बड़े नगरों को छोड़ कर छोटे स्थानों और मंडियों में व्यापारिक बैंकों की शाखाएँ नहीं हैं। वहाँ केवल देशी बैंक ही बैंकिंग की सुविधाएँ प्रदान करते हैं। यद्यपि पिछले वर्षों में देश में मिश्रित पूँजीवाले व्यापारिक बैंकों का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है, नये बैंक खोले गए और पुराने बैंकों ने अपनी शाखाओं का सूत्र ही विस्तार किया, फिर भी देश के विस्तार को देखते हुए बैंकिंग की सुविधा कम है। और भारत जैसे

शुद्धि प्रधान देश में इस बात की तो उम्मीद सम्भावना ही नहीं हो सकती कि बड़े गाँवों, कस्बों और मण्डियों में बँकों की प्राचीन स्थापित हो सकें। यहाँ तो दूरी बँकर ही काम कर सकते हैं।

उनके पास शतान्दियों का बैंकिंग अनुभव है जो पाँची दूर-पीड़ी उनको मिला है। उनके काम करने का ढंग कम खर्चीला है और उनका बैंकिंग अनुभव अनुभूत है। अतएव उसको नाट न होने देना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। वही बातों को ज्ञान में रखकर सेट्रल बैंकिंग कमेटी ने देशी बैंकों के सुधार के लिए सुझाव रखे थे। सेट्रल बैंकिंग कमेटी ने इस बात पर जोर दिया था कि जब रिजर्व बैंक की स्थापना हो जाये तो देशी बँकरो का सम्बन्ध रिजर्व बैंक से स्थापित कर देना चाहिए।

देशी बैंकर और रिजर्व बैंक का सम्बन्ध—यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि सेट्रल बैंकिंग कमेटी ने इस बात पर जोर दिया था कि रिजर्व बैंक से स्थापित हो जाने पर देशी बँकरो का उससे सम्बन्ध स्थापित हो जाना चाहिए। अतः, जब रिजर्व बैंक की स्थापना हो गयी तो रिजर्व बैंक से नीचे निम्नी शर्तों पर देशी बैंकों को अपने से सम्बन्धित करने का प्रस्ताव रखा —

(१) जो भी देशी बैंकर रिजर्व बैंक से सम्बन्धित होना चाहेगा और रिजर्व बैंक से सुविधायें प्राप्त करना चाहगा उसे शुद्ध बैंकिंग के अनिश्चित आय व्यापार को छोड़ देना होगा।

(२) उन्हें अपना रिहाब ठीक प्रकार से निम्न प्रकार रिजर्व बैंक कहे उस प्रकार—रखना होगा। अपने हिस्सा की नियमित रूप से आय-व्यय परीक्षाओं से जाँच (आडिट) करवाना होगी।

(३) रिजर्व बैंक आवश्यकता समझने पर उनके रिहाब और कारबार का निरीक्षण कर सकेगा। उन्हें रिजर्व बैंक से समय समय पर अपने कारबार के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी और सूचनाएँ देना होंगी। रिजर्व बैंक निम्न नीति जानकारी उनको चाहेगा उन्हें देने होगी और रिजर्व बैंक को अपने बैंकिंग कारबारका नियन्त्रण करने का अधिकार होगा।

(४) प्रत्येक देशी बैंकर की निम्न की पूँजी बच से कम पाँच लाख रुपये होगा और ठाँकी अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा करना होगा। रिजर्व बैंक ने इससे मीठा सम्बन्ध स्थापित न करने अप्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने का प्रस्ताव मा रने थे, और उनकी अपनी राय अप्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने के पक्ष में ही अधिक थी।

अब, लिखा प्रस्ताव केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी के मत के विरुद्ध था। केन्द्रीय

बैंकिंग जॉय कमिटी (Central Banking Committee) का यह मत था कि आरम्भ में देशी बैंकों के साथ नरमी का व्यवहार करना चाहिए, उन पर कड़ी शर्तें न लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए आरम्भ में कुछ वर्षों तक देशी बैंकों को रिजर्व बैंक में अनिवार्य रूप से जमा (Deposit) रखने पर विवश न करना चाहिए। किन्तु पहली गश्ती चिट्ठी में रिजर्व बैंक ने जो ऊपर लिखी शर्तें लिखकर भेजीं वे इतनी कठोर थीं कि कोई देशी बैंकर उनको स्वीकार करने के लिए तैयार न था।

इस पहले प्रस्ताव का ऐसा घोर विरोध हुआ कि रिजर्व बैंक को २६ अगस्त १९३७ को एक दूसरी योजना उपस्थित करनी पड़ी जो केन्द्रीय बैंकिंग कमिटी की सिफारिशों के अनुरूप थी और उसमें देशी बैंकों का रिजर्व बैंक से सीधा सम्बन्ध हो जाने की व्यवस्था थी। किन्तु शर्तों पर रिजर्व बैंक देशी बैंकों को अपने से सम्बन्धित करने के लिये तैयार था वे नीचे लिखी थी :—जो देशी बैंकर रिजर्व बैंक से सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं उन्हें अपने कारबार को शुद्ध बैंकिंग तक ही सीमित रखना होगा, वे दूसरे प्रकार का व्यापार न कर सकेंगे। उन्हें अपने हिसाब को ठीक-ठीक रखना होगा और बलियेबुक (Balancesheet) से उसकी जाँच करवानी होगी और जब रिजर्व बैंक चाहेगा तो उनके हिसाब का निरीक्षण कर सकेगा। रिजर्व बैंक उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो भी मूचना चाहेगा वह देनी होगी। शिक्षाबल बैंक जो भी विवरण-पत्र (Statement) अपने कारबार के सम्बन्ध में समय-समय पर रिजर्व बैंक को भेजने हैं वे उन्हें भी भेजने होंगे और लेनी-देनी का लेखा (Balance Sheet) इत्यादि जो कंपनी एक्ट के अनुसार बैंकों को प्रकाशित करना अनिवार्य है वे उन्हें भी प्रकाशित करने होंगे। जब देशी बैंकों की जमा (Deposit) उनकी पूँजी से पाँच गुना अधिक हो जावे तभी उन्हें रिजर्व बैंक में अनिवार्य जमा (Compulsory Deposit) रखनी होगी अन्यथा उन्हें रिजर्व बैंक में अनिवार्य जमा रखने की कोई आवश्यकता न होगी। प्रत्येक देशी बैंकर की कम से कम २ लाख की पूँजी (Capital) रखनी होगी जिसे ५ वर्षों में बढ़ा कर पाँच लाख करना होगा। जो देशी बैंकर इन शर्तों को पूरा करेंगे रिजर्व बैंक उनकी हकिटियों और विलों को मुनावेगा, सरकारी सिक्कुरिटि की जमानत पर ऋण देगा और रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए वही सुविधायें देगा जो वह शिक्षाबल (Scheduled) बैंकों को देता है।

इस प्रस्ताव को भी देशी बैंकों ने स्वीकार नहीं किया। वे न तो अन्य व्यापार को छोड़ना ही चाहते हैं और न अपने हिसाब का निरीक्षण हो कराने

न लिए तैयार है। रिजर्व बैंक का हम प्रस्ताव है कि यह बैंक बैंक और कारबार को छोड़कर अतिरिक्त डिपॉजिट बैंकिंग की जा आवेगी जोट स्टॉक बैंक (Joint Stock Bank) स्वरूप करेगी जो भागधार करेगी। किन्तु यहाँ बैंक द्वारा उठाया गया धन को बैंक को तैयार न हो और न ये यही समझ करों कि वह किसी को अपना दिनांक लिखा है। इसमें कोई संशय नहीं कि इन में यही प्रकार का रिजर्व बैंक के बनाने का भाव है। जहाँ जहाँ रिजर्व बैंक व्यवस्था की गई है वहाँ वहाँ यह सिद्ध हो रहा है कि यही बैंक एक ही में अपनी पुरानी पद्धति को छोड़कर आधुनिक पद्धति को अपनाने का प्रयत्न कर रहा है। रिजर्व बैंक को प्रारम्भ में १९६६ में बनाया गया था। हमें पता है कि रिजर्व बैंक और यही बैंक का एक सम्बन्ध स्थापित हो रहा है। यद्यपि रिजर्व बैंक ने अपनी ओर से ऊपर लिखी शर्तों पर यहाँ उल्लेख की सम्बन्धित करने का प्रस्ताव आपस नहीं लिया है।

रिजर्व बैंक । जहाँ यह सिद्ध हो रहा है कि रिजर्व बैंक से भाग सम्बन्ध स्थापित नहीं करके तो भी भारतीय रुपयाबाजार (Indian Money Market) में उठाया सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है यदि देश में एक खुला बिल बाजार (Open Bill Market) स्थापित हो जाय और उन्नति कर जाय। उक्त बिल बाजार में यहाँ बैंकों के बिल भाग स्थापनापूर्वक बिना रोक-टोक प्रचलित हो और भुनाय जायें। रिजर्व बैंक इस दिशि को सान्ने न लिये स्वीकृत यहाँ बैंकों के बिलों के बिलों तथा धन का स्थापना कर लया यदि वह किसी विश्वव्यापी बैंक के द्वारा उपस्थित हो जायेंगी किन्तु रिजर्व बैंक की यह प्रार्थना कि देश में खुला बिल बाजार स्थापित हो जायगा संदेहास्पद है क्योंकि इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। हम इस सम्बन्ध में आगे विचार करयें।

१ अक्टूबर १९४० का रिजर्व बैंक अधिनियम एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की एक न योजना निकाला। उक्त योजना के अनुसार रिजर्व बैंक करना एक न दूसरे स्थान को स्थापना पर भ्रम का उन देशी बैंक और गैर शिक्षित (Non Scheduled) बैंकों का मुद्रिया तथा जो कुछ धन को प्राप्त करेंगे, और जो रिजर्व बैंक की स्थापना करने पर है। अतः तब तब तब यहाँ बैंकों ने इस मुद्रिया में सामान्य उदाहरण का प्रयत्न किया है और किई रिजर्व बैंक ने स्वीकृत किया है उनका सन्ध्या अनुमति पर गिनी जाने लायक है।

अतः में हमें यह न भूलना चाहिए कि देशी बैंक का अधिकतर धन ही

हाथ में है। उनके स्वार्थ में यही है कि वे अपने कारबार के ढंग में सुधार करें और व्यापारिक बैंकों के अनुसार ही अपनी कार्य-पद्धति बना लें। साथ ही उन्हें अपने कारबार को भी मिश्रित पूँजी वाली कंपनियों (Joint Stock Companies) के रूप में संगठित करना चाहिये। अथवा जैसा कि रिजर्व बैंक का मत है उन्हें बड़ा कंपनियों (Discount Companies) में संगठित हो जाना चाहिए और बिलों के धुनाने का कार्य विशेष रूप से करना चाहिए तभी ये पतप सकेगे।

देशी बैंकों का देशी व्यापार के लिए बहुत उपयोग है अतएव उनका संगठन उनके लिये तथा देश के व्यापार के लिए हितकर होगा। किन्तु जब तक हम प्रकार की व्यवस्था नहीं लाती कि शुद्ध बैंकिंग व्यापार से ही उन्हें यथेष्ट लाभ हो तब तक उनमें यह आशा करना व्यर्थ है कि वे अन्य व्यापार छोड़ देंगे। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें बड़े व्यापारिक बैंक अपना एजेंट बना लें। इस प्रकार उन स्थानों पर भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो जावे जहाँ बैंकों की ग्राह्य अभी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती, और देशी बैंकर बिलों तथा ट्रेडियों को धुनाने का अधिक-अधिक काम अपने हाथ में लें। यह तभी हो सकता है जब देश में बिल बाजार उन्नत हो।

(२) मिश्रित पूँजी वाले बैंक या व्यापारिक बैंक—(Joint Stock Banks) अथवा (Commercial Banks) एजेंसी गृह (Agency Houses)—यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि बैंकिंग व्यवसाय भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से होता आया है, किन्तु आधुनिक ढंग के बैंक अभी थोड़े समय से ही यहाँ स्थापित हुए हैं। वास्तव में बम्बई और कलकत्ते में जो एजेंसी गृह (Agency Houses) थे वही इन बैंकों के जनक थे। इन एजेंसी गृहों की स्थापना अंग्रेज व्यापारियों ने की थी। बम्बई और कलकत्ते के यह एजेंसी गृह वास्तव में व्यापार करते थे। वही उनका मुख्य कार्य था, किन्तु वे व्यापार के साथ बैंकिंग का कारबार भी करते थे। उनके पास निज की पूँजी (Capital) नहीं होती थी। वे जनता से डिपॉजिट (जमा) आकर्षित करके ही कार्यशील पूँजी (Working Capital) इकट्ठी करते थे। वह एजेंसी गृह ईस्ट इंडिया कंपनी के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों ने स्थापित कर लिए थे। जिन कर्मचारियों ने देखा कि भारतीय व्यापार में घनीयता का असौभाग्य क्षेत्र है उन कर्मचारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर व्यापार करना आरम्भ कर दिया। यों-तो यह एजेंसी गृह मुख्यतः व्यापार करते थे किन्तु अंग्रेज व्यापारियों के लिए साख का प्रबंध करने के लिए उन्होंने बैंकिंग विभाग भी खोल रखे-थे। देशी

बैंकिंग की ही व्यवस्था की ओर थी, फिर वे धीमे-धीमे द्वारा किये जा रहे विदेशी व्यापार के लिए साधन का प्रबंध कर मचा। उन धनार्थी थे। हमारा मुख्य कारण यह था कि उन्हें अंग्रेजी दम के विदेशी व्यापार का नतीजा कुछ मान था या प्रारंभिक अंग्रेज व्यापारी उनका भाषा की ही समझ थी।

यह एंग्रेजी यह दृष्टान्तों द्वारा करते थे, उन्होंने नैतिक धर्म, शराब बनाने, चमड़े के कारखाने, कपास, आटा, आर सफाई का बिना के व्यापार में तथा इस्ट इंडिया कंपनी तथा सरकारी वसायतियों और अंग्रेज व्यापारियों के एजेंट तथा बंदर का काम करते थे। वे अविश्वसनीय वास्तविकता लागाते विवादास्पद काफ़िर करते थे। इनके अनिश्चित ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों का अर्थ यह था कि वे बहुत बड़े बंदर का काम ही एंग्रेजों यहाँ के बैंकिंग विभाग में नतीजा करते थे। विवादास्पद द्वारा साधन धर्म का यह एंग्रेजों यह अंग्रेज व्यापारियों को फायदा की लाभाई के लिए तथा अफीम, तेल, कपास तथा रस्म के व्यापार के लिए बहुत ऊँचे दूर पर उधार देते थे। उधम में कुछ एंग्रेजों यह कागज़ी मुद्रा (Paper money) भी निरालते थे। इनमें से कुछ एंग्रेजों यहाँ न भारत में एवं प्रथम योरोपियन धर्म के बैंक स्थापित किये। उदाहरण के लिए मेसर्स एलेक्ज़ेंडर एंड कंपनी ने १७७० में बैंक ऑफ हिरोलान्द स्थापित किया, मेसर्स पागर एंड कंपनी ने 'कलकत्ता बैंक' स्थापित किया, और मेसर्स मैकिन्टॉश एंड कंपनी ने 'बैंक ऑफ कलकत्ता' स्थापित किया। 'बंगाल बैंक' तथा 'बनारस बैंक ऑफ इंडिया' १७८३ के लगभग स्थापित किए गए थे। इन्हें भी कलकत्ते के एंग्रेजों यहाँ ने स्थापित किया था। यह एंग्रेजों यह अपने व्यापार के साथ साथ बैंकिंग का कारखाना भी करते थे अतएव उनकी व्यापारिक लाभ के अनिश्चित बैंकिंग विभाग ने यह और कमीशन की आमदनी भी होती थी। अतः, भारत में प्रथम योरोपियन बैंक के बैंक १ मिथिल गंजी के बैंक के और न थे फलतः शुद्ध बैंकिंग कारखाना ही करते थे। वाक्य या विद्वाने जैसा साधारण व्यापार करने वाली योरोपियन फर्म और बैनितमूलक और प्रोपियेटर जैसी जहाज़ी कंपनियों भी बैंकिंग कारखाना करना थीं। इन बैंकिंग और साधारण व्यापार के मिश्रण का जो परिणाम होता था वही हुआ। इसके अनिश्चित इन एंग्रेजों यहाँ ने विवादास्पद किए हुए रूप से सट्टा (Speculation) करना आरंभ किया, हमारे, कोयले की खानों, बहजों, फहवा तथा गरम मण्डले के बागों तथा भूमि के खरीदने और धातु, कपास और रस्म की मिल्नों को चलाने में अनाप सनाप रूप से लगाया। इस सब का परिणाम यह हुआ कि १८२८-२९ में यह एंग्रेजी-यह रूप गए। एंग्रेजी यहाँ के इनके न साथ ही उनके बैंकिंग विभाग तथा उनके

स्थापित किए हुए बैंक भी डूब गए क्योंकि बैंकों का रुपया उन एजेंसी एहों के कारबार में लग गया था। कलकत्ता बैंक १८२६ में, बैंक ऑफ हिन्दुस्तान १८२२ में, और कमर्शियल बैंक ऑफ कलकत्ता १८२३ में डूब गए।

इन बैंकों ने सर्व प्रथम भारत में कागजी मुद्रा (Paper Currency) का चलन आरम्भ किया। हिन्दुस्तान बैंक के प्रचलित नोटों का मूल्य २५ लाख रुपये था। बंगाल बैंक के नोटों का चलन ८ लाख रुपये के लगभग था। इनमें से प्रत्येक बैंक यह चाहता था कि उनके नोट सरकारी दफ्तरों तथा कजानों में स्वीकार हों। सरकार ने पहले जनरल बैंक के नोटों को स्वीकार किया किन्तु १७६३ में उसके बन्द हो जाने पर 'बैंक ऑफ कलकत्ता' के नोटों को स्वीकार किया। १८७० में इस बैंक के ४३ लाख रुपये के नोट प्रचलित थे। इसी प्रकार का एक बैंक मद्रास (१६८८) और दूसरा बैंक बम्बई (१७९४) में स्थापित हुआ किन्तु १८२६-३० में एजेंसी एहों के साथ ही यह बैंक भी डूब गए। इस प्रकार योरोपियन ढंग के बैंकों की स्थापना का पहला युग समाप्त हुआ।

इस बैंकिंग संकट के उपरान्त १८६० तक बहुत कम बैंक स्थापित हुए। इस काल में १२ बैंक स्थापित हुए जिनमें आठ बैंक डूब गए। यह सब योरोपियनों द्वारा स्थापित हुए थे। डूबने वाले बैंकों ने जनता का धोखा दिया और डिपॉजिट करने वालों का रुपया मारा गया। किन्तु इस काल में तीन प्रेसीडेंट बैंक भी स्थापित हुए जिनका विशेष महत्व था।

प्रेसीडेंट बैंक—प्रेसीडेंट बैंक तीन थे जहां कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के चार्टर द्वारा स्थापित हुए थे। बैंक ऑफ बंगाल १८०६ में, बैंक ऑफ बम्बई १८४० में और बैंक ऑफ मद्रास १८४६ में स्थापित हुआ। बैंक ऑफ बंगाल १८०६ में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से स्थापित हुआ था। १८०६ में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने उसे चार्टर दे दिया। तब ने यह बैंक ऑफ बंगाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

इन तीन प्रेसीडेंट बैंकों की स्थापना ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरी करने तथा देश के भीतरी व्यापार को आर्थिक सहायता देने के लिए की गई थी। जब कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी तो उसके यह आशा की गई थी कि जब सोने या चांदी की मांग होगी तो वह जनता को उचित मूल्य पर देगा तथा सरकारी सिक्कूरिटियों और सरकारी ट्रेजियर्स (Treasury Bills) के मूल्य को गिरने से बचावेगा तथा कागजी मुद्रा को निकालेगा। उस समय बंगाल में करेंसी (मुद्रा) की दशा बड़ी खराब थी। इस कारण वहाँ कागजी मुद्रा चलाने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी।

आरम्भ में प्रेसीडेंसी बैंक सरकार के फंड (Funds) को खर्चते थे, किन्तु अठारहवीं शताब्दी के अन्त में सरकार ने गिरे हुए खजाने (Reserve Treasuries) तथा निज़ा और तख्तान में खजाने स्थापित किए। इस कारण प्रेसीडेंसी बैंकों का सरकारी कारबार में अन्तना सम्बन्ध नहीं रहा। परन्तु सरकार के इस निर्णय से द्रव्य बाजार में बाण की कमी कभी बहुत कम हुई वह बाण गो। लगातार तथा मालगुदारी के रूप में बहुत सा द्रव्य इन खजानों में जमाकर रखा हो जाता था क्योंकि द्रव्य बाजार में लिए वह अभाव था। तब उनका समस्त द्रव्य बाजार (Money Market) को द्रव्य की बहुत अधिक आवश्यकता होना था क्योंकि यह समय गरीब बिक्री का होता था। फिर भी सरकार ने प्रेसीडेंसी बैंकों के पास एक न्यूनतम द्रव्य राशि रखनी का निर्णय कर लिया था। इस न्यूनतम द्रव्य राशि पर प्रेसीडेंसी बैंक कोश भा खुर नहीं देने थे। यदि इस न्यूनतम द्रव्य राशि में कम स्थिति सरकार प्रेसीडेंसी बैंकों के पास रखती तो सरकार का उस काम पर खुर नही पड़ता था। किन्तु व्यवहार में सरकार ने निर्धारित न्यूनतम भाग में गरीब अधिक खर्चा प्रेसीडेंसी बैंकों के पास रखवा। इससे अधिक प्रेसीडेंसी बैंक सरकारों के अधिकारों का निष्कासन तथा उसका प्रबंध करते थे। सरकार ने उन पर कुछ नियंत्रण भी स्थापित कर रखा था। उनसे आप-स्वयं निरीक्षण पर सरकारों नियंत्रण था, सरकार उनमें समय-समय पर उन्नत कारबार के साथ-साथ कुछ नया करना थी तथा उन्हें अपने हिस्से का साप्ताहिक लेखा निकालना पड़ता था।

१८७६ के प्रेसीडेंसी बैंक ऐक्ट के अन्तर्गत प्रेसीडेंसी बैंकों पर कुछ बंधन भी लगा दिए गए थे। प्रेसीडेंसी बैंक विदेशी निविमय (Foreign Exchange) का काम नहीं कर सकते थे, वे भारत के बाहर विनिमय नहीं ले सकते थे। वे ६ महीने से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकते थे और वे अधिकतम संपत्ति की जमानत पर दो ऋण दे सकते थे। इस प्रावधानों नाटों पर भी वे कम नहीं दे सकते थे जिन पर दो स्वयं-व्यवस्था में कम दे इस्तेमाल हो। व्यक्तिगत जमानत पर ऋण नहीं दिया जा सकता था और माल की जमानत पर तथा कप दिया जा सकता था विभव यह माना जा उनसे स्वामित्व भान रा कागज पत्र (Titles) जमानत के रूप में जमा कर देने पर हो।

यह आय बगाल का आरम्भ में ५० लाख फूँटों या विधुम १० लाख सरकार के हिस्से थे। बाद की वर्ष का फूँटों बढ़ा दी गई। फर्रुखा का ग़ज़ल, व्यस्त दशा की मुवारने के लिए बैंक आय बगाल ने कामकी मुद्रा निकाली। सरकार केवल बैंक आय बगाल के ही नोटों को स्वीकार करती थी, इस दृष्टि से

बैंक आब बंगाल प्रमुख प्रेसीडेन्सी बैंक था। बैंक आब बाम्बे की हिस्सा पूँजी ५२,२५,००० रु० थी जो कि ५२२५ हिस्सों में बँटी हुई थी। इसमें ३ लाख रुपये के हिस्से बम्बई सरकार ने लिए थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह-युद्ध होने के कारण संसार में कपास का अकाल पड़ा और भारतीय कपास को माँग और मूल्य वेहद बढ़ गया। उसके कारण बम्बई में नये कारखाने इत्यादि स्थापित हुए और वहाँ जेयरों का सट्टा बहुत हुआ। बैंक आब बाम्बे का रूपरा इस सट्टे में हूँ गया। इस कारण यह बैंक १८६८ में टूट गया। किन्तु ठनी वर्ष तक एक नया बैंक १ करोड़ रुपये की पूँजी से स्थापित किया गया। बैंक आब मद्रास ३० लाख रुपये की पूँजी से स्थापित किया गया। मद्रास सरकार ने उसमें ३ लाख रुपये के हिस्से लिए थे। इस बैंक की कार्य-पद्धति वही थी जो अन्य दो प्रेसीडेन्सी बैंकों की थी।

आरम्भ से ही सरकार तथा प्रेसीडेन्सी बैंकों का घनिष्ठ सम्बन्ध था। सरकार ने इन बैंकों के फेबल हिस्से हाँ नहीं लिये थे किन्तु सरकार इनके संचालक बोर्ड में अपने डायरेक्टर भी नियुक्ति करती थी। इन बैंकों को सरकारी बैंकिंग कारबार करने का एकाधिकार प्राप्त था। १८६२ तक उन्हें कागजी मुद्रा (Paper money) निकालने का भी अधिकार था, किन्तु १८६२ के उपरान्त उनसे यह अधिकार छीन लिया गया और सरकार ने कामजी मुद्रा निकालना आरम्भ किया। १८६१ में जब प्रेसीडेन्सी बैंकों से नोट निकालने का अधिकार ले लिया गया तो उनकी हानि को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने यह निश्चय किया कि प्रेसीडेन्सी नगरों (कलकत्ता, बम्बई, मद्रास) में सरकार अपनी सारी रोकड़ (Cash Balances) प्रेसीडेन्सी बैंकों के पास रखेगी। वास्तव में प्रेसीडेन्सी बैंकों ने कागजी नोट बहुत अधिक कमी भी नहीं निकाले क्योंकि सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेसीडेन्सी बैंकों पर कड़े बन्दन लगा दिये थे। उदाहरण के लिए एक प्रतिबन्ध तो यह था कि सब चालू जमा (Current Deposit) तथा कागजी नोट जो चलन में हैं बैंकों के नगद कोष (Cash Reserve) के तीन गुने से अधिक नहीं हो सकते। बाद को इसको बढ़ा कर चार गुना कर दिया गया।

१८७६ में सरकार ने एक प्रेसीडेन्सी बैंक एक्ट बनाया जिसने इन बैंकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस कानून के अनुसार सरकार ने इन बैंकों में अपनी हिस्सा पूँजी निकाल ली। हिस्सा पूँजी निकालने के साथ ही सरकार ने डायरेक्टरों तथा बैंक के चेक्रेटरी तथा खज़ांची को नियुक्त करने का भी अधिकार छोड़ दिया। साथ ही बैंकों के पास सरकारी रकम रखने की सुविधा

भी समाप्त कर दी गई। आगे से यह बैंक बनता न दिया चिट ले सकता थे तथा सरकारी सिक्कुरिटियों तथा कुछ अन्य प्रकार का सिक्कुरिटियों में रकमा जमा सकते थे। बिलों को खरीद सकते थे उनका भुना सकते थे, स्वीफ्ट बिलों तथा जामिसरा तोटों व आधार पर बन सकते थे। सिक्कुरिटिया को अपने पास घमाहर के रूप में सुरक्षित रखने के लिए दर जार कर सकते थे। तथा नीचे आर राई का खर्चा किसी का काम कर सकते थे। निम्न पैसा ऊपर हम बता चुके हैं कि इन चीजों को भारत में गहर सिंक्रिजिज लान तथा विदेशा विनिमय (Foreign Exchange) का काम करने का मनासा था। इनका मुख्य कारण यह था कि विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Banks) नहीं चाहते थे कि प्रत्येक बैंक उनमें प्रतिस्पर्धा कर सके। सरकार ने कुछ प्रतिबंध तो बैंकों का ठोक लान पर रखा कि सिंक्रिजिज लान तथा विदेशा विनिमय बैंक को ऐसा ही कारण लगाया गया था। प्रत्येक बैंकों को लान द्रव्य प्रसार में सिंक्रिजिज न लेने का परीणाम यह होता था कि नहीं द्रव्य वापार (Money Market) में द्रव्य का कमी होता था ता खुद का दर बहुत ही ऊंचा हो जाता था और वापार का हानि पहुँचता थी। इन प्रतिबंधों से प्रत्येक बैंक की व्यवसायिता तथा कारवार पर बुरा प्रभाव पड़ता था।

इन सब फलाना व हानि को भा प्रभावों को भेड़ा व बहुत उन्नति की। उ होने पेश में बन जाते रजपति का तथा उन जानों पर सरकारी करों का मोटों को भुनाने का मुश्किल कर सरकारी करों का मोटों व नवन का बहुत अधिक बनाया। वही तथा उ होने डिगिजिज बैंकिंग का उन्नति का। सरकार से सम्बन्धित हानि व कारण देश में गहरा प्रभाव था और भारतवासी बैंकों में उनका प्रमुख स्थान था। प्रथम महायुद्ध के समय इन बैंकों ने सरकार का परामारा अर्थ निकालने तथा सरकारी ऋणिया (Treasury Bills) बेचने में बहुत महायता का। इस प्रकार १९२१ तक यह प्रभावों का बैंक सकलतापूर्वक बैंकिंग काय करते रहे। म १९२१ इंग्लिश बैंक बैंक का स्थापना हुआ और उसने इन चीजों को सांभाली तथा का ले लिया। इस प्रकार व समाप्त हो गई।

मिश्रित पूंजी माल बैंक (Joint Stock Banks) — ये सभी बैंक जा कि भारत में इंडियन रुपना एक्ट के अन्तर्गत स्थापित हुए हैं इन बैंकों में आते हैं। यह तो हम पहले ही कह आते हैं कि १८६० तक भारत में बैंकों का प्रारम्भिक काल था। सामित उत्तर दायित्व (Limited Liability) का सिद्धांत उस समय तक कानून द्वारा स्थापित नहीं हुआ था। अस्तु उस समय तक जा मो बैंक नहीं स्थापित हुए थे असीमित दायित्व (Unlimited Liability)

के आधार पर थे। केवल 'जनरल बैंक ऑफ इंडिया' जो १७८६ में स्थापित हुआ इसका अपवाद था। अधिकांश लोगों का विचार है कि अलकॉर्नर एण्ड कंपनी एजेंसी यह द्वारा स्थापित बैंक ऑफ हिन्दुस्तान, भारत में सबसे पहला बैंक था किन्तु ऐसी बात नहीं है। भारत में संभवतः सबसे पहला बैंक मद्रास सरकार ने १६८८ में स्थापित किया। दूसरा बैंक १७२४ में बम्बई प्रान्त में स्थापित हुआ। बैंक ऑफ हिन्दुस्तान तीसरा बैंक था। वह तो हम ऊपर लिख चुके हैं कि १८२६-३० में एजेंसी यहाँ के डूबने से वह बैंक संकट में आ गए और उसके उपरान्त १८६० तक जो १२ बैंक स्थापित हुए वे भी डूब गए। केवल तीन प्रेसीडेंसी बैंक ही इस काल के बैंकों में सफलतापूर्वक कार्य करते रहे। इस काल के बैंकों का केवल एक ही उल्लेखनीय कार्य हुआ अर्थात् उन्होंने भारत में सर्व प्रथम कागजी मुद्रा को प्रचलित किया।

भारतीय बैंकिंग के विकास का दूसरा काल १८६० से १९०० तक था। इस काल में परिमित दायित्व (Limited Liability) का सिद्धान्त अपना लिया गया था फिर भी इन ४० वर्षों में बैंकों का विकास बहुत धीरे हुआ। उत्तर प्रदेश अमेरिका के यह-युद्ध के फल स्वरूप बम्बई में जो उष्टे का वातावरण गरम हुआ उसमें अवश्य बम्बई में कई बैंक स्थापित हुए किन्तु वे शीघ्र ही डूब गए और पीछे कट्ट अनुभव छोड़ते गए। १८७० में भारत में केवल दो मिश्रित पूँजी वाले बैंक थे जिनकी पूँजी (Capital) और रक्षित कोष (Reserve Fund) पाँच लाख से अधिक था। १९०० तक इस प्रकार के बैंकों की संख्या ६ हो गई। उनमें से अधिक महत्वपूर्ण बैंक नीचे लिखे थे—दलाहादाद बैंक (१८६५), दलादस बैंक ऑफ शिमला (१८७४) जो २९२३ में डूब गया, अवध कमर्शियल बैंक (१८८१), यह पहला बैंक था जो भारतीयों द्वारा स्थापित हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक (१८६४), यह बैंक मुख्यतः लाला हर किशन लाल के प्रयत्नों से स्थापित हुआ था। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम २० वर्षों में बैंकों का विकास शीघ्रतापूर्वक हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के दस वर्षों में उनकी डिपॉजिट में ५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जब कि विनिमय बैंकों (Exchange Banks) की डिपॉजिट में केवल ३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और प्रेसीडेंसी बैंकों की डिपॉजिट में ११ करोड़ की कमी हुई। परन्तु यदि हम समस्त काल (४६ वर्षों) पर दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात होगा कि बैंकों का विकास बहुत धीमी गति से हुआ और उनकी उन्नति संतोषजनक नहीं हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि इस काल में देश की आर्थिक उन्नति नहीं हुई, साथ ही

वस्तुओं का मूल्य गिरता गया। यही कारण था कि बैंकों की उन्नति की गति बहुत धीमी रही।

तीसरा काल १९०० से १९१३ तक कहा जा सकता है जिसमें बाद का समय (१९१३-१८) भारतीय बैंकों के लिए बहुत ही संकट का था। इस काल में भारतीय बैंकों की उन्नति का गति तात्त्विक और उनका मातृ में काफी रुकावट नहीं आर। इस काल में बैंकों की उन्नति का एक कारण स्वदेशी आन्दोलन भी था। १९०५ के उपरांत स्वदेशी आन्दोलन की लहर के साथ देश में बहुत ही पथ और उनके साथ ही बैंक भी स्थापित हुए। १९०१ में लाजा हरकिशन लाल के प्रभुत्व में पीपुल्स बैंक स्थापित हुआ जिन्से उपरान्त स्वदेशी आन्दोलन के प्रभाव से जो बैंक स्थापित हुए उनमें बैंक आव बर्मा (१९०४) सर्व प्रथम था। इसने उपरान्त उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में कई बैंक स्थापित हुए। इनमें बैंक आव बर्मा के अतिरिक्त बैंक आव इंडिया, बैंक आव मैसूर, बैंक आव मद्रास की इंडिया तथा बैंक नया मद्रास बैंक आव इंडिया अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ तो आज उड़े पाँव की अवस्था में हैं। १९०६ तक भारतीय मित्रित बैंकों के बैंकों का निष्ठापित म ११ करोड़ रुपये का यदि हुई जबकि विनिमय बैंकों की निष्ठापित म ११ करोड़ रुपये और प्रेसीडेंसी बैंकों की निष्ठापित में ६ करोड़ की वृद्धि हुई। इस काल में (१९००-१३) उन बैंकों की सत्ता जिसका पूँजी और रक्षित धन (Reserve Fund) पाँच लाख रुपये से अधिक था, ६ से बढ़ कर १८ हो गई। इन अतिरिक्त उस काल में छोटे-छोटे बैंकों का सत्ता बहुत अधिक हो गई। बहुत से नये छोटे बैंक स्थापित किए गए।

१९१३-१४ के बीच भारतीय बैंकों की भयंकर संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट काल में २५ बैंक बंद हुए और उनकी २ करोड़ रुपये की पूँजी बंद गई। इनके बाले बैंकों में अधिकांश छोटे छोटे बैंक थे जिन्से आवे वर्तन के लगभग बड़े बैंक भी थे जो बंद हुए। इसका कारण बैंकिंग कारबार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और जनता का उन पर से विश्वास उठ गया। भारत में यह सबसे बड़ा बैंकिंग संकट था। १८२६-३२ में एंग्लो इंडो बैंक बंद होने से, १८५७ में सिन्धु बैंक कारण, तथा १८६४-६६ में अमेरिकन इंड-सुड के फलस्वरूप उत्पन्न संकट के कारण जो बैंकिंग संकट हुए वे इसके सामने नगण्य थे। सबसे पहले १७ सितम्बर १९१३ को पीपुल्स बैंक ने अपनी कारबार बंद किया और फिर रिथित बिगड़ती ही गई। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बम्बई में विशेष रूप से बहुत पैसा बंद। अक्टूबर १९१३-१४ में ५५ बैंक बंद हुए। यद्यपि इस काल में वास्तव

बैंक, बैंक आन-अपर इंडिया तथा इंडियन स्पीशी बैंक जैसे बड़े-बड़े बैंक भी डूब गये, किन्तु अधिकांश डूबने वाले बैंक बहुत छोटे थे। यों भारतवर्ष में व्यक्तिगत निर्वलता के कारण कभी-कभी एक दो बैंक डूब जाते हैं किन्तु ऐसा बड़ा संकट कभी भी नहीं आया। इस सम्बन्ध में हमें एक बात न भूल जानी चाहिए कि केवल भारत के ही बैंक डूबे हों ऐसा नहीं था। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि सभी देशों में बैंकों पर संकट आये हैं और वे डूबे हैं। अस्तु, इस संकट-काल को लेकर जो बहुत से पाश्चात्य विद्वान इस बात की घोषणा करते हैं कि भारतीयों में आधुनिक ढंग के बैंक चलाने की योग्यता ही नहीं है, गलत है। इन बैंकों के डूबने के मुख्य कारण नीचे लिखे हैं।

बहुत से बैंक नकद कोष (Cash Reserve) कम रखते थे, बहुत से डूबने वाले बैंकों का प्रबन्ध खराब था और उनके संचालक ईमानदार नहीं थे, हिस्सेदारों ने कभी बैंकों के प्रबन्ध में दिलचस्पी नहीं ली। वे उसकी ओर से उदासीन रहे। इन बैंकों ने अपने रुपये को लगाने में बैंकिंग सिद्धान्तों की नितान्त अवहेलना की, रुपये को उद्योग में लम्बे समय के लिए अटक दिया। यह बैंक जब अपना लेनी-देनी का लेखा (Balance Sheet) निकालते थे तो उस समय दिये हुए धन को वापस बुला कर नकद कोष को अधिक दिखला देते थे, किन्तु वास्तव में नकद कोष बहुत कम होता था। यह बैंक लाभ न होते हुए भी लाभ बँटते थे। इन बातों से जमा करने वाले धोखे में आ जाते थे। सरकार ने भी बैंकों के इन दोषों को दूर करने का कोई प्रयत्न न किया और न देश में कोई केन्द्रीय बैंक (Central Bank) ही था कि जो बैंकों को बैंकिंग के सिद्धान्तों की अवहेलना करने से रोकता और उनका नियंत्रण करता। इसके अतिरिक्त इन बैंकों में आपस में कोई सहयोग नहीं था वरन् वे एक दूसरे से ईर्ष्या रखते और परस्पर हानि पहुँचाने का प्रयत्न करते थे। इसके अतिरिक्त इन बैंकों के डूबने का एक और भी कारण था। अधिकांश डूबने वाले बैंकों की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) बहुत अधिक थी, किन्तु उनकी चुकती पूँजी (Paid up Capital) बहुत कम थी। इस कारण उन्हें ऊँची दर पर सूद देकर डिपॉजिट आकर्षित करना पड़ती थी। और जब वे अपने ग्राहकों को उनकी डिपॉजिट पर अधिक सूद देते थे तो उन्हें अपने रुपये को जोखिम के कारबार में लगाना पड़ता था, क्योंकि सभी वे उस पर अधिक सूद कमा सकते थे और डिपॉजिटों पर अधिक सूद दे सकते थे। ऊपर लिखे कारणों से ही देश में बैंकिंग संकट उपस्थित हुआ था। इस बैंकिंग संकट का एक अच्छा परिणाम भी हुआ। राज्य तथा जनता सभी को एक केन्द्रीय बैंक (Central

Bank) की आवश्यकता का अनुभव होने लगा कि जो देश में बैंकिंग कारबार का नियन्त्रण कर सके, और साथ ही इस बात का भी आवश्यकता का अनुभव हुआ कि एक बैंकिंग ऐक्ट बनाया जावे जिसमें बैंक नियन्त्रित और अच्छे ढंग से चल सकें। जिससे बैंक की स्थापना से पहली कमी दूर हो गई और बैंकिंग कानून बन जाने से सुरक्षा। यहाँ नहीं, मिथिन पूँजी वाले बैंकों का भी अनुभव में यह बतला दिया कि आरम्भ में जबकि बैंकों का किसी दृष्टि में स्थापना हो तो अधिक द्रव्य कोष (Cash Reserve) रखने की जरूरत है। तब से भारतीय व्यापारिक बैंक उत्पन्न हो गए और अतिवृद्ध कोष रखने लग।

यद्यपि भारतीय बैंकिंग व्यवसाय को १९१३ के सफट से पकड़ा लगा किन्तु कुछ के कारण उनका अचानक और पतन प्रारम्भ नहीं हुआ। १९१४ से १९२० तक कुछ काल में तथा १९२१ का आर्थिक तेज़ी (Boom) में इन बैंकों की सत्ता तथा उनकी डिपॉजिट दोनों में ही वृद्धि हुई। १९१८ में ताता औद्योगिक बैंक की स्थापना हुई तथा अन्य बैंक भी स्थापित हुये, किन्तु १९२० में आर्थिक मंदी (Depression) तथा मुद्रा गतोचल (Deflation) दोनों का आरम्भ हुए और बैंकों को फिर सफट का सामना करना पड़ा। यह आर्थिक संकट १९२४ तक रहा। बैंक की कुल डिपॉजिट जो १९२१ में ८० करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी, गिरने लगी और १९२४ में केवल ५५ करोड़ रह गई। यद्यपि सफट उतना गंभीर नहीं था फिर भी कुछ बैंक बंद गए। १९१८ से १९२५ के बीच में ८४ बैंक बंद हुए जिसमें ४ करोड़ ८० लाख रुपये की पूँजी की हानि हुई। १९२३ सबसे बुरा वर्ष था। उस एक वर्ष में २० बैंक जिसकी शुद्धता पूँजी (Paid up Capital) चार करोड़ ६५ लाख रुपये थी बंद हुए। १९२३ में बंद होने वाले बैंकों में ताता औद्योगिक बैंक तथा एलार्म बैंक अग्रिम स्थान पर मुख्य थे। अंत में ताता औद्योगिक बैंक को सेंट्रल बैंक आर इंडिया ने लिया।

१९२३-२४ की आर्थिक मंदी (Depression) के उपरान्त भारत में व्यापारिक बैंकों के इतिहास को तीन कालों में बाँटा जा सकता है। पहला काल १९२४-२५ से १९३० तक का है। यद्यपि इस काल में बैंकों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ किन्तु उत्पत्ति अतोपेक्षित नहीं हुई। डिपॉजिट १९२१ से (घराना ८० करोड़) बहुत कम रहे। १९३० में कुल डिपॉजिट ६८ करोड़ रुपये थी। इस सुधार के पश्चात् १९३१ में फिर बैंक डिपॉजिट २ करोड़ कम हो गई और बैंक को योद्धा मंदी का सामना करना पड़ा। फिर १९३२ से १९३७ तक दूसरा काल माना जा सकता है। इस काल में बैंकों की स्थिति में पहले की अपेक्षा तेज़ी से सुधार हुआ। १९३७ में बैंकों की डिपॉजिट बढ़ कर १०८ करोड़ रुपये हो गई।

इस काल के उपरान्त १९३८ में फिर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा और बैंकों की कुल डिपॉजिट २ करोड़ रुपये घट गई यद्यपि छोटे बैंकों की डिपॉजिट में वृद्धि हुई। इस काल में छोटे-छोटे बैंक डूबे किन्तु ट्राव्‌कोर नेशनल एण्ड किलन बैंक, बनारस बैंक तथा बंगाल नेशनल बैंक उल्लेखनीय हैं। इसके उपरान्त १९३९ के उपरान्त आश्चर्यजनक तेजी से बैंकों की संख्या तथा डिपॉजिट में वृद्धि हुई।

नये बैंकों में नीचे लिखे बैंक उल्लेखनीय हैं : भारत बैंक, मूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जयपुर बैंक, हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक, बैंक आव बीकानेर, जोधपुर बैंक, हबीब बैंक, एक्सचेंज बैंक आव इंडिया एण्ड अफ्रीका, हिन्द बैंक, डिस्काउन्ट बैंक आव इन्डिया, हिन्दुस्तान मरकंटाइल बैंक, नेशनल सेविंग्स बैंक। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से बैंक स्थापित हुए। वही नहीं कि इस काल में सैफ़ों छोटे बड़े बैंक स्थापित हुए और उन्होंने अपनी शाखायें तेज़ी से स्थापित करना आरम्भ कर दिया वरन् पुराने बैंकों ने भी अपनी पूँजी बढ़ाई तथा अपने कारबार के क्षेत्र का विस्तार किया और ब्रांचों की वृद्धि करना आरम्भ कर दिया। सेंट रामकृष्ण डालमिर्षों के द्वारा भारत बैंक की स्थापना होते ही प्रत्येक बड़े व्यवसायी ने अपना-अपना बैंक स्थापित करना आरम्भ कर दिया और देश में बैंकों की एक वाव ली आ गई। इनमें छोटे-छोटे बैंकों की संख्या ही अधिक थी। जहाँ १९३९-४० में देश में केवल ५५ शिखल बैंक थे वहाँ १९४६-४७ में ६६ शिखल बैंक हो गये और १९४७-४८ में यह संख्या १०१ हो गई। देश के विभाजन के बाद १९४९-५० में भारत में शिखल बैंकों की संख्या ६४ थी। इसी प्रकार जहाँ १९३८ में शिखल बैंकों को १२७८ ब्रांचें थीं वहाँ ३१ मार्च १९४९ में उनकी संख्या ३००८ हो गई। पर १९४९-५० से शिखल बैंकों की ब्रांचों में १२८ ब्रांचें कम हो गईं। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से जो ब्रांचे सफल नहीं हो रही थीं वे बन्द कर दी गईं। द्वितीय महायुद्ध के समय से जो वैकिंग में विस्तार हो रहा था उसका यह स्वाभाविक परिणाम था। बैंकों की डिपॉजिट में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। जहाँ १९३९-४० में शिखल बैंकों की कुल डिपॉजिट २३४.५९ करोड़ थी वहाँ १९४७-४८ में शिखल बैंकों की डिपॉजिट १०५०.५४ करोड़ के लगभग हो गई और देश के विभाजन के बाद १९४९-५० में केवल भारत के बैंकों की डिपॉजिट ८७०.३८ करोड़ थी। जुलाई १३, १९५१ को भारत के शिखल बैंकों की कुल डिपॉजिट लगभग ८९७.७९ करोड़ के थी। नोन-शिखल बैंकों की ३१ मार्च १९५० को कुल डिपॉजिट ३६ करोड़ रुपये के लगभग थी। वैकिंग कम्पनीज़ एक्ट के तहत में जो नोन-शिखल

। अब देश करते हैं उनकी सत्या करावर कम होनी जा रही है
- रक्षा से ठाक डिपॉजिट म या कमी होनी जा रही है। मार्च १९४६ में
इनका डिपॉजिट ४७ करोड़ से जो मार्च १९५० को कम होनहोये ३६ करोड़
तक घटुन गए।

युद्ध काल और उसने उपरान्त दोनों की यह बाड़ मुद्राप्रसार (Inflation) का परिणाम था। सरकार व आदश पर रित्तों बैंक ने जो लेजी से कागजी मुद्रा छापनी आरम्भ कर दी उससे हो परिणामस्वरूप बैंकों का बाड़ आ मद और डिपॉजिट में उड़ि हुए। परन्तु बहुत न बैंक न बिना यह समझे कि उनका पाठ समष्ट बोध्य और दुसाल समसारा है मार्च ज्योनी आरम्भ कर था। मार्च व खालने में उहांन इन बात का भी ध्यान नहीं रक्खा कि कहीं मार्च जोलना लाभदायक होगा और कहीं मार्च जोलना लाभदायक नहीं होगा। बहुत से बकों का पूजी बहुत ही कम था सिन्तु उहोंने भा मार्चें स्थापित कर दीं। इनका परिणाम यह हुआ कि १९४६-४७ में बहुत से छोटे छोटे बैंक जो कि शिकलू पैक नहीं थे (किरायन बंगाल व) ठूठ गए। १५ अगस्त १९४७ व उपरान्त जो भारत में भाष्य लूट-पाट और नर सहार हुआ उसमें भी एबाब के बैंक की बहुत बड़ा हानि हुए। तब १९४८ के मध्य तक बैंक ने देश के विमानन के असर से अपन बापका ममान लिया था। युद्ध और युद्ध के बाद बैंकिंग के विस्तार की प्रवृत्ति का भी अन्त हुआ। डिपॉजिट की माशा में कमी आ-। कुछ शिकलू बैंक और बड़ नोन शिकलू बैंक सिमथर अक्टूबर १९५८ में बूध गए। फिर भी बैंकों व बहुत अधिक हो जाने व कारण कहीं-कहीं बहुत अनुचित प्रतिस्पर्दा दिसलाई पड़नी है। प्रविष्य में बहुत से छोटे छोटे बैंकों को बड़े बैंकों से मिल जाना होगा नहीं तो वे खड़े नहीं रह सकते। वन्दरि लका" के उपरान्त अभी तक आर्थिक मदी (Depression) का भारतीय बैंकों की सांगना नहीं करना पड़ा है फिर भी यह कहा जा सकता है कि रित्तव बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंक उन्नति कर रहे हैं और शिकलू बैंकों की स्थिति अच्छी है।

मिश्रित पूंजी वाले बैंकों के कार्य — अब हम मिश्रित पूंजी वाले बैंकों (Joint Stock Banks) के कार्यों का विवेचन करेंगे। यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि मिश्रित पूंजी वाले बड़ व्यापारिक बैंक (Commercial Bank) होते हैं और वे उन सभी कार्यों को करते हैं जो कि व्यापारिक बैंक करते हैं। इन बैंकों का मुख्य कार्य चालू (Current), मुहती (Fixed) और सेविंग डिपॉजिट आकर्षित करना तथा थोड़े समय के लिए श्रय देना है,

विलों को भुनाना या खरीदना, (यद्यपि भारतीय बैंक यह कार्य कम करते हैं, क्योंकि यहाँ बिल-बाजार का उदय नहीं हुआ है) सरकारी सिक्कूरिटियों (प्रतिभूति) में अपना रुपया लगाना, नकद साख (Cash Credit) देना, खेती की पैदावार को गाँव से नियत कन्दरगाहों तक और कन्दरगाहों से विदेशों से आए हुए माल को देश के भीतरी बाजारों तक पहुँचाने में आर्थिक सहायता देना है। इसके अतिरिक्त यह बैंक और भी छोटे-मोटे कार्य करते हैं, उदाहरण के लिये रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना इत्यादि।

यह बैंक कृषि के घंघे को सीधी आर्थिक सहायता नहीं देते। वे केवल बड़े जमींदारों, चाय इत्यादि के बगीचों के मालिकों तथा ऐसे व्यक्तियों को ही ऋण देते हैं जो कि बाजार में शीघ्र बिक सकने योग्य जमानत (Security) देते हैं। पहले तो यह बैंक मुहत्ती जमा (Fixed Deposits) पर ४ से ५ प्रतिशत वार्षिक सूद देते थे और चालू खाते (Current Account) पर १½ से २ प्रतिशत सूद देते थे किन्तु अब अधिकांश बैंक चालू खाते पर कुछ भी सूद नहीं देते और मुहत्ती जमा पर भी २ प्रतिशत से अधिक सूद नहीं देते।

बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों में जहाँ स्टॉक बाजार की सिक्कूरिटि अधिक मिलती है वहाँ यह बैंक उनको जमानत पर ऋण देते हैं। किन्तु जिन मंडियों तथा बाजारों में स्टॉक बाजार की सिक्कूरिटि अधिक नहीं मिलती वहाँ खेती की पैदावार को रख कर यह बैंक ऋण दे देते हैं। भारतवर्ष में सार्वजनिक गोदाम नहीं हैं इस कारण बैंक अपने गोदाम रखते हैं जहाँ ग्राहक का माल रख कर उसकी जमानत पर उसे ऋण दे दिया जाता है। ऐसा भी होता है कि बैंक ग्राहक के गोदाम पर ही अधिकार कर लेते हैं और वही माल बंद करके ग्राहक को ऋण दे देते हैं। वे सोना चाँदी, कपड़ा इत्यादि वस्तुओं को रखकर भी ग्राहकों को ऋण दे देते हैं। कारखानों को उनको तैयार माल के विरुद्ध तथा अन्य सिक्कूरिटियों के विरुद्ध ऋण देते हैं। कभी-कभी बैंक इमारतों तथा अन्य स्थावर सम्पत्ति को गिरवी रखकर कर्ज़ दे देते हैं किन्तु इस प्रकार का कर्ज़ अधिक नहीं दिया जाता। इसका कारण यह है कि इस प्रकार की सम्पत्ति शीघ्र ही बेची नहीं जा सकती।

बैंक व्यक्तिगत जमानत पर भी कर्ज़ दे देते हैं। ऐसी दशा में कर्ज़दार जो प्राग्वित्री नोट लिखता है उस पर दो अच्छे हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। तराफ तथा मैनेजिंग एजेंटों के हस्ताक्षर होने पर बैंक आसानी से कर्ज़ दे देते हैं। हुंड़ी जो कि व्याप भी भारतीय बाजारों में प्रचलित है (यद्यपि पहले से उसका प्रचार कम है) वास्तव में दो हस्ताक्षरों वाला पत्र है, क्योंकि उस पर देशी बैंकों

का ब्यवान (Endorsement) होता है। किन्तु व्यापार की मात्रा को देखते हुए तथा व्यापारियों की क्षमक्षमताओं को देखते हुए जिनके दो हम्मानर वाले पत्रों को यह बैंक स्वीकार करके व्यापारियों को कन या मान देते हैं वे अप्रत्याशित कम हो सकते हैं।

कज्ञ देने का सबसे अधिक प्रचलित ढग यह है कि कज्ञदार बैंक को प्रामित्विरी नोट लिख देना है और कम्पनियों ने इसमें माल या बॉर्ड अथवा अन्य कोई सिक्कुरिटी बैंक के पास जमागत रूप में रख देता है और बैंक उस कज्ञदार के नाम नकद खात खाता (Cash Credit Account) खोल देता है। यह ढग दोनों पत्रों के लिए सुविधाजनक है। कज्ञदार पिठना कम्पा वारन में निरलगा है उस पर ही उसे छूट देना पड़ता है। फिर उसे यह भी सुविधा रहती है कि वह जब भी चाह तो उस खात में रुपया जमा करके अपना कुछ कन चुकाव। किन्तु कज्ञदार को जितनी नकद साख दी गई है उसकी आपा रकम पर अवश्य छूट देना होगा। कज्ञ देने का यह ढग भारत में बिल-बानार को विकसित नहीं होने देता। किन्तु यह अधिक प्रचलित है, क्योंकि बैंक और व्यापारी दोनों ही उसे पसंद करते हैं। बैंक का सुविधा यह है कि जब चाह तो नकद साख (Cash Credit) की इस सुविधा का ब्यवस ले मरुदा है अर्थात् कन दार को अधिक कज्ञ या खात देना अवकाश कर सकता है और कज्ञ लेने वाले को यह सुविधा होता है कि उसे निश्चय रकम पर ही छूट देना पड़ता है, पूरा रकम पर छूट नहीं देना पड़ता।

यह बैंक अधिकतर देश के मीठरी व्यापार के लिये अल्पकालीन साख (Short Term Credit) का प्रबन्ध करते हैं। विदेशी व्यापार, उद्योग धंधे तथा कृषि को यह बहुत कम सारा देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कुछ बैंकों ने विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) का कारबार करना आरम्भ किया है परन्तु अभी तक वह नहीं के बराबर है। उद्योग-धंधों को यह बैंक थोड़े समय के लिये नकद साख के रूप में या कज्ञ के रूप में सहायता देते हैं। अधिक समय के लिये स्थायी पूँजा (Block Capital) के रूप में यह बैंक उद्योग धंधों को सहायता नहीं देते।

भारतीय व्यापारिक बैंकों की कार्यपद्धति की एक विशेषता यह है कि बिलों की अपना सरकारी सिक्कुरिटियों में अपना रुपया अधिक लगाते हैं। इसका कारण यह है कि देश में व्यापारों बिलों तथा बैंक के स्वीकार योग्य पत्र (Papers) की कमी या अभाव है। अस्तु, बैंक अपना अधिकतर रुपया सरकारी सिक्कुरिटियों में लगाते हैं।

इनके अतिरिक्त भारतीय बैंक और भी सहायक बैंकिंग कार्य करते हैं। उदाहरण के लिये वे अपने ग्राहकों को अर्थ सम्बन्धी सलाह देते हैं, उन्हें व्यापार सम्बन्धी जानकारी कराते हैं, अपने ग्राहकों के लिए सरकारी सिन्क्यूरिटी तथा कम्पनियों के हिस्से खरीदते और बेचते हैं, अपने ग्राहकों के एजल में रुपया चुकाते हैं और वसूल करते हैं, अपने ग्राहकों के एसेट या प्रतिनिधि का काम करते हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त वे चाकियों की सुविधा के लिए साख-पत्र (Letter of Credit) देते हैं, रुपये को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए बैंक ड्राफ्ट देते हैं तथा सरकार, कम्पनियों तथा म्यूनिस्पैलिटी तथा कारपोरेशनों द्वारा निकाले हुए ऋण का अभिगोपन (Underwriting) करते हैं। वे अपने ग्राहकों की साख, आर्थिक स्थिति तथा प्रसिद्ध के सम्बन्ध में अन्य व्यापारियों को अपना मत देते हैं। वे अपने ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रूप से रखते हैं।

भविष्य में भारतीय बैंकों की अधिकाधिक विदेशी व्यापार की ओर ध्यान देना होगा। भारतीय बैंकों ने 'ट्रस्ट' का कारबार भी करना आरम्भ नहीं किया है और वे ग्राहकों के लिए शेयरों की खरीद-बिक्री का भी काम बहुत कम करते हैं। भविष्य में उन्हें इस ओर अधिक ध्यान देना होगा।

भारतीय व्यापारिक बैंकों के दोष तथा उनकी कठिनाइयाँ:—(१) भारतीय बैंकों को अभी तक सरकार से प्रोत्साहन नहीं मिला। म्यूनिस्पैलिटियाँ, विश्व-विद्यालय, पोर्ट ट्रस्ट, कोर्ट आब वार्डस ट्रस्टों इत्यादि का रुपया उनमें नहीं रक्खा जाता। यद्यपि अब धीरे-धीरे स्थिति बदल रहा है। १९३५ के पूर्व देश में कोई केन्द्रीय बैंक न होने के कारण उन्हें कठिनाई के समय ठीक नेतृत्व तथा सहायता नहीं मिलती थी और न उनमें आपस में सहयोग ही स्थापित हो पाता था। किन्तु रिज़र्व बैंक की स्थापना से अब यह कठिनाई दूर हो गई है।

(२) विदेशी विनिमय बैंकों (Exchange Banks) तथा इम्पीरियल बैंक की प्रतिस्पर्धा तथा आपसी सहयोग और सहानुभूति का अभाव भी उनकी उन्नति के मार्ग में एक रुकावट है। यह भी विचार है कि भविष्य में सहकारी बैंक (Co-operative Banks) भी उभरते होड़ करेंगे। जहाँ तक इन बैंकों की एक्सचेंज बैंकों तथा इम्पीरियल बैंकों से स्पर्धा का प्रश्न है, हम उन बैंकों से सम्बन्धित अध्यायों में लिख चुके हैं। और जहाँ तक उनमें आपस में तथा द्रव्य बाजार (Money Market) के अन्य सदस्यों में सहयोग तथा सद्भावना उत्पन्न करने का प्रश्न का है उसके लिए अखिल भारतीय बैंकर्स एसोसियेशन की स्थापना की आवश्यकता है।

(३) अभी तक बहुत से भारतीय भूधन तथा भारतीय व्यापार विदेशियों के हाथ में हैं और न रक्षणान्त आने देख के बैंकों को प्रोत्साहन देने हैं हम कारण भी भारतीय बैंकों की उन्नति तेजी से नहीं हुई। किन्तु अब भारत स्थगित हो गया है और यह कठिनाई अब क्रमशः दूर हो जायेगा।

(४) यही नहीं कि विदेशी व्यापारी तथा विदेशी व्यापारी फर्म अपने देश के बैंकों से अपना आचरण करती हैं परन्तु जो भारतीय व्यापारी इनके प्रोत्सर या प्रोत्साहन का काम करते हैं अथवा जिनका विदेशी बोमा कम्पनियों तथा विदेशी जहाजों कम्पनियों से आचरण हुआ है उनमें भी यह विदेशी फर्म और कम्पनियों विदेशी वित्तीय धर्म से आचरण पर विचार करते हैं।

(५) पिछले बैंक संहिता के कारण जो बैंक टूट गए उनसे बैंकों की स्थापना में कठिनाई हाथी थी, लोग बैंकों में हिस्से नहीं लेने थे और उनमें कदम जमा करने से हिचकिचाते थे, किन्तु अब यह कठिनाई दूर हो गई है। पिछले वर्ष में बैंकों की सहायता तथा डिपॉजिट में जैसी नज़रों में यदि हुई है उसे देखते यह कहना पड़ेगा कि बैंकों में विश्वास अब अविश्वस्यमान जाना रहा है।

(६) भारत की आर्थिक उन्नति में होने के कारण भी भारतीय बैंकों की उन्नति करी रही है। अस्तु, भारत की आर्थिक उन्नति न साथ साथ भारत में बैंकिंग कारबार का विकास होना तथा जनता में बैंकिंग की आदत बनना अविनाश है। अभी तक जनता में बैंकिंग की आदत कम है।

(७) हमने अतिरिक्त बैंकों को कुछ अन्य कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हिंदू तथा मुसलमानों ने पैतृक सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून इतना उलझे हुए हैं कि इस प्रकार की सम्पत्ति की जमानत पर श्रद्धा देना बैंकों के लिए अपने से खाली नहीं है। अस्तु बैंक उस सम्पत्ति की जमानत पर श्रद्धा देने से हिचकते हैं।

थोड़े समय के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि व्यापारी अपनी सम्पत्ति के प्रलेख (Documents) बैंक के पास बिना बंधन पत्र (Mortgage Deeds) लिखे और उनकी रजिस्ट्री कराये रख दें और उन प्रलेखों (Documents) का बैंकों के पास जमा कर देना ही अपेक्षा मान लिया जाये। किन्तु भारत में यह सुविधा केवल बम्बई, कलकत्ता, मदरास वर्र्णो नगरों में ही गई है। अन्य स्थानों में यह सुविधा बैंकों को प्राप्त नहीं है।

(८) व्यापारिक बैंक इस आशा से सरकारी सिक्कुरिटियों में अपना कदम लगाते हैं कि एकदम काल में सरकारी सिक्कुरिटियाँ शीघ्र ही नष्ट हो सकती हैं। किन्तु कभी-कभी उसमें कठिनाई पड़ जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ

कि बैंक इम्पीरियल बैंक से सरकारी सिक्यूरिटियों की जमानत पर ऋण प्राप्त न कर सके। अभी हाल में रिज़र्व बैंक ने भी इसी आशय की घोषणा की है कि यदि किसी बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वह आवश्यक नहीं है कि सरकारी सिक्यूरिटी के आधार पर उन्हें ऋण दे ही दिया जावेगा।

(६) भारत में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बैंक हैं कि जिनके पास अपनी निज की बड़े-छोटे पूँजी नहीं है, इस कारण उन्हें बहुत कठिनाई पड़ती है। वे डिपॉजिट अधिक आकर्षित करने के लिए सूद अधिक देते हैं और इस कारण उन्हें अपना अपना जोखिम के कारबार में लगाना पड़ता है, सभी वे अधिक सूद कमा सकते हैं। डिपॉजिट आकर्षित करने के लिए यह छोटे-छोटे बैंक दूर-दूर अन्य प्रान्तों में ब्रांचें स्थापित करते हैं, इस कारण उनकी देख-भाल और व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पाती और उन्हें बड़े बैंकों की प्रतिस्पर्धा को सहन करना पड़ता है। इस प्रकार के बैंक स्वभावतः निर्बल होते हैं और संकट के समय वे नहीं ठहर सकते।

(१०) इसके अतिरिक्त बहुत से बैंकों के डाइरेक्टर योग्य और अनुभवी नहीं हैं और योग्य वैकिंग कर्मचारियों की कमी है। यही नहीं, नये बैंकों को समायोजन यह अर्थात् क्लियरिंग हाउस (Clearing House) का सदस्य बनने में बड़ी कठिनाई होती है। क्लियरिंग हाउस पर विदेशी बैंकों का बहुत प्रभाव है और वे नये बैंकों को उसका सदस्य नहीं बनने देना चाहते। किन्तु अब क्रमशः यह कठिनाई दूर हो जावेगी।

(११) भारत के सभी बैंक अंग्रेजी में अपना कारबार करते हैं। उनके चेक, रसीदें, तथा हिसाब सभी अंग्रेजी में होता है। केवल कुछ ही बैंक ऐसे हैं कि जो हिन्दी में लिखे गए चेकों को तथा हिन्दी में किये गए हस्ताक्षरों को स्वीकार करते हैं। भारत में व्यापारियों तथा जनता का एक बहुत भाग अंग्रेजी नहीं जानता। भारतवर्ष की स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त अंग्रेजी का महत्त्व अब घटने का रहा है अतएव अब बैंकों को अपना कारबार हिन्दी में अथवा प्रान्तीय भाषा में करना चाहिए।

(१२) भारतीय बैंकों के सामने एक यह भी कठिनाई है कि यहाँ विलों तथा ऐसे पत्रों (papers) की बहुत कमी है जिन्हें बैंक स्वीकार कर सकें। इस कारण बैंकों की विवश होकर अपना अधिकांश कोष सरकारी सिक्यूरिटियों में लगाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत में बिना किसी सम्पत्ति की जमानत पर अथवा दूसरे हस्ताक्षर लिए हुए व्यक्तिगत साख पर ऋण देने की परिपाटी नहीं है, जबकि अन्य देशों में यह बहुत प्रचलित है और अधिकांश ऋण इसी

प्रकार दिये जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि पश्चिमीय देशों में 'एक व्यक्ति एक बैक' का चलन है अर्थात् एक व्यक्ति अपना सारा कारबार केवल एक बैंक से ही करता है। दूसरा कारण मैनेजिंग एजेंट है। बैंक जब किसी कंपनी को ऋण देते हैं तो वे कंपनी के चायरमैन के अतिरिक्त मैनेजिंग एजेंट के हस्ताक्षर अग्रहण लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कंपनी के वास्तविक वर्तमान धर्ता ही मैनेजिंग एजेंट ही हैं। एक तीसरा कारण यह भी है कि अभी तक इस देश में ऐसा 'पारमिट्रिक एजेंसिया' नहीं हैं जो व्यवस्थाओं का राज्य के सम्बन्ध में बैंकों को सारा जानकारी दे सकें।

(१६) भारतीय बैंकों ने अभी तक भारतीयों का परिस्थिति के अनुसार अपने संगठन को नहीं बनाया। वे ऐक्सचेंज बर्का तथा इन्वीरिपल बैंकों की नज़र मात्र रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक होता है फिर भी उनके कमचारियों में न तो यह कुशलता है और न वह योग्यता। भारतीय बैंकों में न तो विद्यार्थी ऐम्प्लॉयमेंट बैंकों का कुशलता ही प्राप्त की और न देशी बैंकों का सार्वजनिक और सिविलियन ही वे अपना मूढ़। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय बैंक भारत के अनुकूल बैंकिंग संगठन की नवीन पद्धति निकालें जो कि कम सर्चाली हो। क्योंकि भारत में ऐसे स्थान बहुत हैं कि जहाँ इतना करबार प्रारम्भ में तो नहीं मिल सकता कि एक आधुनिक शास्त्र का व्यव निकल सके परन्तु फिर भी वहाँ बैंकिंग की सुविधा की आवश्यकता है।

(१७) बहुतों लोग भारतीय बैंकों पर यह दोष लगाते हैं कि वे अपने वास्तविक लाभ का बहुत बड़ा अंश हिस्सेदारों को इसलिये बाँट देते हैं कि निम्न जनता में उनके प्रति विश्वास बना रहे। क्योंकि भारतीय जनता की यह धारणा है कि जो बैंक निम्न अल्प लाभ बाँटता है वह उतना ही अमीर है। जहाँ तक बड़े और पुराने बैंकों का प्रश्न है वह आरोप निराधार है, किन्तु छोटे बैंक यह करते हैं और इसका मुख्य कारण भारतीय जनता की यह भ्रमपूर्ण धारणा है।

अब परिस्थिति बदल गई है। यद्यपि भारत के विभाजन से पाकिस्तान में जिन बैंकों को अधिक प्राप्ति थी उन्हें बहुत क्षति उठानी पड़ी है, परन्तु फिर भी बैंकों का क्षेत्रों से विस्तार हुआ है और बड़े बैंक उन क्षेत्रों की दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

बैंक का वर्गीकरण—भारतवर्ष में बैंकों का वर्गीकरण दो प्रकार से हुआ है। एक वर्गीकरण सरकार का है और दूसरा रिज़र्व बैंक का है। भारत

सरकार जो बैंक सम्बन्धी आंकड़े छापती है उसमें दो प्रकार के बैंकों का उल्लेख होता है (१) पहली श्रेणी तो उन बैंकों की होती है कि जिनका चुकता पूँजी (paid up Capital) तथा रक्षित कोष (Reserve Fund) पाँच लाख रुपये से अधिक है। दूसरी श्रेणी उन बैंकों की है जिनकी चुकता पूँजी और रक्षित कोष १ लाख रुपये से अधिक है और पाँच लाख रुपये से कम है। १९३६ के उपरान्त बैंकिंग सम्बन्धी आंकड़े रिज़र्व बैंक छापने लगा है तब से दो अन्य श्रेणियाँ और जोड़ दी गई हैं। तीसरी श्रेणी के बैंक वह हैं जिनकी चुकता पूँजी और रक्षित कोष ५० हजार रुपये से अधिक तथा १ लाख से कम है और चौथी श्रेणी में वे बैंक आते हैं जिनकी पूँजी तथा रक्षित कोष ५० हजार रुपये से कम है।

रिज़र्व बैंक बैंकों को दो श्रेणियों में बाँटता है—(१) शिष्यूल बैंक (Schedule Banks) और गैर शिष्यूल बैंक (Non-Schedule Banks)। जिस बैंक की चुकता पूँजी और रक्षित कोष ५ लाख रुपये से अधिक हो तथा वह कुछ अन्य शर्तें पूरी करे तो वह शिष्यूल बैंक बन सकता है। किन्तु सभी इस प्रकार के बैंक शिष्यूल बैंक नहीं बन गए हैं।

भारतवर्ष में इंग्लैंड के आधार पर बैंकिंग विषय पर लिखने वाले पाँच प्रमुख बैंकों को 'बड़े पाँच' के नाम से पुकारते हैं। यद्यपि भारत के बड़े पाँच तथा ब्रिटेन के बड़े पाँच में कोई समानता नहीं है, परन्तु फिर भी अध्ययन की दृष्टि से इस प्रकार का विभाजन किया जाता है। यह 'बड़े पाँच' नीचे लिखे हैं (१) बैंक ऑफ इंडिया, (२) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, (३) इलाहाबाद बैंक, (४) पंजाब नेशनल बैंक, (५) बैंक ऑफ बम्बई। इनमें इलाहाबाद बैंक तो विदेशी बैंक है और शेष चार भारतीय बैंक हैं। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा बैंक ऑफ इंडिया के साधन बहुत अधिक हैं, वे 'दो बड़े' कहलाये जा सकते हैं।

नये बैंक जो कि १९४१ के उपरान्त स्थापित हुए उनमें नीचे लिखे 'बड़े पाँच' हैं (१) भारत बैंक, (२) यूनायटेड कमर्शियल बैंक, (३) हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक, (४) जयपुर बैंक तथा (५) हबीब बैंक। अब भारत बैंक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ले लिया गया है।

(३) विनिमय बैंक या एक्सचेंज बैंक (Exchange Banks)—एक्सचेंज बैंक वास्तव में व्यापारिक बैंक हैं किन्तु उनमें तथा भारतीय मिश्रित पूँजी वाले व्यापारिक बैंकों (Indian Joint Stock Banks) में केवल इतना ही अन्तर है कि एक्सचेंज बैंकों के प्रधान कार्यालय विदेशों में हैं और

उनकी शाखायें भारतीय बंदरगाहों और मुख्य व्यापारिक केंद्रों में हैं तथा ये मुख्यतः विदेशी व्यापार में आर्थिक सहायता और विनिमय (Exchange) का सुविधा प्रदान करने हैं। वास्तव में भारतवर्ष के बैंकिंग संगठन की एक विचित्र विशेषता है कि शोध से विदग्धा बैंकों के एक समूह ने भारत के विदेशी व्यापार पर प्रायः अपना एकाधिपत्य साज्जमा लिया है। भारतीय व्यापारिक बैंकों का अभाव तब इस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रवेश हो गया है। वान यह भी कि इस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में अग्रिमतर भारत का विदेशी व्यापार ब्रिटेन से होता था। अतएव यह स्वाभाविक ही था कि लंदन में ऐसे बैंक स्थापित हों जो कि दोनों देशों में विनिमय (Exchange) का काम करें। किन्तु आरम्भ में तो इस्ट इंडिया कंपनी और एन्गो हाऊस जो भारत में व्यापार तथा बैंकिंग का कारबार करते थे इसके विरुद्ध थे कि इस प्रकार के बैंक स्थापित हों। किन्तु १८५३ में इस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रकार के बैंकों की स्थापना का विरोध करना छोड़ दिया और एन्गो हाऊसों के समान हो जाने से उस प्रकार के बैंकों की स्थापना और भी आसन्न हो गई है।

१८५३ के पूर्व जबल ओरियंटल बैंक विनिमय (Exchange) का काम करता था किन्तु १८५३ में चारटर्ड बैंक प्रायः इंडिया, आस्ट्रेलिया और चीन तथा मार्सेटाइल बैंक इंग्लैण्ड में स्थापित हुए। १८८४ में ओरियंटल बैंक फेल हो गया। १८८८ में नेशनल बैंक ऑफ इंडिया कलकत्ता बैंकिंग कारपोरेशन के नाम से स्थापित हुआ किन्तु बाद की इसका नाम बदल दिया गया और इसका प्रधान कार्यालय लंदन ले जाया गया। इसके उपरान्त फ्रांस, जर्मनी, हालैंड, पुर्तगाल, रूस समुच्च राज्य अमेरिका और जापान ने भी इसी नीति को अपनाया और भारत तथा अन्य एशियाई देशों से अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने बैंकों की शाखायें भारतीय बंदरगाहों में स्थापित कर दीं। शीघ्र ही इस लैंड के तीन अन्य बैंकों ने भी अपनी शाखायें यहाँ स्थापित कर दीं (लायड, नेशनल प्रोविडेंशियल तथा थामस)। १९१४ में जब प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ जर्मन बैंक (Deutsch Asiatische Bank) तथा रूसी एशियाटिक बैंक की भारतीय शाखायें बंद हो गईं और फिर नहीं खुलीं। १९४१ में जब जापान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हुआ तो तीन जापानी बैंकों का शाखायें (यानोहाम स्पीडी बैंक, मित्सुबि बैंक तथा तैवान बैंक) बंद हो गईं।

एक्सचेंज बैंकों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। एक तो वे बैंक जिनका अधिक कारबार भारत से होता है अर्थात् उनको डिमण्डिट का २५

प्रतिशत से अधिक भारत में है। दूसरी ओर भी वे बैंक आते हैं कि जो बहुत बड़े बैंक हैं और जिनका कारबार अन्य देशों में अधिक फैला हुआ है, अर्थात् भारत में उनकी कुल डिपॉजिट का २५ प्रतिशत से कम है। किन्तु यह ओरि-विभाजन बहुत उपयुक्त नहीं है क्योंकि दूसरी ओर के बैंक लायब बैंक, हांगकांग शंधार्ड बैंकिंग कारपोरेशन तथा अमेरिका का न्यू-सिटी बैंक बहुत बड़े बैंक हैं, और यद्यपि भारत में उनकी डिपॉजिट उनकी कुल डिपॉजिट की २५ प्रतिशत से कम है परन्तु उनकी भारतीय डिपॉजिट पहली ओर के बैंकों की डिपॉजिट से कहीं अधिक है। १९३६ तक प्रथम ओर के बैंक थे किन्तु १९३६ में चार-टर्ड बैंक ने पी० ओ० बैंकिंग कारपोरेशन को खरीद लिया। अतः अब पहली ओर के बैंकों में केवल पांच बैंक हैं। और १५ बैंक दूसरी ओर के हैं। (इनमें जापान के ३ बैंकों का युद्ध काल में कारबार बन्द हो गया)।

बात यह थी कि भारत का व्यापार बढ़ता जा रहा था, बैंकिंग में अधिक लाभ था और उसी लाभ के लालच से उन देशों के प्रमुख बैंकों ने भारत में अपनी शाखाएँ स्थापित कर दीं कि जिनका भारत से व्यापार होता था। केवल इटली और बेलजियम ही ऐसे देश हैं कि जिनका भारत के साथ बंधे हुए व्यापार होता है किन्तु उनके किसी बैंक ने भारत में अपना कारबार स्थापित नहीं किया।

एक्सचेंज बैंक भारत के अत्यन्त प्राचीन बैंक हैं। जबकि आधुनिक ढंग के मिश्रित पूँजी वाले व्यापारिक बैंकों को भारत में स्थापना भी नहीं हुई थी तब से ही वे भारत में अपना कारबार करते आये हैं। चारटर्ड नेशनल, और मरकैन्टाइल तो १८७० के पूर्व ही काम करते थे। वास्तव में भारतीय व्यापारिक बैंकों का प्रादुर्भाव तो उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में और बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हुआ। अतएव एक्सचेंज बैंकों का देश के व्यापार में प्रधान हाथ रहा तो उसमें आश्चर्य ही क्या है।

एक्सचेंज बैंकों का भारतीय द्रव्य-वाजार में प्रभाव:—इन एक्सचेंज बैंकों का भारतीय द्रव्य-वाजार पर गहरा प्रभाव रहा है। बहुधा इन बैंकों ने भारतीय आर्थिक हितों के विरुद्ध अपने प्रभाव का प्रयोग किया है। यह इन बैंकों के विरोध का ही परिणाम था कि भारत के प्रेसिडेंसी बैंकों को लन्दन के द्रव्य वाजार में सीधे प्रवेश लेने की आज्ञा नहीं मिली और बहुत समय तक भारत में केन्द्रीय बैंक (Central Bank) ही स्थापित न हो सका। इन बैंकों के प्रधान कार्यालय लन्दन में थे इस कारण वे लन्दन द्रव्य-वाजार के द्वारा भारत मंत्री पर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ हो जाते थे। यही नहीं, भारत सरकार को प्रतिवर्ष इंग्लैंड में अपने खर्च (Home Charges) को चुकाने के लिए करोड़ों रुपये के

स्टॉक की आवश्यकता होती थी जो कि एक्सचेंज बैंक ही देते थे इस कारण भारत सरकार पर भी उनका प्रभाव रहता था। एक्सचेंज बैंकों की अग्री प्रदान कार्यालयों के द्वारा लन्दन ड्रॉय बाजार में अथवा एंग्लो का सभी सुविधाएँ प्राप्त हैं इस कारण वे विदेशों का पर निभर नहीं हैं और इस कारण रिजर्व बैंक का उन पर कभी पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता।

एक्सचेंज बैंक का कार्य — एक्सचेंज बैंकों का मुख्य कार्य भारत के विदेशी व्यापार के आर्थिक सहायता प्रदान करना है। एक प्रकार से एक्सचेंज बैंकों की भारत के विदेशी व्यापार के एकाधिकार प्राप्त हैं। हालांकि कुछ भारतीय बैंकों में अब एक्सचेंज के प्रमुख प्रमाण आरम्भ किया है। १९३५ के पूर्व इत्यादिवा देशों को काल द्वारा विदेशी बिलों (Foreign Bills) को गरीबने बचने का भुगतान का मनाही थी। वह समय प्रमाण प्रदान का इतिहास आवश्यक कर्तव्यों के लिए ही भारत के बाहर गया प्रमाण प्रदान करता था, विदेशी व्यापार का कारबार नहीं कर सकता था। भारतीय मिश्रित पूँजीवाले बैंकों (Indian Joint Stock Banks) के अन्तर्गत एक प्रमाण प्रदान प्रक्रिया नहीं था परन्तु वे विदेशी व्यापार को अपने हाथ में लेना न अनुमति थी क्योंकि एक्सचेंज बैंकों का उन पर एकाधिकार स्थापित था। पहला कारण तो यह है कि भारतीय बैंक एक एक्सचेंज बैंक की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते क्योंकि वे बहुत अधिक मजदूर और गैरम सम्पत्ति हैं। उनका पास योग्य सम्पत्ति है उनकी पूँजी और सुरक्षित कोष (Reserve Fund) भारतीय बैंकों की तुलना में गुणा अधिक है और उन्हें लन्दन के ड्रॉय-बाजार में बहुत कम धूर पर छुप लेने की सुविधा प्राप्त है। उनका व्यापारियों का अधिक विश्वास है। भारतीय बैंक के मामले में हम कहना चाहते हैं कि उनका सामर्थ्य अन्य देशों में नहीं है इस कारण वे विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) का लाभदायक काम सुविधापूर्वक नहीं कर सकते। तीसरा कारण यह कि भारत में ही भारतीय बैंकों की कार्यशील पूँजी (Working Capital) की मांग रहती है अतएव उन्हें विदेशी व्यापार में अपने कोष को लगाने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। परन्तु विदेशी देशों में विशेषकर १९४० के उपरान्त भारत में ऐसे बैंकों की स्थापना इस सेजो से हुई है और पुराने बैंकों ने अपनी पूँजी और सामर्थ्य का इस सेजो में वित्तार किया है कि बैंकों की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और भारतीय बैंकों को भी विदेशी व्यापार में हाथ डालने की आवश्यकता का अनुभव होने लगा है। सेट्रल बैंक आवश्यक इत्यादि कुछ बड़े भारतीय बैंकों ने इस कार्य को करना आरम्भ कर दिया है। नहीं नहीं एक भारतीय एक्सचेंज बैंक “एक्सचेंज बैंक ऑफ इण्डिया

एंड अफ्रीका" भी स्थापित हुआ है जो अफ्रीका के व्यापार का काम करता है। इस बैंक ने अफ्रीका में अपनी शाखाएँ भी स्थापित की हैं। अभी तक जो भारतीय बैंक विदेशों में अपने ब्रांच स्थापित करने में सफल नहीं हुए उसके मुख्य कारण नीचे लिखे हैं:—

(१) भारतीय बैंकों की पूँजी इतनी अधिक न थी कि विदेशों के द्रव्य बाजारों में अपनी राख को सरलता से स्थापित कर सकते।

(२) विदेशों में ब्रांचों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कार्यशील पूँजी (Working Capital) भी अधिक होनी चाहिए।

(३) आरम्भ में कुछ वर्षों तक विदेशों में ब्रांचे बाटे पर चलेंगी, अस्तु बैंकों को उस बाटे को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय (International Exchange) के कार-बार को करने के लिए बहुत कुछ बैंक कर्मचारियों की आवश्यकता है जिनकी भारत में कमी है।

(५) आरम्भ में भारतीय बैंकों को विदेशों में अधिक जमा मिलने की सम्भावना नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ के व्यवसायी, व्यापारी और जनता अपने देशीय बैंकों में ही अपना रुपया जमा करने हैं।

(६) भारतीय बैंकों को उन देशों के बड़े बैंकों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

(७) भारतीय बैंकों के प्रधान कार्यालय भारत में होने के कारण भारतीय बैंकों का संसार के मुख्य द्रव्य बाजारों (न्यू-यार्क और लंदन) से सीधा सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता, इस कारण वे अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य सम्बन्धी हलचलों से दूर रहते हैं और निर्यात (Export) और आयात (Import) बिल उन्हें इतने अधिक प्राप्त नहीं हो सकते।

इन्हीं कारणों से भारतीय बैंक विदेशों में अपनी ब्रांचें स्थापित करने में सफल न हो सके। किन्तु अब भारतीय बैंक उस ओर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें भविष्य में परिलिखितवश अधिकाधिक इस ओर अग्रसर होना पड़ेगा।

यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि एक्सचेंज बैंकों का मुख्य कार्य व्यापार को आर्थिक सहायता देना है। किन्तु वे प्रायः सभी उन कार्यों को करते हैं जो कि व्यापारिक बैंक करते हैं। वे चालू (Current), मुहूर्त (Fixed) तथा सेविंग डिपॉजिट स्वीकार करते हैं, विदेशी बिलों को खरादते हैं, नीयतिग्रहण प्रलेखों (Shipping Documents) की नगानत पर श्रेण देते हैं और सोना तथा चाँदी के आयात (Import) में सहायता देते हैं। भारत में नेशनल

बैंक तथा चारटर्ड बैंक के मोटे प पास बहुत प्रचलित रहते हैं। यही नहीं, एक्स्चेंज बैंक आन्तरिक व्यापार (Internal Trade) में भाग्यशिवि न्यायता प्रदान करते हैं। जब माल देश व देश माना न्याय म निर्यात (Export) के लिए बन्दगाहों तक भेजा जाता है अथवा विदेशों में आयात गुप्त माल बन्दगाहों से माना केन्द्रों तक भेजा जाता है तब उस व्यापार का भी एक्स्चेंज बैंक का बहुत करने है। और हम यहाँ विदेशी व्यापार का निर्यात विस्तारपूर्वक करेंगे।

जब भारतीय निर्यात (Export) गुप्त या व्यापारी विदेशियों को माल भेजना है तो किसी लड़क बैंक से साव (Credit) का प्रबंध कर लिया जाता है। मान लें कि वाला लड़क बैंक या फार्मेट हाउस (एक्स्चेंज बैंक वाला व्यापारी) में साव का प्रबंध कर लेता है और एक्स्चेंज बैंक व भारतीय व्यापारी को इसका लड़क दिला देता है जब भारतीय व्यापारी उस साव (Credit) व विदेशी लड़क लड़क बैंक का फार्मेट हाउस पर 'बिल' (Bill) लिख देता है। अधिनिर लिखों का स्थापना हो जाने पर ही प्रलेख (Documents) जहाज का लड़ा (Bill of Lading) इत्यादि द दिए जाते हैं, परन्तु कुछ बिना पम भी होना है कि निर्यात गुप्तता हो जाने पर ही प्रलेख (Documents) दिए जाते हैं।

ये बिल लड़क भरण दिए जाते हैं। एक्स्चेंज बैंक उन्हें स्थापना व लिए देता है। उसका स्थापना हो जाने पर एक्स्चेंज बैंक उस पर चेकान (Endorsement) कर देता है और लड़क व द्रव्य-वातावरण में भुजा लेता है। इस प्रकार एक्स्चेंज बैंक उस बिल को भारत में लड़ा कर जा उसका मूल्य रूपों में चुकाते हैं यह लड़क में स्थिति में मूल्य कर लेते हैं। यदि एक्स्चेंज बैंकों के पास मयेष्ट फंड (Funds) होता है और उसका उस समय कोई लाभदायक उपयोग होने का सम्भावना नहीं होती तो ये बिलों को पकने (Maturity) तक अपने पास ही रखते हैं, किन्तु यदि द्रव्य का बाजार में कम होता है और व्यापार में सपा होता है तो ये इन बिलों को लड़क व द्रव्य बाजार में दुरंग भुजा लेते हैं। ब्रिटन, मध्य तथा अमेरिका तथा उन्निवेशों और भारत व चीन में जो बिल होते हैं वे बहुत स्थिति में होते हैं। जापान के बिल येन (Yen) में होते हैं तथा चीन के बिल रुपों में होते हैं।

भारत के आयात व्यापार (Import Trade) का आर्थिक प्रबन्ध दो प्रकार से किया जाया है। जब भारतीय व्यापारी विदेशों में मान भेजाते हैं अथवा वे योरोपियन व्यापारी माल भेजाते हैं तबका लड़क में चेका कोई कार्यालय नहीं है कि निर्यात द्रव्य-वातावरण में सपा हो, तो माल भेजने वाला व्यापारी भारतीय

या ऐसे यूरोपियन व्यापारियों पर जिन्होंने माल मँगाया है ६० दिन का देखनहार बिल (Sight Bill) काट देते हैं। उसके साथ माल सम्बन्धी सभी प्रलेख (Documents) जहाज की रसीद और समुद्री बीमा पालिसी इत्यादि रहते हैं और ये आवश्यक प्रलेख भारतीय व्यापारी को नहीं दिए जाते हैं कि जब वह बिल का भुगतान करदे। माल भेजनेवाला लन्दन स्थित व्यापारी इन बिलों को लन्दन में ही एक्सचेंज बैंक से भुना (Discount) लेता है। इस प्रकार एक्सचेंज बैंक वालाच में उस माल का स्वामी हो जाता है। जब प्रलेखों (Documents) के साथ एक्सचेंज बैंक की भारतीय शाखा के पास बिल आता है तो माल मँगाने वाला व्यापारी या तो बिल का भुगतान कर देता है और जहाज की बिल्टी (Bill of Lading) तथा समुद्रीय बीमा पालिसी लेकर अपना माल छुड़ा लेता है; अथवा यदि व्यापारी बिल का भुगतान नहीं करना चाहना तो वह एक्सचेंज बैंक से प्रार्थना करता है कि उसे बिना भुगतान किए ही माल लेने दे। ऐसी दशा में माल मँगाने वाला व्यापारी एक्सचेंज बैंक को माल की ट्रस्ट रसीद (Trust Receipt) लिख देता है। अर्थात् वह यह स्वीकार करता है कि जो माल उसने छुड़ाया है वह वास्तव में एक्सचेंज बैंक का है। वह तो उस माल का केवल ट्रस्टी या छमानतदार है। माल लेकर व्यापारी अपने मोदाम ने गन्त लेता है और उसके विक्राने पर बिल का भुगतान कर देता है। इस सुविधा के लिए उसे एक्सचेंज बैंक को सूद देना पड़ता है।

जिन भारतीय या यूरोपीय फर्मों के कार्यालय लंदन में हैं उनके साथ दूसरा ढंग चलता जाता है। लंदन का कार्यालय उस माल की खरीद करता है जिसकी भारतीय फर्म को आवश्यकता होती है। अब जब लंदन का कार्यालय जहाज से माल भारत को भेज देता है तो वह अपनी भारतीय शाखा अर्थात् माल मँगाने वाली फर्म पर प्रलेख बिल (Documentary Bill) देता है। लंदन का कार्यालय लंदन स्थित एक्सचेंज बैंक के सामने उस बिल को उपस्थित करता है और एक्सचेंज बैंक उसको स्वीकार कर लेता है। बिल पर एक्सचेंज बैंक की स्वीकृति हो जाने पर लंदन का कार्यालय उस बिल को लंदन के द्रव्य बाजार में भुना कर माल का मूल्य स्टर्लिंग में वसूल कर लेता है। बिल को स्वीकार करने वाले एक्सचेंज बैंक जहाजी बिल्टी (Bill of Lading) और समुद्रीय बीमा पालिसी इत्यादि आवश्यक प्रलेख अपनी भारतीय शाखा को भेज देता है। एक्सचेंज बैंक की भारतीय शाखा भारतीय फर्म से, जिसने माल मँगाया है, रुपया वसूल करके लंदन भेज देती है। बिल दोनों ही दशा में स्टर्लिंग में ही लिखे जाते हैं। किन्तु दूसरे ढंग में यूरोपीय फर्मों को यह लाभ होता है कि वह बिल लंदन में भुना जाता

है, अतः यह बहुत कम देना पड़ता है क्योंकि बड़ा बड़ा दर (Discount Rate) बहुत कम होता है, किन्तु भारतीय व्यापारियों का रिज हाटने के दिन से और उसका भुगतान लड़ने पहुँचने ४ दिन तक ऊँची दर में यह देना पड़ता है।

बहुत मात्रा में विदेशी व्यापार का अन्तर (Balance of Trade) उसमें पड़ने लगता है। अतः एम्बरबेन बैंक भारत में साप्ताहिक मँगाकर तथा रिज बैंक में स्टॉलिंग (विज्ञापन में भाग लेता है) के लिए उस अन्तर को घटा रहा है। इससे अतिरिक्त एम्बरबेन बैंक सरकार में प्रत्यक्ष व्यापारिक केंद्र पर तार का ट्रांसफर (Telegraphic Transfers) रहता है।

एम्बरबेन बैंक उस विदेशी व्यापार का ही हिसाब नहीं करते परन्तु भारत के भारतीय व्यापारिक केंद्रों में बन्दरगाहों तथा बन्दरगाहों से भीतर व्यापारिक केंद्रों तथा भारत-बाह्य का प्रवाह भाव रखते हैं। विदेशी कुछ वर्षों से एम्बरबेन बैंक भारत में अद्वितीय व्यापार में भारत का भाग्य ही है। एम्बरबेन बैंक भारत में व्यापारिक केंद्रों का हिस्सा बनकर उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करती है। उदाहरण के लिए पी० आ० बैंकिंग कारपोरेशन ने इलाहाबाद बैंक के प्रमुख और बड़े बैंक को खराद लिया और इन प्रकार वह भारत में प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में उनका शाखाओं का शाखा पहुँच गया। और पी० आ० बैंकिंग कारपोरेशन का चारटर्ड बैंक के खराद लिया। इन इलाहाबाद बैंक का प्रमुख फायदा में चारटर्ड बैंक की बचत है जो कि एक प्रमुख एम्बरबेन बैंक है। विदेशी व्यापारिक केंद्रों में एम्बरबेन बैंक का शाखाओं होता है यहाँ के व्यापारिक एम्बरबेन बैंकों का स्थापित शाखा से ही विदेशी में अपना देना (Debt) का भुगतान कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि कानपुर का व्यापारिक लड़ने में माल मँगाना है तो उस पर लड़ने के व्यापारी (माल भेजने वाला) ने जो बिजु लिया है कानपुर शाखा को भेज दिया जाता है और कानपुर की शाखा उसमें सहाय करके उसे पहचाना बिन्दी और समुद्री बाला पालिनी इत्यादि दे देती है। इसी प्रकार भारत के विदेशों की माल भेजने वाला व्यापारी स्थानीय एम्बरबेन बैंक का धन को अपना मिल जो उसने विदेशी व्यापारी पर लिया है देव देता है।

किन्तु यदि किसी भारतीय व्यापारिक केंद्र में एम्बरबेन बैंक का शाखा नहीं होता तो बड़ा से बन्दरगाहों तथा का कारण भारतीय व्यापारिक बैंक करते हैं और बन्दरगाहों में विदेशों तथा का कारण एम्बरबेन बैंक करते हैं। विदेशी व्यापारी एम्बरबेन बैंक की शाखा होता है यहाँ के व्यापारी एम्बरबेन बैंक से ही दोनों व्यवहार (Transaction) करते हैं क्योंकि यह सरल और कम खर्चीला

बैठता है।

विदेशी व्यापार के लिए आर्थिक प्रबंध करने के अतिरिक्त एक्सचेंज बैंक भीतरी व्यापार के कारबार को भी करते हैं। वे व्यापारियों को ऋण देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजते हैं, तीनों प्रकार की जमा लेते हैं। उनकी साख और प्रतिष्ठा अधिक होने के कारण वे भारतीय व्यापारिक बैंकों की अपेक्षा कम सूद देते हैं। वे एजेंसी का काम भी करते हैं और सोना-चांदी के आयात (Import) व्यापारिक के लिए भी आर्थिक प्रबंध (Finance) करते हैं।

एकमचेत्र बैंकों के विरुद्ध आरोप :—यह तो सभी लोग स्वीकार करते हैं कि विदेशी व्यापार के लिए जितनी साख की आवश्यकता होती है वह विदेशी बैंक उसको उचित मूल्य पर देने का प्रबन्ध करते हैं, किन्तु भारतीय व्यापारियों तथा भारतीय व्यापारिक बैंकों को उनसे बहुत सी शिकायतें हैं। जब भारत में केन्द्रीय बैंकिंग जॉब कमेटी बैठी थी उस समय भारतीय बैंकों तथा भारतीय व्यापारियों ने उन पर नीचे लिखे आरोप लगाये थे।

(१) एक्सचेंज बैंकों पर भारत का कोई बैंकिंग सम्बन्धी कानून लागू नहीं होता। कानून ने जो दायित्व भारतीय बैंकों पर लगा दिये हैं वे भी एक्सचेंज बैंकों पर लागू नहीं होते। उनके डायरेक्टर और हिस्सेदार सभी विदेशी हैं। अख्तु उनका नियंत्रण विदेशियों के हाथ में है। रिजर्व बैंक का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। एक्सचेंज बैंकों के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वे भारत में आय-व्यय निरीक्षकों से अपने आय-व्यय की जाँच करावे। वे भारत सम्बन्धी कारबार का पुथक् लेनी-देनी का लेखा (Balance-Sheet) तक नहीं छापते। भारत सरकार को जो वर्ष में एक बार वे अपनी लेनी-देनी का लेखा भेजते हैं उसमें उनके विदेशी और भारतीय कारबार के सम्मिलित आंकड़े रहते हैं, जिनसे उनके भारतीय कारबार का कोई पता नहीं चलता। इसका परिणाम यह होता है कि एक्सचेंज बैंकों का कारबार भारतीयों से एक दम गुप्त रहता है। यह बैंक भारत में बहुत अधिक डिपॉजिट आकर्षित करते हैं। उनके कोष का भारतीय डिपॉजिट एक बहुत बड़ा भाग होती है किन्तु भारतीय जमा करने वालों की डिपॉजिटों की सुरक्षा का कोई भी नियम उन पर लागू नहीं होता। यदि कोई एक्सचेंज बैंक किसी कारणवश फेल हो जाय (टूट जाय) तो भारतीय जमा करने वालों का अपनी डिपॉजिटों को वसूल करने के लिए एक्सचेंज बैंक की भारतीय सम्पत्ति पर पहला हक भी नहीं है।

(२) दूसरी शिकायत उनके विरुद्ध यह थी कि वे बहुधा भारत में उनकी डिपॉजिटों को देखते हुए यथेष्ट नकद कोष (Cash Reserves) भी नहीं रखते।

इस कारण भारतीय द्रव्य बाजार के लिए निबन्धना का कारण बनते हैं। प्रथम महायुद्ध के समय तथा कारण एकत्रित बैंक कठिनाई में पड़ गए थे और उनकी महायुद्ध करनी पड़ी थी। तब से कुछ वर्षों तक उन्होंने अविन नष्ट की पड़ना। विन अब फिर उनका उद्धार को मिलने लगा। अपना वा म एकसर्व बैंक कहते हैं कि वे गवर्नर प्रिन्सिपल (मिनिस्ट्रियल) और सरकारी ट्रेजरी (Treasury Bills) में अपना बचत को लाता है, किन्तु उसमें सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(२) एक प्रकार में एकसर्व बैंक का भारत में विदेशी व्यापार का अर्थ प्रणाली (Finance) का एक अधिकार प्राप्त है और वह इस कार्य को भारत में प्राप्त की गई जमा (डिपॉजिट) में ही करता है। इस प्रकार भारत को बैंकिंग लाभ और व्यापारिक लाभ में बचिप रहना पड़ता है। एकसर्व बैंक के भारतीय विदेशी व्यापार में बहुत हुए प्रभाव का परिणाम यह हुआ कि भारत में विदेशी व्यापार में भारतीयों का हिस्सा घटना गया और विदेशियों का हिस्सा बढ़ता गया। यहाँ तक कि भारतीयों का विदेशी व्यापार में वर्ष १५ में २० प्रतिशत भाग ही रह गया। इसी प्रकार भारतीयों का करोड़ों रुपये का विदेशी व्यापार में होने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ता है। राष्ट्रीय बैंकिंग जांच समिति (Central Banking Enquiry Committee) के आगे गवाही देने हुए कुछ भी व्यापारिक सरकारी ने इस बात का शिकायत की थी कि विदेशी एकसर्व बैंक विदेशी व्यापारियों को अधिकाधिक सुविधाएँ देकर और भारतीय व्यापारियों को उन सुविधाओं से वंचित रखकर उन्हें वञ्चित रह रहे हैं। इसी का परिणाम हुआ कि भारत का व्यापार विदेशियों के हाथ में चला गया।

इन एकसर्व बैंकों का एक दम तो यह है कि जब कोई भारतीय व्यापारी विदेशों में कारबार करना चाहता है तो वह बैंक विदेशों को उतारे जाने में बहुत अच्छी सम्मति नहीं देते। इस सम्बन्ध में एकसर्व बैंक का कहना है कि हम जो इस सम्बन्ध में भारतीय और विदेशी व्यापारियों में भेद करते हैं उसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय व्यापारी बैंकों को अपना लेना देना का लेखा (Balance Sheet) देना नहीं पसन्द करते। जब तक हम उनकी आर्थिक स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते। भारतीय व्यापारियों का कहना यह है कि एकसर्व बैंकों का उसमें अर्थ यह है कि जिन आय-व्यय निरिक्तों (Auditors) को वे स्वीकार करें उनमें हमें अपने हिसाब की जाँच कराएँ तभी वे उसे स्वीकार करेंगे। किन्तु एकसर्व बैंकों के प्रतिनिधियों ने इसकी अस्वीकार किया। उनका कहना

था कि हम सरकार द्वारा स्वीकृत आव-जन्म निरीक्षकों से जांचा हुआ लेनी-देनी का लेखा मात्र ही चाहते हैं। भारतीय व्यापारियों का कहना है कि भारत में एक फर्म और एक बैंक की परिपाटी प्रचलित नहीं है इस कारण एक्सचेंज बैंकों को लेनी-देनी के लेख को मांगने का कोई अधिकार नहीं है। सच बात तो यह है कि एक्सचेंज बैंकों के मैनेजर सब विदेशी हैं इस कारण वे भारतीय व्यापारियों के अधिक सम्पर्क में नहीं आते और उनकी आर्थिक स्थिति का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा सकते।

भारत में जो विदेशी व्यापारी हैं उन्हें माल साख (Credit) पर मँगाने की सुविधा दी जाती है जब कि भारतीय व्यापारी को नक़द मूल्य देना पड़ता है। भारतीय व्यापारियों का यह भी कहना है कि विदेशों के व्यापारी भारतीय व्यापारियों को साख इस कारण नहीं देते क्योंकि एक्सचेंज बैंक उनके सम्बन्ध में अच्छी सम्मति नहीं देते। एक्सचेंज बैंकों का कहना था कि हम जो भारतीय व्यापारियों से ट्रस्ट की रसीद (Trust Receipt) लेकर जहाज़ी बिल्टी इत्यादि दे देते हैं उससे उन्हें भी साख (Credit) की सुविधा मिल जाती है। परन्तु भारतीय व्यापारियों ने इसके उत्तर में यह कहा कि ट्रस्ट-रसीद पर ख़द अधिक देना पड़ता है, अतएव भारतीय व्यापारियों को विदेशी व्यापारियों की अपेक्षा हानि उठानी पड़ती है।

भारतीय व्यापारियों ने इस बात की भी शिकायत की कि जब कोई भारतीय व्यापारी माल बाहर भेजता है तब एक्सचेंज बैंक उसके बिल को बिना अन्तर (Margin) के और बिना ज़मानत लिए कमी नहीं भुनाते, किन्तु जब कोई विदेशी फर्म माल बाहर भेजती है और अपने बिल को भुनानी है तो अन्तर (Margin) या ज़मानत नहीं माँगी जाती। एक्सचेंज बैंकों का कहना है कि विदेशी फर्मों के प्रधान कार्यालय विदेशों में होते हैं और बिल उन्हीं पर होते हैं अतः उनके गुप्तता न होने का कोई भय नहीं होता, परन्तु भारतीयों के साथ ऐसी बात नहीं है। इसी कारण एक्सचेंज बैंक उनके बिलों का पूरा मूल्य यहाँ चुका देते हैं। जो भी हो, किन्तु यह सत्य है कि भारतीयों को विदेशी फर्मों की तुलना में हानि होती है।

भारत में एक्सचेंज बैंक विदेशों के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति के के सम्बन्ध में यहाँ के व्यापारियों को कोई जानकारी नहीं देते। मन्त्रालय के प्रत्येक देश में बैंकों का यह मुख्य कार्य है, किन्तु एक्सचेंज बैंक ऐसा नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि भारत में जो विदेशी फर्म काम करती हैं उन्हें तो अपने विदेशी कार्यालयों से विदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, किन्तु भारतीय

व्यापारियों की उम्मीदों में भी उतार-चढ़ाव आता है।

पहले तो भगवान् "दासरा" वर दिया म मन्त्र मन्त्रने है तो उन्हें पात्र
हो नहीं मिलती, किन्तु तब शङ्के म प्रथम भू जी व भारतीय व्यावस्था को मान
मिलतो भा है उन्हें मा मैसाय दू म मन्त्र व मन्त्र का २५ प्रमाण तब वनों के पास
बना वर दत्ता दत्ता दे सब कि उन दिव्या पत्नी को भी भारत में है कोई
विवाहित है। - तब तभी मन्त्रा पद ।

भारत में अतिरिक्त आयात (Import) और निर्यात (Export) व्यापार में स्थानीय बिना का उदाहरण है। इसका मतलब यह होता है कि भारतीय व्यापारी का माल मैंगल पाल विदेशी व्यापारी नर स्टॉक में ही बिना कायता पड़ता है अतः उक्त बिना भारतीय व्यापारी का न तो निर्यात की वस्तु हो जाता है। जब एक बैंक देश में ही उक्त व्यापारी पड़ता है, जिसकी दर (Discount Rate) ऊँची रहती है। इसके विपरीत भारत में व्यापार करने वाला विदेशी बैंक अपने लार्ज स्थित व्यापारी का मतलब मैंगल पाल है जो न लार्ज स्थित व्यापारी के लार्ज भारतीय व्यापारी पर बिना का काट कर लार्ज स्थित व्यापारी के बैंक का बिल (Bill) काटता है और वे एकदम से बैंक का बिल लेते हैं। एकदम से बैंक का बिल का लार्ज व्यापारी के बैंक का उक्त बिना को लार्ज व्यापारी का भुगतान लेते हैं। लार्ज व्यापारी का दर (Discount Rate) बहुत कम होता है। इस प्रकार विदेशी बैंक को भारतीय व्यापारी का प्रयोजन एक ही बैंक प्रणाली का लाभ हो जाता है।

(४) इन श्रारांग के अभिरिण भारतय न्वासारिया का एगलबैर बैरों के विरुद्ध एक सपन बड़ा प्रारण यह कि न मागनाय प्रकृता, भारतय बैर, भारतय बामा कम्मिया और भारतय बहाना कम्मिया के विरुद्ध शरणे दणों के प्रेरणों, बैरों, कम्मिया तथा बहाना कम्मिया का प्रत्याहित करते हैं। नर भारतीय ब्यापार विदेशों को मान भजने हैं तो एगलबैर बैर उहें विदेशा जहाजा कम्म निवों म माल भजने तथा विदेशा बामा कम्मिया ने उम्का बीना करवाने पर विवश करते हैं। इय प्रकार भारतय बामा कम्मिया तथा भारतीय बहाना कम्म निवों को करोड़ों रुपय की हानि होता है और ये एगलबैर पानी।

(५) एक्सचेंज बैंक एगोसियेशन बिना भारताय व्यापारियों से कोई परामर्श किए ही अपने नियमों में जब चाहता है परिवर्तन कर देती है, और भारतीय व्यापारियों के लिए नियम कठोर रखते जाते हैं। यहाँ नहीं, एगोसियेशन किसी भी बदल को भारताय बैंक तथा सावर से कारबाही नहीं करने देती जो कि विनिमय (Exchange) का काम करता है। दूसरे शब्दों में एकनवेंज बैंक

भारतीय बैंकों को इस लाभदायक कारवार के क्षेत्र से बाहर ही रखना चाहते हैं।

यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि एक्सचेंज बैंक भारत के भीतरी व्यापार को भी करने लगे हैं। इस प्रकार वे भारतीय मिश्रित पूँजीवाले व्यापारिक बैंकों (Indian Joint Stock Banks) से होब करते हैं और उनकी बढ़वार को रोकते हैं। उनकी प्रतिष्ठा और साधन अधिक होने के कारण उनकी प्रतिस्पर्धा में भारतीय बैंकों को कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त इन एक्सचेंज बैंकों के कारण भारतीय बैंकों को एक और भी हानि होनी है। जब कोई देश विदेशों से माल मँगवाता है तो साधारणतः होता यह है कि माल भेजने वाला माल मँगाने वाले के देश की करंसी में बिल लिखता है। यह बिल जहाजी विल्टी इत्यादि के साथ भेज दिए जाते हैं और जब माल मँगाने वाला उस बिल को स्वीकार कर लेता है तो उनको भुनाया जाता है। क्योंकि बिल उस देश की करंसी में होते हैं इस कारण वहाँ के बैंक उनको भुनाते हैं और उन्हें लाभ होता है। परन्तु भारत के व्यापारी जब माल मँगाने हैं तो आयात बिल (Import Bill) रुपये में न होकर स्टर्लिंग में काटे जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि भारतीय व्यापारिक बैंकों के यह काम के नहीं होते और केवल एक्सचेंज बैंक ही इस लाभदायक धंधे को कर सकते हैं। एक्सचेंज बैंक इन बिलों को रुपयों में नहीं कटने देते और इस प्रकार भारतीय बैंकों को वे इस लाभदायक कारवार से वंचित रहते हैं।

एक्सचेंज बैंक के विरुद्ध एक आरोप यह भी है कि जिन देशों के एक्सचेंज बैंक भारत में नहीं हैं उनकी करंसी यह बैंक बहुत ऊँची कीमत पर देते हैं। यही नहीं, बल्कि किसी अन्य देश का कोई बैंक अपनी शाखा भारत में स्थापित करना चाहता है तो वे उसका विरोध करते हैं। जब कभी कोई विदेशी बैंक अपनी ब्राँच भारत में स्थापित करने में सफल हो गया तो उन देशों की करंसी भारतीयों को कम मूल्य में मिलने लगी जिससे कि भारतीय व्यापारियों को लाभ हुआ। एक्सचेंज बैंकों ने ऐसा सुझ बना लिया है कि यदि किसी देश के बैंक की भारत में ब्राँच भी हो तो भी उन देशों की करंसी (स्टर्लिंग को छोड़ कर) का मूल्य वहाँ ऊँचा ही रहता है। यदि कोई उसी करंसी को लन्दन के द्रव्य बाजार में खरीदे तो उसे कम मूल्य देना पड़ता है। उदाहरण के लिए युद्ध के पूर्व यदि कोई डालर लंदन से खरीदता तो कलकत्ता और बम्बई को अपेक्षा कम मूल्य पर खरीद सकता था।

इसके अतिरिक्त इन एक्सचेंज बैंकों का समाशोधन यह था क्लियरिंग हाउस (Clearing House) में बहुत प्रभाव है और यह भारतीय बैंकों को क्लियरिंग हाउस का सदस्य बनने नहीं देते। जहाँ तक हो सकता है यह भारतीय

बैंकों को क्लियरिंग हाउस के बाहर हा रखने हैं। हमने भारतीय बैंक की प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ना है। एक्सचेंज पर भारतीय बैंकों में स्वतन्त्रतापूर्वक जब चाहते हैं तब वाचना ड्रॉ (Call Money) लेन रहते हैं, किन्तु भारतीय बैंकों का तब आसन्नकता होता है तो व उठ उठनी आसानी से वाचना-ड्रॉ नहीं रहे।

अतः एक्सचेंज पर भारत के तत्काल पुगने बैंक में स हैं और उन्हीं स्थापित हुए लगभग ८० वर्ष हो गए किन्तु फिर भी कां भारतवाय उनमें ऊँचे पदों पर नहीं खड़ा गया। इसका परिणाम यह हुआ है कि बैंकों में सभी उच्च कर्मचारियों विशेषा व्यक्ति रहते हैं। ये न भारतवाय भाषा हा जानते हैं और न भारतवाय व्यापारियों के प्रति सम्यक् भाव हा आ सकते हैं, अतएव भारतीय व्यापारियों के साथ उनका महानुभूति नहीं होती। यह एक्सचेंज पर अपने दशाधारियों का हा लाने उद्यमों पर रहते हैं। अतः भारतवाय व्यापार में इतना अधिक लाभ उठाने हैं तब उन्का भारतवाय में ऊँचे पदों पर न लेना उचित नहीं कहा जा सकता।

एक्सचेंज बैंक मिलते क्यों न इस बात का भी प्रयत्न करते रहे हैं कि भारतवाय पूँजी विदेशी धर्मा या निर्युरितियों में न लगे।

एक्सचेंज बैंकों में नदर हा भारत के आर्थिक हितों के विरुद्ध अपने प्रभाव का उपयोग किया है। यह तो हम पहले हा रह आये हैं कि यह उन्हीं के विरोध का एक था कि प्रेसाइमी पैसा तथा इम्पोरियल बैंक को विदेशी प्रिनिमय (Exchange) का कारवार करने का आशा नहीं की गई। यह नहीं, इन एक्सचेंज बैंकों का कारण हा भारत में फेडरल बैंक १९१५ के पूर्व स्थापित न हो सका। इटिया आदि न हाग यह एक्सचेंज बैंक भारत सरकार का अर्थ नानि पर भी गहरा प्रभाव डालने के निमित्त भारत के आर्थिक हितों की हानि होता था।

किन्तु अब भारत स्वतन्त्र हो गया है। एक्सचेंज बैंक के भारत विरोधी दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन होना अनिवार्य है। भारत सरकार का प्रयत्नीति पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड सकता। रिजर्व बैंक नेतृत्व में उन्हे अब स्वाकार करना हा होगा और इस बात का सम्भावना है कि सरकार सविध्य में कोई बैंकिंग कानून बनाकर उसके नियंत्रण का भी प्रयत्न करे। अब हम आगे उन मुद्दों का अध्ययन करेंगे कि जो कन्द्रीय बैंकिंग कमेटी के सामने एक्सचेंज बैंकों की अनुचित प्रतिस्पर्धा से भारतीय बैंकों का रक्षा करने के लिए रखे गए।

कन्द्रीय बैंकिंग कमेटी का मत—इस सम्बन्ध में कन्द्रीय बैंकिंग कमेटी

(Central Banking Committee) का मत था कि भारत-सरकार को विदेशी बैंकों को बिना किसी रोक-टोक के भारत में कारबार करने की छूट न देनी चाहिए। प्रत्येक विदेशी बैंक को जो कि भारत में काम करना चाहे, रिजर्व बैंक से एक लायसेंस प्राप्त करना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि भारतीयों के हितों की रक्षा हो सकेगी। रिजर्व बैंक का एक्सचेंज बैंकों पर नियंत्रण स्थापित हो सकेगा और भारतीय बैंकों के लिए विदेशों में जहाँ सुविधाएँ प्राप्त की जा सकेंगी जो कि भारत में विदेशी बैंक की दी जावेंगी।

कमेटी का बहुमत इस पक्ष में था कि जो एक्सचेंज बैंक भारत में कारबार कर रहे हैं उनको बिना किसी रोक-टोक के लायसेंस दे देना चाहिए। प्रत्येक बैंक को लायसेंस एक निश्चित काल के लिए दिया जाना चाहिए और उस अवधि के समाप्त होने पर यदि रिजर्व बैंक देखे कि लायसेंस की शर्तों का किसी बैंक ने संतोषजनक ढंग से पालन किया है तो उसको फिर लायसेंस दे दे, अन्यथा उसका लायसेंस समाप्त कर दिया जा सकता है। एक्सचेंज बैंकों के लायसेंस की यह आवश्यक शर्त होनी चाहिए कि वे रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट भेजे जिसमें भारतीय तथा गैर भारतीय कारबार का लेनी-देनी लेखा (Balance Sheet) अलग-अलग हो।

कमेटी के बहुमत की यह भी सम्मति थी कि एक्सचेंज बैंकों को अपनी कार्यप्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन कर लेना चाहिए कि वे भारतीय आयात करने वाले व्यापारियों (Importers) के बिलों को खरीदने के बजाय स्वीकार (Accept) कर लिया करें जिससे कि वे बिल लन्दन से भुनाये जा सकें। और भारतीय व्यापारी लन्दन के द्रव्य बाजार में सस्ते द्रव्य का लाभ उठा सकें।

इसके अतिरिक्त यदि भारतीय आयात व्यापारी (Importers) चाहें कि विदेशी निर्यात व्यापारी (Exporters) उन पर क्पों में बिल मिलें तो एक्सचेंज बैंकों को भारतीय व्यापारियों की सहायता करनी चाहिए।

कमेटी की यह भी राय थी कि जब एक्सचेंज बैंकों की एसोशियेशन अपने नियमों में कोई परिवर्तन करे तो उसे भारतीय व्यापारियों से परामर्श करना चाहिए।

कमेटी की यह भी सम्मति थी कि एक्सचेंज बैंकों को भारतीय बीमा कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, भारतीय युवकों को ऊँचे पदों पर नियुक्त करना चाहिये और जहाँ एक्सचेंज बैंक की भी शाखा हो वहाँ एक स्थानीय परामर्श दाता बोर्ड (Local Advisory Board) होना चाहिए जो ज्ञान देने के सम्बन्ध में बैंक को परामर्श दे। यद्यपि बोर्ड की सलाह बैंक मान ले तो यह

आवश्यक नहीं था, कि भी इस प्रकार भारतीय ब्राह्मणों तथा एकसंघ बैंकों में परस्पर अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो सके हैं।

यद्यपि ब्रिटिश बैंकिंग कम्पनी ने उद्यम निम्न सुझाव रखे थे किन्तु एकसंघ बैंकों ने उद्यम सुझावों की आस काँई ध्यान नहीं दिया और न अपना कार्य पद्धति में भी काम आगर किया।

उद्यम भारतीय विद्वानों (निम्न धा सूचनाओं और मतभेद मुख्य थे) की राय थी कि एकसंघ बैंकों पर उदा नियंत्रण रक्खा जावे। रिज़र्व बैंक को इस बात का पूरा अधिकार होना चाहिए कि वह जिस बैंक से चाहे लायकतम देना अस्वीकार कर दें। इससे अतिरिक्त उनका यह भी कहना था कि एकसंघ बैंकों को भारत में उद्यम उद्यमों का निष्पादन करने देना चाहिए जिनकी भारतीय व्यापार के लिए आवश्यक हो। एक मत यह भी था कि एकसंघ बैंक जिनका निष्पादन लो उद्यम पर है प्रतिशत कर लगाया जाय। इससे अतिरिक्त कुछ विद्वानों का यह भी कहना था कि एकसंघ बैंकों से उद्यमों में तथा निष्पादन करने का अधिकार होना चाहिए जब उनका निष्पादन भारत में होना हो उनका पूँजा स्वयं में हो और भारतीय उद्यमों को सहायता हो। ब्रिटिश बैंक मत यह कि एकसंघ बैंकों को भारत में निष्पादन करने का मनाही कर देना जाय। किन्तु ऊपर लिखे मतों का ब्रिटिश बैंकिंग कम्पनी ने स्वागत नहीं किया।

भारतीय एकसंघ बैंक — ब्रिटिश बैंकिंग कम्पनी का यह भी मत था कि यदि इम्पारियल बैंक रिज़र्व बैंक की सहायता से विदेशी विनिमय (Foreign Exchange Business) का कारबार न कर सका तो एक भारतीय विनिमय बैंक स्थापित किया जाय। कम्पनी का मत था कि वह बैंक सरकार का सहायता से स्थापित हो। किन्तु कम्पनी का मत था कि पहले इम्पारियल बैंक के द्वारा ही यह कार्य करना चाहिए। यदि यह सम्भव न हो तथा सोई नया बैंक खोलना चाहिए। इससे अतिरिक्त ब्रिटिश बैंकिंग कम्पनी का यह भी मत था कि भारतीय तथा विदेशीय सम्मिलित एकसंघ बैंक स्थापित होने चाहिये जिससे भारत तथा उन देशों का निम्न भारत व्यापार करना है देना का हो लाभ हो। किन्तु कम्पनी का एक भी सिफारिश कार्य रूप में परिणत नहीं की गई।

उद्यम यह है कि विदेशी विनिमय बैंक का एकाधिकार समा समाप्त होगा जब कि भारतीय व्यापारिक बैंक में विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) का कारबार की अपने हाथ में लें। अतः नए भारतीय बैंक इस ओर म उदासीन रहे हैं जब कुछ बैंकों (विशेष कर सेट्रल बैंक आव इंडिया) ने इस पर ध्यान दिया है। आशा है कि भविष्य में वे इस ओर अधिक ध्यान देंगे। रिज़र्व बैंक

को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिये।

परन्तु विदेशी बैंकों की प्रतिस्पर्धा में विदेशों में कारबार करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि भारतीय बैंक आपस में सहयोग करें और एक दूसरे को सहायता प्रदान करें।

भारतीय बैंक विदेशी विनिमय के कारबार में अधिक भाग ले सकें इस दृष्टि से नीचे लिखे उपायों की ओर ध्यान देना चाहिए—

(१) भारत सरकार को भारतीय व्यापारियों को विदेशों में अपनी शाखाएँ कायम करने की सुविधाये देना चाहिये ताकि भारत के विदेशी व्यापार के विदेशों वाले अंश में भी भारतीयों का हिस्सा हो सके और वे विदेशी विनिमय का कारोबार भारतीय बैंकों को दे सकें।

(२) भारतीय व्यापारिकों को विदेशों बैंकों से अपना सम्बन्ध छोड़कर भारतीय बैंकों से स्थापित करना चाहिये।

(३) भारतीय बैंकों को विदेशी व्यापार के लिये आर्थिक व्यवस्था करने के काम को प्रोत्साहन देना चाहिये और व्यापारियों से यह समझौता करना चाहिये कि विदेशी विनिमय का कारोबार वे इन्हीं को देंगे।

(४) विदेशी विनिमय के कारोबार के लिये भारतीय बैंकों को अपने कर्मचारी और विशेषज्ञ तैयार करने चाहिये।

(५) भारत सरकार को भारतीय बैंकों को विदेशों में अपनी शाखाये स्थापित करने में सहायता देनी चाहिये। अगर किसी देश की सरकार भारतीय बैंकों के विकट पक्षपात करें तो भारत सरकार को भी उस देश के बैंकों के प्रति वही नीति अपनानी चाहिये। जहाँ अपनी शाखायें न हो वहाँ भारतीय बैंक दूसरे बैंकों को अपना एजेंट नियुक्त करें।

(६) भारत सरकार और रिज़र्व बैंक को अपने पास के कुछ विदेशी विनिमय का उपयोग भारतीय बैंकों को देना चाहिये। रिज़र्व बैंक को, विदेशी एजेंट भारतीय बैंकों को जो उधार दे उस पर, गारन्टी देनी चाहिये और उसकी सन्तदन शाखा को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि भारतीय बैंकों को विदेशी विनिमय के कारोबार में अधिक भाग मिल सके।

(७) भारत सरकार को अपना विदेशी विनिमय का कारोबार भी भारतीय बैंकों द्वारा ही अधिकाधिक करना चाहिये।

(८) विदेशी निर्वार्त के व्यापारियों पर भारत सरकार को यह दबाव डालना चाहिए कि वे भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के द्वारा अपना चुकारा स्वीकार करें।

(१) इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया—इम्पेरियल बैंक की स्थापना १९२१ में एक स्वतंत्र एन्ट्रप्राइज इम्पेरियल बैंक एक्ट के अन्तर्गत हुई थी। दोनों प्रेमीटिंग बैंकों का मिल कर इम्पेरियल बैंक बना था। १९३४ में इम्पेरियल बैंक ऐक्ट के अन्तर्गत बना दिया गया।

इम्पेरियल बैंक का अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) १० करोड़ ७५ लाख रुपये हैं निम्न में आधा पूँजी चुकता पूँजी (Paid up Capital) है और आधे आधा रजिस्टर किया हुआ (Reserve Liability) है। बैंक का रजिस्टर किया हुआ पूँजी १९३१ तक बैंक में १६ प्रतिशत लाभ बाँटा और १९३१ में अन्तर्गत बच १२ प्रतिशत लाभ बाँटा रहा है इस कारण बैंक के हिस्सों का मूल्य बाजार में बहुत अधिक है।

प्रश्न ४—इम्पेरियल बैंक का प्रबंध नीति स्थापना बाँड और एक कन्ट्रोल बोर्ड करता है। नीति स्थापना बाँड नीति निम्न है—उम्मेद कन्ट्रोल और मददात। प्रत्येक स्थानाध्यक्ष बोर्ड के सदस्य उस क्षेत्र में रजिस्टर में दत्त हिस्सेदारों द्वारा चुने जाते हैं और यह बाँड अपने मन्त्र तथा सहायका का सहायता से उस क्षेत्र में बैंक के दैनिक कारबार को चलाते हैं।

बैंक का कार्य संचालन कन्ट्रोल बोर्ड करता है। कन्ट्रोल बोर्ड के कार्य का निवारण करता है, स्थानाध्यक्ष बोर्डों का नियंत्रण करता है वह की पर निमित्त 'एडवाइस रेट' करने में निरिच्छता करता है और बैंक में मामूली प्रोमोटर्स का प्रकाशन का धनप्राप्ति करता है। पूरे बोर्ड का मासिक कन्ट्रोल कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। प्रत्येक स्थानाध्यक्ष बोर्ड के सदस्य चुने जाते हैं जो कि कन्ट्रोल बोर्ड के कुछ कार्य संचालन करता है। स्थानाध्यक्ष बोर्ड का चुनाव के लिए कन्ट्रोल बोर्ड का प्रबंधन कार्य संचालन एक स्थान पर नहीं है। बाँड का मासिक कन्ट्रोल कन्ट्रोल में होता है जो कभी बगुन में है।

१९३४ के पूर्व इम्पीरियल बैंक—१९३४ के पूर्व इम्पेरियल बैंक के क्षेत्रीय बोर्डों का संगठन नीति निम्न अनुसार था—(१) गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत नियुक्त (क) दो मैनेजिंग गवर्नर, (ग) ४ गैर सरकारी अधिकारी निम्न भारतीय स्थापनों की रक्षा के लिये गवर्नर जनरल मनोनीत करना था। (२) कर्ली का कन्ट्रोल नीति भारत सरकार का प्रतिनिधि होता था। (३) स्थानीय बोर्ड (Local Boards) में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तथा मन्त्र। उपर्युक्त मदद्यों में से कन्ट्रोल और कर्ली, और स्थानाध्यक्ष बोर्ड के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं था। क्षेत्रीय बोर्ड के ऊपर दिये हुए संगठन से यह स्पष्ट था कि यद्यपि इम्पीरियल बैंक हिस्सेदारों का बैंक था, किन्तु भारत-सरकार का उस पर पूरा

नियंत्रण था। करसी के कंट्रोलर को यह अधिकार था कि वह बोर्ड किसी भी निर्णय को, जो कि सरकारी जमा तथा अर्थनीति से सम्बन्ध रखता हो, कार्य रूप में न परिणत होने दे और उसे सरकार के निर्णय के लिए भेज दे। वह इम्पीरियल बैंक को उसका नीति तथा नक़द कोष की सुरक्षा के सम्बन्ध में आज्ञा दे सकता था। सरकार जो भी जानकारी इम्पीरियल बैंक से करना चाहे कर सकता था। बैंक को अपना हिसाब का लेखा तथा लेनी-देनी का लेखा (Balance Sheet) सरकार की इच्छानुसार प्रकाशित करना होगा। सरकार इम्पीरियल बैंक के हिसाब की जांच के लिए ऑडिटर नियुक्त कर सकती थी।

इम्पीरियल बैंक के कार्य—१९३५ तक इम्पीरियल बैंक सरकार का बैंकर था। जितना भी सरकारी कोष (Fund) होता वह इम्पीरियल बैंक में ही रखा जाता था। सरकार का खज़ाने का काम भी इम्पीरियल बैंक ही करता था। इम्पीरियल बैंक इस कार्य के लिए कोई कमीशन न लेता था। सरकार को जितना रुपया मिलना होता था वह इम्पीरियल बैंक लेता था और सरकार अपने खर्च के लिए उससे रुपया निकालती थी। भारत सरकार के ऋण का प्रबन्ध भी इम्पीरियल बैंक ही करता था। सरकार जो भवितव्य कर्ज निकालती थी वह भी इम्पीरियल बैंक ही निकालता था।

सरकारी कारवार के अतिरिक्त इम्पीरियल बैंक १९३५ के पूर्व केन्द्रीय बैंक (Central Bank) के भी कुछ कार्य करता था। भारत के अधिकांश बैंक उसके साथ डिपॉजिट रखते थे। इसके अतिरिक्त भारत के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में स्थापित ११ क्लियरिंग हाउसों का भी यह प्रबन्ध करता था। इम्पीरियल बैंक जहाँ-जहाँ उसकी शांखें थीं वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुपया भेजने की सुविधा प्रदान करता था। बैंक तथा जनता दोनों ही इम्पीरियल बैंक के द्वारा रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज सकते थे। इम्पीरियल बैंक रुपया भेजने के लिए जो कमीशन लेता था उसको सरकार निबंधित करती थी। इसके बदले में इम्पीरियल बैंक को सरकार ने सरकारी खजानों के द्वारा देश में एक स्थान से दूसरे स्थान को बिना कुछ लिए ही रुपया भेजने की सुविधा दी थी।

जब देश के द्रव्य-बाज़ार में रुपये की कमी पड़े तो उस कमी को पूरा करने के लिये कागज़ी मुद्रा विभाग (Paper Currency Department) बैंक को १२ करोड़ रुपये ऋण दे सकता था। किन्तु बैंक को उसके जमागत स्वरूप हुंडी या विल रखने पड़ते थे। सरकार बैंक से पहले ४ करोड़ रुपये के लिए ६ प्रतिशत और शेष ८ करोड़ रुपये के लिए ७ प्रतिशत सुद लेती थी। देश में बैंकिंग की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से इम्पीरियल बैंक के लिए कानून में ५ वर्षों

के अन्दर १०० शायद्यों स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया था। इम्पेरियल बैंक ने इन बातों का पूरा कर दिया था। जाधा बाँके एवं शायद्यों पर स्थापित की गई थी कि जहाँ कोई बैंक न था। इनके बल पर सरकार इम्पेरियल बैंक के पास अपना व्यवसाय प्रसारित करने में सक्षम था।

एक व्यापारिक बैंक होने के नाते इम्पेरियल बैंक यह सभी कार्य करता था कि एक व्यापारिक बैंक करना है। इम्पेरियल बैंक भारतीय में डिपॉजिट ले सकता था और ऋण ले सकता था किन्तु ऐसा वह नहीं कर सकता था डिपॉजिट ले सकता था और न ऋण ले सकता था। कर्ज लेने के लिए बैंक को यह अधिकार था कि वह प्रसाट्स, बॉन्ड्स व पुराने साहस ॥ डिपॉजिट ग्रहण कर सकता था और बैंक का सम्पत्ति या लाभांश (Assets) का प्रभाव पर बैंक के कारबार के लिए प्रयुक्त सकता था। इम्पेरियल बैंक अपना धन वहाँ लगाए हुए पर कुछ प्रतिबंध लगाए गये थे। इम्पेरियल बैंक केवल रियासत मिर्ज़ादियों में अपना धन लगा सकता था। उदाहरण के लिए भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकार का मिर्ज़ादियों में सरकार द्वारा महाधन प्राप्त मिर्ज़ादियों में, अधिकृत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिर्ज़ादियों तथा विधान में है इम्पेरियल बैंक अपना धन लगा सकता था। इम्पेरियल बैंक अपने निजी मिर्ज़ादियों की प्रभाव पर धन ले सकता था। इम्पेरियल बैंक विदेशी और प्रमुखता मोटों को स्वीकार कर सकता था तथा मात्र अपनी प्रत्येक प्रत्येक (Document) को यदि वह एक में बना कर दिया गया है अथवा एक के नाम कर दिये गये हैं तो उन्हें प्रभाव के रूप में स्वीकार करने के लिए ले सकता था। किन्तु इस महाने में अधिक के लिए धन नहीं ले सकता था और न किसी ऐसी विनिमय साधन पुर्ण (Negotiable Instrument) का ही स्वीकार कर सकता था जिस पर वा व्यापारिक तथा वा जमीन के हस्ताक्षर न हों (जो व्यापार में सम्मिलित न हों) और सिर्फ पत्रों में अथवा ६ महाने ॥ अधिक हो। इसी प्रकार किताब धन या धन का विनिमय अथवा अधिक न अधिक दिया जा सकता है यह भी नियमित कर दिया गया था। इम्पेरियल बैंक केवल उन विदेशी तथा अन्य विनिमय साधन पुर्णों को ले सकता था, भुगत सकता था और स्वीकार कर सकता था जिनका हि भारत में प्रभाव हो या प्रभाव हो। किन्तु कानून द्वारा इम्पेरियल बैंक को 'विदेशी विनिमय' (Foreign Exchange) का कार्य करने की मनाही थी। इम्पेरियल बैंक किताब ऐसे धन इत्यादि को भुगत भी नहीं सकता था कि जिसका अर्थ ६ महाने में अधिक हो, और न किसी ऐसी विनिमय साधन मिर्ज़ादियों (प्रतिभूति) को ही खरीद सकता था

जिसकी अवधि ६ महीने से अधिक हो। बैंक सिक्यूरिटियों, ग्लेनर तथा सोना इत्यादि को सुरक्षित रखने के लिये ले सकता था, सोना खरीद और बेच सकता था, ग्राहकों के लिये सिक्यूरिटियों की खरीद-बिक्री कर सकता था तथा उन पर ग्राहकों के लिये लाय और शुद्ध वसूल कर सकता था।

१९३४ में रिजर्व बैंक की स्थापना होने के उपरान्त अब इम्पीरियल बैंक सरकार का बैंक नहीं रहा। ऊपर लिखे प्रतिबन्ध इम्पीरियल बैंक पर हस्त लिये लगाये गये थे क्योंकि वह सरकार का बैंक था और सरकार का रुपया उसके पास रहता था, किन्तु रिजर्व बैंक की स्थापना के उपरान्त जब वह सरकार का बैंक नहीं रहा तो इम्पीरियल बैंक पर सरकार का जो नियन्त्रण था और उसके कार्यों पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये थे उनको उठा कर दिया गया।

१९३४ के इम्पीरियल बैंक ऐक्ट के अनुसार बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के १६ सदस्यों में से सरकार अब केवल दो सदस्यों को, जो सरकारी कर्मचारी न हों, मनोनीत कर सकती है। इनके अतिरिक्त सरकार एक सरकारी अफसर को भी मनोनीत कर सकती है जो कि बोर्ड की मीटिंगों में जा सकता है किन्तु वोट नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को केवल इतना अधिकार और है कि वह चाहे तो आडिटर नियुक्त करे जो बैंक के हिसाब की जाँच करके उसे रिपोर्ट दे।

केन्द्रीय बोर्ड के १६ सदस्य नीचे लिखे अनुसार हैं।

- १ मैनेजिंग डायरेक्टर—केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त
- १ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर—केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त
- २ सरकार द्वारा मनोनीत किए हुए शीर सरकारी सदस्य
- ६ स्थानीय बोर्डों के समापति और उपसमापति
- ३ स्थानीय बोर्डों के मंत्री
- ३ स्थानीय बोर्डों द्वारा निर्वाचित उनके सदस्यों में से

१९३४ के ऐक्ट के अनुसार सरकार का इम्पीरियल बैंक के प्रबन्ध पर जो प्रभाव और नियन्त्रण था वह दूर कर दिया गया। इसी प्रकार उसके कार्य पर जो प्रतिबन्ध लगाये गए थे वे भी हटा दिए गए। अब इम्पीरियल बैंक भारत के बाहर भी बिपन्नित ले सकता है तथा ऋण प्राप्त कर सकता है। इम्पीरियल बैंक अब विदेशी विनिमय के काम को कर सकता है तथा विदेशी वित्तों को खरीद सकता है तथा भुना सकता है और बेच सकता है। पहले इम्पीरियल बैंक ऊपर लिखे कार्य नहीं कर सकता था। पहले इम्पीरियल बैंक ६ महीने से अधिक के लिए न तो ऋण ही दे सकता था और न ६ महीने की अवधि से अधिक की

अथवा पाले जिनको भुगतान नहीं हो सकता था, किन्तु अब ये बैंकों के धन की आर्थिक सहायता देने के लिये दमन के लिए प्रयत्न कर सकता है अथवा मददगार बैंक के पत्र (Co-operative paper) खरीदकर सकता है। जिन सिन्डिकेटों (प्रतिभूति) व विदेशी इन्वेंचर बैंक पहले प्रयत्न कर सकते थे उसी संख्या में वृद्धि कर दी गई है। अब बैंक कमनिदा व डिबेंचरों की सामान्य पर, बचक रुपये हुए माल पर, (न कि बचक उद्योग माल पर जो कि बैंक के पास जमा कर दिया जावे) मुनिस्त्रिपिटियों द्वारा निम्नलिखित डिबेंचरों या अन्य सिन्डिकेटों पर तथा रिजर्व बैंक व हिस्सा का जमानत पर भी प्रयत्न कर सकते हैं। अब मा. पहल का कुछ इकायें इन्वेंचर बैंक पर लागू हैं। उदाहरण के लिए बैंक अपने हिस्सों का जमानत पर, अथवा मन्थन का जमानत या बचक पर अथवा ऐम निम्नलिखित साधन पुत्र (Negotiable Instrument) पर निम्न पर कम से कम दो स्वतन्त्र व्यक्तियों अथवा फर्मों व इन्वेंचर बैंक हों, जो कि आपस में सम्बन्धित न हों, प्रयत्न नहीं कर सकते। इन्वेंचर बैंक अधिक से अधिक निम्नलिखित अथवा अन्य किसी एक व्यक्ति को अथवा कम से कम दो या अधिक भी कानून द्वारा सीमित है।

ऊपर लिखे प्रतिभूतियों को लगाने का आवश्यकता इन कारणों से है, क्योंकि इन्वेंचर बैंक एक रिजर्व बैंक का एकमात्र एजेंट है और जहाँ रिजर्व बैंक का प्रावधान नहीं है वहाँ इन्वेंचर बैंक ही सरकार की सहायता का काम करता है तथा कोष को रखता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक की तरह ही निम्नलिखित है कि रिजर्व बैंक की स्थापना के समय इन्वेंचर बैंक का जमानत प्रावधान था कम से कम उतनी प्रावधान वह अवश्य बनाए रखने। रिजर्व बैंक ने एकमात्र एजेंट का काम करने के लिए १५ वर्ष के लिए इन्वेंचर बैंक का किया गया है और इन्वेंचर बैंक को उद्योग कार्य के लिये एक निम्नलिखित रजम कमीशन व अन्य भी दी जाती है।

वर्तमान स्थिति — वर्तमान इन्वेंचर बैंक सरकार का बैंक नहीं रहा, किन्तु फिर मा. उद्योग भारतीय द्रव्य बाजार (Money Market) में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब मा. वह बहुत अधिक डिमांड आकर्षित करता है। इन्वेंचर बैंक के ऊपर से प्रतिभूतियों के उठ जाने से वह आर्थिक तथा विदेशी व्यापार को अधिक सहायता प्रदान कर सकेगा। किन्तु भारतीय व्यापारियों को उसने विदेशी बहुत भी शिकायतें हैं। इन्वेंचर बैंक व विदेशी भारतीयों का सबसे अधिक गम्भीर आरोप यह है कि उनका संचालन मुख्यतः विदेशियों के हाथ में है और वे भारतीयों के साथ सहानुभूति का व्यवहार नहीं करते। यदि कोई भारतीय व्यापारी या फर्म उनसे आर्थिक सहायता माँगता है तो उसे कठिनाई

होती है, किन्तु अंग्रेजों को आर्थिक सहायता आसानी से मिल जाती है। इम्पीरियल बैंक के अधिकांश उच्च अधिकारी विदेशी हैं इस कारण भारतीयों को इम्पीरियल बैंक से इस प्रकार की शिकायत रही है। यहाँ नहीं, १९३४ के पूर्व भारतीय व्यापारिक बैंकों (Commercial Banks) को यह भी शिकायत थी कि इम्पीरियल बैंक यद्यपि एक केन्द्रीय बैंक (Central Bank) है परन्तु वह अन्य बैंकों से अनुचित प्रतिस्पर्धा करता है। आज भी उनको यह शिकायत है कि रिजर्व बैंक के एकमात्र एजेंट होने के नाते उसे जो प्रतिष्ठा मिली हुई है उसके कारण वह अन्य बैंकों की उन्नति में एक रुकावट उत्पन्न करता है। भारतीय बैंकों की यह माँग है कि केवल इम्पीरियल बैंक को रिजर्व बैंक का एक मात्र एजेंट बना देना उचित नहीं है। जितने बड़े और सुदृढ़ बैंक हैं उन सभी को यह प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिये।

यद्यपि रिजर्व बैंक की स्थापना हो चुकी है परन्तु फिर भी अभी तक केवल व्यक्ति ही नहीं बैंक तथा देशों के बैंकर भी इसी के पास ऋण तथा अपने बिल या हुएड़ी मुनाने के लिए आते हैं। इस प्रकार इम्पीरियल बैंक द्रव्य बाजार (Money Market) तथा रिजर्व बैंक के बीच में एक मध्यस्थ का काम करता है। इम्पीरियल बैंक के पुराने इतिहास, उसके अनुल साधन और उसकी असीम प्रतिष्ठा को देखते हुए कुछ दिनों तक रिजर्व बैंक को इम्पीरियल बैंक के साथ मिलकर द्रव्य बाजार का नियंत्रण तथा उसका नेतृत्व करना होगा।

इम्पीरियल बैंक को रिजर्व बैंक में क्यों न परिणत कर दिया गया:— रिजर्व बैंक के अध्याय में हमने यह बतलाया है कि हिलटन-यंग कमीशन ने इम्पीरियल बैंक को ही रिजर्व बैंक में परिणत किये जाने की राय क्यों न दी। इसके मुख्य दो कारण थे। एक कारण तो यह था कि यदि इम्पीरियल बैंक को ही रिजर्व बैंक बना दिया जाता तो उस समय जो इम्पीरियल बैंक की बहुत सी ग्राँचे थी वे बन्द करनी पड़नीं। इससे वैकिंग कारखानों को धक्का लगता जबकि देश को अधिकाधिक बैंकों की आवश्यकता थी। इसके अनिश्चित दूसरा कारण यह था कि यदि इम्पीरियल बैंक रिजर्व बैंक बना दिया जाता तो उसके लाभ को कानून के द्वारा सीमित कर दिया जाता जो कि इम्पीरियल बैंक के हिस्सेदार कमी भी पसंद न करते। पिछले दिनों से इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की चर्चा चल रही है। और इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के अपने निर्णय की सरकार ने घोषणा भी कर दी थी। पर फिलहाल सरकार ने अपने इस निर्णय को कार्यान्वित करने से स्थगित कर दिया है।

इम्पीरियल बैंक का भविष्य में महत्त्व:—भविष्य में देश की वैकिंग-व्यवस्था में इम्पीरियल बैंक का स्थान काफी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। 'रुस्त

बैंकिंग इन्वेषामरा कमेटी ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए इम्पीरियल बैंक व सामने यह लक्ष्य उपस्थित किया है कि देश के प्रत्येक जिले, तालुका या मंडा में इम्पीरियल बैंक की शाखा या प ऑफिस काममें किया जाये। बैंकिंग कमेटी ने यह राय दी है कि इम्पीरियल बैंक निजिय बैंक के सहायक के रूप में काम करेगा और उन् कमजोर बनाने का कोई इरदम नहीं उठाना चाहिये।

इम्पीरियल बैंक व विरुद्ध जो शिकायतों का ज्ञात है उन पर भी कमेटी ने अपने विचार प्रकट किये हैं। बैंक व अराध्याय व्यवहार का बात देश के स्वतंत्र हो जाने व धाद कोड महत्त्व नहीं रखना, ऐसा कल्पना का मानना है। चूंकि इम्पीरियल बैंक का निजिय बैंक व एजेंट व नार पर काम करने का एकाधिकार है इसलिये यह शिकायत रहा है कि बैंक अपना इस विषय स्थिति का दूसरे बैंकों व विरुद्ध उद्योग कर सकता है जो कि अनुचित है। स्पष्ट बर्तन कमेटी ने यह शिकायत का है कि बैंक का इस विशेष स्थिति को समाप्त करने का तो आवश्यक कता नहीं है, पर सरकार को बैंक पर पहले जितना नियन्त्रण काम करना चाहिये। उदाहरण व लिंग बर न मैजिस्ट्रेट और डिप्टी मैजिस्ट्रेट गण्डेनटस का नियुक्ति सरकार की स्वीकृति में जाना चाहिये। सरकार अधिनार को यह अधिकार होना चाहिये कि सरकार का नाम में सब वरने पाते केन्द्रीय बोर्ड ने कितना नियन्त्रण को वह स्थिति कल मर और उस सरकार व पाम भिन्नता मने। सरकार द्वारा मनोनाम डाइरेक्टर कन्दाय धाद का समिति के सदस्य होने चाहिये और उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिये। तैर न उच्च कमचार्य आन भी विदेरा है पर भारतीयकरण का पुरा प्रयत्न किया जा रहा है और बैंक न भारत-सरकार को यह आश्वासन दिया है कि १९५५ तक बैंक व सब उच्च कमचारी भारतीय हो जायेंगे। देश में बैंकिंग व प्रसार में योग देने की दृष्टि में बैंक को अधिक शाखायें खोलना चाहिये यह मा कमेटी ने शिफारिश की है। वहा गुरु इम्पीरियल बैंक द्वारा दूसरे बैंकों व माय अनुचित प्रतिस्पर्धा का मवाल है, बैंकिंग कमेटी ने यह शिफारिश की है कि इस आन ध्यान दिया जाना चाहिये कि इम्पीरियल बैंक सरकारी खाना खाने व वारण अनुचित लाभ न उठाव और दूसरे बैंकों के साथ इस प्रकार अनुचित प्रतिस्पर्धा न कर मने। पर साथ ही कमेटी का यह भी शिफारिश है कि इम्पीरियल बैंक को उन स्थानों में भी सरकारी बैंक का काम करना चाहिये जहा अभी उसकी शाखायें न होने में वह नहीं कर सकता।

५—रिजर्व बैंक प्राय इच्छित—भारतवर्ष में एक केन्द्रीय बैंक (Central Bank) की आवश्यकता वृत्त पहले से अनुभव की जा रही थी किन्तु भारत-सरकार ने इसका ओर कर्मी ध्यान नहीं दिया। १९१३ में जब

भारत की करैंसी के सम्बन्ध में जांच करने के लिए 'चेम्बरलेन कमीशन' विटाया गया उस समय श्रीयुक्त कीन्स महोदय ने एक केन्द्रीय बैंक की योजना उपस्थित की जो कि चेम्बरलेन रिपोर्ट के साथ प्रकाशित हुई, किन्तु भारत ने उसकी ओर ध्यान तक न दिया। १९१४-१८ के महायुद्ध में सभी को केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता का अनुभव हुआ। किन्तु जब १९२० में ब्रुसल्स अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक-सम्मेलन ने इस आशय का प्रस्ताव पास किया कि "जिन देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं है वहां भी शीघ्र ही केन्द्रीय बैंक स्थापित होना चाहिए" तब कहीं भारत-सरकार का ध्यान उधर गया। अतएव १९२१ में इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई। किन्तु इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक के सभी कार्य नहीं करता था इस कारण एक स्वतंत्र केन्द्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता होने लगी। जब १९२३ में हिल्टन यंग कमीशन बैठा तो यह समस्या उसके सामने भी उपस्थित हुई। देश में कुछ विद्वानों का मत था कि इम्पीरियल बैंक को ही भारत का केन्द्रीय बैंक बना देना चाहिये किन्तु कुछ उसके विरुद्ध थे। हिल्टन यंग कमीशन के इस प्रश्न का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया और एक स्वतंत्र हिस्तेदारों के केन्द्रीय बैंक की स्थापना का समर्थन किया।

जिन कारणों से हिल्टन यंग कमीशन ने इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक न बनने की सम्मति दी वे निम्नलिखित हैं :—

(१) इम्पीरियल बैंक के पास गयेष्ट पूंजी और डिपॉजिट हैं और उसकी सैकड़ों शाखाएँ भारत भर में फैली हुई हैं। भारत जैसे देश में जहाँ बैंकिंग की सुविधायें नहीं के बराबर हैं, यदि इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक बना दिया गया तो उसका अपनी शाखाओं को बन्द करना होगा। इससे भारतीय व्यापार को गहरा झटका लगेगा। आवश्यकता तो इस बात की है कि इम्पीरियल बैंक को बन्धनों से मुक्त कर दिया जावे और उसे एक सुदृढ़ और महान् व्यापारिक बैंक के रूप में देश की सेवा करने दी जावे। इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक भी बना दिया जावे और व्यापारिक बैंकिंग भी करता रहे यह नहीं हो सकता। क्योंकि यदि इम्पीरियल बैंक व्यापारिक बैंकिंग करेगा तो अन्य व्यापारिक बैंकों से प्रतिस्पर्दा करेगा जो कि अनुचित होगा। क्योंकि केन्द्रीय बैंक के पास राज्य की बिना एट की डिपॉजिट रहेगी और उसके पास इतने विरोध अधिकार रहेंगे कि उसको अन्य बैंकों से होड़ करने देना सर्वथा अन्वायपूर्ण होगा। साथ ही केन्द्रीय बैंक को कागज़ी मुद्रा निकालने का एकाधिकार दिया जायेगा अतएव उसे व्यापारिक बैंकिंग के खतरे को न उठाना चाहिए।

(२) इम्पीरियल बैंक को भारतीय व्यापारिक बैंक अपने प्रतिद्वन्द्वी के रूप

में देखते रहे हैं, क्योंकि यह भारतीय बैंकों से द्रव्य बाजार में प्रतिद्वंद्विता कर रहा है अतएव उसको केन्द्राय बैंक बनाना उचित नहीं है। केंद्राय बैंक को सभी अन्य बैंकों का नेतृत्व करना होगा। अन्तु, किसानों के बैंक को विभिन्न अन्य बैंक अपना प्रतिद्वंद्वी मानते रहे हैं केन्द्राय बैंक बनाना उचित न होगा।

(३) इम्पारियल बैंक व प्रति भारतीय व्यापारिक, देशी बैंकों तथा भारतीय व्यापारिक बैंकों की अच्छी चारणा नहीं है। उनका कहना है कि इम्पारियल बैंक की नीति अस्वाभाविक है। अनेक व्यापारियों तथा श्रमिकों द्वारा संचालित बैंकों के साथ उसका व्यवहार नरम सहानुभूतिपूर्ण और उदार होता है। हिल्टन यंग कमीशन का मत था कि जिन बैंक व प्रति देश में ऐसा भारपा हो वह केंद्राय बैंक व उत्तरदायित्व को एक प्रकार से न निराह सकता।

(४) कमाशन का यह भी राय था कि हिस्तेदार भा हम परिधान को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि यदि इम्पारियल बैंक केंद्रीय बैंक बना दिया जावेगा तो सरकार की कानून व द्वारा उसका लाभ का बर्पादिन कर देना होगा। हिस्तेदारों की व प्रतिशत व लगभग लाभ मिल सकता है। इम्पारियल बैंक के हिस्तेदार कभी पसंद न करेंगे, क्योंकि उन्हें अभी बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसी कारणों से हिल्टन यंग कमीशन ने एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक की स्थापना का समर्थन किया। कमाशन ने जब एक प्रश्नव समस्या के स्थापित किये जाने का ही समर्थन नहीं किया वरन् उसने हम बात का भी समर्थन किया कि रिजर्व बैंक राज्य का न होकर हिस्तेदारों का होना चाहिए।

हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने एक दिन केन्द्राय धारा सभा (Central Legislative Assembly) में उपस्थित किया। हम बिल में एक हिस्तेदारों व रिजर्व बैंक की स्थापना की व्यवस्था थी और उसके संचालन बोर्ड में हिस्तेदारों द्वारा चुने हुए हायरेक्टरों का बटुन था और बैंक व सबनर तथा डिप्टी गवर्नर व सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते का विधान था। किन्तु सेलेक्ट कमेटी ने लगभग महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये। उसमें विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन यह था कि बैंक हिस्तेदारों का न होकर सरकार का होगा। सरकार इस परिवर्तन के लिये नो नेषन हो गई थी कि बैंक राज्य का हो पर संचालक-मंडल के प्रश्न पर एसेम्बली और सरकार में समझौता न हो सका। इस पर भारत सरकार ने हिस्तेदारों का बैंक कायम करने का नया बिल पेश करना चाहा, पर जब तक पुराना बिल सरकार वापस नहीं ले नये बिल को पेश करने की इजाजत नहीं मिला। पुराने बिल के साथ तो भगदा सया ही था। अतः, उस समय भारत में एक केन्द्राय बैंक स्थापित न हो सका।

किन्तु जब भारत में नवीन शासन-सुधार की योजना-सैयार हुई और भारत में संघीय सरकार (Federal Government) की स्थापना का आयोजन होने लगा जो संघीय धारा सभा के लिये उत्तरदायी होती, तो एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता हुई जो कागज़ी मुद्रा (Paper Currency) को निकालने का प्रवन्ध करे। अतएव १९३४ में रिज़र्व बैंक ऐक्ट पास हुआ और उसको हिस्सेदारों के बैंक के रूप में स्थापित किया गया। रिज़र्व बैंक को हिस्सेदारों का बैंक होना चाहिए अथवा राज्य का, इस सम्बन्ध में भारत में बहुत वाद-विवाद चला। अस्तु; हम यहां दोनों पक्षों का मत देंगे।

बैंक हिस्सेदारों का हो अथवा राज्य का हो :—जिन लोगों का कहना था कि बैंक राज्य का होना चाहिए वे नीचे लिखे तर्क उपस्थित करते थे:—

(१) रिज़र्व बैंक को इनके अधिकार दिये गये हैं कि यदि बैंक पर पूँजीपतियों का प्रभाव हो गया तो वे उसका दुरुपयोग करने जिससे देश के आर्थिक हितों को धक्का पहुँचेगा। यदि बैंक हिस्सेदारों का रहा तो पूँजीपतियों का उस पर प्रभाव हो जाना स्वाभाविक है। अस्तु; ऐसा करना खतरनाक है।

(२) क्योंकि बैंक कागज़ी मुद्रा (Paper Currency) निकालेगा तथा राज्य के कोष (Funds) अपने पास रखेगा अतएव उसको बहुत अधिक लाभ होगा। यह लाभ देश के लाभ के लिये राज्य को मिलना चाहिए न कि हिस्सेदारों को।

(३) भारत में राज्य अधिकांश रेलों, पोस्ट आफिस इत्यादि का प्रवन्ध करता है। लोगों को राज्य के प्रवन्ध में अधिक विश्वास है और पूँजीपतियों के प्रवन्ध को वे सन्देह की दृष्टि से देखते हैं।

(४) रिज़र्व बैंक के कार्य ऐसे महत्त्वपूर्ण हैं कि राज्य को उसे अपने नियन्त्रण में रखना ही होगा। अस्तु; उसे राज्य का बैंक ही क्यों न बना दिया जावे।

(५) जिन देशों में केन्द्रीय बैंक हिस्सेदारों की संस्था है वहाँ भी उसका गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर इत्यादि सरकार ही नियुक्त करती तथा बैंक के नीति के निर्धारण में उसका प्रमुख हाथ रहता है। कहना इस प्रकार चाहिये कि राज्य ही बैंक का नीति निर्धारित करता है। ऐसी दशा में हिस्सेदारों का बैंक स्थापित करने का अर्थ नहीं होता।

(६) इस बात का मत है कि हिस्सेदारों का बैंक योरोपियनों के प्रभाव में आजावेगा और हमसे भारतीयों के हितों की उपेक्षा होगी।

तत्कालीन केन्द्रीय धारा सभा का यह भी विचार था कि बैंक केवल राज्य का ही न हो, वरन् उसके संजालकबोर्ड में कुछ बाह्यरेक्टर धारा सभा के

बुने हुए सदस्य होने चाहिये। क्योंकि सरकार जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अस्तु जनता के बुने हुए डायरेक्टर बोर्ड में होने चाहिये।

इसके विरुद्ध हिस्सेदारों के बैंक के एक म जो लोग थे उनमें नीचे लिखे तर्क थे —

(१) समार म जितने कर्तव्य बैंक हैं उनमें से कुछ को छोड़कर सभी हिस्सेदारों के बैंक हैं।

(२) देश के आर्थिक दिनों की दृष्टि से यह आवश्यक है कि रिजर्व बैंक पर कोई राजनैतिक प्रभाव न हो और वह अपने कार्यों को मुक्त रूप से कर सके।

(३) हिस्सेदारों के बैंक म पूर्णतः निरर्थक व प्रभाव बड़ जाने का जो भय है उसको दूर निवारण बनाकर कि एक व्यक्ति अधिक हिस्से न धरीद करने दूर किया जा सकता है। रहा लाभ का प्रश्न वह तो कानून द्वारा सीमित कर दिया जावेगा और अधिकतर लाभ राज्य को मिलेगा।

ऊपर लिखे कारणों का अधिक महत्त्व देने हुए १९१५ के कानून के तहत में रिजर्व बैंक को हिस्सेदारों का बैंक बनाया गया।

रिजर्व बैंक का विधान — यह तो हम ऊपर ही कह चुके हैं कि रिजर्व बैंक को हिस्सेदारों का बैंक बनाया गया है। बैंक की हिस्सा पूँजी (Share Capital) ५ करोड़ रुपये रखा गई। प्रत्येक हिस्सा १०० रु० का रखा गया जो कि पूरा चुका दिया गया था। इस उद्देश्य से कि बैंक पर किसी एक प्रदेश का प्रभाव न हो जावे भारत को पाँच भागों में विभक्त कर दिया गया और हिस्सेदारों के पाँच रजिस्टर खोले गए। भिन्न भिन्न रजिस्टरों की नावे लिखे अनुसार हिस्सा पूँजी बाँट पा गई।

बम्बई १५० लाख

कलकत्ता १५५ लाख

देहली ११५ लाख

मद्रास ७० लाख

रंगून ३० लाख

इसके अनतिरिक्त यह नियम भी बना दिया गया कि प्रत्येक हिस्सेदार को पाँच हिस्सों के पीछे एक मत (Vote) देने का अधिकार होगा, और किसी हिस्सेदार को दस मत (वोट) से अधिक देने का अधिकार न होगा। यह नियम इस उद्देश्य से बनाया गया था कि रिजर्व बैंक के हिस्सों को कुछ लोग न हथिया लें। किन्तु ऊपर लिखे नियमों के रहते हुए भी रिजर्व बैंक के हिस्से कमश बम्बई

रजिस्टर में अधिक बढ़ते गए। यही नहीं कि अन्य रजिस्ट्रारों में हिस्से कम होते गए और बम्बई रजिस्टर में हिस्से बढ़ते गए, वरन् साथ ही हिस्सेदारों की संख्या कम होती गई। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि रिज़र्व बैंक के हिस्से क्रमशः कुछ थोड़े से हाथों में इकट्ठे होते गए।

बैंक के हिस्सेदारों की संख्या में ३० जून १९४१ तक ३८ प्रतिशत की कमी हो गई। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए मार्च १९४० में रिज़र्व बैंक ऐक्ट में इस आशय का संशोधन किया गया कि यदि कोई व्यक्ति २६ मार्च १९४० के उपरान्त रिज़र्व बैंक के हिस्से खरीदता है और उन हिस्सों के सहित उसके पास अपने व्यक्तिगत नाम में अथवा व्यक्तियों के साथ सम्मिलित नाम में २०,००० रु० के मूल्य के हिस्सों से अधिक हो जाने हैं तो उन अधिक खरीदे हुए हिस्सों को उसके नाम नहीं रजिस्टर किया जावेगा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि २६ मार्च १९४० के उपरान्त कोई भी व्यक्ति कुल मिलकर २०,००० रु० के हिस्सों से अधिक नहीं खरीद सकता था। किन्तु इतना होने पर भी रिज़र्व बैंक के हिस्सेदारों की संख्या कम होती गई और क्रमशः हिस्से कुछ हाथों में केन्द्रित होते गये।

रिज़र्व ऐक्ट से बैंक की हिस्सा पूंजी को घटा-बढ़ा सकने का भी विधान किया गया।

रिज़र्व बैंक ऐक्ट के अनुसार बैंक को बम्बई, कलकत्ता, देहली, मद्रास और रंगून में अपने ऑफिस खोलने से और लन्दन में एक ब्रांच स्थापित करनी थी। बैंक ने ऊपर लिखे स्थानों पर अपने ऑफिस स्थापित कर दिये थे। ऐक्ट के अनुसार बैंक को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह भारत-सरकार की पूर्व आज्ञा लेकर भारत में किसी स्थान पर भी अपनी ब्रांच या एजेंसी स्थापित करे। बैंक ने कानपुर, कराँची, ढाका तथा लाहौर में अपनी ब्रांचें स्थापित की तथा जहाँ-जहाँ इम्पीरियल बैंक की ब्रांचें थी वहाँ इम्पीरियल बैंक को अपना एजेंट बना दिया है। युद्धकाल में जापान द्वारा बर्मा पर अधिकार होने पर रंगून का दफ्तर बन्द कर दिया गया और फिर स्थापित नहीं किया गया। देश के विभाजन के बाद जब १ जुलाई, १९४८ को पाकिस्तान बैंक की स्थापना हो गई तो लाहौर, कराँची और ढाका की बैंक की शाखायें राज्य बैंक पाकिस्तान ने लेली।

प्रबन्ध—बैंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय बोर्ड के हाथों में सौंपा गया। राष्ट्रीय-करण के पहले उसमें १६ डाइरेक्टर होते थे। वह १६ डाइरेक्टर नीचे लिखे अनुसार नियुक्त होते थे—(१) एक गवर्नर तथा दो डिप्टी गवर्नरों को भारत-सरकार नियुक्त करती थी। भारत-सरकार नियुक्त करते समय इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश को ध्यान में रखकर ही नियुक्ति करती है।

(२) ४ डायरेक्टरों का भारत सरकार मनोनीत करनी थी। यह डायरेक्टर उन हिता का प्रतिनिधित्व करते थे जो कि साधारण बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व नही पा सकते। (उदाहरण के लिए इषि इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने वाले डायरेक्टर)

(३) ८ डायरेक्टर भिन्न भिन्न रजिस्ट्रार व हिस्सेदारों द्वारा चुन जाते थे। मध्य स्तरीय अर्थशास्त्र में स प्रत्येक का दा दा डायरेक्टर चुनने का अधिकार था और रजून तथा मध्यम का एक एक डायरेक्टर ही चुनने का अधिकार था।

(४) भारत सरकार एक सरकारी समिति का बोर्ड में मनोनीत करता था।

गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर की धनन मिलता है और व बैंक व वन भोगा डायरेक्टर हात है। वर मा राष्ट्रीयकरण होने तक डायरेक्टर पौन वर्षों के लिए नियुक्त निय जात थे किन्तु पांच वष समित हा तान पर व फिर नियुक्त किय जा सकत थे। सरकारा कमचारा डायरेक्टर भारत सरकार का इच्छातुसार अपन पद पर रहता है। डिप्टी गवर्नर तथा सरकारी कमचारा डायरेक्टर बोर्ड का माटिंग में भाग ले सक्त है, उसका माटिंग में उपस्थित हो सक्त है, किन्तु वोट नहीं द सकत। गवर्नर का अनुपस्थिति में एक डिप्टी गवर्नर वोट द सकता है, यदि वह भारत सरकार का लिपित प्राप्त प्राप्त कर ले। अन्य दूतरे सभी डायरेक्टर जब पांच वर्षों तक अपन पद पर रहत थे।

रज्दाय तथा राज्य का धारा यभा का सदस्य, काइ वन भोगी सरकारा कमचारा, किता बैंक का नाकर वा कमचारी किमी बैंक का डायरेक्टर (सहकारी बैंक के डायरेक्टरों को छोड़कर), रिजर्व बैंक का डायरेक्टर या स्थानीय बोर्ड (Local Boards) का सदस्य नही हो सकता। काई व्यक्ति जा कि कर्दाय बोर्ड का डायरेक्टर या स्थानीय बोर्ड का सदस्य चुना गया हा वा मनोनात किया गया हो यदि रिजर्व बैंक व ५००० रु० व हिस्सा का ६ सहान व अन्तर रजिस्टर्ड स्वामा नही बन जाता तो वह डायरेक्टर या सदस्य नहीं रह सकता। यदि काई डायरेक्टर बिना गवर्नर स सुझ प्राप्त किय तीन लगातार माटिंगों में अनुपस्थित हो जाता है तो वह बैंक का डायरेक्टर नहीं रहता।

स्थानीय बोर्ड और उनका कार्य—इसी प्रकार राष्ट्रीयकरण व पहले प्रत्येक रजिस्टर का एक स्थानीय बोर्ड होता था जिसका समपदन इस प्रकार होता था—(१) उस रजिस्टर व हिस्सेदार अपन म से पौन सदस्य चुनते थे। (२) केन्द्रीय बोर्ड उस रजिस्टर के हिस्सेदारों में से अधिक से अधिक तीन सदस्यों को मनोनात करता था। केन्द्रीय बोर्ड को अधिकार इसलिए दिया गया था कि

लिखते कृपि सहकारी बैंक, तथा अन्य ऐसे हितों का स्थानीय बोर्ड में प्रतिनिधित्व हो सके।

स्थानीय बोर्ड के दो कार्यों होते थे। एक तो वे अपने में से केन्द्रीय बोर्ड के लिये टाकरेक्टर चुनते थे और दूसरे वे केन्द्रीय बोर्ड को उन सब बातों पर अपनी राय देते थे कि जो उसकी सम्मति के लिये मेजी जाती थी। स्थानीय बोर्ड के अधिकार बहुत ही सीमित हैं और उनका कोई महत्त्व नहीं है।

रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण—भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत-सरकार ने रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया और इस उद्देश्य से रिज़र्व बैंक अधिनियम (ट्रान्सफर ऑफ़ पब्लिक प्रोपर्टी) एक्ट, १९४८ पास किया गया। १ जनवरी १९४८ से यह एक्ट लागू होगा। इस सम्बन्ध में आगे लिखा गया है।

रिज़र्व बैंक के कार्य—रिज़र्व बैंक के व्यापारिक कार्य—रिज़र्व बैंक नीचे लिखे व्यापारिक कार्य कर सकता है।

(१) रिज़र्व बैंक बिना सूद की डिपॉजिट स्वीकार कर सकता है। रिज़र्व बैंक पर सूद न दे सकने का प्रतिबंध इस कारण लगाया गया है कि वह व्यापारिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा न कर सके।

(२) रिज़र्व बैंक ऐसे बिलों (Bills) और प्रामिसरी नोटों को जो वास्तविक व्यापारिक व्यवहारों (Commercial Transactions) के कारण उत्पन्न हुए हों, जिन पर दो अच्छे हस्ताक्षर हों, उनमें से एक हस्ताक्षर किसी शिखल (Schedule) बैंक का हो और जिनके चलन की अवधि ६० दिन से अधिक यात्री न हो, और जो भारत पर काटे गए हों और जिनका भुगतान भारत में होने वाला हो, खरीद या बेच सकता है अथवा उन्हें पुनः भुना सकता है।

इसका परिणाम यह होगा कि रिज़र्व बैंक रुपयों में काटे या लिखे गये आयात-बिल (Rupee Import Bills) को भुना सकेगा जब कि इस प्रकार के बिलों का आयात व्यापार (Import Trade) में चलन होने लगेगा। भारत सरकार या 'ए' श्रेणी के राज्यों की सरकारों की सिक्यूरिटीज में व्यापार करने की इच्छा से काटे गये बिलों को भी यदि वे ६० दिन में फूटने वाले हों तो, रिज़र्व बैंक बेच, खरीद या भुना सकता है। यदि इस प्रकार के बिल या प्रामिसरी नोट कृपि के बंधे के लिए लिखे गए हों या फसलों की बिक्री का प्रबंध करने के लिए काटे गए हों तो उनके चलन की अवधि अधिक से अधिक ६ महीने की जा सकती है। इन बिलों पर भी दो अच्छे हस्ताक्षरों की आवश्यकता है और उसमें से एक हस्ताक्षर या तो किसी शिखल बैंक अथवा प्रांतीय सरकारी

बैंक का होता चाहिए। इस प्रकार के विचारों को रिज़र्व बैंक पुनर्मुद्रा संकटा है। रिज़र्व बैंक एकदम नाला है। मर्यादा हुआ है उसका अनुसार यह अवधि ६ महीने से बढ़ाकर २५ महीने बढ़ा गई है।

(२) रिज़र्व बैंक अपने विचारों का कि मुद्रास्फोट किया इसमें मर्यादा नहीं है। किसी स्थिति पर बाजार में ही और २० प्रतिशत अन्तर बढ़ा जाने हो सकती है, बैंक और मुद्रा संकटा है। किन्तु यह कार्य वह निम्न लिखित बैंक के द्वारा ही कर सकता है।

(४) भारत में कम से कम १ लाख रुपये का कामना व लिक्विड बैंकों से स्थानीय सरकारी और उच्च स्तर के बैंकों का काम भी रिज़र्व बैंक कर सकता है।

(५) रिज़र्व बैंक 'पी' श्रेणी के बैंकों, स्थानीय शासन संस्थाओं (म्यूनिसिपल नगर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इत्यादि), लिक्विड बैंकों या राज्य सरकारों बैंकों को प्रत्यक्ष सहकारी बैंकों को श्रेष्ठ दे सकता है किन्तु इस प्रकार का श्रेष्ठ अधिक से अधिक ६० दिन के लिए दिया जा सकता है। किन्तु स्थानीय फंड (Funds) या लिक्विड बैंक (अचल सम्पत्ति को छोड़ कर) का प्रमाण पर ही मिल सकता है। जो भी लिक्विड बैंक ट्रस्टी लिक्विड बैंक है उस लिक्विड बैंक के लिक्विड रिज़र्व बैंक श्रेष्ठ दे सकता है। इससे अनिश्चित योजना का कोई अवधान उन बैंकों के अभाव पर भी श्रेष्ठ दिया जा सकता है कि बिना रिज़र्व बैंक सरकारी या मुद्रा संकटा है। किन्तु लिक्विड बैंक अवधान प्रत्यक्ष सहकारी बैंक के प्रमाणित मोड पर भी रिज़र्व बैंक श्रेष्ठ दे सकता है यदि यह वास्तव में व्यापारिक व्यवहारों (Commercial Transaction) के लिये लिया जावे।

(६) रिज़र्व बैंक केन्द्रीय तथा 'पी' श्रेणी के बैंकों को नाला महीने से अधिक के लिए श्रेष्ठ नहीं दे सकता।

(७) रिज़र्व बैंक मुद्रास्फोट किया इसमें की उन लिक्विड बैंकों का सरकारी विक्री कर सकता है जो कि स्वयंसेवकों की नाला में १० वर्षों के अवधि तक जावे। भारत सरकार या प्रान्तीय सरकार की किसी प्रकार की लिक्विड बैंक, यदि उसके पक्षों की श्रेष्ठ किन्हीं हैं, क्यों न हो, रिज़र्व बैंक सरकारी या बैंक संकटा है। 'पी' श्रेणी के बैंकों अवधान स्थानीय शासन संस्थाओं में से केवल उनकी ही लिक्विड रिज़र्व बैंक सरकारी या बैंक संकटा है किन्तु भारत सरकार बैंक-बोर्ड की लिक्विड बैंक सरकारी है। १ जनवरी, १९४६ में जो अधिनियम रिज़र्व बैंक एकट में लागू हुआ है उसके अनुसार उन रिज़र्व बैंक उन देशों की लिक्विड बैंकों में भी अपना कार्य लगा सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष के सदस्य हैं। इन देशों में मुद्रास्फोट किये जाने वाले व्यापारिक बिलों को किन्तु मियाद ६० दिन के

अन्दर पूरी होती हो, रिज़र्व बैंक खरीद, बेच और भुना सकता है। इन देशों के केन्द्रीय बैंकों में रिज़र्व बैंक रूपवा भी जमा कर सकता है।

(८) रिज़र्व बैंक अपनी पूँजी से अधिक ऋण नहीं ले सकता, और वह भी एक महीने से अधिक के लिए नहीं। ऋण केवल किसी शिक्मूल बैंक से अथवा किसी विदेशी केन्द्रीय बैंक (Central Bank) से लिया जा सकता है।

(९) कुछ दशाओं में बैंक को सीधे खुले बाज़ार में ६० दिनों के दिल् भुनाने तथा ३० दिन के लिए ऋण देने का अधिकार दे दिया गया है अर्थात् बैंक कुछ दशाओं में बिना किसी शिक्मूल बैंक अथवा प्रान्तीय सहकारी बैंक के हस्ताक्षरों के ही ऋण दे सकता है या बिलों को भुना सकता है। इसे बैंक की खुले बाज़ार की क्रिया (Open Market Operations) कहते हैं।

वह व्यापार-कार्य जो कि बैंक नहीं कर सकता:—(१) बैंक किसी व्यापारिक तथा व्यावसायिक कार्य को नहीं कर सकता। अर्थात् व्यापार तथा व्यवसाय में दिलचस्पी नहीं ले सकता और न आर्थिक सहायता दे सकता है।

(२) वह अपने हिस्सों या अन्य किसी बैंक या कम्पनी के हिस्सों को नहीं खरीद सकता और न उन हिस्सों की जमानत पर ऋण हाँ दे सकता है।

(३) वह किसी अचल सम्पत्ति को रेहन रखकर ऋण नहीं दे सकता और न अचल सम्पत्ति को खरीद हाँ सकता है। केवल अपने काम के लिए जो भी इमारत इत्यादि की आवश्यकता हो उसे अवश्य खरीद सकता है।

(४) बैंक अरक्षित (Unsecured) ऋण नहीं दे सकता।

(५) वह नुदती जमा (Deposits) या चालू खाते (Current Account) पर कोई नूद नहीं दे सकता।

(६) वह ऐसे बिलों को न काट सकता है और न स्वीकार हाँ कर सकता है कि जिनका मॉगने पर भुगतान न हो।

ऊपर लिखे व्यापारिक कार्यों के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक को भारत के केन्द्रीय बैंक (Central Bank) होने के नाते और बहुत से महत्वपूर्ण कार्य सौंप दिए गए हैं। वे नीचे लिखे हैं।

कागजी मुद्रा (Paper Currency) को निकालने का एकाधिकार— रिज़र्व बैंक को कागजी मुद्रा निकालने का एकाधिकार प्राप्त है। रिज़र्व बैंक की स्थापना के उपरान्त सरकार का कागजी मुद्रा निकालने का अधिकार समाप्त हो गया। रिज़र्व बैंक के नोट कानूनी प्राण (Legal Tender) हैं और भारत-सरकार उनकी गारंटी करती है। भारत-सरकार के पुराने नोट रिज़र्व बैंक ने ले लिए फिर उन्हें अपने नोटों के रूप में खलाया। अक्टूबर १९३८ में सबसे

पहले रिज़र्व बैंक के नोट निकाले गए। रिज़र्व बैंक पर अगले नाटा की गपों में बदलने का कानून उत्तरदायित्व है। रिज़र्व बैंक पांच रुपये, दस रुपये, पचास रुपये, सौ रुपये, पांच सौ रुपये, और दस हजार रुपये के नोट निकाल सकना है।

कागजी मुद्रा निगमन का काम बैंक का नोट विभाग (Issue Department) करता है। नोट विभाग (Issue Department) को बैंकिंग विभाग (Banking Department) में सबका घुसकर रहना जाता है। भारत में यह विभागन अनादर्यक था। यह विभागन बैंक और इंग्लैंड के आधार पर किया गया था। किन्तु बैंक और इंग्लैंड में यह विभागन इंग्लिश आदर्शक था क्योंकि यहाँ नाट विभाग में होत जाला लाम ता सरकार को जाता था और बैंकिंग का लाम हिस्सेदारों को मिलता था। किन्तु अब तक राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तब तक भा भारत में ता कानून द्वारा निधारित (४ प्रविशुन) से अधिक लाभ सरकार को मिलता था, इस कारण यह विभागन अनादर्यक था। राष्ट्रीयकरण के बाद तो इस विभागन का काम महत्व हो नहीं है। इससे ज्ञानि यह है कि बैंक का लेना देना का लेखा (Balance Sheet) दो दुककों में विभक्त हो जाता है।

जहां तक कागजी मुद्रा का सुरक्षा के लिए सुरक्षित धातु (Reserves) रखने का प्रश्न है रिज़र्व बैंक के नोट के अनुसार नूत नोटों का ४० प्रतिशत रक्षित कोष सोन के सिक्के, सोने के पाटों अथवा स्टर्लिंग के रूप में होना चाहिए और शेष रुपये तथा सरकारी सिक्के गिड़िया तथा स्टैंडन व्यापारिक पत्रों (Liable Paper) के रूप में होना चाहिये। पर १ जनवरी, १९४८ में बैंक को उन देशों का निक्कुरिन्ज—जिनमें रिन और नकद भी शामिल है—भा रक्षित कोष में रखने का अधिकार हो गया है जो अंतराष्ट्रीय मुद्राकाय के सदस्य हैं।

सरकार का बैंकिंग कार्य—नोट निकालने के अनिश्चित रिज़र्व बैंक सरकार ने बैंकर का काम भा करता है। यह सरकार का आर से रुपये का भुगतान करता है और सरकार का रुपया स्वाकार करता है। सरकार की निदेशा देनी की चुमाना पड़ता है। सरकारा रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ता है तथा अन्य बैंकिंग कार्य करने पड़ते हैं। जब सरकार अणु लेता है तो इन अणुओं का रिज़र्व बैंक ही निगमनता है और वहां उनका प्रबंध करता है। केन्द्रीय तथा 'अ' श्रेणी के राज्यों की सरकारों का नकद रुपया बैंक के पास ही बिना दूद के डिपॉजिट के रूप में रहता है। बैंक को यह कार्य मुफ्त में नडा करने पड़ते।

रिज़र्व बैंक का यह भी कार्य है कि वह रुपये का विनिमय-दर (Exchange Rates) को स्थिर रखने। इसी उद्देश्य को लेकर रिज़र्व बैंक को

कानून द्वारा विवश कर दिया गया है कि वह अधिक से अधिक १ शि० ६ $\frac{3}{4}$ पे० प्रति रुपये के हिसाब से स्टर्लिङ्ग खरीदेगा और कम से कम १ शि० ५ $\frac{1}{4}$ पे० प्रति रुपये के हिसाब से स्टर्लिङ्ग बेचेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी के पास स्टर्लिङ्ग हैं और वह उनके रुपये करना चाहना है तो वह रिजर्व बैंक को ऊपर लिखी दर पर स्टर्लिङ्ग बैंक सकता है। रिजर्व बैंक को उसके स्टर्लिङ्ग खरीदने होंगे और यदि किसी व्यक्ति को स्टर्लिङ्ग की आवश्यकता है तो उपर्युक्त दर पर स्टर्लिङ्ग खरीद सकता है। रिजर्व बैंक को उसे स्टर्लिङ्ग बेचने होंगे। इस बारे में एक मर्मांश यह है कि खरीदने और बेचने का सीधा दर हज़ार पाँच से कम का नहीं होना चाहिए। जब भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य हो गया तो अप्रैल १९४७ में इस सम्बन्ध में बैंक के विधान में यह संशोधन कर दिया गया कि रिजर्व बैंक को विदेशी विनिमय बेचना और खरीदना होगा और इस बारे में बेचने तथा खरीदने की दरें तथा और शर्तें मारन-सरकार समय-समय पर तय करेगी।

रिजर्व बैंक की अन्य विशेषतायें :—यह तो हम ऊपर ही कह आये हैं कि रिजर्व बैंक की पहली विशेषता यह है कि वह दो विभागों में विभक्त है (१) नोट विभाग (Issue Department) और दूसरा बैंकिंग विभाग (Banking Department)। इन दोनों विभागों के सम्बन्ध में आगे लिखेंगे। इस विशेषता के अतिरिक्त रिजर्व बैंक की नीचे लिखी विशेषतायें उल्लेखनीय हैं।

(१) कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department)—रिजर्व बैंक ऐक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक को वांछित रूप में एक कृषि साख विभाग स्थापित करना पड़ा है। इस विभाग के नीचे लिखे कार्य हैं:—कृषि साख के सम्बन्ध में खोज करने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर कृषि साख के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए कृषि साख के विशेषज्ञों को नियुक्त करना। जब कभी भारत सरकार, प्रान्तीय सरकारों, प्रान्तीय सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकों को कृषि साख के सम्बन्ध में कुछ परामर्श लेना होता है तो वे रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग, रिजर्व बैंक तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्धों को निर्धारित करता है और रिजर्व बैंक की कृषि साख नीति (Agricultural Credit Policy) को निर्धारित करता है।

(२) रिजर्व बैंक और इम्पीरियल बैंक का सम्बन्ध—रिजर्व बैंक ने इम्पीरियल बैंक को अपना एक माध एजेंट (Sole Agent) बना दिया है। रिजर्व बैंक ऐक्ट में इसका विधान है। जो समझौता हुआ है उसके अनुसार १५

घणों के लिए इम्पीरियल बैंक को एक मास एजेंट बना दिया गया है। जहाँ-जहाँ इम्पीरियल बैंक की ताब है, और रिजर्व बैंक का ताब नहीं है, वहाँ-वहाँ इम्पीरियल बैंक रिजर्व बैंक के एजेंट का काम करना है।

इस सेवा के उपरान्त म रिजर्व बैंक इम्पीरियल बैंक को मार्च १९४५ तक नीचे लिखे अनुसार कमीशन देता था। ५० करोड़ रुपये तक एक प्रतिशत का मोलहवा भाग अर्थात् ५० रुपये पर एक आना और ५५० करोड़ रुपये के उपरान्त ५५० रुपये पर एक प्रतिशत का ब्याजभा भाग कमीशन दिया जाता था अर्थात् ५० रुपये पर दो पैसा। इम्पीरियल बैंक रिजर्व बैंक के एजेंट की हेमियन से जितना सरकार का काम करना है उस पर यह कमीशन दिया जाता है। ३ अप्रैल १९४५ में ३१ मार्च १९४० तक ७ लाख कमीशन का यह नये कायम का गढ़ जितना आधार बैंक को इस काम में हानि नाला गहराकर गये था। ५५ वर्ष का इस अवधि में उपरान्त पांच वर्षों के लिए समझौता हुआ और कां भा पा पांच वर्ष की ग्युना देकर समझौते का मम कर सकना है यह भा ग्युना समझौते में था।

इस अनिश्चित हग समझौते का एक अर्थ यह भी था कि यदि इम्पीरियल बैंक का चिन्ता मात्र रिजर्व बैंक एजेंट के लागू हान पर चुका हुआ था, कम से कम उतनी मात्रा वाले रुपया है ना पहले पांच वर्षों में ६ लाख वार्षिक और तीसरे पांच वर्षों में ४ लाख वार्षिक रुपये रिजर्व बैंक इम्पीरियल बैंक को देगा।

शिख्यूल बैंक की डिवाइड—निज बैंक का मुकता पूँजा (Paid up Capital) और सुरक्षित धन (Reserves) पांच लाख रुपये से अधिक हो वह रिजर्व बैंक एजेंट का दूसरी शिख्यूल में सम्मिलित किया जा सकता है अर्थात् शिख्यूल बैंक बन सकता है। रिजर्व बैंक क्रेडिट (Credit) पर नियन्त्रण स्थापित कर के इस उद्देश्य में प्रत्येक शिख्यूल बैंक को अपना चालू जमा (Current Deposits) का पांच प्रतिशत और मुहता जमा (Fixed Deposits) का २ प्रतिशत रिजर्व बैंक में पास रखना होता है। यदि कोई शिख्यूल बैंक इस शर्त को पूरा न कर तो उसको बंद देना पड़ता है। निर्धारित प्रतिशत से जिस बैंक का रिजर्व बैंक के पास कम कोष रहता है उसको कमी पर प्रचलित रिजर्व बैंक रेट से प्रतिशत अधिक सुद देना पड़ता है। और यदि शिख्यूल बैंक अगला लेगा (Return) भेजने के दिन तक उस जमा को पूरा न कर सके तो बैंक रेट से कमी पर पाँच प्रतिशत अधिक सुद देना होता है। यदि उसने आगे लेता भेजने के दिन तक यह जमा पूरी न हो तो रिजर्व बैंक प्रतिदिन ५०० रु० जुमाना कर सकता है और उस बैंक को और अधिक जनता से डिवाइड लेने की माताह कर सकता है। प्रत्येक शिख्यूल बैंक को प्रति सप्ताह रिजर्व बैंक को एक लेगा (Return)

भेजना पड़ता है जिसमें नीचे लिखी बातों का उल्लेख रहता है। (१) बैंक की चालू जमा (Current Deposit) और मुहूर्ती जमा (Fixed Deposit) (२) बैंक के पास किन्तु मूल्य के नोट हैं। (३) बैंक के पास किन्ते रुपये और छोटे सिक्के हैं। (४) बैंक ने कितना ऋण दिया है और कितने मूल्य के बिल भुनाये हैं। (५) बैंक का कितना रूपया रिजर्व बैंक में जमा है। इस लेख को न भेजने पर प्रतिदिन १०० रु० के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है।

रिजर्व बैंक का लाभ और राजस्व कोष :—रिजर्व बैंक ऐक्ट (१९३४) में इस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि रिजर्व बैंक अपने हिस्सेदारों को अधिक से अधिक ५ प्रतिशत लाभ दे सकता है, किन्तु लाभ कितना बाँटा जायगा इसका निर्णय भारत-सरकार करेगी। आरम्भ में सरकार ने ३½ प्रतिशत लाभ बाँटने की अनुमति दी थी, किन्तु १९४६ से रिजर्व बैंक अपने हिस्सेदारों को ४ प्रतिशत लाभ बाँटता रहा। हिस्सेदारों के बाँटने के उपरान्त जो भी लाभ शेष रहता वह सरकार को दे दिया जाता था। ऐक्ट में यह विधान था कि जब तक रक्षित कोष (Reserve Fund) पूँजी के बराबर न हो जायें तब तक कम से कम ५० लाख रूपया रक्षित कोष में प्रतिवर्ष रखना जावेगा। यदि लाभ इतना न हो तो हिस्सेदारों को बाँटने के उपरान्त जो भी लाभ शेष बचे सब रक्षित कोष में रख दिया जावे। जब रक्षित कोष पूँजी के बराबर हो जायें तो सारा शेष लाभ सरकार को दे दिया जावे। १९६६ के पूर्व ही रिजर्व बैंक का रक्षित कोष पाँच करोड़ रुपये हो गया था अतएव उसके बाद हिस्सेदारों को लाभ बाँटने के उपरान्त शेष लाभ सरकार को चला जाता था। १ जनवरी, १९४६ में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने से बैंक का सारा लाभ सरकार को ही मिलता है क्योंकि अब बैंक के सब हिस्से सरकार के पास आ गये हैं।

रिजर्व बैंक संशोधन ऐक्ट १९५१—नवंबर १९५० में रिजर्व बैंक ऐक्ट का संशोधन करने के लिये भारतीय संसद में एक बिल पेश हुआ था, वह २७ अप्रैल, १९५१ को संसद में पास हो गया है। इस संशोधन के फल स्वरूप रिजर्व बैंक के कामों के बारे में नीचे लिखे परिवर्तन होंगे:—

(१) कृषि संबंधी बिल या ग्रामिणरी नोट जो बैंक बेच, खरीद और भुना सकता है उनकी अपधि ६ महीने से बढ़ाकर १५ महीने कर दी गई है—अर्थात् जिन बिलों की मियाद १५ महीने के अन्दर-अन्दर समाप्त होती है उन्हें रिजर्व बैंक खरीद, बेच और भुना सकेगा।

(२) सरकारी बैंकिंग कारोबार के संबंध में यह साफ कर दिया गया है कि 'बी' श्रेणी के राज्यों का रिजर्व बैंक उस तरह से काम नहीं करेगा जैसे 'अ' २७

है, केन्द्रीय बैंक (Central Bank) को बैंकों की जमा या डिपॉजिट पर भी नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता।

भारत में क्रय-शक्ति (Purchasing Power) के तीन मुख्य रूप हैं। रुपये का सिक्का, कागजी मुद्रा अर्थात् करंसी नोट तथा बैंकों का जमा वा बैंक डिपॉजिट। इनमें रुपये का सिक्का अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, उसका व्यवहार अपेक्षाकृत कम ही है, अतएव धुम्रतान करने के मुख्य साधन वा तो करंसी नोट हैं वा वे बैंक डिपॉजिट (जमा) हैं जिन पर चेक काटे जा सकते हैं। इनमें भी चेकों का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। यद्यपि आज यह कहना कठिन है कि भारत में करंसी नोटों के चलने से चेकों का चलन अधिक है, फिर भी इनमें कोई संदेह नहीं कि चेकों का महत्व काफ़ी है और शीघ्र ही यह तमय आने भाला है जबकि भारत में भी चेकों का चलन करंसी नोटों से बहुत अधिक बढ़ जायेगा।

यही कारण है कि रिज़र्व बैंक को करंसी पर पूरा नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया है, अर्थात् रिज़र्व बैंक को कागजां मुद्रा अर्थात् करंसी नोट निकालने का अधिकार प्राप्त है। रिज़र्व बैंक की स्थापना के पूर्व करंसी नोट निकालने का कार्य तो सरकार करती थी और कुछ सीमा तक साख (C. dit) का नियंत्रण इम्पारिअल बैंक के हाथ में था। भारतीय द्रव्य बाजार की यही दुर्बलता थी जो कि रिज़र्व बैंक की स्थापना के उपरान्त दूर हो गई। रिज़र्व बैंक को कानून द्वारा शिष्टू बैंकों के बैलेंस को रखने का अधिकार दे दिया गया। इनके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक के पास सरकारी कोष (Funds) भी रहना है तथा उसको सरकार का बैंकर होने का भी गौरव प्राप्त है। इन सुविधाओं से रिज़र्व बैंक को साख (Credit) पर नियंत्रण स्थापित करने में बहुत सुविधा होती है। इन अधिकारों और सुविधाओं के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ऐक्ट में रिज़र्व बैंक की आवश्यकता पड़ने पर नीचे जमना से व्यवहार करने की प्राज्ञा दे दी गई है। ऐक्ट की धारा १८ के अनुसार यदि भारत के व्यापार-व्यवसाय और इन्फ़ि के विभाग में यह आवश्यक प्रतीत हो, तो रिज़र्व बैंक सभी बिलों को ज़ना सकता है और धन दे सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि रिज़र्व बैंक बिना शिष्टू बैंक वा प्रांतीय सरकारी बैंक की वलाली या मध्यस्थता के खुले बाजार (Open Market) का कारबार कर सकता है। यह अधिकार रिज़र्व बैंक साधारणतः काम में नहीं लायेगा। यह असाधारण अवसरों पर ही काम में लाया जा सकता है।

रिज़र्व बैंक और साख का नियंत्रण—रिज़र्व बैंक साख (Credit) का नियंत्रण करने में कहीं तक सफल हुआ है इसके नियंत्रण में एक कठिनाई यह

हे कि यद्यपि रिज़र्व बैंक की स्थापना हुए इतने वर्ष हो गए किन्तु अभी तक उसकी सारा नियन्त्रण शक्ति का परीक्षा होने का कभी अवसर नहीं आया। क्योंकि जब से रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई है तब से अभी तक द्रव्य-बाज़ार में द्रव्य (Money) का टोटा नष्टा पड़ा, द्रव्य की वृद्धिमान हो रहा अथवा द्रव्य बाज़ार की रिज़र्व बैंक का सहायता का कोई आवश्यकता नहीं पड़ा। अतएव हम जल मैदानिक रूप में ही इस बात का निवेचना कर सकते हैं कि रिज़र्व बैंक माफ़ (Credit) का नियन्त्रण करने में वहाँ तक सफल हुआ।

भारतीय द्रव्य बाज़ार का कुछ विशेषतायें ऐसी हैं जो कि अन्य देशों में नहीं पाई जाया और उनसे यह स्पष्ट होने लगता है कि क्या रिज़र्व बैंक वास्तव में सारा नियन्त्रण करने में सफल होगा। पहली विशेषता यह है कि इन्फ़्लेशन बल का भारतीय द्रव्य बाज़ार में अत्यधिक प्रभाव है, किन्तु ऐसा हम अभी देखेंगे इन्फ़्लेशन बल का इस अर्थव्यवस्था में प्रभाव है। रिज़र्व बैंक का प्रभाव कम नहीं होता। इन्फ़्लेशन बल की भारतीय द्रव्य बाज़ार (Indian Money Market) में विविध परिस्थिति का कारण उत्पन्न नियन्त्रण का यहाँ एक नई पद्धति का आनिर्भाव हुआ जो रिज़र्व बैंक और द्रव्य बाज़ार के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

भारतीय द्रव्य बाज़ार का दूसरा विशेषता है कि यहाँ रिनिमय बैंकों (एससेच बैंकों) का एक ऐसा प्रभावशाली समूह है कि जो यदि चाहता रिज़र्व बैंक का सारा माफ़ (Credit Policy) को प्रसफल कर सकता है, क्योंकि उनका लक्ष्य-द्रव्य बाज़ार में सीधा पड़ता है। किन्तु अब पैसा राजनैतिक स्थिति है एससेच बैंकों का यह साहस नहीं हो सकता है कि यदि रिज़र्व बैंक की भारतीय बैंकों का दृष्टि में विचारित नानि का विरुद्ध कार्य करे, क्योंकि ऐसा करने से उनके विरुद्ध सरकार को कार्यवाही करना पड़ सकता है। प्रत्युत, एससेच बैंक तथा रिज़र्व बैंक में समर्पण होने का सम्भावना नहीं है। वो भी रिज़र्व बैंक तथा एससेच बैंकों का समर्पण तभी हो सकता है कि जब रिज़र्व बैंक सारा को कम करने का प्रयत्न करें, किन्तु भारत का स्थिति यह है कि वहाँ सारा का विस्तार करने का ही अधिक आवश्यकता है।

कुछ निदानों या यह मत है कि भारत जैसे देश में जहाँ कि द्रव्य-बाज़ार असंगठित है, रिज़र्व बैंक का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। किन्तु भारत में तथा अन्य देशों में जहाँ कि द्रव्य-बाज़ार संगठित नहीं है, वहाँ के अनुभव ने हम यह बताना दिया है कि ऐसा कोई सम्भावना नहीं है। अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के केन्द्रीय बैंकों (Central Banks) का द्रव्य-बाज़ार पर पूरा प्रभाव पड़ता है।

भारतीय द्रव्य-बाजार पर रिजर्व बैंक का प्रभाव इसी से शत होता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व बाजार में जो मौसमी द्रव्य की कमी पड़ती थी और बैंक की सूद की दर बहुत अधिक घटती-बढ़ती थी वह रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद दूर हो गई और वर्ष भर बैंक रेट एक समान रहनी है। यही नहीं कि रिजर्व बैंक की स्थापना के उपरान्त बैंक-रेट कम हो गई, साथ ही उसमें घटा-बढ़ी भी बहुत कम हो गई।

सूद की भिन्न दरों में भी कमी ही नहीं आई वरन् उनका आपसी अन्तर भी कम हो गया। इसका सम्भवतः एक कारण रिजर्व बैंक की स्थापना है। रिजर्व बैंक की स्थापना से भारत में बैंकों की प्रोत्साहन मिला है, बैंकिंग पद्धति में सुधार हुआ है और रिजर्व बैंक के नियंत्रण और नेतृत्व के फल स्वरूप बैंकिंग को इस देश में उन्नति हुई है। सर्व-साधारण का शिद्दुल बैंकों पर अधिक विश्वास बढ़ा है और उनके कारण देश में चेक का अधिक प्रचलन हुआ है। रिजर्व बैंक सरकारी हुटियों (Treasury Bills) के बाजार का विस्तार करने का प्रयत्न कर रहा है। यदि वह इसमें सफल हुआ तो रिजर्व बैंक का व्यापारिक बैंकों पर अधिकाधिक नियंत्रण स्थापित हो जावेगा।

रिजर्व बैंक और इम्पीरियल बैंक—यह कहा जा सकता है कि इम्पीरियल बैंक का भारतीय द्रव्य-बाजार में इतना अधिक प्रभाव होने से रिजर्व बैंक की प्रतिष्ठा को आपात पहुँच सकता है और उसके सफलतापूर्वक कार्य करने में बाधा उपस्थित हो सकता है। यदि इन दोनों महान् प्रभावशाली संस्थाओं के परस्पर सम्बन्ध अच्छे न होते तब ऐसी सम्भावना हो सकती थी, किन्तु भाग्यवश ऐसी कोई भी सम्भावना नहीं है। दो बैंकों के आपसी सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं और दोनों ही अपने कर्तव्यों और कार्यों को भले प्रकार समझते हैं। यदि रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर साख (Credit) का निर्माण करता है तो इम्पीरियल बैंक उसका थोक व्यापारी (Wholesale Dealer) बनकर उसे व्यापारिक बैंकों को देनता है और व्यापारिक बैंक उसे जनता के हाथ बेचते हैं। यद्यपि शिद्दुल बैंक रिजर्व बैंक से सीधे ऋण ले सकते हैं, किन्तु दो कारणों से वे इम्पीरियल बैंक के पास आर्थिक सहायता के लिये जाना अधिक पसन्द करते हैं। पहला कारण तो यह है कि इम्पीरियल बैंक तथा व्यापारिक बैंकों का बहुत पुराना सम्बन्ध स्थापित है, दूसरे रिजर्व बैंक से ऋण तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करने में इम्पीरियल बैंक की अपेक्षा कठिनाइयाँ अधिक हैं। इम्पीरियल बैंक ऋण अथवा आर्थिक सहायता देने में कानूनी कन्धनों से इतना अधिक जकड़ा नहीं है जितना कि रिजर्व बैंक। यदि इम्पीरियल बैंक को, किसी व्यापारिक बैंक

की आधिकारिक स्थिति गन्ध है ऐसा दिवासा हो जाना, तो वह अक्षर दो में अधिक उदार हो सकता है।

रिजर्व बैंक और बाजार मार्केट—जब तक हमने रिजर्व बैंक का सेंट्रल-ब्रान्च बाजार पर किस प्रकार नियंत्रण हो सकता है इसका उल्लेख किया। जहाँ न बाजार-मार्केट का अर्थ है वह स्थान है जहाँ रिजर्व बैंक का उस पर बहुत प्रभाव प्रभाव पड़ सकता है। जब तक कि देशी बैंक तथा साहसिक अपना व्यापार प्रवृत्ति की नहीं बदलत तब तक रिजर्व बैंक उनकी कोश सहायता नहीं कर सकता और न रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में ही जा सकते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि बाजार मार्केट बैंक के पास बाजार-मार्केट का तात्पर्य प्रभाव करके न प्रभाव नहीं है ना वह उस पर कितना प्रभाव नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि देशी बैंकों को जो रिजर्व बैंक मार्केट में कार्यवाही करते हैं पारस्परिकता में प्रभाव हाकर इमारतों बैंक तथा व्यापारों बैंक के अक्षर या आधिकारिकता सेना पड़ता है। प्रत्यक्ष बिक्री को इन बिक्री में अन्तर्गत है और स्वातंत्र्य सम्बन्धितता का जमाना पर अक्षर सेते हैं। जहाँ तक उच्च अर्थ बाजार का परिणामात्मक से विचार होकर सगतिष्ठ ब्रान्च बाजार में उदाहरण के लिए आना पड़ता है प्रत्यक्ष बैंक के प्रत्यक्ष प्रभाव में आता है। इसका आंतरिक पिछले दिनों में सम्पादित हुआ रेट और बाजार रेट में जो समानता दृष्टिगोचर होता है वह इस बात को बतलाना है कि दोनों बाजारों में सम्बन्ध पड़ रहा है। अन्तर्गत प्रणाली यह हा रहा है कि रिजर्व बैंक का प्रभाव घटता जा रहा है।

सबसे अधिक प्रभाव का उदाहरण — केंद्र बैंक (Central Bank) का (Credit) का नियंत्रण करने के लिए दा उपाय काम में आता है। एक तो ब्याज दर (Discount rate) का घटा-बढ़ा कर केंद्र बैंक का नियन्त्रण करता है, दूसरे खले बाजार में खनहर (Open Market Operations) करना। इसका रिजर्व बैंक के सम्बन्ध में इन दोनों उपायों का उल्लेख करेंगे।

● **ब्याज दर (Discount Rate)**—ब्याज दर प्रभावशाली है प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अन्तर्गत स्तर (Level) से ही बढ़ा जाना जा सकता बल्कि इसका निर्णय करने में हम यह भावना चाहिये कि रिजर्व बैंक का दृष्टि में कौन से व्यापारिक पत्र (Commercial Paper) बनने तथा अक्षर के आधार स्वस्थ स्वीकार किया जाना — योच है और उन व्यापारिक पत्र (Commercial Papers) का ब्रान्च-बाजार में क्या महत्त्व है।

जहाँ तक कि ब्याज दर [(Discount Rate)] का प्रश्न है, रिजर्व बैंक

की वृद्धि दर—जब से वह स्थापित हुआ है—तब प्रतिशत रही है, इस कारण यह कह सकता है कि रिज़र्व बैंक की वृद्धि दर कहीं तक प्रभावशाली है।

जहाँ तक रिज़र्व बैंक को कुछ व्यापारिक पत्रों (Commercial Papers) को भुनाने और उनके आधार पर ऋण देने का अधिकार प्राप्त है उसका हम दो दृष्टियों से अभ्यस्य कर सकते हैं। पहला तो यह कि रिज़र्व बैंक इस अधिकार का उपयोग साख का नियंत्रण करने के लिए कर सकता है। दूसरे यह कि रिज़र्व बैंक व्यापारिक बैंकों की आड़े समय में केवल उन्हीं व्यापारिक पत्रों (अर्थात् विलों और सिक्कूरिटियों) को स्वीकार करके आर्थिक सहायता कर सकता है। व्यापारिक बैंकों को आड़े समय में आर्थिक सहायता करने के सम्बन्ध में रिज़र्व बैंक ने अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया है। यह इस प्रकार है :—

यद्यपि रिज़र्व बैंक-डिप्ट के अनुसार रिज़र्व बैंक कुछ सिक्कूरिटियों (जिनके सम्बन्ध में पहले कहा आये है) के विरुद्ध व्यापारिक बैंक को साख देकर उनकी सहायता कर सकता है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह किसी भी बैंक को, जो स्वीकार योग्य व्यापारिक पत्र तथा सिक्कूरिटरी दे सके उसे ऋण देने या आर्थिक सहायता करने पर विवश है। रिज़र्व बैंक किसी भी बैंक को आर्थिक सहायता देते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि उस बैंक ने अपना अपना ठीक जगह लगाया है अथवा नहीं, अथवा वह आवश्यकता में अधिक सूद देकर नो डिपॉजिट आकर्षित नहीं करता है? क्या वह, जब बाजार में सफेद फण्ड (Funds) होता है तब भी रिज़र्व बैंक ने सहायता वाहना है और क्या वह सट्टे (Speculation) के लिए साख देना रहा है? कहने का तात्पर्य यह है कि रिज़र्व बैंक किसी बैंक की आर्थिक सहायता, स्वीकार योग्य विल या सिक्कूरिटरी लेकर, तभी करेगा जब उसे विश्वास होगा कि सहायता माँगने वाले बैंक ने बैंकिंग के भिदान्तों की अवहेलना नहीं की है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है।

खुले बाजार व्यवहार (Open Market Operations)—वृद्धि दर को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक को खुले बाजार के व्यवहार करने का भी अधिकार दे दिया गया है। संक्षेप में खुले बाजार के व्यवहारों से अर्थ यह है कि रिज़र्व बैंक सरकारों, सिक्कूरिटियों को खरीद और बेच कर व्यापारिक बैंक के नकद कोष (Cash Balances) में वृद्धि या कमी करता है और इस प्रकार वह व्यापारिक बैंकों को अग्रत्यक्त रूप से साख का अधिक निर्माण करने या साख को कम करने पर विवश करता है। रिज़र्व बैंक

करेंगे। केन्द्रीय बोर्ड का संगठन इस प्रकार का होगा :—

(घ) एक गवर्नर तथा दो डिप्टी गवर्नर केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेंगे।

(ङ) चार डाइरेक्टर चारों स्थानीय बोर्डों में से केन्द्रीय सरकार मनोनीत करेंगे।

(च) ६ डाइरेक्टर केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जायेंगे।

(ग) एक सरकारी कर्मचारी सरकार मनोनीत करेंगे।

स्थानीय बोर्डों में प्रत्येक में पाँच डाइरेक्टरों की नियुक्ति पाँच साल की अवधि और चार साल के लिये ही होगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेंगी। स्थानीय बोर्ड चार होंगे।

केन्द्रीय सरकार बैंक के गवर्नर का सलाह से बैंक का उचित परामर्श देगा जो कि बैंक के दिन में हो।

देश की बैंकिंग व्यवस्था को रिजर्व बैंक में सहायता—प्रायः कई नहीं जानने वाले लोग यह आपत्ति उठाने हैं कि रिजर्व बैंक की नीति बूखे बैंकों के बारे में सहायभूति की नहीं रहती है। जब शिङ्गूल बैंक वा कोपरेटिव बैंकों को आवश्यकता होती है या वे किसी कठिनाई में होते हैं तो बैंक उनकी पूर्ण सहायता नहीं करता। पर वास्तव में बैंक पर इस प्रकार का दोग लगाना ठीक नहीं है। पिछले दस वर्षों में रिजर्व बैंक ने शिङ्गूल बैंकों को बचने से बचाने के लिये जो भी प्रयत्न वह कर सकता था कराकर दिया है। बैंक शिङ्गूल बैंकों वा कोपरेटिव बैंकों को दृढ़ी सिक्यूरिटियों के आधार पर ऋण दे सकता है। और जब जब ऐसा अवसर आया है बैंक ने बराबर सहायता की है। १९४८ में २१.२५ करोड़ और १९४९ में १४.७५ करोड़ रुपये इस प्रकार रिजर्व बैंक ने शिङ्गूल बैंकों को एडवांस के रूप में दिये। कोपरेटिव बैंकों को १९४८ में १.२२ करोड़ और १९४९ में ६.१६ करोड़ रुपये दृढ़ी सिक्यूरिटियों के आधार पर एडवांस किया गया था। १९३७ से १९४७ तक केवल १९४६ को छोड़कर बाकी के वर्षों में बैंक ने शिङ्गूल बैंकों और कोपरेटिव बैंकों ने बहुत कम सहायता ली क्योंकि रुपये की बाजार में कोई तंगी नहीं थी। उपर्युक्त १० वर्षों में कुल ४२.४८ करोड़ रुपये रिजर्व बैंक ने सहायता के रूप में दिये जिसमें २५.०२ करोड़ केवल १९४६ में ही दिये गये थे। पर १९४८ और १९४९ में रुपये की तंगी होने से बैंक ने काफी सहायता की। बैंक से अधिकांश सहायता थोड़े समय के लिये ही ली गई है। ऐसी सहायता जो रुपये की भारी मांग को पूरा करने के लिए ली गई है बहुत थोड़ी रही है। आपत्ति के समय या कृषि सहायता के लिए दिये गए रुपयों पर रिजर्व बैंक व्याज भी २% से

सुले बाजार में किस प्रकार का सिन्चुरिटिटा (प्रतिभूति) का सराद बित्री कर सकता है उनका फण्ट में उल्लेख कर दिया गया है।

अ ॥ उपाय—ऊपर लगे दो मुख्य उपायों के अनिश्चित रिजर्व बैंक का जल्ता से साधा नगरवार रज्जन का भा प्रधिकार है। सिन्चुरिटिटा अधिकार का रिजर्व बैंक विनाश अवस्था में ही नाम में ला सकता है। उनका साधन अपन विनों को रिजर्व बैंक में जना करना और स्वतन्त्र बाजार सिन्चुरिटिटा पर अधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। इस आधेसार के फल स्वतन्त्र रिजर्व बैंक का व्यापारिक बैंक पर बहुत प्रविष्ट प्रभाव स्थापन हो गया है। यदि व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के द्वारा निगमन मानन के नगरद आचरण करत है तो रिजर्व बैंक उस प्रविष्टार का उपयोग कर सकता है। प्रणय व्यापारिक बैंक का रिजर्व बैंक का नाम के नगरद आचरण करने का रभा गाइउ हो मला हो सकता।

प्रत्येक उपाय में साक्ष का राशनिम करना तथा सक्षय बैंकों का सिन्चुरिटिटा बैंकों के विरुद्ध साधा नगरबाहो करन का इस न्याय में अधिक महत्त्व नहीं है, क्योंकि व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से अधिक न्याय नहीं लत। रिजर्व (Publicity) का सुकुल राज्य नगरािका में सात का निगमन करन में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है, सिन्चुरिटिटा में इसका अधिक उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से अधिक न्याय नहीं लते। हाँ, रिजर्व बैंक का नैतिक प्रभाव सक्षय कारगर हो सकता है। जेस-जेम रिजर्व बैंक भारत के व्यापारिक बैंकों के अधिक न्याय में आना जानगा वह अपना नैतिक प्रभाव उनके कारबार पर डालन में सफल होगा और व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक को सात सम्भव नाति को स्वतन्त्र न्याय कर लगे।

रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण—कुछ समय में भारतभय में यह विवाद चल रहा था कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए अथवा नहीं। अन्त में सरकार ने रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का निश्चय स्वीकार कर लिया और ३ सितम्बर १९४८ को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण सम्प्रभा बिल पाउ होने पर यह विवाद समाप्त हो गया।

१ जनवरी १९४९ से रिजर्व बैंक का नवान अवस्था हो गई। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के बारे में हिस्से १९८८ न्याय २० आना प्रति हिस्से के हिताव से सराद लिए और इस प्रकार रिजर्व बैंक भारत सरकार का बैंक हो गया। हिस्से के एधन में भारत सरकार ने कुछ तो नगरद दिया और कुछ ३ प्रतिशत न्याय के प्रोमिटरा नोट दिये गये।

बैंक का न्याय और प्रवच पहले की ही मॉति केन्द्राय तथा स्थानाय के

रुपया जमा करते हैं।

पोस्ट आफिस सेविंग्स-बैंक में अधिक से अधिक पाँच हजार रुपये जमा किये जा सकते हैं। पहले यह नियम था कि एक वर्ष में कोई ७५० रु० ने अधिक जमा नहीं कर सकता था किन्तु अब यह बंधन हटा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति ५ हजार रुपये तक एक बार में जमा कर सकता है। कम से कम दो रुपये जमा किये जा सकते हैं। सेविंग्स बैंक में अब दो सौ रुपये से कम पर १॥ प्रतिशत और २०० रुपये से ऊपर २ प्रतिशत सूद दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति रुपया जमा कर सकता है। रुपया एक सप्ताह में केवल एक बार निकाला जा सकता है।

भारतवर्ष में पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक की स्थापना १८८२ में हुई। तब से उसमें जमा करने वालों की संख्या तथा जमा किया हुआ रुपया बराबर बढ़ता ही गया। पहले महायुद्ध के आरम्भ होने पर (१९१४-१५) अवश्य लोगों में धराहट फैल गई और लोगों ने करोड़ों रुपया निकाल लिया, परन्तु शीघ्र ही लोगों में विश्वास फिर लौट आया और डिपॉजिट बढ़ने लगी। १९३०-३१ में आर्थिक मंदी के कारण जितना रुपया जमा हुआ उससे अधिक रुपया निकाला गया किन्तु फिर डिपॉजिट की वृद्धि होने लगी। ११ मार्च १९३८ में ३७.६ करोड़ जमा करने वाले थे और ७७.५ करोड़ रुपये की डिपॉजिट थी। जब दूसरा महायुद्ध आरंभ हुआ और फ्रांस का पतन हो गया तो जनता में फिर धराहट फैली और लोगों ने अपना रुपया निकालना आरम्भ कर दिया, किन्तु शीघ्र ही लोगों में विश्वास लौट आया और डिपॉजिटों में वृद्धि होने लगी।

पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक से सुधार—केन्द्रीय बैंकिंग जॉन कनेट्री की सम्मति थी कि अधिकतम जमा करने की सीमा पाँच हजार में बढ़ा कर दस हजार रुपये कर देनी चाहिये। कुछ चुने हुए पोस्ट आफिसों में सेविंग्स बैंक हिसाब से चेक द्वारा रुपया निकालने की सुविधा प्रदान करना चाहिए और कमरा: अधिकाधिक पोस्ट आफिसों में इस प्रकार की सुविधा दे देना चाहिए। इसके अतिरिक्त सेविंग्स बैंक हिसाब को संयुक्त नामों में खोले जाने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। रुपया जमा करने वालों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने उत्तराधिकारियों को मनोनीत कर दें कि जो उनकी मृत्यु के उपरान्त उसका मालिक हो। इससे यह संकट नहीं रहेगा कि रुपया जमा करने वाले का उत्तराधिकारी अपने अधिकार को प्रमाणित करे। ऊपर लिखे सुधारों की आवश्यकता तो केन्द्रीय बैंकिंग जॉन कनेट्री ने भी बतलाई किन्तु हम वहाँ नीचे अन्य सुधारों की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक समझते हैं—

बम लेता है। २०% और कोपरेटिव बैंक को १३½% मूद पर भी रिजर्व बैंक द्वारा एडवांस करता है।

इस अलावा रिजर्व बैंक ने ग्राम होमर फण्ड में भा १९४३ में यह संघी बन करवा दिया है कि जिसा सेंट रा म्युनिम बैंक को इस बान का पूरी आज़ाता है कि वह जो किस प्रकार का गिन्तुटिटा न आधार पर रुपया एडवांस करे या इस ट्रस्ट गिन्तुटिटा का उशन उस पर ऐसे व्यवसरो पर लागू न करे। एम्बचर उस ग्राम डिवा ग्राम ग्रमिना नि० का वर है इसी आधार पर गलियना का पर उस धन प्रवन म नया नवाका का मका।

1. ख। रें० १। म० उता २। ३। गुशाइश—बठाने का एक उपाय यह है कि जिस न गानाभा की कम गहन व्यवस्था का ताकि उनमें माल जमा कराकर उनकी रमा न आधार पर रिजर्व बैंक म रुपया एडवांस कराया जा सके, जो कि कानून म समन है। स्वाकि रिजर्व रा गिन्तुल वसों को उतर डिमाट्रोमिडरी नोट न आधार पर कम दशा म एम्बाउ इ मरना है पर एगे प्रोमिगरी नोटों के साथ 'डोन्मट ग्रोन टाइटल व गृहक' का। बादास की रमाद इस प्रकार का डाकमट का नाम व मरना है। अस्त राँग रमटा ने भा यह सिफारिश की है कि फन्डीन सरकार, राज्य की सरकार और गिन्तु बैंक मिलकर 'वेयर हाउस डेपेन्समट बाउ' बनायें जो गोम वनाने के लिये धन आदि को महायता दे।

उपरुक्त प्रिणसिपल म यह स्पष्ट है कि गिन्तु बैंक ने देश की धनिक व्यवस्था का अपना शक्ति भर महायता की है। आगे भा यह प्रता ही करेगा, इसमें कोई शका नदा है।

६ पोस्टग्रामफिस, ग्राम का नीतय फंड (Loan Offices) निधि, तथा पिट पड पोस्टग्रामफिस मेमिंस बैंक—पोस्टग्रामफिस भा भारत में सेविंग बैंक का सम्बार करते हैं और इस प्रकार वे भा प्रव्य बाज़ार म एक अंग हैं। पोस्टग्रामफिस निमिनिलिखित बरिग काय करन हैं। वे मेमिंस बैंक का काम करते हैं, रैम सविपि हट वेंचते हैं, नेशनल सेविंग मार्टिफिरेट देते हैं, सरकारी गिन्तुटिडियों की सराफा आ विका करते हैं तथा जावन वामा करते हैं।

शमी डेड पोस्टग्रामफिसो म, सब पोस्टग्रामफिसो में तथा बहुत से प्राच पोस्टग्रामफिसो म सेविंग बैंक का काम होगा है। इनका मुख्य उद्देश्य किसानों, मजदूरों तथा मध्यम श्रेणी के लोगों म गिनलियता की भावना जाग्रत करना है। किन्तु पोस्टग्रामफिस सेविंग बैंकों में अधिकांश मध्यम श्रेणी के ही व्यक्ति अपनी बचत जमा करते हैं। इनमें अधिकतर सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी, उकील, डाक्टर, अप्पापठ तथा अन्य पेशे वाले लोग ही अपना

रुपया जमा करते हैं।

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में अधिक से अधिक पांच हजार रुपये जमा किये जा सकते हैं। पहले यह नियम था कि एक वर्ष में कोई ७५० रु० से अधिक जमा नहीं कर सकता था किन्तु अब यह वंघन हटा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति ५ हजार रुपये तक एक बार में जमा कर सकता है। कम से कम दो रुपये जमा किये जा सकते हैं। सेविंग्स बैंक में अब दो सौ रुपये से कम पर १॥ प्रतिशत और २०० रुपये से ऊपर २ प्रतिशत रूढ़ दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति रुपया जमा कर सकता है। रुपया एक सप्ताह में केवल एक बार निकाला जा सकता है।

भारतवर्ष में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक की स्थापना १८८२ में हुई। तब से उसमें जमा करने वालों की संख्या तथा जमा किया हुआ रुपया बराबर बढ़ता ही गया। पहले महायुद्ध के आरम्भ होने पर (१९१४-१५) अवश्य लोगों में घबराहट फैल गई और लोगों ने करोड़ों रुपया निकाल लिया, परन्तु शीघ्र ही लोगों में विश्वास फिर लौट आया और डिपॉजिट बढ़ने लगी। १९३०-३१ में आर्थिक मंदी के कारण जितना रुपया जमा हुआ उससे अधिक रुपया निकाला गया किन्तु फिर डिपॉजिट की वृद्धि होने लगी। ११ मार्च १९३८ में ३७.६ करोड़ जमा करने वाले थे और ७७.५ करोड़ रुपये की डिपॉजिट थी। जब दूसरा महायुद्ध आरंभ हुआ और फ्रांस का पतन हो गया तो जनता में फिर घबराहट फैली और लोगों ने अपना रुपया निकालना आरम्भ कर दिया, किन्तु शीघ्र ही लोगों में विश्वास लौट आया और डिपॉजिटों में वृद्धि होने लगी।

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में सुधार—केन्द्रीय बैंकिंग जॉन कमेटी का समानि थी कि अधिकतम जमा करने की सीमा पाँच हजार से बढ़ा कर दस हजार रुपये कर देनी चाहिये। कुछ जुने हुए पोस्ट ऑफिसों में सेविंग्स बैंक हिसाब में चेक द्वारा रुपया निकालने की सुविधा प्रदान करना चाहिए और कमशः अधिकाधिक पोस्ट ऑफिसों में इस प्रकार की सुविधा दे देना चाहिए। इसके अतिरिक्त सेविंग्स बैंक हिसाब को संयुक्त नामों में खोले जाने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। रुपया जमा करने वालों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने उत्तराधिकारी को मनोनीत कर दें कि जो उनकी मृत्यु के उपरान्त उसका मालिक हो। इससे यह भ्रम नहीं रहेगा कि रुपया जमा करने वाले का उत्तराधिकारी अपने अधिकार को प्रमाणित करे। ऊपर लिखे सुधारों की आवश्यकता तो केन्द्रीय बैंकिंग जॉच कमेटी ने भी बतलाई किन्तु हम यहाँ नीचे अन्य सुधारों की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक समझते हैं—

(१) उा पोस्ट आफिस का सम्बन्ध बढ़ा जाना चाहिए कि जहाँ सेविंग बैंक दिनांक मोला जा सक। यदि इस प्रकार के पोस्टऑफिस को प्रोत्साहित न किया जाता तो हमारा देश न हो तो जहाँ से सेवा समाप्त हो जाये वहाँ से सेवा समाप्त हो जाये।

(२) सूचक न प्रवृत्तियों का न न पोस्ट ऑफिस के चलायन के लिए उपयोग किया जाय।

(३) समाप्त न हो सकने वाली सेवा समाप्त करना चाहिए जो निम्नलिखित कारणों से समाप्त होनी चाहिए।

(४) १९१५ ई. में प्रथम जमा करा जाल की दृष्टानुसार प्रत्येक मास में जमा होना चाहिए।

(५) आर्थिक स्थिति में—जहाँ सेविंग बैंक हो रहा है—उच्च पोस्टऑफिस सेविंग बैंक एस. एस. एस. बैंक का नाम सेविंग बैंक का नाम सेविंग बैंक हो रहा है और सेविंग बैंक का नाम सेविंग बैंक हो रहा है।

यदि हम इस प्रकार पोस्ट ऑफिस को चलायन कर में आसानी से सुधार हो जाये तो ये समाप्त होना में निम्नलिखित कारणों से समाप्त हो जाये हैं और उनका अधिकाधिक उपयोग हो सकता है। अर्थात् हमारा काम-बढ़ाने में कुछ धन होय है कि जिससे कारण हमका अधिक उपयोग हो जाय।

पोस्ट ऑफिस बैंक नोट फंड तथा नेशनल सविंग सर्टिफिकेट — प्रथम महायुद्ध (१९१४-१५) में पोस्टऑफिस बैंक नोट फंड निम्नलिखित कारणों से समाप्त हो गया है। इन नोट फंडों को निम्नलिखित कारणों से समाप्त हो गया है कि जनता में स्थायी बचत का प्रवृत्ति बढ़े। इस नोट फंड में प्रविष्टि करने वाले धन के परावर लागू तथा सरकारों और प्रद. सरकारों के माध्यम से बचत की जाती है। कारण यह है कि इनमें गुरु प्रवृत्ति मिलता है और निम्नलिखित बिन्दुओं नहीं है। मध्यम भंडार न लागू प्रविष्टि करने वाले पोस्टऑफिस बैंक सर्टिफिकेटों तथा नव प्रचलित नेशनल सविंग सर्टिफिकेटों में है अर्थात् स्थायी लागू है। यह सर्टिफिकेट पांच वर्षों के लिए है और कां. वार्षिक १०,००० रुपये से अधिक के सर्टिफिकेट नहीं रख सकता। वरन् सर्टिफिकेट १०,००० से लेकर १ हजार रुपये तक के होते हैं। जब पाँच वर्षों के उपरान्त सर्टिफिकेट की अवधि समाप्त हो जाता है तो उसका जो मूल्य मिलता है उसमें और उस सर्टिफिकेट के परावरने में जो मूल्य देना पड़ता है उसका अन्तर हो रहा होता है। इस पर प्रायः कहा जाता है कि १९३६ के पूर्व समय के लिए सर्टिफिकेटों की कीमत में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता रहा है कि यह कां. कर भटती गई। आरम्भ में ६ प्रतिशत

सूद मिलता था किन्तु १९३६ से सूद की दर २½ प्रतिशत चक्र ध्याज की दर से रह गई है। यह सर्टिफिकेट समय पूरा होने से पहले भी भुनाए जा सकते हैं, किन्तु खरीदने के एक वर्ष के अन्दर भुनाने पर कोई सूद नहीं मिलता। दूसरे वर्ष से सूद की दर बढ़ती जाती है किन्तु पूरा सूद सभी मिलना है जब कि पाँच वर्ष समाप्त हो जावें।

सर्टिफिकेटों का आकर्षण सूद की दर के अनुसार कम होता या बढ़ता रहा है। दूसरे महायुद्ध के पूर्व कैश सर्टिफिकेटों का मध्यम श्रेणी की जनता को बहुत आकर्षण था, क्योंकि सूद अच्छा मिलता था और उन पर आयकर (Income-Tax) नहीं लिया जाता था। ३१ मार्च १९३६ को कैश सर्टिफिकेटों का मूल्य ६० करोड़ रुपये था। ३१ मार्च १९४३ को केवल ३५ करोड़ रुपये के कैश सर्टिफिकेट रह गए। इसका कारण यह था कि बहुत से लोग युद्ध के कारण भयभीत हो गए कि कहीं रुपया डूब न जावे। फेडरल बैंकिंग जॉब कमेटी ने कैश सर्टिफिकेटों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इस बात की सिफारिश की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो कि सर्टिफिकेट खरीदे इस बात का अधिकार दिया जावे कि वह अपने मरने पर वह रुपया किसको मिले उसका नाम घोषित कर दे।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट—नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट द्वितीय महायुद्ध के समय निकाले गए थे। यह बारह वर्षों के लिए होते हैं। सर्टिफिकेट खरीदने वाला उन्हें कभी भी भुना सकता है किन्तु पहले ३ वर्षों में कोई सूद नहीं मिलता और उसके उपरान्त क्रमशः सूद की दर बढ़ती जाती है। १२ वर्ष पूर्ण हो जाने पर आरम्भ में लगाया हुआ रुपया छोटा हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति १००० रुपये के कैश सर्टिफिकेट लेता है तो १२ वर्ष के उपरान्त उसको १५०० मिलेंगे। एक व्यक्ति २५ हजार रुपये से अधिक के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट नहीं खरीद सकता। इन पर भी आयकर नहीं लिया जाता। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेटों पर सूद की दर अच्छी है तथा जोखिम बिलकुल नहीं है इस कारण मध्यम श्रेणी का व्यक्ति उनकी ओर अधिक आकर्षित होता है। यदि खरीदने वाले को यह सुविधा दे दी जावे कि वह अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सके जिसे उसकी मृत्यु के उपरान्त रुपया दिया जावे तो यह और भी अधिक प्रचलित हो सकते हैं।

इन कार्यों के अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस जनता के लिए सरकारी सिम्प्लिफिकेटों (प्रतिभूति) को खरीदने और बेचने का काम भी करता है। इस कार्य के लिए पोस्ट ऑफिस कोई फीस नहीं लेता। किन्तु एक वर्ष में पोस्ट ऑफिस किसी

निधि या चिट-फंडः—निधियाँ मदरास प्रान्त में पाई जाती हैं। आरम्भ में यह पारस्परिक ऋण देने वाली संस्थाओं के रूप में काम करती थीं, किन्तु क्रमशः वे अर्द्ध वैकिंग संस्था बन गईं। इस समय मदरास प्रान्त में २२८ निधियाँ काम कर रही हैं। वे कम्पनी ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर की गई हैं। वे या तो डिपॉजिट लेती हैं अथवा हिस्सा पूँजी के रूप में भासिक किरानों में रुपया स्वीकार करती हैं जो कि निकाला जा सकता है। उनका मुख्य उद्देश्य सदस्यों में वचत की भावना जाग्रत करना है, उनके पुराने ऋण को चुकाना तथा महाजन के चंगुल से निकालना तथा उनको उत्तम त्मान पर सभी कार्यों के लिए ऋण देना है। यदि निधि के पास अधिक रुपया होना है जिसका सदस्यों के लिए कोई जहरत नहीं है, तो बाहर वालों को भी ऋण दे दिया जाता है। निधियों में डिपॉजिट आकर्षित करने पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वे अधिकतर रुपया हिस्सा पूँजी (Share-capital) के द्वारा प्राप्त करती हैं। निधियाँ सूद की दर पर ऋण देती हैं। साधारणतः वे ६½ प्रतिशत पर सदस्यों को ऋण देती हैं, परन्तु समय पर न चुकाये जाने वाले ऋण पर वे अधिक सूद लेती हैं और उससे उनको कुछ लाभ होता है। मदरास वैकिंग कमेटी का कथन था कि अधिकतर निधियों का संचालन और प्रबन्ध बहुत अच्छा था।

चिट-फंड—चिट-फंड शब्द से लोगों का एक संगठन मात्र होना है जो एक दूसरे को रुपया उधार देने तथा वचत की भावना को जाग्रत करने के लिए स्थापित किया जाता है। यह अधिकतर मदरास प्रान्त में पाए जाते हैं। इनकी ठीक-ठीक संख्या तो किसी को ज्ञात नहीं किन्तु यह कई हजार होंगे। इसका विधान इस प्रकार होता है। कुछ लोग आपस में यह तय कर लेते हैं कि वे एक निश्चित रकम एक निश्चित समय पर अपने में से एक को दे दिया करेंगे। सदस्यों द्वारा पहली बार दिया हुआ रुपया चिट फंड को स्थापित करने वाले को उसकी संस्थाओं के उपलब्ध में मिल जाता है। इसके उपरान्त प्रत्येक बार का रुपया या तो बारी बारी से प्रत्येक सदस्य को मिलता रहता है अथवा लाटरी डाल ली जाती है। उदाहरण के लिए १०० आदमी एक चिट फंड स्थापित करते हैं और प्रत्येक प्रति मास दस रुपये फंड को दे देता है, तो पहले महीने का रुपया तो चिट फंड के संस्थापक को मिल जायेगा और दूसरे महीने से १००० २० या तो बारी-बारी से प्रत्येक सदस्य को मिलना रहेगा या लाटरी डाल दी जायेगी। जिस सदस्य को १००० २० मिल गया उसको तब तक दुबारा रुपया नहीं मिल सकता जब तक बाकी सब सदस्यों को एक बार १००० २० न मिल जाये। इससे एक लाभ यह होता है कि प्रत्येक सदस्य को एक मुश्त

१००० ६० मिनट जाने हैं जहाँ उसकी लिए सम्मान्य इतना म्यथा एफ माय इच्छा करना सटित हो जाता। किन्तु समाजवाचित फट स्थापित करने वाले धोखा देते हैं और सम्मान्य करने हैं तथा अन्य मदद्यों का म्यथा मारा जाता है। आवश्यकता इस बात का कि इनका प्रचार ठाढ़ हो। उन्नीय वैकिंग जान समझा मा मन था कि निधिया नया मित फल का ठाढ़ ध्यन्या हो, इसके लिए एक ज्ञानन प्रता प्रिया नारा किमन ग्रन्थगत उनका रनिम्न हो।

७ भारतीय मय शासनायुक्त प्रमाणितिलियिंग हाउस (Clearing House)—किता भी देश म नय व्यापारिक वर्गों का स्थापना हो जाता है तो निवर्तमान हाउस का प्राचरयचना पड़ता है। प्रिया समाचारन गड (विलियरिंग हाउस) व वारिंग प्रमाण्य का उच्चतम स्थापन पर जाकर फल पानी है। निवर्तमान हाउस न हाल प्रान्त प्रनमा लभा का नया गिनाना प्राचरयन नहा है। मज्जर म हम कह मस्त है कि निवर्तमान म म का स्थापना व वेंर न नमचारियों का एक मूर न धैर तथा स्फट १ शक्ति का म्यथा प्रचल करने न लिए धार-धार जाना नहा प्यता, प्राच न इन पुन न मगतान हा नकद म्यथा म करना पड़ता है जिसम माग म म्यथा न छुट जान का मर नहा रहता। इतना स्थापना से बैका का प्ररिक्त नक मार (Cash Balance) नहा म्यता पड़ता। निवर्तमान हाउस का स्थापना म वेंर म नमदा म्यथा भा म्यथा काम खला सकते हैं। यह एक लला लाभ है जिसम बैका का कायनयना बडता है।

भारतवर्ष म नागे निवर्तमान पर निवर्तमान हाउस स्थापित हो चुके हैं और अफलतावक नाम मर रह है —बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, देहला, मद्रास, आगरा, इलाहाबाद, अहमदाबाद, अमृतसर, कालासोट, मीरमुर, देहरादून, जालंधर, लखनऊ, लाहलपुर, मद्रास म्यथार, नागपुर, पटना, शिमला तथा बंगलौर हिन्दुस्तान म, तथा लाहौर, कर्गोवा, और गजलपिठी पाकिस्तान म।

उपर का जालिमा म म्यथा हा जाता है कि भारतवर्ष में अभी विलियरिंग हाउस का मुविधा म्यथा थाई ल स्थाना पर है। यह विलियरिंग व्यापार के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। शान अधिकार वड़े सहारा म वयेर वर हैं परन्तु वहाँ विलियरिंग हाउस स्थापित नहीं हुए हैं। रिक्ताव वर को इस ओर शान ध्यान देना चाहिये। बनारस, मद्रास, बरेला, जलपुर, जमशेदपुर, गूरन, पूना जैसे व्यापारिक नगरों म इतने अधिक वर होते हुए भी विलियरिंग हाउस न होना विडी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता।

सदृश्यता —प्रत्येक स्थान का विलियरिंग एगोसियेशन एक स्वतंत्र म्यथा होती है और उसका अपने निवर्तमान होते हैं। परन्तु कुछ विलियरिंग हाउस को छोड़

कर अधिकांश स्थानों की क्लियरिंग एसोसियेशनों ने यह नियम बना दिया है कि जिस बैंक की चुकता पूँजी (Paid up capital) पाँच लाख रुपये हो वही उसका सदस्य हो सकता है। कलकत्ता तथा कुछ अन्य क्लियरिंग हाउसों का नियम यह है कि जिन बैंकों की चुकता पूँजी १० लाख रुपये हो वही उसके सदस्य हो सकते हैं। केवल यह शर्त पूरी हो जाने मात्र से ही कोई बैंक क्लियरिंग हाउस का सदस्य नहीं बन जाता। बैंक को क्लियरिंग हाउस के मंत्री को एक प्रार्थनापत्र देना पड़ता है जिसका प्रस्ताव और समर्थन क्लियरिंग हाउस के सदस्य ही कर सकते हैं। और जब तीन चौथाई सदस्य उस बैंक के पक्ष में अपना मत दें तभी वह बैंक सदस्य बन सकता है। इस नियम का परिणाम यह हुआ कि जिन व्यापारिक केन्द्रों में एक्सचेंज बैंक का प्रभाव तथा बहुमत था वहाँ मारतीय बैंकों की सदस्य बनने में बड़ी कठिनाई हुई। होना चाहिये कि सदस्यता के नियमतन्त्रिक सरल बना दिये जायें। जो भी शिष्टयुक्त बैंक हों उन्हें क्लियरिंग हाउस का सदस्य स्वीकार कर लिया जावे।

उप-सदस्य—जो बैंक ऊपर की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं अर्थात् जिनकी चुकता पूँजी १० लाख या ५ लाख से कम है और उनकी ब्रांच उस केन्द्र में है जहाँ क्लियरिंग हाउस है वो वे उप-सदस्य बनने की प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे बैंकों को एक प्रार्थनापत्र किसी सदस्य बैंक के द्वारा क्लियरिंग एसोसियेशन के मंत्री को देना होता है। जिस सदस्य बैंक के द्वारा प्रार्थनापत्र दिया जाना है उसे प्रवेशकर्ता बैंक (Sponsor Bank) कहते हैं। प्रवेशकर्ता बैंक (Sponsor Bank) को प्रार्थना करने वाले बैंक की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है तब वह उप-सदस्य बना लिया जाता है।

प्रबन्ध—क्लियरिंग हाउस का प्रबन्ध एक प्रबन्धकारिणी समिति करती है जिसमें एक सदस्य रिज़र्व बैंक का (यदि वहाँ रिज़र्व बैंक की ब्रांच हो) एक सदस्य इम्पीरियल बैंक का तथा एक्सचेंज बैंक और मिश्रित पूँजी वाले बैंकों (Joint Stock Banks) के निर्धारित प्रतिनिधि होते हैं। बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े केन्द्रों के एक्सचेंज बैंकों का बहुत अधिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव है।

निरीक्षक बैंक—(Supervising Bank) जहाँ रिज़र्व बैंक की ब्रांच है वहाँ तो रिज़र्व बैंक ही क्लियरिंग हाउस के निरीक्षक बैंक का काम करता है, और जहाँ रिज़र्व बैंक की ब्रांच नहीं होती वहाँ इम्पीरियल बैंक यह काम करता है। प्रत्येक सदस्य बैंक को निरीक्षक बैंक के पास एक निश्चित रकम जमा करनी पड़ती है। कलकत्ता और बम्बई को छोड़कर अन्य स्थानों पर दिन भर में केवल

भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा

एक बार निष्कासन (Clearing) होता है किन्तु नगई और कलकत्ता में दिन में दो बार निष्कासन होता है। अब हम नीचे कलकत्ता में निष्कासन (Clearing) किस प्रकार होता है उसका सक्षिप्त विवरण देंगे।

कलकत्ता क्रियरिंग हाउस,—कलकत्ता के सदस्य तथा उप-सदस्य बैंकों के सब चेक, बिल, तथा प्रलेखों (Documents) का निष्कासन (Clearing) क्रियरिंग हाउस द्वारा होता है। किसी उप-सदस्य बैंक को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने चेक या बिल इत्यादि सधे क्रियरिंग हाउस को दे सके। उप-सदस्य के चेक इत्यादि उगक प्रवश्यकता बैंक (Sponsor Bank) के द्वारा ही क्रियरिंग हाउस को दिने जा सकने हैं। होना यह है कि प्रवेशकता बैंक का प्रतिनिधि अपने बैंक के रजिस्टर में हा उप-सदस्य के चेक इत्यादि चढ़ा लेता है।

प्रत्येक सदस्य बैंक को क्रियरिंग हाउस में एक प्रतिनिधि रखना पड़ता है और उसे एक रजिस्टर देना पड़ता है जिसमें उन सब चेकों, बिलों और प्रलेखों (Documents) को वह दर्ज कर लेता है जो उसे अन्य बैंकों से प्राप्त होते हैं, अपना वह अन्य बैंकों को देता है।

प्रत्येक सदस्य बैंक का प्रतिनिधि एक पृथक स्लिप पर उन सब चेकों, बिलों और प्रलेखों (Documents) का ग्यौरा तथा रकम लिख लेता है जो कि वह अन्य सदस्य बैंकों को देता है और उस रकम को वह सदस्य बैंकों के नाम रजिस्टर में लिख लेता है। तदुपरान्त प्रत्येक सदस्य बैंक का प्रतिनिधि दूसरे सदस्य बैंकों के प्रतिनिधियों को उन पर लिखे गये चेकों और बिलों इत्यादि का बदल तथा उनके ग्यौरों को ग्लिय दे देता है और वे अपने रजिस्टर में उनको दर्ज कर लेते हैं। स्लिपों को बिलों, चेकों तथा प्रलेखों से मिलाकर प्रत्येक प्रतिनिधि अपने रजिस्टर के दोनों कालमों को जोड़ लेता है। इसमें उसे यह ज्ञात हो जाता है कि उसकी अन्य सदस्य बैंकों को कुल किनना लेना है तथा उसने बैंक को अग्न में किनना देना या लेना है। इनका कर चुकने के उपरान्त वह रजिस्टर को क्रियरिंग हाउस के निराकर को सौंप देता है।

यह गो हम पहले ही कह चुके हैं कि कलकत्ते में प्रतिदिन दो साधारण निष्कासन (Clearing) होते हैं परन्तु एक विशेष निष्कासन सायनाल को और होता है जिनमें वापस किए हुए चेक, बिल तथा प्रलेखों का निष्कासन (Clearing) होता है और जिस बैंक के चेक इत्यादि वापस कर दिये जाते हैं उसको इतनी रकम देना पड़ता है।

कलकत्ते में जो बहुत से छोटे बैंक हैं और जिन्हें क्रियरिंग हाउस का सदस्य होने का गौरव प्राप्त नहीं है उन्होंने एक नई संस्था को जन्म दिया है जिसे

मैट्रोपॉलिटन-बैंकिंग एसोसियेशन कहते हैं। यह संस्था उन बैंकों के चेकों विलों तथा प्रलेखों के निष्कासन (Clearing) की व्यवस्था करती है। उसमें दिन में केवल एक बार निष्कासन होता है।

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत में निष्कासन की व्यवस्था बहुत असंतोषजनक है और भविष्य में सभी केन्द्रों में क्लियरिंग हाऊसों की स्थापना होना आवश्यक है। यही नहीं क्लियरिंग हाऊस के सदस्य होने के लिये जो कड़ी शर्तें रख दी गई हैं उन्हें भी नरम करने की जरूरत है।

८- भारतीय द्रव्य-बाजार (Indian Money Market) भारतीय द्रव्य-बाजार के भिन्न विभागों में घनिष्ठ सम्बन्ध का न होना:— भारतीय द्रव्य-बाजार को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—पहला आधुनिक या केन्द्रीय भाग कहलाता है और दूसरा देशी या बाजार भाग कहलाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, इम्पीरियल बैंक, मिश्रित पूँजी वाले बैंक तथा एक्सचेंज बैंक (विनिमय बैंक) आधुनिक या केन्द्रीय भाग के अन्तर्गत हैं और साहूकार, देशी बैंकर, ऋण कार्यालय, चिट फंड तथा निधी देशी या बाजार भाग के अन्तर्गत आते हैं। सह-कारी बैंकों (Co-operative Banks) की स्थिति इन दोनों के बीच की है। भारतीय द्रव्य-बाजार के इन दोनों भागों में अपूर्ण सम्बन्ध है क्योंकि भारतीय बैंकिंग का संगठन अच्छा नहीं है और न एक दूसरे से वे अच्छी तरह सम्बद्ध भी हैं। १९३५ तक अर्थात् रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व तो उनको आपस में मिलाने वाला कोई केन्द्रीय बैंक भी नहीं था। द्रव्य-बाजार का केन्द्रीय भाग सरकार की मुद्रा नीति (Currency Policy) से बहुत अधिक प्रभावित रहता है और उसके द्वारा सरकार बैंक रेट (Bank Rate) पर भी प्रभाव डालती रही है। यही कारण है कि भारतीय द्रव्य-बाजार दोषपूर्ण है और संसार के अन्य उन्नत द्रव्य-बाजारों की समता नहीं कर सकता।

केन्द्रीय बैंक (Central Bank) के अभाव में १९३५ तक इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक के कुछ कार्य करता था। व्यवहार में अन्य बैंक उसके पास अपनी नकदी रखते थे। वह भारत-सरकार की सिन्धूरिटियों पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देता था। यद्यपि बैंकों के लिए यह एक बड़ी सुविधा थी किन्तु अधिक ऊँचा मूद्र लेने के कारण व्यापारिक बैंकों के लिए उनका लाभ कम हो जाता था। पहले भारत सरकार से और अब रिजर्व बैंक से इम्पीरियल बैंक को जो विशेष सुविधाएँ मिली हुई हैं उनके कारण मिश्रित पूँजी वाले बैंक (Joint Stock Banks) उसे अपना अनुचित प्रतिद्वन्दी ही मानते आये हैं न कि मित्र और सहायक। और इसी कारण मिश्रित पूँजीवाले बैंकों तथा इम्पीरियल बैंक में

कभी घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित न हो सका।

भारतीय मिश्रित पूँजी वाले बैंक एक्सचेंज बैंकों (विनिमय बैंकों) को भा अपना प्रबल प्रतियुद्धी और विरोधा मानते हैं, क्योंकि विनिमय बैंकों से साधन बहुत अधिक हैं, वे कम मूद पर यथेष्ट टिपानिट प्राप्त कर लेते हैं और वे बदर माहों तथा भीतरी व्यापारिक चक्रों में देश के अन्दरूनी व्यापार को भी इधिया लेना चाहते हैं।

प्रान्तीय सहकारा बैंक (Provincial Co-operative Banks) इम्पिरियल बैंक के पास थोड़ा सा चालू जमा (Current Deposit) रखते हैं और इम्पिरियल बैंक उन्हें नकद साज (Cash Credit) तथा औपर डाफ्ट (अविनिमय) देता है। सैन्ट्रल सहकारी बैंक भा इम्पिरियल बैंक या कुछ बड़े मिश्रित पूँजीवाले बैंक में चालू खाता (Current Account) रखते हैं, किन्तु प्रारम्भिक सहकारा समितियों केवल सहकारी बैंक से ही सम्बन्ध रखना है, इम्पेरियल बैंक या मिश्रित पूँजीवाले बैंकों से उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं होता।

सहकारा बैंक (Co-operative Banks) का दरी बैंकों तथा महा जनों और सहकारा में तनक भा सम्बन्ध नहीं होता। मिश्रित पूँजी वाले बैंकों की यह शिकायत है कि सहकारा बैंक भी उनसे प्रतियुद्धी करने लगे हैं। उनका कहना है कि महाकारा बैंक यह कारबार भा करते लगे हैं जिसका सहकारिता आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरण के लिए सहकारा बैंक चालू खाता (Current Account) रखते हैं, स्पष्ट दो एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं तथा विलों को खरादते और भुनाने हैं। दरी बैंक भा सहकारी बैंकों के विरुद्ध यही शिकायत करत हैं।

देशा बैंकों और महाजना में अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। यह दोनों अधिकतर इम्पेरियल बैंक में अपना गाना नहीं रखते। इम्पेरियल बैंक से भी देशा बैंक अपने विल या हुडिया भुना लेते हैं किन्तु रिज़र्व बैंक से तो उनका तनक भी सम्बन्ध नहीं है। जब कारबार अधिक होता है तो जिन देशा बैंकों का नाम स्वीकृत सूचा पर होता है उनको हुडियों की इम्पिरियल बैंक या मिश्रित पूँजी वाले बैंक भुना देते हैं या दो देशा बैंकों के हस्ताक्षरों सहित प्रामिचरा नोट पर अक्षर दे देते हैं। इस प्रकार दरी बैंकों का बहुत थोड़े समय के लिए इम्पेरियल बैंक या मिश्रित पूँजीवाले बैंक से सम्बन्ध स्थापित होता है। यह भी सब देशा बैंकों का सम्बन्ध उनसे स्थापित नहीं होता। केवल स्वाइत देशा बैंकों को ही यह सुविधा दी जाना है और उनके लिए भी अधिक से अधिक कितने मूल्य की हुडियाँ भुनाई जा सकती हैं यह निश्चित कर दिया जाता है।

द्रव्य-बाजारों में सूद की दर—संसार के सभी उन्नतिशील राष्ट्रों में लम्बे समय के लिए लगाये हुए रुपये पर थोड़े समय के लिए लगाये हुए रुपये से अधिक सूद मिलता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड अथवा संयुक्तराज्य अमेरिका में सरकारी ऋण तथा प्रथम श्रेणी की कम्पनियों के डिबेंचरों (ऋण पत्र) पर जो सूद मिलता है वह तीन महीने के बिलों पर दिये जाने वाले सूद से अधिक होता है। किन्तु भारतवर्ष में इसका उलटा रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी की पिछली ३० वर्षों में थोड़े समय की सूद की दर लम्बे समय की सूद की दर से एक प्रतिशत अधिक थी, किन्तु बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में और विशेषकर पहले महायुद्ध के उपरान्त थोड़े समय की सूद की दर तथा लम्बे समय के सूद की दर का यह भेद कम हो गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि थोड़े समय के लिए सबसे अधिक ऋण खेती के धन्वे के लिए आवश्यक होता है और खेती का धन्धा इस देश में अत्यन्त पिछड़ा और अचंगठित है। अतएव जो भी ऋण किसानों को दिया जाता है बहुधा वह बसूल जरूरी नहीं होता, उसकी अवधि बढ़ानी ही पड़ती है, अतएव वह लम्बे समय के लिए ही ऋण बन जाता है। और खेती के धन्वे को दिये जाने वाले ऋण के बूब जाने का बहुत भय रहता है जबकि सरकारी ऋण में लम्बे समय के लिए रुपया लगाने में इस प्रकार की कोई जोखिम नहीं रहती। यही कारण है कि इस प्रकार के थोड़े समय के वास्ते लिए हुए ऋण पर सूद बहुत अधिक लिया जाता रहा है। किसानों से अधिक सूद मिलने के कारण गाँवों में थोड़े समय के लिए जब सूद की दर ऊँची रहती है तो उसका प्रभाव संगठित द्रव्य-बाजार पर भी बिना पड़े नहीं रहता। यही कारण है कि भारतीय द्रव्य-बाजार में थोड़े समय की दर अधिक समय के लिए लगाये हुए रुपये पर मिलने वाले सूद की दर से ऊँची रही है। यहाँ एक बात और ध्यान में रखने की है। यहाँ कम्पनियों के डिबेंचर इत्यादि तो अधिक प्रचलित हैं नहीं, केवल भारत सरकार के लम्बे समय के लिए हुए ऋण पर मिलने वाले सूद की दर से ही हम तुलना कर सकते हैं। किन्तु वास्तव में भारत-सरकार के ऋण पर मिलने वाले सूद को हम लम्बे समय की दर नहीं कह सकते, क्योंकि सरकारी ऋण अर्थात् सरकारी सिक्कुरिटि प्रत्येक समय बँची जा सकती है। उनके लिये सदैव बाजार में माँग रहती है। फिर भी यह तो मानना ही होगा कि भारत में थोड़े समय के लिए, लिए जानेवाले ऋण पर सूद की दर ऊँची रही है और उसके कारणों के सम्बन्ध में हमने ऊपर लिखा है। इसके विपरीत भारतवर्ष में जो विदेशी पूँजी आई वह लम्बे समय के लिये लगाई गई। विदेशी पूँजी-पतियों ने भारत में अपनी पूँजी को अधिक लम्बे समय के लिए लगाना पसन्द किया क्योंकि यहाँ लम्बे समय के लिए रेलों, बंधों, तथा सरकारी ऋण में लगाई

साने वाला पूँजा अधिक सुरक्षित था, परन्तु थोड़े समय के निरन्तरता के चयन में साने वाली पूँजा को बहुत जोखिम उठाना पड़ता था। यह कारण था कि नये समय में निरन्तरता पूँजा कम मूल्य पर प्राप्त हो सकी थी। किन्तु वही विदेशी पूँजी अधिक दूरे मिलने पर भी थोड़े समय में पूँजी के रूप में गिरने के निम्न प्राप्त नहीं थी।

भारतवर्ष में १९२२-२३ में, १९२३-२४ में और १९२६-२७ में ही ऐसा अल्पकालीन अल्पकालीन समय का मूल्य का दर (Short-term interest rate) अधिक लम्बे समय का मूल्य का दर (Long term rate) दर में गिरने का कारण था। १९२२-२३ में थोड़े समय का मूल्य का दर में गिरने का कारण यह था कि रुपये का धितमिल दर (Exchange rate) में गिरने में देश में बाहरी का आयात (Import) बहुत अधिक हुआ। इनका परिणाम यह हुआ कि बैंकों के पास आवश्यकता में बहुत अधिक धन (Cash) इकट्ठा हो गई इस कारण कम समय का मूल्य का दर नीचे गिर गया। १९२३-२४ में थोड़े समय का मूल्य का दर में गिरने का कारण यह था कि सरकार ने लकड़ों के लिये को कमाने के निम्न धन्यायुक्त कागजात मुद्रा (Paper Currency) छाप दी थी। इस कारण थोड़े समय का मूल्य का दर नीचे गिर गया। उधर सरकार ने बहुत से मुद्रास्फोट निकाल कर जनता का धन का सहायक के लिए खींच कर लम्बे समय का मूल्य का दर को ऊँचा कर दिया। और १९२६-२७ में जो थोड़े समय का मूल्य का दर लम्बे समय का मूल्य का दर का तुलना में गिर गई उसका कारण यह महान् आर्थिक मन्दता (Economic Depression) की जो १९२६ में आई।

बैंक द्वारा जमा पर मूल्य का दर—द्वितीय पर मूल्य का दर निर्धारित करते समय बैंकों को दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो यह कि वे कितना धन आकर्षित करना चाहते हैं और किन्ना कोष लाभदायक बन वे लगा सकते हैं। इस दृष्टिकोण में बैंक चालू जमा (Current Deposits) पर मूल्य नहीं दे सकते क्योंकि चालू खाता (Current Account) में धन जमा करने वाले लोग सुविधा की दृष्टि से ही चालू खाता रखते हैं न कि मूल्य देने के लिए। मूल्य प्राप्त करने के लिये ओ धन उनका आवश्यकताओं से अधिक है वह सुरक्षित जमा (Fixed Deposit) में जमा किया जाता है। अतः, यदि चालू जमा पर थोड़ा मूल्य दे दी दिया जावे तो भी चालू जमा (Current Deposits) अधिक नहीं बढ़ जावेगा। किन्तु चालू जमा पर मूल्य देने का बैंकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें अधिक मूल्य कमाने के लिए रुपये को कहीं न कहीं लगाना ही पड़ता है, फिर चाहे कुछ जोखिम हो क्यों न उठाना पड़े। इसका

परिणाम घुरा होता है। यही कारण है कि ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका में चालू खाते पर सूद नहीं दिया जाता। किन्तु भारतवर्ष में इम्पीरियल बैंक को छोड़कर सभी बैंक चालू खाते पर सूद देते हैं। १९३० तक भारतीय व्यापारिक बैंक चालू खाते पर २½ प्रतिशत तक सूद देते थे, किन्तु यही उनकी निर्बलता थी। क्योंकि भारत में प्रथम श्रेणी के विलों तथा याचना द्रव्य (Call money) का बाज़ार अभी निर्मित नहीं हुआ है इस कारण बैंकों को जिस लेनी (Assets) में अपना रुपया लगाना पड़ता है वह शीघ्र ही नफ़्दा में परिणत नहीं की जा सकती। परन्तु क्रमशः भारतीय बैंकों ने चालू जमा पर सूद की दर को कम करना आरम्भ कर दिया। १९२१ में वे १ प्रतिशत सूद देते थे बाद को घटाकर उन्होंने चालू खाते पर ½ प्रतिशत सूद कर दिया और दूसरे संसार व्यापी महायुद्ध के समय जबकि देश में रुपये की बहुतायत थी उन्होंने सूद घटाकर ¼ प्रतिशत कर दिया। आशा है कि भारतवर्ष में भी बैंक चालू जमा कर सूद देना बन्द कर देंगे।

मुहती जमा (Fixed Deposit) पर सूद की दर—मुहती जमा पर बैंक जो सूद देते हैं उस पर ही मुहती जमा का अधिक होना या कम होना निर्भर रहता है। यदि सूद अधिक दिया जाता है तो मुहती जमा अधिक आती है और यदि सूद का दर कम कर दी जाती है तो मुहती जमा घट जाती है। क्योंकि मुहती जमा वही करता है जिसे उस रुपये की कुछ समय के लिए आवश्यकता नहीं होती या वह उस पर सूद कमाना चाहता है। यदि मुहती जमा पर सूद बहुत कम हो जावे तो मुहती जमा चालू जमा में परिणत हो सकती है, क्योंकि यदि मुहती जमा पर सूद बहुत कम हो जावेगा तो लोग अपने रुपये को उस पर कम्बे समय के लिये छटकाने रहना पसन्द नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त बैंक मुहती जमा पर सूद की दर निर्धारित करते समय वह भी देख लेते हैं कि वे अपने ग्राहकों से कितना सूद ले सकते हैं। अस्तु; मुहती जमा पर सूद की दर दो बातों पर निर्भर रहती है—एक तो इस बात पर कि अन्य सिक्यूरिटियों में रुपया लगाने पर कितना सूद मिल सकता है, दूसरे द्रव्य-बाज़ार में थोड़े समय के लिये अण देने में कितना सूद मिल सकता है। जहाँ तक रुपया जमा करने वाले का प्रश्न है उसके लिए बैंक में रुपया जमा करने के अतिरिक्त दूसरा सीधा रास्ता यह है कि वह भारत-सरकार की सिक्यूरिटि में अपना रुपया लगा दे। अस्तु; सरकार अपने अण जिस सूद की दर पर निकालती है उसका मुहती जमा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यद्यपि दोनों में बहुत भेद भी है। भारतवर्ष में अधिकतर मुहती जमा ६ महीने या उससे अधिक समय के लिए ली जाती है अधिकतर डिपॉजिट एक वर्ष के लिये होती है। बन्ध, कलकत्ता जैसे बड़े केन्द्र

म ६ महीने से कम की भी मुदता डिपॉजिट से ला जाते हैं।

बैंक दिये हुए कजा पर इतिना मूद लेंगे यह अन्य देशों में—जहाँ द्रव्य-बाजार पूर्ण रूप से समायोजित है—बैंक रेट (Bank rate) पर निर्भर रहता है। यदि कन्द्रीय बैंक (Central Bank) का मूद की दर, जिस पर यह अन्य बैंक की कजा देता है, ऊँचा हो जाना है तो अन्य बैंक भी अपने कजाधारों से और ऊँचा दर से मूद लेते हैं और यदि कन्द्रीय बैंक की मूद की दर घटती है तो अन्य बैंक भी उस पर मूद की दर घटा लेंगे हैं। अन्य बैंक जब कितना मी मूद देते हैं तो जो उग समस्त कन्द्रीय बैंक (Central Bank) का मूद का दर (Bank rate) होना है उससे एक निश्चित या मदी अधिक मूद लेते हैं। उन देशों में यह वह मूदना जमा पर जो मूद देने है वह कुछ निश्चित प्रतिशत 'बैंक रेट' से कम होता है। इस प्रकार उा देशों में जहाँ द्रव्य-बाजार समायोजित है वहाँ मूदना जमा पर दिये जाने वाले तथा कजा पर लिण जाने वाले मूद की दर वही कन्द्रीय बैंक (Central Bank) का बैंक रेट पर निर्भर रहती है और उससे सम्बन्धित होता है।

किन्तु भारतवर्ष में स्थिति दूसरा है। यहाँ मूद का दर का कोई नियम नहीं है। प्रत्येक स्थान और प्रत्येक बैंक का मूद का दर भिन्न होती है। उदाहरण के लिए यदि कितना स्थान पर देयल एक हा बैंक है तो वह अपने एकाधिकार का पूरा लाभ उठाता है और अधिक मूद लेता है, और यदि कोई दूसरा बैंक यहाँ अपना माव खाल देता है तो मूद का दर गिर जाती है। यह नहीं कि भिन्न भिन्न स्थानों में मूद का दर भिन्न होता है, प्रत्येक बैंक का कारबार भी बहुत भिन्न होता है इस कारण उनका मूद भी दर में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। भारतवर्ष में कुछ बैंक ऐसे हैं जो कजा पर बहुत उचित मूद लेते हैं, फिर भी वे योग्य लाभ कमाते हैं। किन्तु यदि दूसरे बैंक उगा मूद की दर पर खर्च दें तो उन्हें बहुत घाटा सहन करना पड़े। भारतवर्ष में बैंकों की मूद की दर में घुगुने से अधिक का अंतरापाया जाना है। सत्य में हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में बैंकों का मूद का दर में बहुत भिन्नता पाई जाती है।

भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अमा उपयोगियों का पूरा तरह से विस्तार नहा हुआ है और जहाँ द्रव्य-बाजार अभी पूर्ण रूप से समायोजित नहीं है, भिन्न भिन्न प्रदेशों में मूद की दर भिन्न होना कुछ सोमा तक अनिवार्य है। किन्तु यहाँ बैंकों में अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा के कारण जो मूद की भिन्नता पाई जाती है वह भारतीय बैंकिंग का एक बड़ा दोष है। कुछ बैंक केवल इसलिए अधिक मूद देते हैं जिससे वे डिपॉजिट प्राप्त करने में सफल हों। इसका फल यह होता है कि उन्हें

अपना रुपया ऐसी जगह लगाना पड़ता है जो बहुत सुरक्षित नहीं होती और उनकी स्थिति कमजोर रहती है। तब से संकट में इस प्रकार के बैंक डूब जाते हैं और सभी बैंकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सभी देशों में अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि डिपॉजिटों पर दिए जाने वाले सूद की दर में अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा न तो किसी एक बैंक के ही लिए लाभदायक होती है और न बैंकिंग संस्था (Banking System) के लिए ही लाभदायक सिद्ध होती है। अन्य देशों में बैंक स्वयं मिल कर डिपॉजिट पर सूद की दर क्या हो यह निश्चित कर लेते हैं; किन्तु भारतवर्ष में इस प्रकार सूद की दर को नियंत्रण नहीं किया जाता। आवश्यकता इस बात की है कि भारतवर्ष में भी प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित किया जाये और कम से कम एक वर्ष की मुदती जमा की सूद की दर निश्चित कर दी जाये।

विनियोग (Investments) पर मिलने वाले सूद की दरें—आधुनिक द्रव्य-बाजार में दो प्रकार की सूद की दर पाई जाती हैं। ये सूद की दरें जो खुले बाजार में प्रचलित होती हैं और जिन्हें हम खुले बाजार की दरें (Open market rate) कहते हैं, और दूसरी ये सूद की दरें जो ग्राहकों से ऋण देने पर ली जाती हैं। ग्राहकों से जो सूद लिया जाता है उसके सम्बन्ध में ठीक-ठीक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं, परन्तु खुले बाजार की दरों के बारे में हमें प्रासांगिक आंकड़े मिलते हैं। ग्राहकों से लिये जाने वाले सूद की दरों में बहुत भिन्नता होती है। यदि किसी एक प्रदेश में सूद की दर बहुत ऊँची है तो दूसरे प्रदेश में सूद की दर नीची होती है। बात यह है कि जहाँ तक ग्राहकों से लिए जाने वाले सूद की दर का प्रश्न है वह स्थानीय कार्यों पर निर्भर रहती है, अतएव सूद की दर का भिन्न होना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए बैंकों को किसी प्रदेश में डिपॉजिट कम मिलती है तो वे वहाँ ऋण अधिक सूद लेकर ही देंगे; और जहाँ डिपॉजिट बहुत अधिक मिलती है वहाँ कम सूद लेकर भी उस रुपये को लगाने का प्रयत्न करेंगे। जिस स्थान या प्रदेश का देश के केन्द्रीय बैंक से सम्बन्ध होता है वहाँ सूद की दर कुछ कम रहती है। अतएव कहने का अर्थ यह है कि ग्राहकों से लिए जाने वाले सूद की दर स्थानीय कारणों पर निर्भर रहती है और उन्हीं कारणों से उसमें भिन्नता पाई जाती है।

खुले बाजार की दरें (Open Market rates)—(१) अमियाचन ऋण (Demand Loan) पर इम्पीरियल बैंक जो सूद लेता है वह देश में अल्पकालीन पूँजी (Short-term capital) पर कितनी आय हो सकती है इसको बतलाता है। इम्पीरियल बैंक की अमियाचन ऋण की दर अल्पकालीन पूँजी पर होने वाली आय को नापने का यंत्र है। यह दर नकद साख (Cash

credits) तथा साधारण ऋणों पर लिए जाने का सूद की दरों का भी प्रतिनिधित्व करती है।

(२) इम्पारियल बैंक हुआ रेट वह सूद की दर है जिस पर इम्पीरियल बैंक प्रथम श्रेणी के व्यापारिक ऋणा को भुनाता है। १९३५ तक इम्पारियल बैंक केवल ३ महान शहरों में बिना कांटा भुना सकता था। किन्तु व्यवहार में उन बिना का एक्से का अवधि अल्प ६० या ६५ दिन रहता था।

हुआ रेट अर्थात् इम्पारियल बैंक का अभियाचन ऋण (Demand Loan) का सूद का दर ४ साप्ताहिक घटना बढ़ता है, किन्तु कभी-कभी इम्पारियल बैंक का रेटा दर उनका अभियाचन ऋण का दर से ऊँची हो जाती है और कभी नाच गिर जाता है।

(३) याचना द्रव्य रेट (Call money rate) उस सूद की दर को कहते हैं जो कि २४ घण्टे के लिए दिए हुए ऋण पर लिया जाता है। याचना द्रव्य (Call money) का वह निम्न समय चाह वापस माग सकता है और लेने वाला उसे जब चाहे वापस दे सकता है। भारतवर्ष में बैंक इस प्रकार ऋण केवल उन्हीं व्यक्तियों का देता है जो उमर जाने-बूझ सकते हैं और जिनकी सख्त बहुत अच्छी होती है। बैंक इस प्रकार के ऋण ४ लिए कोई जमानत नहीं लेते केवल ऋण लेने वाले का व्यक्तिगत नाम पर यह देते हैं।

भारतवर्ष में याचना द्रव्य (Call money) अधिकतर केवल मोते-चौदो के बाज़ार और शेयर बाज़ार में कारबार करने के लिए लिया जाता है। परन्तु बम्बई में बड़े व्यापार साधारण व्यापार के लिये भी याचना द्रव्य लेते हैं, क्योंकि उन्हें कम सूद पर रुपया मिल जाता है।

याचना द्रव्य का दर इम्पारियल बैंक की अभियाचन ऋण का दर (Demand Loan rate) के अनुसार घटती-बढ़ता है। कभी-कभी याचना द्रव्य की दर बहुत ही ऊँची चढ़ जाती है, यहाँ तक कि इम्पारियल बैंक को अभियाचन ऋण का दर (Demand Loan rate) के बराबर पहुँच जाती है। जब कारबार की बहुत तेज़ा होती है तो कभी-कभी याचना द्रव्य ऊँची दर पर भी नहीं मिलता और गंदी के समय उसकी सूद की दर बहुत गिर जाती है। इन अवसरों पर याचना द्रव्य की सूद की दर का इम्पारियल बैंक के अभियाचन ऋण की दर से कोई सम्बन्ध नहीं रहता।

(४) बाज़ार मिल रेट या बाज़ार हुडी रेट भारतीय द्रव्य बाज़ार (Money market) में सबसे ऊँची सूद की दर होती है। यह सूद की दर उन बिलों पर होती है जो थोड़े छोटे व्यापारियों के लिये भुनाते हैं। बाज़ार

बिल रेट फलकता की अपेक्षा बम्बई में कम रहती है। इसका मुख्य कारण यह है कि बम्बई में श्राफों (Shroffs) का बैंकों से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है।

ऊपर दिये हुए विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुनंगठित द्रव्य-बाजारों की मांग भारतीय द्रव्य-बाजार में प्रचलित सूद की दरों का एक दूसरे से कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं है। यदि बाजार में कारबार का तेज़ी हुई और रुपये की मांग अधिक हुई और रुपया कम हुआ तो सूद की दरें ऊंची चढ़ जाती हैं, और यदि कारबार मंदा हुआ तो सूद गिर जाता है। किन्तु बाजार में प्रचलित सूद की दरों का आपस में कोई निश्चित और घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होता। इसका कारण यह है कि भारतीय बैंकों में इस बात की भावना नहीं है कि उनके स्वार्थ एक हैं। रिज़र्व बैंक अर्थात् तक इतना अधिक प्रभावशाली नहीं है कि द्रव्य-बाजार पर अपना पूरा प्रभाव डाल सके और पूँजी (Capital) के एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीमातापूर्वक पहुंचाने में रुकावटें हैं।

बैंकों की उन्नति और द्रव्य-बाजार को अधिक संगठित बनाने के लिये यह आवश्यक है कि सूद की दरों के सम्बन्ध में बैंक एक आपसी समझौता कर लें तथा एक परम्परा बना लें। इससे एक बड़ा लाभ यह होगा कि बैंकों में आपस में अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जावेगी। उदाहरण के लिए लंदन में बैंकों ने यह निश्चय कर लिया है कि अल्पकालीन डिपॉजिट पर बैंक रेट से १ प्रतिशत सूद कम दिया जावे। बैंक रेट तथा डिपॉजिटों पर दिये जाने वाले सूद की दर का सम्बन्ध जोड़ देने से एक लाभ यह होगा कि बैंक डिपॉजिटों को खींचने के लिए अस्वास्थ्यकर होड़ नहीं कर सकेंगे।

भारतीय द्रव्य-बाजार में अस्थिरता तथा अधिक उतार-चढ़ाव का डोना— भारतीय द्रव्य-बाजार का एक बड़ा दोष यह रहा है कि उसमें स्थिरता नहीं रहती थी। बैंक रेट में बहुत अधिक परिवर्तन होते रहते हैं। १९२२ के पूर्व अर्थात् आर्थिक मंदी (Economic Depression) के अधिक गहरे हो जाने के पूर्व जब व्यापार मंदा होता तो बैंक रेट ३ प्रतिशत पर रहती और तेज़ी के मौसम में ७ और ८ प्रतिशत तक बढ़ जाती। इस अस्थिरता के कारण व्यापार का जोखिम बढ़ जाता है तथा व्यापारियों को बहुत आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उद्योग-धंधों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता था क्योंकि वे भी बहुत कुछ थोड़े समय के लिए प्राप्त किए श्रम पर निर्भर रहते थे। जब कारबार की तेज़ी होती और बैंक रेट ऊंची हो जाती तो देश के भीतरी व्यापार तथा खेती के लिए पूँजी मिलने में बहुत कठिनाई होने लगती थी, क्योंकि बन्दरगाहों में भी उस समय पूँजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी और वहाँ के व्यापार-

में अधिक खर्च देने की सुझाई रहता था। अतएव बैंक उस समय प्रस्ताव दिया नदगाहों को धन देने से तथा देश में मान्य व्यापार तथा सेवा के लिए द्रव्य (money) का टोटा पड़ जाना था। इसका कारण यह था कि जब कारबार की तेजी होती तो प्रथम द्रव्य का अट्टा पड़ नग था। कारण यह था कि भारतवर्ष में मेनिन्डर देश होने से कारण नग मेनी का पैदावार की वस्तु के सम्य पराव होती तो बहुत अधिक द्रव्य की आवश्यकता पड़ता थी, और जो भी कर्मों (मुद्रा) देश में मापकरण होना वह हम कार्य के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। किन्तु समस्याओं तथा क्या व मौद्रिक में नग कारबार मंद रहता था तो वही कर्मों आवश्यकता में बहुत अधिक हो जाना था।

१९०१ में इम्पेरियल बैंक व म्याग्नि होने में एक सरकार प्रत्यक्ष और स्वतंत्र रूपान्तरित रहता थी जो चलन में से बहुत अधिक द्रव्य (Money) की आवश्यकता रख लेने से। कारण यह था कि मानवजाति के रूप में विमान जो द्रव्य देते थे वह ही स्वार्थों में आकर बंद हो जाता था और यह उस समय होता था जब बजार में द्रव्य का बहुत अधिक माग होता था। इस कारण बाजार में द्रव्य का बेहद टोटा पड़ जाता था। १९०१ के उपरान्त यह स्पष्ट इम्पेरियल बैंक के पास आने लगा और यह इसकी व्यापारियों का दक्षता था अतः १९०१ के उपरान्त इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ। फिर भी भारत सरकार तथा भारत-भर प्रत्यक्ष और स्वतंत्र रूप से मौद्रिक का कारबार करने से जिसके कारण द्रव्य-बाजार में बहुत अधिकता उत्पन्न हो जाना था। मान यह था कि भारत सरकार तो मुद्रा (Currency) का नियंत्रण करता था और इम्पेरियल बैंक कुछ हद तक खास (Credit) का नियंत्रण करता था। इस दावे के नियंत्रण का फल यह होता था कि मुद्रा नीति (Currency Policy) और मौलाना (Credit need) में कमा साम्य स्थापित नहीं हो पाता था। परिदृष्टिवाद और व्यापार में वृद्धि होना तो अधिक धन (Credit) की आवश्यकता होगी था, परन्तु अधिक धन का निर्माण तभी हो सकता है जब अधिक द्रव्य (Money) हो। परन्तु यदि उस समय सरकार अधिक नोट छाप कर द्रव्य-बाजार को न बढ़ानी तो बैंकों को धन कम करनी पड़नी थी। इस प्रकार उस समय देश में मुद्रा (Currency) तथा धन का कोई ठीक प्रबंध न था। कारण यह था कि धन का ठीक नियंत्रण तो था नहीं किन्तु जो कुछ भी नियंत्रण था वह इम्पेरियल बैंक के हाथ में था और धन मुद्रा (Currency) पर निर्भर रहती है किन्तु मुद्रा का नियंत्रण सरकार के हाथ में था।

रिज़र्व बैंक की स्थापना से द्रव्य-बाजार (Money Market) का यह दोष दूर हो गया। जब रिज़र्व बैंक के अधिकार में दोनों ही कार्य हैं। यह कागजी

मुद्रा (Paper Currency) तथा साख (Credit) दोनों का ही नियंत्रण करता है, अतः अब रिज़र्व बैंक द्रव्य की अधिक मांग होने पर अधिक नोट निकाल कर द्रव्य की कमी को दूर कर सकता है।

भारतीय द्रव्य-बाजार में व्यापारिक बिलों का अभाव—भारतीय द्रव्य-बाजार में एक मुख्य दोष यह है कि यहाँ व्यापारिक बिलों की बहुत कमी है। भारतीय बैंकों की लेनी (Asset) में बिल बहुत कम होते हैं जबकि विदेशों में बैंक अपने कोष (Funds) का बहुत बड़ा भाग इनमें लगाते हैं। भारतीय मिश्रित पूँजी वाले बैंक तथा इम्पीरियल बैंक अपनी कुल डिपॉजिटों का केवल ३ से ६ प्रतिशत रुपया बिलों के भुनाने में लगाते हैं। इसी से यह स्पष्ट हो जाना है कि भारतीय द्रव्य-बाजार में बिलों का नितान्त अभाव है। इनके नीचे लिखे मुख्य कारण हैं :—

(१) भारत में बैंक अपना रुपया सरकारी सिक्कुरिटियों अर्थात् परम प्रतिभूति (Gold-edged Securities) में लगाना अधिक पसंद करते हैं। इसके कारण दो हैं, एक तो भारत में वैकिंग अभी अधिक उन्नत अवस्था में नहीं है इस कारण बैंक अपना रुपया ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जो शीघ्र ही नक़्दा में परिणत किया जा सके; और दूसरे सरकारी सिक्कुरिटियों पर सूद अच्छा मिलता था। किन्तु अब जितना सूद बिलों के भुनाने से मिलता है उससे अधिक परम प्रतिभूति (Gold-edged Securities) अर्थात् सरकारी सिक्कुरिटियों पर नहीं मिलता। अतएव जैसे-जैसे सर्वसाधारण का बैंकों पर अधिक विश्वास जमाता जावेगा वैसे-वैसे बैंक सरकारी सिक्कुरिटियों में कम रुपया लगाने लगेंगे।

(२) जब-जब बैंकों को ऋण की आवश्यकता होती है तब-तब वे इम्पीरियल बैंक से सरकारी सिक्कुरिटियों की जमानत पर ऋण लेना पसंद करते हैं और अपने बिलों को इम्पीरियल बैंक से पुनः भुनाना (Rediscount) पसंद नहीं करते। इसके नीचे लिखे कारण हैं :—

(क) इम्पीरियल बैंक केवल उन्हीं बिलों को पुनः भुनाता है जिन्हें वह ठीक समझता है और पसंद करता है। किन्तु वह किस प्रकार के बिलों को पसंद करेगा इसका उसने कोई मानदंड (Standard) कायम नहीं किया है जिसके अनुसार अन्य बैंक यह जान सकें कि वह किन् बिलों को पसंद करेगा। अतएव बैंकों को सदैव यह खतरा रहता है कि कहीं उनके बिलों को इम्पीरियल बैंक अस्वीकार न कर दे।

(ख) भारतीय द्रव्य-बाजार में यह प्रचलित धारणा है कि बिलों का पुनः भुनाना आर्थिक निर्बलता का सूचक है, अतएव भारतीय बैंक बिलों को पुनः इम्पीरियल बैंक से भुनाने में इस कारण हिचकते हैं कि इससे उनकी साख पर

द्वारा प्रभाव पड़ेगा।

(ग) इम्पीरियल बैंक अन्य बैंकों के लिये बड़ा दर (Discount Rate) में कोई रियायत नहीं करता। वह उनमें भा बड़ा दर लेता है जो वह दरी बैंकों से लेता है।

(घ) क्योंकि इम्पीरियल बैंक व्यापारिक बैंकों का प्रतिद्वन्दी है इस कारण व उस यह नहीं बचना चाहता कि उस पास कितने और केम बिज है।

(ङ) भारत में बिज या हुडियों पर हस्ताक्षर करने वालों का आर्थिक स्थिति या मांस कैसा है यह जानने का मुखिया नहीं है। इंग्लैंड तथा अमेरिका में ऐसा एजेंसियाँ हैं जो किसी भा व्यापारी या व्यवसायी की आर्थिक स्थिति और हाल के सम्बन्ध में थोड़ा सा पास लकर ठीक जानकारी दे देती हैं।

(च) भारत में हुडियों तथा बिजों का उपयोग बहुत अधिक होने और लेने में किया जाता है। उदाहरण के लिये यदि 'क' 'ख' में २ हजार रुपये लेना चाहता है तो 'क' 'ख' पर हुज या बिज लिख देगा और 'ख' उनको स्वीकार कर लेगा। अब 'क' उस हुज या बिज का मुद्रा कर गपवा प्राप्त कर लेगा। इन हुडियों को देखने मात्र में यह कोई नहीं बता सकता कि यह गपवा कर्ज लेने के उद्देश्य से लिखी गया है अथवा व्यापारिक हुज है, क्योंकि हुज के माय में तो रेल को मिला होनी है और न अन्य प्रकार में कोई कामकाज पत्र होते हैं।

(छ) भारत में मुहनी हुज का चलन लगभग समान हो गया, क्योंकि उस पर रदाम्त छुट्टी का खर्चा अधिक होता है, वह खर्च बंगाल में तथा बम्बई और शिकारपुर में ही अधिक प्रचलित है। अब मुहनी हुज का स्थान दर्शना हुज ने ले लिया है, किन्तु उनमें बन्त थोड़ा दिनों का ही मांस मिल पाती है। यहाँ हुडियों के चलन में एक कठिनाई यह है कि उनके सकारने में बन्त सा शर्त होता है। यहाँ नहीं, हुडियों का कोई निश्चित रूप या नहीं है। न तो उनकी निधि और माया हा एक होता है और बिज बिजस्थान पर निकारने और सकारने (Acceptance and payment) के नियम भी भिन्न होते हैं।

(झ) भारत में बिज या हुडियों के अभाव का एक कारण यह भी है कि बैंक नकद साव (Cash Credit) अधिक दत्त हैं। नकद साव बैंकों तथा कर्ज लेने वालों दोनों के ही लिए लाभदायक सिद्ध होता है। कर्ज लेने वालों का लाभ तो यह है कि जितना साव का वह उपयोग करते हैं उनमें पर ही उन्हें दर देना पड़ता है और बैंक का लाभ यह होता है कि बैंक रुपया जब चाहे वापस माग सकता है। यदि कर्जदार की आर्थिक स्थिति बिगड़ी मालूम पड़े तो बैंक तुरन्त उससे रुपया वापस ले सकता है। किन्तु नकद साव से बिज दोनों के लिए अधिक

उपयोगी सिद्ध होंगे। क्योंकि कर्ज़ लेने वालों को बिलों की अवधि तक एक निश्चित राक़म की साख़ (Credit) मिल जावेगी और यदि पुनः भुनाने की सुविधा हो तो बैंकों को एक अत्यन्त तरल लेनी (Liquid Asset) में अपना रुपया लगाने का अवसर मिल जावेगा। फिर कर्ज़दार को यह भी लाभ होगा कि वह नफ़्द साख़ पर जितना सूद देता है उससे कम पर बिल को भुना सकेगा।

(७) भारतीय द्रव्य-बाज़ार में बिलों या हुंडियों का चलन न होने का एक यह भी कारण है कि भारत सरकार बहुत अधिक राशि में सरकारी हुंडियों (Treasury Bills) बेचती है। बैंक इन सरकारी हुंडियों को बहुत बड़ी राशि में खरीदते हैं, क्योंकि वे बहुत सुरक्षित होते हैं और निश्चित समय पर उनका भुगतान हो जाना है। वे तरल भी होते हैं क्योंकि रिज़र्व बैंक उन्हें खरीदने के लिए सबैव तैयार रहता है।

किली सेन्ट्रल बैंकिंग जांच कमेटी तथा सभी बैंकिंग विरोधों की राय है कि जब तक देश में व्यापारिक बिलों का चलन और उपयोग नहीं बढ़ना और भारत में संगठित बड़ा बाज़ार (Discount Market) का उदय नहीं होता तब तक भारतीय बैंक सबल और उन्नत नहीं हो सकते। रिज़र्व बैंक ही इस देश में हुंडियों और बिलों के चलन और उपयोग को बढ़ा सकता है और देश में बड़ा बाज़ार (Discount Market) स्थापित कर सकता है। रिज़र्व बैंक को चाहिए कि वह अन्य बैंकों को अपने बिलों को पुनः भुनाने (Rediscount) की सभी सुविधाएँ दे; उन्हें यह निश्चित रूप से बतला दिया जाय कि किस प्रकार के बिल या हुंडियों को यह पसन्द करेगा। रिज़र्व बैंक को चाहिए कि वह देशी बैंकरो (Indigenous Bankers) को बड़ा यह (Discount Houses) का काम करने के लिए प्रोत्साहित करे। देशी बैंकर व्यापारियों के बिलों या हुंडियों को भुनावें और यदि उन्हें अधिक कोष (Funds) की आवश्यकता हो तो वे रिज़र्व बैंक से उन बिलों या हुंडियों को पुनः भुनायें। रिज़र्व बैंक को देशी बैंकरो को अपने बिलों को पुनः भुनाने की सभी सुविधाएँ देना चाहिये। इससे एक लाभ यह भी होगा कि देशी बैंकरो तथा द्रव्य-बाज़ार का सम्बन्ध स्थापित हो जावेगा। यदि देश में प्रमाणित भंडारों तथा गोदामों की व्यवस्था हो जाये, जिनका प्रबंध विषयनीय हो, तो हुंडियों और बिलों का चलन अधिक बढ़ सकता है; क्योंकि इन गोदामों और भण्डारों की रसीद के साथ जो बिल या हुंडी होमी उसके व्यापारिक बिल या हुंडी होने में तनक भी सन्देह नहीं रहेगा और बैंक उन हुंडियों को भुनाने से नहीं हिचकेंगे। जो कुछ भी हो, बैंकिंग की उन्नति के लिए बिलों और हुंडियों की बहुत आवश्यकता है।

६—भारत में बैंकिंग सम्बन्धी कानून — १९३६ तक भारत में बैंक सम्बन्धी कोई विशेष कानून नहीं था। बैंक भी अन्य मिथित पूँजी वाली कम्पनियों (Joint Stock Companies) की भाँति (१९३३ के कम्पनी ऐक्ट २ अनुसूची) रजिस्टर होते थे और वहाँ के लिए भी वही नियम थे जो अन्य कम्पनियों के लिए लागू थे। १९२३ के कम्पनी ऐक्ट में बैंकों तथा अन्य कम्पनियों के बीच में बहुत बड़ा फर्क ला दिया गया था। एक अनुसूची में यह था कि १० प्रतिशत से अधिक गारंटीदारों वाला फर्म बैंकिंग कारबार नहीं कर सकती था, और बैंकों को लेना देना का लेखा (Balance Sheet) एक निश्चित ढंग से तैयार करने का व्यवस्था की निम्न सुनिश्चित श्रृंखला (Secured Debts) तथा अरक्षित ऋण (Unsecured Debts) अलग-अलग दिखाना आवश्यक था।

किन्तु इस कानून के द्वारा बैंक का ठीक नियंत्रण नहीं किया जा सका था। माला देशों में बैंकिंग का कारबार विशेष महत्त्व का सम्मान पाता है, क्योंकि वे जनता का डिपॉजिट आसपास करते हैं और देश के आर्थिक जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। यहाँ कारण है कि भारत के प्रत्येक देश में बैंकों का नियंत्रण करने के लिये विशेष बैंकिंग कानून आवश्यक समझा गया। भारतवर्ष में बैंकिंग सम्बन्धी विशेष कानून का न होना सब को परेशान था और विशेषकर जब १९२३ और २४ में भारतवर्ष में बैंक का संकट उपस्थित हुआ और बहुत सारे बैंक बंद हो गए उस समय से सबका विश्वास टूट हो गया कि देश में विशेष और स्वतंत्र बैंकिंग कानून के बन जाने से स्थितियाँ और अच्छे बैंकों के उदय होने में सहायता मिलेगी।

यद्यपि हमें यह न भूल जाना चाहिये कि वारे केसा हा अच्छा बैंकिंग कानून क्यों न बनाया जाय वह सारे प्रबंध, दानि और बैंकों के इच्छा को नहीं रोक सकता। बैंक या बैंकर को सब कानून द्वारा उत्तर नहीं दिया जा सकता। यही नहीं, यदि बैंकों के लिये बहुत लम्बा चौड़ा कानून बना दिया जावे तो उनकी उन्नति में रुकावट होता है। बैंकों पर बहुत अधिक बंधन लगा देना उनकी उन्नति को रोकना है। बैंकों को जहाँ तक हो सके स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। हॉ रिज़र्व बैंक के नियंत्रण की शक्तों की उन्नति के लिये आवश्यक आवश्यकता है। इतना सब होते हुए भी बैंकिंग कानून का इसलिये आवश्यकता है कि जिससे वैश्यानी, धोखे और कुप्रबंध को कुछ हद तक रोका जा सके। यही कारण था कि संजुल बैंकिंग ऑन कमेटी ने एक स्वतंत्र बैंक कानून की आवश्यकता बतलाई।

उस समय भारत-सरकार ने यद्यपि स्वतंत्र बैंक कानून तो नहीं बनाया परन्तु १९३६ के कंपनी ऐक्ट में बैंकों के लिए कुछ विशेष नियम बना दिये जो नीचे दिये गये हैं :—

(१) बैंकिंग कम्पनी की कंपनी ऐक्ट में इस प्रकार परिभाषा की गई— बैंकिंग कम्पनी वह कम्पनी है जिसका मुख्य कारबार जमता के रुपये को ऐसी डिपॉजिटों के रूप में स्वीकार करना है, जो चेक, ड्राफ्ट या ब्याज के द्वारा निकाली जा सकें। इसके अतिरिक्त वह नीचे लिखे कार्य भी कर सकती है :—
(क) रुपया कर्ज़ लेना और देना, विलों और हुन्डियों, प्रामिसरी नोटों, कंपनियों के हिस्सों, डिबेंचरों, रेलवे रसीद तथा सोने-चांदी की खरीद-बिक्री करना और द्रव्य और सिक्कूरिटियों को बचल करना और एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना। (ख) सरकार, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तथा व्यक्तियों के एजेंट का काम करना। लेकिन बैंक किसी कंपनी का मैनेजिंग एजेंट नहीं हो सकता। (ग) सरकार तथा व्यक्तियों के लिए ऋण दिलाना तथा ऋण को निकालना। (घ) सरकारी तथा म्युनिसिपल ऋण का अभिगोपन (Underwritings) करना तथा कंपनियों के हिस्सों या डिबेंचरों का अभिगोपन करना। (ङ) किसी व्यापारी कारबार को आर्थिक सहायता देना। (च) ऋण अथवा अचल सम्पत्ति की खरीद-बिक्री करना। (छ) किसी का ट्रस्टी बनना। (ज) किसी दूसरी कम्पनी के हिस्से खरीदना या प्राप्त करना जिसके उद्देश्य उसके ही समान हों। (झ) उन संस्थाओं और कोषों (Funds) को स्थापित करना जो कम्पनी के कर्मचारियों के लाभ के लिये हों। (ञ) कंपनी के लिए आवश्यक इमारतों को खरीदना।

कोई भी बैंकिंग कम्पनी ऊपर लिखे कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं कर सकती और भविष्य में कोई बैंकिंग कम्पनी रजिस्टर नहीं की जा सकती जिसके उद्देश्य डिपॉजिट लेने तथा ऊपर के कार्यों तक सीमित न हों।

किसी भी बैंकिंग कम्पनी का प्रबन्ध मैनेजिंग एजेंट नहीं कर सकते। भविष्य में कोई भी बैंकिंग कम्पनी जो रजिस्टर की जा चुकी हो, उस समय तक कार्य नहीं कर सकती जब तक उसकी चुकता पूँजी कम से कम ५०,००० रुपये न हो।

प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी उस समय तक जब तक उसका रक्षित कोष (Reserve Fund) उसकी चुकता पूँजी (Paid up Capital) के बराबर नहीं हो जाता लाभ का कम से कम २० प्रतिशत रक्षित कोष में जमा करेगा और शेष लाभ ही हिस्सेदारों में बाँट सकेगा। रक्षित कोष या तो

सरकारा अथवा ट्रस्ट मिन्स्ट्रिटिया म लगाया जावगा अथवा गिती अन् शिद्दूल बैंक म जमा नर दिया जावगा ।

प्रत्येक बैंक (शिद्दूल बैंक वा लुइकर) का मिन्डर्व बैंक के पास अन्तः चालू जमा (Current Deposit) का ५ प्रतिशत तथा मुदता जमा (Fixed Deposit) का १९ प्रतिशत जमा करना होगा और प्रत्येक महान् रजिस्ट्रार का एक लेखा भेजना होगा जिसमें पिछले महीने के प्रत्येक शुक्रवार को उसका जितना देना (Liability) थी तथा उसका पास किताब नज़्द कोष (Cash Reserve) था वह बताना होगा ।

जो भा व्यक्ति किसी बँकिंग कम्पनी का छूटा हो अथवा आगे चल कर उसका छात्रदार हो चाहे उसका ऑडिटर (आय-व्यय निराकृष्ट) नहीं बनाया जा सकता । बैंकिंग कम्पनी का अपना लता दर्जी के लिये (Balance Sheet) में बैंक के डायरेक्टर्स, मैनेजरा तथा कम्पनी के अन्य कर्मचारियों पर किताब अलग है यह अलग-हदा दिखना होगा ।

रिजर्व बैंक का बैंक एकट बनाये जान का प्रस्ताव—जानवर १९१६ में रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा और उसमें इतना बैंक एकट बनाये जान का आग्रह्यकता बतलाई । साथ ही बैंक ऐक्ट में नित बातों का समावेश होना चाहिये उसका एक लेखा बनाकर भेजा । रिजर्व बैंक का कहना यह था कि अधिकांश बैंक का पूँजा और रजिन कोष बहुत कम है तथा वे डिपॉजिटर्स के हितों का चिन्ता नहीं करते इस कारण सरकार को एक कानून बना कर डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करनी चाहिये ।

रिजर्व बैंक का प्रस्तावित बैंक बिल इस प्रकार था—“बैंक की परिभाषा अधिक निश्चित और सीमित कर देनी चाहिये और कोई भी कंपनी जो बैंकिंग-कार्य नहीं करता उस अपने नाम में आगे बैंक शब्द जोड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिये । जो कंपनी बैंकिंग-कार्य करती है वह अपने नाम के साथ बैंक शब्द अवश्य जोड़े । कोई भी बैंक उन कार्यों के अनतिरिक्त अन्य कारबार नहीं करेगा जिनका बिल में समावेश है ।

“कोई भी बैंक उस समय तक बैंकिंग कार्य न कर सरेगा जब तक उसका चुकता पूँजा और रजिन कोष (Reserve) कम से कम एक लाख रुपये न हो, और यदि बैंक नाचे लिखे स्थान में स किसी म कारबार करता है अर्थात् नाच खोलता है तो उसको प्रत्येक स्थान के लिए नीचे लिखे अनुसार पूँजा भरानी होगा—बम्बई और कलकत्ते के लिए ५ लाख, प्रत्येक ऐस स्थान के लिए जिसकी आबादी एक लाख से अधिक हो कम से कम २ लाख रुपये । यदि बैंक

उस प्रान्त या राज्य के बाहर बाँच खोलना चाहता है जिसमें उसका हेड ऑफिस है तो उसकी चुकता पूँजी (Paid up Capital) और रक्षित कोष कम से कम २० लाख रुपये होना चाहिए। अर्थात् यदि बैंक की चुकता पूँजी और रक्षित कोष २० लाख रुपये से अधिक है तो वह भारतवर्ष भर में जहाँ चाहे बाँचे खोल सकता है।

“किसी बैंक की विक्रीत पूँजी (Subscribed capital) उसकी अधिकृत पूँजी (Authorised capital) की आधी से कम और चुकता पूँजी (Paid up capital) विक्रीत पूँजी से आधी से कम न होनी। उदाहरण के लिए यदि किसी बैंक को अधिकृत पूँजी (Authorised capital) ४ करोड़ रुपये है तो कम से कम २ करोड़ रुपये उसकी विक्रीत पूँजी होनी चाहिए और १ करोड़ रुपये उसकी चुकता पूँजी होनी चाहिए।

“प्रत्येक बैंक को रिज़र्व बैंक के पास अपनी चालू जमा और मुहती जमा का ३० प्रतिशत या नक़द कोष (Cash Reserve) के रूप में अपना रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत सिफ़रिटियों के रूप में रखना होगा। प्रत्येक बैंक को प्रत्येक वर्ष १ फरवरी के पहले रिज़र्व बैंक में अपनी कुल डिपॉज़िटों का लेखा तथा बैंक के पास किमती लेनी (Assets) है उसका लेखा भेजना होगा। कुल देनी (Liabilities) की ७५ प्रतिशत लेनी (Assets) वह होगी जिन्हें रिज़र्व बैंक स्वीकार करे।”

किन्तु भारत सरकार ने उस समय बैंक ऐक्ट बनाना अस्वीकार कर दिया। भारत सरकार का कहना था कि युद्ध समाप्त हो जाने के उपरान्त ही इस प्रकार का कानून बनाना उचित होगा। किन्तु १९४१ और १९४२ में नये बैंकों की एक बाढ़-सी आ गई, बहुत से नये बैंक स्थापित हुए। उनमें से बहुतों की अधिकृत पूँजी (Authorised capital) तो बहुत अधिक थी किन्तु चुकती पूँजी बहुत कम थी। साथ ही बहुत से बैंकों ने पूर्वाधिकार वाले हिस्से (Preferential Shares) साधारण हिस्से (Ordinary Shares) तथा विलम्बित हिस्से (Deferred Shares) निकाले और पूर्वाधिकार वाले हिस्सों की मत देने का अधिकार ही नहीं दिया और विलम्बित हिस्सों (Deferred Shares) का मूल्य बहुत थोड़ा रक्खा - एक या दो रुपया, और उनको भी मत का अधिकार उतना ही दिया जितना साधारण हिस्से वालों को था जिनका मूल्य बहुत अधिक था। सब तो यह था कि यह युक्ति कुछ लोगों ने बैंक में बहुत कम पूँजी लगा कर बैंक को अपने हाथ में रखने के लिए निकाली थी। उदाहरण के लिए यदि एक बैंक स्थापित किया जाता है, उसकी विक्रीत पूँजी (Subscribed capital) केवल एक करोड़ रुपया है। इसमें २० हजार पूर्वाधिकार वाले हिस्से (Preferential Shares) हैं, जिनका

मूल्य प्रति हिस्सा १०० रुपया है जो पूरा चुका दिया गया है। ७५ हजार साधारण हिस्से हैं जिनका मूल्य प्रति हिस्सा १०० रुपया है जो पूरा चुका दिया गया है और २ लाख विलम्बित हिस्से (Deferred Shares) जिनका मूल्य प्रति हिस्सा १०० है और जिन पर प्रति हिस्सा बचत ॥ रुपया चुकाया गया है। अब बैंक का स्थापित करने वाले नवुर व्यवसाया विधान ॥ यह नियम बना है कि पूर्वाधिकार वाले हिस्सा को मतदान का कोई अधिकार न होगा अथवा एक हिस्से का एक वोट होगा और प्रत्येक साधारण हिस्से का एक वोट होगा और प्रत्येक विलम्बित हिस्से का भी एक वोट होगा और १ लाख विलम्बित हिस्से खराद लगे हैं और उन पर प्रति हिस्से ५ हिस्से ॥ एक रुपया चुका दत्त है तो वे केवल १ लाख रुपय लगा कर लाख वोट प्राप्त कर लगे और साधारण हिस्सेदार और पूर्वाधिकार वाले हिस्सेदार ६५ लाख रुपय लगाकर भाग लें ६५ हजार वोटों का अधिकारी होंगे। इस प्रकार बैंक का लाभा ५ विधान चालाका से विलम्बित हिस्से लगाने लिए हैं अधिकार न चला पायगा।

जब रिजर्व बैंक ने कहा कि नवम स्थापित बैंकों में यह दोष नहीं माना में पाया जाता है तो नवम भारत सरकार का ज्ञान इन और आकर्षित किया। भारत सरकार ने ६८ में स्थापना एक्ट में संशोधन कर दिया और उससे अनुसार यह निश्चित हुआ कि जिस कम्पनी के नाम के साथ बैंक का बैंक लगता है उसका जमान कम्पनी स्थापित किया जायेगा, फिर बाद उसका मुख्य कार्य ऐसा लिखा कि लेना या कि चेक से निकाला जा सके हो या न हो। उससे साथ ही सरकार ने यह भी निश्चित करा दिया कि प्रत्येक बैंक की विज्ञाप पूँजी (Subscribed capital) कम से कम अधिकृत पूँजी (Authorised capital) की आधी होगी और चुका पूँजी (Paid-up capital) बिना पूँजी की कम से कम आधा होगी। और बैंक या ना केवल साधारण हिस्से (Ordinary Shares) हा कम या यदि भिन्न प्रकार के हिस्से रखें तो उनके मतदान का अधिकार उठाया पूँजी १ अनुपात में ही होगा। उदाहरण के लिए अगर जिस कल्पित बैंक का हमने उल्लेख किया है, यदि उसमें पूर्वाधिकार वाले हिस्सेदारों का २० हजार, साधारण हिस्सेदारों को ७५ हजार तथा विलम्बित हिस्सेदारों को केवल २ हजार मत देने का अधिकार होगा।

इसका यह कुछ होने पर भी कुछ काल में नये बैंकों की स्थापना इस तर्ज से हुई और उनमें कुछ ऐसे दोष इष्टिगोचर होने लगे कि भारत सरकार को स्वतंत्र बैंक कानून बनाने के लिए विवश होना पड़ा और १९४५ में भारत सरकार ने एक बिल धारा समा में उपस्थित किया। यह प्रस्तावित बैंक कानून रिजर्व बैंक के

प्रस्तावित बैंक बिल के अनुसार ही था। केवल उसमें इतना ही अन्तर था कि इस प्रस्तावित कानून में बैंक की परिभाषा इस प्रकार की गई—बैंक वह है जो अभिया-
चन डिपॉजिट या जमा (Demand Deposit) स्वीकार करे। इस प्रस्तावित
कानून के अनुसार कोई भी बैंक अपने ढायरैक्टरों को अथवा उस फर्म या
कम्पनी को जिसका साकेदार, ढायरैक्टर या मैनेजिंग एजेंट बैंक का कोई ढाय-
रैक्टर हो अरक्षित ऋण (Unsecured loan) नहीं दे सकता था, और प्रत्येक
बैंक को जो अपने जन्म प्रांत के बाहर कारबार करे कम से कम २० लाख रुपये की
शुक्ता पूँजी और रक्षित कोष रखना आवश्यक था। इस प्रकार बम्बई या
कलकत्ता में प्रांच खोलने के लिए ५ लाख, प्रत्येक ऐसे स्थान पर जिसकी आबादी
१ लाख से ऊपर हो २ लाख और प्रत्येक दूसरी प्रांचों के लिए प्रति प्रांच के हिसाब
से १० हजार रुपये की पूँजी और रक्षित कोष आवश्यक था। कोई भी बैंक एक
लाख की पूँजी और रक्षित कोष के बिना बैंक-कार्य नहीं कर सकता था। इसके
अतिरिक्त प्रस्तावित कानून में प्रत्येक बैंक को अपनी कुल डिपॉजिट का २५ प्रतिशत
रिज़र्व बैंक के पास नकद कोष (Cash Reserve) अथवा सरकारी और ट्रस्ट
सिक्कूरिटियों के रूप में रखना अनिवार्य किया गया था।

इस बिल में उन कार्यों का भी उल्लेख किया गया था जो एक बैंक कर
सकता था। यह इसलिये किया गया था कि जिससे कपया जमा करने वालों की
अमानत (जमा) को सुरक्षा हो। बिल का उद्देश्य यह था कि व्यापारिक बैंक
अपना धन उद्योग-धंधों में लम्बे समय के लिये न लगावें। उसके लिये औद्योगिक
बैंकों की स्थापना आवश्यक है। जर्मनी, इटली और बेल्जियम में जिस प्रकार
व्यापारिक कारबार करने के साथ-साथ स्थायी अथवा अर्ध स्थायी रूप से उद्योग-
धंधों में पूँजी लगाने की परिपाटी चल पड़ी है उसे भारत में न पनपने देना ही
इस धारा का उद्देश्य था।

बिल में दो धारायें इस आशय की भी थीं कि बैंक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप
से किसी प्रकार का व्यापारिक जोखिम को अपने ऊपर नहीं लेंगे और इस उद्देश्य
से वे बैंकिंग कार्य के अनिरिक्त अन्य किसी व्यापार को नहीं करेंगे।

बिल में एक धारा इस आशय की भी थी जो बैंक भारत या ब्रिटेन के बाहर
स्थापित हुए हैं और वे भारत में अपना कारबार करते हैं उन्हें रिज़र्व बैंक के पास
रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित अमानत (जमा) रखनी होगी। इसके द्वारा उन
भारतीयों को जो विदेशी बैंकों में अपना रुपया जमा करते हैं थोड़ी सुरक्षा देने का
प्रयत्न किया गया था।

इस बिल के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया कि

वे प्रत्येक महाने अपने कारबार का लेखा और उन्होंने अपना पूँजी कहीं लगाई इसका व्यौरा रिज़र्व बैंक को देंगे जिनमें रिज़र्व बैंक उनकी गतिविधि में पूरा ठप्पे से परिचित हो सके।

बिना क अनुसार रिज़र्व बैंक की अन्य बैंकों को जांच करने का भी अधिकार प्राप्त था।

जिन्नु १९५५ का यह बैंकिंग बिजनेस रेगुलेशन अधिनियम ने भग हो जाने के कारण व्यवस्थापिका गन्ना व सामान उपस्थिति में किया जा सके।

अन्य में १९५५ अधिनियम १९५५ का गवर्नलान अधिनियम के तहत रिज़र्व बैंक ने पुराने बिजनेस का लेखा रन करके फिर एक नया व्यवस्थापिका गन्ना व सामान उपस्थिति किया जा मल्लिक वमदा व सुपुद कर दिया गया। यह बिजनेस १९५५ के बिजनेस के आधार पर हा बनाया गया था। इसमें नए नए गवर्नलान किया गया था। इस नए बिजनेस व अनुसार रिज़र्व बैंक का किया भा बैंक व रिज़र्व तथा कारबार की जांच करने का अधिकार था। यह बिजनेस रिज़र्व बैंक पर भी लागू होता था। इसके अनुसार एक विशाल प्रकार का लेखा रन का लेखा (Balance Sheet) निर्धारित कर दिया गया तथा रिज़र्व बैंक को अन्य बैंकों से सारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया था। बैंक को बैंकिंग कार्य व अनिश्चित अन्य कार्य करने का मनाहा कर दा गई थी। बिना पूरा आग्रा लिए कोई दो बैंक का जहा तक पूँजी व मगदल का प्रथम था वह पृथक् ही रक्खा गया।

किन्तु यह बिजनेस भा शास्य पास न हो सके। इस बीच में आवश्यकता पड़ने के कारण मन्त्रालय ने १९५६ में एन आर्थिनेंस बनाकर रिज़र्व बैंक को अन्य बैंकों का जांच का अधिकार दे दिया। साथ ही रिज़र्व बैंक को यह भा अधिकार दे दिया गया कि यदि उसका जांच का परिणाम यह निकले कि बैंक का कार्य ठीक नहीं है तो रिज़र्व बैंक उस बैंक को आगे जमा न लेने की आग्रा दे सकता है और उसको गिबल बैंक का भेजा स निगल सकता है। रिज़र्व बैंक ने इस अधिकार का प्रयोग किया और इंडियन नेशनल बैंक आदि इंडिया, आर्थिनेंस बैंक तथा ज्वाला बैंक को आगे डिपॉजिट न लेने का आग्रा दे दा।

एक दूसरे आर्थिनेंस से मारनाम बैंकों को वेयरर प्रामिसरी नोट निकालने की मनाही कर दा गई। वान यह थी कि यदि कोई बैंक वेयरर प्रामिसरी नोट निकाले तो वे बिना किसी अडचन के एक हाथ में दूसरे हाथ में जा सकते हैं और उनका चलन बैंक नोटों के अनुसार होने लग सकता है।

एक तामरा रिधान यह बनाया गया कि कोई बैंक बिना रिज़र्व बैंक की आग्रा प्राप्त किए कोई नए शाखा नहीं खोल सकेगा और न स्थापित शाखा के

स्थान को हाँ बदल सकेगा। रिज़र्व बैंक उस बैंक की आर्थिक स्थिति, प्रबन्ध, उस बैंक का पुराना इतिहास, लाभ की आशा तथा जनहित को ध्यान में रखकर किसी बैंक की स्थापित ब्रांच को बंद करने तथा उसके स्थान परिवर्तन की आज्ञा देगा अथवा नहीं देगा।

वैकिंग बिल १९४८ :—१९४६ का बैंक बिल भी केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में न लाया जा सका क्योंकि अगस्त १९४७ में भारत स्वतन्त्र हो गया अतएव उस बिल में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। अस्तु; पुराने बिल को सरकार ने वापस ले लिया और १९४८ में एक नया बिल सारे देश के बैंकों के लिये व्यवस्थापिका सभा के सामने उपस्थित किया गया। परवरी, १९४९ में संसद से यह बिल पास हो गया, और १६ मार्च १९४९ से यह एक्ट के रूप में लागू कर दिया गया। इस एक्ट की मुख्य मुख्य बातें ये हैं :—

(१) बैंक की एक विस्तृत परिभाषा स्वीकार कर ली गई है। उस परिभाषा के अनुसार जो भी संस्था ज़रूर देने के लिए अथवा विनियोग (Investment) के लिए किसी भी प्रकार की जमा (डिपॉजिट) स्वीकार करे और जो बैंक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य प्रकार से धारित लिखा जा सके, वह बैंक की श्रेणी में गिनी जावेगी।

(२) प्रत्येक बैंक को रिज़र्व बैंक से लाईसेंस प्राप्त करना होगा। विदेशी बैंक के बारे में रिज़र्व बैंक यह इतमीनान करेगा कि उसके देश में भारतीय बैंक के विरुद्ध जो भारत में रजिस्टर हुआ है कोई पक्षपात तो नहीं होता।

(३) बैंक की न्यूनतम पूँजी और रक्षित कोष के बारे में एक्ट में विधान किया गया है।

(४) शिष्यूल बैंक तो रिज़र्व बैंक एक्ट १९३४ के तहत में रिज़र्व बैंक के पास जमा रखते हैं और साप्ताहिक स्टेटमेंट पेश करते हैं। इस एक्ट के तहत में नोन-शिष्यूल बैंकों को 'डिमांड लाइबिलिटी' का ५% और 'टाइम लाइबिलिटी' का २% रिज़र्व बैंक में जमा के रूप में रखना होगा। और मासिक स्टेटमेंट, जिसमें नकद और 'डिमांड तथा टाइम लाइबिलिटीज़' दिये होंगे, पेश किया जाएगा।

(५) एक्ट के लागू होने के दो वर्ष बाद बैंकिंग कम्पनियों को उनकी भारत में जितनी 'डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़' हैं उनका २०% नकद, सोना, या ऐसी स्वीकृत सिक्यूरिटीज़ में जिन पर कोई देनदारी नहीं है रखना होगा। उनको राज्यों में हर तीसरे माह के अन्त में उनकी 'टाइम और डिमांड लाइबिलिटीज़' का कम से कम ७५% के बराबर ऐसेदस्त रखने होंगे।

(६) बैंकों में डाइरेक्टरों की आपस में नियुक्ति (इंटर लोकिंग) नहीं

हो सकती, मैनेमिंग एजेंट नहीं नियुक्त हो सकते, डाइरेक्टरों या जिन्हें वमों से वे दिलचस्पी रखते हैं उनको बिना जमानत के कूज़ नहीं दिया जा सकता। जिन कम्पनियों में बैंक के डाइरेक्टरों का स्वायत्त है उनका बिना जमानत पर दिये गये कूज़ का स्टैटमेट प्रगतिमान रिज़र्व बैंक का मन्त्रा हागी।

(७) रिज़र्व बैंक दश न बैंक पर हर प्रकार से नियन्त्रण रख सोंगा। बैंक उनका उनकी श्रेय नाति न बारे में आदेश दे सकता है। जिस काम के लिये कूज़ दिया जाय या न दिया जाए, किस सूद का दर पर दिया जाय, कितना मार्जिन रक्खा जाय, अमुक या अमुक प्रकार के लोन किये जाय, यह सब आदेश रिज़र्व बैंक दे सकता है। वह आवश्यक जानकारी मांग सकता है, उसे प्रकाशित कर सकता है, बैंकों का निरन्तर कर सकता है। यह ब्रांच खोलने या मीटूदा ब्रांच का स्थान बदलने के लिए बैंक का लाइसेंस आवश्यक है। भारत-सरकार को देश की बैंकिंग स्थिति के बारे में रिज़र्व बैंक का सालाना रिपोर्ट पेश करना हीगा।

(८) रिज़र्व बैंक को स्वच्छता से कारोबार चला करने और बैंकों के आपस में मिलने के सम्बन्ध में जो कुछ अधिकार दिये गए हैं। उसे ओपिशियल लिमिटेडर भी नियुक्त किया जा सकता है। मार्च १९५० में मुख्यतः बैंकों के आरक्ष में मिलान या उनसे लिक्विडेशन के बारे में सरल पद्धति का व्यवस्था करने के उद्देश्य में उपयुक्त एक्ट का अधोपन भी किया जा चुका है।

१०. द्वितीय मन्त्रिपुत्र तथा मन्त्र के विभाजन का भारतीय बैंकिंग पर प्रभाव—(१) द्वितीय महायुद्ध का भारतीय बैंकिंग पर पहला प्रभाव यह पड़ा कि यहाँ नये बैंकों की बाढ़ सा आ गई, अनेक नये बैंक स्थापित हुए और पुराने बैंक ने तेजी से अपना कार्यों को बढ़ाया। इसका कारण यह था कि युद्धकाल में धंधों को रक्का करना के लिए मशीन तथा यन्त्र तो विदेशों से आ नहीं सकते थे जो कैम्बेडरिया स्थापित का जा सकता और न इमारतों इत्यादि बनाने का सुविधा थी। किन्तु बैंक स्थापित करने में इन बाधा का आवश्यकता न थी। उसी लिए केवल अल्पकालीन फंड (Short term Funds) की आवश्यकता थी और यह युद्ध काल में इस देश में बहुतानत से उपलब्ध था। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक धंधे में जोषति या व्यवसाय न अपना कर पड़ा कर दिया। ज्ञान इसा कोई प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी नहीं है जिसने नम मजदूर घर घर स्थापित नहीं किया। यदि भारत सरकार नई मिनिश्ट्रिजों वाला कम्पनियों के स्थापित होने पर रोक न लगा देती तो सम्भवतः भारत में अनाप शनाप बैंकों का वृद्ध होती। फिर भी जहाँ १९३८-३९ में सिम्पल ब्यांकी सख्या ५० था वह १९४७-४८ में बढ़ कर १०० हो गई थी और १९४९-५० में १४ थी। इसी प्रकार १९३८ में

शिङ्गल बैंकों की ब्रांचों की संख्या जो १२७८ थी वह ३१ मार्च १९४६ को बढ़ कर ३००८ हो गई थी।

बैंकों की इस कल्पनातीत वृद्धि के होने पर प्रति ब्रांच बड़े बैंकों में १५ लाख रुपये और साधारण और छोटे बैंकों में ३ लाख रुपये से डिपॉजिटों का औसत कम नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यह है कि युद्ध-काल में बैंकों को डिमॉणिट भां देहद बढ़ गई। इम्पैरियल बैंक विनियम बैंकों और भारतीय मिश्रित पूँजी वाले बैंकों की स्थिति १९४१ तक लगभग पूर्ववत् ही रही, परन्तु जापान के युद्ध में सम्मिलित होने ही विनियम बैंकों (एक्सचेंज बैंकों) की आनु-पानिक डिमॉणिट मिरने लगी। जहाँ युद्ध के पूर्व एक्सचेंज बैंकों की डिमॉणिट कुल बैंकों की डिमॉणिटों का २६.५ प्रतिशत थी वहाँ १९४२ में यह २५ प्रतिशत और १९४६ में २० प्रतिशत से भी कम हो गई। ३१ दिसम्बर १९४६ को कुल डिपॉजिट का १८ प्रतिशत भाग एक्सचेंज बैंक, ७७ प्रतिशत भाग दूसरे शिङ्गल बैंक और ५ प्रतिशत भाग नोन शिङ्गल बैंकों का था।

युद्ध का दूसरा प्रभाव यह हुआ कि बैंकों की डिपॉजिट में कल्पनातीत वृद्धि हुई। इम्पैरियल बैंक, एक्सचेंज बैंक तथा अन्य शिङ्गल बैंकों की कुल डिपॉजिट युद्ध आरम्भ होने के समय २३८ करोड़ रुपये थी। १९४४ में वही बढ़कर ७८२ करोड़ रुपये हो गई। और जनवरी १९४८ में वही बढ़कर १०८० करोड़ रुपये के लगभग हो गई। पर इसके बाद कई कारणों से डिपॉजिट कम हुए हैं। डिपॉजिट वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि युद्ध के व्यव के कारण मुद्रा का देश में बहुत विस्तार हुआ था। रिज़र्व बैंक तथा सरकार ने अनाप-शनाप नोट छापे। बैंकों की डिपॉजिटों की वृद्धि का एक कारण था कि बैंकों ने नये क्षेत्रों में प्रवेश किया था तथा ब्रांचों का बहुत विस्तार हुआ था।

बैंकों की डिपॉजिटों के सम्बन्ध में एक और अन्वेषजनक बात हुई। युद्ध आरम्भ होने के पूर्व मुहती जमा (Fixed Deposits) का कुल डिपॉजिटों का अनुपात ५० प्रतिशत था अर्थात् मुहती जमा आधी थी, किन्तु युद्ध काल में मुहती जमा तो बहुत कम बढ़ी किन्तु चालू जमा (Current Deposit) बहुत अधिक बढ़ गई। इसके तीन मुख्य कारण थे। पहला कारण तो यह था कि युद्ध की दर बहुत मिर गई थी। १९३१ के उपरान्त युद्ध की दर मिरती ही चली जा रही थी इस कारण सर्वसाधारण को एक वर्ष के लिए रुपया अटकाने में कोई लाभ नहीं दिखता था। वह चालू खाते में रुपया जमा करना पसन्द करती थी। किन्तु यह प्रभाव युद्ध के पहले से ही काम कर रहा था। दूसरा कारण यह था कि सर्वसाधारण कीमतें बहुत ऊँची होने के कारण अपनी वचत को

तरल रूप (Liquid Form) में रक्कत वाहना थी कि जब अचानक अपने नवी अर्थात् उद्योग का इन चीजों के खराब होने से उत्पन्न हो गई। नौमरा कारण चालू काम का अत्यधिक उद्विग्नता यह था कि युद्ध काल में मशीनें तथा अन्य सामान न मिलने से कारण नये सामानों का स्थापित हो नहीं सकने थे कि जिससे अचानक तथा अचानक अपने उद्योग में काम का लगा सकने, अर्थात् वे उद्योगों को अपने अचानक अचानक का रूपरेखा में जो (Working Capital) को उद्योगों में लगाने से विविध उद्योगों में अचानक से अधिक से अधिक उद्योगों का करें। १९४६ में कुल ६०० करोड़ रु. दिखाते थे जिसमें मुद्रा की मात्रा ३३० करोड़ रु. थी, १९४६ में ६०० करोड़ रु. थी, १९४६ में ६०० करोड़ रु. थी, १९४६ में ६०० करोड़ रु. थी। [कमर्च ३ मार्च, १९४७]

युद्ध का प्रभाव प्रभाव था कि युद्ध का प्रभाव पूर्णतः परिदृष्ट पूर्णतः (Paid up Capital) का अर्थ रक्कत रूप में उद्योगों का प्रभाव में बहुत बड़ा था। इन्फ्लेशन के कारण पूर्णतः अर्थ रक्कत रूप में उद्योगों का प्रभाव में बहुत बड़ा था। १९४६ में १०० प्रतिशत का यह बड़ा कर ४४ प्रतिशत रह गया, पाँच बड़ों का अर्थ रक्कत रूप में ६३ प्रतिशत में बड़ा कर ४४ प्रतिशत रह गई। इनका फल यह हुआ कि बहुत से बैंकों ने अपनी पूर्णतः (Capital) को बढ़ाया।

युद्ध का प्रभाव यह हुआ कि उद्योगों के और व्यापार के लिये जो अर्थ का मौल्य था वह कम हो गई किन्तु सरकार ने एक नए ढंग से अर्थ निकालने आरम्भ किए। १९४६ में नई ही अर्थ का प्रभाव दिखाते थे ५० प्रतिशत अर्थ, नई नए तथा विनों के रूप में अर्थ और व्यापार में जाता था वहाँ १९४५ में उद्योगों के अर्थ का प्रभाव ३० प्रतिशत इस रूप में लगाया। जैसे जैसे युद्ध चलता गया उद्योगों के बैंकों से उधार लेने की आवश्यकता कम होना गई। उद्योगों के अर्थ का प्रभाव चालू काम में रखने से और उद्योगों के अर्थ का प्रभाव (Working Capital) के रूप में लाते थे। इनका स्थापित परिणाम यह हुआ कि बैंकों ने अपने फंड (Funds) को सरकारों में अर्थ का प्रभाव लगाया आरम्भ कर दिया। वहाँ नहीं, बैंकों ने नई फंड (Cash Reserve) को अधिक रखना आरम्भ कर दिया। सिड्कू बैंक १५ प्रतिशत, इन्फ्लेशन बैंक १५ में २५ प्रतिशत, बड़ा पाँच १८ प्रतिशत, और वे बैंक जो सिड्कू बैंक नहीं हैं २२ प्रतिशत नई फंड रखने लगे। उद्योगों में युद्ध काल में बैंकों का तरल लेन (Liquid Assets) का अनुपात बड़ा गया। इनका परिणाम यह हुआ कि बैंकों को अपने फंड पर

सूद की कम आय होने लगी इस कारण उन्होंने भी डिपॉजिटों पर सूद कम कर दिया।

युद्ध का पॉंचवॉ प्रभाव यह पड़ा कि बैंकों में कुछ खराबियाँ और उनकी कार्य-प्रवृत्ति में कुछ कमी दृष्टिगोचर होने लगी। अतएव रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया और भारत सरकार ने कंपनी एक्ट में कुछ सुधार किये तथा एक बैंक-कानून पास किया।

युद्ध का छठा प्रभाव यह पड़ा कि बैंकों की वृद्धि होने के कारण बैंक-कर्मचारियों का डोटा पड़ गया। नये बैंकों ने पुराने बैंकों के कर्मचारियों को अधिक वेतन देकर अपने यहाँ रख लिया और प्रत्येक बैंक को यह आवश्यकता अनुभव होने लगी कि युवकों को अपरेंटिस रखकर उनको बैंक-कार्य सिखाने का प्रयत्न किया जाये।

अन्तिम प्रभाव यह हुआ कि भारतीय बैंक यह अनुभव करने लगे कि अखिल भारतीय बैंकर्स एसोसियेशन स्थापित की जावे जो अस्वास्थ्यकर होश को रोकें तथा बैंकों में सद्भावना और परस्पर सम्बन्ध स्थापित करे। साथ ही जैसे-जैसे बैंकिंग परम्परा का निर्माण करे तथा बैंकों और रिज़र्व बैंक के बीच में एक कड़ी का काम दे। यह एसोसियेशन भारतीय बैंकों की कठिनाइयों तथा मँगों को सरकार के सामने रख सकेगी और उनका प्रतिनिधित्व कर सकेगी। यही कारण था कि बम्बई के बैंकरों ने उसको स्थापित करने का प्रयत्न किया।

यद्यपि युद्ध के फलस्वरूप भारत में बैंकों का तेज़ी से विस्तार हुआ किन्तु उस बाढ़ में बहुत से निर्बल बैंक भी स्थापित किए गए और वे डिपॉजिट लेने के लिए अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा करने लगे। विशेष कर बंगाल और पंजाब में इस प्रकार के बहुत से छोटे-छोटे बैंक स्थापित हुए। १९४७ में इनमें से पचास से अधिक बैंक बंद हो गये। भविष्य में बैंकों को सबल और सुदृढ़ बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि छोटे बैंक दूसरे बैंकों से मिल जायें। देश में इस समय बैंकिंग सम्मिश्रण (Banking Amalgamation) की आवश्यकता है तभी बैंकिंग व्यवसाय उन्नति कर सकेगा।

देश के स्वतंत्र होने तथा विभाजन का प्रभाव—१५ अगस्त १९४७ को भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया किन्तु साथ ही उसका विभाजन भी हो गया। उसके फलस्वरूप जो पंजाब, सीमाप्रान्त तथा सिंध इत्यादि में इत्याकांड हुआ उसमें उत्तर-पश्चिम भारत में फैले हुए बैंकों की बहुत अधिक हानि हुई है। वहाँ का व्यापार तथा व्यवसाय नीपट हो गया और बैंकों का जो रुपया लगा हुआ था वह बहुत कुछ डूब गया। फिर भी यह कहना होगा कि बैंकों ने इस हानि को सहन

कर लिया और उनमें से अधिकांश का स्थिति अशुद्ध है। हाँ इसका एक प्रमुख अर्थ है। पंचाब तथा पाकिस्तान के बहुत से बैंक अब भी अस्थिरता की चपेट में हैं। गन्ध हाँ बहुत से बैंक सम्भवतः वहाँ अस्थिरता का भाव कर रहे हैं।

॥ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Fund) तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank)—इसका समारम्भ मद्रास (१९१६ में १९४६) के मुद्रा मुद्रा राज्य सम्मेलन तथा ब्रिटेन के अर्थशास्त्रियों के यह अनुभव कि यह सम्मेलन के प्रत्येक देश की करणी की स्थिति प्रदान करना तथा भिन्न भिन्न देशों की दरों का विनिमय दर (Exchange Rates) का अर्थिक घटन या वृद्धि न देना तथा का आर्थिक उन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के लिए आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय १९४४ में मुद्रा राज्य सम्मेलन ने ब्रिटेन मुद्रा नामक सम्मेलन पर एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन (International Monetary Conference) द्वारा ब्रिटेन में एक 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का स्थापना का निश्चय हुआ है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति या मुद्रा पद्धति (Monetary System) का पुनः स्थापना करना है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धों में सहयोग स्थापित हो सके। अर्थशास्त्रियों का यह दृष्टिकोण था कि बिना इस सम्मेलन के भिन्न भिन्न देशों में उद्योगों को सेवा में बढ़ाया नहीं जा सकता और वे बचत का दृष्टिकोण को बढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य का पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) के साथ ही एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का भी स्थापना आवश्यक समझी गई जो भिन्न-भिन्न देशों का आर्थिक उन्नति में सहायक होगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों का अल्पकालीन ऋण (Short Term Credit) का आवश्यकताओं को पूरा करना और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक उद्योगों तथा आर्थिक विकास के निम्न लक्ष्य समय के लिए पूरा का व्यवस्था करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्वानों का मत था कि भारत व्यापक मुद्रा मुद्रा अधिकांश देशों का आर्थिक विकास हो गया है। अतः यदि प्रत्येक देश मुद्रा का समानि के उपरान्त अपना अर्थिक विकास का स्वतन्त्र रूप से प्रवृत्त करेगा तो विनिमय दर (Exchange Rates) में घट-बढ़ होगी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गति अवरोध होगा। इसका प्रभाव उन देशों को आर्थिक स्थिति पर पड़ा होगा और उनका आर्थिक उन्नति नहीं होगी। अतः एव इस बात को आवश्यकता है कि भिन्न भिन्न देशों की करणी तथा उनकी विनि-

मय दर (Exchange Rates) को स्थायित्व प्रदान किया जावे। इसी के साथ 'कोप' का यह उद्देश्य भी है कि विनिमय दर सम्बन्धी तमाम प्रतिबंध, और मुद्रा सम्बन्धी भेद नीति का अन्ततोगत्वा अन्त हो। हां, कुछ समय के लिए किन्हीं प्रतिबन्धों को रहने दिया जा सकता है।

१९३१ के पूर्व स्वर्ण प्रमाण (Gold Standard) के द्वारा संसार के भिन्न-भिन्न देशों की करेंसी की विनिमय दर को स्थायित्व (Stability) प्रदान होता था। किन्तु एक के बाद दूसरे देश ने स्वर्ण प्रमाण को छोड़ दिया और अब अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मत है कि स्वर्ण प्रमाण (Gold Standard) बहुत ही कम लचीला और अन्वयवहार्य है। अस्तु; इस बात की आवश्यकता हुई कि एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य पद्धति (International Monetary System) को जन्म दिया जावे जो अधिक लचीली हो। इसी उद्देश्य ने अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोप तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोप और दिनमय दर का स्थायित्व :—यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोप का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की करेंसी की विनिमय दरों को स्थायित्व प्रदान करना है। इसके लिए आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न देशों की करेंसी के लिए एक सर्वमान्य आधार हो। अस्तु; प्रत्येक सदस्य देश को अपनी करेंसी का मूल्य सोने में निश्चित कर देना होगा। अस्तु; सोने के द्वारा संसार के प्रत्येक देश की करेंसी की विनिमय की सममूल्य दर (Parity of Exchange) निर्धारित हो जावेगी। अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोप के द्वारा (International Monetary Fund) भिन्न-भिन्न सदस्य देशों की विनिमय दरों की एक सीमा के अन्दर ही रखने का आवाहन किया जावेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि देशों की करेंसी की विनिमय दर एक निश्चित सीमा से अधिक घट-बढ़ न सकेगी।

युद्ध के कारण बहुत से देशों का आर्थिक ठोँचा जर्जर हो गया है इस कारण प्रारम्भ में बहुत से देशों का व्यापार संतुलन (Balance of Trade) उनके विपक्ष में होगा, अर्थात् वे जितने मूल्य का माल बाहर भेजेंगे उससे बहुत अधिक मूल्य की वस्तुएँ बाहर से मँगानेंगे। ऐसी दशा में उन देशों को विदेशों की करेंसी की बहुत अधिक आवश्यकता होगी और यदि उनको विदेशों की करेंसी को निश्चित विनिमय दर (Exchange Rates) पर देने का प्रयत्न न किया तो उनकी करेंसी की विनिमय दर कमी स्थिर नहीं रह सकती। यदि युद्ध-जनित आर्थिक गन्दगी को छोड़ भी दें तो भी साधारण व्यापार में कमी-कमी व्यापार का संतुलन (Balance of Trade) किसी समय किसी देश के पक्ष में हो

संरक्षा के और किसी देश के विपक्ष में। ऐसा अवस्था में उन देशों की जितना व्यापार अनुमत्त उसके विपक्ष में है यदि अन्तराष्ट्रीय द्रव्य-कोष में गहायता मिले तो उनका बरमा का विभिन्न दर स्थिर नहीं रह सकता।

प्रस्तुत इस अवस्था में अन्तराष्ट्रीय द्रव्य-कोष उन देशों को अन्य देशों का करेगा एक स्वतन्त्र देशों के अन्तर्गत दान का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस कार्य को अन्तराष्ट्रीय द्रव्य-कोष (International Monetary Fund) सम्भाल-पुष्ट कर सकता है उद्देश्य में प्रत्येक सदस्य देश अन्तराष्ट्रीय द्रव्य-कोष में जो उसका भाग निधारित है उसका कुछ भाग लाने में और जब अपना करेगी (मुद्रा) में चुकायेगा। इस प्रकार अन्तराष्ट्रीय द्रव्य-कोष के पास प्रत्येक सदस्य देश का करेगा यथेष्ट मात्रा में रक्कत जिनमें से आवश्यकता पड़ने पर सदस्य देशों को एक दूसरे से करेगा उधार देना सकेगा। अन्तराष्ट्रीय द्रव्य-कोष में भिन्न भिन्न प्रमुख देशों का भाग इस प्रकार है।

विश्वतः कुछ द्रव्य सम्मेलन में जो ४४ राष्ट्र सम्मिलित हुए थे (शुद्ध राष्ट्र उस समय सम्मिलित नहीं हो सके थे) उनके लिए सम्मेलन ने कुल ८,८००,०००,००० डॉलर का कष्ट निवारित किया था। और १,२००,०००,००० डॉलर का कोष शुद्ध राष्ट्रों के लिए छोड़ दिया गया था कि मुद्रा के उपरान्त ये भी कोष में सम्मिलित हों तो उनकी उममें हिरण दिया जा सके। अन्तराष्ट्रीय द्रव्य-कोष में प्रमुख राष्ट्रों का भाग इस प्रकार है—युनित राज्य अमेरिका २,७५०,०००,००० डॉलर, यूनाइटेड किंगडम १,३००,०००,००० डॉलर, सोवियत रूस १,०००,०००,००० डॉलर, चीन ५५०,०००,००० डॉलर, फ्रांस ४५०,०००,००० डॉलर, भारत वर्ष ४००,०००,००० डॉलर, कनाडा ३००,०००,००० डॉलर, निदरलैंड २७५,०००,००० डॉलर, बेल्जियम २२५,०००,००० डॉलर, आस्ट्रेलिया २००,०००,००० डॉलर, नमोलोवाकिया तथा पोलैंड १२५,०००,००० डॉलर, इतिहास अफ्रीका युनियन १००,०००,००० डॉलर, मैक्सिको ६०,०००,००० डॉलर, चाइल और कोलंबिया ५०,०००,००० डॉलर इत्यादि।

अन्तराष्ट्रीय द्रव्य-कोष में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने भाग का २५ प्रतिशत अपना सदस्य राष्ट्र के पास कुल जितना सोना या अमरालन डॉलर होगा उसका १० प्रतिशत सोना देना होगा (जो भी उस समय कम हो) और शेष रकम प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपना करेगा (मुद्रा) में चुकायेगा। इनका परिणाम यह होगा कि अन्तराष्ट्रीय द्रव्य-कोष के पास सभी सदस्य राष्ट्रों की करेगा (मुद्रा) यथेष्ट राशि में इकट्ठी हो जावेगा और जब किसी सदस्य राष्ट्र का व्यापार अनुमत्त (Balance of Trade) उसने विपक्ष में होगा और उसके पास अपने विदेशी व्यापार

अणु को चुकाने के कोई साधन नहीं रहेंगे तो वह अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष से उसी देश की करंसी को खरीद लेगा और अपने व्यापार अणु को चुका देगा। इस प्रकार उस देश की करंसी की विनिमय दर (Exchange Rates) में विशेष घट-बढ़ न होगी। इसका वह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र आरम्भ से ही अपने विदेशी व्यापार के अणु को चुकाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष पर निर्भर रहेगा। साधारणतः प्रत्येक देश अपने व्यापारिक वैको के द्वारा अपने लेन-देन का मुग्तान करते रहेंगे और जब कोई देश विदेशी व्यापार का संतुलन (Balance of Foreign Trade) अपने विपक्ष में होने के कारण किसी विदेशी करंसी को साधारणतः पाने में असमर्थता अनुभव करेगा तभी वह अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष से करंसी को खरीद लेगा।

साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष (International Monetary Fund) के पास प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की करंसी इतनी मात्रा में होगी कि उसकी कमी नहीं पड़ेगी। परन्तु विशेष परिस्थितियों में यह सम्भव है कि किसी देश विशेष का व्यापार-संतुलन (Balance of Trade) इतना अधिक उसके पक्ष में हो और अन्य सदस्य राष्ट्रों को उस देश विशेष की करंसी को अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष से इतनी अधिक राशि में खरीदना पड़े जावे कि उस देश विशेष की जितनी भी करंसी अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष के पास है वह सभी समाप्त हो जावे, ऐसी स्थिति में कठिनाई उपस्थित हो सकती है। उदाहरण के लिए पिछले महायुद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार-संतुलन उसके इतना अधिक पक्ष में था और संसार के अन्य राष्ट्र उसके इतने अधिक देनदार हो गए थे कि प्रत्येक देश को अमेरिका की करंसी अर्थात् डालर की आवश्यकता थी और डालर का टोटा पड़ गया था। यदि कभी ऐसी स्थिति खड़ी हो जावे कि किसी देश विशेष का करंसी का संसार में टोटा पड़ जावे और अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष के पास भी वह करंसी कम होने लगे तो अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष उस करंसी का टोटा है ऐसी घोषणा कर देगा और जितनी भी उस देश की करंसी 'कोष' के पास होगी वह प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को उनकी आवश्यकता को ध्यान में रख कर बांट देगा। अन्य सदस्य राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष से परामर्श करके थोड़े समय के लिये अस्थायी रूप से उस देश से माल के आयात (Import) पर रोक लगा सकेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि उस देश से अन्य देशों का निर्यात (Export) कम हो जावेगा और उस की करंसी की माँग कम हो जावेगी। किन्तु व्यापार पर यह रोक केवल उतने समय के लिये लगाई जा सकेगी जितने से करंसी की वह कभी दूर की जा सके। जब अन्तर्राष्ट्रीय-द्रव्य-कोष इस बात की घोषणा कर देगा कि उक्त देश की

करसी की श्रव कमी नहीं है तो फिर हम देश के व्यापार पर कौनों बन्धन नहीं लगाया जा सकता।

अगर अतिरिक्त अन्तराष्ट्रीय द्रव्य-काय के पास किसी देश की करसी का कमा का दूर करने के और भी उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि 'कोय' उस देश में निम्नका करमा की कमी है अपना भोगा देने या उस देश में खर्च से। ऐसा करने से अन्तराष्ट्रीय द्रव्य-काय के पास उम द्रव्य का करसी अधिक मात्रा में आ जावगी और फिर वह उन मददगारों का दाँ जा सकगी जिनसे उस करसी का आनन्दकता हो। उमर लिए 'पाया' के अतिरिक्त दो उपाय और भी हैं। अन्तराष्ट्रीय बैंक (International Bank) का 'मो' की मून करसी (Scarce Currency) में अमर द मरता है जिह 'मून करसी' का आवश्यकता हो तो फिर वह देश जिनकी करमा 'मून' है मरन हो अन्य देशों की अमर द व, नहा मो उसका निर्यात (Export) पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक हो जावता। इस प्रकार अन्तराष्ट्रीय द्रव्य-काय प्रत्यक्ष 'मो' की विनिमय दर (Exchange Rates) की मर्यादा रतार का प्रयत्न करमा।

हम भी उक्त मरु अन्तराष्ट्रीय द्रव्य-कोय में एक मीमा मरु अपनी करसी केर अन्य निमा भी मरु की करसी मरान मरना है और उम मरमा के उपरान्त वह मीमा मरु कमा भी निमा देश की करमा मरान मरना है। जहाँ तक अपनी करमा मरु निमा अन्य देश का करसी मरान का मरु है प्रत्यक्ष देम अपने मरमा (मोटा) का मवल २५ प्रतिशत मरु एक वय के अन्दर मरान सकता है। जब कोई देश अपना करसी मरु मरु देश का करसी 'मो' से मरानगा तो 'मो' के पास मरान वाले देश की मरमा अधिक बढ़ जावगी। परन्तु एक वय में उम देश का 'मो' में तो मरमा (मोटा) है उसका २५ प्रतिशत से अधिक उस देश (मराने वाले) की मरमा कोय के पास मरान मराने में इकट्ठा मरु मरु मरु मरु और उम मरमा कर २०० प्रतिशत अमरान् मरुने से अधिक उस देश (मराने वाले) की करमा 'मो' में कमो मरु इकट्ठी न मीमा चाहिए।

जब कोई देश अन्य देश की करमा मरानगा तो मरमूल्य दर (Parity) के अनुसार मूल्य देने के अतिरिक्त उस देश की ३ प्रतिशत मरु का देमा होमा। परन्तु यदि 'मो' के पास निमा देश की करमा उस देश के 'मोटा' से अपिच मात्रा में लगातार मरु मराने से ऊपर मरमव तक इकट्ठा रहनी है तो उस देश की मरु, मराने मरान हो मरने के उपरान्त निमा करसी उमर मरमा से अधिक 'मो' के पास होगी उस पर बढता हुई दर से मरु देमा होमा।

पहले तीन महीने तक कोई सूद नहीं लिया जावेगा। तीन महीने के उपरान्त शेप ६ महीने के लिए $\frac{3}{4}$ प्रतिशत अतिरिक्त ($\frac{3}{4}$ प्रतिशत के ऊपर) सूद लिया जावेगा और उसके उपरान्त प्रतिवर्ष के हिसाब से $\frac{1}{4}$ प्रतिशत अधिक सूद देना होगा। इस प्रकार जितने अधिक समय के लिए करंसी ली जावेगी उतनी ही प्रतिवर्ष के हिसाब से सूद की दर $\frac{3}{4}$ प्रतिशत बढ़ती चली जावेगी। यही नहीं यदि किसी देश की करंसी उस देश के माग (कोटा) से २५ प्रतिशत से अधिक इकट्ठी हो जावे किन्तु ५० प्रतिशत से कम रहे तो $\frac{3}{4}$ प्रतिशत अधिक सूद लिया जावेगा और उसके उपरान्त प्रति २५ प्रतिशत के लिए $\frac{1}{4}$ प्रतिशत अधिक सूद देना होगा। इस प्रकार करंसी की राशि और जितने अधिक समय के लिए करंसी ली जावेगी उसी हिसाब से सूद की दर बढ़ती जावेगी। अधिक सूद लेने की व्यवस्था इस कारण की गई है जिससे विदेशों की करंसी खरीदने वाले देश जल्दी से जल्दी उस करंसी को वापस करने का प्रयत्न करें। अन्य देशों की करंसी लेने वाले देश को केवल अधिकाधिक सूद ही नहीं देना पड़ता बल्कि उसका अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोप में जितने बोझ (भन) देने का अधिकार है वह भी कम-से-कम होता जाता है और जिस देश की करंसी उसने उधार ली है उसकी बोझ बढ़ती जाती है।

सममूल्य परिवर्तन (Changes in Par Values) : प्रत्येक देश को अपनी करंसी की सममूल्य दर (Par of Exchange) में तभी परिवर्तन करने का अधिकार होगा जब अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोप उसकी अनुमति दे दे। जब तक कोई सदस्य राष्ट्र अपनी करंसी के सममूल्य (Par of Value) में केवल १० प्रतिशत तक वृद्धि या कमी करता है तब तक कोप उसमें कोई आपत्ति नहीं करेगा, अर्थात् १० प्रतिशत तक प्रत्येक देश में अपनी करंसी के सममूल्य में परिवर्तन कर सकेगा। किन्तु इसके उपरान्त परिवर्तन तभी हो सकेगा जब अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोप उसकी अनुमति दे दे।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank) : अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति और उनके पुनर्निर्माण में सहायता पहुंचाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए उन्हें ऋण देगा और अन्य देशों द्वारा दिए गए ऋण की गारंटी देगा। इस प्रकार सदस्य राष्ट्रों के औद्योगिक विकास के लिए पूँजी (Capital) की व्यवस्था करेगा, यही उसका मुख्य कार्य होगा।

साधारणतः जब कोई सदस्य राष्ट्र अपने प्राकृतिक साधनों का औद्योगिक उन्नति के लिए उपयोग करना चाहेगा और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए पूँजी चाहेगा तो वह अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को अपनी योजनाएँ बतला कर उससे गारंटी की

ब्यवस्था कर लेगा। वह सब हीनाने के उपरान्त वह सदस्य राष्ट्र संसार के प्रमुख द्रव्य-बाजारों (Money Markets) में, उदाहरण के लिए लंदन या न्यूयार्क के द्रव्य-बाजार में, अणु लेने का व्यवस्था करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक उस अणु का गारंटी कर देगा। जब क्रिया सदस्य राष्ट्र को व्यक्तिगत रूप से द्रव्य-बाजारों में अणु नहीं मिल सकेगा तब बैंक उस राष्ट्र को सीधा अपने पास में अणु देगा। जब तक किसी देश को अणु देशों से साधारणतः अणु मिल सकेगा तब तक बैंक उसे स्वयं अणु नहीं देगा। इस व्यवस्था का परिणाम यह होगा कि गिद्धे और निचन राष्ट्र जिन्होंने अपने उद्योग वृद्धि के विकास के लिए पूँजी का आवश्यकता होगा पूँजी या सहेँगे और जिन राष्ट्रों के पास बचे हुए अतिरिक्त पूँजी (Surplus Capital) इकट्ठी हो जायेगा वे बैंक का गारंटी होने के कारण उन राष्ट्रों को अणु स्वरूप द सकेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक उस अणु की अदायगी का गारंटी देगा और अपनी इस सेवा के पारिश्रमिक स्वरूप वह कर्ज लेने वाले राष्ट्र से गारंटी मिले हुये अणु पर कम से कम १ प्रतिशत और अधिक से अधिक २२ प्रतिशत फास लगा। कर्ज लेने वाले राष्ट्र का साधारण तौर पर अपनी आर्थिक योजनाओं की पूरा करने के लिए अणु न मिल सके तो अन्तर्राष्ट्रीय बैंक उन्हें अपने पास से अणु दे देगा।

निम्न अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अणु का गारंटी तभी करेगा या स्वयं तभी अणु देगा जब वह उस योजना को देख लेगा और अणु लेने वाले देश की अदायगी की क्षमता का जँच कर लेगा। साथ ही यदि अणु सदस्य राष्ट्र का सरकार नहीं ले रहा है तो वह अणु लेने वाले देश के केन्द्रीय बैंक (Central Bank) से उस अणु की अदायगी का गारंटी ले लेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की पूँजी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) १०,०००,०००,००० डॉलर है। उसमें से ब्रिटन वृद्ध द्रव्य सम्मेलन ने ६,०००,०००,००० डॉलर भिन्न राष्ट्रों में (उन ४४ राष्ट्रों में जो सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे) बाँट दी और शेष शत्रु राष्ट्रों के लिए छोड़ दी गई। प्रत्येक राष्ट्र का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का पूँजी में उनका ही भाग मिला बिना उसकी अन्तर्राष्ट्रीय कोष में मिला था। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की ४२५,०००,००० डॉलर, चीन को ५०,०००,००० डॉलर, और कनाडा को २५,०००,००० डॉलर की पूँजी अधिक दी गई और दक्षिण अमेरिका के देशों, यूगोस्लाविया, ग्रीस और फिन को कुल मिला कर २००,०००,००० डॉलर की पूँजी कम दी गई। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का वही राष्ट्र भद्र हो सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष का भी सदस्य हो।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की पूँजी का विनाश भाग प्रत्येक देश को दिया गया है उसकी केवल २० प्रतिशत पूँजी ही सदस्यों ने जुकाई है। शेष ८० प्रतिशत पूँजी सुरक्षित गारंटी के पीर पर है बिना बैंक जब चाहे मांग सकता है। वस्तु में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के मुख्य कार्य सदस्य बैंकों द्वारा लिए हुए धरा को गारंटी देना है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को बहुत अधिक पूँजी इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि कोई देश अपना धरा न जुका सके तभी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को उस धरा का दायित्व तथा उसका खर्च देना होगा क्योंकि उसने उस धरा की गारंटी दी है। ऐसी स्थिति बहुत कम उत्पन्न होगी। अतः अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के लिए यह चरम नहीं था कि वह प्रत्येक देश से उसके हितों की पूरी रकम वसूल कर लेता। अतः बैंक ने प्रत्येक देश से उसके हितों की २० प्रतिशत रकम ही वसूल की है। शेष ८० प्रतिशत जब बैंक चाहे तो वसूल कर सकता है।

प्रत्येक देश ने अपने हितों की २० प्रतिशत रकम को इस प्रकार जुकाया है :— २ प्रतिशत स्वर्ण या अमेरिकन डालर के रूप में और शेष उन देश की अपनी मुद्रा में। यदि कभी बैंक को शेष ८० प्रतिशत पूँजी को मांगना पड़ा तो सदस्य देश को सुव्यवस्थित स्वर्ण में, अथवा अमेरिकन डालर में, अथवा उन मुद्रा में जिसकी बैंक को भुगतान करने के लिए उन अपने आवश्यकता हो चुकाया होगा।

यह तो हम ऊपर कह आये हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने प्रत्येक देश ने उसके भाग का केवल २० प्रतिशत रकम ही वसूल की है। यही अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की कार्यशैली पूँजी है। किन्तु इसमें यह न समझ लेना चाहिये कि इसने ही बैंक की सदस्य देशों को धरा देने की शक्ति सीमित हो गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक धरा को गारंटी देने अथवा सीधा धरा देने के अनिश्चित आवश्यकता पड़ने पर किसी सदस्य देश के वातावरण में अपनी निष्पक्षीयता (अनपक्ष) बँककर धन जान कर सकता है और उन धन को धरा लेकर अन्य देश को दे सकता है। उदाहरण के लिए बात लें कि पाकिस्तान को अपनी औद्योगिक उन्नति के लिए धरा चाहिए और उसे अमेरिका से अक्षयकर भुगतान करना है तो स्वभावतः पाकिस्तान अमेरिका में धरा लेना चाहेगा। यदि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक पाकिस्तान की योजनाओं को ठीक समझे तो पाकिस्तान को सीधे अपने धन से धरा दे सकता है, अथवा पाकिस्तान द्वारा अमेरिका में लिए गये गये धरा की आवश्यकता को गारंटी दे सकता है। यदि इस प्रकार धरा न मिल सके तो अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अमेरिका की सहमति से अपने अक्षय्य अथवा निष्पक्षीय अमेरिका के वातावरण में वैदेशी और इस प्रकार उसे जो धन जान होता वह उसे पाकिस्तान को धरा के रूप में दे देगा। अतः अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की धरा देने की शक्ति केवल उसकी कार्यशैली

पूँजी में सीमित नहीं है।

किसी भी देश में अन्तराष्ट्रीय बैंक गारंटी के रूप में अथवा ऋण के रूप में बैंक का वित्तित पूँजी (Subscribed Capital), मुद्रागत कोष तथा अन्य वस्तु से अधिक धन नहीं देगा।

अन्तराष्ट्रीय बैंक सदस्य देशों में उस देश के वित्तीय बैंक, अथवा सरकारों को वित्तित (Treasury) के द्वारा ही कार्रवार करेगा और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र भी अन्तराष्ट्रीय बैंक से अपने वित्तीय बैंक द्वारा ही कार्रवार करेगा।

अन्तराष्ट्रीय बैंक नापे लगा देशों में हा ऋण देगा —

(१) यदि कोई सदस्य राष्ट्र को सरकार स्वयं ऋण लेना चाहे तब तो अन्तराष्ट्रीय बैंक बिना राष्ट्रीय बैंक का गारंटी के हा ऋण दे देगा अथवा जिस देश में कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है उससे ऋण देने के पूर्व अन्तराष्ट्रीय बैंक उस देश के वित्तीय बैंक से ऋण की अदायगी की गारंटी लेगा।

(२) अन्तराष्ट्रीय बैंक उस देश में आर्थिक सहायता देगा जब उसको विश्वास हो जाय कि वर्तमान स्थिति में उचित मूल्य पर उस कार्य के लिये किसी देश में ऋण नहीं मिल सकता।

(३) अन्तराष्ट्रीय बैंक उस योजना का नाच के लिये विशेषज्ञों का एक समिति नियुक्त करेगा और जब उस समिति का सम्मति में वह योजना आर्थिक दृष्टि से ठीक होती तब वह आर्थिक सहायता देगा। मन्त्रार्थ यह नहीं है कि उस योजना से प्रत्यक्ष रूप में लाभ होगा आवश्यक है। ऐसी योजना के लिये भी बैंक ऋण दे सकता है जिसका देश के आर्थिक विकास के लिए अग्रतन्त्र सदस्य हो। जिस योजना विशेषज्ञों के विचार करते हुए बैंक इस बात का ध्यान करता है कि देश के आर्थिक विकास की प्रगति में उसका मिलन किया जाय, न कि एकांगी दृष्टि से।

(४) ऋण देने समय वह हम बात का भान रखता है कि सदस्य राष्ट्र उस ऋण की चुकाने का समर्थन करता है या नहीं। यदि बैंक स्वयं किसी सदस्य राष्ट्र को ऋण देगा तब तो वह उचित मूल्य लेगा हा, परन्तु यदि बैंक किसी राष्ट्र को दिये गये ऋण का अदायगी की गारंटी देगा तब भी वह इस जोखिम के बदले में कुछ गारंटी वसूल लेगा।

बैंक इस बात की देय भाल रखेगा कि किसी राष्ट्र ने जिस योजना को कार्यान्वित करने के लिये ऋण लिया है वह रकम उस योजना पर व्यय होती है। इस दृष्टि से बैंक ऋण देने वाले सदस्यों को टेक्निकल सलाह भी देता है। इससे अलावा ऋण नहीं लेने के हालत में भी वह देश अपने आर्थिक विकास के संबंध में बैंक से टेक्निकल सलाह चाहते हैं और बैंक ऐसा सलाह देता है।

साधारणतया बैंक किसी योजना के संबंध में विदेशी विनिमय का जो खर्च होने वाला है उसके लिये ही ऋण देता है।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का प्रबन्ध : अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष (International Monetary Fund) के १२ संचालक (Directors) होंगे। उनमें से पाँच डायरेक्टर तो क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के प्रतिनिधि होंगे। इन पाँचों राष्ट्रों को एक-एक स्थायी सदस्य रखने का अधिकार होगा। दो डायरेक्टर अमेरिकन प्रजातन्त्रों की ओर से चुने जावेंगे और शेष पाँच डायरेक्टर अन्य सब देशों की ओर से चुने जावेंगे। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि फंड पर बड़े राष्ट्रों का ही प्रभाव रहेगा। भारतवर्ष ने इस योजना का इसी प्रश्न को लेकर विरोध किया था कि भारतवर्ष का व्यापारिक महत्त्व फ्रांस तथा चीन से अधिक है। इन देशों का कोटा राजनैतिक कारणों से अधिक रखा गया और भारत का कम रखा गया। फिर भारतवर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य के प्रबन्ध संचालक बोर्ड पर कोई स्थायी जगह भी नहीं दी गई। परन्तु बाद को भारतवर्ष को संचालक बोर्ड में एक जगह मिल गई। परन्तु यह कहना कठिन है कि जब सभी देश उसके सदस्य हो जावेंगे तो भारतवर्ष की चुनाव में क्या स्थिति रहेगी। उसे शेष पाँच जगहों में से एक जगह के लिये चुनाव लड़ना पड़ेगा। होना तो यह चाहिये कि भारत के महत्त्व को देखते हुए उसे एक स्थायी जगह दी जाने। यदि कोई सदस्य चाहे तो नोटिस देकर फंड से पृथक् हो सकता है।

जो स्वर्ण कोष में इकट्ठा होगा वह संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस, फ्रांस या चीन में रहेगा। कोष का प्रधान कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में रहेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के भी १२ डायरेक्टर होंगे। उनमें से पाँच डायरेक्टर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन नियुक्त करेंगे और ७ डायरेक्टर शेष सदस्यों द्वारा चुने जावेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स पर भी भारत को कोई स्थाई स्थान नहीं मिला।

रूस अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का सदस्य नहीं बना इस कारण भारत पाँच बड़े राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया और उसको बैंक के बोर्ड पर एक स्थायी स्थान मिल गया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और भारत को स्थायी स्थान प्राप्त है और शेष ७ स्थानों को शेष सदस्यों में से चुनकर भरा जाता है।

डायरेक्टर एक प्रेसीडेंट का चुनाव करते हैं। प्रेसीडेंट बोर्ड का अध्यक्ष होता है। बोर्ड ही वास्तव में बैंक का संचालन करता है।

बैंक का कार्य जैसे हा बैंक स्थापित हुआ डालर अणु के लिए की देशों न प्रार्थना पर आये किन्तु मई १९४७ में जाकर वही बैंक ने पहला अणु दिया। शायद यह बात स्पष्ट हो गई कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को अणु देने के लिए समुत्त राज्य अमेरिका के द्रव्य बाजार में अणु लेना होगा। नैटनउड्स सम्मेलन में लोगों का यह विचार था कि प्रत्येक देश जो डालर अणु लेना चाहेगा वह अपने बौद्ध समुत्त राज्य अमेरिका में बचगा और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक उनका अदायगी का गारन्टी दे दगा। विद्वानों का विचार था कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का गारन्टी अमेरिका पूँजापनियों को उन देशों में बौद्ध में अपना धन लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। परन्तु बैंक ने द्रव्य-बाजार की अध्ययनस्थित देशों के कारण अन्य देशों में बौद्ध का गारन्टी न देकर स्वयं अपने बौद्ध समुत्त राज्य अमेरिका के द्रव्य-बाजार में बैंचकर धन प्राप्त करना आरम्भ किया। बैंक का जून १९५० में समाप्त होने वाले साल का रिपोर्ट से निहित है कि मार्च १९५० में बैंक ने स्वित्स बैंकों और 'बैंक फार इन्टरनेशनल सेटिलमेंट' को भी अपने बौद्ध भेजे।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने मई १९४७ से, जबकि उसने सबसे पहला अणु स्वीकार किया था, ११ जुलाई १९५० तक जो अणु भिन्न भिन्न देशों को दिये हैं वे इस प्रकार हैं —

यूरोप	करोड़ डालर (अमेरिकन)
मान्स	२५०
मेदरलैंड्स	२२२
डेनमार्क	४०
लक्जम्बर्ग	१२
बेल्जियम	१६
फिनलैंड	१४८
टुर्की	१६४
युगोस्लेविया	०२७

कुल ५७३६

लटिन अमेरिका

चाइल	१६
मेक्सिको	६०
ब्राज़ील	६०

कोलंबिया	० ५
एलसेलेपेडर	१ २५५

कुल १८ ३५५

एशिया और मध्य पूर्व :

भारत	६ २५
इराक	१ २८

कुल ७ ५३

महा योग ८३ २७५

उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने अभी तक युरोपीय देशों को ही अधिकतर ऋण दिया है। भारत को तीन ऋण मिले हैं। पहला ऋण ३ करोड़ ४० लाख का रेलवे एंजिन, उनके हिस्से और बोगलर्स खरीदने को दिया गया था। दूसरा ऋण १ करोड़ डालर का कृषि के लिये ट्रैक्टर तथा अन्य यंत्र खरीदने के लिये दिया गया है और तीसरा ऋण १ करोड़ ८५ लाख का दामोदर घाटी योजना के लिये दिया गया है।

जून १९५० तक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा कुल ६१ ४१६ करोड़ अमेरिकन डालर का कर्ज बाँटा गया। कर्ज का यह रुपया जिन जिन देशों में खर्च हुआ उस का स्वीरा इस प्रकार है—संयुक्त राज्य अमेरिका ४५.२३ करोड़ डालर, केनाडा ३ ४८ करोड़ डालर, लेटिन अमेरिका ५ ५५ करोड़ डालर, यूरोप ६ ६७ करोड़ डालर, अफ्रिका, निकटपूर्व और सुदूरपूर्व ० ४८ करोड़ डालर।

भारत और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा बैंक : भारत इन दोनों संस्थाओं का उनके जन्म से ही सदस्य है। ३१ दिसंबर १९४५ के पहले पहले आरम्भ से ही सदस्य बनने की अवधि निश्चित थी। भारत ने २७ दिसंबर १९४५ को अपने सदस्यता के हस्ताक्षर कर दिये।

जहाँ तक रुपये के सममूल्य (पेरिटी) का संबंध या भारत ने १ शि. ६ पै. के आधार पर ही रुपये का सोने में मूल्य निश्चित किया। इस आधार पर रुपये का मूल्य ४ १ ४५ १ ४ २८ ५७ ग्रेन शुद्ध सोना तय किया गया है। 'कोष' ने इस सममूल्य को स्वीकार कर लिया। बाद में जब स्टर्लिंग का अवमूल्यन हुआ तो उसके साथ रुपये का भी अवमूल्यन हो गया। इस अवमूल्यन के फल-

स्वरूप रुपये का सोने में सममूल्य भी बदल गया।

भारत ने अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अपने हिस्से का सोना और चाँदी का हिस्सा रुपये और प्रोमिसरी नोट्स काश्तल में चुका दिया। इसी प्रकार अन्तराष्ट्रीय बैंक को अपने हिस्से का पचा (४० करोड़ अमेरिकन डॉलर) का जो भाग बैंक ने वसूल किया है (२०%) वह भी चुका दिया है।

भारत के गाँवों में बैकिंग का विस्तार आने देश में सामने सबसे बड़ा समस्या उत्पादन बढ़ाने का है। उसमें लिये पचा का आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक और तो इस बात की जरूरत है कि ग्राम जनता राष्ट्र का दृष्टि से जहाँ तक सम्भव हो अपना आय में से बचन करके उत्पादन के काम में रुकना लगाने का तैयार हो और दूसरा शीघ्र यह आवश्यक है कि इस प्रकार लोग जो कुछ बचन कर उसे उत्पादन में लगाने का ठीक ठीक व्यवस्था हो। इन दोनों ही बातों के लिये इस बात की जरूरत है कि देश में बैकिंग का अधिक से अधिक विस्तार हो और यह विस्तार गाँवों में होना चाहिए क्योंकि भारत का ६० प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में है। गाँवों में बैकिंग का विस्तार न महत्व का एक तात्कालिक कारण और है। दूसरे महापुरुष ने समय से जो महंगाई बढ़ी है उसका कारण उन किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है जो खेतिहर मजदूर का भेजा में नहीं आते हैं। पर इस बड़ी हुई आय का आज कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। अगर इस आय का कुछ भाग उत्पादन के लिये काम में आये तो देश का बहुत भला हो। इसका लिये भी आवश्यक है कि गाँवों में बैकिंग का विस्तार किया जाय।

इस समय देश में बैकिंग का विस्तार स्वयं में है। प्रभा विज्ञान बैंक ने १९४६ में व्यापारिक बैकिंग के बारे में आरम्भ प्रकाशित किया है और बैकिंग की आगि के बारे में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। उन में प्रकट हुआ है कि यदि हम केवल उन स्थानों का विचार करें जहाँ कि बैंक का दफ्तर है तो बैंक का प्रत्यक्ष दफ्तर औसतन ७/८० व्यक्तियों के पीछे है। अगर हम देश का सम्पूर्ण जनसंख्या का विचार करें तो ६२५.७६ व्यक्तियों के पीछे बैंक का एक दफ्तर आता है। दूसरा उल्लेखनीय बात यह है कि देश में इस समय जो भी इन तरह के बैंक हैं वे कुछ ही प्रांतों और शहरों में केन्द्रित हैं। इस दृष्टि से दक्खिन, मध्यम और पश्चिम बंगाल में ही बैकिंग का एक प्रमाण से केन्द्रीकरण है। यही देश के औद्योगिक प्रांत हैं। सार यह है कि गाँवों में बैकिंग का विस्तार होना चाहिए।

भारत सरकार ने पिछले वर्ष हमारे गाँवों में बैकिंग के विस्तार के प्रश्न पर जांच करने के लिये श्री पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास की अध्यक्षता में 'ग्राम बैकिंग

इन्कायरी कमेटी' नियुक्त की थी। उसकी रिपोर्ट भी अगस्त १९५० में प्रकाशित हो चुकी है। उसने गांवों में बैंकिंग के विस्तार के संबंध में अनेकों सिफारिशों की हैं। कमेटी का कहना है कि किसी एक प्रकार का बैंकिंग संगठन इस काम को नहीं कर सकता। सब प्रकार के बैंकिंग संगठनों का देश भर में समन्वय होना आवश्यक है। कमेटी ने यह कल्पना की है कि देश की बैंकिंग का ढांचा निम्न आधार पर सड़ा किया जाना चाहिये—(१) रिजर्व बैंक जिसकी प्रत्येक बड़े राज्य में शाखा या दफ्तर हो; (२) इम्पीरियल बैंक और अन्य व्यापारिक बैंक जो तालुका और तहसील के प्रमुख शहरों तथा दूसरे कस्बों तक फैले हों; (३) प्रान्तीय सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक जिन की शाखाएँ या जिन से संबंधित बैंक तमाम कस्बों और बड़े बड़े गांवों तक में हों; (४) राज्य द्वारा स्थापित राज्य के कृषि बैंक; (५) प्रत्येक प्रदेश के लिये भूमि बंधक बैंकों की शृंखला। गांवों में वचत की आदत को प्रोत्साहन देने के लिये कमेटी ने व्यापारिक बैंकों की शाखा खोलने की अपेक्षा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक पर ही अधिक जोर दिया है। सरकारों बैंकों के महत्व को भी कमेटी ने स्वीकार किया है। जहाँ तक कि गांवों में साख फी व्यवस्था करने का सवाल है, कमेटी ने अल्प-कालीन साख के लिये सहकारी बैंकों और दीर्घकालिक साख के लिये भूमि बंधक बैंकों के विस्तार पर जोर दिया है। व्यापारिक बैंकों को अपना कारोबार इन दिशा में बढ़ाने की सिफारिश भी कमेटी ने की है। साथ ही उसका यह भी कहना है कि गांव के महाजन और देशी बैंकर का बड़ा महत्व है और उनके प्रतिकूल पड़ने वाले कानूनों को बना कर उनके कारोबार की मर्यादित करने के पक्ष में कमेटी ने राय नहीं दी है। कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि गोदामों का निर्माण करके, बातायात के साधनों का विस्तार करके, रुपये लाने लेजाने की सुविधाओं को बढ़ाकर और उन्हें अधिक सस्ता बना कर, तथा ऋण, महाजन और भूमि संबंधी अन्न तक के बने हुए और नष्ट बन रहे कानूनों में महाजन आदि के अनुकूल परिवर्तन करके, तथा बैंकों की किन्हीं शाखाओं को 'शॉर्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट्स' और औद्योगिक ट्रिब्यूनल के निर्णयों से मुक्त करके हम व्यापारिक और सहकारी बैंकों को गांवों में अपना कारोबार बढ़ाने के लिये अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं।

करल बैंकिंग कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उन में कोई विशेष बात नहीं है। इस संबंध में एक बात की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। यदि हम देश के मौजूदा आर्थिक ढांचे की पृष्ठ भूमि में देश की किसी आर्थिक समस्या को हल करना चाहेंगे तो वह वास्तव में हल होगी नहीं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे

गांव व लाग कठिनाई उठाकर भी रुपया बचाने कोशिश करें, तो यह तमी हो सकता है जब उनको यह मान्य हो कि उनको इस कोशिश का लाभ उन्हें ही मिलने वाला है। इसमें शक में अगर वह आशा की जाए कि उनकी बचत का रुपया चांद पेंतावादा व्यवसाय और उद्योगों में लगाने के लिये शहरों में पहुँचाया जाय, तो इसमें क्या उफलना नहीं मिल सकती। इस लिये यदि हम गाँव वालों में रुपया बचान का आदत पैदा करने के लिये उत्सुक हैं तो वह तमी हो सकता है जब उस बचत का सीधा उपयोग गाँव के बिजार में होछके, इसका भी व्यवस्था की जाय। देश में आर्थिक विकास का जो योजना बन रही है उसने इस बात का अधिक से अधिक ध्यान रखने का आवश्यकता है। यह तमी समय हो उम्मा जब हमारा आर्थिक धनना में गाँवों की दुर्दीर उपयोगों का स्थान किसी सुनिश्चित सिद्धान्त के आधार पर नष्ट होगा और हमारे गाँवों में जो साधन आज उपयोग में नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं उनका गाँवों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से उपयोग करने पर पूरा पूरा विचार किया जायगा।

परिच्छेद ११ मुद्रा और विनिमय

रूपया पूर्ण कानूनी सिक्का : मुगल साम्राज्य के अन्तिम दिनों में उस समय के हिसाब से भारत की आर्थिक स्थिति सुव्यवस्थित थी जिसका यह अर्थ भी था कि देश में मुद्रा की व्यवस्था भी संतोषजनक थी। सोने और चांदी दोनों के सिक्कों का देश में चलन था। अकबर के समय से सोने की मुहर और चांदी का रूपया चला आ रहा था। कानून की दृष्टि से दोनों सिक्कों का तापेक्षिक मूल्य निश्चित नहीं था, पर दोनों का वजन समान था, अर्थात् १७५ ग्रेन ट्रोय। दक्षिण भारत में चांदी का सिक्का नहीं था। वहाँ का सिक्का सोने का 'पिगोडा' था। इसका कारण यह था कि दक्षिण में मुगलों का, जो चांदी का सिक्का पसंद करते थे, प्रभाव स्थापित नहीं हो सका था।

मुगल साम्राज्य के पतन के साथ देश में जो अव्यवस्था पैदा हुई उसका अंतर आर्थिक क्षेत्र में भी पड़ा। कई स्वतंत्र सिक्कों का, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था, चलन जारी हो गया। एक सिक्के को दूसरे सिक्के में बदलने का व्यापार खूब चल निकला। यह अवस्था आर्थिक दृष्टि से संतोषजनक नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापार का विस्तार करने के लिये इस स्थिति का अन्त करना जरूरी मालूम पड़ा। थोड़े बाद-विवाद के बाद आखिरकार १८३५ में यह तय हो गया कि भारत में चांदी के रुपये को पूर्ण कानूनी सिक्का मान लिया जाय। इस आशय का एक कानून बन गया। रुपये का वजन १८० ग्रेन का निश्चित हुआ और उसमें ३३ वां हिस्सा खालिस चांदी का रखा गया। सोने के सिक्कों की कानूनी हैसियत खतम होगई हालांकि उन की ठकसालें कायम रहीं। चांदी के सिक्के डालने की ठकसालें सर्वसाधारण के लिये खोल दी गईं। चांदी के रुपये का कानूनी मूल्य और उसमें की चांदी का मूल्य समान हो गया। १८३६ तक यह व्यवस्था हमारे देश में चलती रही।

स्वर्णमान की मॉर्ग : १८३५ में रूपया पूर्ण रूप से कानूनी सिक्का (कुल लॉगल टेन्डर मनी) घोषित कर दिया गया। यह वैसे तो भारतीय मुद्रा के क्षेत्र में एक बड़ा बुधार था, पर चांदी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होने से, देश की जितनी संख्या में रुपये चाहिये थे उसमें कमी रहती थी। चांदी की कमी के कई कारण थे। यूरोप के देशों ने चांदी के निर्यात पर रोक लगा रखी थी। जब यह रोक हट गई तब भी बाहर से चांदी नहीं आती थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो माल यहाँ से खरीद कर बाहर में बेचती थी उसके लिये उसकी यहाँ की आय

कासी होती थी। जब यह आय कम पड़ने लगी तो दुनिया में चाँदा का उत्पादन कम हो गया। १८५० से चाँदा के उत्पादन की यह कमी सामने आई लगी। जो चाँदी आना भी थी और निर्यात करने भी डाल लिये जाते थे तो वे रुपये ही मिलने के तौर पर काम में न लेकर चर और आदि दूसरे कामों में लिये जाते थे। यद्यपि यह है कि देश में मुद्रा का बगल नगा अनुभव होनी रही। बैंकिंग व्यवस्था का ना उस समय जिन ही क्या था, जो चाँदा के द्वारा इंग कमी को पूरा करती। नतीजा यह हुआ कि देश में सोने का मुद्रा बायम करने का माग का जाने लगा। सरकार ने यह माँग ना अस्वीकार करदा पर मुद्रा की कमी पूरा करने के लिए कागजात मुद्रा का चलन जारी कर दिया गया। १८६१ में पहला 'पपर करेंसा ऐक्ट' पास हुआ।

पर इसमें मुद्रा का नगा का समस्या हल नहीं हुई। कागजात मुद्रा का देश में चलना बड़ा नहीं। दृष्टान्तमान में पक्ष में ब्रिटिश सरकार था नहीं। भारत सरकार ने १८९४ में एक विधिति प्रकाशित की कि ब्रिटिश का ना सोने का 'सोवरेन' नाम का सिक्का है उसका मुद्रा रूप में भारत में उपयोग हो सकेगा और भारत सरकार के राजाना में 'सोवरेन' दस रुपये की और 'अर्द्ध सोवरेन' पाँच रुपये की दर से स्वीकार किये जायेंगे और जो व्यक्ति स्वीकार करेंगे उनको वे दिए भी जायेंगे। बाद में २८ अक्टूबर १८९८ को एक विधिति द्वारा यह दर बढ़ाकर १०३ १० प्रति सोवरेन करदा गई। पर इस में भी सोवरेन का देश में चलन बड़ा नहीं और मुद्रा का नगा चलना रहा। सरकार ने इस समस्या पर विचार करने के लिए 'मेसपाउट कमिशन' नियुक्त किया। उक्तो सोने का मुद्रा को कानूनी मुद्रा बनाने की सिफारिश की पर उक्तरी यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई। आगिर मुद्रा की तगा, समय से अपने आय कम हो गई। पर दृष्टान्तमान की माग देश में बना रहा, यद्यपि इस समय यह माग निर्यात हो रहा।

स्वयं पूरा कानूनी मुद्रा नहीं रहा। ऊपर हमने चाँदा का कमी का जिक्र किया है। पर अब १९५१ शताब्दी में अन्तिम चाँदा में एकदम स्थिति बदल गई और भारत में यूरोप देशों में बहुत जगह आय लगा। इसका कारण यह था कि कई यूरोपियन देशों (नर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, डालैंड, फ्रान्स, बेलजियम, स्विजरलैंड, इटली, रूस, आस्ट्रिया और जर्मनी) ने १८७१ में चाँदा को मुद्रा के काम में नहीं लेने का फैसला कर लिया और हमने बहुत चाँदा उपलब्ध हो गई। फिर चाँदी का पैदावार भी देशों समय बढ़ने लगा। साथ ही साथ चाँदा के स्थान पर सोने की मुद्राओं का यूरोपीय देशों ने चलन जारी किया। इससे सोने की माग बढ़ा। पर सोने का उत्पादन कम हो गया। इस प्रकार एक ओर तो

चांदी की मांग घटी और उसकी पूर्ति बढ़ी और दूसरी ओर सोने की मांग बढ़ी और उसकी पूर्ति कम हो गई। परिणाम चांदी की कीमतें घटने का आया। १८७५ में ५८ पैसे प्रति आउन्स से १८७६ में ५२½ पैसे, १८८८ में ४३ पैसे, १८९२ में ३७½ पैसे और १८९६ में २७ पैसे प्रति आउन्स हो गया। इसका असर हमारे और ब्रिटेन के बीच के विनिमय दर पर पड़ा और वह कम होने लगा। अभी तक विनिमय दर १ रु० = १ शि० १०½ पैसे के आस पास रहा करता था। अब वह गिरने लगा। १८७१ में विनिमय का दर १ रु० = २ शि० के था, वह १८९२ में १ रु० = १ शि० २ पैसे के रह गया।

रुपये का विनिमय दर गिरने से भारत सरकार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत सरकार को 'होम चार्ज' के लिये सोने में हर साल ब्रिटेन को रुपया भेजना पड़ता था। रुपये का विनिमय दर गिरने से भारत सरकार को इस कारण से रुपये में अब बहुत खर्च करना पड़ने लगा। इससे उसके बजट पर असर पड़ने लगा और उसे पूरा करने के लिये जनता पर कर का बोझ बढ़ाना पड़ा। फिर रुपये की विनिमय दर कम होने का नत्काल असर आया तो को मंहा करने का भी हुज्रा। निर्यात के सस्ता होने से निर्यात में विस्तार होने का लाभ अवश्य हुआ पर वह लाभ अल्पकालिक ही था क्योंकि निर्यात की मांग बढ़ने से आह्वार मूल्य वृद्धि होनी ही थी। पर मजदूर वर्ग की मजदूरी मूल्य वृद्धि के अनुपात में बढ़ती नहीं, और इस लिये सारी मजदूर को तो इससे भी हानि हुई और थोड़े से व्यवसायी उस लाभ को उठा सके। जो अंग्रेज कर्मचारी भारत में थे उनको भी विलायत रुपया भेजने में मुक़्तान होने लगा। इसके अलावा चांदी के गिरते हुए मूल्य से आने वाली विनिमय दर की अस्थिरता का विदेशी व्यापार पर घुरा असर पड़ा। उधर विदेशी पूंजी लगाने वाले भी संशंकित हो उठे क्योंकि चांदी की गिरती हुई कीमतों ने उनके मन में से विश्वास उठा दिया।

इस डांवाडोल स्थिति का हल निकालने के लिये फिर स्वर्णमान कायम करने की मांग उठी। स्वर्णमान की योजनाएं जैसे १८७२ में अर्थमन्त्री सर थार. टेम्पल की और बाद में मिट मास्टर कर्नल जे. टी. स्मिथ की योजनाएं, तैयार हुईं। पर भारत की विदेशी सरकार ने कुछ समय तो जुपचाप रहने को नानि अपनाये रखी। उधर इसी प्रश्न को लेकर १८७८ से १८९६ तक कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन रूप में हो रहे थे। वह आशा थी कि शायद सोना और चांदी दोनों ही धातुओं के चलन के पक्ष में इन सम्मेलनों का निर्णय हो जाय। यह आशा भी पूरी नहीं हुई। १८९२ की जुलाई में ब्रुसल्स सम्मेलन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका

ने भी समझ एकट को, निम्नके अनुसार मुद्रा ने भिये अमेरिका एक निश्चित मात्रा में चादी खरोदना था, रह कर दिया। इसने चादी का स्थिति और गिर गई। भारत सरकार ने आप्रकार १८८२ में इस प्रश्न पर विचार करने के लिये हाथल कमेटी को नियुक्ति का। हाथल कमेटी ने ये सिफारिश की कि सोने और चादी दोनों का मुक्त टक्का (फ्री कोण्ट्रेन्ट) बंद कर दिया जाये, स्पेसि शर्माहित कानूनी सिक्का (अनलिमिटेड लागन टेंडर) बना रह, कुछ समय तक, बिना हद तक, सोने की मुद्रा का तरह काम में लिया जाय, और आप्रकार पुरा नीर पर स्पेसिमास कायम कर दिया जाय।

भारत सरकार ने उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। १८८३ के एक कानून के अन्तर्गत रुपये का मुक्त टक्का बंद कर दिया गया, और सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे तब रुपये का टक्का करावे। एक निश्चित द्वारा १ र० = १६ पैस के दर से टक्काल में अगर काँड़ सोना या सोने का सिक्का रुपये में बदलवाने को लेजाये तो उसका बदलना अनिवार्य कर दिया गया। एक दूसरी विधि के अनुसार यदि कोई रत्ना दर में सोनरिन और अर्द्ध सोनरिन में सरकारी तुकारा करना चाहे तो जर मरगा, यह घोषित कर दिया गया। और एक तीसरा विधि द्वारा सोना या सोने के सिक्के के प्रचल में उपरोक्त दर (१० = १६ पैस) पर ही सरकार का नोट जारी करने का अधिकार होगया। इन सब आदर्शों का अर्थ यह था—(१८३५ में स्थापित मुद्रा व्यवस्था समाप्त होगई, रुपये का विनिमय दर १६ पैस से न गिर सके इसका रोक लग ग, और आम लोग सोने के सोनरिन के चलन के आदा बताय जायें, इनकी कोशिश आरम्भ हुई, तथा रुपये असाहित कानूनी मुद्रा के रूप में बना रहा, यद्यपि यह पूर्ण मुद्रा नहीं रहा। इस व्यवस्था का सब से बड़ा दोष यह था कि जिस प्रकार सरकार पर सोने या सोने के सिक्के के बदले में रुपये देने का ज़िम्मा था उसी प्रकार रुपये के बदले में सिक्का देने का ज़िम्मा उस पर नही डाला गया।

फाउलर कमेटी रुपये का मुक्त टक्का जब बन्द होगया तो रुपये का विनिमय दर उँचा जाने लगा। १८८४ में औसत विनिमय दर १ र० = १६ शि० १२ पैस के थी। १८८६ तक १ शि० ४ पैस तक विनिमय दर पहुँच गया था। १८८८ के अंत तक मुद्रा का तगा भा फिर अनुभव होने लगी। भारत सरकार ने यह सोचा कि सोने के सिक्के का चलन जारी करने का यह उपयुक्त समय है। इस प्रश्न पर विचार करने के लिये १८८८ में उसने फाउलर कमेटी का नियुक्ति की।

फाउलर कमेटी ने सारे प्रश्न पर विचार किया। उसने सामने कुछ दूसरे स्थितियों द्वारा पक्ष की गई सोचनेवाले भी था। उदाहरण के लिये लिडसे और

प्रोबोन योजनायें थीं। लिन्डसे योजना के अनुसार किन्हीं निश्चित दरों पर भारत में भारत सरकार द्वारा लन्दन पर स्टर्लिंग बिल बेचने और लन्दन में भारत मन्त्री द्वारा भारत पर रुपया बिल बेचने की बात कही गई थी ताकि रुपये का विनिमय दर एक मर्यादा से न नीचे गिर सके और न ऊपर जा सके। स्टर्लिंग बिल की दर १५ $\frac{3}{4}$ पैसे और रुपया बिल की दर १६ $\frac{3}{4}$ पैसे सुझाई गई थी। इन बिलों का जुकारा करने के लिये भारत में और लन्दन में स्वर्णमान कोष (गोल्ड स्टैंडर्ड रिज़र्व) कायम करने की बात थी। फाउलर कमेटी ने यह योजना नापसंद कर दी क्योंकि उसकी राय में यह ठीक नहीं था कि भारत की स्वर्णमान पद्धति का आधार इंग्लैंड में रखा जाने वाला छोटा सा कोष हो। प्रोबोन की योजना का सार यह था कि भारत में स्वर्णमान तो कायम हो पर देश के अन्दर सोने के सिक्के का चलन न हो। योजना यह थी कि मौजूदा दस हजार के नोट तो रह कर दिये जायें और नये दस हजार के नोट सोने के एवज़ में हो जारी हों और उनके एवज़ में लेने वाले की इच्छानुसार सरकार सोना या रुपया देने की तैयार रहे। अनुमान यह था कि देश के अन्दर उपयोग के लिये तो कोई इतने बड़े नोटों के एवज़ में सोना चाहेगा नहीं। इस लिये केवल अन्तर्राष्ट्रीय जुकारे के लिये ही सोने का उपयोग होगा। फाउलर कमेटी को यह योजना भी पसंद नहीं आई। कमेटी के सामने फिर से चांदी के मान (सिल्वर स्टैंडर्ड) को कायम करने का सुझाव भी आया था पर वह भी उसे मंजूर नहीं था।

फाउलर कमेटी की सिफारिशें : सारे प्रश्न पर विचार करने के बाद फाउलर कमेटी ने यही सिफारिश की कि भारत में सोने के सिक्के के चलन सहित स्वर्णमान की स्थापना होनी चाहिये और सोने के आयात-निर्यात की पूरी स्वतन्त्रता रहनी चाहिये। इसके लिये नीचे दी गई बातों की कमेटी की राय में आवश्यकता बताई गई—(१) सोवरिन और अर्द्ध सोवरिन कानूनी सिक्के मान लिये जायें और भारत में उनके मुक्त टंकन की व्यवस्था की जाय; (२) रुपये का मुक्त टंकन बंद रहे हालांकि रुपया असीमित कानूनी सिक्के के रूप में चलता रहे; (३) रुपये का विनिमय दर १ शिल्लिंग ४ पैसे निश्चित कर दिया जाय; (४) भारत सरकार सोने के बदले में रुपये देने का ज़िम्मा नो रहने दे, पर रुपये के बदले हमें सोना देने का ज़िम्मा न ले; (५) जब तक सोने के सोवरिन, अर्द्ध सोवरिन की मात्रा आवश्यकता से अधिक न हो जायें, सरकार नए रुपये न डलवाये, पर नए रुपये जब भी डाले जायें तो उससे होने वाले लाभ से एक नया कोष कायम किया जाय, इस कोष में सोना रहे; (६) जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन भारत के विरुद्ध चला जाय और उसकी पूर्ति के लिये सोने का निर्यात

करता हो तो सरकार उपरोक्त कोष में नया और जोरों में न और चलन में न सोना उपलब्ध करने की व्यवस्था करे। उपरोक्त मुद्रा पद्धति का मनेर में पर सार आता था कि सोना और चादा दोनों के बिना अर्थमित्र कानूनी मुद्रा के रूप में माने जायें, दोनों का मापनिक मूल्य निर्दिष्ट हो, पर मन्त्र टकन देवन सोने व सिक्कों का हो।

फाउलर कमेटी का मानना था कि 'उक्त' मुद्रा पद्धति में मन्त्र करने से मन्त्र मान वाल देशों में भारत का जो अधिस्त्य व्यापार है उस व्यापार में अनिश्चितता नष्ट रहेगी, और विदेशी पूँजी का भाग में लगाने का प्रोत्साहन मिलेगा, तथा मुद्रा का नाम दूर होगा।

सरकार की फार्मलाइज्ड फाउलर कमेटी में जो सुझाव दिये थे उसकी कार्यान्वित करने का सरकार ने प्रयत्न किया। मोन्टगुमरी और 'ग्रैंड' मोन्टगुमरी की १८८६ व एक्ट द्वारा फाउलर कमेटी द्वारा प्रस्तावित दर पर कानूनी मुद्रा का रूप दे दिया गया। (६) मन्त्र ने नये रुपये इलाजों और जो लाभ हुआ उससे गोल्ड स्टैंडर्ड रिपार् (स्वर्णमान कोष) कायम किया गया। रुपये का प्रतिमय दर १ सि० ४ पै० तक पहुँच हा गया म और उस कायम रखा जा रहा था। रुपये का मन्त्र टकन था और उसे अर्थमित्र मुद्रा व रूप में माना हुआ था ही। सोने व रुपये में सरकार तथा ना था। अब तो सोने के सिक्के चलाने की व्यवस्था कायम करने का मन्त्र और था पर फाउलर कमेटी का यह सिफारिश ब्रिटिश ट्रेजरी के विरोध करने में कार्यान्वित नष्ट हुई। भारत में स्वयंसाय कायम करने व लिये यह पहला आवश्यक शर्त था, और यहाँ पूरा नष्ट की जा सका।

स्वर्णमान से स्वर्ण प्रतिमय मान की और रुपये बाद भारत का मुद्रा पद्धति में कुछ ऐसा घटनाय परिदृष्टिनिश्चय घटी कि स्वर्णमान का घनाय एक दूसरा हा पद्धति—स्वर्ण प्रतिमय मान—की स्थापना हमारे देश में होगी। इस पद्धति की कायम करने का बाद सोचा हुआ निश्चय नष्ट था, न भारत सरकार ने ही यह सोचा था कि इस समय उसर द्वारा किये गए निर्णयों का यह निर्णय आयेगा। यह सब कैसा हुआ, इस सम्बन्ध में अब हम लियेंगे।

स्वर्णमुद्रा के चयन का प्रयत्न १८८६-१९०० में भारत सरकार ने सोव रिन और ग्रैंड मोन्टगुमरी का, जो अब कानूनी मुद्रा प्रसार दे दिय गये थे, चलन जारी किया। पर लोगों ने उन्हें स्वीकार नष्ट किया और वे लौट लौट कर सरकार के पास वापिस आने लगे। सरकार ने यह सोचा कि सोने के सिक्कों का भारत में चलन हो हा नहीं सकता। वास्तव में वान यह था कि भीषण अकाल पड़ जाने में उस समय आम जनता की छोटे छोटे सिक्कों की विशेष माँग थी।

फिर सरकार ने एक मूल वह की कि ठीक इसी समय नए रुपये भी डलवाये और इस वजह से भी सोने के सिक्कों का जनता में प्रवेश होना कठिन हो गया। सरकार को इस प्रकार जल्दों से निर्णय नहीं कर लेना चाहिये था। जरूरत होने पर सरकार द्वारा नोट और सोवरिन के बढ़ले रुपया देने की अनिवार्यता को भी समाप्त करके सरकार को इच्छा पर रुपया देने न देने की बात छोड़ी जा सकती थी। पर उन्ची बात तो यह है कि बिना पूरा प्रचल किये सरकार ने यह मान लिया कि भारत में सोने के सिक्के लोक प्रिय नहीं हो सकते। सोने के सिक्के डालने के लिये टकराल कायम करने का सवाल १९१२ में दुबारा उठा। भारत मंत्री ने दस रुपये के बराबर का सोने का सिक्का डालने की स्वीकृति भी देदी। पर भारत सरकार ने चेम्बरलेन कमीशन की राय के लिये यह प्रश्न उस समय छोड़ दिया।

स्वर्णमान कोप : जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं सन् १९०० में नए रुपये डालने से जो नुनाफा हुआ उससे स्वर्णमान कोप की स्थापना तो करदी गई, पर उसमें फाउलर कमेटी की राय के विरुद्ध कुछ वातें हुईं। वक्ताब खारा कोप सोने की शकल में रखने के, भारत मंत्री ने यह फ़ैसला किया कि वह लंदन में स्टर्लिंग सिम्प्रीटिज की शकल में रहे। नये रुपये डालने के लिये बांदी पेपर करेन्सी रिज़र्व के सोने से खरीदी जानी थी। १९०६ में स्वर्णमान कोप की रुपये की शाखा भी हिन्दुस्तान में कायम की गई। १९०७ में फाउलर कमेटी की सिफारिश के विरुद्ध भारत मंत्री ने यह फ़ैसला भी कर दिया कि नए रुपये डालने से होने वाले नुनाफे का आधा हिस्सा उस समय तक भारत में रेलवे विकास के लिये अलग रखा जाय जब तक कि स्वर्णमान कोप में २ करोड़ पाउण्ड नहीं हो जाते हैं।

कौंसिल ड्राफ्ट : भारत में स्वर्ण विनिमय गान पद्धति कैसे कायम होगई यह समझने के लिये कौंसिल ड्राफ्ट का पद्धति के बारे में जानकारी करना आवश्यक है। भारत सरकार को हर साल 'होम चार्ज' का कुछ रुपया ब्रिटेन में भारत मंत्री को भुक्ताना पड़ता था। इसके लिये भारत मंत्री भारत सरकार पर रुपये में बिल फाटते थे। ये बिल भारत मंत्री ब्रिटेन में उन लोगों को बेच देते थे जिन्हें व्यापार आदि किसी कारण भारत को रुपया भेजना होता था। बदले में भारत मंत्री को स्टर्लिंग मिल जाते थे। बिल खरीदने वाले उन विलों का हिन्दुस्तान में उनके लेनदार को भेज देते थे। चूंकि वे बिल भारत सरकार के नाम कटे होते थे इसलिये वे लेनदार भारत सरकार से रुपया नगूल कर लेते थे। इन विलों को कौंसिल ड्राफ्ट इस वजह से कहते थे कि भारत मंत्री अपनी कौंसिल सहित अपना काम करता था। ये बिल या ड्राफ्ट भी उस कौंसिल के नाम पर पुकारे जाने लगे।

१८६२ तक भारत मया जाने रुपये के कागजि द्राफ्ट भेजते थे जिसका रुपया 'होम चार्ज' के नाम का भारत सरकार को भारत मया का नुकारा करने के लिए सूच करवा पड़ता था। १८६३ के बाद कुछ वर्षों तक इस कौंसिल द्राफ्ट का बचना भारत मया कभी-कभी, रुपया की विनिमय दर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से, बका कर देता था। अर्थात् विनिमय दर का एक निश्चित दिशा में नियंत्रण करने के लिए इन कागजि द्राफ्ट का उपयोग होना लगा। मगर १८६८ में इसका उपयोग भारत में मुद्रा की मात्रा बढ़ाने के लिये किया जाने लगा। इन द्राफ्ट को बेचने से भारत मया का जा माना मिलता यह बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भारत सरकार का पेश करना विज्ञापन में उठा हो जाता और उसके एवज में भारत सरकार हिन्दुस्तान में पोट जारी कर देती। बाद में इस गौरे का उपयोग नये रुपये डालने के लिये आवश्यक चादी मुद्राओं में किया जाने लगा था, जैसा पहले किया जा चुका है। १८७४ में भारत मया ने यह घोषणा कर दी कि रुपये के विनिमय दर को १ शि० ४३ पै० से ऊपर न जाने देते के लिये निम्ने कौंसिल बिल या द्राफ्ट बेचने की आवश्यकता होगी उनसे बेचेंगे। अर्थात् कौंसिल बिल का उपयोग विनिमय दर का अनुक मर्यादा से ऊँची जाने से रोकने के लिए भी होना लगा। मिस और आस्ट्रेलिया से जो सोवरेन भारत जाते थे उनको भारत जान से रोकने और उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए इस सोवरेन के बदले में १ शि० ४ पै० से १ शि० ४३ पै० तक के दर पर टिकायात्रिक ट्रान्सफर बेचने का फैसला भी किया गया। भारत सरकार यह मानती थी कि भारत में 'सोवरेन' की आवश्यकता नहीं है और इसलिये उनका भारत को निर्यात नहीं होने देना चाहिये। भारत मया द्वारा बराबर बेचे जाने वाले कौंसिल बिलों का नुकारा करने के लिए भारत सरकार के पास हर समय पर्याप्त मात्रा में रुपये का होना आवश्यक था। इसलिये जैसा ऊपर लिखा जा चुका है स्वयंमान कीय को रुपये या चाँदी की राशियाँ भारत में आगम की गई। कौंसिल बिलों की बिक्री द्वारा भारत स्थित स्वयंमान कीय और दूसरे कोषों का महत्व बढ़ाने के लिये एक सरल तरीका निम्न आया। इस प्रकार भारत में स्वयं विनिमय मान पद्धति को चालू रखने के तराजे के एक अनिवार्य अंग का कागजि बिलों के रूप में विद्यमान हो गया। स्पष्ट मान कीय का उपयोग यह भी सम्भवा गया कि इससे आधार पर १ शि० ४ पै० की दर पर सोवरेन को स्पष्ट में बदलने के लिये भारत सरकार हर समय तैयार रह सकता है। १८६३ की यह धिसति भी वापस ले ली गयी जिसने अनुसार 'सोवरेन' से अलग सोने के बदले में भी नोट या रुपये जारी करने का भारत सरकार को अधिकार था।

ऊपर हम लिख चुके हैं कि काँसिल विलों का उपयोग स्वर्ण विनिमय मान-पद्धति को कायम रखने के लिये होने लगा। पर काँसिल विलों का उपयोग रुपये की विनिमय दर को एक मर्यादा से ऊपर जाने से रोकने का ही हो सकता था। स्वर्ण विनिमय मान को कायम रखने के लिये यह भी जरूरी था कि रुपये की विनिमय दर अनुक्त मर्यादा से नीचे भी न गिरे। क्योंकि स्वर्ण विनिमय मान-पद्धति का अर्थ हो यह था कि रुपये का पींड के, जो स्वर्ण मान पर आधारित मुद्रा थी, साथ एक निश्चित विनिमय दर बना रहे। रुपये की विनिमय दर को एक निश्चित मर्यादा से नीचे गिरने से रोकने के लिए काँसिल विल तो काम दे नहीं सकते थे। इसलिए किसी दूसरे उपाय की आवश्यकता थी। वह उपाय १९०७-८ में 'रिवर्स काँसिल विलों' के रूप में निकल आया। बात यह थी कि जब विदेशी व्यापार के संतुलन के भारत के विवक्षित जाने से रुपये की विनिमय दर गिरने लगी तो उसे रोकने की भारत सरकार को आवश्यकता हुई। भारत सरकार ने भारत मंत्री पर स्टर्लिंग में विल काट करके उन लोगों को बेचना शुरू कर दिया जिन्हें लंदन स्टर्लिंग मेजना था। इस प्रकार भारत सरकार को रुपये में जुकारा करके खरीदने वाले इन विलों को अपने लेनदार को लंदन मेज दिया करते थे और वहां यह भारत मंत्री से स्टर्लिंग वसूल कर लिया करता था। भारत मंत्री इन 'रिवर्स काँसिल विलों' का जुकारा करने के लिये पेपर करंसी रिज़र्व के सोने, और गोल्ड स्टैंडर्ड रिज़र्व की सिक्कुरिटीज़ का उपयोग करता था। पेपर करंसी रिज़र्व से जितना सोना इस काम में लिया जाता था उसके एक्ज में पेपर करंसी रिज़र्व की भारत की शाखा में उतनी क्रिमिट के रुपया जमा कर दिये जाते थे। भारत सरकार रिज़र्व काँसिल १ शि० २३१ पै० प्रति रुपये के हिसाब से बेचती थी। इन विलों का नाम 'रिवर्स काँसिल' इस वजह से पड़ा कि रुपये की विनिमय दर पर भारत मंत्री द्वारा बेचे जाने वाले काँसिल विलों से बिल्कुल उल्टा (रिवर्स) अंतर इनका पड़ता था। इनको बेचने का एक अंतर यह भी हुआ कि भारत सरकार के पास जो सोना विभिन्न कोषों में था उसमें काफ़ी कमी आ गई। इस पर से १९०६ में भारत सरकार ने भारत मंत्री के पास एक तो यह प्रस्ताव रखा कि स्वर्ण मान कोष में कम से कम २३ करोड़ पींड रहने चाहिये और वे सोने की शक्ति में न कि सिक्कुरिटीज़ की शक्ति में होने चाहिये। भारत मंत्री ने २३ करोड़ पींड की बात तो मान ली पर वह सब सोने की शक्ति में रहे वह उसे स्वीकार नहीं हुआ। केवल १० लाख पींड बैंक जमा या अल्पकालिक धन में रखने को वह तैयार हुआ। भारत सरकार ने दूसरा प्रस्ताव यह किया था कि पेपर करंसी रिज़र्व में जितना सोना है उसका २/३ भाग भारत में रहना चाहिये

क्योंकि भारत में सोवरेन का चलन बढ़ता जा रहा था और इसके लिये पेर करसी रिज़र्व में रुपये की आपूर्ति होना रहना ज्यादा आवश्यक था। पर भारत मंत्र ने इस प्रस्ताव को चिल्लुन अस्वाकार कर दिया।

स्वर्ण विनिमय मान पद्धति में प्रमुख लक्षण भारत में स्वर्ण विनिमय मान (गोल्ड एम्बैज स्टैंडर्ड) की स्थापना किंग प्रकार बिना किसी पूर्ण विश्वास में हो गई, इसका विवरण ऊपर आ चुका है। इस मुद्रा पद्धति में मुख्य-मुख्य कारण ये थे —

(१) रुपये असोमित कानूनी मुद्रा था और कानून में अन्तर्गत सोन में उसका परिवर्तन नहीं हो सकता था।

(२) सोवरेन और अर्ध सोवरेन भा असोमित कानूनी मुद्रा मान लिये गये थे और १५ रुपये का एक सोवरेन माना गया था।

(३) एक सोवरेन में १५ रु० में दिखाव के भारत सरकार रुपये का एक्ज में सोवरेन दिया करता था हालांकि उसपर हमबान का कानूनी हिस्सा नहीं था।

(४) सोना, सोवरेन या स्टैरलिंग में एक्ज में आ लन्दन में दिया जाता था १ सि० ४३ पै० प्रति रुपये में दिखाव से भारत सरकार क्लॉक या बम्बई में रुपये या रुपये में नोट चलने का बराबर पैसा रहनी था। यही कीमत बिना जो प्रथा था।

(५) इस प्रकार भारत सरकार भारत में रुपये लेकर १ सि० ३३ १/२ पै० में दर से लन्दन में भेजा, सोवरेन या स्टैरलिंग देने का पैसा रहनी भी। ये हा 'रिपर्स काउन्सिल' को चलने का प्रथा था।

न० ४ और ५ में दिय गये लक्षण इस पद्धति में आधारभूत लक्षण थे क्या कि यही में दाया रुपये और सोना या सोवरेन आपस में एक दूसरे में बदले जा सकते थे। इस काम में लिय भारत मंत्र ने पाग जा पपर करसी और गोल्ड स्टैंडर्ड के काय में माना उपलब्ध होता था उसका था जो नरुद उसके पास रहता था उसका उपयोग वह करता था। इसी प्रकार भारत सरकार भा गोल्ड स्टैंडर्ड रिज़र्व को रुपये की आपूर्ति, भारत स्थित पपर करेंसी रिज़र्व, और नरुद जो उस के पास हो उसका उपयोग करता था। इस प्रकार पपर करेंसी रिज़र्व और नरुद रुपये जो कि इस काम के लिये नहा थे उनका भा रुपये का विनिमय दर को स्थिर रखने में उपयोग हो जाता था, हालांकि ऐसा करना सहा नहा था। इस मुद्रा पद्धति में धार में देश में एकमत नहा था। कुछ लोगों की राय में इसमें कम खर्च था और लोभ था जब कि कुछ की राय यह था कि इस में स्थिरता का अभाव था और इसमें संस्थापन भी नहा था।

चेम्बरलेन कमीशन : १९१३ की अप्रैल में आस्टिन चेम्बरलेन की अध्यक्षता में इस समस्या की जांच करने के लिये एक कमीशन बैठा और फरवरी, १९१४ में उसने अपनी रिपोर्ट दी। कमीशन ने यह राय दी कि स्वर्णविनिमय मान पद्धति ठीक-ठीक चल रही है और सोने के सिक्के का चलन बरतरी नहीं है। भारत-वासियों की इच्छा पूरी करने के अलावा सोने के सिक्के डालने के टकसाल की देश में कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्णमान कोष की मात्रा बढ़नी चाहिये, उसमें केवल सोना होना चाहिये और वह लंदन में रहना चाहिये। रुपये की शक्ति समाप्त कर देनी चाहिये। रुपये डालने से जो लाभ हो उसका सिवाय इस कोष में जमा करने के दूसरा कोई उपयोग कुछ वर्षों तक तो नहीं होना चाहिये। भारत सरकार की २ शि० ३३½ पैसे की दर से रिवर्स कौन्सिल्लि बेचने की बराबर तैयार रहना चाहिये।

प्रथम महायुद्ध : प्रथम महायुद्ध में ब्रिटेन ने व्यक्तियों द्वारा देश से सोना निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्ट्ररलिंग के प्रयत्न में सोना मिलना बंद हो गया और भारत की मुद्रा पद्धति स्वर्ण विनिमय मान की बजाय स्ट्ररलिंग विनिमय मान पर स्थापित हो गई। लड़ाई का असर रुपये की विनिमय दर को कम करना भी हुआ, क्योंकि रुपये पर से लोगों का विश्वास उठता हुआ लगा। रिवर्स कौन्सिल्लि की बिक्री के जरिये विनिमय दर गिरने से रोक गई। बाद में १९१६ के अन्त तक कोई खास बात सामने नहीं आई। पर फिर भारतीय मुद्रा की कई कारणों से मांग बढ़ने लगी। एक कारण तो यह था कि भारत से दूसरे देशों को निर्यात बढ़ा क्योंकि युद्ध सामग्री के लिये आवश्यक माल यहाँ से मित्र राष्ट्रों को भेजा जाता था। इससे विदेशी व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में हो गया। युद्ध से पहले तो सोना और चांदी भेजकर इस संतुलन को बराबर किया जाता था पर लड़ाई के कारण इन धातुओं के निर्यात पर तो रोक थी। इस लिये वह उपाय काम में लिया जाने लगा कि जिन्हें भारत की रपया खुलाना होता था वे भारत में ही द्वारा बेचे जाने कीविल बिल लंदन में खरीद कर भारत में भेज देते थे और भारत सरकार को यहाँ उनका चुकारा करना पड़ता था और इसके लिये उनको रुपये की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा भारत सरकार को भी युद्ध के कारण काफी खर्च करना पड़ता था और ब्रिटिश सरकार और मित्र राष्ट्रों का और का खर्च भी उसे यहाँ करना होता था। इससे भी रुपये की मांग बढ़ने का परिणाम आता था।

इस वृत्ति हुई रुपए की मांग के पूरी करने का एक उपाय नए रुपए डालना

(६) २६ जून, १९१७ को सोने और चांदी के सिक्कों का, सिक्कों के अतिरिक्त और दूसरे प्रकार के उपयोगों पर कानूनी रोक लगा दी गई। भारत में जितना भी सोना बाहर से आयात किया जाये वह सभी इत्तों नारीख के एक आर्डिनेन्स के अनुसार भारत सरकार के सुपुर्द करना अनिवार्य कर दिया गया ताकि उसके 'सोवरिन' ढाहो जायें। इस उद्देश्य से अगस्त १९१८ में एक सोने सिक्के का मिन्ट भी कायम हुआ पर अप्रैल, १९१९ में वह बंद हो गया।

(७) नई कागजी मुद्रा को जारी किया गया और उसको रुपये में परिवर्तन की सुविधाये कम कर दी गई ताकि नई कागजी मुद्रा के जारी करने में इस कारण कम अड़चन महसूस हो।

(८) सरकार ने युद्ध के अतिरिक्त और बातों पर खर्चा कम करने का प्रयत्न किया और साथ ही कर अथवा ऋण के द्वारा जनता से ज्यादा रुपया बगूल करने का प्रयत्न किया।

वेविंगटन स्मिथ कमेटी : उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रथम महायुद्ध के समय में देश की मुद्रा प्रणाली अस्तव्यस्त हो गई। ३० मई, १९१६ को भारत मंत्री ने श्री हेनरी वेविंगटन स्मिथ की अध्यक्षता में इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक कमेटी की नियुक्ति की। कमेटी को मुख्य-मुख्य सिफारिशें नीचे लिखे अनुसार थी :—

(१) रुपये का सम्बन्ध स्टर्लिंग की बगह सोने से होना चाहिये क्योंकि स्टर्लिंग की स्थिरता का कमेटी को भरोसा नहीं था। विनिमय दर के बारे में कमेटी ने १ रु० = २५ शि० (सोना) की सिफारिश की थी। इस ऊंची दर को निश्चित करने का कारण यह था कि अगर चांदी का मूल्य ४३ पैस प्रति औंस से भी ऊपर चला जाय तब भी रुपये की विनिमय दर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कमेटी चाहती यह थी कि रुपये का सोने के साथ ऐसा विनिमय दर निश्चित किया जाय कि चांदी के मूल्य में संभवतः जितनी वृद्धि का अनुमान किया जा सकता है उतनी वृद्धि होने पर भी रुपये की विनिमय दर पर असर न पड़े। रुपये का सोने के साथ सम्बन्ध रखने का कमेटी के सामने एक कारण यह भी था कि बिना इस संबंध के रुपये और सोवरिन दोनों का देश में एक साथ चलन बावजूद दोनों के कानूनी मुद्रा होने के असंभव हो सकता है, क्योंकि उनका आपसी मूल्य उस हालत में सोने के रुपये में मूल्य के उतार-चढ़ाव के साथ बदलता रहना आवश्यक है।

(२) रुपये की विनिमय दर जब २ शि० सोना तक पहुँच जाये तो युद्ध-कालीन सोने और चांदी के आयात पर जो प्रतिबंध हैं उन्हें हटा लेना चाहिये।

(३) सोवरेन का टंकन करने व लिये सम्मान में दुबारा रोदन मिटका शास्त्रा क्रियम होना चाहिये।

(४) सोवरेन व बदले म रुपये देने का निम्मा सरकार को ध्यान पर नहीं रखना चाहिये नकि चाँदा का क्रयन यदि बढ़ जाय मब भी सरकार को परेशानी न हो।

(५) सम्मान काय पर रक्षम की हो मपादा नहीं रहनी चाहिये। उसमें सोने का अंश काय माया म होना चाहिये और बाका निक्यूमिट्रीज में लगाना चाहिये। कुल सोने का आधा भाग भारत में रहना चाहिये।

(६) भारत मया का अपना आवश्यकता न अधिक कौंसिल बिल सराइन पालो व प्रतियोगिता व आधार पर बचना चाहिये। विनिमय दर जब गिरने लगे तो रिबन कौंसिल या भारत सरकार को बरना चाहिये।

भी दलाल का मतमद सर दादा माद दलाल इस पक्ष में नहीं थे कि रुपये की विनिमय दर १ रु० = २ शि० माना चिनना ऊँचा रखा जाये। वेदवार आर लेनगार के आपसी व्यवहार पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, निर्वाण करने पालो को हानि होगा, और कामगरी मुद्रा व कारों का जिनका अंश सोने या स्टर्लिंग चिकूरीदाय का शकल म है उसका करने म क्रयन कम हो जायगा। नारी व मूल्य को बढने में रोकने व लिये, या सम्मान के निमत, सरकार को चाँदी व नियान पर स रोक हटा लेनी थी, और नथ रुपये दालना बढ करके नया भारत मया की जबरन व अनुमान ही कौंसिल रिपोर्ट को बेचकर भी इस स्थिति को सरकार उम्हाल सकती थी।

सरकार का निर्णय भारत सरकार ने कमेटी व सम्मान का सम्मान काय को और परदरी १९२० म कने विनियम प्रकाशित करने नीचे लिखे कदम उठाये —

(१) रुपये का विनिमय दर २ शि० माना हा निश्चित किया गया।

(२) चाँदी के आयात और चाँदा सोने व सिक्कों को मदाने पर स प्रतिषेध हटा निवे गये। चाँदा में आयात का भी हटा लिया गया। २१ कुल को सोना और सोने के सिक्का के आयात पर स रोक हटा ला गई। सरकार के चाँदा में धुकारा करने पर स प्रतिषेध हटा लिन गय और नोटों को रुपये में बदलने की प्रवृत्त सुविधायें फिर से बारा कर दा गय।

(३) सोवरेन और अर्द्ध सोवरेन व बदले म रुपया देने का सरकार का निम्मा हटा लिया गया।

(४) जून २१, १९२० के एक्ट आर्डिनेंस से सोवरेन और अर्द्ध सोवरेन का

कानूनी मुद्रा की हैसियत समाप्त कर दी गई, पर २१ दिन तक १५ रु० प्रति सोव-रिन के हिसाब से सरकार ने उनकी स्वीकार करने की घोषणा कर दी। उस के बाद ब्रिटिश सोने के सिक्कों के भारत में आयात पर जो प्रतिबंध था वह भी हटा लिया गया। १९२० के इंडियन कोयनेज एक्ट के अन्तर्गत सोवरिन और अर्ध सोवरिन १० रु० और ५५० के दर से फिर कानूनी मुद्रा करार दे दिये गये। पर सोवरिन का बाजार-भाव इस से अधिक था और इसलिये मुद्रा के रूप में इनका चलन नहीं हो सका। इसी कारण से सोने की टंकियां खोलना भी अनावश्यक समझा गया। सोने के बाजार-भाव को कम करने के लिये भारत सरकार आयात का सोना अपने सुपुर्द करा कर बाजार में सोने की सितम्बर १९१६ से ही पब्लिक बिक्री करनी शुरू कर दी थी पर जब वेविंगटन कमेटी ने २शि० सोने की विनिमय दर निश्चित की थी तब भी सोने का बाजार-भाव ऊंचा था। फरवरी १९२० और सितम्बर १९२० के बीच में भी सरकार ने काफी सोना बेचा। पर जब तक सरकार बिक्री करती रही तब तक तो सोने का भाव कुछ मंदा रहा और ज्योंही बिक्री बंद हुई कि भाव फिर ऊंचा चला गया। भारत सरकार इस काम में विल्कुल असफल रही।

(५) यह घोषणा कर दी गई कि प्रति सप्ताह खुले ट्रेन्डर से कौंसिल ब्राफ्ट और 'टेलीग्राफिक ट्रान्सफर' की बिक्री होगी और रुपये की विनिमय दर में जब कमजोरी मालूम पड़ेगी तो भारत की लन्दन सोना भेजने के खर्च पर आधारित दर के हिसाब से 'रिजर्व कौंसिल्स' भी बेचे जायेंगे।

२ शि० सोने की विनिमय दर की असफलता : जब २ फरवरी, १९२० को रुपये का विनिमय दर २ शि० सोना तब हांगका तो रुपया स्टरलिंग दर बढ़ने लगा और ११ फरवरी, १९२० को यह दर २शि० १० $\frac{3}{4}$ पें. प्रति रुपया तक पहुंच गया। विनिमय दर के बढ़ने से इससे भी सहायता मिली कि निर्यात के व्यापारियों ने अपने निर्यात विलों को शुमाने की जल्दी करना शुरू कर दिया ताकि विनिमय दर के बढ़ने से होने वाले नुकसान से वे बच सकें। विनिमय दर २ शि. १० $\frac{3}{4}$ पेंस स्टरलिंग तक पहुंच गई तो उसका गिरना आरंभ हुआ। इसके कई कारण थे। निर्यात के व्यापारियों द्वारा निर्यात विलों की बिक्री तो कम हो गई और आयात करने वालों की ओर से बढ़ी हुई दर से लाभ उठाने के लिये स्टरलिंग की मांग आने लगी। हमारे विदेशी व्यापार का संतुलन बिपन्न में चले जाने से भी विनिमय दर में गिरावट आने लगी। सरकार ने रिजर्व कौंसिल्स की बिक्री द्वारा विनिमय दर को गिरने से रोकने का प्रयत्न किया पर उसमें बड़ा फल नहीं हुआ। सरकार ने हार मान कर २ शि. सोने की बजाय २४ जून, १९२०

से १ शि स्टर्लिंग की दर पर कायम रखने का निर्णय किया। पर विनिमय दर तो गिरता ही गई और सरकार को उस हिसाब से खर्च करने द्वारा निश्चित दर का बम करना पड़ा। बाजार दर से सरकार की दर कुछ ऊँचा अवश्य रखा जाता था। आगिरकार हार मान कर सरकार ३ सितम्बर १९२० के अन्त में विनिमय दर पर नियन्त्रण रखने का इरादा ही ठाढ़ दिया। इस मौक़े पर भारत सरकार ने ५ करोड़ ५० लाख ८० हजार पाँच के रिज़र्व कीमिन्स बेचे जिन का मुक़ाबला करने के लिये पार क़ानून रिज़र्व का स्टर्लिंग डिपॉज़िट बैंक ऑफ़ इंग्लैंड को नुस्तान उठाकर मा बचना पड़ा क्योंकि ५६ प्रति पाँच दर में वसूली हुई थी और ७ म १० के तब तक दर पर ने बचना पड़ी। रिज़र्व कीमिन्स की बिक्री से देश में मुद्रा सङ्कुचन भी हुआ। सरकार ने विनिमय दर का उस नियन्त्रण करना छोड़ा था उस समय १ शि १० पैसों पर दर था। दिसम्बर १९२० में १ शि ५१ पै, दिसम्बर १९२१ में १ शि ३६ पै और अप्रैल १९२२ में १ शि ३३ पै हो गई था।

असफलता के कारण विनिमय दर के नियन्त्रण में सरकार का इस असफलता का मुख्य कारण यह था कि बेविंगटन कमेटी ने देश की मुद्रा स्थिति का जो निदान किया वह सत्य था और सरकार ने उसी सत्य निदान के अनुसार कार्यवाही की। बेविंगटन स्मिथ कमेटी की यह धारणा थी कि चांदी का मूल्य बढ़ जाने से ही रुपये का विनिमय दर बढ़ा और इस लिये उन्होंने रुपये का विनिमय दर इतना ऊँचा निश्चित करने की सिफारिश की कि विरचान का मूल्य बढ़ जाने से कोई बढ़बड़ा पैदा हो गये। कमेटी का इस ओर भी ध्यान नहीं गया कि चांदी का मूल्य स्थानीय रूप में इतना ऊँचा रहने वाला नहीं था। इसने अलावा चांदी की क़ामत बढ़ने का एक कारण यह था कि रुपये और स्टर्लिंग दोनों का ही चीनो में सामान्य मूल्य गिर गया था और इसलिए चांदी में भी उसका मूल्य गिर गया था। रुपया सांकेतिक मुद्रा के रूप में बना रहे और उसका चलन जारी रहे इस लिये तो आवश्यकता यह थी कि रुपये में चांदी का मात्रा कम कर दी जाते न कि उससे विनिमय दर को बढ़ाना। इस अलावा चाहे रुपये का सांकेतिक मुद्रा का रूप में रहता तब भी उसका चलन तो जारी रहता ही, क्योंकि क़ानून म रुपये चलन में थे। जब बेविंगटन स्मिथ कमेटी की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार किया तब चांदी का मूल्य गिरने लग गया था और ४४ पैसों प्रति औंस तक आ गया था। कारण यह कि कमेटी ने रुपये को इतना ऊँचा विनिमय दर की सिफारिश कर दी गली कि और उन्नत भी नहीं गनी सरकार ने उस सिफारिश को मान कर और अन्त में

दिखते हुए भी उस पर खमे रहने का प्रयत्न करके की। सच्ची बात यह थी कि रुपये की जो शक्ति थी उसके हिसाब से कहीं अधिक उसकी विनिमय दर को कायम नहीं रखा जा सका।

विनिमय दर का १ शि० ६ पै० तक पहुँचना : वह हम ऊपर लिख चुके हैं कि जब सरकार ने विनिमय दर का निर्वन्धन करना छोड़ दिया था तो विनिमय दर बराबर कम होती गई पर थोड़े समय के बाद परिस्थिति बदली। यूरोपीय देशों की शक्ति बढ़ने से १९२२-२३ में हमारा विदेशी व्यापार बढ़ने लगा। इसके अलावा विनिमय दर को ऊँची रखने के प्रयत्न में देश में मुद्रा संकुचन भी कारगर हुआ था। १९२१-२२ और १९२२-२३ में लंदन में जो स्टर्लिंग सिक्यूरिटीज़ थी वह भारत मंत्री की गैरुद्ध में जमा करवी गई, और इंडियन ट्रेजरी बिल जो रिज़र्व में थे उनको भी रुपये में बदल लिया गया। इसका असर भी मुद्रा संकुचन का हुआ। नतीजा यह हुआ कि एक ओर तो नियांत के बढ़ने से और दूसरी ओर मुद्रा संकुचन से रुपये के विनिमय दर में फिर वृद्धि होने लगी। सितम्बर १९२३ में रुपये की कीमत १ शि० ३½ पै० सोना के बराबर थी और उस समय प्रथम महायुद्ध के पहले का १ शि० ४ पै० का विनिमय दर फिर से आसानी से निश्चित हो सकता था। पर सरकार ने ऐसा न करके विनिमय दर को बढ़ने दिया। कॉंसिल बिलों के स्थान पर अब सरकार ने इंपीरियल बैंक और विदेशी विनिमय बैंकों के द्वारा स्टर्लिंग खरीदना शुरू कर दिया। ये स्टर्लिंग तो भारत मंत्री के पास रह जाता और भारत में सरकार बैंकों को रुपये में स्टर्लिंग के एचज में सुकारा कर देती। अप्रैल, १९२५ में जब इंग्लैंड ने फिर स्वर्णमान स्वीकार कर लिया तो रुपये का विनिमय दर १ शि० ६ पै० सोना हो गया। सितंबर १९३१ तक यही विनिमय दर कायम रखा गया।

डिफ्लेशन बंग कमीशन की स्थापना : २५ अगस्त, १९२५ को भारतीय मुद्रा और विनिमय पर विचार करने के लिए लेफ्टीनेंट कमान्डर हिल्टन बंग की अध्यक्षता में एक शाही कमीशन की नियुक्ति हुई। ४ अगस्त, १९२६ को इस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कमेटी की सिफारिशों को विषय के आधार पर तीन भागों में बाँटा जा सकता है—(१) मुद्रा मान (मोनिटरी स्टैंडर्ड) (२) विनिमय दर और (३) केन्द्रीय बैंक। हम इस परिच्छेद में पहले दो विषयों के बारे में ही विचार करेंगे। नीचे विषय के बारे में पिछले परिच्छेद में लिखा जा चुका है।

स्वर्ण विनिमय मान के दोष : हिल्टन बंग कमीशन ने मुद्रा पद्धति के

बारे में अपना राय देने से पहले स्वर्ण विनिमय मान पद्धति के दोषों का उल्लेख किया। कमोशन का राय में ये दोष इस प्रकार थे—

(१) स्वर्ण विनिमय मान सरल पद्धति नहीं था और रुपये और सोने का मन्थ साधारण जनता को स्पष्ट नहीं हो सकता था। कौंसिलबिल्ड, और रिजर्व कासिल रिल्ड का इस पद्धति में स्थान, रुपया नोट, और सोवरेन तथा ब्रद मोवरेन का शान्ना मुद्रा होना पर सोवरेन ब्रद मोवरेन का चलन में नहीं होना और नोट के बदले में रुपये मिल सकता—ये सब धर्मादमी पैदा करने वाला बातें थीं।

(२) इस पद्धति में मुद्रा का सञ्चन या विस्तार किमी निश्चित परिस्थिति में अपने आप न होकर सरकार का इच्छा अनिच्छा पर निर्भर था। कौंसिल बिलों के बदले अगर सरकार सञ्चन में रुपये नुका दिये जायें तो रुपया का विश्वास नहीं होता और इंगी तरह रिजर्व कौंसिल का सुवारा गोल्ड स्टैडर्ड रिजर्व से उधार लेकर कर दिया जाय तो मुद्रा का सञ्चन नहीं होता। इस तरह से मुद्रा विस्तार और मुद्रा सञ्चन के जो ये उपाय थे उनका असर मुद्रा विस्तार और मुद्रा सञ्चन का होगा हो, ऐसा अनिवाय नहीं था।

(३) देश में पेपर करेंसी रिजर्व नोटों का नष्ट म परिवर्तन करने के लिये, गोल्ड स्टैडर्ड रिजर्व रुपये के बदले सोना देने और इस प्रकार रुपये का विनिमय दर स्थिर रखने के लिये, और सरकारा सञ्चन सरकारा रोन-बनौन व काम को चलाने के लिये कायम किये गये थे। पर वास्तव में इन कोषों और सरकारी सञ्चनों का उपयोग अपनी-अपना मर्यादा में होना नही था। जैसे पेपर करेंसी रिजर्व का उपयोग विनिमय दर को स्थिर रखने के लिये या नया ढालने के लिये चादा लौटाने में कर लिया जाता था और गोल्ड स्टैडर्ड रिजर्व का उपयोग भी मौका पड़ने पर कर लिया जाता था। देश में विभिन्न बैंकों के कोष भी थे पर उनका और करेंसी रिजर्व का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं था। इसके अलावा गोल्ड स्टैडर्ड रिजर्व में वास्तव में सोना ही हो या वह भारत में ही रखा जाना पेटा नहीं था। स्टोरिंग सिम्यूरिटोड में भी वह रिजर्व रहता था। १९०६ में इस रिजर्व का रुपये का शायद गुना पर बाद में चेम्बरलेन कमोशन का राय पर यह नद करदा गई। पेपर करेंसी रिजर्व का भा एक भाग लंदन में रखा जाता था।

(४) स्वर्ण विनिमय मान में कुछ और दोष भी थे। यह किसी सोचा-समझा हुई नीति या योजना के अनुसार स्थापित किया गया ही, ऐसी बात नहीं थी। इसका कुछ आधार तो कानूनी था पर जैसे कौंसिल और रिजर्व कौंसिल बिलों का नेचने की प्रथा का आधार कोई कानून नहीं था। कौंसिल बिलों को नेचने

का अन्तर भारत में सोने के आयात पर प्रतिकूल पड़ता था।

(५) इस पद्धति का एक गुण तो यह बताया जाता था कि बिना सोने के सिक्के का खर्च किये स्वर्णमान का लाभ देश को मिल जाता था। पर इस बारे में मतभेद था। प्रत्यक्ष स्वर्णमान से जनता में जो भरोसा पैदा होता वह तो इससे पैदा हो ही नहीं सकता था। दूसरा इसका गुण यह था कि रुपये का विनिमय दर में स्थिरता रहती थी पर उसी के साथ रुपये की आन्तरिक मूल्य शक्ति की स्थिरता जो अधिक महत्वपूर्ण थी इसके द्वारा प्राप्त नहीं होती थी।

उपर्युक्त कारणों से हिल्टन यंग कमीशन ने इस पद्धति को अस्वीकार कर दिया।

कुछ विकल्प : हिल्टन यंग कमीशन के सामने कुछ विकल्प उपस्थित किये गये थे। उनमें से एक तो यह था कि स्टैरलिंग या स्वर्ण विनिमय मान में ही सुधार किया जाये। पर कमीशन भारत की मुद्रा पद्धति का किसी दूसरे देश की पद्धति पर आश्रित रखने के सिद्धान्तन ही विरोध में था। फिर स्टैरलिंग या स्वर्ण विनिमय मान में यह दर तो था ही कि चांदी के मूल्य में अचानक मर्यादा के बाध वृद्धि हो जाने पर चांदी के रुपये को सिक्के के तौर पर काम में लेना लाभप्रद न होने से उसका चलन न रहे। तीसरे बड़े माधारण में विश्वास पैदा करने के लिये आन्तरिक उपयोग के लिये रुपये को सोने में बदलना आवश्यक था। इसलिये ये विकल्प कमीशन ने स्वीकार नहीं किये।

अब रहा सोने के सिक्के के साथ स्वर्णमान स्थापित करने का। कमीशन सोने के सिक्के के पक्ष में भी नहीं था क्योंकि उसे भय था कि इस कारण से एक ओर तो सोने की इतनी मांग बढ़ेगी कि न तो उसे पूरा करना संभव होगा और उस से खनार का उपयोग-व्यापार भी अस्त-व्यस्त हो जायगा, क्योंकि बीजों का रोल में मुख्य गिर जायगा। इससे भारत की भी हानि होगी। दूसरे उसे चांदी की कीमत गिर जाने का भी भय था। यह भी उन भारतीयों के लिये जिसके साथ चांदी जमा है हानिकर होगा।

गोल्ड जुलियन स्टैण्डर्ड : कमीशन ने अपनी राय 'गोल्ड जुलियन' स्टैण्डर्ड के पक्ष में दी। उसने जो सिफारिशें की वे ये थीं :—

(१) चांदी के रुपये और नोटों का चलन बदलूँ जारी रहे।

(२) सोने का सिक्का चलन में रखना आवश्यक है। इसलिये सोवरेन और आर्द्ध सोवरेन को कानूनी मुद्रा न माना जाये। इस से यह लाभ भी होगा कि देश में जो रिजर्व में सोना है उसका उपयोग खान्ना व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में हो सकेगा।

बारे में आसानी से भरोसा हो सकता है। कमीशन ने इस बारे में यह अवश्य कहा था कि बाद में जब सोना रिजर्व में पर्याप्त मात्रा में हो जाय तो सोने का भिना अग्रर जरूरी समझा जाय तो चालू किया जा सकता है।

माराश यह है कि स्थान विनिमय मान को अस्वीकार करके तो हिटलर यय ने मुर्ही पैगना किया पर भारत में सोने के भित्ति वाला स्वर्ण मान स्थापित करने की भिफारिश न करने भारत का अहित किया। उस समय भारत में भाने के सिर्फ धोला स्वर्ण मान कायम करना चाहिये था।

विनिमय दर की समस्या: हिटलर यय कर्माशन के सामने रुपये की विनिमय दर १ शि० ६ पै० तय किया जाय या १ शि० ४ पै० यह बहुत बाद विवाद का प्रसूत रहा। बाद में भा हमारे देश में यह बाद विवाद बहुत वर्षों तक चलता रहा। कर्माशन ने यमुन में १ शि० ६ पै० का पन में राय दा और उग्रर नाचे दिये कारण उपस्थित रिये —

(१) कामना और मन्तूरा न जन न इस दर के साथ सामन्त्य बैठ गया है।

(२) जो अन्तराष्ट्रिय मुद्राहिद (कोट्रेरद) के डा पर तो विनिमय दर को १ शि० ६ पै० तय करने का कोई अस्तर पड़ेगा नहीं। और जो लान जैते साथ रानिज मुद्राहिद है उनका म कर्माशन का यह कहना था कि १९१४ न बाद कृषि पदार्थों का मूल्य बढ़ जाय से उग्रर लगान देने वालों पर वास्तविक भार कम हो गया है।

१ शि० ४ पै० न निरुद्ध कर्माशन ने कई तर दिये थे जैसे —

(१) मूल्य और मन्तूरा का इस दर में सामन्त्य नहीं हुआ था।

(२) उग्रमोनाश्रा और मरकारु मिल व्यवस्था पर १ शि० ४ पै० की दर का मुरा अग्रर पड़ेगा।

कर्माशन का इस साथ से मर पुरुषोत्तमदास टाडुरदास सहमत नहीं थे और १ शि० ४ पै० न पन में उन्होंने अपनी राय दा था। उन्होंने जो कारण पेश किये थे वे इस प्रकार थे —

(१) यह इस से इनकार करत थे कि १ शि० ६ पै० में मूल्यों और मन्तूरा का सामन्त्य हो गया था।

(२) भारतीय उद्योग ने लिए यह दर (१ शि० ६ पै०) हानिकर होगा क्योंकि इसका अस्तर नियान को कम करने और आयात का प्रोत्साहन देने का उस समय तर होगा जब तक कि मूल्य का इसके साथ सामन्त्य न बैठ जाये।

(३) कनधारों पर, और अधिकांश नियान कर्जदार हैं, कर्ज न बोले

अधिक हो जायगा क्योंकि १ शि० ४ पैस की विनियम दर के समय का लिया हुआ कम है।

(४) दूसरे देशों ने भी मुद्रा के पूर्व के विनियम दर को फिर स्वीकार किया है। भारत को भी ऐसा ही करना चाहिये।

(५) सरकारी वित्त व्यवस्था और उन उपभोक्ताओं को जो साथ-साथ उत्पादक भी नहीं है अधिक महत्व देना आवश्यक नहीं है।

सर्वा बात यह है कि १ शि० ४ पैस की विनियम दर ही तय होना चाहिये थी। ब्रिटिश व्यापारों और व्यवसायी वर्ग और भारत के ब्रिटिश राज कर्मचारियों का हित तो बराबर इसी में रहा कि रुपये की विनियम दर ऊँची रहे ताकि भारत में कीमतें कम रहें और विलायत रुपया भेजने में लाभ रहे। इसके अलावा इस विनियम दर से मूल्यों और मजदूरी के सामंजस्य हो जाने पर भी, १ शि० ४ पैस की विनियम दर से जित भारतीय व्यवसायों ने मशीनें आदि खरीद लीं थी वे उस हद तक अपने ब्रिटिश प्रतिद्वन्द्वियों का मुकाबला करने में मुकद्दाम में रहने वाले थे जब तक कि वे उस दर से लगी पूँजी को कम ही नहीं कर देते। पर लगी हुई पूँजी का मूल्य घटाने को कोई व्यवसायी तैयार नहीं होता है।

उपरोक्त बातों के बावजूद कमीशन ने १ शि० ६ पै० के विनियम दर की सिफारिश की और भारत सरकार ने उसे स्वीकार किया।

कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार की कार्रवाई : कमीशन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने १६२७ में इंडियन करेंसी एक्ट पास किया। इसके अनुसार—

(१) रुपये का विनियम दर १ शि० ६ पै० तय कर दिया गया और उसे कम होने से रोकने का कानून से सरकार को जिम्मा सौंपा गया।

(२) सरकार को २१ व० ३ आ० १० पाई प्रति तोला के भाव पर ४० तोले से कम मात्रा में सोना नहीं खरीदना था और सोना या स्टरलिंग जो भी सरकार की इच्छा हो इसी भाव पर लंदन में देने के लिये, सोना हो तो कम से कम ४०० औंस की मात्रा में और स्टरलिंग हो तो उस मूल्य के बराबर स्टरलिंग, बेचना था। स्टरलिंग के बारे में सम्बन्ध से लंदन भेजने का खर्च अवश्य बसूल करजा था और इस दृष्टि से भारत सरकार ने १ शि० ५ १/४ पै० की दर की घोषणा की थी।

(३) सोवरिन और अर्द्ध सोवरिन के कानूनी मुद्रा का रूप खतम कर दिया गया। पर सरकार पर यह जिम्मा रहा कि वे अपने खजानों और करेन्सी

ओरिसों में १३ रु० ५ आ० ४ पा० प्रति मोनरिन व हिस्सों से इन गिरों का स्वीकार करें।

इस प्रकार भारत सरकार ने 'गोल्ड बुलियन कम स्टारलिंग एक्सचेंज स्टैंडर्ड' की स्थापना की। कमीशन की सिफारिश व अनुसार विगुड गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड यह नहीं था क्योंकि सरकार पर सोना या स्टारलिंग दोनों में से कोई धारण हज्जानुमार बेचने का निम्मा था न कि कबल सोना बेचने का। वृत्ति स्टारलिंग स्वयंमान पर आधारित था इस नियम इसे स्वर्ण विनिमय मान मो कहा जा सकता है। यह स्वर्ण विनिमय मान पहले वाले स इस अर्थ में अशुद्ध था कि इस सरकार पर कानून न सोना या स्टारलिंग बेचने का भी निम्मा था, ज्ञानी मरीदने का हा नहीं। और तब बागों में यह पहले स्वर्ण विनिमय मान की तरह दोगुनी था।

विनिमय दर १६-७-३१ इन वर्षों में कथ व विनिमय दर का प्रवृत्ति १ शि० ६ पै० से नाचे की ओर जाने को रहा और उस १ शि० ६ पै० पर कथन रखने के लिये सरकार का बैंक रेट को ऊँचा करके, मुद्रा सङ्कुचन करके, और ट्रेजरी बिल्लु जारी करके विराग रूप में प्रपन्न करा। पछा। जो लोग १ शि० ४ पै० व पछ में स डाक्री बराबर यह शिकायत रही कि वास्तव में १ शि० ४ पै० व साथ मूल्यों का सामञ्जस्य बैठा नहीं था और ने बराबर विनिमय दर कम करने व पछ में आन्दोलन करते रहे। यह सही है कि १९२६ की विश्वव्यापी मारी का भी मूल्यों व गिरने और विदेशी व्यापार व सङ्कुचन व विपन्न में जाने में हाथ था पर वह भा स्वीकार करना पड़ेगा कि विनिमय दर ऊँचो होने व स्थिति बिगड़ी और बाद में उसने मुधार में बाधा भी पहुँची।

१९३१ का सङ्कट विश्वव्यापी मारी का सामना करने व लिये २० सितंबर १९३१ को इंग्लैंड ने स्वर्ण मान का त्याग कर दिया। २१ सितंबर १९३१ का पहले वा भारत सरकार ने एक आर्डिनेंस इस आशय का जारी कर दिया कि १९२७ व करेमी एक्ट व मागहन जो सरकार पर सोना या स्टारलिंग बेचने का निम्मा था उससे यह मुक्त रहेगी। पर उसी दिन भारत मारी ने स्वर्ण की १ शि० ६ पै० की दर से ही स्टारलिंग व साथ सबविन रखने की घोषणा कर दी। २४ सितंबर को गवर्नर जनरल ने एक आर आर्डिनांस, 'गोल्ड एन्ड स्टारलिंग सहस्र रग्लेशन आर्डिनेंस', जारी किया जिसन २१ सितंबर व आर्डिनेंस को रद्द किया और १९२७ व करमा एक्ट को वापिस लागू कर दिया, पर व्यवहार में स्टारलिंग की बिक्री पर कुछ प्रतिबंध भी लगाय—जैसे स्टारलिंग केवल स्वीटन बैक को हा १ शि० ५-११ पै० की दर पर बचा जाना था, या सामान्य व्यापारिक आवश्यकता पूर्ति के लिय और २१ सितंबर व पहले के कॉन्वेंशन

को पूरा करने के लिये, या व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरत पूरी करने के लिये ही बेचा जाना था। सोना चांदी का आयात करने या विदेशी विनिमय संबंधों [स्मैकूलेटिव] लेन-देन के लिये स्टरलिंग की चिन्ती बन्द कर दी गई थी। इस प्रकार हमारे देश में नियंत्रित स्टरलिंग विनिमय मान की स्थापना हो गई।

स्टरलिंग का सोने में मूल्य गिरता जा रहा था। इसका असर रुपये का सोने में मूल्य गिरने का भी हुआ ही क्योंकि स्टरलिंग के साथ रुपये का संबंध स्थिर कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में सोने का मूल्य बढ़ने लगा। १९३१ के अगस्त के अन्त में सोने की कीमत २१ रु० १३ आ० ३ पाई प्रति तोला थी, वह दिसम्बर १९३१ में २६ रु० २ आ० प्रति तोला हो गई। तब से सोने की कीमत बराबर बढ़ती गई है और आज तो वह १०० रु० तोला से भी अधिक है। सोने के भाव में तेज़ी आने से लोगों ने अपने पास जो सोना जमा था उसे बेचना शुरू किया और सोना भारत से बाहर जाने लगा। इस प्रकार करोड़ों रुपये का सोना बाहर चला गया। बदले में स्टरलिंग की मात्रा बढ़ गई और ३१ जनवरी १९३२ को सरकार ने 'गोल्ड एंड स्टरलिंग सेल्स रेगुलेशन आर्डिनेन्स' रद्द कर दिया। कानून की दृष्टि से तो १९२७ का करेंसी एक्ट फिर लागू हो गया जिसके अनुसार सरकार पर सोना या स्टरलिंग बेचने का जिम्मा था पर व्यवहार में भारत मंत्री का रुपये का १ शि० ६ पैसे की दर पर स्टरलिंग से संबंध रखने का निर्णय ही लागू रहा।

रुपया-स्टरलिंग संबंध : बिना भारतीय जनमत का विचार किये जब भारत सन्नी ने रुपया-स्टरलिंग सम्बन्ध स्थिर कर दिया तो देश में इस का बहुत विरोध हुआ। रुपया-स्टरलिंग संबंध की निश्चित करने के पक्ष में जो कारण दिये जाते थे वे ये थे :—

(१) भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार स्टरलिंग वाले देशों से है और स्टरलिंग में भारत को बहुत सा चुकारा करना पड़ता है इसलिए रुपया-स्टरलिंग सम्बन्ध में निश्चितता होना आवश्यक है।

(२) स्टरलिंग के साथ साथ सोने की रुपये में भी कीमत बढ़ेगी। वर्णमान के देशों के साथ विनिमय दर घटेगा और फलतः थोड़े समय के लिये ही सही पर उनके साथ का हमारा निर्यात व्यापार बढ़ेगा।

तो तर्क रुपया-स्टरलिंग सम्बन्ध को स्थिर करने के विरुद्ध दिये जाते थे ये थे :—

(१) किसी भी देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा पर इस प्रकार

ओक्सिडों में ११ ६० ५ आ० ४ पा० प्रति मोनरिन व हिंसॉब से इन पिक्सों का स्वीकार करें।

इस प्रकार भारत सरकार ने गोल्ड बुलियन कम स्टर्लिंग एन्ड स्टैंड को स्थापना की। बर्माइन की सिफारिश के अनुसार विशुद्ध गोल्ड बुलियन स्टैंड यह नहीं था क्योंकि सरकार पर सोना या स्टर्लिंग दोनों में से कोई अपने इच्छानुसार बेचने का निम्मा था कि केवल सोना बेचने का। चूंकि स्टर्लिंग स्वयंमान पर आधारित था इस नियम से स्वर्ण विनिमय मान भा जा सकता है। यह स्वर्ण विनिमय मान पहले बाले से इस अर्थ में अच्छा था कि घर परफार पर कानून से सोना या स्टर्लिंग बेचने का भी निम्मा था, आली सरोरने का ही नही। और मय बातों म यह पहले स्वर्ण विनिमय मान की तरह दोषपूर्ण था।

विनिमय दर १६२७-३१ इन वर्षों में दरय व विनिमय दर का प्रति १ शि० ६ पै० से नीचे का और जाने की रही और उम १ शि० ६ पै० पर काम रखने के लिय सरकार को बैंक रेट को ऊँचा करने, मुद्रा सङ्कुचन करके, और ट्रेजरी बिल्लु जारी करके विशेष रूप से प्रयत्न कराया गया। जो लोग १ शि० ४ पै० के पक्ष में थे उनको बराबर यह सिकायत रही कि वास्तव १ शि० ४ पै० के साथ मूल्यों का सामञ्जस्य बैठा नहीं था और ये बराबर विनिमय दर कम करने के पक्ष में आशोलन करते रहे। वह सही है कि १६२६ की विश्वव्यापी मरी का भी मूल्यों के गिरने और विदेशी व्यापार के घुलन के विपक्ष में जाने में हाथ था पर यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि विनिमय दर ऊँची होने से मा स्थिति बिगड़ी और बाद म उसका सुधार म बाता भी पहुँचा।

१६३१ का सकुट विश्वव्यापी मदी का सामना करने व लिये २० सितंबर १६३१ को इंग्लैंड ने स्वर्ण मान का स्वाग कर दिया। २१ सितंबर १६३१ का पहले तो भारत सरकार ने एक आर्डिनेन्स इस आशय का जारी कर दिया कि १६२७ व व रेसा एक्ट व मानहग जो सरकार पर सोना या स्टर्लिंग बेचने का निम्मा था उससे वह मुक्त रहेगी। पर उन्ही दिन भारत मंत्री ने रुपये को १ शि० ६ पै० की दर से ही स्टर्लिंग के साथ संबंधित रखने का घोषणा कर दी। २४ सितंबर को मन्तर जनरल ने एक और आर्डिनेन्स, 'गोल्ड एन्ड स्टर्लिंग सेल्ल रेगुलेशन आर्डिनेन्स', जारी किया जिसने २३ सितंबर के आर्डिनेन्स को रद्द किया और १६२७ व व रेन्सी एक्ट को वापिस लागू कर दिया, पर व्यवहार में स्टर्लिंग की बिनी पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए—जैसे स्टर्लिंग बेचने स्वीकृत बैंकों को ही १ शि० ५ १/२ पै० की दर पर बेचा जाना था, या सामान्य व्यापारिक आवश्यकता प्रति के लिये और २१ सितंबर के पहले के कोट्रेन्ड्स

भी ठीक है कि अगर रुपये-स्टरलिंग का सम्बन्ध १ शि० ६ पैं० से ऊँचा निश्चित होता तो सोने के निर्यात में अवश्य कमी आती क्योंकि विदेशों में सोने की रुपये में कम कीमत मिलती।

जहाँ तक यह सवाल है कि इतना सोना देश से बाहर चला गया, यह ठीक था या नहीं, इस बारे में भी वैसे तो दो रायें थीं। एक पक्ष का कहना था कि यह अच्छा हुआ कि इतने ऊँचे दामों पर सोना बिक गया क्योंकि इससे लोगों को काफ़ी लाभ हुआ तथा ज़रूरत के समय पैसा मिल गया। सरकार की वित्त व्यवस्था और देश के व्यापारिक संतुलन पर इसका इन लोगों की राय में अच्छा असर हुआ। सोने के निर्यात के बढ़ते में या वैसे खरीदने से सरकार के पास स्टरलिंग जमा हो गया और बढ़ते में सरकार ने रुपये या नोटों में चुकावा कर दिया। इसका एक और तो यह नतीजा हुआ कि सरकार के पास जो स्टरलिंग था उसका उपयोग तो विदेशों के कर्ज़ को चुकाने में कर लिया गया, और दूसरी ओर रुपये की मात्रा के बढ़ जाने से व्याज की दर में कमी आ गई और उससे देश के आर्थिक विकास में सहायता मिली। इस पक्ष का यह भी कहना था कि अगर सरकार सोने पर निर्यात-कर लगा देती तो वह बेचने वाले पर ही पड़ता क्योंकि उसे बेचने की ज़रूरत ज्यादा थी। अगर सरकार स्वयं सोना खरीद कर अपने पास जमा रखती तो वह इतने सोने का करती क्या? पर एक दूसरा पक्ष भी था जो यही ठीक समझता था कि सरकार को सोना अपने पास जमा करना चाहिये था। स्टरलिंग जिसका मूल्य गिरता जा रहा था सरकार ने अपने पास जमा करके भूल की। इसके अलावा अब सोने का मूल्य बढ़ता जा रहा था उस समय सोना बेच कर व्यक्तिः और राष्ट्र ने भी काफ़ी मुफ़्तान उठाया। बात यह थी कि जहाँ तक लोगों के पास जो सोना जमा था और वह निकल कर बाहर आ गया यह तो अच्छा हुआ। पर यह सोना सरकार को और बाद में रिज़र्व बैंक को अपने पास रखना चाहिये था और आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करना चाहिये था। इस प्रकार उसको विदेश जाने देना देश के हित में नहीं था।

विनिमय दर में परिवर्तन की माँग जारी : यह हम लिख चुके हैं कि जब १९२७ में १ शि० ६ पैं० की विनिमय दर निश्चित की गई तो उसका बड़ा विरोध था। उसके बाद से द्वितीय महायुद्ध आरंभ होने तक विनिमय दर को कम करने की माँग बराबर उठती रही। १९२६ की विश्वव्यापी मंदी के आरंभ होते ही, खास तौर से जब सरकार को १ शि० ६ पैं० की दर कायम रखने में कठिनाई हो रही थी और निर्यात गिर रहा था, वह माँग उठाई गई। १९२९ में जब रुपया-स्टरलिंग का संबंध स्थिर किया गया तो यह प्रश्न उठा। रिज़र्व बैंक

आभित कर देना और उसकी स्वतन्त्रता को छीन लेना, जैसा कि रुपये का स्टर्लिंग से सम्बन्ध निश्चित कर देने से हुआ, ठीक नहीं है। हिस्टन यंग कमीशन ने स्पष्ट शब्दों में इसका विरोध किया था।

(२) भारत जैसे देश में रुपये की आन्तरिक मूल्य शक्ति और मूल्यों तथा उत्पादन की स्थिरता का विदेशी विनिमय की स्थिरता की अपेक्षा बहुत कम महत्व है।

(३) वर्तमान के देशों के साथ के निर्यात में जो कुछ भी लाभ हो उसी के साथ आयात में होने वाला हानि का और इंग्लैंड की जो अपने आने से साम्राज्यात्मक सख्त (इम्पीरियल प्रिन्सिपल) मिल जाये वाला है उसका भी ध्यान होना चाहिये।

(४) कुछ लोगों का यह भी मन था कि स्टर्लिंग के अवमूल्यन के बावजूद भी १ शि० ६ पैसों को दर भारत के लिए ऊँची थी और इसलिये वह दर पर स्टर्लिंग सम्बन्ध स्थिर करने के विरोध में था।

(५) १ शि० ६ पै० की दर पर स्टर्लिंग रुपये का सम्बन्ध स्थिर करने का ही यह परिणाम था कि भारत से इतना सोना विदेशों की चला गया कि भारत के हित में नहीं हुआ। इस राय के अन्तर्गत स्टर्लिंग के मुकाबिले में रुपये का मूल्य कम आया गया, अर्थात् रुपये का विनिमय दर ऊँची निश्चित होना चाहिये थी। इस दृष्टिकोण से सब लोग सहमत नहीं थे।

उपरोक्त विमर्श का कारण यह है कि रुपये का स्टर्लिंग के साथ सम्बन्ध निश्चित कर देना अनुचित था। भारत का अपने आर्थिक विकास का आवश्यकता को ध्यान में रख कर अपनी स्वतन्त्र विनिमय नीति बनाना चाहिये था। कुछ लोगों का यह राय था कि स्टर्लिंग के साथ सम्बन्ध का निश्चित किया जाना पर कम दर पर।

सोने के निर्यात की समस्या भारत से रुपये का स्टर्लिंग के साथ सम्बन्ध हो जाने पर करोड़ों रुपये का सोना विदेश चला गया, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। सोने के इस निर्यात के बारे में पहली बात ध्यान में रखने की यह है कि जो सोना निर्यात हुआ वह ऐसा सोना था जो लोगों ने आर्थिक कठिनाई के कारण बेचा, अन्यथा वे शायद न बचते। दूसरी बात यह है कि यह सब सोना देश से बाहर इस कारण से गया कि भारत में रुपये में सोने का मूल्य, विदेशों में जो रुपये में उसका मूल्य आता था उससे कम था। भारत में मूल्य कम होने के कई कारण थे—जैसे मामलासियों की इस मामले में जानकारी का कमी, सोना खरीदने वालों का प्रचार, और पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास सोना का होना। यह

भारतीय कागजी मुद्रा

प्रारम्भिक इतिहास : १८६१ के एक एक्ट द्वारा पहली बार भारत में कागजी मुद्रा या नोट जारी करने का एकाधिकार भारत सरकार के कागजी मुद्रा विभाग को दिया गया। उससे पहले प्रत्येक बैंक को यह अधिकार था ; हालांकि प्रेसीडेन्सी बैंक ही अपनी विशेष स्थिति के कारण इस अधिकार का वास्तव में उपयोग कर पाते थे, अन्य बैंक अपेक्षाकृत बहुत कम। प्रेसीडेन्सी बैंकों के नोट गवर्नमेंट भी स्वीकार करती थीं।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है १८६१ का पेपर करेंसी एक्ट इस लिये पास किया गया था कि उस समय देश में जो मुद्रा की तंगी महसूस हो रही थी वह दूर हो जाये।

१८६१ के पेपर करेंसी एक्ट के अन्तर्गत नोट जारी करने के संबंध में 'इंगलिस बैंक चार्टर एक्ट १८४४' का सिद्धान्त अपनाया गया था। यह सिद्धान्त 'क्लिंसड फाइन्सियरी सिस्टम' कहलाता था जिसके अनुसार एक निश्चित मर्यादा तक तो नोट केवल सिम्पूरिटीज के बदले में जारी किये जा सकते थे पर उस मर्यादा के बाद सोने और चांदी के एक्जेंट में। १८६१ के एक्ट में यह मर्यादा ४ करोड़ रुपये की तय की गई थी। इससे अधिक नोट रुपये या चांदी के बदले में ही जारी हो सकते थे।

नोटों की दृष्टि से भारतवर्ष की तीन क्षेत्रों में बांटा गया था—एक का प्रधान कार्यालय बम्बई, दूसरे का कलकत्ता, और तीसरे का मद्रास में था। बाद में इनकी संख्या ७ हो गई और कराची, लाहौर, कानपुर और रंगून के चार नये क्षेत्र और कायम हो गये। १८१० में इस प्रकार ७ क्षेत्र कायम हो गये थे। नोट १०, २०, ५०, १००, ५००, १०००, और १०००० रु० के जारी किये जाते थे। १८६० में ५ रु० के नोट भी जारी होने लग गये। अपने अपने क्षेत्र के अन्दर नोटों को अपरिमित कानूनी मुद्रा का रूप दे दिया गया था। कायदे से तो अपने क्षेत्र के प्रधान कार्यालय में ही नोटों को रुपये में बदलबाया जा सकता था पर जैसे सरकारी खजाने दूसरे क्षेत्रों के नोट स्वीकार कर लेते थे और भुमा भी देते थे।

१८१४ के पूर्व की स्थिति : उक्त कागजी मुद्रा पद्धति में कई दोष दिखाई पड़ने लगे। नोटों के अपने अपने क्षेत्र में ही कानूनी मुद्रा स्वीकार किये जाने और मुन सकने से उनकी सर्वमान्यता पर असर पड़ा। इसलिये धीरे धीरे नोटों को देश भर में कानूनी मुद्रा स्वीकार किया जाने लगा। सबसे पहले १८०१ में ५ रुपये के नोट को बर्मा के अलावा शेष ब्रिटिश भारत में कानूनी मुद्रा मान

को १९३५ में जब स्थापना होने लगी तब भी यह सवाल मामो आया। अक्टूबर १९३६ में जब फ्रांस और दूसरे स्वयं मुद्रा वाले देशों ने अन्तर्मुद्रा किया तब भी यह सवाल पैदा हुआ। १९३८ का जून में जब रुपये की 'विनिमय दर' फिर नीचे की आर जाने लगी तो भी यह भाग की गद् और वापस वर्जिंग कमेटी ने भी इस भाग का समर्थन किया। पर हा तमाम भागों के वास्तविक सरकार अपने विचारों पर जमी रहा। १९३९ में महायुद्ध आरम्भ होने तक विनिमय दर स्थिर रही और युद्ध आरम्भ होते ही तो सारी स्थिति बदल गई।

१९२९ से १९३९ तक विनिमय दर को कम करने की गंगा निम्नलिखित कारणों को लेकर गी गई —

(१) सरकार मुद्रा सङ्कुचन करके ही १ शि० ६ पै० की दर कायम रख सका है—जैसे १९२६ २७ और १९३० ३१ के बीच में १०२१ करोड़ रुपया चलन में कम किया गया। रिज़र्व बैंक को स्टैरलिग बचने पड़े, और इम्पोर्टिड बैंक को विदेशी परिस्थिति में १९२३ १/४ एकट के चलनगत सरकार द्वारा रुपया उधार देने का व्याज भी बढ़ाया पड़ा—यह सब भी इसी बात का सफल था।

(२) विनिमय दर ऊँची होने का प्रभाव इस से भी गिलाता है कि हमारे देश में विरध्यायी मही के समय में जैसे ब्रिटेन की अपेक्षा मूल्य अधिक गिरे, औद्योगिक उत्पादन शक्ति बढ़ रहा, हमारे निर्यात के मूल्य आयात की अपेक्षा अधिक गिरे और विदेशी व्यापार का सन्तुलन हमारे पक्ष में होते हुए भी उसकी मात्रा में कमी आई।

(३) १९३१ में रुपया-स्टैरलिग दर का समर्थन स्थिर कर देने में स्टैरलिग के साथ रुपये का गिला। विनिमय मूल्य गिरा वह कम था।

(४) देश से बढ़ी मात्रा में खोने का निर्यात होने से १ शि० ६ पै० की दर बनी रह सकी। यदि ऐसा न होता तो इस दर को कायम रखने में कठिनाई होती।

उपरोक्त दलीलों का जैसा ऊपर लिखा जा चुका है सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। कभी उसने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के स्पष्ट न होने की दलील दी और कहा कि ऐसा अनिश्चित स्थिति में निर्णय करना अशुभ नहीं होगा, तो कभी उपभोक्तियों को बाहर का मान में होगा पड़ेगा यह दलील दी गई और कभी सरकार के वित्त व्यवस्था पर प्रतिकूल अंतर पड़ने की बात कही गई। द्वितीय महायुद्ध तक यही विवाद चलता रहा। रिज़र्व बैंक एकट में १ शि० ६ पै० के विनिमय दर को कानूनी रूप दी दिया गया था।

वा नहीं क्योंकि चांदी की कमी थी। नए नोट भी सिक्कूरिटीज़ के बदले में जारी किये गये। 'फाइव शिवरी' मर्यादा इस प्रकार बढ़ते बढ़ते १९१६ में १२० करोड़ रुपये तक पहुँच गई। धातु कोष का अनुपात १९१४ में ७८.६% था वह १९१६ में ३५.८% रह गया। १ रुपया और २३ रुपये के नोट भी जारी किये गये और कानून के अतिरिक्त नोटों को मुनाने की जो सुविधायें थी वे बंद कर दी गईं। नोटों की कुल संख्या ३१ मार्च १९१४ को ६६ करोड़ रुपये की थी वह ३१ मार्च, १९१६ को १५३३ करोड़ के आसपास पहुँच गई।

प्रथम महायुद्ध के बाद : बेविगटन स्मिथ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर १९२० में इंडियन पेपर करेंसी एमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के अनुसार :—

(१) धातु कोष की मर्यादा कुल की ५०% निश्चित कर दी गई। बेविगटन स्मिथ कमेटी ने ४०% की सिफारिश की थी।

(२) २० करोड़ की उन सिक्कूरिटीज़ के अलावा जो भारत में थी बाकी सब इंग्लैंड में रखना तय किया गया। ये सिक्कूरिटीज़ अल्पकालिक होना चाहिये थीं।

(३) जारी होने से ६० दिन में सिकरने वाले आन्तरिक बिलों की एवज में इम्पीरियल बैंक को ५ करोड़ रुपया ८% ब्याज पर कर्ज दिया जा सकता था। बाद में १९२३ में यह मर्यादा १२ करोड़ तक बढ़ा दी गई। धातु कोष के लिये इसको गितने की आवश्यकता नहीं थी।

(४) भारत मंत्री को लंदन में सोने में ५० लाख पौंड से अधिक अपने पास नहीं रखना था।

१९२० के करेंसी एक्ट में उपरोक्त बातों के अलावा कुछ और बातें भी थीं। सोना और स्टरलिंग सिक्कूरिटीज़ की कीमत २ शि० प्रति रुपये के हिसाब से जब लगाई गई तो सोना और स्टरलिंग सिक्कूरिटीज़ के पहले के मूल्य के मुकाबिले में अब कमी हो गई क्योंकि पहले २ शि० से कम पर उनका मूल्य आँका गया था। दुबारा मूल्यांकन करने से जो फ़रक रहा उसे पूरा करने के लिये भारत सरकार को रुपया सिक्कूरिटीज़ जारी करने और उन्हें पेपर करेंसी रिज़र्व को देने का अधिकार दिया गया। पर कुल रुपया सिक्कूरिटीज़ की मर्यादा २० करोड़ पर निश्चित थी जिसमें से १९२३ के एक्ट के अनुसार १२ करोड़ तक की भारत सरकार की अस्थायी सिक्कूरिटीज़ हो सकती थीं। दुबारा मूल्यांकन के कारण उससे अधिक जो अस्थायी रुपया सिक्कूरिटीज़ जमा हो गई थीं उन्हें धीरे धीरे स्टरलिंग सिक्कूरिटीज़ में बदलना तय किया गया था।

अहाँ तक पेरर करेंगी रिजर्व में सिम्पूरिटीज़ का संचाल था उनकी माशा ८२ करोड़ नव की ग* क्योंकि दुबारा मूल्यवर्त में घातु कोर का अनुमान ५०% से कम रहने वाला था। बाद में १९२५ ने एक एक्ट व अन्तर्गत यह मयादा १२४ करोड़ करदा गये थी पर साथ माश यह भा तय कर दिया गया था कि इन १०० करोड़ में से ५० करोड़ में ज्यादा की भारत सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर चारा का मद मिक्चुरिटीज़ नहीं होनी चाहिय थी।

भारत सरकार द्वारा चारा की मद अस्थायी मिक्चुरिटीज़ को स्ट्रॉनिंग मिक्चुरिटीज़ में बदलना व निव गपना नहीं था। इंग्लिने यह निश्चय किया गया कि पेरर करमा रिजर्व में बाज़ में अनुमान जो मिक्चुरिटीज़ है उनका व्याप, नये रूप डालने पर उनमें डाल वाला लाभ, श्रीर गोल्ड स्टैड्ड रिजर्व में जब ४ करोड़ पौंड हो जाये (जो ३० अक्टूबर १९२१ को हो गये थे) ता उसका व्याप और उा व्यापारिक बिलां का व्याप जो अस्थायी नोट जारी करने के लिये इन्वोसिपल बैंक से कटान ऑफ करेंगी को प्राप्त हों—यह सब एकम पेरर करेंगी रिजर्व को दे दा जावे। पर आर्थिक संगी के कारण ये आमदनी न। मर्दे सरकार बजट में जमा हाती रही। १९२१-२२ में गोल्ड स्टैड्ड रिजर्व में जब ४ करोड़ पौंड से अधिक हो गया तो वह अधिक रकम इन भारत सरकार का अस्थायी मिक्चुरिटीज़ को रह करने के काम में लिया गया।

१९२७ में जब हिल्टन वग कमीशन का सिफारिशों को कार्यान्वित करने को करेंगी एक्ट पास हुआ तो सोना और स्ट्रॉनिंग मिक्चुरिटीज़ का १ टि० ६ पैस की दर के हिमाज में फिर मूल्यवर्त किया गया जिसका नतीजा ६१० करोड़ से उनकी कीमत बढ़ने का आया। इसी बड़ी रकम का उपयोग इतने ही रूपों व ट्रेनर बिलों को रह करने में कर लिया गया और उनकी मात्रा ४९७७ करोड़ से कम हो कर ४०४८ करोड़ रुपये की रह गई।

१९३५ में जब रिजर्व बैंक कायम हुआ तो नोट जारी करने का एकाभि कार उसका पास आ गया। बैंक का इश्यू डिपार्टमेंट इस काम को करता है। गोल्ड स्टैड्ड और पेरर करली रिजर्व मिला दिये गये और सारा सोना रिजर्व बैंक व इश्यू डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। इश्यू डिपार्टमेंट ग सोने का सिक्का, सोना, स्ट्रॉनिंग मिक्चुरिटीज़, रुपया, और कया मिक्चुरिटीज़ एसेट्स तौर पर रहत है। कुल का ४०% सोना और सोने का सिक्का या स्ट्रॉनिंग मिक्चुरिटीज़ में रखना नय किया गया। और सोना और सोने के सिक्का ४० करोड़ रुपये में कम के किसी समय न हों यह भी निश्चय कर दिया गया।

विशेष परिस्थिति में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से निश्चित कर देने पर सोना, सोने के सिक्के, और स्टर्लिंग सिक्कूरिटीज़ का अनुपात ४०% कम कुछ समय के लिये किया जासके यह विधान भी किया गया। पर ऐसी आवश्यकता कभी हुई नहीं।

नोटों के प्रचलन के बारे में जानने की बात यह है कि वह बराबर बढ़ता ही गया है। केवल विश्वव्यापी मन्दी के १९२९-३० और १९३०-३१ के वर्ष इस संबंध में अपवाद के तौर पर माने जा सकते हैं। मन्दी के बाद की मूल्यों के बढ़ने की श्रद्धा, और सोने की बिक्री के कारण भी नोटों की वृद्धि हुई। १९१९-२० में औसत क्रियाशील प्रचलन १५१ करोड़ के लगभग था, १९२८-२९ में १७२ करोड़ हो गया, १९३०-३१ में १५१ करोड़ रह गया और १९३७-३८ में १८६ करोड़ तक पहुँच गया। दूसरे महायुद्ध के बाद तो इस संख्या में कई गुना वृद्धि होगई है।

कौन कौन से नोट अधिक लोकप्रिय रहे, इस बारे में यह बताना आवश्यक है कि १० रु० और १०० रुपये के नोटों का बहुत प्रचार हुआ और ५० रुपये के नोटों का बहुत कम प्रचार हुआ। १ रुपये और २३ रुपये के नोट १ जनवरी, १९२६ से और २० रुपये के नोट १९१० से बंद कर दिये गये। रिज़र्व बैंक ने १९३८ में यह निर्णय किया कि ५० रु० और ५०० रु० के वह अपने नोट जारी नहीं करेगा हालाँकि भारत सरकार के नोट तो चलन में रहेंगे ही।

दूसरी बात ध्यान देने की यह भी है कि जनता में रुपयों की अपेक्षा नोटों का चलन बढ़ा है। रुपये की जगह लोगों ने १९३१ के पहले सोने का संचय करना आरम्भ कर दिया था इससे भी रुपये की चलन में संख्या में कमी आई। विश्व मंदी के समय तो रुपयों और नोट दोनों की ही मांग कम रही। मंदी समाप्त होने के बाद नोटों की मांग बढ़ी। १९३७-३८ में जब व्यापार की गति फिर थोड़ी धीमी हुई तो देश में मुद्रा की मांग कम हुई और लोगों ने कुल मिला कर रिज़र्व बैंक को मुद्रा लीटाई। दूसरे वर्ष भी वही स्थिति रही। पर १९३६-४० में फिर स्थिति ने पल्टा खाना और मुद्रा की मांग बढ़ने लगी।

पेपर करेंसी रिज़र्व में रुपया और सोना दोनों का अनुपात बढ़ा। सोना १९२५ में २२ करोड़ रुपये का था वह १९३५ में ४४ करोड़ रुपये तक पहुँच गया। इसका कारण यह था कि भारत सरकार चाँदी तो बेचती रही और रुपया सिक्कूरिटीज़ में उसी हद तक कमी करती रही। यह इस प्रकार हुआ—चाँदी बेचने से जो रकम आई वह स्टर्लिंग सिक्कूरिटीज़ में जमाई और वह सिक्कूरिटीज़-गोल्ड स्टैन्डर्ड रिज़र्व को देकर बदले में पेपर करेंसी रिज़र्व को सोना मिल गया

और उस हद तक रुपया विक्रयिटाङ्ग रह कर दी गइ। इसमें स्टर्लिंग विक्रयिटाङ्ग में कमी आते-आते १९३१-३३ में वे रही हो नहीं और फिर १९३४ में उनका घाना शुरू हुआ। उसके बाद यह बढ़ती रही। स्टर्लिंग विक्रयिटाङ्ग में कमी आने का कारण तो यह था कि भारत मन्त्री को रकम भेजना मुश्किल हो रहा था और बाद में उनमें वृद्धि इस कारण से हुई कि भारत मन्त्री के लहान में जो अनिश्चित रकम थी और चाँदी की बिना से जो रुपया मिलता था उसका उपयोग पेरर कौंसा रिज़र्व के लिए स्टर्लिंग विक्रयिटाङ्ग खरीदने में लगाया जा रहा था।

परिच्छेद १२

द्वितीय महायुद्ध और मुद्रा

जब १९३६ में द्वितीय महायुद्ध आरंभ हुआ तो उसका असर भारतीय मुद्रा व्यवस्था पर भी कई प्रकार से हुआ। अब हम इस संबंध में विचार करेंगे।

मुद्रा का विस्तार : महायुद्ध का एक स्वामानविक असर तो यह हुआ कि देश में बहुत बड़ी मात्रा में मुद्रा का विस्तार हुआ। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि १ सितम्बर, १९३६ को भारत में सक्रिय प्रचलन में १८२*१६ करोड़ रुपये के नोट थे जब कि १९ अक्टूबर १९४५ को उनकी संख्या ११५९*८५ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि ६७७*७२ करोड़ रुपये या ५३६ प्रतिशत की नोटों में वृद्धि हुई। इसी प्रकार सितंबर १९३६ से अगस्त १९४५ तक कुल १४२*१६ करोड़ के रुपये के सिक्के और ६७*५६ करोड़ रुपये की रेज़रवी भी अधिक प्रचलन में आई। बैंक के डिपॉजिटों की मात्रा भी बढ़ी। केवल सिविल बैंकों के डिपॉजिटों में युद्ध के आरंभ से ३१ मार्च १९४५ तक ४६० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। युद्ध काल में मुद्रा के कुल प्रचलन में ११६८*६४ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसमें से ८२*५ प्रतिशत वृद्धि नोटों में, ११*६ प्रतिशत रुपये के सिक्कों में और ५*६ प्रतिशत रेज़रवारी में हुई थी। यह अवश्य है कि मुद्रा प्रचलन की गति में कुछ कमी आई थी क्योंकि युद्ध की अनिश्चित परिस्थितियों में सर्व साधारण, बैंक और व्यापारी सभी अपने हाथ में नकद रुपया अधिक मात्रा में रखना चाहते थे।

मुद्रा के उक्त विस्तार के कारणों का वहीं तक उवाच है, मूल कारण तो एक ही था कि युद्ध के खर्च को चलाने के लिये भारत सरकार को रुपये की आवश्यकता थी। भारत सरकार की इस आवश्यकता का एक विशेष कारण यह भी था कि उसे मित्र राष्ट्रों के लिये भी खर्च करना पड़ता था। अपनी आवश्यकता को पूरी करने का भारत सरकार के पास सबसे बड़ा साधन मण्ड नोट जारी करने का था, क्योंकि जनता पर कर लगा कर या कर्ज लेकर जो रुपया सरकार प्राप्त कर सकती थी उसकी आखिरकार एक मरवादा थी। इसलिये सरकार को विवश होकर मण्ड नोट जारी करने पड़े। पर मण्ड नोट जारी सभी हो सकते हैं जब उनके बदले में रिज़र्व बैंक के पास कोई 'एसेट्स' जमा हों। ये एसेट्स 'स्टेरलिंग सिन्क्यूरिटीज़' और 'रुपया सिन्क्यूरिटीज़' की शकल में जमा किये गये और बदले में नोट जारी किये गये। अब हम ये

‘स्टरलिंग सिम्पूरिटीज़’ और ‘रुपया सिम्पूरिटीज़’ कहाँ से आई इस बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे।

स्टरलिंग सिम्पूरिटीज़ का जमा होना रिज़र्व बैंक कानून के अन्तर्गत सोना या सोने का सिक्का, स्टरलिंग सिम्पूरिटीज़, रुपये का सिक्का, और रुपया सिम्पूरिटीज़ के अन्तर्गत मोटा ज़ारों कर सकता है। युद्ध काल में रुपये मोटा ज़ारी करने के लिये रिज़र्व बैंक को न तो मोना या सोने का सिक्का उपलब्ध हो सकता था और न रुपये का सिक्का ही। मोना या सोने के सिक्के मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं था और देश में रुपये की माग बढ़ने से रुपये का सिक्का भी उपलब्ध नहीं था। यह एक एक्ट नवम्बर १९३६ से लेकर ३१ अगस्त १९४५ के बीच में रिज़र्व बैंक के इश्यू विभाग में ५८४ करोड़ का रुपये का सिक्का और कम हो गया जब कि इस समय में ६७४ करोड़ की स्टरलिंग सिम्पूरिटीज़ और २०५ करोड़ रुपये की रुपया सिम्पूरिटीज़ की मात्रा में वृद्धि हुई।

स्टरलिंग सिम्पूरिटीज़ जो इतनी बड़ी हुई मात्रा में इकट्ठी हो गई उसका कारण यह था भारत सरकार ब्रिटिश सरकार और दूसरे मित्र राष्ट्रों के लिये यहाँ युद्ध सामग्री ख़रीदना थी। ब्रिटिश सरकार इस सामग्री की कामत भारत सरकार को लंदन में स्टरलिंग में चुका देती थी। भारत सरकार इस स्टरलिंग का उपयोग ‘होम वॉरेंट्स’ के लिये और भारत पर जो स्टरलिंग ऋण था उसे चुकाने में करना था और इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को ऋण के रूप में दे देती थी। इस ऋण के बदले में ब्रिटिश सरकार उसे अपने थ्रॉटल ओं गूज़ या स्टरलिंग सिम्पूरिटीज़ दे देती थी जो लंदन में भारत के रिज़र्व बैंक के एसेट्स के तौर पर लंदन में जमा करवा जाती थी। ये स्टरलिंग सिम्पूरिटीज़ रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग में जमा होनी पर जब उनके अन्तर्गत नोट जारी करने होते तो ये सिम्पूरिटीज़ बैंक के इश्यू डिपार्टमेंट में जमा करवा जाती और उनसे ही नोट जारी कर दिये जाते। इस प्रकार युद्ध काल में हमारे देश में स्टरलिंग सिम्पूरिटीज़ जो जमा होता गई और नोट जारी होते गये और उनके द्वारा मुद्रा प्रसार किया गया। रिज़र्व बैंक के पास स्टरलिंग आने का एक दूसरा साधन यह था कि भारत को ऋण माल के बदले में रुपया भेजना होता था उनसे बैंक स्टरलिंग तो ख़रीद लेता था और अन्त में उनको रुपया चुका देता था।

रुपया सिम्पूरिटीज़ युद्ध काल में देश में जो मुद्रा विस्तार हुआ उसका एक आधार रुपया सिम्पूरिटीज़ भी थी। रिज़र्व बैंक एक्ट में परवरी

१९४१ के आर्डिनेन्स से यह संशोधन कर दिया गया कि इससे पहले जो रुपया सिक्कूरिटीज़ के बैंक के इश्यू विभाग में जमा होने की ५० करोड़ की अधिकतम मर्यादा थी वह आगे नहीं रहेगी। फलस्वरूप अब भारत सरकार के लिये यह संभव हो गया कि वह रिजर्व बैंक को अपने ट्रेजरी बिल या आई० ओ० पूज जारी कर दें। कुछ सिक्कूरिटीज़ उन स्टरलिंग सिक्कूरिटीज़ का स्थान लेने के लिये भी जारी की गईं थी जो स्टरलिंग ऋण जुकने के पहले ब्रिटिश सेनदारों या ऋणदाताओं के पास थीं।

रुपया और रेजगारी की मांग में वृद्धि : युद्ध आरंभ होने के बाद १९४० की शुरुआत तक तो देश की कामगिरी मुद्रा में जनता का विश्वास बना रहा। पर फ्रांस के पतन और इटली और बाद में जापान के युद्ध में शामिल हो जाने के बाद लोगों का विश्वास हिलने लगा और नोटों को रुपये में बदलवाने की मांग बढ़ने लगी। इसके साथ-साथ लोगों ने रुपया और रेजगारी इकट्ठी करना आरम्भ कर दिया। इस स्थिति का सामना करने के लिये एक ओर तो २५ जून, १९४० की एक विज्ञप्ति द्वारा नाजिव व्यक्तिगत या व्यापारिक आवश्यकता से अधिक रुपया या रेजगारी इकट्ठा करना अपराध घोषित कर दिया गया, दूसरी ओर सरकार ने नए रुपये और रेजगारी जारी करके, नई कम चांदी की [५० प्रतिशत चांदी, २२ भाग के बजाय] अठन्नी और चवन्नी और बाद में कम चांदी का रुपया भी जारी करके, नए अक्षर, इकनिश और दोअनिश जारी करके और रुपये में नई बदले जाने वाले एक रुपये के नोट जारी करके इस स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत समय तक वास्तव में सब प्रयत्नों के स्थिति गंभीर बनी रही थी। भारत सरकार ने रुपये के पुराने सिक्कों की जिनमें २२ भाग चांदी का था धीरे धीरे कानूनी हैसियत खत्म कर दी। विक्टोरिया छाप के रुपये और अठनिशों का चलन ३१ मार्च, १९४१ से, एटवर्ड छाप के रुपये और अठनिशों का चलन ३१ मई, १९४२ से और जार्ज पंचम और जार्ज षष्ठ के रुपये और अठनिशों का चलन ३१ मई, १९४३ से बंद कर दिया गया।

विदेशी विनियम की स्थिति और उसका नियंत्रण : यह हम पहले लिख चुके हैं कि रुपये की १ शिलिंग ६ पैसे के बराबर विनियम दर बनाये रखने में सरकार की बड़ी कठिनाई अनुभव होती रही और इस कारण देश का बहुत सा घेना भी विदेशों को भेजना पड़ा। पर युद्ध के आरम्भ होते ही रुपया-स्टरलिंग दर में हड़ता आ गई क्योंकि युद्ध का असर भारतीय व्यवसाय और व्यापार के पक्ष में पड़ा, देश का निर्यात बढ़ा और विदेशी व्यापार का संतुलन

हमारे अनुकूल जाने लगा। रिज़र्व बैंक ने स्टर्लिंग की खरीद बड़ी मात्रा में करना आरम्भ कर दिया। अब १ शिलिंग ६ पैसे की विनियम दर कायम रखा आया हो गया।

पर जैसे ही डालर, पेन और दूसरी मुद्राओं का तुलना में स्टर्लिंग गिरने लगी, रुपये का विनियम दर भी इन मुद्राओं में गिरने लगी। बाद में स्टर्लिंग डालर दर ४२ पर निश्चित कर दी गई तो रुपये डालर का दर भी १०० डालर=३३२ रुपये के दर पर निश्चित हो गई।

जहाँ तक विदेशी विनियम के नियंत्रण का प्रश्न है, भारत सरकार ने रिज़र्व बैंक के एक्ज़चेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट को यह कार्य सौंप दिया। इस नियंत्रण का उद्देश्य विदेशी विनियम का अप्रत्यक्ष रोकने का था। रिज़र्व बैंक ने फिन्की प्लायट स्टॉक और एक्ज़चेंज बैंकों को विदेशी विनियम में लेन देन करने का अधिकार दे दिया। उनको यह आदेश था कि रुपये-स्टर्लिंग दर और लंदन एक्ज़चेंज कंट्रोल का दलों के आधार पर वे अपना लेन देन करें। ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत देशों को स्टर्लिंग क्षेत्र का नाम दिया गया। इस क्षेत्र में विदेशी-विनियम के लेन देन बिना किसी रोक-टोक के हो जाते थे। पर इन क्षेत्र के बाहर स होने वाले लेन देन पर बड़ा नियंत्रण था। केवल वाणिज्य व्यापारिक या व्यक्तिगत और यात्रा संबंधी आवश्यकता पूर्ति के लिए विदेशी विनियम मिल सकता था और पूँजा के निष्कासन और विदेशी विनियम में होने वाले स्वम्पूलेसन को रोकने का प्रयत्न किया जाता था।

आयात निर्यात नियंत्रण विदेशी विनियम के नियंत्रण की एक अति मार्ग दर्शन यह थी कि आयात और निर्यात का भी नियंत्रण किया जावे। भारत सरकार ने आयात और निर्यात पर भी नियंत्रण कायम कर दिया। जब तक कि मातृ माल को—जिसको आयात करने के लिये लाइसेंस लेना आवश्यक था—आयात करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता उसने लिये विदेशी विनियम नहीं मिल सकता था। इसी प्रकार स्टर्लिंग क्षेत्र के बाहर जो माल निर्यात होता था उस पर इस बात का रिज़र्व बैंक के द्वारा नियंत्रण था कि निर्यात के बदले में विदेशी विनियम भारत को मिल जावे और निर्यात के बदले में सुरास इस प्रकार बिना जावे कि माल के एक्स में अधिक से अधिक विनियम मूल्य प्राप्त हो सके। भारतवासियों तथा दूसरे साम्राज्यान्तर्गत देशों के निवासियों के पास जो भां डालर की आमदनी होनी थी वह सब 'एम्पायर डालर पुल' में जमा कर दी जाती थी। इसका उपयोग मुद्र के लिये होता था।

माल के आयात-निर्यात पर होने वाले नियंत्रण के साथ ही साथ विदेशी सिम्बूरिटीज़ और सोना चाँदी और करेंसी नोटों के आयात-निर्यात पर भी नियंत्रण कर दिया गया था। सोना के आयात और निर्यात के लिये लाइसेंस लेना होता था। आयात के लिये लाइसेंस आधानी से मिल जाता था। इसी प्रकार सिम्बूरिटीज़ विना रिज़र्व बैंक की इजाजत के बाहर नहीं भेजी जा सकती थीं और न बाहर से उनका आयात हो सकता था। भारत से बाहर एक सीमा से अधिक जवाहरात और नकद भेजने के लिये भी लाइसेंस लेना आवश्यक था। शत्रुओं का जिन देशों पर अधिकार हो गया था उनके करेंसी नोटों का आयात बन्द था।

एम्पायर डालर पूल—१९३९ में इंग्लैंड ने स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों को विदेशी विनिमय के जो रक्षित कोष थे उन पर नियंत्रण कर लिया। अगर किसी स्टर्लिंग क्षेत्र से बाहर के देश में होने वाले व्यापार के फलस्वरूप किसी स्टर्लिंग क्षेत्र के देश का लेना रहता था तो उस देश को तो बुकारा स्टर्लिंग में हो जाता और डालर 'एम्पायर डालर पूल' में जमा हो जाता। अगर किसी सदस्य देश को डालर की आवश्यकता होती तो वह उस पूल में से जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा रहता था ले सकता था। भारत भी इस डालर पूल का सदस्य था। पर इसका देश में बराबर विरोध था कि भारत जो डालर कमाता है उसको डालर पूल में क्यों जमा किया जाय। भारत द्वारा कमाये हुए डालर पर भारत का ही पूरा अधिकार रहना चाहिये। १९४७ में भारत को यह आश्वासन भी मिल गया कि वह अपने डालर साधनों का स्वतंत्रता से उपयोग कर सकेगा। पर इस बारे में १९४८ में फिर कुछ प्रतिबंध लगाये गये जो १९४९ में फिर हटा दिये गये थे। जब स्टर्लिंग के साथ रुपये का अवमूल्यन हुआ तो अन्य देशों के साथ भारत ने भी डालर को कम खर्च करने की नीति स्वीकार की। इस समय डालर संबंधी स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है।

द्वितीय महायुद्ध के बाद भारतीय मुद्रा

द्वितीय महायुद्ध का भारतीय मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में हमने लिखा है। महायुद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय मुद्रा संबंधी स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आया, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटीं तथा आज भारतीय मुद्रा से संबंध रखने वाले जीवित प्रश्न क्या हैं, अब हम इस बारे में विचार करेंगे।

मुद्रा का विस्तार इस विषय में सबसे पहला प्रश्न मुद्रा के विस्तार से संबन्ध रखता है। मुद्रा समाप्त होने के बाद प्रतिवर्ष साल के अन्त के आंकड़ों के आधार पर प्रचलन में कुल नोटों की संख्या में तो वृद्धि जारी रही पर प्रचलन में प्रतिशत वृद्धि और कुल वृद्धि में तो १९४३-४४ से ही कमी आना शुरू हो गई थी। १९४८-४९ में पहली बार प्रचलन में नोटों की कुल संख्या में भी कमी आई। जहाँ १९४७-४८ में अन्त में प्रचलन में कुल नोटों की संख्या १३०८ करोड़ तक पहुँच गई थी वह संख्या १९४८-४९ में ११९९ करोड़ और १९४९-५० में ११६३ करोड़ पर आ गई। ३१ अगस्त, १९५१ की प्रचलन में कुल नोटों का संख्या ११५८ करोड़ के आसपास थी। भारत में प्रचलन में नोटों की संख्या में १९३७-३८ के बाद पहला बार १९४८-४९ में ७.८४ करोड़ रुपये की और १९४९-५० में ५.८४ करोड़ रुपये की कमी आई। इसी प्रकार रुपये के सिक्के के बारे में भी हम यही देखते हैं कि १९४२-४३ के बाद से इसकी मांग में कमी आने लगा है यद्यपि कुल रुपये के सिक्के के परिमाण में कुछ न कुछ वृद्धि होती रही। पर १९४७-४८ में तो रुपये के सिक्के के प्रचलन की संख्या में ही १२३४ करोड़ की कमी आ गई। १९४८-४९ में ४११ करोड़ रुपये प्रचलन में कम हुए हालांकि १९४९-५० में २२९ करोड़ की वृद्धि हो गई। रेजर्वी की मांग भी १९४४-४५ में पर्याप्त कम हो गई। यहाँ तक कि १९४८-४९ में केवल २४ लाख रुपये की नई रेजर्वी प्रचलन में ज्यादा आई जब कि १९४७-४८ में ४ करोड़ २ लगभग, १९४६-४७ में ६ करोड़ के लगभग और १९४५-४६ में १० करोड़ के लगभग की अधिक रेजर्वी प्रचलन में आई थी। १९४४-४५ में १९ करोड़ रुपये की नई रेजर्वी प्रचलन में आई थी। १९४९-५० में तो २१६ करोड़ की रेजर्वी प्रचलन में कम हो गई। नोट, रुपया और रेजर्वारी सबको मिला कर देखने से यह मालूम पड़ता है कि १९४२-४३ में सबसे अधिक मात्रा में मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। वह मात्रा ३१८ करोड़ से भी अधिक रुपये की थी। उसके बाद कमी आता यह और १९४६-४७ में वृद्धि की वह मात्रा ३१ करोड़ के आसपास ही रह गई। १९४८-४९ में तो कुल मात्रा में १२ करोड़ रुपये के लगभग का और १९४९-५० में ५.७ करोड़ रुपये की कमी ही आई। यह व डिपोजिट के बारे में जो आंकड़े मिलते हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि मार्च १९४४ तक तो डिपोजिट में वृद्धि की दर बराबर बढ़ती गई पर उसके बाद कमी आने लगा। १९४८-४९ में डिपोजिट का मात्रा में भी कमी आ गई और १९४९-५० में भी कमी रहा हालांकि १९४८-४९ की अपेक्षा कम। यदि हम कुल मुद्रा की मात्रा का जिसमें करेंसी (रेजर्वारी के अलावा) और डिपोजिट दोनों ही का समावेश है,

विचार करें तो हम देखेंगे कि कुल मात्रा में मार्च १९४८ तक तो वृद्धि होती रही वद्यपि मार्च १९४३ के बाद से वृद्धि की मात्रा की दर में कमी आने लगी। १९४८-४९ में तो कुल मात्रा में ही ४३ करोड़ के लगभग की कमी हो गई और १९४९-५० में १८ करोड़ के लगभग कमी हो गई। ३० जून १९५१ को समाप्त होने वाले साल की रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार १९५०-५१ में देश में कुल मुद्रा की मात्रा में १०२ करोड़ (८६ करोड़ करेंसी और १६ करोड़ डिपोजिट) की वृद्धि हुई जब कि १९४९-५० में ११ करोड़ की वृद्धि हुई थी और १९४८-४९ में १३४ करोड़ रुपये की कमी हुई थी।

उपरोक्त विवरण का सार यह है कि युद्ध के अन्तिम वर्षों में मुद्रा प्रसार की गति धीरे धीरे कम होने लगी; यहां तक कि एक समय ऐसा भी आगया जब कुल मात्रा में ही कमी होना आरम्भ हो गई। पिछले दो वर्षों में मुद्रा की मात्रा में फिर वृद्धि होना आरम्भ हुआ है।

स्टरलिंग सिक्यूरिटीज : द्वितीय महायुद्ध का एक बड़ा असर यह हुआ था कि रिजर्व बैंक के पास स्टरलिंग सिक्यूरिटीज काफ़ी बड़ी मात्रा में जमा हो गई थी। स्टरलिंग सिक्यूरिटीज की यह वृद्धि अप्रैल १९४६ तक बराबर जारी रही। पर उसके बाद उसकी मात्रा फिर कम होने लगी। स्टरलिंग सिक्यूरिटीज में अगस्त १९३९ के मुकाबले में सबसे अधिक वृद्धि अप्रैल १९४६ में हुई जब कि १७३१.१७ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। उसके बाद स्टरलिंग सिक्यूरिटीज की मात्रा गिरने लगी। ३१ मार्च १९५० में उनका मूल्य ८५७.७७ करोड़ रुपये के बराबर था। ३१ अगस्त १९५१ को रिजर्व बैंक के इश्यू विभाग में विदेशी सिक्यूरिटीज ६१३ करोड़ रुपये से कुछ अधिक मूल्य की थी जब कि १ सितम्बर १९३९ के तुलनात्मक आंकड़ों को लें तो उनका मूल्य ३६३ करोड़ रुपये के बराबर ही था। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि १ जनवरी १९४९ से भारत के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हो जाने से रिजर्व बैंक को स्टरलिंग सिक्यूरिटीज के अलावा दूसरी विदेशी सिक्यूरिटीज खरीदने का भी अधिकार हो गया और तब से इश्यू विभाग के स्टेटमेंट में स्टरलिंग सिक्यूरिटीज की जगह विदेशी सिक्यूरिटीज ने ले ली है।

रुपया सिक्यूरिटीज : रुपया सिक्यूरिटीज की मात्रा में भी बराबर उतार-चढ़ाव आता रहा है। द्वितीय महायुद्ध के समय में आरम्भ होने वाली वृद्धि का जहाँ तक सवाल है वह मार्च १९४३ तक जारी रही। मार्च १९४४ में समाप्त होने वाले साल में तो एकदम बहुत कमी आ गई। उसके बाद फिर कुछ वृद्धि आरंभ हुई और मार्च १९४९ में समाप्त होने वाले साल में तो वृद्धि की मात्रा एक साथ बहुत बढ़ गई। इसका मुख्य कारण यह था कि भारत-ब्रिटेन आर्थिक समझौते के

अनुसार जब स्टर्लिंग मिन्सुरिटीज़ ब्रिटेन को दे दी गईं तो ठाकुर स्थान भारत सरकार के देहरी बिलों ने लिया। ३१ मार्च १९५० को कया मिन्सुरिटीज़ का मात्रा ४४० २० करोड़ थी। १ मिनम्बर १९३९ को कया मिन्सुरिटीज़ की मात्रा ३७ करोड़ रुपये से कुछ अधिक थी। मुद्रकाल में १३६ करोड़ रुपये की अधिक से अधिक वृद्धि हुई। ११ अगस्त १९५१ को कया मिन्सुरिटीज़ ५०१ करोड़ से ऊपर था। इसका अर्थ यह है कि कया मिन्सुरिटीज़ में मुद्रकाल में भी अधिक मुद्रोत्तर काल में वृद्धि हुई है।

विदेशी विनिमय का नियंत्रण मुद्र काल में जो विदेशी विनिमय का नियंत्रण आरम्भ हुआ था वह आज तक भी चला है। इसी प्रकार दूसरे प्रकार के नियंत्रण जैसे चाहा ने आयात नियंत्रण पर नियंत्रण और गोले-न्यासी व आयात नियंत्रण पर भी नियंत्रण कायम है। नियंत्रण मन्त्रालय नियमों में अथवा समर्थ मन्त्र पर परि वर्तन होता रहता है। १७ फरवरी १९५१ में पाकिस्तान भी विदेशी विनिमय के नियंत्रण के क्षेत्र में आ गया है क्योंकि भारत ने आधिकारिक पाकिस्तान का अपने रुपये का प्रयोजन नहीं करने का निश्चय स्वीकार कर लिया।

स्टर्लिंग पावना की समस्या यह हम लिए चुके हैं कि किस प्रकार दिनांक महाबुद्ध व समय भारत के पास स्टर्लिंग पावना एक बड़ी मात्रा में जमा हो गया। यह स्टर्लिंग पावना मुख्यतः रिज़र्व बैंक व इश्यू डिपार्टमेंट और बैंकिंग डिपार्टमेंट में जमा हुआ। हालांकि यदि हम देश भर के सामान स्टर्लिंग पावने का विचार करें तो हम रिज़र्व बैंक के अनिश्चित दूसरे बैंकों और अन्य व्यक्तियों या कंपनियों आदि उनके पास भी स्टर्लिंग हो उसका भी विचार करना चाहिए। पर हमारे पास रिज़र्व बैंक व अलावा और निम्न पास कितना स्टर्लिंग है इसका आकड़े उपलब्ध नहीं है और इसलिए रिज़र्व बैंक व पास जो स्टर्लिंग जमा हुआ उस पर हम अपना ध्यान नष्ट करना होगा।

स्टर्लिंग पावने में किस प्रकार वृद्धि हुई इसका अनुमान हमसे लगाया जा सकता है कि अगस्त १९३९ (अन्तिम शुक्रवार) में रिज़र्व बैंक के इश्यू विभाग में ५९ ५० करोड़ और बैंकिंग विभाग में ३ ८० करोड़ हम प्रकार कुल ६३ ३० करोड़ रुपये का स्टर्लिंग पावना रिज़र्व बैंक के पास था। मुद्र के समय में वृद्धि होते होते १९४५ ६६ में इश्यू विभाग में १०६१ २६ करोड़ और बैंकिंग विभाग में ४८८२३ करोड़ रुपये के और इस प्रकार कुल १५४९ ४९ करोड़ रुपये का स्टर्लिंग पावना रिज़र्व बैंक के पास जमा हो गया। १९४६ ४७ में इसका मात्रा बढ़कर १६६२ ७१ करोड़ रुपये तक पहुँच गई। अप्रैल १९४६ में स्टर्लिंग पावने की मात्रा सबसे अधिक थी। रिज़र्व बैंक के इश्यू विभाग में ११२४ ०७ करोड़ और बैंकिंग

विभाग में ६०७.१० करोड़ रुपये का स्टरलिंग पावना एकत्रित हो गया था। अर्थात् अप्रैल, १९४६ में कुल १७३१.१७ करोड़ रुपये का स्टरलिंग पावना रिज़र्व बैंक के पास इकट्ठा हो गया था। इसके बाद स्टरलिंग पावने की मात्रा में कमी आना आरंभ हुआ। १९४७-४८ में इश्यू विभाग में तो स्टरलिंग पावने में वृद्धि हुई और ११३५.३२ करोड़ रुपये तक उसकी मात्रा पहुँच गई पर बैंकिंग विभाग में स्टरलिंग पावने की मात्रा घटकर ४०६.६५ करोड़ रह गई और फलस्वरूप कुल मात्रा १५४२.२७ करोड़ रुपये की ही रही। बैंकिंग में स्टरलिंग पावने की कमी १९४६-४७ में ही आरम्भ हो गई थी और वह सितम्बर १९४७ तक तो बराबर जारी रही। इस कमी का कारण यह था कि हमारे विदेशी व्यापार का संतुलन प्रतिकूल होने लग गया था। १९४८-४९ में स्टरलिंग पावने की मात्रा इश्यू विभाग में तो कम होते होते ६०७.४७ करोड़ रुपये और बैंकिंग विभाग में ३०७.७८ करोड़ रुपये तक और इस प्रकार कुल ९२१५.२५ करोड़ रुपये तक पहुँच गई। स्टरलिंग पावने में एकदम इतनी कमी आ जाने के मुख्य कारण तीन थे। सबसे बड़ा कारण तो यह था कि विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिज़र्व बैंक के एसेट्स का जो बंटवारा हुआ उसके कारण पाकिस्तान बैंक को १ जुलाई १९४८ को १४.५२ करोड़ रुपये का स्टरलिंग पावना दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान को भारत के नोट लौटाने पर भी स्टरलिंग दिया गया। दूसरा कारण यह था कि भारत-इंग्लैंड में भारत स्थित युद्ध सामग्री और पेन्शन संबंधी सालाना किरातों को चुकाने के बारे में जो आर्थिक समझौता हुआ था उसके कारण भी भारत को २८४.१६ करोड़ रुपये का स्टरलिंग पावना इंग्लैंड को देना पड़ा। स्टरलिंग पावने में कमी आने का तीसरा कारण आयात के अधिक होने का भी रहा। सन् १९४६-४७ में स्टरलिंग पावने की मात्रा और भी कम हो गई—इश्यू विभाग में ६४७.०४ करोड़ रुपये के और बैंकिंग विभाग में १८०.६१ करोड़ रुपये के, इस प्रकार कुल ८२७.६५ करोड़ रुपये का स्टरलिंग पावना बैंक के पास रह गया। इस कमी का एक कारण तो यह था कि आयात के प्रारम्भ में अत्यधिक आयात हुआ यद्यपि बाद में आयात नीति में कड़ाई आने से, निर्यात को बढ़ाने से और रुपये के अवमूल्यन से इनकी मात्रा में वृद्धि भी हुई। दूसरे, करेंसों की मात्रा में कमी आने का भी यह असर हुआ कि इश्यू विभाग में स्टरलिंग की मात्रा कम हुई यद्यपि बैंकिंग विभाग में बढ़ी। १९४६-४७ का ठीक ठीक अन्दाज़ इस बात से लगाया जा सकता है कि २५ मार्च १९४६ को रिज़र्व बैंक के इश्यू विभाग में ७४१.६२ करोड़ रुपये और बैंकिंग विभाग में २०२.५२ करोड़ रुपये और इस प्रकार कुल ९४४.१४ करोड़ का स्टरलिंग था। १७ जून १९४६ तक ये मात्राएँ कम होकर

इश्यू विभाग में ७१० ३४ करोड़ रुपये तक और बैंकिंग विभाग में १२७ ६५ करोड़ रुपये तक घाना कुल ८३८ २६ करोड़ रुपये तक हो रहे गये। अर्थात् १९४६-५० के प्रथम ताल महीनों में १०५ ८५ करोड़ का कुल कमी आगम। पर बाद में आयात को कम करने, निर्यात को बढ़ाने और रुपये का अवमूल्यन से स्थिति में सुधार आया और ३१ मार्च १९५० को रिजर्व बैंक के इश्यू विभाग में ६५० १४ करोड़ रुपये और बैंकिंग विभाग में २०८ ४३ करोड़ रुपये, इस प्रकार कुल ८५८ ७७ करोड़ रुपये का स्टैरलिंग पावना बैंक के पास था। इसका अर्थ यह हुआ कि १७ जून १९४६ के बाद से ३१ मार्च, १९५० तक के लगभग ६३ महीने में कुल २०३ करोड़ रुपये का स्टैरलिंग पावना बढ़ा। यह, जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, आयात का कमी, निर्यात का वृद्धि और रुपये का अवमूल्यन का असर था। दिसम्बर १९५० के अन्त में स्टैरलिंग पावना ८३४ करोड़ रुपये का था। इससे बाद स्टैरलिंग पावने में वृद्धि होने लगी। २३ मार्च, १९५१ को उनका मूल्य ८८४ करोड़ रुपये तक पहुँच गया था। पर बाद में कमी आई। स्टैरलिंग पावने के सबसे ताज़ा आँकड़े इस प्रकार हैं कि ३१ अगस्त, १९५१ को रिजर्व बैंक के इश्यू विभाग में ६१३ १५ करोड़ रुपये का और बैंकिंग विभाग में २१३ ६८ करोड़ रुपये का स्टैरलिंग पावना मौजूद था। ३१ अगस्त, १९५१ को कुल स्टैरलिंग पावना ८२७ १३ करोड़ रुपये का था जब कि ३१ मार्च, १९५० को कुल ८५८ ७७ करोड़ का और दिसम्बर १९५० के अन्त में ८३४ करोड़ का स्टैरलिंग पावना मौजूद था।

स्टैरलिंग पावने में कब कितना वृद्धि हुई और कितनी कमी हुई इसका नियन्त्रण ऊपर था। इसने सम्भव है दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार भारत का इंग्लैंड कर्जदार हो गया और भारत और इंग्लैंड के बीच की स्थिति गर्मपा बदल गई। पहले भारत से इंग्लैंड को कर्ज लेना था पर अब भारत को इंग्लैंड से लेना हो गया। भारत को यह स्थिति देश की अत्यन्त गरीबी के होते हुए मिली। इसका सचेत में सार यह है कि भारत की सारी जनता ने अपना पेट काटकर युद्ध के समय इतना रुबे बर्दाश्त किया।

यह युद्ध समाप्त हो गया तो यह सवाल उठा कि इंग्लैंड से जो इतना स्टैरलिंग लेना है वह साम्प्रतिसीमा वगूल हो। भारत का मत इस बारे में यह था कि देश की जनता ने कष्ट उठाकर के इंग्लैंड तथा दूसरे मित्र राष्ट्रों की मदद की और अन्तस्वरूप यह स्टैरलिंग पावना जमा हुआ। अब इंग्लैंड को देश की आर्थिक उन्नति के लिये आवश्यक इस स्टैरलिंग पावने का भारत

को चुकारा करना चाहिये। इंग्लैंड की स्थिति भी युद्ध के कारण आर्थिक दृष्टि से बहुत बिगड़ गई थी। वह ऐसा अनुभव करता था कि उसकी जैसी स्थिति है उसमें भारत का इतना कर्ज चुकाना संभव नहीं है। जिस समय यह कर्ज हुआ उस समय भारत में चीन्नों का मूल्य बहुत ऊँचा था और इस कारण कर्ज की मात्रा बड़ गई। इन बातों का विचार करके इंग्लैंड कर्ज में कुछ कटौतरी चाहता था। इससे देश में एक बड़ा विरोध खड़ा हो गया। पर आखिरकार कटौतरी का विचार समाप्त हो गया और भारत को कर्ज चुकाने के बारे में दोनों देशों में बातचीत आरम्भ होगई।

उपरोक्त बात-चीत के फलस्वरूप अगस्त १९४७ में ब्रिटेन और भारत में एक अन्तरिम समझौता हुआ। इस समझौते की श्रवधि ३१ दिसंबर १९४७ को समाप्त होती थी और १५ जुलाई १९४७ से वह लागू समझा गया था। इस समझौते के अनुसार रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में अकाउन्ट नं० १ और नं० २ इस प्रकार दो खाते खोले। १४ जुलाई १९४७ को रिज़र्व बैंक के कुल स्टरलिंग पावने की रकम ११६ करोड़ पाँड निश्चित की गई और वह नं० २ के अकाउन्ट में जमा की गई। इन ११६ करोड़ पाँड में से ६५ करोड़ पाँड नं० १ में जमा किया गया। इन ६५ करोड़ पाँड में ३५ करोड़ पाँड तो चालू खर्च के लिये थे और ३ करोड़ पाँड बतौर चालू वेर्लेस के थे। समझौते में यह साफ कर दिया गया था कि अकाउन्ट नं० १ में जो स्टरलिंग है वह चालू खर्च के लिये उपलब्ध रहेगा और सब विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित हो सकेगा। समझौते होने की तारीख के बाद स्टरलिंग की चालू आमद अकाउन्ट नं० १ में जमा रहेगी और नं० २ से जो रकम चुकाई जायगी वह भी नं० १ के अकाउन्ट में जमा होगी। नंबर २ के अकाउन्ट का स्टरलिंग चालू खर्च में नहीं आया और समय समय पर होने वाले समझौतों के अनुसार ही नंबर २ से नंबर १ में स्टरलिंग जमा होता रहेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत के स्टरलिंग परिव्या में होते हुए भी नंबर १ के अकाउन्ट की रकम को ध्यान रखते हुए यहाँ स्टरलिंग के चुकारे पर उसी तरह से नियंत्रण करना पड़ा जैसे नॉन-स्टरलिंग देशों की मुद्रा पर था।

जनवरी १९४८ में फिर ६ महीने के लिये समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार १८ करोड़ पाँड की और रकम नंबर २ से नंबर १ के अकाउन्ट में ३० जून १९४८ तक के चालू खर्च के लिये जमा की गई। इस प्रकार नंबर १ के अकाउन्ट में कुल ८३ करोड़ पाँड जमा हुये। पर इस बार स्टरलिंग के दूसरी विदेशी मुद्राओं के परिवर्तन की मर्यादा एक करोड़ पाँड

की निश्चित कर दी गई। पहले वाले समझौते में इस तरह की कोई मर्यादा नहीं थी। इसका अर्थ यह था कि १९४८ के पहले छ' महीने में भारत को दुर्लभ मुद्रा का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से श्रृङ्ख के रूप में या सामान्य व्यापार के सिलसिले में जितनी दुर्लभ मुद्रा का आम्दानी हो उससे अधिक से अधिक एक करोड़ पाँच की दुर्लभ मुद्रा वह और मन कर सकता था। दुर्लभ मुद्रा में बचत करने की दृष्टि से यह प्रतिबंध स्थापित किया गया था।

भारत और इंग्लैंड के बीच में नौ जुलाई १९४८ को एक और समझौता हुआ। इस अनुसार भारत-इंग्लैंड के समझौते का अवधि १० जून १९५१ तक बढ़ा दी गई। छ' छ' महाने के लिये जो समझौते होने थे उनमें विदेशी व्यापार और विदेशी विनियम के संबंध में एक प्रकार का अनिश्चितता का स्थिति बनो रहनी थी। इस समझौते में तीन बातों का उल्लेख था—अनिमाजित भारत ने अप्रैल १९४७ में निम्न से जो सामग्री और इन्ट्रा शेड्स ले लिये थे उनका मूल्य तय किया गया, भारत के अग्रज कर्मचारियों को जो पेंशन भुगतान था उसका पुँजीकरण किया गया और स्टर्लिंग पावने के जुआरे ४ बारे में निश्चय किया गया। हमारा यहाँ आगिरी माँग से ही सम्बंध है। इस बारे में यह निश्चय हुआ कि ३० जून, १९५१ तक समाप्त होने वाले तीन सालों में से आसिरा मो मालों में ८ करोड़ पाँच स्टर्लिंग नंबर २ न नंबर १ साते में और जमा किया जाय। पहले के ८ ३ करोड़ पाँच में से केवल १० लाख पाँच ही रख हुआ था। इसलिये इस नंबर १ के लिये में इस प्रकार दुर्ल १६ करोड़ पाँच नंबर २ के लिये से आई हुई रकम में से इन तीन सालों में सर्व के लिये उपयुक्त किया गया। नंबर २ से नंबर १ के अकाउंट में रकम जमा होने के बारे में यह निश्चय किया गया कि ५०-५० लाख पाँच की किराई में रकम जमा हो और नंबर २ के अकाउंट में ६ करोड़ पाँच से कम रकम जमा न रहे। समझौते के पहले वर्ष में १२ करोड़ पाँच दुर्लभ मुद्रा में बदलने का तय हुआ और दूसरे और तीसरे साल ४ लिये यह निश्चय बाद में करना निश्चय हुआ।

इस समझौते के बाद भारत में आयात बहुत हुआ और नंबर १ के अकाउंट में से रकम ग्व हो गई। इस सम्मन्ध को हल करने के लिये जून-जुलाई १९४९ में भारत सरकार का प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड गया। वहाँ यह समझौता हुआ कि जून १९४९ में समान होने वाले साल के लिये यहाँ पहले समझौते में कोई रकम नहीं रखी गई थी अब ८ १ करोड़ पाँच की रकम नंबर २ से नंबर १ के साते में जमा की जाये। इसके अलावा ५ करोड़ पाँच

तक मई १९४६ तक औपनि जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत जो माल बाहर से मंगाना नय हो गया था उसके लुकारे के लिये देना तय हुआ। इसके अलावा जून १९५० और १९५१ में समाप्त होने वाले वर्षों के लिये नंबर २ से नंबर १ के अकाउन्ट में ४ करोड़ की बजाय ५ करोड़ पौंड की रकम तय की गई। पिछले समझौते में यह मर्यादा भी तय कर दी गई थी कि भारत जुलाई १९४८ तक १.३ करोड़ पौंड (६ करोड़ डालर) दुर्लभ मुद्राओं में बदल सकेगा। इस समझौते में यह निश्चय हो गया कि भारत पर इस प्रकार की कोई मर्यादा न लगाई जावे। दूसरे शब्दों में भारत फिर स्टरलिंग क्षेत्र का पूरा सदस्य हो गया। इसके पक्ष में कॉमनवेल्थ के दूसरे राष्ट्रों के साथ साथ भारत ने भी यह स्वीकार किया कि १९४८ में दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों से जितना आयात उसने किया था उसका ३/४ ही जुलाई १९४६ से जून १९५० तक वह आयात करेगा। जो आयात अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से श्रवण लेकर किया जायगा वह इससे अलग होगा।

स्टरलिंग पावने के संबंध में भारत और इंग्लैंड में अन्तिम समझौता दिसम्बर १९५० में हुआ। इस समझौते के अनुसार जुलाई १९५१ से आगामी छः वर्षों तक १.३ करोड़ पौंड प्रतिवर्ष भारत को इंग्लैंड से वसूल करने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी एक वर्ष में कोई रकम वसूल न की जाय तो वह कमी आगामी वर्ष में पूर्ण हो सकेगी। इसी प्रकार ५० लाख पौंड तक किसी वर्ष में अगले वर्ष के हिसाब में से हवाला भी लिया जा सकेगा। हाल में यह मालूम पड़ा है कि ब्रिटेन भारत से स्टरलिंग पावने संबंधी समझौते में पाकिस्तान से जुलाई १९५१ में जो समझौता हुआ है उसी आधार पर संशोधन करना चाहता है। एक तो यह कि नं० २ के अकाउन्ट की सब रकम नं० १ के अकाउन्ट में जमा कर दी गई है, हालांकि पाकिस्तान बिना ब्रिटेन से सलाह किये उन्हें खर्च नहीं कर सकेगा। दूसरे यह कि नं० २ के अकाउन्ट की कुछ रकम पाकिस्तान को लेने में दी गई है। इस आधार पर भारत को भी संशोधन कर लेना चाहिए। केवल यह बात साफ़ होना चाहिए कि भारत स्टरलिंग खर्च करने के सम्बन्ध में ब्रिटेन से सलाह चाहे करे पर ब्रिटेन को उसे रोकने का अधिकार नहीं होगा।

स्टरलिंग पावने के संबंध में भारत और ब्रिटेन के बीच में जो समझौते हुए हैं वे सारी परिस्थिति में ठीक माने जाने चाहिए। अब तक स्टरलिंग पावने का उपयोग देश की आर्थिक उन्नति के लिए नहीं हो सका, पर आगे इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। स्टरलिंग पावने की मात्रा को बहुत बढ़ने देना भी उचित नहीं होगा।

रुपये का अवमूल्यन : शुद्धोत्तर काल में सितम्बर १९४६ में इंग्लैंड द्वारा

स्टरलिंग का अन्वूलन करो के कारण भारत ने अपने रुपये का जो अन्वूलन किया वह भारतीय मुद्रा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक लिखना आवश्यक है।

अन्वूलन का अर्थ यह है कि जिस मुद्रा का अन्वूलन किया जाय उसकी विदेशी विनिमय मूल्य समान बन जाय। स्टरलिंग के अन्वूलन का अर्थ यह था कि अन्वूलन के पहले जहाँ १ पौंड स्टरलिंग के बदले में ४.०२ डालर मिलते थे अब अन्वूलन के पक्ष-पर १ पौंड स्टरलिंग के बदले में २.५० डालर ही मिलने लगे। स्टरलिंग के साथ साथ दुनिया के कई देशों ने अन्वूलन किया। भारत भी उसमें से एक था इसलिए अन्वूलन के पहले जहाँ १ रु० के बदले में ३१ सेंट आते थे अब अन्वूलन हो जाने में २१ सेंट ही आने लगे। पौंड स्टरलिंग के मूल्य में अन्वूलन से ३०.४% का कमा की गई था। भारत ने भी इतना ही कमी की। दूसरे देशों में से कई में ब्रिटेन के साथ अन्वूलन किया तो वही पर कड़ियों की अन्वूलन की मात्रा अलग अलग थी—जैसे कनाडा ने ६.१% डेलवियम ने १२.३% इटली ने ६.४% अन्वूलन किया था। अधिकतर अन्वूलन का दर वहाँ भी जो इंग्लैंड का था। पाकिस्तान ने अपने रुपये का अन्वूलन नहीं किया।

अन्वूलन का मूलभूत कारण यह था कि दुनिया के मुद्रा बाजार में डालर की कमा आगे जा रहा था। इसी कारण डालर एक दुर्लभ मुद्रा बन गया था। डालर को इस बढ़ती हुई कमा के कारण कई वे लेते —

(१) अमेरिका के माल की बड़ी हुई मांग। सुदोतर पुनर्निर्माण के निवे, और सुदोतराला दसा हुई चार्ज की मांग को पूरा करने लिये अमेरिकन माल की यह मांग बढ़ती जा रहा था।

(२) अमेरिका अपने कच्चे माल की आवश्यकता बहुत कुछ स्वयं पूरा करने लगा था। मगाना यह हुआ कि दूसरे कच्चे माल पैदा करने वाले देशों के लिये अब अमेरिका में अपना कच्चा माल बेचकर डालर कमाना समय नहीं रहा।

(३) दुनिया के दूसरे देशों में सुदन कारण जो विनाश हुआ उत्तले उत्पादन में बहुत कमी हुई।

(४) इस तरह से विदेशी विनियोग और इन्वोरेंस तथा चहाइराना की सेवाओं में होने वाला आय भी सुदन के समय में कम हो गई था।

अमेरिका के साथ साथ दुनिया का धाटा कितना बढ़ गया था इसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है कि सुदोतर काल का सबसे अधिक पाटा १९४३ में ११.३ मिलियन डालर (१ बिलियन = १ अरब) तक पहुँच गया था। इस स्थिति में उपार-बढ़ाव आता रहा। अब दुनिया के डालर और होने के

रक्षित कोष की मात्रा में भी इसी तरह उतार-चढ़ाव आता रहा। पर १९४६ के दूसरे त्रिमास में शेष दुनिया के डालर और सोना के कोष में ३३० मिलियन डालर की कमी आई। पर डालर की कमी संबंधी सब देशों की स्थिति समान नहीं थी। डालर के रक्षित कोष में १९४६ के तीसरे त्रिमास (जुलाई-सितंबर) में भी कमी आई। इस-कमी को ठीक करने के प्रयत्न तो जारी थे, जैसे अमेरिका से निर्यात की मात्रा बढ़ाने और आयात को मात्रा कम करने की कोशिश की जा रही थी, पर इन प्रयत्नों के बावजूद भी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इस समय अमेरिका में जो व्यापारिक और व्यवसायिक गति शिथिलता (रिसेशन) आरंभ थी उसका असर भी स्थिति को बिगाड़ने का हो रहा था क्योंकि अमेरिका ऐसी स्थिति में अपने आयात में कमी करने के प्रयत्न में था।

उपरोक्त स्थिति का असर स्टर्लिंग क्षेत्र पर तो बहुत ही घातक हो रहा था। स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के लिए अमेरिकन माल का महत्व भी विशेष था। १९४६ के दूसरे त्रिमास की अपेक्षा अमेरिका को जाने वाले माल से ६३ मिलियन डालर की आमदनी कम हुई और अमेरिका से आने वाले माल पर ८५ मिलियन डालर का खर्च कम हुआ। १९४६ के दूसरे त्रिमास में स्टर्लिंग क्षेत्र के डालर और सोने के रक्षित कोष में २६१ मिलियन डालर की कमी आ गई और उसकी मात्रा १६५१ मिलियन डालर तक पहुँच गई। १९४५ के बाद यह सबसे कम मात्रा थी। सोने और डालर के रक्षित कोष में जिस दर से कमी आ रही थी अगर वही गति चलती रहती तो वर्ष भर के अन्दर-अन्दर चारा रक्षित कोष समाप्त हो जाने का भय था। इस स्थिति का सामना करने के लिये १२ जुलाई, १९४६ को कॉमनवेल्थ के राष्ट्रों के वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। इसी में यह निश्चय किया गया था कि १९४८ की अपेक्षा १९४६ जुलाई से १९५० जून तक ७५% डालर व्यव में कटौतरी की जाये। १९४६ के तीसरे त्रिमास में स्टर्लिंग क्षेत्र की स्थिति तो और भी बिगड़ी बढपि सारी दुनिया की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ था। इस तीसरे त्रिमास में इंग्लैंड के डालर और सोना रक्षित कोष में २२६ मिलियन डालर की कमी आ गई थी।

सितंबर के दूसरे सप्ताह में अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की सरकारों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें इस स्थिति का सामना करने के कई उपाय सोचे गये, पर स्टर्लिंग का अवमूल्यन करने का कोई संकेत नहीं था। पर १८ सितंबर को यकायक इंग्लैंड ने अवमूल्यन की घोषणा कर दी।

ब्रिटेन ने अवमूल्यन की घोषणा करने से पहले भारत सरकार से कोई विचार विनिमय नहीं किया था और न इस निर्णय की भारत को कोई पूर्व सूचना

थी थी। ऐसा करना ब्रिटेन का नैतिक कर्तव्य था। कॉमनवेल्थ के राष्ट्रों के प्रति उसकी सघात और बलादारा की यह भाव थी। ब्रिटेन के इस एकांगी निर्णय का भारत में बहुत विरोध हुआ। नहीं तो भारत के स्वयं के निर्णय का मयाल या भारत के सामने मान्य विषय थे—(१) अवमूल्यन नहीं करना, निम्नका परिणाम रुपवास्टरलिंग दर में वृद्धि होने का आना, (२) अवमूल्यन करना पर ब्रिटेन से कम माना न और (३) ब्रिटेन से बराबर ही अवमूल्यन करना। देश में हम प्रश्न पर वाद विवाद भी चला पर अन्तर्योगवा भारत ने निर्णय यही किया कि इंग्लैंड के बराबर रुपये का भी अवमूल्यन किया जाये। भारतीय रुपया १० २२½ सेंट से घट कर २१ सेंट पर बराबर रह गया और सोने में भी रुपये का मूल्य ० ०६८६०१ ग्राम से गिरकर ० ०६६६२१ ग्राम शुद्ध सोना हो गया। इस नये विनिमय दर का निर्णय नो २० सितंबर १९४६ को ही घोषित हो गया था पर वह लागू २२ सितंबर से हुआ क्योंकि बैंक आदि की १६ से २१ सितंबर तक की छुट्टी था।

भारत ने अवमूल्यन का निर्णय इसलिये किया कि अन्यथा दूसरे स्टर्लिंग देशों का मुद्रा के मुद्राबल में रुपये का मूल्य बढ़ जाता। भारत का उन देशों के साथ निर्यात, जो कि देश के पुनर्निर्यात का एक बहुत बड़ा भाग है, कम हो जाना, और भारतीय उद्योग का प्रतिस्पर्धा शक्ति पर भी मुद्रा अक्षर पड़ना। पर भारत के अवमूल्यन से दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र और प्रधानतः अमेरिका से जो माल हमें मँगाना पड़ना है जैव खाद्यान्न, मयानगी आदि वह मँहगा हो गया। पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया इसका भा अक्षर पुरा पड़ा। ब्यापक और पटखन जैम कच्चे माल का मूल्य बढ़ गया। अवमूल्यन से देश में मूल्य बढ़ने की और उड़ चीनों का निर्यात मूल्य बढ़ने की आशावा थी। इस स्थिति का सामना करने के लिये भारत सरकार ने कई चीनों पर निर्यातकर लगाया जैसे लौहा और इस्पात तथा केमिकल तेल पर और चूड़ और जूट के माल पर निर्यातकर बड़ा दिया। दूसरे अनिश्चित इसी उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें जाचे निम्न आठ बातें शामिल थी—

(१) विदेशी व्यापार का इस प्रकार संचालन किया जाय कि विदेशी विनिमय का व्यय कम से कम हो।

(२) किन देशों की मुद्राओं का रुपये का अपेक्षा मूल्य बढ़ गया है उनसे जो औद्योगिक कच्चा माल खरादना पड़े उसकी कामत कम करने का हर तरह से प्रयत्न हो।

(३) दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र को निर्यात होने वाला चीनों पर निर्यातकर लये

ताकि देश को अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय प्राप्त हो और अवमूल्यन से होने वाले लाभ में विदेशी खरीदार और भारतीय बेचने वाले के साथ साथ भारत सरकार का भी हिस्सा हो।

(४) कानूनी और शासन सम्बन्धी उपायों और साख व्यवस्था के नियंत्रण से मूल्य वृद्धि को रोकने का प्रयत्न किया जाये।

(५) विनियोग को प्रोत्साहन दिया जाये और बचत करने के पक्ष में प्रचार किया जाये और गाँवों में बैंकिंग सुविधा की व्यवस्था की जाये।

(६) धान्य-कर के वक़ाया को मिलजुल कर तय किया जाये।

(७) सरकारी खर्च में १९४६-५० में ४० करोड़ की और १९५०-५१ में १९४६-५० के बजट के अनुमान की अपेक्षा कमसे कम ८० करोड़ रुपये की बचत की जाये।

(८) आवश्यक जीवन पदार्थों, निर्मित पदार्थों, अन्न की रिटेल कीमतों में १०% कमी की जाये।

उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार भारत सरकार ने कई व्यावहारिक कदम भी उठाये। आयात नीति में कड़ाई लाई गई। जूट के निर्यात मूल्य तय किये गये, कई चीजों का निर्यात-कर बढ़ गया और कई पर लगाया गया। जैसे कच्चे कपास पर ४० ह० से १०० ह० निर्यात-कर कर दिया गया और काली मिर्च पर ३०% निर्यात-कर लगा दिया गया। कपास के बीज में 'फारवर्ड ट्रेडिंग' बन्द कर दिया गया और गुड़, गुड़ शकर और राव में भी सट्टा बन्द कर दिया गया। अनिवार्य बचत की योजना राज कर्मचारियों पर लागू की गई और १९५०-५१ के बजट में उद्योग धंधों के साथ कई रियायतें की गईं। ग्रामीण बैंकिंग जांच कमेटी भी नियुक्त की गई जिसकी रिपोर्ट भी पेश हो चुकी है। भारत सरकार के खर्चों में कमी करने के प्रयत्न भी जारी हुए यद्यपि उनमें नाम मात्र को कुछ हुआ। अनाज के मूल्य को कम करने के लिये लेवी बट्टी की कीमतें कम की गईं और अनाज के मूल्य भी कम किये गये। कपड़े की कीमतों में भी कमी की गई।

अब विचारने का प्रश्न यह है कि अवमूल्यन के बाद हमारे विदेशी व्यापार, विदेशी विनिमय और मूल्यों का हाल क्या रहा?

अवमूल्यन के परिणाम का उल्लेख करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी ३० अप्रैल १९५० को समाप्त होने वाला वार्षिक रिपोर्ट में लिखा है कि १९४८ के अन्तिम त्रिमास और १९४९ के प्रथम त्रिमास में अमेरिका से प्राप्त होने वाले भाल और सेवाओं के कारण ६८ मिलियन डालर प्रति वर्ष के हिसाब से अमेरिका के पक्ष में संतुलन रहता था वह १९४९ के अन्तिम त्रिमास में ४४

विलियम डालर प्रतिवर्ष के हिसाब सही रहा। स्टर्लिंग क्षेत्र के विषय में रिपोर्ट में लिखा है कि इंग्लैंड का सोना और डालर के रक्षित कोष में भी १९४६ के अन्त में २६८८ मिलियन डालर सन् १९५० के अन्त में २४११ मिलियन डालर तक की वृद्धि हो गई। अन्तर्राष्ट्रीय कोष का यह कहना था कि अवमूल्यन का जो मन्त्राल का उद्देश्य था वह पूरा हो गया। अवमूल्यन करने वाले देशों की डालर संख्या स्थिति में सुधार होने का प्रमाण कारण आयात के कम होने का था और निर्यात व बढ़ने का अपेक्षाकृत कम अंतर था।

जहाँ तक भारत का संबंध है अवमूल्यन का हमारे विदेशी व्यापार पर अनुकूल अंतर पड़ा। अवमूल्यन के बाद के साल भर के हमारे विदेशी व्यापार के आंकड़ों के अनुसार अगस्त १९५० में समान होने वाले ११ महीनों में हमारा कुल निर्यात ४५८ करोड़ रुपये का हुआ जबकि १९४८-४९ के समान समय में वह ३६० करोड़ रुपये का ही हुआ था। दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों की १२७ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ जब कि १९४८/९ में यह ८६ करोड़ का था। मुख्य मुद्रा क्षेत्र को होने वाले निर्यात का मूल्य ३३१ करोड़ था जबकि १९४८-४९ में उसका मूल्य २७१ करोड़ रुपया था। इस बढ़े हुए निर्यात का कारण कुछ चीजों की मात्रा बढ़ना और कुछ का मूल्य बढ़ना दोनों ही थे। मूल्य वृद्धि के निर्यात में बहुत वृद्धि हुई। कपास, मसाला, अबरक, धमका आदि का निर्यात भी बढ़ा। हाल में रत्नचंद्र बैंक की करैसी और फाइनेंस कंपनी १९५०-५१ की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें भी १९५० के विदेशी व्यापार के सन्तुलन के जो आँकड़े दिये गये हैं उनमें यह प्रगट होता है कि बालू हिसाब में जहाँ १९४६ में कुल मुद्रा के सन्तुलन १६६.३ करोड़ रुपये से भारत के प्रतिफल था वह १९५० में ६१५ करोड़ रुपये से भारत के अनुकूल हो गया। यदि हम करैसी की दृष्टि से विचार करें तो मान्य होता है कि स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के सम्बन्ध में जहाँ १९४६ में भारत को ४६ करोड़ रुपये का घाटा था वहाँ १९५० में ५६.७ करोड़ रुपये की बचत हुई। इसी प्रकार दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र के देशों के बारे में भी जहाँ १९४६ में ५३ करोड़ रुपये का घाटा था वहाँ १९५० में २६ करोड़ रुपये का बचत हो गई। दूसरे क्षेत्रों के बारे में स्थिति यह थी कि १९४६ में ७०.३ करोड़ रुपये का घाटा था वह १९५० में कम होकर २७.१ करोड़ रुपये का हो रहा गया।

उपरोक्त स्थितिक बारे में इस यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि उसके निम्ने अवमूल्यन के अलावा कोरिया युद्ध से उत्पन्न यह परिस्थिति भी कारण है जिसने युद्ध की आशंका से युद्ध की दृष्टि से आवश्यक चीजों की अन्तर्राष्ट्रीय मात्र में वृद्धि करता है।

अवमूल्यन के बाद मूल्यों पर क्या असर हुआ यह भी जानने का विषय है। यह तो ठीक है कि अवमूल्यन के तुरन्त बाद ही मूल्यों में वृद्धि रोकने में सरकार किसी हद तक सफल हो सकी। अक्टूबर १९४६ में जनरल इन्डेक्स बढ़कर ३६३'३ तक पहुँच गया था पर यह कहना कठिन है कि यह वृद्धि किस हद तक तो अप्रैल १९४६ में जो मूल्य वृद्धि आरंभ हुई थी उसका परिणाम थी और किस हद तक अवमूल्यन का। पर उसके बाद जनरल इन्डेक्स में कमी आई और दिसंबर १९४६ में कम होते-होते वह ३८१'३ प्वाइंट तक पहुँच गया। पर बाद में वह वापस ऊपर की ओर जाने लगा और मार्च १९५० में ३६२'४ तक पहुँच गया था। इसी समय कोरिया युद्ध के आरंभ होने से मूल्यों की वृद्धि न केवल भारत में बल्कि संसार के दूसरे देशों में भी अधिक तेजी से होने लगी। उदाहरण के लिये अमेरिका में १९५० के पूर्वार्द्ध में जहाँ योक्त मूल्यों में ४ प्रतिशत वृद्धि हुई थी वहाँ मार्च १९५१ तक १७ प्रतिशत वृद्धि होगई। इसी प्रकार ब्रिटेन में १९५० के पूर्वार्द्ध में ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी पर उसके बाद के ११ महीनों में २५ प्रतिशत तक वृद्धि हो गई। कनाडा में अप्रैल १९५१ तक जून १९५० से १६ प्रतिशत मूल्यों में वृद्धि हुई। भारत में, १९५० के पूर्वार्द्ध में ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई और जून १९५० से अप्रैल १९५१ तक १६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत में जनरल इन्डेक्स जहाँ जून १९५० से ३६५'६ तक पहुँच गया था वह १६ जून १९५१ को ४५८'२ तक पहुँच गया। यह ठीक है कि इसके बाद मूल्यों में कुछ कमी आई है पर अब भी जून १९५० से वह कहीं अधिक है। अगस्त १९५१ में भारत में जनरल इन्डेक्स ४३७'६ था।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अवमूल्यन के बाद मूल्यों में वृद्धि आई है। पर इस वृद्धि का एक बड़ा कारण कोरिया युद्ध रहा।

क्या रुपये का पुनः मूल्यन किया जाय : स्टर्लिंग पींड के अवमूल्यन के साल भर बाद ही ब्रिटेन में यह चर्चा चल पड़ी कि पाँड का फिर से मूल्यन (रिवैल्यूशन) किया जाय। भारत में भी पुनः मूल्यन के बारे में चर्चा चली। जब भारत ने पाकिस्तान द्वारा उसके रुपये का अवमूल्यन नहीं करने का फैसला कर लिया तो भारत में रुपये के पुनः मूल्यन की चर्चा ने विशेष जोर पकड़ा। इस समय (अगस्त १९५१) भी यह चर्चा चल रही है। हम इस संबंध में थोड़ा विस्तार से विचार करेंगे।

पुनः मूल्यन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क उपस्थिति किये जाते हैं :—

(१) पुनः मूल्यन से हमारे देश में मूल्यों में कमी आ सकेगी। कोरिया युद्ध के कारण जो मूल्य वृद्धि दुनिया में हो रही है उसका असर भारत पर भी

पड़ा है और पुनः मूल्यन से इस मूल्य वृद्धि को रोकना आ सकेगा। यह मूल्य वृद्धि इस तरह से एक संशय की कि जब रुपये का विदेशी विनिमय बढ़ जायगा तो बाहर से आने वाले सामान का भारत में खपना में बढ़ा हुआ मूल्य नहीं होगा और इस प्रकार भारत में उनका मूल्य वृद्धि करने का अवसर नहीं होगा। पर यह आशा दुराशा माना जावेगा होगा। इसका एक कारण तो यह है कि रुपये का पुनः मूल्यन अगर बर दिया गया तो जो देश भारत को आयात करने हैं वे अपने माल का मूल्य बढ़ा सकते हैं—जैसे देश में बाहर से आने वाले सामान में ४०-५० प्रतिशत डिस्टा प्याच का है तो हमें बर्मा, पाकिस्तान, हिन्द-चीन और मियान्मार से सरकारों के माध्यम मिलता है। ये देश अपने आयात का क्रयित बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार गेट के चार में मा यह समझ है कि अन्तराष्ट्रीय गेहूँ समझौते में जो गुंताहट छोड़ा गया है उसका लाभ उठा कर गेहूँ का क्रयित में भी वृद्धि करनी जाय। नहीं तो कि पुँजा पदार्थों का खप है उनके बेचने वाले कम हैं और खरीदने वाले अधिक हैं और इसलिए उन्हीं क्रयित में भी बेचने वालों द्वारा वृद्धि करना समझ है। जहाँ तक दूसरा आयात का चार्ज का संबंध है अगर आयात के व्यापारियों को न खर्ची मिल भी गई तो वह आवश्यक नहीं है कि उन सस्ते मूल्यों का लाभ आयात व्यापारी अपने तक ही न रक्कर उपभोक्ताओं तक पहुँचाने दें। गाराय यह है कि रुपये के पुनः मूल्यन से मूल्य वृद्धि को रोकना समझ नहीं होगा। यह भी स्पष्ट तार पर समझ लेना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है कि विदेशी मिलें अपने माल की क्रयित क्या भारत के लिये न बढ़ा सके। ऐसा करना सम्भव है। साथ ही अन्तराष्ट्रीय मूल्यों में अब कुछ गिरावट आने दे और मूल्य नियंत्रण के लिये प्रयत्न मा किया जा रहा है।

(२) पुनः मूल्यन के पल में दूसरा नई यह दिया जाता है कि अन्तराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में व्यापार का आधार इनारे पल में हो जायगा। इसका अर्थ यह है कि आयात का अपेक्षा समान निर्यात के बदले में हम अधिक मात्रा में आयात कर सकेंगे या कम मात्रा में निर्यात करने समान मात्रा में आयात कर सकेंगे। पर यदि दूसरे देश भी अपना मुद्रा का पुनः मूल्यन करें, और ऐसा मानने का कोई कारण नहीं कि वे ऐसा नहीं करेंगे, तो हम यह लाभ नहीं मिल सकेगा।

(३) पुनः मूल्यन के समर्थनों का एक दलील यह रही है कि कोरिया युद्ध के कारण अन्तराष्ट्रीय मूल्यों का वृद्धि हुई है, पर भारत के निर्यात वस्तुओं का डालर की कीमतों की अपेक्षा कम मूल्य है। इसलिये पुनः मूल्यन आवश्यक है ताकि डालर और रुपये में मूल्यों की असमानता जाता रहे। इस बारे में एक शिवा तों ध्यान देने की यह है कि उन्हीं चीजों का मूल्य खास तौर से बढ़ा है जो

युद्ध की दृष्टि से आवश्यक है। पुनः मूल्यन का असर इन्हीं चीजों तक सीमित न रह कर आम तौर पर पड़ेगा। इसलिए सही यह है कि जहाँ आवश्यक हो निर्यात कर लगा कर भारत से निर्यात की चीजों की मूल्य वृद्धि कर दी जाये।

(४) पुनः मूल्यन के समर्थकों का यह भी कहना है कि रुपये की विनिमय दर अधिक हो जाने से हमारा निर्यात कम नहीं होगा क्योंकि हमारे निर्यात की वस्तुओं की मांग ऐसी अनिवार्य मांग है जिसे पूरा करना ही होगा। पर हमारा सब से ताज़ा अनुभव इस विषय में ऐसा नहीं है। यदि हम अब मूल्यन नहीं करते और निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न नहीं किया जाता तो हमारा निर्यात अचर्य ही कम हो जाता। बृट्ठ के निर्यात में युरोपीय देशों से प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। सूती कपड़े में भी हमारी स्थिति गिराई है और जापान और लंकाशायर की प्रतिस्पर्धा से हमारी स्थिति और कठिन होगी। चाय के निर्यात के बारे में भी हम सर्वथा निश्चिन्त नहीं हो सकते। इसी प्रकार दक्षिण-पूर्व एशिया में अच्छा उत्पादन होने पर काली मिर्च की पूर्ति की स्थिति में सुधार आना आवश्यक है। दूसरी निर्यात की वस्तुओं के बारे में भी हमने विदेशों से जो व्यापारिक समझौते किये हैं उनमें कुछ बन्धन अपने पर लगा रखे हैं। सारांश यह है कि पुनः मूल्यन का हमारे निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ना अनिवार्य होगा।

ऊपर हमने यह लिखा है कि पुनः मूल्यन के पक्ष में जो तर्क उपस्थित किये जाते हैं वे ठोस आधार पर आधारित नहीं हैं। अब हम उन बातों का विचार करेंगे जो पुनः मूल्यन के विपक्ष में जाती हैं :—

(१) पुनः मूल्यन के खिलाफ सब से बड़ी दलील यह है कि उसका असर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और सुकाये की स्थिति पर बुरा पड़ेगा। १९५१ में अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन में १६५० की अपेक्षा कम वचत की संभावना है। १९५१ के प्रथम त्रिमास में १४ करोड़ रुपये की वचत का अनुमान है जब कि १६५० के अन्तिम त्रिमास में ४६ करोड़ की वचत थी। पिछले महीनों में हमारे आयात में वृद्धि हुई है और निर्यात के मूल्यों में कमी आई है। पुनः मूल्यन का असर आयात को बढ़ाने और निर्यात को कम करने का होगा। रिज़र्व बैंक के रिसर्च विभाग ने भी अप्रैल १९५१ में इस बात की पुष्टि की है। उसका यह मत था कि १५% पुनः मूल्यन से ५० करोड़ के लगभग और ३०% से १३५ करोड़ के लगभग अन्तर्राष्ट्रीय सुकाये को दृष्टि से हमें घाटा होगा।

(२) इससे मिलाकुला प्रश्न विदेशी विनिमय का है। पुनः मूल्यन के कारण हमारा आयात बढ़ेगा पर उसका सुकाया करने के लिये आवश्यक विदेशी

विनिमय को पूर्ति होनी चाहिये। पर पुन मूल्य से इसमें सहायता नहीं मिलेगी। इसने अलावा विदेशी विनिमय का प्रश्न निर्यात का स्थिति से तय होना चाहिए न कि आयात का स्थिति से।

(२) रुपये के पुन मूल्यन का असर हमारे स्टरेलिंग पावने का रुपये में मूल्य कम कर देने का होगा।

(४) पुन मूल्यन का असर सरकार के बजट की स्थिति पर भी बुरा पड़ेगा क्योंकि निर्यात-कर से जो आय सरकार को आय होता है वह कम हो जायगी और यह लाभ व्यक्तिगत व्यवसायियों को होने लगेगा। इस समय भारत सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह आय के इस साधन का परित्याग करदे। आयात-कर में भी आय कम होगी क्योंकि बाहर से आने वाले माल की रुपये में पुन मूल्यन से क्रॉमन कम हो जायगी।

(५) पुन मूल्यन के विषय में एक दर्नाल यह भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ध्यान बहुत अनिश्चित अवस्था में है। एक समय हमें पुन मूल्यन के पक्ष में स्थिति मालूम हो सकती है और गुरत हो वह स्थिति बदल सकती है। ऐसी हालत में बार बार रुपये के विदेशी विनिमय को बदला नहीं जा सकता। ऐसा करना देश के हित में नहीं हो सकता। फिर इस सम्बन्ध में भारत को ही सबसे आगे होकर इदम उठाने का कोई आवश्यकता नहीं है, खास तौर से जबकि मूल्यों में व रहन सहन के स्तर में भारत की अपेक्षा दूसरे देशों में अवमूल्यन के बाद स्थिति अधिक बिगड़ी है। उदाहरण के लिये सितम्बर १९४६ से मार्च १९५१ तक जहाँ भारत में मूल्य में १३% और रहन सहन के व्यय में ६% वृद्धि हुई यहाँ अमेरिका में २०% और ६%, ब्रिटेन में ३६% और ७%, कनाडा में २२% और ११% तथा ऑस्ट्रेलिया में ४३% और २०% वृद्धि हुई।

उपरोक्त त्रिमेन का सार यही है कि इस समय हमें रुपये के पुन मूल्यन का विचार नहा करना चाहिये। भारत सरकार की यही नीति है जिसकी स्पष्ट घोषणा १९५१-५२ के बजट पर होने वाली बहस के मिनटिले में वित्त मंत्री ने करवायी।

अवमूल्यन नहीं करने का पाकिस्तान का निर्णय यह हम लिल चुके हैं कि पाकिस्तान ने अपने रुपये में अवमूल्यन नहीं किया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के इस निश्चय को स्वीकार कर लिया। भारत-पाकिस्तान का विनिमय दर १०० पाकिस्तानी के रुपये = १५४ भारतीय रुपये के आधार पर तय हो गया। प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान ने इस निर्णय का सबसे बड़ा कारण यह दिया है कि उसे इस बात का मरोसा है कि भारत को उसका कच्चा ब्यास

और जूट हर हालत में खरीदना पड़ेगा और इससे उसे बड़ा लाभ होगा। पर भारत की यह विवशता जल्दी कपास और जूट के उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर समाप्त कर दी जायगी। लेकिन पाकिस्तान को लोहे व कोयले जैसी चीजों की भारत से मैंगाने की जरूरत रहेगी और इसलिये अवमूल्यन नहीं करने का निश्चय अन्ततोगत्वा पाकिस्तान के हित में साबित नहीं होगा। पाकिस्तान के पूँजी पदार्थों के आयात में लाभ होगा पर कुल मिलाकर न तो पूँजी पदार्थों का बहुत आयात हो सकेगा और न उनसे होने वाले लाभ के धारे में बहुत निश्चित रूप से कहा जा सकता है। पाकिस्तान ने यह लाभ भी देखा कि भारत को जो ऋण चुकाना है उसकी मात्रा पाकिस्तान के रुपये में कम हो जायगी। पाकिस्तान का यह कहना कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन उसके पक्ष में है आज अवश्य सही है। पर यह स्थिति अनिश्चित और अस्थिर है। युद्ध की संभावना से जो अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में मुख्य वृद्धि हो रही है उससे पाकिस्तान के लिये अपने रुपये की इतनी क़ौची विनिमय दर रखना संभव हो रहा है। इस स्थिति का अन्त होते ही पाकिस्तान के सामने यह प्रश्न उपस्थित होगा कि वर्तमान विदेशी विनिमय की दर को कैसे कायम रखा जाये। जब पाकिस्तान अपने औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक चीज़ों का आयात करेगा, भारत कपास और जूट में स्वावलम्बी हो जायगा, अवमूल्यन नहीं करने का जब आयात को बढ़ाने और निर्यात को कम करने का असर होने लगेगा तो आज जो पाकिस्तान के अनुकूल विदेशी व्यापार का संतुलन है कम यह उसके प्रतिकूल चला जायगा और वर्तमान विनिमय दर से होने वाली कठिनाई सामने आ जायगी।

उपरोक्त विवेचन का सार यह है कि आज की स्थिति में चाहे पाकिस्तान के अवमूल्यन न करने से उसे लाभ हो पर यह स्थिति बहुत समय तक चलना शायद संभव नहीं होगा। पाकिस्तान में इस समय कृषि पदार्थों के मूल्य बहुत गिर रहे हैं। इससे भी यह स्पष्ट है कि अवमूल्यन नहीं करने के बावजूद भी पाकिस्तान की आन्तरिक आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती।

विदेशी विनिमय संबंधी नीति क्या हो : अवमूल्यन और पुनः मूल्यन के संबंध में हमने अपने विचार प्रकट किये हैं। पर यहाँ एक अपारभूत प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में विदेशी विनिमय संबंधी सही नीति क्या होनी चाहिये। १९३१ के पहले अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धामान के जमाने में विभिन्न देशों के विनियम दर में सोने के आधार पर सम्बन्ध निश्चित होता था। अगर किसी देश में आयात निर्यात से अधिक हो जाता था तो विदेशी विनियम उस देश के प्रतिकूल हो जाता था और उसे ठीक करने का उपाय यह होता

या कि छाल और कारोबार में कमी की जाती थी, इसमें साथ गिरनी थी और चीजों का मूल्य गिरना था, आयात कम होना था, निर्यात बढ़ना था और परिमाण स्वरूप सारा संतुलन ठीक हो जाता था। इस व्यवस्था का यह दोष देखा गया, खास तौर से बीगवी सनम्दा के नीतियों की मदी में, कि विदेशी विनियम की स्थिरता के लिये देश की आन्तरिक स्थिरता का परित्याग करना पड़ना था और देश में बेकारी और मदी का सामना करना पड़ना था। नतीजा यह हुआ कि उस पद्धति का दुनिया ने परित्याग कर दिया। इसके सर्वथा विपरीत यह नीति हो सकती है कि विदेशी विनियम का किसी के साथ भी सम्बन्ध स्थिर न किया जाय। विदेशी विनियम को दर को सर्वथा स्वतंत्र छोड़ दिया जाये और बाजार के माग और पूर्ति के सिद्धान्त के आधार पर समय समय पर यह निश्चिन होना रहे। गिनवर १९५० के अन्त में कनाडा ने और उसने पहले फ्रान्स और इटली ने इस नीति को अपनाया है। अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ठीक दोनों मातियों के बीच का रास्ता अपनाया है। इस बीच के रास्ते के अनुसार विदेशी विनियम की स्थिरता व पुराने सिद्धान्त और आन्तरिक स्थिरता व नव सिद्धान्त में मेल बिठाने का प्रयत्न किया गया है। यदि किसी देश को विदेशी विनियम का अनुकूल दर को कायम रखने के लिये आन्तरिक अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन करना उचित नहीं मालूम पड़े तो अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्यों को विनियम दर बदलने का इजाजत देना है। यह अर्थ है कि इस प्रकार होने वाला परिवर्तनों के अन्तर काल में विनियम दर स्थिर रहता है। इस स्थिर दर में २ प्रतिशत तक कम और ज्यादा दोनों दिशाओं में परिवर्तन हो सकता है। अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पद्धति में परिवर्तन के लिए गुआडरु होते हुए या एक प्रकार की मर्यादा और स्थिरता है।

हमारे सामने मौखने का प्रश्न यह है कि हम स्वतंत्र और स्थायी विनियम दर पद्धति में से किसके पक्ष में हैं। अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्वीकृत पद्धति में जल्दा जल्दी विनियम दर में परिवर्तन करना सम्भव नहीं, उसका वस्तुतः आधार आधार है जिसका मरिष्य अनिश्चित मालूम पड़ता है, और अस्थायी तौर पर सम्भावित विनियम दर के परिवर्तन से लाभ उठाने के लिए पूँजी के आने-जाने की इसमें गुआडरु है। पर स्थायी विनियम दर नीति का इन कमियों ने वावजूद स्वतंत्र विनियम दर पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि अगर दुनिया के अधिकांश देश इस पद्धति को अपना लें तो अन्तराष्ट्रीय व्यापार में बड़ी अनिश्चितता और अस्थिरता फैल जाये। इसलिये साथ ही एकता इस बात की है कि अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने नियमों में कुछ ऐसे

परिवर्तन करे कि जिससे आवश्यकता होने पर विनिमय दर में अपेक्षाकृत कम कठिनाई से परिवर्तन हो सके। हमें चाहिये यह कि विनिमय दर में रोज़-ब-रोज़ परिवर्तन भी न हो, उसमें स्थायित्व भी रहे, और फिर भी वह स्थायित्व अति की सीमा तक पहुँचा हुआ न हो। इसलिये हम इस पक्ष में भी नहीं हैं कि रुपया को सर्वथा त्वन्त कर दिया जाये।

विनिमय दर में कब परिवर्तन करना चाहिये : विनिमय दर में कभी-कभी परिवर्तन करना आवश्यक हो सकता है यह हम ऊपर लिख चुके हैं। प्रश्न यह है कि इस स्थिति की पहचान क्या कि अमुक समय परिवर्तन करना आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि इस प्रश्न का निर्णय कई संभावित अवस्थाओं और स्थितियों के अध्ययन पर निर्भर होता है और इस अध्ययन में विचार भेद होना स्वाभाविक है। इसलिये कई बार इस प्रश्न पर मतभेद होता स्वामाधिक है। फिर भी कुछ बातों का विचार रखना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि विनिमय दर में परिवर्तन काफ़ी सख्त विचार कर और दूसरे उपाय उपलब्ध न होने पर ही किया जाना चाहिये। सही विनिमय दर का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि सामान्यतया एक देश का दूसरे बाज़ी के देशों से माल और सेवाओं का क्रय विक्रय इस प्रकार हो कि लेना देना बराबर सार रहे। इसलिये यदि किसी देश के विदेशी व्यापार में असंतुलन उत्पन्न हो और खासतौर से घाटा हो तो या तो देश के अन्दर लागत-मूल्य का संबंध ठीक करके असंतुलन मिटाना चाहिये और अगर वह संभव न हो तो विनिमय दर में परिवर्तन करके उसे ठीक करना चाहिये। सितंबर १९४६ में स्टर्लिंग का अबमूल्यन इसीलिए किया गया कि स्टर्लिंग क्षेत्र की चीज़ों का डालर में उस समय इतना अधिक मूल्य था कि अमेरिका में बिक्री कम होती थी और इससे डालर को आमद बहुत कम होती जा रही थी। इस स्थिति को चूँकि आन्तरिक लागत-मूल्य संबंध को ठीक करके नहीं सुधारना संभव था इसलिए अबमूल्यन किया गया। इसी प्रकार इस समय हम रुपये के पुनः मूल्यन के विषय में हैं क्योंकि कोरिया युद्ध के कारण जो डालर मूल्यों में वृद्धि हुई है और रुपये में निर्यात मूल्य अपेक्षा कृत कम है ; इस असंतुलन को हम अन्य उपायों से, जैसे निर्यात-केर लगाकर, ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा पुनः मूल्यन का असर हमारी राय में हमारे निर्यात को कम करना, आयात को बढ़ाना और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के प्रतिशुद्ध असंतुलन पैदा करना होगा। इस लिये रुपये के पुनः मूल्यन की इस समय आवश्यकता नहीं है। स्थिति बदलने पर पुनः मूल्यन उचित भी हो सकता है।

परिच्छेद १३ सार्वजनिक वित्त

सार्वजनिक वित्त का महत्त्व आज राज्य व कार्यों का रूप बराबर बढ़ता जा रहा है। हमारा देश भी इसका अपवाद नहीं है। न केवल शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना बल्कि जनता व सामाजिक और आर्थिक जीवन को उन्नति करना भी राज्य व प्रत्यक्ष कार्यों में समाविष्ट होता है। अपनी बढ़ा हुआ ज़िम्मेदारी को पूरा करना व लिये राज्य का बड़ा भार बढ़ा देने का अर्थ करना होता है, और वह व्यय किया जा सके इसलिये उस अपने आय व संपत्ति बढ़ा देने हैं। यदि ठीक समय आय का अपवाद व्यय अधिक है ना शून्य लेकर भी काम चलाना पड़ता है। कई ऐसे काम भी राज्य आज अपने हाथ में लेता है जो आगे चलकर आमदनी का जरिया हो जाते हैं पर आरम्भ में उनमें पूँजी लगाना पड़ती है। यह पूँजी भी शून्य लेकर लगाई जाना है। जब मुक्त होता है तो सरकारों का बहुत व्यय करना पड़ता है। ऐसे समय में भी सरकारें शून्य लेती हैं। जब हम किसी देश व सांख्यिक वित्त का अध्ययन करते हैं तो हमें इन सब पक्षों पर विचार करना पड़ता है—सांख्यिक व्यय, सार्वजनिक आय, और सांख्यिक शून्य। आज व युग में इस अध्ययन का बड़ा महत्त्व है। देश की शान्ति, व्यवस्था और उन्नति का इस पर बहुत दारोमदार रहता है।

सांख्यिक वित्त का जब हम विचार करने हैं तो हमें फ़ैद, राज्य व प्रांत और स्वायत्त शासन सस्था—सभी का विचार करना चाहिये। अब हम इसी आधार पर भारत व सार्वजनिक वित्त का अध्ययन करेंगे।

भारत व सांख्यिक वित्त की विशेषतायें जिस प्रकार देश का आर्थिक अवस्था बहुत थोड़ी में सार्वजनिक वित्त पर निर्भर रहती है, उसी प्रकार देश की वित्त व्यवस्था भी देश विशेष का परिस्थिति—आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक—संनियंत्रित अवस्था निर्धारित होता है। हमारे देश की वित्त व्यवस्था पर निम्नलिखित आर्थिक व्यवस्थाओं और राजनैतिक परम्पराओं ने प्रभाव डाला है।

(क) इतिहास की प्रभावना, गाँवों का स्वास्थ्य निर्भरता और उनका एकाकीपन—देश की आर्थिक जनसंख्या गाँवों में रहती है और आज भी वह बहुत थोड़ी में अपनी आवश्यकताओं व बारे में स्वावलंबी है। मामूली जनता अपनी आवश्यकताओं की कई वस्तुएँ स्वयं हाँवैदा कर लेती है। इस बात का प्रभाव उत्पादकर (Excise Duty) के ऊपर पड़ता है। उत्पादकर की आय

में अधिक प्रसार नहीं किया जा सकता ।

भारतीय गाँवों के दूर-दूर बसे हुए होने के कारण उनमें आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता पैदा करने के लिये अधिक व्यय की आवश्यकता होती है।

(ख) कृषि-निर्भरता—उद्योगों के समुचित प्रसारित होने के अभाव में देश की लगभग ६६% जनता कृषि पर अवलंबित है। इसीलिये भारतवर्ष में राजकीय वित्त का सबसे अधिक उत्पादक स्रोत राजस्व (Revenue) का मद्द है और उद्योगों से प्राप्त आय का आनुपातिक महत्व कम है।

भारतीय कृषि की अनिश्चितता और संदिग्धता के ऊपर प्रकाश डालते हुए भारतीय सरकार के वित्त-मन्त्री विल्सन ने यह उक्ति कही थी कि भारतीय वित्त वर्षा के साथ जूझा खेलने के जैसी है (Indian agriculture is a gamble in the rains)। किसी अग्रक वर्ष में अनादृष्टि का हानिप्रद प्रभाव विभिन्न राज्यों की राजस्व-आय के ऊपर ही नहीं पड़ता परन्तु परोक्ष में केन्द्रीय सरकार की आय के ऊपर भी। अनादृष्टि के कारण राज्यकीय सरकारों के दुर्भिक्ष-सहायता के ऊपर किये गये व्यय में वृद्धि होती है, पीड़ित किसानों को राजस्व (Revenue) से मुक्त करना पड़ता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केन्द्रीय सरकार के वित्त विभाग के ऊपर भी इसका परोक्ष में प्रभाव पड़ता है। अनादृष्टि के कारण जनता की क्रय-शक्ति कम हो जाती है, इस कारण केन्द्रीय सरकार की आय के विभिन्न स्रोतों—आयकर, बहिःशुल्क (Custom Duty) और रेल द्वारा प्राप्त आय में भी कमी आ जाती है।^७

(ग) निर्धनता—देश की अधिकांश जनता के निर्धन होने के कारण उनकी कर-दान-क्षमता (Taxable Capacity) भी कम है। इसी कारण हम राष्ट्र-निर्माणकारी प्रवृत्तियों पर अग्र्य प्रगतिशील राष्ट्रों की तुलना में अधिक व्यय नहीं कर सकते। राष्ट्रीय-आय जाँच-समिति (National Income Enquiry Committee) के अनुसार हमारे देश में प्रति व्यक्ति औसत आय केवल २२५ रुपये वार्षिक ही है।

(घ) केन्द्रित प्रबन्ध की परम्परा—अंग्रेजों के शासन-काल में सत्ता तथा शक्ति का जो केन्द्रीकरण हुआ उससे परम्परा से प्रचलित स्वतंत्र ग्रामीण पंचायतों का विघटन हो गया। तभी से स्थानीय वित्त (Local Finance) का महत्व कम हो गया। आज भी स्थानीय संस्थाओं (जिला बोर्ड और पंचायतें इत्यादि) को अपनी आर्थिक-स्थिति में सुधार करने के लिये बहुत अंशों में राजकीय सरकारों के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी राजकीय सरकारों की

वित्तीय नीति का स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक स्थानाय स्वायत्त शासन संस्था की कर-नीति भी पृथक् है और उसका सम्बन्ध दूसरों की नीति से विलुप्त नहीं है। इस प्रकार की अनियमित और पृथक् कर प्रणाली के दोष स्पष्ट हैं। इसने व्यक्तियों के बीच में और जिलों के बीच में आर्थिक असमानता पैदा कर दी है। स्थानाय संस्थाओं के परस्पर समीकरण के अभाव में मितव्ययिता और कार्य कुशलता में भी कमी आ जाती है।[†] इसने अनिश्चित राजस्व अनुदान पर परावलम्बी होने के कारण और साथ ही साथ अपने क्षेत्र में पूर्ण-रूपेण स्वतन्त्र होने के कारण स्थानीय संस्थाएँ अपने क्षेत्र की समुचित आर्थिक उन्नति नहीं कर सकती। जहाँ समुक्त राज्य अमेरिका में कुल व्यय का ५५% व्यय, जापान में ३७% व्यय और जर्मनी में ४०% व्यय स्थानीय प्रबन्ध में होता है वहाँ भारत में (१९३७-३८) केवल १६% मात्र होता है। ‡ चेन्नई की बात है कि हमारे देश के नये संविधान में भी स्थानीय वित्त की गौरवशाली और महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया है।

(४) राजनैतिक स्थिति लगभग दो शताब्दियों के शासन-काल में देश की पराधीनता का प्रभाव भी हमारे सार्वजनिक वित्त पर पड़ा है। हमारा सार्वजनिक ऋण, सेना व्यय और ऊँचे सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा सामाजिक सेवाओं पर होने वाला व्यय इनके उन्नत उदाहरण माने जा सकते हैं।

केन्द्र और राज्य का वित्त संबंध भारत एक संघीय राज्य है। यहाँ के सार्वजनिक वित्त का अध्ययन करने के पहले हमलिये यह अनिवार्य है कि हमारे संविधान के अनुसार केन्द्र और राज्य के आपस के संबंध को हम अच्छी तरह से समझ लें। इस सम्बन्ध का आधार उद्ग और राज्य की सरकारों के कार्य विभाजन पर भी बहुत हद तक है। जो कार्य केन्द्र के करने के हैं उनके खर्च की जिम्मेदारी भी केन्द्र पर चाली है और उनकी आय भी उसी को मिलती है जैसे सेना, विदेश नीति, रेल, डाक, तार आदि। इसी प्रकार जो काम राज्य के करने के हैं उनके सम्बन्धी व्यय और आय के लिये राज्य जिम्मेदार है जैसे भूमि का लगान, श्रृष्टि, आयकर, आदि। इससे अलग हम सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखने का प्रयत्न किया गया है कि केन्द्र और राज्य दोनों की आय के पर्याप्त साधन प्राप्त हों। विगत परिस्थिति में केन्द्र द्वारा राज्य की सहायता देने का विधान भी किया गया है। राज्यों की वित्त व्यवस्था पर केन्द्र को आवश्यक नियंत्रण और

† B R Misra Indian Provincial Finance—पृष्ठ २७१

‡ डी व मेहता एण्ड एस एन अग्रवाल पब्लिक फायनांस थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस—पृष्ठ ६३७।

पारस्परिक समन्वय का अधिकार भी दिया गया है।

पहले की रियासतों के वित्त का एकीकरण : हमारे पराधीनता के युग में एक महत्वपूर्ण स्थान तत्कालीन देशी रियासतों का था। ब्रिटिश सरकार के राजनैतिक नियंत्रण में उन्हें एक खास तरह की आज़ादी थी और तत्कालीन ब्रिटिश प्रान्तों और इन देशी राज्यों की शासन प्रणाली और व्यवस्था में बहुत असमानता थी। भारत ने स्वतंत्र होते ही इस समस्या को हल किया। छोटी-छोटी रियासतों की या तो पड़ोस के राज्यों में मिला दिया गया या फिर उनका एकीकरण कर दिया गया। कुछ केन्द्र के शासनाधिकार में सेली गईं और कुछ पूर्ववत् बनी रहीं। जो देशी राज्य केन्द्र में या पास के राज्यों में मिल गये उनकी वित्त व्यवस्था भी केन्द्र या संबंधित राज्यों में शामिल हो गई। पर जो देशी राज्य और देशी राज्य संघ बच रहे उनका प्रश्न रहा। इन सबको नए विधान में राज्य का नाम दिया गया, हालाँकि पूर्ववत् प्रान्तों से इनका भेद करने के लिये इनको 'बी' राज्य का नाम दिया गया जबकि प्रान्तों को 'ए' राज्य का नाम दिया गया।

भिन्न भिन्न 'बी' राज्यों का देश के संघीय शासन में शामिल होने का निर्णय अलग अलग समय पर हुआ। पर शासन के इस प्रकार एकीकरण होने के बाद भी वित्त का एकीकरण आवश्यक था। बिना इस एकीकरण के सारे देश के वित्त की समन्वयित व्यवस्था हो नहीं सकती थी। इस विषय में विचार करने के लिये श्री पी० टी० कृष्णमाचारि की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की और उसकी सिफारिश के अनुसार १ अप्रैल १९५० से 'बी' राज्यों के वित्त का [काश्मीर के अलावा] एकीकरण कर लिया गया। इन राज्यों में केन्द्रीय विषय अब भारत सरकार के नियंत्रण में आ गये। इस एकीकरण से एकाएक कोई आर्थिक अव्यवस्था न उत्पन्न हो जाये इस दृष्टि से यह निश्चय किया गया कि यह एकीकरण १० वर्षों में धीरे धीरे पूरा किया जाये। इस एकीकरण के फलस्वरूप आयात-निर्यात कर, आय कर, केन्द्रीय उत्पादन कर, और रेलवे आय केन्द्रीय सरकार के पास चली गई है। इसी प्रकार खर्च में सेना, ब्रॉडकास्टिंग और राष्ट्रीय सड़कों का जिम्मा भी केन्द्र पर चला गया है। राजाओं को मिलने वाला खर्च [ग्रीवि पर्स] तो संविधान के अनुसार केन्द्र का जिम्मा हो ही गया था। 'ए' राज्यों की भाँति 'बी' राज्यों को भी केन्द्र से 'सर्वक्वैशन' और 'ग्रान्ट' लेने का हक मिल गया है। राज्य के कार्यों से संबंधित 'एसेट्स' और 'लाइ-बिलिटीज़' [संपत्ति और देनदारी] राज्यों के पास रह गये हैं और केन्द्र

सबकी पन्द्रों के पास चले गये हैं। भारत सरकार ने 'बी' राज्यों से समझौते किये हैं जो अधिक से अधिक दस साल तक लागू रह सकते हैं। पांच साल पूरे होने पर उपरान्त भारत सरकार को वाइसेन्स कमीशन की रिपोर्ट का निवार करने पर ये समाप्त या संशोधित भी किये जा सकते हैं। इन समझौतों के अनुसार पन्ड को मध्याह्न और व्यव के निमाण दे देने में राज्य की जो घाटा होगा उसकी प्रति आगामा पांच साल तक तो पूरा तौर पर और उसके बाद के पांच साल सालों में हर साल एक निश्चित आधार पर का जाने वाला कमा का अनुसार रेड को सरकार द्वारा की जायगी। आन्तरिक करदम के समान होने से राज्यों को तो हानि होगा वह राज्य की ही बढती पड़ेगी। एका करण होने से वेने तो इन आन्तरिक करदम करों की समाप्त कर देना चाहिये या पर चुनि राखरान, मध्य भारत और हैदराबाद राज्यों को आन्तरिक करदम से काफ़ा आय होता है इसलिये यह तय किया गया है कि राजस्थान और मध्य भारत में ५ साल और हैदराबाद में ४ साल के अंदर अंदर आन्तरिक करदम समाप्त कर दिया जाय। आय-कर 'पन्ड' और द्रावनकोर कोचीन में १९५०-५१ में पूरे दर पर लागू करने और मध्य भारत तथा राजस्थान में सौराष्ट्र के दरा के हिसाब में लागू करने का निर्णय किया गया है। यह भी तय किया गया है कि दो से छु वर्ष में सब 'बी' राज्यों में पूरे भारतीय दर से आय कर लागू हो जायगा। भारतीय आय कर के पूरे पर लागू होने से दो वर्ष तक 'बी' राज्यों की यह सततता होगी कि वे बाहें तो आय कर के अगित भारतीय आधार पर जादे जाने वाले कोष [पूल] में शामिल न हों। इस बीच में अस्थायी व्यवस्था के तौर पर प्रत्येक राज्य में निजना आय कर से ग्रामदनी होगा उसकी आपी उसकी मानी जायगी। सघीय आय-व्यय के केन्द्र के पास चले जाने से प्रत्येक राज्य को जो आय का घाटा [रेवेन्यू गैप] होगा और राज्य में बढने वाला आय [डिजिटल रेवेन्यू] का जो उसका हिस्सा होगा उनमें से जो भी अधिक होगा वह उसे मिल जायगा। इस आधार पर हैदराबाद, मैसूर, द्रावनकोर-कोचीन और सौराष्ट्र को तो 'रेवेन्यू गैप' का रकम मिलेगा और 'पन्ड', मध्य भारत और राजस्थान को आय कर का उनका हिस्सा मिलेगा।

केन्द्र और राज्या में आय के भाषना का विभाजन केन्द्र और राज्य की सरकारों के बीच में आय के साधना का क्या विभाजन है, इस संबंध में जान करनी आवश्यक है। तभी हम केन्द्र और राज्यों के सार्वजनिक विच का अध्ययन कर सकते हैं।

भारत को १९३५ के विधान में सबसे पहले संघ शासन का रूप दिया गया था। १९३५ के विधान में केन्द्र और राज्यों के बीच में आय के साधनों का एक विभाजन स्वीकार किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत ने भी एक संघीय शासन व्यवस्था स्वीकार की। केन्द्र और राज्यों में आय के साधनों का भारत के नये विधान में जो विभाजन किया गया वह १९३५ के विधान में जो विभाजन किया गया था लगभग वही है। नये संविधान के अनुसार आय के साधनों का जो विभाजन किया गया है, अब हम उस पर विचार करेंगे।

पहले हम केन्द्रीय सरकार के संबंध में विचार करेंगे। इस बारे में पहली ध्यान देने की बात यह है कि वे तमाम कर जो संघीय सरकार द्वारा लगाये जायेंगे, संघीय सरकार के आय के साधन ही हों ऐसा जरूरी नहीं है। इस दृष्टि से संघीय सरकार द्वारा लगाये जाने वाले करों को पांच श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे कर और शुल्क आते हैं जो संघीय सरकार ही लगायेगी, वही वसूल करेगी और वही उनका उपयोग कर सकेगी, जैसे—(१) सीमा शुल्क जिसके अन्तर्गत निर्यात शुल्क भी है, (२) निगम [कॉर्पोरेशन] कर, (३) मूलधन-मूल्य कर [टैक्स ऑन केपिटल वेल्थ] जिसमें कृषि भूमि को छोड़कर व्यक्तियों या समूहों [कम्पनीज़] की आस्ति [एसेट्स] और समूहों का मूलधन शामिल है, और (४) अमुक निश्चित करों और शुल्कों पर संसद द्वारा लगाया गया अधिभार [सुपरग्रांट]। दूसरी श्रेणी में वे कर आते हैं जो संघ की सरकार लगायेगी और वसूल करेगी पर जिनकी आय उसमें और राज्यों में निश्चित सिद्धान्त के अनुसार बांटी जायेगी। इसमें कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर लगने वाले कर का समावेश है। तीसरी श्रेणी में वे कर आते हैं जो संघ की सरकार लगायेगी, वही वसूल करेगी, पर संसद द्वारा ऐसा कानून बनाने पर उनकी आय के बराबर की पूरी रकम या उसका कोई अंश उक्त कानून द्वारा निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर भारत के संविधान की धारा [कनसोलिडेटेड फ़ंड] से लेकर राज्यों में बांट दिया जायगा। इस श्रेणी में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क [एक्साइज़ ड्यूटीज़] जिनमें भारत में निमित्त या उत्पादित तम्बाकू तथा—[क] मानव उपभोग के मखसारीक पानों, [ख] अफीम, मांस और अन्य पिनक लाने वाली औषधियों तथा स्वापकों तथा [ग] ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय [टोयलेट] सामग्री जिनमें उपरोक्त [क] और [ख] का कोई पदार्थ शामिल हो, को छोड़कर—अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क आता है। चौथी श्रेणी में वे कर और शुल्क आते हैं जो संघीय सरकार द्वारा लगाये जायेंगे और वसूल

भी किये जायेंगे पर जिनको आय संसद द्वारा कानून से निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर राज्यों में बाँटा जायगी। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति के बारे में संपत्ति शुल्क [एस्टेट ड्यूटी], कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार के बारे में शुल्क, रेल या समुद्र या वायु से ले जाई जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा कर [टरमिनल टैक्स], रेल के जन भाड़े और वस्तु भाड़े पर कर, मुद्राक शुल्क को छोड़कर भेजि चत्वर [स्टाक एक्सचेंज] और बादा बाजार [फ्यूचर मार्केट्स] के खरीदों पर कर और समाचार-पत्रों के कब या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर इस श्रेणी में लिये गये हैं। पाचवीं श्रेणी में वे शुल्क आते हैं जो लगाये तो केन्द्र द्वारा जायेंगे पर अपने अपने राज्य में लगाने वाले शुल्क की आय की वसूला और उपयोग संबंधित राज्य करेंगे। इस श्रेणी में ऐसे मुद्राक शुल्क [स्टैम्प ड्यूटी] तथा औपधीय और प्रसाधनीय सामग्री पर ऐसे उत्पादन शुल्क आते हैं जो सघ-सूची में दिये गये हैं। विनिमय-पत्रों [बिल ऑफ एक्सचेंज], चेकों, वचन-पत्रों [प्रोमिसरी नोट], वहन-पत्रों [बिल ऑफ लोडिंग], प्रत्यक्ष-पत्रों [लेटर्स ऑफ क्रेडिट], बीमा पत्रों [इश्योरेंस पालिसीज़], अशों के हस्तान्तरण [ट्रांसफर ऑफ शेयर्स] अणु पत्रों [डिबेंचर्स], प्रति-पक्षियों [प्रोसीक्यूटर्स] और प्राप्तिओं [रिसीट्स] के सम्बन्ध में लगाने वाले मुद्राक शुल्क और ऊपर तीसरी श्रेणी [ग] में दिया उत्पादन-शुल्क इस श्रेणी में आते हैं।

उपरोक्त विभिन्न करों और शुल्कों के अलावा केन्द्र की आय का एक प्रमुख साधन उसके व्यापारिक विभागों की आय का है—इसमें रेल, डाक, और तार विभाग प्रमुख हैं।

राज्यों के आय के साधनों का जहाँ तक संबंध है, कुछ शिक्षा तो केन्द्र के आय के साधनों का उत्प्रेषण करते समय उपरोक्त विवरण में किया जा चुका है। ये तमाम साधन ऐसे करों या शुल्कों के हैं जो केन्द्रीय सूचा [यूनियन लिस्ट] में दिये गये हैं और इसलिये जाको लगाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को ही है, पर जिनकी आय का सारा या आंशिक लाभ राज्यों को मिलने वाला है। यहाँ यह स्पष्ट रहने में जान है कि राज्यों से अर्थ 'घ' और 'ब' श्रेणी के राज्यों का है। 'ग' श्रेणी के राज्यों का हिस्सा तो केन्द्र की सरकार के पास ही रहगा।

आय के उपरोक्त साधनों के अलावा राज्य के अपने स्वतंत्र साधन भी हैं। राज्य-सूची में इनका उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राज्य के मुख्य-मुख्य आय के साधन ये हैं—(१) राजस्व, (२) जग्गाव, (३) सिंचाई, (४) कृषि आय पर कर, (५) कृषि भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क;

(६) कृषि-भूमि के विषय में संपत्ति शुल्क; (७) भूमि और भवनों पर कर; (८) संसद से, कानून द्वारा, खनिज विकास के सम्बन्ध में लगाई गई मर्यादाओं के अन्तर्गत खनिज-अधिकार पर कर; (९) राज्य में निर्मित वा उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क तथा भारत में अन्यत्र निर्मित वा उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर उसी या कम दर से प्रति शुल्क—(क) मानव उपभोग के लिये मद्यसारिक पान, (ख) अफीम, मांग, और अन्य पिनक लाने वाली औषधियाँ और स्थापक किन्तु ऐसी औषधियों और प्रसाधनीय सामग्रियों को छोड़ कर जिनमें उपरोक्त (क) और (ख) का कोई पदार्थ शामिल हो; (१०) किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग वा विक्रय के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर; (११) विद्युत के उपभोग वा विक्रय पर कर; (१२) समाचार-पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय वा विक्रय पर कर; (१३) समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर; (१४) सड़कों या अन्तर्देशिय जल-पथों पर ले जाये जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर कर; (१५) सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर कर, चाहे वे यान बंधचालित हों या न हों तथा जिनमें ट्राम गाड़ियाँ भी शामिल हैं, वद्यपि वे सिद्धान्त जिनके अनुसार बंध-चालित यान पर कर लगाया जायगा समवर्ती सूची [कॉनकर्रेट लिस्ट] का विषय होंगे; (१६) पशुओं और नौकाओं पर कर; (१७) पथ-कर [टोल] ; (१८) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर; (१९) प्रति व्यक्ति कर; (२०) विलास वस्तुओं पर कर, जिनके अन्तर्गत आमोद, विनोद, पथ लगाने (वेटिंग) और जुआ खेलने पर भी कर है; (२१) मुद्रांक-शुल्क [स्टैम्प ड्यूटीज़] की दरों के सम्बन्ध में सूची (१) में दिये दस्तावेजों को छोड़कर अन्य दस्तावेजों के बारे में मुद्रांक-शुल्क की दर और (२२) रजिस्ट्रेशन ।

उपरोक्त आय के साधनों के अलावा आसाम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को जूट और जूट के सामान पर लगाई गई निर्यात-शुल्क से होने वाली आय के इन राज्यों को मिलने वाले हिस्से के एवज में भारत सरकार से सहायक-अनुदान [ग्रांट-इन-एड] देने की विधान में व्यवस्था है । इसके अलावा पार्लियामेंट को यह अधिकार भी दिया गया है कि कानून द्वारा यह यह तब करदे कि भारत सरकार अमुक राज्यों को अमुक मात्रा में सहायक अनुदान देगी । परन्तु राज्य की उन विकास योजनाओं के लिये जो राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये वा अनुसूचित क्षेत्रों के शासन के स्तर को शेष क्षेत्रों के शासन-स्तर तक उन्नत करने के लिये बनाई जायगी भारत सरकार

से राज्यों को सहायक अनुदान दिया जायगा। इसा के साथ भारत सरकार आषाढ राय को अनुमूर्चित क्षेत्रों के शासन और विकास सम्बंधी स्वयं के बारे में भी सहायक अनुदान देगी।

‘बी’ राज्यों के साथ समझौता हमारे विधान में एक धारा ‘बी’ राज्यों के साथ भारत सरकार द्वारा समझौता करने के सम्बन्ध में भी है। इस धारा २ अनुसार विधान में ही गई धार्ता २ बाबजूद, भारत सरकार को यह अधिकार है कि यह किसी भी ‘बी’ राज्य से उस राज्य में भारत सरकार द्वारा लगाये जाने वाले किसी कर या शुल्क २, जो अब इस विधान के अनुसार भारत सरकार ही लगा सकता है, नहीं लगा सकने के कारण होने वाला राजस्व की हानि या अन्य कारण से होने वाला राजस्व की हानि को पूर्ति करने लिये को जाने वाली आर्थिक सहायता के बारे में समझौता करले। ऐसे समझौते अधिक से अधिक विधान लागू होने के समय से दस वर्ष तक के लिये हो सकते हैं पर पाँच वर्ष पूरे होने पर उनमें संशोधन या उनको समाप्त भी किया जा सकता है। धारा २६१ २ अनुसार पुराना देशों रियासतों के राजाओं को उनसे प्राप्त हुए समझौते या केबेनेट के अनुसार आयकर से मुक्त जो प्रीवि परस मिलेगा वह भारत सरकार का रख होगा। पर ‘ए’ या ‘बी’ राज्य में जिन राजाओं के राज्य आज शामिल हैं उन राजाओं को भारत सरकार से जो प्रीवि परस का स्वयं मिलेगा उसने बदले में भारत सरकार को संबंधित ‘ए’ या ‘बी’ राज्य और भारत सरकार में इस विषय में जो भी समझौता हो उससे अनुसार उस राज्य से समझौते में निश्चित समय २ लिए अनुदान [कम्प्लैन्स] मिल सकेगा।

अधून के सम्बन्ध में अधिकार विधान ने अन्तर्गत भारत सरकार को भारत की सचिन निधि [क्वॉलिफाइड फंड ऑफ इन्डिया] की प्रतिभूति पर अधु लेने का अधिकार है। भारत सरकार के इस प्रकार से अधु लेने की यदि कोई सीमायें होंगी तो वह समय समय पर कानून द्वारा निश्चित कर देगी। अधु लेने के अलावा अधु की प्रत्याभूति गारंटी देने का भी भारत सरकार को अधिकार है।

इसी प्रकार राज्य को राज्य के सचिन निधि की प्रतिभूति पर अधु लेने का अधिकार है। इस प्रकार से अधु लेने की यदि कोई सीमायें होंगी तो वह संबंधित राज्य का विधान मण्डल कानून द्वारा समय समय पर निश्चित कर देगा। अधु लेने के अलावा अधु की प्रत्याभूति [गारंटी] देने का भी राज्य को अधिकार है।

भारत सरकार भी राज्यों को इस सम्बन्ध में संसद द्वारा बनाये गये

क्रान्त में जो शर्तें हों उनके अन्तर्गत अथवा अथ के लिये प्रत्याभूति दे सकता है। यदि किसी राज्य पर भारत सरकार का अथवा या ऐसा अथ जिसको भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी गई है, बाकी है तो भारत सरकार की स्वीकृति के बिना राज्य नया अथ नहीं ले सकता है।

संचित निधियां और लोक लेखे तथा आकस्मिकता निधि : भारत सरकार के पास राजस्व, अथ और अथ के चुकारे के रूप में जो रुपया आयगा वह एक कोष के रूप में जमा रहेगा। इस कोष को भारत सरकार की संचित निधि [कनसोलिडेटेड फंड] कहा जायगा। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य का भी एक संचित कोष होगा। राज्य के अर्थ 'ए' और 'बी' राज्य से हैं। संचित निधि में जमा होने वाले रुपये के अलावा जो भी दूसरा रुपया भारत सरकार को प्राप्त होगा वह भारत सरकार के लोक-लेखे [पब्लिक अकाउन्ट] में, और जो राज्य को प्राप्त होगा वह राज्य के लोक-लेखे में जमा होगा। इसके अलावा भारत की और प्रत्येक राज्य की एक आकस्मिकता-निधि [कन्टिजेंसी फंड] होगी जो संसद या राज्य के विधान-मंडल द्वारा कानून से स्थापित होगी। इस निधि में समय समय पर वह रुपया जमा होगा जो निधि संबंधी कानून द्वारा निश्चित होगा। यह निधि भारत के राष्ट्रपति या राज्य के गवर्नर या राजप्रमुख के हाथ में रहेगी जिसमें से अनपेक्षित व्यय किये जायेंगे, जब तक ऐसे व्यय की बाकायदा संसद या राज्य के विधान-मंडल से स्वीकृति न मिल जाये।

केन्द्र और राज्य के वित्त-सम्बन्धों का इतिहास : केन्द्र और राज्य के हमारे संविधान के अनुसार जो वित्त-सम्बन्ध हैं उनका उल्लेख ऊपर किया गया है। पर इन संबंधों का एक इतिहास रहा है। वर्षों के विकास के बाद हम आज की स्थिति में पहुंचे हैं। संक्षेप में इस इतिहास की जानकारी कर लेना आवश्यक होगा। अब हम इसी पर विचार करेंगे।

१६१६ के सुधार के पहले तक का इतिहास : सन् १८११ तक प्रत्येक प्रान्त वित्त की दृष्टि से अपने आप में स्वतंत्र था, अपना राजस्व स्वयं जुटाता और स्वयं व्यय करता था।

सन् १८३३ से लेकर १८७१ तक केन्द्रीय सरकार के हाथ में समस्त वित्त अधिकार केन्द्रित थे। सारे देश का राजस्व केन्द्र के अधिकार में रहता था और प्रान्तों का काम तो राजस्व इकट्ठा करना और उसे खर्च करना मात्र था। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि चूंकि प्रान्तों पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी इसलिए राजस्व को बढ़ाने या व्यय में कृपावश करने में उनका कोई सहयोग नहीं मिलता था और केन्द्र से अधिक से अधिक रुपया प्राप्त कर लेने

का प्रत्येक राज्य प्रयत्न करता था।

उपरोक्त दोषपूर्ण व्यवस्था को सुधारने का लार्ड मेयो ने १८७१ में जिस सघर्षी विभेदाकरण की नीति अपना कर प्रयत्न आरम्भ किया। लार्ड मेयो ने कुछ प्रान्तीय महत्व के विभाग—जैसे पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, जेल आदि—प्रान्तों को सौंप दिये। इन विभागों के व्यय को चलाने के लिये विभागीय आय के अलावा पन्द्रह से निश्चित दक्षम सहायता के रूप में दी जाती थी। अगर फिर भी पादा रह जाता तो केंद्र की स्वायत्ति से स्थानीय कर लगा कर पूरा किया जाता। १८७७ में लार्ड लिटन ने इस व्यवस्था में और सुधार किया। स्थानाय महत्व के कुछ और विभाग प्रान्तों को सौंप दिये गये—जैसे स्टैम्प, ज्वानून और न्याय, सामान्य शासन आदि। इन नये हस्तान्तरित विभागों का खर्च चलाने के लिये प्रान्तों को कुछ आय के साधन भी सौंप दिये गये। स्टैम्प, एक्ससाइज, ज्वानून और न्याय आदि के कुछ ऐसे आय के साधन थे जो प्रान्तों को सौंप दिये गये। इसने अलावा यह भी तय कर दिया गया कि प्रान्त की विभागात्मक प्राप्तिओं और प्रान्त को सौंपे गये आय के साधनों से होने वाली कुल आय का अनुमान लगा लिया जायगा और इस अनुमान में तथा प्रान्त की वास्तविक आय में जो भी कमी बचा होगी वह प्रान्त और केंद्र दोनों में बाँट जायगी। इसके बाद १८८२ में लार्ड रिपन द्वारा किये गये सुधार आते हैं। इन सुधारों की एक विशेषता तो यह थी कि प्रान्तों के साथ वित्तीय समझौतों की अवधि पांच वर्ष निश्चित कर दी गई ताकि वित्त में अधिक स्थिरता आ सके। १८८७, १८८९, और १८९७ में यह पंचवर्षीय समझौते हुए। १९०४ में ये समझौते अर्द्ध-स्थायी कर दिये गये और १९१२ में ये सर्वथा स्थायी कर दिये गये। तब १९१६ तक यह व्यवस्था जारी रही। इसने अलावा एक नई बात यह भी की कि आय के कुछ साधन तो सर्वथा प्रान्तों के पास थे ही पर कुछ अन्य आय के साधनों—जैसे जगलगत, रजिस्ट्रेशन, आबकारी, स्टैम्प आदि—का प्रान्तों और केंद्रों में विभाजन कर दिया गया। यदि किसी प्रान्त का आय उसका सर्व चलाने के लिये काफी नहीं होता तो उस घाट के पूरा करने के लिये भूमि के लगान का एक हिस्सा प्रान्त को और दे दिया जाता था। जैसा कि ऊपर भीते होते रहे। १९०४ में केंद्र की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक यह न मालूम पड़ेगा कि यह व्यवस्था अनुकूल प्रान्त या केंद्र के प्रति उपलब्ध है, १९०४ के समझौते अर्द्ध-स्थायी कहे जाते हैं।

सन् १९०७-०८ की विकेन्द्रीकरण कमीशन ने इस व्यवस्था पर विचार किया। कमीशन के सामने इस संबंध में जो विचार प्रगट किये गये वे प्रायः इस व्यवस्था के विरुद्ध ही थे। केन्द्र की सरकार प्रान्तों पर हावी रहती है, प्रान्तों को निश्चित रकम में सहायता देने की पद्धति फिर केन्द्र की सरकार ने श्रारंभ करदी है, और प्रान्तीय राजस्व की दरें वह निश्चित करती है, और एक सीमा के बाद प्रान्तीय खर्च में उसका हस्तक्षेप होता है—इस तरह की आपत्तियाँ इस व्यवस्था के धारे में विकेन्द्रीकरण कमीशन के सामने पेश की गईं पर कमीशन ने सारी स्थिति पर विचार करके यह सिफारिश की कि कुछ संशोधन के साथ इसी व्यवस्था को स्थायी कर दिया जाय। इस सिफारिश के अनुसार १९१२ में यह व्यवस्था स्थायी करदी गई। निश्चित रकम में सहायता की मात्रा कम करदी गई और विभाजित आय के साधनों में प्रान्तों का हिस्सा बढ़ा दिया गया। इसके अलावा और कोई खास संशोधन नहीं किया गया। १९१६ के सुधारों तक यही व्यवस्था चलती रही। केन्द्र और प्रान्त की सरकारों की आय के, इस व्यवस्था के अनुसार, निम्न साधन निश्चित किये गये :—(१) केन्द्रीय आय के साधन—अफीम, सीमा-शुल्क, नमक, टफ-साल और विनिमय, डाक और तार, रेल, सेना से प्राप्तियाँ, और देशी राज्यों से मिलने वाला 'ट्रिब्यूट'। (२) केन्द्र और प्रान्त में विभाजित साधन—लगान, आयकर, आयकारी [बंबई, बंगाल के अलावा] सिचाई और स्टैम्प। प्रत्येक प्रान्त के साथ विभाजन का आधार अलग अलग था जो प्रायः आधा था। इन विभागों के खर्च का विभाजन भी किया गया था। (३) प्रान्तीय आय के साधन—जंगलात्, आयकारी [बंबई, बंगाल], रजिस्ट्रेशन और विभागीय प्राप्तियाँ जैसे शिक्षा, न्याय और कानून आदि।

उपरोक्त व्यवस्था में मुख्य मुख्य दोष यह थे :—(१) आय के विभाजित साधनों के कारण केन्द्र और प्रान्तों में लोभ, (२) निश्चित रकम की सहायता पद्धति से आय की व्यवस्था में लचीलापन का अभाव, (३) कभी कभी केन्द्र द्वारा प्रान्तों को एक मुश्त सहायता देने से प्रान्तों में केन्द्र का हस्तक्षेप, (४) विभिन्न समझौतों की आपस में असमानता, (५) प्रान्तों को कर लगाने और अणु लेने का अधिकार नहीं होना, (६) केन्द्र का प्रान्तीय खर्च और बजट पर अत्यधिक नियंत्रण। उदाहरण के लिये, प्रान्त घाटे का बजट बनाने और अपनी रोकड़ खर्च करने में स्वतंत्र नहीं थे।

१९१६ के सुधार और विचार संबंध में सन् १९१६ के सुधारों के अन्तर्गत प्रान्तीय स्वायत्त शासन का सीमित आधार पर आरंभ हुआ। इसी के

अनुसूचित देश का वित्त व्यवस्था स्थापित की गई। इन वित्त व्यवस्था के मुख्य लक्ष्य ये थे — (१) आय व साधनों का केन्द्र और प्रान्त में बटवारा कर दिया गया और विभाजित आय के साधन सब नहीं रहे। केन्द्र के आय के साधन इन प्रकार तय किये गये — (i) अर्थ, (ii) नमक, (iii) गीमा शुल्क, (iv) आय कर, (v) रेल, डाक और तार, (vi) मेला से प्राप्तियाँ। प्रान्त व आय के साधन ये तय किये गये — (i) लगाव और सिंचाई, (ii) स्टैम्प (आय और व्यापार दोनों सदर), (iii) रजिस्ट्रेशन, (iv) जंगलान। प्रान्तों को आय कर में भी कुछ हिस्सा दिया गया। (२) उपरोक्त आय के विभाजन के आधार पर केन्द्रीय बजट में होने वाले पाठ का परिचरों के लिये प्रात फंड को असादान दें, यह भी निश्चित किया गया। मेस्टन कमेटी ने अन्य बातों के साथ साथ असादान का रकम तय करने के बारे में विचारों का भी। ये असादान १९२०-२१ में मज्रात हुए। प्रान्तों ने इनके बारे में बराबर आपत्तियाँ का। (३) एक प्रभु सूचि पद्धति में दिया गया करा को लगाने का प्रात को स्वतंत्र अधिकार मिल गया, यद्यपि कुछ उसे रोक भी सकता था। इस सूची के बाहर केन्द्र की स्वीकृति से कर लगाने का प्रातों को अधिकार मिल गया। (४) किसी भी प्रातों में प्रात की अणु लेने का अधिकार भी मिल गया। (५) उपरोक्त व्यवस्था के कारण केन्द्र और प्रातों में अलग अलग बजट बनने लगे।

सन् १९१९ के विधान के अन्तर्गत जो वित्त व्यवस्था स्थापित हुई उसने निम्नलिखित दोष पाये गये — (१) प्रातों पर राष्ट्रनिर्माण के विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के पकने हुए सर्व की जिम्मेदारी तो बाल ही गई पर उनकी आय के साधन अप्रवात थे क्योंकि इन साधनों से आय में वृद्धि होने का आशा नही था जैसे लगान, आयकारी आदि। केन्द्र के पास आय कर और सामा शुल्क जैसे बढ़ने वाला आय के साधन थे हालांकि उसकी जिम्मेदारी बड़ा हुआ था। (२) विभिन्न प्रातों में भी समानता नहीं थी। कृषि प्रधान प्रातों को अधिक लाभ और उद्योग में प्रधान प्रातों को अधिक हाँपि हुई। (३) केन्द्र और प्रात में आय के साधनों का इतना प्रण बटवारा उचित नहीं था।

१९३५ का विधान और वित्त सम्बन्ध १९३५ के विधान बनाने के समय देश का वित्त व्यवस्था के बारे में फिर सविस्तार विचार किया गया। अन्त में १९३५ के विधान में जो वित्त व्यवस्था स्वीकार की गई वह लगभग वही थी जो स्वतंत्र भारत के संविधान में स्वीकार की गई है। संघीय सरकार

के आय के साधनों में चार श्रेणियाँ थीं :—(१) जो पूर्णतया संघीय सरकार के थे, जैसे सीमा-शुल्क, निगम-कर, रेल, डाक वार से आय आदि; (२) जो संघ और प्रान्त में बटे हुए थे, जैसे आय कर; (३) जो संघ के पास थे पर जिन्हें संघ सरकार को पूरा या आंशिक रूप से प्रान्त को देने का अधिकार था जैसे केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, निर्यात-शुल्क, नमक-शुल्क; और (४) अमुक अमुक करों पर संघ के उपयोग के लिये लगाये गये अधिभार (सरचार्ज)।

इसी प्रकार प्रान्तों की आय के निम्न साधन थे :—(१) प्रान्तीय कर जैसे लगान, कृषि आयकर, आदि; (२) आयकर में प्रान्त का हिस्सा; (३) मुद्रांक शुल्क (व्यापारिक), सीमा-कर (टर्मिनल टेक्स), उत्तराधिकार शुल्क आदि ऐसे कर जो केन्द्र द्वारा लगाये और वसूल किये जायेंगे पर जो प्रान्त को मिलेंगे; (४) केन्द्र से मिलने वाली सहायता।

निम्नर रिपोर्ट : १९३५ के विधान के अन्तर्गत जब प्रान्तीय स्वायत्त शासन लागू करने का समय आया तो वित्त की दृष्टि से प्रान्तों की स्थिति पर विचार करने के लिये भारत मन्त्री ने सर ओटो निम्नर को नियुक्त किया। १९३६ के अप्रैल में उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि १९३७ की अप्रैल में प्रान्तीय स्वायत्त शासन और वर्ष भर बाद संघीय शासन की स्थापना की जा सकती है। सर ओटो ने ये सिफारिशें कीं :—(१) आय कर का ५% प्रान्तों का भाग माना जाना चाहिये। इस आय का प्रान्तों में आपसी बटवारे का आधार भी सर ओटो ने सुझाया। (२) पाँच साल तक केन्द्रीय सरकार को प्रान्तों का वह भाग अपने उपयोग में लेने का अधिकार होना चाहिये। केन्द्रीय सरकार प्रान्तों का या तो पूरा भाग उपयोग में ले सकती है या उसका उतना अंश जितना केन्द्र को रेलवे से मिलने वाली आय में मिलाने से केन्द्र को १३ करोड़ की रकम मिल जाय। इन दोनों में से जो रकम कम होगी वही केन्द्र उपयोग में लेगा। (३) दूसरे पंचवर्षीय अवधि में केन्द्रीय सरकार आयकर के प्रान्तीय भाग को प्रान्तों को धीरे धीरे लौटाना शुरू करदे ताकि आखिरी साल के बाद प्रान्त को अपना पूरा भाग मिल सके। (४) प्रान्तों को तीन तरह में आर्थिक सहायता दी जाये—१ अप्रैल, १९३६ के पहले जो असल ऋण हो उसे रद्द करके, नकद सहायता देकर, और जूट पैदा करने वाले प्रान्तों को ५.०% से १२.३% अधिक इस प्रकार कुल ६२.३% जूट निर्यात-शुल्क का हिस्सा देकर। बंगाल, बिहार, आसाम, उत्तर-पश्चिम सरहद्दी प्रान्त, और उड़ीसा के ऋण रद्द किये गये। संयुक्त प्रान्त, आसाम, उड़ीसा, उत्तर-पश्चिम सरहद्दी प्रान्त, और सिंध को नकद सहायता देने की सिफारिश की गई। भारत

सरकार ने सर छोटी की जब सिफारिशें थोड़े संशोधन के साथ स्वीकार कर लीं और ३ जुलाई, १९३६ को ऑर्डर इन कौंसिल जारी कर दिया गया।

निम्नलिखित रिपोर्ट से थोड़ा थोड़ा अन्वेषण केन्द्र और विभिन्न प्रान्तीय सरकारों का रहा, खास कर आयकर के अपने हिस्से के बारे में, पर निम्नलिखित निर्णय का पालन हुआ। प्रान्तों को १९३७-३८ में आयकर के अपने भाग से कुछ मिला था।

निम्नलिखित निर्णय में परिवर्तन द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो जाने से देश की वित्त व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। १९४०-४१ में निम्नलिखित निर्णय में पहला संशोधन हुआ। इसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि केन्द्र की सरकार को, रेल से मिलने वाला आय का निवार किये बिना, आयकर के प्राप्ति के भाग में से ४३ करोड़ रुपये प्रति वर्ष दिया जाय और १ अप्रैल, १९३९ से इस निर्णय पर व्यवहार किये जावे। यह संशोधन केन्द्र की सरकार के पत्र में था। पहले तो इस संशोधन की अवधि १९४१-४२ तक ही निर्दिष्ट थी गई थी पर बाद में १९४६-४७ तक वही संशोधन निर्णय लागू रहा, यद्यपि १९४२-४३ में केन्द्र का हिस्सा ४३ करोड़ से बराबर ७८ होता गया और १९४७-४८ में प्राप्ति के भाग में से केन्द्र का कुछ कुछ नहीं रहा।

जब देश का निमाजन हुआ तो निम्नलिखित निर्णय में दूसरा संशोधन किया गया। यद्यपि इस संशोधन निर्णय का आदेश तो १७ मार्च, १९४८ को जारी हुआ पर इस पर अमल १५ अगस्त, १९४७ से ही किया गया। इस दूसरे संशोधन में प्राप्ति में उनके हिस्से के आयकर के बटवारे का आधार बढ़ाया गया, पटसन निर्वात शुल्क में पटसन पैदा करने वालों का हिस्सा ६९.३% से घटाकर ९.०% कर दिया गया, सहायता के रूप में अनुदान केवल आसाम और उड़ीसा को १९४७-४८ और १९४८-४९ में ही देना तय हुआ, और आयकर की असल रकम का १% चाक कमिशनर के प्राप्ति को देना तय किया गया। यह संशोधन १९४७-४८ और १९४८-४९ के लिये ही था।

देशमुख निर्णय निम्नलिखित निर्णय में देश के निमाजन के बाद जो संशोधन हुआ था वह अस्थायी था। नवम्बर १९४९ में रिज़र्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर श्री चिन्तामणि देशमुख को भारत सरकार ने इसलिये नियुक्त किया कि आयकर और पटसन के निर्वात शुल्क का प्राप्ति में किस आधार पर बटवारा किया जाये इस बारे में वह सिफारिश करें। श्री देशमुख ने अपना निर्णय जापरी १९५० में दिया। १९५०-५१ के आर्थिक वर्ष ही से उसे लागू किया गया। विधान का २८ धारा के अनुसार नियुक्त होने वाली फाइनेंस कमीशन की इस

सम्बन्ध में सिकारिश नहीं होने तक वह लागू रहेगा और वह केवल 'ए' श्रेणी के राज्यों पर ही लागू होगा। देश के विभाजन के पहले विभिन्न प्रान्तों में आयकर की आय का प्रतिशत के हिसाब से बटवारा हो रहा था। जब कुछ प्रान्त या प्रान्तों के हिस्से पाकिस्तान में चले गये तो उनके हिस्से का प्रतिशत या तो बच गया या कम होगया। इस प्रकार बंगाल ७.५, पंजाब ४, सिंध २, और उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त १ और कुल १४.५ प्रतिशत का बचत हुई। श्री देशमुख ने इन १४.५% का ही भारत के सभी 'ए' राज्यों में जनसंख्या के आधार पर, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर राज्यों का थोड़ा ध्यान रखते हुए, फिर से बटवारा कर दिया। देशमुख निर्णय में जो प्रतिशत प्रत्येक 'ए' राज्य को दिया गया है वह इस प्रकार है :—मद्रास १७.५, बम्बई २५, पश्चिम बंगाल १२.५, उत्तर प्रदेश १८, पंजाब ५.५, बिहार १२.५, मध्य प्रदेश ६, आसाम ३, और उड़ीसा ३—कुल १००।

पटसन निर्यात शुल्क के कारण पश्चिम बंगाल को १०.५ लाख रुपये, आसाम को ४० लाख रु० और बिहार को १५ लाख तथा उड़ीसा को ५ लाख—कुल १८५ लाख की सहायता देने की देशमुख निर्णय में सिकारिश की गई, क्योंकि संविधान के अनुसार पटसन निर्यात शुल्क से सारी आय तो केन्द्र के पास जायगी पर केन्द्र उपरोक्त राज्यों को सहायता देगा। देशमुख निर्णय द्वारा निश्चित सहायता की अवधि १० वर्ष या जब तक पटसन निर्यात शुल्क जारी रहे इनमें से जो भी समय पहले समाप्त हो तब तक रहेगी। देशमुख निर्णय के अनुसार सरकार ने १९५० में ही आदेश जारी कर दिया था।

भारत सरकार और राज्यों के बजट : भारत सरकार का वित्त मंत्रालय भारत सरकार की वित्त व्यवस्था करता है। वित्त मंत्रालय के मंत्री वित्त मंत्री कहे जाते हैं। भारत सरकार का वित्त वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक का है। इसी आधार पर भारत सरकार का बजट तैयार होता है। भारत सरकार के बजट के दो भाग होते हैं—एक राजस्व बजट (रेवेन्यू बजट) और दूसरा पूंजीगत बजट (कैपिटल बजट)।

राजस्व बजट में वार्षिक आय और चालू व्यय बताया जाता है। कर और शुल्क तथा व्यापारिक विचारों की आय इसी बजट में दिखाई जाती है। सामान्य खर्च व्यय में बताया जाता है। प्रति वर्ष जो बजट का स्टेटमेंट संसद में पेश होने के लिये तैयार होता है उसमें तीन वर्ष की आर्थिक स्थिति का हाल होता है—(१) आगामी वर्ष के आय और व्यय का अनुमान, (२) चालू वर्ष के आय और व्यय के संशोधित अनुमान और (३) गत वर्ष के वास्तविक आय-व्यय का हिसाब। प्रतिवर्ष फरवरी-मार्च

में बजट गणद म पेश होता है। गणस बजट में पहले तो यह अनुमान लगा जाता है कि वर्तमान करो के आधार पर बजट की क्या स्थिति होगी। उसके बाद सरकार यह बताना है कि नये कर काई लगाये जाने वाले हैं और कौद पुराने कर हटाय जाा वाले का कम होन वाले हैं वा नही। इस प्रकार सये सल म करो आदि स जो जुन आय होता है उसम व्यय अधिक होने पर बजट में घाटा और कम होने म बजट में बचन माना जानी है। अगर बचन होने है तो सरकार का नकद मौकद उम हद तक बढ़ जानी है। अगर घाटा होता है तो सरकार का नकद ाम उम हद तक कम हो जानी है। पर सरकार की मीरुद रोक [गननेट बैलेंसेज] को बढ़ाने का एक उपाय बाज़ार में अण लेने का है। सरकार हर साल कुछ न कुछ अण लेनी ही रहनी है और पुराने अण चुकाना भा रहता है।

यही पर सरकार के पु नामन बजट का प्रश्न उठता है। जैसा ऊपर कहा आ चुका है राजस बजट तो सरकार का शामदनी और गुच का बजट होता है। पु नामन बजट म प्राप्ति और चुकार का अनुमान होता है। प्राप्ति की ओर विभिन्न प्रकार क अण, फड और जमा से जो रकम आने वाली होता है यह दिखाइ जानी है और चुकारे की ओर जो पु नामन गुच होता है—जैसे रेलवे निमाण और औद्योगिक विकास का व्यय या राज्यों को विकास के लिये दी जाने वाली सहायता आदि का निनरण होता है। यदि चुकारे से प्राप्ति अधिक होती है तो बचन, और कम होती है तो घाटा माना जाता है। घाटा या बचन का असर सरकार की रोक पर पड़ता है।

जब ससद से बजट पास हो जाना है तो ससद 'प्रप्रीप्रियेशन एक्ट' पास करना है जिससे भारत सरकार की सचिव निधि से बजट के अनुसार गुच करने का सरकार का अधिकार मिल जाता है। इस कानून म ससद कौद संशोधन नहीं करना।

विशेष परिस्थितियों म सहायक बजट भा पास करने की आवश्यकता आ जाता है।

राज्यों के जो बजट बाते हैं उनम भी आय और व्यय क अलावा अण, जमा तथा पु नामन सच सबका आकड़े तथा साल के आरम्भ और अंत क सरकारी रोक क आकड़े भी होते हैं। पर भारत सरकार की तरह राज्यों के बजट दो अलग अलग भागों म नहं बनते।

भारत सरकार के गणस और पु नामन बजट और राज्य के बजट के नमूने इस परिच्छेद के अंत में दिये गये हैं।

केन्द्रीय वित्त

अब तक हमने भारतीय वित्त की विशेषताओं और उसके विकास तथा केन्द्र और प्रान्त के वित्त संबंधों के बारे में विचार किया। अब हम भारतीय वित्त का केन्द्रीय वित्त, राज्यकोष वित्त और स्थानीय स्वायत्त शासन संबंधी वित्त की दृष्टि से विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम केन्द्रीय वित्त का अध्ययन करेंगे। यह अध्ययन आय, व्यय और ऋण तीनों दृष्टियों से करना आवश्यक है। सबसे पहले भारत सरकार की आय के बारे में विचार करेंगे।

भारत सरकार की आय : भारत सरकार की आय की मुख्य मुख्य मदों का अब हम अध्ययन करेंगे।

(१) सीमा-शुल्क (कस्टम्स) : इसमें विदेश से आने वाले माल पर आयात-शुल्क और विदेश को जाने वाले माल पर निर्यात-शुल्क दोनों का ही समावेश होता है। आयात-शुल्क लगाने के दो अमिप्राय होते हैं—एक तो आय का और दूसरा राष्ट्र उद्योगों को संरक्षण देने का। भारत में प्रथम महायुद्ध तक सीमा-शुल्क का महत्त्व बहुत कम था, क्योंकि तब तक भारत इंग्लैंड के तत्त्वाधान में मुक्त व्यापार की नीति पर चलता था। प्रथम महायुद्ध के बाद भारतीय किसानों की कमीशन की नियुक्ति हुई और उसका सिफारिश पर भारत ने सन् १९२२ से वियेकपूर्ण संरक्षण नीति अपनाई। तभी से आयात-शुल्क का महत्त्व बढ़ गया। १९३२ में जो छोटावा समझौता हुआ उसके अनुसार इंग्लैंड से आने वाले कई तरह के माल पर अपेक्षाकृत कम आयात शुल्क लगाना पड़ा। द्वितीय महायुद्ध के समय फिर भारत सरकार ने आयात-शुल्क में वृद्धि की। युद्ध समाप्त होने के बाद कई चीजों पर सीमा शुल्क कम किया गया। पर १९४६-५० से फिर वृद्धि की और प्रवृत्ति है। सीमा-शुल्क से होने वाली आय में निर्यात-शुल्क का महत्त्व कम रहा है, वद्यपि पिछले वर्षों में कई चीजों पर निर्यात-शुल्क लगाया या बढ़ाया गया है। इन वर्षों में निर्यात-शुल्क लगाने के मुख्यतः दो प्रयोजन रहे हैं—या तो विदेश में कच्चे मूल्य होने से निर्यात से होने वाले लाभ में सरकार की हिस्सा बढ़ाने की इच्छा, जैसे वूड पर निर्यात-शुल्क का लगाया जाना, या फिर किसी चीज को बाहर जाने से रोकने की कोशिश करना, जैसे कच्चे कपास पर या तिलहन पर लगाया गया निर्यात-शुल्क। सीमा-शुल्क लगाने की दो पद्धतियाँ हैं—मूल्य के आधार पर (एड वैलरम क्यूटी) या मात्रा के आधार पर (स्पेसिफिक क्यूटी)।

भारत सरकार की आय में सीमा-शुल्क का हिस्सा बराबर पिछले वर्षों में विभाजन के बावजूद भी बढ़ा है। १९३८-३९ में सीमा-शुल्क से ४०½ करोड़

रुपये की आय थी वह १९४६-४७ में ८२ करोड़ रुपये के लगभग हो गई और १९४८-४९ में १२६ १६ करोड़ रुपये के लगभग हो गई और १९५०-५१ के उसी धित अनुमान के अनुसार १४३ करोड़ रुपये और १९५१-५२ के प्रस्तुत बजट के अनुमान के अनुसार १५० करोड़ रुपये के लगभग इस मद में आय होना है।

सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और विनाश-वस्तुओं दोनों पर है। आवश्यक वस्तुओं पर का कर आम जनता पर पड़ता है। जिस हद तक यह कम हो सकता है किया जाना चाहिये।

(२) आयकर भारत में नवम पहले १८६० में आयकर पाँच वर्ष के लिये १८५७ के विद्रोह के कारण सरकार का स्थिति को सुधारने के लिये लगाया गया था। पाँच वर्ष बाद यह कर हट गया। १८६६ में फिर यह कर लगाया गया। कर की दरों, न्यूनतम कर से मुक्त आय, और आयकर सनपी कानून में समय-समय पर परिष्करण होता रहा है। इस समय भी आयकर कानून में संशोधन का प्रश्न संसद के सामने विचारार्थ है।

भारतीय आयकर की कुछ विशेषताएँ ये हैं—आयकर व्यक्तियों, कर्मी (रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड), कम्पनियों और समुक्त परिवारों की आय पर लिया जाता है। कर का दर आय के साथ साथ बढ़ता है। व्यक्ति, समुक्त परिवारों, और अनरजिस्टर्ड फर्म पर आयकर के अलावा १५ हजार से अधिक आय पर सुपर टैक्स भी लगाया जाता है। १९२६ के आयकर कानून के द्वारा आयकर लगाने की प्रणति भी 'स्लेज' प्रणाली में बदल कर अब 'स्लैब' प्रणाली करवा गई है। 'स्लेज' प्रणाली में सारा आय पर कर एक समान दर से ही लगाया था। पर 'स्लेज' प्रणाली के अनुसार आय के बड़े भाग कर दिये जाते हैं और प्रत्येक बर के साथ पर बढ़ा हुई दर में कर लगता है। इससे कर का भार निम्न पर कम और उन्नत पर ज्यादा पड़ता है। न्यूनतम आय की एक छोटी सीमा निश्चित होता है जिस पर आयकर नहीं लगता। इस समय यह सीमा एक व्यक्ति के लिये ३६००० रु और समुक्त परिवार के लिये ७२०००० वार्षिक आय है। सन् १९४५-४६ में एक और सुधार यह किया गया था कि कमाई हुई आय और बिना कमाई हुई आय में भेद कर दिया गया था और कमाई हुई आय के १ भाग तक का—वर ६००० का अधिकतम मर्यादा के अनर्गल—कर से मुक्त कर दिया गया था। पर वह भेद वास्तव में हटा दिया गया है। आयकर उन तमाम व्यक्तियों से जो भारत में रहते हैं वसूल किया जाना है और उन तमाम आय पर जो इन व्यक्तियों द्वारा भारत में अन्दर या बाहर कमाई गई है कर लगाया

जाता है। जो व्यक्ति भारत में रहते नहीं हैं पर जो भारत में कमाई करते हैं उनकी इस कमाई पर भी आयकर लगता है। आयकर आय पैदा होने के स्थान पर ही वसूल हो जाता है। उदाहरण के लिये जब कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है तो आयकर काट कर दिया जाता है। आयकर भारत सरकार और राज्यों में बँट जाता है, इस सम्बन्ध में हम पहले लिख ही चुके हैं। आयकर से सम्बन्ध रखने वाला एक बड़ा प्रश्न यह है कि लोग आयकर की चोरी करते हैं। सरकार ने इस चोरी को रोकने के लिये कानून में सुधार किये हैं और आयकर विभाग के अधिकारियों को कई प्रकार के अधिकार भी दिये हैं। आयकर जाँच कमिशन भी नियुक्त किया गया है जो काम कर रहा है। पर इन सब प्रयत्नों के बाद भी समस्या का हल नहीं हो सका है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष ७५ करोड़ रुपये की आयकर की चोरी हमारे देश में होती है।

आयकर कर की दृष्टि से अच्छा कर है। यह प्रत्यक्ष, लचीला, निश्चित और कम खर्च में वसूल होने वाला कर है।

आयकर में कई सुधार आवश्यक हैं—जैसे बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक दृष्टि से निर्भर लोगों की संख्या और वृद्धावस्था का आयकर की दृष्टि से लिहाज़ रखा जाना चाहिये। आयकर की चोरी रोकने के लिये और अधिक कड़ाई व्यवहार में लाना चाहिये और उसके लिये कानून में आवश्यक सुधार करना चाहिये।

पिछले वर्षों में भारत सरकार की आयकर से आय भी बड़े-बड़े मात्रा में बढ़ी है। युद्ध के पूर्व आयकर और निगम-कर से १५-१६ करोड़ रु० के आसपास आय होती थी। आज वह आय १५५-१६० करोड़ रुपये के आसपास है।

(२) निगम-कर (कॉर्पोरेशन टैक्स) : निगम-कर वह कर होता है जो सीमित दायित्व वाली मिश्रित पूँजी की कम्पनियों पर इसलिये लगाया जाता है कि इन कम्पनियों को कानून से कुछ विशेष सुविधाएँ मिली हुई होती हैं—जिनके कारण वे अधिक पूँजी इकट्ठी कर सकती हैं, और अधिक लाभ कमा सकती हैं। सब कम्पनियों को समान सुविधाएँ होने से समान कर देना होता है। इसलिये यह अनुपातिक कर है। भारत में सब कम्पनियों को यह कर देना होता है और कोई न्यूनतम सीमा कर नहीं देने की नहीं है। कम्पनियों के कुल असल मुनाफे पर यह कर लगता है। कम्पनियों पर लगने वाला एक तरह से 'सुपरटैक्स' ही निगम-कर है। इससे भारत सरकार को ३० करोड़ रुपये के आसपास आय होती है। आयकर की तरह राज्यों

का इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता।

(५) अनिश्चित लाभ पर ऐसा कि इस नाम से भी अन्त मित हो, असाधारण लाभ पर ही अनिश्चित लाभ कर लगाया जाता है। इसी नियम यह एक शर्तों पर होता है जो युद्ध आदि समय में जब असाधारण लाभ होता है तब लगाया जाता है। अनिश्चित लाभ का माप या तो क्रिडा वगैरह विषय से या लाभ का प्रमुख मात्रा मानी जाती है। इस प्रकार का कर लगाना मर्यादा उचित है क्योंकि अनिश्चित लाभ क्रिडा वगैरह विषय पर कर का परिणाम न होकर परिस्थितियों का परिणाम होता है।

भारत में प्रथम महायुद्ध के समय १९१६ में अनिश्चित लाभ कर सबसे पहले लगाया गया था। १९०० में यह कर हट गया था। उस समय ५०% दर से कर लगा था। द्वितीय महायुद्ध के समय १९४० में फिर यह कर लगाया गया। कर का दर वहाँ ४०% था। ३०,००० वार्षिक से अधिक आय वालों से ही कर लिया जाता था और प्रमुख धर्म विषय के लाभ से अनिश्चित लाभ की माप की जाती थी। १९४१-४२ में कर का दर ६६.३३% करदी गई गई और शेयर ३३.३३% पर आयकर और सुपरटैक्स लगता था। इसका दर दे देन के बाद अनिश्चित लाभ का २०% व्यक्ति के पास रहता था। १९४२ में भारत सरकार ने अनिश्चित लाभ-कर का १/५ अंश अनिश्चित लाभ का १३.३३% सरकार के पास जमा कराना अनिवार्य कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि केवल ६.३३% अनिश्चित लाभ का व्यक्ति के पास में रहता था। १९४४ में अनिवार्य जमा की दर और बढ़ा दी गई जिससे कि अनिश्चित लाभ में से व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचना था। यह अनिवार्य जमा की रकम वापस की जाने ली है। मार्च १९४५ में यह कर उठा लिया गया।

(६) क्या पार लाभ पर अनिश्चित लाभ-कर उठाने के बाद उसके स्थान पर मर १९४०-४८ के बीच में ही निषादनश्रद्धा एवं निषादनश्रद्धा लाभ-कर लगाया। यह भी असाधारण लाभ पर लगनेवाला कर था। जो लोग १ लाभ प्रति वर्ष से अधिक लाभ कमाते थे उन सब पर १६.३३% कर लगाया गया। १९४८-४९ में कर की दर २०% और 'यूनितम' बूट का मर्यादा २ लाख रुपया करदी गई। १९५०-५१ में यह कर विलुप्त हो उठा लिया गया।

(६) पूँजीगत लाभ पर ऐसा कि इसके नाम से भी प्रकट होता है यह कर उस लाभ पर लगता है जो किसी चीज के मूल मूल्य (कैपिटल वल्यू) में वृद्धि हो जाने से उत्पन्न होता है। यह कर जिना कमाई हुई आय पर होने से इस लगाना उचित है और अप्रतिष्ठा, इन्फ्लेक्शन आदि दशा में यह लगता है।

श्री लियाक़तअली खॉं ने अपने १९४७-४८ के बजट में पहली बार भारत में यह कर लगाया। यह कर केवल उस पूँजीगत लाभ पर लगाया गया था जो कृषि भूमि को छोड़कर दूसरे पूँजीगत ‘एसेट्स’ के विनिमय या हस्तांतरण से, जो ३१ मार्च १९४६ के बाद किया गया हो, उत्पन्न हो। ‘केपिटल एसेट’ की परिभाषा से व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुएँ, जैसे जेवर, फर्नीचर आदि या कच्चा, माल या विकने के लिये रखा हुआ माल, अलग कर दी गई थी। कर की दर प्रगतिशील थी। सात साल या अधिक समय से यदि संपत्ति किसी के स्वामित्व में है तो उसके बेचने पर कर नहीं लगता था। इसी प्रकार उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्ति भी कर से मुक्त थी। एक सीमा के बाहर पूँजीगत हानि को पूँजीगत लाभ में से कम करने की व्यवस्था भी थी। १९४९-५० में यह कर भी उठा लिया गया।

(७) उत्पादन-शुल्क : उत्पादन-शुल्क भारत सरकार और राज्य की सरकारें दोनों ही लगाते हैं। पर राज्य की सरकारें तो देशी शराब, भंग, गांजा आदि जैसी वस्तुओं को विक्री और उत्पादन पर यह शुल्क लगानी हैं और बाक़ी सब वस्तुओं पर भारत सरकार यह शुल्क लगाती है। भारत सरकार द्वारा लगाये गये शुल्क उत्पादन पर ही लगाये जाते हैं। इस लिये उत्पादन करने वाले से वह वसूल होता है और उत्पादन की मात्रा के साथ वह कम-ब्यादा होता है। भारत सरकार द्वारा मोटर स्प्रिट, केरोसीन, शकर, धियासलाई, इस्पात के टुकड़े, टायर, तम्बाकू, चाय, काफी, धूती कपड़ा, और घनत्वति माल पर उत्पादन-शुल्क लगाया जाता है। इनमें कई चीज़ें आम लोगों के उपयोग की हैं। इससे उनका भार साधारण जनता पर पड़ता है। उत्पादन-शुल्क से भी भारत सरकार की आय काफ़ी बढ़ी है। जहाँ १९३७-३८ में उत्पादन लागत से ८ करोड़ से कुछ कम ही आय थी वहाँ १९५१-५२ के प्रस्तुत बजट में उत्पादन लागत से ८५ करोड़ के लगभग आय का अनुमान लगाया गया है।

(८) नमक-शुल्क : नमक-शुल्क से भारत सरकार को लगभग ८ करोड़ रुपये वार्षिक की आय होती थी। विदेश से जो नमक आता था उस पर भी आयात-शुल्क लगता था और हमारे देश में जो उत्पादन होता था उस पर भी उत्पादन-शुल्क लगता था। भारत में पैदा होने वाले नमक पर उत्पादन-शुल्क लगाने के दो तरीके थे—(i) सरकार या तो स्वयं उत्पादन करती थी या व्यक्तिगत उत्पादन करने वाले पर यह प्रतिबंध था कि वह सारा नमक सरकार को ही बेचे। भारत सरकार फिर उत्पादन-शुल्क वसूल करके नमक बेचती थी। (ii) दूसरा तरीका यह था कि नमक पैदा करके बेचने का काम व्यक्तिगत तौर पर व्यापारी करते थे, पर सरकार उनसे उत्पादन शुल्क वसूल करती थी।

नमक शुल्क का देश में जब हम पराधीन थे बड़ा-विरोध था क्योंकि इसका भार शरीर जनता पर था। जब १९४६ में भारत में अन्तरिम सरकार बनी तो भी लियाक़ाग़ली खाँ ने १९४७-४८ के बजट में से इस शुल्क को १ अप्रैल १९४७ से बिल्कुल उठार लिया। पर आज इस बारे में बड़ा मतभेद है कि केवल मावना व आंधार पर स्वनर भारत की सरकार को यह शुल्क उठा लेना चाहिए या क्या? कई अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि भारत सरकार को ८ करोड़ रुपये की यह आय नहीं छोड़ना चाहिये। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि यह कहना कि कर के मामले में भावना से विचार न करके ठोस आर्थिक आधार पर विचार करना चाहिये, सही नहीं है—न तार्कामिक दृष्टि से और न व्यवहार की दृष्टि से। मनुष्य का कोई व्यवहार ऐसा नहीं होगा जो भावना के प्रभाव से मुक्त हो। दूसरे, कर के सबब में तो मावना का बड़ा महत्व रहता है। यह कहा जाता है कि जो कर पुराना हो जाता है और जिते देने के लोग अल्प हो जाते हैं उस पर जो लगाने में आपत्ति नहीं क्योंकि यह लोगों को अवरोध नहीं। यह सिद्धान्त मावना पर आधारित नहीं है तो और किस पर है? और सब अर्थशास्त्री इस सिद्धान्त का स्वीकार करते हैं। इसलिये यह तो प्रश्न है नहीं कि भावना का सिद्धान्त खराब है और यह नहीं रखा जाना चाहिये, प्रश्न तो यह है कि जारी स्थिति को देखकर इस सवाल के बारे में भावना की कितनी सीमा होना चाहिये, इस बारे में थोड़ा विचार करना चाहिये।

नमक शुल्क के पक्ष में दो दलालें हैं—(i) एक तो यह कि नमक-शुल्क के हटाने से सरकार को ८ करोड़ का आय की हानि हो गई, (ii) दूसरी यह कि किसी भी देश की कर-व्यवस्था में आखिर ऐसे कर भी रहते हैं और रहने चाहिये जो सारी से गरीब लोगों पर भी पड़ें। नागरिकता के भाव को जाग्रत करने में और शासन में अनादायित्व अनुभव करने में प्रत्येक व्यक्ति को इससे सहायता मिलना है और प्रत्येक व्यक्ति से जो कर वसूल होता है वह कितना ही कम हो जुल गिनाकर उसकी मात्रा पर्याप्त हो जानी है। जहाँ तक इन दलीलों का अपने आप से संबंध है वे ठीक हैं। पर जिन आधार और दृष्टिकोण पर ये दलालें आधारित हैं उन आधार और दृष्टिकोण का पूरा करने वाले और कर भी हो सकते हैं। केवल नमक ही ऐसा पदार्थ नहीं है जो प्रत्येक व्यक्ति काम में लाता है। और भी एसी कई चीजें हैं। काका उनमें से एक है। बल्कि नमक से कपड़ा एक मफार से ज्यादा उपयुक्त है। नमक पशुओं व लिये भी बहुत उपयोगी और आवश्यक पदार्थ है। इसका सार यह है कि नमक शुल्क से होने वाली आय का घाटा और तरह से समान कोटि के करों से और एक या अधिक करों से पूरा हो सकता है। इससे नमक शुल्क को दुबारा नहीं

लगाने के पक्ष में एक दूसरी बड़ी दलील है। वह दलील यह है कि नमक-शुल्क का देश के स्वतंत्रता-संग्राम से घनिष्ठ लाञ्छित और भावात्मक सम्बन्ध रहा है। महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह इस देश की आज़ादी में अपना गौरवमय स्थान रखता है। हमें इस ऐतिहासिक घटना को चिरस्थायी बनाना चाहिये। आने वाली असंख्य पीढ़ियों और अनन्त काल तक यह बात घर-घर में और व्यक्ति-व्यक्ति को याद रहे कि भारत से नमक-कर उस समय हटा था जब भारत ने एक अपूर्व ढंग से महात्मा गांधी के अपूर्व नेतृत्व में स्वाधीनता प्राप्त की थी।

(६) व्यापारिक विभागों से आय : रेल—भारत सरकार को रेलवे, डाक और तार, तथा टंकन और मुद्रा से भी आय होती है। रेल से होने वाली आय के बारे में यहाँ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है। आतायात वाले परिच्छेद में इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा गया है। यहाँ तो इतना लिख देना ही पर्याप्त होगा कि रेल अपना पूरा का पूरा लाभ भारत सरकार को न देकर एक समझौते के अनुसार निश्चित रकम भारत सरकार को देती है। १९२४ में यह समझौता सबसे पहली बार हुआ। समय समय पर उसमें संशोधन हुये। इस समय १९४० में जो संशोधन हुआ उसके आधार पर रेल भारत सरकार को निश्चित रकम में अंशदान देती है। इस समझौते के अनुसार पाँच साल तक सगरे पूंजी जो रेलों में लगी हुई है उस पर ४% रेल भारत सरकार को देती रहेगी। युद्ध के समय में भारत सरकार को रेलों से बहुत आय हुई। जहाँ १९३६-४० में यह आय ४ करोड़ रुपये की थी वहीं १९४२ में १२ करोड़ रुपये ने ऊपर और १९४५-४६ में ३२ करोड़ रुपये तक पहुँच गई। उसके बाद इस आय में बहुत कमी आय गई और अब ६-७ करोड़ रुपये के आसपास यह है।

डाक और तार—इस विभाग से भी लबाई के दिनों में आय बढ़ी। १९३६-४० में १ करोड़ ४० के लगभग इसकी आय थी वह १९४२-४३ में ४ करोड़ ४० से ऊपर और १९४५-४६ में ११ करोड़ से ऊपर पहुँच गई। इस समय यह आय २-३ करोड़ रुपये के आसपास होती है।

टंकन और मुद्रा—इस मद में आय के दो साधन हैं—एक तो भारत सरकार रुपये और रिजर्वी का टंकन करती है उससे, और दूसरे रिजर्व बैंक से। जब से रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से उससे होने वाली आय भी बढ़ गई है। द्वितीय युद्ध काल में इस मद की आय भी बढ़ गई थी। अब फिर कम होगई है। टंकन और रिजर्व बैंक से मिलाकर १०-१२ करोड़ रुपये की आय इस समय है। इस में परिवर्तन होता रहता है।

(१०) आय के न्याय मायन भारत सरकार की आय ने महत्वपूर्ण मरों का ऊपर उल्लेख किया गया है। पर इनके अलावा उसकी आय के कुछ अन्य मद भी हैं—जैसे अफाम ब्याज, 'सि वल एडमिनिस्ट्रेशन', 'सिविल वर्क', आदि। महा अफीम से होने वाला आय के बारे में दो शब्द लिखना अनुचित न होगा। अफीम का उत्पादन और बितरण दोनों ही पर भारत सरकार का एकाधिकार है। सरकार से लाइसेंस मिलने पर ही अफीम की बेचनी का जा सकती है जो पैसा करने के बाद सरकार को ही बेचना होता है। सरकारी कारखानों में वह पैसा की जाती है। अफीम को बेचने, अफाम पर निर्यात शुल्क और अफाम बेचने वालों को बेचने के अधिकार प्राप्त करने के लिये जो फीम देनी होती है, इससे जो आय होती है वह सरकार को मिलती है। पर अफीम की आय का प्रधान भाग निर्यात शुल्क से ही आता है। जो अफीम बेचने वालों द्वारा दी गई फीम से आय होता है वह उत्पादन शुल्क की अंशों में और शेष आय अफीम शीपिंग से हा बोट में दिखाई जाती है। भारत से चीन को पहले बहुत अफाम जानी थी। पर १९०७ में भारत सरकार और चीन का सरकार में यह समझौता हुआ कि धीरे-धीरे भारत चीन को अफीम भजना कम कर देगा और दस वर्ष में बिल्कुल बंद कर देगा। बाद में राष्ट्र सभ ने जो इस प्रश्न को हाथ में लिया और १९१६ में राष्ट्र सभ के बहने के अनुसार भारत सरकार ने यह घोषणा की ३१ दिसंबर १९३५ तक अफीम का निर्यात पूर्णतः और वैज्ञानिक उपयोग के अलावा अन्य प्रकार के उपयोग के लिये बंद कर दिया जाएगा। इस घोषणा के अनुसार अब अफीम का निर्यात बहुत कम होगया है। इस समय अफीम से २ करोड़ ३ करोड़ रुपये के बीच में आय होता है। म्यांमार से २ करोड़ से कुछ कम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ८ करोड़ के आसपास और सिविल वर्क में ११ करोड़ के आसपास आय होती है।

भारत सरकार का व्यय किसी देश की वित्त व्यवस्था में सार्वजनिक व्यय का बहुत महत्व होता है। किसी देश तक वित्त व्यवस्था का स्वरूप ही इससे निर्भर होता है कि सावजनिक व्यय किस प्रकार होता है। भारत सरकार के व्यय को ठान बड़े मामलों में बांटा जा सकता है — रक्षा व्यय, राजस्व एकत्रित करने सम्बंधी व्यय और नागरिक व्यय।

(१) रक्षा व्यय भारत सरकार के कुछ व्यय का एक बड़ा भाग रक्षा पर खर्च होता है। पराधीनता के समय हमारे देश में रक्षा पर जो बड़ा चढ़ा व्यय होता था उसका एक कारण तो यह था कि भारत ब्रिटेन के पूर्वी साम्राज्य की रक्षा का वन्द माना जाता था, सेना में विदेशी अधिकारियों की सख्या बहुत

भी और उनके वेतन तथा दूसरी आवश्यकताओं पर बहुत व्यय होता था। द्वितीय महायुद्ध के समय तो यह व्यय बहुत ही बढ़ गया। उसके बाद इस खर्च में कमी आई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लोगों के मन में स्वामाविक रूप से यह आशा हुई कि रक्षा व्यय अब कम होगा। पर दृष्टा इसके विपरीत। स्वतंत्रता के बाद से रक्षा व्यय धरावर बढ़ता ही गया है। पुरानी रियासतों का रक्षा व्यय भी अब भारत सरकार के पास आ गया है। काश्मीर के भूगढ़ के कारण व्यय बहुत हो रहा है। सैनिक शिक्षा पर हमें व्यय बढ़ाना पड़ा है क्योंकि हमारे नवयुवकों को सैनिक शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे देश में होना आवश्यक है। संसार में संपर्क की स्थिति का बना रहना भी एक कारण है। निकट भविष्य में देश का रक्षा व्यय कम हो इसकी आशा नहीं की जा सकती। इस समय रक्षा पर कुल व्यय का लगभग आधा खर्च होता है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व रक्षा व्यय ५० करोड़ के आसपास था। युद्ध में ४५० करोड़ से ऊपर यह व्यय पहुँच गया। उसके बाद उस में कमी आने लगी और १९४७-४८ में १५ अगस्त, १९४७ से ३१ मार्च, १९४८ तक का ८७ करोड़ रुपये के लगभग खर्च था। १९५१-५२ के प्रस्तुत बजट में १८० करोड़ से ऊपर इस खर्च का अनुमान लगाया गया है।

(२) रालस्व संग्रह पर होने वाला व्यय—भारत सरकार को करों को वसूल करने के लिये व्यवस्था रखनी होती है। आयकर, निगमकर, उत्पादन-शुल्क, सीमा-शुल्क आदि भारत सरकार ही वसूल करती है। आयकर, निगम-कर के लिये आयकर विभाग है। इसी प्रकार सीमा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क आदि के लिये भी अलग-अलग व्यवस्था है। इस सारी व्यवस्था पर जो व्यय होता है उसे संघीय राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग का नाम दिया जाता है और उसकी रक्षा व्यय या नागरिक शासन से अलग स्वीकृति लेनी होती है। इस व्यय में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। १९४४-४५ में यह व्यय ८ करोड़ के आसपास था। १९५१-५२ के प्रस्तुत बजट में इस व्यय का १४½ करोड़ का अनुमान लगाया गया है और १९५०-५१ के संशोधित अनुमान १३ करोड़ से ऊपर है। इस व्यय में कमी करने की आवश्यकता है।

(३) नागरिक व्यय—इस श्रेणी में मूलतः दो प्रकार के खर्च आते हैं। एक तो वह व्यय जिसका संबंध सामान्य शासन संचालन से है—इसमें सामान्य शासन, विदेशों से संबंध, न्याय, पुलिस, जेल, प्रचार, प्रकाशन, विस्थापितों पर होने वाला व्यय, राज्यों को सहायता और साक्षात् पर दी जाने वाली सहायता का खर्च, आदि आते हैं। दूसरा वह व्यय है जिसका संबंध शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वैज्ञानिक खोज आदि ऐसे विभागों से है जो जनता के हित

और मजदूरी से सबन रखते । भारत सरकार का यह खर्च भी बराबर बढ़ता गया है । पर इसमें शिक्षा, निरक्षरता और स्वास्थ्य पर जो आज भी जितना व्यय होता है वह बहुत कम है । इसके विपरीत जो सामान्य शासन संचालन का खर्च है उसमें कमी करने की ज़रूरत है । १९५१-५२ के प्रस्तुत बजट में ५.५३ करोड़ रुपये की किरायेत भारत सरकार द्वारा की गई है । इस विषय में विचार करने के लिए सितंबर १९४७ में भारत सरकार ने एक 'इकोनोमी कमेटी' भी नियुक्त की थी । इस कमेटी ने भी खर्च में कमी करने की आवश्यकता पर जोर दिया था । इस संबंध में भारत के वित्त मंत्री ने १९५१-५२ के प्रस्तावित बजट पर बोलते हुए कहा था कि नागरिक व्यय में जिसमें घर संप्रदाय का व्यय भी शामिल कर लिया गया है कमी की गुंजाहट सामिन है । लगभग २०० करोड़ रुपये का कुल नागरिक व्यय में से १०८ करोड़ ४० का व्यय तो ऐसा बनाया गया जो अनिवार्य रूप से करना ही होगा जैसे व्यापार, व्यापार का मुकाबला, पेंशन, राज्यों की निश्चित सहायता विभाजन-पूर्व सक्ती देना, अधिकृत अन्न उपभोग तथा खाद्यान्न सहायता पर व्यय, और निष्ठागिरी पर होने वाला खर्च । वित्त मंत्री ने कहा कि इनका अर्थ यह है कि कुल व्यय में १२२ करोड़ रुपये का खर्च ऐसा है जिसमें किरायेत करने का प्रयत्न हो सकता है । वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इसमें भी राष्ट्र निर्माण के विभागों, घर संप्रदाय आदि का ऐसा व्यय है जो बहुत कम नहीं हो सकता । वित्त मंत्री ने कहने का सार यह था कि किरायेत की बहुत आशा करना व्यर्थ है । वित्त मंत्री का यह दृष्टिकोण सही नहीं है । फरवरी १९५१ में 'एस्टीमेट्स कमेटी' ने अपनी रिपोर्ट में कई प्रकार के अपव्यय और समीकरण के अभाव का उल्लेख किया है । सरकारो कर्मचारियों की संख्या पहले से अब कई गुनी हो गई है । सारांश यह है कि भारत सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, निरक्षरता, वैज्ञानिक विभागों जैसे राष्ट्र निर्माणकारी कामों पर अधिक खर्च करने की और शासन संचालन के दूसरे खर्च कम करने की बड़ी ज़रूरत है । यह ठीक है कि विद्युत पंपों में शिक्षा, स्वास्थ्य, निरक्षरता और वैज्ञानिक विभागों पर भी व्यय बढ़ा है पर उसमें आवश्यकता को देखते हुए वृद्धि की बहुत गुंजाहट है । १९४६-४७ में १३ करोड़ रुपये की तुलना में १९५०-५१ में ५ करोड़ के ऊपर वैज्ञानिक विभागों का, १९४६-४७ में ८२ लाख की तुलना में ३ करोड़ के लगभग १९५०-५१ में शिक्षा का, १९४६-४७ में ५० लाख की तुलना में ७६ लाख तक १९५०-५१ में स्वास्थ्य का और १९४६-४७ में ५४ लाख की तुलना में १ करोड़ ३७ लाख तक १९५०-५१ में चिकित्सा का खर्च का बजट में अनुमान लगाया गया है ।

(४) पूंजीगत व्यय—भारत सरकार इस सामान्य व्यय के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय भी करती है जिसका उल्लेख ऊपर पूंजीगत बजट के संबंध में किया जा चुका है।

भारत सरकार का सार्वजनिक ऋण : भारत सरकार की आय और व्यय का विचार कर लेने के बाद सार्वजनिक ऋण का विचार कर लेना आवश्यक है।

प्रत्येक राज्य को समय-समय पर अपना खर्च चलाने के लिये ऋण लेना होता है। यह खर्च प्रायः विशेष प्रकार का होता है—जैसे, युद्ध से सम्बन्धी या किसी निर्माण कार्य से सम्बन्धी। पर कभी-कभी चालू खर्च को चलाने के लिये भी ऋण लेना होता है। जो विशेष खर्च के लिये ऋण लिये जाते हैं वे अल्प-कालीन ऋण होते हैं। जो ऋण एक वर्ष बाद चुकाने होते हैं या जिनको चुकाने का समय निश्चित नहीं होता है उन्हें 'फ्लैट डेट' कहते हैं। जो ऋण छाल भर के अन्दर-अन्दर चुका दिये जाते हैं उन्हें 'अनफ्लैट डेट' कहते हैं। ट्रेजरी बौन्ड द्वारा लिया हुआ ऋण दूसरे प्रकार का ही होता है। सार्वजनिक ऋण अन्तर्देशीय और विदेशीय दोनों ही प्रकार के होते हैं। जो देश के अन्दर जारी किये जाते हैं वे अन्तर्देशीय और जो विदेशों में जारी किये जाते हैं वे विदेशीय होते हैं।

भारत सरकार के ऋण के संबंध में विचार करने से हमें गालूम पड़ता है कि उसमें भी उपरोक्त भेद मौजूद है। रुपया ऋण भी है और स्टरलिंग ऋण भी है जो भारत सरकार को चुकाना है। पर गत महायुद्ध के समय में स्टरलिंग ऋण प्रायः समाप्त सा हो गया। १९३६ की ३१ मार्च को भारत सरकार पर रुपया ऋण ७०६.६६ रोकड़ रुपये का, और स्टरलिंग ऋण ४६६.१० रोकड़ रुपये का और इस प्रकार कुल ११७२.७६ करोड़ रुपये का कुल ऋण था। द्वितीय महायुद्ध के समय रुपया ऋण तो बढ़ता गया और स्टरलिंग ऋण कम होता गया। ३१ मार्च, १९४५ को रुपया ऋण की मात्रा १५७१.४२ रोकड़ रुपये पर पहुँच गई। इसके विपरीत स्टरलिंग ऋण की मात्रा घट कर ३८.१३ करोड़ रुपये पर आ गई। [इस स्टरलिंग ऋण में रेल्वे एन्व्यूटीज़ शामिल नहीं है।] युद्ध के बाद भी यही प्रवृत्ति जारी रही है। ३१ मार्च, १९४६ को कुल रुपया ऋण की मात्रा २३७७.८२ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी और स्टरलिंग ऋण की मात्रा २६.६८ करोड़ रुपये तक आ गई। हाल में १९५१-५२ के बजट को लेकर जो तुलनात्मक आंकड़े प्रकाशित हुये हैं [कॉमर्स, ३, मार्च १९५१ पृष्ठ ४१२] उनके अनुसार ३१ मार्च १९३६ को रुपया ऋण ४८४.८२ करोड़ रुपये का स्टरलिंग ऋण ४६४.६५ करोड़ रुपये का और कुल ऋण

१४६४७ करोड़ रुपये का था। इसकी तुलना में ३१ मार्च, १९५१ को रुपया अणु २०११.०१ करोड़ रुपये का, स्टर्लिंग अणु ३३ करोड़ रुपये का और डालर अणु २४६० करोड़ रुपये का, और कुल अणु २०८८६१ करोड़ रुपये का आका गया है और ३१ मार्च १९५२ को रुपया अणु २०४३६० करोड़ रुपये का, स्टर्लिंग अणु ३०५४ करोड़ रुपये का और डालर अणु २८५६ करोड़ रुपये का और कुल अणु २१०२७१ करोड़ रुपये का आका गया है। इसके अभाव में भारत सरकार को पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, कैश सर्टिफिकेट्स, प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिटेशन और रिजर्व फंड और कुछ दूसरे डिपोजिटिव भी चुकाने हैं। ऐसा अनुमान है कि ३१ मार्च १९५१ को ये सारी वस्तु ६८८ करोड़ रुपये के लगभग और ३१ मार्च १९५२ को ७०० करोड़ रुपये के लगभग [पाकिस्तान का हिस्सा निकाल कर] होगी।

रुपया अणु और स्टर्लिंग अणु के बारे में एक बात ध्यान में रखने की यह भी है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि भारत रुपया अणु भारतीयों के पास हो और सारा स्टर्लिंग या डालर अणु विदेशियों के पास हो, हालांकि प्रायः ऐसा ही होता है।

भारत सरकार के अणु के सम्बन्ध में दूसरी जानने योग्य बात यह है कि इसमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के अणु शामिल हैं। अल्पकालीन अणु का प्रमुख साधन ट्रेजरी बिल है। ये बिल सबसे पहले १९१७ में जारी किये गये थे और इनका अवधि २ से १२ महीने तक की होती है, पर ३ महीने के ट्रेजरी बिल बहुत प्रचलित हैं। रिजर्व बैंक से ली जाने वाली हना लगी भी इसी श्रेणी में आती है। अल्पकालीन अणु का तीसरा मुख्य साधन 'ट्रेजरी डिपोजिट रिपॉजिट' का है। ये १५ अक्टूबर १९४८ को सबसे पहले जारी की गई थी। इनका उद्देश्य सम्भाओं के लिये अल्पकालीन निधियों का साधन प्रदान करना है और इसलिये यह २५००० रुपये से कम रकम की नहीं होती। इनकी अवधि छ, नौ, बारह महीना होती है और यह हस्तांतरित नहीं की जा सकती। द्वितीय महायुद्ध के समय भारत सरकार के अल्प कालीन अणु की मात्रा बढ़ गई थी। ३१ मार्च, १९३६ को अल्पकालीन अणु की मात्रा ४६६० करोड़ रुपये थी जो कुल अणु का ६५ प्रतिशत होता था। ३१ मार्च, १९४३ को इसकी मात्रा २६४७० करोड़ रुपये तक पहुँच गई जो कुल अणु का २१८ प्रतिशत था। १९४८ से फिर इस अणु की मात्रा बढ़ने लगी है। ३१ मार्च, १९४९ को इसकी मात्रा ३५४३६ करोड़ रुपये की थी। ३१ मार्च १९५१ को ३७३२० करोड़ रुपये तक इसने पहुँचने का अनुमान है।

और बड़ी अनुमान ३१ मार्च १९५२ के बारे में है।

भारत सरकार के ऋण के वर्गीकरण का एक अन्य आधार उत्पादक और अनुत्पादक ऋण का है। बहुत सा ऋण रेल, डाक-तार और सिंचाई जैसे उत्पादक कामों के लिये लिया गया है। भारत सरकार ने १८६० से उत्पादक कामों के लिये ऋण लेना आरम्भ किया और उत्पादक ऋण की मात्रा तब से बराबर बढ़ती गई। १८६६ से १९१३ के बीच में उत्पादक ऋण १०६.६ करोड़ रुपये से बढ़कर ३६१.६ करोड़ रुपये तक पहुँच गया। इसी समय में अनुत्पादक ऋण १००.८ करोड़ रुपये से घटते घटते १६.१ करोड़ पर आ गया। १९१५ में इसकी मात्रा केवल ३ करोड़ रुपये रह गई। पर प्रथम महायुद्ध आरंभ हो जाने से अनुत्पादक ऋण में फिर वृद्धि होने लगी। १९२४ में अनुत्पादक ऋण २०४.६५ करोड़ रुपये तक पहुँच गया और उत्पादक ऋण ५७८.३६ करोड़ रुपये का था। व्यापारिक मंदी के कारण, जो १९२६ में आरम्भ हुई, अनुत्पादक ऋण की मात्रा और बड़ी क्योंकि बजट के घाटों की इसी प्रकार पूर्ति की जा सकती थी। १९३८-३९ में अनुत्पादक ऋण की मात्रा २०६ करोड़ तक पहुँच गई। द्वितीय महायुद्ध के समय अनुत्पादक ऋण की मात्रा में फिर वृद्धि हुई। अनुत्पादक ऋण की वर्तमान स्थिति के बारे में यह अनुमान है कि १९५१ के मार्च ३१ को ५७६ करोड़ रुपये का था। पर इस सारे ऋण को अनुत्पादक मानना ठीक नहीं होगा क्योंकि इसमें राज्यों को विकास के लिये दिया हुआ ऋण और केन्द्रीय सरकार की संपत्ति पर किया गया व्यय [दिल्ली राजधानी के निर्माण में किया गया खर्च] भी शामिल है।

भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के बारे में अन्तिम बात ध्यान में रखने की यह है कि इस ऋण का आरंभ ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने के लिये ही हुआ था। जब देश में ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य था उसी समय हमारे सार्वजनिक ऋण का आरम्भ हो गया था। ये ऋण प्रायः उन लड़ाइयों के लिये लिया गया था जो कम्पनी ने भारतीय राजाओं, नवाबों और हुमरों विदेशी शक्तियों से भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये लड़ी थीं। जब १८३४ में कम्पनी के स्वतंत्र निबंधन से ब्रिटिश पार्लियामेंट के निबंधन में भारत का शासन आ गया तो कम्पनी का सारा ऋण भारत का ऋण मान लिया गया। इस प्रकार कम्पनी का ३४ करोड़ पाँव का ऋण भारत के सिर पर लाद दिया गया। इसके बाद भी कई लड़ाइयाँ हुईं, १८५७ का विद्रोह दबाया गया और इस सबके लिये ऋण लिया गया वह भारत के सिर पर पड़ा। जब कम्पनी से ब्रिटिश सरकार के हाथ में भारत का शासन आया तो सारा ऋण भी भारत पर

बना रहा। १८५७ के विद्रोह के बाद १८६० में भारत पर ६०३ करोड़ पाँड का अध्र था। यह सब अनुत्पादक अध्र था। भारत को परासीन बनाने में इसका उपयोग किया गया था और भारत को ही इसका देनदार बनाया गया था। भारत के सार्वजनिक अध्र को इस प्रारम्भिक स्थिति को भारत के सार्वजनिक अध्र पर विचार करते समय हम भूल नहीं सकते।

अध्र का चुकारा अध्र से सम्बन्ध रखने वाली एक समस्या उसे चुकाने की है। १६२४ तक इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पास कोई निश्चित योजना नहीं थी। बजट की बचत जब होती या तो वह अध्र चुकाने के काम में ली जाती थी। इनके अलावा रेलवे एन्वुटीज़ और सिकिंग फंड द्वारा भी अध्र चुकाने का प्रयत्न किया गया। फेरीन इन्वेंट्रीज़ बजट का भी इससे लिये उपयोग किया गया। पर १६९४ में वित्तीय विचार सदन सर बेसिल ब्लेकट ने एक योजना सिक्किंग फंड कायम करने की जारी की। १६३६-३८ में जब व्यापारिक मंदी के कारण भारत सरकार की स्थिति ख़ाबाख़ाल हो गई तो सिक्किंग फंड में १६९४ की योजना के अन्तर्गत रुपया जमा करना सम्भव नहीं मालूम पड़ा। इसलिये योजना स्थगित कर दी गई। यद्यपि सिक्किंग फंड में कोई रुपया नहीं जमा किया गया पर अध्र के चुकाने के लिये ३ करोड़ रुपया बजट में रखा गया। अभी तक भी यही प्रणाली चल रही है। केवल इतना अन्तर अवश्य हुआ है कि द्वितीय महायुद्ध के कारण अध्र बजट जाने में ३ करोड़ रुपये की जगह १६४६४७ से ५ करोड़ रुपये अध्र चुकाने के लिये बजट में रखे जाने लगे हैं।

स्टरलिंग अध्र का 'रिपेट्रियेशन' यह हम लिय चुके हैं कि द्वितीय महायुद्ध के पहले तक भारत व अध्र में स्टरलिंग अध्र का काफी बड़ा अंश था। १६९७ में ही भारत सरकार ने स्टरलिंग अध्र को 'रिपेट्रियेट' [चुकारा] करना आरम्भ कर दिया था। 'रिपेट्रियेट' करने का अर्थ है स्टरलिंग अध्र को चुका देना। पर एक बार तो स्टरलिंग की कमी के कारण यह कार्य रोक दिया गया। जब द्वितीय महायुद्ध के समय स्टरलिंग जमा होने लगे तो स्टरलिंग चुकाने का कार्यक्रम भारत सरकार ने फिर आरम्भ कर दिया। स्टरलिंग को चुकाने के लिये कई योजनाएँ बनाई गई जैसे खुले बाज़ार में स्टरलिंग अध्र खरीदने की योजना, लाइसेंस योजना, अनिवार्य प्राप्ति योजना, स्वेन्डा से स्टरलिंग अध्र को रुपया अध्र में बदलने की योजना, रेलवे 'एन्वुटीज़' को दीर्घकालीन अध्र में बदलने और रेलवे विवेचक स्टॉक का चुकाने की योजना। इन विभिन्न योजनाओं के विस्तार में गये बिना इतना जान लेना काफी होगा कि १६३६-३७ के अन्त में कुल ३५६.०५ मिलियन पाँड भारत सरकार को स्टरलिंग में देना था। इस

३५६.०५ मिलियन पाँड के स्टर्लिंग देने में २६१.५३ मिलियन पाँड के ऋण, ३६.८६ मिलियन पाँड की रेल्वे एन्पूटीज़ और २४.६६ मिलियन पाँड के रेल्वे डिबेंचर थे। १६३७-३८ से १६४४-४५ तक कुल ३२२.८४ मिलियन पाँड के स्टर्लिंग ऋण का जुकारा किया गया जो वर्षों में ४३०.४६ करोड़ का होता है। पर इस रकम में १ अक्टूबर १६४२ तक रेल्वे एन्पूटीज़ के रूप में जो जुकारा किया गया था वह और रेल्वे डिबेंचर्स जो ईस्ट इन्डिया लोन्स एक्ट १६३७ के मातहत खारिज कर दिये गये थे वह भी शामिल हैं। ४३०.४६ करोड़ रुपये के बराबर के स्टर्लिंग के इस जुकारे में ११६.८७ करोड़ के टर्मिनेबल स्टॉक और २३१.३४ करोड़ के नॉन-टर्मिनेबल स्टॉक थे, ३६.०८ की रेल्वे एन्पूटीज़ और ४३.१७ करोड़ के रेल्वे डिबेंचर थे। १६३६-३७ के २६१.५३ मिलियन पाँड के स्टर्लिंग ऋण के मुकाबिले में इस जुकारे के फलस्वरूप १६४४-४५ के अन्त में १० मिलियन पाँड का स्टर्लिंग ऋण रह गया। इसमें १५.४७ मिलियन पाँड का 'वार लोन' शामिल नहीं था क्योंकि १६३१ से ही वह स्थगित है। स्टर्लिंग देनदारी के जुकारे के बारे में दूसरी बात रखने की बात यह है कि यह नहीं समझना चाहिये कि जितनी स्टर्लिंग देनदारी जुकादी गई उतनी कुल देनदारी भारत सरकार की कम हो गई। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक ओर भारत सरकार ने अपने पर की स्टर्लिंग की देनदारी जुकाई तो दूसरी ओर किसी हद तक उसने उसके एवज में रुपया प्रतिभूति [रुपी काउन्टरपार्ट] जारी भी की। इसलिये वास्तव में १६१.६७ करोड़ रुपये की स्टर्लिंग देनदारी इस समय में कम हुई थी और २४२.०१ करोड़ रुपये का रुपया ऋण बढ़ गया था। इस २४२.०१ करोड़ रुपये के रुपये ऋण में ३.५२ करोड़ रुपये का रुपया ऋण ऐसे स्टर्लिंग ऋण के कारण बढ़ा था जो ४३०.४६ करोड़ रुपये के उपरोक्त स्टर्लिंग ऋण में शामिल नहीं था। इसलिये उपरोक्त स्टर्लिंग ऋण में से केवल २३८.४६ [२४२.०१ - ३.५२] करोड़ रुपये का रुपया ऋण नया जारी किया गया और १६१.६७ करोड़ रुपये का स्टर्लिंग ऋण चुकाया गया, और इस प्रकार कुल २३८.४६ + १६१.६७ = ३९०.४६ करोड़ रुपये की स्टर्लिंग देनदारी शेष हो गई। इस सबका सार यह है कि स्टर्लिंग देनदारी चुकाने के लिये सरकार को जो स्टर्लिंग चाहिये था वह तो जो स्टर्लिंग युद्ध के समय जमा हो रहा था उसमें से सरकार को रिज़र्व बैंक ने दे दिया पर उसके एवज में सरकार ने या तो रुपया ऋण जारी करके जुकारा किया या फिर बाकी का जुकारा अपनी रोकड़ में से या अस्थायी ट्रेजरी बिल जारी करके किया। इस प्रकार १६४४-४५ तक भारत सरकार ने अपनी स्टर्लिंग देनदारी का जुकारा प्रायः समाप्त कर दिया

या। हमके बाद स्टर्लिंग रिपट्रियेशन केवल टा स्टाकों का जारी रहा है जो पहले सुकारे क लिये नहीं पेश किय गये थे। १९४६ ५० तक ३२८७६ मिलियन पाउंड स्टर्लिंग श्रेण का ४३७ १३ करोड़ रुपये की लागत पर सुकारा हो चुका था।

दश का विमानन और सार्वजनिक श्रम १७ अगस्त १९४७ का दश का विभाजन हुआ। विभाजन क कारण देश क 'एसट्स' और 'लाइबिलिटीज' का विभाजन मा किया गया। दिसम्बर १९४७ में भारत और पाकिस्तान म एक समझौता हुआ। इस १९४७ क भारत पाकिस्तान बिच समझौते में सार्वजनिक श्रेण क बार में हुय समझौते का समावेश भी था। इस समझौते क अनुसार सार्वजनिक श्रेण में पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान म जो एसट्स हैं या जो पाकिस्तान सरकार ने ले लिये हैं उनमें मूल्य में श्रविमाजिन भारत की लाइबिलिटीज म से एसट्स कम करने पर जो श्रेण बच जाता है उसका १७.५% जोड़ देने पर और इस जोड़ में से पाकिस्तान सरकार ने जो लाइबिलिटीज लैनी हैं उनको कम करने पर जो बच जाता है उसका बराबर तय किया गया है। ऐसा अनुमान किया गया है कि इस आधार पर पाकिस्तान को ०० करोड़ रुपये भारत की श्रेण के रूप में देना होगा। पाकिस्तान सरकार १५ अगस्त १९५२ से आरम्भ करके बराबर की ५० वार्षिक किश्तों में मूल श्रेण और उस पर ३% ब्याज दोनों हा रकमों का एक साथ सुकारा करेगा।

मुद्रा बाजार में श्रेण मिलान में कठिनाई विद्यते कुछ वर्षों स भारत क मुद्रा बाजार में एक प्रवृत्ति यह दखने में आइ है कि सरकार की अपनी आवश्यकता क अनुसार श्रेण प्राप्त करने म सफलता नहीं मिल रही है। १९४७ ४८ से स्थिति विशेष तौर स बिगड़ने लगी। इस वर्ष केवल ४० ६५ करोड़ रुपये के नये श्रेण सरकार बाजार स उपार ले सकी। १९४८ ४९ म लहा १५० करोड़ रुपये के श्रेण लग का विचार था वहा केवल ५५ ०४ करोड़ रुपये क श्रेण मिल सके। इस प्रकार १९४९ ५० में मा ८५ करोड़ रुपये के श्रेण क अनुमान के गिलाफ केवल १० ७५ करोड़ क श्रेण ही सरकार प्राप्त कर सकी। १९५० ५१ के बजट में बाजार स ७५ करोड़ रुपये क श्रेण लेने का अनुमान था उसमें मुश्किलों में मा सरकार ३० करोड़ रुपये ही उपार ले सकी। १९५१ ५२ क बजट में बाजार से १०० करोड़ रुपये का श्रेण लेने का अनुमान है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले वर्षों में मुद्रा बाजार में बहुत तणा रही है। इसका एक कारण तो सरकार का सली रुपये नाति बताया जाता है। यदि सरकार ब्याज का दर ३% स बढ़ादे ता स्थिति में सुधार आ सकता है। इन

में कुछ राज्यों ने बाजार से ऋण ३३% व्याज की दर पर लिये हैं। दूसरा कारण बढ़ती हुई मंहगाई का है जिससे मध्यम श्रेणी की वचत की क्षमता बहुत गिरती जा रही है। तीसरा कारण यह है कि गत युद्ध से शहर से गांव वालों के हाथ में रुपया बचा है और गांव वालों के हाथ का रुपया विनियोग के काम में नहीं आता। पर इन कारणों के अलावा एक बड़ा कारण व्यवसायी वर्ग की छिपी हुई सरकार के प्रति असहयोग की यह नीति है जो वह बराबर सरकार को दवाने के लिये घेरत रहा है। देश का पूंजीपति वर्ग इस प्रकार सरकार पर यह छाप बालना चाहता है कि अगर सरकार राष्ट्रीयकरण की बात करती है तो उसका असर पूंजी के निर्माण पर प्रतिकूल होगा। इस सारी स्थिति को ठीक करने का वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत तो यही उपाय हो सकता है कि एक छोर तो सरकार व्याज की दर कुछ बढ़ावे और दूसरी छोर यह व्यवसायी वर्ग को संतुष्ट करने का भी प्रयत्न करे। पर इस से देश की आचारभूत आर्थिक समस्या का हल नहीं होगा। यहां एक बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सरकार बाजार से ऋण लेने के अलावा छोटे पैमाने की वचत से भी कुछ रुपया इकट्ठा करती है। उस श्रेणी में डाकखाने के वचत, सर्टिफिकेट, सेविंग बैंक डिपोजिट, नेशनल और रक्षा सेविंग सर्टिफिकेट आदि आते हैं। १९५१-५२ के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि इस दिशा में स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है।

राजकीय वित्त

भारत सरकार की वित्त व्यवस्था के विषय में विचार करने के बाद अब हमें राज्यों की वित्त व्यवस्था के बारे में विचार करना होगा। सबसे पहले राज्यों की आय के बारे में हम अध्ययन करेंगे।

राज्यों की आय : राज्यों की आय के मुख्य मुख्य भेद इस प्रकार हैं:—

(१) भूमि राजस्व [लैन्ड रेवेन्यू]—भूमि राजस्व या लगान एक अत्यन्त प्राचीन कर है। कुछ वर्षों पहले तक राज्यों की आय का एक बड़ा आधार भूमि से मिलने वाला लगान था। पर इधर पिछले वर्षों में लगान का महत्व कम हो गया है और जमींदारी प्रथा की समाप्ति के कारण इसका महत्व अभिन्न में और भी कम होने की संभावना है।

भूमि लगान पद्धति में कई दोष हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है। लगान वसूल करने का देश में एकसा आधार नहीं है और जिस दर से लगान वसूल किया जाता है उसमें भी कोई समानता नहीं है। जमींदारी प्रथा का तो शीघ्र अन्त होने जा रहा है। पर केवल इसी से काम नहीं चल सकता। देश में ऐसी भूमि

व्यवस्था कायम होनी चाहिये जिसने अन्तर्गत वास्तव में खेती करने वाला किसान भूमि का मालिक हो और लगान वसूल करने का आधार भूमि का उप-जाऊपन हो। जो जमीन अधिक उपजाऊ हो उसे अधिक लगान देना पड़े।

लगान में 'ए' श्रेणी के राज्यों की तुलना आय ३० करोड़ रुपये के आस पास इस समय है। १९३८-३९ में २५ करोड़ रुपये के लगान पर यह आय थी। इसका अर्थ यह है कि शायद यह जरिया प्रायः स्थिर था है। मैदानी में नई भूमि का उपयोग होने पर और उत्पादों की मात्रा बढ़ने पर लगान से होने वाली आय में कुछ वृद्धि हो सकती है। १९५०-५१ के बजट के अनुसार 'बी' राज्यों की लगान से कुल आय १६-१५ करोड़ रुपये आंकी गई थी।

(२) आधारभूत शुल्क—राज्यों की छोड़े क्यों पहले तक लगान के माध्यम द्वारा महत्वपूर्ण आय का जरिया आबकारी का महकमा रहा है। १९१९ के पहले तो केन्द्र के पास ही यह आय का जरिया था था पर १९१९ के सुधारों के बाद यह प्रांत के पास आ गया और आज तक उनके पास बना आता है। दखी शराब, ठाकी, माग, गात्रा और चढ़ा देना करने वालों से शुल्क और बेचने वालों से लाइसेंस फीस वसूल की जाती है। १९१९ से १९३७ तक प्रान्तों की नीति शराब की बिक्री को कम करने की थी। शराब की दुकानों की संख्या कम करके, उनके खुलने का समय कम करके और शराब पर शुल्क बढ़ाकर बिक्री कम करने का प्रयत्न किया जाता था। १९३७ से जब से कार्यवाही सरकारें सत्ता में आईं तो मद्य निषेध के कार्यक्रम की ओर भी कुछ प्रान्तों का ध्यान गया। पहले १९३७ में ही मद्रास ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। १९३८ में बम्बई में भी शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में भी कुछ किया गया। इस समय मद्रास और बम्बई में पूर्ण मद्य निषेध है। अन्य राज्यों में इस ओर जाने की प्रवृत्ति है।

मद्य निषेध होना चाहिये या नहीं यह प्रश्न बड़े लंबे विवाद का बना हुआ है। भारत सरकार मद्य निषेध के विपक्ष में है। सबसे बड़ी दलील यह है कि आज जब राज्यों के सामने आर्थिक संकट है, मद्य निषेध करके करोड़ों दरवां की आय लौना उचित नहीं है। पर यह दलील एकानो है। मद्यपान का प्रसार होना बुरा है। जनता की इससे भलाई नहीं होगी। इसलिये आय की हानि का ध्यान किये बिना मद्य निषेध के कार्यक्रम को अपनाना चाहिये।

१९३८-३९ में इस प्रश्न से १२ करोड़ रुपये का लगभग आय थी। पर आय आज ने ६ 'ए' श्रेणी के राज्यों की थी। १९४५-४६ में ५१ करोड़ रु० के लगभग यह पहुँच गई था। पर १९४९-५० में २६ करोड़, १९५०-५१ के संशोधित

अनुमान के अनुसार २५ करोड़ से कुछ अधिक और १९५१-५२ के प्रस्तुत वजट के अनुसार २५ करोड़ रुपये से कुछ कम इन ६ 'ए' श्रेणी के राज्यों की यह आय थी। पिछले वर्षों में इस मद का महत्व कम हुआ है और भविष्य में और कम होने की संभावना है। १९५०-५१ के वजट के अनुसार 'बी' राज्यों को इस मद से २०.०७ करोड़ की आय होने का अनुमान था।

(१) सिंचाई—किसान से सिंचाई के पानी के लिये भी कर लिया जाता है। नहरों से जो पानी किसान को दिया जाता है उस पर यह कर लगता है। कर की दर अलग अलग जगह अलग अलग है और एक बार निश्चित हो जाने के बाद उसमें साधारणतया परिवर्तन नहीं होता।

(४) जंगलात—राज्य की सरकारों को जंगलात से भी कुछ आय होती है। लकड़ी बेचने, जंगल की अन्य पैदावार बेचने और चराई की फीस से यह आय होती है। १९३६-४० में जंगलात से ३ करोड़ के लगभग तत्कालीन प्रान्तों की आय थी। आज यह आय १६-१७ करोड़ के लगभग है।

(५) रजिस्ट्रेशन—जब अचल संपत्ति सम्बन्धी दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराई जाती है तो उसकी फीस वसूल की जाती है। यह भी राज्य की सरकारों की आय का एक साधन है। १९३६-४० में तत्कालीन ब्रिटिश भारत में यह आय १ करोड़ रुपये के लगभग थी।

(६) स्टेम्पस—स्टेम्पस या मुद्रांक-शुल्क दो प्रकार का होता है—एक तो न्यायालयों द्वारा वसूल किया जाने वाला और दूसरा जो व्यापारिक दस्तावेजों पर लगता है। इनसे भी राज्य की सरकारों को आय होती है। न्याय सम्बन्धी मुद्रांक-शुल्क को कम करना उचित हो सकता है। इस समय सब राज्यों की आय इस मद से १८ करोड़ से भी ऊपर है।

(७) विक्रय-कर—जैसा कि इस के नाम से प्रकट है विक्रय-कर चीजों की बिक्री के समय लगाया जाता है और इसलिये यह बेचनेवाले से वसूल किया जाता है। यह कर एक या कई चीजों पर लगाया जा सकता है और बिक्री के किसी एक मीके पर या सब मौकों पर लगाया जा सकता है।

भारत में विभिन्न राज्यों की आय का विक्रय-कर आजकल एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। मद्रास में यह कर १९३६ में सबसे पहले लगाया गया था और उत्तर प्रदेश में १९४८ में सबसे बाद में। एक न्यूनतम मर्यादा तक, जो ५००० से ३०००० वार्षिक बिक्री के बीच में विभिन्न राज्यों में पाई जाती है, विक्रय-कर नहीं लगाया जाता। इसी प्रकार कई चीजें—जैसे खाद्यान्न, आटा, दाल, ईंधन, मसाला, केरोसीन, किताबें, खादी, साब आदि—भी इस कर से

मुक्त है। दोनों तरह का विक्रय कर हमारे राज्यों में है—अर्थात् वह जो एक ही बार वसूल होता है और वह जो जितना बार किसी एक चीज़ या निजी से उतनी ही बार वसूल किया जाता है। अलग अलग 'रीज़ों' पर अलग अलग कर की दरें भी लगाई जाती हैं।

विक्रय-कर अग्रतत्त्व कर है और अमीरों का अथवा शरीकों पर रक्ता याम अधिक पड़ता है। विक्रय कर में 'ए' राज्यों की कुल आय ४५-५० करोड़ के आस-पास इस समय है। यह 'बी' राज्यों में राजस्थान के अनिवार्य सब राश्या में है पर इससे कुल आय ५ करोड़ रुपये के घास पास है। हमारे संविधान के अनुसार अब राज्य उन चीज़ों पर विक्रय कर नहीं लगा सकते जो किसी राज्य में बाहर बचे और लौटते जाते हैं, या जो अन्तर्राष्ट्र के या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अंग हैं या उनको सहद ने सर्व साधारण के जीवन के लिये अनिवार्य घोषित कर दिया है। इसका अन्तर इस कर की आय घटने का होगा।

(८) कृषि आयकर—१९३७ में जब प्रांतीय स्वायत्त शासन की देश में स्थापना हुई कृषि आयकर राज्यों द्वारा लगाया जाने लगा। सबसे पहले बिहार ने यह कर १९३८-३९ में लगाया। बाद में आसाम, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी यह कर लगाया गया। 'ए' राज्यों में से इन पांच राज्यों में ही यह कर लगाया जाता है। 'बी' राज्यों में से हैदराबाद और द्रवाकोर कोचिन में ही यह कर (१९५०-५१ तक) था। जबलपुर भूमि का आय पर यह कर लगता है जो लगान देती है। कृषि आय का एक न्यूनतम भाग कर से मुक्त रहता है। 'ए' राज्यों का इस कर से कुल आय ३ करोड़ रुपये वार्षिक के लगभग है। ज़मींदारी प्रथा उठ जाने पर इस भद से आय और भी कम होने वाली है।

(९) मनोरंजन कर—मनोरंजन कर सबसे पहले १९२२ में बंगाल में लगाया गया था। उसके बाद सम्प्र १९२३ में लगा। अन्य प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्त शासन प्राप्त हो जाने के बाद यह कर लगाया गया। इस समय सभी 'ए' क्षेत्रों के राज्यों में यह कर लगा हुआ है। इस कर को लगाने का तरीका यह है कि मनोरंजन के लिये जब व्यक्ति पीस देता है तो उसी के साथ यह कर भी उससे ले लिया जाता है। मनोरंजन के लिये टिकट बचनेपाल जैसे सिनेमाघाटों इस कर को वसूल करते हैं और सरकार को चुकाते हैं। कर की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है और टिकट के मूल्य के हिसाब से लगाई जाती है। मध्य प्रदेश में १९४८-५० में टिकट के मूल्य का ५.०% कर

रूप में लिया जाता है। अन्य राज्यों में २५% के आस-पास यह कर है। उत्तर प्रदेश में ३३.३% है। इस कर से आय पिछले वर्षों में बराबर बढ़ती जा रही है।

(१०) पण लगाने (वेस्टिंग) पर कर—हमारे देश में वैसे तो सब प्रकार का पण लगाना और वृद्धा बंद है पर घोड़ों की दौड़ पर पण लगाना जायज़ है। सबसे पहले बंगाल में १६२२ में पण लगाने पर कर लगाया गया था। १६२५ में बम्बई में भी यह कर लगा। मद्रास में १८३५ में यह कर लगा। कुछ और राज्यों में भी इस समय यह कर लगा हुआ है। पण लगाने में कितना रुपया जाता जाता है उसके ऊपर अमुक प्रतिशत के हिसाब से कर लगाया जाता है। अलग-अलग राज्यों में कर की दर अलग-अलग है और ४% से १५% के बीच में विभिन्न राज्यों में यह कर लगा हुआ है। एक प्रकार के व्यवसन पर यह कर है और इसलिये इसकी मात्रा और बढ़ाई जानी चाहिये। वास्तव में तो घोड़ों की दौड़ पर पण लगाने का भी निषेध होना चाहिये।

(११) मोटर गाड़ियों पर कर—मोटर गाड़ियों पर भी—जिनमें कार, टेम्पली, बस, लोरी, मोटर साइकिल सब आ जाती हैं, सब राज्यों में कर लगता है। कर लगाने का आधार अलग-अलग प्रकार की गाड़ियों के लिये और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। कहीं तो जगह के हिसाब से कर लिया जाता है, तो कहीं खाली गाड़ों का कितना बोझ होता है उसके आधार पर कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में अलग-अलग मायों के आधार पर अलग-अलग कर लिया जाता है। कर की दर भी अलग-अलग है। इस कर को लगाने का एक औचित्य यह भी है कि मोटर गाड़ि से सड़क खराब होती है और उसका सुआवज़ा किसी हद तक मोटर गाड़ियों के चलानेवालों से लिया जाता है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखने ला भी आवश्यक है कि मोटर वातायात के राष्ट्रीयकरण की ओर राज्यों की दृष्टि १६३७ से ही जा रही है और उत्तर प्रदेश तथा बम्बई में तो व्यापक आधार पर राष्ट्रीयकरण हुआ भी है। और राज्य भी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। यह प्रयत्न उचित ही है।

(१२) आयकर—उपरोक्त करों के अतिरिक्त राज्यों की आय का एक बड़ा साधन आयकर में जो उनकी हिस्सा मिलता है वह है। कुल 'ए' श्रेणी के राज्यों की आय ४५ करोड़ के आसपास इस मद से होती है। 'बी' राज्यों की भी इस आय में हिस्सा मिलने लगा है।

(१३) केन्द्र से सहायता—बूट निर्यात-शुल्क की धुरी आय संविधान के अनुसार केन्द्र की जाती है पर उसके श्वक में केन्द्र से पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा को सहायक अनुदान मिलता है। देशमुख निर्यात के

अनुसार इस अनुदान की मात्रा १८१ करोड़ रुपये है। इससे अलावा भारत सरकार से विकास योजनाओं के विषय भी 'ए' और 'बी' राज्यों को अनुदान मिलता था। पर १९५१-५२ के बजट में ये अनुदान बढ़कर दिये गये हैं। 'राष्ट्रीय सड़क कोष' से भी राज्यों को सहायता मिलती है। इनके अलावा केन्द्र राज्यों को अणु भी देता है।

राज्यों का व्यवसायिक स्वयंशासन स्थापित होने के पहले तत्कालीन भातों का अधिकतर खर्च पुलिस और न्याय विभाग पर होता था। पर जब मामलों में १९३७ में लोकप्रिय सरकारों कायम हुई तो राष्ट्र-निर्माणकारी कार्यों पर व्यय बढ़ने लगा। अब हम राज्यों के व्यय की मुख्य-मुख्य मदों का अध्ययन करेंगे। यह अध्ययन 'ए' राज्यों पर ही आधारित होगा।

(१) राश्वर्य पर प्रत्यक्ष भाग—कुल 'ए' राज्यों का इस मद पर व्यय २५ करोड़ के आसपास है जो कुल खर्च का ८% के लगभग आता है। यह यह व्यय है जो कर वसूली के लिये करना पड़ता है।

(२) सिवार्ड—सिवार्ड के मद में 'ए' राज्यों का खर्च पिछले वर्षों में बराबर बढ़ा है। १९५१-५२ के बजट में १४६२ करोड़ रुपये का इस मद में होने वाले व्यय का अनुमान है जो कुल खर्च का ४६% आता है।

(३) शांति व्यवस्था (सिन्डिकेटेड सर्विसेज)—इस भेड़ी में पुलिस, जेल तथा न्याय विभाग आदि में खर्च शामिल है। देश के स्वतंत्र होने के बाद भी राज्यों का यह खर्च बढ़ा है। १९४८-४९ में ७१३६ करोड़ का खर्च था। उसके मुकाबले में १९५१-५२ के बजट में ८०४० करोड़ का यह खर्च रखा गया है। कुल खर्च का २६.०१% यह खर्च है जबकि १९४८-४९ में कुल खर्च का २६.२५% इस मद पर खर्च होता था।

(४) सामाजिक सेवा काय—इसमें शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कृषि, उद्योग आदि शामिल आते हैं। इस मद में खर्च बराबर बढ़ता जा रहा है। १९४८-४९ में यह खर्च ६७६६ करोड़ रुपये का था। १९५१-५२ के बजट में यह खर्च ८६०६ करोड़ रुपये का अनुमान किया गया है। १९४८-४९ में २७.०१% कुल खर्च का इस मद में खर्च होता था। १९५१-५२ में कुल खर्च का ३०.८४% इस मद में खर्च होने का अनुमान है।

(५) अणु सेवाएँ (डेटेड सर्विसेज)—१९४८-४९ में इस मद में ४२२ करोड़ अर्थात् कुल खर्च का १.६८% खर्च होता था। उसके बाद यह खर्च कम हुआ है। १९५१-५२ के बजट में २८० करोड़ ६० अर्थात् कुल खर्च का ०.६०% इस मद पर खर्च होने का अनुमान है।

(६) पूंजीगत खर्च—उपरोक्त सामान्य खर्चों के अलावा राज्यों के पूंजीगत खर्च भी होते हैं। बहु उद्देशीय नदी घाटी योजनाएँ, सिंचाई, विद्युत्, निवास और ज़मींदारों को मुआवज़ा इत्त मद् के खास-खास खर्च हैं। इसके अलावा राज्य विस्थापितों, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं, सहकारी समितियों और किसानों को ऋण भी देता है। अगर हम अन्न, वस्त्र, खाद आदि चीज़ों का राज्य द्वारा व्यापार पर होने वाला आमदनी और खर्च बराबर भी मामलें तो १९५१-५२ में पूंजीगत खर्च १०७.५१ करोड़ होगा जबकि १९५०-५१ में ७५.४१ करोड़ और १९४९-५० में ५८.४३ करोड़ का यह खर्च आँका गया है, या हुआ है।

(७) 'बी' राज्यों का खर्च—१९५०-५१ में 'बी' राज्यों का कुल खर्च २०.८३ करोड़ रु० का बजट किया गया था। शांति-व्यवस्था (सिक्यूरिटी सरविसेज) और सामाजिक सेवाओं संबंधी खर्च की दो बड़ी मदें हैं। शांति-व्यवस्था पर २२.३ करोड़ अर्थात् कुल का २५% और सामाजिक सेवाओं पर ३१.२८ करोड़ अर्थात् कुल का ३६% व्यय माना गया है। सामाजिक सेवाओं में शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च है। 'बी' राज्य राष्ट्र-निर्माणकारी कामों पर अधिक और शांति व्यवस्था पर कम खर्च 'ए' राज्यों के मुकाबले में करते हैं। इसका कारण मैसूर और ट्रावकोर-कोर्चीन जैसे प्रगतिशील राज्यों पर होने वाला खर्च है। ये राज्य पूंजीगत खर्च भी काफ़ी करते हैं।

राज्यों का सार्वजनिक ऋण : १९१९ के पहले तत्कालीन प्रान्तों को ऋण लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। उसके बाद से यह अधिकार उनको मिला और हमारे संविधान में भी राज्यों को यह अधिकार प्राप्त है। १९३९-४० के अन्त में तत्कालीन प्रान्तों का कुल ऋण १५० करोड़ रुपये के लगभग था और उसमें से अधिकांश उत्पादक ऋण था। मार्च १९४९ के अन्त में कुल ऋण 'ए' राज्यों का १४५.३८ करोड़ था। मार्च १९५२ को ३३७.३६ करोड़ तक कुल ऋण पहुँच जायेगा; ऐसा अनुमान है। मार्च १९४९ को १४५.३८ करोड़ का जो ऋण था उसमें से ४५.९३ करोड़ का स्थायी ऋण, १०.८३ करोड़ का चालू (फ्लोटिंग) ऋण, ६३ करोड़ का केन्द्रीय सरकार से लिया हुआ ऋण और २५.६२ करोड़ का अल्पकालीन ऋण था। मार्च १९५२ को ३३७.३६ करोड़ के कुल ऋण में से ६३.६३ करोड़ का स्थायी ऋण, २६.४६ करोड़ का चालू ऋण, २१४.५२ करोड़ का केन्द्रीय सरकार से लिया हुआ ऋण और ३२.७५ करोड़ का अल्पकालीन (अनफ्लेव्ड डेट) ऋण का अंश होगा। राज्यों की कुल आय का १०.९% उनका कुल ऋण है।

केन्द्र और राज्य की वित्त-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति केन्द्र और राज्य के आय-व्यय की मुख्य मुख्य मदों का हम विचार कर चुके हैं। अब हम केन्द्र और राज्यों की सम्पूर्ण वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में अलग अलग विचार करेंगे। पहले केन्द्र की वित्त व्यवस्था के बारे में हम निम्नलिखित करेंगे।

हम सम्बन्ध में सबसे पहला प्रश्न यह है कि भारत सरकार की वित्त नीति क्या रही है और आज क्या है। यदि हम गिड़ले पचास वर्षों पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि भारत सरकार का वित्त नीति किसी निश्चित दोर-कालीन आर्थिक आदर्श से प्रभावित नहीं रही है बल्कि तात्कालिक परिस्थितियों का उस पर सबसे अधिक असर पड़ा है। जब कोई विशेष तात्कालिक प्रश्न उठा आता है कि इस शताब्दी के पहले बीस वर्षों में नहीं था तब तो भारत सरकार की दृष्टि बजट को उल्लिखित रखने तक ही सीमित रही। जब कोई विशेष तात्कालिक प्रश्न उपस्थित हो गया—जैसे १९२६ की व्यापारिक मंदी, १९३६-४५ का द्वितीय महायुद्ध और उसके उत्पन्न और आज तक चलने वाली महंगाई—तो सरकार की वित्त नीति उस प्रश्न के असर में रही। आजकल भारत की वित्त नीति पर मई गांधी की कम करने, उत्पादन को बढ़ाने और देश का आर्थिक विकास करने का असर किसी हद तक देखने को मिलता है पर साहस पूर्वक किसी निश्चित योजना को लेकर सरकार नहीं चली है। यह इसकी वर्तमान नीति का बड़ा खोप है। उदाहरण के लिये विकास की योजनाओं के बारे में कमी लेनी आती है तो कमी घीमापन। आयोजन नीति कभी उदार हो जाती है तो कभी कड़ा। कभी राष्ट्रीयकरण का बहुत चर्चा होता है तो कभी वह दब जाती है। कहीं मध्य-निवेश पर बड़ा आग्रह है तो कहीं नहीं। इस तरह की बातों का वित्त नीति पर असर पड़ता है और उसमें निश्चिन्ता और स्थिरता का अभाव रहता है। इस लिये आज हम बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सरकार दीर्घकालीन निश्चित नीति को लेकर चले। देश के वर्तमान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करके माधोवा और समाजवादी विचारों के वैज्ञानिक सामञ्जस्य पर नई समाज रचना व आदर्श को लेकर देश की वित्त नीति का निर्धारण करना देश के हित में होगा। वित्त व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाला दूसरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार की आर्थिक स्थिति आय और व्यय को देखते हुए कैसी है और भविष्य की संभावनाएँ क्या हैं। मात्रा का जहा तक सवाल है भारत सरकार की आय और व्यय की मात्रा बराबर बढ़ती गई है। १९२८-२९ में भारत सरकार की कुल आय ८४.४७ करोड़ थी। युद्धकाल में ३६१.१६ करोड़ तक १९४५-४६ में इसमें वृद्धि हो गई। उसके बाद इसमें कमी

आई। पर फिर वृद्धि हुई। इस समय के ताज़ा आंकड़े यह हैं कि १९५०-५१ में संशोधित अनुमान ३८७.२१ करोड़ और १९५१-५२ का प्रस्तुत बजट का अनुमान ४०१.०४ करोड़ रुपये का संसद के सामने पेश किया गया था। पिछले १२-१३ वर्षों में लगभग ४३ गुनी आय में वृद्धि हो गई। इस आय में कर से होने वाली आय का १९३८-३९ में ८७.५% भाग था। महायुद्ध के समय इसका अनुपात कम हो गया और १९४३-४४ में ६८.५% तक वह आ गया। पर इसके बाव फ़िर इसमें वृद्धि हुई और १९४९-५० के स्वीकृत बजट में यह अनुपात ९०.२% तक पहुँच गया। यह वृद्धि करों में प्रधानतः आयकर-सीमा-शुल्क, और उत्पादन-शुल्क से तथा दूसरे प्रकार की आय में रेलवे आय से हुई है। आयकर और निगम-कर का भाग १९३८-३९ में कुल कर से होने वाली आय का २२.९% था वह १९४९-५० में ४४.७% हो गया। जहाँ तक व्यय का प्रश्न है आय के साथ ही साथ भारत सरकार के व्यय में वृद्धि हुई है। १९३८-३९ में कुल व्यय ८५.११ करोड़ था। युद्धकाल में अधिक से अधिक व्यय ४९६.२५ करोड़ १९४४-४५ में हो गया था। उसके बाद कमी आई और १९४९-५० के स्वीकृत बजट में ३२२.५३ करोड़ का व्यय माना गया। संसद के सामने प्रस्तुत १९५०-५१ का संशोधित अनुमान ३७९.२८ करोड़ और १९५१-५२ के बजट का अनुमान ३७५.४९ करोड़ का बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि युद्ध के बाद आय की अपेक्षा व्यय अधिक कम हुआ है। भारत सरकार के व्यय में जो वृद्धि हुई है उसमें राष्ट्र-निर्माणकारी विभागों में होने वाली वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है। आय-व्यय को यदि हम मिला कर देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि १९३८-३९ से लगा कर १९४७-४८ तक बराबर घाटा रहा है। जैसे जैसे युद्ध की भीषणता बढ़ती गई इस घाटे की मात्रा भी बढ़ती गई। यहाँ तक कि १९४३-४४ में घाटे की मात्रा १८९.९० करोड़ तक पहुँच गई। १९५०-५१ के संशोधित बजट में ७.९३ करोड़ की बचत और १९५१-५२ के संसद के सामने जो बजट पेश हुआ उसमें २५.६१ करोड़ की बचत का अनुमान लगाया गया है। भारत सरकार के पूँजीगत वजटों को देखें तो मालूम होगा कि युद्धकाल में १९४१-४२ को छोड़ कर बराबर उनमें बचत रही है। १९४४-४५ में वह बचत ४३७.५१ करोड़ तक पहुँच गई थी। इसका कारण यह था कि भारत सरकार बाज़ार से बहुत बड़ी मात्रा में अणु ले रही थी। इससे युद्ध का वह खर्च जो भारत सरकार को वापिस मिलने वाला था, अवश्य अलग था। पर युद्ध के बाद १९४७-४८ से भारत सरकार के पूँजीगत बजट में बराबर घाटा रह रहा है। १९४८-४९ में यह घाटा १६७.४८ करोड़ तक पहुँच गया। इसके बाद घाटे में कमी आ गई है पर घाटा

अमी तक भी जारी है। १९५०-५१ के स्वीकृत बजट में २३ ६४ करोड़ का घाटा आका गया था पर बजट के संशोधित अनुमान के अनुसार पूँजीगत बजट का यह घाटा कुछ बढ़ा ही है। यदि हम 'मिसेलेनियस' मद की ओर राजस्व और पूँजीगत आय-व्यय एक साथ करके देखें तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि १९४६-४७ से १९५०-५१ के स्वीकृत बजट तक बराबर घाटा रहा है।

भारत सरकार की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने का एक अन्य तरीका उसकी नक़द रोकड़ की देखने का है। १९३८-३९ में साल के प्रारंभ में १९ ११ करोड़ रुपया सरकार की रोकड़ (केश बैलेंसेज़) में था। १९४५-४६ के अन्त और १९४६-४७ के आरम्भ में रोकड़ में ५२९ ४३ करोड़ रुपया हो गया। भारत में विनाश के बाद १५ अगस्त, १९४७ को ९७० ३० करोड़ रुपया भारत सरकार की रोकड़ में था। १९५१-५२ के प्रारम्भ में (१ अप्रैल, १९५१) भारत सरकार की रोकड़ में ६५ करोड़ रुपया था। इसने मुक़ाबले में १९५०-५१ के करों के आधार पर १९५१-५२ के राजस्व बजट में ५५५ करोड़ और पूँजीगत बजट में ७८ करोड़ का और इस प्रकार कुल ८३५ करोड़ का घाटा आता था। अगर नये कर और श्रृंखला का विचार छोड़ दें तो १९५१-५२ के अन्त में सरकार के पास १२ करोड़ से भी कम रोकड़ रह जाती जब कि कम से कम ५० करोड़ की रोकड़ भारत सरकार के पास रहना चाहिये।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पिछले वर्षों में और खास तौर से स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ा है। अब प्रश्न यह है कि इस स्थिति का सुधारने का क्या उपाय है। जहाँ तक आय को बढ़ाने का सम्बन्ध है अधिक गुणाईय नहीं मानी जा सकती। हमारी राष्ट्रीय आय का केन्द्र और राज्यों की कुल आय १०% के लगभग है। यद्यपि आधुनिक औद्योगिक राष्ट्रों में राष्ट्रीय आय का ३०% तक भाँ सरकार की आय में जाता है पर भारत की जैसी पिछड़ी हुई आर्थिक अवस्था में इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि राष्ट्रीय आय का आज से बहुत अधिक भाँ राज्यों की आय के रूप में ली जा सकती है। इस वाले भारत सरकार की आर्थिक स्थिति को ठाक करने के दो उपाय हैं। तत्काल का उपाय तो यह है कि अनावश्यक खर्च को हर तरह से कम करने का प्रयत्न किया जाय और विकास योजनाओं पर भी बचाव रखा हो खर्च किया जाय। दूसरी और बड़ी बात यह है कि देश की आर्थिक उन्नति के लिये योजना पूर्वक और दृढ़ता के साथ प्रयत्न किया जाये। देश की आर्थिक स्थिति ठाक होने पर सरकार की स्थिति अवश्य ही ठीक होगी। खर्च करने के अभाव में सामाजिक सेवाओं पर होने वाले खर्च को कम करने की प्रवृत्ति को

को अवश्य सथासंगव रोकने की आवश्यकता है।

अब हम राज्यों की सरकारों की वित्त व्यवस्था के बारे में विचार करेंगे। जहाँ तक राज्यों की सरकारों की वित्त नीति का सवाल है इतना ही लिख देना पर्याप्त होगा कि १९३७ के सुधारों के बाद से उन्होंने राष्ट्र-निर्माण के कामों पर अधिक व्यय करना आरम्भ किया है और इस बढ़े हुए खर्च को उन्होंने अपनी आय बढ़ा कर, भारत सरकार से कर्ज लेकर और मुद्रा वातार में ऋण लेकर पूरा करने की कोशिश की है। युद्ध के समय में राज्य की सरकारों के बजट घाटे के बजट नहीं रहे। १९१८-३६ में तत्कालीन प्रान्तों की कुल आय ८४'७४ करोड़ रुपये थी। वह युद्धकालीन वर्षों में बढ़ते बढ़ते १९४५-४६ में २२६'३३ करोड़ २० तक पहुँच गई। इसके बाद भी वृद्धि जारी रही। १९५१-५२ के बजट में कुल आय ३०८'८१ करोड़ रुपये की आंकी गई है और १९५०-५१ के संशोधित अनुमान के अनुसार २६६'५८ करोड़ की कुल आय होगी। १९५०-५१ में सब 'बी' राज्यों की आय ६०'३३ करोड़ की अनुमानित की गई है। प्रान्तों की यह आय वृद्धि विभिन्न कारणों से आमद बढ़ने के कारण ही हुई। नये करों का कोई बोझ जनता पर नहीं डाला गया। अहाँ तक राज्यों के व्यय का सम्बन्ध है उस में भी १९१८-३६ में ८५'७६ करोड़ से बढ़ते बढ़ते १९४५-४६ में २१८'१४ करोड़ तक वृद्धि होगई। याव में भी यह वृद्धि जारी रही। १९५०-५१ के सब 'ए' राज्यों की आय का संशोधित अनुमान ३०१'६६ करोड़ का और १९५१-५२ का ३११'६१ करोड़ का अनुमान है। 'बी' राज्यों का १९५०-५१ का खर्च का बजट ६०'८३ करोड़ था। आय-व्यय दोनों को मिलाकर देखने से मालूम होगा कि १९४६-५० तक 'ए' राज्यों के बजटों में घाटा नहीं रहा। पर १९५०-५१ और १९५१-५२ में 'ए' राज्यों की आर्थिक स्थिति में थोड़ी गिरावट आई। राजस्व और पूंजीगत दोनों प्रकार के आय-व्यय के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो 'ए' राज्यों के बारे में यह नतीजा आता है कि विभिन्न ऋणों से असल आमद १९५०-५१ में ६४'७० करोड़ और १९५१-५२ में ८५'४७ करोड़ होती है और डिपोजिट और अन्य मदों के लेन-देन का विचार कर लेने पर राजस्व और पूंजीगत दोनों ही का कुल मिला-जुला घाटा १९५०-५१ में ३६'१ करोड़ और १९५१-५२ में ६६'२७ करोड़ का आता है। १९४६-५० में इसके मुकाबले में ३'२१ करोड़ की-वचत थी। १९५१-५२ में ६६'२७ करोड़ के घाटा का ब्यौरा इस प्रकार है—राजस्व भाग में घाटा ११'६६ करोड़ और पूंजीगत खर्च और ऋण की मदों में घाटा ५४'२८ करोड़ का। इस घाटे का छसर यह हुआ है कि १७'४१ करोड़ की कमी तो सकुद रोकड़ में, २६'३६ करोड़ की कमी

नकद रोकड़ विनियोग लागे (केश बैंक इन्वेस्टमेंट अकाउंट) में आरणा और ७५० करोड़ की उत्तर प्रदेश सरकार जमींदारी उन्मूलन बोर्ड से इवातगी लेने और १५ करोड़ रुपया मद्रास सरकार अपने राजस्व रक्षित बोर्ड से और तिरुवेली। इसी प्रकार १९५०-५१ के घाटे का भी अंश रह गया है। १९५१-५२ में राजस्व बजट के बाहर का पूजागत गुर्व १९५०-५१ का अपेक्षा कहीं अधिक आया गया है। १९४६-५० में ५२६० करोड़, १९४७-४९ में ६८८८ करोड़ और १९५१-५२ में १०९६० करोड़ का यह गुर्व आया गया है। १९५०-५१ में 'बी' राज्यों के पूजागत राज्यों में भी १८३६ करोड़ का घाटा था। पर' तुल्य मिलकर 'बी' राज्यों के पास अपने पूजागत राज्यों के लिये अब तरु की जगा हुई रोकड़ और प्रभु भूतियों के रूप में यथेष्ट साधन हैं। मार्च १९५० के अन्त में उनसे इन्वेस्टमेंट १९४६७ करोड़ रुपये के थे। 'ए' राज्यों के बारे में जैसा ऊपर बताया गया है वत दो बरों में राज्यों की नकद रोकड़ में कमी आइ है, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, और कहीं-कहीं निश्चिन कामों के लिये निर्मित कोषों से रुपया भी लिया गया है। मार्च १९४८ के अन्त में राज्यों की नकद रोकड़ और नकद रोकड़ का विनियोग १७४ करोड़ था। पुरानी देशी रिपायर्स के कुछ राज्यों में मिलने से यह रोकड़ बढ़ा जा होगी। फिर भी ऐसा अनुमान है कि १९५१ के मार्च के अन्त तक यह रोकड़ की रक्कम ८० करोड़ हो रह जायगी। उपरोक्त स्थिति को सुधारने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि राज्य की सरकारें अपने गुर्व को अपनी क्षमता की मर्यादा में रखने का पूरा पूरा प्रयत्न करें। तभी पिछले दो बरों में राज्यों की आर्थिक स्थिति में जो विगाड़ आया है उस में सुधार होना सम्भव होगा।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि इन समय भारत सरकार और राज्यों की सरकारों की आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

भारत सरकार और राज्यों की वित्त व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उसकी क्या व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में पहला बात तो यह है कि यद्यपि पिछले बरों में प्रत्यक्ष करों का मात्रा और-उनका अनुपात बढ़ा है पर फिर भी अभी उनका अनुपात जितना चाहिये उतना नहीं है। केन्द्र और राज्य दोनों को मिलाकर आज भी उनका भाग ६०% के लगभग है। भारत का कर-व्यवस्था का बोझ सम्पूर्ण लोगों पर कम और मध्यम और निम्न वर्गों पर अधिक है। पिछले सालों में भारत सरकार ने जो कई उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क में वृद्धि की है या नए शुल्क लगाये हैं उनका भी यही अंश रहा है। पिछले बरों में मध्यम वर्ग पर एक ओर तो करों का बोझ बढ़ा है और दूसरी ओर महंगाई का बुरा प्रभाव भी उहीं पर सब से

अधिक पड़ा है। इस दृष्टि से हमारी कर-व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। राज्यों में भी विक्रय-कर का बोझ आम लोगों पर ज्यादा पड़ा है। नये करों में उत्तराधिकार-कर लगाने की आवश्यकता और औचित्य स्पष्ट है। इसी प्रकार राज्यों में कृषि-आयकर सब जगह लगना चाहिये। विक्रय-कर को सरल और सब राज्यों में समान बनाना चाहिये। इसी प्रकार खर्च में राज्यों में भी अनावश्यक व्यय और सामान्य शासन के व्यय में फिक्कायत करने की जरूरत है। इसी सम्बन्ध में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के खर्च का आपस में ठीक समन्वय हो। आज तो राज्यों को यह शिकायत है कि केन्द्र उनको पूरे साधन नहीं देता और स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं को इसी प्रकार की शिकायत राज्यों से है। इस स्थिति में सुधार आवश्यक है।

स्थानीय वित्त

अब तक हमने केन्द्रीय सरकार और राज्यों की वित्त व्यवस्था के बारे में विचार किया है। पर देश की वित्त व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग स्थानीय वित्त का है—अर्थात् नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों आदि की वित्त व्यवस्था का। अब हम इसी पर विचार करेंगे।

नगरपालिका वित्त : नगरपालिकाओं को दो प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं—(१) अनिवार्य और (२) वैकल्पिक। अनिवार्य कार्यों के अन्तर्गत सफाई, लोक स्वास्थ्य, रोशनी, सबक, पानी, शिक्षा—प्रारम्भिक और सेकेंडरी—की व्यवस्था आती है। वैकल्पिक कार्यों में पुस्तकालय, म्यूजियम, पब्लिक पार्क, खेल-कूद के मैदान आदि का व्यवस्था आती है।

नगरपालिका को उपरोक्त कार्यों के लिये व्यय करना होता है। उसके लिये उनको आम के साधन चाहिये। प्रत्येक राज्य में एक नगरपालिका एकट होता है जिसमें नगरपालिका को कौन कौन से कर लगाने का अधिकार है यह भी निर्दिष्ट रहता है। आधारभूततया नगरपालिकाओं द्वारा लगाये जाने वाले करों की सूची इस प्रकार होगी :—

(१) प्रत्यक्ष कर—इस श्रेणी में मकानों, जमीन या संपत्ति पर कर, पेशे और व्यापार आदि पर कर, व्यक्तियों पर हेतियत-कर, रोशनी, अग्नि, और शौचालय कर तथा दूसरे-कई छोटे छोटे कर जैसे संपत्ति के हस्तांतरण पर कर, वाहान-कर, कुत्तों और नौकरों पर कर, नावों पर कर, सवारी के साधनों और गालियों पर कर आते हैं।

मकान या संपत्ति-कर प्रायः सब नगरपालिकाओं लगाती हैं। मकान या

ज़मीन के वार्षिक मूल्य पर यह कर लगता है। वार्षिक मूल्य वार्षिक किराये की आय में बराबर माना जाता है। कर की दर लगभग ७½% वार्षिक किराये पर होती है। सार्वजनिक उपयोग की इमारतों पर कर नहीं लगता। कर संपत्ति के मालिक से वसूल किया जाता है।

पेशे और व्यापार पर जो कर लगाया जाता है वह इस प्रकार लगता है कि विभिन्न पेशे और व्यापारों की आय की समानता के आधार पर कुछ श्रेणियों में बांट दिया जाता है। फिर अलग-अलग श्रेणी के लोगों की अलग-अलग लाइसेंस वीस देनी होती है।

हेतियत-कर व्यक्ति की स्थिति और संपत्ति को देख कर लगाया जाता है।

रोशनी, अग्नि, सौचालय-कर सेवा के आधार पर लगाए जाते हैं। मकान के वार्षिक मूल्य की ही इस प्रकार की सेवा से मिलने वाले लाभ का आधार मान लिया जाता है।

संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर तय होता है।

बाजार-कर चीजों की बिक्री पर कर होता है। जब से बिक्री-कर राज्य की सरकारों द्वारा लगाया जाने लगा है नगरपालिकाएँ ये कर नहीं लगा सकती हैं।

नौकरों पर कर तो बहुत कम जगह है। पर कुँचों पर और दूसरे पालतू जानवरों पर कर अक्षय्य है। नानों पर कर उत्तर प्रदेश में लगता है। सवारी गाड़ियों पर कर लाइसेंस वीस के रूप में नामे, मोटर, बैचगाड़ी, रिकशा और साइकलों आदि पर लिया जाता है।

(८) अप्रत्यक्ष कर—इस श्रेणी में चु गो सबसे महत्वपूर्ण कर है जो नगरपालिका की हद में बाहर से माल आने पर लगता है। यह कर सड़ियों पर पड़ता है और इसलिए इसका बराबर कड़ा विरोध रहा है। इसको बण्ड करने में बहुत रुचि होता है। दूसरा कर सीमा-कर (टर्मिनल टेक्स) है जो रेल विभाग के ज़रिये नगरपालिका की हद में उपयोग के पदार्थों पर वसूल किया जाता है। चु गो का स्थान इस कर को कई नगरपालिकाओं ने दिया पर यह प्रवृत्ति ज्यादा चली नहीं। सीमा-कर सुविधाजनक है—वसूल करने वाले और देने वाले दोनों के लिये। इसे वसूल करने का व्यय भी कम होता है। इसलिये चु गो से यह हर तरह से अच्छा है। इसकी दर भी कम होती है। सीमा-कर के साथ साथ सड़क या 'बल मार्ग' से आने वाले माल पर 'टर्मिनल टॉल' भी लगाना आवश्यक होता है।

(३) व्यापारिक कार्यों से आय—नगरपालिकाओं की आय का एक साधन वे व्यापारिक कार्य हैं जो वह करती है—जैसे, पानी की व्यवस्था करने पर पानी की रेट से होने वाली आय, बिजली की व्यवस्था करने पर उससे होने वाली आय, नगरपालिका द्वारा बनाए हुए कसाईखानों के किराये से होने वाली आय, और नगरपालिका द्वारा की गई बातायात की व्यवस्था से होने वाली आय इस श्रेणी में आती है। आय के इन साधनों को बढ़ाना चाहिये।

ज़िला बोर्डों की वित्त व्यवस्था : ज़िला बोर्डों का मुख्य काम शिक्षा, सड़क, अस्पताल, सफाई, आदि होता है। इसके अलावा वे और भी कई काम करते हैं जैसे मेलों और प्रदर्शिनियों का आयोजन, टीका लगाने की व्यवस्था, आदि। ज़िला बोर्डों की आय के मुख्य मुख्य साधन इस प्रकार हैं :—

(१) भूमि उपकर—ज़िला बोर्डों की कुल कर से होनेवाली आय का ७० से ६० प्रतिशत भाग इससे होता है। लगान के साथ यह उपकर वसूल किया जाता है। इस कर को लगाने का आधार कहीं तो लगान होता है—जैसे मद्रास, बम्बई, आसाम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में है—और कहीं इसका आधार भूमि का वार्षिक मूल्य होता है। कहीं ज़मींदार को दिया जानेवाला 'रेन्ट' भी इसका आधार होता है—जैसे मद्रास के ज़मींदारी क्षेत्र में। खेती की प्रति एकड़ भूमि के आधार पर भी यह कर वसूल किया जाता है। लगान के सब दोष इस कर में भी मौजूद हैं।

(२) स्थिति और संपत्ति पर कर—यह एक प्रकार का हैसियत-कर है। १९१५ के बाद से किसी नए ज़िला बोर्ड को यह कर लगाने की स्वीकृति नहीं है क्योंकि यह कर व्यापक जैसा है। यह कर व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है पर कृषि-आय इससे मुक्त रहती है।

(३) टोल—सार्वजनिक नावों के उपयोग पर टोल वसूल किया जाता है और कभी-कभी यह कर वसूल करने का अधिकार नीलाम भी कर दिया जाता है। नीलाम करने की प्रथा अनुचित है और बन्द की जाना चाहिये।

(४) जुर्माना किराया और फ़ीस—इन तीनों प्रकार के साधनों से भी ज़िला बोर्डों को आय होती है।

(५) अनुदान—राज्य की सरकारों से ज़िला बोर्डों को काफी सहायता भी मिलती है। इससे राज्य की सरकारों का इन पर नियंत्रण भी रहता है। कभी-कभी यह नियंत्रण और हस्तक्षेप अनुचित सीमा तक भी पहुँच जाता है।

स्थानीय वित्त में सुधार की आवश्यकता : स्थानीय वित्त की सबसे बड़ी

समस्या यह है कि इन सस्थाओं के साधन बहुत सीमित हैं। इन साधनों में वृद्धि होना आवश्यक है। भारतीय कर जान समित ने १९२४ में इस सम्बन्ध में ये सुझाव दिये थे —

(१) लगान की दर कम की जाय ताकि स्थानाय सस्थाओं के लिये अधिक गुंजाइश रहे सके। (२) ग्राम्य वा सरकारों की भूमि किराया (पाउण्ड रेंट) और कृषि के काम में नहीं आनेवाली भूमि की दर में वृद्धि होने से जो आय हो उसका एक भाग स्थानीय सस्थाओं को दिया जाये। (३) नगरपालिकाओं को विज्ञापन पर कर लगाने का अधिकार दिया जाये। (४) मनोरंजन और पण्य (विटिंग) पर लगनेवाले करों में स्थानीय सस्थाओं को हिस्सा दिया जाये। (५) संपत्ति और वृत्ति करों का समझौता सुधार किया जाये। (६) मोटरों के आय कर को कम करके ग्राम्य की सरकारों को पथ-कर (टोल) के स्थान पर राज्य भर में कर लगाने दिया जाये और उसका आय स्थानीय सस्थाओं को बांटी जाय। (७) स्थानीय सस्थाओं को विवाहों की रजिस्ट्रार करने पर कहीं-कहीं कर लगाने दिया जाये। (८) ग्रामीय सरकारों से सहायता दी जाय। १९४० की धम्माई का स्थानीय स्वराज्य जाच समिति ने इन सुझावों का समर्थन किया था। उत्तर प्रदेश की स्थानीय स्वराज्य जाच समिति ने भी इनका समर्थन किया था और सुझाव भी दिये थे—जैसे (i) महापनों पर कर लगाया जाय, (ii) ग्रामीय कोर्टों कीस में स्थानीय स्वराज्य सस्थाओं को हिस्सा दिया जाये, (iii) स्टैम्प ड्यूटी पर अभिमार (सरचार्ज) लगा कर स्थानीय स्वराज्य सस्थाओं को दिया जाये। ग्राम पंचायतों के बारे में भी इस समिति ने कुछ सिफारिशों की थी, (i) लगान का पांच प्रतिशत पंचायतों को दिया जाये, (ii) भूमि उपकर का २५% ज़िला बोर्ड पंचायतों को दे दे, (iii) जो टिनट है उनसे 'रेट' का ५% लिया जाय। स्थानीय सस्थाएँ कुछ और कर भी लगा सकती हैं जैसे घरातों पर कर, जब वे सार्वजनिक रास्तों पर चलें, दीवार पर निय आने वाले विज्ञापन पर कर, सड़क उपकर आदि। मोटर गाड़ियों और पेट्रोल पर जो कर राज्य की सरकारें लगाती हैं उनका कुछ भाग भी स्थानीय स्वराज्य सस्थाओं को दिया जा सकता है। इसी प्रकार नगरपालिकाएँ सगरी गाड़ियों—जैसे कार, लोरी आदि—पर जो कर लगानी हैं उनका एक हिस्सा ज़िला बोर्डों आदि को दिया जाये क्योंकि ये गाड़ियाँ उनकी सड़कों का भी उपयोग करती हैं।

राज्य की सरकारों का स्थानीय स्वराज्य सस्थाओं को अनुदान समानता के आधार पर देना चाहिये, और अनुदान के अलावा स्थानीय सस्थाओं को व्यापारिक कामों से जैसे पानी, बिजली, आदि की व्यवस्था करने भी अपनी

आय बढ़ाना चाहिए। सिनेमा घर, बाज़ार, सभा भवन आदि बनाकर भी आय में कुछ वृद्धि की जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होगा कि स्थानीय वित्त की अपर्याप्त साधन उनकी समस्या को हल करना कितना आवश्यक है और उसको हल करने के लिये चारों ओर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इस व्यापक प्रयत्न के बिना समस्या का हल होना संभव नहीं होगा।

भारत सरकार का राजस्व और व्यय का बजट

राजस्व
लाल कपड़ों में

	१९५०-५१ बजट	१९५०-५१ संशोधित	१९५१-५२ बजट
सीमा-शुल्क	१,०६,५४	१,४५,३१	१४,१,२६ ८,७५*
संघीय उत्पादन-शुल्क	७१,५०	६६,६८	७१,६३ १३,१५*
निगम-कर	३८,१०	३८,६२	३०,४८ २,२५*
आयकर - [निगम-कर को छोड़कर]	१,२८,६८	१,२७,८८	१,२६,५७ ६,००*
अफीम	१,४५	३,००	२,३५
ख़द	१,१४	१,७६	१,६७
नागरिक शासन	७,८७	१०,४६	८,४२
मुद्रा और टंकन	६,५२	१२,८७	१२,३२
सार्वजनिक निर्माण	१,२७	१,४६	१,५२
विभाजन-पूर्व प्राप्तिपां
राजस्व के अन्य साधन	६,७६	१३,६६	११,६१ १,००*
बाक और तार :-			
असल अंश दान	४,०४	३,०७	२,००
रेल :-			
असल अंशदान	६,३७	६,७६	७,२६
राज्य को दिया जाना वाला आयकर का भाग—कम	—४७,७८	—४७,६८	—४७,५३
कुल	३,३८,५६	३,८७,२१	३,६६,८६ ३१,१५*

* १९५१-५२ के बजट का अंतर

	व्यय लास व्ययों में		
	१९५०-५१ बजट	१९५०-५१ संशोधित	१९५१-५२ बजट
राजस्व पर प्रत्यक्ष माध	१३,८१	१३,३४	१४,५८
सिंचाई	२३	२०	२७
अणु सम्बन्धी	३६,५०	३६,४६	३५,३२
नागरिक शासन	५०,०६	५०,७५	५६,०२
मुद्रा और टक्कन	१,७६	२,६५	०,६६
सार्वजनिक निर्माण	६,६७	१०,८८	१३,३८
पेन्शन	७,४५	७,१८	७,३५
अन्य			
विस्थापितों पर व्यय	६,००	१३,६७	६,८६
साधारण पर सहायता	२१,००	३५,०७	३५,३७
अन्य व्यय	४,०४	५,६६	—५०
राष्ट्रों के अनुदान	१५,४१	१५,७०	१५,४३
विशेष मद	१,४५	१,५७	१०,६७
रक्षा (असल)	१६८,०१	१७६,५७	१८०,०२
विमानन-पूर्व अदायगी	०,००	४,६४	२,७५
कुल व्यय	३३७,८८	३७६,०८	३७५,४३
वचन	१.३१	७.६३	०५.६१

उत्तर प्रदेश का वजट (१९४६-५०)

राजस्व की मद

१—राजस्व की मुख्य मदें

आयकर (निगम कर को छोड़कर)	६,३३ १५,०६०
संगान	६,७८,०४,५००
प्रान्तीय उत्पादन शुल्क	५,६०,३५,१००
मुद्राक-शुल्क	२,३०,००,०००
जगनात	०,०१,५५,५००
रिस्ट्रेशन	—०,००,०००
मोटर विकल्प एकट से प्राप्ति	३६,०६,२००
अन्य कर और शुल्क	१०,३१,८८,०००

२—सिंचाई	२,३६,८२,३००
३—अणु सर्वधी	२८,३१,२००
४—नागरिक शासन	३६,३६,७००
न्याय	११,६१,८००
जेल और कनविकट सेटलमेंट	५३,४७,५००
पुलिस	३०,६०,८००
शिक्षा	१५,६६,६००
विक्रिया	१०,३१,६००
सार्वजनिक स्वास्थ्य	१,२२,०१,३००
कृषि	४,६००
ग्राम सुधार	८६,३५,२००
पशु चिकित्सा	२,२०,७००
सहकारिता	५४,७६,२००
उद्योग
वायु यात्रा	२,५४,१०,३००
अन्य विभाग	
५—सार्वजनिक निर्माण	४०,१६,३००
६—विजली योजनाएं	१२,६४,६००
७—अन्य	२,३१,६८,५००
८—केन्द्र और राज्य के बीच में अंशदान तथा अन्य एडजस्टमेंट	१५,०००
९—विशेष मदें	६,०४,५६,६००
कुल राजस्व	५५,७३,४४,१००
१०—अणु जमा और रेमिटेन्स की मदें	२६,००,००,०००
सार्वजनिक अणु	७५,४०,०००
अनफन्डेड डेट	२६,५३,८२,६००
जमा और हवालगी	२,००,४१,०००
अणु और हवालगी राज्य की सरकारों से	६६,७०,००,०००
रेमिटेन्सेज	
कुल अणु जमा आदि की मदें	१२७,६६,६३,६००
कुल प्राप्तियां	१८३,७३,०८,०००
११—प्रारंभिक रोकड़	२,०७,०५,६३३
महायोग	१८५,८०,१३,६३३

उत्तर प्रदेश का बजट (१९४६-५०)

व्यय की मदें

१—राजस्व पर प्रत्यक्ष भाग

आयकर	१,६२,५००
लगान	२,००,०१,६००
राज्यकीय उत्पादन शुल्क	८०,८८,५००
मुद्राक	५,३१,६००
जगलात	८३,७१,६००
रजिस्ट्रेशन	१३,५५,०००
मोटर विहकल एकट के कारण व्यय	३१,७०,८००
आयकर और शुल्क	७१,८८,४००

२—सिंचाई राजस्व ग्राता

२,१५,८२,४००

३—सिंचाई पूंजीगत खर्चा

६१,४६,३००

४—अणु संबंधी

८६,०५,६००

५—नागरिक प्रशासन

सामान्य प्रशासन	{ १,०८,८३,५००
न्याय	{ ३,५२,०८,१००
जल कनविकट सेटलमेंट	१,२३,६६,८००
पुलिस	१,००,६०,५००
विज्ञान सक्धी विभाग	६,८४,५१,५००
शिचा	६७,४००
स्वास्थ्य	६,६८,०४,६००
चिकित्सा	१,८८,८६,३००
कृषि	२,१६,०१,१००
ग्राम सुधार	८,०३,१०,२००
पशु चिकित्सा	२५,१८,०००
सहकारिता	१,३७,१४,८००
	२८,४४,५००

उद्योग	१,२३,६६,६००
हवाई यातायात	४,३४,१००
अन्य विभाग	१८,३३,६००
				२,४४,४८,१००
६-सार्वजनिक निर्माण	६,३०,६४,४००
७-विजली योजनाएँ	८,१४,०००
८-अन्य	४,३६,७६,८००
९-विशेष मद	१,६६,६३,८००
			कुल खर्च राजस्व से	४४,४८,११,६००
१०-राजस्व के बाहर पूंजीगत खर्च		१६,६२,४४,६००
११-श्रण, जमा और रेमिटेन्स मदें				
सार्वजनिक श्रण	१०,४३,७१,३००
अनफाटेड डेट	४६,६४,४००
जमा हवालगी	२३,७६,३२,६००
श्रण और हवालगी राज्य की सरकारों से	६,७४,६६,२००
रेमिटेन्सेज	६६,७०,००,०००
			कुल जमा और श्रण आदि की मदें	१११,३१,६८,४००
			कुल चुफारा	१८३,८२,३४,६००
१२-शेष रोकड़	१,६७,७७,७३३
			महायोग	१८४,८०,१३,६३३

मध्य प्रदेश का बजट (१९५०-५१)

राजस्व की मदें

१. राजस्व की मुख्य-मुख्य मदें

आयकर (निगम-कर को छोड़ कर)	२, ८१, १६,०००
लगान	३, ७१, ७६,०००
प्रान्तीय उत्पादन-शुल्क	२, २६, ६०,०००
जंगलात्	२, २४, २६,०००

मुद्रांक शुल्क	₹५,४१,०००
रजिस्ट्रेशन	₹६,००,०००
मोटर विहकलस एक्ट से प्राप्तियां	₹८,६१,०००
अन्य कर और शुल्क	₹२,४६,२६,०००

कुल ₹४,६७,८३,०००

२ सिंचाई

₹०,६७,०००

३ ग्रन्थ संबंधी

₹८,०६,१००

४ नागरिक प्रशासन

स्वाय	₹६,६६,०००
जेल और कनविक्ट सेटलमेंट्स	₹१,६२,०००
पुलिस	₹५,४१,०००
शिखा	₹५,३५,०००
चिकित्सा	₹३,५६,०००
सार्वजनिक स्वास्थ्य	₹२,४६,०००
कृषि	₹६,५४,०००
पशुचिकित्सा	₹३,८३,०००
सहायिता	₹१,२१,०००
उद्योग और रसद	₹३,७२,०००
अन्य विभाग	₹२,७१,०००

कुल ₹३,१७,०००

५—सार्वजनिक निर्माण

₹७,१६,०००

६—बिजली योजनायें

₹६,०००

७—अन्य

₹२,१४,०००

८—फेड और राज्य की सरकारों के बीच में निमित्त एडनस्टमेंट ₹७,०००

९—विशेष प्राप्तियां

₹१,७१,०००

१०—रेवेन्यू रिजर्व फण्ड से

₹२,७६,०००

कुल राजस्व ₹७,२७,६३,०००

११—ग्रन्थ, जमा, हवालगी, रेमिटेन्स आदि कुल जोड़ ₹८,३६,६६,०००

कुल राजस्व और प्राप्तियां ₹७,६७,६०,०००

१२—प्रारम्भिक रोकट

₹३,६५,४१,०००

सहायोग ₹१,६३,०३,०००

मध्य प्रदेश का बजट (१९५०-५१)

व्यय की भेद

१-राजस्व पर प्रत्यक्ष मांग

लगान	****	****	****	६६,६०,०००
राजकीय उत्पादन शुल्क	****	****	****	१५,४४,०००
मुद्रांक शुल्क	****	****	****	२,८०,०००
जंगलात्	****	****	****	६३,४३,०००
रजिस्ट्रेशन	****	****	****	३,८६,०००
मोटर व्हिकल्स एक्ट के कारण व्यय	****	****	****	२,६३,०००
अन्य कर और शुल्क	****	****	****	३,५७,०००

कुल १,८८,४३,०००

२-सिंचाई-राजस्व खाता

३-अणु सम्बन्धी	****	****	****	२४,४५,०००
----------------	------	------	------	-----------

४-नागरिक प्रशासन

सामान्य प्रशासन	****	****	****	१,४६,४७ ०००
न्याय	****	****	****	४०,७१,०००
जेल और कनविक्ट सेटलमेंट	****	****	****	१८,७२,०००
पुलिस	****	****	****	२,२८,२६,०००
वैज्ञानिक विभाग	****	****	****	१,६५,०००
शिक्षा	****	****	****	२,६६,१७,०००
चिकित्सा	****	****	****	५६,८०,०००
सांख्यिक स्वास्थ्य	****	****	****	२७,५८,०००
कृषि	****	****	****	७२,८२,०००
पशु-चिकित्सा	****	****	****	३१,६२,०००
सहकारिता	****	****	****	२८,७४,०००
व्योग और रसद	****	****	****	१०,५६,०००
हवाई यातायात	****	****	****	६५,०००
अन्य विभाग	****	****	****	३,३२,०००

कुल ६,४२,५७,०००

५—सार्वजनिक निर्माण	२,१३,८६,०००
६—विजली योजनाएँ	३०,६०,०००
७—अन्य	१,७६,८४,०००
	<hr/>
कुल व्यय	१६,१६,६५,०००
८—पूजोगत व्यय	०,०६,६०,०००
९—श्रम, जमा, हवालगी आदि	३६,३१,३१,०००
	<hr/>
कुल व्यय और चुकारा	५२,५४,१८,०००
१०—शेष रोकट	४,१७,८५,०००
	<hr/>
महायोग	६१,६३,०३,०००

बम्बई का धजट (१९५०-५१)

राजस्व की मदें

१—राजस्व की मुख्य मुख्य मदें	
आयकर (निगम कर को छोड़कर)	६,८४,०६,०००
लगान	६,०६,००,०००
प्रांतीय उत्पादन शुल्क	१,१३,०३,०००
मुद्राक शुल्क—	
जो न्याय सम्बन्धी नहीं है	३,१०,१७,०००
जो न्याय सम्बन्धी है	१,०८,००,०००
अगलास	३,१३,१३,०००
रजिस्ट्रेशन	३५,१५,०००
मोटर विहकलस एकट से प्राप्तिमा	१,५०,६०,०००
अन्य कर और शुल्क	१७,६६,०६,०००
	<hr/>
कुल	४४,१६,८०,०००
२—नागरिक प्रशासन	
न्याय	८३,६०,०००
जेल और कनविकट सेटलमेंट	१६,५६,०००
पुलिस	४७,२०,०००
पोस्ट और पाहलटेज	५,०००
हॉम डिस्ट्रिक्ट	२८,१०,०००

शिक्षा	६४,३३,०००
चिकित्सा	४६,३६,०००
सार्वजनिक स्वास्थ्य	४६,१२,०००
कृषि	२,०४,३३,०००
पशु-चिकित्सा	२,५८,०००
सहकारिता	१०,६६,०००
उद्योग	२४,०७,०००
अन्य विभाग	१,६०,१६,०००
कुल			७,१६,६६,०००
३—सार्वजनिक निर्माण	४१,१४,०००
४—सिंचाई, जल यातायात आदि (जिनके लिए पृथकी-लेखा रखा जाता है और जिनके लिए नहीं रखा जाता है)			४७,३६,०००
५—श्रृण सम्बन्धी	१,१०,७२,०००
६—अन्य	३७,८७,०००
७—केन्द्र और राज्य की सरकारों में एडजस्टमेंट्स	१४,०००
८—विशेष प्राप्तिर्थाँ	३,८८,३०,०००
९—नागरिक रक्षा	४,००,००,०००
महायोग			६१,३६,०६,०००
रेवेन्यू खाते में खर्च से अधिक राजस्व	१,६८,०००
१०—श्रृण, जमा और हवालगी आदि	१,६३,३१,८२,०००
कुल प्राप्तिर्थाँ			२,५४,७०,८८,०००
११—प्रारम्भिक रांकड़	—२४,२४,६१,०००
असल महायोग			२,२६,४६,६७,०००

बम्बई का बजट (१९५०-५१)

व्यय की मदे

१—राजस्व पर प्रत्यक्ष भाँगा	१,६०,६८,०००
लगाव	—८१,५०,०००
प्रान्तीय उत्पादन शुल्क	४,६३,०००
मुद्रांक शुल्क	

जगन्नाथ	१,२६,१६,०००
रजिस्ट्रेशन	१५,३७,०००
मोटर गिक्ल्स एक्ट के कारण व्यय	१,१२,३८,०००
अन्य कर और शुल्क	७०,६८,०००

कुल ५,७१,७०,०००

२—सिवाई-राजस्व स्रोत

१,४४,३२,०००

३—सागरिक प्रशासन

सामान्य प्रशासन	३,७२,८७,०००
न्याय	१,८४,१८,०००
जेल और फनक्विट सेटलमेंट	६८,६८,०००
पुलिस	८,८०,५२,०००
पोर्ट्स और पाइलटेंज	५,०००
हैल्थ	२८,१०,०००
वैज्ञानिक विभाग	५,४६,०००
शिक्षा	१२,१७,३६,०००
चिकित्सा	७,४०,१३,०००
सार्वजनिक स्वास्थ्य	२,८६,६६,०००
कृषि	२,७८,२६,०००
पर्यटन चिकित्सा	४८,३३,०००
सहकारिता	१,०७,८१,०००
उद्योग	५३,७४,०००
अन्य विभाग	३,३६,४८,०००

कुल ४०,१६,७६,०००

४—सार्वजनिक निर्माण

७,०६,६७,०००

५—धन्य

५,४६,७४,०००

६—अणु सम्बन्धी

१,२१,५७,०००

७—विशेष मदें

६२,०००

कुल स्वर्ध्व राजस्व से

६१,३७,०८,०००

८—पूर्वजागत व्यय

८,३६,४८,०००

९—अणु, जमा और हवालगो

१,६५,६१,१२,०००

कुल चुकारा

७,६५,३७,६७,०००

१०—रोप रोकड़

—३५,६१,७०,०००

महायोग

७,२९,४५,६७,०००

राजस्थान का बजट (१९५१-५२)

राजस्व और प्राप्तियाँ

१-राजस्व की मुख्य गद्दे

संघीय उत्पादन-शुल्क	६२,००,०००
आयकर (निगम-कर को छोड़कर)	४२,००,०००
लागान	४,०६,७२,०००
राज्य का उत्पादन-शुल्क	२,६८,४०,०००
मुद्रांक	४२,००,०००
जंगलराज	४०,६३,०००
रजिस्ट्रेशन	२,६०,०००
मोटर विहिकल्स एक्ट से प्राप्तियाँ	२३,५०,०००
अन्य कर और शुल्क (कस्टम सहित)	४,२१,४२,०००

कुल १३,४२,५७,०००

२-भिचाई, जल-यातायात आदि

१५,६३,०००

३-ग्राम सम्बन्धी

६६,५०,०००

४-नागरिक प्रशासन

न्याय	५,२५,०००
जेल और कनविक्ट सेटलमेंट	३,०५,०००
पुलिस	१,८१,०००
शिक्षा	५,००,०००
चिकित्सा	३,०८,०००
सार्वजनिक स्वास्थ्य	११,३६,०००
कृषि	२,१०,०००
ग्रामसुधार
पशु-चिकित्सा	३,२५,०००
सहकारिता	१०,०००
उद्योग और रसद	२१,०५,०००
हवाई यातायात
अन्य विभाग	६०,००,०००

कुल १,१६,०५,०००

५—सार्वजनिक निर्माण	- - -	६,१६,०००
६—विजली योजनाएँ	- - -	---
७—अन्य	- - -	७,१५,०००
८—विशेष मद	----	४८,११,०००
	कुल राजस्व	१६,०५,१७,०००
९—श्रृणु, जमा, इवालागी आदि	----	७८,३८,६३,०००
	कुल राजस्व और प्राप्तियाँ	४४,४४,१०,०००
१०—प्रारम्भिक रोकड़	----	१,०३,६०,०००
	महावीम	४६,०८,०० ०००

राजस्थान का बजट (१९५१-५२)

व्यय का लेखा

१—राज्य पर प्रत्यक्ष भाग

लगाव	६२,००,०००
राज्य का उत्पादन-शुल्क	३७,९५,०००
मुद्राक-शुल्क	१,७५,०००
जगलाव	२८,५०,०००
रक्षितक्षेत्र	१,७०,०००
मोटर विहिकल्स एक्ट के कारण व्यय	---
अन्य कर और शुल्क	६८,००,०००

कुल १,७६,००,०००

२—सिंचाई आदि का राजस्व राता

६५,००,०००

३—श्रृणु सम्पत्ती

७५,००,०००

४—नागरिक प्रशासन

सामान्य शासन

१,४५,१०,०००

न्याय

३३,००,०००

जेल और कनविक्ट सेटलमेंट

२८,००,०००

पुलिस

२,७०,००,०००

वैज्ञानिक विभाग

११,५०,०००

सार्वजनिक वित्त

५६५

शिक्षा	२,२७,००,०००
चिकित्सा	१,१५,००,०००
सार्वजनिक स्वास्थ्य	३८,००,०००
कृषि	२०,००,०००
ग्राम सुधार और समाज सेवा	७,५०,०००
पशु चिकित्सा	११,८३,०००
सहकारिता	६,००,०००
उद्योग और रसद	१८,००,०००
हवाई यातायात
अन्य विभाग	४५,००,०००
		कुल	६,७५,६३,०००
५—सार्वजनिक निर्माण आदि	१,१४,००,०००
६—विजली यो जनार्थ
७—अन्य	१,६१,००,०००
८—विशेष मदें	५०,००,०००
		कुल खर्च राजस्व से	१६,२०,१७,०००
		राजस्व से अधिक खर्च	१५,००,०००
९—पूँजीगत व्यय	२,३२,७३,०००
१०—ऋण, जमा और हवालगी	२७,५५,१०,०००
		कुल खर्च और चुकारा	४५,५३,६८,०००
११—शेष रोकल	५४,३२,०००
		महायोग	४६,०८,००,०००

परिच्छेद १७

मूल आर्थिक समस्या—महंगाई और उत्पादन वृद्धि

देश के आर्थिक जीवन के क्षेत्रों का हमने अब तक विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। इस अध्ययन का एक ही परिणाम है और वह यह कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति आज अत्यन्त बुरा है। देश में पैली हुई निर्धनता और बेकारी अथवा अर्द्ध बेकारी इसका जाविब प्रमाण है। हमारा बढ़ती हुई महंगाई और अक्षमता अनेक उत्पादन की स्थिति इसका स्पष्ट लक्षण है। देश में आर्थिक जीवन की आज तो मूल समस्या एक ही है और वह यह कि किस प्रकार यह भयंकर महंगाई समाप्त हो और उत्पादन में वृद्धि हो। इस परिच्छेद में हम महंगाई के प्रश्न पर थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे।

द्वितीय महायुद्ध और महंगाई दूसरे महायुद्ध के समय में यह महंगाई आरम्भ हुई थी। सवाल यह है कि इस महंगाई का कारण क्या हुआ? महंगाई का अध है रुपये का मूल्य घट जाना और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाना। हमारे समझने का विषय यह है कि रुपये का मूल्य तो क्यों घटा और वस्तुओं का मूल्य क्यों बढ़ा? अर्थशास्त्र का सामान्य सिद्धान्त है कि जब किसी चीज़ की मांग बढ़ जाती है पर उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उस चीज़ का मूल्य बढ़ जाता है। अगर एक और मात्रा बढ़ जाय और दूसरा और माग कम हो जाये तब तो कहना ही क्या? फिर तो उस चीज़ का मूल्य अत्यधिक घट जायगा। द्वितीय महायुद्ध के समय में हमारे देश में रुपये की यही स्थिति हुई। रुपये का माना में तो वृद्धि हो गई और उसका माग में कमी हो गई। इसने पहले कि हम अपनी इस बात का प्रमाण दें रुपये की माग में कमी होने का अर्थ क्या है यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है और रुपये की पूर्ति या मात्रा कैसे तय होती है यह भी जान लेना है। पहले रुपये का मात्रा की ही लें। किसी भी देश की रुपये का मात्रा उस देश की कुल मुद्रा और बैंकों का चालू जमा तथा उसने प्रचलन की गति से निर्दिष्ट होती है। जहां तक रुपये की मात्रा का संबंध है यह इस बात से निर्दिष्ट होता है कि देश में मध्य विक्रय की मात्रा कितना है क्योंकि रुपये का काम मध्य विक्रय के लिये उपयोग में आना ही है। जब देश में उत्पादन अधिक होता है और व्यापार-व्यवसाय में तेज़ा होती है तो रुपये के लिये काम अधिक होता है और जब उत्पादन कम होता है और व्यापार-व्यवसाय में मंदी होती है तो रुपये के लिये काम कम होता है। रुपये की मात्रा और माग के बारे में इतना स्पष्टीकरण कर देने के बाद हम यह देखेंगे कि द्वितीय महायुद्ध के समय हमारे

देश में रुपये की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई । और फिर रुपये की मांग के बारे में भी विचार करेंगे । द्वितीय महायुद्ध के समय देश में रुपये का कितना प्रसार हुआ यह नीचे दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट हो सकेगा ।

वर्ष (अप्रैल से मार्च)	कुल मुद्रा (करेंसी) प्रचलन में	जमा मुद्रा प्रचलन में	कुल मुद्रा प्रचलन में	इनडेक्स नम्बर
	(करोड़ रुपयों में)			

अन्तिम शुक्रवार

१९३६-४०	३३६	१४५	४८४	११६.३
१९४०-४१	३५५	१७६	५३१	१२७.६
१९४१-४२	४६२	२३४	७२६	१७४.५
१९४२-४३	७५०	३६१	१,११४	२७७.१
१९४३-४४	६६१	५५६	१,५५०	३७२.६
१९४४-४५	११६७	६४८	१,८४५	४४३.५

आधार वर्ष १९३८-१९३९ = १००

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि द्वितीय महायुद्ध के समय हमारे देश में कुल रुपये या मुद्रा की मात्रा में काफ़ी [चार गुना] विस्तार हुआ । अपने आपसे भी इस विस्तार का असर रुपये का मूल्य गिरना या चीजों का महंगा होना ही होता । पर रुपये की मांग की दृष्टि से भी अगर विचार किया जाये तो इससे भिन्न कोई परिणाम नहीं आसकता था । इन वर्षों में देश के औद्योगिक आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि अगस्त, १९३६ को १०० मान कर यदि चेला जाये तो १९३६-४० में ११०.३, १९४०-४१ में ११४.२, १९४१-४२ में १२३.२, १९४२-४३ में १२५.५, १९४३-४४ में १२६.८ और १९४४-४५ में १२९.७ औद्योगिक उत्पादन का इनडेक्स था । कृषि उत्पादन का इनडेक्स १९३६-३७ से १९३८-३९ के औसत को १०० मानने पर १९३९-४० में ६६, १९४०-४१ में ६८, १९४१-४२ में ६५, १९४२-४३ में १०२ और १९४३-४४ में १०६ और १९४४-४५ में १०१ था । इसका अर्थ यह है कि १९४३-४४ के बाद से तो हमारा औद्योगिक उत्पादन गिरना आरंभ हो गया पर १९४३-४४ में भी उसमें रुपये के विस्तार की अपेक्षा बहुत कम वृद्धि हुई थी । इसी प्रकार कृषि उत्पादन का हाल तो और भी असंतोष जनक रहा । १९४१-४२ तक तो इनडेक्स नम्बर १०० से कम रहा और अधिक से अधिक इनडेक्स १९४३-४४ में १०६ तक पहुँचा । जब औद्योगिक उत्पादन का अधिकतम इनडेक्स १२६.८ और कृषि का १०६ था तब रुपये के विस्तार का इनडेक्स ३७२.६ तक पहुँच गया और १९४४-४५ में तो

औद्योगिक उत्पादन का इन्डेक्स १२१७ और कृषि उत्पादन का १०१ ही रह गया पर रुपये के विस्तार का इन्डेक्स ४८३५ तक पहुँच गया। याराय यह है कि एक ओर तो रुपये का विस्तार हुआ, दूसरी ओर उत्पादन की मात्रा उसका अपेक्षा बहुत कम अनुपात में बढ़ी या फिर कम हो गई। इसका सिवाय इसके और नतीजा क्या हो सकता था कि देश में महंगाई बढ़ती जाता। इस सब में एक बात ध्यान में रखने की और है कि जहाँ तक जन साधारण व उपभोग के लिये वस्तुओं की उपलब्धि का प्रश्न था उसी मात्रा में मैनिफ़ आवश्यकता के बढ जाने से बहुत कम आ गई। इसका अंतर भी महंगाई की बढ़ावा हुआ। बाहर के देशों से आने वाले माल का आयात में माँकड़ कारणों से कुछ काल में बर्बाद हो गई था। चर्मा व शत्रुओं व अधिकार में चले जाने से वहाँ से आने वाले चावल का आना बन्द हो गया। इसी तरह ने दूसरे कारण भी उपस्थित हुए। मातापात का कठिनाई भी एक कारण था जिसने कारण महंगाई बढ़ने में मदद मिली। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों व कारण देखें। महंगाई बढ़ने लगी। पर इन परिस्थितियों का आधार रुपये का मात्रा का बढ़ना और उत्पादन का व बढ़ना वस्तु नागरिक उपभोग के लिये वस्तुओं की उपलब्धि मात्रा में उल्टी कमी आ जाना ही था। युद्ध काल में हमारे देश में महंगाई और रहन सहन का व्यय कितना बढ़ा इसका अनुमान नीचे की तालिका से लगाया जा सकता है —

वर्ष	योग मूल्य देशनाक आधार १६ अगस्त, १९३६ की समाप्त होने वाला		रहन सहन का व्यय देशनाक (बर्बर) आधार वर्ष	
	मताह=१००		अगस्त १९३६=१००	
१९३६ ४० (सितंबर माह)	१२३६		१०५	
१९४० ४९	११४८		१०६	
१९४१ १२	१३७०		१२२	
१९४२ १३	१७१०		१६६	
१९४३ १४	२३६५		२२६	
१९४४-४५	२७७०		२२५	

उपरोक्त आंकड़ों का सार यह है कि युद्ध के पहले जो कीमते थीं वे युद्ध समाप्त होने तक ढाई गुनी के लगभग बढ़ गईं। रहन सहन के व्यय में भी लगभग इसी अनुपात में वृद्धि हुई। हमारे देश की इस स्थिति का मुकाबला दुनिया के कुछ दूसरे देशों से करें तो मान्य होगा कि हमारी स्थिति बहुत खराब रही है। उदाहरण के लिये १९३७ को आधार मान कर देखने पर पता चलता है कि

अमेरिका में थोक माल की कीमतों का देशानांक १९४५ में १२३, यूनाइटेड किंगडम में १२५, कनाडा में १२२, और आस्ट्रेलिया में १२० ही थे। इसका अर्थ यह है कि युद्ध समाप्त होने तक जहाँ भारत में ठाई गुनी कीमतें बढ़ गईं, इन देशों में डेढ़ गुनी या उससे कम वृद्धि हुई।

युद्ध आरंभ होने के प्रथम कुछ वर्षों में तो भारत सरकार ने इस मंहगाई के प्रश्न की ओर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। १९४३ के उत्तरार्द्ध जब स्थिति बहुत बिगड़ गई तो भारत सरकार ने मूल्य नियंत्रण करना आरंभ किया। इस समय तक देश की खाद्य स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। दमा से चावल अनाज बन्द हो गया था। परिणामस्वरूप बंगाल में अत्यन्त भीषण अकाल पड़ा और लाखों मनुष्य काल के आस बन गये। भारत सरकार ने बढ़ती हुई मुद्रा स्थिति और मंहगाई को रोकने के लिये करों की वसूली जल्दी करना शुरू कर दिया (अतिरिक्त लाभ-कर साल भर की बत्ताय हर तीसरे महीने वसूल किया जाने लगा); रिज़र्व बैंक ने सोना बेचना आरंभ किया; कॉटन क्लॉथ एण्ड थर्न कन्ट्रोल आर्डर तथा होर्जिंग एण्ड; प्रीफेक्टियरिंग प्रीवेन्शन आर्डिनेन्स पास किये गये, और ग्रामीण जनता में छोटे पैमाने पर वचत करने के लिये प्रचार की व्यवस्था की गई; अणु लेने का सरकार ने कार्यक्रम बनाया; देश में उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा की गई; बाहर से अधिक माल और अन्न मंगाने का प्रयत्न किया गया और बड़े बड़े शहरों और कस्बों में अन्न, बल, शकर तथा दूसरे आवश्यक पदार्थों का राशनिंग जारी किया गया। सारांश यह है कि सरकार ने स्थिति को काबू में लाने के चहुँमुखी प्रयत्न करने शुरू किये। इन सबका नतीजा किसी हद तक आया। १९४३ के आखिरी महीनों में स्थिति थोड़ी काबू में आई। मंहगाई की गति धीमी पड़ी। तेजी से जो कीमतें बढ़ने लगी थीं उस स्थिति में थोड़े समय के लिये तुल्य आया। थोक मूल्य का देशानांक १९४२-४३ में १७१ से बढ़कर १९४३-४४ में जहाँ २३६.५ पर पहुँच गया था वहाँ १९४४-४५ में २४४.२ तक ही बढ़ा। इसी समय अगस्त, १९४५ में युद्ध समाप्त हो गया। अब इस युद्ध के बाद की स्थिति पर विचार करेंगे।

युद्ध के बाद की मंहगाई की स्थिति : जब युद्ध समाप्त हुआ तो लोगों के मन में यह स्वामानविक आशा थी कि युद्ध काल की मंहगाई का अन्त हो जायगा, नियंत्रण नहीं रहेगा और आर्थिक जीवन पूर्ववत् चलने लगेगा। पर जैसा कि आज देखा जा रहा है, यह सब कुछ हुआ नहीं। न मंहगाई में कमी आई और न नियंत्रण ही उठा। लोगों की आर्थिक दशा बराबर बिगड़ती जा रही है, मंहगाई बढ़ती जा रही है और हमारा आर्थिक जीवन एक प्रकार से

जर्जरित हो चुका है और बराबर होता जा रहा है। युद्ध के बाद मंहंगई कितनी बढ़ी इसका अनुमान नाचें दी गई तालिका से लग सकेगा —

१६ अगस्त, १९३६ में समाप्त होने वाला सप्ताह=१००

वर्ष

शोक मूल्य देशनाक

[अग्रेल मार्च]

१९४६-४७

२४४.६

१९४६-४७

२७५.४

१९४७-४८

२००.०

जनरल वरपन्थ सिरीज

अगस्त १९४६ में समाप्त वर्ष=१००

१९४७-४८

२०८.२

१९४८-४९

२७६.२

१९४९-५०

३८६.४

१७ जून १९५०

को समाप्त सप्ताह

३६४.०

१६ जून १९५२ को

समाप्त सप्ताह

४५८.२

अगस्त १९५१

४३७.६

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि मूल्यों में वृद्धि बराबर जारी है। प्रश्न यह है कि युद्ध समाप्त होने के बाद मूल्यों में यह वृद्धि क्यों जारी रही। नीचे हम उत्पादन और मुद्रा सम्बन्धा आम्ने देते हैं जिससे यह पता चलेगा कि युद्ध के बाद के वर्षों में देश के उत्पादन और मुद्रा सम्बन्धा स्थिति क्या रही।

कुल मुद्रा

करोड़ रुपयों में

उत्पादन के देशनाक

कृषि

उद्योग

१९४५-४६

२०८७३

६४

१००

१९४६-४७

२१०५

६६

१०५

१९४७-४८

२२२३

२००

१०५.६

१९४८-४९

२०७४

६४

११५.६

१९४९-५०

२१६७

६६

१०६.५

१९५०-५१

२३५३

—

१०८.०

अगस्त १९५१

२३८५

१९४१-५१

—

११०.१

मार्च १९५१

२३०१

उपरोक्त तालिका से दा बातें स्पष्ट होनी हैं। एत तो यह कि हालांकि १९४७-४८ तक मुद्रा की कुल मात्रा वृद्धि होना यह पर वृद्धि की मात्रा में कमी

आगई। १९४७-४८ और १९४८-१९४९ के बीच में तो कुल मुद्रा की मात्रा बिल्कुल बराबर ही रही। फिर उसके बाद १९४९-५० में तो मुद्रा की मात्रा कम होगई। हालांकि गतवर्ष फिर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई है। पर जहाँ तक मूल्यों का सम्बन्ध है वे बराबर बढ़ते ही जा रहे हैं। मूल्यों को यह वृद्धि मुद्रा की मात्रा में होने वाले विस्तार से स्पष्ट नहीं होती। १९४७-४८ और १९४८-४९ के बीच में यद्यपि मुद्रा की मात्रा लगभग वही रही पर मूल्य में ६८ पोइन्ट की वृद्धि होगई और १९४९-५० में मुद्रा की मात्रा कम होगई तब भी मूल्यों में ६२ पोइन्ट की वृद्धि हुई। प्रश्न यह है कि इसका कारण क्या? उत्पादन के आकड़ों से यह मालूम पड़ता है कि १९४४-४५ से कृषि में १०६ से देशनांक कम होकर १९४५-४६ में ६४ पर और १९४६-४७ में ६६ पर और १९४७-४८ में १०० पर और १९४८-४९ में ६४ पर रहा। इसी प्रकार से उद्योग का देशनांक १९४४-४५ से कम होते होते १९४६-४७ और १९४७-४८ में १०५ के आसपास तक आगया और १९४८-४९ में बढ़ कर १०५.६ पर पहुँच गया पर उसके बाद फिर कम होने लगा। सारांश यह है कि इन वर्षों में कृषि उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा १२ पोइन्ट का और उद्योग के उत्पादन में २२ पोइन्ट की कमी आई पर मूल्यों में उसके मुकाबले में १९४५-४६ से १९४९-५० के बीच में १४०.५ की वृद्धि होगई। दूसरे शब्दों में कृषि में उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा कमी जो किसी वर्ष में १९४३-४४ के मुकाबले में हुई वह ११% और उद्योग में १७% के लगभग हुई जबकि मूल्यों में ६३% से भी अधिक वृद्धि हुई। स्पष्ट है कि मूल्यों की वृद्धि उत्पादन में जो कमी हुई है उससे कहीं अधिक हुई है। इसका यह स्पष्ट कारण है कि मूल्यों की इस वृद्धि के लिये कोई न कोई मुद्रा सम्बन्धी कारण भी जिम्मेदार रहा है। यह मुद्रा सम्बन्धी कारण सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रति वर्ष बढ़ता हुआ खर्च है। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत सरकार के बजट बराबर घाटे के बजट रहे हैं और इससे देश में मंहगाई बढ़ने में बड़ी सहायता मिली। पिछले दो साल से अवश्य वृद्धि के बजट बने हैं पर उसमें भी अगर राजस्व और पूँजीगत दोनों बजटों के आमद और खर्च को मिलाकर देखें तो स्थिति संतोषजनक नहीं मालूम पड़ती। इधर पिछले दो वर्षों में राज्यों द्वारा बहुत व्यय हुआ है और राज्य की सरकारों की आर्थिक स्थिति विगड़ी है। सार यह है कि युद्ध के बाद जो मंहगाई हुई है उसमें सरकार के घाटे के वित्त का बहुत बड़ा हिस्सा है। इधर पिछले साल मर से अधिक हुआ कोरिया युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हुई है और उसका असर भारत पर भी पड़ा है। १९४९ में रुपये का अचमूयन किया गया। इसने भी मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया।

डालर की कमी के कारण आयात में भी कमी हो गई। हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बीच में वह महीनों तक व्यापार बंद रहा क्योंकि विनिमय दर का प्रश्न नहीं सुलभ रहा था। कपास और पदसन की दमस्त कमा आदि और इसका असर मूल्यों की बढ़ाने का हुआ। पाकिस्तान ने आखिर अपने रुपये के अवमूल्यन करके के निरन्तर को हा कायम रखा। इससे पाकिस्तान से आने वाले माल का भारत में महंगा पड़ने का असर हुआ। उपरोक्त मुख्य-मुख्य कारणों से युद्ध के बाद भा मूल्य बढ़ते ही रहे।

१९४८ में जब मूल्यों में बहुत तेजा आँच लगी भारत सरकार ने इस प्रश्न पर कुछ स्थान अधशास्त्रियों ने राय ली। उन्होंने जो महंगाई के कारण बताये थे उनमें उपरोक्त कारणों के अलावा युद्ध और फागुनों का भी उल्लेख था। वे कारण यह थे—(१) पाकिस्तान से आया विस्थापित आयें उन्होंने अपना पूँजी को रुपये में बदल लिया और इससे भी रुपये का माप बढ़ी। (२) विनिमय बैंक न भारत सरकार का प्रतिभूतियों के मूल्य को कायम रखने के लिये उनकी परीक्षा उससे रुपये की मात्रा बढ़ी। (३) खेर बाना में कमाये हुए और आयकर का बोरी करने वाले रुपये का असर भा मूल्य बढ़ाने का ही हुआ। (४) वेतन और महंगाई की वृद्धि। (५) सरकार के अर्थ लेने और बचत को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम की अतत्फलता। (६) हमारे देश में निर्मित और बाहर से आने वाले दोनों प्रकार के माल की कमा। (७) सहा और मन्वय करने की वृद्धि। यह वृद्धि व्यापारियों या सट्टे करने वाला तक हा सीमित न रहकर सवसाधारण तक में युद्ध काल में फैल गई थी। (८) भारत सरकार की नियंत्रण नीति की अतत्फलता। वे ही वे सब कारण थे जिन्होंने युद्ध और युद्धोत्तर काल में महंगाई को जन्म दिया और उसे बढ़ने दिया।

महंगाई का रोकन क सरकार के प्रयत्न महंगाई को रोकने के भारत सरकार और राज्य की सरकारों ने बराबर प्रयत्न किये। नई मुद्रा की मात्रा में सरकार ने घाटे घाटे कमा का। वह प्रकार से कर भी बढ़ाये। बचत को प्रोत्साहन देने की योजनायें अमन में लाने का प्रयत्न किया गया। सट्टे पर प्रतिबंध लगाया गया। कपास में 'हिज कॉन्ट्रैक्ट' पर रोक लगा दी गई। गेहूँ आदि चीजों के आगे के लेन देन बंद कर दिये गये। सोना और चाँदी के आगे के लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कपाटल दरयू कंट्रोल आर्डर लागू किया गया। राशनिय और मूल्यों का नियंत्रण किया गया। वातायात के सम्बन्ध में सुधार करने की कोशिश हुई और अन्न आदि वस्तुओं को लाने सेजाने में प्राथमिकता दी गई। सरकार ने यह भी बराबर चाहा है कि देश

में उत्पादन बढ़े ! पर इन सब प्रयत्नों का कोई ग्रास असर नहीं हुआ और हमारी आर्थिक स्थिति दिनों दिन संकट के किनारे पहुंचती जा रही है ! प्राकृतिक और अन्तर्राष्ट्रीय कारकों का भी इस स्थिति को बिगाड़ने में हाथ रहा है । पर यदि हमारी आर्थिक नीति सही होती तो स्थिति आज जितनी नहीं बिगड़ती । प्रश्न यह है कि इस स्थिति को सुधारने का अब उपाय क्या है ?

उत्पादन वृद्धि और नई मुद्रा जारी नहीं करना—मुख्य उपाय : जिस स्थिति का हमने ऊपर उल्लेख किया है उसको सुधारने के आधारभूत उपाय दो ही हैं । एक तो यह है कि अब आगे घाटे के बजट बनाकर और नई मुद्रा जारी करके देश में मुद्रा का माप्रा को हरमिल न बढ़ाया जाये । आगे मुद्रा स्थिति को रोकने का बड़ी आवश्यकता है । इसके लिये जरूरत यह है कि सरकारें अपने अनिवार्य खर्चों को एकदम कम करें । नये खर्चों को समझ सोचकर उनका खरे राष्ट्र के जीवन पर पड़ने वाले असर को देखकर किया जाये । इसी के साथ-साथ आप को बढ़ाने का और ऋण लेने का भी हर प्रकार से प्रयत्न किया जाना चाहिये । बैंक-खाता पर इस प्रकार नियंत्रण किया जाना चाहिये कि जिससे सट्टे को प्रोत्साहन न मिले । मूल्य नियंत्रण और राशनिंग का जहां आवश्यकता हो वहां पूर्णकालीन होना चाहिये । पर ये उपाय तात्कालिक हैं । अन्ततोगत्वा हमें देश का उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा । और जब तक इसमें सफलता नहीं मिलेगी हमारा आर्थिक संकट दूर नहीं हो सकेगा ।

देश में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है । इस संबंध में सबकी एक ही राय है । इस विषय में भी आज कोई मतभेद नहीं है कि उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें एक न एक प्रकार की योजना के आधार पर चलना होगा । आज पूंजीपति भी यह नहीं कहते कि व्यक्तिगत व्यवसाय पर राज्य का हस्तक्षेप ही नियंत्रण नहीं होना चाहिये । मतभेद है तो इस प्रश्न पर कि देश की भावी आर्थिक योजना कैसी हो । भारत सरकार चाहते हुए भी अभी तक देश में उत्पादन को बढ़ाने में सफल नहीं हो सकी है । इसका मुख्य कारण है भारत सरकार की अस्पष्ट और अन्तर्विरोधी आर्थिक नीति और भारत सरकार और राज्य की सरकारों में समन्वय का अभाव । उदाहरण के तौर पर एक ओर राष्ट्रीयकरण की बात करना और दूसरी ओर दूसरे ही क्षण पूंजीपतियों से चाहना कि वे उत्पादन बढ़ाने का पूरा-पूरा प्रयत्न करें, सर्वथा परस्पर विरोधी बातें हैं । इस तरह के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं । पर इसकी आवश्यकता नहीं । वहाँ तो इतना ही लिख देना पर्याप्त है कि बिना किसी निश्चित आर्थिक योजना के आधार पर चले इस देश का आर्थिक विकास संभव नहीं हो सकता । अगले परिच्छेद में हम इसी विषय पर विचार करेंगे ।

परिच्छेद १५ आर्थिक योजना

आज सब विचारमान व्यक्ति इस बात से सहमत हैं कि पूँजीवाद अर्थ व्यवस्था सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के ध्वज की पूर्ति नहीं कर सकते। साथ में इस बात में भी कोई मतभेद नहीं है कि देश का आर्थिक जीवन पूर्णतया व्यक्तिगत व्यवसायियों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। जाद्विहीन दृष्टि में उनमें राज्य का हस्तक्षेप होना अनिवार्य है। पर इसमें आगे विचारों का समानता का अन्त हो जाता है। जब हम भावी अर्थ रचना के प्रश्न पर विचार करना आरम्भ करते हैं तो अनेकों प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं, और उन प्रश्नों का भिन्न भिन्न विचार के साथ करना अपनी दृष्टि से भिन्न निष्कर्ष देते हुए पाये जाते हैं। भारतवर्ष के सामने इस समय जो सबसे आचार्यपूर्ण प्रश्न है वह समाज की इस नई रचना में ही समाप्त रहता है। हम इस परिच्छेद में इसी समस्या पर विचार करेंगे।

हमारा जीवन दर्शन क्या है? समान रचना के प्रश्न पर विचार करना जब हम आरम्भ करते हैं तो सब से पहला सवाल जो हमारे सामने आता चाहिये यह है जीवन भरपी हमारे दर्शन का। वर्तमान पश्चिम की सम्प्रदाय ने हमारे सामने जिस जीवन दर्शन को उपस्थित किया है उसका आधार आध्यात्मिकताओं को बढ़ाने जाना और उनका नृति के लिए बराबर प्रयत्न करते रहना है। औद्योगिक पूँजीवाद के प्रसार और विनाश के लिए इस जीवन दर्शन को ही आवश्यकता थी। और इसलिये आप उसका सर्वत्र प्रचार भी हमें देखने के मिलता है। जिस जीवन दर्शन के हम पक्ष में हैं और जो भावी शोषण रहित और बग विहीन समान व अनुकूल हो सकता है उसने अनुसार आवश्यकताओं का जल अभिवृद्धि है हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। जिस समाज रचना के लिये लाभ कमाना नहीं बल्कि मनुष्य का आवश्यकता पूर्ति होगा, उस समाज रचना के अनुसार तो यहाँ जीवन दर्शन हो सकता है कि मनुष्य अपना सर्व उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी विकास करना समझे। ऐसा दृष्टा मनुष्य उहाँ आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहेगा जो उसने व्यक्ति के विकास में सहायक होगा। इसका अर्थ करने आप से मरल और मारे जीव को और सुख होना हो जाना है और आवश्यकताओं का अभिवृद्धि नहीं बल्कि उनको पूर्ण करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य बन जाता है। हम जिस नयी समान रचना की कल्पना करना चाहते हैं उसका आधार जीवन सर्व

वही दृष्टिकोण होना चाहिये ।

हमारा सामाजिक लक्ष्य—सुरक्षा, स्वतंत्रता और अवकाश : जीवन-दर्शन के बारे में विचार कर लेने के बाद दूसरा प्रश्न हमारे सामाजिक लक्ष्य का उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में हम किस प्रकार की समाज रचना को ठीक समझते हैं। यह हम पहले लिख चुके हैं कि मनुष्य का सच्चा उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। जो समाज रचना इस उद्देश्य को प्रति में कदापक हो वही हमारे विचार से सही समाज रचना समझी जानी चाहिये। इस दृष्टि से भावी समाज रचना में प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित तीन बातों की प्राप्ति होना आवश्यक है—(१) सुरक्षा (२) स्वतंत्रता (३) अवकाश।

‘सुरक्षा’ से हमारा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को आधुनिक सभ्य समाज के अनुरूप रहन-सहन का दर्जा प्राप्त होना चाहिये। इसके लिये यथेष्ट मात्रा में उत्पादन और न्याय पूर्ण वितरण की आवश्यकता होगी। ‘सुरक्षा’ से हमारा अर्थ आर्थिक सुरक्षा है। परन्तु मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिये आर्थिक सुरक्षा के अलावा राजनैतिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ‘स्वतंत्रता’ भी चाहिये। संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव होना चाहिये कि वह केवल किसी महान यंत्र अथवा व्यवस्था का एक पुर्ण अथवा अंश मात्र ही नहीं है, बल्कि अपने भाग्य का वह स्वयं निर्माता है, और जिस समाज व्यवस्था में वह रहता है उसका वह संचालक है। इनके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिये जो काम करना पड़ता है उसको करने के बाद उसके पास ‘अवकाश’ रहे जिसका उपयोग वह जीवन की उच्चतर प्रवृत्तियों, जैसे कला, साहित्य आदि के लिये कर सके। सारांश यह है कि मनुष्य के ‘व्यक्तित्व’ के विकास की दृष्टि से उसी समाज व्यवस्था को श्रेष्ठ माना जा सकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन की दृष्टि से सुरक्षा, नागरिक की दृष्टि से स्वतंत्रता और उपभोक्ता की दृष्टि से ‘अवकाश’ प्राप्त हो।

सही अर्थ रचना का स्वरूप : यह तो सर्वमान्य बात है कि उपरोक्त आदर्श को पूरा करने वाली अर्थ रचना पूर्णजीवादी नहीं हो सकती। उसका स्वरूप जिसे आज मिलीजुली अर्थ व्यवस्था [मिक्सड इकोनमी] कहते हैं वह भी नहीं हो सकता। इस संबंध में एक विद्वान लेखक के ये शब्द उल्लेखनीय हैं :—
“अर्थ रचना के केवल दो स्वरूप हैं जिनमें से किसी एक को चुनना होगा—
(१) राजकीय आधार पर चलने वाली व्यवस्था और (२) व्यक्तिगत आधार पर चलने वाली व्यवस्था।” “इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच में दोनों का सम्मिश्रण

हो सकता है। पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती जो इन दोनों से ही भिन्न हो।" जहाँ एक आर्थिक योजना का प्रश्न है—इन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में मौलिक भेद है। राज्य मंचालित व्यवस्था में देश के उत्पादन साधनों पर राज्य का पूर्ण अधिकार होता है और इस वाले राज्य सीधी तौर पर आयोजन कर सकता है। पर जिस व्यवस्था में व्यक्तिगत व्यवसाय की प्रधानता होती है वहाँ सरकार साधा आयोजन नहीं कर सकती। ऐसी व्यवस्था में राज्य का काम यह हो जाता है कि व्यक्तिगत व्यवसाय का कमी-बेशी को पूरी करे, उसे आवश्यकता पड़ने पर प्रोत्साहन दे या उस नियंत्रित और प्रतिबंधित करे। इनसे यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय प्रदान अर्थ रचना में योजना के अनुसार आर्थिक जीवन का संचालन उतना सफल नहीं हो सकता जितना राज्य संचालित अर्थ व्यवस्था में संभव है। व्यक्तिगत व्यवसाय प्रदान आर्थिक जीवन में योजना के अनुसार काम करने की कठिनाइयों का उत्पन्न करते हुए जे० थार० बलेरला अपनी 'इकोनॉमिक रिक्लमेटेशन' नाम पुस्तक के प्रथम भाग में एक स्थान पर लिखते हैं, "ऐसे प्रमाण हैं कि व्यक्तिगत व्यवसाय प्रदान अर्थ रचना में गहनैतिक, औद्योगिक, और सामाजिक ऐसी कई कठिनाइयाँ किती भी योजना के माग में पैदा होंगी कि चाहे अल्प कल्प होने पर उसमें से प्रत्येक को जीतना संभव मान्य पड़े पर सब मिलकर एक बहुत बड़ी कठिनाई का रूप में वे हमारे सामने आवें।" व्यक्तिगत व्यवसाय प्रदान अर्थ रचना में जिस प्रकार का आर्थिक जीवन का नियंत्रण आवश्यक होगा उसने हम इन कठिनाइयों का कुछ अनुमान लग सकते हैं। यदि हम सब लोगों को समुचित रूप से पूरा काम देने का दृष्टि से व्यक्तिगत व्यवसाय प्रदान अर्थ रचना को कायम रखने हुए कोई आर्थिक योजना बनाना चाहते हैं तो "इस तरह की किन्हीं भी योजना के तीन मुख्य विभाग होंगे—(१) उसमोलाखा के हाथ में कदमचाल का विस्तार (२) मूल्य का नियंत्रण और (३) विशेष योजनायें जिनका उद्देश्य बेकारों को काम देना और विनियोग का नियंत्रण करना होगा।" (जे० थार० बलेरला) इस प्रकार एक दूसरे लेखक ने आवेष्टित अर्थ व्यवस्था में नियंत्रण के संबंध में लिखते हुए कहा है कि उत्पादन की मात्रा को अधिकतम बनाने के निम्ने सीमित साधनों का दुरुपयोग या अपव्यवहृत कम आवश्यक कामों में उपयोग होने से रोकने, तथा सचि का अनुचित बटवारा न हो सके इस दृष्टि से और मजदूरी का नियंत्रण करने, मिल-भट्ठार संबंधों को ठीक-ठाक बनाये रखने और सब के निम्ने पूरा-पूरा काम मिल सके इसकी व्यवस्था करने का दृष्टि से मूल्यों और आय पर नियंत्रण करने व उद्देश्य से भी नियंत्रण आवश्यक हों। पर इतना सब नियंत्रण

तभी संभव है जबकि पूंजीपति वर्ग इसमें पूरा-पूरा सहयोग दें। उनका इतना सहयोग मिल सकेगा यह बहुत शंका का विषय है। वह खतरा हमेशा बना रहेगा कि पूंजीपति असहयोग करके सारी व्यवस्था को सुपचाप अन्दर से अस्तप्ल बनाने का प्रयत्न करें। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने की है कि जिस अर्थ रचना का उद्देश्य सबको पूरा काम देने के अलावा उत्पादन की कुशलता में अधिकतम वृद्धि करना और न्यायपूर्वक वितरण करना भी है, उसमें उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अधिक विलंबित आधार पर करना होगा धनित्व उस अर्थ रचना में जिसका लक्ष्य सबको केवल पूरा-पूरा काम देना ही है। सबको काम देने की दृष्टि को सामने रखकर ही जी० डी० एच० कोल ने अपनी 'मीन्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट' नामक पुस्तक में यह लिखा है कि जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक होगा उनमें मकान, सिविल एनजीनरिंग, वातायत और अन्य सार्वजनिक सेवा के उद्योग जैसे पूंजीगत पदार्थों का उपयोग करने वाले उद्योगों को तो कम से कम शामिल करना होगा। परन्तु कार्य-कुशलता को अधिकतम बनाने के लिये और अन्याय और शोषण को कम से कम करने के लिये, और कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी करना होगा। तमाम रक्षा संबंधी तथा भारी उद्योगों को इन्हीं श्रेणियों में गिनना होगा। राष्ट्रीयकरण के अभाव से केवल राज्य के नियंत्रण द्वारा उत्पादन की कार्यकुशलता बढ़ाने में किस हद तक बाधाएँ आ सकती हैं इसका अनुभव गन महायुद्ध में ब्रिटेन और भारत में हो चुका है। इस विवेचन का सार यह है कि जिसे मिलीजुली अर्थ व्यवस्था कहते हैं और जो सत्यतः पूंजीवादी व्यवस्था ही का एक स्वरूप है वह कभी सफल नहीं हो सकती। और पूंजीवाद के दोषों से बचने का एक ही उपाय है कि देश में समाजवादी व्यवस्था कायम की जाये। पर यहाँ जहाँ तक कम से कम भारत का प्रश्न है, एक और प्रश्न उपस्थित होता है। वह है गांधीजी के अर्थ रचना संबंधी विचारों का। इस पर अब हम विचार करेंगे।

गांधीजी के अर्थ रचना संबंधी विचार : गांधीजी का वह कहना था कि वर्तमान उद्योगवाद का दोष उसका पूंजीवादी आधार तो है ही पर इसके अलावा यह भी है कि उसका आधार केन्द्रित उत्पादन को बड़े-बड़े कारखानों में किया जाता है वह भी है। उनका तर्क यह था कि केन्द्रित उत्पादन में यह तो अनिवार्य है कि आर्थिक सत्ता उन कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित हो जायगी जो उस सारी व्यवस्था के संचालन करने वाले होंगे। इसका परिणाम यह होगा कि यह व्यवस्थापकों का वर्ग आज के पूंजीपतियों की तरह ग्राम लोगों पर अपना अधिपत्य बना लेगा और ग्राम जनता को तब भी 'स्वतंत्रता' प्राप्त नहीं होगी।

इसलिये महात्मा गांधी ने ऐसे सरल आर्थिक जीवन का जिसका आधार स्वावलंबी गांव या गांवों का समूह हो और जिनमें उत्पादन का छोटे-छोटे ग्रामोद्योग में विरेन्द्रीकरण हो, समर्थन दिया। उनका यह विचार था कि विरेन्द्रित उत्पादन होने पर ही प्रत्येक व्यक्ति सभी 'स्वतंत्रता' अनुभव कर सकेगा। बड़े पैमाने के केंद्रित उद्योगों के विरुद्ध एक आपत्ति यह भी है कि उनमें काम करने वाले मजदूरों का जीवन मशीनबद्ध हो जाता है और उनसे व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। जब जहां तक आधुनिक उद्योगवाद के प्रति उठाई गई इन आपत्तियों और ग्रामोद्योगों के उपरोक्त लाभों का भ्रवाल है, गांधी के विचारों में बहुत सुस्पष्ट तथ्य है। पर हम यह नहीं कह सकते कि बड़े पैमाने पर चलने वाले उद्योगों का जनता और उसके प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रण हो ही नहीं सकता और न यह कह सकते हैं कि ग्रामोद्योग गहरा एवं हा व्यक्तित्व व विकास में सहायक होने वाले हैं। इससे अनिश्चित पाद रस्ते का ज्ञान यह भी है कि हमारा सामाजिक लक्ष्य क्या 'स्वतंत्रता' महा है। उससे साथ बढ़ती हुई जनसंख्या को रहन रहन का एक सम्य स्तर मिले एवं इस दृष्टि से उनकी 'सुरक्षा', और वे जीवन का आनंद उठा सकें इस दृष्टि से उनके 'अवकाश' का प्रश्न भी हमारे सामने है। 'सुरक्षा' और 'अवकाश' दोनों का दृष्टि से बड़े पैमाने के केंद्रित उत्पादन का आवश्यकता हो सकता है, यह बात भी हम भूलना नहीं चाहिये। पर इससे निपटान भारत जैसे देश का अपना विरासत परिस्थिति है जिनमें उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक भ्रम व उपयोग करने की और पूजा व कम उपयोग करने की जरूरत है। इनमें ग्रामोद्योग का महत्व भारत के लिये बिगड़ हो जाता है। उपरोक्त सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि विरेन्द्रित उत्पादन व ताल बड़े लाभ हैं। एक तो यह है कि यह सरल और सादा जीवन को अपनाने व पत्र में हमारा मा यत्न का सक्त करता है। दूसरे उससे समाज के प्रत्येक नागरिक को एक तरफ स्वतंत्रता मिलने का आशा है और दूसरी तरफ हमारा वृद्धता हुई जनसंख्या को अधिक काम दे सकने का सम्भावना है। हम साथ ही साथ यह भी जानते हैं कि आधुनिक युग में कई रक्षा, शक्ति, खनिज पदार्थ, वन, और मशीन इजिनियरिंग तथा भारी रसायनिक पदार्थों सम्बन्ध उपयोग हैं जो केंद्रित आधार पर ही चल सकते हैं। इसी प्रकार रेलवे तथा दूसरे सार्वजनिक सेवा के उद्योगों का बात है। इस सबका परिणाम यह है कि आज के युग की अर्थ व्यवस्था में हम दोनों प्रकार के उद्योगों का एक समन्वय बिठाना होगा।

मावी अर्थ रचना गांधीवाद और समाजवाद का समन्वय उपरोक्त

विवेचन से यह तो स्पष्ट है कि हमारी राय में भावी अर्थ रचना गांधीजी के और समाजवादी विचारों के समन्वय के आधार पर स्थापित की जानी चाहिये। अब प्रश्न केवल यह रह जाता है कि इन दोनों के समन्वय का आधार क्या हो। जहाँ तक ऐसे उद्योग हैं जो स्वभावतः बड़े या छोटे पैमाने पर ही संगठित किये जा सकते हैं उनके बारे में तो कोई कठिनाई है नहीं। पर जो उद्योग दोनों ही आधार पर चल सकते हैं उनके बारे में यह निर्णय करना होगा कि कौन से उद्योग केन्द्रित आधार पर चले और कौन से विकेन्द्रित। इस सम्बन्ध में एक तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारा यह निर्णय ऐसा हो जिसमें सुरक्षा, स्वतन्त्रता, और अवकाश इन तीनों दृष्टियों का समुलान रह सके। दूसरी बात हमारे सामने यह रहनी चाहिये कि जहाँ तक उपभोक्ता पदार्थों के और उनमें भी खास तौर से अन्न-वस्त्र जैसे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरी करनेवाले पदार्थों के उत्पादन का प्रश्न है वह उत्पादन विकेन्द्रित आधार पर ही किया जाय क्योंकि जीवन के इस क्षेत्र में 'स्वतन्त्रता' का अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व है। इस प्रकार के गांधीवाद और समाजवाद के समन्वय पर बनी मार्गी अर्थ रचना के द्वारा ही हम अपने सामाजिक लक्ष्य 'सुरक्षा', 'स्वतन्त्रता' और 'अवकाश' की प्राप्ति कर सकेंगे।

भारत में आर्थिक योजना के प्रयत्न : भावी अर्थ रचना के बारे में वैज्ञानिक रूप से विचार कर लेने के बाद अब हम इस सम्बन्ध में भारत में जो प्रयत्न हुए हैं उनका विचार करेंगे।

भारत में आर्थिक योजना का प्रश्न सबसे पहले कांग्रेस ने १९३८ में उठाया और उसने एक राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण भी किया। इस योजना समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयम् थे। इस योजना समिति ने २६ उपसमितियाँ बनाईं और इन उपसमितियों ने अपने-अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में रिपोर्टें प्रकाशित कीं। इन रिपोर्टों में देश के आर्थिक जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। राष्ट्रीय योजना समिति द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गई थी उसका मुकाबला समाजवादी व्यवस्था की ओर था।

भारत सरकार ने भी गत महायुद्ध समाप्त होने के बाद इस सम्बन्ध में कुछ कार्य किया। १९४४ में योजना और विकास विभाग की स्थापना की गई और सर आर्देशीर दलाल उस विभाग के कौन्सिल सदस्य नियुक्त किये गये। इस विभाग ने भी एक योजना प्रकाशित की जिसके दो भाग थे—एक अल्पकालिक और दूसरा दीर्घकालिक। पर देश का विभाजन हो जाने और स्वतन्त्रता मिल जाने से सारी स्थिति बदल गयी और इस योजना के स्थान पर एक नयी योजना

का आवश्यकता पड़ गयी।

देश के लिये आर्थिक योजना प्रस्तुत करने के कुछ और भी प्रयत्न हुए। १९४० में बम्बई के कुछ पृथिवियों द्वारा बम्बई योजना या किरला टाटा योजना के नाम से एक योजना देश के सामने उपस्थित की गयी। यह योजना १५ वर्ष के लिये तैयार की गयी थी। इस हजार रुपये खर्च करने का इसमें आशय था, और इसका लक्ष्य था बढ़ती हुई जनसंख्या का विचार करते हुए १५ वर्ष में देश का प्रति व्यक्ति औसत आय को दुगुना करना। इस योजना का आधार पृथिवीवाद था।

एक दूसरी योजना जन योजना (पापुलर प्लान) के नाम से भारतीय मजदूर संघ ने प्रकाशित की। इसे राय योजना भी कहते हैं। इसकी अवधि दस वर्ष रखा गयी और इसमें कुल १५ हजार करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान किया गया। इस योजना के अनुसार दस वर्ष समाप्त होने पर देश का कृषि उत्पादन चार गुना और औद्योगिक उत्पादन छह गुना होने का अनुमान लगाया गया। जनता के रहन-सहन का दसवां भाग गुना होने का अनुमान था। यह समाजवादी योजना थी।

तीसरी योजना गार्फीवादी योजना थी। इसमें दस वर्ष में तीन हजार पाब सौ करोड़ रुपये खर्च करने का आशय था। इस योजना में कृषि और प्रायोगिक का विशेष महत्व था।

कालम्बो योजना दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये राष्ट्र मंडल के विभिन्न देशों ने कालम्बो योजना नाम की एक ६ साल की योजना १९५० में तैयार की। इस योजना में भारत ने भी अपने लिये एक योजना शामिल की। इसमें कुल भारत का जहाँ तक सम्बन्ध है १८४० करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। कृषि और वानायात को विशेष महत्व दिया गया है। इसका उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या का ध्यान रखते हुए प्रति व्यक्ति प्रति दिना १६ ग्रांस अनाज और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष १५ गन कपड़ा उपलब्ध कर देने का है।

पंचवर्षीय योजना

हाल ही में भारत सरकार ने एक प्रस्तावित पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की है। इस योजना में कालम्बो योजना के भारतीय अंग का आवश्यक संशोधनों के साथ समावेश किया गया है।

भारत सरकार ने मार्च, १९५० में एक योजना आयोग (प्लानिंग कमीशन) की नियुक्ति की थी। इस योजना आयोग ने भारत के लिये इस पंचवर्षीय योजना को बनाना और सरकार के विचारार्थ प्रकाशित की है। इन

पंक्तियों में इसी योजना के बारे में विचार किया जायगा।

योजना का आधार जनतंत्र : इस योजना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका आधार समाज और राज्य की जनतंत्रीय व्यवस्था है। योजना आयोग का यह दृष्टिकोण विल्कुल सही है। जनतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग इसका हृदय से स्वागत करेंगे।

जनता का सहयोग आवश्यक : जनतंत्र के आधार पर यही योजना ठीकी सफल हो सकती है जब उसे जनता का हार्दिक सहयोग प्राप्त हो और उस योजना से उनके मन में उत्साह और उमंग उत्पन्न हो। प्लानिंग कमीशन ने बहुत साफ साफ शब्दों में इस बात को मंजूर किया है। उनका लिखना है कि 'किसी भी जनतन्त्रीय राष्ट्र में सरकार की योजना बनाने, सुसंगत रीति-नीति का निर्णय करने, और उसे पूरी कामवाची के साथ व्यवहार में लाने की योग्यता इन बात पर निर्भर रहनी है कि जनता का कितना समर्थन और सहयोग उसको मिल सकता है।' इसीलिए 'ऐसी योजना में केवल राज्यों की सरकारों को ही नहीं, बल्कि म्यूनिसिपैलिटीयों, जिला बोर्डों, ताल्लुका बोर्डों और पंचायतों जैसी स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं तथा भूखंडों के आधार पर संगठित संस्थाओं को काफी महत्वपूर्ण हिस्सा लेना होगा।' केन्द्रीय सरकार का काम तो एक सुव्यवस्थित नीति का निश्चय करना और स्थानीय तथा दूसरे विभिन्न हितों में पैदा होने वाले मतभेदों को मिटाने का है।

सहयोग और उत्साह का आधार क्या ? : सवाल तो यह है कि जनता का समर्थन और सहयोग कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? प्लानिंग कमीशन ने जो योजना प्रकाशित की है क्या उसके आधार पर जनता का समर्थन और उत्साहपूर्वक सहयोग मिलने की आशा हो सकती है ? प्लानिंग कमीशन की यह योजना क्या है और आम जनता की आर्थिक दशा में उसके परिणाम स्वरूप सुधार की क्या सम्भावना मानी जा सकती है ? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्लानिंग कमीशन ने जो योजना प्रस्तुत की है उसका विस्तार से विचार किये बिना, देश के आर्थिक जीवन से सीधा सम्बन्ध रखने वाली कुछ खास-खास बातों पर ही यहाँ प्रकाश डालना काफी होगा। पहली बात अन्न की समस्या की है। स्वयं प्लानिंग कमीशन ने लिखा है "जब तक अन्न की समस्या का संतोषजनक हल नहीं निकलता, देश की आर्थिक स्थिति में वह स्थिरता नहीं आ सकेगी जो इस योजना को क्रमशः में लाने के लिये जरूरी है।" इस सम्बन्ध में प्लानिंग कमीशन ने जो योजना पेश की है, वह बहुत उत्साह देने वाली नहीं है। बढ़नेवाली आवादी का लिहाज रखने के बाद, पाँच वर्ष में देश में अन्न का जिनना उत्पादन पाँच अर्धव

योजना के अनुसार बढ़ेगा उसे और जो ३० लाख टन अनाज सामाना बाहर में भेजा जायेगा उसे मान लेते पर भी, १९३५-३६ में प्रत्येक ग्रीक व्यक्ति के हिस्से में औसतन १४ छींग प्रतिदिन अनाज आवेगा। पाँच वर्षों में अनाज के उत्पादन में ७२ लाख टन का वृद्धि होने का अनाज लगाया गया है। १९५० में प्रति पौंड व्यक्ति प्रति दिना १३ १७ छींग के हिस्से से अनाज मौजूद था। इसका अर्थ यह है कि अनाज में ४ साल बाद भी अनाज की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं होगा। दूसरा स्थान कपड़े का है। पंचवर्षीय योजना के अनुसार जो कनास का उत्पादन बढ़ेगा उसका भागकर हमारा कपड़े का पिन्नों में १९५५-५६ में ५५० करोड़ गज कनास तैयार होगा। इसमें घलासा हाथ करण से १६० करोड़ गज कनास तैयार होने का आया है। यह सब मिनाकर १९३५-५६ में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग १५ गज कपड़े का आसन पड़ेगा। दूसरे महायुद्ध के पूर्व यह औसत १५ २६ गज कपड़े का था। १९४६-५० में यह औसत १३ ४ गज कपड़ा ही था। जो अनाज न बाहर में हमारे साथे लगभग १६० छींग प्रति कपड़े के बारे में भा है। नतीजा इसका यह है कि जायाजना हमारे सामने पेश का यह है उसके द्वारा आने वाले पावनाला में दज का जनता को, रोटा करके के सामने में तो, हमारा उत्पादन योजना के अनुसार धराधर बढ़ना लायक तब मा, कोई राशन मिल नहीं पड़ेगा।

जनता के आर्थिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाली एक नीति महानायक चीन में महाकाव्य का है। इसका यह है कि पंचवर्षीय योजना के द्वारा हम स्थिति में कोई सुधार होगा या नहीं। इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अनाज आने वाले कुछ वर्षों में मूल्यों सम्बन्ध नीति का परला लक्ष्य यह होना चाहिए कि अनाज और खाद्य का कीमते बढ़ नहीं और जहाँ तक मुम्किन हो उनको कम किया जाय और दूसरा लक्ष्य यह होना चाहिए कि विभिन्न चीजों के मूल्यों की आपस के सम्बन्ध का समानता बना रहे। उदाहरण के लिए लाद्यान और कच्चे मान के मूल्यों में समानता रहना चाहिए ताकि किसी एक के उत्पादन का कम करके दूसरे को बढ़ाते की नीति में आवे। पर मूल्यों सम्बन्धी इस नीति का पालन करना कहीं तक सम्भव है इसके बारे में स्वयं प्लानिंग कमिशन को ही शक है। इसमें प्लानिंग कमिशन का कोई दोष नहीं है। किसी देश में जब आर्थिक विहास को कोई योजना लागू होता है तो उसका लाजिमी नतीजा यह होता है कि उत्पादन बढ़ाने में पूँजी के तीर पर खर्च तो हो जाता है और चीजों का उत्पादन खन होने के बाद होता है। इसका यह अर्थ पड़ता है कि किसी हद तक इस उत्पादन में लगे हुए लोगों की कर्ष करने

की योग्यता तो बढ़ जाती है पर बाजार में माल की माँदा उतनी जल्दी नहीं बढ़ती। इसका नतीजा कीमतों के बढ़ने का होता है। इसी सम्भावना को मँबर करते हुए कमीशन ने भी लिखा है कि “अर्थ व्यवस्था में मँहगाई बढ़ाने वाली प्रवृत्तियों तो काम करती रहेंगी पर मँहगाई अधिक न हो सके इसके लिए मूल्य नियन्त्रण की व्यवस्था को और अधिक पक्का बनाना पड़ेगा और उसमें आवश्यक सुधार करना होगा।” अगर राज्य को नये रुपये का विस्तार करना पड़ा तब तो स्थिति और भी कठिन हो जायगी। नये रुपये का विस्तार करना इसलिए जरूरी हो सकता है कि राज्य को आर्थिक विकास के लिये जितने साधन चाहिये वे अगर कर अथवा श्रृण से नहीं प्राप्त हो सके तो फिर नये रुपये को छापकर सरकार को इस घाटे की पूर्ति करनी पड़ेगी। यही युद्ध के समय में भी हुआ था। इस सबका सार यह है कि आने वाले ५—७ साल में तो मँहगाई कम होने की कुछ भी आशा करना ठीक नहीं होगा।

उपरोक्त विवेचन से यह साफ है कि जो पंचवर्षीय योजना पेश की गई है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे लोगों की आर्थिक हालत सुधारने की तत्काल कोई बहुत बड़ी आशा हो सके। क्या ऐसी कोई योजना हो सकती है जो पाँच साल में ही जमीन पर स्वर्ग उतार दे? यह एक शक्तिव सवाल है। पर इस सवाल को हम यहाँ नहीं उठावेंगे। यह एक तकसील का सवाल है। यहाँ हम इस योजना पर आधारभूत दृष्टि से विचार करना चाहते हैं। इसके अलावा इसका पक्का जवाब वही दे सकता है जिसके पास वह सब सामग्री हो जो कमीशन के पास मौजूद थी। हम यह बात तो मान कर चलते हैं कि देश के आर्थिक विकास में पहले हमें काम करना होगा, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, अपने स्वर्गों को कम करके विकास के काम में पूँजी के तौर पर खर्च लगाना पड़ेगा। यह सब करने के बाद ही हमें अपनी महनत का फल मिल सकता है। पर आस लोग इस सब कठिनाई को उठाने के लिए और दिल से पूरा-पूरा सहयोग देने के लिए उसी हालत में तैयार हो सकते हैं जब उन्हें यह भरोसा हो कि उनके प्रयत्न के फलस्वरूप जो आर्थिक व्यवस्था बनेगी, वह उनके हित के लिए काम करने वाली होगी। इसलिए प्रस्तुत योजना में ग़िब तरह की आर्थिक व्यवस्था की कल्पना की गई है उस चारे में विचार करना जरूरी हो जाता है। यह देखने की बात है कि उस आर्थिक व्यवस्था के जरिये किस हद तक सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की स्थापना संभव माननी चाहिए।

हम ऊपर यह लिख चुके हैं कि जो पाँच साला योजना प्लानिंग कमीशन द्वारा प्रकाशित हुई है वह हमारे रोटी कपड़े और मँहगाई जैसे रोज बरोज के

आर्थिक मसलों का आनेवाले पांच सालों में कोई बहुत सन्तोषजनक हल नहीं निकाल सकेगा। और फिर भी यदि योजना का सफल होना है, और संसाधारण को उस कायाविन करने के लिए उत्साहित करना है तो यह तभी हो सकता है जब 'उह यह भरोसा हो कि उनका प्रयत्न के फलस्वरूप जो आर्थिक व्यवस्था बनेगी, वह उनके हित के लिए काम करने वाली होगी।' दूसरे शब्दा में उस आर्थिक व्यवस्था के द्वारा सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता का स्थापना हो सकता, ऐसा विश्वास आम लोगों में पैदा होना आवश्यक है। इस दृष्टि से इस पंचवर्षीय योजना पर अब विचार किया जायगा।

कृषि व्यवस्था का मन्त्र किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए यह जानना होता है कि उस देश में उत्पादन की क्या व्यवस्था है? उत्पादन से जो सम्पत्ति पैदा होता है उसका लाभ किसको होता है? आपा अघिकाय सम्पत्ति चन्द लोगों के हाथ में चला जाती है या उसका समान में न्यायपूर्ण और अप्रदाहृत समान बटवारा होता है? इसका अनुमान राष्ट्र का औसत आम से भी किसी हद तक हो सकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के तुल्य काम करने वालों का लगभग ७० प्रतिशत भाग आज भी खेती से ही अपना जीविका कमाता है। इससे यह साफ है कि देश के आर्थिक जीवन में कृषि व्यवस्था का बहुत महत्व है। कृषि व्यवस्था का महत्व इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र की तुल्य आय का लगभग आधा भाग कृषि से ही मिलता है। १९४६ में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की थी। उसकी पहली रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई है। उसके अनुसार १९४८-४९ के साल में हमारा राष्ट्रीय आय ८७१० करोड़ रुपया थी और इससे से ४८ प्रतिशत आय कृषि से होती थी। इससे यह है कि पंचवर्षीय योजना में देश का कृषि व्यवस्था के सम्बन्ध में किन किन मुद्दों का कल्पना की गई है और आज जो दोष उसमें पाये जाते हैं उनका इस योजना के आधार पर कहाँ तक निराकरण हो सकेगा।

देश की कृषि व्यवस्था के आधारभूत दोष हमारी कृषि व्यवस्था में वैसे तो कई छोटे मोटे दोष आज मौजूद हैं। पर जो आधारभूत और बड़े दोष माने जाते हैं वे ये हैं — खेती की जितनी जमीन है उसका हिस्सा में खेती करने वालों की संख्या बहुत है इसलिए खेती के मुद्दों के लिए पहली जरूरत इस अत्यधिक खेती की भूमि के जोर को कम करने की है। इसी में सम्बन्धित दूसरी समस्या यह है कि बहुत छोटे-छोटे खेतों पर खेती की जाता है। आर्थिक दृष्टि से इनके छोटे-छोटे खेत लाभदायक सिद्ध नहीं होते। समय और साधनों का

सुरूपयोग और अपव्यय होता है और उत्पादन कम होता है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर अलग-अलग प्रदेशों में जांच भी की गई है। इस तरह से की गई जांचों से भी उपरोक्त कथन का समर्थन ही होता है। उदाहरण के लिए अविभाजित पंजाब में की गई एक जांच से मालूम पड़ा था कि लगभग ८१ प्रतिशत खेत (होलिडिंग्स) १० एकड़ से कम थे और ६४ प्रतिशत खेत ५ एकड़ से कम थे। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन समिति ने जो जानकारी एकत्रित की थी उससे यह मालूम पड़ा कि ८१ प्रतिशत खेत ५ एकड़ से कम के और ६४ प्रतिशत खेत १० एकड़ से कम के थे। इसके अलावा करोड़ों व्यक्ति खेती में ऐसे हैं जो खेतिहर मजदूर हैं। केवल बंधी हुई मजदूरी पर वे काम करते हैं। उनकी दशा बहुत ही शोचनीय है। स्वयं प्लानिंग कमीशन ने लिखा है कि “ग्रामीण जनसंख्या का लगभग एक तिहाई भाग खेतिहर मजदूरों का है।...उनमें से भारी बहुमत ऐसे लोगों का है जो मुश्किल से अपना पेट भरते हैं।” खेती की व्यवस्था सुधारने के लिए इस समस्या का हल भी निकालना होगा। आखिरी बात देरा की कृषि व्यवस्था के बारे में जागीरदारी और जमींदारी प्रथा की है। जमींदारी प्रथा का अन्त करने के प्रयत्न जारी हैं और जागीरदारी का सवाल भी विचाराधीन है।

कृषि व्यवस्था के जिन दोषों का ऊपर जिक्र किया गया है उनका जब तक कोई सन्तोषजनक हल नहीं निकलता है तब तक कृषि सम्बन्धी अन्य आवश्यक सुधार वास्तव में सम्भव नहीं हो सकते। और जिस हद तक वे सम्भव हो भी सकते हैं उस हद तक उसका लाभ पूरी तौर पर आम किसान जनता को नहीं मिल सकता। इसलिए उपरोक्त दोषों को आधारभूत दोष कहा गया है जिनके मिटने पर ही दूसरे सुधार फलदायी हो सकते हैं। पांच वर्षीय योजना में इन दोषों को दूर करने के बारे में किन-किन उपायों की सिफारिश की गई है और कहाँ तक उनके द्वारा वास्तव में सुधार मुमकिन हैं, अब इस पर विचार किया जायेगा।

प्लानिंग कमीशन के सुझाव : जहाँ तक जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का सवाल है, जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है, उनको समाप्त करने के प्रयत्न जारी हैं। कमीशन ने भी इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कार्रवाई की सिफारिश की है।

दूसरा सवाल छोटे-छोटे खेतों की समस्या को हल करने का है। प्लानिंग कमीशन ने चार उपायों पर विचार किया है:—(१) भूमि का राष्ट्रीयकरण और उस पर सामूहिक खेती; (२) मौजूदा खेतों की अधिक से अधिक सीमा निर्दिष्ट

कर लेना और अतिरिक्त भूमि को जिनके पास छोटे छोटे खेत हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं और सहकारी सेवा करना चाहते हैं उनमें बाँट देना, (३) छोटे छोटे खेत वाले किसानों को सहकारी सेवा के लिय प्रोत्साहित करना, और (४) सारे गांव को इकाई मान कर गांव की सारी गेती योग्य जमीन को एक ही खेत मानते हुए सेवा के लिए अलग अलग हिस्सा में उसको बाँट देना और मांग मरक़ी जमीन का सहकारी आधार पर प्रबंध करना। प्लानिंग कमिशन ने पहले और दूसरे उपायों का समर्थन नहीं किया है। राष्ट्रीयकरण के विना एक मुख्य आपत्ति यह है कि एक तो राज्य के लिए इतने बड़े पैमाने पर मुद्रासहायता देना समझ नहीं आता। दूसरे, भारत का किसान परम्परा से अपनी व्यवस्था को पसन्द करता है जो किसान को जमीन का मालिक माने। इनके विपरीत छोटी जमीन का राष्ट्रीयकरण कर लेने का अर्थ किसानों का जबरदस्ती विरोध बढ़ा कर लेना होगा। समाधान का यह रास्ता ठीक ही है। अधिक व्यावहारिक बात यही है कि जो जमान आज किसान के पास है वह उसी के पास रहने का जमान। पर जो नई जमीन खेती के योग्य बनाई जाय उसे अवश्य ही सामूहिक सेवा के काम में लेनी चाहिए, ताकि सामूहिक सेवा का देश में प्रयोग किया जा सके और व्यक्तिगत सेवा के लिये यह एक उदाहरण का काम कर सके। प्लानिंग कमिशन भी इससे सहमत है।

मीनूदा खेतों की अधिकतम सीमा निश्चित कर देने और उससे अधिक भूमि का प्राप्त करने के लिये द्वारा कम भूमि वालों को बाँट देने के बारे में भी कमिशन ने कई कठिनाइयाँ उपस्थित की हैं। एक तो इस काम को करने की सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। प्राप्त ना हुई जमान का बाँटने में कई प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयाँ आ सकती हैं। दूसरा अलावा जो जमीन प्राप्त की जायगी वह एक लगातार टुकड़े में न होकर गाँव के विभिन्न भागों में नर टुकड़ों में बटा होगा और इसलिये उसे सामूहिक सेवा के काम में लेना आसान नहीं होगा। कमिशन का यह भी मत है कि बड़े बड़े खेतों के टुकड़े करने से पैदावार में कमी आ सकता है जो जनसाधारण के हित में नहीं होगी। इस प्रकार के निर्णय का विरोध माँ हो सकता है और उससे एक भय पैदा हो सकता है। इन तमाम कारणों से कमिशन ने इस उपाय का भी समर्थन नहीं किया है। सब बातों पर विचार करने के बाद यहाँ लगता है कि कमीशन के मत में इस उपाय का समर्थन करने में जो भिन्नता रही है उसका आधार तो है। हालांकि यह भी सही है कि इस प्रकार के सुधार के बिना देश में वातावरण बनाना आवश्यक है और उपयुक्त समय का चुनाव करके ऐसे सुधारों को अमल में भी लाया जा

सकता है। इस तरह के बँटवारे से छोटे छोटे खेतों की समस्या वास्तव में किस हद तक सुधार सकती है और उसका असर कितने लोगों के विपरीत पड़ सकता है, इन बातों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। सरकारों, कालेजों और विश्वविद्यालयों तथा दूसरे गैर सरकारी अध्ययन केन्द्रों और रचनात्मक संस्थाओं को इस ओर ध्यान देना चाहिये। सरकारों को तो इस दिशा में जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। चारांश यह है कि भूमि सुधार के इस उपाय का अधिक अध्ययन और जाँच करने की जरूरत है। इसका सर्वथा रह कर देना सही नहीं होगा।

भूमि सुधार का अन्तिम मध्येय प्लानिंग कमीशन ने यह सिफारिश की है कि भूमि सुधार का लक्ष्य सहकारी आधार पर सारे गाँव की भूमि की व्यवस्था करना होना चाहिए। गाँव की इस सहकारी व्यवस्था के मुख्य मुख्य लक्षण ये होंगे :—

(१) गाँव की सारी भूमि प्रवन्ध की दृष्टि से एक ही इकाई समझी जायगी।

(२) गाँव में जिन-जिन की जमीन है उनका अपनी अपनी जमीन पर स्वामित्व बद्ध माना जायगा और हर फसल पर उनको जमीन के मालिक होने के कारण 'ओनरशिप डिपिडेण्ड' के नाम से मुआवजा मिलेगा। जहाँ तक स्वामित्व का सवाल है उसके बारे में वह व्यवस्था कर देने के बाद, फिर गाँव की सारी खेती योग्य जमीन का गाँव के हित में उपयोग किया जा सकेगा।

(३) खेती में काम करने वाले सब लोगों को, चाहे वे जमीन के मालिक हों या न हों, काम के अनुसार उजरत मिलेगी।

(४) गाँव की जमीन को खेती की दृष्टि से अलग अलग ब्लाक या टुकड़ों में बाँटा जायगा और एक-एक परिवार को या एक से अधिक परिवारों के समूह को अलग-अलग उचित शर्तों पर खेती करने के लिए ये ब्लाक दिये जा सकेंगे।

(५) जब गाँव की कुल खेती की जमीन के आधे भाग के मालिक या स्थायी कास्तकार, जिनकी संख्या कि कुल ऐसे लोगों की दो तिहाई संख्या है, सहमत होंगे तभी सहकारी ग्राम प्रवन्ध किसी गाँव में लागू किया जायगा।

जब किसी गाँव में वह प्रवन्ध चालू करने का निर्णय हो जायगा तो वह खेती का सब जमीन पर ही लागू किया जायगा।

(६) उपरोक्त व्यवस्था कायम करने का अधिकार देने वाला कानून हर एक राज्य में पास होना चाहिये। इसमें इस व्यवस्था को चलाने के लिए

आवश्यक संगठन, 'आंतरायित डिपार्टमेंट' और महत्कारा व्यवस्था जारी करने आदि बातों का समावेश होना चाहिए।

प्लानिंग कमिशन ने इस व्यवस्था में अनेक लाभ होने का आशा प्रकट का है। छोटे-छोटे पेना की समस्या हल हो सकेगी। गैरिहस किंगडम की भी उच्च काम के लिए उनका ही मन्दिरा मिलेगा जिन्हीं कि उम्मीद, बिगड़ पाठ प्रमान है। लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी का भावना पैदा होगा और अपनी आय में से बचन परत दश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पैसा इकट्ठा करने में ये सहयोग देंगे।

प्लानिंग कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में स्वाकार किया है कि गृहकारी ग्राम व्यवस्था के आधार पर एक गांव पट्टवना समझ नहीं होगा। पहले इन आधार पर प्रयोग करने होंगे। इस अन्तर्गत इस व्यवस्था को उसी हद तक जारी किया जा सकेगा जिस हद तक कि लोगों में जो लोग हटने वाले लिए अन्य काम की व्यवस्था का जो सचेता। यह काम का व्यवस्था प्रदान करने वाले उद्योगों के विकास से हो संभव हो सकेगा। पर प्लानिंग कमिशन ने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया है। जल्द ही इस बात की है कि इस समस्या के सामाजिक रूप का अर्थों के आधार पर अध्ययन किया जाय और किन किन उद्योगों या दूसरे कामों के बितने विकास में इनका कहीं तक हल होना संभव है, इस बारे में स्पष्ट रूप से सा चेष्टा की जाय। प्लानिंग कमिशन ने इस बारे में स्थिति का स्पष्टीकरण नहीं किया है। इसलिए यह कहा जा सकता कि प्लानिंग कमिशन की यह योजना कहीं तक अमल में लाई जा सकती है और उसके फलस्वरूप जैती पर से कितना भार कम हो सकेगा और कम होने वाले लोगों की क्या-क्या काम देना संभव होगा। भूमि मुद्दा के अन्तिम ध्येय के रूप में इस उद्देश्य को गौतम प्रबंध की स्वीकार करने का कमिशन का प्रस्ताव सम्भारता मुख्य विचारने योग्य है। हमारा विचार है कि कुछ मशीनरी के साथ इस ध्येय की स्वीकार करना ठीक हो सकता है। एक तो यह कि राज्य की धारा समा को कानून बाध करने ग्राम सुधार की इस व्यवस्था को लागू करने का अधिकार होता चाहिए। यह सार्य रखना ठीक नहीं है कि किसी भी गाँव में अमुक संख्या में और जमीन के अमुक भाग के मालिक या स्थायी कारखानों की सहमति से ही इन व्यवस्था को जारी किया जाय। इससे जो लोग इस व्यवस्था के विरोधी हैं उन्हें प्रदत्त पैदा करने का अवसर मिलेगा, अलग-अलग गाँवों में लोगों की राय जानने की व्यवस्था करने में कठिनाई होगी, जिनके बिम्बे गाँवों का राय जानने का काम होगा, न यदि चाहेंगे तो इस व्यवस्था को चुनचाप असफल बना सकेंगे, तथा और

भी कई कठिनाइयाँ पैदा होंगी। इसके अलावा इस बारे में एक बात और ध्यान देने की है। 'ग्रोनरशिप डिविडेण्ड' के बारे में यह होना चाहिए कि धीरे धीरे उसकी दर कम होती जाय और अमुक समय के बाद वह सर्वथा बन्द हो जाय तथा गाँव की सारी जमीन के सामूहिक रूप से गाँव के लोग ही मालिक हो जायें। यह इसलिए जरूरी है कि आज जो जमीन के स्वामित्व के बारे में अरमानता फैली हुई है इसका इस प्रकार एक समय के बाद अन्त हो जायगा। इन परिवर्तनों के बाद भूमि सुधार की उपरोक्त योजना के द्वारा हमारे देश में न्यायोचित भूमि व्यवस्था की स्थापना हो सकती है।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, प्लानिंग कमिशन का यह मानना है कि सहकारी ग्राम प्रबन्ध के लक्ष्य तक पहुँचने में समय लगेगा। उस लक्ष्य तक पहुँचने में कई पूर्व अवस्थाएँ पार करनी पड़ सकती हैं। इसलिए प्लानिंग कमिशन ने भूमि सुधार का एक तत्काल शुरु हो सकने वाला कार्यक्रम भी उपस्थित किया है। उस कार्यक्रम के तीन मुख्य अंग हैं :—

(१) गाँव उत्पादन परिपदों की स्थापना; (२) रजिस्टर्ड फार्मों की स्थापना और (३) सहकारी खेती समितियों का विकास। इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से लिखने की आवश्यकता है।

प्लानिंग कमिशन की यह सिफारिश है कि प्रत्येक राज्य को कानून बनाकर यह निश्चित कर देना चाहिए कि अमुक मर्यादा से बड़े जितने भी खेत होंगे उनको रजिस्टर्ड फार्म की श्रेणी में मान लिया जायगा। यह मर्यादा भिन्न-भिन्न स्थानों के लिए अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है। मामूली तौर से कमिशन की राय में रजिस्टर्ड फार्मों की गिनती में उन सब खेतों को मान लेना ठीक हो सकता है जिनका क्षेत्रफल आज जो इकोनोमिक इन्डिग (आर्थिक दृष्टि से लाभदायक छोटे से छोटे खेत) माना जा सकता है उसके क्षेत्रफल से छः गुने से ज्यादा हो। जो रजिस्टर्ड फार्मों के मालिक होंगे उन पर कानून के अन्तर्गत नीचे लिखी जिम्मेदारियाँ होंगी :—(१) खेती करने के स्वीकृत वैज्ञानिक उपायों को काम में लेना और अधिक से अधिक उत्पादन की दृष्टि से खेतों का विकास करना; (२) अच्छा बीज सरकार को बेचना; (३) अतिरिक्त अनाज सरकार को बेचना; और (४) खेतिहर मजदूरों को निश्चित मजदूरी देना तथा काम की दूसरी शर्तों का पालन करना। सरकार का काम होगा कि इनको आवश्यक साधन, सुविधायें, सलाह और मार्ग दर्शन दे।

जो खेत रजिस्टर्ड फार्म की गिनती में नहीं आ सके, उनके लिए कमिशन ने यह सिफारिश की है कि उनके मालिकों को सहकारी खेती समितियों बनाने

के लिए प्रासादन देना चाहिए। इस सहकारा सार समितियों के लिए कमीशन नाच लिख शने लगाना उचित समझना है —(१) सहकारा सेवी समिति के पास भी कम से कम इतनी जमान होना चाहिए जितना कम से कम जमान रजिस्टर्ड फार्म के लिए निश्चित की जाय। (२) आर्थिक सहायता, उन्नियन सुनाह, क्रय विक्रय का सुविधा और दूसरा आवश्यक चीजों का व्यवस्था के बारे में सरकार सहकारा सेवी समितियों का पहले ध्यान रखे। (३) जिन गावों में सहकारी सेवी समितिया स्थापित हो चुकी हैं उन गावों का जमान की चक्कादा के लिए और गावों की अपेक्षा पहले चुनना। अगर बिना सारे गाव का जमीन चक्कादी किये भा सहकारी सार समितियों का जमान की चक्कादा करना समभव है तो उस करना। (४) पड़न जमान का सेवी के लिए उठाने में सहकारा सेवी समितियों को पहले मौका देना और ऐसा जमान का सेवी योग्य बनाने के लिए सरकार स सहायता देना। (५) यह व्यवस्था करना कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी जमीन सहकारा सेवी समिति के पास है स्वयं सेवी भी नहीं करता है तो भी उसके भूमि सम्बन्ध अधिकार पर इसका कोई प्रतिकूल अगर नहीं पड़ेगा। इसमें सहकारी सेवी समितियों का निर्माण करने और सेवा पर स अनिश्चित और अनावश्यक सख्या का कम करने में मदद मिल सकता है।

गावों में उत्पादन बढ़ाने के काम का इस्तेमाल करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक गांव या गावा के किन्ना समूह में एक 'ग्राम उत्पादन परिषद' कायम की जाना चाहिए। गाव पंचायत का कोई उपसमिति इस पारम्परिक काम कर सकता है निम्न गाव के दो तीन कितान और गाव की सार समिति के कुछ पदाधिकारों में शामिल किये जा सकते हैं। किसी गाव में अगर पंचायत न हो तो उस गाव का सहकारा सार समिति का प्रबन्ध समिति को उत्पादन परिषद का काम भाग्य जा सकता है। या फिर एक नई समिति का ही इस काम के लिए निर्माण किया जा सकता है। गाव उत्पादन पारम्परिक की निम्नदातियों और कायचन का कृषि में निश्चय करने का प्लानिंग कमीशन ने सिफारिश की है। ये निम्नदातरदा और कायचन इस तरह का होगा —

- (१) हर साल के लिए गाव भर के वार्षिक पैदावार का कार्यक्रम बनाना।
- (२) उपराज कार्यक्रम को पूरा करने के लिए पन और दूसरी चीजों का कितनी जितनी आवश्यकता होगी इसका बजट तैयार करना।
- (३) हर फसल के बाद कितना पैदावार हुआ इसका जांच करना।
- (४) गाव के लिए सहकारा सहायता प्राप्त करना।
- (५) पड़न जमान को सेवी के काम में लेने का व्यवस्था करना।

(६) कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से खेती करने के तरीकों के बारे में कम से कम एक स्टैंडर्ड कायम करना जिसके अनुसार गांव के सब लोग काम करें।

(७) जिस जमीन के मालिक अपनी जमीन पर खेती नहीं करते हैं उस पर खेती करने की व्यवस्था करना।

(८) इनाम तथा दूसरे प्रोत्साहन देकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करना।

(९) अधिक पैदावार वाले खाद्यान्न की खेती को बढ़ाना।

(१०) सार्वजनिक हित के कामों के लिये स्वयंसेवकों का संगठन करना जो ऐसे कामों को अपनी इच्छा से करने को तैयार हों।

(११) गांव के हाथ के उद्योग में लगे कारीगरों को कितने कच्चे माल की आवश्यकता है इसका अन्दाज लगाना और उसका प्रबन्ध करना।

(१२) अतिरिक्त अनाज को 'प्रोक्योर' करने और बेचने में मदद करना।

ऊपर के विवरण से यह साफ हो जाना चाहिये कि गांव उत्पादन परिपक्व का काम गांव के सब प्रकार के किसानों की सहायता करना और उत्पादन बढ़ाने में उनकी मदद करना होगा—फिर चाहे वे व्यक्तिगत रूप से खेती करने वाले किसान हों, या सहकारी खेती समिति के सदस्य हों या रजिस्टर्ड फार्म पर खेती करने वाले हों। कृषि योजना का सारा आधार और उसे अमल में लाने का सारा जिम्मा ही इन गांव उत्पादन परिपक्वों का होगा। उत्पादन का किस गांव में क्या लक्ष्य होना चाहिये उसका प्रस्ताव गांव वाले अपनी इसी परिपक्व के द्वारा करेंगे और यही परिपक्व उस लक्ष्य को पूरा कराने का एकमात्र साधन होगी।

प्लानिंग कमीशन ने भूमि सुधार और कृषि उत्पादन को बढ़ाने को जो उपरोक्त तात्कालिक कार्यक्रम पेश किया है वह स्वागत करने लायक है। गांव उत्पादन परिपक्वों के जरिये गांव वालों को उत्पादन के काम में जिम्मेदार बनाया जा सकेगा। रजिस्टर्ड फार्मों से हम यह आशा रख सकते हैं कि वैज्ञानिक उत्पादन का गांव में वे एक आदर्श उपस्थित करेंगी और गांव वालों के मन पर बड़े खेतों पर खेती करने के लाभ को अंकित करने का यह एक अच्छा प्रयास होगा। इससे सहकारी खेती समितियों और भूमि की चकबन्दी के काम को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना में केवल इतना और जोड़ने की आवश्यकता है कि गांव में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एक बढ़ता हुआ हिस्सा गांव की आवश्यकता को पूरी करने के लिये गांव में छोड़ दिया जायगा और गांव के अतिरिक्त अनाज का अनुमान इसे छोड़ कर लगाया जायगा। इसके अलावा अनाज के 'रिजर्व' बनाने का प्रश्न भी सोचने योग्य है। हर तहसील में एक

अच्छा मोदाम हो जहाँ अकाल व समय के लिये अनान मुरखि रखा जा सके। बंदे हुये उत्पादन का एक हिस्सा इसक लिय मुरखि रखा जाये। इनकी व्यवस्था गाव उत्पादन परिषद् व हाथ म और सरकार का देम रेख में रहे। मोदाम बनाने का जिम्मा गाव वालों पर छोड़ा जाना चाहिये। सरकार इसम मदद दे सकती है और आवश्यक माम दर्शन कर सकती है। गाव उत्पादन परिषद् को अधिक प्रतिनिधायक गा बनाया जा सकता है और उसने कार्यक्षेत्र को थोड़ा बिल्टन भी किया जा सकता है। इस दृष्टि से इसका नाम उत्पादन परिषद् व स्थान पर आर्थिक परिषद् रखना उचित हो सकता है। लक्ष्य हमारा यह जाना चाहिय कि आगे चलकर यह परिषद् गाव व समस्त आर्थिक जीवन की ढल रेख करने वाली परिषद् बने, क्योंकि गाव का आर्थिक जीवन एक अति भाग्य इकाई है और एक ही भगटन द्वारा नियंत्रण और उसकी व्यवस्था करना अधिक सहा होगा। इन परिषदा व कार्यक्षेत्र में गाव के कपड़े की उचित व्यवस्था का तो तुरन्त ही समावेश करना चाहिये ताकि रोटा और कपड़े के दो आधारभूत समालों का ढल करने में तो उसका तुरन्त ही उपयोग हो सके। यह भी विचारने योग्य बात है कि गाव परिषदों व आधार पर नहसाल, बिला प्रान्त और देश-बापा भगटन खड़ा किया जाव ताकि सारे देश के आर्थिक जीवन का समाकरण सम्भव हो सके।

जेलों सम्बन्धी जिन आधारभूत समस्याओं का हमने उल्लेख किया है उनम स जमादारा-जमादारी प्रथा और छोटे छोटे गेनों की समस्या के बारे में प्लानिंग कमिशन व मुफ्त और उनमें क्या क्या गरावन आवश्यक हैं—इस बारे में अब तक लिखा गया है। अब दो आधारभूत समस्याएँ और रह जाती हैं। एक है जेलिहर मजदूर का और दूसरी है जेलों पर जो अतिरिक्त जनसंख्या है उसे कम करन और उन लोगों का दूसरा काम देने का।

जेलिहर मजदूरों की सत्ता, प्लानिंग कमिशन का एसा ख्याल है, मुल प्रामाण जनसंख्या का एक निहाइ भाग है। इनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफी खराब है। पिछले ज्यों में जो किसानों को राहत पट्टाने का दृष्टि स 'टानेला' तथा दूसरे कानून बन रहे, वे मा इन जेलिहर मजदूरों का समस्याओं को प्राय नहा छूते। जब तक हमारा साम्य अर्थ व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं होता, जेलिहर मजदूरों का स्थिति में कोई कदम लावक सुधार करना संभव नहीं है, यह स्वयं प्लानिंग कमिशन का भी राय है। क्योंकि आज तो हालत यह है कि जो जमान का मानिक किसान है उस भी जेलों स पूरा रोजगार नहीं मिलता। इस बारे में प्लानिंग कमिशन ने यह आशा प्रकट की है कि जैसे जैसे

सहकारी गांव प्रबंध का विस्तार होया खेतिहर मजदूर की स्थिति भी सुधरेगी और उसे पूरा काम मिल सकेगा, फिर चाहे वह खेत मजदूर की हैसियत से मिले और चाहे अन्य किसी हैसियत से। पर जब तक ऐसा नहीं होता उन्होंने नीचे दी गई सिफारिशों की हैं :—

(१) राज्यों को उन प्रदेशों में जहां खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बहुत कम हो, १९४८ का न्यूनतम मजदूरी कानून लागू करके उनकी न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर देनी चाहिए।

(२) अनुक मर्यादा से ऊपर के खेतों पर काम करने वाले खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय कर दी जाय। यह मर्यादा रजिस्टर्ड फार्मों की जो मर्यादा तय हो चली हो सकती है। चूंकि बड़े बड़े फार्मों पर खेती व्यापारिक आधार पर होती है, इसलिए उनको अपने मजदूरों को उचित मजदूरी दे सकना चाहिए।

(३) पद्धत भूमि पर राज्य द्वारा संचालित फार्मों की आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद खेती करने की सुविधा सबसे पहले खेतिहर मजदूरों की सहकारी समितियों को देनी चाहिए।

(४) खेतिहर मजदूरों की भलाई के लिए अन्य आवश्यक बातों जैसे मकान बनाने के लिए जमीन, पीने के लिए पानी, शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ आदि की व्यवस्था करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनकी श्रम-मुक्त करने के लिए कानून बनाना चाहिए। उनकी भलाई के और कानून भी बनाये जाने चाहिए।

जहां तक खेती से अतिरिक्त जनसंख्या को हटा कर दूसरा काम देने का प्रश्न है, कमीशन ने इस प्रश्न की गंभीरता को तो स्वीकार किया है। उसने यह भी मंजूर किया है कि सहकारी ग्राम प्रबंध योजना की प्रगति इस बात पर भी निर्भर रहेगी कि जो लोग आवश्यकता नहीं होने से खेती के काम से निकल जाते हैं उनके लिए और कोई काम की व्यवस्था है या नहीं। यह भी ठीक है कि प्रधानतः उद्योग धर्मों और उनमें भी खास कर कुटीर उद्योग धर्मों के विकास के अलावा इस अतिरिक्त जनसंख्या को काम देने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्लानिंग कमीशन ने कुटीर उद्योगों के इस महत्व को स्वीकार किया है और उनके विकास के लिए कई सुझाव भी पेश किये हैं। पर खेती में जिसकी जरूरत नहीं है ऐसी अतिरिक्त जनसंख्या को और कोई काम देने की समस्या का आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग ने अध्ययन नहीं किया है। उसने यह अनुमान नहीं लगाया है कि अन्य धर्मों का जितना विकास होया उसको देखते हुए इस समस्या का कहां तक हल हो सकेगा और पांचों धर्मों की योजना अगर अमल

में आ जानी है तो हमारे देश की जनसंख्या का विभिन्न धर्मों और पेशों में कैसा बंटवारा होगा। यहाँ यह ध्यान में रखने की बात आवश्यक है कि आर्थिक विकास के साथ साथ उद्योग धर्मों के अलावा दूसरे पेशों में भी—फिर चाहे वह श्रमिक से सम्बन्ध रखते हों, या वाणिज्य व्यापार से, या यातायात तथा ऐसी ही दूसरी सेवाओं से—काम करने वालों की संख्या क्रिश्चैष्टिक बढ़ेगा।

देश की कृषि व्यवस्था का जो स्वरूप प्लानिंग कमीशन ने उपस्थित किया है, और भूमि व्यवस्था में सुधार करने के जो मुद्दा उठाने रखे हैं वे, हमारी आज की खेती की गिरी हुई अवस्था को सुधारने में सहायक होंगे। उन संशोधनों के साथ जो ऊपर सुझाव गये हैं इस आधार पर कृषि व्यवस्था का जो नया ढांचा खड़ा होगा वह आर्थिक दृष्टि में अधिक सफल और सामाजिक दृष्टि में अधिक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील होगा। पर यहाँ एक बात याद दिलाना आवश्यक है। निम्ना देश में सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था का उसकी कृषि व्यवस्था एक अंग मात्र होता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग उद्योग धर्मों से सम्बन्ध रखता है। किसी भी देश का आर्थिक व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से सफल और सामाजिक दृष्टि से न्यायपूर्ण और प्रगतिशील तभी हो सकती है जब उसके समस्त अंग प्रत्यंगों का संगठन इस आधार पर हो। कृषि और उद्योग धर्मों के अलावा वाणिज्य व्यापार, बैंकिंग, यातायात, इन्फ्रेस्ट्रक्चर आदि आर्थिक व्यवस्था के अन्य अंगोपांग हैं। पर हम यहाँ केवल औद्योगिक व्यवस्था के बारे में ही विचार करेंगे। देश के आर्थिक संगठन का आधार कृषि और उद्योग इन दो स्तम्भों पर ही खड़ा रहता है। जब तक दोनों स्तम्भ स्वस्थ नहीं हों, अन्य आर्थिक व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता, और न केवल किसी एक स्तम्भ के स्वस्थ होने का लाभ ही समाज को मिल सकता है।

औद्योगिक उन्नति की आवश्यकता हमारे देश का अर्थ व्यवस्था का एक बड़ा दोष यह है कि कृषि के अलावा दूसरे धर्मों में बहुत कम लोग लगे हुए हैं। कृषि की सफलता पर ही हमारा सारा आर्थिक ढांचा खड़ा है। इस स्थिति में सुधार करने के लिए एक ओर तो खेती उद्योग को उन्नत बनाना होगा और दूसरी ओर उद्योग धर्मों का प्रसार करना होगा जैसा कि पहले लिखा भी जा चुका है। अब इस तक ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। बिना उद्योग धर्मों के विस्तार के खेती पर जो आय सम्पत्ति से अधिक लोग निर्भर हैं उनको यहाँ से हटा कर दूसरा काम नहीं दिया जा सकता। और बिना खेती की उन्नति के उद्योग धर्मों के लिए न कच्चे माल की और न तैयार माल की स्वयं की ही समस्या का कोई सन्तोषजनक हल हो

सकता है। देश की सुरक्षा का प्रश्न भी उद्योग धन्धों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश के औद्योगिक विकास की बढ़ी जरूरत है। प्लानिंग कमीशन के इस चारे में जो प्रस्ताव हैं उन पर अब विचार किया जायेगा।

आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय का महत्व : उद्योग धन्धों से सम्बन्ध रखने वाले दैते तो छोटे मोटे कई सवाल हैं। पर यहाँ कुछ बड़े और आंतरभूत सवालों पर ही विचार किया जायगा—उन सवालों पर जिनका सम्बन्ध इस बात से है कि देश में प्लानिंग कमीशन की सिफारिशों के अनुसार जो औद्योगिक व्यवस्था का स्वरूप बनेगा उसमें आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए कहाँ तक गुंजायश हो सकेगी। आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के महत्व को स्वीकार करते हुए स्वयं प्लानिंग कमीशन ने लिखा है :—“हमारे देश में सम्पत्ति और आय का वर्तमान बँटवारा असन्तोषजनक है और उसमें विभिन्न वर्गों के बीच में अपेक्षाकृत अधिक समानता लाना सामाजिक न्याय के लिये तो जरूरी है ही, पर देश के उत्पादन के साधनों का पूरा पूरा उपयोग करने के लिए भी यह आवश्यक है। जनतंत्र के अस्तित्व के लिये आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय का होना अनिवार्य है। किसी भी योजना की अनिवार्य शर्त यह है कि आय और सम्पत्ति की असमानता को मिटाने के लिए अच्छी तरह से सोची हुई नीति को अपनाया जाय।”

आर्थिक संगठन का रूप कैसा हो : इस बात को सब स्वीकार करते हैं कि उद्योग धन्धों का संचालन अगर पूरी तीर से पूंजीपतियों के हाथ में छोड़ दिया जाय तो उससे आम जनता की भलाई नहीं हो सकती। पूंजीपति अपना सारा कारोबार अपनी लाभ हानि को धामने रख कर चलाते हैं। अपना लाभ कमाने के लालच में न तो उन्हें समाज की जरूरत का ध्यान रहता है और न इस बात का कि जो मज़दूर वर्ग उनके कारखानों में काम करते हैं उनका शोषण न किया जाए। इसी की पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं जो आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय को जन्म देती है, उन्हीं के आधार पर वह पनपती है और आखिरकार उन्हीं के कारण उसका अन्त भी होता है। पूंजीवाद के दोषों को मिटाने के लिए एक दूसरी व्यवस्था की कल्पना की गई है। इस व्यवस्था का आधार यह है कि उद्योग धन्धे तथा उत्पादन के दूसरे काम पूंजीपतियों पर न छोड़े जायें ; उनकी व्यवस्था राज्य करे। राज्य समाज की प्रतिनिधि संस्था होने से समाज की भलाई की दृष्टि से सारे कारोबार को चलायेगा ; उसे मुनाफ़ा कमाने का लोभ नहीं होगा ; मज़दूरों का शोषण नहीं होगा आदि। इसी को समाज-

वादी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था की पूँजीनियों और ठाकुर समर्थकों ने यह कहकर आलोचना की कि राज्य इन कामों को नहीं कर सकता। इन कामों को करने की उसके पास योग्यता नहीं हो सकता। उसके पास आवश्यक साधन भी नहीं जुट सकते। राज्य के पास इतनी शक्ति जमा हो जायेगा जिसका वे लोग जो राज्यतन्त्र की चलाते वाले होंगे दुष्टयोग करेंगे यानी जनता की आज़ादी नष्ट हो जायेगा। अर्थात् जनतन्त्र और समाजवाद का मेल नहीं है। पर यह आपत्ति इनकी सही नहीं है, यह बात आज प्रायः सब जानकार और अनुभवी लोग मान कर रहे हैं। इसमें जिनका या न्यून है उसका इलाज या बिना पूँजीवाद को कायम रखते और उठाया स किया जा सकता है। इसलिए पूँजीवाद को बनाये रखने के लिए यह दलील देना कि समाजवाद स्वतन्त्रता के लिए घातक होगा, ईमानदारी की बात नहीं है। इंग्लैंड ने समाजवाद अथ व्यवस्था के या राज्य द्वारा उद्योग धर्मों को चलाने में विरुद्ध आज तो सबसे बड़ी दलील यही दी जाती है कि राज्य इस काम को कर नहीं सकता। हमारे देश में तो जबसे हम आज़ाद हुए हैं इस दराल का बहुत प्रचार हुआ है। कई ईमानदार आदमी भी आज इससे बेग़ार हट कर प्रभावित हैं। यहाँ तो यह और कहा जाता है कि भारत के सामने तो मुख्य आर्थिक समस्या उत्पादन की है, वितरण की नहीं। भारत एक ग़रीब देश है। राज्य के पास या साधन कम हैं और काम ज्यादा है। कुछ काम ऐसे हैं जो राज्य के ही करने के हैं—जैसे यातायात, सिंचाई, विद्युत्-शक्ति आदि की योजनाओं को कार्यान्वित करना। ऐसी हालत में राज्य को अपने साधनों का उपयोग इन ज्यादा जरूरी कामों को करने में करना चाहिये न कि उन उद्योग धर्मों का राष्ट्रीयकरण करने में जो मजदूरी वाला रत हैं या उन नये उद्योगों को शुरू करने में जिनको पूँजीपति बना सकते हैं। इसके साथ एक तर्क और उपस्थित किया जाता है कि सरकार का भ्रष्टाचार और उसके कर्मचारियों का इस योग्य नहीं है कि उद्योग धर्मों को चला सकें। उनके हाथ में अगर यह काम जायेगा तो सारा कारोबार ध्वस्त हो जायेगा। पर ये सब तर्क करने वाले लोगों में सामने भी यह सवाल तो रह जाता है कि अगर पूँजीपतियों ने हाथ में सारा कारोबार छोड़ दिया जायेगा तो समाज का ज़रूरतें पूरा नहीं होंगी, समाज में शोषण कायम रहेगा, आर्थिक असमानता बढ़ेगी और सामाजिक न्याय का अभाव रहेगा। हमने जवाब में आज यह यह कहते हैं कि राज्य को उन पर नियंत्रण रखना चाहिये। इससे अलावा कुछ उद्योग धर्मों को चलाने का जिम्मा भी स्वयं राज्य लेले। पर यह उद्योग धर्म ऐसे हों जिनमें पूँजीपति वर्ग को बहुत दिलचस्पी न हो और राज्य का कारोबार

कुछ मिलाकर इतना न पैल जाय कि पूंजीपति वर्ग और व्यक्तिगत व्यवसाय के लिये यथेष्ट अवसर ही न रहे। इसीको आज मिलीजुली अर्थ व्यवस्था (मिक्स्ड इकोनोमी) का नाम दिया जाता है जिसमें राज्य और पूंजीपति दोनों का ही अर्थ व्यवस्था के संचालन में मिलाजुला हाथ रहता है और दोनों के ही कार्यक्षेत्र निश्चित होते हैं।

प्लानिंग कमीशन मिलीजुली अर्थ व्यवस्था में पक्ष में लगभग उपरोक्त धलीलों से प्रभावित होकर ही प्लानिंग कमीशन ने भी मिलीजुली आर्थिक व्यवस्था के पक्ष में ही अपनी राय दी है। औद्योगिक उन्नति संबंधी उसके सुझाव इसी प्रकार की अर्थ व्यवस्था की देश में स्थापना करने के लक्ष्य से किए गए हैं। एक जगह प्लानिंग कमीशन ने लिखा है—“योजना को कार्यान्वित करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि उत्पादन साधनों का करीब करीब पूरी तौर से राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये, उनका किन किन कामों के लिये उपयोग करना है इस पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो, और राष्ट्रीय आय के बंटवारे पर भी सरकार का नियंत्रण रहे। योजना को अमल में लाने का यह एक बहुत ही सफल तरीका भालूम पड़ सकता है। पर व्यवहारिक दृष्टि से आर्थिक मामलों में सरकार के कार्यक्षेत्र का इतना विस्तार करना न आवश्यक है और न उचित ही।” आगे चलकर कमीशन का कहना है—“जनतंत्रीय समाज में योजना को कार्यान्वित करने के लिये देश के उत्पादन साधनों का नया बंटवारा करने में कम से कम जबरदस्ती की जानी चाहिये। राज्य के पास इस समय जो साधन हैं उनका उपयोग नए कामों को जारी करने में करना चाहिये न कि मौजूदा उद्योग धंधों और उत्पादन साधनों का राष्ट्रीयकरण करने में। कुछ कामों में उत्पादन साधनों पर राज्य का स्वामित्व होना जरूरी हो सकता है और कुछ में राज्य का नियंत्रण ही काफी हो सकता है। व्यक्तिगत व्यवसाय का उत्पादन और वितरण दोनों में ही बड़ा हिस्सा रहने वाला है। वर्तमान परिस्थितियों में योजना का अर्थ है ऐसी अर्थ व्यवस्था कायम करना जिसका मार्ग दर्शन और नियंत्रण राज्य के हाथ में हो पर उसके अन्तर्गत कारोबार को चलाने का काम थोड़ा राज्य और थोड़ा व्यक्तिगत रूप से व्यवसायियों के हाथों में रहे।” प्लानिंग कमीशन ने व्यक्तिगत व्यवसाय और राज्य के बीच में कार्यक्षेत्र का बंटवारा करने के जो सुझाव दिये हैं उनका सार यह है कि कृषि, सिंचाई व विद्युत-शक्ति संबंधी योजनाओं का बिम्बा राज्य पर डाला गया है और औद्योगिक क्षेत्र बहुत कुछ पूंजीपति वर्ग के लिये खुला छोड़ दिया है। इसका कारण राज्य के पास उत्पादन साधनों की कमी बताई गई है। इस विषय में प्लानिंग कमीशन के ये शब्द

उल्लेखनीय हैं—“चूँकि विकास के लिये जो उपलब्ध साधन हैं वे सीमित हैं और चूँकि इष्टि उत्पादन को बढ़ाने वाले कार्यों की योजना में सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है, इसलिये औद्योगिक विस्तार के लिये जो साधन बचते हैं, वे बहुत कम हैं।” इसी बात का समर्थन करते हुए प्लानिंग कमीशन ने शून्यत्र लिखा है —

‘चूँकि जो उत्पादन साधन राज्य को उपलब्ध हो सकते हैं, उनका अधिकांश भाग ऊँचि, सिंचाई तथा शक्ति व विकास में लग जायगा, इसलिये उद्योग पधों में अधिक रकमा लगाना राज्य के लिये संभव नहीं हो सकेगा।’ साधनों का कमी व अभाव प्लानिंग कमीशन ने मिलीजुली अर्थ व्यवस्था के पक्ष में कृत्रिम कारण यह बताया है कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन करने योग्य कर्मचारी वर्ग भा राज्य के पास नहीं है। इस संबंध में प्लानिंग कमीशन ने लिखा है—‘व्यक्तिगत व्यवस्था में संबंध में जिस मानि को अपनाने का हमने प्रस्ताव किया है उनका आधार नब्बल यह नहीं है कि राज्य के पास अधिक साधनों का कमी है। एक कारण यह भी है कि जो कुछ मुश्किल हमने रखा है उससे अधिक कर सकने के लिये राज्य सरकार के पास आन्तरिक योग्यता के कर्मचारी भी नहीं हैं।’ यह दस्तावेज कोइ प्लानिंग कमीशन न हो पहला बार दा हो, ऐसी बात नहीं है। जब से देश हमन हुआ तब से पूँजीपति और व्यवसायी वर्ग तथा उनके समर्थकों का और से लगातार यह बात कही जा रही है कि अर्थ व्यवस्था का संचालन करने की समता राज्य ने सामने रखा में नहीं है। इस तर्क का देश में बहुत योजना पूर्वक प्रचार हुआ हो, ध्यान पूर्वक सावने पर कुछ इस प्रकार की आशंका भा होती है।

मिलीजुली अर्थ व्यवस्था की सफलता का आधार उपरोक्त त्रिवेकन से यह साफ हो जाता है कि प्लानिंग कमीशन न देश में मिलीजुली व्यवस्था के पक्ष में अपनी राय क्यों दा। राज्य के पास पर्याप्त आर्थिक साधन का अभाव और योग्य कर्मचारियों का कमी, ये दो मुख्य कारण हैं जो मिलीजुली अर्थ व्यवस्था के पक्ष में राय देने में प्लानिंग कमीशन के सामने रहे हैं। पर इन दो कारणों के अलावा एक और कारण भी प्लानिंग कमीशन के सामने रहा है, हालांकि उसका बहुत साफ साफ उल्लेख नहीं किया गया है। यह कारण यह रहा है कि जनमत में कोई योजना अभी सफल हो सकता है जब उसमें कम से कम राज्य का दबाव हो। उनका आशय संभवतः यह है कि व्यवसायी वर्ग को प्रसुप्त और नाराज करके किसी अर्थ व्यवस्था को न तो कायम करना ठीक हो सकता और न उसका सफलता पूर्वक संचालन ही हो सकता है। सफल योजना के लिये जो राजनैतिक और व्यवस्था संबंधी शर्तें गिनाई हैं, वे ये हैं —

(१) समाज में उद्देश्य के बारे में अधिक से अधिक एकमतता ।

(२) जनता के सहयोग के आधार पर प्राप्त, राज्य के हाथ में वास्तविक शक्ति, और उद्देश्य पूर्ति के लिये इस शक्ति का राज्य द्वारा उपयोग ।

(३) कार्यक्रम और योग्य शासन तंत्र ।

यैसे तो इन तीनों ही शर्तों का पूरा होना आवश्यक है । पर जो पहली शर्त है कि समाज में योजना के उद्देश्य के बारे में एकमतता होनी चाहिए उसका यदि कोई व्यावहारिक अर्थ हो सकता है तो वह यही हो सकता है कि सामान्यतया जिन लोगों के विरोध की आशंका ऐसे प्रश्नों पर हो सकती है उनके विरोध को कम किया जाये । आम जनता के लाभ की यदि कोई योजना बनती है तो उसके प्रति विरोध की आशंका उन वर्गों की ओर से ही हो सकती है जिनका स्वार्थ आम लोगों के स्वार्थ से टकरा सकता है । इन वर्गों में आज पूँजीपति वर्ग की प्रधानता है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि पूँजीपति वर्ग का विरोध न हो, ऐसी योजना ही सफलतापूर्वक चल सकती है, ऐसा बहुत करके प्लानिंग कमीशन का मानना है ।

प्लानिंग कमीशन ने जगह-जगह मिलीजुली अर्थ व्यवस्था की सफलता किस बात पर आधारित है इस बारे में जो कुछ लिखा है उससे भी इस बात का समर्थन होता है कि प्लानिंग कमीशन पूँजीपति वर्ग के सहयोग का कितना महत्त्व मानता है । प्लानिंग कमीशन एक जगह लिखता है “व्यक्तिगत व्यवसाय के क्षेत्र में इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर है कि व्यवसायी कितना प्रयत्न स्वयं करते हैं ।” आगे चलकर कमीशन कहता है “योजनावाद अर्थ व्यवस्था का अर्थ ही यह है कि राजकीय व्यवसाय (पब्लिक सेक्टर) और व्यक्तिगत व्यवसाय (प्राइवेट सेक्टर) में अधिकाधिक सामंजस्य हो । एक दूसरी जगह कमीशन लिखता है “योजनावाद आर्थिक व्यवस्था में व्यक्तिगत व्यवसाय को अपने नये कर्तव्य को समझना होगा और देश के व्यापक हित में नए प्रकार का अनुशासन अपने पर लगाना होगा ।” इसी का स्पष्टीकरण करते हुए कमीशन फिर लिखता है “व्यक्तिगत व्यवसाय के स्वस्व को आज के उसके स्वल्प से बहुत भिन्न होना पड़ेगा । उसके समूचे दृष्टिकोण में एक नयापन लाना होगा । सामाजिक और आर्थिक नीति संबंधी उद्देश्यों को तो व्यक्तिगत व्यवसाय को स्वीकार करना ही होगा । पर इसी के साथ भयदूर, उपमोक्षा और विनियोग करने वाले (इन्वेस्टर) के प्रति भी उसे कर्तव्य को मंजूर करना होगा ।” इन उद्धरणों से यह प्रकट हो जाता है कि व्यक्तिगत व्यवसाय के सहयोग के बिना, और उसके द्वारा समाज के व्यापक हित के दृष्टिकोण को बढ़ाते बिना, मिली-

जुलो अर्थ व्यवस्था सफल नहीं हो सकती, यह बात प्लानिंग कमीशन ने साफ कर दी है।

सरकार का नियंत्रण आवश्यक क्या व्यक्तिगत व्यवसाय और पूँजी पनि वगैरहों दृष्टिकोण को बदल लेगा ? क्या जनता की व्यापक हित की जो योजना होगा उसमें उनका सहभाग मिल सकेगा, चाहे उसने उनसे स्थापों पर हा क्यों न आपात पहुँचता हो ? इस बारे में प्लानिंग कमीशन को मरोसा नहीं है। उसने निम्न है 'किन्ना निश्चिन्ता व साथ यह नहीं कहा जा सकता कि व्यक्तिगत व्यवसाय का जो योजना न था है उसमें पास्त्र में कितनी प्रगति हो सकेगा। कुछ उद्योगों व भाषा विकास व कार्यक्रम का मोटा रूपरेखा का दिशा का समत मान किया जा सकता है।' यही तो कारण है कि व्यक्तिगत व्यवसाय पर सरकारी नियंत्रण का आवश्यकता को कमेशन मानना है। उसने यह सिफारिश की है कि इस सम्बन्ध का जो कानून संसद के विचारामान है उसे जल्द से जल्द पास करना चाहिये।

नियंत्रण व उद्योग 'व्यक्तिगत व्यवसाय पर नियंत्रण रखने के लिए प्लानिंग कमीशन ने जिन कानूनों को पास करने का आवश्यकता समझा है, उसकी मुख्य मुख्य बातें प्लानिंग कमीशन का राय में यह होनी चाहियें —

(१) फ़ैक्ट्रीय सरकार स लाइसेन्स प्राप्त बिधे बिना न तो कोई नया औद्योगिक कारोबार आरम्भ किया जाये और न मौजूदा कारोबार में बिस्तार किया जाये। लाइसेन्स देते समय इसे कारखानों का जहाँ तक सम्बंध है, भारत सरकार उन्हे स्थान और उनका 'साइज' आदि के बारे में शर्तें लगा सकेगी।

(२) सरकार को यह अधिकार होगा कि यह नाचे बनाये गये उद्योगों या उन उद्योगों व किन्हीं कारखानों को बन्द पड़ताल कर सके — (i) जिनका उत्पादन या माल का प्रकार गिरता जाता हो या गिरने का प्रवृत्ति हो, (ii) जो राष्ट्र भर का दृष्टि से महत्त्व रखने वाले प्राङ्गिक साधनों का उपयोग करते हैं और (iii) जिनका प्रबंध इस तरह से हो रहा हो कि हित्सेधर्तों या उपभोक्ताओं के हितों को हानि होने की निशाने आसना हो। सरकार को जांच पड़ताल करने के बाद आवश्यक हिदायतें जारी करने का अधिकार तो होगा ही।

(३) जो उद्योग घड़े सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों का पालन करने में असमर्थ रहें उनको सरकार प्रबंध और नाति सम्बंधानों में सुधार करने के लिए अपने प्रबंध में ले सकेगा।

कमीशन ने यह भी सिफारिश का है कि उपरोक्त अधिकारों का उपयोग

सरकार की ओर से एक ऐसा तीन व्यक्तियों का केन्द्रीय बोर्ड करे जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये और जिस के सदस्यों को औद्योगिक, व्यापारिक, टेकनिकल, न्याय और शासन सम्बन्धी मामलों का काफी अनुभव हो। कमिशन ने यह भी साफ कर दिया है कि तमाम महत्वपूर्ण उद्योग धन्धों पर उपरोक्त नियन्त्रण लागू होना चाहिये।

कमिशन ने व्यक्तिगत व्यवसाय को योजना के अनुसार चलाने के लिए कानूनी नियंत्रण के अलावा एक और उपाय भी सुझाया है। सुझाव यह है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण उद्योग के लिए एक विकास परिषद् (डेवलपमेंट कांसिल) का संगठन किया जाये। इन परिषदों को सरकार नियुक्त करे और उनमें उद्योग मजदूर और टेकनिकल मेनेजमेंट के प्रतिनिधि हों। इन परिषदों का काम उन तमाम समस्याओं का विचार करना होगा जो इस उद्योग विशेष के सम्बन्ध में पैदा हों—जैसे उत्पादन कितना किया जाय, इसका लक्ष्य निर्धारित करना, कार्य क्षमता (एफीशियेंसी) की नाप के लिए मापदण्ड तय करना, उद्योग और खासकर कम कार्य क्षमता वाले कारखानों की कार्य पद्धति में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव करना, और किसी तथा वितरण की ऐसी व्यवस्था करने में सहायता देना जिससे कि उपभोक्ताओं को सन्तोष हो।

प्लानिंग कमिशन का यह भी मानना है कि पूँजी के विकासन (कैपिटल इश्यू), विदेशी विनिमय के उपयोग और आयात-निर्वाह और, मुख्य भाषि पर भी सरकार को नियन्त्रण रखना होगा।

ऊपर जो कुछ लिखा जा चुका है उससे यह साफ हो जाता है कि मिली-जुली अर्थ व्यवस्था के सफल संचालन के लिए व्यक्तिगत व्यवसाय के सहयोग के साथ साथ उस पर किस सीमा तक नियन्त्रण रखना होगा। अब प्रश्न यह है कि क्या मिली-जुली आर्थिक व्यवस्था से जनता के आर्थिक हितों की रक्षा हो सकती है और क्या इस तरह की अर्थ व्यवस्था इस दृष्टि से सफल हो सकती है ? इसी के साथ यह सवाल भी लग्न हुआ है कि जिन कारणों से मिलीजुली आर्थिक व्यवस्था के पक्ष में प्लानिंग कमिशन ने अपनी राय बनाई है क्या वे कारण वास्तव में ठीक हैं ?

मिलीजुली अर्थ व्यवस्था ठीक नहीं : जिस मिलीजुली अर्थ व्यवस्था का प्लानिंग कमिशन ने समर्थन किया है उससे आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की वास्तव में स्थापना हो नहीं सकती। ऐसा क्यों ! बहुत तात्त्विक दृष्टि से यदि विचार किया जाये तो कोई भी व्यवस्था हो, आखिरकार वह उसके संचालकों की भावना पर बहुत कुछ निर्भर

करती है। इस दृष्टि से यह कल्पना हो सकती है कि पूँजीवादी व्यवस्था भी शोषण-मुक्त हो जाये अगर पूँजीपति वास्तव में जनता के हित में उस व्यवस्था को चलावे। पर बात वास्तव में यह है कि व्यक्ति अपने व्यवहार में पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होता। जिस परिस्थितियों में अगर जिस व्यवस्था के अन्तर्गत वह काम करता है उन परिस्थितियों और उस व्यवस्था के नियमों का असर उस पर पड़ता है और उसके आनन्दन बहुत कुछ उनका आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पूँजीवादी व्यवस्था जाना कि गन्धे दिनों की रक्षा करने में इस-लिए असमर्थ नहीं है कि जिन्हे पूँजीपति हैं वे सब दूरे व्यक्ति हैं और उनके स्थान पर अगर किसी दूसरे भले व्यक्तियों को पूँजीवादी व्यवस्था का संचालक बना दिया जाय तो सारे सवाल हल हो जायेंगे। जब तक पूँजीवादी व्यवस्था मौजूद है, जो व्यक्ति भा उससे अभ्यस्त व्यवसाय, व्यापार आदि करेगा उसे उस व्यवस्था के जो अपने नियम हैं उनका अनुसरण ही करना होगा इसलिए वह उन सब लोगों का भागीदार होगा जो पूँजीवाद के दोष माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था का सारा कारोबार व्यक्तिगत लाभ को सामने रखकर चलता है। और जब तक अर्थ व्यवस्था का यह आधार बना रहता है तब तक उसमें जनहित की आशा नहीं की जा सकता। इसलिये यदि हम जन कल्याण की दृष्टि से आर्थिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो हम पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना ही होगा।

अब रहा सवाल मिताजुला आर्थिक व्यवस्था का। इस बारे में विचार-शील प्रश्न यह है कि एक दृष्टि से तो वास्तव में कोई व्यवस्था मिताजुली अर्थ व्यवस्था नहीं हो सकती, और दूसरी दृष्टि से हर एक व्यवस्था मिताजुली अर्थ व्यवस्था ही होती है। किसी भा अर्थ व्यवस्था को हम लेते, देखते की बात यह है कि उसमें प्रधानता किस तत्व की है। या तो किसी व्यवस्था में व्यक्तिगत व्यवसाय की प्रधानता होगी या उसका प्रधानता नहीं होगी। यह तो असमय है कि किसी भी तत्वों की एक साथ प्रधानता हो। निम्न मिताजुली अर्थ व्यवस्था की प्लानिंग एमीशन ने सिफारिश की है और निष्कर्ष हम इनकी चर्चा सुनते हैं वह वास्तव में पुरी अर्थ व्यवस्था है जिसमें व्यक्तिगत व्यवसाय की प्रधानता रहने वाली है। इसलिए इस प्रकार की मिताजुली व्यवस्था तबत पूँजीवादी व्यवस्था ही है, और यदि पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय समझ नहीं है तो इस प्रकार की मिताजुली व्यवस्था में भी समझ नहीं हो सकता। हाँ, यदि ऐसी मिताजुली आर्थिक व्यवस्था कायम की जाय जिसमें प्रधानता राजकीय या सहायिता के

आधार पर संगठित व्यवसाय की हो, और आर्थिक जीवन का एक संचालन व्यक्तिगत व्यवसाय और पूँजीपतियों के हाथ में न हो, तो बात दूसरी है। पर ऐसी मिलीजुली व्यवस्था का प्रश्न तो हमारे सामने है नहीं।

उपरोक्त विवेचन से यह भी साफ हो जाता है कि हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि जब तक समाज में पूँजीवादी व्यवस्था का तत्त्व प्रधान रहता है तब तक पूँजीपति वर्ग उस व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध जन कल्याण की दृष्टि से आचरण करेंगे। दूसरे शब्दों में यह असंभव है कि एक ओर तो पूँजीवादी तत्त्वों की इस प्रधानता बनाये रखें, और दूसरी ओर पूँजीवादी व्यवस्था के नियंत्रण में हमें उन्हीं तत्त्वों का सहयोग भी मिले। भारतवर्ष का पिछले चार वर्षों का हमारा यही अनुभव है। कॉंग्रेसी सरकारों ने बराबर व्यावहारिकता के नाम पर देश के पूँजीपति और व्यवसायी वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया है पर उसका उल्लेखनीय अंतर पूँजीपति वर्ग के रवैये पर पड़ा हो ऐसा नहीं लगता। इसके विपरीत वास्तव में स्थिति यह है कि पूँजीपति वर्ग सरकार के साथ बराबर एक छिपी लड़ाई लड़ता रहा है और जब राष्ट्रीयकरण का या व्यक्तिगत व्यवसाय के नियंत्रण का जहाँ भी प्रश्न उपस्थित होता है वह विरोध और असहयोग उपस्थित करता है। जब उनको यह विश्वास हो जायगा कि अब उनकी सर्वथा विजय होगई है, जैसी कि प्रायः हो चुकी है, तभी वे राष्ट्र की उत्पादन शक्ति का पूरा पूरा उपयोग करने में अपना सहयोग देने वाले हैं। पर यह हम जानते हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत जो भी उत्पादन होता है, उसका समान उपयोग सर्व साधारण को नहीं मिलता, और इसलिए उनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो सकता।

क्या व्यक्तिगत व्यवसाय का नियंत्रण संभव है? : अब दूसरा प्रश्न यह रह जाता है कि जिस हद तक पूँजीपति का सहयोग नहीं मिलेगा उस हद तक राज्य व्यक्तिगत व्यवसाय का देश के हित में नियंत्रण करेगा। मिलीजुली अर्थ व्यवस्था के समर्थक इसी बात पर बहुत आधार रखते हैं। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, प्लानिंग कमीशन ने भी इस बात पर अपना आधार माना है, और इस संबंध में शीघ्र एक व्यापक कानून पास करने की उसने सिफारिश की है। प्रश्न यह है कि क्या यह नियंत्रण व्यवहार में संभव हो सकेगा? थोड़ा सा विचार करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि यह संभव नहीं हो सकता। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाज में जो वर्ग प्रतिष्ठित और प्रमुखशाली होता है उस पर राज्य और राज्य कर्मचारियों का वास्तव में कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। सामंतशाही समाज व्यवस्था में अगर कोई सामंतों का वास्तव में नियंत्रण कर

सकना समान मानता हो, तो पूँजीवाद प्रधान समाज व्यवस्था में, फिर नान उसका कुछ भी हो, पूँजीपतियों का भी नियन्त्रण हो सकता है। अगर पहली बात असम्भव है तो दूसरा बात और भी अधिक असम्भव है क्योंकि पूँजीवाद के काम करने के लिये अधिक परीक्षा होने है। दूसरा बात यह है कि किसी भी व्यवस्था का बाहर में नियन्त्रण करना ज्यादा कठिन होता है और उसका साथ सफल करना अपेक्षाकृत अधिक आसान होता है। प्लानिंग कन्ट्रोल में नियन्त्रण संवर्धित जिस कानून का विचार किया जा है उसमें राज्य को उद्योगों का जांच पड़ताल करने और आवश्यकता ज्ञान पर उनका सरकार के प्रबंध में ले लेने तक का अधिकार होगा। पर क्या सरकार वास्तव में इन अधिकारों का उपयोग कर सकेगा? हमारा आज तक का अनुभव हम ऐसा समझ हो सकेगा यह नहीं बताता है। हमारे देश का हा एक राजा उदाहरण भारत सरकार द्वारा नियुक्त 'इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कमीशन' का है। आज यह बात जाहिर है कि 'इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कमीशन' को आयकर में चोरी करने वाले पूँजीपतियों से समझौते करने पड़े हैं। कानून के अन्तर्गत अपने स्वयं में सफल नहीं हो सका है। जो व्यक्ति इन बातों से थोड़ा भी परिचित रहता है उसे मालूम है कि सरकारी अधिकारी वास्तव में व्यापारियों और व्यवसायियों को मन्त्रियों को कहा कह सकते हैं। विपणन उद्योग में वास्तव में कितना लाभ है, उसके संचालन में कहा कहाँ कितना खर्च है, इसका पूरा पता बाहर में सच्चे से सच्चे और ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति नहीं लगा सकते। इस सबका साथ यह आता है कि राज्य के जिस नियन्त्रण पर मिलीजुली अर्थ की सफलता व्यवस्था का आधार माना जाता है वह नियन्त्रण राज्य इस तरह की अर्थ व्यवस्था में कर ही नहीं सकता। इसके अलावा एक तीसरा कारण और है।

बात यह है कि पूरी अर्थ व्यवस्था अपने आप में एक स्वयं संपूर्ण इकाई होती है। यदि आप चाहें कि किसी एक अंग का संचालन एक प्रकार से हो और दूसरे अंग का दूसरे प्रकार से, तो यह सम्भव हो नहीं सकता क्योंकि विभिन्न अंगों का आपस में एक दूसरे से आत्मिक संबंध होता है। किसी उद्योग पर नियन्त्रण करने के लिए उससे लिए आवश्यक कच्चे माल, अन्य सहायक उद्योगों, पूँजी, बाजार आदि सब पर नियन्त्रण करना आवश्यक होगा। बिना इसके किसी एक अंग को नियन्त्रण सफल नहीं हो सकता। इसलिये जिस मिलीजुली आर्थिक व्यवस्था में 'व्यवस्थित व्यवसाय' का प्रमुख है उसका जन कल्याण की दृष्टि से सफलतापूर्वक राज्य द्वारा नियन्त्रण नहीं हो सकता। अगर ऐसा नियन्त्रण वास्तव में और सफलतापूर्वक किया जाता है तो उसका परिणाम एक ही हो सकता है

और वह है मिलीजुली अर्थ व्यवस्था का अन्त होना।

परस्पर विरोधी दलील : यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है। प्लानिंग कमीशन ने मिलीजुली अर्थ व्यवस्था के पक्ष में एक दलील यह दी है कि राज्य के पास ऐसे योग्य कर्मचारियों का अभाव है जो राजकीय व्यवसाय का संचालन कर सकें। यदि यह तर्क सही है तो फिर व्यक्तिगत व्यवसाय का राज्य के लिए निर्वन्धन करना कैसे संभव होगा। जैसा ऊपर लिखा जा चुका है किसी व्यवस्था का अन्दर से संचालन करना अपेक्षाकृत आसान होता है और बाहर से जब संचालन दूसरों के हाथ में हो, उनकी इच्छा के विरुद्ध उसका नियन्त्रण करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। इसलिए प्लानिंग कमीशन अपने मन्तव्य के लिए अगर परस्पर विरोधी दलीलों का सहारा लेता है तो उसके विचार की कमजोरी का इससे संकेत मिलता है।

प्लानिंग कमीशन के तर्क सही नहीं : सच्ची स्थिति यह है कि प्लानिंग कमीशन ने मिली जुली अर्थ व्यवस्था के संबंध में जो तर्क दिये हैं वे ठोस आधार पर आधारित नहीं हैं। यह ठीक है कि आज जिस प्रकार का शासनतन्त्र है उसकी यह क्षमता नहीं है कि वह किसी अर्थ व्यवस्था का सफल संचालन कर सके। वह तो सामान्य शासन व्यवस्था को भी ठीक ठीक चलाने में आज असफल हो रहा है। इसलिए सामान्य शासन व्यवस्था के लिए भी मौजूदा शासन तन्त्र को सुधारना होगा। जहां तक आर्थिक व्यवस्था के संचालन का सवाल है उसके लिए तो नये तन्त्र का निर्माण करना होगा। इसके अतिरिक्त आज जो लोग विभिन्न उद्योगों में टेक्नीशियनों या मैनेजर्स की हैसियत से काम करते हैं कल बड़ी लोग राष्ट्र के लिए अधिक उत्साह से काम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जहां तक उद्योगपतियों का सवाल है, यह ठीक है कि पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में उनका विशेष स्थान है। उद्योगपति खास तौर से दो काम आज करते हैं। एक तो वे लाभ हानि के लिए जिम्मेदार रहते हैं; दूसरे, उद्योग संबंधी बड़ी नीति का वे निर्णय करते हैं। उस नीति का निर्णय आज पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था की पृष्ठ भूमि में करना पड़ता है। कब कच्चा माल खरीदना, कितना खरीदना, कहाँ से खरीदना, किन भाव पर खरीदना, कितना उत्पादन करना, बाजार की क्या स्थिति है—आदि ऐसे प्रश्न हैं जिनका उद्योगपति निर्णय करते हैं। आर्थिक जीवन में कोई योजना न होने से आज इन निर्णयों को कई अनिश्चितताओं का अनुमान लगाकर करना पड़ता है। यदि देश की आर्थिक व्यवस्था पूंजीवाद के आधार पर संगठित न हो, और उत्पादन लाभ के लिए न होकर उपभोग के लिए हो, तो इन निर्णयों को बहुत सारी अनिश्चिततायें

मिट जायेंगी और उस हालत में उद्योगपतियों की जो दक्षता और योग्यता आज अनिवार्य हो मान्य होगी है वह उमरी उस रूप में समाज की आवश्यकता नहीं रहेगी। लाभ हानि का विम्वार भी समाज उठावेगा। इसके अलावा तब की बात यह है कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण हो जाने मात्र से आतिरकार देश में जो जन शक्ति प्राप्त है वह समाप्त नहीं हो जायगी। न यह मानना ठीक होगा कि उसका उपयोग राज्य को नहीं मिल सकेगा। और हमीनिष्ठ यह धारणा करना सही नहीं है कि राष्ट्रीयकरण हो जाने पर उद्योगों का राज्य द्वारा सरल संचालन नहीं हो सकेगा। न यह ठीक है कि आरम्भ में कुछ कठिनाइयाँ आवें। पर उन कठिनाइयों को हल करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। और दूसरे यह भी है कि परिवर्तन जितना जल्दी और एक साथ व्यापक आधार पर होगा उतना ही उसमें अधिक सफलता मिलेगी।

मिनीयुली अर्थ व्यवस्था के पक्ष में दूसरी बड़ी दलील साधनों के अभाव की है। इस समय में तो जाना ही रहता है कि यदि नरुद में मुआवजा देकर कोई राष्ट्रीयकरण करने का कभी बात खोचता है तो वह अउमव और गलत बात है। हमने साधन तो राज्य के पास कभी होने वाले ही नहीं हैं। और जैसे जैसे उद्योगों का विकास होगा जैसे जैसे वह और भी अधिक असमर्थ होता जाएगा। इसलिए साधन की कमी को लेकर राष्ट्रीयकरण की बात टालना ठीक नहीं हो सकता। रहा नये उद्योगों को राज्य द्वारा स्थापित करने का प्रश्न। इसका भी सिद्धांत तो वही उत्तर है जो जन शक्ति के बारे में दिया गया है। यदि देश के उत्पादन साधनों पर समाज और राज्य का अधिकार स्थापित हो जाता है तो यह मानने का कोई कारण नहीं कि जितने साधन पूँजीपति वर्ग औद्योगिक विकास में लगा सकते हैं उतने राज्य नहीं लगा सकेगा। इस प्रश्न को अधिक तफसील में जाने की न यहाँ जरूरत है और न वह उचित है। केवल पाद रत्न की बात यही है कि देश के साधनों के राज्य के पास हस्तान्तरित होने मात्र से उनमें कोई कमी नहीं आने वाली है। अगर कुछ होने वाला है तो यही कि आज जो साधनों का अपव्यय होता है और उनका अनुचित उपयोग होता है वह बंद हो जायगा, और उन इत तक आम जनता के लिए अधिक साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

आज के उदाहरण सही नहीं। राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध और इसलिए मिनीयुली अर्थ व्यवस्था के पक्ष में आजकल एक तरह का उपरिष्ठा किया जाता है कि राज्य द्वारा स्थापित जो भी उद्योग आज मौजूद हैं कि उनका अनुभव कोई अच्छा नहीं है। यह कहा जाता है कि वह गलत का भी ऐसा ही अनुभव है।

नतीजा यह निकाला जाता है कि जब इन इनके दुक्के उद्योगों में ही सफलता नहीं मिल सके तो सारी अर्थ व्यवस्था का राज्य कैसे संचालन करेगा ! इसका एक बड़ा कारण यह बताया जाता है कि आज हमारे देश में उस कर्तव्य भावना का सर्वथा अभाव है जिसकी राज्य के कामों को ठीक-ठीक चलाने के लिए अत्यन्त आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत लाभ का आधार न दिखाई पड़े वह किसी काम को पूरी जिम्मेवारी से करना नहीं चाहता। और यह वृत्ति राष्ट्रीयकरण के लिए बाधक है। इन दर्शाओं के बारे में थोड़ा गम्भीरता से सोचना आवश्यक है।

पहली बात तो यह है कि आज जिन उद्योगों का संचालन राज्य करता है उन उद्योगों की भी पृष्ठभूमि तो वही है जो व्यक्तिगत व्यवसाय प्रधान समाज में होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की समाज व्यवस्था में व्यक्ति काम करता है, इसका उसकी मनोवृत्ति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। एक तो समाज की वर्तमान व्यवस्था है जिसमें मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिलता। ऐसी हालत में जो धेनन या मजदूरी पर काम करने वाले लोग हैं उनको उस कान से और देश में उनके प्रयत्नों से कुल उत्पादन कितना होता है इस बात से कोई सरोकार नहीं रहता। इस बात से वे अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानते और इसलिए जो काम करते हैं उसके करने में उनको कोई अपनापन और उत्साह नहीं होता। वे जानते हैं कि हमारा हिस्सा तो जितना वेतन या मजदूरी हमें मिल जाती है उतना ही है, बाकी तो पूंजीपति के जेब में जाने वाला है। ऐसी समाज व्यवस्था में अगर कोई इनका दुक्का कारखाना या उद्योग राज्य द्वारा भी चलाया जाय तो उसका काम करनेवाले लोगों की उपरोक्त मनोवृत्ति में कोई अंतर नहीं हो सकता। आज की समाज व्यवस्था में जो साधन राज्य के पास फर आदि के रूप में आते हैं उनका उपयोग भी सर्व साधारण को समान रूप से नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में जो तथा कथित जनतन्त्रीय राज्य व्यवस्था होती है उसे भी आखिरकार पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था की मर्यादाओं को मानकर चलना पड़ता है। ऐसी हालत में उस राज्य के बारे में और उसके द्वारा संचालित उद्योगों के बारे में तत्त्वतः लोगों का वही दृष्टिकोण रहता है जो पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीपति द्वारा चलने वाले कारखानों के बारे में होता है। पूंजीवादी व्यवस्था की पृष्ठभूमि में ही ये राजकीय कारखाने भी चलते हैं। इसलिए एक ओर तो पूंजीवाद का जो मूलभूत दोष है वह इन राजकीय कारखानों के साथ भी लगा रहता है और इन कारखानों में काम करने वाले लोग वह स्फूर्ति और उत्साह नहीं अनुभव कर सकते जो कि उनको

उस समय हो सकता है जबकि वे एक शोषणहीन समाज के सदस्य को हेसियस से काम करें। और इसका असर उनकी कर्तव्य भावना को स्थिर करने का भी होता है। दूसरी ओर पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत भी, राजकीय कारखाने उस व्यक्तिगत लाभहृति की प्रेरणा से तो वंचित रहते ही हैं जो व्यक्तिगत व्यवसायों का सफलता का कारण मानी जाती है। कारखाने का जो स्वामी होता है वह अपने लाभ की दृष्टि से उस कारखाने के संचालन में स्वयं कुछ लेता है और इस कारण से किसी हद तक वह प्रकार का अप्रत्यक्ष भव्यता है। पर उस राजकीय कारखानों में जो वस्तुमान व्यवस्था ने अन्तर्गत चलते हैं, न केवल उस व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अभाव रहता है जो व्यक्तिगत व्यवसायी अपने व्यवसाय के बारे में अनुमन करता है, बल्कि उस सामाजिक हित और कर्तव्य की भावना का भी, जो लोगों को प्रेरित कर सकता है और आज के व्यक्तिगत लाभ में मिलने वाली प्रेरणा का स्थान ले सकती है। सारांश यह है कि अगर हम वास्तविक दृष्टि में विचार करें तो वर्तमान राजकीय उद्योगों में पूँजीवादी और पूँजीवाद विहीन किन्हीं भी न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था, दोनों ही के गुणों का अभाव और दोषों का अस्तित्व पाया जाता है। इसलिए आज के वातावरण में जो राज्य द्वारा संचालित उद्योग हैं उनसे आचार पर सर्वथा बदली हुई समाज व्यवस्था में राज्य द्वारा संचालित उद्योगों का कोई अनुमान लगाना गलत है। आज व राज्य द्वारा संचालित इन्के दुर्बले उद्योग उस नई शोषणहीन समाज व्यवस्था में राज्य द्वारा चलने वाले उद्योगों का कोई उदाहरण नहीं हो सकते।

यहाँ एक दूसरी बात की ओर संकेत करना भी जरूरी है। यह तो ठीक है कि चूंकि पूँजीपति अपने लाभ की ध्यान में रख कर सारा कारोबार चलाता है इसलिए अप्रत्यक्ष न हो, इसका यह एक प्रकार से ध्यान रखता है। पर व्यक्तिगत या पूँजीपति का लाभ और राष्ट्र के साधनों का अन्ध्रा से अन्ध्रा उपयोग, य दो अलग अलग बातें हैं यह भी भूलना नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में रूप में मिलनेवाला लाभ और उत्पादन की कार्यकुशलता (एफिशियेंसी) जिसमें कम से कम साधनों का उपयोग करने अधिक से अधिक परिणाम लाने की चेष्टा होती है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पूँजीपतियों की दृष्टि में अपेक्षाकृत तत्काल होनेवाले लाभ ने गतस्तन रहता है और समाज का हित उत्पादन की कार्य कुशलता (एफिशियेंसी और प्रोडक्शन) को अधिकाधिक बढ़ाने में है। और यह होता है कि रूप में मुनाफा तो हो जाय पर उत्पादन की कार्यकुशलता में घटि होती रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि प्रेरक शक्ति

का हम इतना गुणगान करते हैं वह भी समाज के हित में ही कार्य करती हो ऐसा नहीं है। इसी के साथ यह बात भी आजाती है कि व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होकर जो नई-नई खोजों के लिए पूंजीवाद में वैज्ञानिकों को साधन सुविधायें दी जाती हैं उनका लक्ष्य भी कुल मिलाकर पूंजीवाद को पुष्ट करना ही होता है। आम जनता को जो लाभ आज तक इन वैज्ञानिकों की खोजों से पहुंचा है या आगे पहुंच सकता है वह व्यक्तिगत लाभ और पूंजीवाद के स्वार्थ की पूर्ति करते हुये अपने आप से जितना होजाता है वही है। और यह मानने का तो कोई कारण नहीं कि जब समाज से व्यक्तिगत लाभ की प्रेरक शक्ति निकल जायेगी तो समाज और राज्य सर्वथा जीवनहीन संस्थायें बन जायेगी, उनमें गतिशील विकास की क्षमता का सर्वथा अन्त हो जायेगा। पूंजीवाद में जो प्रतिस्पर्धा होती है वह रचनात्मक या निर्माणकारी न होकर विध्वंसकारी होती है। समाज के विकास के लिए जो प्रतिस्पर्धा का तत्त्व चाहिए वह इस विध्वंसकारी स्पर्धा का नहीं बल्कि उस रचनात्मक और निर्माणकारी प्रतिस्पर्धा का चाहिए जिसमें समान लक्ष्य के आधार पर सहयोग की प्रवृत्ति बनी रहती है। समाज के विकास में मित्र-मित्र की प्रतिस्पर्धा चाहिए, शत्रु-शत्रु की प्रतिस्पर्धा नहीं। और मित्र-मित्र की प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद में नहीं होती। वह तो शत्रु-शत्रु की प्रतिस्पर्धा होती है। इसलिए यह तर्क भ्रम पैदा करनेवाला है कि भावी प्रगति के लिए होकर और प्रतिस्पर्धा चाहिये और वह पूंजीवाद में ही पाई जाती है।

आज की व्यवस्था में चलने वाले राजकीय कारखाने सर्वथा बदली हुई व्यवस्था के राजकीय कारखानों का उदाहरण नहीं हो सकते, यह ताल्लिक दृष्टि से तो हमने समझ लिया। पर इस बारे में एक दो बातें और हो सकती हैं। यदि राजकीय आधार पर चलनेवाला कोई उद्योग असफल होता है तो इसका यह अर्थ लगाना कि यह राजकीय आधार का स्वाभाविक दोष है, सही नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि व्यक्तिगत आधार पर चलनेवाले सभी कारोबार सफल नहीं होते। बहुत से असफल भी होते हैं। इसलिए राजकीय आधार पर चलने वाले असफल कारोबार की व्यक्तिगत आधार पर चलनेवाले अधिक से अधिक सफल कारोबार से तुलना करना और फिर कोई परिणाम निकालना गलत है। इसके अलावा किसी राजकीय उद्योग की अक्षमता या अक्षमता के कारणों को हम जानें और उनका निश्लेषण करें तो यह देखेंगे कि उन कारणों का राजकीय उद्योग के साथ कोई आत्मिक या अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। फिर कई बार असफलता का कारण यह भी होता है कि जिन व्यक्तिगत व्यवसायों से उस राजकीय उद्योग का सम्बन्ध आता है वे उसके साथ आगे बढ़कर सहयोग नहीं

करते और उसकी सफलता की व्यापकता में रखकर उनका जिस तरह संयोजन होना चाहिए वह नहीं होना। और आभिरुचि और राज्य द्वारा चलने वाले इन कारोबार असफल हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। निवारण की बात यह भी है कि अगर व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा व अभाव में मनुष्य ठीक काम नहीं करता तो फिर वह सभी क्षेत्रों में नहीं करेगा। और इस आधार पर तो सिवाय उन कामों व जो कि राज्य व अलावा दूसरी कोश संधा कर ही नहीं सकते, और कोश काम राज्य व सुगुप्त होना ही नहीं चाहिए। और ऐसे अनिवार्य काम तो राज्य का आर्थिक और बाह्य सुरक्षा के तथा थोड़े से कुछ और काम हो सकते हैं। पर राज्य के कार्यक्षेत्र का अतिरिक्त विस्तार आज आर्थिक क्षेत्र में पूँजीवाद व मध्यक स्वीकार करते हैं उतना विस्तार तो अनुचित व समझा जाना चाहिए। पर हम जानते हैं कि ऐसा समझा नहीं जाता है। योंही खा मानने में इस प्रकार व तर्क की अर्थव्यवस्था हमारे सामने आ सकती है। जैसे यदि व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा व अभाव में राज्य उद्योग घरों का गन्तव्य ठीक ठीक प्रकार से नहीं कर सकता तो उस व्यक्तिगत प्रेरणा व अभाव में उद्योगों का वह ठीक ठीक नियन्त्रण भी नहीं कर सकता है।

मिली-जुली व्यवस्था में समाज में समझ नहीं आता वह तब विभिन्न दृष्टियों से विचार किया गया है उस सब का अंतर्गतता एक ही बार प्राप्त है और यह वह कि जिस मिली-जुली अर्थ व्यवस्था का चित्र प्लानिंग कमिशन ने उपस्थित किया है वह वास्तव में अव्यवस्था है, जिन बातों पर उसका आधार है वे दलाली नहीं है, और उसके द्वारा आर्थिक समानता और सामाजिक शांति व लक्ष्य का पूर्ण कदापि नहीं हो सकता। प्लानिंग कमिशन द्वारा प्रस्तुत इस की आर्थिक योजना का यह एक बहुत ही आधारभूत दोष है।

कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्त्व इस का औद्योगिक उन्नति से संबंध रखने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न कुटीर उद्योगों का है। कुटीर उद्योगों का महत्त्व औद्योगिक उन्नति व साथ साथ हमारे लोगों की आर्थिक उन्नति से भी अनिवार्य सम्बन्ध रखता है। इसका कारण यह है कि अधिकांश कुटीर उद्योग गाँवों में ही पाए जाते हैं।

भारतीय अर्थशास्त्र का प्रत्येक विद्वान् इस बात को स्वीकार करता है कि देश की आर्थिक उन्नति के लिए कुटीर उद्योगों की उन्नति बहुत आवश्यक है। योजना आयोग ने कुटीर उद्योगों के विषय में एक जगह लिखा है "यदि यदि उद्योग का पुनर्निर्माण करना है तो देश की जनसंख्या के लगभग एक तिहाई भाग

के लिए कोई दूसरा काम तलाश करना होगा। इसका अर्थ यह है कि गाँवों में एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या, जिसका सम्बन्ध देश के बहुत बड़े जन समूह से भी आता है, हल करने को पड़ी हुई है। इस दृष्टि से कुटीर उद्योगों के प्रश्न का तत्काल ही इतना महत्व है और उसको इतनी प्राथमिकता है कि उस पर जितना जोर दिया जाय उतना ही कम है। इसलिए एक ऐसी योजना की जरूरत है जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय कुशल शक्ति का विकास हो और ऐसे आर्थिक संगठन का निर्माण हो जिसमें कि कुटीर उद्योगों के सफलता पूर्वक चलने की पूरी पूरी आशा हो।

कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए प्लानिंग कमीशन ने निम्नलिखित बातों में सुधार करने को आवश्यकता बताई है—(१) संगठन (२) स्थानीय मांग (३) उत्पादन पद्धति (४) कच्चा माल और (५) अर्थ व्यवस्था। संगठन के बारे में प्लानिंग कमीशन की राय है कि अमुक स्थान के विभिन्न कुटीर उद्योगों में लगे हुए सब कारीगरों को एक ही औद्योगिक सहकारी समिति में संगठित होना चाहिए। मांग का जहाँ तक संबंध है प्लानिंग कमीशन का कहना है कि स्थानीय लोगों में अपने स्थान की बनी चीजों को खरीदने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसी के साथ कुटीर उद्योगों के काम करने की पद्धति में वैज्ञानिक खोज और अन्वेषण के द्वारा बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है, और उनको आवश्यक कच्चा माल और पूँजी पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसकी व्यवस्था करना भी जरूरी है। इन बातों में राज्य और केन्द्र की सरकारों को अधिक योजनापूर्वक काम करना होगा, यह भी सही है। इन तमाम बातों में सुधार होने से कुटीर उद्योगों की स्थिति में सुधार होगा और किसी हद तक बड़े बड़े कारखानों में तैयार माल के मुकामले में उनके माल की बाजार में टिकने की क्षमता आज से ज्यादा हो सकेगी पर एक ठो इस स्थिति तक उद्योगों को पहुँचने में समय लगेगा। दूसरे हस्के बाद भी बड़े पैमाने पर कारखानों में तैयार होने वाले माल के मुकामले में छुली प्रतिस्पर्धा में वे पूरी तौर से ठहर सकें, यह मुश्किल होगा। इसलिए जब तक देश की आर्थिक योजना में उनका स्थान सुरक्षित नहीं कर दिया जायगा तब तक कुटीर उद्योगों का सवाल पूरी तौर से हल नहीं होगा। प्लानिंग कमीशन के सामने भी यह आश्चंका है। यह उसके इन वाक्यों से स्पष्ट हो जाता है: “जब तक कि गाँव की जनता में स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार माल के लिए एक निश्चित और स्थायी बचि पैदा नहीं होती है, कुटीर उद्योगों का पतन जारी रहेगा और उनको पुनर्जीवित करने के और जो भी उपाय काम में लाये जा सकते हैं केवल उनके आधार पर कुटीर उद्योगों को रखा नहीं की जा सकेगी।”

आगे चलकर प्लानिंग कमीशन ने फिर लिखा है "गाँव का जिन तरह मंगलन है उसमें प्रामोद्योगी न मरद्वय के लिए और उाके द्वारा गाँव में अमुक मात्रा में रोजगार कायम रखने के लिए कोई गुमादर नहीं है। किसी न किसी रूप में गाँव का जनता को यह स्वीकार करना चाहिए कि जहाँ तक उनका दश चलना है गाँव न सब लोगों को, चाहे फिर वे किसान हों, या मजदूर हों या कारीगर हों, काम देने का जिम्मा उनका ही है।" अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। गाँव को जनता अपने हक जिम्मे का ज़ुम्बन करे, हमकी व्यवस्था कैसे हो। यह दो प्रकार से हो सकता है। एक तो यह कि गाँव वालों में इतना विवेक जागृत हो कि वे अपने तात्कालिक हितों की दृष्टि में आचरण न करें और अपने गाँव की बना-चाओ कोड़ा काम में लें। महात्मा गाँधी ने स्वदेशी का जिस भावना पर इतना जोर दिया था उसका पालन यहाँ दृष्टिकोण था। पर किसी आर्थिक व्यवस्था का आधार केवल भावना पर नहीं रह सकता। व्यवस्था के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण भी करना होगा है। प्रामोद्योगी के प्रश्न पर भा हमें इसी दृष्टि से विचार करना चाहिए। इसी बात का ग्याल रखने हुए सभ्यता प्लानिंग कमीशन ने यह विचार प्रकट किया है कि "बहुत संभव है कि प्रामोद्योगी की सहायता के लिये जिन उपायों का निर्देशन किया गया है उनमें परित्याग स्वरूप प्रामनिवासी कारागार की प्रतिस्पर्धा शक्ति में अनुकूल परिवर्तन हो जायगा पर अतन्तोगत्या अगर छात्राध्ययन करना न हित में प्रामोद्योगी कारीगर और बड़े पैमाने के उत्पादक के बीच में समानता लाने का दृष्टि से यह जरूरी ही मान्य पड़े तो बड़े पैमाने के उत्पादक पर 'सेम' (कर) लगाया जा सकता है। आगे चलकर हमारा न तो यह भी निष्कर्ष है कि "हमारी राय में प्रामोद्योगी एवं उद्योगों का कार्यक्रम सशक्ति बड़े पैमाने के उद्योगों में अलग नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण के लिए तेल न मिल उद्योग और तेल प्रामोद्योग का कार्यक्रम एक साथ बाँटा जाना चाहिए।" इस संवत्सार यह है कि यदि हम प्रामोद्योगों का दश की आर्थिक रचना में स्थायी स्थान रखना चाहते हैं, तो यह तभी हो सकता है जबकि केवल भावना के बल पर ही नहीं बल्कि आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना के अन्तर्गत ही इसकी व्यवस्था की जाय। प्रश्न खाल यह है कि यह व्यवस्था कैसे हो ?

इस सम्प्रदाय में प्लानिंग कमीशन ने किसी स्पष्ट भाग का निर्देशन नहीं किया है। प्रामोद्योगी और बड़े पैमाने के उद्योगों का एक साथ उत्पादन कार्यक्रम बनाने और बड़े पैमाने के उद्योगों पर 'सेम' लगाने की प्लानिंग कमीशन ने सिफारिश की है। पर इस प्रश्न पर ज्यादा आधारभूत दृष्टि में विचार किये बिना कोई स्थायी हल नहीं निकल सकता।

ग्रामोद्योगों के प्रश्न पर तीन दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। एक दृष्टि है उत्पादन विधि की, दूसरी दृष्टि है देश में पर्याप्त मात्रा में संवकी पूरा काम देने की, और तीसरी दृष्टि है व्यापक मानव हित की। उत्पादन विधि की दृष्टि केवल टेक्नीकल दृष्टि है। इसका आधार यह है कि उत्पादन का वह ढंग अपनाया चाहिये जिसमें कम से कम श्रम लगे और जो अधिक से अधिक वैज्ञानिक समझा जावे। जो कुटीर उद्योग इस आधार पर जीवित रह सकें वे रहें और जो न रह सकें वे न रहें। इस दृष्टि को कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। उत्पादन में कौनसी पद्धति अपनानी चाहिये और कौनसी नहीं इसका निर्णय केवल इस दृष्टि से नहीं किया जा सकता कि कम से कम श्रम खर्च करके अधिक से अधिक उत्पादन जिस पद्धति से हो सके उसी पद्धति को अपनाना चाहिये। दूसरी दृष्टि देश में काम करने योग्य शक्तियों को काम देने की है। अर्थात् अधिक से अधिक लोगों को जिस तरह काम मिले उस तरह से हम अपने आर्थिक संगठन का निर्माण करें। आज हमारे देश में श्रम का बाहुल्य है और पूँजी की कमी है। इसलिये हमें ऐसी उत्पादन विधियों को अधिक अपनाना होगा जिनमें श्रम की आवश्यकता अधिक हो और पूँजी की कम। यद्यपि प्लानिंग कमीशन ने इस प्रकार से इस प्रश्न का विश्लेषण नहीं किया है पर ग्रामोद्योग के प्रश्न पर उनके विचार करने का दृष्टिकोण यही है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है प्लानिंग कमीशन ने यह मंजूर किया है कि कुपि पर जो अनावश्यक जनसंख्या आज निर्भर है वहाँ से हटा कर दूसरा काम देने का एक ही रास्ता है और यह है कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने का। न तो इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने का सवाल है और न इस दृष्टिकोण के महत्व को कम करने की आवश्यकता है। पर इस दृष्टिकोण से आये जाने की जरूरत अवश्य है, ताकि व्यापक मानव हित की दृष्टि से कुटीर उद्योगों से सवाल को हल किया जा सके। प्लानिंग कमीशन ने इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया है। यह प्लानिंग कमीशन के विचार में एक आधारभूत दोष है। इस दृष्टि के बारे में थोड़ा सा खुलामा करने की जरूरत है।

समाज संगठन का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिये समुचित पाठन और सुविधा उत्पन्न करना है। समाज के आर्थिक संगठन का स्वरूप भी इसी लक्ष्य को सामने रख कर निश्चित होना चाहिये। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिये जनतन्त्र के महत्व को सभी स्वीकार करने हैं। समाज का आर्थिक संगठन भी ऐसा होना चाहिये जो जनतन्त्र को मुढ़ रखने में सहायक हो। जनतन्त्र के लिये सच्चा के केन्द्रीकरण को रोकने की आवश्यकता है। यह केन्द्री-

करण राजनैतिक और आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में असाध्यनीय है। जनता की शासनतन्त्र के मुकाबले में अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने की शक्ति को अक्षुण्ण रखना है तो यह निम्नान आवश्यक है कि आम जनता अन्न वस्त्र आदि जीवन की अनिवार्य प्रारम्भिक आवश्यकताओं के बारे में अधिक से अधिक स्वावलम्बी रहे। इस दृष्टि से विकेंद्रित प्रामोद्योगों का बड़ा महत्व है और अन्न तथा वस्त्र सभी उद्योगों का महत्व तो और भी विशाल है। दूसरी बात यह है कि उपयोग की वस्तुओं के सम्बन्ध में मनुष्य के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना मानव हित की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। कई ऐसी वस्तुएँ हैं जो कुटार उद्योगों में हाथ से ही यदि तैयार की जायें तो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होती हैं और यदि उनका उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है तो उनका स्वास्थ्यपर्यक तत्त्व गूँथ हो जाता है। पोलिश चावल की अपवा हाथ कुट चावल और मिल के तेल या बास्ती घी की अपवा घानी के तेल का भेष्यता सवमान्य है। हमारे आर्थिक भगवत का निर्माण ही इस तरह से होना चाहिये कि जिनमें उन्नत दृष्टि का पूरा पूरा समावेश हो सके। हमारा ऐसा मन है कि उन्नत आचार पर ही हमें भारी अर्थ रचना में कुटीर उद्योगों का स्थान निर्दिष्ट करना चाहिये। और इस प्रकार जिन कुटार उद्योगों का दाय के लिए महत्व हो उनका बड़े पैमाने के उद्योगों से रक्षा करने का भार राज्य को लेना चाहिये। प्लानिंग कमीशन ने जो प्रस्ताव किये हैं उनमें इस दृष्टिकोण का कहीं आभास नहीं मिलता। कुटार उद्योगों की रक्षा के उपायों का जहाँ तक सम्बन्ध है, हमें इतना ही कहने की आवश्यकता है कि यदि आवश्यक हो तो यह व्यवस्था भी राज्य द्वारा लागू की जानी चाहिये कि अधिक अधिक वस्तुओं का उत्पादन कुटार उद्योगों के आचार पर ही होगा।

किसी हद तक कुटार उद्योगों के साथ ही लगा हुआ प्रश्न छोटे पैमाने के उद्योगों का भी है। इन उद्योगों में और कुटार उद्योगों में एक अन्तर तो यह है कि छोटे पैमाने के उद्योग शहरों में स्थित हैं जबकि कुटीर उद्योग गाँवों में हैं। दूसरा अन्तर यह है कि ये उद्योग मशीन उद्योग हैं जिनमें मजदूरों द्वारा काम होता है, जबकि कुटीर उद्योग प्रायः हाथ से परिचार के सदस्यों द्वारा ही चलते हैं। इन छोटे उद्योगों का महत्व भी कई कारणों से है, जैसे देश में धन का नाशुल्य और पृथ्वी की कमी का होना, कच्चे माल को कारखानों तक और कारखानों से तैयार माल को बाजार तक लाने लेजाने के खर्च में बचत करना, और कच्चे माल और धन का जहाँ का जहाँ तैयार माल के उत्पादन में उपयोग हो जाना आदि। इन छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में भी प्लानिंग कमीशन की यह निष्कारिण है कि सम्बन्धित छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों का कार्यक्रम एक

दूसरे के सम्बन्ध के आधार पर तैयार किया जाना चाहिये। छोटे पैमाने के उद्योग के बारे में भी एक हद तक वही दृष्टि लागू होती है जो कुटीर उद्योगों के बारे में। देश में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण न हो इस विचार की इन उद्योगों के बारे में भी प्रधानता रहनी चाहिये और इसी आधार पर इनका संरक्षण होना चाहिये।

उद्योग धंधों के सम्बन्ध में जो कुछ विचार हमने अब तक प्रकट किये हैं उनका सार यह है कि प्लानिंग कमीशन ने इस सम्बन्ध में जो योजना देश के सामने प्रस्तुत की है वह आम जनता की दृष्टि से दोषपूर्ण है और उसमें उनका वास्तविक हित सुरक्षित नहीं है। मिलीजुली अर्थ व्यवस्था के आदर्श को सामने रख कर उसने आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों का इनन किया है और कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में उनकी दृष्टि किसी जीवनव्यापी विचार धारा से प्रभावित नहीं है। इसका परिणाम यह आता है कि कुल मिला कर देश में जो औद्योगिक व्यवस्था इस योजना के आधार पर बनी होगी उससे आम जनता की सामाजिक तथा आर्थिक आजादी का प्रश्न हल नहीं होगा। घन के बंटवारे में असमानता के तत्व बने रहेंगे और आम लोगों की गरीबी और बेकारी का सवाल हल करने के लिये जिस सही दिशा में देश को आगे बढ़ाना चाहिये उसमें वह नहीं बढ़ सकेगा।

योजना का आधार प्रगतिशील अर्थ रचना नहीं : अब तक हमने यह जानने का प्रयत्न किया है कि पञ्चवर्षीय योजना में जिस तरह के आर्थिक विषय की कल्पना की गई है वह क्या है और देश की आम जनता के आर्थिक हितों की उससे कहां तक रक्षा होनी है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार वहां की कृषि और उद्योग व्यवस्था होती है। इसीलिए प्लानिंग कमीशन ने देश की भावी आर्थिक उन्नति के लिए कृषि और उद्योग के सम्बन्ध में जो प्रस्तावित योजना प्रकाशित की है उसका हमने अध्ययन किया है। जैसा कि यथा स्थान हमने पहले भी लिखा है, हमारे इस अध्ययन का सार यह है कि प्लानिंग कमीशन ने देश की कृषि व्यवस्था के बारे में जो सिफारिशें की हैं वे मूलतः ठीक हैं पर उद्योग धंधों के बारे में जो सुझाव उन्होंने पेश किए हैं वे ठीक नहीं हैं। ऐसा मानने के कई कारण हैं। एक तो यह कि जिस तरह की मिलीजुली आर्थिक व्यवस्था के पक्ष में प्लानिंग कमीशन है वह वास्तव में पूँजीवादी व्यवस्था ही होगी और इसलिए उसके द्वारा आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकेगी। दूसरे, कुटीर उद्योगों के बारे में जो दृष्टिकोण प्लानिंग कमीशन ने अपनाया है वह निश्चित और स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ी कमी

प्लानिंग कमिशन द्वारा प्रस्तुत योजना नंबर ३ यह है कि योजना व्यापक मानव कल्याण का दृष्टि का सामन रखकर बना हुआ नहीं है। जीवन सम्बन्धी जो दृष्टिकोण इस योजना में पाये गलूम पड़ता है, वह यही दृष्टिकोण है जिसके अनुसार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मूल्यों को मान कर चला जाता है। दूसरे शब्दों में प्लानिंग कमिशन की प्रस्तावित योजना इस आधार पर बनाई नहीं है कि आर्थिक जीवन मनुष्य जीवन और आप में एक संपूर्ण इकाई है और व्यवहार के क्षेत्र में उसका अलग अलग हिस्सा नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक, नैतिक आदि में बांटना और हस्तगत ३ लिए अलग अलग विधानों की स्वीकार करना नहीं है। यही एक बात माफ कर देना जरूरी मालूम होता है। चूंकि खेती का जिस तरह का पुनसंरचना कमिशन ने सुझाया है वह मूलतः सही है और चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग ६८% जन एकात्मिकी से अपनी आजीविका कमाती है, इस लिए यह कहा जा सकता है कि उद्योग वर्गों का विचार एक बार छोड़ भी दिया जाए तब भी देश की अधिकांश जन संख्या का तो इस योजना से मेल हो जायगा। पर ऐसा सोचना पूरा तथ्या नहीं है। देश की आर्थिक व्यवस्था एक संपूर्ण इकाई होती है इसलिए यह सुझाव नहीं हो सकता कि उनका एक अंग तो प्रगतिशील हो और दूसरा अग्रगतिशील। अब तक देश की औद्योगिक व्यवस्था का आधार ठीक नहीं होता बरत कृषि व्यवस्था के स्वरूप को बदलने से कोई काम नहीं हो सकता। कृषि का वह अंग जो उद्योग वर्गों के लिए कच्चा माल पैदा करता है, वास्तव में औद्योगिक व्यवस्था के एक अंग के रूप में है और इसलिए औद्योगिक व्यवस्था की आवश्यकतों और सुराहियों से यह मुक्त नहीं हो सकता। जिस कृषि के द्वारा खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है उसमें काम करने वाले लोगों पर भी उपभोक्ता के नाते और कई ढंगों में उत्पादक के नाते भा देश की औद्योगिक व्यवस्था का असर पड़ता है। नतीजा यह है कि औद्योगिक व्यवस्था में अगर कोई मूलभूत दोष है तो उसका असर देश के समस्त आर्थिक जीवन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। इसलिए प्लानिंग कमिशन की योजना के पक्ष में यह दलील नहीं दी जा सकती कि चूंकि खेती के पुनसंरचना के बारे में उनका दृष्टिकोण मूलतः प्रगतिशील है इसलिए खेती में लगी हुई जनता का रक्षा तो उसके द्वारा हो ही जायगी।

७. नया क्या है ? प्लानिंग कमिशन द्वारा प्रस्तुत योजना का आधारभूत विधानों की दृष्टि से अध्ययन कर लेने के बाद यह भी आवश्यक है कि उस योजना वास्तव में क्या है, इस सम्बन्ध में भी कुछ जानकारी करली जाये। हम

योजना के अन्तर्गत राजकीय क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) में कुल १७६३ करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है । इसके दो भाग हैं । पहले भाग पर १४६३ करोड़ रुपया खर्च करने का अनुमान है । यह धारा की गई है कि जो साधन उपलब्ध हैं उनसे यह खर्च निम्नलिखित आवेगा । पर प्लानिंग कमीशन को यह शंका अवश्य है कि संभव है २६० करोड़ रुपए की कमी पड़ जाए और उस हद तक नया रुपया जारी करके खर्च की पूर्ति करनी पड़े । योजना के पहले भाग के कार्यान्वित हो जाने पर द्वितीय महायुद्ध के पहले जिस मात्रा में आवश्यक उपभोक्ता पदार्थ उपलब्ध थे, उसी मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे । पर यदि हम चाहते हैं कि देश की आर्थिक प्रगति इसमें कुछ तेज गति से हो तो विनियोग की मात्रा किसी हद तक बढ़ानी पड़ेगी । इसके अलावा पहले भाग में जिन योजनाओं को शामिल किया गया है उनकी दृष्टि से जो कुछ टेक्निकल व्यवस्था की जायगी, उसका पूरा पूरा उपयोग करने के लिए भी यह जरूरी है कि विनियोग की मात्रा बढ़ाई जाए । इन्हीं सब कारणों से पंचवर्षीय योजना का दूसरा भाग तैयार किया गया है जिसमें ३०० करोड़ रुपया खर्च करने की सिफारिश है । इस खर्च के लिए विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

योजना के प्रथम भाग में १४६३ करोड़ रुपए के खर्च का विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार से बँटवारा किया गया है :—

	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत
कृषि और ग्रामविकास	१६१'६६	१२'८ "
सिंचाई और शक्ति	४५०'०६	३०'२ "
यातायात और संवाहन	३८८'१२	२६'१ "
उद्योग	१००'६६	६'७ "
सामाजिक सेवाएं	२५४'२२	१७'० "

[शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान

मजदूर, विछुटी जातियां]

पुनर्स्थापन	७६'००	५'३ "
विभिन्न	२८'५४	१'६ "

कुल १४६२'६२ १०० "

१४६३ करोड़ रुपए का उपरोक्त व्यय केन्द्रीय और राज्य की सरकारों में बराबर बराबर सा बँटा हुआ है । केन्द्रीय सरकार का हिस्सा ७३४ करोड़ रुपए का और राज्य की सरकारों का ७५६ करोड़ रुपए का है । राज्य की सर-

कारों में 'अ' राज्य का ५६० करोड़, 'ब' राज्य का १७१ करोड़ और 'स' राज्य का २८ करोड़ का है। पन्द्राय सरकार के खर्चों में माकरा नागन, दामोदर घाटी, हीराबुद्ध और हरिजे योजनाओं पर होने वाला खर्च और पुनरुत्थापन के खर्च का बहुत सा हिस्सा शामिल है। वास्तव में इसमें से बहुत सा खर्च राज्य की सरकारों के द्वारा होगा। यदि राज्य की सरकारों के खर्चों में इस खर्च को भी जोड़ लिया जाए तो राज्यों का हिस्सा ६७५ करोड़ तक पहुँच जाता है।

पंचवर्षीय योजना में व्यक्तिगत व्यवसाय के आधार पर चलने वाले उद्योग धर्मों के संबंध में इन वाले खर्च का भी अनुमान लगाया गया है। प्लानिंग कमिशन का कहना है कि उनकी योजना के अनुसार बड़े पैमाने पर चलने वाले उद्योग धर्मों में इन वाले पाँच सालों में लगभग २५० ६०० करोड़ रुपया खर्च होगा। पर जहाँ तक व्यक्तिगत व्यवसाय के आधार पर चलने वाली खेती सम्बन्धी योजनाओं का सवाल है प्लानिंग कमिशन ने उनमें होने वाले खर्च के कोई आँकड़े नहीं दिये हैं। इसका कारण यह है कि प्लानिंग कमिशन के पास जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध थी उसके आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सका कि आने वाले पाँच वर्षों में राष्ट्र की आय का कितना हिस्सा बचाकर आर्थिक विकास में लगाया जा सकेगा।

जहाँ तक कि देश के विभिन्न भागों में पाई जाने वाला आर्थिक प्रगति सम्बन्धी असमानता का सवाल है, उस योजना द्वारा उसमें कोई खास सुधार नहीं हो सकेगा क्योंकि साधनों का कमी और जो योजनाएँ शुरू की जा चुकी हैं उनको पूरी करने के कारण इस प्रकार की आर्थिक असमानता को दूर करने की दृष्टि से नई योजनाओं का समावेश नहीं किया जा सका है। फिर भी उद्योग धर्मों सम्बन्धी योजना का कम विकसित भागों को किसी हद तक लाभ अवरुद्ध मिलेगा।

कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि: पंचवर्षीय योजना में खेती सम्बन्धी जिन कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया है उनके अनुसार बड़ी योजनाओं से ८० लाख एकड़ और छोटी योजनाओं से ७० लाख एकड़ पड़त जमीन और १५ लाख एकड़ जमीन के द्वारा ड्रेक्टर सगठन द्वारा खेती के योग्य बनाई जा सकेगी। कृषि उत्पादन में निम्नलिखित वृद्धि होने की आशा की गई है —

अन्न	७९ ०० लाख टन
पटसा	०० ६० " गाँठ
कपास	१० ०० " "

तिर	१७५ लाख टन
शक	६२० " "

सायाज का उपरोक्त आधार पर उत्पादन बढ़ जाने के बाद भी देश स्वावलम्बी नहीं हो सकेगा। प्लानिंग कमिशन की विचारिश है कि ३० लाख टन अनाज प्रतिवर्ष बाहर से मँगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तब १९५५-५६ में बढ़ी हुई जनसंख्या को मानते हुये अनाज का औसत खपत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन १४३ ग्राम के हिसाब से हो सकेगी। कच्चे माल संबंधी देश की स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक सुधार होने की आशा है।

औद्योगिक क्षेत्र में मौजूदा उद्योगों के उत्पादन को उनकी मौजूदा उत्पादन क्षमता तक बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। कपड़े के उत्पादन के बारे में प्लानिंग कमिशन का अनुमान है कि मिलों का उत्पादन ४५० करोड़ गज और हाथ कापड़े का १६० करोड़ गज कपड़े तक हो जायगा। इस आधार पर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कपड़े की औसत खपत १९५५-५६ में १५ गज कपड़ा हो सकेगी। बड़े पैमाने पर चलने वाले कुछ दूसरे उद्योग धंधों में १९५५-५६ तक निम्नलिखित उत्पादन वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है :—

	१९५५-५६ में अनुमानित	१९५०-५१ में वास्तविक
हस्तात	११.१५ लाख टन	१०.०५ लाख टन
सीमेंट	४६.०० "	२६.१३ "
एलुमिनियम	००.२० "	००.०३६ "
कागज	०१.६५ "	०१.०६ "
म्यूजमिट	००.२४ "	
नमक	३०.७५ "	२६.२२ "

यातायात और संवाहन : यातायात और संवाहन के क्षेत्र में रेलों पर ही सबसे अधिक खर्च करने की योजना है। प्रधानतः यह खर्च नई रेलें खोलने का न होकर मौजूदा रेलों की स्थिति को ठीक करने का ही है। योजना के दूसरे भाग में कुछ नई योजनाओं को शामिल करना सम्भव हो सकेगा। जहाँ तक सड़कों का ताल्लुक है मुख्यतः मौजूदा राष्ट्रीय सड़कों के जो हिस्से छूटे हुए हैं उन्हें तैयार करने और राज्य की सड़कों के विस्तार की मौजूदा प्रगति को बनाए रखने पर ही ध्यान दिया जायगा। जहाँनी यातायात के क्षेत्र में योजना के प्रथम भाग में मौजूदा एनेज में ७० प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है और दूसरे भाग में और अधिक विस्तार का कार्यक्रम रखा गया है। नागरिक हवाई यातायात और टेलीफोन सम्बन्धी सुविधाओं में विस्तार करने का भी योजना में प्रस्ताव

किया गया है।

आर्थिक माधनों की व्यवस्था पंचवर्षीय योजना के प्रथम भाग में १९६३ करोड़ रुपये के व्यय का कार्यक्रम है। उसमें ११२१ करोड़ रुपये केन्द्रीय और राज्य की सरकारों का नीचे लिखे अनुसार प्राप्त हो सकेगा —

केन्द्रीय सरकार को होने वाली व्यय से	१२० करोड़ रुपये
राज्य की सरकारों को होने वाला व्यय से	८१ " "

दाय कालान्तर अणु से—

केन्द्रीय सरकार ३५

राज्य की सरकारों ७६

११४ " "

छाटे पैमाने पर होने वाली व्यय और 'ग्रनफन्देड' अणु से

२५० " "

केपीटल अकाउंट से मिलने वाले अन्य माधन—

केन्द्रीय सरकार ७८

राज्य की सरकारों ४५

१२३ " "

रेवेन्यू अकाउंट से मिलने वाले माधन—

केन्द्रीय सरकार ११८

राज्य की सरकारों २७५

३९३ " "

रेल्वे से

३० " "

कुल

११२१ करोड़ रुपये

११२१ करोड़ रुपये इस प्रकार प्राप्त हो जाने के बाद बाकी के ३७२ करोड़ रुपये में से कुछ रुपये भारत की अमेरिका से जो हाल में अन्न सम्बन्धी अथ मिना है उससे और कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से मिलने वाली सहायता से मिल सकेगा। इस प्रकार विदेशों से और सहायता मिलने की सम्भावना भी हो सकती है। यह तो दूर योजना के पहले भाग के लिए आवश्यक अर्थ व्यवस्था की बात। योजना के दूसरे भाग का जहाँ तक सम्बन्ध है, प्लानिंग कमिशन ने कहा है कि इसमें लिये आवश्यक अर्थ व्यवस्था के बारे में विदेशी सहायता पर ही निर्भर रहना होगा।

केन्द्रीय और राज्य की सरकारों को उपलब्ध होने वाले साधनों के बारे में प्लानिंग कमिशन यह मानकर सोचता है कि अन्न तथा सामान्य जैसी वस्तुओं में कृषि नहीं होगी और राज्य की सरकारों को मौजूदा करों से अधिक आय नहीं हो सकेगी तथा स्वर्च में कमी की जा सकेगी और समान्य अणु भी मिल सकेगा। अन्तिम व्यवसाय के आधार पर चलने वाले बड़े पैमाने के उद्योगों के

लिये जो १५०-३०० करोड़ रुपया चाहिये उसमें से नए विकास के लिये लगभग १२५ करोड़ रुपया तो बचत में और इन्वस्ट्रियल फाइनेन्स कोरपोरेशन जैसी संस्थाओं से और राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता से मिल सकेगा। इसके अलावा जो १२५-१७५ करोड़ रुपया चाहियेगा वह अनिश्चित मुनाफा करके धारस मिलने वाले रुपये से रक्षित कोष से तथा उत्पादन लागत में बचत करके पूरा किया जा सकेगा।

प्लानिंग कमिशन ने यह अनुमान लगाया है कि राज्य द्वारा होने वाले खर्च और बड़े पैमाने के उद्योगों में व्यक्तिगत व्यवसाय द्वारा होने वाले खर्च को मिलाकर देखें तो पांच साल तक लगभग ४०० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष से कुछ अधिक ही का विनियोग करना होगा। भारत जैसे देश के लिये विनियोग की यह दर काफी ऊँची है। पर इस हिसाब से विनियोग सम्भव हो सकेगा ऐसा प्लानिंग कमिशन का मानना है।

योजना कैसी है ? : प्लानिंग कमिशन ने जो पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की है उसका संक्षिप्त विवरण हमने ऊपर दिया है। अब हम सैद्धान्तिक विवेचन को छोड़ कर [इस बारे में पहले विचार किया जा चुका है] केवल यह विचार करेंगे कि यह योजना कैसी है और क्या इसे कार्यान्वित करना संभव होगा।

योजना के संबंध में सब से पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या इसे वास्तव में योजना का नाम देना सही है ? आज योजना का शुभ है। भावी विकास के जो भी प्रस्ताव या सुझाव हों उन्हें योजना का नाम दे देने के हम अभ्यस्त से हैं। साधारण भाषा के हिसाब से किसी भी सुझाव या प्रस्ताव को योजना का नाम दिया भी जा सकता है। परन्तु जब हम किसी राष्ट्र के सम्पूर्ण जीवन के नव-निर्माण की पृष्ठ भूमि में योजना शब्द का प्रयोग करें तो हमारा अर्थ दूसरा होता है। किसी योजना को 'राष्ट्रीय योजना' का नाम वास्तव में देना उस समय सही हो सकता है जब उस राष्ट्रीय योजना में मूलतः तीन बातों का समावेश हो। वे तीन बातें यह हैं :—

(१) जीवन की किसी स्पष्ट विचार धारा से प्रभावित समाज व्यवस्था की कल्पना, (२) समाज व्यवस्था की इस कल्पना के अनुरूप और उसकी मर्यादा में राष्ट्र की आवश्यकताओं का अनुमान, और (३) उक्त आवश्यकताओं को पूरी करने वाली एक निश्चित योजना और उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक साधनों और उपयुक्त संगठन की समुचित व्यवस्था। इस दृष्टि से यदि विचार करें तो प्रस्तावित पंचवर्षीय योजना को वास्तव में योजना नहीं कह सकते। इसमें जीवन संबंधी किसी क्रान्तिकारी और व्यापक दृष्टिकोण का

सर्वथा अभाव है और यही कारण है कि यह समाज व्यवस्था के किसी आन्तिकारी चित्र को अपना आदर्श मान कर नहीं चली है। इसका तो एकमात्र आधार यह रहा है कि जो योजनाएँ भारत सरकार या राज्य की सरकारों ने हाथ में लेली हैं उनको पूरा किया जाय। हमारा आशय यह नहीं है कि कमोशन को इन योजनाओं को पूरी करने की ओर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए था। इस पर तो ध्यान देना ही था अगर अब तक जो व्यव हो चुका है उसे नष्ट होने से बचाना था। पर एक तो यह तरीका हो सकता था कि मौजूदा योजनाओं को किसी एक समाज व्यवस्था के रूप में समाविष्ट किया जाता और दूसरा तरीका यह रहा कि इन योजनाओं से आगे दृष्टि गई हो नहीं। योजना आयोग इस दूसरे तरीके से हो चला। दूसरी बात राष्ट्र की विभिन्न आवश्यकताओं का अनुमान लगाने से सम्बन्ध रखती है। प्लानिंग कमोशन की योजना में इस दृष्टि को भी पूरा तौर से नहीं रखा गया है। यह समझ हो सकता है कि इस प्रकार योजना बनाने के लिए आवश्यक तथ्यों और आंकड़ों का अभाव रहा हो। पर इस बारे में तो यह अत्यन्त आवश्यक था कि इस अभाव को पूरा करने का प्रयत्न किया जाय। और चाहे आवश्यकतानुसार पूरी जानकारी न आती तो न आती पर जो जानकारी उपलब्ध हो उसका तो इस दृष्टि से उपयोग हो ही सकता था पर वह नहीं हो सका। उदाहरण के तौर पर देश के सब लोगों को काम देने के दृष्टिकोण का इस योजना में बिल्कुल अभाव है यद्यपि किसी भी योजना का पहला लक्ष्य यह होना चाहिए। इसी प्रकार देश के जीवन के कई क्षेत्रों में कुल कितनी आवश्यकता जिस चीज का है और विभिन्न आवश्यकताओं में कैसे भेज भेटना चाहिए, इस दृष्टि से यह योजना नहीं बनी है। इसका तो दृष्टिकोण इससे सन्या विपरीत यह रहा है कि अलग अलग उत्पादन क्षेत्रों में सारी स्थिति में कितना कितना उत्पादन सम्भव हो सकता है इसका योजना बनाली जाय। विभिन्न चीजों का आपस में कैम समन्वय होगा इस ओर ध्यान नहीं गया है। जिस योजना में आवश्यकताओं का अनुमान न किया गया हो उसमें तीसरी बात की छलना करना तो बेकार है ही। सारास यह कि सही अर्थ में हम इसे राष्ट्रीय योजना का नाम नहीं दे सकते। देश को हम बात की जरूरत है कि इस में उच्च दृष्टियों के आधार पर संशोधन कर दिया जाए। इन समय तो इसका रूप राज्य द्वारा किये जाने वाले सर्वे का योजना का रूप है।

योजना से सम्बन्ध रखने वाली दूसरी बड़ी बात यह होगी कि आर्थिक जीवन के विभिन्न अर्थों के समुचित विकास का उसमें ध्यान रक्खा गया है या नहीं। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई शक्ति और यातायात पर जो

महत्व दिया गया है वह तो ठीक है पर उद्योग धर्मों तथा शिक्षा और सांस्कृतिक विकास पर कम जोर दिया गया है। यह असंतुलन का लक्षण है और इसे सुधारने की जरूरत है। जहाँ १४६३ करोड़ में से १६२ करोड़ कृषि, ४५० करोड़ सिंचाई और शक्ति और ३८८ करोड़ यातायात पर खर्च होगा वहाँ उद्योग पर १०० करोड़ और सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पिछड़ी जातियों आदि पर २५४ करोड़ ही खर्च करने की योजना है। यह देश की जरूरत को देखते हुए बहुत कम है। सिंचाई और यातायात में कुछ कम खर्च करके समाज सेवा और उद्योगों पर खर्च अधिक किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि सिंचाई के लिए छोटी छोटी योजनाओं को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर गांधी में कुआँ, छोटी छोटी नहरों, तालाब आदि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसी प्रकार छोटे उद्योगों और ग्रामोद्योगों पर भी वेशल १६ करोड़ रुपया खर्च करने की योजना है। इस ओर अधिक खर्च करना संभव होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन ने देश की इन्फ्लोरेन्स और बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में तो कोई ध्यान दिया ही नहीं।

योजना से संबंध रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात आवश्यक साधनों की व्यवस्था करने से ताल्लुक रखती है। पंचवर्षीय योजना के पहले भाग का ही अगर हम विचार करें तो कुल १४६३ करोड़ रुपये के खर्च की बात है। एक दृष्टि से तो यह लगता है कि यह योजना काफी व्यावहारिक है। इसमें इस तरह की हवाई कल्पनाएँ नहीं हैं जिनको अमल में ही नहीं लाया जा सके। इस सम्बन्ध में हमें पिछली कुछ योजनाओं का ध्यान आता है। भारत के व्यवसायियों ने एक योजना बनाई थी जो बम्बई योजना या ताता-बिड़ला योजना के नाम से विख्यात है। यह १५ वर्षीय योजना थी जो ५-५ वर्ष की तीन अवस्थाओं में कार्यान्वित किये जाने की थी और योजना का कुल व्यय १०,००० करोड़ रुपया आँका गया था। इसी प्रकार जनता योजना थी एम० एन० राय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह योजना १० वर्षीय थी और इसमें १५,००० करोड़ रुपया खर्च आँका गया था। एक तीसरी योजना गांधी योजना थी जिसका निर्माण गांधी विचारों के आधार पर किया गया था। इसका समय भी १० वर्ष का था और कुल ३५०० करोड़ रुपया खर्च करने की योजना थी। उपरोक्त योजनाओं की तुलना में प्लानिंग कमीशन की योजना बहुत ही व्यावहारिक माध्यम पक्षी है। पर इस पर भी कई लोगों को यह शक है कि प्लानिंग कमीशन ने जो आशा रूपों के बारे में लगाई है वह ठीक उतरेगी भी या नहीं। इस सम्बन्ध में थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। प्लानिंग कमीशन ने २६

और योजना आयोग की इस पंचवर्षीय योजना की यह भी एक कमी है।

प्लानिंग कमीशन ने जो योजना प्रस्तुत की है उसका विशद विवेचन इन पंक्तियों में हमने किया है। उस सारे विवेचन का सार यह है कि इस योजना की सूची यह है कि इसने व्यावहारिकता का ध्यान रखा है। आर्थिक व्यवस्था संबन्धी उसके आधार में कई दोष तो हैं पर हमारा ऐसा विचार है कि कुल मिलाकर पांच वर्षों में देश के लिये इतना क्या योजना को कार्यान्वित करने में लगाना संभव हो सकेगा। हमें तो योजना में सबसे बड़ी दो बातों की कमी मालूम पड़ती है। एक तो इस योजना में किसी व्यापक प्रगतिशील विचार धारा का अभाव है और दूसरे इस आधार पर देश की आवश्यकताओं का अनुमान लगा कर उनकी पूर्ति करने का इसमें कोई प्रयत्न नहीं है। इसके अलावा एक तीसरी बात यह है कि योजना के मौजूदा स्वरूपमें भी विभिन्न आर्थिक आवश्यकताओं में आपस में और आर्थिक विकास तथा समाज सेवा के कार्यों में समुचित संतुलन का अभाव है। यदि योजना कमीशन कोई ऐसी योजना प्रस्तुत करना चाहता है, जो देश की आम जनता को उत्साहित करे और जिसे कार्यान्वित करने में वह कष्ट उठाकर भी पूरा पूरा योगदान दे तो यह आवश्यक है कि योजना में उपरोक्त आधार पर सुधार किया जाये।